

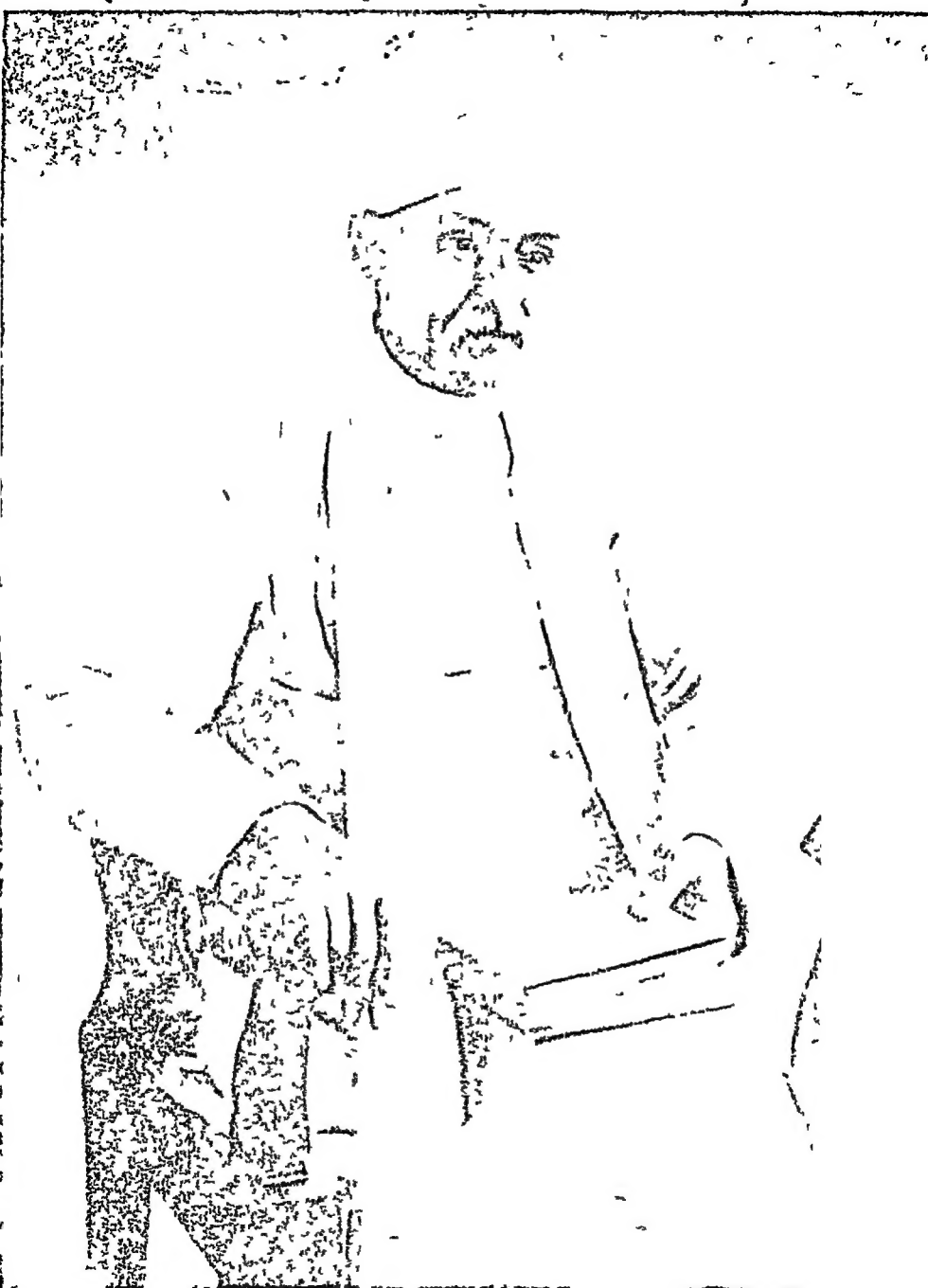
प्रथम आवृत्ति
मालवीय जयन्ती
पौष कृष्ण अष्टमी सं० २०३४
(२ जनवरी, १९७८)

मूल्य : चालीस रुपये

प्रकाशक : मालवीय अध्ययन संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

मुद्रक : तारा प्रिंटिंग वर्क्स, वाराणसी

भारतीय श्रुत दर्शन केन्द्र
जयपुर



प्राक्कथन

पंडित मदनमोहन मालवीय महापुरुष और श्रेष्ठ आत्मा थे। उन्होंने समर्पित जीवन व्यतीत किया, तथा धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि बहुत-से क्षेत्रों में अपने लोगों की उत्कृष्ट सेवाएं की। घमकियों से निडर और प्रलोभनों से अनाकर्षित उन्होंने अन्याय और क्रूरताओं से सघर्ष किया, तथा साहस और दृढ़ता पूर्वक अपने उद्देश्य की नैतिकता पर दृढ़ विश्वास के साथ अपने देशवासियों के सामूहिक हित और उत्कर्ष के लिए पचास वर्ष से अधिक काम किया। निःसन्देह उनका व्यक्तित्व उनकी महान् उपलब्धियों से कहीं अधिक प्रतिष्ठित था। वे आध्यात्मिक सद्गुणों, नैतिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक उत्कर्ष के असाधारण सश्लेषण (सिथिसिस) थे। वे निःसन्देह अजात शत्रु थे।

पंडित मालवीय जीवन और समाज का समन्वित विकास पसन्द करते थे और उन्होंने उसके लिए अपनी शक्ति भर अनवरत प्रयत्न किया। रूढ़ता (स्टेगनेशन), अधोगति, दरिद्रता और दुर्दशा उन्हें दुःखी करती थी, और उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत विदेशी दासता के चंगुल में रहेगा, तब तक भारतीय जनता इन बुराइयों से छुटकारा नहीं पा सकती। उनकी धारणा थी कि स्वस्थ विकास स्वतन्त्रता का वातावरण मांगता है। विदेशी आधिपत्य और शोषण से, भारतनिवासी अंग्रेजों के प्रजातीय दम्भ से, और ब्रिटिश अफसरों की नौकरशाही निरकुशता से वे घृणा करते थे। वे चाहते थे कि पुलिस राज्य कल्याण राज्य में बदल जाये, नौकरशाही ढाँचा के स्थान पर लोकतांत्रिक संस्थाएँ स्थापित हो, आधिपत्य की भावना का अन्त हो, और हिन्दुस्तान को ब्रिटिश कामनवेल्थ में स्वतन्त्र और समान साक्षादारी का स्थान प्राप्त हो, तथा अपने देश की सेवा के लिए भारतीय नवयुवकों को सेना में और सार्वजनिक प्रबन्ध के सब क्षेत्रों में सब स्तरों पर समान सुविधाएँ मुहैया की जायें।

राजाओं, जमींदारों और औद्योगिकों के साथ मालवीयजी के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थे। पर वे यह नहीं चाहते थे कि वे अधिकार और पोजीशन की इजारादारी का उपभोग करें। उनकी तो इच्छा थी कि श्रम और मानव व्यक्तित्व के गौरव को यथोचित मान्यता और सम्मान प्राप्त हो, हिन्दुस्तानी रियासतों में संवैधानिक सरकारें स्थापित की जायें, सबको स्वशासन का अधिकार दिया जाय,

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र

जयपुर

वयस्क मताधिकार पर लोकतन्त्र स्थापित किया जाय, और कानून द्वारा नागरिक स्वतन्त्रताएँ सबके लिए सुनिश्चित की जायें, आर्थिक कल्याण की वृद्धि के निमित्त किसानों के लिए स्थायी काश्तकारी बन्दोबस्त किया जाय और लगान में २५ प्रतिशत कमी की जाय, शोषण और अत्याचारों से मजदूरों की रक्षा की जाय, और सबको अच्छी शिक्षा और जीवन के अच्छे साधन मुहैया किए जायें।

पंडित मालवीय ने पचीस वर्ष तक केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-सभाओं में निर्वाचित सदस्य की हैसियत से काम किया। प्रान्तीय कांसिल के सदस्य की हैसियत से उन्होंने सरकार की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों की आलोचना ही नहीं की, बल्कि जनता की दुर्गति की ओर भी उसका ध्यान आकृष्ट किया, और जनता के भौतिक, शैक्षिक और नैतिक उत्थान के लिए काम करने की भी उससे कामना की, और उसके सामने कई योजनाएँ प्रस्तुत की।

केन्द्रीय विधायिका में पंडित मालवीय ने स्वशासन की राष्ट्रीय माँग के लिए बार-बार आग्रह किया। उन्होंने अध्यादेशों के आरोपण की निन्दा तथा प्रेस विधेयक, राजविद्रोह सभा विधेयक, रौलेट बिल और पब्लिक सुरक्षा विधेयक जैसे दमनकारी विधानों का विरोध ही नहीं किया, बल्कि यह भी माँग की कि सबके लिए नागरिक स्वतन्त्रताएँ पुनः प्रतिष्ठित की जायें, तथा सरकार द्वारा अपने सब कार्यों में उनका ध्यान रखा जाय। उन्होंने सेना के खर्चों को कम करने का तथा सेना और लोकसेवाओं के भारतीयकरण करने का आग्रह किया, और बार-बार वित्त विधेयक को रद्द करने के लिए वोट किया, तथा सरकार की नीतियों और उसके साम्राज्यिक व्यवहार के विरुद्ध प्रोटेस्ट के रूप में सेना-विभाग तथा शासन-परिषद के बजट में कटौती के प्रस्तावों का समर्थन किया।

वे सरकार की सीमा शुल्क सम्बन्धी नीतियों के बड़े आलोचक थे, जो उनके विचार में हिन्दुस्तान के सर्वोत्तम हितों में सोची नहीं गयी थी, बल्कि ब्रिटिश हितों को बढ़ाना ही उनका लक्ष्य था। उन्होंने सूती कपड़ों पर उत्पादक शुल्क लादने का, ब्रिटिश माल को साम्राज्यिक अधिमान देने का, हिन्दुस्तान में यूरोपियन कम्पनियों द्वारा तैयार किये गये माल को वदान्यता और आर्थिक सहायता देने का, रुपये की विनिमय दर अठारह पैस निर्धारित करने का, भारत के रिजर्व बैंक को शेयर होल्डर बैंक के रूप में स्थापित करने का डट कर विरोध किया।

सन् १९१९ के मार्शल-ला के अत्याचारों ने तथा एकमात्र गोरो के साइमन कमीशन की नियुक्ति ने न्याय की ब्रिटिश भावना पर से उनका सब विश्वास खत्म कर दिया। इन्होंने उन्हें उन लोगों को, जिन्होंने सन् १९१९ में पंजाब में अत्याचार किये थे, क्षमा प्रदान करने का विरोध करने को, तथा साइमन कमीशन का 'बाईकाट' करने के लिए जनता को आह्वान करने को ही प्रेरित नहीं किया, बल्कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनों का समर्थन करने तथा उनमें भाग लेने को भी प्रेरित किया। सन् १९३७ में उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी थी कि वह सन् १९३५ के भारतीय शासन विधान के अन्दर पद स्वीकार न करे, मन्त्रिमण्डल न बनाए।

धार्मिक मामलों में उनके विचार शास्त्र की प्रामाणिकता तथा उदारवाद का मिश्रण थे। सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों की उनकी व्याख्या निश्चय ही बहुत उदार थी। वह मानवता की भावना से, सार्वजनीन प्रेम से तथा मानवहित के प्रति निःस्वार्थ निष्ठा से ओत-प्रोत थी, और इन्हें ही वे सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धान्त मानते थे। पर शास्त्रों के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें बहुत-सी सामाजिक समस्याओं पर उस तरह पर विचार करने नहीं दिया जिस तरह समाजसुधारक चाहते थे कि वे करें। फिर भी हिन्दू समाज के परम्परानिष्ठ वर्ग पर उनका प्रभाव कुल मिलाकर स्वस्थ और प्रगतिशील था। उन्होंने अपने ढंग पर हरिजनों के उत्थान तथा हिन्दू समाज के शेष भाग से उनके निकट सम्मिलन (इंटीग्रेशन) में बहुत योगदान किया।

जबकि धर्म से सम्बन्धित सामाजिक विषयों में उन्होंने शास्त्र के आदेशों का पालन करने का प्रयत्न किया, राजनीतिक और आर्थिक विषयों में उनके विचार बहुत हद तक उदार लोकतन्त्र के बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित थे। जान स्टुअर्ट मिल, प्रोफेसर टी. एच. ग्रीन और ग्लैडस्टन की उन पर गहरी छाप थी। हर्वर्ट स्पेंसर से भिन्न, जो पुलिस राज्य के समर्थक थे, मालवीयजी ग्लैडस्टन की तरह कल्याण राज्य के पक्ष में थे, और चाहते थे कि लोकतान्त्रिक ढंग पर संगठित सरकार जनता के कल्याण और उन्नति की वृद्धि करे। वे मिश्रित अर्थतन्त्र—स्वतन्त्र व्यवसाय और जहाँ समाज के अत्यावश्यक हितों के लिए आवश्यक हो वहाँ राष्ट्रीयकरण—के पक्ष में थे।

मालवीयजी उच्च कोटि के नीतिज्ञ थे। नैतिक सिद्धान्तों और नैतिक व्यवहार को वे धर्म और संस्कृति का सार समझते थे। उनका अपना व्यक्तिगत जीवन प्राचीन हिन्दुस्तान की सर्वोत्तम नैतिक परम्पराओं और उदार लोकतन्त्र

के नैतिक आदर्शों का मूर्तरूप था । वे इस तरह भौतिक पटल पर संस्कृति के प्राचीन और अर्वाचीन तत्त्वों के संश्लेषण के समर्थक थे । शिक्षा के क्षेत्र में भी मालवीयजी पूर्व और पश्चिम के संश्लेषण के पक्ष में थे । वे चाहते थे कि भारत के नवयुवक भारत के इतिहास और संस्कृति में अच्छे तौर पर शिक्षित किये जायें, उनके उत्तम आदर्शों से अनुप्राणित किये जायें, तथा पश्चिम के सचित ज्ञान और अनुभव और आधुनिक विचारधाराओं में परिशिक्षित किये जायें ।

दिसम्बर सन् १८८६ में मालवीयजी कांग्रेस में शरीक हुए, और सन् १९३७ तक उसके वार्षिक अधिवेशनों में करीब-करीब नियमित रूप से वे उपस्थित होते रहे और जीवन के अन्त तक वे उससे सम्बन्धित रहे । जब उसकी नीतियों और कार्यक्रमों से उनका मतभेद हुआ, तब भी उस संस्था और उसके उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा अविचल बनी रही । छ-सात वर्ष तक उन्होंने हिन्दू महासभा आन्दोलन को उत्प्रेरित किया, जिसमें साम्प्रदायिक पुट अनिवार्य ही थी । पर जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 'आत्मकथा' में स्वीकार किया है, जब तक पंडित मालवीयजी उसके प्रमुख प्राण रहे, महासभा अपने सम्प्रदायवाद के बावजूद, राजनीति में प्रतिक्रियावादी नहीं रही (पृ० ४५८) । वे चाहते थे कि हिन्दू महासभा हिन्दू समाज के सब वर्गों में अधिक ऐक्य और संहति प्रोत्साहित करे और उन्हें एक जैव (आर्गेनिक) समष्टि के अवयवों की तरह निकट से (क्लोजली) जोड़े तथा "हिन्दुओं और भारत के दूसरे सम्प्रदायों में सद्भावना प्रोत्साहित करे और संयुक्त स्वशासित भारतीय राष्ट्र की सिद्धि के लिए उनके साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करे ।" उन्होंने 'हिन्दू राष्ट्र' और 'हिन्दू राज्य' के शब्दों में कभी नहीं सोचा, और दृढ़ निश्चय के साथ जाति और सम्प्रदाय के लिहाज के बिना सब हिन्दुस्तानियों को समान भ्रातृत्व में बाधने-वाली राष्ट्रीयता का समर्थन किया ।

पंडित मालवीय ने बहुत-सी रचनात्मक योजनाओं को प्रवर्तित और समर्थित किया और बहुतसी संस्थाओं को स्थापित किया, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण 'वनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी' थी । वे चाहते थे कि भारत के नवयुवक अपनी बौद्धिक, भावात्मक और शारीरिक शक्तियाँ विकसित करें, और अपने जीवन में सामाजिक उत्तरदायित्व के विवेक का, तथा निःस्वार्थ सेवा का, और सर्वसामान्य हित के निमित्त समर्पण की भावना का पोषण करें ।

पंडित मालवीय उतने उग्र भले ही न हों, जितना कुछ लोग उन्हें देखना चाहते थे, पर वे निःसन्देह गतिशील और प्रगतिशील थे । अपनी योग्यता से अपनी

मातृभूमि और देशवासियों की भरसक सेवा की प्रखर कामना से वे स्पंदित थे, और शायद ही कोई दावा कर सके कि उन्होंने हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन के इतने बहुल क्षेत्रों में उनसे अधिक सेवा की।

कुछ प्रसिद्ध और क्षमतासम्पन्न विद्वानों द्वारा भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन पर कुछ अच्छी और विस्तृत पुस्तकें जरूर लिखी गयी हैं। कुछ प्रभावशाली सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के स्मरणपत्रों, भाषणों और लेखों के संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। पर कुल मिलाकर जीवनियों में भारतीय साहित्य बहुत दुर्बल है। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय की विस्तृत जीवनी लिखने के लिए हम प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल के कृतज्ञ हैं।

प्रोफेसर लाल भारतीय राजनीति के उत्साही विद्यार्थी हैं, वे लगभग पच्चीस वर्ष तक पंडित मालवीय के निकट सम्पर्क में भी रहे थे, और बहुत वर्षों तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा हिन्दुस्तान के आधुनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भाषण दिये हैं। जैसी उनसे आशा की जा सकती थी, उन्होंने उत्तम रीति से अच्छी पुस्तक लिखी है। यह हमें मालवीयजी के जीवन, व्यक्तित्व, विचारों और राष्ट्र-सेवाओं का उत्तम विवरण देती है, और उसके साथ ही इसमें बहुत से दूसरे भारतीय नेताओं के विचारों और उनकी सेवाओं का विश्लेषण भी है। इससे राष्ट्रीय आन्दोलन का काफी अच्छा परिचय भी प्राप्त हो सकता है। उन सबको जो भारतीय राजनीति के अध्ययन में रुचि रखते हैं मैं इस पुस्तक की सिफारिश करता हूँ।

हृदयनाथ कुजूरू

१९-१-७५

प्रस्तावना

कोई महापुरुष केवल अपने बलबूते पर मनमाने ढंग पर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। उसका चिन्तन सामाजिक गतिविधि से प्रभावित होता है। उसके क्रियाकलापो और कार्यक्रम पर देशकाल की गहरी छाप होती है। उसे कतिपय सांस्कृतिक मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है, कतिपय अन्य महापुरुषों के विचारों को ग्रहण करना होता है, बहुतों से मिलकर काम करना होता है, सहयोग की इस प्रक्रिया में ही अपना योगदान करना होता है।

मालवीयजी का जीवन, चिन्तन और योगदान ऐतिहासिक तथ्यों से वंचा है। वे स्वयं व्यक्ति को समष्टि का अंग मानते थे और निःस्वार्थ सेवा द्वारा जीवन में समष्टि को आत्मसात करना मानव का पुनीत कर्तव्य समझते थे। उनका जीवन समाज के समरस था। उनका विकास सामाजिक स्थिति के संदर्भ में ही हुआ था। वे महापुरुष इसलिए नहीं थे कि उन्होंने किसी निर्जन स्थान में समाज के क्रियाकलापो से उदासीन हो किसी यौगिक क्रिया द्वारा जीवनसिद्धि या आत्मज्ञान प्राप्त किया था। वे महापुरुष इसलिए थे कि उन्होंने अपने देश की आवश्यकताओं तथा जनता के सन्तापो और कष्टों को अपने जीवन में आत्मसात कर जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में तथा देश के गौरव की दृष्टि में अपना सारा जीवन लगा दिया था। उन्होंने स्वार्थ और अहंकार त्याग कर जन-कल्याण और देशहित में जिन विचारों को ग्रहण करना और जिन्हें सत्य मान करना उचित समझा उन्हें किया, और जिन विचारों और न्यायों का विरोध करना उचित समझा उनसे व्यक्तिगत विरोधावादे से ऊपर उठकर साहस के साथ टक्कर ली।

ऐसे जीवन के क्रियाकलापों का अव्ययन, विश्लेषण और मूल्यांकन युग की स्थिति, गतिविधि और विचारधारा के संदर्भ में करना ही सम्भव और उचित है। इस पुस्तक में इस बात का प्रयत्न किया गया है। इसमें लेखक कहाँ तक सफल हुआ है इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकते हैं।

किसी महापुरुष की जीवनी लिखते समय लेखक को अपनी निजी धारणाओं को अलग रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण से महापुरुष के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धान्तों का निष्पक्ष पर सहानुभूतिपूर्ण विश्लेषण करना होता है। यही सर्वमान्य

उचित है। इस पुस्तक को लिखते समय इस बात का यथासम्भव ध्यान रखा गया है। इस प्रयास में लेखक कहीं तक सफल हुआ है, इसका निर्णय भी पाठक ही कर सकते हैं। वह तो इतना ही कह सकता है कि उसने मालवीयजी की भावनाओं और विचारों की पृष्ठभूमि में ही उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व और योगदान का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है, और पुस्तक के अन्तिम अध्याय में मालवीयजी के व्यक्तित्व और आदर्शों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ उनके कतिपय विचारों और व्यवहारों का अनुसरण इस लोक-तान्त्रिक युग के निर्माण के लिए नितान्त आवश्यक है, वहाँ उनके बहुत से ऐसे विचार हैं जो सब लोग स्वीकार नहीं कर सकते। उनके आधार पर जहाँ कुछ लोग एक राष्ट्रनीति और कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं, वहाँ दूसरे लोग उनका विरोध करते हुए दूसरा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं।

जैसा कि सर तेज बहादुर सप्रू ने एक सस्मरण में बताया है। मालवीयजी का जीवन और उनकी सेवाएँ भारत की प्रगति के एक महत्त्वपूर्ण युग की कहानी है। सन् १८६१ में मालवीयजी ने प्रयाग में जन्म लिया और इसी वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए सेना के बहुत से विभागों में भारतीयों की भरती बन्द कर दी गयी। भारत की सेना में ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया, तथा भारतीय सैनिकों को घर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर इस तरह विभिन्न कम्पनियों में विभाजित कर दिया गया कि सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत और पुष्ट हो न हो सके। कानून बनाने के लिए विधान कौंसिलों की व्यवस्था अवश्य की गयी, पर उन पर नौकरशाही की निरकुशता पहले से भी अधिक कड़ी कर दी गयी। पर इसी वर्ष, जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया है, “भारतमाता ने मई के महीने में रवीन्द्र नाथ ठाकुर और मोतीलालजी को जन्म दिया और आगे चल कर प्रफुल्ल चन्द्र राय और मोहन मोहन को जन्म दिया। इन चारों बच्चों ने अपनी प्रतिभा से माता का मस्तक ऊँचा किया, तथा साम्राज्यशाही की भावना से अनुप्राणित यूरोपियन राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को भारत के सम्बन्ध में अपनी धारणाओं और नीतिरिति को बदलने पर मजबूर किया।”

यद्यपि सन् १८५७ के विप्लव से तीस वर्ष पहले ही राम मोहन रायजी ने उदारवादी मध्यवर्गीय चिन्तन और भारत के नवनिर्माण का सूत्रपात कर दिया था, पर सन् १८७० के बाद मध्यवर्गीय शिक्षितों ने अपने नेतृत्व में राजनीतिक संस्थाएँ स्थापित करना प्रारम्भ की और अन्ततोगत्वा सन् १८८५ में इंडियन

नेशनल कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था स्थापित की। सन् १८८६ में नवयुवक भदन मोहन ने उसमें भाग लेना प्रारम्भ किया और ५० वर्ष तक उसके तत्वावधान में भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता और नवनिर्माण के लिए वे सतत प्रयत्न करते रहे और आजीवन उससे सम्बद्ध रहे। प्रारम्भ में कांग्रेस के क्रियाकलापो का स्वरूप विशुद्ध संवैधानिक था, पर आगे चलकर इन प्रयत्नों ने संवैधानिक संघर्षों के साथ साथ अहिंसात्मक प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह का रूप भी धारण कर लिया। इन संवैधानिक प्रयत्नों और राष्ट्रीय संघर्षों में बहुत से नेताओं और हजारों कार्यकर्त्ताओं का भरपूर योगदान था। मालवीयजी का भी इनमें महत्त्वपूर्ण अंशदान था, जिसका विस्तृत विवरण इस पुस्तक में दिया गया है।

लेखक उन सब व्यक्तियों का, जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में या समाज की प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, महापुरुष के रूप में आदर करता है और यदि उसने उनके विचारों की कहीं-कहीं टिप्पणी की है तो उसका यह अर्थ नहीं कि वह उनके महत्त्व को स्वीकार नहीं करता। उसका अर्थ केवल इतना ही है कि घटनाओं के संदर्भ में उनकी प्रतिक्रियाओं की चर्चा आवश्यक थी और मालवीयजी की जीवनी में उन पर किये गये आक्षेपों का निरीक्षण अनिवार्य था। इसी कर्त्तव्य बुद्धि ने लेखक को मालवीयजी के कतिपय विचारों और क्रियाकलापों पर भी आलोचनात्मक विचार व्यक्त करने को बाध्य किया है। आशा है कि सहृदय पाठक क्षमा करेंगे।

मालवीयजी का योगदान और उनकी सेवाएँ बहुत ही विस्तृत थी और उनके क्रियाकलापों की सामग्री बहुत बिखरी हुई है। उन सबको इकट्ठा करना तो सम्भव नहीं था, फिर भी जितनी सामग्री जुटाई जा सकी है उससे मालवीयजी की सेवाओं और नेतृत्व का काफी परिचय हो सकता है। इस सम्बन्ध में लेखक अपने मित्र प्राचार्य सीताराम चतुर्वेदी तथा पंडित राम नरेश त्रिपाठी एवं मालवीयजी के पौत्र पंडित पद्म कान्त मालवीय का विशेष रूप से आभारी हैं जिनकी जुटाई सामग्री इस पुस्तक के लिखने में बहुत सहायक हुई है। सर्वश्री शिवनन्दन लाल दत्त और सोमस्कन्दन द्वारा लिखित हिन्दू विश्वविद्यालय के इतिहास का, तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की आत्मकथा, पंडित जवाहर लाल नेहरू की आटोबायोग्राफी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 'इण्डियन स्ट्रगिल', श्री पट्टाभि सीतारामैया द्वारा लिखित कांग्रेस के इतिहास का भी काफी प्रयोग किया गया है। चौधरी खलीक उज्जमा की आत्मकथा तथा कई अन्य प्रसादों का भी थोड़ासा प्रयोग किया गया है। लेखक उन सबका भी आभारी हैं। हिन्दू विश्व-

विद्यालय की मयाजीराय गायकवाट लाइब्रेरी, काशी विद्यापीठ को भगवान दाम स्वाध्यायपीठ और अभिमन्यु पुस्तकालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी वह आभारी है जिन्होंने सामग्री जुटाने में नेत्रक की सहायता की। तारा प्रिंटिंग प्रेस और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इन पुस्तक के छापने और प्रकाशन का भार वहन किया। लेखक इनका भी कृतज्ञ है।

लेखक पण्डित हृदय नाथ कुंजरू का विशेष रूप में कृतज्ञ है। उन्होंने बहुत अस्वस्थ होते हुए भी लेखक को निरन्तर प्रोत्साहित किया और प्रावधान लिखकर कृतार्थ किया। कुंजरू साहब मालवीयजी के बहुत ही विश्वसनीय सहयोगी थे। इस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे कुंजरू साहब से अधिक मालवीयजी के नार्बजनिक जीवन का ज्ञान हो, जिन्होंने उनसे अधिक मालवीय जी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा की हो, और जिन्होंने अपने जीवन में उनसे अधिक मालवीयजी का विश्वास प्राप्त हुआ हो। इन पुस्तक के लेखक को इन दोनों महापुरुषों के नेतृत्व में वर्षों स्वदेशी, हरिजनोद्धार और शिक्षा के क्षेत्रों में काम करने का और उनका वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वह उनका ऋणी है।

भाई शिवनन्दन लाल दत्त को निरन्तर प्रेरणा और सहायता के बिना इस पुस्तक का लिखना और प्रकाशन असम्भव ही था। लेखक उनका भी विशेष रूप से अनुगृहीत है। पुस्तक के लिखने में कुछ अन्य मित्रों से भी समय समय पर सहायता मिलती रही है। पर इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है, उसका सारा उत्तरदायित्व लेखक पर है। सामग्री का चयन, विचारों का विश्लेषण सब कुछ उसका ही है।

१५ जुलाई १९७७

मुकुट चिहारी लाल

विषय सूची

- | | | |
|-----------------------------|------|-------|
| प्राक्कथन—प० हृदयनाथ कुंजरू | | i-v |
| प्रस्तावना | | vii-x |
१. देश की दशा—ब्रिटिश साम्राज्यशाही की निरंकुशता, मध्यवर्गीय जन-जागृति, राजा राममोहन राय और ब्रह्मसमाज, दादा भाई नौरोजी, प्रार्थना समाज और महादेव गोविंद रानडे, स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज, सनातनधर्म की प्रतिक्रिया, रामकृष्ण परमहंस, पत्रकारिता, राजनीतिक संस्थाओं का गठन, नेशनल कांग्रेस की स्थापना और पहला अधिवेशन, जमींदारों का विरोध, सर सैयद अहमद खाँ, १-२४
 २. प्रारम्भिक जीवन—मालवीयजी का जन्म, सन् १८६१ का प्रयाग और भारत, मालवीयजी के पूर्वज, शील, उनकी कविता, शिक्षा, विनोद, विवाह, अध्यापन, सार्वजनिक कार्य २५-३७
 ३. प्रारम्भिक सार्वजनिक काम—कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, मालवीयजी का भाषण, दीनदयालु शर्मा से भेंट, भारत धर्म महा-मण्डल, सनातन धर्म सम्मेलन, ऋषिकुल, सम्पादक, राजनीतिक काम, वकालत, नागरी लिपि, भारती भवन पुस्तकालय, प्रयाग म्युनिसिपैल्टी, मेकडोनल हिन्दू बोर्डिंग हाउस, प० सुन्दर लाल, पुरुषोत्तम दास टंडन, यू० पी० औद्योगिक काफरेन्स और पण्डित बलदेव राम दवे, 'अभ्युदय' और कृष्ण कान्त मालवीय, 'लीडर' और चिन्तामणि, मिंटो पार्क, पिता का निधन, सेवा समिति और बालचर, हृदय नाथ कुंजरू, हरिद्वार की गंगा नहर, मोतीलाल नेहरू और मालवीयजी ३८-६१
 ४. कांग्रेस में काम—देश की निर्धनता पर क्षोभ और कांग्रेस की वित्तनीति की समीक्षा, नामजदगो का विरोध, लोकसेवाएँ, सन् १८९२ के एक्ट की समीक्षा और राजनीतिक सुधार की माँग, निरंकुशता का विरोध, बंगमंग का विरोध, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन और गोखले, गरमदल और नरमदल में संघर्ष, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन और दादाभाई नौरोजी, वाइसराय के पास मुस्लिम शिष्ट मंडल, १९०६ में मुस्लिम लीग का संगठन, ६२-७६

५. दमन, विघटन, सुधार—जनजागृति राजनीतिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में मालवीयजी के प्रयत्न और विचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता, धर्म और साम्प्रदायिक एकता, देशभक्ति, सच्ची राजभक्ति, स्वदेशी, राष्ट्रियता, स्वराज्य, स्वराज्य की सिद्धि और साधन, आक्रमणशील और क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी शक्तियों का क्रियाकलाप, कांग्रेस में तनाव और फूट, नेशनल कन्वेंशन, मालवीयजी का क्षोभ, १९०८ में प्रान्तीय काफरेन्स की अध्यक्षता, मार्ले-मिटो सुधार योजना और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समीक्षा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, मालवीयजी का अध्यक्षीय भाषण, कांग्रेस के प्रस्ताव, मालवीयजी की सद्भावना ७७ १०५
६. प्रान्तीय कौंसिल में काम—सरकार की वित्तीय व्यवस्था आदि की आलोचना, कल्याणराज्य की पुष्टि, समाज और जीवन के उत्कर्ष और विकास की सुविधाओं की मांग, शिक्षा और चिकित्सा के समुचित प्रबन्ध की मांग, लगान में कमी की तथा स्थायी बन्दोवस्त और कृषि-शिक्षा की मांग, देशज उद्योगों के संरक्षण और प्रोत्साहन की तथा औद्योगिक शिक्षा की मांग, प्रशासन के भारतीयकरण की मांग, स्वास्थ्य, बजट पर विचार १०६-११६
७. कमेटियों में गवाही और काम—विकेन्द्रीयकरण कमीशन के सामने गवाही, इसलिंगटन कमेटी के सामने गवाही, औद्योगिक कमीशन में काम और एक विस्तृत नोट, सेना के भारतीयकरण और उच्च-स्तरीय सैनिक शिक्षा की मांग, कृषि आयोग के सामने गवाही ११७-१२९
८. उदार हिन्दू धर्म और सरल हिन्दी—मुस्लिम लीग के सम्बन्ध में मालवीयजी की प्रतिक्रिया, उदार सनातन धर्म की व्याख्या, परम्परावादी सनातनियों की धारणा, सनातन धर्म सम्मेलनों के अधिवेशन, मन्त्रदीक्षा, गोसेवा, पंजाब में सनातन धर्म सभा का काम, सरकार से संघर्ष और धर्मोपदेश, प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता, सन् १९१० और सन् १९१९ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता, हिन्दी के सम्बन्ध में मालवीयजी के विचार १३०-१४८

६. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी—शिक्षा का प्रसार, मालवीयजी की योजना, श्रीमती बेसेन्ट की योजना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की योजना, हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए काम, सेन्ट्रल हिन्दू कालेज के अधिकारियों से समझौता, सरकार से विवाद, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल, विश्वविद्यालय का उद्घाटन, पदाधिकारी और सहयोगी, विश्वविद्यालय की विशेषताएँ, विश्वविद्यालय के प्रबन्धकों में विवाद, मालवीयजी का वात्सल्य, राजकुमार का स्वागत, सन् १९२९ का मालवीयजी का दीक्षान्त भाषण, सरकार से विवाद, राधाकृष्णन की नियुक्ति, रजत जयन्ती, सन् १९४२ का आन्दोलन, प्रगति, इकबाल नारायण गुट्टे १४९-१७९
१०. भारतीय विधान कौंसिल—कौंसिल की शक्ति, रचनात्मक समीक्षा, केन्द्रीय सरकार की वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक नीति-रीति की समीक्षा, रेलों के राष्ट्रीयकरण की माँग, किसान, समाज-सुधार के प्रश्न, शिक्षा का विस्तार, अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा विधेयक, सरकार की प्रतिक्रियाएँ, प्रतिज्ञा बद्ध कुली प्रथा, सरकार की संवैधानिक निरंकुशता, प्रेस विधेयक, विद्रोह सभा विधेयक, भारत रक्षा विधेयक, रौलेट बिल, कांग्रेस का प्रयाग अधिवेशन, राजनीतिक सुधारों पर प्रस्ताव, इस्लिगटन कमीशन की सिफारिशों का विरोध, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का प्रस्ताव, युद्ध के लिए अनुदान, मालवीयजी का नेतृत्व १८०-२१५
११. राजनीतिक जागृति, दमन और सुधार—विश्वयुद्ध, मुसलमानों की प्रतिक्रिया, क्रान्तिकारी विद्रोह श्रीमती बेसेन्ट और तिलक की प्रतिक्रियाएँ, होमरूल आन्दोलन, कांग्रेस के पुराने नेताओं की प्रतिक्रियाएँ, कांग्रेस और लीग में सहयोग, १९ सेम्बरो का मेमोरंडम, कांग्रेस लीग योजना, साम्प्रदायिक समझौता, मालवीयजी का प्रचार, दमन, कर्टिस-ड्यूक योजना, भारत सरकार की १९१६ की योजना, चेम्बरलैन का इस्तीफा और माटेग्यू की नियुक्ति, २० अगस्त सन् १९१७ की घोषणा, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, माटेग्यू की भारत-यात्रा, सुधार योजना, मालवीयजी की समीक्षा, बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, एकता के प्रयत्न, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन और मालवीयजी का अध्यक्षीय भाषण, प्रस्ताव २१६-२४८

१२. रीलेट अधिनियम और पंजाब कांड—कमेटी की रिपोर्ट, मालवीयजी का विरोध, मालवीयजी आदि का कौंसिल से इस्तीफा, गांधीजी का आन्दोलन, पंजाब कांड, कांग्रेस की मांगें, मालवीयजी आदि का पंजाब में काम, कौंसिल में जाँच के लिए कमिशन की मांग, क्षमा विधेयक का विरोध, सम्राट् की घोषणा, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, हुटर कमेटी, कांग्रेस जाँच कमेटी और उसकी रिपोर्ट, हुटर कमेटी की रिपोर्ट २४९-२८१
१३. असहयोग आन्दोलन—खिलाफत का प्रश्न, खिलाफत काफरेन्स का गठन, अहिंसात्मक आन्दोलन का निर्णय, हिजरत, कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम, खिलाफत काफरेन्स का सेना सम्बन्धी निर्णय, कांग्रेस का समर्थन, राजकुमार का बहिष्कार, मालवीयजी की धारणाएं, समझौता कराने के विफल प्रयास, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, बम्बई में सर्वदलीय काफरेन्स, चोरी चौरा कांड, असहयोग स्थगित, गांधीजी की गिरफ्तारी, मालवीयजी का काम २८२-३०१
१४. हिन्दू सघटन—पंजाब हिन्दू सभा, लाला लालचन्द के विचार, अखिल भारतीय हिन्दू सभा का गठन, मालवीयजी की विचार धारा, मोपला उपद्रव, मुलतान में उपद्रव, हिन्दू महासभा का गया अधिवेशन, महासभा का वाराणसी अधिवेशन, मालवीयजी का नेतृत्व, अस्पृश्यता की समस्या, शुद्धि की समस्या, स्त्रियों के उत्थान की समस्या, संरक्षा की समस्या, हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द, महासभा के उद्देश्य, मालवीयजी की नीति-रीति, विद्वत् परिषद, गौओं की सेवा, ब्राह्मण-अब्राह्मण सौहार्द पर जोर, लाला लाजपत राय का अध्यक्षीय भाषण, राजनीतिक प्रश्नों पर निर्णय, मालवीयजी के नेतृत्व की उपेक्षा, भाई परमानन्द की आलोचना की समीक्षा ३०२-३३२
१५. साम्प्रदायिक और संवैधानिक समस्याएं—सितम्बर सन् १९२३ में साम्प्रदायिक समझौते का प्रयत्न, अन्सारी-लाजपतराय नेशनल पेक्ट, देशबन्धु दास का बगाल पैक्ट, कोकानाडा में कांग्रेस का अधिवेशन, मई सन् १९२४ को गांधीजी का वक्तव्य, मालवीयजी के विचार, गांधीजी का उपवास और एकता सम्मेलन, बम्बई में

सर्वदलीय सम्मेलन, कोहाट के दंगो की जाच, मालवीयजी को मानपत्र, अली बन्धुओ का रोष, खिलाफत काफरेन्स सन् १९२६, इंडियन नेशनल यूनियन, लार्ड अर्विन का भाषण, याकूब का प्रस्ताव, मुसलमानो के विचार, श्रद्धानन्द का वलिदान, कांग्रेस का गोहाटी अधिवेशन, वक्तव्य, शिमला एकता सम्मेलन (१९२७), कलकत्ता में एकता सम्मेलन, मद्रास कांग्रेस का एकता सम्बन्धी प्रस्ताव, मालवीयजी का समर्थन, मौलाना मुहम्मद अली के उद्गार ३३३-३५३

१६. भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली (१६२४-१६२६)—चुनाव, नेशनलिस्ट पार्टी का गठन, सैनिक व्यवस्था पर मालवीयजी के विचार, राजनीतिक माग, बजट पर बहस, वित्त विधेयक का विरोध, ली कमीशन की सस्तुतियों का विरोध, मुडीमैन कमेटी, राष्ट्रीय माग का प्रस्ताव, मानवस्वतंत्रता की पुष्टि, लोक-न्याय की पुष्टि, सीमा शुल्क नीति, फौलाद संरक्षण विधेयक, मुद्रा और वित्तमय कमीशन, सन् १९२५ में बजट और वित्त-विधेयक पर बहस, मालवीयजी की गतिविधि, कटुता और सहयोग, स्वराज्य पार्टी द्वारा असेम्बली का बहिष्कार, स्वराज्य पार्टी पर दोषारोपण और मालवीयजी का उत्तर ३५४-३७६

१७. चुनाव संघर्ष (१६२६)—कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, तेजबहादुर सप्रू का प्रयास, मोतीलालजी का प्रयास, नेहरू-जयकर वार्ता, मोतीलाल-मालवीय वार्ता, लाजपतराय का दृष्टिकोण, चुनाव घोषणापत्र, चुनाव अभियान में कटुता, जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की समीक्षा ३७७-३९३

१८. लेजिस्लेटिव असेम्बली (१६२७-३०)—दलो की स्थिति, समाज-सुधार, मुद्रा विधेयक, फौलाद संरक्षण विधेयक, देशी उद्योगो का संरक्षण, रिजर्व बैंक विधेयक, बजट और वित्त विधेयक पर बहस, सरकार की सैनिक नीति की समीक्षा, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, कांग्रेस पार्टी द्वारा असेम्बली का बहिष्कार, बजट पर बहस १९३०, कटौती का प्रस्ताव, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी, टेरिफ बिल का कडा विरोध, मालवीयजी का त्यागपत्र, साइमन कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना, समीक्षा ३९४-४३१

१९. साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट—कमीशन की नियुक्ति का निर्णय, वाइसराय की घोषणा, विरोध, मालवीयजी की आलोचना, कमीशन का वाईकाट, मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया, कमीशन की कार्यप्रणाली, केन्द्रीय असेम्बली में बहस, कमीशन का देशव्यापी वाईकाट, लाजपतराय के निधन पर असेम्बली में बहस, सर्वदलीय काफरेन्स, नेहरू कमेटी की नियुक्ति, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस की प्रतिक्रिया तथा रिपोर्ट का समर्थन, सर्वदलीय कांफरेन्स का कलकत्ता अधिवेशन ४३२-४४६
२०. नमक सत्याग्रह और गोलमेज काफरेन्स—मालवीयजी का वाइसराय को पत्र, वाइसराय की ३१ अक्टूबर सन् १९२९ की घोषणा, भारतीय नेताओं की प्रतिक्रियाएँ, कांग्रेस का निर्णय, पूर्ण स्वराज्य दिवस, गांधीजी के ग्यारह सूत्र, गांधीजी का वाइसराय को पत्र, डाढ़ी यात्रा, पेशावर कांड, समझौते का विफल प्रयास, संघर्ष और दमन, गोल मेज काफरेन्स, प्रधान-मन्त्री की घोषणा, गांधी-अविन समझौता, कांग्रेस का कराँची अधिवेशन, साम्प्रदायिक समस्या पर कांग्रेस का वक्तव्य, मौलिक अधिकारों पर कांग्रेस का प्रस्ताव ४४७-४६६
२१. गोलमेज काफरेन्स का दूसरा सत्र—लन्दन-यात्रा, गांधीजी के विचार, मालवीयजी का योगदान, सम्पत्ति अधिकार, अल्पसंख्यक कमेटी, साम्प्रदायिक समस्या, अल्प-संख्यक पैक्ट, फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में केन्द्र में उत्तरदायी शासन की माँग, पार्लियमन्टरी सेशन में गांधीजी, मालवीयजी आदि के भाषण, प्रधानमन्त्री की घोषणा, भारतमन्त्री की दमनकारी नीति, मालवीयजी की सम्राट् तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से भेंट, मालवीयजी की गतिविधि की आलोचना और उसका उत्तर ४६७-४८८
२२. दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन, एकता कांफरेन्स, हरिजनोद्धार—सरकार का दमन, वाइसराय से गांधीजी का पत्र-व्यवहार, सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ, मालवीयजी के प्रयास, स्वदेशी संघ की स्थापना, कांग्रेस की अध्यक्षता, भारत मन्त्री का वक्तव्य, मालवीयजी का उत्तर, साम्प्रदायिक निर्णय पर गांधीजी का

अनशन, पूना पैक्ट, बम्बई में हरिजनोद्धार के सम्बन्ध में विराट् सभा और अस्पृश्यता सम्बन्धी निर्णय, मालवीयजी द्वारा आयोजित एकता काफरेन्स, एकता काफरेन्स के निर्णयों का मुसलमानों द्वारा विरोध, मुस्लिम यूनिटी बोर्ड का गठन, मालवीयजी की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता और योगदान, गांधीजी का अनशन और हरिजनोद्धार का काम, व्यक्तिगत सत्याग्रह, मालवीयजी का अन्त्यजोद्धार सम्बन्धी काम

४८९-५२३

२३. साम्प्रदायिक निर्णय—साम्प्रदायिक निर्णय, मालवीय-जिना वार्ता, राची काफरेन्स, मालवीयजी का वक्तव्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, कांग्रेस के निर्णय, कांग्रेस के साम्प्रदायिकता सम्बन्धी निर्णय पर मालवीयजी का विरोध और कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड से इस्तीफा, नेशनलिस्ट मुसलमानों का दृष्टिकोण और उसकी सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा समीक्षा, कांग्रेस के निर्णय के सम्बन्ध में नेहरू, सुभाष और राजेन्द्र बाबू की राय, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का गठन, मालवीयजी द्वारा साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध, कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन, चुनाव, साम्प्रदायिक निर्णय विरोधी काफरेन्स, केन्द्रीय असेम्बली में जिना का संशोधन स्वीकार, जिना-राजेन्द्र बाबू वार्ता, नेहरूजी द्वारा मालवीयजी की आलोचना की समीक्षा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, सन् १९३६ की चुनाव-

घोषणा, मालवीय-रफीअहमद समझौता

५२४-५४८

- २४ अन्तिम दस वर्ष—डी० ए० बी० कालेज लाहौर में मालवीयजी का भाषण, फैजपुर कांग्रेस में मालवीयजी का भाषण, कायाकल्प, हिन्दू विश्वविद्यालय की चिन्ता, महारुद्रयाग, जनसेवा, पारिवारिक शोक, सामाजिक कार्य, देश की राजनीतिक गतिविधि, सन् १९४२ का संघर्ष, मालवीयजी की सेवा, मालवीयजी की मन स्थिति, नोआखाली पर मालवीयजी का वक्तव्य, च्यवनान्त्रम, मालवीयजी का निधन, शोक और श्रद्धाञ्जलि

५४९-५७६

२५. मालवीयजी का व्यक्तित्व—धर्मनिष्ठ जीवन, देशभक्त, सात्त्विक सार्वजनिक जीवन, जनसाधारण की सेवा, करुणा और सौहार्द, उच्चकोटि के वक्ता, सद्भावना, प्राणिमात्र के प्रति प्रेम, शील, साहित्य और संगीत में रुचि, त्रुटियाँ, अद्वितीय व्यक्तित्व

५७७-५९७

२६. समुक्त म्यशासित भारतीय राज्य—राजस्थान के अध्यापित और
राजनीतिक विभाग १९१०-१९११
२७. जनसंख्या और सामाजिक स्थिति की प्रति—राजस्थान के
आर्य समाज १९१०-१९११
२८. जीवन का समीक्षात्मक विभाग—राजस्थान के राजनीतिक विभाग
समय-विभाग १९१०-१९११
२९. समीक्षात्मक विभाग—राजस्थान के राजनीतिक विभाग
समय-विभाग १९१०-१९११
३०. निष्कर्ष १९१०-१९११
- विशेषज्ञ १९१०-१९११
- समुदायिक विभाग १९१०-१९११
- समय-विभाग १९१०-१९११

१. देश की दशा

(१८५८-१८८५)

महारानी विक्टोरिया की घोषणा

सन् १८५७ के विप्लव के बाद महारानी विक्टोरिया की ओर से गवर्नर-जनरल लार्ड कैनिंग ने १ नवम्बर १८५८ को प्रयाग में सगम के तट पर शाही घोषणा को प्रसारित किया। इस घोषणा में महारानी विक्टोरिया ने घोषित किया, "हम अपने-को अपनी भारतभूमि के निवासियों के प्रति कर्तव्य के उत्तरदायित्व से उसी प्रकार बधा हुआ समझती हैं जिस प्रकार अपनी दूसरी प्रजाओं के प्रति, और ईश्वर की अनुकम्पा से हम उन उत्तरदायित्वों को ईमानदारी और शुद्ध अन्तःकरण से पूरा करेंगी। हमारी यह भी इच्छा है कि जहाँ तक सम्भव हो हमारी सब प्रजा, चाहे वह किसी सम्प्रदाय या प्रजाति की हो, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ हमारी नौकरिया के पदों पर नियुक्त की जाये, जिनके कर्तव्यों के पालन के लिए वे शिक्षा, योग्यता तथा सत्यनिष्ठा से योग्य हों। हिन्दुस्तान में शान्तिपूर्ण प्रयत्न को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक उपयोगिता और उन्नति के कार्यों को बढ़ाना, तथा वहाँ बसनेवाली सारी प्रजा के हित के लिए शासन का संचालन करना हमारी गम्भीर कामना है। उनकी समृद्धि में हमारी शक्ति है, उनके सन्तोष में हमारी रक्षा और निश्चिन्तता है, और उनकी कृतज्ञता में हमारा पुरस्कार है। हमारी जनता के हित के लिए हमारी इन इच्छाओं को वहन करने की क्षमता ईश्वर हमें और हमारे अधीन अधिकारियों को प्रदान करे।"१

साम्राज्यशाही ढाँचा

इस शाही घोषणा से कुछ दिन पहले ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को उसके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर भारत के शासन का सारा उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण कर उसका सारा भार सम्राट् के मन्त्रिमण्डल के सुपुर्द कर दिया। भारत के प्रशासन का नियन्त्रण, निर्देशन तथा निरीक्षण

१. सी. वाई. चिन्तामणि इण्डियन पालिटिक्स सिन्स दी म्युटिनी, १९४०, पृ. १७-१८.

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य भारतमन्त्री को हस्तान्तरित करते हुए शासन-व्यवस्था इस तरह केन्द्रित कर दी गयी कि शासन का कोई भी नया काम शुरू करना, या कोई भी नया कानून बनाना उनकी आज्ञा के बिना केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के लिए असंभव हो गया। भारतमन्त्री की सहायता के लिए एक कौंसिल गठित की गयी, जिसके आधे सदस्य अवसर-प्राप्त अंग्रेज प्रशासक थे और आधे भारतीय व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाले अंग्रेज व्यापारी थे। इस कौंसिल के अधिकांश निर्णय पुराने कालातीत प्रशासनिक अनुभवों तथा साम्राज्य-शाही मनोवृत्ति एवं ब्रिटिश व्यापार की हितकामना से प्रभावित होते थे, और यह कौंसिल भारत सरकार की उन सस्तुतियों को बदल देती थी जो नयी परिस्थिति और भारतीय जनमत के अनुकूल, पर कौंसिल के सदस्यों के पुराने प्रशासनिक अनुभव के प्रतिकूल होते थे, या जिन्हें ब्रिटिश व्यापार के हित में ठीक नहीं समझा जाता था। इस कौंसिल के अधिकार सीमित थे, पर इसका प्रभाव बहुत व्यापक था। ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल को भारत की समस्याओं पर विस्तार के साथ विचार करने का समय ही नहीं मिलता था। इस इंडिया कौंसिल की सलाह से ही ब्रिटिश जनता तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट और सम्राट् के नाम पर सारे भारतीय प्रशासन का संचालन होता था।

वरीय ब्रिटिश प्रशासक या अंग्रेज राजनीतिज्ञ ही बहुधा भारत के गवर्नर-जनरल नियुक्त होते थे। पर उसकी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के करोड़-करीब सभी सदस्य इंडियन सिविल सर्विस के अंग्रेज सदस्य ही होते थे। उनका दृष्टिकोण राजनीतिक के बजाय प्रशासनिक ही होता था। सेनाध्यक्ष (कमाण्डर-इन-चीफ) इस कौंसिल का विशिष्ट सदस्य होता था, जिसकी मनोवृत्ति स्वभावतः सैनिक ही होती थी।

मद्रास और बम्बई के गवर्नर कभी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और कभी अनुभवी ज्येष्ठ अंग्रेज प्रशासक होते थे। पर इन दोनों की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सभी सदस्य इंडियन सिविल सर्विस से सम्बन्धित अंग्रेज अफसर ही होते थे। अन्य प्रान्तों का सारा प्रशासन लेफ्टिनेन्ट गवर्नर या चीफ कमिश्नर के हाथ में होता था, जो सदा इंडियन सिविल सर्विस के अनुभवी प्रतिभाशाली अंग्रेज सदस्य होते थे। कानून बनाने के निमित्त केन्द्रीय और प्रादेशिक एक्जीक्यूटिव कौंसिलों में कतिपय अतिरिक्त सदस्य बढ़ा दिये जाते थे। ये सभी अतिरिक्त सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे। इनमें से कुछ संभ्रान्त हिन्दुस्तानी होते थे, जो भारतीय जनता के विचारों, हितों और भावनाओं के बजाय उच्चकुलीन मनोवृत्ति और हित-

कामना का ही प्रतिनिधित्व कर सकते थे। इन हिन्दुस्तानी सदस्यों की मनोवृत्ति कितनी संकुचित होती थी, इसका अनुमान इस बात से ही हो सकता है कि जब सन् १८८२ में गवर्नर-जनरल लार्ड रिपन ने किसानों के हितों के संरक्षण के लिए एक विधेयक तैयार किया, तो उसे भारतीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, और सरकारी सदस्यों की सहायता से ही उसे पास कराया जा सका।

सन् १८६१ के इंडियन कौंसिल एक्ट के अन्दर बम्बई और मद्रास के अतिरिक्त बंगाल में भी कानून बनाने के लिए एक कौंसिल गठित कर दी गयी, पर संयुक्त प्रान्त में इस प्रकार की कौंसिल का गठन सन् १८८६ में किया गया। इन व्यवस्थापिका कौंसिलों के अधिकार सन् १८५३ की व्यवस्था के अन्दर निर्मित केन्द्रीय कौंसिलके अधिकारों से भी अधिक सीमित थे, और वे उससे अधिक निस्तेज थी। वास्तव में भारत-मन्त्री की पूर्ण स्वीकृति के बिना ये कौंसिलें कोई अधिनियम पास ही नहीं कर पाती थी, और प्रस्तुत विधेयक के अतिरिक्त किसी दूसरे विषय पर इन कौंसिलों में विचार या आलोचना हो ही नहीं सकती थी।

सारे प्रशासन पर इंडियन सिविल सर्विस का बोलबाला था। इनके सदस्यों की नियुक्ति प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर होती थी। ये परीक्षाएं लन्दन में होती थी। इस खुली परीक्षाओं में भारतीय और अंग्रेज नवयुवक समान रूप से भाग ले सकते थे। ग्रीक और लैटिन भाषा और साहित्य, ग्रीस और रोम का इतिहास, इंग्लैण्ड का इतिहास, तथा इंगलिश न्यायव्यवस्था का इतिहास, एवं अंग्रेजी साहित्य परीक्षा के कतिपय विशिष्ट विषय थे। २२-२३ वर्ष की आयु में इंगलिस्तान जाकर प्रतियोगिता परीक्षा में अंग्रेज नवयुवकों का मुकाबला करना भारतीय नवयुवकों के लिए कठिन था। पर जब सन् १८६६ में श्री सत्येन्द्रनाथ ठाकुर लन्दन में जाकर प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए, तब सन् १८६६ में ही परीक्षा के लिए अधिकतम आयु घटाकर २१ वर्ष कर दी गयी। इस पर भी सन् १८६९ में सर्वश्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रमेशचन्द्र दत्त और के० जी० गुप्त ने सफलता प्राप्त की। इस पर गवर्नर-जनरल लार्ड नार्थब्रुक की इच्छा के विरुद्ध भारतमन्त्री लार्ड सालिसबरी ने अधिकतम आयु १९ वर्ष कर दी। गवर्नर-जनरल लार्ड लिटन ने एक गोपनीय पत्र में स्वीकार किया कि जिस प्रकार से लन्दन में प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही है और जिस तरह से अधिकतम आयु घटायी गयी है, ये सब वायदे को 'निरर्थक' बनाने के लिए की गयी चालबाजियाँ हैं। इंडियन सिविल सर्विस अंग्रेज नवयुवकों से

भरी पड़ी थी। उन्हीं का बोलबाला था। वही देश के वास्तविक प्रशासक थे। प्रशासन के सभी विभागों के उच्च पदों पर इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य आसीन थे। फौजदारी अदालतों तथा मालगुजारी सम्बन्धी अदालतों के न्यायाधीश भी सिविल सर्विस के सदस्य ही होते थे। दीवानी अदालतों के मुनसिफ अलग से भारतीय वकीलों में से नियुक्त होते थे पर बहुत से जिला-सेशन जज तथा बहुत से हाईकोर्ट के जज भी इस सिविल सर्विस के सदस्य होते थे। प्रशासन और न्यायिक अदालतों का समुचित पार्थक्य न होने के कारण फौजदारी के मुकदमों में बहुधा न्यायदृष्टि के वजाय प्रशासनिक दृष्टि से फैसले हो जाते थे। जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के स्थान पर पुलिस की कठिनाइयों पर अधिक ध्यान रखा जाता था। राजनीतिक मुकदमों में तो बहुधा न्याय की भ्रूण-हत्या ही हो जाती थी। दमनकारी कानूनों की मदद से राजनीतिक चहल-पहल दबा देना, उसे राज-विद्रोह घोषित करके न्यायालयों के जरिये और प्रशासनिक निरोधादेश द्वारा कुचल डालना सरकार के लिए सम्भव था। जो कानून उन्नीसवीं शताब्दी के पहले चरण में शत्रुओं की गतिविधि के निरोध के लिए कम्पनी ने बनाये थे, उन्हें उस समय भी भारत की दण्ड-व्यवस्था का अंग बनाये रखना, जबकि सारे भारत पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गयी थी, न्यायबुद्धि से अधिक साम्राज्यशाही मनोवृत्ति का परिचायक था।

ब्रिटिश साम्राज्यशाही को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए सन् १८६१ में पील कमीशन की सस्तुतियों पर भारत में सेना का नया संगठन किया गया। तोपखाने में हिन्दुस्तानी सिपाहियों की भरती बन्द कर दी गयी। हिन्दुस्तानी सिपाहियों की पलटनें जाति, प्रान्त और सम्प्रदाय के आधार पर इस तरह संगठित की गयी कि उनके लिए देशभक्ति की भावना से अनुप्राणित हो मिल कर काम करना सम्भव ही न हो। फौज में गोरी की संख्या बढ़ा दी गयी। बहुत-सी गोरी पलटनें आन्तरिक सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दी गयी, ताकि विद्रोह को स्थानीय स्तर पर ही आसानी से दबाया जा सके। बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा भी इन पलटनों का प्रमुख कार्य निर्धारित किया गया, पर एशिया में ब्रिटिश साम्राज्यशाही की नीतियों को सैनिक और सामरिक प्रयोगों द्वारा परिपुष्टि ही इन पलटनों का एक वास्तविक उद्देश्य था। बड़े-बड़े औहदे गोरे अफसरों के लिए सुरक्षित रखे गये, हिन्दुस्तानी सैनिक सुबेदार-मेजर से ऊँचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता था। सेनडहर्स्ट में शिक्षा-प्राप्त सैनिक ही 'किंग कमीशन' का अधिकारी हो सकता था। पर वहाँ कोई भारतीय सैनिक

शिक्षा के लिए भरती ही नहीं किया जाता था। उच्च सैनिक शिक्षा के लिए भारत में कोई सैनिक शिक्षा संस्था संस्थापित ही नहीं की गयी थी।

जनकल्याण की उपेक्षा

भारतीय शासन-व्यवस्था भी मूलरूप से साम्राज्यशाही पुलिस व्यवस्था थी। ब्रिटिश साम्राज्यशाही के प्रभुत्व को बनाये रखना, तथा शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखना ही प्रशासन के प्रमुख लक्ष्य थे। ब्रिटिश प्रशासक कल्याण-राज्य के सिद्धान्त को मानते ही नहीं थे।

देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान नगण्य और नकारात्मक था। सन् १८५७ के विप्लव के पहले ही ईस्ट इण्डिया कंपनी ने अपनी एक सौ वर्ष की आर्थिक नीति द्वारा भारत की आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। बहुत से पुराने उद्योग धन्धे नष्ट-प्राय हो गये थे। औद्योगिक पदार्थों का निर्यात बहुत कम हो गया था। सारा देश बहुत हद तक कृषि-प्रधान बन गया था। विप्लव के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रही। जनता की आर्थिक दशा बिगड़ती चली गयी। किसी विपत्ति को सहने की उसमें शक्ति ही न रही। इस काल में (१८५८-१८८५) डेढ़ करोड़ से अधिक व्यक्तियों की अकाल से मृत्यु हो गयी। सन् १८७६-७८ के भयानक अकाल में ही ८२ लाख आदमियों को मौत का सामना करना पड़ा। इस परिस्थिति पर विचार करते हुए अकाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि 'भारतीय जनता की घोर दरिद्रता तथा अकाल की विपत्ति दोनों का कारण यही है कि अधिक जनसंख्या की जीविका केवल खेती से चलती है, और तब तक इन विपत्तियों से छुटकारा पाने का उपाय नहीं हो सकता, जब तक भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योगों का प्रसार नहीं किया जाता, जिनके द्वारा अधिक जनसंख्या खेती के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों और उद्योगों से भी अपनी जीविका चला सके।' कमीशन का सुझाव था कि 'खेती के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों की उन्नति की जाय, जिन पर ऋतुओं के परिवर्तन का कुछ भी प्रभाव न पड़ता हो।' इसके बाद भी सरकार ने पुराने उद्योगों के संरक्षण तथा नये उद्योगों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मुक्त व्यापार के सिद्धान्त का इस दृढ़ता से पालन किया गया कि सन् १८६९ में लार्ड लिटन ने अपनी कार्य-परिषद के सदस्यों के विरोध के बावजूद सूती कपड़ों के आयात पर लगे सीमा-शुल्क को वापस ले लिया। इसका देशी उद्योग के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा, जबकि ब्रिटेन से सूती कपड़ों के आयात में इतनी वृद्धि हुई कि जहाँ सन् १८७८-७९ में केवल ३३ लाख रुपये का कपड़ा भारत में आया, वहाँ सन् १८८०-८१ में ९४७ लाख

रुपये के सूती कपड़ों का आयात हुआ। लार्ड रिपन के शासन-काल में भी बहुत-सी विदेशी वस्तुओं पर से आयात-शुल्क वापस ले लिया गया, और जब सन् १८९४ में वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार को विदेशी कपड़ों पर आयात-शुल्क लगाना पड़ा, तब उसने भारत के कल-कारखानों में तैयार होनेवाले सूती वस्त्रों पर उस शुल्क के बराबर का उत्पादन-शुल्क लगा दिया। सरकार ने रेलों के निर्माण में अवश्य ही महत्त्वपूर्ण योगदान किया, पर उसकी रेलवे नीति भी मूल रूप से देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के बजाय ब्रिटेन के व्यापार को बढ़ाने के लक्ष्य से ही प्रेरित थी।

भूमि व्यवस्था

सन् १८५७ के विप्लव के पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भूमि-व्यवस्था स्थापित कर दी थी। इन व्यवस्थाओं को लागू करते समय खेतिहर किसानों और मजदूरों के हितों के संरक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। विप्लव के बाद भी किसानों के हितों के प्रति उपेक्षा जारी रही। लगभग पच्चीस वर्ष के बाद सन् १८८२ में लार्ड रिपन ने एक अधिनियम द्वारा बंगाल प्रदेश के किसानों की रक्षा के निमित्त जमींदारों की मनमानी पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझा। इस अधिनियम से किसानों को कुछ राहत जरूर मिली, पर यह पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई। दूसरे क्षेत्रों की कृषि-व्यवस्थाओं में सन् १८८५ तक सामाजिक न्याय की दृष्टि से कोई संशोधन नहीं किया गया। वहाँ की कृषक जनता तो जमींदारों की ज्यादातियों का पूर्ववत् शिकार बनी रही।

गतिविधि

इस जमाने में “सरकार की नीति” जैसा कि श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने बताया, “धीमी उन्नति और तगड़ी प्रतिगामिता में बदलती रही”, और उसका स्वरूप भारतीय जनमत के बजाय “ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पार्लियामेंट की बदलती हुई नीतियों पर निर्भर होता था।”^१

जहाँ सन् १८७४ तक कतिपय क्षेत्रों में थोड़ी बहुत उन्नति हुई, वहाँ सन् १८७४ के बाद लार्ड लिटन के जमाने में भारत को भारी अवनति का सामना करना पड़ा। उन्होंने भारतीय जनहित और शिक्षित समाज

की भावनाओं की उपेक्षा करते हुए भारत पर सन् १८७९ में 'आर्म्स एक्ट' लादकर भारतीयों को बिल्कुल निहत्था कर दिया, सन् १८७८ में 'बर्निकुलर प्रेस एक्ट' चालू करके देशी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता नष्ट कर दी। उसी जमाने में ब्रिटिश सरकार ने अपनी साम्राज्यशाही अग्रवर्ती नीति (फारवर्ड पालिसी) के अधीन अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, और थोड़ी-सी रकम को छोड़कर, जो ब्रिटेन के खजाने से दी गयी, युद्ध का बाकी सब खर्चा भारत को वहन करना पड़ा। उसके बाद ब्रिटेन की उदारदलीय सरकार ने लार्ड रिपन को सन् १८८० में गवर्नर-जनरल बनाकर भेजा। उन्होंने 'बर्निकुलर प्रेस एक्ट' वापस ले लिया, तथा किसी मात्रा में स्थानीय स्वायत्त शासन की प्रणाली को चालू करने के निमित्त स्थानीय निकायों के पुनर्गठन का आदेश जारी किया। उन्होंने बंगाल प्रदेश के कृषकों के हितों की रक्षा के निमित्त एक अधिनियम भी पास कराया, कतिपय प्रगतिशील व्यक्तियों को विधान-सभाओं का सदस्य भी मनोनीत किया, तथा हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेटों को भी यूरोपियन अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार देकर रंगभेद को अदालती मामलों में किसी हद तक कम करने की कोशिश की। उन्हें अपने अंग्रेज अफसरों के प्रतिरोध और अंग्रेज निवासियों के विरोध और रोष का ऐसा सामना करना पड़ा कि उन्हें अपनी अवधि के एक वर्ष पूर्व हा लन्दन वापस चले जाना पड़ा, और उनके प्रयत्नों के कारण प्रजातीय भावना में कोई कमी नहीं हो पायी।

सर हेनरी काटन ने हिन्दुस्तानियों के प्रति अंग्रेजों के अभद्र, क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवहार की भर्त्सना करते हुए लिखा है कि "यदि किसी चायवागान के किसी मालिक पर किसी असहाय कुली पर दारुण प्रहार करने का अपराध लगता, तो उसकी सुनवाई चायवागान के मालिकों की ज्यूरी द्वारा होती, जिसका स्वाभाविक झुकाव मालिक के पक्ष में होता, और यदि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के कारण उसे सजा दी जाती, तो सब अंग्रेज मिलकर दुन्द मचा देते। एंग्लो-इंडियन समाचार-पत्रों में सजा की कड़ी आलोचना होती, दोषी के खर्चों के लिए चन्दा जमा किया जाता, तथा उसकी रिहाई के लिए सरकार को प्रभावशाली अंग्रेजों के हस्ताक्षर से मेमोरियल दिया जाता" १।

इस तरह लार्ड रिपन की उदार नीति के बावजूद भारत की शासन-व्यवस्था महारानी विक्टोरिया की शाही घोषणा के विपरीत बनी रही। गवर्नर-जनरल

लार्ड लिटन ने तो अपने शासन-काल में ही स्वीकार कर लिया था कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा पर आधारित दावों और आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक गुप्त विज्ञप्ति में लिखा कि ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार, दोनों ने उन सब तरीकों से जो उनकी शक्ति में थे, वायदों को जी भर तोड़ा है। इस दृष्टि से महारानी विक्टोरिया की घोषणा काल्पनिक और अव्यावहारिक थी, जबकि शासन-व्यवस्था वास्तविकता पर आधारित तथ्य था। पर घोषणा भी एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य था जिसके अस्तित्व को बिल्कुल भुला देना अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था, और वह एक ऐसी कल्पना थी जिसे भारत की प्रगति के लिए भारतीय राजनीतिज्ञ इसी प्रकार प्रयोग कर सकते थे जिस प्रकार इंगलिस्तान के राजनीतिज्ञों ने वर्तमान युग के प्रभातकाल में मध्य-युगीय सामन्तशाही 'मेगना-कार्टा' को ब्रिटिश जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पुष्टि में प्रयोग किया था।

मध्यवर्गीय जन-जागृति

विप्लव की विफलता के बाद सशस्त्र विद्रोह की कल्पना लुप्त हो गयी। फिर भी कतिपय मौलवियों द्वारा विद्रोह के षड्यन्त्र किसी हद तक जारी रहे, पर इनकी शक्ति सन् १८७० तक बिल्कुल क्षीण हो गयी। मध्ययुगीय धारणाओं और मर्यादाओं के प्रति निष्ठवान् मौलवियों के लिए समाज को सार्थक प्रगतिशील नेतृत्व प्रदान करना, तथा नवीन उदार धारणाओं के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना भी संभव नहीं था। यही बात उन पण्डितों और पुरोहितों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है जो हर परिस्थिति में परम्परागत मान्यताओं का अक्षरशः अनुसरण आवश्यक समझते थे, और कोई नयी बात ग्रहण करने को तैयार नहीं थे।

अभिजात वर्ग भी, जिसे समाज के स्वाभाविक नेता होने का दावा था, समाज का सार्थक नेतृत्व करने में असमर्थ था। राजे, नवाब इतने शक्तिहीन थे कि वे अपनी परेशानियों और कठिनाइयों को भी सामूहिक रूप से भारत सरकार के सामने पेश नहीं कर सकते थे। एक स्थान पर इकट्ठे होकर अपनी निजी समस्याओं पर विचार-विमर्श नहीं कर सकते थे। जमींदारों तथा तालुकेदारों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों ने विप्लव से पहले ही सन् १८५१ में 'ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन' के नाम से एक संस्था गठित कर ली थी। उसने सन् १८५२ में संयुक्त संसदीय समिति (ज्वाइन्ट पार्लियामेन्टरी कमेटी) के सामने एक बहुत ही विस्तृत परिपत्र

पेश किया था, जिसमें उसने शासन की व्यवस्था और नीति की आलोचना करते हुए माग की थी कि उन्हें सुधारा जाये, और प्रतिनिधि विधान सभा स्थापित की जाय। विप्लव के बाद सयुक्त प्रान्त के जमीदारों और तालुकेदारों ने भी 'ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन' के नाम से एक सोसाइटी गठित कर ली थी। पर यद्यपि इन दोनों संस्थाओं के कतिपय प्रतिभाशाली सदस्य बहुत ही सुसांस्कृतिक थे, और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था, पर इन संस्थाओं के लिए युग के अनुकूल राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करना संभव नहीं था। राजभक्ति उनका मूलमन्त्र था। सरकार के कर्मचारियों और अफसरों का विरोध करना उनके लिए कठिन था। इन संस्थाओं का दृष्टिकोण मूलतः सामन्तवादी था, जबकि उदारवादी लोकतन्त्र युग की पुकार थी। ऐसी स्थिति में युगानुकूल नेतृत्व का समर्थन करने के बजाय अपने वर्ग के हितों और मान की पुष्टि ही उनका मुख्य कार्य था।

किसानों और मजदूरों की दशा तो बहुत ही दयनीय थी। वे असहाय और असंगठित थे, और देश के नेतृत्व का भार वहन करना उनके लिए असंभव था। वे न तो शासन के कुचक्रों को समझ सकते थे, और न उनका सफल सक्रिय विरोध कर सकते थे। उन्हें तो वास्तव में स्वयं अपने हितों की रक्षा और पुष्टि के लिए दूसरों के नेतृत्व और सहयोग की आवश्यकता थी। किसानों का असन्तोष दीर्घकालीन राजनीतिक आन्दोलन का रूप धारण नहीं कर पाता था।

इन कारणों से देश के राजनीतिक नेतृत्व का भार वहन करना आधुनिक शिक्षा-प्राप्त मध्यवर्गीय शिक्षितों का कर्तव्य बन गया। यह वर्ग बहुत छोटा और असंगठित पर क्रमशः विकासशील था। इसके बहुत से सदस्यों में समाज-सेवा की भावना की कमी थी। पर इसके अधिकांश सदस्य इंग्लैण्ड के उदार विचारों और लोकतान्त्रिक भावनाओं से परिचित और प्रभावित थे। वे गतिशील और प्रगतिशील थे और अपने देश में ब्रिटेन के ढंग की शासन व्यवस्था प्रतिष्ठित करना चाहते थे। महारानी विक्टोरिया की शाही घोषणा उनका 'मेगना कार्टा' (महाधिकार-पत्र) था। उसकी मान्यताएँ ही उनकी मांगों का आधार थी। वे राजभक्त थे, भारत की प्रगति में ब्रिटेन के योगदान को स्वीकार करते थे, ब्रिटेन के साथ अपने देश का सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे। पर उनके विचार में भारतीय शासन की त्रुटियों को और ब्रिटिश सरकार और जनता का ध्यान आकृष्ट करना, शाही घोषणा की मान्यताओं को कार्यान्वयन करने की माँग करना, ब्रिटेन की न्याय भावना की दुहाई देना, तथा उसके आधार पर शासन की नीति-

रीति को निर्धारित करने की माँग करना, एवं भारत में ब्रिटेन के ढंग की प्रतिनिधि सस्थाओं की स्थापना की कामना करना किसी प्रकार भी राजभक्ति के विरुद्ध नहीं समझा जा सकता ।

राजा राम मोहन राय

इस उदारवादी मध्यवर्गीय चिन्तन का सूत्रपात विप्लव से तीस पैतीस वर्ष पहले राम मोहन राय ने किया, जिन्हें गोखले के शब्दों में 'आधुनिक उदारवाद का पिता' कहा जा सकता है । राम मोहन राय एक सामान्य जमींदार के पुत्र थे । उनके बहुत से मित्र और सहयोगी द्वारकानाथ ठाकुर जैसे उच्च कोटि के जमींदार थे । पर उनका जनजागृति आन्दोलन मूलतः मध्यवर्गीय था । वे एक ऐसे मध्यवर्गीय शिक्षित समाज का निर्माण करना चाहते थे, जो प्राचीन वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति पर आस्था रखते हुए रूढ़िवाद का विरोधी हो, अन्य धर्मों और संस्कृतियों के सजीव नैतिक तथ्यों को ग्रहण करते हुए व्यापक मानवीय भावना से भारतीय समाज का नवनिर्माण करे । राम मोहन राय की जनजागृति मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक थी । पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका मार्ग-दर्शन महत्वपूर्ण था । वे रहस्यवाद, रूढ़िवाद तथा जटिल कर्मकाण्ड के विरोधी तथा एकेश्वरवाद, नैतिकता और सांस्कृतिक संश्लेषण के समर्थक थे । वे चाहते थे कि हिन्दू समाज पाखण्ड को छोड़कर केवल एक परमात्मा की पूजा करने लगे । विभिन्न धर्मों में वर्णित नैतिक उपदेशों को रहस्यमय अंधविश्वासों और ऐतिहासिक सामग्री से अलग कर जीवन में आत्मसात किया जाय, तथा प्रत्येक मनुष्य दूसरों के साथ वही व्यवहार करे जो अपने प्रति चाहता है । वे तर्क और शास्त्रीय प्रमाण, दोनों की मदद से सत्य की खोज करते थे, बुद्धिसंगत शास्त्रीय वाक्य को ही प्रामाणिक समझते थे, और स्वतन्त्र चिन्तन को मनुष्य का मौलिक अधिकार मानते थे । वे यह भी चाहते थे कि भारतीय नवयुवक भारतीय दर्शन और पाश्चात्य विज्ञान का साथ-साथ अध्ययन करें, अपने चरित्र का निर्माण कर सामाजिक कुरीतियों और अन्याय का विरोध करें, तथा सहिष्णुता, न्याय और पारस्परिक सौहार्द के आधार पर सामाजिक जीवन गठित करें । भारतीय समाज की उन्नति के लिए वे निर्धनो, स्त्रियों और पिछड़े वर्गों का उत्थान नितान्त आवश्यक समझते थे । वे सती प्रथा और बहुविवाह के कट्टर विरोधी तथा विधवा-विवाह के समर्थक थे । वे चाहते थे कि समाज में स्त्रियों का समुचित आदर हो, उन्हें आत्मोत्कर्ष के साधन उपलब्ध हो, पति और पिता की सम्पत्ति में उनका भी

हिस्सा हो। राजा राम मोहन राय जाति प्रथा के जटिल बन्वनों को राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक समझते थे, और चाहते थे कि तथाकथित कुलीन वर्ग के लोग हिन्दू धर्म की उदार भावनाओं से अनुप्राणित हो जातिगत विनिष्टता के विचार को त्याग कर सबके साथ सौहार्द और आत्मीयता का व्यवहार करें।

राजा राम मोहन राय की इच्छा थी कि सरकार निर्धनों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रवन्ध करे, एवं किसानों के हितों को रक्षा की ममुचित व्यवस्था करे। वे चाहते थे कि किसानों को लगान में छूट दी जाय, और राजस्व की क्षतिपूर्ति विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगा कर की जाय। वे यह भी चाहते थे कि अंग्रेजों के बजाय भारतीय सरकारों नौकरियों पर नियुक्त किये जायें। उन्होंने अपने परिपत्र में मांग की कि दीवानों न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीश हों, जुरी व्यवस्था लागू की जाय, न्यायाधीश व लगान आयुक्त भिन्न व्यक्ति हों, न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट एक ही व्यक्ति न हो, तथा स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों से परामर्श के बाद दीवानी व फौजदारी कानून बनाये जायें।

२० अगस्त सन् १८२८ को उन्होंने ब्रह्म सभा स्थापित की। ब्रह्मसमाज की घोषणा में कहा गया कि एक ही प्रार्थना-मन्त्र में सभी प्रकार के व्यक्ति बिना भेदभाव के जमा होंगे, और एक व्यवस्थित विनम्र वार्मिक व भक्ति भावना से निराकार, सर्वव्यापी ईश्वर की पूजा व स्तुति करेंगे। किसी मूर्त अथवा अमूर्त वस्तु की ईश्वर के रूप में किसी मनुष्य द्वारा पूजा नहीं की जायेगी। ब्रह्म-समाज के विद्वानों ने एक ईश्वर की संस्तुति में ब्रह्म-संगीतो की रचना की। ब्रह्म-समाज के स्वयं-सेवकों ने बाल-विवाह, बहु-विवाह व जात-पात की जड़ता को समाप्त करने का प्रयत्न किया।

इन प्रयासों के विरुद्ध रुढ़िवादी हिन्दुओं ने ब्रह्म-समाज की प्रतिद्वन्द्वी 'धर्म सभा' की स्थापना की। श्री रावाकान्त के नेतृत्व में उसने ब्रह्म-समाज और समाज-सुधार का विरोध किया। ये लोग धर्म की परम्पराओं तथा समाज की व्यवस्था में परिवर्तन या सुधार करना धर्म-विरुद्ध समझते थे। उनकी धारणा थी कि नारी की अपेक्षा पुरुष का स्थान ऊँचा है। शास्त्र के अनुसार नारी को पिता, पति या पुत्र के अधीन रहना चाहिए। सती-प्रथा के विरोधियों का विरोध करने के लिए 'धर्म सभा' ने स्वयं-सेवकों का एक दल संगठित किया।

इस विरोध की उपेक्षा करते हुए बहुत से प्रतिभाशाली नवयुवक, जिन्होंने आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में समाज को महत्वपूर्ण सेवा की और अपनी क्षमता

के लिए यश प्राप्त किया, ब्रह्म-समाज के सदस्य बन गये। पर कुछ काल बाद ब्रह्म-समाज में फूट पड़ गयी और वह तीन भागों में विभक्त हो गया। आगे चल कर नवविधान-समाज और आदिब्रह्म-समाज साधारण ब्रह्म-समाज में शामिल हो गये, और फिर एकता स्थापित हो गयी। पर विभाजन और पारस्परिक वाद-विवाद ने उनकी गति और प्रतिष्ठा को क्षति अवश्य पहुँचायी।

दादाभाई नौरोजी

राजा राम मोहन राय के निधन के आठ वर्ष पहले ४ सितम्बर सन् १८२५ को बम्बई में एक साधारण मध्यवर्गीय पारसी परिवार में दादाभाई नौरोजी ने जन्म लिया, और अपनी शिक्षा समाप्त करने से पहले ही बीस वर्ष की आयु में सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ कर दिया। दादाभाई सच्चे मानो में मध्यवर्गीय शिक्षित समाज की क्षमता और भावना के प्रतीक थे। उन्होंने एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लेकर, एक निर्धन मध्यवर्गीय बालक की तरह आधुनिक पद्धति से शिक्षा प्राप्त कर आजीवन मध्यवर्गीय नवयुवकों के साथ काम किया, उन्हें सामाजिक सेवा में प्रोत्साहित किया, उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त किया, तथा देशव्यापी स्तर पर उनका नेतृत्व किया। राम मोहन राय की तुलना में दादाभाई नौरोजी का योगदान धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सीमित, पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत व्यापक था। जबकि राम मोहन राय अपने जीवन-काल में बंगाल के हिन्दू नवयुवकों को ही अनुप्राणित और प्रभावित कर पाये, दादाभाई नौरोजी ने पारसी समाज के नवयुवकों के साथ-साथ सारे देश के नवयुवकों की राष्ट्रीय भावनाओं और आकांक्षाओं को जागृत, विकसित और पुष्ट करते हुए एक देशव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया। यदि राम मोहन राय 'आधुनिक उदारवाद के पिता' थे, तो दादाभाई नौरोजी 'धर्म निरपेक्ष राष्ट्रीयता तथा मध्यवर्गीय राष्ट्रीय आन्दोलन के पिता' थे।

दादा भाई उच्च कोटि के समाज-सुधारक थे। अपने जीवन के आरम्भिक काल में स्त्री-शिक्षा के प्रसार, तथा पारसी धर्म की परिशुद्धि में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। पर उनकी धारणा थी कि सामाजिक उत्कर्ष के लिए राजनीतिक उत्कर्ष परमावश्यक है। अतः देश के सर्वांगीण विकास के निमित्त राजनीतिक सुधारों के लिए सतत प्रयत्न उनके सार्वजनिक जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया।

सन् १८५२ में 'बाम्बे एसोसिएशन' की स्थापना-गोष्ठी में उन्होंने ब्रिटिश राज्य की न्यायप्रियता के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए न्याय व्यवस्था, राजस्व

व्यवस्था, तथा किसानों की दशा के सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत किया, और कहा कि देश की मर्यादाओं, परम्पराओं तथा रीतियों की जानकारी न होने के कारण अंग्रेज अफसर सद्भावना रखते हुए भी ऐसे कानून और अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो उनकी दृष्टि में ठीक होते हुए भी जनता को ठीक न जँचें। उन्होंने कहा कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए 'बाम्बे एसोसिएशन' जैसी सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण, जिनके द्वारा सरकार को जनता की प्रतिक्रियाओं का पता चलता रहे, आवश्यक है। इसके बाद बुद्धि-जीवियों की राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, तथा उनके द्वारा जनता की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मांगों की पुष्टि उनके सार्वजनिक जीवन का मुख्य घंटा बन गया।

लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों पर उनकी दृढ़ निष्ठा थी। वे हिंसात्मक विद्रोह या सशस्त्र क्रान्ति के वजाय शान्तिमय संवैधानिक ढंग से लोकतन्त्र को प्रतिष्ठित करने के पक्ष में थे। वे प्रजातिवाद (रेशियलिज्म) के विरोधी थे। वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि अंग्रेजों में कुछ ऐसे स्वाभाविक विशिष्ट गुण हैं जो भारतीयों में नहीं पाये जाते हैं और जिसके कारण भारतीयों में प्रतिनिधि-शासन के संचालन की क्षमता नहीं है। उनकी धारणा थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक मानव तथा ब्रिटिश प्रजा का विशिष्ट जन्मसिद्ध अधिकार है, और दोनों हैसियतों से भारतीयों के इस अधिकार को ब्रिटेन को स्वीकार कर लेना चाहिए। उनका उदारदलीय चिन्तन मानवता की भावना से अनुप्राणित था। श्रमिक जनता के हितों और अधिकारों की समुचित रक्षा और पुष्टि वे लोकतन्त्र का कर्तव्य समझते थे। वे देशबन्धुत्व के आधार पर विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के भारतीयों में सौहार्द स्थापित कर भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। वे तो वास्तव में मानव समाज की एकता पर विश्वास करते थे, तथा विभिन्न राष्ट्रों और सस्कृतियों में सौहार्दपूर्ण सम्पर्क प्रतिष्ठित करने के पक्ष में थे।

महादेव गोविन्द रानडे

विप्लव के कुछ वर्षों बाद महाराष्ट्र में 'प्रार्थना-सभा' के नाम से सामाजिक जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। यह जागृति राजा राम मोहन राय की जन-जागृति से प्रभावित थी, पर प्राचीन भागवत धर्म और महाराष्ट्र सन्तों की धारणाओं की भी इस पर गहरी छाप थी। ईश्वर पर अटल निष्ठा और मानव-प्रेम इसके मूल मन्त्र थे। 'प्रार्थना-सभा' मुख्यतः उदार मानवीय भावनाओं से अनुप्राणित

मध्यवर्गीय शिक्षितों की संस्था थी। जिन विद्वानों ने इसकी प्रगति और प्रतिष्ठा में महत्त्वपूर्ण योगदान किया, उनमें महादेव गोविन्द रानडे प्रमुख थे। वे स्वयं एक व्यापक संस्था थे। उन्होंने बहुत से नवयुवकों को समाजसेवा में दीक्षित किया, तथा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में स्वयं प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में उन्होंने हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय अर्थतन्त्र के कुछ मुख्य सिद्धान्तों को प्रतिपादित करते हुए उसकी बुनियाद डाली।

देश की औद्योगिक उन्नति के लिए रानडे ने 'औद्योगिक कान्फ़ेंस' की बुनियाद डाली, और समाज-सुधार के लिए 'सोशल कान्फ़ेंस' कायम की। इन कान्फ़ेंसों में प्रतिवर्ष किसी न किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर वे स्वयं लेख प्रस्तुत करते, और दूसरे सहयोगियों और नवयुवकों को उनमें भाग लेने को प्रोत्साहित करते थे। वे उच्चकोटि के समाजसुधारक थे। समाज सुधार पर उनके लेख समाजविज्ञान के कतिपय मूलसिद्धान्तों पर आधारित, और मानवता की भावना से अनुप्राणित होते थे। सम्पूर्ण समाज का समन्वित विकास ही उनके सामाजिक नेतृत्व का लक्ष्य था। देश के समुचित आर्थिक विकास के लिए नवीन वैज्ञानिक तकनीक का बुद्धिसंगत प्रयोग, नये-नये उद्योग-धंधों की स्थापना, पुराने कुटीर-उद्योगों का पुनरोत्थान और विस्तार, तथा कृषीय व्यवसाय और व्यवस्था का समुचित सुधार वे आवश्यक समझते थे। वे उदारवादी थे। पर उनका उदारवाद सामाजिक न्याय और समाजकल्याण की भावना से अनुप्राणित था। वे सामूहिक कल्याण को व्यक्तिगत हितों से कहीं ऊँचा स्थान देते थे। वे भारतीय संस्कृति के विकास में मुसलमानों का योगदान स्वीकार करते थे, और चाहते थे कि सब भारतवासी प्रजाति, सम्प्रदाय और जात-पात की संकीर्णताओं से ऊपर उठ कर अपने को भारतीय समझें और पूर्ण सहयोग के साथ देशोत्थान का काम करें।

स्वामी दयानन्द और रानडे

जबकि महादेव गोविन्द रानडे ने रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत को पुष्ट किया, उनके समकालीन महर्षि दयानन्द ने निम्बार्क की तरह ईश्वर, जीव और प्रकृति-तीनों की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया। जबकि रानडे ने जीवन-सिद्धि के लिए प्रार्थना द्वारा ईश्वर की उपासना, तथा जीवन में सद्गुणों का विकास और जनहितकारी सत्कर्मों को आवश्यक बताया दयानन्द ने इनके साथ-साथ मनोयोग और वैदिक कर्मकाण्ड का अनुसरण, एवं बुढ़ापे में वानप्रस्थ और सन्यास धर्म का पालन भी आवश्यक बताया। स्वामी दयानन्द ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को

भी पुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण के पद और गौरव के महत्त्व को भी स्वीकार किया। पर उन्होंने जन्म के वजाय गुण, कर्म और स्वभाव को वर्ण का आधार बताया। जबकि रानडे ने ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत को पुष्ट करते हुए जीवन और समाज की प्रगति के लिए ऐतिहासिक स्थिति के संदर्भ में आचार-व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक बताया, दयानन्द ने सब मध्ययुगीय और अर्वाचीन प्रथाओं का परित्याग करके अतिप्राचीन वैदिक प्रथाओं, सिद्धान्तों तथा कर्मकाण्ड का अनुसरण हिन्दू जाति के उत्कर्ष के लिए आवश्यक बताया। वैदिक संस्कृति का पुनरुज्जीवन ही स्वामी दयानन्द का लक्ष्य था।

स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज

स्वामीजी वेद को अपौरुषेय समझते थे, उसे चार ऋषियों के माध्यम से अवतरित ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करते थे। वे वेदों को सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार मानते थे, और उनकी सत्यता और प्रामाणिकता पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। उन्होंने प्रचलित मूर्तिपूजा तथा पौराणिक आचार-विचार और कर्मकाण्ड की आलोचना करते हुए विशुद्ध वैदिक कर्मकाण्ड, उपासना पद्धति तथा आचार-व्यवहार का समर्थन किया, और उनका अनुसरण आवश्यक बताया। उन्होंने अन्य धर्मों और सम्प्रदायों का भी खण्डन करते हुए उनके अनुयायियों को शुद्धि द्वारा वैदिक धर्म में प्रवेश करने का हिन्दुओं को परामर्श दिया। वे पुरानी गुरुकुल पद्धति को आधुनिक शिक्षा-पद्धति से अधिक उपादेय समझते थे, और विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर देते थे। यद्यपि वे वर्णव्यवस्था को स्वीकार करते थे, पर वे प्रचलित जातिप्रथा के विरोधी थे। स्वामीजी का व्यक्तित्व बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। उनकी चिद्वत्ता और तर्कशक्ति भी अपूर्व थी।

उनके प्रचार ने पंजाब और उत्तर भारत में आर्य-समाज के रूप में धीरे-धीरे काफी जोर पकड़ा, और बहुत से निम्न मध्य वर्ग के नवयुवकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। उसने जातिप्रथा के बन्धनों को ढीला किया, शूद्र समझी जानेवाली जातियों में नयी आशा और जागृति विकसित की, उन्हें आत्मशुद्धि की ओर प्रेरित किया। आर्यसमाज ने जहाँ साम्प्रदायिक असहिष्णुता और वाद-विवाद को प्रोत्साहित किया, वहाँ शिक्षा और समाज-सुधार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया, और बहुत से हिन्दू नवयुवकों को समाज-सेवा की प्रेरणा प्रदान की।

सनातन धर्म सभा

आर्य समाज के जवाब में 'सनातन धर्म सभा' कायम हुई। ये दोनों संस्थाएँ वेदों पर आस्था रखती थी, उन्हें अपने धर्म का मूलाधार मानती थी, और संस्कृत साहित्य के अध्ययन पर जोर देती थी, तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति को ससार की सर्वोत्तम संस्कृति समझती थी। दोनों ही अपने पूर्वजों के गुणगान से नहीं थकती थी, तथा धार्मिक नित्य नैमित्तिक कार्यों और संस्कारों को विधिवत् करने पर जोर देती थी। फिर भी अवतारवाद, पुराणों की प्रामाणिकता, मूर्तिपूजा, समाज-सुधार आदि विषयों पर दोनों में काफी मतभेद था। इस कारण काफी कटुता पैदा हो गयी थी। समाज-सुधार को लेकर तो विवाद बहुधा वैमनस्य और विघटन का स्वरूप धारण कर लेता था।

रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में जिस महापुरुष ने बंगाल में धर्म के प्रति निष्ठावान् व्यक्तियों को सबसे अधिक आकृष्ट किया, वे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। उनके व्यक्तित्व में बच्चों जैसी सरलता और कोमलता के साथ-साथ सिद्धों जैसी आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय था। वे बच्चों जैसा व्यवहार करते-करते समाधिस्थ हो जाते थे। वे प्रत्येक स्त्री में, अपनी धर्मपत्नी में भी, माता का दर्शन करते थे। वे उच्च कोटि के योगी और भक्त थे। उन्होंने जिन नवयुवकों को अपनी ओर आकृष्ट किया, उनमें अनेक उनके सम्पर्क में आने से पहले अनीश्वरवादी या अज्ञेयवादी थे और आध्यात्मवाद को कोरी कल्पना मानते थे। इन सबमें प्रमुख नरेन्द्र नाथ दत्त थे, जो आगे चलकर स्वामी 'विवेकानन्द' के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने अपनी सब पुरानी भौतिकवादी कल्पनाओं को त्यागकर एक सन्यासी के भेष में देश-विदेश में आध्यात्मवाद का प्रचार किया। उन्होंने सन् १८९३ में शिकागो के 'विश्व धर्म सम्मेलन' में अपने भव्य व्यक्तित्व तथा अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक निष्ठाओं के बल पर विश्वख्याति प्राप्त की।

पत्रकारिता

विप्लव के बाद बीस-पच्चीस वर्ष तक समाचार पत्र ही विचारों के प्रसार के मुख्य साधन थे। यद्यपि विप्लव के पहले ही अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं में समाचार-पत्र निकलने लगे थे, पर सन् १८५८ के बाद तो सार्वजनिक कार्य-कर्ताओं ने इस काम में विशेष दिलचस्पी लेना शुरू की। सन् १८७५ में लगभग

५२५ पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती थी। इनमें १४७ अंग्रेजी भाषा में और ३७४ भारतीय भाषाओं में या अंग्रेजी के साथ किसी देशी भाषा में प्रकाशित होती थी। इनमें अधिकांश पत्र मासिक या साप्ताहिक थे, पर कुछ दैनिक भी थे। इनमें से कुछ यूरोपियन और पादरियों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, और कुछ यूरोपियन और एंग्लो-इण्डियन व्यापारियों द्वारा किसी प्रसिद्ध यूरोपियन के सम्पादकत्व में प्रकाशित होते थे। ब्रिटिश साम्राज्य की पुष्टि, भारत सरकार की नीति का समर्थन, तथा भारत-निवासी यूरोपियन और एंग्लो-इण्डियनों के गौरव और हितों की रक्षा और पुष्टि इन पत्रों का मुख्य लक्ष्य था।

भारतीय हितों की रक्षा और वृद्धि, देश की समस्याओं का भारतीय दृष्टिकोण से विश्लेषण, जनता के कष्टों के निवारण पर आग्रह, जनता की आकांक्षाओं का समर्थन, तथा लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार भारतीय पत्रकारों का मुख्य उद्देश्य था। प्रजातीय अहंकार से निर्मुक्त व्यवहार, पक्षपातरहित न्याय, जनहितकारी नीतियों का अनुसरण, प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास, तथा भारत के शासन में समता और क्षमता के आधार पर भारतीय प्रजा की साक्षादारी इस युग के भारतीय पत्रकारों की माँगें थी।

यद्यपि अधिकांश भारतीय पत्रकार मध्यवर्गीय विचारों और आकांक्षाओं का प्रतिपादन, प्रचार और पोषण करते थे, पर ये बातें सब पत्रों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। मिसाल के तौर पर क्रिस्तो दासपाल द्वारा सम्पादित 'हिन्दू पेट्रियट' ब्रिटिश शासन के समर्थन के साथ-साथ जमींदारों के हितों को विशेष रूप से पुष्ट करता था, और फुले द्वारा संचालित और भालेकर द्वारा सम्पादित 'दीनबन्धु' जनता की गरीबी, बीमारी और निरक्षरता को दूर करने पर ही विशेष जोर देता था। गरीब जनता के हित की रक्षा और पुष्टि ही उसका मुख्य ध्येय था। कतिपय पत्रकारों का दृष्टिकोण मूलतः परम्परावादी था, और कतिपय समाजसुधार पर ही जोर देते थे। अधिकांश किसी न किसी अंश में सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के सुधारों के पक्ष में थे।

राजनीतिक संस्थाओं का गठन

सन् १८७० के बाद मध्यवर्गीय शिक्षितों ने अपने नेतृत्व में राजनीतिक संस्थाएँ स्थापित करना शुरू की। कलकत्ता में 'अमृत बाजार पत्रिका' के संस्थापक और सम्पादक श्री शिशिर कुमार घोष ने, जो अपनी योग्यता तथा देशभक्ति और पवित्र जीवन के लिए समाज में बहुत सम्मानित थे, 'बंगाल नेशनल लीग'

संस्थापित की। कुछ दिन बाद सन् १८७६ में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और श्री आनन्द मोहन बोस के प्रयास से कलकत्ता में 'इंडियन असोसिएशन' स्थापित हुआ। सन् १८७७ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उत्तर भारत के कई नगरों में जाकर वहाँ अपने राजनीतिक विचारों का प्रसार किया, तथा लाहौर में 'इंडियन असोसिएशन' खोलने का प्रयत्न किया।

सन् १८७८ में उन्होंने पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भ्रमण किया। इन दोनों यात्राओं में उन्होंने इंग्लैण्ड के साथ-साथ भारत में सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तथा परीक्षा में बैठने के लिए आयु की सीमा बढ़ाने की माँग की, और उनके प्रयास से सिविल सर्विस के प्रश्न पर अखिल भारतीय मेमोरियल पार्लियामेन्ट को भेजा गया।

सन् १८८३ में तथा सन् १८८५ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि के प्रयास से कलकत्ता में 'इंडियन नेशनल कांफ्रेंस' आयोजित हुई, जिसमें बंगाल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त देश के अन्य भागों के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इन कांफ्रेंसों की योजना में आनन्द मोहन बोस का भी भरपूर योगदान था। वही सन् १८८५ की कांफ्रेंस के अध्यक्ष थे। ये दोनों सज्जन बहुत ही प्रतिभाशाली वक्ता और उदारदलीय राजनीतिज्ञ थे। सन् १८८५ की कांफ्रेंस में 'इंडियन असोसिएशन' के अतिरिक्त 'ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन' और 'नेशनल मुहामिडेन असोसिएशन' का भी योगदान था। यह कांफ्रेंस वास्तव में इन तीनों संस्थाओं द्वारा आमंत्रित की गयी थी। तीनों का यह संयुक्त प्रयास था।

उधर बम्बई में प्रसिद्ध विधि-विशेषज्ञ श्री विश्वनाथ नारायण माण्डलिक ने 'बम्बई असोसिएशन' का, जो विघ्नव से पहले ही स्थापित हो चुकी थी, नेतृत्व और संचालन सम्भाला। आगे चल कर सन् १८८५ में दादा भाई नौरोजी की प्रेरणा तथा सर्व श्री फीरोज साह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, काशीनाथ त्र्यम्बक तैलंग और इंदुलजी दिनशा वाचा के प्रयास से 'वाम्बे प्रेजिडेन्सी असोसिएशन' गठित हुई, और उसने शीघ्र ही बम्बई प्रदेश की मुख्य राजनीतिक संस्था का स्थान प्राप्त कर लिया।

सन् १८७० में पूना में गणेश वासुदेव जोशी आदि ने 'सार्वजनिक सभा' संगठित की। इसने महादेव गोविन्द रानडे की देख-रेख और नेतृत्व में महत्त्वपूर्ण काम किया। उसने महाराष्ट्र की कृषिक समस्या का अध्ययन किया, और सन् १८७६ में माँग की कि सरकार द्वारा घोषित 'अकाल नियम' लागू करके

किसानों के कष्ट दूर किये जायें। उसने महाराष्ट्र की कतिपय अन्य आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण कर उन्हें सुलझाने के रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किये।

सन् १८८४ में मद्रास में 'महाजन सभा' संगठित की गयी। उसने सन् १८५१ में आयोजित 'मद्रास नेटिव असोसिएशन' का, जिसने सन् १८५२ में संयुक्त पार्लियामेन्टरी कमेटी को आवेदन पत्र भेजा था, स्थान ग्रहण कर लिया। सन् १८८४ में 'महाजन सभा' के तत्त्वावधान में मद्रास प्रान्तीय कान्फ्रेंस आयोजित की गयी। दिसम्बर सन् १८८४ में बहुत से कार्यकर्ता दीवान बहादुर रघुनाथ राव के घर इकट्ठे हुए, और उन्होंने देश के विभिन्न भागों में काम करके एक राष्ट्रीय संस्था गठित करने का निश्चय किया।

इसके आस पास ही मिस्टर ह्यूम आदि ने मिलकर 'इंडियन यूनियन' गठित की, जिसने मार्च १८८५ में एक लोक-घोषणा द्वारा आगामी दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में 'राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं' की एक ऐसी कान्फ्रेंस करने का निश्चय व्यक्त किया, जिसमें 'वे एक दूसरे से परिचित हो सकें, और आगामी वर्ष के लिए राजनीतिक कार्यक्रम निश्चित कर सकें।'।

नेशनल कांग्रेस का गठन

काफी सोच-विचार के बाद तथा वाइसराय लार्ड डफ्रिन से परामर्श करने के बाद २८ दिसम्बर सन् १८८५ को बंगाल के सुप्रसिद्ध नेता श्री व्योमकेश चन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में गोकलदास तेजपाल हाईस्कूल के हाल में सत्तर सज्जनों ने 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' की बुनियाद डाली।

श्री व्योमकेश बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस की भावी नीति-रीति और गतिविधि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विभिन्न भागों में देशहित के कार्यों में सलग्न कार्यकर्ताओं में 'व्यक्तिगत घनिष्टता और मैत्री का प्रोत्साहन', 'प्रत्यक्ष मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत ससर्ग द्वारा सब देशभक्तों में हर संभव प्रजातीय, साम्प्रदायिक और प्रान्तीय द्वेष का उन्मूलन' तथा 'राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का पूर्ण विकास और दृढीकरण', एवं देश की कतिपय महत्त्वपूर्ण और बहुत आवश्यक समस्याओं पर पूरी तौर पर विचार-विमर्श के बाद भारत के शिक्षित वर्गों के परिपक्व विचारों का प्रामाणिक अभिलेखन, और आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम का निर्णय ही कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य होंगे।

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में उपस्थित हम सभी प्रतिनिधि भारत की प्रगति में ब्रिटिश शासन के महत्त्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हैं, और ब्रिटेन से भारत के सम्बन्ध अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते हैं। पर हम सबकी राय में इस सम्बन्ध को अधिक सुदृढ़ और लाभकारी बनाने के लिए शासन की कमियो, कमजोरियो तथा त्रुटियो का निराकरण और भारतीय जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति जरूरी है, और इन सबकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। उन्होंने कहा कि शासन के विधिविधान की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए शान्तिमय वैधानिक ढंग से देश की दशा को सुधारने का प्रयत्न किया जायगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी राय में प्रतिनिधि संस्थानों की स्थापना, तथा प्रशासन में भारतीयों की प्रभावकारी सक्रिय सहभागिता अधिक आवश्यक है। इन दोनों बातों को स्वीकार करके ही शासन अपने को ठीक तौर पर लोकप्रिय और सुदृढ़ बना सकता है, महारानी विक्टोरिया की सन् १८५८ की घोषणा को साकार करने का दावा कर सकता है, तथा जनता की भावनाओं और विचारों के अनुरूप अपनी नीतिरीति निर्धारित कर सकता है।

कांग्रेस ने अपने पहले अधिवेशन में माँग की कि भारतीय प्रशासन की जाँच के लिए एक 'शाही कमीशन' नियुक्त किया जाय, विधानों का विस्तार और सुधार किया जाय, तथा इंडियन सिविल सर्विस के लिए ब्रिटेन के साथ-साथ भारत में भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ आयोजित हो। कांग्रेस ने यह भी माँग की कि भारत-मन्त्री से सम्बद्ध इंडिया कौंसिल भंग कर दी जाय, और सैनिक व्यय कम किया जाय। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह भी सन्तुति की कि अपर वर्ग पर आधिपत्य प्रतिष्ठित न किया जाय, और यदि ब्रिटेन उस पर अधिकार स्थापित ही करना चाहता है, तो उसे भारत से अलग एक 'क्राउन कालोनी' (शाही उपनिवेश) के रूप में रखा जाय, भारत के ऊपर उसके प्रबन्ध का खर्चा न लादा जाय। इस तरह कांग्रेस ने अपने पहले अधिवेशन में ही ब्रिटेन की साम्राज्य-विस्तार की नीति का, तथा उसकी पूर्ति के लिए भारतीय राजकोश पर उसका बोझ लादने का विरोध किया। उसने प्रशासनिक त्रुटियों और अव्यय को खत्म करने की, सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर हिन्दुस्तानियों को भरती करने की, प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित करने की, तथा क्रमशः उनके अधिकारों को विस्तृत करते हुए देश में प्रतिनिधि सरकार प्रतिष्ठित करने की माँग की, और उनके लिए सतत प्रयत्न करना अपना लक्ष्य निश्चित किया।

कांग्रेस का स्वरूप

यद्यपि कांग्रेस मुख्यतः मध्यवर्गीय संस्था थी, पर उसके संस्थापक उसे सर्ववर्गीय राष्ट्रीय संस्था का रूप देना चाहते थे। अतः उसके संचालको ने निश्चय किया कि आर्थिक वर्ग-संघर्षों से अपने को अलग रखते हुए वह देश की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करे, सरकार की उन नीतियों का और कार्यों का विरोध करे जिनसे देश के आर्थिक हितों की हानि होती है, जो राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में बाधा पहुँचाते हैं। कांग्रेस के संचालको ने समाज-सुधार के प्रश्नों की उलझनों से भी उसे अलग रखना ही तय किया। वे चाहते थे कि देश-प्रेम के आधार पर सब वर्गों, सम्प्रदायों, जातियों और प्रान्तों के भारतीयों को एक सूत्र में बाँध कर बृहद् भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया जाय, और उसके राजनीतिक जीवन और व्यवस्था को धीरे-धीरे उदार लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों पर स्थापित किया जाय।

कांग्रेस को अपने इस प्रयास में कुछ सफलता अवश्य प्राप्त हुई। उसने शीघ्र ही सर्वप्रान्तीय राष्ट्रीय संस्था का रूप धारण कर लिया। उसे कालाकाकर के राजा रामपाल सिंह, बंगाल के सर राजेन्द्रलाल मित्र, दरभंगा के महाराजा सर लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर, विजयानगरम् के महाराजा सर गजपतिराज आदि जमींदारों की सहायता और सहानुभूति प्राप्त हो गयी। कलकत्ते के 'ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन' ने अपने सभा-भवन में कांग्रेस को अपना दूसरा वार्षिक अधिवेशन करने की अनुमति दी, तथा दस बारह प्रतिनिधि भेजे। लगभग बीस अन्य जमींदारों ने भी प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया। पर यह सहयोग न तो व्यापक बन पाया और न स्थायी सिद्ध हुआ। यद्यपि कांग्रेस के तीसरे और चौथे अधिवेशन में कुछ जमींदारों और सम्प्रान्त परिवारों के व्यक्तियों ने भाग लिया, और सरकार के विरोध की उपेक्षा करते हुए महाराजा दरभंगा ने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के लिए प्रयाग में अपनी कोठी के प्रयोग की अनुमति दे दी, पर अधिकांश जमींदारों की उपेक्षा और विरोध के कारण कांग्रेस मुख्य रूप से मध्यवर्गीय संस्था बनी रही।

सरकार द्वारा प्रोत्साहित जमींदारों का विरोध

सन् १८८८ में कांग्रेस की गतिविधि से क्षुब्ध हो वाइसराय लार्ड डफरिन ने घोषित किया कि कांग्रेस 'एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग है', जिसका लक्ष्य 'अज्ञात में बड़ी छलांग है।' इसी समय उत्तर पश्चिमी प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश)

के लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर सर आकलैण्ड कालविन ने इलाहाबाद के 'ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन' के प्रमुख नेताओं को कांग्रेस का विरोध करने को प्रोत्साहित किया। उसके प्रमुख नेता राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द तथा सर सैयद अहमद खाँ आदि ने 'देशभक्त सभा' (पेट्रियाटिक असोसिएशन) गठित की। सर सैयद अहमद खाँ ने तो सन् १८९३ में 'मुस्लिम डिफेन्स असोसिएशन' स्थापित कर, और मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहने की सलाह देकर विरोध को साम्प्रदायिक रूप भी दे दिया। उनके इशारे पर सन् १८८८ में कुछ मौलवियों ने फतवा द्वारा मुसलमानों को कांग्रेस से रोकने की कोशिश की। इसके जवाब में देवबन्द और लखनऊ के कुछ मौलवियों ने फतवा दिया कि राजनीतिक मामलों में मुसलमान हिन्दुओं से मिलकर काम कर सकते हैं। सन् १८८८ के अधिवेशन में १२४८ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें २२१ मुसलमान थे। इन प्रतिनिधियों में बहुत से सम्भ्रान्त जमीदार वर्ग के थे। सन् १८८९ के अधिवेशन में १८८९ प्रतिनिधियों में २५४ मुसलमान थे। पर आगे चल कर जमीदारों और मुसलमानों की संख्या घटती चली गयी, और उनका विरोध बढ़ता गया।

इस विरोध के पीछे अंग्रेज कर्मचारियों की गहरी साजिश थी। पर इसका मूल कारण वर्गीय भावना ही थी। जमीदार अपने को ममाज का स्वाभाविक नेता समझते थे, और वे इस नेतृत्व को साधारण निम्न मध्यश्रेणी के परिवारों के शिक्षित नवयुवकों को सौंपने को तैयार नहीं थे। जमीदार चाहते थे कि सरकार भारतीय नेताओं के परामर्श से कानून बनाये, नीतिरिति निश्चित करे, भारतीय नवयुवकों को प्रशासन में सक्रिय योगदान करने का अवसर प्रदान करे। पर उनके विचार में नेतृत्व का निर्णय चुनाव के बजाय परम्परागत पारिवारिक प्रतिष्ठा और महत्त्व से हो, और प्रशासन के लिए नवयुवकों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के बजाय नामजदगी द्वारा हो, ताकि उन सम्भ्रान्त कुलों के नवयुवक प्रशासन के ऊँचे पदों पर नियुक्त हो सकें जो सदा से प्रशासन में योगदान कर रहे हैं। मध्यवर्गीय शिक्षितों को जमीदार वर्ग की ये धारणाएँ स्वीकार नहीं थी, क्योंकि पारिवारिक मान-प्रतिष्ठा के बजाय क्षमता और जनविश्वास ही उनके नेतृत्व का आधार हो सकता था। उनका यह भी कहना था कि क्षमता किसी जाति या कुल की वपौती नहीं, और वही जनता का नेता है जिसे जनता का विश्वास प्राप्त हो। जन-विश्वास का निर्णय, उनके विचार में, चुनाव द्वारा ही हो सकता है। उनकी यह भी धारणा थी कि सरकार द्वारा मनोनीत विधायक और प्रशासक विदेशी सरकार के हाथ की कठपुतली ही होंगे। उनके लिए निर्भीकता के साथ जनता की सेवा करना सम्भव नहीं होगा। सन् १८६१ के

इंडियन कौंसिल एक्ट के अन्तर्गत एकमात्र पारिवारिक मान के आधार पर मनोनीत विधायकों की हुकूमत-परस्ती और सार्वजनिक हितों की उपेक्षा इससे प्रत्यक्ष प्रमाण थे।

सर सैयद अहमद खा स्वीकार करते थे कि हिन्दुस्तान के रईस कौंसिलों की "कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है", पर कहते थे कि उस पर "अदना कौम या अदना दर्जा का आदमी ख्वाह " वह लायक भी हो" नहीं बिठाया जा सकता, उसे रईसों के "माल, जायदाद का हाकिम" नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सरकार उस कुर्सी पर "सिवाय मुअज्जिज के किसी को नहीं बिठा सकती।"^१ सर सैयद अहमद खा का यह भी विचार था कि "अगर हिन्दू मेम्बर को हिन्दू मुनतखिव करे (चुनें) और मुसलमान मेम्बर को मुसलमान " दोनों की तादाद मसावी (बराबर) हो," तो भी "मुसलमानों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि सस्थाओं का समर्थन उचित नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान मेम्बरान वहाँ हिन्दुओं का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।"^२ नामजदगी द्वारा कौंसिलों की मेम्बरी तथा सरकारी नौकरिया प्राप्त करना ही वे मुसलमानों के लिए मुनासिब समझते थे।

सर सैयद अहमद खा और मुसलमान जमींदारों का विरोध हिन्दू जमींदारों के विरोध की तुलना में कांग्रेस की प्रगति में अधिक हानिकार सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय जबकि हिन्दुओं के मध्यवर्गीय शिक्षितों ने हिन्दू समाज में काफी ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था, और बंगाल के जमींदारों में यह विश्वास पैदा होने लगा था कि उनके बच्चे सत्येन्द्र कुमार ठाकुर की तरह खुली प्रतियोगिता परीक्षा में अंग्रेज नवयुवकों से टक्कर लेकर इण्डियन सिविल सर्विस में प्रवेश कर सकते हैं, और डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र की तरह अपनी योग्यता के आधार पर शिक्षित समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, उत्तर भारत की मुसलमान जनता का नेतृत्व उन जमींदारों के हाथ में था, जो अपने बच्चों की योग्यता से अधिक अपने पारिवारिक गौरव पर विश्वास करते थे। विरोध का वर्गीय लक्षण ही भारत की प्रगति में रोड़ा था। उसके साम्प्रदायिक स्वरूप ने तो एक ऐसी समस्या पैदा कर दी, जिसका समाधान कांग्रेस के लिए असंभव हो गया।

कांग्रेस के लिए हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति पर निष्ठावान् उन हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त करना आसान था, जो राजा राम मोहन राय, महादेव गोविन्द

१ सन् १८८७ की सर सैयद की तफरीर।

२. वही।

रानडे प्रभृति विद्वानों के विचारों से अनुप्राणित थे, उनकी उदार व्याख्या को स्वीकार करते थे, और उनके आदेश के अनुसार पाश्चात्य के भौतिक विज्ञान तथा उदार लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। पर कांग्रेस को उन हिन्दुओं का विरोध सहन करना पड़ा जो अपने धर्म और संस्कृति की मध्य-युगीय व्याख्या को ही प्रामाणिक मानते थे, और उसमें कोई परिवर्तन करने को, तथा अपनी संस्कृति में लोकतान्त्रिक मान्यताओं को, जिनके आधार पर कांग्रेस संगठित थी, स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनसे टक्कर लेने की कांग्रेस के नेताओं में शक्ति जरूर थी, पर उनका भी जनता पर काफी प्रभाव था, और देश की कुछ समस्याओं को हल करने के लिए उनके सहयोग की भी आवश्यकता थी। उनकी राजभक्ति की भावना को देशभक्ति में परिणत करना, उनमें नृपतन्त्र के स्थान पर लोकतन्त्र के प्रति आस्था पैदा करना, जात-पात के बन्धनों को ढीला करके उनमें पारस्परिक सौहार्द पैदा करना, देश बन्धुत्व के आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करना, तथा उन्हें प्रगति की ओर अग्रसर करना काफी कठिन काम था।



२. प्रारम्भिक जीवन

जन्म

विप्लव के साढ़े चार वर्ष बाद २५ दिसम्बर सन् १८६१ ई० को अर्थात् पीप कृष्ण ८ सम्बत् १९१८ वि० को बुधवार के दिन प्रयाग में लालडिग्गी मुहल्ले में जो आगे चल कर भारती भवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मदन मोहन ने जन्म लिया ।

प्रयाग

प्रयाग उस समय आज जैसा विभूति-सम्पन्न नगर नहीं था । वह उस समय भी 'तीर्थराज' के नाम से प्रसिद्ध था, और बहुत से धर्मनिष्ठ यात्री त्रिवेणी में स्नान करने, तथा १७वीं शताब्दी में मुगल सम्राट् अकबर द्वारा बनवाये हुए दुर्ग में समवस्थित पवित्र अक्षयवट के दर्शन करने के निमित्त आते रहते थे । उनकी सुविधा के लिए उदार व्यक्तियों द्वारा बनवायी गयी कुछ धर्मशालाएँ तथा पड़ो के कुछ बड़े मकान थे । घनाढ्य जमींदारी और व्यापारियों की कुछ हवेलियाँ भी थी । पर अन्यथा उस समय का प्रयाग भौतिक समृद्धि-विहीन छोटा-सा नगर था । यहाँ अधिकांश दुकानें और मकान खपरैल के थे, जिनके बीच में पतली चक्करदार गलियाँ बनी हुई थी । लाल डिग्गी मुहल्ले के पास दक्खिन की ओर पीपल और बैर का जङ्गल था, जहाँ पीलवान अपने हाथियों को पीपल के पत्ते खिलाने ले जाते थे । इस मुहल्ले में एक नाला भी था । इसके पास ही कुछ ब्राह्मणों के खपरैल के मकान थे । इसी में एक मकान में मदन मोहन ने जन्म लिया^१ ।

सन् १८६१

भारत के इतिहास में सन् १८६१ ई० का निःसन्देह महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस वर्ष ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ओर अपनी मर्यादाओं के अनुकूल हार्ड-कोर्टों के संगठन की व्यवस्था की, और दूसरी ओर अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं की उपेक्षा करते हुए ऐसी कौंसिलों के संगठन की व्यवस्था की, जिनके अधिकार, बहुत सीमित और जिनके सब सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे । इसी वर्ष

महामना मदन मोहन मालवीय जीवन और नेतृत्व

महारानी विक्टोरिया की घोषणा की सर्वथा उपेक्षा करते हुए सेना के बहुत से विभागों में भारतीयों की भरती विल्कुल बन्द कर दी गयी, और ब्रिटिश साम्राज्य-शाही को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए भारत की सेना में ब्रिटिश सिपाहियों का अनुपात बढ़ा दिया गया, तथा भारतीय सैनिकों को जाति, सम्प्रदाय और क्षेत्र के आधार पर इस तरह विभिन्न कम्पनियों में विभाजित कर दिया गया कि उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत और पृष्ठ ही न हो सके। पर इसी वर्ष भारत-माता ने मई के महीने में रवीन्द्रनाथ ठाकुर और मोतीलालजी को जन्म दिया और आगे चल कर प्रफुल्ल चन्द्र राय और मदन मोहन को जन्म दिया। इन चारों बच्चों ने अपनी प्रतिभा से माता का मस्तक ऊँचा किया, तथा साम्राज्य-शाही की भावना से अनुप्राणित यूरोपियन राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को भारत के सम्बन्ध में अपनी धारणाएँ और नीति-रीति बदलने पर मजबूर किया।

पूर्वज

मदन मोहन का जन्म पंडित विष्णु प्रसादजी के सुपुत्र पंडित प्रेमधरजी के परिवार में हुआ। इनके पूर्वज मध्य भारत के मालवा में रहते थे। पन्द्रहवीं शताब्दी ईसवी में मालवा के किसी राजा ने निश्चय किया कि पंच द्रविड और पंच गौड ब्राह्मणों को एक पंगत में बैठाकर भोजन कराया जाय। बहुत से ब्राह्मण इस पर राजी नहीं हुए। प्रेमधरजी के पूर्वज कुछ अन्य ब्राह्मणों के साथ अपना घर और गाँव छोड़कर पूरब को चल दिये, और मार्ग में बहुत से कष्ट सहते हुए पटना पहुँच कर उन्होंने वहाँ अपना डेरा डाल दिया। कुछ काल वहाँ रहने के बाद इन प्रवासी ब्राह्मणों में से कुछ मिर्जापुर और कुछ प्रयाग में आ बसे। मदन मोहन के पूर्वजों ने तीर्थराज प्रयाग को ही अपना निवासस्थान बनाया।

पितामह

मदन मोहन के पितामह पंडित प्रेमधरजी संस्कृत के बड़े विद्वान् थे। धर्म के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके पास दो फुट ऊँची साँवले रंग की श्रीकृष्ण की एक मूर्ति थी, जिसकी वे प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा किया करते थे। अपनी विद्वत्ता और निष्ठा के कारण वे 'महाभागवत' के नाम से प्रसिद्ध थे। चौरासी वर्ष की आयु में वे गंगातट पर स्वेच्छा से जा कर, स्नान-ध्यान करके, पद्मासन लगाकर इह-लोला समाप्त कर, स्वर्गलोक सिंघार गये। पितामह की तरह पितामही भी धर्मनिष्ठा, शील-सम्पन्ना थी।



मालवीयजी के पूज्य पिताजी

परिवार

पण्डित प्रेमधर जी पाँच भाई थे। वे सभी प्रतिभाशाली थे। पण्डित साधोधरजी वैयाकरणी थे। पण्डित मुरलीधर ने साधु का जीवन व्यतीत किया। पण्डित वंशीधर सस्कृत साहित्य के विद्वान् थे। पण्डित बालाधर उच्चकोटि के ज्योतिषी थे।

पण्डित प्रेमधरजी के चार पुत्र हुए—लालजी, बच्चूलालजी, गजाधर प्रसाद जी, और ब्रजनाथजी। इनमें पण्डित गजाधर प्रसादजी और पण्डित ब्रजनाथजी काफी प्रतिभाशाली सिद्ध हुए।

मदन मोहनजी के पिता पण्डित ब्रजनाथजी के छ पुत्र और दो कन्याएँ हुई—लक्ष्मी नारायण, सुखदेई, जयकृष्ण, शुभद्रा, मदन मोहन, श्यामसुन्दर, मनोहर लाल और बिहारी लाल। इन सबमें मदन मोहनजी ही विशेष रूप से प्रतिभाशाली सिद्ध हुए। उन्होंने ही व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की, अपने माता-पिता और परिवार की प्रतिष्ठा की, तथा भारत-माता और भारतीय सस्कृति के गौरव की पुष्टि और वृद्धि की।

पूज्य पिता

मदन मोहनजी के पूज्य पिता पण्डित ब्रजनाथजी, जिन्होंने अपने ननिहाल में रहकर सस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी, अपने पिता पण्डित प्रेमधरजी की तरह धर्मनिष्ठ, सस्कृत के विद्वान् तथा राधाकृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका रूपरंग सुन्दर, कठ मधुर, स्वभाव बहुत कोमल था। वे सन्तोषी, सदाचारी, तथा आचार नियम के पक्के थे। सगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। वे बाँसुरी बहुत ही अच्छी बजाते थे। श्रीमद्भागवत का समुचित ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने चौबीस वर्ष की आयु में उसकी कथा कहना प्रारम्भ कर कुछ वर्षों में ही अच्छे कथावाचक व्यास की प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। जनसाधारण के साथ-साथ महाराजा रीवाँ, महाराजा बनारस और महाराजा दरभंगा भी उनकी विद्वत्ता के प्रशंसक थे। उन्होंने भक्ति प्रतिपादक 'सिद्धान्त दर्पण' नामक ग्रन्थ भी लिखा था, जिसे उनके पुत्र मदन मोहन ने सन् १९०६ में प्रकाशित कराया। परिवार की आर्थिक दशा काफी दयनीय होते हुए भी वे दान नहीं लेते थे। कथा पर भगवदिच्छा से जो कुछ चढ़ जाता, उसी पर वे सन्तोष कर लेते, उसीसे जीवन निर्वाह करते, बाल-बच्चों का पालन पोषण करते थे।

माता

मदन मोहनजी की माता श्रीमती मूना देवीजी स्वभाव की बड़ी सरल और हृदय की बड़ी कोमल थी। वे दूसरों का दुःख देखकर शीघ्र ही द्रवित हो जाती, और उनसे जो कुछ सेवा बन पड़ती तत्काल कर देती थी। मुहल्ले के बच्चों को वे बहुत प्यार करती थी। बच्चे उनको घेरे रहते थे। वे काफी कार्यकुशल थी, घर का सारा प्रबन्ध उनके हाथ में था।

शील

बालक मदन मोहन पर परिवार की आर्थिक दशा का, माता के शील तथा स्नेह का, पिता और पितामह की भगवद्भक्ति तथा धर्म के प्रति अनुराग का गहरा प्रभाव पड़ा। उनका जीवन धर्मनिष्ठ, शीलसम्पन्न, भगद्भक्त, दीनबन्धु, समाज-सेवी के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने अपनी पिछहत्तरवीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर कहा था कि “मेरे पितामह, पितामही, पिता और माता बड़े धर्मात्मा, सदाचारी और नि स्वार्थी ब्राह्मण थे, उन्हीं के प्रसाद से मैं इतना काम कर सका हूँ।”^१ उन्होंने बचपन में ही ऐसा नियम बना लिया था कि वह कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसे वह माता से न कह सकें। उन्होंने विद्यार्थियों को यह भी बताया कि ‘इस नियम से मैं कई पापों से बचा, मुझे शक्ति मिली और मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योति से उज्ज्वल हुआ’। परिवार की आर्थिक स्थिति ने मालवीयजी को सादा, सरल जीवन विताने की ओर प्रेरित किया, और उनके हृदय में निर्धनों के प्रति सहानुभूति जागृत की, जिसकी चर्चा वे बार-बार जीवन भर करते रहे।

मदन मोहन की बालकाल की जीवन-चर्या से ही उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का पता चल जाता है। आठ वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिताजी ने ही उन्हें गायत्री मन्त्र की दीक्षा दी। तब से उन्होंने नियमित रूप से प्रातःकाल और सायंकाल सन्ध्या का जो नियम बनाया, उसका उन्होंने हर परिस्थिति में जीवन भर निर्वाह किया। वे स्कूल जाने के पहले प्रतिदिन हनुमान का दर्शन करने जाते थे और उस समय यह श्लोक पढ़ते थे —

मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम् ।

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं धीरामदूतं शिरसा नमामि ॥

उनके पिता जब कथा कहने जाते तो वह नित्य उनके साथ जाते और उनकी चौकी के पास बैठ कर बड़े ध्यान से उसे सुनते थे। उन्होंने अपने संस्मरण



मालवीयजी की पूज्य माताजी

में बताया कि “पिताजी ने एक दिन कहा, तू बड़ा भक्त है। यह सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी।”^१

उन्होंने एक बार वचन में गायत्री का जाप इम तत्परता से करना प्रारम्भ किया कि उनके माता-पिता चिन्तित हुए कि कहीं यह बालक आगे चलकर सन्यासी न हो जाय।

कृष्णजन्माष्टमी के अवसर पर वे बहुत उत्साह के साथ झाँकी सजाते, संगीत का प्रबन्ध करते, तथा घूम-घाम से कृष्णोत्सव मनाते थे। कुछ बड़े होने पर उन्होंने सितार बजाना सीख लिया था, तथा मीरा और सूरदास के बहुत से पदों को याद करके वे उन्हें सितार पर बजाने लगे थे। अपने पिता और पितामह से उन्होंने बहुत से श्लोक भी सीख लिये थे, जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब उनकी अवस्था पन्द्रह वर्ष की हुई, तब से वे घर में रखी पुस्तकों की बैठन खोलने और वाचने लगे। उन्होंने इन पुस्तकों को पढ़कर उनमें से बहुत से श्लोक कंठ भी कर लिये। इन पोथियों में ‘इतिहास समुच्चय’ नाम की एक पुस्तक थी, जिसमें महाभारत के चुने हुए ३२ इतिहास थे। मालवीयजी के “धर्म सम्बन्धी विचारों और ज्ञान के बढ़ाने में यह पुस्तक बड़ी सहायक हुई।”^२ बड़े होने पर इस पुस्तक के अतिरिक्त उन्होंने मनुस्मृति और भगवद्-गीता भी पढ़नी शुरू कर दी।

माता पिता के शील, स्नेह का उन्होंने वचन में ही भरसक अभ्यास किया। वे बड़ों का आदर करते, साथी-संगियों के साथ शील का ध्यान रखते हुए खेल-कूद करते थे। पन्द्रह वर्ष की आयु में ही उन्होंने कविता करना प्रारम्भ कर दी थी। पर उनकी सब रचनाएं शील से विभूषित होती थी। इसी समय उन्होंने अश्लील शृङ्गार के सम्बन्ध में लिखा था.—

यह रस ऐसो है बुरो, मन को देत बिगारि।

याते पास न आवहु, जेते अहि अनारि॥

अपने लडकपन के जमाने में ही एक बार मालवीयजी ने प्रातः काल अपनी छत से अनायास एक युवती स्त्री को नंगा देख लिया। इसका उन्हें बहुत दुःख हुआ। नीचे उतर कर उन्होंने अपने माता-पिता से इसकी चर्चा की। उन्होंने समझाया कि ‘अनिच्छा से ऐसा हो जाने पर कोई विशेष दोष नहीं है। भगवान का भजन

१ रामनरेश त्रिपाठी . मालवीयजी के साथ तीस दिन, पृ० ३३।

२ वही, पृ० १०।

कर लो ।' मदनमोहनजी ने कहा उसे तो वह प्रतिदिन करते ही हैं, प्रायश्चित्त कुछ दूसरा होना चाहिए । अन्त में दृष्टि-दोष से छुटकारे के लिए उन्होंने दिन भर का उपवास किया, और अपनी खाट नीचे उतार कर छत के वजाय नीचे सोने लगे ।^१

मस्ती

इस तरह भारतीय शील और समय के पालने का अभ्यास उन्होंने वचपन में ही प्रारम्भ कर दिया था । पर अन्यथा मदन मोहनजी वचपन में इतने प्रसन्न और चैतन्य रहते थे कि उनके मुहल्ले के एक घुरहू साहु उन्हें "मस्ता" कहा करते थे । मौजी मदन मोहन को वचपन में ही व्यायाम, संगीत और कविता का शौक हो गया था । वे उस समय गिल्ली डडा भी खेलते, डड भी पेलते, मुद्गर भी घुमाते, अखाड़े में कुश्ती भी लड़ते, तथा होली के अवसर पर काफी हुडदग भी मचाते थे । कालेज में वे क्रिकेट और टेनिस भी खेलने लगे थे ।

उनकी एक रचना से उनकी बालकाल की आन्तरिक भावनाओं और आकांक्षाओं का कुछ परिचय प्राप्त होता है । उन्होंने लिखा—

गरे जूही के है गजरे पड़ा रंगीं दुपट्टा तन ।
भला क्या पूछिए धोती तो ढाके से मँगाते हैं ॥
कभी हम वारनिश पहनें कभी पंजाब का जोड़ा ।
हमेशा पास डंडा है, ये फक्कड सिंह गाते हैं ॥
न ऊधो से हमें लेना न माघो का हमें देना ।
कटे पैदा जो खाते हैं व दु खियो को खिलाते हैं ॥
नही डिप्टी बना चाहे न चाहे हम तसिल्दारी ।
पडे अलमस्त रहते हैं यूँही दिन को बिताते हैं ॥
न देखें हम तरफ उनकी जो हमसे नेक मुँह फेरें ।
जो दिन से हमसे मिलते हैं झुक उनको देख जाते हैं ॥
नही रहती फिकर हमको कि लावें तेल और लकड़ी ।
मिले तो हलवे छन जावें नही झूरी उडाते हैं ॥
सुनो यारो जो सुख चाहो तो पचडे से गृहस्थी के ।
छुटो फक्कड़पना ले लो यही हम तो सिखाते हैं ॥

हमें मत भूलना यारो बसे हम पास 'मनमोहन' ।

हुई हैं देर जाते हैं, तुम्हारा शुभ मनाते हैं ॥^१

इस कविता के लिखने के वर्ष दो वर्ष बाद ही उनका विवाह हो गया । उन्होंने अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन किया, और विवाह न करने का कभी किसी को उपदेश नहीं दिया । उनके पहनावे में भी आगे चलकर काफी परिवर्तन हो गया । फिर भी इस रचना की बहुत-सी मुख्य बातों का उन्होंने जीवन भर निर्वाह किया । उन्होंने अपने जीवन में किसी सरकारी प्रशासनिक पद को प्राप्त करने की कभी कोई इच्छा नहीं की, और जो कमाया उसका बड़ा अंश दुःखियों की सेवा में लगा दिया । वे अलमस्त फक्कड़ तो नहीं बने, देश की चिन्ता जीवन के अन्तिम घड़ी तक उन्हें सताती रही, पर विनय के साथ अकड़ अन्त तक उनके जीवन के गुण बने रहे । उन्होंने जीवन भर देश की निःस्वार्थ सेवा की, और इसी का दूसरो को उपदेश दिया ।

कविता

युवावस्था में मालवीयजी ने 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' नाम की मासिक पत्रिका के लिए समस्या-पूर्तियाँ भी की । उन्होंने 'मकरन्द' उपनाम से उन्हें इस पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेजा ।

'राधिका रानी' समस्या पर लिखी रचना इस प्रकार है :—

इन्दु सुवा बरस्थौ नलिनीय पै वे न बिना रवि के हरिखानी ।
 त्यों रवि तेज दिखायो तऊ बिनु इन्दु कुमोदिनी ना विक्रमानी ॥
 न्यारी कछु यह प्रीति की रीति नही "मकरन्दजू" जात बखानी ।
 साँवरे कामरीचारं गुपाल पै रीझि लटू भई राधिका रानी ॥

*

*

*

वे कवते उत ठाढ़े अहै इत बैठि अही तुम नारि चुपानी ।
 थाकी तुम्हें सुझावत सामते ऐसी मैं रावरी बानि न जानी ॥
 मोहि कहाँ पे यहै "मकरन्द" हूँ जो कहूँ खीझि पे रूसन ठानी ।
 आजि मनाये न मानती हौ कल्ह आप मनाइहौ राधिका रानी ॥

*

*

*

माँगत मोतिन माल नही नहि माँगत तोसो मैं भोजन पानी ।
 सारी न माँगत हौं "मकरन्द" न थारी अनेक सुगन्धन सानी ॥
 माँगत हौं अधरा-रस रंचक सोउ न दीजत हौ सनमानी ।
 सूम्ता . एती तुम्हें नही चाहिए बाजति हौ चहूँ राधिका रानी ॥

धूम मची ब्रजफागुरा आजु बजै उफ झाँझ अवरि उडानी ।
ताकि चलै पिचका दुहु ओर गलीन में रंग की धार बहानी ॥
भीजै भिजोवै ठढे “मकरन्द” दुहु लखि सोभा न जात बखानी ।
ग्वालन साथ इतै नन्दलाल उतै सग ग्वालिन राधिका रानी ॥

‘डारन’ पर समस्या-पूर्ति इस प्रकार थी —

भूलिहै सो हँसि माँगिवो दान को रञ्च दही हित पानि पसारन ।
भूलिहै फागु के रागु सबै वह ताकहि ताकि कै कुकुम मारन ॥
सो तो भयो सबही “मकरन्दजू” दाखि चाखिबै बैर विसारन ।
जापर चीर चुराय चढे वह भूलिहै कैसे कदम्ब की डारन ॥
ढूँढ्यो चहूँ झँझरीन झरोखन ढूँढ्यो किते भर दाव पहारन ।
मंजुल कुजन ढूँढि फिरयो पर हाथ मिल्यो न कहूँ गिरिधारन ॥
लावत नाहि तरु परतीति सह्यो इतनो दुख प्रीति के कारन ।
जानत स्याम अजौ उतहि चित चौकत देखि कदम्ब की डारन ॥^१

शिक्षा

जब मदन मोहनजी पाँच वर्ष के थे, तब उनको विद्यारम्भ कराया गया । पहाडा पढने वे एक पंडित के पास महाजनी पाठशाला भेज दिये गये । उसके बाद वे पंडित हरदेवजी की धर्मज्ञानोपदेश पाठशाला में भरती हुए । वहाँ उन्होंने संस्कृत, लघुकौमुदी आदि पढी । अपने सहपाठियों के साथ मनुस्मृति, गीता और नीति के बहुत से श्लोक कंठ किये, तथा धार्मिक शिक्षा और शारीरिक बल बढ़ाने की शिक्षा भी प्राप्त की । यहाँ गुरुजी अपने शिष्यों को दूध पिलाते, तथा कुश्ती भी लडवाते थे । गुरु हरदेवजी भागवत के श्रेष्ठ विद्वान् और साधक थे । वे सगीत के भी बड़े प्रेमी थे । इसके बाद मदन मोहनजी ने विद्या धर्म-प्रवर्द्धिनी सभा की पाठशाला में पढना शुरू किया । पंडित देवकी नन्दनजी इस पाठशाला के सर्वेसर्वा थे । वे मदन मोहन को माघ मेले पर एक मोढे पर खडा कर उनसे व्याख्यान दिलवाया करते थे ।

सन् १८६८ में प्रयाग में गवर्नमेण्ट हाई स्कूल खुला, और माताजी की आज्ञा से उन्होंने वहाँ पढना प्रारम्भ कर दिया । वे अपने बड़े भाई जयकृष्णजी के साथ, जो उनसे ६ वर्ष बड़े थे, स्कूल जाया करते थे । घर पर पढने की सुविधा न होने के कारण मदन मोहन संध्या को लालटेन और पोथी लेकर अपने मकान से

थोड़ी दूर पर सोहन लाल के बाग में अपने साथी गंगा प्रसाद के पास उनके साथ पढ़ने को चले जाते थे। वहाँ पढाई के साथ-साथ गणशप भी होती थी। स्कूल में भरती होने के बाद भी वे संस्कृत पढ़ने पाठशाला जाया करते थे। वहाँ उन्होंने पंडित ठाकुर प्रसादजी से, जो भागवत के बड़े विद्वान् थे, संस्कृत श्लोको के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्राप्त की। सोलह-सतरह वर्ष की आयु में उन्होंने एट्रेंस की परीक्षा पास की।

इस परीक्षा को पास करने के बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई पंडित जयगोविन्दजी से सम्पूर्ण काशिका पढ़ी तथा अपने चाचा पंडित गजाधर प्रसाद जी से, जो संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे, भागवत पढ़ी।

पंडित गजाधर प्रसादजी उस समय मिर्जापुर के गवर्नमेण्ट हाई स्कूल में हेड पंडित थे। मदनमोहनजी प्रायः छुट्टियों में उनके पास जाया करते थे। एट्रेंस परीक्षा पास करने के बाद जब वह एक बार मिर्जापुर गये, तब वहाँ धर्मसभा का अधिवेशन हो रहा था। अपने चाचा की अनुमति से नवयुवक मदन मोहन ने भी वहाँ धर्म विषय पर व्याख्यान दिया, जिसकी काफी प्रशंसा हुई। उससे उनका उत्साह बढ़ा।

एट्रेंस पास करने के बाद मालवीयजी म्योर सेंट्रल कालेज में पढ़ने लगे। परिवार के लिए कालेज की पढाई का आर्थिक बोझ वहन करना कठिन था। पर माता ने कठिनाई सह कर, अपना पेट काट कर, अपने जेवर गिरवी रख कर अपने बच्चे को पढ़ाने का निश्चय किया। प्रिन्सिपल हैरिसन ने उन्हें एक मासिक वजीफा दिया। फिर भी मदन मोहनजी को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

कालेज में एक 'फ्रेन्ड्स डिबेटिंग सोसाइटी' थी। उसमें जब उन्होंने पहली स्पीच अंग्रेजी में दी, तब उस सस्था के मन्त्री लाला सावलदास ने, जो बाद को डिप्टी-कलक्टर हो गये थे, उनका उत्साह-वर्द्धन किया। लाला सावल दास मालवीयजी से आयु में आठ वर्ष बड़े थे। मालवीयजी उन्हें 'उस्ताद' कहकर पुकारते थे, और सावल दासजी उन्हें उनकी पढाई में मदद करते रहते थे।

चिनोद

कालेज में एक बार 'मचेंट आफ वेनिस' का नाटक खेला गया। मदन मोहनजी ने उसमें पोशिया का पार्ट बहुत ही खूबी से किया।

इसी जमाने में 'आर्य नाटक मण्डली' की ओर से 'शकुन्तला' नाटक का अभिनय हुआ। इसमें मदन मोहनजी को शकुन्तला का पार्ट दिया गया। परदा उठने पर प्रियम्बदा और अनुसूया सखियों के साथ शकुन्तला हाथ में घड़ा लिये रंगमंच पर आयी, तब दर्शक दंग रह गये। शृङ्गार और करुणा दोनों रसों के हाव-भाव दिखला कर शकुन्तला के अभिनेता ने दर्शकों को मुग्ध कर दिया।^१

कालेज में संस्कृत मालवीयजी का एक पाठ्य विषय था। इस सिलसिले से वे संस्कृत के प्राध्यापक पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य के सम्पर्क में आये। लोकसेवा के कार्यों में अपने शिष्य की रुचि देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए, और जीवन भर गुरु शिष्य को सार्वजनिक कार्यों में प्रोत्साहित करते रहे, और उसपर पुत्र का-सा स्नेह करते रहे। शिष्य भी उनके साथ गुरु योग्य भक्तियुक्त बर्ताव करता रहा। गुरु ने प्रयाग में 'हिन्दू समाज' नाम की एक सभा सन् १८८० में स्थापित की। शिष्य उस सभा में जाने लगा।

विवाह

मालवीयजी का विवाह सोलह वर्ष की आयु में उनके चाचा पंडित गजाधर प्रसादजी के माध्यम से मिर्जापुर के पंडित नन्दलालजी की कन्या कुनन देवी से हुआ। वे माना पिता के दुलार में पली थी। लडकपन में उन्हें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं था। समुराल की आर्थिक दशा ने उन्हें बड़े धैर्य और साहस से निर्धनता के कष्ट सहन करने को बाध्य किया। 'उन्हें आधा पेट खा कर सन्तोष करना पड़ता था, फटी धोतिया सी कर पहननी पड़ती थी। एक दिन बहुत वर्षों बाद मालवीयजी ने उनसे पूछा, 'तुमने न भी अपनी सास से खाने पहनने के कष्ट की शिकायत नहीं की?' इस पर देवीजी ने उत्तर दिया, 'शिकायत करके क्या करती? वे कहा से देती? घर का कोना-कोना जितना वे जानती थी, उतना मैं भी जानती थी। मेरा दुःख सुनकर वे रो देती और क्या करती?'

देवीजी को धैर्य के साथ-साथ पतिदेव का स्नेह तथा भगवद्भक्ति के प्रति अनुराग भी प्राप्त था। जैसा कि मालवीयजी ने पंडित रामनरेश त्रिपाठी को बताया, पति पत्नी दोनों वैवाहिक जीवन के प्रारम्भ से ही रामकृष्ण के उपासक थे। दोनों कोई भी काम करते, चाहे दूध पीते, चाहे पानी पीते, रामकृष्ण का स्मरण किये बिना नहीं करते। पतिदेव की तरह पतिव्रता साध्वी ने भी भगवान् की भक्ति में कई दोहे कहे थे। वे कहती थी—

‘ऐसा कोई घर नहीं, जहाँ न मेरा राम’।



मालवीयजी की धर्मपत्नी



मालवीयजी अपने पुत्रों के सहित
(बाएँ से—मुकुन्दजी, रमाकान्तजी, राधाकान्तजी तथा गोविन्दजी
नीचे बैठे हुए—मालवीयजी के पौत्र श्रीधरजी)

मालवीयजी अपनी पत्नी के स्वभाव और व्यवहार से काफी संतुष्ट थे। उन्हें उसका गर्व था। उन्होंने पंडित रामनरेशजी त्रिपाठी को कहा कि “वे सदा शान्त और जो कुछ मिल गया उसी में संतुष्ट रहने वाली गृहलक्ष्मी हैं।”^१ उन्होंने त्रिपाठीजी से यह भी कहा कि “अपनी स्त्री के साथ गृहस्थी का सुख धर्म के अनुसार मनुष्य जितना भोग सकता है, मैंने उतना भोगा।”^२ कुनन देवीजी निश्चय ही बहुत साध्वी और भाग्यशाली सिद्ध हुईं। धीरे-धीरे उनके पतिदेव की प्रतिभा का ऐसा विकास हुआ कि उन्हें देश के एक महान् नेता की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। उनके अपने शील ने इस सौभाग्य को चार चाद लगा दिये। उन्होंने पांच पुत्रों और पांच पुत्रियों को जन्म दिया, जिनमें उनके चार पुत्र—रमाकान्त, राधाकान्त, मुकुन्द और गोविन्द और उनकी दो पुत्रियां, रमा और मालती, उनके निधन के समय भारी कुटुम्ब सहित उनकी सेवा में उपस्थित थे।

अध्यापन

सन् १८८४ में बी० ए० परीक्षा पास करने के बाद मालवीयजी संस्कृत में एम० ए० की परीक्षा पास करके अपने पिता की तरह धर्म-प्रचार में अपना जीवन लगा देना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने अपने चचेरे भाई जय गोविन्दजी के आग्रह पर भी गवर्नमेण्ट स्कूल में अध्यापक का काम करने से इनकार कर दिया। पर जब उनकी माता को इसका पता चला और वे उनसे कहने आयीं, तब उनकी ‘सब कल्पनाएँ मा के आसुओं में डूब गयीं’ और वे नौकरी करने के लिए राजी हो गये। ४०) रुपये मासिक के वेतन पर उन्होंने गवर्नमेण्ट हाई स्कूल में, जहाँ उन्होंने पढ़ा था, अध्यापक की नौकरी कर ली। बाद को उनका मासिक वेतन ६०) रु० हो गया। इस आमदनी का अधिकांश भाग वे अपनी माता को परिवार के भरण-पोषण के लिए दे देते थे। दो रुपये मासिक वे अपनी धर्मपत्नी को उसके निजी खर्च के लिए देते थे, और बाकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में तथा सार्वजनिक कामों में खर्च कर देते थे।

मालवीयजी सफल अध्यापक सिद्ध हुए। वे अपने पाठनीय विषय को भलीभाँति तैयार करके उसे बहुत रोचक ढंग से पढ़ाते थे, तथा सदा विद्यार्थियों के प्रति स्नेह-भावना बनाये रखते थे। उनके एक प्रसिद्ध नागरिक छात्र का कहना है कि ‘छात्रों के ऊपर उनकी स्नेहपूर्ण कृपा का, कोमल व्यवहार का, वाणी के

१ वही, पृ० ८०।

२. वही, पृ० ८१।

माधुर्य का, तथा उनके आकर्षक व्यक्तित्व का' बहुत प्रभाव था। सभी उनका सम्मान करते थे। पर जैसा कि मालवीयजी स्वयं कहते थे, उनका स्नेह दृढ़ता से समन्वित था। अनुशासन के सम्बन्ध में वे काफी दृढ़ थे। किसी छात्र का अभद्र या अशोभनीय व्यवहार सहन करने को वे तैयार नहीं थे। इस सम्बन्ध में वे काफी निर्भीक थे। इस पुस्तक के लेखक को एक दिन दृढ़ता और निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन करने का उपदेश देते हुए उन्होंने बताया कि जब एक बार एक उद्दण्ड विद्यार्थी को उन्होंने दण्डित किया और इस पर उसके साथियों ने उन्हें पीटने की धमकी दी, तब उनके बड़े भाई घबड़ा गये, पर वे स्वयं प्रतिदिन की तरह निडर अकेले स्कूल से अपने घर चले गये।

सार्वजनिक कार्य

प्रोफेसर आदित्य राम भट्टाचार्य के प्रोत्साहन से मालवीयजी ने सन् १८८० में ही सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय योगदान करना प्रारम्भ कर दिया था। उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर 'प्रयाग हिन्दू समाज' नाम की संस्था के संचालन में काफ़ी काम किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में प्रकाशित होने-वाले पत्र में मालवीयजी ने धार्मिक और सामयिक विषयों पर लेख लिखना प्रारम्भ किये। उन्होंने सन् १८८२ में स्वयं स्वदेशी का व्रत लेकर उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। इसी समय उनके कतिपय मित्रों ने 'देशी तिजारत कम्पनी' खोली, जो कई वर्ष तक चलती रही। इस काम में वे अपने मित्रों को यथासम्भव परामर्श और सहयोग देते रहे। इसी समय मालवीयजी ने एक छात्र की हैसियत से कुछ दूसरे छात्र-मित्रों के सहयोग से रातोंरात म्योर सेन्ट्रल कालेज के द्वार को झड़ी बन्दनवार आदि से सजाकर लार्ड रिपन का, जिनका स्वागत उस समय कालेज के अंग्रेज प्रिंसिपल करना नहीं चाहते थे, स्वागत किया। सन् १८८४ में प्रयाग में 'हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा' स्थापित हुई। मालवीयजी उसके एक प्रमुख कार्यकर्ता बन गये। सन् १८८२ में माघ मेले के अवसर पर उन्होंने अपने सहपाठियों के उपहास की उपेक्षा करते हुए व्याख्यानो द्वारा जनता में अपने विचारों का प्रचार किया, धार्मिक सिद्धान्तों तथा स्वदेशी का प्रसार किया।

सन् १८८५ में पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य ने 'इंडियन यूनियन' के नाम से अंग्रेजी में एक साप्ताहिक निकालना प्रारम्भ किया। इसके सम्पादन का सारा भार उन्हें ही वहन करना पड़ता था। इसे देखकर उनके आदेश पर मालवीयजी ने उसके सम्पादन का बहुत कुछ भार अपने ऊपर ले लिया।



मालवीयजी के गुरु पं० आदित्यराम भट्टाचार्य

सन् १८८५ में दशहरे के अवसर पर 'प्रयाग हिन्दू समाज' के तत्त्वावधान में 'मध्य भारत हिन्दू समाज' का समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बड़े-बड़े विद्वान् उपस्थित हुए। बरावाँ के राजा श्री महावीर प्रसादजी ने इसका सभापतित्व किया। मालवीयजी ने इसके प्रबन्ध में सक्रिय योगदान करते हुए स्वदेशी पर भाषण दिया। सभा में कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह भी उपस्थित थे। वे बीच-बीच में उठकर बोलने लगते थे। यह बात मालवीयजी को बुरी लगी और उन्होंने राजा साहब के कान में कुछ कहकर उन्हें रोकने की चेष्टा की। पर इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अन्त में राजा साहब ने अपने पत्र 'हिन्दुस्तान' में इस समारोह की प्रशंसा करते हुए लिखा कि 'उसमें दो एक लौड़े ऐसे ढीठ थे कि वे बड़े राजा-रईसों और बाबुओं को व्याख्यान देते समय उनके कान में सलाह देने की धृष्टता करते थे।' राजा साहब चाहे कुछ कहें, मालवीयजी का व्यवहार निश्चय ही ठीक और राजा साहब का व्यवहार अनुचित था।



३. प्रारम्भिक सार्वजनिक जीवन

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन

सन् १८८६ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में मालवीयजी पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में शामिल होने कलकत्ता गये, और वहाँ अपने गुरु की अनुमति से उन्होंने श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना पर बहुत ही उत्तम भाषण दिया, तथा अपनी प्रतिभा के लिए यश तथा आशीर्वाद प्राप्त किया ।

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि संस्थाएँ अंग्रेजों के जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग हैं और वे संसार के सभी सम्य समानों की प्रगति के लिए आवश्यक हैं । इसलिए भारत में निरंकुश संस्थाओं को बनाये रखने का प्रयत्न करने के बजाय प्रतिनिधि संस्थाएँ प्रतिष्ठित करना ही अंग्रेजों का कर्तव्य है । जबकि 'प्रतिनिधित्व के बिना कोई टैक्स नहीं', यह ब्रिटिश राजनीति का मूल मन्त्र है, तब प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रतिष्ठित किये बिना भारतवासियों पर टैक्सों का बोझ लादते जाना अंग्रेजों के लिए सर्वथा अनुचित है । उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व हमारी क्षमता का प्रमाण है । अच्छे अंग्रेज को यह जानकर दुःख होगा कि भारत सरकार 'निरंकुश' है, वह हमारे साथ 'गुलामों' जैसा व्यवहार करती है । देश के शासन में भाग लेने से हमें वंचित करना अनुचित है । प्रतिनिधित्व का अधिकार ब्रिटिश प्रजा का मौलिक अधिकार है, वह हमें मिलना ही चाहिए ।^१

मालवीयजी का यह भाषण निश्चय ही वाग्मिता का उच्चतम नमूना था । अधिवेशन के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने इसे सुनकर कहा कि इस नवयुवक की वाणी में स्वयं भारतमाता ही मुखर हो रही है । श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने स्वीकार किया कि 'यह भाषण मेरे सुने हुए भाषणों में सबसे अच्छा था, जिसका कांग्रेस के प्रतिनिधियों के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और जिसने उन्हें कांग्रेस के भावी नेता के रूप में निर्दिष्ट कर दिया' । ह्यूम साहब ने अपनी रिपोर्ट में

१. दी आनरेबल पंडित मदनमोहन मालवीय * लाइफ एण्ड स्पीचेज, सेकेण्ड एडिशन, १९१८, गनेशन, मद्रास, पृ० ६-७ ।

लिखा कि मालवीयजी का यह भाषण 'श्रोताओं ने तन्मय होकर सुना', उनके धारा-प्रवाह भाषण से सभी लोग मन्त्रमुग्ध हो गये ।

पंडित दीनदयालु शर्मा

कलकत्ता अधिवेशन में मालवीयजी को पंडित दीनदयालु शर्मा से पड़ली भेंट हुई । सम्पर्क शीघ्र ही घनिष्ठ मित्रता और सहयोग में परिपक्व हो गया । धर्म के प्रति दोनों की एक जैसी निष्ठा थी । दोनों ही उदार सनातन धर्म के व्याख्याता तथा प्रभावशाली वक्ता थे । पंडित दीनदयालुजी अपनी वाक्पटुता के कारण आगे चलकर 'व्याख्यान वाचस्पति' के नाम से विख्यात होने लगे । धर्म-प्रचार के कार्य में पंडित दीनदयालुजी मालवीयजी के सबसे बड़े साथी सिद्ध हुए । हिन्दू सभा के कार्य में भी दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । दोनों एक दूसरे को 'भाई' कहा करते थे । मालवीयजी कुछ मास बड़े थे । इसलिए पंडित दीनदयालु उन्हें "ज्येष्ठ भ्राता करके ही मानते रहे" ^१ ।

भारत धर्म महामण्डल

सन् १८८७ में पंडित दीनदयालु शर्मा ने हरिद्वार में सनातन-धर्मियों की एक बड़ी सभा आयोजित की । लाहौर के राजा हरिवंश सिंह, पंडित नन्दकिशोर देव शर्मा, पंडित अम्बिका दत्त व्यास, पंडित देवीसहय, बाबूलाल, मुकुन्द गुप्त आदि कितने ही विद्वान् उसमें सम्मिलित हुए । सुप्रसिद्ध थियासाफिस्ट कर्नल आलकाट ने भी इस सम्मेलन में उपस्थित हो व्याख्यान दिया । इस सभा में भारतधर्म महामण्डल की नींव पड़ी, और मालवीयजी भारत धर्म महामण्डल के महोपदेशको में गिने जाने लगे ।

लगभग पन्द्रह वर्ष इस संस्था से उनका गहरा सम्बन्ध बना रहा, और इसके तत्त्वावधान में आयोजित सम्मेलनों और सभाओं में सनातन धर्म, हिन्दू संस्कृति की विशेषताओं आदि विषयों पर वे व्याख्यान देते रहे ।

सन् १९०२ में महामण्डल की रजिस्ट्री हुई, और वह स्वामी ज्ञानानन्द के प्रबन्ध में चला गया । स्वामीजी की कार्य-प्रणाली से मतभेद हो जाने के कारण मालवीयजी का उससे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया, और उन्होंने सनातन धर्म के उदार सिद्धान्तों के प्रचार के निमित्त सन् १९०६ में प्रयाग में कुम्भ के अवसर पर सनातन धर्म महासभा का एक विराट सम्मेलन स्वतन्त्र रूप से आयोजित

किया। पंडित दीनदयालु शर्मा भी स्वामी ज्ञानानन्द के साथ काम नहीं कर सके। वे भी भारत धर्म महामण्डल को छोड़ मालवीयजी के साथ हो गये।

ऋषिकुल

सन् १९०६ में सनातन धर्म महासभा के सम्मेलन में राय बहादुर पंडित दुर्गादत्त पन्त भी उपस्थित थे। वहाँ से जाते ही उन्होंने हरिद्वार में एक 'ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम' खोलने का प्रयत्न किया। मालवीयजी ने इस प्रयास में योगदान किया। वे शुरू से ही उसके ट्रस्टियों में रहे, और लगभग दस वर्षों तक उसकी शिक्षा-समिति के अध्यक्ष भी रहे। वे बराबर उसके अधिवेशनों में सम्मिलित होते रहे।

सम्पादक

कलकत्ता कांग्रेस में किये गये मालवीयजी के भाषण से राजा रामपाल सिंह भी इतने प्रसन्न हुए कि जब वे प्रयाग आये तब उन्होंने मालवीयजी को बुलाकर उन्हें पुरस्कार-स्वरूप १०) रुपये भेंट किये। छ महीने बाद 'हिन्दुस्तान' के सहायक सम्पादक की जगह खाली हुई, तब राजा साहब ने मालवीयजी से इस पद को स्वीकार करने का अनुरोध किया। राजा साहब, जो विलायत हो आये थे, निर्भीक देशभक्त थे। वे विचारों में उदार और प्रगतिशील थे। वे गुणग्राही थे, प्रगतिशील नवयुवक विद्वानों का आदर करते थे। समाचारपत्रों के माध्यम से प्रगतिशील विचारों का प्रसार ही उनकी पत्रकारिता का ध्येय था। पर राजा साहब खाने पीने में बड़े आजाद थे। इसलिए मालवीयजी ने कुछ संकोच के बाद इस शर्त पर 'हिन्दुस्तान' का सम्पादन स्वीकार कर लिया कि जब राजा साहब खाते-पीते हों तब वे उन्हें न बुलायें। मालवीयजी की नियुक्ति डेढ़ सौ रुपये मासिक पर हुई, पर पन्द्रह दिन के बाद दो सौ रुपये कर दिये गये।

इस तरह मालवीयजी ने जुलाई सन् १८८७ में अध्यापन का कार्य छोड़कर 'हिन्दुस्तान' के सम्पादन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उनके सम्पादकत्व में 'हिन्दुस्तान' ने काफी लोकप्रियता अर्जित की। तत्कालीन समस्याओं पर उनके संपादकीय लेख और टिप्पणियाँ संतुलित और लाभप्रद होती थी। सम्पादकीय शालीनता का पालन, सत्पथ का समर्थन, राष्ट्रहित की पुष्टि, व्यक्तिगत कटाक्ष से निर्मुक्त समालोचना उनकी पत्रकारिता के सद्गुण थे। सरकार भी उनके पत्र को लोकोपयोगी स्वीकार करती थी। राजा साहब मालवीयजी के कार्य से पूरी तौर पर सन्तुष्ट थे, और उनका बड़ा आदर और सम्मान करते थे।

पर लगभग ढाई वर्ष के बाद एक दिन राजा साहब ने मालवीयजी को उस समय बुला भेजा, जब वे नशे में थे और उनका कमरा शराब की गंध से भरा था। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद राजा साहब ने पंडित अयोध्यानाथ के सम्बन्ध में कुछ ऐसी अपमानजनक बातें कही, जो मालवीयजी को बुरी लगी। उन्होंने उसी समय राजा साहब का काम छोड़ कर कालाकाकर से चले जाने का निश्चय किया। उन्होंने राजा साहब से कहा कि 'आज से मेरा अन्न जल आपके यहा से उठ गया, आपने जो शर्त की थी, वह तोड़ दी।' यह कह कर मालवीयजी घर चले गये।

दस-बारह दिन के बाद जब वे राजा साहब से मिलने गये, तब खबर पाकर राजा साहब स्वयं बाहर निकल आये और सिर झुका कर कहने लगे— "मालवीयजी, उस दिन मैंने नशे में क्या-क्या कहा, मुझे याद नहीं, फिर भी यदि कोई अपमानजनक बात निकली हो तो यह सिर आपके सामने है, इस पर उसकी सजा दे डालिये।" राजा साहब की नम्रता देख कर मालवीयजी को विश्वास हो गया कि "राजा साहब ने जानबूझ कर पंडित अयोध्यानाथ के विषय में अपमानजनक बात नहीं कही थी।"^१ फिर भी मालवीयजी कालाकाकर में रह कर सम्पादकत्व का भार फिर से ग्रहण करने को राजी नहीं हुए।

इस पर राजा साहब ने मालवीयजी को वकालत पढने की सलाह दी, और पढाई का खर्च देने का वायदा किया। वे मालवीयजी को सौ रुपये महीना भेजने लगे। जब मालवीयजी वकील हो गये और अच्छी कमाई करने लगे, तब भी यह रकम वर्षों नियमित रूप से आती रही। जब मालवीयजी ने एक बार राजा साहब से कहा कि वे अब उनका कोई काम नहीं करते, उनकी नौकरी में भी नहीं है, तब रुपया क्यों भेजा जाता है? यह सुनकर राजा साहब बिगड़ गये और कहने लगे— "नौकरी में? मालवीयजी, क्या आपने मेरे व्यवहार में कोई ऐसी बात पायी है, जिससे आपके साथ नौकर का बर्ताव पाया जाता हो? आपके पास विद्या है। आप गुणों की खान हैं। आप उसके द्वारा मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और मैं थोड़े पैसे से आपकी सहायता करता हूँ। इससे आप पर मेरा एहसान क्या है?"^२

सार्वजनिक काम

मालवीयजी जब कालाकाकर में रह कर सम्पादन का कार्य करते थे, तब वे प्रति सप्ताह प्रयाग आ जाते, और देश की राजनीतिक प्रगति में यथासंभव

१. त्रिपाठी : मालवीयजी के साथ तीस दिन, पृ० २३०-३१।

२. वही, पृ० २२९।

सक्रिय योगदान करते थे। दिसम्बर सन् १८८७ ई० में उन्होंने अपने प्रान्त से चालीस से अधिक प्रतिनिधि जुटा कर कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भाग लिया और वहाँ अपने भाषण के लिए राजा सर टी० भागवत राव, अर्द्धले नार्टन और ह्यूम जैसे विख्यात व्यक्तियों से प्रशंसा और आशीर्वाद प्राप्त किया।

मालवीयजी ने अपने भाषण में कहा कि प्रतिनिधि संस्था की स्थापना ब्रिटिश प्रजा की हैसियत से हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जबकि रूस के अतिरिक्त यूरोप के सभी देश सरकार की गतिविधि में जनता के प्रतिनिधियों का योगदान आवश्यक समझते हैं, और ब्रिटेन ने अपने बहुत से उपनिवेशों में किसी न किसी अंश में प्रतिनिधि सरकार प्रतिष्ठित कर दी है, तब भारत को इससे वंचित रखना अनुचित है। जबकि यूरोप के वे देश भी, जहाँ की प्रजा और शासक एक ही जाति और धर्म के हैं, प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता स्वीकार करते हैं, तब भारत में, जहाँ प्रजा और शासक वर्ग की भाषा और संस्कृति बिल्कुल भिन्न है, ये संस्थाएँ निश्चय ही नितान्त आवश्यक हैं। इस समय भारत के प्रशासन तथा राजकोश की देखभाल का सारा उत्तरदायित्व ब्रिटिश पार्लियामेंट पर है। पर जैसा कि प्रोफेसर फाकेट, चार्ल्स ब्रेडला आदि ने स्वीकार किया है, पार्लियामेंट इस बोझ को ठीक तौर पर वहन नहीं कर रही है। ऐसी दशा में भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित कर उन्हें इस भार को सौंपना ही उचित है। इस कांग्रेस का अस्तित्व इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम प्रतिनिधि संस्थाओं के सर्वथा योग्य हैं।^१

इस अवसर पर वे कांग्रेस द्वारा अपने प्रान्त के 'पोलिटिकल एसोसिएशन' तथा स्थायी कार्यसमिति के मन्त्री नियुक्त किये गये, और उनके निमन्त्रण पर अगले वर्ष प्रयाग में कांग्रेस का अधिवेशन करने का निश्चय किया गया। कांग्रेस के प्रयाग अधिवेशन की सुव्यवस्था का श्रेय पंडित अयोध्यानाथ, पंडित विश्वम्भर नाथ, श्री चारुचन्द्र मित्र और राय बहादुर रामचरण दास आदि बुजुर्गों के साथ मालवीयजी को भी था, जिन्होंने स्वागत समिति के सहायक मन्त्री की हैसियत से जी-तोड़ कर काम किया। मालवीयजी पंडित अयोध्या नाथ के 'उत्तेजक उत्साह' तथा पंडित विश्वम्भर नाथ के गम्भीर उत्सर्ग के बहुत प्रशंसक थे और उनके नेतृत्व में उनके अधीन रहकर काम करना अपने लिए 'गौरवप्रद' समझते थे।^२

१. दी आनरेबल पंडित मदनमोहन मालवीय . लाइफ एंड स्पीचेज, पृ० ११-१२।

२. सन् १९०८ का प्रान्तीय कांग्रेस का अध्यक्षीय भाषण।

अयोध्यानाथजी तो एक प्रकार से उनके राजनीतिक गुरु ही थे । दोनों के बहुत मधुर सम्बन्ध थे ।

सन् १८८८ में कांग्रेस के अधिवेशन में विषय समिति की ओर से आयकर के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मालवीयजी ने किसी हद तक अप्रासंगिक ढंग से बहुत से प्रमाणों द्वारा सन् १८५८ की शाही घोषणा की वास्तविकता सिद्ध करते हुए माग की कि इस घोषणा में निहित प्रणों को ईमानदारी के साथ पूरा किया जाय । उन्होंने प्रतिनिधि संस्थाओं के विस्तार की आवश्यकता पर भी जोरदार भाषण दिया ।

सन् १८८९ में कालाकाकर से प्रयाग लौट आने पर मालवीयजी पंडित अयोध्यानाथ के नेतृत्व में अग्रेजी दैनिक 'इंडियन ओपीनियन' में सह-सम्पादक का काम करने लगे । उन्होंने वकालत की पढाई भी शुरू कर दी । हिन्दू ला के साथ विधिविज्ञान तथा इंगलिस्तान के सविधान के अध्ययन में उनकी विशेष दिलचस्पी थी । लोकतान्त्रिक सविधान तथा नागरिक स्वतन्त्रता के मूलभूत सिद्धांतों के सम्बन्ध में ब्रिटेन के विद्वानों और विधि-विशेषज्ञों के विचारों का अध्ययन कर उन्होंने अपनी लोकतान्त्रिक भावनाओं और धारणाओं को परिपुष्ट किया ।

परीक्षा से कुछ दिन पहले उनके एक छोटे भाई ने किसी अज्ञात कारण से अफीम खाकर आत्महत्या कर ली । इस दुःखद घटना के कारण मालवीयजी का उत्साह इतना क्षीण हो गया कि उन्होंने परीक्षा देने का विचार ही छोड़ दिया । पर पंडित अयोध्यानाथजी के समझाने पर मेहनत करके परीक्षा में बैठ गये ।

वकालत

सन् १८९१ में वकालत की परीक्षा पास करके मालवीयजी ने पंडित बेनी राम कान्यकुब्ज के साथ जिला अदालत में काम शुरू किया । दो वर्ष बाद वे हाईकोर्ट में वकालत करने लगे । धीरे धीरे उनकी वकालत काफी चमक गयी । शेरकोट की रानी का मुकदमा जीतने पर मालवीयजी को बड़ी कीर्ति प्राप्त हुई । उससे आमदनी भी इतनी हुई कि उन्होंने घर का सारा कर्जा चुका कर भारती भवन में अपने जन्म-गृह से सटे हुए मकान को पक्का करा लिया ।

सन् १८९१ में जब उन्होंने वकालत शुरू ही की थी, तो उन्हें अपना ध्यान सार्वजनिक कामों की ओर से कुछ हटाना पड़ा, जिसकी कुछ शिकायत भी हुई ।

पर जब सन् १८९२ में प्रयाग में दूसरी बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब उन्होंने उसकी समुचित व्यवस्था के लिए भरसक प्रयत्न किया, और उसकी सफलता बहुत अंशों में उनके प्रयत्नों का परिणाम थी।

जब इलाहाबाद में मालवीयजी व्यस्त वकील थे, तब वे घोड़ा-गाड़ी से अदालत जाते थे। इलाहाबाद में यह बात मशहूर थी कि उनके घोड़े को चाबुक नहीं लगती थी और गाड़ी का कोचवान, जिसका नाम 'घोताल' था, नित्य प्रातः स्नान कर, चंदन का टीका लगा, स्वच्छ एवं शुभ्र वस्त्र पहन कर, सूर्य को अर्घ्य देकर, अपने काम पर हाजिर होता था।^१

हाई कोर्ट में वकालत निश्चय ही कीर्ति और प्राप्ति दोनों का अच्छा साधन था। यदि एकाग्र-चित्त हो वे उसे करते तो वे अवश्य ही सुख-समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सकते थे। पर लक्ष्मी उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी। राष्ट्रसेवा ही उनका मुख्य धंधा बना रहा। सन् १९०८ में उन्होंने वकालत का धंधा कम करने का निश्चय किया। सन् १९१० उन्होंने वकालत छोड़ देने का निश्चय किया, और सन् १९१३ में उन्होंने वकालत करना विल्कुल छोड़ दिया। इस अवसर पर मालवीयजी के द्वितीय पुत्र पंडित राधाकान्त जी ने जो उन दिनों इलाहाबाद में अच्छे वकीलों में गिने जाते थे, मालवीयजी से कहा "बाबू, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। बहुधा (राधाकान्त की मा) के पास हमने पर्याप्त रुपये जमा कर दिये हैं, जिससे घर की व्यवस्था होती रहेगी। तुम चिन्ता छोड़कर देश की सेवा करो।"^२

यद्यपि वकालत में वे इतना ऊँचा स्थान प्राप्त नहीं कर सके, जितना वे कर पाते, यदि वे दत्तचित्त होकर उसे करते। फिर भी उन्होंने वकीलों की मण्डली में बहुत ही सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया था। सर तेज बहादुर सप्रू ने लिखा है, 'वकालत प्रारम्भ करने के थोड़े ही वर्षों के भीतर दीवानी पक्ष में मालवीयजी की अच्छी वकालत चमक उठी थी, जिससे उनका नाम पंडित सुन्दर लाल, पंडित मोती लाल नेहरू और श्री चौधरी के पश्चात् लिया जाने लगा था। वकालत में वे अत्यन्त तीव्र मेधावाले वकील के रूप में प्रसिद्ध थे। किसी मुकदमे पर वादविवाद करते हुए वे अत्यन्त निष्पक्षतापूर्वक घोलते थे। वे अपने विरोधी वकीलों का बड़ा सम्मान करते थे। किन्तु सबसे अधिक बात यह थी जो उन दिनों के हम छोटे वकीलों के सामने ज्वलन्त उदाहरण के रूप

१. मालवीयजी के दौहित्र श्री शिवकुमार जी से प्राप्त सूचना।

२. मालवीयजी के दौहित्र श्री शिवकुमारजी से प्राप्त सूचना।

में प्रस्तुत की जाती थी कि वे ऐसे वकील हैं, जिनमें अत्यन्त उच्च श्रेणी की योग्यता के साथ परम विवेक भी विद्यमान है। मैं भलीभाँति जानता हूँ कि एक के पश्चात् एक न्यायाधीश और सर जान स्टेनली और रिचार्ड जैसे मुख्य न्यायाधीश केवल उनकी योग्यता के कारण ही नहीं, वरन् उनके निष्कलंक चरित्र के कारण भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। सफल वकील होने के तीन विशेष गुण मालवीयजी में विद्यमान थे—मुकदमे की पक्की तैयारी, प्रभावशाली वाणी, और अपने मुकदमे को ऐसे ढंग से रखने की कला कि सुनने-वाला तत्काल बात मान ले। वे पुराने निर्णयों के उद्धरण तथा कानूनी और तथ्यात्मक पक्ष को ऐसे शान्त और प्रामाणिक रीति से प्रस्तुत करते थे कि उनके विरोधी वकीलों को उन तथ्यों या उनके तर्कों का खडन करना सदा कठिन हो जाता था।'

बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन ने भी अपने एक भाषण में उनकी सच्चाई और ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका व्यावसायिक जीवन उतना ही धवल था, जितना उनका व्यक्तिगत जीवन। उन्होंने कहा कि मालवीयजी ने अपने वकालत के जमाने में न कभी किसी दलाल का प्रयोग किया, न कभी मुंशी द्वारा किसी को घूस दिलवायी, और न कभी किसी से झूठी गवाही देने को कहा।

त्याग और सेवा

वकालत छोड़ कर सारा जीवन राष्ट्र की उन्नति में लगा देने का निर्णय अवश्य ही मालवीयजी के त्याग का उच्चतम उदाहरण है। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था—त्याग तो मालवीयजी महाराज का है। वे निर्धन परिवार में उत्पन्न हुए और बढ़ते-बढ़ते प्रसिद्ध वकील होकर सहस्रो रुपया मासिक कमाने लगे। उन्होंने वैभव का स्वाद लिया, और जब दृश्य से मातृभूमि की सेवा की पुकार उठी, तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर पुनः निर्धनता स्वीकार कर ली।'^१

प्रथम विश्वयुद्ध से पहले जो वकील सार्वजनिक कार्यों में दिलचस्पी लेते थे, उनमें से अधिकांश का कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित होता था। उनकी प्रतिभा की तुलना में राष्ट्रसेवा में उनका योगदान बहुत कम होता था। पर मालवीयजी का कार्यक्षेत्र वकालत के जमाने में भी बहुत विस्तृत और व्यापक था, तथा राष्ट्र-सेवा में उनका योगदान उनकी वकालत से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था। इन वीस

वर्षों में (१८९२-१९११) जो मान और प्रतिष्ठा उन्होंने वकील की हैसियत से प्राप्त की, उससे कहीं अधिक उन्होंने राष्ट्रसेवा द्वारा अर्जित की।

यों तो सन् १८९२ में पंडित अयोध्यानाथ के निधन के बाद लगभग दस वर्ष तक प्रयाग की राजनीति में मालवीयजी पंडित विश्वम्भर नाथजी के नेतृत्व में उनके सहयोगी की हैसियत से मुख्यतः काम करते रहे, पर इन दस वर्षों में भी उन्होंने एक स्वतन्त्र कार्यकर्ता की हैसियत से समाज की महत्त्वपूर्ण सेवा की तथा एक उत्कृष्ट नेता की ख्याति प्राप्त कर ली।

नागरी लिपि

इस दशक में उनका सबसे महत्त्वपूर्ण काम अदालतों में देवनागरी लिपि के प्रयोग को सरकार द्वारा स्वीकृत कराना था। इसके लिए उन्हें लगातार तीन वर्ष तक कठिन परिश्रम करके एक प्रार्थनापत्र तैयार करना पड़ा। इस प्रार्थनापत्र में उन्होंने बहुत से विद्वानों और प्रशासकों के विचारों तथा बहुत से तथ्यों के आधार पर नागरी लिपि के दावे को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर मोनियर विलियम्स, सर आइजैक पिटमैन, चीफ जस्टिस अर्सकिन पेरी जैसे विद्वान् नागरी लिपि की सर्वांगपूर्णता स्वीकार करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि इन अक्षरों की मनोहरता, सुन्दरता, स्पष्टता, पूर्णता और शुद्धता निर्विवाद है। प्रार्थनापत्र में यह भी बताया गया कि 'यदि यह भी मान लिया जाय कि फारसी में अधिक शीघ्रता से काम चलता है,' तो भी नागरी के गुणों तथा स्वत्वों को भुलाया नहीं जा सकता। शिकस्त लिखने में यदि अदालत का कुछ समय बच जाता है, "तो उन्हीं कागजों के पढ़ने में बहुत समय नष्ट हो जाता है, और अन्त में नामों आदि के विषय में सन्देह बाकी रह जाता है।" इस पत्र में आंकड़ों द्वारा सिद्ध किया गया कि इस प्रान्त में प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी पढ़नेवाले बालकों की संख्या उर्दू पढ़नेवाले बालकों से दुगुनी तिगुनी है, और यदि उर्दू लिपि की तरह नागरी लिपि का भी अदालतों में प्रयोग होने लगे, तो हिन्दी पढ़नेवालों की संख्या और भी अधिक बढ़ जायेगी। इस प्रार्थनापत्र में यह स्वीकार किया गया कि सन् १८९५-१८९६ में वर्नाकुलर मिडिल स्कूलों में उर्दू पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या हिन्दी पढ़नेवालों से चौगुनी है। पर यह कहा गया कि सन् १८७३-१८७४ में हिन्दी पढ़नेवालों की संख्या उर्दू पढ़नेवालों से तिगुनी थी, और इस भारी परिवर्तन का मूल कारण सरकार की सन् १८७७ की यह आज्ञा है, जिमने सरकारी दफ्तरों में नौकरी के लिए उर्दू या फारसी में एंग्लो वर्नाकुलर परीक्षा

पास करना अनिवार्य कर दिया था। इस आज्ञा के औचित्य को चुनौती देते हुए परिपत्र में प्रार्थना की गयी कि उर्दू लिपि के साथ-साथ नागरी लिपि का भी अदालतों में प्रयोग किया जाय। बहुत से प्रमाणों से हिन्दी भाषा की व्यापकता को सिद्ध करते हुए प्रार्थनापत्र में कहा गया कि हिन्दी ही उत्तर भारत की भाषा है, और नागरी अक्षरों का प्रचार 'पञ्चिमोत्तर प्रान्त और अवध' (मौजूदा उत्तर प्रदेश) में शिक्षा के प्रसार के लिए नितान्त आवश्यक है।^१

मालवीयजी के प्रयास से सन् १८९६ में सर एण्टोनी मेकडानल ने प्रान्तीय सरकार की सन् १८७७ की वह आज्ञा वापस ले ली, जिसने सरकारी दफ्तर में दस रुपये या उससे अधिक की नौकरी पाने के लिए उर्दू या फारसी में एंग्लो-वर्नाकुलर मिडिल परीक्षा पास करना अनिवार्य बना दिया था। मालवीयजी के प्रयास से २ मार्च सन् १८९८ को अयोध्या नरेश महाराजा प्रताप नारायण सिंह, माण्डा के राजा राम प्रसाद सिंह, आवागढ के राजा बलवन्त सिंह, पंडित सुन्दरलाल तथा मालवीयजी का एक डेपुटेशन सर एण्टोनी मेकडानल से, जो उस समय उनके प्रान्त के लैफ्टिनेन्ट गवर्नर थे, मिले और मालवीयजी ने उसकी ओर से नागरी लिपि के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र उन्हें पेश किया। सर एण्टोनी ने प्रार्थनापत्र पर विचार करने का वायदा किया, और १४ अप्रैल सन् १९०० ई० को अदालतों में फारसी लिपि के साथ नागरी लिपि के भी चलन की आज्ञा जारी कर दी।

मुसलमानों ने सरकार की आज्ञा का विरोध करते हुए मालवीयजी पर साम्प्रदायिकता का दोष लगाया, और नागरी लिपि तथा हिन्दी की तरह-तरह से हिजो की। पर एक दिन मालवीयजी ने एक अरबी की नजीर नागरी लिपि में लिख कर हाईकोर्ट में पढ़कर इस तरह ठीक ठीक सुनायी कि मौलवी जामिन अला, जो मशहूर वकील थे, मुकदमा खतम होने पर उनसे कोर्ट के बरामदे में मिले और उनका हाथ पकड़ कर कहने लगे—“पंडित साहब, आज मैं नागरी अक्षरों की उमदगी का कायल हो गया, लेकिन मैं पब्लिक में यह नहीं कहूँगा।”^२

भारती भवन पुस्तकालय

नवम्बर सन् १८८६ में पंडित बालकृष्ण भट्ट के प्रयास से, श्री बृजमोहन भल्ला की उदारता से, तथा बहुत से नवयुवकों के उत्साह से मालवीयजी के निवास

१. सीताराम चतुर्वेदी : महामना पंडित मदनमोहन मालवीय, खण्ड ३, पृ० ८०-१०६।
२. रामनरेश त्रिपाठी : मालवीयजी के साथ तीस दिन, पृ० १९४-१९६।

स्थान के निकट 'भारती भवन' के नाम से एक पुस्तकालय स्थापित हुआ। आगे चल कर लाला रामचरण दास के आर्थिक दान से, तथा श्री जयगोविन्द मालवीय द्वारा संस्कृत पुस्तको के उपहार से वह अधिक समृद्ध हुआ। हिन्दी और संस्कृत पुस्तको का संग्रह और अध्ययन इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रयाग में यह अपने ढंग का पहला पुस्तकालय था। मालवीयजी ने इस प्रयास में काफी दिलचस्पी ली। वही इसकी परिरक्षक समिति (बोर्ड आफ ट्रस्टीज) के अध्यक्ष नियुक्त हुए, और आजीवन इस पद से उसकी सेवा करते रहे। उन्हीं के प्रयास से उनका मुहल्ला 'भारती भवन' के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

प्रयाग म्युनिस्पैलिटी

वकालत के जमाने में मालवीयजी ने प्रयाग की भरपूर सेवा की। उन्होंने उसके सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को समृद्ध किया। प्रयाग नगरपालिका के वरीय उपाध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने नगर की स्वच्छता और सुन्दरता के लिए यथासंभव कार्य किया, तथा एक भयंकर महामारी के अवसर पर अपने स्वास्थ्य की चिन्ता छोड़ कर पीडित जनता की सेवा की। उन्होंने घर-घर जाकर पीडितों को अस्पताल पहुँचाया, जो निरोग थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा, सब घरों में कीटाणुनाशक औषधि छिड़कवायी, और जो निराश्रित हो गये थे, उनके भोजन और आवास की व्यवस्था की। वे सन् १९१६ तक प्रयाग म्युनिस्पैलिटी के सदस्य की हैसियत से अपने जन्मस्थान की सेवा करते रहे।

छात्रावास का निर्माण

मालवीयजी ने हिन्दू विद्यार्थियों के रहने के लिए एक छात्रावास के निर्माण के निमित्त प्रान्त में धूम-धूम कर चन्दा एकत्र किया। सन् १९०३ में छात्रावास तैयार हो गया। इसके निर्माण में लगभग ढाई लाख रुपया लगा, जिसमें एक लाख रुपया सरकार ने दिया, बाकी चन्दे से जमा हुआ। इस छात्रावास में, जो "मेकडानल हिन्दू बोर्डिंग हाउस" के नाम से प्रसिद्ध हुआ, दो सौ तीस विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था थी। इसके निर्माण और प्रवन्व में पंडित सुन्दरलालजी का, जो प्रयाग हाईकोर्ट के दीवानी पक्ष के सर्वश्रेष्ठ वकील थे, महत्त्वपूर्ण योगदान था। वही उसकी प्रवन्व समिति के पहले अध्यक्ष थे।

पंडित सुन्दरलाल

पंडित सुन्दरलाल बहुत प्रतिभाशाली, कार्यकुशल व्यक्ति थे। वे प्रयाग विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम हिन्दुस्तानी वाइस-चान्सलर थे। प्रयाग के सांस्कृतिक

जीवन के निर्माण में उनका योगदान निश्चय ही महत्वपूर्ण था। मालवीयजी, जो उनसे साढ़े चार वर्ष छोटे थे, उनकी योग्यता के कायल थे, उनके प्रति 'अदब का वर्तवि' करते थे, और अपने निर्माण-कार्यों में उनका परामर्श और सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का सदा प्रयत्न करते थे। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना में उनका बड़ा हाथ था। वे ही उसके सर्वप्रथम वाइस-चान्सलर थे। उन्होंने सन् १९१० में कांग्रेस के प्रयाग अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष की हैसियत से काम किया, तथा सन् १९०४ के बाद लगभग दस वर्ष तक प्रयाग में कांग्रेस के नरमदलीय पक्ष को पुष्ट किया। वे लगभग चौदह वर्ष तक युक्त प्रान्त की विधान कौंसिल के सदस्य रहे, और इस जमाने में ही उन्होंने सन् १९०१ में यूनिवर्सिटी कमीशन, सन् १९०८ में डिसेन्ट्रीलाइजेशन (विकेन्द्रीकरण) कमीशन तथा, सन् १९१३ में इस्लिगटन की अध्यक्षता में आयोजित पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गवाही दी, तथा भारतीय पक्ष का समर्थन किया। वे अपने जमाने में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्व-सम्मानित, सर्वश्रेष्ठ वकील थे, और सम्राट् द्वारा राय बहादुर, सी०आई०ई०, और 'सर' की उपाधियों से विभूषित किये गये।

बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन

प्रयाग के सांस्कृतिक जीवन की अभिवृद्धि के लिए मालवीयजी ने बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यालय को प्रयाग में स्थापित कर उसका संचालन करने को प्रोत्साहित किया। टण्डनजी से मालवीयजी के बहुत ही मधुर सम्बन्ध थे। वे तो एक प्रकार से टण्डनजी के राजनीतिक गुरु थे। उन्हीं से टण्डनजी ने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक सेवा की प्रथम प्रेरणा प्राप्त की थी।^१ टण्डनजी सयमी, दृढप्रतिज्ञ, कर्तव्य-परायण, निस्पृही राष्ट्रसेवी थे। किसानों के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति थी। वे स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी और नायक थे। प्रयाग के नागरिक जीवन तथा प्रान्त के राजनीतिक जीवन में अपने त्याग और सेवा के आधार पर उन्होंने बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया था। जमींदारों की लूट-खसोट के प्रतिरोध के लिए किसानों का संगठन, तथा किसान आन्दोलन का नेतृत्व उनके राजनीतिक क्रिया-कलापों का महत्वपूर्ण अंग था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तो वे प्राण ही थे। वे ही उसके प्रमुख कर्ता-धर्ता थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय

१ पुरुषोत्तमदास टण्डन : महामना मालवीयजी वर्थ सेन्टिनरी कोमिमारेणन वाल्यूम।

कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, तथा उससे पहले ही सन् १९३७ में प्रान्तीय विधान सभा के अध्यक्ष पद से बहुत ही निष्पक्षता और निर्भीकता से उसका विधिवत् संचालन किया ।

औद्योगिक प्रगति और बलदेवराम दवे

सन् १९०७ में मालवीयजी ने यू० पी० इण्डस्ट्रियल कान्फ्रेंस (औद्योगिक सम्मेलन) का अधिवेशन प्रयाग में आयोजित किया, तथा 'प्रयाग इंडस्ट्रियल असोसिएशन' की स्थापना की । इस कार्य में उन्हें अपने पुराने स्नेही पंडित बलदेवराम दवे का भरपूर सहयोग प्राप्त था । 'कांग्रेस के कामों में चारुचन्द्र के समान वे भी बहुत परिश्रम किया करते थे, और हर बात में अगुआ बनकर जोर-शोर से काम करते थे ।' ^१ बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के निर्माण और प्रबन्ध में भी उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था । रचनात्मक कामों में उनकी विशेष अभिरुचि थी । उन्होंने दस वर्ष तक इलाहाबाद इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से नगर की सेवा की, तथा 'हिन्दू ग्रन्थालय' की स्थापना की । प्रयाग की अन्य बहुत-सी संस्थाओं के संचालन में भी उनका भरपूर हाथ था । साठ वर्ष की आयु में वकालत का धंधा छोड़कर उन्होंने अपने जीवन के अगले बीस वर्ष समाज के रचनात्मक कार्यों में ही लगा दिये ।

'अभ्युदय' और कृष्णकान्त मालवीय

सन् १९०७ में ही वसन्त पंचमी के दिन मालवीयजी ने अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारों के प्रसार के लिए हिन्दी में 'अभ्युदय' नाम का साप्ताहिक निकालना प्रारम्भ किया । दो वर्ष तक उसका स्वयं सम्पादन किया । उसके बाद बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन आदि ने इस भार को सम्भाला । सन् १९१० में मालवीयजी के भैंसले भाई पंडित जयकृष्णजी के सुपुत्र पंडित कृष्णकान्त मालवीय ने सम्पादन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया । मालवीयजी की भद्रता, कर्तव्यपरायणता, और देशभक्ति की कृष्णकान्तजी पर गहरी छाप थी । वे मरते दम तक राष्ट्र की सेवा में संलग्न रहे । यही उनके जीवन का मुख्य धंधा था । 'अभ्युदय' का सम्पादन इसी का एक साधन था । 'पंडित कृष्णकान्तजी हिन्दी के एक प्रधान पत्रकार थे । उनका राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान बहुत बढ़ाचढ़ा था । वे जनता की रुचि और आवश्यकता को पहचानते थे । हिन्दी के टकसाली लेखक थे । उनके लिखने का अपना ढंग, उनकी अपनी शैली थी । उनकी भाषा में

सादगी, प्रवाह, जीवन और आकर्षण था।^१ कृष्णकान्तजी सहृदय, निर्भीक, प्रगतिशील देशभक्त थे। उन्होंने गांधीजी के नेतृत्व में आयोजित स्वतन्त्रता संग्रामो में योगदान किया, तथा पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित 'स्वराज्य पार्टी' के सदस्य की हैसियत से केन्द्रीय असेम्बली में भरपूर काम किया। वे सदा मालवीयजी के प्रिय बने रहे। वे मालवीयजी महाराज के भतीजे ही नहीं, उनके 'राजनीतिक पुत्र' भी थे। इसी नाम से वे प्रसिद्ध थे। 'अभ्युदय' के सह-कारी सम्पादक श्री सत्यव्रतजी ने अपने एक स्मरण में लिखा है—“ 'अभ्युदय' सदा निःस्वार्थ, निर्भीक और नम्र रहा। उसने अपनी मर्यादा को कभी हाथ से नहीं जाने दिया। जिन बात में उसने जनता का हित देखा, जोरो से कहा और देखटके कहा। कर्तव्यपालन में उसने कभी लोक-प्रियता और अप्रियता का विचार नहीं किया। अमीर और गरीब 'अभ्युदय' की निगाह में सदा समान रहे। उसने कभी गरीबों पर अमीरों के अत्याचारों को सहन नहीं किया। देशी राज्यों की प्रजा का पक्ष-समर्थन, और किसानों की हिमायत तो इसकी मशहूर है ही, इसने एक गरीब उपलो वाली तक की इज्जत की रक्षा के लिए हलचल मचा दी। शिष्टाचार को 'अभ्युदय' ने कभी नहीं छोड़ा। यद्यपि इ की 'सीधी-टोढी खरी मजेदार बातें' चोखो चुटकियाँ होती थी, तथापि वे अशिष्ट कभी नहीं हो पायी, और उनका उद्देश्य भी दूसरों का सुधार ही रहा—निन्दा नहीं। अपने सहयोगियों और विरोधियों दोनों के साथ 'अभ्युदय' का वर्तव सज्जनतापूर्ण रहा।”^२ प्रारम्भ में ढाई वर्ष तक मालवीयजी ने उसका सम्पादन किया। उस काल में जो अग्रलेख उन्होंने लिखे उनमें 'मालवीयजी के व्यक्तित्व का समग्र रूप' हमें दिखाई देता है। उनमें 'उनके शब्दों में मालवीयजी की प्रतिभा प्रकाशित है और उनमें उनके जीवन का अनुभव समाया हुआ है।' “देश की स्थिति के अनुसार उस समय उन्होंने राष्ट्रीयता का जो सन्देश हमें दिया है, गाज भी हम उससे लाभ उठा सकते हैं। एक सच्चे ब्राह्मण के रूप में जो उपदेश उन्होंने हमें दिये, उनमें भारतीय आत्मा और संस्कृति बसती थी।”^३

‘लीडर’ और चिन्तामणि

सन् १९०९ में मालवीयजी के प्रयास तथा बहुत से मित्रों के सहयोग से विजया दशमी के दिन २४ अक्तूबर से अग्रेजी दैनिक ‘लीडर’ का प्रकाशन शुरू हुआ। इस काम में पंडित मोतीलाल नेहरू का भी बड़ा हाथ था। मालवीयजी

१. मालवीयजी—जीवन झलकिया—पृ० २९३-२९४।

२. वही, पृष्ठ २९३।

३. राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद, अप्रैल सन् १९६२, ‘मालवीयजी के लेख’ की भूमिका।

ने उसके संपादन का भार ग्रहण किया, और मोतीलालजी ने कंपनी की प्रबंध-समिति की अध्यक्षता सुशोभित की। सन् १९११ में श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने दैनिक 'लीडर' के सम्पादन का भार ग्रहण किया, और मालवीयजी ने मोतीलालजी के स्थान पर अध्यक्ष का भार संभाला। चिन्तामणिजी के सम्पादकत्व में 'लीडर' ने नि स्वार्थ भाव से देश की और प्रान्त की बड़ी लगन से सेवा की। लगभग दस वर्ष तक इसने ही मुख्य रूप से संयुक्त प्रान्त में राष्ट्रीय विचारों का निर्भीकता से प्रसार और प्रतिनिधित्व किया। पर आगे चल कर राष्ट्रीय प्रश्नों पर मतभेद बढ़ जाने के कारण पंडित मोतीलाल नेहरू ने 'इंडिपेंडेंट' पत्र चलाया, और वह राष्ट्रवादी विचारों का प्रमुख पत्र बन गया।

चिन्तामणि

श्री सी० वाई० चिन्तामणि कुशल उदारदलीय पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे। सन् १९२१ में उन्होंने शिक्षा-मन्त्री का पद ग्रहण किया, और युक्त प्रान्त (मौजूदा उत्तर प्रदेश) की शैक्षिक व्यवस्था के पुनर्गठन में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्हीं के अधिकार-काल में लखनऊ के कर्निंग कालेज ने, तथा प्रयाग के म्योर सेण्ट्रल कालेज ने शैक्षिक और निर्वासीय विश्वविद्यालयों का रूप धारण किया।

मिटो पार्क

सन् १९१० में मालवीयजी ने सोचा कि जिस स्थान पर गवर्नर-जनरल लार्ड केनिंग ने १ नवम्बर सन् १८५८ को दरबार करके महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़कर सुनायी थी, उस स्थान पर एक घोषणा-स्तम्भ (प्रोक्लेमेशन पिलर) खड़ा करके उस पर घोषणा के वाक्य खुदवा दिये जायें, ताकि उसकी यादगार बनी रहे, और उसके चारों ओर एक पार्क बनाया जाय। शिलान्यास के लिए उन्होंने तत्कालीन वाइसराय लार्ड मिंटो को निमंत्रित किया। उन्होंने मालवीयजी की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। तिथि निश्चित हो गयी। ९ नवम्बर सन् १९१० को किले के पास यमुना के तट पर लार्ड मिंटो ने एक वृहद् जलसे में शिलान्यास किया, और पंडित मोतीलाल नेहरू ने 'माल इंडिया मिंटो मेमोरियल कमेटी' के संयुक्त मन्त्री को हैसियत से स्वागत-पत्र पढ़ा। उत्सव निर्विघ्न समाप्त हुआ।

विना किसी तैयारी के जिम तरह मालवीयजी ने लार्ड मिंटो को निमंत्रित कर लिया था, उससे गोखले साहब को चिन्ता पैदा हो गयी थी कि यदि निश्चित

समय तक धन इकट्ठा नहीं हो सका, तों मालवीयजी ही क्या, सभी भारतीय सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की वंदना भी हो जायेगी।' इस लिए उन्होंने मालवीयजी को सलाह दी कि वे और सब काम छोड़कर धन जमा करने में जुट जायें। पर मालवीयजी ने पत्नी द्वारा ही मिंटो पार्क के निर्माण के लिए एक लाख वत्तीस हजार आठ सौ सत्तानवे रुपये जमा कर लिये।

पिता का निधन

इस उत्सव के समय ही मालवीयजी को अपने पिता की सख्त बीमारी की सूचना मिली। पर बार-बार बुलाये जाने पर भी वे उत्सव को छोड़कर उन्हें देखने नहीं जा सके, जब उत्सव के बाद गये, तब तक उनकी आवाज बन्द हो चुकी थी। मालवीयजी को दुःख था कि प्रयाग में होते हुए भी वे अपने पिता से अन्तिम समय बात नहीं कर सके। अपने सन्ताप को व्यक्त करते हुए उन्होंने एक दोहा लिखा, जो इस प्रकार है :—

मन पिरात घोरज छुटत, समुझि चूक अरु पाप।

सर्व प्राणिन के प्राण प्रभु, छमहु मिटे संताप ॥

सेवा समिति

सन् १९१२ में मालवीयजी ने अर्धकुम्भ के अवसर पर अपने ज्येष्ठ पुत्र पंडित रामकान्त मालवीय को यात्रियों की सेवा के लिए स्वयंसेवक दल संगठित करने को प्रोत्साहित किया। इस दल ने इस अवसर पर जनता की बहुत सेवा की। सन् १९१४ में भाग के मेले के अवसर पर उसका नाम 'दीन-रक्षक समिति' पड़ गया। यही समिति कुछ समय बाद फरवरी सन् १९१५ में मालवीयजी की अध्यक्षता में 'प्रयाग सेवा समिति' के रूप में संगठित हुई। पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने प्रधान-मन्त्री का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। मालवीयजी की अनुमति से महाभारत में बताया गयी शिवि की प्रार्थना समिति का आदर्श स्वीकार हुआ—

न त्वऽहंकामये राज्य न स्वर्गं ना पुनर्भवम् । ॥

कामये दुःखतप्ताना प्राणिनामार्तिनाशनम् ॥ ॥

'मुझे राज्य, स्वर्ग और मोक्ष की कामना' नहीं है। मैं तो दुःखों से तप्त प्राणियों के दुःख का निवारण करना चाहता हूँ।'

मालवीयजी के प्रोत्साहन और पंडित हृदयनाथ कुंजरू की लगन, क्षमता और सेवा-भावना के कारण 'प्रयाग सेवा समिति' ने प्रयाग के बाहर भी जनता की

वहुत सेवा की, और सन् १९१८ में अखिल भारतीय संस्था का स्वरूप धारण कर लिया। बहुत से स्थानों पर 'प्रयाग सेवा समिति' के नमूने पर सेवा समितियाँ बनायी गयी, और उन्होंने 'अखिल भारतीय सेवा समिति' के नेतृत्व में इससे अपने को सम्बन्धित करते हुए जनता की सेवा की। 'सेवा समिति' ने हरिद्वार और कुम्भ के मेले के अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, अकाल आदि विपत्तियों के अवसर पर जनता की सहायता की। अप्रैल सन् १९१५ में पंडित कुंजरू के नेतृत्व में आयोजित स्वयं-सेवकों को मण्डली में गांधी जी और उनके १९ साथियों ने भी उसमें शामिल होकर हरिद्वार में कुम्भ मेले में स्नानार्थियों की सेवा की। सन् १९१९ में समिति ने अपने मन्त्री श्री बंकटेश नारायण तिवारी की देखरेख में तथा मालवीयजी की प्रेरणा से पंजाब में वहाँ की जनता की बहुत साहस और तत्परता से सेवा की, जबकि वह मार्शल-ला के अत्याचारों से बहुत व्यथित हो गयी थी।

बालचर

सन् १९१८ में कुम्भ में यात्रियों की सेवा के लिए श्री श्रीराम बाजपेयी शाहजहापुर से 'व्वाय स्काउट' का एक दल लाये। मालवीयजी और हृदयनाथजी ने उनके काम को बहुत पसन्द किया, और इन दोनों के अनुरोध पर श्री श्रीराम बाजपेयी प्रयाग में रह कर 'सेवा समिति' के तत्त्वावधान में 'व्वाय स्काउट दल' का गठन और परिशिक्षण करने को राजी हो गये। 'अखिल भारतीय व्वाय स्काउट एसोसियेशन' की स्थापना की गयी। मालवीयजी चीफ स्काउट बने, तथा पंडित हृदयनाथ कुंजरू चीफ स्काउट कमिश्नर नियुक्त हुए। इस संस्था का कार्यक्षेत्र प्रयाग तक सीमित नहीं रहा। उसे धीरे-धीरे देशव्यापी लोकप्रियता प्राप्त हो गयी। बहुत से स्थानों पर इसकी शाखाएँ खुल गयी। इस संस्था से सम्बन्धित स्काउटों ने मेलों और पर्वों के अतिरिक्त सार्वजनिक विपत्तियों के अवसरों पर भी जनता की प्रशंसनीय सेवा की।

मालवीयजी द्वारा संचालित व्वाय स्काउट आन्दोलन वेडिन पावल द्वारा संचालित संस्था से कुछ बातों में विशेष रूप से भिन्न था। वेडिन पावल का चीफ स्काउट एक सरकारी अधिकारी अर्थात् गवर्नर-जनरल था, जबकि एक देशभक्त राजनीतिज्ञ नेता सेवा समिति बालचर का चीफ स्काउट था। जबकि ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान वेडिन पावल के बालचरों की मुख्य वन्दना थी, 'वन्दे मातरम्' का राष्ट्रीय गान सेवा समिति के बालचरों की वन्दना थी। इस तरह जबकि वेडिन पावल के बालचरों को सम्राट् की भक्ति की शपथ लेनी होती थी,

सेवा समिति के बालचर देशभक्ति की शपथ लेते थे। सेवा समिति और बालचर आन्दोलन के गहरे सम्बन्ध के कारण मालवीयजी के बालचरो को समाज की सेवा करने के भी अधिक अवसर आसानी से मिलते रहते थे। सन् १९२१ में वेडिन पावल और मालवीयजी की बातचीत हुई। वेडिन पावल ने स्वीकार किया कि उन्हें यह नहीं कहना या समझना चाहिए कि भारतीय युवक स्काउट बनने की क्षमता नहीं रखते। दोनों में मेल मिलाप की बातें भी हुईं, पर समझौता नहीं हो सका। सेवा समिति स्काउट आन्दोलन अलग से चलता रहा।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू

पंडित हृदयनाथजी ने विद्यार्थी जीवन में ही राष्ट्रसेवा का व्रत लिया, तथा आगरा कालेज में अपनी पढ़ाई समाप्त करने के फौरन बाद वे 'सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी' में शामिल होकर उसके अध्यक्ष गौपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में समाज की सेवा में जुट गये। सन् १९०८ में कुंजरू साहब मालवीयजी के सम्पर्क में आये और शीघ्र ही एक दूसरे में पिता-पुत्र जैसा प्यारा सम्बन्ध स्थापित हो गया। कुंजरू साहब की सज्जनता, क्षमता, देशभक्ति, कर्तव्य-परायणता पर मालवीयजी को पूरा विश्वास था। सन् १९२० में कुंजरू साहब कांग्रेस से अलग होकर लिबरल पार्टी में शामिल हो गये, जबकि मालवीयजी कांग्रेस में बने रहे। पर इसका दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सार्वजनिक कामों में भी बहुत हद तक दोनों का पारस्परिक सहयोग जारी रहा। कुंजरू साहब ने मालवीयजी द्वारा संस्थापित बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के प्रबन्ध में महत्त्वपूर्ण योगदान किया, तथा सन् १९२७-३० में मालवीयजी के नेतृत्व में 'नैशनलिस्ट पार्टी' के सदस्य की हैसियत से केन्द्रीय असेम्बली में बड़ी योग्यता तथा तत्परता के साथ भरपूर काम किया। इसी तरह सन् १९३२ में मालवीयजी द्वारा गठित 'स्वदेशी संघ' में उन्होंने उसके उपाध्यक्ष की हैसियत से, तथा उसकी युक्त प्रान्तीय शाखा के अध्यक्ष के रूप में देश में स्वदेशी भावना को पुष्ट किया, तथा उसके काम को आगे बढ़ाया। मालवीयजी ने भी केन्द्रीय असेम्बली के चुनावों में कुंजरू साहब की भरपूर सहायता की। राष्ट्रसेवा के व्रती हृदयनाथजी का कार्यक्षेत्र बड़ा व्यापक है। 'इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स' तथा 'इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज' बहुत हद तक उन्हीं के प्रयत्नों का फल है। 'सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी' के संचालन का उत्तरदायित्व भी वे उसके अध्यक्ष की हैसियत से १ जनवरी सन् १९३६ से वहन कर रहे हैं। प्रान्तीय कौंसिल, केन्द्रीय

असेम्बली और राज्य सभा की सदस्यता, रेलवे कमिशन की अध्यक्षता, राज्य-पुनर्गठन कमेटी की सदस्यता, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्यता आदि द्वारा भी उन्होंने राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा की है। अखिल भारतीय सेवासमिति और स्काउट आन्दोलन के संचालन में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने 'हरिजन सेवक संघ' की युक्तप्रांतीय शाखा के अध्यक्ष की हैसियत से हरिजनों की भरपूर सेवा की।

हरिद्वार

जब सन् १९१६ में मालवीयजी ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम के एक उत्सव में भाग लेने हरिद्वार गये, तब उन्हें पता चला कि सरकार का नहर विभाग एक बाध बाध कर गंगा के अविच्छिन्न प्रवाह को रोक कर गंगा का अधिकांश जल नहर में डाल देना चाहता है, और सन् १९१४ में नहर के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ था उससे जनता सन्तुष्ट नहीं है। मालवीयजी ने इसका विरोध करना आवश्यक समझा। देहरादून में एक मास रहकर एक मेमोरेण्डम तैयार किया और आन्दोलन किया। कई राजाओं ने भी इसमें दिलचस्पी ली। अन्त में संयुक्त प्रान्त के लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर जेम्स मेस्टन ने एक सभा आयोजित की, जिसमें कई महाराजाओं तथा सरकारी अफसरों के अतिरिक्त सोलह अन्य सज्जनों ने, जिनमें मालवीयजी भी थे, भाग लिया। मालवीयजी ने कहा कि "नहर में अधिक पानी ले लेने में भी उनका विरोध नहीं है, परन्तु वे चाहते हैं कि बाध में एक ऐसा मार्ग बना दिया जाय कि हमारी आवश्यकता के लिए उसमें से निरन्तर पर्याप्त मात्रा में जल आता रहे। धारा विल्कुल प्राकृतिक हो, हर की पैड़ियों पर प्रवाह अविच्छिन्न हो।" मेस्टन साहब के सवाल का उत्तर देते हुए मालवीयजी ने कहा कि "यदि फाटक इसी तरह खुला हो, जैसे खम्भों पर बना हुआ पुल होता है, तो मुझे आपत्ति नहीं है"। सरकार ने सभा का निर्णय स्वीकार कर धारा को अविच्छिन्न रखने का प्रवन्ध कर दिया, धारा प्रवाह के लिए छह फुट चौड़े फाटक का प्रवन्ध कर दिया। मालवीयजी अपने इस काम से बहुत ही सन्तुष्ट थे।^१

पण्डित मोतीलाल नेहरू और मालवीयजी

इलाहाबाद में मालवीयजी के प्रमुख समयस्क ममकालीन पण्डित मोतीलाल नेहरू थे। वे बहुत ही प्रतिभाशाली उच्चकोटि के वकील थे। उनके रहन-सहन

का ढंग और सांस्कृतिक दृष्टिकोण मालवीयजी से बहुत ही भिन्न था। जबकि मालवीयजी का जीवन बहुत ही सादा और सयत्न था, और उस पर प्राचीन परम्पराओं की पूरी छाप थी, वहा मोतीलाल नेहरूजी का जीवन खर्चीला, आनन्दमय तथा प्राचीन मर्यादाओं के प्रति उपेक्षित था। जबकि शाकाहारी मालवीयजी चाय और काफी का भी सेवन नहीं करते थे, मोतीलालजी खाने पीने में काफी आजाद थे। मोतीलालजी ने प्रारम्भ में फारसी का अध्ययन किया था, और फारसी साहित्य से वे काफी अनुप्राणित थे। दूसरी ओर मालवीयजी के जीवन पर संस्कृत वाङ्मय का प्रभाव था। वे आदर्श रूप में संस्कृत के श्लोको को अपने भाषणों में उद्धृत करते रहते थे। मोतीलालजी सामाजिक कुरीतियों के बड़े आलोचक थे, पर हानिकारक प्राचीन रूढ़ियों के विरुद्ध मालवीयजी की समीक्षा काफी नरम और शास्त्र पर आधारित होती थी।

प्रारम्भ में दोनों के राजनीतिक विचार बहुत हद तक एक जैसे थे। दोनों ही उदार लोकतांत्रिक सवैधानिकता के समर्थक, तथा कांग्रेस के प्रति निष्ठावान् थे। मालवीयजी ने सन् १८८६ में ही कांग्रेस का काम करना प्रारम्भ कर दिया था। मोतीलालजी ने सन् १८८८ में कांग्रेस के प्रयाग अधिवेशन में सबसे पहली बार एक डेलिगेट (प्रतिनिधि) के रूप में भाग लिया। उन्होंने सन् १८८९ में और सन् १८९१ में उसकी विषयनिर्धारिणी समिति के सदस्य के रूप में, तथा सन् १८९२ में उसके प्रयाग अधिवेशन की स्वागत-समिति के सदस्य की हैसियत से काम किया। उसके बाद दस वर्ष तक कांग्रेस के अधिवेशनों में उन्होंने कोई भाग नहीं लिया, जबकि मालवीयजी कांग्रेस के कामों और विचार-विमर्श में प्रतिवर्ष योगदान करते ही रहे। मालवीयजी की तरह मोतीलालजी को भी लोकमान्य तिलक और उनके साथियों की उग्रनीति पसन्द नहीं थी। उग्रपंथ और नम्रपथ के विवाद में दोनों ने नम्रपथ का समर्थन किया। पर सम्भवतः सन् १९०७ में उग्रपंथियों के प्रति मोतीलालजी का रुख मालवीयजी की तुलना में अधिक कड़ा था। मोतीलालजी ने दिसम्बर सन् १९०७ में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि डाक्टर रासबिहारी घोष अध्यक्ष चुने जाय। मालवीयजी कांग्रेस में फूट हो जाने पर रोये, और सन् १९०८ में वे दोनों दलों में एक का समर्थन करते रहे।

सन् १९०७ में प्रयाग के नवयुवकों के आग्रह पर प्रयाग में आयोजित 'प्रान्तीय राजनीतिक कान्फ्रेंस' की मोतीलालजी ने अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने गरमदलीय राजनीतिज्ञों की नीति-रीति की कड़ी

आलोचना की। 'वाइकाट' और प्रतिरोध का उपहास उड़ाया, और घोषित किया कि "हम संवैधानिक आन्दोलनकर्ता हैं और हम संस्थापित सत्ता (authority) के माध्यम से सुधारो को सम्पादित करना चाहते हैं।"^१ उन्होंने अपने भाषण में ब्रिटेन के प्रति आभार प्रकट करते हुए स्वीकार किया कि अपनी प्रगति के लिए भारत ब्रिटेन का बहुत आभारी है। उन्होंने कहा : 'ब्रिटेन ने उस सर्व-श्रेष्ठ आहार से हमारा पोषण किया है जो उसकी भाषा, उसका साहित्य, उसका विज्ञान, उसकी कला और सबसे ऊपर उसकी स्वतंत्र संस्थाएँ प्रदान कर सकती थी। हम उस पौष्टिक आहार पर एक शताब्दी तक जीवित रहे और बढ़े। अब हम प्रौढ़ता की आयु पर तेजी से पहुँच रहे हैं। हम बच्चों की उस पोशाक से, जो इंग्लैण्ड से हमें प्राप्त हुई थी, आगे बढ़ निकले हैं।'^२ उन्होंने कहा कि अंग्रेज "भला चाहता है, बुरा चाहना उसका स्वभाव ही नहीं है। उसे स्थिति को समझने में देर लगती है। पर जब वह समस्याओं को स्पष्ट रूप से जान जाता है, वह अपने सुस्पष्ट कर्तव्य को करता है और संसार में कोई शक्ति नहीं, इस देश में या अन्यत्र उसके सम्बन्धी भी नहीं, जो उसे शक्तिशाली संकल्प की सफलता से रोक सकें।'^३

सन् १९०८ में मालवीयजी ने लखनऊ में 'प्रान्तीय राजनीतिक कान्फ्रेंस' के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस की फूट पर दुःख प्रकट किया, पर गरमदल की नीति-रीति या गतिविधि की कोई समीक्षा नहीं की। उन्होंने अंग्रेजों के गुणगान करने के बजाय जनता के दुःख-दर्दों की विस्तार से व्याख्या की, और उसके लिए सरकार की उपेक्षा को तथा उसकी गलत नीति-रीतियों को उत्तरदायी ठहराया। इस भाषण में उन्होंने जनता की गरीबी, भुखमरी, परेशानी, तथा सरकार की दमन नीति को ही जनता के असन्तोष और नवयुवकों के विद्रोह का कारण बताया, और इन कारणों को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने महारानी विक्टोरिया की घोषणा तथा लार्ड मिंटो और लार्ड मार्ले की सदिच्छा पर विश्वास प्रकट करते हुए आशा व्यक्त की कि प्रस्तावित राजनीतिक सुधारों को अधिक उदार बनाया जायगा। उन्होंने राष्ट्रीय माँग के लिए जनमत तैयार करने, प्रत्येक प्रान्त और जिले में कांग्रेस संघटन को कायम करने, तथा जनता की दशा को सुधारने की ओर उपस्थित सज्जनों का ध्यान आकृष्ट किया।

१. नन्दा : नेहरूजी, पृ० ६१।

२. वही, पृ० ६०।

३. वही, पृ० ६०।

सन् १९०९ में मोतीलालजी ने लखनऊ में 'प्रान्तीय सोशल कान्फ्रेंस' के तृतीय सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से सामाजिक कुरीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए पर्दे की प्रथा और जाति-व्यवस्था की विशेषरूप से भर्त्सना की, और मालवीयजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से प्रस्तावित राजनीतिक सुधारों की कड़ी समीक्षा की, तथा 'अभ्युदय' के सम्पादक की हैसियत से प्राचीन धार्मिक सिद्धान्तों और मान्यताओं की प्रगतिशील व्याख्या करके उदार हिन्दू धर्म को स्थापित करने का प्रयत्न किया।

सन् १९०९ में मालवीयजी और मोतीलालजी दोनों ने मिलकर उदार विचारों के प्रसार के निमित्त अंग्रेजी दैनिक 'लीडर' के प्रकाशन का प्रबन्ध किया। सन् १९१० में मोतीलालजी प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल के और मालवीयजी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए, और सन् १९२० तक दोनों ही इन हैसियतों से काम करते रहे। सन् १९११ में मालवीयजी ने वकालत का धंधा छोड़कर सारा समय राष्ट्र की सेवा में लगाने का, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का व्रत धारण किया। मोतीलालजी वकालत करते रहे, पर साथ ही समाज-सेवा के कामों में भी दिलचस्पी लेते रहे। सन् १९१३ से तो कांग्रेस के अधिवेशनों में वे भी बराबर भाग लेते रहे।

सन् १९१९ में मालवीयजी और मोतीलालजी दोनों ने मिलकर पंजाब की जनता की सेवा की। सन् १९१९ के राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में भी दोनों की करीब-करीब एक सी राय थी। सन् १९१८ में जिन बातों की मोतीलालजी ने प्रान्तीय कौंसिल में पुष्टि की, उन्हीं बातों को मालवीयजी ने अपने कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में पुष्ट किया। सन् १९१९ में जो धारणाएँ और बिचार मोतीलालजी ने अपने कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में व्यक्त किये, वे करीब-करीब सभी मालवीयजी के विचारों के अनुकूल थे।

सन् १९२० में दोनों की नीतिरीति में गहरा भेद पैदा हो गया, जिसका पूर्ण विवरण इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में दे दिया गया है। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त है कि राजनीतिक नीतिरीति के सम्बन्ध में गम्भीर मतभेद हो जाने के कारण, बहुत से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों पर मतैक्य होने पर भी, बहुधा विवाद कटुता का रूप धारण कर लेता था। इस कटुता ने सन् १९२६ में विशेष रूप से भयंकर रूप धारण कर लिया था, यद्यपि सन् १९२०-२२ में असहयोग के प्रश्न पर, और सन् १९२३ में 'स्वराज पार्टी' की नीति-रीति को लेकर भी काफी मनमुटाव पैदा हो गया था।

सन् १९२० से लेकर सन् १९३१ तक, जबकि दुर्भाग्यवश मोतीलालजी का निधन हो गया, मोतीलालजी की नीति-रीति मालवीयजी की नीति-रीति की तुलना में अधिक उग्र समझी जाती रही। किस कारण से मोतीलालजी ने अपनी पुरानी नीति को छोड़ा, इसके सम्बन्ध में दो राय हैं। कुछ व्यक्तियों का, जिनमें उनकी जीवनी के लेखक श्री वी० आर० तन्दा भी हैं, मत है कि इस परिवर्तन का मूल कारण उनके सुपुत्र जवाहरलालजी की उग्रता थी। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि डायर और ओडायर के अत्याचारों, तथा भारत सरकार और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों द्वारा पंजाब काण्ड के समर्थन ने मोतीलालजी के राष्ट्रीय अभिमान को ऐसा घक्का लगाया कि फिर अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास बनाये रखना, और उसके आधार पर नरम नीति का अनुसरण करना उनके लिए असम्भव हो गया। सम्भवतः उनकी उग्रता के ये दोनों ही कारण थे। जो भी हो, उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम बारह वर्ष एक वीर राष्ट्रवादी नेता की हैसियत से अपनी दृष्टि में उग्रनीति का अवलम्बन करते हुए शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यशाही से टक्कर लेने में, तथा राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने में समर्पित किये। सन् १९३० में बहुत अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' का नेतृत्व किया और जेल की यातनाएँ सही। यह निःसन्देह उनके वीरत्व का, उनकी देशभक्तिका, स्वराज्य के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा का उच्चतम उदाहरण है।

मालवीयजी ने भी आजीवन हिन्दू धर्म, जाति और भारतीय राष्ट्र की नि स्वार्थ सेवा की। यद्यपि सामाजिक कुरीतियों के सम्बन्ध में उनके विचार बहुत से संमार्ज-सुधारकों की दृष्टि में बहुत ही कम प्रगतिशील थे, पर इस क्षेत्र में भी उन्होंने पुरानी मर्यादाओं पर आस्था रखने वालों को प्रभावित करते हुए समाज की कुछ सेवा अवश्य की। पर राष्ट्रीय जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में उनका योगदान भरपूर था, गांधीजी के अतिरिक्त किसी से कम नहीं, सम्भवतः अधिक था। उन्होंने कभी उग्रवादी होने का दावा नहीं किया, पर सन् १९२४ से सन् १९३० के युग में केन्द्रीय असेम्बली में उनका काम किसी तरह भी मोतीलालजी या किसी दूसरे नेता से कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। कोई भी ऐसा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न नहीं था, जिस पर उन्होंने वैमनस्य या दुराग्रह के कारण मोतीलालजी का साथ देने से इनकार किया हो, या उनके भाषण की तीव्रता या उग्रता मोतीलालजी या किसी दूसरे नेता के भाषणों की तुलना में कम रही हो।

मालवीयजी अवश्य ही मोतोलालजी की तरह ही निर्भीक नेता थे, और यदि उनकी नीतिरीति कतिपय प्रश्नों पर अधिक लोचदार थी, तो उसका कारण उनकी भीखता नहीं, उनकी सूझबूझ थी। सन् १९३० और सन् १९३२ के राष्ट्रीय संघर्षों के जमाने में उन्होंने जिस प्रकार राष्ट्र की सेवा की, तथा सन् १९३१ में लन्दन की गोलमेज कान्फ्रेंस में उन्होंने जिस प्रकार गांधीजी का समर्थन किया, ये उनकी देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र के आदर्शों के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा के उज्ज्वल प्रमाण हैं। मालवीयजी निर्भीक थे, पर साथ ही निरभिमानी थे। उनकी दृढ़ता तितिक्षा और सहयोग की भावना से समन्वित थी। इसलिए वे संघर्ष के युग में भी सहयोग की संभावनाओं पर विचार करते रहते, किसी प्रश्न पर या चुनाव में हारजीत के बाद बीती बात भुला कर आगे की सुध लेते, प्रेम और उत्साह से समाज की सेवा करते।



४. कांग्रेस में कार्य

(१८८६-१९०६)

मालवीयजी के राजनीतिक कार्यों का प्रमुख मंच कांग्रेस ही था । वास्तव में जैसा कि श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने बताया, "प्रारम्भ में बीस वर्ष तो संयुक्त प्रान्त में मालवीयजी ने ही गंगा प्रसाद वर्माजी के संयोग से कांग्रेस का झण्डा फहराए रखा ।" कांग्रेस के मंच से मालवीयजी ने राष्ट्र के हितों को पुष्ट किया, सरकार की दमन-नीति का विरोध किया, तथा राजनीतिक सुधारों की, जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की, विधान कौंसिलों के अधिकारों के विस्तार की, एवं सेना में भारतीयों को उच्च-स्तरीय कमीशन दिये जाने की मांग की । उन्होंने देश की दयनीय दशा और जनता के कष्टों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रशासकीय खर्चों को कम करना, शिल्प विद्या की शिक्षा के विस्तार का प्रबन्ध करना, भारत में भी सिविल सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षा का प्रबन्ध करना, तथा योग्य भारतीयों को उच्चकोटि के प्रशासकीय पदों पर नियुक्त करना जरूरी बताया । उन्होंने यह भी मांग की कि भारत की सीमा के बाहर आयोजित युद्धों का खर्चा ब्रिटेन स्वयं बर्दाश्त करे, मालगुजारी का स्थायी बन्दोबस्त किया जाय, किसानों के लगान में कमी की जाय, किसानों के पट्टों की मियाद बढ़ा दी जाय, किसानों को अनुचित लगान की वृद्धि से और जमींदारों द्वारा मनमानी बेदखली से सुरक्षित किया जाय । उन्होंने लार्ड कर्जन के विश्वविद्यालय-विधेयक का विरोध करते हुए उच्चस्तरीय शिक्षा के प्रबन्ध में सरकारी अफसरों के हस्तक्षेप की वृद्धि की निन्दा की । उन्होंने बंगभंग की कड़ी आलोचना करते हुए उसके विरुद्ध बंगाल कांग्रेस कमेटी की बहिष्कार नीति का समर्थन किया ।

इस काल (१८८५-१९०६) में कांग्रेस के सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से निश्चित होते और पास किये जाते थे, और बहिष्कार को छोड़ कर यह सभी बातें सम्पूर्ण कांग्रेस स्वीकार करती थी । बहिष्कार के सम्बन्ध में मतभेद जरूर था । जबकि कुछ नेता इसके वित्कुल विरोधी थे, कुछ नवयुवक इसे देशव्यापी

बना देना चाहते थे। पर मालवीयजी प्रभृति काँग्रेसी कार्यकर्त्ता उसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे।

मृदुभाषी मालवीयजी के भाषणों की भाषा सदा सन्तुलित होती थी। पर उनकी आलोचना स्पष्ट, युक्तियुक्त और कभी कभी काफी कड़ी होती थी। सन् १८८९ में उप-भारतमन्त्री सर जान गोसट के इस विचार की कि “खर्चा बढ़ा है, बढ़ना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए” आलोचना करते हुए मालवीयजी ने कहा कि इस समय जबकि जनता की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, खर्च की वृद्धि केवल अनुचित ही नहीं बल्कि निश्चय ही “पापमय” है।^१

सन् १८९२ में उन्होंने कहा कि जबकि प्रत्येक भारतीय की औसत वार्षिक आमदनी सरकारी वक्तव्य के अनुसार सत्ताईस रुपया और दादा भाई नौरोजी और डिगवी के हिसाब से इक्कीस रुपया है, जनता की गरीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। देश की बढ़ती हुई गरीबी तथा उसके कारणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग दस करोड़ भारतीयों की कमाई प्रतिवर्ष अंग्रेजी अफसरो के वेतन और उनकी पेंशन के रूप में इंग्लैंड चली जाती है, और इसलिए ऊँचे पदों पर भारतीयों को भरती न करने की सरकार की नीति केवल अन्यायपूर्ण ही नहीं, बल्कि आत्मघाती है।^२ उन्होंने कहा: “सरकार जनता के बिना जीवित नहीं रह सकती,” यदि “जनता अधिक निर्धन होती जाती है, तब सरकार कहीं भी नहीं है, कम से कम ‘सरकार’ कहलाने योग्य तो वह नहीं ही है”।^३

सन् १८९३ में उन्होंने बड़े सन्तप्त हृदय से कहा कि जबकि लगभग पाँच करोड़ भारतीय भुखमरी जैसा दुःखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और लाखों प्रतिवर्ष भुखमरी के शिकार होते रहते हैं, सरकार जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व का अनुभव ही नहीं कर रही है। उसके शासन में अन्याय, दमन और कष्ट फैला हुआ है।^४

सन् १८९५ में सरकार के बढ़ते हुए खर्च की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने भुखमरी के कारण लाखों मौतों के लिए भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार और इंग्लैंड की जनता को, उनके “अयोग्य शासन और अत्यधिक करारोपण”

१ आनरेबुल पण्डित मदन मोहन मालवीय . लाइफ एंड स्पीचेज , गणेशन एंड कं०, मद्रास, सेकिड एडिशन, १९१८, पृ० २०५।

२ वही, पृ० २१८।

३ वही, पृ० २१८।

४. वही, पृ० २२३।

को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने कहा, “इंग्लैंड की जनता अवश्य ही उत्तरदायी है” क्योंकि “वह जो दमन होने देता है, अपराध में शरीक है।”^१

उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटेन की जनता जिसने अपने ऊपर भारत के शासन के उत्तरदायित्व का भार विधिवत् ग्रहण किया है ऐसी मौतें होने देती हैं जिन्हें रोका जा सकता है तो वे अवश्य ही ईश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं। उन्होंने कहा—“क्या इस महाभियोग के बाद उनका यह कर्तव्य नहीं है कि शासन की उन नीतियों की जिन पर सार्वजनिक खर्च निर्धारित है पूरी तौर पर खुली जाँच करावें ?”^२

सन् १८९६ में उन्होंने देश की निर्धनता तथा अकाल की स्थिति की आलोचना करते हुए कहा : “यदि सरकार ने भारत में कला-कौशल तथा उद्योगधन्धों को प्रोत्साहित और पुष्ट किया होता और प्रशासन के कार्यों में देशी योग्यता और शक्ति का प्रयोग किया होता, तो देश की दशा बुरी न होती, सूखे की स्थिति का अधिक आसानी से सामना किया जा सकता था।”^३

नामजदगी का विरोध

सन् १८९० में मालवीयजी ने यह माँग करते हुए कि विधान-सभाओं के कम से कम आधे गैरसरकारी सदस्य जनता द्वारा चुने जायें, नामजदगी की प्रथा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि “सरकार ने अधिकतर ऐसे सज्जनों को सदस्यता के लिए चुना है जो जनता के अधिकारों और हितों को निर्भीकता से प्रतिपादन करने में अयोग्य सिद्ध हुए हैं, जिनकी कौंसिल में उपस्थिति ने जनता की दुर्दशाओं को बढ़ाने में मदद की है।”^४ उन्होंने कहा : “उन सज्जनों की कौंसिल का सदस्य बनाने से क्या लाभ है जो जनता के वित्कुल संपर्क में न हों, और जो उनकी वास्तविक दशा और आवश्यकताओं से अनभिज्ञ होने के कारण उन कार्यवाहियों का, जो जनता के कष्टों और असन्तोष को बढ़ाती हैं, असावधानी से समर्थन करके उनके प्रति सहानुभूति के झूर अभाव को प्रकट करते हैं।”^५ ऐसे “गैरसरकारी सदस्यों के होने से तो किसी गैरसरकारी सदस्य का न होना ही अच्छा है।”^६

१. वही, पृ० २६१-२६२।

३. वही, पृ० २३२-२३३।

५. वही, पृ० २४।

२. वही, पृ० २६२।

४. वही, पृ० २४।

६. वही, पृ० २४।

पब्लिक सर्विस

सन् १८९२ में पब्लिक सर्विस कमीशन की संस्तुतियो, और उन पर लिये गये भारत सरकार के निर्णयो की आलोचना करते हुए मालवीयजी ने कहा : “यद्यपि पार्लियामेंट ने कानूनो द्वारा और महारानी विक्टोरिया ने अपनी शाही घोषणा द्वारा यह निर्धारित कर दिया है कि भारतनिवासी हर उस स्थान पर बेरोकटोक भरती किये जायेंगे जिसके लिए उनमें पर्याप्त योग्यता और न्यायनिष्ठा हो, पर वास्तविक व्यवहार में जानबूझ कर, और निर्लज्जता के साथ उनके दावो को अवहेलना की जाती है, और पारिश्रमिक के उन स्थानो पर जिन्हें भरने की, अपनी योग्यता और चरित्र से, भारतीय पूरी क्षमता रखते हैं, यूरोपियन नियुक्त कर दिये जाते हैं।”^१ उन्होने कहा कि सन् १८८९-१८९० में दस हजार से बीस हजार रुपये वार्षिक वेतन पानेवालो में ७१३ यूरोपियन, ८ यूरोशियन और ४५ भारतीय थे, और बीस हजार से लेकर तीस हजार रुपये वार्षिक वेतन पानेवालो में ३०० यूरोपियन, २ यूरोशियन और ४ भारतीय थे। इससे यह प्रत्यक्ष है कि सब अच्छे पदो का बड़ा भाग यूरोपियनो के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जबकि इस देश के बच्चे छोटे वेतन की छोटी नौकरियाँ ही पाते हैं। सब विभागो में एक हजार या उससे अधिक वेतनवालो में यूरोपियन १३,१७८, यूरोशियन ३,३०९ और हिन्दुस्तानी १२, ५५४ हैं। पर जबकि कुल मिलाकर यूरोपियनो का वेतन लगभग ९ करोड़ रुपया, यूरोशियनो का लगभग ७३ लाख रुपया है, हिन्दुस्तानियो का ढाई करोड़ रुपया है। हिन्दुस्तानियो को पेंशन में ६० लाख रुपया और यूरोपियनो को पेंशन में ३७ लाख पाँड (साढे पाँच करोड़ रुपया) मिलता है। इस कारण हिन्दुस्तान का करोडो रुपया प्रतिवर्ष ब्रिटेन को पेंशन और वेतन के रूप में खिंचा चला जा रहा है।^२ अतः हिन्दुस्तान गरीब होता जा रहा है। “इस दयनीय दशा को सुधारने के लिए जरूरी है कि प्रशासन में बहुत ही खर्चीली विदेशी एजेन्सी के स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक सस्ती देशी योग्यता और श्रम का प्रयोग किया जाय।”^३

उन्होने कहा कि अपने देश में नौकरी करने की क्षमता सिद्ध करने के निमित्त परीक्षा देने के लिए देश के बच्चो को हजारो मील जाने को बाध्य करना “सरासर अन्याय” है। कही भी कोई दूसरे लोग इस “भयंकर असुविधा” से आक्रान्त नहीं हैं। फिर हमी इसके लिए क्यो विवश किये जायें, क्योकि हम

१. वही, पृ० ४८६।

२. वही, पृ० ४८७-४८८।

३. वही, पृ० ४९०।

इंग्लैंड जैसी बड़ी शक्ति की प्रजा हैं ?' उन्होंने कहा कि सच बात तो यह है कि जो लोग हमारे देश में नौकरी करना चाहते हैं, वे यहाँ आकर परीक्षा में बैठकर अपनी योग्यता सिद्ध करें। पर यदि सरकार ऐसा नियम बनाने को तैयार न हो, तो उसे इंग्लैंड के साथ-साथ भारत में भी सिविल सर्विस में भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रवन्ध करना ही चाहिये। अन्त में मालवीयजी ने कहा कि "भारतीयों का दावा न्याय पर आश्रित है। वे न्याय के प्रार्थी हैं, अनुग्रह के नहीं।"^१

विधान सभा

कांग्रेस के अधिकांश प्रस्तावों के प्रति सरकार उपेक्षित रही। पर उसने सन् १८८६ में, सम्भवतः कांग्रेस के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, 'युक्त प्रान्त' में, जो इस समय 'उत्तर प्रदेश' के नाम से प्रसिद्ध है और उस समय आगगा और अवध के संयुक्त प्रान्तों के नाम से विख्यात था, विधान कौंसिल की व्यवस्था कर दी।

सन् १८९० में चार्ल्स ब्रेडला ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की कमन्स सभा में कांग्रेस के सन् १८८९ के प्रस्ताव के आधार पर कौंसिलों की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत किया, पर ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की उपेक्षा के कारण वह पारित नहीं हो सका।

सन् १८९२ का कौंसिल अधिनियम

सन् १८९२ में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की संस्तुति पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नया उडियन कौंसिल एक्ट पारित किया। इस अधिनियम द्वारा कौंसिलों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी, तथा गैरसरकारी सदस्यों में से तत्काल आधे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर मनोनीत होने लगे। कौंसिल के सदस्यों को सार्वजनिक मामलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने का, तथा बजट पर अपने विचार प्रकट करते हुए प्रगामन का समाचोचना करने का अधिकार प्राप्त हो गया। राष्ट्र की प्रगति में इन कौंसिलों का योगदान सन्तोषप्रद नहीं था। सरकार निर्वाचित सदस्यों के विचारों की उपेक्षा करते हुए अपनी मनमानी करती थी। वास्तव में कौंसिलों के सरकारी सदस्य, जिनकी संख्या सर्वाधिक थी, इस तरह ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के आदेशों से बंधे हुए थे कि यदि वे भारतीयों के किसी आदेश को भारत के हित के प्रतिकूल भी समझें, तब भी उन्हें उपाय

समर्थन करना होता था और उसके पक्ष में वोट देकर उसे कौंसिल से पास कराना होता था ।

इन सब सम्भावनाओं को ध्यान मे रखकर कांग्रेस ने सन् १८९३ में ही नये वैधानिक नियमों को दोषपूर्ण बताते हुए अनुरोध किया कि इन नियमों को अधिक उदार बनाया जाय, ताकि सन् १८९२ का इंडियन कौंसिल एक्ट देश की जरूरतों को ठीक तौर पर पूरा कर सके । सन् १८९४ में इसी प्रकार के एक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मालवीयजी ने सस्तुति की कि जनता के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ायी जाय, और प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति का विस्तार किया जाय । उन्होंने दो तीन उदाहरण देकर बताया कि ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों का विरोध करके उनमें भारत के हितों की रक्षा जनता के प्रतिनिधि ही कर सकते हैं, और इसलिए उनकी संख्या और अधिकार बढ़ाना आवश्यक है ।^१

सन् १८९७ में कांग्रेस ने अपनी पुरानी मांगों को दुहराते हुए मांग की कि (१) कौंसिलों के गैर-सरकारी सदस्य अधिक प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि हों, और उन्हें बजट में संशोधन पेश करने का तथा मत देने का अधिकार हो, (२) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों की सस्तुति पर प्रतिष्ठित और अनुभवी भारतीय पर्याप्त संख्या में भारतमन्त्री की कौंसिल के सदस्य नियुक्त किये जायें, (३) भारत की आर्थिक दशा की जाँच के लिए प्रतिवर्ष ब्रिटेन की कामन्स सभा के सदस्यों की एक निर्वाचित कमेटी गठित की जाय, (४) सैनिक तथा अन्य अनुत्पादक खर्चों में कमी की जाय, तथा जनता के कल्याण और उत्कर्ष के लिए अधिक धन व्यय किया जाय, (५) सार्वजनिक नौकरियों के उच्च पदों पर जहाँ तक सम्भव हो अंग्रेज कर्मचारियों के स्थान पर, अधिक वचत तथा अधिक सुयोग्य शासन की दृष्टि से, भारतीय कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जायें, तथा (६) सीमा के परे के युद्धों के व्यय का अधिकांश ब्रिटिश राजकोष वहन करे ।^२

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मालवीयजी ने निराशाजनक स्थिति का विस्तार से विश्लेषण किया और कहा कि भारतीय व्यय पर कन्ट्रोल बहुत ही 'दोषपूर्ण' है । जबकि टैक्सों और कर्जों का बोझ बढ़ता चला जाता है, जनता की आमदनी नहीं बढ़ रही है, देशहित की दृष्टि से सरकार की आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण नितान्त आवश्यक है । उन्होंने प्रस्ताव के विभिन्न अंगों के औचित्य की व्याख्या

१ वही, पृ० ३२-३३ ।

२. वही, पृ० २६४-२६५ ।

करते हुए आगा व्यक्त की कि यदि सरकार कांग्रेस के इन सुझावों को स्वीकार करते हुए महारानी विक्टोरिया की घोषणा में निहित उद्देश्यों और नीतियों का अनुसरण करेगी तो शासक और प्रजा में सौहार्द की वृद्धि होगी, तथा अविश्वास और नैराश्य की भावनाएँ, जो इस समय सरकार और शिक्षित भारतीयों को परेशान कर रही हैं, दूर हो जायेंगी।^१

सन् १९०४ में कांग्रेस ने अपनी कतिपय मवैधानिक मांगों को अर्थात् केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान कौंसिलों के विस्तार तथा भारतमन्त्री की कौंसिल में भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति से संबंधित मांगों को दुहराते हुए यह भी मांग की कि प्रत्येक प्रान्त और प्रदेश को ब्रिटेन की कामन्स सभा के लिए दो सदस्य चुनने का अधिकार दिया जाय, और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनोनीत भारतीय प्रतिनिधि केन्द्रीय तथा बम्बई और गड्राम की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य नियुक्त किये जायें।

इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मालवीयजी ने कहा कि ब्रिटेन की कामन्स सभा के सदस्यों को भारत की समस्याओं पर विचार करने का समय ही नहीं मिलता, और इसलिए शासन को भारत-हितकारी बनाने के लिए कामन्स सभा में कतिपय योग्य और अनुभवी भारतीय प्रतिनिधियों का सहयोग अवश्य लाभदायक सिद्ध होगा।^२

उन्होंने कहा कि हम मौजूदा विधान कौंसिलों को खिलवाट नहीं समझते। उन्होंने अच्छा गम किया है, वे सफ़्त सिद्ध हुई है। निर्वाचित सदस्यों ने अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है।^३ पर यदि इन कौंसिलों का कुछ विस्तार हो जाय और इनके अधिकारों में कुछ वृद्धि कर दी जाय तो वे अधिक लाभदायक हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को "क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं चाहती," वह तो केवल यह चाहती है कि सन्देश की भावना के बजाय उदार विश्वास की भावना में काम किया जाय और रंगभेद को भुनाकर महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रतिपादित "मिहान्तों पर अमल किया जाय।"^४ उन्होंने अन्त में कहा कि यदि ऐसा किया गया तो "हमारी गवर्नमेंटें रात्म हो जायेंगी", और जिन सुधारों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वे हमें शीघ्र प्रदान कर दिये जायेंगे।^५

१. यही, पृ० २६६-२८२।

३. यही, पृ ४५।

५. यही, पृ० ५२।

२. यही, पृ० ४२-४३।

४. यही, पृ० ४९।

इस तरह मालवीयजी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता सरकार की निरंकुशता को कम करके निरंकुश शासन के स्थान पर धीरे-धीरे प्रतिनिधि शासन प्रतिष्ठित करना चाहते थे। वे अनुत्पादक कार्यों में व्यय को घटाकर, सरकारी खर्च पर जनता के प्रतिनिधियों का समुचित नियंत्रण स्थापित करके राजकोष को अधिक से अधिक जनहितकारी कामों में लगाना चाहते थे। वे रंगभेद, असन्तोष, अविश्वास और वैमनस्य की भावनाओं के स्थान पर पारस्परिक सहयोग और विश्वास की भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहते थे।

पर गवर्नर-जनरल लार्ड लैसडाउन, लार्ड एलगिन और लार्ड कर्जन और उनके सहयोगियों को कांग्रेस की यह नीति पसन्द नहीं थी। उन्होंने अपने अधिकार-काल में विश्वास तथा सद्भावना को बढ़ाने के बजाय अपनी नीतिरीति से अविश्वास और कटुता की वृद्धि की। लार्ड कर्जन ने शिक्षित समाज के प्रति खुला वैमनस्य प्रकट किया, तथा हिन्दुस्तानियों पर चरित्रहीनता का दोषारोपण किया। उन्होंने राजनीतिक अपराधों के लिए दण्डविधान अधिक कड़ा कर दिया, तथा सिविल मामलों में भी सरकारी बातों को प्रकट करने पर आफिशियल सीक्रेट एक्ट (राजकीय रहस्य अधिनियम) लागू कर दिया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के अधिकार अधिक विस्तृत कर दिये, तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट में हिन्दुस्तानियों की संख्या घटा कर सरकारी अफसरों की प्रधानता कर दी। उन्होंने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर भी सरकारी नियन्त्रण अधिक कड़ा कर दिया, कलकत्ता कारपोरेशन में गैरसरकारी सदस्यों की संख्या घटाकर सरकारी अफसरों की संख्या बढ़ा दी। उन्होंने ऊँचे पदों के लिए रंगभेद को अधिक स्पष्ट कर दिया। अन्त में बंगाल को दो हिस्सों में बाँट कर उन्होंने अपनी निरंकुशता तथा अन्याय का सबसे बड़ा सबूत दिया।

बंगभंग

सन् १९०३ में सर हर्बर्ट रिसले ने घोषित किया कि सरकार बंगाल को दो भागों में बाँट देना चाहती है। इस घोषणा का सब वर्गों और सम्प्रदायों के हिन्दुस्तानियों ने कड़ा विरोध किया। इस पर लार्ड कर्जन ने अपनी योजना को साम्प्रदायिक रंग में रंग दिया। उन्होंने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों से कहा कि वे बंगभंग द्वारा शासन का बोझ ही हलका नहीं करना चाहते, बल्कि एक ऐसे प्रान्त का निर्माण भी करना चाहते हैं जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों। लार्ड कर्जन की यह चाल किसी हद तक सफल हुई। बहुत से वे मुसलमान जो पहले विभाजन का विरोध करते थे अब इसका समर्थन करने लगे। १९ जुलाई

सन् १९०४ को वगभंग पर सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, और १० सितम्बर को भारत-मन्त्री की स्वीकृति से घोषित किया गया कि १६ अक्टूबर सन् १९०४ को बंगाल प्रान्त दो प्रान्तों में विभाजित कर दिया जायगा। यह विभाजन इस तरह किया गया कि बंगला भाषा-भाषी क्षेत्र दो भागों में बँट गया।

बंगभंग का विरोध

बंगाल की जनता के साथ-साथ कांग्रेस भी वगभंग की योजना के विरुद्ध थी। सन् १९०३ और सन् १९०४ में कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशनों में इसका कड़ा विरोध किया। लार्ड कर्जन ने यह कहकर कि कांग्रेस उत्तेजना फैलाती है, उसके डेपुटेशन से मिलने से इनकार कर दिया। सन् १९०५ में कांग्रेस की ओर से श्री गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय इंग्लैंड गये। पर वहाँ पर भी उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। कजरवेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी ने बंगाल की परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

वगभंग ने बंगाल की जनता को विह्वल कर दिया। उसने इसके विरोध में दो वर्षों के अन्दर (दिसम्बर १९०३—अक्टूबर १९०५) लगभग २,००० सभाएँ की, बहुत-सी प्रमुख मार्गजनिक सस्थाओं ने मेमोरियल पेश किये। जुलाई १९०५ को पूर्वी बंगाल के लोगो ने ७०,००० हस्ताक्षरों से भारत सरकार को प्रार्थनापत्र भेजा। करीब-करीब सभी प्रमुख समाचार पत्रों, राजनीतिज्ञों तथा संचान्त व्यक्तियों ने किसी-न-किसी रूप में शोक प्रकट किया। समाचार पत्रों की आलोचना बहुत कड़ी थी, नवयुवकों की उद्विग्नता का ठिकाना ही नहीं था।

वगभंग ने अंग्रेजों की तथाकथित न्यायप्रियता का भंडा फोड़ दिया। नवयुवकों को सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही से न्याय की आशा बेकार है, तर्क और विनय के बजाय शक्ति का शक्ति से मुकाबला करना होगा। इसी समय यूरोपियों ने इटली को और जापान ने रूस को पराजित किया। इन विजयों ने एशिया में नये विद्रोह का संचार किया, और नवयुवकों की भावनाओं को अधिक तीव्र बना दिया। पुराने कांग्रेसी नेताओं का गवैयामिकता की नीतिरोति का समर्थन करना उनके लिए असम्भव हो गया। कुछ नायकों ने अराजकता के हिंसात्मक मार्ग का अनुसरण ठीक समझा। कुछ का अहिंसक और गवियनय प्रतिरोध का मार्ग ठीक जँचा।

कांग्रेस गरमदल और नरमदल, दो भागों में विभाजित हो गयी। गरमदल के नेताओं ने 'स्वराज्य' को अपना ध्येय उद्घोषित किया, तथा जनजागृति, जनान्दोलन और जनसंगठन के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार तथा सविनय प्रतिरोध (पैसिव रजिस्टेंस) पर जोर दिया। उनका विश्वास था कि कोई बाहरी शक्ति जनता के सहयोग के बिना जनता पर शासन नहीं कर सकती। 'जनता सरकार का बहिष्कार कर अपने ध्येय की सिद्धि कर सकती है। कांग्रेस का पुराना नेतृत्व स्वदेशी का सिद्धान्त स्वीकार करता था, पर बहिष्कार और सविनय प्रतिरोध के वजाय पुराने संवैधानिक ढंग पर चलना ही उचित समझता था। पुराने नेताओं को राष्ट्रीय शिक्षा की बात भी अव्यावहारिक दिखायी देती थी। वे उत्तरदायी शासन की अपनी माँग को भी 'स्वराज्य' शब्द से सम्बोधित करने को तैयार नहीं थे।

बनारस अधिवेशन और गोखले

दिसम्बर सन् १९०५ में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। उसकी विषय समिति में इतना मतभेद प्रकट हुआ कि कांग्रेस टूटती नजर आयी। पर अन्त में समझौता हो गया। बंगाल के प्रतिनिधियों को इस बात पर राजी कर लिया गया कि जब युवराज और युवराज्ञी के स्वागत का प्रस्ताव पेश होने लगे तो बंगाल के प्रतिनिधि खुले अधिवेशन में न जायें, और नरम दल के प्रतिनिधियों को राजी किया गया कि वे गरम दल वालों के बहिष्कार को किसी अंश में स्वीकार कर लें।^१ दमन के विरोध में जो प्रस्ताव विषय समिति में तैयार किया गया उसमें यह बात जोड़ दी गयी कि 'जनता के तीव्र विरोध और अपील की उपेक्षा करके वगभंग के निर्णय में भारत सरकार ने जो आग्रह किया उस काम की ओर ब्रिटिश जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विदेशी माल का बहिष्कार ही संभवतः बंगाल की जनता के पास एकमात्र संवैधानिक और कार्यसाधक उपाय रह गया था'। इस समझौते में मालवीयजी और लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा हाथ था। कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल ने सन् १९०५ के अधिवेशन की रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि मालवीयजी ने विषय समिति में स्वदेशी और बहिष्कार के तात्त्विक भेद का स्पष्टीकरण करके तथा स्वदेशी की व्यापकता तथा बंगाल की स्थिति में बहिष्कार की आवश्यकता प्रतिपादित करके इन प्रश्नों पर विषय समिति में मतैक्य कराने में बड़ा योगदान किया।

दमन के विरोध में प्रस्ताव उपस्थित करते हुए मालवीयजी ने काफी विस्तार के साथ बताया कि संवैधानिक सरकार में अपनी कठिनाइयों को सरकार के समक्ष पेश करने के लिए जो कुछ किया जा सकता था, वह सब बंगाल की जनता ने किया। उन्होंने एक आवेदनपत्र पार्लियामेंट को भी भेजा, जिस पर विचार भी हुआ, पर उसका भी कोई फल नहीं निकला। जबकि जनता बहुत विह्वल थी और उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तब भी उसने शान्ति बनाये रखी, कोई आपत्तिजनक काम नहीं किया। यह एक बड़ी बात थी। इस पर भी बंगाल की जनता को दोषी ठहराना, उसकी बात न सुनना, उसकी परेशानियों पर ध्यान न देना उसके साथ 'घोर अन्याय' है। इस अन्याय का विरोध करना सारे देश का कर्तव्य है। बंगाल की मुसीबत के प्रति उदासीन रहना अनुचित होगा।^१

मालवीयजी ने स्वीकार किया कि अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों में निरर्थक तनाव पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं है।^२ यदि सरकार चाहती है कि 'वाइकाट' के कारण जो तनाव की भावना पैदा हो गयी है वह दूर हो, तो इसका उपाय उसके पास है। वह बंगाल का विभाजन खत्म करे। बंगभंग के खत्म होते ही वाइकाट भी आपसे आप खत्म हो जायगा। उन्होंने कहा कि वाइकाट और स्वदेशी में मौलिक तात्त्विक भेद है। स्वदेशी आन्दोलन बहुत पुराना है, लगभग तीस वर्ष से चल रहा है और आगे भी चलना रहेगा। पर वाइकाट उस समय खत्म हो जायगा जब कि वह बात दूर हो जायगी जिसके कारण वह आरम्भ किया गया है। अगर यह जारी रहता है तो इसका उत्तरदायित्व जनता पर नहीं, उन अधिकारियों पर है जिन्होंने उस स्थिति को पैदा किया है जिसके कारण उसे बंगाल में वाइकाट शुरू करना पड़ा। मालवीयजी ने कहा कि कांग्रेस वाइकाट को देशव्यापी बनाना नहीं चाहती, पर जिन परिस्थितियों में वह बंगाल में प्रारम्भ किया गया, उसे ध्यान में रखते हुए वह बंगाल के वाइकाट आन्दोलन को अनिवार्य समझती है, और सरकार ने जो दमनचक्र चला रखा है उसका विरोध करती है।^३ प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया।

सन् १९०६ में स्थिति ने अधिक भयंकर रूप धारण कर लिया। पूर्वी बंगाल की सरकार ने दमन को तेज कर दिया। उसने 'बन्देमातरम्' के नारे को भी गैर-कानूनी घोषित करते हुए बारिसाल में बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस को भंग कर

१. अनरेविल पंडित मदनमोहन मालवीय : लाइफ एण्ड रीपोज़, पृ० ५३३-५३५।

२. वही, पृ० ५३५।

३. वही, पृ० ५३९-५४०।

दिया, और बंगभंग की विरोधी हिन्दू जनता पर, विशेषतः नवयुवकों पर अत्याचार शुरू कर दिये। कुछ उत्तेजित नवयुवकों ने आतंक का उत्तर आतंक से देने का इरादा किया।

लार्ड मार्ले से राजनीतिक सुधारों की घोषणा द्वारा असन्तोष को शान्त करने की आशा की जा सकती थी, पर उन्होंने अगस्त सन् १९०६ में जो प्रारूप प्रकाशित किया, वह बहुत ही निराशाजनक था। परिस्थिति को शान्त करने के बजाय वाइसराय मिंटो ने उसे गहरे साम्प्रदायिक रंग में रंगकर अधिक गम्भीर बना दिया। उन्होंने मुसलमानों के शिष्ट-मंडल को आश्वासन दिया कि भावी सुधार योजना में उनके राजनीतिक महत्त्व को ध्यान में रखा जायगा। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन पद्धति और सुरक्षित स्थानों की योजना बनानी शुरू कर दी।

इस तरह लार्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति और पूर्वी बंगाल की सरकार के दमन तथा लार्ड मार्ले की सकीर्णता और लार्ड मिंटो के कुचक्र ने विषम स्थिति पैदा कर दी। वैमनस्य, दमन और विद्रोह के वातावरण में सद्भावना काफूर होने लगी।

कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन

कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, इसके सम्बन्ध में स्वागत समिति तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी विवाद खड़ा हो गया। गरमदलीय नवयुवक चाहते थे कि लोकमान्य तिलक को अध्यक्ष बनाया जाय। कांग्रेस का पुराना नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं था। इस विषम परिस्थिति में सर्वश्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और भूपेन्द्रनाथ वसु ने सोचा कि दादाभाई नौरोजी को अध्यक्षता के लिए निर्मंत्रित किया जाय। ८१ वर्ष की आयु में वे इस भार को वहन करने को तैयार हो गये। इस पर तिलक ने अपना नाम वापस ले लिया।

दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 'स्वराज्य' को भारत का राजनीतिक लक्ष्य घोषित करते हुए कहा कि हम अपने देश में ब्रिटेन और स्वशासित उपनिवेशों की तरह का स्वायत्त शासन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह ब्रिटेन और उपनिवेशों में करारोपण (टेक्सेशन), विधि निर्माण (लैजिस्लेशन) तथा करो को खर्च करने की सब शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में है, उसी तरह वह हिन्दुस्तान में भी होनी चाहिये। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ब्रिटिश सरकार 'हिन्दुस्तान के लिए स्वायत्तशासन की नीति अपनायेगी तथा इस लक्ष्य की ओर बढ़ने की फौरन शुरुआत की जायगी। उन्होंने वाइकाट के प्रश्न

पर चुप रहते हुए स्वदेशी का समर्थन लिया, जनजागृति और जनान्दोलन को आवश्यकता पर जोर दिया, और बगला भापा-भापी क्षेत्रों को एक प्रान्त में गठित करने की मांग की। अन्त में उन्होंने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे संगठित रहकर स्वायत्तशासन प्राप्त करें, ताकि दसों लाख जो इस समय गरीबी, अकाल, और प्लेग से मर रहे हैं, और करोड़ों जो अपर्याप्त जीविका से भूखे मर रहे हैं, उनकी रक्षा की जा सके और हिन्दुस्तान फिर एक बार ससार के बड़े और सुसंस्कृत देशों में अपना पुराना स्थान प्राप्त कर सके।

दादाभाई नौरोजी के प्रयत्न से दोनों दलों का तनाव बहुत हद तक शान्त हुआ। गरमदल के समर्थक चाहते थे कि (१) स्वदेशी (२) वहिष्कार और (३) राष्ट्रीय शिक्षा पर कामगैर स्पष्ट रूप में प्रस्ताव स्वीकार करें। इन तीनों विषयों में से राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव बिना किसी कठिनाई के स्वीकार हो गया। पर स्वदेशी तथा वहिष्कार के प्रश्न पर विरोध का तूफान खड़ा हो गया। अन्त में निश्चय हुआ कि ब्रिटिश उपनिवेशों को जो स्वायत्तशासन प्राप्त है, वही हिन्दुस्तान को मिलना चाहिये, और उसका श्रीगणेश कतिपय निश्चित सुधारों के रूप में होना चाहिये, जिन्हें तत्काल लागू किया जाय। दूसरे प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय हुआ कि साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा टेक्निकल (प्रावधिक) शिक्षा राष्ट्रीय नीति पर राष्ट्र की देखरेख में होनी चाहिये। स्वदेशी आन्दोलन का हार्दिक स्वागत करते हुए जनता से अनुरोध किया गया कि स्वदेशी की गफनता के लिए तत्परता से काम किया जाय, देशी उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रयत्न किया जाय, और यदि कुछ त्याग भी करना पड़े तो भी विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाय। यह भी निश्चय हुआ कि यह देराले हुए कि यहाँ की जनता का शासन में कोई हाथ नहीं है और उसके आन्दोलनों पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती बगल का वहिष्कार आन्दोलन, जो विभाजन के विरोध में शुरू किया गया, न्यायसंगत था और है।

मालवीयजी ने, जो समझौते के पक्ष में थे और दादा भाई नौरोजी की धारणाओं से पूरी तौर पर सहमत थे, तथा जिन्होंने उन्हें समझौता कराने में सहायता की थी, कांग्रेस के खुले अधिवेशन में स्वदेशी आन्दोलन तथा बाइकाट आन्दोलन से सम्बन्धित प्रस्तावों का समर्थन किया। उन्होंने इन प्रस्तावों पर बोलते हुए यह स्पष्ट किया कि वहिष्कार का प्रस्ताव केवल बगल और विदेशी वस्तुओं तक ही सीमित है, स्वदेशी का प्रस्ताव सारे देश के लिए है। उन्होंने कहा कि जनता की अभिवृद्धि के लिए स्वदेशी आन्दोलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण

है, और उसके लिए सतत प्रयत्न करना निःसन्देह 'देशभक्ति' और 'मानवता' दोनों की माँग है। स्वदेशी, उन्होंने कहा, देश की निर्धनता दूर करने का साधन है, और देश की जनता के प्रति हमारा "धार्मिक कर्तव्य" है।^१ वह निःसन्देह "मानवता का धर्म" है।^२ अकाल और प्लेग से होनेवाली असंख्य मौतों का मूल कारण जनता की निर्धनता और बेकारी है, और देश में उद्योगों की वृद्धि उनका उपकरण है। चूँकि इंगलिस्तान उस समय मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण कर रहा है, भारत सरकार के लिए भारत के उद्योगों को वित्तीय संरक्षण देना संभव नहीं है। ऐसी हालत में स्वदेशी आन्दोलन द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, "त्याग का विचार प्रस्ताव को पवित्र करता है। वह तो वास्तव में स्वदेशी की धारणा में शामिल ही है।"^३ उन्होंने धनवानों और शिक्षित नवयुवकों से अपील की कि वे मिल कर देश में उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रयत्न करें, और जनता से अनुरोध किया कि वह कुछ अधिक दाम देकर भी स्वदेशी वस्तु खरीदें। अंत में उन्होंने कहा कि स्वदेशी के प्रश्न का राजनीतिक पक्षपात और द्वेष से कोई सम्बन्ध नहीं, इस जनहितकारी पवित्र काम में तो जनता और सरकार दोनों की सहायता को मिला देना चाहिये।^४

मुसलिम शिष्टमण्डल

१ अक्टूबर सन् १९०६ को अलीगढ़ कालेज के प्रिन्सिपल आर्चीबोल्ड के माध्यम और परामर्श से सर आगा ख़ाँ के नेतृत्व में ३५ प्रतिष्ठित मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वाइसराय से मिला और उसने उन्हें एक पत्रक पेश किया। इसमें मुसलमानों के ऐतिहासिक महत्त्व की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वाइसराय से प्रार्थना की गयी थी कि उनके हितों की विशेष रूप से रक्षा और पुष्टि की जाय, और वाइसराय को विश्वास दिलाया गया था कि 'मुसलमानों के हितों को आगे बढ़ाकर सरकार राजभक्ति के वन्धन को सुदृढ़ करेगी, और उनकी राजनीतिक प्रगति और राष्ट्रीय अभिवृद्धि की बुनियाद डालेगी'। इस पत्रक में सरकार से माँग की गयी कि देश के विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में मुसलमानों को पोजीशन को निश्चित करते समय उस पोजीशन का भी ध्यान रखा जायगा जो सौ वर्ष से कुछ पहले उन्हें हिन्दुस्तान में प्राप्त थी, और देश की सुरक्षा में इस समय जो उनका योगदान है, वह भी याद रखा जायगा।

शिष्टमण्डल चाहता था कि प्रतिनिधि कौंसिलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो। उनके प्रतिनिधियों की नियुक्तियाँ

१. वही, पृ० ५४९।

३. वही, पृ० ५५०।

२. वही, पृ० ५४९।

४. वही, पृ० ५५२।

नामजदगी के बजाय चुनाव द्वारा हो, तथा मुसलमान जमींदारों, वकीलों, व्यापारियों और दूसरी प्रतिनिधि सस्थाओं के मुसलमान सदस्यों आदि सम्मानित व्यक्तियों को मुसलमान सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया जाय। गिष्टमण्डल ने यह भी मांग की कि सरकारी लोक सेवाओं में भी मुसलमानों को अधिक स्थान देने की व्यवस्था की जाय। गिष्टमण्डल गवर्नर-जनरल की कार्य-परिपद में भी मुसलमानों के लिए एक स्थान चाहता था।

लार्ड मिंटो ने गिष्टमण्डल को विश्वास दिलाया कि वे उनके विचारों में पूरी तौर पर सहमत हैं, और स्वीकार करते हैं कि हिन्दुस्तान में उस निर्वाचन प्रतिनिधित्व को अनिष्टकर विफलता का सामना करना पड़ेगा जो इस महाद्वीप से सम्बन्धित सम्प्रदायों के विश्वासों और परम्पराओं की उपेक्षा करते हुए व्यक्तिगत मताधिकार देने की चेष्टा करे। इस तरह लार्ड मिंटो ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता और औचित्य को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय और प्रान्तीय कॉमिलो में तथा म्युनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों में मुसलमानों के लिए पृथक् साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने का उन्हें काफी स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया। लेडी मिंटो वाइसराय की युक्ति से बहुत प्रसन्न थी। उनकी धारणा थी कि इस तरकीब से मुसलमानों को राजद्रोह के कुमार्ग से बचा लिया गया है।

मुसलिम लीग

इसके बाद ३० दिसम्बर सन् १९०६ को एक मुसलिम कन्वेंशन आयोजित हुआ, जिनमें आगा ख़ां साहब की स्थायी अध्यक्षता और नेतृत्व में मुसलिम लीग स्थापित करने का निर्णय किया। इसके निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित हुए—(१) हिन्दुस्तान के मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य के प्रति राजभक्ति के भाव को बढ़ाना, (२) ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये किसी कानून में सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलतफहमी फैल जाय तो उसे दूर करना, (३) हिन्दुस्तान के मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना, तथा सौम्य भाषा में उनकी मांगों और आकांक्षाओं को ब्रिटिश सरकार के सामने पेश करना, तथा (४) न० १ या न० ३ में जो उद्देश्य बताये गये हैं उनकी किसी तरह हानि न करते हुए मुसलमानों में दूसरे सम्प्रदायों के प्रति द्वेष की भावना को रोकना।



५. दमन, विघटन, सुधार

जनजागृति

गरम दल की नीति नवयुवको को अधिक रुचिकर थी। इसके कारण पुराने नेताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर मालवीयजी ने इन सब की उपेक्षा करते हुए बहुत ही तितिक्षा के साथ अपना काम अपने विवेक और अन्तःकरण के अनुसार जारी रखा। भारत के सर्वोत्कृष्ट नेता दादाभाई नौरोजी की नीति का अनुसरण करते हुए उन्होंने कांग्रेस की नीतिरीति का स्पष्टीकरण तथा प्रसार किया, राष्ट्र की मांगों का समर्थन किया, एवं जनजागृति और जनान्दोलन को पुष्ट किया।

इन सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मालवीयजी ने सन् १९०७ में बसन्त पंचमी के दिन 'अम्युदय' के नाम से हिन्दी साप्ताहिक निकालना प्रारम्भ किया। दो वर्षों तक इस पत्र का सम्पादन उन्होंने स्वयं किया। अपने सम्पादकीय लेखों में उन्होंने ऊपर लिखी सब बातों को पुष्ट करने के साथ साथ सनातन धर्म के कतिपय मूल सिद्धान्तों की जनहितकारी उदार व्याख्या की तथा देशभक्ति, देशसेवा, साम्प्रदायिक एकता, राष्ट्रीयता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, स्वदेशी, देशभक्ति पर आश्रित राजभक्ति आदि की व्याख्या करते हुए नवयुवको को प्रेरित किया कि वे इन सब को अपने जीवन में आत्मसात कर अपने जीवन को पवित्र और उत्कृष्ट बनायें, निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र की ठोस सेवा करें, और भारत माता की कीर्ति की वृद्धि में योगदान करें।

राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न

मालवीयजी ने अपने लेखों में एक ओर महारानी विक्टोरिया की घोषणा तथा अन्य उच्चाधिकारियों के वक्तव्यों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आशा व्यक्त की कि वह जनता की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करेगी तथा भारतीयों के स्वशासन के अधिकार स्वीकार करेगी, दूसरी ओर जनता को बताया कि अंग्रेज आसानी से अधिकार देनेवाले नहीं हैं। उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। उसे प्राप्त करने के योग्य अपने को बनाना होगा।

उन्होंने लिखा "जिस समय हम अपने को इस योग्य बना लेंगे कि इंग्लैंड : वे सब अधिकार हमको दे जो अंग्रेजों को प्राप्त हैं, उस समय इंग्लैंड को हमें वे

सब अधिकार देते ही देनेगा। योग्य होने का यह अर्थ है कि न केवल हमको उन अधिकारों को काम में लाने की और उनसे देश के हित के कामों को करने की बुद्धि और योग्यता हो, अपितु यह भी कि हमारे हृदय में उनके पाने की ऐसी अभिलाषा हो कि उनको पाये बिना हम अपने को सुखी न मानें, और उनके पाने के लिए जितना गुल और स्वार्थ का त्याग करना जरूरी हो उसे करने की तैयार हो।”^१

उनकी धारणा थी कि “किसी मनुष्य अथवा किसी जाति की तब तक उन्नति नहीं हो सकती, जब तक वह अपनी वर्तमान दशा से अमनुष्ट होकर उसे सुधारने का यत्न न करे”, “प्रत्येक देश या जाति का अम्युद्ध मूल रूप में उसकी प्रजा के आत्मवीर्य पर निर्भर है”, और “इस दृष्ट निश्चाय से जब हम अच्छे कामों में उद्योग करेंगे, तब फिर हमारे दिन फिरेंगे और हमारे देश का वैभव और गौरव बढ़ेगा।”^२ वे चाहते थे कि हम अपने अधिकारों के लिए “मर्यादा के अनुसार आन्दोलन” करें^३, गवर्नमेंट और प्रजा इन दोनों की शक्तियों को जहाँ तक अनुकूल और निगुक्त कर सों, करें^४, और “निष्कारण ऐसी बातें न करे जिनसे गवर्नमेंट और हमारा विरोध बढ़े”।^५

सर्वांगीण उन्नति और एकता

उनकी राय में “देश और जाति का उद्धार करने के लिए, इसके सुग, सम्पत्ति और प्रतिष्ठा पाने के लिए सब प्रकार की उन्नति—धर्मसम्बन्धी, सामाजिक, व्यापार सम्बन्धी और राजनीतिक उन्नति—जरूरी है। ये सब एक-दूसरे की सहायक और एक-दूसरे की अंग हैं। सिर्फ एक प्रकार की उन्नति से हम उस रथान पर नहीं पहुँच सकते, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। इन सब प्रकारों की उन्नति के लिए एकता की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक और व्यापार सम्बन्धी उन्नति के लिए तो हिन्दुस्तान की सब जातियों में परस्पर प्रीति और एकता की बहुत ही जरूरत है। बिना इसके हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। हम लोगों को इन बातों को गूँथ विचार कर अपने-अपने विश्वासों में जमा लेना चाहिये”।^६

हिन्दू-मुसलमान एकता

मालवीयजी का कहना था कि “हिन्दुस्तान में अब केवल हिन्दू ही नहीं बसते हैं। हिन्दुस्तान अब केवल उन्हीं का देश नहीं है। हिन्दुस्तान जमे हिन्दुओं

१. मा. तोमजी के लेख, सम्पादन-यस्मान्त मालवीय, पृ० १५।

२. वही, पृ० ५१।

३. वही, पृ० ६।

४. वही, पृ० १२।

५. वही, पृ० १५।

६. वही, पृ० ७।

७. वही, पृ० ७।

८. वही, पृ० २४।

का प्यारा जन्म-स्थान है, वैसा ही मुसलमानों का भी है। ये दोनों जातियाँ अब यहाँ बसती हैं और सदा बसी रहेंगी। जितना इन दोनों में परस्पर मेल और एकता बढ़ेगी, उतनी ही देश की उन्नति करने में हमारी शक्ति बढ़ेगी, और इनमें जितना ही वैर या विरोध या अनेकता रहेगी, उतना ही हम दुर्बल रहेंगे। जब ये दोनों एकता के साथ उन्नति की कोशिश करेंगे, तभी देश की उन्नति होगी। इन दोनों जातियों में और भारतवर्ष की सब जातियों—हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी—में सच्ची प्रीति और भाइयो जैसा स्नेह स्थापित करना हम सब का बड़ा कर्तव्य है। इससे देश का बहुत कल्याण होगा। जो हमारी उन्नति नहीं चाहते, वे हमको एक दूसरे से लड़ाने के लिए यत्न करते हैं और करेंगे। लेकिन यदि हमारे आपस में एक दूसरे के विचार और भाव शुद्ध रहें, तो हमारे किसी वैरी का हमको लड़ाने का यत्न सफल न होगा” ।^१

उन्होंने लिखा “यह दुःख की बात है कि हम लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जाति को दूसरी से लड़ाने का यत्न करते हैं। हमको इस बात को कहने में कुछ भी सकोच नहीं कि जो हिन्दू या मुसलमान ऐसा करता है, वह देश का शत्रु है। इतना ही नहीं, बल्कि वह अपनी विशेष जाति का भी शत्रु है। हम सबको उचित है कि सब एक दूसरे के चित्त को संताप पहुँचानेवाली बातों को भूल जावें, एक दूसरे का हित और सुख चाहे, और एक दूसरे के हित और सुख के यत्न में सहायक हों” ।^२

धर्म और साम्प्रदायिक वैमनस्य

मालवीयजी के विचार में साम्प्रदायिक वैमनस्य का कारण धर्म के बजाय हमारी हठधर्मी है। उन्होंने लिखा . “क्या धर्मों के भेद से हिन्दुओं, आर्यों, मुसलमानों, और ईसाइयों का आपस में झगडा करना कोई धर्म कहा जा सकता है ? हिन्दू मूर्ति-पूजक हैं और आर्यसमाजी नहीं। इसलिए इन दोनों में सदैव तनातनी रहे, यह कोई धर्म है ? हिन्दू और मुसलमान के मत अलग अलग हैं, तो इस विचार से यदि कोई मुसलमान हिन्दुओं के सदैव विरुद्ध रहे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की दृष्टि में उनको बागी साबित करने का झूठा सच्चा प्रयत्न करें, तो क्या वे अपने धर्म में लगे हुए हैं ? कदापि नहीं। यदि ऐसा करते हैं तो हिन्दू और आर्य अपने वेदों के, ईसाई इजील के, और मुसलमान अपने कुरानशरीफ के विरुद्ध चल रहे हैं। धर्म यह है कि प्राणी की प्राणी के साथ सहानुभूति हो। एक

दूसरे को अच्छी अवस्था में देखकर प्रसन्न हो, और गिरी हुई अवस्था में सहायता दे"।^१

देशभक्ति

मालवीयजी एकना को देशभक्ति से परिपुष्ट तथा राष्ट्रीयता में परिष्कृत करना चाहते थे। उनका कहना था कि 'गाढ़ देशभक्ति से एकता उत्पन्न होती है, एकता से राष्ट्रीयता का भाव और राष्ट्रीयता के भाव से देश की उन्नति होती है।'^२ उन्होंने बताया कि जिग तरह भगवद्भक्त वे होते हैं जो अपने समस्त कार्यों को भगवान् को अर्पण कर देते हैं और एकाग्र लगन से भगवान् का ध्यान और उपासना करते हैं। सच्चे देशभक्त वे हैं, जो "जो कुछ करें करें, गध कुछ देश के ही लिए हो, और देश - कार्य में प्रति क्षण तत्पर रहें, और एकाग्र लगन से देश के ही ध्यान और उपाराना में लगे रहें।"^३

वे देवानुराग को धर्म का महत्त्वपूर्ण अंग मानते थे। उनका कहना था कि "सच्चा तप यह है कि अपने भाइयों के तप में तपा जाय, सच्चा गज यह है जिसमें अपने स्वार्थ की आहुति दी जाय। सच्चा दान यह है कि परमार्थ किया जाय, और सच्ची ईश्वर सेवा यह है कि उसके दु गरी जीवों को सहायता की जाय। परमात्मा सबके हृदय में व्यापक है। इसलिए हम जितने प्राणियों को प्रगट करे, उतने ही गुना ईश्वर को प्रसन्न करेंगे। यह मन्त्रा धर्म देशभक्ति द्वारा प्राप्त है। देश-भक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थ को निकाल कर फेंक देगा। हम अहङ्गदर्शी, स्वार्थी और गुणामदियों की तरह मेरे काम कराने न करेंगे जिनसे देशवागियों को हानि पहुँचे, धार्मिक दूरदर्शी, परमार्थी, सत्यजीव, और दृढ़ताप्रिय आत्माओं की भाँति असांख्य तप उठाने हुए गड़ी करेंगे जिससे देश का भवता हो, निर्धन धनवान्, निर्बल बलवान् और मूर्ख भी बुद्धिमान् हो जायें। प्रत्येक प्रश्न के सामाजिक दुःख मिटे और दुस्मिता आदि विपत्तियाँ दूर होकर लागों बिलबिलाने लगे आत्माओं को गुण पहुँचे। देशभक्ति द्वारा होने भर्मा का सम्पादन होता हुआ देखकर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ नहीं समझता, उस पुरुष को जान लीजिये कि वह धर्म के सत्ता को नहीं पहचानता। यह 'धर्म' 'धर्म' मन्त्र गा रहा है, परन्तु यह नहीं जानता कि धर्म क्या वस्तु है।"^४

१. यही, पृ० १०६।

२. यही, पृ० १०८।

३. यही, पृ० १००।

४. यही, पृ० १०१-१०४।

इस तरह मालवीयजी चाहते थे कि भारतवासी “स्वार्थ-भक्ति” छोड़कर “देश-भक्ति” को अपनायें, जिसके आगे हम अपने को भूल जायें, देश की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझें, देश के यश में अपना यश समझें, देश के जीवन में अपना जीवन समझें, और देश की मृत्यु में ही अपनी मृत्यु समझें।^१

स्वदेशी

मालवीयजी स्वदेशी की भावना को देशभक्ति का महत्त्वपूर्ण अंग समझ कर उसका संचार आवश्यक समझते थे। उनकी धारणा थी कि “गहरा, गाढा, उत्कृष्ट, अन्य सब भावों को दबा देनेवाला अपने देश का प्रेम ही स्वदेशी का अर्थ है।”^२ स्वदेशी आन्दोलन की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि उसका “मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक दशा को सुधारना है। देश की दशा तभी सुधर सकती है, जब देश में देशी चीजों का व्यापार बढ़े, और जो हमारे नित्य की आवश्यक चीजें हैं, वे यहाँ बनने लगें। हमारे देश में व्यवसाय और शिल्प अभी नवजात हैं। इनकी रक्षा और वृद्धि बड़ी सावधानी से करनी पड़ेगी। जिन देशों में स्वराज्य है, उन देशों में इनकी रक्षा गवर्नमेंट कर लगाकर और रुपया देकर करती है। पर इस देश में इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट से बहुत आशा नहीं की जा सकती। इसलिए आत्मसहाय और स्वार्थ-त्याग से हमें इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। सरकार कर नहीं लगायेगी तो हम अपने ऊपर स्वयं कर लगा सकते हैं। अर्थात् देशी चीज यदि महगी हो तो भी उसको अधिक दाम देकर ले सकते हैं।”^३

सच्ची राजभक्ति

मालवीयजी के विचार में “सच्ची देशभक्ति ही राजभक्ति है।”^४ “प्रजाभक्ति ही सच्ची राजभक्ति है।”^५ उनके विचार में “समस्त राजभक्तों का यह कर्तव्य है कि राजभक्ति दिखलाने में देशभक्ति का सबसे पहले ध्यान रखें और राजा को उसी मार्ग पर लायें जिसमें उसके देश और प्रजा का भला हो।”^६ उनका कहना था कि “जो लोग किसी राजा की प्रजा को सुख पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं, वे राज्य को सुख पहुँचाते हैं। जो देश की सामाजिक, साम्प्रतिक और प्राज्ञिक दशा को संभालने में लगे हुए हैं, वे राज्य के बल को बढ़ा रहे हैं और राजा का मंगल चाह रहे हैं, और जो इसके विरुद्ध प्रजा और

१. वही, पृ० १०८।

३. वही, पृ० ८५।

५. वही, पृ० १११।

२. वही, पृ० ३०।

४. वही, पृ० १११।

६. वही, पृ० १११।

देश को हानि पहुँचा कर राजभक्ति दर्शा रहे हैं, वे मर्यादा में राजा के साथ शत्रुता कर रहे हैं।”^१

राजा का कर्तव्य

“प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के दुःख में राजा का दुःख, प्रजा की उन्नति में राजा की उन्नति, और प्रजा की ध्वनति में राजा की ध्वनति है। राजा का यह प्रधान धर्म है कि यह देश के कल्याण का मदैय ध्यान रखे। जिस प्रकार एक कृषक अपने रेत में चर-पात को काट कर रेत के पौधों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा का भी यह कर्तव्य है कि वह राज्य के दुःखदायक निमित्तों को दूर करके प्रजा की रक्षा करे।”^२

राष्ट्रीयता

मालवीयजी ने अपने लेखों में राष्ट्रीयता के महत्त्व पर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीयता ही जापान, इंग्लैंड आदि देशों की उन्नति का मुख्य कारण है, और वही भारत का भी उद्धार कर सकती है।^३ उन्होंने लिखा - “राष्ट्रीयता उस भावना का नाम है जो देश के सम्पूर्ण निवासियों के हृदय में देश-हित की लालसा से व्याप्त रही हो, जिसके आगे अन्य भावों की श्रेणी नीची हो रहती है।”^४ वे चाहते थे कि “देश ही समस्त देशवासियों के प्रेम और भक्ति का विषय” बन जाय, “मातृभेद, वर्णभेद और जातिभेद के होते हुए भी राष्ट्रीयता का श्रेष्ठ भाव देवतावादी” हो जाय, और इतना बल जाय कि “उसके आगे अन्य भावों का दर्जा नीचा” लगे।^५

स्वराज्य

अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर ही स्वराज्य की उपलब्धि के प्रयत्नों की पुष्टि करते हुए मालवीयजी ने बताया कि “प्रजा के चने प्रतिनिधियों द्वारा प्रजा की सम्मति से राज्य के प्रबन्ध का विनियार” ही ‘स्वराज्य’ है,^६ और हम भारतीय “पूर्ण रूप से उसके योग्य हैं”। उन्होंने विभिन्न देशों और विद्वानों का प्रमाण देते हुए लिखा : “प्रजा के प्रतिनिधियों की सम्मति से सामन्य का क्रम सब सम्यक् समार में सामन्य का अन्तः क्रम सम्मति से है।”^७ प्रिन्स के

१. वही, पृ० १११।

३. वही, पृ० १०४।

५. वही, पृ० ९९।

७. वही, पृ० ७४।

२. वही, पृ० १११।

४. वही, पृ० ९९।

६. वही, पृ० ७४।

भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री सर हैनरी कैवल वेनमैन ने स्वयं कहा है : कि "सुराज्य (अच्छा राज्य) उस राज्य के समान नहीं हो सकता जिसमें प्रजा स्वयं अपने ऊपर आप शासन करती है" ।^१

मालवीयजी ने लिखा कि जहाँ "एक जाति का दूसरी जाति पर आक्रमण या अधिकार" अनुचित है, वहाँ "न्याय और धर्म की बात यही है कि प्रत्येक देश और जाति के लोग अपने देश में स्वाधीन हो और अपने ऊपर स्वयं राज्य करें ।"^२ अंग्रेज जाति, जो स्वयं स्वतन्त्रता की प्रेमी है, हिन्दुस्तान को सभ्यता के नाम पर सदा अपने अधीन नहीं रख सकती । उसका कर्त्तव्य है कि "वह हमको अपने देश का आप शासन करने के योग्य बनावे",^३ और यहाँ प्रतिनिधि शासन या स्वराज्य प्रतिष्ठित करे, क्योंकि "जब तक यह नहीं होता, तब तक हिन्दुस्तान का वर्तमान दुर्दशा से उद्धार नहीं होगा ।"^४

मालवीयजी ने बताया कि स्वराज्य, जो "मानवजाति के लिए सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ी नियामत है",^५ वह केवल मनोरथ करने से नहीं मिलेगा, बरन् उसके लिए तपस्या करनी होगी ।^६ इसके लिए हमें अपने में "शान्ति और सहयोग, धीरज और उत्साह, प्रज्ञा और पीठष, तेज और सहन-शीलता, प्रेम और स्वार्थत्याग, तथा इनके समान अनेक उत्तम गुणों का संग्रह करना होगा ।"^७

स्वराज्य की सिद्धि का साधन

उनके विचार में देशभक्ति ही स्वराज्य की सिद्धि का पहला और सबसे बड़ा साधन है ।^८ वे चाहते थे कि देश में, जहाँ तक सम्भव हो प्राणी-प्राणी में, देश की भक्ति का भाव बढ़ाया जाय ।^९ वे यह भी चाहते थे कि "जहाँ तक हो सके, नगर-नगर, गाँव-गाँव लोगों को 'स्वराज्य' का अर्थ, उसकी आवश्यकता और उसकी महिमा समझायी जाय, जिससे उनके हृदय में उसको पाने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो" तथा "प्रत्येक नगर और गाँव में सभाएँ स्थापित हो जो स्वराज्य पाने के लिए न्यायपूर्वक लगातार आन्दोलन करें" ।^{१०}

१. वही, पृ० ६४ ।

२. वही, पृ० ६३ ।

५. वही, पृ० ७८ ।

७. वही, पृ० ७८ ।

९. वही, पृ० ७८ ।

२. वही, पृ० ६१ ।

४. वही, पृ० ६६ ।

६. वही, पृ० ७८ ।

८. वही, पृ० ७८ ।

१०. वही, पृ० ७९ ।

इस तरह दादा भाई नौरोजी के सिद्धान्तों के अनुकूल मालवीयजी ने सन् १९०७ ई० में जल्दा में स्वराज्य, स्वदेशी, देशभक्ति, राष्ट्रीयता तथा पारस्परिक सहाय का प्रचार किया, तथा जनान्दोलन को प्रोत्साहित किया।

आक्रमणशील और उग्रवादी राष्ट्रीयता

सन् १९०७ में बंगाल और पंजाब में सरकार के दमन के कारण स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी। आक्रमणशील राष्ट्रीयता ने आतंक का रूप धारण कर लिया, दमनकारी अगुयों को हत्या उसका एक ध्येय बन गया। आतंकवादियों ने दम बनाना, विप्लव आदि तैयार करना और इच्छा करना, तथा डकैतियों द्वारा धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया।

दूसरी ओर बाइकाट के समर्थक उग्र राष्ट्रीयतावादियों ने स्वदेशी और बाइकाट का काम जोर जोर से शुरू किया। उन्होंने बाइकाट को सफल बनाने के लिए विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करनेवालों का जाति से बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं को छीन कर ज्वा डालना, तथा विदेशी चीनी से बनी मिठाइयों को और लिबरपूल के नमक को फेंक देना प्रारम्भ किया।

इन कामों का मुसलमानों से कोई सम्बन्ध नहीं था। न तो आतंकवादों और न बाइकाट के समर्थक उन्हें किसी प्रकार से परेशान करते थे। पर ४ मार्च सन् १९०७ को कोमिल्ला में ढाका के नवाब सलीमुल्ला का जुलूम निकला, और उसने साम्प्रदायिक दंगे का रूप धारण कर लिया। दंगे चार दिन तक होने लगे। कुछ दिन बाद जिला मैजिस्ट्रेट के कमालपुर में दंगे हुए। अंग्रेज अफसरों का कहना था कि इन दंगों का मूल कारण स्वदेशी आन्दोलन था। मुसलमानों को जबरदस्ती स्वदेशी वस्तुएं खरीदने पर मजबूर करना था, जबकि हिन्दू नेताओं का कहना था कि इन दंगों का स्वदेशी से कोई सम्बन्ध नहीं था। उनका कहना यह भी था कि मुसलमानों के उत्पातों का मूल कारण उनकी यह भावना थी कि सरकार उनकी अपेक्षा करेगी, किसी को उनके कारण दण्ड नहीं देगी।^१

पंजाब में दमन

दूसरी ओर पंजाब सरकार ने पंजाब की राजनीतिक चेतना-‘नयी हवा’ को दबाने के लिए दमन का रास्ता पकड़ा। उसे भय हुआ कि पंजाब के कतिपय राजनीतिज्ञ १८५७ के विप्लव की स्वर्ण जयन्ती मनाना चाहते हैं। इस प्रयत्न को

१. आर. एस. मजूमदार : हिस्ट्री आफ़ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, पृ० ११५-११९।

कुचलना सरकार ने अपना कर्तव्य समझा। चेनाव उपनिवेश योजना के नये नियमों से उत्तेजित किसानों को भी भयभीत करना उसने ठीक समझा। वह जो कुछ करना चाहती थी, उसे साधारण कानून द्वारा नहीं कर पाती थी। इसलिए पंजाब सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने सन् १८१८ का बगाल रेगुलेशन नं० ३ पंजाब में चालू कर दिया। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह चुपके से गिरफ्तार करके माण्डले जेल भेज दिये गये। कुछ अर्से के बाद दोनों छोड़ दिये गये। पर इस गिरफ्तारी ने उग्र राष्ट्रवादियों में लाला लाजपत राय की प्रतिष्ठा को काफी बढ़ा दिया।

कांग्रेस में तनाव

इन सब बातों का कांग्रेस की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पुराने कांग्रेसी नेताओं ने स्वदेशी और बाइकाट के आन्दोलन में खतरे की आशंका अनुभव की। वे उन्हें इतना समर्थन भी करना नहीं चाहते थे जितना सन् १९०६ के कलकत्ता अधिवेशन में उसे मिल चुका था। दूसरी ओर गरमदलीय राजनीतिज्ञ इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस तनावपूर्ण के वातावरण में मालवीयजी और लाला लाजपत राय समझौते के पक्ष में थे। वे उसे राष्ट्र के हित में आवश्यक समझते थे। लालाजी ने तिलक महाराज से कह दिया था कि वे इस अवसर पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। तिलक महाराज भी इस आश्वासन पर कि राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और बाइकाट पर सन् १९०६ के प्रस्ताव फिर स्वीकार होंगे, और अध्यक्षीय भाषण में इनकी कोई प्रतिकूल आलोचना नहीं होगी अपना अध्यक्ष सम्बन्धी प्रस्ताव वापस लेने को तैयार थे। पर कोई समझौता नहीं हो सका।

कांग्रेस के अधिवेशन में जैसे ही डाक्टर रासबिहारी घोष का नाम अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित किया गया, दुंदुभ मच गया। अधिवेशन दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। पर समझौता फिर भी नहीं हो पाया। दूसरे दिन २७ दिसम्बर को डाक्टर घोष का नाम सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा प्रस्तावित और पंडित मोती लाल नेहरू द्वारा समर्थित होने के बाद घोष साहब ने जैसे ही अध्यक्ष की कुर्सी संभालने की चेष्टा की, वैसे ही लोकमान्य तिलक ने एक संशोधन प्रस्तुत करते हुए विरोध में भाषण देना प्रारम्भ किया। स्वागतार्थ्यक्ष ने उन्हें मना किया, पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। पंडाल में हंगामा मच गया। उपद्रव होने लगा, और अधिवेशन खत्म कर दिया गया।

नेशनल कन्वेंशन

दूसरे दिन अर्थात् २८ दिसम्बर को नरम-दलीय नेताओं ने कांग्रेस के उन प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कन्वेंशन) आयोजित किया जो इन तीन बातों को स्वीकार करने को तैयार हो—(१) उनकी राजनीतिक अभिलाषाओं का लक्ष्य भारत द्वारा ऐसा स्वायत्त शासन प्राप्त करना, तथा साम्राज्य के अधिकारों और उत्तरदायित्वों में समता के आधार पर भाग लेना है जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य स्वायत्तशासित सदस्यों को प्राप्त है ; (२) पूर्णरूप से संवैधानिक उपायों द्वारा मौजूदा शासन-व्यवस्था में सुधार कराना, तथा राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक भावना को पुष्ट करना, और जनता की दशा की उत्थान करना ही इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग होगा, (३) इन लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो बैठकें या सभाएं आयोजित होंगी, वे सुव्यवस्थित ढंग से उन लोगों के आदेशानुसार संचालित होंगी जिन्हें उनके संचालन का अधिकार है ।

कांग्रेस के अधिकांश प्रतिनिधि पुराने नेतृत्व के निर्देशन में कांग्रेस को बनाये रखना चाहते थे । वे इन शर्तों पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हो गये ।

दूसरे दिन अर्थात् २९ दिसम्बर को अरविन्द घोष की अध्यक्षता में वाम-पक्षीय राष्ट्रवादियों की बैठक हुई । इसमें निश्चय हुआ कि नये दल के लक्ष्यों का जनता में प्रसार किया जाय । लोकमान्य तिलक के आग्रह पर अरविन्द की रजामन्दी से नरमदलीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भी एक कमेटी गठित की गयी ।

बंगाल के कतिपय नरमदलीय नेता कांग्रेस में फूट को खत्म करने के पक्ष में थे । भूपेन्द्रनाथ वसु ने इस सम्बन्ध में फीरोजशाह मेहता को लिखा भी, पर वे गरमदलीय कार्यकर्ताओं को फिर से कांग्रेस में शामिल करने को राजी नहीं हुए । दिसम्बर सन् १९०८ में डाक्टर रासबिहारी घोष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषित किया कि 'हमारे मार्ग बहुत भिन्न है । बहुत बड़ी खाई हमें अलग करती है । हम उस समय तक जबतक कि वे अपनी नीति पर अड़े रहते हैं, उन्हें साहचर्य (संसर्ग) का हाथ नहीं बढ़ायेंगे, नहीं बढ़ा सकते, और बढ़ाने का साहस नहीं कर सकते ।'

इस तनाव, अविश्वास और फूट के कारण कांग्रेस की शक्ति काफी क्षीण हो गयी, और देश को वर्षों उग्र राष्ट्रवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सेवाओं से वंचित रहना पड़ा । सरकार ने फूट से लाभ उठाकर बहुत से गरमदलीय

राजनीतिज्ञों को बिना मुकदमे के नजरबन्द कर दिया। लोकमान्य तिलक पर राज-विद्रोह का अभियोग लगा कर उन्हें छः वर्ष की सजा दे दी। अरविन्द घोष भी षड्यन्त्र के अभियोग में फाँस लिये गये।

मालवीयजी का शोभ

इस फूट से अधिकांश कार्यकर्ता क्षुब्ध थे। पर मालवीयजी के लिए तो वह इतनी असह्य थी कि वे छयालीस वर्ष की आयु में पडाल में ही एक खंभे से लगे बहुत देर तक रोते रहे, और उनके ज्येष्ठ पुत्र रमाकान्तजी बहुत कठिनाई से उन्हें उनके निवासस्थान पर ले जा सके।

इस फूट के लिए मालवीयजी गरमदल को ही मुख्यतः उत्तरदायी ठहराते थे। उनका यह भी विचार था कि देश की राजनीतिक प्रगति के लिए कांग्रेस को बनाये रखना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने फीरोजशाह मेहता द्वारा आयोजित सभा में भाग लेना, और नवसंघटित कांग्रेस में काम करते रहना उचित समझा। पर उनके और मेहता साहब के विचारों में बहुत अन्तर था। जबकि मेहता साहब कांग्रेस पर पुराने नेतृत्व का प्रभुत्व बनाये रखना चाहते थे, मालवीयजी को इसकी कोई चिन्ता नहीं थी कि कांग्रेस नरम दल के हाथ में जाती है या गरम दल के हाथ में, वे तो केवल यह चाहते थे कि भारतीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित न होकर “देश भर की एक कांग्रेस होती हुई अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा करती रहे, और बाहरी दिखावट और बातों से बढकर कुछ असली कार्य करे।”^१ उनकी तो इच्छा थी कि सब मिलकर काम करें, कांग्रेस का एका बनाये रखें, “सदैव विचार-शक्ति, दूरदर्शिता, कार्यकुशलता और एकता से काम लें, उन लोगों का सत्कार करें जिन्होंने कांग्रेस के लिए कुछ किया है या कर रहे हैं, और उन लोगों में उत्साह उत्पन्न करें जो कुछ कर सकते हैं।”^२

प्रान्तीय काफ़ेस में भाषण

सन् १९०८ में मालवीयजी अपने प्रान्त के द्वितीय सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश की तथा अपने प्रान्त की दयनीय दशा का विश्लेषण करते हुए बताया कि पिछले पचास वर्षों में बाईस अकाल पड़े जिनमें दो करोड़ नब्बे लाख आदमियों की मृत्यु हुई, तथा पिछले ग्यारह वर्षों में पचपन लाख व्यक्ति प्लेग से मरे। उन्होंने यह भी बताया कि जहाँ ब्रिटेन की मृत्यु-संख्या फी हजार सोलह है, वहाँ भारत की फी हजार पैंतीस

१. ‘अम्युदय’, पौष कृष्ण ३०, सम्वत् १९६४।

२. वही।

और इस प्रान्त की फी हजार चीवालिस है। उन्होंने कहा कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ता जा रहा है, पर बीस वर्ष से मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जनता की निर्धनता जनता के दुःखों का मूल कारण है, तथा महँगी शासन-व्यवस्था, देशी कला तथा व्यवसाय की अवनति, तथा किसानों पर आपत्तिजनक अधिक लगान निर्धनता के मूल कारण है।^१

देश की दशा तथा सरकार की नीति-रोति को समीक्षा करते हुए मालवीयजी ने कहा कि व्यापक असन्तोष के मूल कारण जनता की गरीबी और उसकी स्वाभाविक आकांक्षाओं की उपेक्षा ही है।^२ संसार में कोई ऐसा देश नहीं जो हिन्दुस्तान से अधिक गरीब हो और जहाँ प्रशासकों का वेतन यहाँ से अधिक हो।^३ सैनिक और सिविल सेवाओं में ऊँचे पदों पर यूरोपीयनों की 'वास्तविक इजारादारी' के कारण हमें उन सेवाओं के लिए अधिक वेतन देना पड़ता है और प्रतिवर्ष देश का बहुतसा धन देश के बाहर खिंचा चला जाता है।^४ यद्यपि सिद्धान्त में ऊँचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति का औचित्य स्वीकार कर लिया गया है, पर व्यवहार में "बुरी तरह नियमित रूप" से उसकी उपेक्षा की जा रही है।^५ देश का शासन ठीक तौर से नहीं हो रहा है, और वह उस समय तक नहीं होता, जब तक भारतीयों को प्रबन्ध में समुचित भाग नहीं दिया जाता^६, और "स्वशासन की बड़ी मात्रा" उन्हें प्राप्त नहीं होती।^७ देश के प्रबन्ध में जनता के प्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं है, विधान कौंसिलों के अधिकार बहुत ही सीमित हैं, जनता के कल्याण में राजस्व का एक चौथाई से भी कम भाग खर्च किया जा रहा है। इस व्यवस्था में जनता की नैतिक और भौतिक उन्नति सम्भव नहीं है।^८ स्थिति के सुधार के लिए देश के ढाँचे में परिवर्तन नितान्त आवश्यक है। स्वशासन का अधिकार स्वीकार किया जाय, योग्य भारतीय शासन-परिपदों के सदस्य बनाये जायें, और साधारणतः जनता के प्रतिनिधियों के मतानुकूल ही देश का शासन हो।^९

"मनोनीत निर्देशिका कौंसिलें", उन्होंने कहा, विधान कौंसिलों के स्वाभाविक और समुचित विकास में बाधक होगी, रियासतों के राजाओं और नवाबों को

- | | |
|---|----------------------|
| १. आनरेबिल मदन मोहन मालवीय: लाइफ एण्ड स्पीचेज, पृ० ७६-९१। | |
| २. वही, पृ० ७५-७६। | ३. वही, पृ० ८५। |
| ४. वही, पृ० ८५-८६। | ५. वही, पृ० ८७-८८। |
| ६. वही, पृ० १००। | ७. वही, पृ० १०९। |
| ८. वही, पृ० १०३। | ९. वही, पृ० १०४-१०८। |

ब्रिटिश भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने की व्यवस्था करना सर्वथा अनुचित है। व्यावसायिकों, व्यापारियों, औद्योगिकों और मध्यवर्ग के प्रतिनिधियों से अधिक महत्वपूर्ण जमींदारों को नहीं समझा जा सकता। विधान कौंसिलों की उपस्थिति में सलाहकार कौंसिलों की नियुक्ति अर्थहीन है।^१ शासकों की इच्छा पर आश्रित सलाहकार समितियों का गठन "प्रगति नहीं, बल्कि अधोगति है"^२, और इस विचार का परित्याग नितान्त आवश्यक है।

सरकार की यह शिकायत कि विधान कौंसिलों में वकीलों की संख्या सबसे अधिक थी बेकार है। यदि वकीलों ने सार्वजनिक कामों में अधिक काम किया, तो इसमें शिकायत की कौन बात है? कौंसिलों में वकीलों ने सिद्ध कर दिया है कि "वे सब वर्गों के लोगों के हितों को बढ़ाने के इच्छुक हैं।"^३ वकीलों ने जमींदारों के हित में मालगुजारी के स्थायी बन्दोबस्त का समर्थन किया, किसानों के हित में काश्तकारी की अवधि की स्थिरता की माँग की, गरीबों के हित में नमक-कर की छूट की अपील की। उन्होंने गरीब मध्य वर्गीय जनता के हित में आय-कर की निम्नतम सोमा को ५०० रुपये के बजाय १००० रुपये कर देने की माँग की, तथा सारी जनता के कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयत्न किया। इस पर भी यदि सरकार उनसे नाराज है, तो उन्हें कौंसिलों की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है, पर अपनी इच्छा के अनुसार अपना प्रतिनिधि चुनने की जनता को स्वतन्त्रता देनी ही होगी। सरकार द्वारा निश्चित मंडल के अन्दर से अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए जनता को बाध्य नहीं किया जा सकता।^४ वकील तो केवल यह चाहते हैं कि "जनता के प्रतिनिधि वे हों जो अपनी बुद्धि, विद्या, अनुभव और स्वतन्त्र विवेक से कौंसिलों में उपस्थित प्रश्नों पर सरकार द्वारा नियुक्त इंडियन सिविल सर्विस के अत्यधिक योग्य सदस्यों से विचार विमर्श कर सकें, और उनके सामने सार्वजनिक मत को व्यक्त कर सकें, उसका दृढ़तापूर्वक समर्थन कर सकें।"^५ जमींदार, किसान, व्यापारी और व्यावसायिक—सबको प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, पर किसी को अपने वर्ग के आदमी को चुनने के लिए बाध्य न किया जाय।^६

मालवीयजी ने कहा कि हमारे लिए यह स्वीकार करना सम्भव नहीं कि भारत की विधान-सभाओं में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का अवश्य ही बहुमत होना चाहिये। कांग्रेस ने इस सिद्धान्त का शुरू से विरोध किया है। कांग्रेस

१ वही, पृ० ११४-११९।

३. वही, पृ० १२२।

५. वही, पृ० १२३।

२ वही, पृ० ११९।

४. वही, पृ० १२२।

६. वही, पृ० १२३।

तो चाहती है कि कौंसिलो के कम से कम आधे सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हो। सरकारी सदस्यों की संख्या एक चौथाई से अधिक न हो। कौंसिलों का विस्तार किया जाय। प्रति दस लाख आबादी के लिए एक सदस्य की व्यवस्था हो, और कौंसिल के अधिकारों का इस तरह विस्तार किया जाय कि निर्वाचित सदस्य सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय नीति पर प्रभाव डाल सकें, तथा उन्हें जनहितकारी बना सकें।^१

वित्तीय विकेन्द्रीकरण पर जोर देते हुए मालवीयजी ने कहा कि प्रान्तीय सरकारें “अर्धस्वतन्त्र” बनायी जायें, उन्हें राजस्व को जमा करने और खर्च करने की आजादी हो, प्रान्तीय सरकारों के कामों पर जनता के प्रतिनिधियों का कंट्रोल हो, और उसके लिए प्रान्तीय विधान कौंसिलो के आकार और अधिकारों का विस्तार किया जाय, तथा प्रान्तों की शासन परिषदों में भारतीय सदस्य नियुक्त किये जायें।^२

अन्त में मालवीय जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे स्वदेशी का प्रचार करें, राजनीतिक सुधारों के लिए जनमत तैयार करें, जनता में राजनीतिक चेतना पुष्ट करें, खेती और उद्योगों की उन्नति के लिए प्रयत्न करें, तथा विवादों के निबटारे के लिए पचायतें कायम करें, शिक्षा के विस्तार के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न करें, सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित करें, तथा स्वास्थ्य, शारीरिक उन्नति और सार्वजनिक सफाई को बढ़ाने का ध्यान रखें। उन्होंने कहा • “लोगों का वास्तविक आनन्द, जिसे हम सब बढ़ाना चाहते हैं, केवल भौतिक लाभों से प्राप्त नहीं हो सकता, और वे सब भौतिक लाभ जो प्राप्त करने योग्य हैं मानव के प्रति मानव के उन शाश्वत कर्तव्यों के पालन करने से मिल सकते हैं जिन्हें हमारे धर्म ने हम पर लागू किया है। निःसन्देह कोई बात इससे अधिक अभीष्ट नहीं है कि हमारा सब काम सच्ची धार्मिक भावना से किया जाय। अगर हम धार्मिक कर्तव्य की भावना से प्रेरित नहीं हैं, तब उस काम में, जिसे हमने प्रारम्भ किया है, हमारी रुचि स्थायी नहीं होगी। पर यदि इस विश्वास से काम करें कि ईश्वर के दीन प्राणियों की, अपने गरीब देशवासियों की, सेवा भगवान् की सेवा, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, तब चाहे निन्दा हो, चाहे प्रतिष्ठा, दूसरे सहायता करें या रुकावट डालें, हम अन्त तक अपनी शक्ति भर अपने लोगों के कल्याण की वृद्धि करते रहेंगे, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर हमारे प्रयत्नों को सफलता से अभिनन्दित करेंगे।”^३

१. वही, पृ० १२३-१२९।

२ वही, पृ० १३३।

३. वही, पृ० १४९।

सन् १९०८ की माले की सुधार-योजना

कुछ समय बाद सन् १९०८ में भारत-मन्त्री लार्ड माले ने राजनीतिक सुधारों की अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की। यह योजना सन् १९०६ की योजना से निःसन्देह अच्छी थी। इसमें निर्देशिका कौंसिल को स्थापित करने की कोई चर्चा नहीं थी। विधान कौंसिलों के आकार और अधिकारों के विस्तार के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव थे, कार्य परिषदों में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की चर्चा थी, और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अनिश्चित रखी गयी थी।

दिसम्बर सन् १९०८ में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मालवीयजी ने कांग्रेस के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें प्रस्तावित राजनीतिक सुधारों का स्वागत किया गया था, और स्वीकार किया गया था कि विधान कौंसिलों का विस्तार तथा उनके अधिकारों और कार्यों का परिवर्धन, कार्यपरिषदों में भारतीय सदस्यों की नियुक्तियाँ, तथा स्थायित्वशासन का अधिक परिवर्धन सुधारों की उदार किस्त है। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भी मालवीयजी ने माँग की कि केन्द्रीय विधान सभा के आठे सदस्य निर्वाचित भारतीय हों, कार्यपरिषदों में एक भारतीय के वजाय दो नियुक्त किये जायें, और कानून द्वारा उनकी व्यवस्था की जाय। उन्होंने धर्म के आधार पर किसी सम्प्रदाय को प्रतिनिधित्व दिये जाने का विरोध करते हुए आशा व्यक्त की कि इसे स्वीकार नहीं किया जायगा।^१

साम्प्रदायिक चुनावों का विरोध

उन्होंने अपने 'अभ्युदय' पत्र में लिखा कि "धर्म के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव अनावश्यक और असंभव है"।^२ उन्होंने लिखा : "कौंसिलें तभी शक्तिमान् और लाभदायक हो सकती हैं, जब उनमें उदार चित्तवाले और योग्य प्रतिनिधि चुने जायें"।^३ मालवीयजी ने कहा कि जो प्रतिनिधि हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा मिलकर चुना जाता है, वह भलोभाँति यह समझता है कि मैं हिन्दु और मुसलमान, दोनों का प्रतिनिधि हूँ और मुझे दोनों जातियों का हित करने का यत्न करना चाहिए। किन्तु जब मुसलमान प्रतिनिधि अलग चुने जायेंगे, तब यह बात न हो सकेगी। आश्चर्य नहीं, यदि मुसलमान प्रतिनिधि यह समझें कि हमें मुसलमानों का ही हित करना चाहिए और यह भी संभव है कि वे हिन्दुओं के प्रस्तावों का विरोध करें, और इस प्रकार हिन्दुओं को हानि पहुँचाने के साथ ही साथ अपने को भी हानि पहुँचायें। कौंसिलों में जो प्रस्ताव

१. वही, पृ० ६०-६८।

२. 'अभ्युदय', २९ फरवरी, सन् १९०९।

३. वही।

पेश होंगे, वे सभी जातियों के लिए हितकारी होंगे, और उनके पास न होने से सभी जातियों को हानि पहुँचेगी। सब विचारवान् देशहितैषियों का यह मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश में जो भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं वे एकमत होकर कार्य करना सीखें, और हमारा देश एक राष्ट्र बने, किन्तु भिन्न-भिन्न जातियों में इस प्रकार भेद बढ़ने से इस उद्देश्य का सफल होना असंभव है। इस प्रकार के भेदयुक्त चुनाव से न केवल प्रजा को हानि पहुँचेगी, अपितु गवर्नमेंट के काम में बाधा भी पड़ेगी। कौंसिलो में शान्ति से कार्य नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त जब मुसलमानों के ऊपर उनकी राजभक्ति आदि के विचार से विशेष कृपा की जायगी, तो आश्चर्य नहीं होगा कि यदि सिक्ख, पारसी आदि जातियाँ भी अपने को विशेष कृपापात्र दिखलाने के लिए अपने दावे पेश करें।^१

मार्ले-मिटो सुधार

सन् १९०९ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन कौंसिल एक्ट पास किया और सरकार ने इसके अधीन रेगुलेशन (नियम) पास किये। सुधारों की यह योजना मार्ले-मिटो-सुधारों के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस व्यवस्था में केन्द्रीय और प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिलो में गैर-सरकारी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी, और कौंसिलो के अधिकार भी विस्तृत कर दिये गये।

कौंसिलो को बिलो पर विचार करके अधिनियम पास करने, तथा वजत पर भाषण करते हुए सरकार की नीति-रीति की समीक्षा करने के अतिरिक्त, आयव्ययक की मदों और करो पर तथा सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर प्रस्ताव पास करने के भी अधिकार दे दिये गये। सार्वजनिक हित में प्रश्न पूछने के साथ साथ एक पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रश्नकर्ता को मिल गया। पर सार्वजनिक हित की रक्षा के नाम पर किसी प्रश्न को पूछने, और किसी प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत देने से इनकार किया जा सकता था।

केन्द्र की कौंसिल में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, पर बर्मा और पंजाब को छोड़कर अन्य सब प्रान्तों को कौंसिलो में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक कर दी गयी। पर बंगाल को छोड़कर अन्य सब प्रान्तों में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का बहुमत बना रहा। इस तरह प्रान्तीय कौंसिलो में शक्ति-सन्तुलन सरकार द्वारा मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों के हाथ में रहा। बंगाल की कौंसिल में शक्ति-सन्तुलन मनोनीत गैर-सरकारी

सदस्यों के साथ साथ निर्वाचित यूरोपियन सदस्यों के हाथ में था। मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य सदा से सरकार के इंगारे पर काम करते थे, यूरोपियन सदस्यों से भी सरकार की नीति-रीति के समर्थन की ही आशा की जा सकती थी।

निर्वाचित स्थानों में से अधिकांश को साम्प्रदायिक तथा आर्थिक हितों के आधार पर बाँट दिया गया। मुसलमानों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पृथक् प्रतिनिधित्व दे दिया गया, और उन्हें सामान्य स्थानों में भी चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया। व्यापारियों और जमींदारों को भी सामान्य चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की इजाजत देते हुए वर्ग-हितों के आधार पर पृथक् प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था कर दी गयी। सामान्य क्षेत्रों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति बनाये रखी गयी, अर्थात् प्रान्तीय कौंसिल के सामान्य स्थानों का चुनाव जिला बोर्डों और म्युनिसिपैलिटियों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा, तथा केन्द्रीय कौंसिल के सामान्य स्थानों का चुनाव प्रान्तीय कौंसिल के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा किया जाना चालू रहा।

नयी व्यवस्था में भी मतदान और सदस्यता के अधिकार पुरुषों तक सीमित थे। स्त्रियाँ न वोट दे सकती थी, न कौंसिल का सदस्य बन सकती थी। मताधिकार किसी व्यापक सिद्धान्त पर आधारित नहीं था। विभिन्न प्रान्तों तथा विभिन्न सम्प्रदायों के लिए मताधिकार की शर्तें भिन्न थी। जबकि मुसलमानों को जहाँ वे अल्प-संख्यक थे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक संख्या में कौंसिलों का सदस्य चुनने का अधिकार था, वहाँ यह अधिकार पंजाब में हिन्दुओं को जहाँ वे अल्पसंख्यक थे नहीं दिया गया था। इसी तरह मालगुजारी के चुनाव क्षेत्रों में हिन्दू और मुसलमान मतदाताओं की निर्धारित योग्यताओं में बहुत अन्तर था। उम्मीदवारी के लिए जो शर्तें लगायी गयी थी उनमें यह भी था कि (१) कोई वह व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकेगा जो सरकारी नौकरी से वरखास्त कर दिया गया हो, (२) जो वकालत करने से वंचित कर दिया गया हो, (३) जिसे किसी फौजदारी अदालत ने किसी ऐसे अभियोग में कैद की सजा दी हो जिसमें छ. महीने से अधिक का दण्ड या कालापानी की सजा दी जा सकती है, (४) जिसके सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार ने घोषित कर दिया हो कि उसकी ख्याति और पूर्वाचरण ऐसे हैं कि उसका निर्वाचन सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। ये चारो नियोग्यताएँ किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा हटायी भी जा सकती थी।

मालवीयजी का भाषण

दिसम्बर सन् १९०९ में मालवीयजी ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में नयी सुधार व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उन्होंने केन्द्रीय कार्यपरिषद् (एक्जीक्यूटिव कौंसिल) तथा बम्बई, मद्रास और बंगाल की कार्य परिषदों में भारतीय सदस्यों की नियुक्तियों का स्वागत किया और सरकार से माँग की कि अन्य प्रान्तों में भी कार्य परिषदें स्थापित की जायें और भारतीयों को उनका सदस्य नियुक्त किया जाय।^१ उन्होंने इसे उन प्रान्तों की जनता की उन्नति तथा स्वशासन के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि विकेन्द्रीकरण कमीशन ने स्वीकार किया है कि लेफ्टिनेंट-गवर्नर के लिए अकेले शासन का सारा बोझ बहन करना कठिन हो रहा है। कमीशन ने यह भी लिखा है कि प्रान्तीय शासन का सारा उत्तरदायित्व एक व्यक्ति को सौंप देना भी ठीक नहीं समझा जा सकता। कमीशन की सर्व-सम्मत सन्तुति पर अमल करना श्रेयस्कर है।^२

उन्होंने सुधार-व्यवस्था का वर्गीय विश्लेषण करते हुए बताया कि उसमें मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग के साथ, जिसने राजनीतिक सुधारों के लिए सबसे अधिक प्रयत्न किया है, न्याय नहीं किया गया है। उनकी उपेक्षा करते हुए जमींदारों को अधिक प्रतिनिधित्व देना सर्वथा अनुचित है। उन्होंने कहा कि “धन या आय का अधिकार निश्चित रूप से यह नहीं बतलाता कि मनुष्य योग्य है और आचरण की परीक्षा तो इससे बिलकुल ही नहीं हो सकती। यह स्वयं किसी मनुष्य में उसके साथियों का विश्वास पैदा नहीं करता।”^३ इस व्यवस्था के कारण तो, उन्होंने कहा “मिस्टर दादा भाई नौरोजी और मिस्टर गोखले जैसे नि स्वार्थ देशभक्त” भी प्रान्तीय कौंसिल के सदस्य नहीं हो सकते।^४ मालवीयजी ने प्राचीन विधिकर्ता मनु का एक श्लोक उद्धृत करते हुए कहा कि इस चिर सम्मानित शिक्षा के अनुसार विद्या सबसे ऊँची योग्यता है और धन का स्वामित्व सबसे नीची है। रेगुलेशन ने इस क्रम को बदल ही नहीं डाला है, वरन् विद्या को योग्यता की श्रेणी से निकाल दिया है।^५

मुसलमानों के लिए की गयी व्यवस्था की आलोचना करते हुए मालवीयजी ने कहा कि हम मुसलमानों के लिए किसी मात्रा में प्रतिनिधित्व की गारंटी देने

१. रिपोर्ट, ट्वेंटीफोर्थ इन्डियन नेशनल कांग्रेस, १९०९, पृ० २४-२५।

२. वही, पृ० २५।

३. वही, पृ० २८।

४. वही, पृ० २९।

५. वही, पृ० २९।

को तैयार थे, और इस व्यवस्था के लिए भी तैयार थे कि यदि सर्वसाधारण चुनाव द्वारा किसी कारण से निश्चित संख्या में उनका चुनाव न हो पाये, तो विशेष मुस्लिम चुनाव क्षेत्रों द्वारा इस कमी को पूरा कर लिया जाय। पर रेगूलेशन्स ने मुसलमानों को पृथक् साम्प्रदायिक क्षेत्रों द्वारा अपनी आवादी के अनुपात से अधिक सीटें ही प्रदान नहीं की हैं, बल्कि उन्हें सर्वसाधारण चुनाव द्वारा भी सीटें प्राप्त करने की इजाजत दे दी है। इस प्रकार से मुसलमानों को अत्यधिक प्रतिनिधित्व देना न्यायसंगत और उचित नहीं है।^१ उन्होंने पूछा कि जब अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना उचित समझा गया, तब क्या कारण है कि पंजाब तथा 'पूर्वी बंगाल और आसाम' के अल्पसंख्यक हिन्दुओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी?^२

उन्होंने यह भी पूछा कि जब सरकार ने मुसलमानों को सीधा प्रतिनिधित्व देना निश्चित किया, तब इतर जातियों को भी उतना ही न्यायपूर्ण और उदार प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया?^३ उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सबके लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाय और उन सबको जो आय-कर देते हैं, वोट देने का अधिकार दिया जाय।^४

“सम्प्रदाय और सम्पत्ति पर आधारित निर्वाचन पद्धति का विरोध”, उन्होंने कहा, “कांग्रेस इसलिए नहीं करती कि वह चाहती है कि मुसलमान और भूमि-पति प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सकें। बल्कि उसका विचार है कि चूँकि विधान कौंसिलो को ऐसे प्रश्नों पर विचार करना होगा जो सभी वर्गों, और मतों के लिए समान हित के हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधियों को सभी वर्गों, जातियों की सम्मिलित राय से निर्वाचित होना चाहिए। उनके प्रति देशवासियों के विश्वास का आधार उनमें लगन के साथ जनता के हितों की रक्षा और उन्नति करने की योग्यता, बुद्धिमत्ता और आचरण होगा, न कि उनका किसी विशेष धर्म से सम्बन्ध या कई एकड़ भूमि का उत्तराधिकारी होना।”^५

चुनाव सम्बन्धी नियमों की समीक्षा करते हुए मालवीयजी ने अयोग्यता सम्बन्धी धाराओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कई प्रान्तों में सर्वसाधारण सीटों से प्रान्तीय कौंसिल बनने के लिए किसी म्युनिसिपल बोर्ड (नगरपालिका) या जिला बोर्ड का सदस्य होना जरूरी करार दिया गया है,

१. वही, पृ० २७।

२. वही, पृ० २७।

३. वही, पृ० २७-२८।

४. वही, पृ० २७।

५. वही, पृ० २९-३०।

इस व्यवस्था के कारण बहुत से योग्य व्यक्ति कौंसिल के सदस्य बनने से वंचित हो गये हैं, और बहुत से स्थानों पर उन्हें जिला बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों का मनोनीत सदस्य बनना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह वे सब लोग, जो किसी कारण से सजा पाये हैं या सरकारी नौकरी से बर्खास्त किये गये हैं, कौंसिल की सदस्यता से वंचित कर दिये गये हैं। यह व्यवस्था भी, उन्होंने कहा, सर्वथा अनुचित है। नैतिक अवोगति का अपराध ही इस अयोग्यता का मूलधार होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों और सम्प्रदायों के नागरिकों के लिए वोट देने की विभिन्न योग्यताओं की व्यवस्था भी न्यायोचित नहीं समझी जा सकती। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को सदस्यता के अयोग्य घोषित करने का जो अधिकार प्रान्तीय गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों को दिया गया है वह तो सर्वथा अनुचित और अन्याय है। इस प्रकार की व्यवस्था से लाभ उठाकर बम्बई प्रान्त के गवर्नर ने श्री एन सी. केलकर जैसे सम्मानित व्यक्ति को प्रान्तीय कौंसिल की सदस्यता से वंचित कर दिया था, और यदि यह व्यवस्था बनी रही तो भविष्य में भी इसका इसी प्रकार दुरुपयोग हो सकता है।^१

मालवीयजी ने कहा कि प्रान्तीय कौंसिलों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत तो 'शून्य में परिणत कर दिया गया है।'^२ गैर-सरकारी मनोनीत सदस्य तो सदा सरकार का साथ देते हैं। युक्त प्रान्त के लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर जान हेवट ने जिन छः सज्जनों को मनोनीत किया है उनमें तीन नवाब रामपुर, राजा साहब टेहरी और महाराजा बनारस हैं। वे ब्रिटिश भारत की समस्याएँ कब अध्ययन करते हैं, और यदि उन्होंने किसी मामले में कोई राय बना भी ली हो, तो भी वे उसे उस समय तक व्यक्त नहीं कर सकते जब तक वह सरकार की राय से मेल न खाती हो।^३ 'ब्रिटिश सरकार की किसी प्रजा को इन लोगों के मामलों के प्रबन्ध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तब इन चीफ्स को ब्रिटिश भारतीय सरकार की प्रजा की भलाई और बुराई से सम्बन्धित विधेयक के विचार-विमर्श या दूसरे विवाद में राय देने का अधिकार देना किस तरह न्यायसंगत है?'^४ इस प्रकार की व्यवस्था ने प्रान्तीय कौंसिलों को सलाहकार कौंसिलों के सदृश बना दिया है।^५ उन्होंने कहा कि मुसलमानों और जमींदारों के अत्यधिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षित वर्गों के सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ने शिक्षितों की इन माँग को कि अपने देश के शासन में जनता के निर्वाचित

१ वही, पृ० २८-३०।

२ वही, पृ० ३०।

३ वही, पृ० ३१।

४ वही, पृ० ३१।

५ वही, पृ० ३०।

सदस्यों को प्रभावकारी अधिकार प्राप्त हो, निरर्थक बना दिया है।^१ योजना के अन्दर बनाये गये रेगुलेशन्स, मालवीय जी ने कहा, योजना की भावना के बहुत हद तक विपरीत है। “वे अनुदार और किसी अंश में प्रतिगामी है।”^२ शिक्षित समाज बहुत क्षुब्ध है, और उसका संशोधन नितान्त आवश्यक है। वाइसराय ने अपने एक भाषण में कहा कि वे अनुभव के आलोक में संशोधित कर दिये जायेंगे। पर बिना किसी व्यावहारिक अनुभव के भी उनकी बहुत सी बुराइयाँ दूर की जा सकती है। तब व्यापक असन्तोष दूर करने के लिए, तथा जनता और सरकार में सद्भावना को बढ़ाने के लिए क्या यह अच्छा नहीं होगा कि शीघ्र ही इस बात की घोषणा की जाय कि रेगुलेशन्स के विरुद्ध आपत्तियों पर विचार किया जायगा।^३

मालवीयजी ने अपने अव्यक्षित भाषण में अराजकता के क्रियाकलापों की निन्दा करते हुए कहा कि इस प्रकार की राजनीतिक हत्याओं से “देश को कभी कोई लाभ नहीं हुआ है।” वरन् वे ‘बहुत हानि’ पहुँचा रही है। शास्त्रों ने इनकी निन्दा की है और वे हमारी श्रेष्ठ परम्पराओं के विरुद्ध है।^४ नवयुवकों को कुमार्ग से बचाने का प्रयत्न होना ही चाहिए। पर उसके लिए व्यापक असन्तोष को दूर करना भी जरूरी है।

उन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए माँग की कि बंगला भाषा-भाषी क्षेत्रों का एक प्रान्त में एकीकरण किया जाय, और उनके साथ न्याय करके जनता के क्षोभ और असन्तोष को शान्त किया जाय।^५

उन्होंने सन् १८१८ के अधिनियम न० ३ को “विधिविहीन संहिता”^६ बताते हुए उसके अन्दर लाला लाजपतराय तथा सरदार अजीत सिंह के निर्वासन की निन्दा की। उन्होंने कहा कि उन लोगों को, जो शान्तिमय और गौरवपूर्ण जीवन बिता रहे हो, उनके पीठ पीछे लगाये आरोपों को सुनने और उत्तर देने का अवसर दिये बिना रेगुलेशन के अन्दर दूसरे प्रदेशों में निर्वासित कर देने और जेल में बन्द करने की प्रक्रिया ब्रिटिश सरकार के लिए प्रशंसनीय नहीं है, और उसे यथासम्भव शीघ्रता से बन्द कर देना चाहिए।^७

१. वही, पृ० ३२।

२. वही, पृ० ३३।

३. वही, पृ० ३३।

४. वही, पृ० ३९।

५. वही, पृ० ४०।

६. वही, पृ० ३९।

७. वही, पृ० ४०।

गरीबी

मालवीयजी ने बढ़ती हुई गरीबी और महँगाई की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उसे दूर करने के लिए प्रयत्न करने की माँग की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहले से अधिक समृद्ध जरूर हो गये हैं, पर अधिकांश जनता अब भी 'भुखमरी के छोर पर दुःखमय जीवन' व्यतीत कर रही है और इस दयनीय दशा के कारण प्लेग, ज्वर आदि का शिकार हो रही है, बढ़ती हुई महँगाई के कारण जनता की कठिनाइयाँ और भी बढ़ गयी हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता के स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, तथा राष्ट्र की समृद्धि की वृद्धि के लिए समुचित प्रयत्न करे।^१

शिक्षा

उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की त्रुटियों की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि अधिकांश जनता अब भी अशिक्षित है, और उसका अज्ञान उन्नति में बाधक है। सरकार ने वायदा किया था कि प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क कर दी जायगी, पर अभी तक इस वायदे को पूरा नहीं किया गया है। जबकि इंगलिस्तान में सन् १८७० में ही प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बना दी गयी है, हिन्दुस्तान किस कारण से इस व्यवस्था के लाभ से वंचित रखा जा रहा है? उन्होंने औद्योगिक और शिल्प शास्त्र सम्बन्धी शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय बुद्धि और पराक्रम में किसी से कम नहीं है, पर शिल्प ज्ञान की कमी के कारण वे विदेशी औद्योगिकों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं।^२

प्रशासनिक सुधार

मालवीयजी ने जनता की दशा को सुधारने के लिए प्रशासनिक और सैनिक व्यय को कम करने पर, तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की दशा तब तक नहीं सुधर सकती जब तक राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग जनता के हित से सम्बन्धित कामों में प्रान्तीय सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। उन्होंने माँग की कि चूँकि भारत में इतनी बड़ी सेना भारत की रक्षा के अतिरिक्त ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य प्रयोजनों के लिए भी रखी गयी है, इसलिए उसके व्यय का कुछ भाग ब्रिटेन के राजकोष को भी वहन

करना चाहिए ।^१ उन्होंने सेना के भारतीयकरण को नितान्त आवश्यक बताते हुए सेना के ऊँचे पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने का अनुरोध किया । उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से “सम्राट् की महत्त्वपूर्ण प्रजा को स्वाभाविक और बुद्धिसंगत आकांक्षाओं को सन्तुष्ट करने का दरवाजा खुलेगा ।”^२

दक्षिण अफ्रीका

मालवीयजी ने दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले भारतीयों की दयनीय दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए उनके प्रति वहाँ की सरकार और गोरी जनता के “अन्यायपूर्ण, क्रूर और निन्दनीय”^३ व्यवहार की भर्त्सना की । उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को जो अपमान और कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं, उन्होंने सारे देश में, हर वर्ग के लोगों में, “रोष और शोक की गहरी भावनाएँ उत्तेजित की हैं”^४ । जिस “निर्भीक साहस और अनन्य दृढ़ता” से गांधीजी और उनके साथी भारत की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वह अवश्य ही बहुत प्रशंसनीय है ।^५ हमारी सहानुभूति उनके साथ है । हम ब्रिटिश सरकार से माग करते हैं कि भारतीय आप्रवासियों के साथ मानुषिक व्यवहार करने के लिए वह दक्षिण अफ्रीका की सरकार को बाध्य करे ।^६ उन्होंने भारत सरकार से माग की कि जब तक दक्षिण अफ्रीका के गोरे औपनिवेशिक भारतीयों को समान नागरिक मानने को तैयार न हो, तब तक दक्षिण अफ्रीका के लिए भारतीय श्रमिकों की भरती बन्द कर दी जाय ।^७

कांग्रेस

मालवीयजी ने काफ़ी विस्तार के साथ कांग्रेस के उद्देश्यों का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने की अपील की । उन्होंने कहा “एकता में ही आशा और देश का सुखद भविष्य निहित है ।”^८ जहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं में बहुधा मतभेद हो जाता है, पर उसकी ‘उपेक्षा’ करते हुए सब सच्चे और उत्साही देशभक्तों को सर्वमान्य उपायों द्वारा सार्वजनिक लक्ष्यों की सिद्धि के सामूहिक प्रयत्नों में मिलकर काम करना चाहिए ।^९

१. वही, पृ० ३५-३६ ।

३. वही, पृ० ३७ ।

५. वही, पृ० ३७ ।

७. वही, पृ० ३८ ।

९. वही, पृ० ४४ ।

२. वही, पृ० ३७ ।

४. वही, पृ० ३७ ।

६. वही, पृ० ३७-३८ ।

८. वही, पृ० ४४ ।

राष्ट्रीय एकता

मालवीयजी ने समता के आधार पर संयुक्त राष्ट्रीयता के विकास पर जोर देते हुए कहा : “किसी हिन्दुस्तानी को, चाहे वह हिन्दू, मुसलमान या पारसी हो, अपने को देशभक्त कहाने का गौरव प्राप्त नहीं होगा, जो एक क्षण के लिए भी चाहता है कि उसका कोई देशवासी, चाहे वह किसी प्रजाति या धर्म का हो, उसके विश्वास के लोगो के शासन में हो या कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय या समुदायों पर श्रेष्ठता प्राप्त करे। देशभक्ति की माग है कि हम अपने सब देश-भाइयों का समान रूप से हित चाहें।”^१ उन्होंने कहा कि वेद व्यासजी ने ‘सब धार्मिक और देशभक्त कार्यकर्ताओं के लिए श्रेष्ठ आदर्श’^२ एक प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत किया है। वेद व्यासजी कहते हैं :—

“सर्वे च सुखिन. सन्तु सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्” ॥

अर्थात् सब सुखी हो, सब दूसरों के लिए सुख का स्रोत बनें, सबका कल्याण हो, किसी को कोई दुःख न हो।^३

उन्होंने मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे पार्थक्य की नीति को त्याग कर देशभक्ति के उच्च आदर्श को अपनायें, जिसके द्वारा हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई भाई-भाई की तरह कन्धा मिलाकर सबके साथ सबके समान हित के लिए काम करें।^४

उन्होंने मुसलमानों को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस सब के साथ न्याय चाहती है, और यदि किसी हिन्दू को मुसलमान पर तरजीह दी जाती है इसलिए नहीं कि वह बढ़िया योग्यता रखता है बल्कि इसलिए कि वह हिन्दू है, तब यह मुसलमानों की शिकायत का न्याय-सगत आधार है, और मुसलमान ही नहीं बल्कि सब जातियाँ कांग्रेस के सिद्धान्तों से हटे बिना इसका विरोध करने की हकदार हैं।^५

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सरकार की पक्षपात की नीति से, तथा मुसलमानों की पार्थक्य की नीति से हिन्दुओं की कुछ हानि हुई है, और वे सरकार के पक्षपात का विरोध करने का हक रखते हैं। पर उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिन्दू पार्थक्य की नीति को नहीं अपनायेंगे, अपने आदर्शों से विमुख नहीं

१. वही, पृ० ४४ ।

२. वही, पृ० ४४ ।

५. वही, पृ० ४५ ।

२. वही, पृ० ४४ ।

४. वही, पृ० ४४ ।

होगे, वे ऐक्य के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, संकीर्ण साम्प्रदायिक ईर्ष्या के बजाय न्याय की दृष्टि से पक्षपात का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि वे आशा करते हैं कि देश के कुछ भागों में जो अल्पकालिक असुविधा (हानि) हिन्दू भाइयों को हो रही है, वह उन्हें कर्तव्य, समझदारी और सम्मान के उस पथ से जिसे कांग्रेस ने सब देशभक्त हिन्दुस्तानियों के लिए अनुसरण करने को प्रस्तुत किया है, विचलित होने को प्रेरित नहीं करेगी।^१

उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि "पक्षपात-पूर्ण व्यवहार तथा दूसरी सब अडचनें जो भारत के विभिन्न सम्प्रदायों को अलग कर रही हैं, धीरे धीरे, पर स्थिर गति से दूर होगी तथा ईश्वर के निर्देशन में हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों में देशभक्ति और बन्धुत्व की भावनाओं की वृद्धि होती जायगी, और वह दिन आयेगा जब ये भावनाएं सब सम्प्रदायों के लोगों को एक बड़े और सयुक्त राष्ट्र में एक करते हुए एक शान्त और महान् नदी की तरह बहेंगी।"^२

कांग्रेस अधिवेशन के अन्त में धन्यवाद के वोट का उत्तर देते हुए उन्होंने सरकार से फिर अपील की कि वह और उसके कर्मचारी भारतीयों के उद्देश्यों और अभिलाषाओं के प्रति विरोध की भावना का परित्याग करें और उन्हें उनकी पूर्ति में समुचित सहायता प्रदान करें। उन्होंने इस अवसर पर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया कि वे संवैधानिक आन्दोलन को और तेज करके उसके द्वारा राष्ट्रीय मांगों के पक्ष में विवेकशील और सबल जनमत तैयार करें, तथा सरकार की सहायता पर ही निर्भर न रहकर अपने स्वतन्त्र प्रयत्नों द्वारा देश की दशा सुधारने का प्रयत्न करें।^३ उन्होंने कहा कि स्वदेशी का प्रचार, शिक्षा का प्रसार, नगरों और गांवों की सफाई, देशज उद्योगों का विकास आदि बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे हम स्वयं देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं।^४ उनकी धारणा थी कि "यदि हम अपनी देशभक्ति को कुछ अधिक सक्रिय कर लें और देश की सेवा में अधिक निष्ठा से जुट जायें, तो हम अपने देश को अधिक समृद्धिशाली बना सकते हैं,"^५ हमारे प्रयत्नों द्वारा हमारा देश समुन्नत राष्ट्रों में समान और सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा : "हमारे धर्म हमें बताते हैं कि मनुष्यों की सेवा द्वारा ही ईश्वर की सेवा

१. वही, पृ० ४५।

२. वही, पृ० ४६।

३. वही, पृ० १२९।

४. वही, पृ० १२९।

५. वही, पृ० १२९।

सर्वोत्तम है", और आशा व्यक्त की कि इसका ध्यान रखते हुए हम निष्ठा के साथ जनता की सेवा में तथा देशोन्नति के कार्यों में जुट जायेंगे।^१

उन्होंने इस अवसर पर यह स्वीकार करते हुए कि विद्यार्थियों को राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए, शिक्षा विभाग की उन आज्ञाओं और विज्ञप्तियों की भर्त्सना की जो विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भाषण सुनने के लिए सार्वजनिक सभाओं में जाने पर भी रोक लगाती थी। मालवीयजी ने कहा कि राजनीति का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नेताओं का भाषण सुनना अवश्य ही लाभप्रद है। नवयुवकों में देशभक्ति का संचार नितान्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उस शिक्षा का क्या लाभ जो विद्यार्थियों में देश-भक्ति भी संचरित न कर सके ?

अन्त में उन्होंने स्वागत समिति तथा कार्यकर्त्ताओं और स्वयंसेवकों को धन्यवाद देते हुए अधिवेशन समाप्त किया।

कांग्रेस में प्रस्ताव

दूसरे दिन श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने विषय समिति की ओर से कौंसिलो की नयी व्यवस्था के सम्बन्ध में खुले अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया। इसमें कांग्रेस ने इस देश की जनता के लिए उदार सवैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में लार्ड मार्ले और लार्ड मिंटो के प्रयत्नों के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हुए दुःख के साथ रेगुलेशन्स को नापसन्द किया। प्रस्ताव में कहा गया कि रेगुलेशन्स में लार्ड मार्ले की गतवर्ष की विज्ञप्ति की उदारभावना का अभाव है। धर्म पर आधारित निर्वाचन पद्धति की विशेष रूप से निन्दा की गयी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि नीचे लिखे पाँच कारणों से नये नियमों और रेगुलेशन्स ने देश में व्यापक असन्तोष पैदा कर दिया है—

१. एक विशिष्ट धर्म के अनुयायियों को प्रतिनिधित्व में अत्यधिक और अनुचित रूप से गुस्तर भाग दिया जाना।

२. निर्वाचन पद्धति, मताधिकार और उम्मीदवारों की योग्यता के सम्बन्ध में सरकार द्वारा मुसलमान और गैर-मुसलमान प्रजाओं में अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण अनुचित भेद करना।

३. कौंसिलो के उम्मीदवारों पर व्यापक, मनमानी, अनुचित अयोग्यताओं और प्रतिबन्धों को लगाना।

४. शिक्षित वर्गों पर व्यापक रूप से अविश्वास करना।

५. प्रान्तीय कौंसिलो मे गैर-सरकारी सदस्यो के लिए प्रभाव-हीन तथा वास्तविकता-विहीन बहुमत की व्यवस्था करना ।

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने मालवीयजी की तरह रेगुलेशन्स की कड़ी आलोचना और निन्दा की । उन्होने कहा कि नियमो और रेगुलेशन्स ने राजनीतिक सुधारो की योजना को बरवाद कर दिया है । उन्होने कहा कि उनकी राय में इसका उत्तरदायित्व नौकरशाही पर है, जिसने हम (शिक्षित वर्ग) से, जिन्होने राजनीतिक सुधारो के लिए प्रयत्न किया था, बदला लिया है । उन्होने कहा कि गैर-सरकारी सदस्यो का बहुमत तो केवल 'भ्रामक' है, क्योंकि गैर-सरकारी मनोनीत सदस्य तो सदा सरकार के पक्ष में ही राय देते हैं । उन्होने बहुत क्षोभ से कहा कि उम्मीदवारी की अयोग्यताओ ने तो बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियो को कौंसिल की सदस्यता से वंचित कर दिया है । पर उन्होने अन्त में कहा कि इस निराशा के मध्य में भी हमें अपने राष्ट्रोत्थान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने सैवधानिक और न्याय-संगत उपायो की निर्णायक विजय पर अत्यन्त अटल विश्वास बनाये रखना चाहिए । प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

कांग्रेस ने अपने इस अधिवेशन में श्री सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा को गवर्नर-जनरल की कार्यपरिषद् का, तथा मिस्टर अमीर अली को प्रिवी कौंसिल का सदस्य नियुक्त किये जाने पर सम्राट् की सरकार को धन्यवाद दिया । उसने माँग की कि मध्य प्रदेश और बरार में भी प्रान्तीय विधान कौंसिलें स्थापित की जायें, तथा संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बर्मा तथा पूर्वी बंगाल और आसाम में प्रान्तीय कार्यपरिषद् गठित की जायें ।

पंजाब से संबंधित रेगुलेशनों की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने कहा कि ये सन्तोषजनक नहीं हैं, क्योंकि इनमें (१) कौंसिल के सदस्यो की संख्या बहुत ही अपर्याप्त है, (२) निर्वाचित सदस्यो की संख्या तो और भी कम है, (३) अल्प-संख्यक मुसलमानो की संरक्षा का सिद्धान्त जो दूसरे प्रान्तो में लागू किया है, यहाँ गैर-मुसलमानो के लिए लागू नहीं किया गया है, और (४) केन्द्रीय कौंसिल में पंजाब के गैर-मुसलमानो का चुनाव संभव नहीं है ।

कांग्रेस ने इस अधिवेशन में बंगभंग के विरुद्ध तथा स्वदेशी के पक्ष में प्रस्ताव पास किये, और माँग की कि पंजाब की भूमि-व्यवस्था की जाँच के लिए एक कमेटी नियुक्त की जाय । उसने यह भी माँग की कि निष्कासन सम्बन्धी पुराने रेगुलेशन रद्द किये जायें, निष्कासितो को छोड़ा जाये तथा न्यायपालिका को शासनपालिका से अलग किया जाय ।

उसने यह भी माँग की कि महँगाई के कारणों पर जाँच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाय, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाय, उत्तर पश्चिमी प्रान्त की जनता की शिकायतों की जाँच के लिए कमेटी नियुक्त की जाय। कांग्रेस की यह भी माँग थी कि इस देश में उच्चस्तरीय सैनिक कालेज खोले जायें, सिविल सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षाएँ भारत में भी हो, और ऊँचे सैनिक और असैनिक पदों पर भारतीय नियुक्त किये जायें। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के आन्दोलन के पक्ष में भी एक प्रस्ताव पास किया गया।

मालवीयजी की सद्भावना

फूट, कटुता और सघर्ष की स्थिति में भी क्रान्तिकारियों और उग्रवादियों के प्रति मालवीयजी की कितनी सद्भावना थी, इस बात का पता नीचे लिखे उदाहरणों से लगाया जा सकता है।

केलकर साहिब ने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब सन् १९०८ में वे लोकमान्य तिलक के आदेश पर युक्त प्रान्त के राजनीतिक सम्मेलन की गति-विधि देखने गये, तब उनका मिशन स्पष्ट शब्दों में एक राजनीतिक विरोधी का था, क्योंकि पंडित जी (मालवीय जी) नरमदलीय नेताओं में गिने जाते थे, और वे अपना सारा प्रभाव तिलक के विरुद्ध अपने मित्र माननीय गोखले के पक्ष में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने मेरे साथ अपार सौजन्य का व्यवहार किया, यद्यपि वे चाहते तो मुझे निकाल सकते थे।^१

जब सन् १९०९ में कतिपय क्रान्तिकारियों की भर्त्सना के लिए प्रान्तीय सरकार ने एक सभा आयोजित की, और मालवीयजी आतंक के विरुद्ध बोलने को आगन्त्रित किये गये, तब उन्होंने अधिकारियों के सभावित रोष की उपेक्षा करते हुए स्पष्ट कह दिया कि वे उस समय तक क्रान्तिकारियों के विरुद्ध कुछ कहने को तैयार नहीं हैं, जब तक उस सभा में उन्हें सरकार की उस गतिविधि की आलोचना करने का मौका न हो जिसके कारण क्रान्तिकारी भावनाएं प्रज्ज्वलित होती हैं। प्रान्त के गवर्नर ने उनकी कड़ी आलोचना की, पर मालवीयजी ने इसकी कोई परवाह नहीं की।

१ केलकर साहब के संस्मरण: मालवीय कोमेमोरेशन वॉल्यूम : सन् १९३५, पृ० १०३०। (इस संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि वे इलाहाबाद प्रान्तीय राजनीतिक कान्फ्रेंस में गये, पर प्रयाग के बजाय उन्हें लखनऊ लिखना चाहिए था, क्योंकि प्रयाग सम्मेलन तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन से पहले हुआ था। सन् १९०८ में कांग्रेस के नये विधान के अनुसार प्रान्तीय सम्मेलन लखनऊ में ही मालवीयजी की अध्यक्षता में हुआ था।)

इसी तरह जब सन् १९०९ में प्रयाग के 'स्वराज्य' नाम के उर्दू पत्र के आठ सम्पादक दस महीने के अन्दर राजद्रोह में फास लिये गये, तब मालवीयजी ने उन्हें आर्थिक सहायता दी, तथा श्री पुरुषोत्तमदास टंडन से उनकी वकालत करने को कहा और जेल में पड़े हुए सम्पादकों के परिवारों का पोषण किया। मालवीयजी के कुछ मित्रों को यह बात अच्छी नहीं लगी। तब मालवीयजी ने उनसे कहा "मैंने जो कुछ किया है, वह इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता दृढ़ करने के लिए किया है। यदि मैं ऐसा न करता तो मैं विचार-स्वातन्त्र्य समाप्त करने के दोष का भागी होता। जहां तक इन नवयुवकों की सहायता की बात है, मैं कैसे न करता? क्या कोई पिता अपने पुत्रों को मतभेद के कारण छोड़ता है, विशेषतः उन पुत्रों को जिनकी देशभक्ति चमचमाते हुए स्वर्ण के समान समुज्ज्वल हो? मैं यह पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता कि द्रोणाचार्य के समान अभिमन्यु की हत्या के दोष का भागी बनूं।"^१

युक्त प्रान्त के क्रान्तिकारियों को भी मालवीयजी की सद्भावना का कितना अहसास था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सन् १९६२ में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता योगेशचन्द्र चटर्जी ने, जबकि वे राज्य सभा के सदस्य थे, इस पुस्तक के लेखक से क्रान्तिकारियों के प्रति मालवीयजी की सहानुभूति की प्रशंसा करते हुए कहा था कि युक्तप्रान्त में मालवीयजी क्रान्तिकारियों के सबसे बड़े हमदर्द थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने जिस दूसरे व्यक्ति का नाम लिया वह आचार्य नरेन्द्रदेव थे। मनमाड बम केस के वीर क्रान्तिकारी मनमोहन गुप्त आदि ने भी क्रान्तिकारियों के प्रति मालवीयजी की सहानुभूति के लिए कृतज्ञता प्रकट की है।^२

इस सबसे यह स्पष्ट है कि यद्यपि मालवीयजी क्रान्तिकारियों के क्रिया-कलापों को ठीक नहीं समझते थे, तथापि वे उनकी देशभक्ति और आत्म-बलिदान की भावना की कद्र करते थे, और उनसे मतभेद रखते हुए भी उनके और उनके परिवारों को उनके कष्टों में सहायता करना अपना कर्तव्य समझते थे। वे क्रान्तिकारियों के क्रियाकलापों पर खेद प्रकट करते समय सरकार की निरंकुशता और जनहित के प्रति उसकी उपेक्षा को आलोचना भी जरूरी समझते थे। वे सरकार की नीतिरिति को ही असन्तोष और क्रान्तिकारी क्रियाकलापों का मूल कारण मानते थे, तथा निरंकुशता और दमन का त्याग शान्ति और सुव्यवस्था के लिए आवश्यक समझते थे।

१. सीताराम चतुर्वेदी . महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, खंड १, पृ० २३।

२. मालवीयजी . जीवन शलकियाँ, पृ० ३२, ३४।

६. प्रान्तीय कौंसिल में कार्य

सन् १९०३-१९१२

कौंसिलो की गतिविधि

सन् १९०२ में मालवीयजी दो वर्ष के लिए युक्तप्रान्त की कौंसिल के सदस्य चुने गये। इसके बाद बराबर चुने जाने पर उन्होंने सन् १९०३ से सन् १९१२ तक वहाँ निर्वाचित सदस्य की हैसियत से काम किया। कौंसिल के अधिकार बहुत ही सीमित थे। प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्रान्तीय कौंसिल में बहुत ही कम विधेयक प्रस्तुत किये जाते थे। इसलिए सदस्यों को उन पर बहस करने के भी कम अवसर प्राप्त होते थे। प्रतिवर्ष वित्तीय वक्तव्य (बजट की रूपरेखा) कौंसिल में सरकार द्वारा पेश किया जाता था, और उस समय निर्वाचित सदस्यों को प्रशासन की गतिविधि पर अपने विचारों को व्यक्त करने का सरकार द्वारा काफी अवसर दिया जाता था। उसी अवसर पर मालवीयजी आदि प्रगतिशील सदस्य सरकार की नीतिरीति तथा क्रियाकलापों की समीक्षा करते हुए जनता की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करते थे। युक्त प्रान्तीय कौंसिल की कार्यवाही के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि युक्त प्रान्तीय कौंसिल में मालवीयजी ने ही इस अवसर का सबसे अधिक उपयोग किया।

वित्तीय व्यवस्था

सन् १९०४ की वित्तीय व्यवस्था की आलोचना करते हुए मालवीयजी ने कहा कि वह किसी 'न्यायसंगत नियम' पर आधारित नहीं है और उसके द्वारा युक्त प्रान्त के प्रति बरते जानेवाले अन्याय का निराकरण नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत बम्बई और बंगाल की सरकारों को इन प्रदेशों में अर्जित राजस्व का ६४ और ५३ प्रतिशत प्रदान किया गया है। पर युक्त प्रान्त में अर्जित राजस्व का ४३ प्रतिशत ही इस प्रान्त की सरकार को दिया गया है। इसी तरह मद्रास, बम्बई और बंगाल को ५० लाख रुपये एक-मुश्त दिये गये हैं, जबकि युक्त प्रान्त को केवल ३० लाख रुपये ही दिये गये हैं।

इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण अन्य प्रादेशिक सरकारों की तुलना में युक्त प्रान्त की सरकार की दशा अधिक गम्भीर और शोचनीय है।^१

मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि प्रति हजार जनसंख्या पर जबकि बम्बई सरकार २५३ रुपये शिक्षा पर खर्च करती है, युक्त प्रान्त की सरकार केवल ९१ रुपये खर्च कर पाती है, और घन की कमी के कारण उसकी शिक्षा सम्बन्धी योजनाएँ बेकार पड़ी रहती हैं। परिणाम यह है कि जबकि बम्बई प्रान्त और बंगाल में २२-२३ प्रतिशत बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, युक्त प्रान्त में १० प्रतिशत बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं।^२

इसी तरह प्रतिवर्ष जनता की चिकित्सा पर युक्त प्रान्त में १८ लाख ६५ हजार रुपये खर्च होते हैं, पर मद्रास में, जिसकी जनसंख्या युक्त प्रान्त से ८० लाख कम है, ३४ लाख ६६ हजार रुपये खर्च किये जाते हैं, और बम्बई प्रदेश में, जिसकी जनसंख्या युक्त प्रान्त की जनसंख्या की तुलना में आधी से भी कम है, २५ लाख १५ हजार रुपये खर्च होते हैं।^३

इस अन्यायपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मालवीयजी ने माँग की कि युक्त प्रान्त के साथ भी बम्बई और बंगाल जैसा व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने यह भी माँग की कि जनता की अभिवृद्धि के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को राजस्व में प्रान्तीय सरकारों का हिस्सा बढ़ा देना चाहिए। उन्होंने माँग की कि भूराजस्व (माल गुजारी) का ३।८ के बजाय आधा हिस्सा प्रान्तीय सरकारों को दिया जाय।^४

लगान में कमी

‘बुन्देलखण्ड भूमि-हस्तान्तरण विधेयक’ पर बोलते हुए मालवीय जी ने कहा कि लगान का अधिक निर्धारण तथा उसकी उगाही ही किसानों पर कर्जों के बोझ के मुख्य कारण है। लगान में कमी करके और उसे सुविधा-जनक समय पर वसूल करके ही किसानों के कष्ट दूर किये जा सकते हैं, हस्तान्तरण पर प्रति-बन्ध लगाकर उन्हें दूर नहीं किया जा सकता।^५

१. दी आनरेबिल पंडित मदनमोहन मालवीय : लाइफ एण्ड स्पीचेज, सेकेण्ड एडिशन, पृ० ३२७-३३१।

२. वही, सन् १९०४, पृ० ३३५, सन् १९०८, पृ० ४७२।

३. वही, सन् १९०८, पृ० ४७२।

४. वही, सन् १९०४, पृ० ३२४-३३२, पृ० ४४५, पृ० ४७०-४७२।

५. वही, सन् १९०३, पृ० २८३-२८९।

मालवीय जी ने सन् १९०७ में बताया कि सन् १८८८ में लार्ड डफरिन के आदेश पर इस प्रान्त के मजदूरो और किसानों की आर्थिक स्थिति की जो जाँच की गयी उससे पता चला कि उनकी दशा बहुत ही असन्तोषजनक है और वह पहले से भी कही खराब है।^१ उन्होंने कहा कि यह मानने का कोई ठोस कारण नहीं कि पिछले पच्चीस-तीस वर्षों में उनकी दशा में कोई सुधार हुआ है।^२ किसानों की दशा को सुधारने के लिए लगान में कमी करने की माँग करते हुए उन्होंने बताया कि सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स) के भूतपूर्व डाइरेक्टर-जनरल ओकोनर का सुझाव था कि किसानों पर लगान का बोझ पच्चीस-तीस प्रतिशत कम किया जाय ताकि वे सुविधा से अपना जीवन निर्वाह कर सकें।^३ मालवीय जी ने बताया कि सन् १९०१ के अकाल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में लगान में कमी करने की सन्तुति करते हुए लिखा है : “अकाल की रोक के लिए कोई दूसरी बात इतनी लाभदायक नहीं हो सकती जितनी किसानों की आर्थिक दशा में सुधार, ताकि वे कठिन समय की विपत्ति को सहन करने योग्य बनाये जा सके, और इस सुधार में कोई बात इतनी बाधक नहीं जितनी ऐसी कृषि-व्यवस्था जिसके अन्दर किसान अपने उद्योग का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पाते और उन्हें कर्ज की स्थिति में रहना पड़ता है।”^४

मालवीय जी ने माँग की कि किसानों पर से लगान के बोझ को कम किया जाय। उसे पच्चीस-तीस प्रतिशत घटाया जाय, और घटाये हुए लगान के आधार पर लगान व्यवस्था और किसानों के अधिकारों का स्थायी बन्दोबस्त किया जाय, तथा किसानों के हितों की पूरी तौर पर रक्षा करते हुए मालगुजारी का भी स्थायी बन्दोबस्त किया जाय।^५

उन्होंने बताया कि बहुत से अंग्रेज प्रशासकों और अधिकारियों ने स्थायी बन्दोबस्त का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नरम कर-निर्धारण के आधार पर लगान और मालगुजारी का स्थायी बन्दोबस्त ही किसानों की समृद्धि का सबसे अच्छा उपाय है।^६

१ वही, पृ० ३९४-३९६।

२ वही, पृ० ४००-४०१, पृ० ४५५।

३ वही, सन् १९०६, पृ० ३७१।

४ वही, सन् १९०८, पृ० ४५५।

५ वही, सन् १९०८, पृ० ४५७।

मालवीयजी ने अकाल की भयानक स्थिति पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि लगान की कमी के साथ-साथ सिंचाई तथा कृषि-शिक्षा का समुचित प्रबन्ध तथा उद्योग-धन्धों का विस्तार अकाल का मुकाबला करने के आवश्यक उपाय हैं।

सिंचाई

मालवीयजी ने कहा कि सन् १८७५ के लगभग मिस्टर चेसने ने अपनी पुस्तक 'इंडियन पालिटी' में लिखा है कि चूँकि अनावृष्टि (सूखा) के कारण हिन्दुस्तान में अकाल पड़ते ही रहते हैं, इसलिए अकाल को रोकने के लिए सिंचाई का समुचित प्रबन्ध सरकार का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यदि वह सिंचाई द्वारा अकाल का निराकरण नहीं करती, तो "हिन्दुस्तान में अग्नेज भले ही अराजकता के स्थान पर शान्ति स्थापित कर दें, समान न्याय फैला दें और अज्ञान दूर कर दें, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इस देश की जनता के प्रति अपने सम्पूर्ण कर्तव्य का पूरी तौर पर निर्वाह किया है।"^१

मालवीयजी को दुःख था कि अकाल कमीशनों द्वारा भी सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार की ओर ध्यान दिलाने पर भी सरकार सिंचाई से कहीं अधिक रेलों के निर्माण पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी नहरों के अतिरिक्त कुओं और तालाबों की आवश्यकता अकाल कमीशनो ने स्वीकार की है, और आशा व्यक्त की कि सन् १९०१ के अकाल कमीशन की संस्तुति के अनुसार सरकार सिंचाई के निमित्त कुओं और तालाबों को खोदने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी^२ और सिंचाई सम्बन्धी उनके निजी प्रयत्नों द्वारा पैदावार में जो वृद्धि होगी उस पर लगान नहीं लिया जायगा।^३

कृषि शिक्षा

मालवीयजी ने सरकार से अनुरोध किया कि जापान की तरह युक्त प्रान्त में भी कृषि शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो। उन्होंने बताया कि जापान में ४०३ प्रारंभिक कृषि स्कूल हैं, जिनमें प्रारम्भिक शिक्षा-प्राप्त विद्यार्थियों को खेती की प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। इसी तरह वहाँ ७३ माध्यमिक कृषि शिक्षा संस्थाएँ हैं जिनमें मध्यम श्रेणी के भावी कृषकों को कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। मालवीयजी ने माँग की कि जापान की इन

१ वही, सन् १९०६, पृ० ३७१-३७२।

२ वही, सन् १९०८, पृ० ४५८।

३. वही, सन् १९०६, पृ० ३७३।

प्रारम्भिक और माध्यमिक कृषि संस्थाओं की तरह इस प्रान्त में भी काफी संस्था में कृषि शिक्षा संस्थाएं खोली जायें, और आशा व्यक्त की कि टोकियो के कृषि कालेज की तरह कानपुर कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थी भी उच्च कोटि का अनुसन्धान करने की, तथा योग्य कृषि शिक्षक बनने की अपने में क्षमता पैदा करेंगे। अन्त में मालवीयजी ने कहा कि यदि जापान की तरह इस देश में भी "वैज्ञानिक खेती के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जायगा, तो भारतीय कृषक जापान, अमरीका और यूरोप के किसान की तरह बेहतर और अधिक प्रचुर फसल पैदा कर सकेंगे, और घरती की उपज बढ़ा पायेंगे।"^१

औद्योगिक शिक्षा

देश के औद्योगिक विकास की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मालवीयजी ने सरकार से औद्योगिक शिक्षा के विस्तार, तथा भारतीय उद्योगों के संरक्षण और प्रोत्साहन की मांग की। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि प्रत्येक जिले में, कम से कम प्रत्येक कमिश्नरी में, ऐसी माध्यमिक स्तर की औद्योगिक शिक्षा संस्थाएं खोली जायें, जिनमें दुनाई रंगाई, घुलाई, वस्त्र छपाई, लोहारी, बढईगिरी, मीनाकारी आदि की शिक्षा का प्रबन्ध हो। इन संस्थाओं में फोरमैन और उनके सहायकों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध हो।^२

उन्होंने यह भी कहा कि युक्त प्रान्त जैसे बड़े भूभाग में कम से कम एक उच्चस्तरीय औद्योगिक शिक्षा महाविद्यालय खोला जाय, जिसमें विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री (औद्योगिक रसायन विज्ञान), मेकेनिकल (यांत्रिक) इंजीनियरी, कपड़ा उत्पादन और चीनी-परिष्करण की उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान की जाय, तथा फोरमैन और मैनेजर परिशिक्षित किये जायें। इसी तरह मालवीयजी की मांग थी कि उन सब छोटे-बड़े उद्योगों के प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध किया जाय जो युक्त प्रान्त में चालू हैं या चालू किये जा सकते हैं।^३

औद्योगिक विकास

मालवीयजी देश के आर्थिक उत्थान के लिए पुराने घरेलू उद्योग-वधों का पुनरुत्थान तथा नवीन बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना, दोनों जरूरी समझते थे। वे मिस्टर जे० ए० हावसन के विचार से सहमत थे कि किसी देश की सारी

१. वही, सन् १९०७, पृ० ४१९।

२. वही, सन् १९०९, पृ० ४२२-४२३।

३. वही, सन् १९०७, पृ० ४२२-४२३।

औद्योगिक शक्ति बृहद् उद्योगों में केन्द्रित नहीं की जा सकती। बहुत विकसित देशों में भी पुराने मझोले उद्योग बने रहते हैं, और नये मझोले उद्योगों का विकास होता रहता है। वे देशी उद्योगों का प्रोत्साहन और संरक्षण राज्य का कर्तव्य समझते थे, और युक्त प्रान्त की सरकार से उनकी मांग थी कि वह अपने इस कर्तव्य का यथाशक्ति निर्वाह करे।^१

मालवीयजी रूस के वित्तमंत्री काउंट डिविटे के इन विचारों से सहमत थे कि “उपभोग के क्षेत्र में राज्य जनता के लिए सस्ते और उपयुक्त माल मुहैया करे, और उत्पादन के क्षेत्र में वह देश की उत्पादक शक्ति का विकास करे। देश की आर्थिक सम्पत्ति के विकास के लिए लाभदायक स्थितियाँ पैदा करके, तथा इसी तरीके से धीरे-धीरे घरेलू होठ प्रोत्साहित करके संरक्षण की नीति इस उद्देश्य की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करती है। अपनी सीमाएँ सारे संसार को खोलकर स्वच्छन्द व्यापार जनता को सस्ता माल मुहैया करता है, पर राष्ट्रीय के आर्थिक विकास के इतिहास में एक भी ऐसा दृष्टान्त नहीं, जिसमें राष्ट्र की उत्पादन शक्तियों का विकास इस नीति से हुआ हो। संरक्षण और मुक्त नीति का चयन समय की स्थिति पर निर्भर होता है। इसीलिए हम पाते हैं कि अपने ऐतिहासिक विकास के दौरान में राष्ट्रों ने अपनी व्यापारिक और औद्योगिक पद्धतियाँ बहुधा बदली हैं।”^२

मालवीयजी ने रूस के वित्तमंत्री के इस उद्धरण को देते हुए मांग की कि आयात शुल्क द्वारा युक्त प्रान्त के चीनी के उद्योग का संरक्षण किया जाय। उन्होंने कहा कि सन् १८९९ में विदेशी चीनी पर आयात शुल्क लगाते समय सर जेम्स वेस्टलैंड ने कहा था. “हमारा दावा है कि इस देश में अपने उद्योगों को बनाये रखने का हमें वैसा ही अधिकार है जैसा कि विदेशी राष्ट्र अपने क्षेत्रों में चीनी का उद्योग और गन्ने की खेती को बनाये रखने और प्रोत्साहित करने का दावा करते हैं।”^३ मालवीयजी ने कहा कि यह दलील, इस समय भी चीनी व्यवसाय के संरक्षण के लिए उतनी ही न्यायसंगत है जितनी वह सन् १८९९ में थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित आयात शुल्क उस समय तक ही चालू रहना चाहिए जब तक सरकार की सहायता और सहयोग से हमारा चीनी

१. वही, सन् १९०७, पृ० ४२४-४२६।

२. वही, सन् १९०७, पृ० ४१५-४१६।

३. वही, सन् १९०७, पृ० ४१७।

का व्यवसाय इतना समुन्नत नहीं हो जाता कि वह विदेशी चीनी का खुले बाजार में मुकाबला कर सके।^१

जनकल्याण नीति

मालवीयजी ने 'अज्ञानता में फैसी, निर्धनता से दबी, अस्वास्थ्यकर प्रतिवेश में रहनेवाली तथा रोगों से त्रस्त जनता' की दयनीय दशा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उसको सुधारने के लिए आवश्यक प्रयत्न करने की सरकार से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जनता की स्थिति में सुधार ही अच्छी सरकार की कसौटी है और इस कर्तव्य का समुचित निर्वाह करके ही भारत सरकार सम्यक् सरकार होने का दावा कर सकती है।^२ उन्होंने कहा कि जनोपयोगी सेवाओं पर राजकोष से जितना धन खर्च किया जा रहा है, वह नाकाफी है। उनका सुझाव था कि प्रशासन और फौज पर खर्चा कम करके जिलाबोर्डों, नगर पानिकाओं तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा जनोपयोगी सेवाओं, विशेषतः शिक्षा और स्वास्थ्यरक्षा सम्बन्धी सेवाओं, पर अधिक धन खर्च किया जाय, ताकि जनता सुखी और सुशिक्षित जीवन व्यतीत कर सके। उनका सुझाव था कि जिला बोर्डों को लगान का २५ प्रतिशत दिया जाय, तथा राजस्व में प्रान्तीय सरकारों का भाग बढ़ा दिया जाय।

शिक्षा

वे बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर एल्फिंस्टन के इस विचार से सहमत थे कि "गरीबों की सुख शान्ति बहुत हद तक शिक्षा पर निर्भर है। इसके जरिए ही वे विवेक और आत्म सम्मान के वे स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं जिनसे सब गुण विकसित होते हैं", और वे चाहते थे कि सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षा का व्यापक प्रसार करे। मालवीयजी प्रारम्भिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य समझते थे, और चाहते थे कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। उनकी माँग थी कि प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क दी जाय, तथा सब बच्चों के लिए उसका प्रबन्ध किया जाय।^३ उनका सरकार से अनुरोध था कि वह ऊँचे पैमाने पर वैज्ञानिक पद्धति द्वारा कृषि शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, तथा उच्चस्तरीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध करे। उनको माँग थी कि सर्वसाधारण स्कूलों में वैदिक शिक्षा के

१. वही, सन् १९०७, पृ० ४१७-४१८।

२. वही, सन् १९०७, पृ० ३९४।

३. वही, सन् १९०८, पृ० ४६५-४६६।

साथ-साथ हस्त कला की शिक्षा भी दी जाय। विद्यार्थियों के ज्ञान को व्यावहारिक और प्रयोगात्मक बनाया जाय। लेवोरेटरी वर्क और शापवर्क द्वारा उनमें प्रेक्षण (आवजरवेशन) की शक्ति पैदा की जाय। उनके ज्ञान को यथा-तथ्य बनाया जाय, उनमें आत्मनिर्भरता की आदत डाली जाय। उनके ज्ञान को जीवनोपयोगी बनाया जाय।^१ वे चाहते थे कि प्रयाग के म्योर सेंट्रल कालेज को उच्चकोटि की शिक्षा-संस्था का स्वरूप दिया जाय, और प्रान्त में एक ऐसा प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय, जहाँ विभिन्न विषयों के उच्चस्तरीय विद्वान् अपने अध्यापन और अनुसन्धान द्वारा विद्यार्थियों को अनुप्राणित और प्रशिक्षित करें, और जो वास्तव में विद्वत्ता, प्रतिभा की खोज और विकास, वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसन्धान की तरक्की एवं व्यावसायिक स्तर के उन्नयन का केन्द्र बन सकें।^२

स्वास्थ्य

मालवीयजी को दुःख था कि स्वास्थ्य-रक्षा का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण प्रतिवर्ष हजारों बच्चे और नवयुवक, माताएँ और बहनें मौत का शिकार हो जाती हैं, और लाखों अपनी शारीरिक और बौद्धिक शक्ति का ठीक ठीक विकास नहीं कर पाते। उन्होंने बहुत ही सतप्त हृदय से कहा कि जबकि ग्रेट ब्रिटेन में प्रतिवर्ष मृत्यु संख्या १६ प्रति हजार है, वहाँ भारत में प्रतिवर्ष मृत्यु संख्या ३५ प्रति हजार, और युक्त प्रात में ४४ प्रति हजार है। उन्होंने यह भी बताया कि युक्त प्रात के २५ जिलों में तो मृत्यु संख्या जन्म संख्या से भी अधिक है।^३ सन् १९०४ में उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों में युक्त प्रान्त में दो लाख से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु प्लेग से हुई है, और जबकि इस प्रान्त में प्रति सप्ताह दस हजार इस महामारी के शिकार हो रहे हैं, सारे देश में उनकी संख्या चालीस हजार प्रति सप्ताह है।^४

उनका सरकार से अनुरोध था कि वह स्वास्थ्य-रक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए उसका समुचित प्रबन्ध करे। वे चाहते थे कि इंगलिस्तान की तरह यहाँ भी कानून द्वारा गन्दगी से नदियों के स्वच्छ जल की रक्षा की जाय, नगरों की गन्दगी को नदियों में न डाला जाय। उनके समापन का दूसरा प्रबन्ध किया

१ वही, सन् १९०७, पृ० ४२६-४२७।

२ वही, सन् १९०४, पृ० ३४३।

३ वही, सन् १९०७, पृ० ३९८।

४. वही, सन् १९०४, पृ० ३५२।

जाय।^१ उनका सुझाव था कि चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाय। नगरों के अपवाह तंत्र (ड्रेनेज) को ठीक किया जाय, वस्तियों की स्वच्छता को सुधारा जाय। उनकी घरती को शुद्ध और स्वस्थ रखा जाय। भस्मको द्वारा नगर की झाड़न भस्म कर दी जाय। नगरों के बाहर स्वस्थ स्थान पर शोड़े से मगान बनाये जायें, जिनमें प्लेग आदि महामारी के अवसरों पर रोगाक्रान्त लोगों से नगर-निवासी भेजे जा सकें।

वज्र पर विचार

मालवीयजी को उस वान का धोंग था कि वज्र विलुप्त तैयार कर लेने के बाद कोसिल के सामने रखा जाता है, जिसके कारण कोसिल की वृद्ध यथार्थ-हीन हो जाती है, उमका सरकार के वित्तीय निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। सन् १९०८ में उन्होंने सरकार में अनुरोध किया कि वज्र को अन्तिम रूप से स्वीकार करने से पहले उमका प्रारूप कोसिल के सामने रखा जाय, ताकि गैर-सरकारी सदस्यों के सुझावों के सदर्थ में सरकार उसे संशोधित कर सके।^२ यद्यपि बम्बई और मद्रास में यह प्रथा चालू हो गयी थी, पर युक्त प्रान्त की सरकार ऐसा करने को राजी नहीं हुई।

वित्तीय वक्तव्य की समीक्षा के दौरान मालवीयजी ने सरकार की कतिपय प्रशासनिक नीतियों की भी कड़ी आलोचना की। कमायूँ में प्रचलित बेगार की प्रथा की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने सन् १९०७ में जोरदार शब्दों में घोषित किया कि 'बेगार ब्रिटिश प्रशासन पर कलंक' है, उसे फौरन रद्द कर देना चाहिए।^३ उन्होंने कहा कि उस समय जबकि जनता की दशा को सुधारने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य-रक्षा पर अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता है, उस समय अनावश्यक कामों पर रुपया बर्बाद करना अवश्य ही अनुचित है। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति में जहाँ एक भारतीय नियुक्त किया जा सकता है वहाँ यूरोपियन नियुक्त करना 'पाप' है।^४ उन्होंने कहा कि सचिवालयों के उच्च पदों पर योग्य भारतीयों के बजाय भारत में रहनेवाले यूरोपियनों को नियुक्त करना भारतीय नवयुवकों के साथ अन्याय है।^५ उन्होंने मांग की कि प्रान्त की सार्वजनिक सेवाओं में

१ वही, सन् १९०४, पृ० ३५०-३५१।

२ वही, सन् १९०८, पृ० ४५०।

३. वही, सन् १९०७, पृ० ४४८।

४. वही, सन् १९०८, पृ० ४७४।

५ वही, सन् १९०४, पृ० ३५९-३६३।

भरती होने का भारतीयों का मौलिक अधिकार है। यदि सरकार भारतीयों के इस दावे की उपेक्षा करते हुए केवल प्रजाति, देश, धर्म और रंग के कारण यूरोपियनों या यूरोशियनों को भारतीयों पर तरजीह देती है, तो वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है।^१ उन्होंने कहा कि उनकी राय में किसी एक वर्ग के प्रति अनुचित पक्षपात की तथा व्यक्तियों पर किये गये अन्यायों की शिकायतों की प्रतियोगिता परीक्षा ही सबसे बड़ी रक्षा है। पर उन्हें खेद था कि इस प्रथा का विस्तार करने के बजाय उसे डिप्टी कलक्टरों की नियुक्तियों के विषय में समाप्त कर दिया गया है।^२

सन् १९०६ में मालवीयजी ने वित्तीय वक्तव्य पर बोलते हुए कहा : “वित्त व्यवस्था केवल अकगणित नहीं है। वित्तव्यवस्था एक बड़ी नीति है। निर्दोष वित्तव्यवस्था बिना निर्दोष शासन संभव नहीं है, और निर्दोष शासन भी बिना निर्दोष वित्त-व्यवस्था संभव नहीं है।”^३ इन शब्दों के साथ मालवीयजी ने भारत सरकार से अपील की कि वह युक्त प्रान्त के अशदान और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी वित्तनीति अपनाये जिससे जनता के लिए एक बड़ी सम्य सरकार की प्रजा की तरह रहना और फलना फूलना संभव हो।^४

सन् १९०८ में उन्होंने कहा . “सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान के एक विद्वान् ने कहा है कि जहाँ अग्नि का भय अधिक हो, वहाँ असंख्य चिनगारियों के बुझाने से समाज की इतनी सेवा नहीं होती जितनी मकान का बुद्धि-संगत निर्माण और उसका प्रस्तुत परिस्थितियों से अनुकूलन।”^५ इसी तरह “अकाल और महामारी की स्थितियों में जनता की सहायता करते रहने से कही अच्छा यही है कि सरकार अपनी शक्तियों और साधनों को जनता की शक्ति के निर्माण में, उसके मस्तिष्क को ज्ञान से प्रदीप्त करने में, उसके घरों के स्वास्थ्य प्रतिवेश के सुधार में, तथा अपनी आमदनी को बढ़ाने के नये स्रोतों को अपनाने की क्षमता प्राप्त करने में इस तरह प्रयोग करे कि वह अकाल और रोगों का आज से कही अधिक अच्छी तरह स्वयं मुकाबला कर सके।”^६

श्री सो० वाई० चिन्तामणि का विश्वास था कि “केन्द्रीय विधान सभा में सर फोरोजशाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ने, बंगाल कौंसिल में

१. वही, सन् १९०८, पृ० ४७५।
२. वही, सन् १९०४, पृ० ३६४-३६५।
३. वही, सन् १९०६, पृ० ३९०।
४. वही, सन् १९०६, पृ० ३९०-३९१।
५. वही, सन् १९०८, पृ० ४७५-४७६।
६. वही, सन् १९०८, पृ० ४७६।

श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी और श्री आनन्द मोहन बोस ने, मद्रास में सर्वश्री विजय राघवाचार्य और सुवाराव पन्तलू ने, बम्बई में सर चिमनलाल सीतलवाड और सर गोकुलदास पारख ने, और युक्त प्रान्त में पण्डित मदन मोहन मालवीय ने अपनी ससदीय क्षमता का तथा उत्तरदायित्व भावना का जो परिचय दिया, उसने मार्ले-मिंटो सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया ।^{११}

नये सुधारों की प्राप्ति में नि सन्देह जनान्दोलन और जनजागृति का भी महत्त्वपूर्ण योगदान था । इनके बिना विधायकों द्वारा क्षमता के प्रदर्शन मात्र से नये सुधारों का मिलना संभव नहीं था । पर विधायकों की क्षमता का भी अंशदान अवश्य था । जनजागृति और जनान्दोलन में विधायकों के अतिरिक्त बहुत से दूसरे नेताओं और राजनीतिज्ञों का भी भरपूर योगदान था । पर इन मामलों में भी इन विधायकों के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता । युक्त प्रान्त की जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करने में मालवीयजी का तो नि सन्देह ही बहुत बड़ा हाथ था ।



७. कमेटियों में गवाही और कार्य

विकेन्द्रीकरण संघ व्यवस्था

सन् १९०८ में युक्त प्रान्त की विधान कौंसिल के सदस्य की हैसियत से मालवीयजी ने विकेन्द्रीकरण कमीशन (डीसेण्ट्रेलाइजेशन कमीशन) के सामने गवाही देते हुए कहा : “प्रान्तीय सरकारें भारत सरकार की केवल प्रतिनिधि मात्र हैं। उन्हें अपने आर्थिक तथा अन्य सभी प्रश्नों की स्वीकृति भारत सरकार से लेनी पड़ती है। प्रान्तों की सारी व्यवस्था भारत सरकार के कठोर नियंत्रण में है। बिना उसकी स्वीकृति के प्रान्तीय सरकारें ‘कोई भी परिवर्तन नहीं’ कर सकती।”^१

उन्होंने बताया कि “भारत सरकार सम्पूर्ण करो का अपने को स्वामी समझती है”^२, और यद्यपि कुछ वित्तीय सुधारों के बाद सन् १९०४ की व्यवस्था में कुछ करो की सम्पूर्ण आय और कुछ करो की आय का एक अंश प्रान्तीय सरकारों को प्रदान कर दिया गया है, पर भारत सरकार आवश्यकता के नाम पर इस व्यवस्था में अपनी इच्छा से परिवर्तन कर सकती है। इस व्यवस्था से संपूर्ण राजस्व का लगभग एक चौथाई भाग ही प्रान्तीय सरकारों को मिल पाता है।^३ इसी बात से, मालवीयजी ने कहा, प्रान्तीय सरकारों की शासन शक्ति और आर्थिक स्थिति का ठीक पता लग सकता है। सरकार की वित्त-नीति और वित्त-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मालवीयजी ने कहा कि सम्पूर्ण राजस्व का “एक चौथाई से भी कम भाग” जनकल्याण सम्बन्धी कामों पर खर्च होता है, जिसका परिणाम यह है कि “बाहर से इस साम्राज्य की जितनी तड़क-भड़क दिखाई दे रही है, उतनी ही भारतवासियों की दशा बुरी हो गयी है”,^४ और जब तक “इस व्यवस्था में एकदम परिवर्तन नहीं किया जायगा, तब तक जनता के अत्यन्त हितकर स्वत्वों की उन्नति असम्भव है।”^५

मालवीयजी ने बताया कि भारत के “आठ प्रमुख प्रान्तों का क्षेत्रफल और इनकी जनसंख्या यूरोप के कई बड़े बड़े राज्यों के बराबर है, और इन प्रान्तों में

१. सीताराम चतुर्वेदी—महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, खण्ड ३, पृ० १४२-१४३।
२. वही, पृ० १४३।
३. वही, पृ० १४३।
४. वही, पृ० १४३।
५. वही, पृ० १४४।

से प्रत्येक अलग-अलग राज्य प्रबन्ध करने के लिए पर्याप्त, विस्तृत, और उपयुक्त है।^१ इन प्रान्तों की सरकारों को प्रशासन का काफी अनुभव है, और देश का हित इसी में है कि इनके प्रशासनिक और आर्थिक अधिकारों का विस्तार करके इन्हें अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जाय।^२

मालवीयजी ने कहा कि उनकी राय में "इस ध्येय की पूर्ति के लिए वर्तमान प्रचलित व्यवस्था को रांघ व्यवस्था में बदल देना चाहिए, प्रान्तीय सरकारों को अब भारत सरकार की आज्ञाकारिणी प्रतिनिधि मात्र न रखकर अलग अर्द्धस्वतंत्र सरकारें बना देना चाहिए।"^३ उन्होंने बताया कि लार्ड मेयो के जमाने में इस बात की चर्चा चली थी, पर प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। पर यह विचार यदि उस समय स्वीकार हो गया होता, तो "प्रान्तीय सरकारों ने अपनी शासित जनता की समृद्धि तथा सर्वतोमुखी उन्नति में अधिक ध्यान दिया होता।"^४

उन्होंने कहा कि रांघ व्यवस्था, जिगमो बहुत आवश्यकता है, आसानी से स्थापित की जा सकती है। उससे साम्राज्य की एकता में कोई शिथिलता नहीं आ पायेगी, भारत सरकार की फजूलखर्ची की आदत बन्द होगी, और प्रान्तीय सरकारें जनता का विरोध हित कर पायेगी।^५

मालवीयजी ने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करके प्रान्तीय सरकारों पर से भारत सरकार का नियंत्रण हटा लेने पर उनका स्वरूप बदलना होगा। प्रत्येक प्रान्त में कार्यपरिपक्व स्थापित करनी होगी और कम से कम दो ऐसे योग्य और अनुभवी भारतीयों को उसका सदस्य नियुक्त करना होगा जो अपने विचार और दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से सरकार के सम्मुरा रख सकें। प्रान्तीय विधान कौंसिलों का विस्तार करना होगा, उनमें जनता के प्रतिनिधियों की संख्या काफी बढ़ानी होगी, और उन कौंसिलों को बजट पर बहस करने के साथ साथ प्रस्ताव द्वारा उसमें संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार देना होगा। मालवीयजी का कहना था कि कौशलपूर्ण व्यय, लाभयुक्त और न्यायसंगत कर, तथा आय और व्यय का पूर्ण सामंजस्य तभी संभव है जब विवेकशील तथा परिश्रमी जनसमुदाय उस पर अपने विचारों द्वारा शासन करे। अतएव जनता के विचारों को समुचित रूप से प्रकट करने के लिए विधान कौंसिलों में जनता के प्रतिनिधियों को स्थान देना चाहिए, और उस विचार को प्रभावशाली बनाने

१. वही, पृ० १४४।

२. वही, पृ० १४४।

५. वही, पृ० १४५।

२. वही, पृ० १४४।

४. वही, पृ० १४४।

के लिए प्रतिनिधियों को कच्चे चिट्ठे पर स्वतंत्ररूप से वादविवाद करने का अवसर देना चाहिए।^१

अन्त में मालवीयजी ने कहा कि बम्बई और मद्रास प्रान्तों के समान ही युक्त प्रान्त की उचित शासन-व्यवस्था के लिए इस प्रान्त में भी चार सदस्यों की कार्यपरिषद् स्थापित की जाय, जिसके दो सदस्य भारतीय हों, और उसका प्रमुख शासक गवर्नर हो जो “इंग्लैंड का कोई योग्य और अनुभवी राजनीतिज्ञ हो।”^२

सिविल सेवाएं

३१ मार्च सन् १९१३ को मालवीयजी ने लार्ड इस्लिगटन की अध्यक्षता में गठित पब्लिक सर्विस कमीशन को युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एक मेमोरैंडम पेश किया, तथा लिखित और मौखिक गवाही दी। मेमोरैंडम प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कमेटी का विश्वास है कि “भारतीय जनता की नैतिक, आर्थिक और वौद्धिक उन्नति ही इस देश में अंग्रेजों के अस्तित्व का नैतिक औचित्य है, और ब्रिटिश राज्य की शक्ति और स्थायित्व पिचहत्तर हजार सैनिकों के बजाय उसकी नेकनियती और न्यायभावना के प्रति जनता का विश्वास है, जिसे बनाये रखना भारतीय प्रशासन की असल समस्या है”, और इसके लिए “भारत की राजनीतिक आकाक्षाओं के प्रति इंग्लैंड की यथार्थ सहानुभूति आवश्यक है।”^३

उन्होंने कमेटी के मेमोरैंडम तथा अपनी गवाही दोनों में प्रतिद्वन्द्विता की प्रथा का समर्थन करते हुए मांग की कि इंग्लैंड के अतिरिक्त भारत में भी सिविल सर्विस में भरती के लिए परीक्षा का प्रबन्ध हो। वे चाहते थे कि परीक्षा द्वारा ही योग्य नवयुवकों का चुनाव किया जाय। परीक्षार्थी की आयु २२ से २४ वर्ष तक की हो, और वह किसी विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट हो। उनका सुझाव था कि प्रशासन और न्याय विभाग के लिए अलग-अलग परीक्षाएं हो, और प्रशासन विभाग के सिविल सर्वेंटों को न्याय विभाग में नियुक्त न किया जाय। उनका सुझाव था कि परीक्षा के विषयों का चुनाव भारत की आवश्यकताओं को देख कर किया जाय। अतः ग्रीक और लैटिन साहित्य एवं

१. वही, पृ० १४५-१४६।

२. वही, पृ० १४५-१४६।

३. इस्लिगटन पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट, जिल्द ५ (युक्तप्रान्त की गवाहियाँ)।

रोमन और ग्रीक इतिहास के वजाय सस्कृत और अरबी, तथा भारतीय इतिहास और कानून परीक्षा की विषय सूची में शामिल किये जायें।^१

उन्होंने कहा कि प्रशासन का कोई पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित नहीं किया जाय, और ब्रिटिश उपनिवेशों के नागरिकों को इंडियन सिविल सर्विस में भरती होने का अधिकार समी दिया जाय, जब उपनिवेशों में भारतीयों के अधिकार समान हों, और उन्हें वहाँ की सिविल सर्विस में भरती होने का अधिकार हो।^२

उनकी कमेटी और उनकी यह भी राय थी कि फौजी अफसरों को सिविल पोस्टों पर नियुक्त न किया जाय। प्रान्तीय सिविल सर्विस में भी परीक्षा द्वारा ही भरती हो। मुंसिफों को फौजदारी मुकदमों की न्यायिक जाँच करने का भी अधिकार दिया जाय। प्रवेशकों की शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय चालू करने के वजाय उन्हें वरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाय।^३

जाति, वर्ग या सम्प्रदाय के आधार पर सरकारी नौकरियों पर नियुक्तियों के सुझाव का विरोध करते हुए मालवीयजी ने कहा कि खुली परीक्षा द्वारा ही सब वर्गों और सम्प्रदायों के नवयुवक योग्यता के आधार पर निष्पक्ष भाव से सरकारी नौकरी में भरती किये जायें। उन्होंने कहा कि सब वर्ग और सम्प्रदाय शिक्षा तथा सरकारी नौकरों के लिए समान अवसरों को माँग करने के हकदार हैं, पर वे यह माँग करने के हकदार नहीं कि उनके नवयुवक सरकारी नौकरी में भरती किये जायें, जब तक कि वे हमारे सम्प्रदायों के नवयुवकों का सफलता से मुकाबला करके उसके लिए अपनी योग्यता सिद्ध न कर दें। सरकारी नौकर सारे समाज की सेवा के लिए, न कि किसी सम्प्रदाय की सेवा के लिए, नियुक्त किये जाते हैं, और जनहित की माँग है कि उत्तरदायित्व और अधिकार के पदों पर वही नियुक्त किये जायें जो जनसेवा (सरकारी नौकरी) के लिए अपेक्षित क्षमता के मानदण्ड पर पहुँच चुके हैं।^४

औद्योगिक विकास

मार्च सन् १९१६ में सर इब्राहीम रहमतुल्ला ने केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्ताव किया कि भारत में उद्योगों के विकास के उपायों पर विचार करने के लिए सरकार एक कमेटी नियुक्त करे। इस प्रस्ताव में उन्होंने भारत सरकार को पूर्ण वित्तीय स्वशासन विशेषतः आयात, निर्यात और उत्पादन शुल्कों के

१. वही।

२. वही।

३. वही।

४. वही।

दिये जाने पर विचार करने पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने अपने भाषण में भी औद्योगिक उन्नति के निमित्त वित्तीय स्वशासन की आवश्यकता पर जोर देते हुए आशा व्यक्त की कि जनमत की यह माँग शीघ्र स्वीकार की जायगी।

सरकारी प्रवक्ता सर विलियम क्लार्क ने घोषित किया कि सरकार ने एक कमेटी के बजाय एक कमीशन नियुक्त करने का पहले ही निश्चय कर लिया है, पर वित्तीय स्वशासन के प्रश्न पर युद्ध के बाद अलग से विचार किया जायगा।

इस तरह वित्तीय स्वशासन के प्रश्न को तथा आयात, निर्यात और उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नीतियों को स्पष्ट रूप से कमीशन की जाँच से अलग करते हुए भारत सरकार ने सर टी० एच० हालैड की अध्यक्षता में १९ मई सन् १९१६ को इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन (भारतीय औद्योगिक आयोग) नियुक्त किया। मालवीयजी भी इस कमीशन के एक सदस्य नियुक्त हुए। सर फजल भाई करीम भाई, सर राजेन्द्र मुकर्जी और सर दोराबजी जमशेदजी इस कमीशन के तीन दूसरे भारतीय सदस्य थे। ये तीनों प्रसिद्ध भारतीय औद्योगिक थे। इसके अतिरिक्त पाँच अंग्रेज सदस्य नियुक्त किये गये। पर इनमें दो काम नहीं कर सके। अतः आठ सदस्यो ने सन् १९१८ में अपनी रिपोर्ट तैयार की। कहा जाता है कि मालवीयजी के आग्रह के कारण रिपोर्ट को पाण्डुलिपि कई बार बदलनी पड़ी, और जब उसके बाद भी उन्होंने एक अलग नोट लिखने का विचार व्यक्त किया, तब सर राजेन्द्र मुकर्जी, जो हालैड साहब की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का काम करते थे, उन पर रष्ट हो गये। पर मालवीयजी अपनी बात पर डटे रहे।

रिपोर्ट में संस्तुति की गयी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भविष्य में सरकार को देश की औद्योगिक उन्नति में सक्रिय भाग लेना चाहिए, और इसके लिए उसे पर्याप्त वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक मशीनरी भी सघटित करनी चाहिए। कमीशन ने अनुभव किया कि कच्चे माल तथा औद्योगिक सम्भावनाओं में सम्पन्न होते हुए भी भारत की औद्योगिक उपलब्धियाँ बहुत ही कम हैं। भारतीय श्रमिकों में क्षमता की कमी है, भारतीय बुद्धजीवियों में उद्योगवाद की सही परम्परा का अभाव है, औद्योगिक शिक्षा का प्रबन्ध बहुत ही अपर्याप्त है। भारतीय पूँजी का झुकाव उद्योगों के बजाय व्यापार की ओर है। पुराने कुटीर उद्योगों का ह्रास होता जा रहा है। नवीन यान्त्रिक उद्योगों के विकास की गति बहुत ही धीमी है। बुनियादी उद्योगों की कमी के

कारण अन्य देशों पर भारत की औद्योगिक निर्भरता युद्ध के अवसर पर विशेष रूप से भयावह सिद्ध हो सकती है। नवीन वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोगों का अभाव खेती के उत्पादन की वृद्धि में बाधक है, तथा रेलवे की भाड़ा सम्बन्धी नीति देश के औद्योगिक विकास के प्रतिकूल है। कमिशन की निश्चित धारणा थी कि इन कमियों और त्रुटियों को दूर करने में सरकार का सक्रिय भाग नितान्त आवश्यक है।^१

उसकी संस्तुतियाँ थी कि प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाया जाये, तथा जिन क्षेत्रों में सम्भव हो वहाँ उसे अनिवार्य बनाया जाय।^२ औद्योगिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाय। गिल्प विज्ञान की शिक्षा को अधिक प्रयोगात्मक बनाया जाय।^३ यान्त्रिक इंजीनियरी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय।^४ श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य तथा कल्याण की वृद्धि पर समुचित ध्यान दिया जाय,^५ और औद्योगिक बैंक खोले जायें।^६ कुटीर उद्योगों की वृद्धि के लिए औद्योगिक सहकारिता को प्रोत्साहित किया जाय,^७ रेलवे की भाड़ा नीति में आवश्यक तब्दीली की जाय।^८ जल मार्गों को ठीक किया जाय,^९ खेती के आधुनिक तरीकों को प्रोत्साहित किया जाय,^{१०} वैज्ञानिक और प्राविधिक सेवाओं को स्थापित किया जाय, तथा भारत और विदेश में अनुसंधान की व्यवस्था की जाय।^{११} व्यापारिक और औद्योगिक आँकड़े तैयार करने का प्रयत्न किया जाय,^{१२} यथा सम्भव रेलवे और सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान भारत में खरीदें,^{१३} तथा सरकार उद्योगों को प्राविधिक^{१४} और आर्थिक सहायता दे।^{१५}

मालवीयजी ने कमिशन की इन सब संस्तुतियों की पुष्टि करते हुए एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी भी लिखी। इसमें उन्होंने सरकार की औद्योगिक और वित्तनीति की विस्तार से समीक्षा करते हुए बहुत से महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। यह टिप्पणी

-
- | | |
|---|-----------------------|
| १. इंडियन इंडस्ट्रियल कमिशन रिपोर्ट, पृ० ४९-५६। | |
| २. वही, पृ० २८२। | ३. वही, पृ० २७६-२७८। |
| ४. वही, पृ० २७७। | ५. वही, पृ० २८२। |
| ६. वही, पृ० २८६। | ७. वही, पृ० २८४। |
| ८. वही, पृ० २८५। | ९. वही, पृ० २८६। |
| १०. वही, पृ० ५८-६०। | ११. वही, पृ० २७५। |
| १२. वही, पृ० २७८। | १३. वही, पृ० २७९। |
| १४. वही, पृ० २८०। | १५. वही, पृ० २८४-२८६। |

नि.संदेह भारत के व्यावसायिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही लाभप्रद है।^१

इसमें बहुत से प्रमाणों के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि अति प्राचीन काल से भारत सुखसुविधा-सम्पन्न था, अपनी समृद्धि तथा कलाकौशल के लिए प्रसिद्ध था, और अंग्रेजों के शासन काल में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से कही अधिक अंग्रेज अधिकारियों की वित्तीय और आर्थिक नीति ही भारत के औद्योगिक ह्रास का कारण थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासनकाल में जबकि ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के उद्योगों की रक्षा के लिए हिन्दुस्तानी माल पर बहुत अधिक आयात-कर लगा दिये थे, कम्पनी के अधिकारियों ने भारत में आनेवाले ब्रिटिश माल को कर-भार से मुक्त कर रखा था, तथा भारत के उद्योग धंधों की रक्षा करने के बजाय ब्रिटिश माल के आयात को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने प्रमाणों से यह भी सिद्ध किया कि सन् १८५७ के बाद ब्रिटिश सरकार ने भी मुक्त व्यापार के नाम पर भारत के औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं की उपेक्षा की, जिसके फलस्वरूप भारत का औद्योगिक ह्रास हुआ, कृषि पर जीवन-निर्वाह का बोझ बढ़ा, तथा जनता की निर्धनता बढ़ती गयी।^२

मालवीयजी ने स्वीकार किया कि दुर्भिक्ष का आगमन सूखा पड़ने के कारण होता है, पर जैसा कि अकाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जनता की निर्धनता के कारण ही लाखों व्यक्ति मौत के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बहुत ही संतप्त हृदय से भारतीय सरकार की औद्योगिक नीति तथा गतिविधि की समीक्षा करते हुए संस्तुति की कि अकाल आयोग की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीयों की निर्धनता को दूर करने के निमित्त देश के व्यावसायिक और औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार प्रयत्न करे।^३

उन्होंने इस सम्बन्ध में कृषि शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा, तथा प्रयोगात्मक विज्ञान की शिक्षा के समुचित प्रवन्ध पर विशेष जोर दिया, एवं पुराने उद्योग धंधों का समुचित संरक्षण तथा नये उद्योगों का प्रोत्साहन सरकार का कर्तव्य बताया। उन्होंने प्रान्तों तथा केन्द्र में औद्योगिक विभाग के गठन की तथा एक अर्धस्वतन्त्र वैज्ञानिक परिषद् या बहुशिल्प शिक्षण संस्था (इम्पीरियल पालिटेकनिक इन्स्टीट्यूट) के आधीन रासायनिक अन्वेषण के संचालन की व्यवस्था

१. इंडियन इण्डस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट—नोट, पृ० २९२-३५५।

२. वही, पृ० २९४-३०५।

३. वही, पृ० ३०६-३०८।

की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, और वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक वृत्तियों की व्यवस्था की सरकार से संस्तुति की। देश में प्रारम्भ होने योग्य व्यावसायिक उद्योगों की स्थापना के लिए उन्होंने संस्तुति की कि "शीघ्रातिशीघ्र बाहर से कलो तथा विशेषज्ञों को प्रधान व्यवस्थापक के पदों के लिए बुलाया जाय, तथा भारतीय पूँजीपतियों को उद्योगों को प्रारम्भ करने में सभी प्रकार की संभव सहायता दी जाय।"^१

अन्त में उन्होंने फ्रेड्रिक निकलसन के इस विचार की पुष्टि की कि "भारतीय उद्योगों के मामले में भारत का हित हमारा पहला, दूसरा तथा तीसरा ध्येय होना चाहिए। पहले से मेरा मतलब है कि यहाँ के माल को प्रयोग में लाना चाहिए, दूसरे, उद्योग धंधे खोलने चाहिए और तीसरे इनका लाभ देश में ही रहना चाहिए।"^२ उन्होंने आशा व्यक्त की कि "यदि इस भाव से प्रेरित होकर भारत के औद्योगिक साधनों को काम में लाया जायगा, तब हिन्दुस्तान समृद्धिशाली और शक्तिशाली होगा, तथा इंग्लैंड और भी अधिक समृद्धिशाली बनेगा।"^३

सेना का भारतीयकरण

सन् १९२१ में भारत सरकार ने सेनाध्यक्ष रॉलिसन की अव्यक्तता में भारत की सैनिक आवश्यकताओं की जाँच के लिए एक कमेटी गठित की। इस कमेटी के समक्ष गवाही देते हुए मालवीयजी ने सेना के भारतीयकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट् की भारतीय प्रजा को भी सेना में सम्राट् का कमीशन अर्थात् ऊँचे से ऊँचा पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत में सेनडहर्स्ट कालेज के स्तर का एक उच्चस्तरीय सैनिक कालेज तथा कई सैनिक स्कूल खोले जायें। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन संस्थाओं की स्थापना तथा व्यवस्था में आवश्यक धन खर्च किया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार के लिए संभव न हो तो वे स्वयं सैनिक कालेज के लिए धन एकत्र करने को तैयार हैं। मालवीयजी ने यह भी माँग की कि सेना के सब विभागों में भरती होने का अधिकार भारतीयों को प्रदान किया जाय, आन्तरिक सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भारतीय सैनिकों को सौंपा जाय, तथा क्रमशः गोरी पलटनें ब्रिटेन वापस बुला ली जायें।^४

१. वही, पृ० ३०८-३५४।

२. वही, पृ० ३५५।

३. वही, पृ० ३५५।

४. राउडटेविल कार्रफेंस (सेकेंड सेशन), पृ० ९८८, लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स, १९२८, जि० २, पृ० १६५६।

कृषि-विकास

२२ फरवरी सन् १९२७ को लार्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में गठित कृषि आयोग (एग्रीकलचरल कमीशन) के सामने मालवीयजी ने कृषि-शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अपने नोट में लिखा कि इस क्षेत्र में जापान ने बहुत काम किया है, और इस देश में भी जापान की तरह प्राग्भिक और माध्यमिक कृषि विद्यालय काफी संख्या में खोले जाने चाहिए।^१ वे यह भी चाहते थे कि साधारण माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में भी खेती एक पाठ्य विषय हो, ताकि जब विद्यार्थी कालेज में प्रवेश करें तब उन्हें खेती की काफी शिक्षा प्राप्त हो।^२

मालवीयजी ने कहा कि खेती की उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में कृषि सकायेँ स्थापित की जायें, और कृषि कालेज खोले जायें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय देश के सर्वोत्तम उदीयमान विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। वह विचारों के प्रसार का, तथा विद्यार्थी समाज में किसी विषय के लिए उत्साह पैदा करने का सर्वोत्तम केन्द्र है। अगर कृषि विज्ञान सकाय के विद्यार्थी और प्रोफेसर दूसरे विज्ञानों के ज्ञाताओं के निकट सान्निध्य में एक केन्द्र में काम करेंगे, तो वे विश्वविद्यालय से दूर एक पृथक् संस्थान की तुलना में इस वातावरण को कहीं अधिक प्रेरणाप्रद पायेंगे।^३

उनकी राय में विश्वविद्यालय में दूसरे विद्वानों के सम्पर्क और सहयोग से ही कृषि विज्ञान के विशेषज्ञ कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अनुसन्धान अच्छे ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूसा इन्स्टीट्यूट, जिसने अनुसन्धान के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है, इससे भी कहीं अच्छा काम कर पाता, यदि किसी निवासीय विश्वविद्यालय में वह स्थापित किया गया होता, और वह उसका एक अंग होता।^४

उनकी यह भी राय थी कि वनस्पति-विज्ञान, जीव-विज्ञान आदि विषयों के समान ही कृषि-विज्ञान का सम्मान हो। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी कृषि-विज्ञान का अध्ययन करें तो वे अपने जीवन में दूसरे बहुत से विषयों से, जिन्हें वे पढ़ते हैं, उसे अधिक लाभदायक पायेंगे।^५

मालवीयजी ने आशा व्यक्त की कि यदि इन कृषि कालेजों में पर्याप्त संख्या में स्नातक परिशिक्षित कर दिये गये, और वे किसानों की सहायता से खोज के

१. एग्रीकलचरल कमीशन रिपोर्ट, जिन्द ७, पृ० ७०४-७०५।

२. वही, प्रश्न ४०, ०५१। ३. वही, पृ० ७०२।

४. वही, पृ० ७०२। ५. वही, पृ० ७३२, प्रश्न ४०, ०३३।

काम में लगाये गये, तो वे इन अनुसधानो में तथा खेती के वैज्ञानिक विवेचन में किसानो की दिलचस्पी हासिल कर सकेंगे ।^१

मालवीयजी ने बम्बई प्रदेश के भूतपूर्व गवर्नर एलफिन्सटन के वक्तव्य को, सर चार्ल्स वुड की सन् १८५४ की शिक्षा सम्बन्धी प्रज्ञप्ति को, तथा अकाल कमीशन की सन् १८८१ की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए कहा कि यदि कृषि आयोग नहीं चाहता हो कि उसकी संस्तुतियों का वही हाल हो जो अकाल कमीशन की संस्तुतियों का हुआ है, तो बालको के लिए सर्वत्र निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय ।^२ इस सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के लिए यदि आवश्यक हो तो शिक्षा अवकाश (उप-कर) लगाया जा सकता है । जब किसान के बच्चे लिखना पढ़ना भी नहीं जानेंगे, बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य बने रहेंगे, तब वे नये वैज्ञानिक आविष्कारो और कृषिक छात-वीन की उपलब्धियों से ठीक ठीक लाभ कैसे उठा सकेंगे ?

किसानो की दयनीय दशा का चित्र खींचते हुए मालवीयजी ने संस्तुति की कि लगान का बोझ कम किया जाय, किसानो को अपनी मेहनत से पैदा की गयी खेती से अधिक लाभ उठाने दिया जाय । उन्होंने कहा कि लगान में कमी ही किसानो की आर्थिक दशा को सुधारने का सबसे अधिक विश्वसनीय ढंग है, और किसी दूसरे ढंग से उनको दशा में आवश्यक सुधार नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में उन्होंने ओकनोर महोदय के कतिपय वाक्यों को उद्धृत किया जिनमें लगान के बोझ को कम करने की सलाह दी गयी थी, और कहा गया था कि इसमें सन्देह है कि किसानों को साहूकारो के चंगुल से बचाने के लिए जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनका बहुत प्रभाव होगा, और यदि उनका पूरा पूरा प्रभाव हो भी जाय, तो भी वे किसानो की दशा को पर्याप्त ढंग से सुधार पायेंगी, जब तक कि धरती की उपज का बड़ा भाग उनके पास नहीं छोड़ा जाता, और सरकारी अफसरों और जमींदारों द्वारा की गयी करवृद्धि से उनकी रक्षा नहीं की जाती । मालवीयजी ने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि यदि मालगुजारी (राजस्व) में पच्चीस तीस प्रतिशत की कमी किसान के हित में सुरक्षित कर दी जाय, तो वह उस वर्ग की उन्नति में अधिक लाभदायक सिद्ध होगी, "जो आबादी का अधिकांश है और राज्य की अर्थव्यवस्था में जिसका सबसे अधिक योगदान है ।"^३

१. वही, पृ० ७०५ ।

२. वही, पृ० ७१० ।

३. वही, पृ० ७१० ।

कमीशन के सदस्य सर गंगा राम ने मालवीयजी से प्रश्न किया कि बिहार में एक राजा है जो किसानों से लगान में पाँच रुपया एकड़ वसूल करते हैं, जबकि सरकार को तीन आना एकड़ के हिसाब से मालगुजारी देते हैं, ऐसी दशा में वे स्थायी बन्दोबस्त के विरुद्ध प्रचार क्यों नहीं करते ? इस पर मालवीयजी ने कहा : “मुझमें साहस की कमी नहीं है, मैं ससार में सब अच्छी चीजों का प्रचार नहीं करता, पर जब लेजिस्लेटिव असेम्बली में बहस के बाद इस पर वोट करने का अवसर आये और मैं वोट न दूँ तब आप मेरी निन्दा करें।”^१ उन्होंने एक दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा : “मैं सरकारी अफसरों या जमींदारों द्वारा काश्तकारों के लूटे जाने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार और जमींदार दोनों अपने काश्तकारों का आज जितना ध्यान रखते हैं, उससे अधिक ध्यान रखें।”^२ सर गंगाराम ने इसे प्रचार घोषित करते हुए पूछा कि क्या वे अपने प्रान्त के जमींदारों से यह बात कहते हैं ? इसके उत्तर में मालवीयजी ने कहा “हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें आपके सामने पेश कर सकूँ और आपसे कह सकूँ कि आप उनसे प्रश्न करें। मैंने सब स्थानों पर जमींदारों से कहा है और पिछले चुनावों में भी यह कहा है कि यदि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तब आपको अपने काश्तकारों के साथ न्यायसंगत होने के लिए राजी होना चाहिए, उन्हें उनका दातव्य (due) देने को राजी होना चाहिए, और मैं काश्तकारों को सलाह दूँगा कि वे आपको आपका पावना दें। मैंने यह बात इस वर्ष ही नहीं, पिछले बहुत वर्षों में बार-बार कही है।”^३

मालवीयजी ने कहा कि यह प्रतियोगिता का युग है, इसमें हमारे किसानों को ससार के किसानों से टक्कर लेनी है। “इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के धरती के जोतनेवालों के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक उपकरण (इन्विपमेंट) महत्त्वपूर्ण और निर्धारी तत्त्व बनेंगे। यदि किसान की भलाई सुनिश्चित करनी है, यदि उसे औद्योगिक संघर्ष में जिसका उसे मुकाबला करना है, डटे रहना है, तब भविष्य में अधिक हृष्ट-पुष्ट तथा आर्थिक दृष्टि से अधिक ऊँचा जीवन बिताने के लिए उसकी सहायता करनी चाहिए। अधिक आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता और उचित गौरव की भावना का उसमें पोषण करना चाहिए। उसे सरकारी प्रशासनिक, न्यायिक, माल और पुलिस अफसरों की, तथा जमींदारों और उनके कारिन्दों की ओर मुँह उठाकर देखने की सीख देनी चाहिए। उसे बताना चाहिए

१. वही, पृ० ७३२, प्रश्न ४०,०२२।

२. वही, पृ० ७३२, प्रश्न ४०,०२४।

३. वही, पृ० ७३२, प्रश्न ४०,०२६।

कि उसे नागरिकता के वही प्राथमिक अधिकार प्राप्त हैं जो उसके अधिक सम्पन्न संगी-साथियों को प्राप्त हैं।”^१

कमीशन के सदस्य सर हेनरी लारेन्स के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मालवीयजी ने कहा कि काश्तकार इस समय ‘छोटा आदमी’ समझा जाता है। उसका यथोचित आदर नहीं होता। “मैं चाहता हूँ कि अच्छे काश्तकार का उतना ही सम्मान हो जितना कि एक वकील या डाक्टर का, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वह राष्ट्रीय सम्पत्ति में योगदान करता है।”^२ उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि दूसरे सम्मानित पुरुषों की तरह काश्तकार भी दरबारों में आमंत्रित किये जायें, उनके साथ ईमानदार संगी-साथियों का-सा बर्ताव किया जाय, जो देश के भरणपोषण के लिए सब कठिनाइयाँ सहते हुए खेत जोतते हैं, जो सरकार की पुष्टि करते हैं, और जिनके हम आभारी हैं।^३ एक दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि काश्तकार स्वयं अनुभव करे कि वह दूसरे लोगों के समान ही देश का अच्छा और आदरणीय कार्यकर्ता है, वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता है, और इस रूप में उसका सम्मान और उसकी कदरदानी होनी चाहिए।^४

इस कार्य की सिद्धि के लिए उनका सुझाव था कि एक “शाही कृषिक और औद्योगिक संस्थान” खोला जाय, जिसकी शाखाएँ प्रत्येक जिले में हो, और जिनकी बैठको और सम्मेलनों में किसान सम्मान-सहित निमंत्रित किये जायें। मालवीयजी चाहते थे कि सम्राट् स्वयं उसके सर्वोच्च संरक्षक, तथा वाइसराय और राजे महाराजे उसके संरक्षक हों।

मालवीयजी की राय थी कि खेती की दशा को सुधारने के लिए मनु की व्यवस्था और आधुनिक व्यवस्था दोनों की अच्छी बातों का प्रयोग किया जाय।^५ वे चाहते थे कि पशुपालन के निमित्त चरागाहों का समुचित प्रबन्ध किया जाय, गोबर जलाने के बजाय खाद के काम में लाया जाय, किसानों को समझा बुझाकर उनकी रजामन्दी से छोटी-छोटी जोतों की चकबन्दी की जाय।

प्रश्नों का उत्तर देते हुए मालवीयजी ने कहा कि उनकी राय में निरामिष भोजन काफी पौष्टिक है, और शरीर की पुष्टि के लिए गोشت या अडे खाना

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| १. वही, पृ० ७०९। | २. वही, पृ० ७१५, प्रश्न ३९, ८४८। |
| ३. वही, पृ० ७१५, प्रश्न ३९, ८४९। | |
| ४. वही, पृ० ७१६, प्रश्न ३९, ८५२। | |
| ५. वही, पृ० ७१६, प्रश्न ३९, ८५३। | |

आवश्यक नहीं है। वे चरागाहों की समस्या को सरल बनाने के नाम पर बूढ़ी गायों का बध उचित नहीं समझते थे। उनका कहना था कि बूढ़ी गाय भी "साल व साल बछड़े देती रहती है, और यदि वह दूध नहीं देती तो बछड़ा तो देती है, जो अधिक मूल्य की चीज है, और यदि वह धरती पर रहती और चरती है, तो वह धरती के लिए खाद भी देती है, और अन्त में जब वह मरती है तो अपनी खाल छोड़ जाती है। उस मनुष्य को जिसके वच्चों ने उसका दूध पिया है गाय का कृतज्ञ होना चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए, और उसे वूचरखाने को नहीं भेजना चाहिए।"^१ एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में इन्हीं बातों को दुहराते हुए उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो बूढ़ी गाय को उस घास की उपज के लिए, जिसे वह खाती है, धरती जोतने को हल में जोता जा सकता है।^२

भूमि पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए, तथा देश को अकाल की भयानक स्थिति से बचाने के लिए मालवीयजी ने देश की औद्योगिक उन्नति भी आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि कच्चे माल के निर्यात और औद्योगिक सामान के आयात के कारण भारत के उद्योगों का बहुत क्षति हुई है, और औद्योगिक वर्ग के लोगों को अपनी जीविका के लिए अब खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। खेती के अतिरिक्त दूसरे उद्योगों की कमी के कारण देश की आर्थिक दशा बिगड़ती जा रही है और जनता में अकाल का मुकाबला करने की शक्ति भी बहुत कम हो गयी है, औद्योगिक विकास की नितान्त आवश्यकता है।

कमीशन के सदस्य श्रीकामथ के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि उद्योगों की उन्नति के परिणाम-स्वरूप खेतिहर मजदूरों का वेतन बढ़ेगा, पर, उन्होंने कहा, "खेतिहर मजदूरों को इस समय काफी नहीं मिल रहा है। अगर खेतिहर को अपने श्रम के लिए कुछ और मिल जाता है तो वह उसके लिए अच्छा ही है। अगर उद्योगों की वृद्धि होगी तो राष्ट्र की औसत आमदनी भी बढ़ेगी।"^३



१. वही, पृ० ७३०, प्रश्न ४०,०११।

२. वही, पृ० ७३०, प्रश्न ४०,०१२।

३. वही, पृ० ७३०, प्रश्न ४०,००८।

८. उदार हिन्दू धर्म और सरल हिन्दी

प्रतिक्रिया

मुस्लिम लीग की गतिविधि से बहुत से हिन्दू नेता और कार्यकर्ता क्षुब्ध थे। उनमें से कुछ किसी हिन्दू मंच से उसके दावों और मागों का विरोध, तथा हिन्दू हितों का पोषण आवश्यक समझने लगे थे। पंजाब के कतिपय हिन्दू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तो सन् १९०७ में मुस्लिम लीग की स्थापना के कुछ दिन बाद ही अपने प्रान्त में हिन्दू सभा के संघटन के संवध में कार्य प्रारम्भ कर दिया था। उन्होंने सन् १९०९ में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से कुछ दिन पहले एक कान्फ्रेंस द्वारा निश्चय किया कि हिन्दू हितों की रक्षा कांग्रेस द्वारा नहीं हो सकती, हिन्दुओं को इसके लिए कांग्रेस से अलग मुस्लिम लीग की टक्कर के लिए उस जैसी राजनीतिक संस्था बनानी होगी।

मालवीयजी भी मुस्लिम लीग की गतिविधि, दावों और मागों से क्षुब्ध थे। उन्हें सरकार की भेद-नीति पर भी खेद था। पर वे कांग्रेस से अलग मुस्लिम लीग जैसी प्रतिद्वन्दी हिन्दू राजनीतिक पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं थे। वे ऐसा करना सारे देश के लिए, हिन्दू जाति के लिए भी, हानिकर समझते थे। वे तो कांग्रेस को देशव्यापी राष्ट्रीय भावना के आधार पर देश का ऐसा सक्रिय राजनीतिक संघटन बनाना चाहते थे जिसकी बात स्वीकार करना सरकार के लिए आवश्यक हो जाय।^१

वे हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य को भी बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी धारणा थी कि 'इन दोनों में जितना ही वैर या विरोध या अनेकता रहेगी, उतना ही हम दुर्बल रहेंगे।'^२ इसलिए जो हिन्दू या मुसलमान "एक जाति को दूसरी जाति से खटाने का प्रयत्न" करता है, वह "देश का शत्रु है,—अपनी विशेष जाति का भी शत्रु है।"^३

वे स्वीकार करते थे कि हिन्दुओं को अपने ही देश में "किसी जाति से राजनीतिक महत्त्व में कम समझा जाना हमारी जाति के लिए अत्यन्त कलक

१ देखिये, दिसम्बर सन् १९०९ में कांग्रेस में किया गया मालवीयजी का अध्यक्षीय भाषण।

२. 'अभ्युदय', फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, सम्बत् १९६३। ३. वही।

और अपमान का विषय है”,^१ पर उनकी राय में “यह कलक और अपमान मुसलमानों या किसी और जाति का विरोध करने से नहीं मिटेगा। इसको मिटाने का एकमात्र उपाय अपने कर्तव्यों का पालन करना है।”^२ इसके लिए वे ‘धर्मोपदेश’ आवश्यक समझते थे। मालवीयजी ऐसा चाहते थे कि हिन्दू जनता में सनातन धर्म के सजीव तत्त्वों और मूल सिद्धान्तों का प्रसार किया जाय, उसमें उचित गुण उत्पन्न किये जायें, उसे अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाय, और इस तरह समाज में जीवन और शक्ति संचारित की जाय।

वे ये सब काम ‘भारत धर्म महामण्डल’ द्वारा कराना चाहते थे। पर जब उन्होंने देखा कि उसके धर्मोपदेशक और संचालक उसे ठीक तौर पर करने को तैयार नहीं हैं, तब उन्होंने अलग से अपने मन की ‘सनातन धर्म सभा’ स्थापित की, और उसके द्वारा धर्म के मूल सिद्धान्तों के प्रचार का प्रबन्ध किया। उन्होंने स्वयं लेखों, भाषणों और कथाओं द्वारा अपने धार्मिक विचारों से हिन्दू जनता को लाभान्वित किया।

सुधार

उन्होंने स्वीकार किया कि (“शास्त्रविहित विधियों का अन्धवत् अनुकरण” निःसन्देह “हानिकर” है^३, तथा हमारे नित्य कर्मों में कई ऐसी प्रथाओं का समावेश हो गया है जो किसी प्रकार शास्त्र-विहित नहीं हैं।^४ उन्होंने यह भी बताया कि समय के हेरफेर से शास्त्रविहित शब्दों के अर्थ और उनके आन्तरिक भावों में भी ऐसी तब्दीली हुई है जिसने हमारे विचारों, चरित्रों, रीतियों और व्यवहारों को कुछ का कुछ बना दिया है, और इसके कारण हमारे जातीय जीवन को काया ऐसी पलटी है कि जब तक उन शब्दों के वास्तविक तात्पर्य और अर्थ को हिन्दू जाति के सामने दुबारा पूर्णरूप से न रखा जायेगा, और उन शब्दों के साथ श्रेष्ठ और उच्च भावों और विचारों से सम्बन्ध न पैदा किया जायगा, तब तक हमारे सामाजिक व्यवहार और नीति का सुधार होना बहुत कठिन है।^५)

धर्म के मूल सिद्धान्त

मालवीयजी ने धर्म के मूल सिद्धान्तों के प्रचार की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा . “विना मूल सिद्धान्तों को दृढ़ किये धर्म का प्रचार

१. वही, २६ मार्च सन् १९०९।

२. वही।

३. ‘अभ्युदय’, २ मई, सन् १९०८।

४. वही।

५. ‘अभ्युदय’, २५ जनवरी, सन् १९०९।

और उसकी उन्नति करना ऐसा ही असम्भव है जैसा कि बिना किसी बुनियाद के किसी इमारत को खड़ा करना। यही कारण है कि धर्म अपना स्वरूप नहीं ग्रहण कर रहा है, और धर्म से उत्पन्न होनेवाली लोक-संग्रहकारी (समाज को बाँधने-वाली) शक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है।^१

धर्म के मूल सिद्धान्तों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया : "वस्तुतः धर्म उन व्यवस्थाओं, उन नियमों का नाम है जो समाज को, राज्य के भिन्न-भिन्न अंगों को, धारण किये रहते हैं।"^२ धर्म के जो मूल सिद्धान्त हैं उन सब का उद्देश्य देश में शान्ति, समृद्धि और सुख उत्पन्न करना, तथा मनुष्य को पारलौकिक गहन विषयों का चिन्तन करने के योग्य बनाना है।^३

उन्होंने मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म के लक्षणों को धर्म के मूल सिद्धान्त स्वीकार करते हुए कहा "धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध—में वे सब गुण आ गये हैं जिनसे लोगो में सदाचार की पवित्रता हो, एकता हो, बल आने और वे सुखी हों।"^४

सच्चा सुख

सुख का विश्लेषण करते हुए मालवीयजी ने बताया : "(१) मनुष्य भले घुरे जितने कर्म करता है, अपने सुख के लिए हो करता है, (२) सुख उसके उद्देश्य और अभिलाषाओं की पूर्ति में मिलता है, (३) उद्देश्य और अभिलाषाएं जितनी ही ऊँची हो, उतना ही अधिक सच्चा और चिरस्थायी सुख मिलता है।"^५ इस तरह "सच्चे सुख का अनुभव वही मनुष्य करता है, जिसके चित्त में उत्कृष्ट अभिलाषाएं और उद्देश्य हो और जो उनकी पूर्ति के लिए दृढ़तापूर्वक यत्न करता रहे।"^६ उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निकृष्ट व्यक्ति भी देशोपकार और परोपकार के मार्ग का अनुसरण कर अपने चित्त को निर्मल बना सकते हैं, तथा उच्च उद्देश्य और अभिलाषा से उसे समन्वित कर सकते हैं। उन्होंने सबसे अनुरोध किया कि वे 'प्रण' करें कि वे जितने कार्य करेंगे, उनमें उनका मुख्य उद्देश्य अपने भाइयों के क्लेशों को दूर करना और उनकी यथाशक्ति सेवा करना होगा।^७

१ 'अभ्युदय', २ मई, सन् १९०८।

२. 'अभ्युदय' २ मई, सन् १९०८। ३. वही।

४ वही। ५. 'अभ्युदय', ७ अगस्त, सन् १९०८।

६ वही। ७ वही।

परोपकार

देशोपकार और परोपकार के महत्त्व की महिमा का वर्णन करते हुए मालवीयजी कहते हैं “अपनी जाति को ससार की सम्य जातियों के समान बलवान् बनाना, उसके बीच आदरणीय पद पाना, इससे अधिक बड़ा एवं पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है ? मनुष्य और पशु में क्या भेद रहा, यदि वह अपने असंख्य भाई बहनो को अत्यन्त क्लेश की दशा में देखकर भी स्वयं सुख भोग करता है ? चाहे हम कुछ काल तक वज्र-सा हृदय बनाकर अपने पीडित भाइयों के बीच में आनन्द और सुख भोग कर लें, पर सदा हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। जो दशा हमारे भाइयों की हो रही है, उसका कभी न कभी हमें भी भागी बनना पड़ेगा। यदि भाग्यवश हमें न बनना पड़ेगा, तो हमारी सन्तानों को अवश्य बनना पड़ेगा।”^१

सेवा धर्म का मार्ग

मालवीयजी ने बताया कि सेवाधर्म के पालन के लिए तप, सत्याचरण, निष्काम भावना, आत्मोपम्य व्यवहार, स्वार्थत्याग, तथा ईश्वर की आराधना नितान्त आवश्यक है। उन्होंने कहा “बिना कई लोगों के मिले कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता। लोग आपस में मिलकर तभी कार्य कर सकते हैं, जब उनमें परस्पर विश्वास हो। परस्पर विश्वास तभी हो सकता है, जब सब के सब सत्य के अनुगामी हो।”^२

निष्काम कर्म

निष्काम कर्म की महिमा को बताते हुए उन्होंने कहा . “जो लोग निष्काम भाव से काम नहीं करते, उन लोगों में परस्पर ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं और कार्य सफल नहीं होने पाता। किन्तु जहाँ निष्काम भाव से कार्य होता है वहाँ लोग एक दूसरे की सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं, और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव उत्पन्न होता है, और कार्य में शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। सकाम भाव से कर्म करनेवालों की आपत्तियाँ काम करने से विमुख कर देती हैं, किन्तु निष्काम भाव से कर्म करनेवाले लोग, यह समझकर कि जो कार्य हम कर रहे हैं, वह ईश्वर का कार्य है और इसमें ईश्वर हमारा सहायक है, किसी विघ्न या बाधा के कारण पीछे नहीं हटते।”^३

१. ‘अम्युदय’, २६ मार्च, सन् १९०९।

२. वही।

३. वही।

आत्मोपम्य व्यवहार

आत्मोपम्य व्यवहार की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया : “हमारे शास्त्रों का हमें आदेश है कि ‘आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्’ अर्थात् जो कार्य अपने लिए अहितकर हो, उसे पराये के लिए न करे।” उन्होंने कहा कि यदि हम इसका प्रतिपालन करें, तो देश में परस्पर फूट और विरोध के एव जातीय दुर्धनता के जितने कारण हैं, वे सब दूर हो जायेंगे।^१

स्वार्थत्याग

स्वार्थत्याग की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने लिखा . “अलोभकी भी हमारे शास्त्रों में बहुत महिमा लिपी गयी है। गह लाभ में पड़ने का फल है कि हमारे अनेक देश भाई एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि हमारे देश भाई लोन को छोड़ दे, तो देशद्रोहियों एव धर्मद्रोहियों, सभी का लोप हो जायगा। हमारे नगरनिकारी ने हमें उपदेश दिया है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसे हम ईश्वर की सेवा में अर्पण करें। ईश्वर की सेवा करना, उसके उत्पन्न किये हुए प्राणियों की सेवा करना है। जो ईश्वर की दी हुई शक्तियों को उसकी सेवा में, अर्थात् उनके प्राणियों की सहायता देने के काम में, नहीं लगाना, वह ‘चोर’ कहा गया है।”^२

तप

तप के महत्त्व को बताते हुए उन्होंने कहा . [“तप में अम्युदय और नि-श्रेयस, स्वर्ग और मोक्ष, धन और पम्पनि, नाम और यज्ञ, बल और पराक्रम, सुख और शान्ति, राज्य और अधिकार सब की ही प्राप्ति होती है।”^३] उन्होंने बताया : [“जिस जाति में जितना और जिस प्रकार का और जिस दर्जे का तप होगा, वह उतनी ही अधिक बलवान्, तेजस्वी, बुद्धिमान्, धर्मनिष्ठ और ज्ञानवान् होगी। कोमी इमारत का तप ही मूल, तप ही मध्य, और तप ही अन्त है।”^४]

विभिन्न प्रकार के तपों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सात्त्विक तप का अनुसरण करने का उपदेश दिया और बताया : “जो तप निष्काम भाव से, फल की इच्छा त्याग कर, शम-दम से सम्पन्न होकर श्रद्धा और धैर्य के साथ मन, वाणी और शरीर से किया जाता है, वह सात्त्विक कहलाता है।”^५ इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा : [“मन को जीतना अर्थात् काम-क्रोध-लोभ-मोह

१. वही।

२. वही।

३. ‘अम्युदय’, २५ जनवरी, सन् १९०९।

४. वही।

५. वही।

से बचना और शुद्ध संकल्पयुक्त रहना, किसी विषय वृत्ति के कारण विक्षिप्त होकर फिर भी उस पर विजय प्राप्त करना, व्यवहार-काल में छल-कपट, धोखा, फरेब से मन को दूर रखना, मन को सात्त्विक बनाना—यह मन द्वारा सात्त्विक तप करना है। वाणी का सात्त्विक तप यह है कि जो वाक्य असत्य, दुःखदायी, अप्रिय और खोटा हो, उसको किसी समय, किसी भी अवस्था में मुँह से न निकालना, बल्कि प्रिय, सत्य, मीठे और मधुर वचन बोलना—यह वाणी द्वारा सात्त्विक तप करना है। शरीर से अर्थात् शरीरावयवों, हस्तपादादि कर्मेन्द्रियों के द्वारा दूसरों की सहायता और सेवा करना, गिरे हुएों को उठाना, देश और जाति की सेवा के लिए अपने शरीर के कष्ट और दुःख की परवाह न करना, बल्कि यदि आवश्यक हो तो धर्म और परोपकारार्थ शरीर अर्पण कर देना, यह काया का सात्त्विक तप है।”^{१)}

तप और देश-सेवा

सात्त्विक तप का कार्यकर्ताओं को उपदेश करते हुए उन्होंने बताया - ‘सच्चे तप का भाव उस देशभक्त में है जो अपने देश एवं अपनी जाति के गौरव और प्रतिष्ठा, कीर्ति और मान, सम्पत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि और उन्नति के लिए दृढ़ इच्छा रखता है, तथा अनेक प्रकार के दुःखों, संकटों और कष्टों को सहन करने, कठिन से कठिन मेहनत और श्रम को उठाने, और विघ्नो से मुकाबला करने के लिए उद्यत रहता है। सच्चे देशप्रेमी और देशानुरागी कल्याण की इच्छा करते, तप का अनुष्ठान करते, आत्मा और मन को धर्माचरण रूपी प्रचण्ड अग्नि में दग्ध करके अपनी और अपने देश की अपवित्रता, मलिनता और अन्य अशुद्धियों को दूर कर जाति को आरोग्यता एवं सुखसम्पत्ति की योग्यता प्रदान करते हैं।”^{२)} उनका यह भी कहना था कि “जिन देशानुरागी पुरुषों में तपश्चर्या नहीं, जो मुसीबतों, विघ्नो और आफतों का मुकाबला करने से घबराते हैं, जो द्वन्द्वों को सहन नहीं कर सकते, जो भूख और प्यास, सर्दी और गर्मी, धूप और छाह, कोमल और कठोर, मीठा और खट्टा आदि दोनों के दास हैं, वे संसार रूपी युद्धक्षेत्र में कदापि कृतकृत्य नहीं हो सकते।”^{३)}

परम्परावादी और मालवीयजी

मालवीयजी की व्याख्या भारत धर्म महामण्डल और कट्टर-पथी सनातन-धर्मियों को स्वीकार नहीं थी। वे देशभक्ति से अधिक राजभक्ति को तथा

१. वही।

२. वही।

३. वही।

लोकतन्त्र से अधिक नृपतन्त्र को प्राचीन भारतीय संस्कृति और मनातनधर्म की परम्पराओं के अनुरूप संभक्षते थे। भारत धर्म महामण्डल के महोपदेशक स्वामी दयानन्द ने तो अपनी पुस्तक 'धर्मविज्ञान' में शास्त्रों के आधार पर नृपतन्त्र की व्याख्या करते हुए आशा व्यक्त की कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद फिर एक बार आगे चलकर इन देश में नृपतन्त्र स्थापित होगा। पण्डित लक्ष्मण शास्त्री द्राविण ने तो 'वर्णाश्रम स्वराज्य मंत्र' स्थापित कर कांग्रेस की नीति-रोति तथा शास्त्रों की प्रगतिशील व्याख्या का डटकर विरोध किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि हमारे पास सब कुछ है, हमें दूसरों से कुछ लेना नहीं है। उनकी यह भी धारणा थी कि प्रचलित परम्पराओं में हेरफेर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पुराने शास्त्रों और गिद्धान्तों का नयी व्याख्या भी सारहीन और धर्म-विपरीत दिखाई देती थी।

अपनी उदार व्याख्या का प्रचार करने के लिए मालवीयजी ने सन् १९०६ में प्रयाग में कुम्भ के अवसर पर 'मनातन धर्म सम्मेलन' आयोजित किया, और इसके बाद कुम्भ के अवसर पर अर्थात् पत्येक छ वर्ष पर त्रिवेणी के तट पर बहुत ही धान के साथ मनातन धर्म सम्मेलन आयोजित होते रहे, जिनमें हजारों श्रद्धालु यात्रियों के अतिरिक्त बहुत से साधु-सन्त और विद्वान् किसी न किसी रूप में भाग लेते रहे। सन् १९१८ में कुम्भ के अवसर पर विभिन्न सेवा समितियों के सहयोग से मालवीयजी की अध्यक्षता में 'अग्निल भारतीय सेवा समिति' गठित हुई। इसी अवसर पर श्री श्रीराम बाजपेयी के सहयोग से 'सेवा समिति त्राय स्काउट असोसिएशन' गठित किया गया। मालवीयजी उसके चीफ स्काउट मनोनीत हुए। इसी वर्ष कुम्भ मेले के अन्तिम दिन नफाई का काम करनेवाले कर्मचारियों में कुर्ता, धोती और पटका वितरित किया गया और सबको भोजन कराया गया। मालवीयजी के परिवार की महिलाओं ने भोजन बनाने का काम किया और मालवीयजी ने स्वयं उनका स्वागत किया, सबको धर्मापदेश और आशीर्वाद दिया। सन् १९२४ में कुम्भ के अवसर पर प्रयाग में गंगा के तट पर सफाई का काम करने वाले १५,००० कर्मचारियों को इकट्ठा करके मालवीयजी ने उनमें कपड़े बाँटे, तथा उन्हें प्रह्लाद की कथा सुनायी।

मालवीयजी ने सन् १९२३ में और सन् १९२४ में काशी और प्रयाग में विद्वत् परिषदे आयोजित की, और उनसे शुद्धि, समाजसुधार तथा निम्न वर्गों की उन्नति के सम्बन्ध में शास्त्रों पर आधारित व्यवस्थाएँ लेने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्वयं नासिक, प्रयाग, काशी, कलकत्ता आदि स्थानों पर तथाकथित

अस्पृश्यों के साथ सब वर्णों और जातियों के हिन्दुओं को मन्त्र दीक्षा दी तथा विभिन्न स्थानों में सनातन धर्म सभाएँ स्थापित की, जिन्होंने सनातन धर्म के प्रति जनता की निष्ठा दृढ़ करते हुए मालवीयजी की उदार भावनाओं और व्याख्या का प्रसार किया ।

गोसेवा

सन् १९२८ में प्रयाग में मालवीयजी की अध्यक्षता में सनातन धर्म महासभा का सम्मेलन हुआ, जिसने गोवंश के भयंकर सहार पर सन्तप्त करते हुए गोरक्षा के निमित्त एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पारित किया । इस प्रस्ताव में हिन्दू जनता से अनुरोध किया गया कि (१) वे गौओं को कसाइयों के हाथ में पड़ने से बचावें, (२) कसाइयों के साथ किसी तरह के लेन-देन का व्यवहार न करें, (३) जहाँ तक हो सके चमड़े का व्यवहार न करें, (४) स्वाभाविक मौत से मरे हुए पशुओं के चमड़े से बने हुए जूते आदि ही काम में लायें । प्रस्ताव में हिन्दुओं से यह भी अनुरोध किया गया कि (१) जिसको सामर्थ्य हो वह एक गौ पाले, (२) जहाँ उचित जान पड़े वहाँ एक गौशाला खोली जाय, (३) वे गौशालाओं और पिजरापोलो को दुग्धालय के रूप में परिणत करें, और अपने साँडों द्वारा गौओं की नस्ल सुधारें और दूध बढ़ावें, (४) योग्य पात्र को ही जो गौ का पालन कर सकें, वे गोदान दें और गो-दान के योग्य गौओं का ही दान करें, (५) वृषोत्सर्ग में वे केवल उत्तम जाति के साँड छोड़ें, और वही छोड़ें जहाँ उनकी आवश्यकता हो, और छोड़ने से पहले इस बात का पक्का प्रबन्ध कर लें कि छोड़े हुए साँड का ठीक-ठीक पालन-पोषण और रक्षा होगी । महासभा ने जमींदारों से अनुरोध किया कि (१) वे गाँवों में गोचारण के लिए काफी भूमि छोड़ने का नियम करें, और जिस गोचारण भूमि को खेती में मिला लिया गया हो, उसे छोड़ दें, (२) जहाँ उनकी जमींदारी के भीतर गौ-चैल के बाजार लगते हैं, उनमें वे ऐसा प्रबन्ध करें कि वहाँ धोखे में पड़कर कोई हिन्दू गौ को कसाई के हाथ न वेचे और धोखा देकर कोई कसाई गौ को न खरीद सके ।

इस प्रस्ताव में ही सनातनधर्म सभा ने निश्चय किया कि (१) एक अखिल भारत-वर्षीय गोरक्षा कोष की स्थापना की जावे, जिससे गोचर-भूमि की वृद्धि और गोरक्षा के और साधन प्रस्तुत किये जावें, (२) कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ल अष्टमी अर्थात् गोवर्धन पूजा के दिन से गोपाष्टमी तक प्रतिवर्ष 'गोसप्तह' मनाया जाय, जिसमें गोरक्षा सम्बन्धी उत्सव, गोपूजा, गोकथा, गो-महात्म्य, व्याख्यान तथा गोपरिपालन के साहित्य का प्रचार किया जाय, और प्रतिपदा के दिन सारी हिन्दू जनता से गो-रक्षा के लिए दान माँगा जाय ।

महासभा ने अपनी कार्य समिति को आदेश दिया कि वह स्थान-स्थान पर गोचर भूमि को छुड़ाने और गोरक्षा के अन्य उपायों को करने के लिए, विशेष कर सरकारी जंगलों में गोचर-भूमि छोड़े जाने के लिए, प्रान्तीय कौंसिलों तथा व्यवस्थापिका सभा और देशी राज्यों के द्वारा कानून बनवाने का प्रयत्न करे।

पंजाब में सनातन धर्म सभा का काम

सन् १९२४ में रावलपिंडी में पंजाब प्रान्तीय सनातन धर्म सम्मेलन में मालवीयजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए अस्पृश्यों को सार्वजनिक कुओं से जल भरने देने का, और सार्वजनिक स्कूलों में उनके बच्चों को पढ़ने देने का सर्वर्ण हिन्दुओं को उपदेश दिया। सन् १९२५ में धर्मयज्ञ करवा कर उन्होंने अमृतसर के प्रसिद्ध दुर्गयाना मन्दिर और सरोवर की स्थापना की। सन् १९२८ और सन् १९२९ में उन्होंने सनातन धर्म के निमित्त पंजाब में दौरा किया।

सन् १९३४ में पंजाब प्रान्तीय सनातन धर्मसभा के सम्मेलन की मालवीयजी ने दोबारा अध्यक्षता की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा . “सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। यह प्राणी मात्र के लिए है। मनुष्य मात्र के लिए है”^१ और “ईश्वर का ज्ञान” उसकी सबसे पहली शिक्षा है। वह बतलाता है कि “ससार का रचनेवाला, पालन करने वाला और संहार करनेवाला केवल वही परमात्मा है जिसका कोई सानी नहीं” और जो “प्राणी-प्राणी में व्यापक है।”^२ उन्होंने कहा कि “जब एक बार यह मान लिया कि ईश्वर घट-घटव्यापी है, तब सिद्धान्त है कि जो बात अपने लिए चाहते हो, वही दूसरों के लिए चाहो।”^३

उन्होंने वर्णव्यवस्था की व्याख्या करते हुए कहा कि वह न तो असर्वर्ण विवाह के पक्ष में है^४, और न जात-पात तोड़क विचार को ठीक समझते है।^५ पर हमें अपनी जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए, और न दूसरी जाति का निरादर करना चाहिए।^६ हमें यह समझना चाहिए कि “जो ब्राह्मण अच्छा काम करेगा उसकी इज्जत होगी, जो बुरा काम करेगा उसका यश न होगा, और शूद्र से भी नीचे गिर जायगा। वह शूद्र जिसमें ब्राह्मण के गुण आजायेंगे, वह ब्राह्मण के समान आदर पाने के योग्य हो जायगा, मगर ब्राह्मण नहीं हो जायगा।”^७

१. महामना श्री पंडित मदन-मोहन जी मालवीय के लेख और भाषण, भाग १—धार्मिक, पृ० १८५।

२. वही, पृ० १८४।

३. वही, पृ० १८४।

४. वही, पृ० १८६।

५. वही, पृ० १८७।

६. वही, पृ० १८७।

७. वही, पृ० १८६।

मालवीयजी ने इस व्याख्यान में “ॐ नम शिवाय” तथा “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” एवं “ॐ नमो नारायणाय” मन्त्रों की महिमा की व्याख्या करते हुए कहा : “पुराणों के अनुसार इन मन्त्रों के उच्चारण और जाप से पतित भी ‘पवित्र’ हो जाता है, वह ‘सब पाप से छूट जाता है’।”^१ इन मन्त्रों की दीक्षा लेने का सबको अधिकार है। हमारा कर्तव्य है कि हम अन्त्यज पर्यन्त सब हिन्दुओं को इन मन्त्रों से दीक्षित कर उनके जीवन को पवित्र बनाने में सहायक हो।

मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा : “मैं यह नहीं कहता हूँ कि भगी और डोम आकर शिवजी की पूजा करें, यद्यपि इसका भी प्रमाण शास्त्र में है। मैं तो यह कहता हूँ कि उन्हें दूर से दशन कर लेने दो। वे भी प्रवेश न करें जब तक उन्हें दीक्षा न मिले।”^२ उन्होंने यह भी बताया कि जिन शास्त्रों ने अस्पृश्यता की व्यवस्था की है उन्होंने यह भी कहा है : “तीर्थ, यात्रा, देवालय, सड़क आदि में तथा नगर में आग लगने के अवसर पर छुआछूत का विचार नहीं होना।”^३ उन्होंने यह भी कहा है “प्रत्येक अछूत को अधिकार है कि वह अपने घर में प्रतिमा रखे। मेरी इच्छा है कि प्रतिमा के रूप में भगवान् को सब के घर पहुँचा दें, ताकि सभी लोग भगवान् का पूजन करे।”^४

आश्रम धर्म की व्याख्या करते हुए मालवीयजी ने कहा : “आयुर्वेदवाले कहते हैं कि २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष की स्त्री का परस्पर सम्बन्ध होना चाहिए। इस अवस्था से पहले जो बालक होगा, वह या तो मर जायगा या दुर्बल होगा।” ब्रह्मचर्याश्रम सब धर्मों का मूल है, नीव है। नीव कमजोर हो जायगी तो क्या करोगे? सनातनधर्म का उपदेश यही है कि पहले पचीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो।”^५

मालवीयजी ने अपने इस भाषण के प्रारम्भ में ही सनातनधर्म प्रतिनिधि सभा को, इसके सभापति राय बहादुर राम शरण दास, मन्त्री गोस्वामी गणेश दत्त तथा अन्य कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हुए कहा “पंजाब में धर्म सम्बन्धी शिक्षा प्रारम्भ करने का श्रेय आर्यसमाजियों को है। विद्याविभाग में उन्होंने काफ़ी उन्नति की है। डी०ए०वी० कालेज के अतिरिक्त लगभग ४४ स्कूल इस प्रान्त में आर्य भाइयों द्वारा संस्थापित हैं। यह कार्य उन लोगों ने कुछ पहले किया। पर सन्तोष की बात है कि सनातनधर्मियों ने, यद्यपि इस में पीछे हाथ

१ वही, पृ० १९६-१९७।

३ वही, पृ० १८९।

५. वही, पृ० १८८।

२ वही, पृ० १९२।

४. वही, पृ० १९३।

लगाया, फिरभी नियत समय में उचित उन्नति की। सन् १९२३ ई० में केवल १२३ सनातनधर्म सभाएँ थी। महावीर दल का श्रीगणेश अभी नहीं हुआ था। पर आज दस वर्ष बाद ४०० सनातनधर्म सभाएँ, ३३५ महावीर दल, ३२ हाई स्कूल, ८ मिडिल स्कूल, १ कालेज तथा १४८ कन्या पाठशालाएँ इस प्रान्त में काम कर रही हैं। हाई स्कूल में २२,००० विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। किसी भी सस्था के लिए इतने कम समय में इतना काम करना सन्तोष की बात है।”^१ उन्हें इस बात का भी सन्तोष था कि १४५ उपदेशक घूम रहे हैं^२, पर वे चाहते थे कि संगठन और सुदृढ़ किया जाय।

संघर्ष

हिन्दुओं को विघटित करने के उद्देश्य से एक बार जनगणनाधिकारी रिसले ने इरादा किया कि तथाकथित अस्पृश्यों की गणना हिन्दुओं से अलग की जाय। मालवीयजी ने इसका डट कर विरोध किया और काशी आदि स्थानों में सभाएँ की, जिनमें उनके प्रोत्साहन पर गजाधर प्रसाद आदि उन जातियों के नवयुवकों ने भी, जिन्हें सरकार हिन्दू जाति से अलग करना चाहती थी, घोषित किया कि वे हिन्दू हैं, और उनके भाई बन्धु हिन्दू समाज से सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं। उन्होंने माग की कि उनकी विरादरियों के लोगों की गणना हिन्दुओं की श्रेणी में ही होनी चाहिए। जनगणनाधिकारी ने उनकी अलग गणना का विचार छोड़ दिया, फिर भी रिसले साहब ने अपनी रिपोर्ट में शारीरिक आकृति के आधार पर हिन्दुओं के आन्तरिक सामाजिक भेदों को प्रजातीयता का स्वरूप देने की कोशिश की। पर उनके उत्तराधिकारी ने दस वर्ष बाद अपनी जनगणना रिपोर्ट में रिसले साहब के विश्लेषण और निष्कर्षों का खण्डन करते हुए लिखा कि व्यावसायिक और आर्थिक स्थिति की विभिन्नता से भी शारीरिक आकृतियों और बनावट में भेद हो सकता है।

सन् १९२६ में मालवीयजी के आग्रह पर सर जेम्स मेस्टन की अध्यक्षता में हरिद्वार की गंगा नहर के सम्बन्ध में हरिद्वार में ही सरकार ने एक सभा आयोजित की, जिसमें कतिपय सरकारी अफसरों के अतिरिक्त कई राजाओं-महाराजाओं ने भी भाग लिया। मेस्टन साहब ने मालवीयजी के अनुरोध पर सन् १९१४ के निर्णय को बदलते हुए घोषित किया कि जलमार्ग पाँच फुट के बजाय छः फुट कर दिया जायगा, और हर की पैड़ियों पर गंगा की धारा को अविच्छिन्न रखने का भी प्रबन्ध कर दिया जायगा।

सन् १९२४ में अर्ध कुम्भी के अवसर पर प्रयाग में धारा ने ऐसा मोड़ लिया कि त्रिवेणी संगम पर स्नान संकटपूर्ण समझ कर सरकार ने हुक्म निकाल दिया कि त्रिवेणी संगम पर कोई स्नान नहीं करेगा। वहाँ जाने के मार्ग में बल्लियाँ गाड़ दी गयीं। मालवीयजी ने संगम पर स्नान करने की आज्ञा मांगी। जब अधिकारियों ने आज्ञा नहीं दी, तब उन्होंने सत्याग्रह करने का निर्णय किया। उन्होंने बल्लियों के मजबूत घेरे को पार करने के लिए एक सीढ़ी ली। पर वहाँ पहुँचने पर पुलिस ने उनसे सीढ़ी ले ली, और उन्हें बल्लियाँ पार करके संगम नहीं जाने दिया। मालवीयजी और दूसरे बहुत से स्नानार्थी गंगा की रेती में सत्याग्रही के रूप में जम कर बैठ गये। यह सत्याग्रह कई घंटे तक चलता रहा। घुड़सवार और पुलिस किसी को घेरे के पास जाने नहीं देती थी, जो जाने का प्रयत्न करता उसे पीछे हटा देती थी। आखिर में मालवीयजी ने स्नान करने का निश्चय कर घुड़सवारों और पुलिस के सिपाहियों के घेरे में से निकलकर संगम पर जाने का निर्णय किया। वे बड़ी फुर्ती और दक्षता से सवारों और सिपाहियों के बीच से निकल गये। मालवीयजी जैसे बूढ़े के लिए यह काम निःसन्देह बहुत ही विस्मय की बात थी। मालवीयजी के पीछे पीछे दूसरे स्नानार्थी सत्याग्रही भी इसी तरह आगे बढ़े। घुड़सवारों और पुलिस के सिपाहियों ने कुछ देर उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, पर अन्त में ठंडे पड़ गये। मालवीयजी ने दूसरे स्नानार्थियों के साथ त्रिवेणी संगम पर स्नान किया।^१

सन् १९२७ में हरिद्वार में कुम्भ होनेवाला था। उसके प्रबन्ध के लिए हर की पैडियों के पास जिलाधिकारी की अनुमति से म्युनिसिपैलटी ने एक पुल बनवाया ताकि उस पर से सरकारी अफसर प्रबन्ध का निरीक्षण कर सकें। हरिद्वार की गंगासभा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि निरीक्षण के लिए पुल के बजाय पास में एक चबूतरा या मंचान बनवाया जा सकता है। चमड़े का जूता पहन कर पुल पर चढ़ना तो, उसने कहा, हिन्दू जनता की भावनाओं के विरुद्ध है। पहले तो जिलाधिकारी इस बात पर राजी हो गये कि चमड़े का जूता पहन कर कोई अफसर पुल पर नहीं चढ़ेगा, पर पुलिस के इन्स्पेक्टर-जनरल के विरोध पर जिलाधिकारी ने अपनी बात वापस ले ली, और गंगा सभा के अधिकारियों को डराना धमकाना शुरू किया। इस पर मालवीयजी ने १० अप्रैल सन् १९२७ को युक्त प्रान्त के गवर्नर को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सब बातों को विस्तार से बताते हुए गवर्नर से अनुरोध किया कि पुल

को काम में लाने का विचार त्याग दिया जाय। इस पत्र में हिन्दू जनता के असन्तोष और क्षोभ की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सत्याग्रह की संभावना का भी उन्होंने संकेत किया। मालवीयजी के अनुरोध पर गवर्नर ने मेले के अधिकारियों को आदेश दिया कि पुल का प्रयोग न किया जाय।^१

इसी हरिद्वार में मालवीयजी ने एक बार वहाँ की नगरपालिका के आदेश का उल्लंघन करते हुए ब्रह्मकुण्ड पर कथा कही और 'धर्मो रक्षति रक्षितः' की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि साहस और धैर्य के साथ धर्म का पालन करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। 'प्राण जाहि पर, धरम न जाही'—यही तो आर्य-सन्तानों का प्रण है। उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर ने कहा है—

मम प्रतिज्ञा च निबोध सत्या ।

वृणे धर्मममृताञ्जीविताञ्च ।

राज्य च पुत्राश्च यशो धन च ।

सर्वं न सत्यस्य कलामुपैति ।

अर्थात्—'मेरी प्रतिज्ञा को सत्य जानो। मैं धर्म को जीवन से और मोक्ष से भी अधिक अच्छा समझता हूँ। राज्य और पुत्र एवं यश और धन—ये सब सत्य के पासग के बराबर के नहीं हैं।'

माता कौशल्या ने अपने लाडले पुत्र राम के वन जाते समय मंगल मनाते हुए कहा है—

यं पालयति धर्मं त्वं प्रीत्या च नियमेन च ।

स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥

अर्थात्—'हे रघुकुल शार्दूल, जिस धर्म का तुम प्रीति और नियम के साथ पालन करके वन को जाते हो, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करे।'

मालवीयजी ने कहा, याद रखो—

जो हठि राखै धर्म को, तेहि राखै कर्तार ।

उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी ने सब वेदों और पुराणों के उपदेशों के निचोड़ को महाभारत में इस प्रकार बताया है—

न जातु कामान्न भयान्न लोभात्,

धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।

धर्मो नित्य सुखदुःखेत्वनित्ये,

जीवो नित्यो हेतुस्त्वनित्यः ॥

अर्थात्—‘धर्म को कभी काम के वश होकर, भय से अथवा किसी प्रकार के लोभ में पड़कर भी कभी न छोड़ो, प्राण बचाने के लिए भी न छोड़ो ! धर्म अविनाशी है, सुखदुःख आते जाते हैं। जीव अविनाशी है, जिन कारणों से वह देह को धारण करता है, वे अनित्य हैं।’

मालवीयजी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से भारत के इतिहास का दिग्दर्शन कराते हुए बताया कि किस तरह मर्यादापुरुषोत्तम राम और सत्यवादी हरिश्चन्द्र ने धर्म के कारण कष्ट सहें, किस प्रकार राणा प्रताप आदि ने अपने बालबच्चों के सुखदुःख की चिन्ता न कर शत्रु से लड़ते-लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी, और किस तरह चित्तौड़ और राजपूताने की ललनाओं ने चिता लगाकर अपने सुकुमार शरीर को जला देना स्वीकार किया, पर अपने धर्म से डिगने का विचार तक मन में नहीं आने दिया। हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करें।

हिन्दी भाषा और साहित्य

१० अक्टूबर सन् १९१० को काशी में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में मालवीयजी ने अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने हिन्दी भाषा-भाषी जनता से हिन्दी सीखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा: “मातृभाषा को सीखने में कौन लज्जा” की बात है? सब तो यह है कि जो पुरुष अपने देश की भाषा न जानता हो वह क्या कभी गौरवान्वित हो सकता है?

उन्होंने कहा कि देश की सब भाषाओं की उन्नति हो, “उर्दू के प्रेमी उर्दू की उन्नति का यत्न करें, और हिन्दी के जाननेवाले हिन्दी की उन्नति का।”^२ उन्होंने कहा कि अच्छा तो यही होगा कि “हिन्दी और उर्दू दोनों को यथासंभव एक स्थान में लाया जाय”, और “दोनों ओर से यत्न होने से हम भाषा के क्रम को बहुत कुछ एक कर सकते हैं।”^३

मालवीयजी ने कहा कि हिन्दी साहित्य के भण्डार को समृद्ध करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमें अन्य भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा में लिखे उत्तम ग्रन्थों का अनुवाद भी करना चाहिए। अंग्रेजों ने अनुवाद द्वारा अंग्रेजी भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाया है, और हमें भी ऐसा करना चाहिए।^४

-
१. सीताराम चतुर्वेदी. महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, खंड २, पृ० २४।
 २. वही, पृ० २६।
 ३. वही, पृ० २७-२८।
 ४. वही, पृ० २९।

मालवीयजी ने कहा : "हिन्दी साहित्य का निर्माण यथासंभव सरल हिन्दी में किया जाय । हमें ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे इस प्रान्त के लोग समझ सकें । लिखने की भाषा यथासंभव बोलने की भाषा से मिलती-जुलती हो ।"^१ जैसी बातें कहिये वैसी ही लिखिये । उन्होंने कहा कि जो शब्द भाषा में चलते हैं और जिन्हें हम जानते हैं, उन्हीं को हमें पुस्तकों और समाचार-पत्रों में लाना चाहिए । "जब हम कोई काव्यपाला लिखें तो आलंकारिक भाषा से काम लें । विज्ञानादि लिखने में पहले भाषा के शब्द लें, जब भाषा में शब्द न मिलें तब संस्कृत से ले या बनायें ।"^२

मालवीयजी ने यह भी कहा कि "हिन्दी में फारसी-अरबी के बड़े-बड़े शब्दों का व्यवहार जैसा बुरा है, हिन्दी को अकारण ही संस्कृत शब्दों से भूँस देना भी वैसा ही बुरा है । जहाँ तक हो हिन्दी में हिन्दी ही रखा जाय ।"^३ वे चाहते थे कि 'अनावश्यक शब्दों को हिन्दी से अलग' किया जाय ।

मालवीयजी चाहते थे कि 'हिन्दी में उर्दू-फारसी के जो शब्द आ गये हैं, उनका व्यवहार जारी रखा जाय' । उनका कहना था . "हिन्दी में कितने ही ऐसे शब्द हैं जो देश की बहुतेरी भाषाओं में ज्यों के त्यों या कुछ बदले हुए रूप में काम में लाये जाते हैं । इन शब्दों के व्यवहार में संकोच न कीजिये । हमें यह देखना चाहिए कि हमारी भाषा के शब्द ऐसे हो जिनसे सब प्रदेश के लोग लाभ उठावें ।"^४

मालवीयजी ने यह भी कहा : "सब भाषाएँ हमारी भाषाएँ हैं"^५ पर "हिन्दी अपनी वहनों में सबसे प्राचीनतम और 'बड़ी वहन' है और माता का रूप और उसी प्रकृति इससे बहुत मिलती-जुलती है ।"^६ उन्होंने हिन्दी भाषा-भाषियों को सम्बोधित करते हुए कहा : "आप भी ऐसा यत्न करें जिससे आपकी भाषा राष्ट्रभाषा बन सके ।"^७

राष्ट्रभाषा

१९ अप्रैल सन् १९१९ को बम्बई में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मालवीय जी ने "देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय भाषा" की मान्यता प्रदान करने पर जोर दिया ।^८ उन्होंने कहा कि

१. वही, पृ० २७ ।
३. वही, पृ० २७ ।
५. वही, पृ० २१ ।
७. वही, पृ० २८ ।

२. वही, पृ० २८ ।
४. वही, पृ० २८ ।
६. वही, पृ० २१ ।
८. वही, पृ० ३० ।

हिन्दी भाषा अन्य देशी भाषाओं की 'बड़ी बहिन'^१ है, "यह भारत के अधिकांश प्रान्तों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है।" "अन्य प्रान्तीय भाषाओं की अपेक्षा इसके बोलनेवालों की संख्या कहीं अधिक है।" "इसी भाषा को बत्तीस करोड़ भारतवासियों में साढ़े तेरह करोड़ लोग बोलते हैं।"^२ उन्होंने यह भी कहा : "गुजराती, बंगाली, मराठी आदि बहुत सी भारतीय भाषाओं से हिन्दी का बहुत मेल है।"^३ उन्होंने बताया कि 'सर आशुतोष मुखर्जी, जस्टिस शारदा चरण मित्र' तथा 'श्रीयुक्त कृष्णस्वामी' जैसे महानुभाव हिन्दी के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर चुके हैं, तथा इसी भाँति गुजराती और महाराष्ट्रीय सज्जन भी हिन्दी के पक्ष में अपनी सम्मति प्रकट कर चुके हैं।"^४

मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए मालवीयजी ने कहा "मुसलमान भाइयों का हिन्दी को मानना कोई नवीन बात नहीं है। प्राचीन काल से मुसलमान कवि हिन्दी में कविता करते आये हैं। सम्राट् अकबर तक ने हिन्दी से प्रेम दिखलाया है। वे स्वयं हिन्दी में बहुत अच्छी कविता करते थे।"^५ उन्होंने बताया कि इसी तरह "रहीम कवि ने क्या ही अच्छी उपदेशप्रद कविता की है।" और मुबारक, जायसी, रसखान आदि अनेक मुसलमान सज्जनों ने "हिन्दी को अपनी माँ की बोली समझ कर उसकी सेवा की है।"^६ मुसलमान भाइयों की भाँति ईसाई मिशनरियों ने भी हिन्दी का मान करके उसकी बड़ी सेवा की है।^७ मालवीयजी ने यह भी बताया कि "इसी भाँति सैकड़ों हिन्दुओं ने उर्दू में भी काव्य और ग्रन्थ लिखे हैं। ब्रज नारायण 'चक्रवर्त' की तरह अनेक हिन्दू कवि और लेखक अब भी उर्दू की सेवा कर रहे हैं।"^८

मालवीयजी ने कहा "हिन्दी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है जिसे सब भेदभाव छोड़कर प्रत्येक भारतीय स्वीकार कर सकता है।" उन्होंने यह भी कहा : साहित्य और देश की उन्नति अपने देश की भाषा के द्वारा ही हो सकती है"^९, और "जिस देश की जो भाषा है, उसी भाषा में वास्तव में उस देश के न्याय, कानून, राजकाज, कौंसिल आदि का काम होना चाहिए।"^{१०} "जब प्रजा के अधीन राज्य होगा, तब हमको ऐसी भाषा द्वारा राजकाज करना होगा, जिसको बहुजन समाज समझता हो। मुठ्ठी भर आदमी जिस भाषा को

१ वही, पृ० ३७।

३ वही, पृ० ३७।

५ वही, पृ० ३८।

७. वही, पृ० ३८।

९. वही, पृ० ३४।

२ वही, पृ० ३७।

४ वही, पृ० ३७।

६. वही, पृ० ३७।

८ वही, पृ० ३८।

१०. वही, पृ० ३३।

बोलते और समझते हैं, उनको द्वारा सारी प्रजा का कार्य नहीं किया जा सकता । प्रजा की सम्पत्ति उसी भाषा में प्रकट होनी चाहिए, जिसे वह समझती है । उसका ज्ञान उसी भाषा में होना चाहिए, जिसको वह बोलती हो ।”^१ उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी को ‘उच्च शिक्षा’ का माध्यम बनाया जाय ।^२

अपने विचारों को व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने कहा कि हिन्दी को राष्ट्र-भाषा मानकर यदि प्रान्त-प्रान्त की भाषाओं का सेवन किया जाय तो सर्वोत्तम होगा । उन्होंने कहा : “हम यह नहीं कहते कि देश भर में एक ही भाषा रहे, अन्य प्रान्तीय भाषाएँ न रहें । हर प्रान्त में अपने-अपने प्रान्त की भाषा उन्नति करे । गुजरात में गुजराती को, महाराष्ट्र में मराठी की उन्नति होनी चाहिए । ये सब प्रान्तीय भाषाएँ हैं । इन सबके रहते हुए हिन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा के तौर पर प्रयुक्त की जा सकती है । अभी तक जो काम अंग्रेजी द्वारा होता आता है, वह अब हिन्दी द्वारा होना चाहिए ।”^३

अन्त में मालवीयजी ने प्रार्थना की कि “सब भाई बहन राष्ट्र-भाषा के गौरव को मानकर अपनी भाषा के साथ-साथ प्रत्येक बालक को हिन्दी का ज्ञान भी करावें”, और आशा व्यक्त की कि कोई दिन आवेगा जब जिस भाँति अंग्रेजी जगत्-भाषा हो रही है, उसी भाँति हिन्दी का भी सार्वत्रिक प्रचार होगा ।^४

अक्टूबर सन् १९३९ में विजयदशमी के अवसर पर काशी में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ । मालवीयजी ने स्वागताध्यक्ष की हैसियत से हिन्दी के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण भाषण किया । उन्होंने कहा : “मुसलमानों के समय में बहुत से मुसलमानी शब्द हमारी भाषा में मिल गये, और अब वे भाषा के अङ्ग हैं । इसी प्रकार अंग्रेजों के आने से कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हमारी भाषा में मिल गये हैं । किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हमारी भाषा उन शब्दों से बनी है या उनके कारण बनी है । हमारी भाषा उन्हीं शब्दों से बनी है, जो ससृष्ट से प्राकृत और अपभ्रंश बनकर हिन्दी की शोभा को बढ़ाते हैं । जीवित भाषाओं की यह स्वाभाविक गति है कि उनमें प्रयोजन के अनुसार दूसरी भाषा के शब्द मिला लिये जाते हैं । किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं होना चाहिए कि हम अपने शब्दों को छोड़कर उनके स्थान पर दूसरी भाषा के शब्द ग्रहण करें । हमें केवल उन्हीं विदेशी शब्दों को ग्रहण करना चाहिए जिनसे

१. वही, पृ० ३५ ।

३. वही, पृ० ३४ ।

२. वही, पृ० ३४ ।

४. वही, पृ० ३८ ।

हमारी भाषा की शक्ति बढ़े, और भाव को स्पष्ट करने में सहायता मिले।”^१ उन्होंने यह भी कहा - “जब से भारतीयों में राष्ट्र को फिर से स्थापन करने का जतन होने लगा, तब से इस बात की चिन्ता बहुत से देशभक्तों को हो गयी है कि राष्ट्रीय कार्यों और व्यवहार के लिए एक राष्ट्रीय भाषा मान ली जाय। अतः उन्होंने हिन्दी को ‘राष्ट्र भाषा’ मान लिया है, क्योंकि वही देश के अधिक स्थानों में बोली और समझी जाती है। यह उद्योग सर्वथा सराहने योग्य है। किन्तु जिस रीति से आजकल भाषा का स्वरूप बदलने का जतन हो रहा है, वह मेरी राय में देश और समाज के लिए हितकारी नहीं होगा, और हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक भावों को इससे क्षति पहुँचने की आशंका है।”^२ उन्होंने इस भाषण में लिपि के अकारण संशोधन का भी विरोध किया। उनको भय था कि “अनावश्यक परिवर्तन करने से यह लिपि कल की वस्तु हो जायेगी, और हमारा सम्पूर्ण लिखा हुआ और छपा हुआ साहित्य अजायबघर की सामग्री बन जायेगा।”^३

पण्डित बलदेव उपाध्यायजी ने अपने संस्मरण में लिखा है—“भाषा तथा शैली के विषय में वे (मालवीयजी) सर्वदा सरल भाषा, तथा सुबोध शैली का आग्रह करते थे। उनका भेष था जैसा निर्मल, उज्ज्वल तथा निष्कलंक, उनकी भाषा थी वैसी ही विशुद्ध, सरस तथा सरल। सम्बत् २००० में विक्रमादित्य की द्विसहस्राब्दी के अवसर पर ‘अखिल भारतीय विक्रम परिषद्’ की स्थापना हुई। महाकवि कालिदास की सम्पूर्ण रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद इसकी प्रमुख योजना थी। अनुवाद की भाषा के विषय में महामना ने हम सबको स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं चाहता हूँ कि अनुवाद की भाषा इतनी सरल हो कि हिन्दी का साधारण पाठक भी उसे मजे से समझ जाय। उसे सरस भी होना चाहिए, जिससे किसी को पढ़ने में विरक्ति न हो। वे अपने भाषण में भी सुबोध विधा का प्रयोग किया करते थे। तत्सम शब्दों में विशेष रुचि नहीं रखते थे, तद्भव शब्दों के विशेष हिमायती थे तथा विशेष पारखी भी। हिन्दी भाषण या लेख में वे अंग्रेजी शब्दों का पुट किसी भाँति भी गवारा नहीं कर सकते थे।”^४

समीक्षा

हिन्दी के सम्बन्ध में मालवीयजी की धारणाएँ किसी हद तक बहुत से अन्य हिन्दी-प्रेमियों से भिन्न थी। जहाँ मालवीयजी चाहते थे कि हिन्दी

१. सीताराम चतुर्वेदी : महामना मालवीयजी, पृ० ८३।

२. वही, पृ० ८३।

३. वही, पृ० ८३।

४. महामना मालवीयजी बर्थ सेनटिनरी कोमेमोरेशन वाल्यूम, पृ० २१६।

में प्रचलित उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग जारी रहे, और अकारण कठिन संस्कृत शब्दों की तथा दुर्बोध समासों की भरमार न की जाय, सरल भाषा में हिन्दी साहित्य का निर्माण हो, वहाँ हिन्दी के बहुते से प्रेमी हिन्दी भाषा की परिशुद्धि, उर्दू और फारसी शब्दों का सर्वथा परित्याग, तथा संस्कृत शब्दों और समासों का भरपूर प्रयोग आवश्यक समझते हैं। इसी तरह जबकि मालवीयजी नागरी लिपि में लिखी हिन्दी भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, गांधीजी नागरी लिपि और फारसी लिपि दोनों के प्रयोग के पक्ष में थे, और मिली जुनी सरल भाषा को 'हिन्दुस्तानी' कहने को तैयार थे। पर ये दोनों नेता सरल भाषा के समर्थक थे, और चाहते थे कि हिन्दी और उर्दू का वैमनस्य दूर हो, तथा हिन्दी के प्रेमी उर्दू आदि देश की सभी भाषाओं के प्रति प्रेम और सद्व्यवहार अपना कर्तव्य समझे।



६. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी

(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय)

शिक्षा का प्रसार

जिस समय लार्ड कर्जन हिन्दुस्तान के शिक्षितों पर चरित्रहीनता का दोषारोपण करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में सरकार के आधिपत्य को अधिक दृढ़ बनाने के प्रयत्न में थे, उस समय देश के बहुत से नेता शिक्षापद्धति को राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप देने के पक्ष में थे। श्रीमती एनी बेसेंट और मालवीयजी भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में उच्चस्तरीय शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे जिसके द्वारा भारतीय नवयुवकों के चरित्र का निर्माण हो, उनमें देशप्रेम और देशसेवा की भावनाओं का संचार हो, उन्हें भारतीय संस्कृति का समुचित ज्ञान हो, और वे आधुनिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर देश की समृद्धि में समुचित योगदान कर सकें।

इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने वाराणसी में सन् १८९८ में सेंट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना की, और मालवीयजी ने सन् १९०४ में वाराणसी में काशीनरेश प्रभुनारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभा में काशी विश्वविद्यालय की योजना प्रस्तुत की।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय

अक्तूबर सन् १९०५ में प्रस्तावित विश्वविद्यालय की योजना की रूपरेखा विभिन्न प्रान्तों के संभ्रान्त हिन्दू सज्जनों के पास भेजी गयी। इस योजना के प्राक्कथन में हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म की तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालते हुए ज्ञान के व्यापक प्रसार और धर्म की पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना देश की उन्नति के लिए आवश्यक बताया गया। उसमें कहा गया कि “भारत के प्राचीन धर्म की शिक्षा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने को एक बड़ी समष्टि की इकाई समझ कर उसके हित के लिए जीवित रहे और काम करे, लोककल्याण और लोकसंग्रह को परम पुरुषार्थ समझे।” उसमें यह भी बताया गया कि प्राचीन धर्म लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक सिद्धि, दोनों के लिए

१. दर और सोमसकंदन—हिस्ट्री आफ दी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, पृ० ५१।

प्रयत्न करना मानव का कर्तव्य निर्धारित करता है, और हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिपादित नैतिकता में उन सब गुणों का समावेश है जो "मानव समाज के अनाक्रान्त अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए आवश्यक हैं।"^१ इस प्राक्कथन में भारतीय संस्कृति के बहुत से अन्य सद्गुणों की विवेचना करते हुए उसकी समुचित शिक्षा हिन्दुओं के वास्तविक उत्थान के लिए आवश्यक बताया गयी। पर इसके साथ ही लौकिक अम्युदय के लिए आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन और प्रयोग की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उसकी समुचित शिक्षा के प्रबन्ध पर भी जोर दिया गया, और यह भी बताया गया कि देश में विज्ञान का व्यापक प्रसार और प्रयोग भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही सम्भव है। इस तरह प्राक्कथन में हिन्दू धर्म और प्राचीन भारतीय विद्याओं की शिक्षा के साथ ही साथ भारतीय भाषा के माध्यम से आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और शिल्पशास्त्र की शिक्षा को प्रस्तावित विश्वविद्यालय का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसके पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया।^२

३१ दिसम्बर सन् १९०५ को यह योजना वाराणसी के टाउनहाल में वरार के श्री बी० एन० महाजन की अध्यक्षता में आयोजित सभा में प्रस्तुत की गयी। सभा में उपस्थित सज्जनों ने मालवीयजी के इस प्रयास की सराहना करते हुए उसे स्वीकार किया। दूसरे दिन इसकी घोषणा कांग्रेस के अधिवेशन में कर दी गयी। इसके कुछ दिन बाद ही जनवरी सन् १९०६ में कुम्भ के अवसर पर 'सनातन धर्म महासभा' के सम्मेलन में गोवर्धन मठ के परमहंस परिव्राजकाचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य की अध्यक्षता में इस योजना पर विचार हुआ, और निश्चित किया गया कि 'भारतीय विश्वविद्यालय' के नाम से वाराणसी में प्रस्तावित विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। इस अवसर पर मालवीयजी ने सकल्प किया कि इसे प्रतिष्ठित करने के लिए वे भरसक प्रयत्न करेंगे। १६ मार्च सन् १९०६ को विश्वविद्यालय का विवरण प्रकाशित किया गया, तथा उसके शिलान्यास के लिए शृंगेरी मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य निमंत्रित किये गये। उन्होंने विचार का स्वागत करते हुए नियत तिथि पर वाराणसी पहुँचने में असमर्थता प्रकट की। इसके बाद लगभग चार वर्ष तक इस योजना के सम्बन्ध में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। सन् १९१० में मालवीय जी ने इसके लिए जोर-शोर से काम करने का निर्णय किया।

१. वही, पृ० ५३-५४।

२. वही, पृ० ५९-६२।

श्रीमती बेसेंट की योजना

इधर सन् १९०७ में श्रीमती एनी बेसेंट ने वाराणसी में ही 'यूनिवर्सिटी आफ इंडिया' के नाम से विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय किया, और चार्टर के लिए सम्राट् को एक आवेदन-पत्र भेजा। इस आवेदन-पत्र पर कई प्रतिष्ठित हिन्दू और पारसी विद्वानों के अतिरिक्त तीन प्रसिद्ध मुसलमान नेताओं के भी हस्ताक्षर थे। श्रीमती एनी बेसेंट चाहती थी कि उनका प्रस्तावित विश्व-विद्यालय मुख्यतः निवासीय शिक्षण संस्थान हो, पर उसे देश भर में सस्थापित कालेजों को भी अपने से सम्बद्ध करने का अधिकार हो। सरकार ने कई वर्ष तक इस पर कोई विचार ही नहीं किया। सितम्बर सन् १९१० में भारत सरकार ने भारत-मन्त्री के पास यह योजना भेज दी, जिन्होंने उसे भारत सरकार की राय के लिए उसके पास लौटा दिया।

मुस्लिम यूनिवर्सिटी

सन् १९११ में हिज हाइनेस आगा खाँ के नेतृत्व में मुसलमानों का एक डेपुटेशन भारत सरकार से मिला, और उसने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए चार्टर प्रदान करने की प्रार्थना की। भारत सरकार ने उसे आश्वासन दिया कि यदि इस काम के लिए २५ लाख रुपये जमा कर लिये जायेंगे, तो इस पर सहानुभूति से विचार किया जायगा।

नया उत्साह

इस समाचार ने मालवीयजी की योजना के समर्थकों में एक नया उत्साह पैदा कर दिया। मार्च-अप्रैल सन् १९११ में मालवीयजी और श्रीमती एनी बेसेंट ने काशी में विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित करने के लिए मिलकर काम करने का निश्चय किया। ११ अप्रैल को श्रीमती एनी बेसेंट ने एक वक्तव्य में अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि तीन प्रमुख मुसलमानों ने उनके आवेदन-पत्र से अपने हस्ताक्षर वापस ले लिये हैं, अलीगढ़ कालेज ने यह कहकर कि वह स्वयं अपना विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, उनकी योजना में अपना सहयोग देने से इनकार कर दिया है, और हिन्दू जनता में अपना एक अलग विश्वविद्यालय खोलने की इच्छा जागृत हो गयी है। इन सब कारणों से- सब मित्रों की यही राय है कि सब लोग मिलकर काशी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करें। श्रीमती बेसेंट ने कहा कि उनकी और मालवीयजी की सहमति है कि नया विश्वविद्यालय 'यूनिवर्सिटी आफ इंडिया' या 'काशी विश्वविद्यालय'

के नाम से विख्यात हो और वह एक निवासीय शिक्षण-संस्थान हो, पर उसे उन सब संस्थाओं को, जहाँ धर्म और नैतिकता की शिक्षा दी जाती हो, अपने से सम्बद्ध करने का अधिकार हो। भारतीय दर्शन, इतिहास और साहित्य की शिक्षा द्वारा हिन्दू संस्कृति का विकास इसी प्रमुख विशेषता होगी।^१

जुलाई में मालवीयजी ने एक संशोधित योजना प्रसारित करते हुए एक करोड़ रुपये की अपील की, तथा वे महाराजाधिराज दरभंगा से मिले और उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी योजना को भी उनकी योजना में मिला दें। महाराजाधिराज ने कुछ ऐसी शर्तें रखीं जिनके कारण दोनों का मेल लगभग तीन मास के लिए टल गया। इन तीन महीनों में युक्त प्रान्त (मौजूदा उत्तर प्रदेश), बिहार, बंगाल, पंजाब और मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर मालवीयजी और उनके साथियों ने दौरा किया, और प्रतिष्ठित नेताओं, विद्वानों और धनीमानी व्यक्तियों के सहयोग से कई लाख रुपये चन्दे में एकत्र किये।

पादसराय से भेंट और हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी

११ अक्टूबर सन् १९११ को मालवीयजी और महाराजाधिराज दरभंगा वाइसराय लार्ड हार्डिंग और शिक्षा-मन्त्रिय सर हारकोर्ट वटलर से मिले, और उन्होंने कुछ शर्तों के पूरा होने पर विश्वविद्यालय को मान्यता देने का आश्वासन दिया। इसके बाद महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिंहजी मालवीयजी के साथ काम करने को राजी हो गये और उन्होंने पाँच लाख रुपये दान में दिये। २१ अक्टूबर को मालवीयजी ने श्रीमती एनी वेसेंट से मिलकर उनकी अनुपस्थिति में सेट्रल हिन्दू कालेज के अन्य मंचालको और ट्रस्टियों से जो मतभेद पैदा हो गया था उसका समाधान किया। २७ अक्टूबर को यह घोषित किया गया कि श्रीमती वेसेंट, मालवीयजी और महाराजा दरभंगा की योजनाएँ मिलाकर एक कर दी गयी हैं, और नये विश्वविद्यालय का नाम 'हिन्दू यूनिवर्सिटी' होगा, तथा उसका धर्म विज्ञान विभाग केवल हिन्दुओं के हाथ में होगा।^२

२८ नवम्बर सन् १९११ का 'हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी' के नाम से सर रामेश्वर सिंहजी की अध्यक्षता में बनारस में हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए एक संस्था स्थापित हो गयी। डाक्टर सुन्दर लाल मन्त्री का भार वहन करने को राजी हो गये। सर गुरुदास बनर्जी, श्रीमती एनी वेसेंट और डाक्टर रासबिहारी घोष उपाध्यक्ष चुने गये। बाबू भगवान दास, पण्डित गोकर्ण नाथ

मिश्र, पंडित कृष्णराम मेहता, पंडित इकबाल नारायण गुर्दा, तथा बाबू मंगला प्रसाद संयुक्त मन्त्री नियुक्त हुए। बीकानेर-नरेश सर गंगा सिंह भी सक्रिय सहयोग देने को तैयार हो गये।

४ दिसम्बर सन् १९११ को इस सस्था से संबंधित ३२ सम्मानित व्यक्तियों का एक डेपुटेशन दिल्ली में वटलर साहब से मिला, जिन्होंने बहुत ही सन्तोषजनक ढंग से बातचीत की। इस समय यह निश्चय हुआ कि यूनिवर्सिटी एकट पास हो जाने पर उसका तभी कार्यान्वयन होगा जब बैंक में ५० लाख रुपया जमा हो जायें और सोसाइटी एक करोड़ रुपया जमा करने की स्थिति में हो।

चन्दा

सन् १९१२ में देश के विभिन्न नगरों में बड़े उत्साह के साथ जलसे हुए, जिनमें बहुत से राजाओं, महाराजाओं, नेताओं, विद्वानों और धनीमानी सज्जनों ने भाग लिया। मालवीयजी और महाराजा दरभंगा आदि ने चन्दे की अपील की, और लाखों रुपये इकट्ठे हुए। ३१ मार्च सन् १९१३ तक साठे इक्कीस लाख रुपये से अधिक जमा हो गये, और छत्तीस लाख से अधिक वायदे प्राप्त हो गये। चन्दा जमा करने का मिलसिला जारी रहा। सन् १९१५ के प्रारम्भ तक पचास लाख रुपये जमा हो गये, जिसमें महाराजा बीकानेर, महाराजा जोधपुर और महाराजा काश्मीर के वार्षिक अनुदानों के पूँजीकृत मूल्य भी सम्मिलित थे।

सेंट्रल हिन्दू कालेज

४ मई सन् १९१३ को सेंट्रल हिन्दू कालेज के ट्रस्टियों ने निश्चय किया कि सेंट्रल हिन्दू कालेज के प्रबन्ध को यथाशीघ्र हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी के सुपुर्द कर देने का प्रवर्ध किया जाय। इसके बाद कानूनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी ने तथा सेंट्रल हिन्दू कालेज की प्रबन्ध समिति तथा ट्रस्टियों की सभा ने आवश्यक प्रस्ताव पास किये, और सब औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद २७ नवम्बर सन् १९१४ को सेंट्रल हिन्दू कालेज एसोसिएशन हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी में मिला दिया गया, और उसे सेंट्रल हिन्दू कालेज, सेंट्रल हिन्दू स्कूल, तथा रणवीर संस्कृत पाठशाला हस्तान्तरित कर दिये गये।

सरकार से विवाद

शिक्षा का माध्यम तथा सरकार का नियंत्रण, इन दो विषयों पर विश्व विद्यालय के प्रवर्तकों और भारत सरकार में गहरा मतभेद था। मालवीयजी अंग्रेजी

के बजाय हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। उनका विचार था कि भारतीय भाषाओं द्वारा ही अधिकांश जनता शिक्षित हो सकती है, तथा देश में ज्ञान-विज्ञान का प्रसार और मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति सुगमता से हो सकती है। भारत सरकार और भारत-मन्त्री अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाये रखना चाहते थे। अन्त में मालवीयजी को यह स्वीकार करना पड़ा कि हिन्दू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी ही अर्वाचीन विद्याओं की शिक्षा का माध्यम होगी।

हिन्दू विश्वविद्यालय और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवर्तक गवर्नर-जनरल को चान्सलर बनाने को तैयार थे। पर सरकार संयुक्त प्रान्त (मौजूदा उत्तर प्रदेश) के लेफ्टिनेंट-गवर्नर को दोनों विश्वविद्यालयों का चान्सलर बनाना चाहती थी। इसके लिए दोनों तैयार नहीं थे। अन्त में सरकार इस बात पर राजी हो गयी कि दोनों विश्वविद्यालय स्वयं अपना चान्सलर निर्वाचित करें, संयुक्त प्रान्त के गवर्नर दोनों के पदेन विजिटर हों, और इस हैसियत से उन्हें नियन्त्रण के वे सब अधिकार प्राप्त हों जो साधारणतः दूसरे विश्वविद्यालयों में चान्सलर के सुपुर्द होते हैं।

भारत-मन्त्री नास्तब में इन दोनों पर दूसरे विश्वविद्यालयों से कहीं अधिक कड़ा सरकारी नियन्त्रण स्थापित करना चाहते थे। वे तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरो, अध्यापको और परीक्षको की नियुक्तियों का उत्तरदायित्व तक लेफ्टिनेंट-गवर्नर को सौंपना चाहते थे। इस प्रकार का कड़ा नियन्त्रण और अविश्वास दोनों विश्वविद्यालयों के समर्थक स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सरकार की इस मनोवृत्ति की कड़ी आलोचना हुई। बहुत से दाताओं ने हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी के अधिकारियों को लिखा कि आपत्तिजनक, अपमानकर प्रतिबन्धों को स्वीकार न किया जाय, और यदि सरकार अपनी बात पर डटी रहे तो एकत्रित धन किसी दूसरे समाजोत्थान के कार्य में लगाया जाय। जनमत को ध्यान में रखकर सरकार कुछ ढीली पड़ी। उसने प्रोफेसरो और अध्यापको की नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप की जिद छोड़ दी, और निश्चय किया कि अन्य विशेष अधिकार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में स्वयं भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त होंगे। गवर्नर-जनरल को लार्ड रेक्टर बनाना निश्चित हुआ, और नियन्त्रण के विशेष अधिकार इस हैसियत से उन्हें सौंपना तय हुआ।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल

२२ मार्च सन् १९१५ को सर हार्कोर्ट बटलर ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल प्रस्तुत किया। इस नये विश्वविद्यालय

की विशेषताओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा - “आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की तरह यह निवासीय और शिक्षण विश्वविद्यालय होगा, और इस तरह लन्दन विश्वविद्यालय के नमूने पर बने विश्वविद्यालयों से भिन्न होगा।” दूसरे इस विद्यालय में जहाँ सब जाति और सम्प्रदाय के विद्यार्थी दाखिल हो सकेंगे, वहाँ हिन्दू विद्यार्थियों को हिन्दू धर्म की शिक्षा दी जायगी, तथा यहाँ हिन्दू धर्मविज्ञान की उच्चस्तरीय शिक्षा का प्रबन्ध होगा। तीसरे इसका संचालन और प्रबन्ध हिन्दू समाज और अधिकतर गैर-सरकारी सज्जनों द्वारा ही होगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विधान से प्रस्तावित विश्वविद्यालय के विधान की तुलना करते हुए बटलर साहब ने कहा कि इसकी व्यवस्था निःसन्देह अधिक उदार है, और गवर्नर-जनरल के विशेषाधिकार केवल आपत्कालीन हैं, जिनके आधार पर इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था को अनुदार कहना उचित नहीं है।^१

सर गंगाधर बितनवीस, महाराजा मनीन्द्र चन्द्र नन्दी, श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, राय सतीनाथ बहादुर, श्री मधुसूदन दास, मिस्टर मानकजी दादाभाई, सर फजल भाई करीम भाई आदि ने विधेयक का समर्थन किया। मिस्टर ए० के० गजन्वी ने कहा कि उस समय जबकि देश को हिन्दू-मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करने की जरूरत है, हिन्दू यूनिवर्सिटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हानिकर हो सकती है।^२ श्री चिम्मनलाल सीतलवाद ने कहा कि धर्म-विहीन और नैतिकता-विहीन शिक्षा के दुष्परिणामों को हर कोई जानता है, पर जबतक धर्म के आधार पर भारतीय शिक्षा को सुव्यवस्थित करने का भार लोग अपने ऊपर न ले, तबतक उनको दूर करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। हिन्दू यूनिवर्सिटी भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारम्भ करेगी। दूसरी यूनिवर्सिटियों से भिन्न, धर्म हिन्दू यूनिवर्सिटी की जीवन-प्रदायनी शक्ति होगी, जो स्नातकों के सुनम्य मन को भिन्न और अधिक मनोहर रूप में ढालेगा^३, पर गजन्वी साहब की तरह उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी ‘साम्प्रदायिक विश्वविद्यालयों’ में भय दिखाई देता है।^४ पर अब जब हिन्दू और मुसलमान, दोनों ने अपने-अपने विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय ही कर लिया है, तब इस पर कुछ अधिक कहना व्यर्थ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस विश्वविद्यालय के संचालक साम्प्रदायिक विभाजन से उसे अधिक प्रभावित नहीं होने देंगे।^५

१. प्रोसीडिंग नवर्नर-जनरल की कौंसिल (लेजिस्लेटिव) सन् १९०५ पृ० ५२५।

२. वही, जि० ५३, पृ० ५३२।

३. वही, जि० ५३, पृ० ५३५।

४. वही, जि० ५३, पृ० ५३५।

५. वही, जि० ५३, पृ० ५३६।

उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, और यदि कोई मुसलमान या ईसाई विश्वविद्यालय की प्रगति में योगदान करने को तैयार हो, तो उसे यूनिवर्सिटी के कोर्ट का सदस्य बनाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।

मालवीयजी ने कहा कि यद्यपि यह संस्था साम्प्रदायिक होगी, पर मतान्व नहीं होगी। इस विश्वविद्यालय में मकुचित सम्प्रदायिकता को आश्रय नहीं दिया जायगा, वरन् उन व्यापक और उदार धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित किया जायगा जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भ्रातृत्व की भावना का विकास करें।^१

१ अक्टूबर सन् १९१५ को शिक्षा-सदस्य सर हारकोर्ट वटलर ने प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका बहुत से सदस्यों ने समर्थन किया। मालवीय जी ने इस अवसर पर बोलते हुए आशा व्यक्त की कि “ज्योति और जीवन का यह केन्द्र जो अस्तित्व में आ रहा है, उन विद्यार्थियों को तैयार करेगा जो ज्ञान में संसार के दूसरे भागों के विद्यार्थियों के समान ही नहीं होंगे, वरन् उत्तम जीवन बिताने में, ईश्वर-भक्ति, देश-प्रेम तथा सम्राट् के प्रति निष्ठा में भी परिशिक्षित होंगे।”^२

विश्वविद्यालय का उद्घाटन

(१ अक्टूबर सन् १९१५ को बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी एकट पास हुआ, और ४ फरवरी सन् १९१६ अर्थात् माघ शुक्ल प्रतिपदा सम्बत् १९७२ वि० को लार्ड हार्डिंग ने उसका शिलान्यास किया।) इस अवसर पर बंगाल के गवर्नर, तीन प्रान्तों के लेफ्टिनेंट-गवर्नर, १२ महाराज, बहुत से विद्वान्, जमींदार, साहूकार, और प्रतिष्ठित नेता उपस्थित थे। वाइसराय महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि उनके विचार में “धार्मिक शिक्षा की नींव, तथा धार्मिक वातावरण के संतुलित प्रभाव के बिना मानसिक और नैतिक संयम तथा अध्यापकों के उपदेशों और उदाहरण की खिसकती हुई रेत पर चरित्र का निर्माण कठिन है।”^३ उन्होंने विश्वविद्यालय के आदर्शों तथा उसके प्रवर्तकों की अभिलाषाओं के प्रति अपनी शुभ कामना व्यक्त की। शिलान्यास के उत्सव का समारोह कई दिन तक चलता रहा।

१ वही, जि० ५३, पृ० ५३७-५३९। २. वही, जि० ५४, पृ० १८९।

३. दर और सोमत सकंदन—हिस्ट्री आफ दी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, पृ० ३४७।



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास स्थल पर भाषण देते हुए मालवीयजी

12

13

14

बहुत से विद्वानों ने तथा गांधीजी ने सारगर्भित व्याख्यान दिये। गांधीजी ने अपने भाषण में सरकार तथा राजाओं-महाराजाओं की कड़ी आलोचना की, जिसके कारण काफी बदमजगती पैदा हो गयी। राजे-महाराजे तथा श्रीमती बेसेंट आदि कई लोग उठकर चले गये, पर मालवीयजी बैठे रहे।

पदाधिकारी

१ अप्रैल सन् १९१६ को यूनिवर्सिटी एक्ट चालू कर दिया गया। मैसूर के महाराजा कृष्णराज वादियर चान्सलर, ग्वालियर के महाराजा माधव राव सिधिया प्रोचान्सलर तथा डाक्टर सुन्दरलाल वाइस-चान्सलर नियुक्त किये गये। महाराजा मैसूर और महाराजा ग्वालियर छः वर्षों तक अपने पदों पर आसीन रहे। इनके बाद ३० नवम्बर सन् १९२२ को बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड चान्सलर, तथा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह प्रोचान्सलर निर्वाचित हुए। ये दोनों भी इन पदों पर ३१ मार्च सन् १९२९ तक आसीन रहे। इसके बाद महाराजा गंगासिंहजी चान्सलर निर्वाचित हुए, और १ फरवरी सन् १९४३ तक वे इस पद को सुशोभित करते रहे। काशी-नरेश प्रभुनारायण सिंह ३१ मार्च सन् १९२९ को प्रोचान्सलर निर्वाचित हुए। उनके निधन पर ३० नवम्बर सन् १९३१ को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह प्रोचान्सलर निर्वाचित हुए, और वे १० जून सन् १९४७ तक इस पद पर रहे। ३० नवम्बर सन् १९३१ को काशीनरेश सर आदित्य नारायण सिंह भी प्रोचान्सलर निर्वाचित हुए, और वे ४ अप्रैल सन् १९३९ तक इस पद को सुशोभित करते रहे। उनके निधन पर मई सन् १९३९ में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह को प्रोचान्सलर निर्वाचित किया गया।

डाक्टर सुन्दरलालजी का १३ फरवरी सन् १९१८ को निधन हो गया, और उनकी जगह पर १३ अप्रैल सन् १९१८ को सर पी०एस० शिवस्वामी अय्यर वाइस-चान्सलर निर्वाचित हुए। पर उन्होंने ८ मई सन् १९१९ को इस्तीफा दे दिया, और उनकी जगह पर २९ नवम्बर सन् १९१९ को मालवीयजी तीन वर्ष के लिए वाइस-चान्सलर निर्वाचित हुए, पर वे बराबर चुने जाते रहे, और सितम्बर सन् १९३९ तक इस पद पर काम करते रहे। उसके बाद मालवीयजी के अनुरोध पर सर राधाकृष्णन् ने वाइस-चान्सलर का भार सम्भाला।

कोर्ट ने मालवीयजी के गुरु महामहोपाध्याय आदित्यराम भट्टाचार्य को पहला प्रो-वाइस-चान्सलर नियुक्त किया। पर उन्होंने ८ अगस्त सन् १९१८

को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कुछ समय तक मालवीयजी और ज्ञानेन्द्र नाथ चक्रवर्ती ने इस पद का भार संभाला। अप्रैल सन् १९२० में आचार्य आनन्दशंकर बापू भाई ध्रुव प्रो-वाइस-चान्सलर निर्वाचित हुए और वे बार बार चुने जाकर ३१ मार्च सन् १९३६ तक काम करते रहे। आचार्य ध्रुव संस्कृत वाङ्मय के प्रतिभाशाली विद्वान् थे। वे अपनी उदार और प्रगतिशील धारणाओं, सद्भावनाओं और सौजन्य के लिए प्रसिद्ध थे। सभी उनका आदर करते थे। १ अप्रैल सन् १९३६ को राजा ज्वाला प्रसाद प्रो-वाइस-चान्सलर निर्वाचित हुए और दिसम्बर १९४० तक वे काम करते रहे। तदुपरान्त मालवीयजी के आग्रह पर पंडित इकबाल नारायण गुर्तूजी ने इस भार को ग्रहण किया। राजा ज्वाला प्रसाद और डाक्टर इकबाल नारायण गुर्तू के विश्वविद्यालय से पुराने सम्बन्ध थे। विश्वविद्यालय के निर्माण में राजा ज्वाला प्रसादजी का महत्त्वपूर्ण योगदान था। वे ही विश्वविद्यालय के इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे, और प्रो-वाइस-चान्सलर बनने से पहले युक्तप्रान्त के चीफ इंजीनियर के पद को सुशोभित कर चुके थे। गुर्तू साहब का प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर की हैसियत से शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान था।

सहयोग

काशी विश्वविद्यालय निःसन्देह मालवीयजी की सबसे बड़ी कृति है। इसके निर्माण में बहुत से राजाओं-महाराजाओं, विद्वानों, जमींदारों तथा धनीमानी सज्जनों का भरपूर योगदान था। पर मालवीयजी का साहस, उत्साह, कल्पना, लगन और तपस्या ही उसका प्रमुख आधार था। राष्ट्रसेवा के बहुत से कामों में फँसे रहने के कारण वे अपना सारा समय तो विश्वविद्यालय को अर्पित नहीं कर सके, पर उसके अम्युदय की चिन्ता उन्हें जीवन की अन्तिम घड़ी तक सदा बनी रही। सन् १९२० से सन् १९३९ तक तो उनके संचालन और प्रबन्ध का भार उन्हें ही मुख्यतः वहन करना पड़ा। सन् १९१६ के बाद उसके प्रबन्ध और संचालन में जिन महानुभावों ने उनके साथ काम किया उनमें पंडित बलदेव राम दवे, पण्डित कन्हैया लाल दवे और पण्डित हृदयनाथ कुंजरू का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पण्डित इकबाल नारायण गुर्तू और मुशी ईश्वर शरण का भी अच्छा योगदान था। कोषाध्यक्ष की हैसियत से राजा मोती चन्द का, तथा इन्जीनियर की हैसियत से ज्वाला प्रसादजी का भी भरपूर योगदान था। महाराजा बनारस और महाराजकुमार विजयानगरम् को ही आतिथ्य-सत्कार का भार वहन करना होता था। विडला परिवार का भी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के उत्थान में विशिष्ट योगदान रहा।

इस सम्बन्ध में बाबू शिवप्रसादजी का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने सन् १९१० और सन् १९११ में चन्दा जमा करने के लिए मालवीयजी के साथ देश में भ्रमण किया, पर जब अक्तूबर सन् १९११ में पण्डितजी सरकारी मान्यता प्राप्त करने को राजी हो गये, तब उन्होंने विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया, पर मालवीयजी की सेवा करना वे तब भी अपना पुनीत कर्तव्य समझते रहे, और इसका निर्वाह वे आजीवन पुत्रवत् करते रहे। उनका 'सेवा उपवन' मालवीयजी के अतिरिक्त पण्डित बलदेव राम दवे, पण्डित कन्हैया लाल दवे, पण्डित हृदयनाथ कुजूरू आदि के लिए भी अतिथिगृह बना रहा। विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर आमंत्रित बहुत से अन्य विद्वानों और नेताओं का आतिथ्य-सत्कार भी वही होता था।

विद्यार्थियों के जीवनोत्कर्ष में बहुत से विद्वानों का महत्त्वपूर्ण योगदान था, पर सभवतः इन सब में प्रोफेसर श्यामाचरण दे के व्यक्तित्व का विशिष्ट स्थान था। बाल ब्रह्मचारी का निर्मल चरित्र, निष्कपट व्यवहार, व्यापक सहानुभूति और प्रेम, तथा निष्काम सेवा उत्कृष्ट जीवन के विमोहक उदाहरण थे, जिनका अनुसरण कठिन होते हुए भी जीवनोत्कर्ष का उत्तम आदर्श था।

विशेषताएँ

अंग्रेजी साहित्य तथा आधुनिक मानविकी और विज्ञान के साथ-साथ हिन्दू धर्म-विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति एवं विभिन्न प्राच्य विद्याओं का अध्ययन इस विश्वविद्यालय की विशेषता थी। यहाँ एक विद्यार्थी प्राच्य विद्या संकाय में प्राचीन पद्धति से संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन करते हुए कला संकाय में अर्वाचीन अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र का अध्ययन कर सकता था, एक ही समय में प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानों के ज्ञान से लाभान्वित हो सकता था।

यद्यपि बीस पचीस वर्ष हिन्दी भाषा शिक्षा का माध्यम नहीं बन पायी, पर हिन्दी भाषा-भाषी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा का अध्ययन कला संकाय में इण्टर और बी० ए० कक्षाओं तथा विज्ञान संकाय में इण्टर की कक्षाओं में अनिवार्य था, और तोन चार वर्ष के अन्दर ही कला संकाय में हिन्दी साहित्य को अध्यापन का एक प्रमुख वैकल्पिक विषय बना दिया गया। कुछ वर्षों तक तो यही विश्वविद्यालय हिन्दी साहित्य की शिक्षा का मुख्य केन्द्र था। यही बाबू श्याम सुन्दर दास, पण्डित रामचन्द्र शुक्ल, पण्डित अयोध्या सिंह उपाध्याय, बाबू भगवान दीन जैसे विद्वानों से हिन्दी-प्रेमी विद्यार्थी हिन्दी

साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर दूसरे विद्यालयों में उस ज्ञान से विद्यार्थियों को लाभान्वित करते थे। इस तरह हिन्दी का प्रसार इस विश्वविद्यालय की दूसरी विशेषता थी।

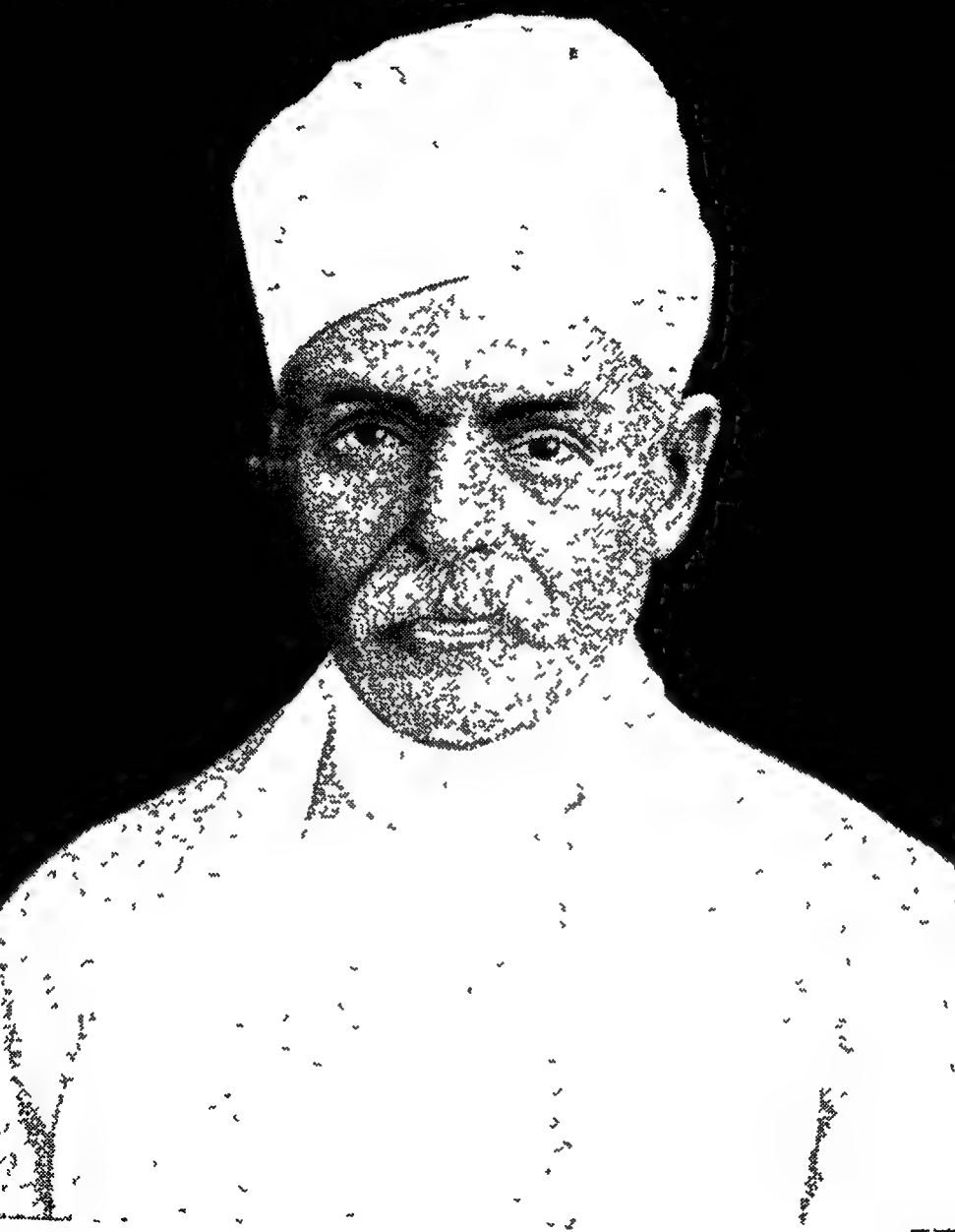
कला सभा में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में अर्वाचीन पाश्चात्य विद्वानों के साथ ही साथ प्राचीन भारतीय विद्वानों के विचारों और सिद्धान्तों का ज्ञान भी शामिल था। दर्शनशास्त्र के विद्यार्थियों को काट और हीगल के साथ-साथ अनिवार्य रूप से कपिल और शंकर के सिद्धान्तों का भी अध्ययन करना होता था। राजनीति के विद्यार्थियों को भारतीय राजनीतिक विचारों और संस्थाओं का ज्ञान भी प्राप्त करना होता था। यह विश्वविद्यालय की तीसरी विशेषता थी।

यहाँ मालवीयजी की सरक्षता में राजनीति विभाग में स्वतंत्रता प्राप्त होने से पन्द्रह-सोलह वर्ष पहले ही भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचार, तथा समाजवादों सिद्धान्तों का इतिहास आदि विषयों का अध्यापन काफी निर्भीकता से किया जाता था, और यह भी उसकी एक विशेषता थी, क्योंकि उस समय इन विषयों के पठन-पाठन का प्रबन्ध हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों में सम्भव भी नहीं समझा जाता था।

प्रायोगिक विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध नि सदेह इस विश्वविद्यालय की एक प्रमुख विशेषता थी। धन का अभाव होते हुए भी मालवीयजी ने बहुत से विरोधों का मुकाबला करते हुए इस विश्वविद्यालय में धातु विज्ञान, खनन विज्ञान, भूविज्ञान, विद्युत इंजीनियरी, यान्त्रिक इंजीनियरी, रसायन विज्ञान, मृत्तिका शिल्प, औषध निर्माण विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध किया। सम्भवतः उनमें से बहुत से विषय उस समय भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाये जाते थे। यहाँ का इंजीनियरिंग कालेज निःसन्देह सारे भारत का शिक्षा-केन्द्र था।

सदुपदेश

धार्मिक शिक्षा भी इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। मालवीयजी 'धर्म की सजीव शक्ति पर विश्वास' करते थे, और धर्म का ज्ञान तथा अनुसरण जीवन के उत्कर्ष के लिए आवश्यक समझते थे। उनकी धार्मिक भावना मनुष्यता से विभूषित थी। वे धार्मिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में उन 'व्यापक और उदार भावनाओं' को प्रोत्साहित करना चाहते थे, 'जो मनुष्य के बीच



69

भ्रातृत्व की भावना का विकास करें' । विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को धर्म का उपदेश करते समय व सदा इसका ध्यान रखते थे । उनका उपदेश निःसदेह नैतिकता और देशप्रेम से समन्वित, तथा उदात्त मानवीय भावना से अनुप्राणित होता था । वे शील और देश-प्रेम को धर्म का महत्त्वपूर्ण अंग, तथा प्राणीमात्र के प्रति सौहार्द भावना को धर्म का प्राण समझते थे । वे अपने विद्यार्थियों को बताते थे कि शील और देशप्रेम से रहित ज्ञान निरर्थक है । वे कहते थे : "शीलं प्रधानं पुरुषे"—शील ही मनुष्य में प्रधान है, "शीलं परं भूषणम्"—शील ही मानव का सबसे उत्तम भूषण है । उनकी शिक्षा थी कि चरित्र ही मनुष्य को ऊँचा उठाता है, शील-सम्पन्न विद्वान् ही अपने जीवन का समुचित उत्कर्ष तथा समाज की ठोस सेवा कर सकता है । वे कहा करते थे कि नगवा के साडो, कोई ऐसा काम मत करना जिससे माता के आँचल पर घब्बा लगे, और राष्ट्र के गौरव की क्षति हो । वे विद्यार्थियों से कहते थे : "हृदय को पवित्र बना लो, मन को निर्मल बना लो, संसार में जहाँ जाओगे वहाँ मान के अधिकारी होंगे" । वे अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे . "जो शिक्षा तुमने यहाँ प्राप्त की है वह व्यर्थ है, यदि उसने तुम में अपने देश को स्वतंत्र और स्वशासित देखने की उत्कट आकांक्षा पैदा नहीं की ।" विद्यार्थियों के जीवन को राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित करने के लिए वे विश्वविद्यालय में डाक्टर एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, डाक्टर एम० ए० अन्सारी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित जवाहर लाल नेहरू प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं को बुलाते और उनके व्याख्यानो की व्यवस्था करते थे ।

सब गुरुजनो का आदर, विश्वविद्यालय की सेवा, उसकी मानमर्यादा और गौरव की रक्षा वे विद्यार्थियों का पुनीत कर्तव्य तथा परम धर्म समझते थे । वे चाहते थे कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपनी "विद्यादायिनी माता की सेवा में लग जायें, माता की कीर्ति उज्ज्वल कर दें, और विश्व को दिखा दें कि यह हमारी जननी है, यही सरस्वती की अमरावती है ।" वे कहते थे—"गुरुश्रूषया विद्या" अर्थात् गुरु की सेवा से विद्या प्राप्त होती है । मनु महाराज के इस पद की ओर वे विद्यार्थियों का ध्यान बहुधा आकृष्ट करते :—

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्धन्तेऽप्युविद्या यशोबलम् ॥

१. सन् १९२९ का दीक्षान्त भाषण । दर एंड सोमसकन्दन : वही पृ० ५७३ ।

अर्थात् 'अपने से बड़े गुरुजनों को प्रणाम करने तथा उनकी सेवा करनेवाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है' ।

विद्यार्थियों को उनका उपदेश और आशीर्वाद था—

ज्योतिरात्मनि नान्यत्र सम तत्सर्वजन्तुषु ।

स्वयं च शन्यते दृष्टु सुसमाहित चेतसा ॥ (व्यास)

सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्यया ।

देशभक्त्या त्यागेन सम्मानहं सदा भव ॥

अर्थात् 'ब्रह्म की ज्योति अपने भीतर ही है, वह सब जीवधारियों में समान है । मनुष्य मन को अच्छी तरह शान्त और सुसमाहित कर उसे देख सकता है' । 'सत्य से, ब्रह्मचर्य से, व्यायाम से, विद्या से, देश-भक्ति से और आत्म-त्याग से सदा आदर के योग्य बनो' ।

यद्यपि धन की कमी के कारण सब विद्यार्थियों और शिक्षकों के रहने का प्रबन्ध विश्वविद्यालय के भीतर नहीं किया जा सका, फिर भी यह मुख्यतः निवासीय था । यहाँ विभिन्न प्रान्तों और रियासतों के हजारों विद्यार्थी होस्टलों में रहकर गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करते, तथा पारस्परिक सम्पर्क से अपने जीवन में भारतीयता विकसित करते थे । सर्वर्ण हिन्दू विद्यार्थियों के साथ ही साथ हरिजन विद्यार्थी भी रहते और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे । अन्य विश्व-विद्यालयों की तुलना में काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रहने-सहने का ढंग अधिक सादा था । गरीब छात्रों के लिए यहाँ शिक्षा प्राप्त करना अधिक आसान था । मालवीयजी के युग में यहाँ का वातावरण नि सन्देह अधिक धार्मिक और राष्ट्रीय था ।

विवाद

७ मार्च सन् १९१९ को धर्मविज्ञान के सकाय ने निर्णय किया कि केवल ब्राह्मण ही धर्मागता के लिए नियुक्त किया जा सकता है । इस पर बाबू भगवान दास आदि विद्वानों ने बहुत आपत्ति की, और विश्वविद्यालय को विवाद का सामना करना पड़ा । सकाय की दूसरी बैठक में अर्थात् ६ मई को बाबू भगवानदास ने प्रस्ताव किया कि पुराना प्रस्ताव रद्द कर दिया जाय । मालवीयजी ने प्रस्ताव किया कि पुराने निर्णय में यह जोड़ दिया जाय कि "वसतें कि ब्राह्मण विद्वान् भी इंग्लिश विभाग में धार्मिक विषयों पर, जहाँ तक कि वे धर्मविज्ञान सकाय के नियमों के अनुकूल हैं, व्याख्यान दे सकते हैं ।" बाबू भगवानदास चाहते थे कि

इस संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया जाय कि वे नियुक्त भी किये जा सकते हैं। पर सकाय ने मालवीयजी के संशोधन को ही मूल रूप में स्वीकार किया। इसके बाद कौंसिल में इस पर काफी वादविवाद हुआ, और अन्ततोगत्वा २४ जनवरी सन् १९२० को कौंसिल ने कोर्ट से संस्तुति की कि वह धर्मविज्ञान संकाय को आदेश दे कि वह नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्णय न ले जिससे विश्व-विद्यालय के अन्दर किसी जाति के लिए नियुक्ति बन्द हो जाय। कोर्ट ने ११ दिसम्बर सन् १९२० को बहुत बहस के बाद कौंसिल की संस्तुति स्वीकार कर ली। १४ दिसम्बर सन् १९२१ को पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री ने कोर्ट की बैठक में इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की प्रार्थना की, और कोर्ट ने बाबू ज्ञानेन्द्र नाथ बसु के इस संशोधन को स्वीकार किया कि 'धर्मविज्ञान संकाय हिन्दू धर्म में अध्यापको को, कोई ऐसी नीति निश्चित किये बिना जिससे समाज के किसी अंग की भावनाओं को चोट पहुँचे, मानव धर्मशास्त्र की व्यापक भावना की उदार व्याख्या के आधार पर नियुक्त करे।'^१

१२ दिसम्बर सन् १९२० को कोर्ट की बैठक में बाबू भगवानदास ने विश्वविद्यालय के प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक बहुत ही आलोचनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसका विरोध करते हुए श्रीमती एनी बेसेट ने प्रस्ताव किया कि "यह कोर्ट बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में स्वतन्त्र विज्ञान और दर्शन की सच्ची भावना प्रदान करने में, और वहाँ सरकार की राय और तरीकों से प्रभावित हुए बिना, सांस्कृतिक और व्यावसायिक शिक्षा के स्थापित करने में, तथा उस अध्ययन को चालू करने में, जिसके द्वारा सरकारी नौकरी तथा तत्संबंधित व्यवसायों के अतिरिक्त जीवन-निर्वाह के अन्य साधन उपलब्ध हो सकें, जो प्रगति वहाँ हुई है उसके लिए वाइस-चान्सलर, कोर्ट और सिनेट को धन्यवाद देती है।"^२ श्रीमती एनी बेसेट का यह संशोधन और प्रस्ताव ५ मतों के विरुद्ध २६ मतों से स्वीकार हो गया। इस पर बाबू भगवानदास जी ने कोर्ट, कौंसिल, सिनेट तथा विश्वविद्यालय की अन्य संस्थाओं से त्यागपत्र दे दिया। इस ही जमाने में मालवीयजी ने प्रयत्न किया कि संस्कृत महाविद्यालय और उसकी परीक्षाएँ विश्वविद्यालय का अंग बन जायें, पर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली।

वात्सल्य

विद्यार्थियों से मालवीयजी के सम्बन्ध बहुत ही मधुर थे। वे सब विद्यार्थियों को अपना चन्चा समझते थे। उनका वात्सल्य सबके लिए था। गरीब विद्यार्थियों के प्रति उनका विशेष अनुराग था। उन्होंने विश्वविद्यालय सोलते ही हरिजन विद्यार्थियों की शिक्षा निशुल्क कर दी थी। अन्य गरीब विद्यार्थियों को भी वे यथासंभव आर्थिक सहायता देते रहते थे। गरीब छात्रों की सहायता तथा उनकी समुचित शिक्षा का प्रबन्ध करने में वे बहुत संतोष और सुख का अनुभव करते थे। संयुक्त प्रान्त के भूतपूर्व मन्त्री चौधरी गिरधारी लाल ने अपने संस्मरण में ठीक ही कहा है कि मालवीयजी को 'मालूम भर हो जाना चाहिए कि यह बालक हरिजन है और उनकी उदारता के कपाट उसके लिए खुल जाते थे। शिक्षा शुल्क और छात्रावास शुल्क तो माफ हो ही जाता था, उसके दूसरे खर्च भी महामना अपने पास से पूरा कर दिया करते थे। आज शिक्षित हरिजन समुदाय में काफी संख्या उन लोगों की है, जिन्हें मालवीयजी की उदारता के कारण ही सारी सहूलियतें प्राप्त हुई हैं।' चौधरी गिरधारीलालजी के अतिरिक्त श्री जगजीवन राम आदि बहुत से हरिजन हैं, जिन्होंने सारी सहूलियतें प्राप्त करके काशी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त कर राष्ट्र की सेवा की और कर रहे हैं। यही बात दूसरे अनेक सज्जनों के संबंध में भी कही जा सकती है।

विद्यार्थी भी मालवीयजी के व्यक्तित्व के आगे सदा नतमस्तक रहते थे। छात्रों को निमंदेह उनके देशव्यापी गौरव पर गर्व था। कम से कम उनकी उपस्थिति में विद्यार्थियों के लिए अशोभनीय कार्य करना असंभव ही होता था। वे तो सभाओं में उँगली के इशारे से अनुशासन और भद्र व्यवहार प्रतिष्ठित करते थे।^१

राष्ट्रीय आन्दोलनों के अवसरों पर ही उन्हें अनुशासन बनाये रखने में कभी कभी कुछ कठिनाई हो जाती थी। यह कठिनाई भी उन्हें सन् १९२० में ही विशेष रूप से हुई, जब कि उन्हें परेशान होकर विश्वविद्यालय को कुछ दिनों के लिए बन्द कर देना पड़ा था। इस अवसर पर गांधीजी का विद्यार्थियों को आदेश था कि वे विश्वविद्यालय छोड़ दें, जबकि मालवीयजी विद्यालयों के बाइकाट की नीति गलत समझते थे, और विद्यार्थियों से कहते थे कि वे शिक्षा प्राप्त करके अपने को राष्ट्रसेवा के योग्य बनायें।

१, मालवीयजी : जीवन झलकिया, पृ० ११८।

२. महामना मदनमोहन मालवीयजी वर्थ सेंटिनरी कोमेमोरेशन वाल्यूम, (प्रोफेसर नारलिकर का लेख), पृ० १३१।

एक बार मालवीयजी की अध्यक्षता में गांधीजी ने विद्यार्थियों के सामने अपने विचार रखते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे विश्वविद्यालय की पढाई को छोड़ कर राष्ट्र-सेवा में लग जावें। अन्त में उन्होंने यह भी कहा कि मालवीयजी उनके बड़े भाई हैं, जो कुछ करना उनका आशीर्वाद लेकर करना। दूसरे दिन मालवीयजी ने लगभग चार घंटे के भाषण में विद्यार्थियों को समझाया, पर अन्त में कहा कि यदि किसी विद्यार्थी का अन्त करण यही कहता है कि उसे इस समय अपना जीवन राष्ट्र-सेवा में अर्पित कर देना चाहिए तो उसे मेरा आशीर्वाद है। लगभग सौ विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय छोड़ा। उन सबसे मालवीयजी के मधुर सम्बन्ध बने रहे। जब दिसम्बर में कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होने मालवीयजी नागपुर गये, तब वहा उपस्थित पुराने छात्रो ने 'हर-हर महादेव' का नारा लगाकर उनका स्वागत किया।

युवराज का स्वागत

पर जब दिसम्बर सन् १९२१ में मालवीयजी ने विश्वविद्यालय की ओर से वेल्स के युवराज, ब्रिटिश सम्राट् के उत्तराधिकारी, एडवर्ड का स्वागत किया तब, वे अपने छात्रो का सहयोग प्राप्त नहीं कर सके। उस समय जबकि कांग्रेस के आदेश पर गांधीजी के नेतृत्व में सारे देश ने युवराज की यात्रा का बहिष्कार कर दिया था, काशी विश्वविद्यालय में उनका स्वागत विद्यार्थियों को बुरा लगा। पर मालवीय जी मजबूर थे। कांग्रेस ने दिसम्बर सन् १९१९ में युवराज के स्वागत का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। एक राजनीतिक संस्था नयी परिस्थिति के सन्दर्भ में पुराना निर्णय बदल सकती थी, स्वागत के प्रस्ताव को रद्द करके बहिष्कार का प्रस्ताव पास कर सकती थी, पर सरकार द्वारा अधिकृत एक विश्वविद्यालय के लिए स्वागत का निर्मन्त्रण वापस लेना असम्भव था। स्वागत-प्रबन्ध देखने के लिए १ दिसम्बर सन् १९२१ को लार्ड रीडिंग विश्व-विद्यालय पधारे, तथा १३ दिसम्बर को युवराज पधारे। विश्वविद्यालय के चांसलर महाराजा मैसूर तथा अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। विशेष दीक्षान्त समारोह में युवराज को सम्मानार्थ डाक्टर की डिग्री से विभूषित करते हुए चांसलर ने आशा व्यक्त की कि "यह डिग्री एक ऐसा चमकदार रेशमी सम्बन्ध होगा जो युवराज को भारत के नवयुवको के साथ उनकी राष्ट्रीय आकाक्षाओं में बाँध देगा, और इस प्राचीन देश की जनता की सम्यता, संस्कृति, प्रगति और समृद्धि में आप की अभिरुचि को दृढ़ करेगा।"

राष्ट्रवादी विद्यार्थी

असहयोग आन्दोलन के बाद उन विद्यार्थियों में से, जिन्होंने गांधीजी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय छोड़ दिया था, बहुतों ने मालवीयजी की अनुमति और आज्ञा से फिर इसी विश्वविद्यालय में प्रवेश करके अपनी पढाई प्रारम्भ कर दी। बहुत से दूसरे असहयोगी विद्यार्थियों ने भी मालवीयजी द्वारा संचालित विश्व-विद्यालय को राष्ट्रीय संस्था समझकर दूसरे विश्वविद्यालयों के बजाय यहाँ शिक्षा प्राप्त करना ही उचित समझा। इन सब विद्यार्थियों ने काशी विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्वरूप को पुष्ट किया। ये सब बातें सरकार को कहीं अच्छी लगने-वाली थी? पर मालवीयजी की उपस्थिति में उसके लिए आसानी से हस्तक्षेप करना सम्भव भी नहीं था।

विस्तार

आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद विश्वविद्यालय में नये-नये विभाग खुलते रहे, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गयी, और गांधीजी आदि नेताओं के उपदेशों से विद्यार्थी समाज अनुप्राणित होता रहा। मालवीयजी स्वयं अपने प्रोत्साहन और सहयोग द्वारा छात्रों के पाठ्येतर क्रियाकलापों को परिपुष्ट करते, तथा अपने उपदेशों और व्याख्यानो द्वारा छात्रों को भगवद्भक्ति, देशभक्ति, सदाचार तथा लोकतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा प्रदान करते रहे।

दीक्षान्त भाषण

सन् १९२९ में मालवीयजी ने अपने दीक्षान्त भाषण में विश्वविद्यालय के स्नातको को उपदेश दिया कि वे अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने को सदा उद्यत रहे, अपने देशवासियों से प्रेम करें, और उनमें एकता की वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि आप सबसे तितिक्षा और धैर्य की प्रचुर भावना, तथा स्नेहमयी सेवा की विस्तृत भावना की अपेक्षा है। हम आशा करते हैं कि अपने दीन-हीन भाइयों के उत्थान के लिए आप जितना समय और शक्ति बचा सकें, उसे आप लगावेंगे। हम आशा करते हैं कि आप उनके मध्य में काम करेंगे, उनके कष्टों और उनके आनन्द में भाग लेंगे, और जिस तरह भी आपके लिए संभव हो, उनके जीवन को अधिक सुखमय बनाने का प्रयत्न करेंगे। मालवीयजी ने इस भाषण में उन्हें सलाह दी कि वे जनता में शिक्षा का प्रसार करें, स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा का प्रचार करें, सहकारी संस्थाओं को स्थापित करें। उन्होंने कहा : “आप स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने देश में स्वशासन चाहते हैं, इसके लिए जो कुछ त्याग आपसे अपेक्षित हो उसके लिए तैयार रहिये। आप अपने में स्वातंत्र्य-

प्रेम, और मातृभूमि के गौरव के लिए त्याग की भावना पुष्ट करें। इस तरह हम फिर एक बड़ा राष्ट्र बन सकेंगे।”

सरकार से संघर्ष

इस अभिभाषण के कुछ दिन बाद ही कांग्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता के निमित्त सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करने का निर्णय किया, और मालवीयजी ने भी उसमें सक्रिय भाग लेने की ठान ली। आन्दोलन ने विश्वविद्यालय के लिए विकट समस्या उपस्थित कर दी। स्थानीय कांग्रेस कमेटी किसी न किसी तरह विश्वविद्यालय को बन्द करवा देने के फेर में थी। उन्होंने पिकेटिंग में हर प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया। पर जब स्थानापन्न कांग्रेस अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को प्रो-वाइस-चान्सलर से इसकी सूचना मिली, तब उन्होंने आदेश दिया कि स्थानीय कांग्रेस कमेटी ने जो तरीके अपनाये हैं वे कांग्रेस की नीति के विरुद्ध हैं, और यदि स्थानीय कमेटी किसी दूसरे तरीके से पिकेटिंग नहीं कर सकती, तो उसे बन्द कर दिया जाय।

इसके तुरन्त बाद ही मालवीयजी ने ३१ जुलाई-१ अगस्त की रात्रि को बम्बई में सत्याग्रह किया, और वहाँ वे गिरफ्तार कर लिये गये। इस पर लगभग १०० विद्यार्थी सत्याग्रह करने बंबई चल दिये, पर मालवीयजी के कहने पर वापस चले आये। इधर स्टाफ के दो तीन सदस्यो तथा बहुत से विद्यार्थियो ने सविनय-अवज्ञा में सक्रिय भाग लेना शुरू किया, और अगस्त के अन्तिम सप्ताह में मालवीयजी ने एक सदस्य की हैसियत से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, जो पहले ही गैरकानूनी घोषित कर दी गयी थी, भाग लिया, और उन्हें छः मास की सजा दे दी गयी। इसके बाद प्रो-वाइस-चान्सलर ध्रुव को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। सरकार ने विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर, अध्यापको और विद्यार्थियो की गतिविधि से रूष्ट हो अनुदान की पहली किस्त भेजने से इनकार कर दिया, और विश्वविद्यालय के अधिकारियो से अपना क्षोभ प्रकट करते हुए बहुत से प्रश्नो का उत्तर माँगा, और विश्वविद्यालय की नीति को स्पष्ट करने की माँग की। ध्रुवजी को कई बार दिल्ली और लखनऊ सरकार के अधिकारियो से, तथा नैनी सेंट्रल जेल प्रयाग में मालवीयजी से बातचीत करने जाना पड़ा, तथा विश्वविद्यालय की कार्यसमिति और सिंडीकेट को प्रश्नो का उत्तर तथा नीति का स्पष्टीकरण करना पड़ा।

१. दर और सोमसकन्दन . हिस्ट्री आफ़ दी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, पृ० ५७२-५७३।

मालवीयजी के परामर्श से विश्वविद्यालय की कार्य समिति (एक्जीक्यूटिव कौंसिल) ने २५ नवम्बर सन् १९३० को भारत सरकार को लिखा : “बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय संस्था है, धर्म और नैतिकता (देशभक्ति और नागरिकता) की शिक्षा द्वारा नवयुवकों के चरित्र का निर्माण उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। उसका विश्वास है कि धर्म ‘चरित्र का सर्वश्रेष्ठ आधार’ है, और ‘देशभक्ति’ एक शक्तिशाली उत्कर्षशील प्रभाव है, जो स्त्री-पुरुषों को उच्च मनस्क और निःस्वार्थ कार्य के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यह विश्व-विद्यालय अपने विद्यार्थियों के मन में इन्हें संचारित करने का, तथा सार्वजनिक और राष्ट्रीय प्रश्नों के संबंध में निर्णय और व्यवहार के उच्च स्तर को उनमें विकसित करने का प्रयत्न करता है। पर इसके अतिरिक्त सक्रिय राजनीति से वह अपने को अलग रखता है, क्योंकि वह एक ‘शैक्षिक संस्था है न कि राजनीतिक’, उसका उद्देश्य ‘शिक्षा, न कि राजनीतिक सुधारों की वृद्धि’ है, और चूँकि वह विभिन्न राजनीतिक विचारों से सम्बन्धित जनता, भारतीय रियासतों और सरकार की सहायता से चलता है। पर राष्ट्रीय आन्दोलनों के अवसर पर उसे ‘राष्ट्रीय भावना की लहर’ का ध्यान रखना होता है। उस समय जबकि बहुत से सम्मानित भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करते हों, विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों से उससे प्रभावित न होने की आशा नहीं की जा सकती।”

पत्र में बताया गया कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार वही अध्यापक उसकी सेवा से अलग किये जा सकते हैं, जिन्हें अदालत ने किसी ‘नैतिक अपचार’ के ‘संगीन अपराध’ में दण्डित किया हो, पर ‘सविनय-अवज्ञा’ द्वारा कानून की किसी धारा के उल्लंघन के लिए प्राप्त दण्ड किसी तरह भी नैतिक अपचार से आविष्ट नहीं समझा जा सकता। इसलिए सविनय-अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण दण्डित अध्यापकों को विश्वविद्यालय अपनी सेवा से अलग नहीं कर सकता।

इस पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की राय में जो विद्यार्थी सविनय-अवज्ञा से संबंधित किसी अपराध पर सजा भुगत चुका है, उसे उसी अपराध के लिए कोई दूसरी सजा देना, जिससे उसका सारा जीवन ही बर्बाद हो जाय, न्यायसंगत नहीं होगा। इसीलिए सिंडिकेट की राय में उसे विश्वविद्यालय में फिर से दाखिल न करना ठीक नहीं होगा। विश्वविद्यालय का अनुभव है कि पिछले असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के बाद जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए फिर से विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, उनमें से

कुछ अच्छे विद्वान् बन कर बहुत लाभदायक काम कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए इन कारणों से विश्वविद्यालय का द्वार सदा खुला रहेगा।^१

दिसम्बर सन् १९३० में बनारस के कमिश्नर ने विश्वविद्यालय को सूचना दी कि 'भारत सरकार अनुदान के संबंध में विचार कर रही है', और जानना चाहती है कि 'विश्वविद्यालय को सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के प्रभाव से रक्षित करने के लिए' विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने क्या किया ?

इसके उत्तर में प्रो-वाइस-चान्सलर ने लिखा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की निश्चित धारणा है कि "विद्या का प्रसार ही विश्वविद्यालय का प्राथमिक और प्रमुख उद्देश्य है, और राजनीतिक प्रचार और आन्दोलन का उसके कार्य में स्थान नहीं है"। पर उन्हें इस देश तथा दूसरे देशों के अनुभवों से यह भी स्पष्ट है कि "राजनीतिक दबाव और सकट के अवसरों पर यह आशा करना कठिन है कि नवयुवक बाहरी प्रभावों के प्रति विलकुल उदासीन और भाव-शून्य रहेंगे।" उन्होंने यह भी लिखा: "वाइस-चान्सलर की भावपूर्ण अपील, पिकेटिंग को खत्म कराने के हमारे प्रयत्न, विश्वविद्यालय को बन्द न करने का हमारा निर्णय, प्रो-वाइस-चान्सलर का विद्यार्थियों को यह समझाना कि वे जत्था बना कर बम्बई न जावें, इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी विश्वविद्यालय में शैक्षिक शान्ति यथासंभव बनाये रखना चाहते हैं।"^२

सरकार के कठिन दृष्टिकोण ने विश्वविद्यालय के सामने कठिन आर्थिक समस्या उपस्थित कर दी। उसके लिए अध्यापकों को ठीक समय पर पूरा वेतन देना भी कठिन हो गया। इस स्थिति में विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने एक पत्र द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सूचित किया कि "विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और हितों की रक्षा के निमित्त विश्वविद्यालय के अध्यापक-समाज के अधोहस्ताक्षरी सदस्य विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर पण्डित भदनमोहन मालवीय को वित्तीय सकट की अवस्था में उस समय तक और उन शर्तों पर अपनी सेवा अर्पित करते हैं, जिन्हें वे निश्चित करें।"^३

इस समय यह भी उड़ती खबर थी कि मालवीयजी पर दबाव डाला जा रहा है कि वे उपकुलपति के पद से त्यागपत्र दे दें। इस समाचार ने विश्वविद्यालय के बहुत से अध्यापकों में काफी क्षोभ और उत्तेजना पैदा कर दी। पर इस खबर का शीघ्र ही खण्डन कर दिया गया।

बीमारी के कारण मालवीयजी छः मास की अवधि के पहले ही २४ दिसंबर सन् १९३० को जेल से रिहा कर दिये गये। १९ जनवरी सन् १९३१ को उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर मेकंजी साहब विश्वविद्यालय आये। उन्होंने बातचीत में मालवीयजी से अनुरोध किया कि वे कम से कम इस बात की घोषणा करें कि जिन विद्यार्थियों ने अनुशासन भंग कर आन्दोलन में भाग लिया है, उन्हें लिखित क्षमा प्रार्थना पर ही विश्वविद्यालय में भरती किया जा सकेगा। पर मालवीयजी ने इस प्रकार की घोषणा करने से साफ इनकार कर दिया।

काशी में पुराने छात्रों की एक बैठक में २३ जनवरी सन् १९३१ को आर्थिक कठिनाई की चर्चा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे किसी शर्त के साथ सरकार से अनुदान लेने को तैयार नहीं हैं। यदि आवश्यकता होगी तो बिना सरकारी अनुदान के विश्वविद्यालय चलाया जायगा।

१७ फरवरी सन् १९३१ को लार्ड अर्विन ने गांधीजी से राजनीतिक समझौते पर बातचीत प्रारम्भ की। २५ फरवरी को विश्वविद्यालय को सरकारी अनुदान की पहली छः-मासिक किस्त मिली। ५ मार्च को गांधी-अर्विन समझौता हुआ, और उसके बाद सरकार ने आवर्तक अनुदान की दूसरी किस्त और पूरा अनावर्तक अनुदान भेज दिये।

गांधी-अर्विन समझौते के बाद १६ मार्च सन् १९३१ को प्रोफेसर यू० ए० असरानी और पण्डित जगन्नाथ प्रसाद वाजपेयी, जिन्होंने सत्याग्रह में भाग लेने के बाद जेल से इस्तीफा भेज दिया था, विश्वविद्यालय द्वारा फिर नियुक्त कर लिये गये। विश्वविद्यालय का काम यथावत् चलता रहा।

कठिनाइयाँ

आर्थिक कठिनाइयों के कारण सरकार ने आवर्तक अनुदान में दस प्रतिशत की कटौती कर दी, और विश्वविद्यालय को भी सौ रुपये से अधिक वेतन पाने-वाले अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन में दस प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी। यह कटौती चार वर्ष तक चलती रही। यद्यपि इन चार वर्षों में विश्वविद्यालय को कुछ नये आवर्तक और अनावर्तक अनुदान प्राप्त हुए, पर कुछ पुराने आवर्तक अनुदान बन्द हो गये, जिनके कारण विश्वविद्यालय की आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गयीं। कर्जों तीन लाख रुपये से बढ़कर तेरह लाख हो गया।

इन चार वर्षों में विश्वविद्यालय के बहुत से पुराने सहायक और समर्थक देवलोक चले गये। सन् १९३१ में बनारस के महाराजा सर प्रभुनारायण सिंह,

३० सितम्बर सन् १९३३ को श्रीमती डा० एनी बेसेंट, तथा २७ मार्च सन् १९३४ को राजा मोती चन्द का निधन हो गया ।

विस्तार

इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी विश्वविद्यालय में नये सकाय, नये विभाग और नये कालेज खुलते रहे । सन् १९३४ में भेषजिकी और औषध विज्ञान की शिक्षा आरम्भ हुई, सन् १९३५ में औद्योगिक रसायन विज्ञान में बी० ए० और एम० ए० की पढाई का नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया, सन् १९३६ में मृत्तिका शिल्प का पृथक् विभाग खोला गया, तथा सन् १९३७ में ग्लास टेक्नालोजी की शिक्षा के लिए विभाग खोला गया । सितम्बर सन् १९३५ में सेंट्रल हिन्दू कालेज के विज्ञान विभागों को अलग करके साइन्स कालेज गठित किया गया, और प्रोफेसर कृष्ण कुमार माथुर उसके प्रिन्सिपल नियुक्त हुए । नवम्बर सन् १९३६ में फैकल्टी आफ टेक्नालोजी गठित की गयी । इस वर्ष आचार्य ध्रुव के स्थान पर राजा ज्वाला प्रसाद प्रो वाइस-चान्सलर हुए ।

सार्वजनिक सेवा का केन्द्र

दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ होने पर प्रोफेसर यू० ए० असरानी आदि अध्यापकों ने फिर सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया । इधर मालवीयजी के कारण विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कार्यों का केन्द्र बन गया । उनके साथ प्राच्य विद्यालय के प्राचार्य (प्रिन्सिपल) पंडित प्रमथनाथ तर्कभूषण ने मन्त्रदीक्षा आदि शास्त्रविहित उपायों द्वारा अन्त्यजोद्धार का कार्य किया । प्राच्य विद्यालय के साहित्य विभाग के अध्यक्ष पंडित महादेव पाण्डेय, तथा साख्य विभाग के अध्यक्ष पंडित हीरावल्लभ शास्त्री आदि अध्यापकों ने भी अन्त्यजोद्धार तथा उदार सनातन धर्म के प्रसार में उनका साथ दिया । दूसरी ओर प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल, मालवीयजी की अध्यक्षता में आयोजित, अखिल भारतीय स्वदेशी संघ के मन्त्री नियुक्त हुए, और उन्होंने विश्वविद्यालय के अहाते में अपने निवास-स्थान पर ही संघ का कार्यालय स्थापित कर वही से स्वदेशी के प्रसार का कार्य किया, तथा हरिजन सेवक संघ की जिला शाखा का मन्त्रित्व ग्रहण कर हरिजनोद्धार का कार्य किया । मालवीयजी का अपना निवास-स्थान तो उनके राजनीतिक और धार्मिक कार्यों का केन्द्र ही था । यही स्थानीय, प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता और नेता आते, मालवीयजी से राष्ट्रीय प्रश्नों पर बातचीत करते, तथा यथासंभव सहायता प्राप्त करते थे ।

कहा जाता है कि दूसरे सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के जमाने में मालवीयजी की तथा हिन्दू यूनिवर्सिटी की गतिविधि से क्षुब्ध हो भारत सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपति महाराजा बीकानेर को लिखा कि चूँकि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की दशा बहुत खराब है, अनुशासन का नितान्त अभाव है, इसलिए वे अपने पद से इस्तीफा दे दें। महाराजा गंगा सिंह ने उत्तर में लिखा कि यदि दशा खराब है, तो उसे सुधारने का प्रयत्न किया जायगा।

विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए मालवीयजी महाराजा गंगा सिंह से मिलने बीकानेर गये। उन्होंने मालवीयजी को सहयोग का पूरा आश्वासन दिया, और कहा कि वे उनका साथ छोड़नेवाले नहीं हैं। काशी लौटने से पहले मालवीयजी राजस्थान की कई अन्य रियासतों में भी गये, और वहाँ सब महाराजाओं ने विश्वविद्यालय के समर्थन का उन्हें आश्वासन दिया।

सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के बाद मालवीयजी ने सन् १९३४ और सन् १९३५ में प्रधानमन्त्री के साम्प्रदायिक निर्णय काट कर विरोध किया, और सन् १९३६ में जब कांग्रेस ने उसे रद्द करना ही उचित समझा, तब मालवीयजी ने प्रान्तीय कौंसिल के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का डट कर समर्थन किया। जनवरी सन् १९३८ में उन्होंने पण्डित हरदत्त शास्त्री के साथ चालीस दिन का कायाकल्प किया। इससे प्रारम्भ में कुछ लाभ दिखाई दिया, पर वास्तव में स्वास्थ्य सुधरने के बजाय विगड़ गया। सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन करते रहना उनके लिए असम्भव हो गया। १७ सितम्बर सन् १९३९ को उनकी अनुमति से यूनिवर्सिटी कोर्ट द्वारा सर एस० राधाकृष्णन् वाइस-चान्सलर निर्वाचित हुए।

राधाकृष्णन्जी लब्ध-प्रतिष्ठ दार्शनिक थे। वे कई वर्ष आन्ध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति रह चुके थे, और इस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के वरिष्ठ प्रोफेसर थे, तथा प्रतिवर्ष कुछ महीने आक्सफोर्ड भी भारतीय दर्शनशास्त्र के अध्यापन के लिए जाते थे। इन दोनों कामों के साथ-साथ एक बड़े विश्वविद्यालय के उपकुलपति के उत्तरदायित्व को ग्रहण करना बहुत साहस की बात थी। पर वे इस उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए निःसन्देह सर्वथा समर्थ थे। आगे चलकर वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के वजाय हिन्दू यूनिवर्सिटी में ही दर्शनशास्त्र के वरिष्ठ प्रोफेसर का काम करने लगे। पर वे फिर भी अध्यापन के लिए आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाते ही रहे।

१८ सितम्बर सन् १९३९ को मालवीयजी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की कौंसिल ने विश्वयुद्ध में 'अन्तर्गत समस्याओं की गंभीरता' अनुभव करते



मालवीयजी और गांधीजी (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती के अवसर पर)

हुए 'स्वतंत्रता और जनतंत्र के सिद्धान्तों की विजय की, जिनसे ग्रेट ब्रिटेन सम्बन्धित है, कामना की' और आशा की कि 'ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उनका सार्थक प्रयोग समृद्ध भारत तथा विश्वशान्ति का निर्माण करेगा।' इस प्रस्ताव में कौंसिल ने 'विद्यार्थियों को हर प्रकार की सैनिक शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का प्रवन्ध करने की भी सरकार से प्रार्थना की।'

२५ नवम्बर सन् १९३९ को यूनिवर्सिटी की सिनेट (शिक्षा परिषद्) ने अपनी विशेष बैठक में मालवीयजी की सेवाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय का आजीवन रेक्टर बनाने की सस्तुति की, जिसे चान्सलर ने २ जनवरी सन् १९४० को स्वीकार कर लिया। २५ नवम्बर को ही मालवीयजी सिनेट की साधारण बैठक में सिनेट, सिंडिकेट और बोर्ड आफ अपाइन्टमेंट (नियुक्ति बोर्ड) के सदस्य निर्वाचित किये गये। २२ दिसम्बर सन् १९३९ को कोर्ट ने अपने वार्षिक अधिवेशन में मालवीयजी को सर्वसम्मति से कौंसिल का सदस्य निर्वाचित किया।

३० नवम्बर सन् १९४० को कोर्ट ने अपने वार्षिक अधिवेशन में मालवीयजी के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से पण्डित इकवाल नारायण गुट्टू को तीन वर्ष के लिए प्रो-वाइस-चान्सलर नियुक्त किया।

रजत जयन्ती

१० जनवरी सन् १९४२ को विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती मनायी गयी। महात्मा गांधी ने दीक्षान्त भाषण किया। उन्होंने अपने भाषण में मालवीयजी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा - "प्रेम का दृढ़ बन्धन मुझे मालवीयजी से बांधे हुए है, और मैं उनके आदेश का पालन, जब कभी यह मेरे लिए संभव होता है, बड़े गर्व और सन्तोष के साथ करता हूँ।" उन्होंने कहा - "यद्यपि मालवीयजी की बहुत सी सेवाएँ हैं, पर यह विश्वविद्यालय उनकी सबसे बड़ी कृति है।" "मालवीयजी", उन्होंने कहा, 'सादा जीवन और उच्च चिन्तन के सजीव उदाहरण हैं।' उन्होंने आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी याद रखेंगे कि वे गरीबों के बच्चे हैं, और "मालवीयजी की तरह सरल और सादे जीवन का तथा उच्च विचारों का नमूना बनेंगे।" उन्होंने भारतीय भाषाओं तथा देवनागरी की समुचित शिक्षा प्राप्त करने पर जोर देते हुए आशा व्यक्त की कि हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम बना दी जायगी। अन्त में उन्होंने भारतीय संस्कृति के महत्त्व की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा "ससार

के साथ मित्रवत् व्यवहार करना, शत्रु को भी मित्र बनाना इस संस्कृति का विशेष योगदान है। पवित्र गंगा की तरह हमारी संस्कृति ने बाहर से आनेवाली बहुत सी धाराओं को अपने में मिला लिया है।” उन्होंने आशा व्यक्त की कि “यह हिन्दू यूनिवर्सिटी, जो हिन्दू संस्कृति और हिन्दू सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न करती है, दूसरी संस्कृतिओं के उत्तम तत्त्वों को निमन्त्रित और आत्मसात करेगी, तथा साम्प्रदायिक एकता और सामजस्य का नमूना बनेगी।”^१

अन्त में मालवीयजी ने उन सबको धन्यवाद और आशीर्वाद देते हुए, जिन्होंने विश्वविद्यालय के निर्माण में योगदान किया, आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सादे जीवन के आदेश और आदर्श को ध्यान में रखेंगे और उसका पालन करेंगे। उन्होंने गांधीजी को विश्वास दिलाया कि हिन्दी में पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जा रही हैं, और उनके तैयार होने पर विश्वविद्यालय में हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम बनेगी। अन्त में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे धर्म के प्रति हमारी निष्ठा को दृढ़ करें, हममें देश-प्रेम की भावना संचरित करें, तथा विश्वविद्यालय को समुचित सहायता प्राप्त होती रहे।^२

‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन

८ अगस्त सन् १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ‘भारत छोड़ो’ संघर्ष प्रारम्भ करने का निश्चय किया। ९ अगस्त को प्रातःकाल गांधीजी तथा कांग्रेस के बहुत से सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। उसी रात को काशी विश्वविद्यालय के आवास में प्रोफेसर यू० ए० असरानी गिरफ्तार कर लिये गये। १० अगस्त को वाइस-चान्सलर डाक्टर राधाकृष्णन् ने विद्यार्थियों और अध्यापकों की एक बैठक में विश्वविद्यालय में शान्त वातावरण बनाये रखने का तथा हिंसात्मक कार्यवाहियों से बचे रहने का सबसे अनुरोध किया।^३ पर संघर्ष की परिस्थिति में नवयुवकों के लिए शान्त रहना असंभव था। ऐसी हालत में १२ अगस्त को एक मास के लिए विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया। विद्यार्थियों को घर चले जाने की सलाह दी गयी। बहुत से विद्यार्थी घर चले गये, पर लगभग ३०० विद्यार्थी छात्रावास में बने रहे, और उनमें से कुछ किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भाग लेते रहे। प्रोफेसर राघवेश्याम शर्मा और डाक्टर के० एन० गैरोला विश्वविद्यालय के एक छात्रावास से ही गुप्तरूप से विद्यार्थियों का सक्रिय मार्ग-दर्शन करने लगे। १३ अगस्त को कुछ विद्यार्थियों ने शस्त्रागार के दफ्तर पर छापा मारने का प्रयत्न किया।

एक दिन विद्यार्थियों के जुलूस को, जबकि वह शहर जा रहा था, हरिश्चन्द्र घाट की तिमुहानी पर पुलिस ने गोली के छरों से आहत किया। २५-२६ विद्यार्थियों को छरें लगे। जब मालवीयजी वहाँ पहुँचे, तो विद्यार्थियों ने कहा कि 'छरें पीठ पर नहीं, छाती पर लगे हैं।' मालवीयजी मुसकराये, पर उनकी आँखों में आँसू भी आगये। लौटते हुए उन्होंने राधेश्यामजी से कहा 'अगर आन्दोलन बन्द हुआ तो गांधीजी मर जायेंगे, पर मैं अपने विद्यार्थियों को मरते नहीं देख सकता, ऐसा देखकर मैं मर जाऊँगा। यह सोच कर काम करना चाहिए।' राधेश्याम ने कहा कि हम इसका ध्यान रख कर काम कर रहे हैं।

१३ अगस्त को मालवीयजी ने विद्यार्थियों को सवोधित करते हुए उन्हें भारत के विश्वविद्यालयों में 'उच्च देशभक्ति' का 'कीर्तिमान' उपस्थित करने का, तथा अहिंसा के सिद्धान्तों का दृढ़ता से अनुसरण करने का मन्त्रावली दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए, तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों द्वारा राष्ट्र की सम्पत्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए, शस्त्रागार के निकट नहीं जाना चाहिए, तथा लड़कियों द्वारा पिकेटिंग बन्द कर देना चाहिए।^१

१४ अगस्त को सायंकाल ४ बजे जिलाधिकारी फिनले, डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस और सुपरिंटेंडेंट पुलिस कुछ सैनिकों के साथ विश्वविद्यालय के सिद्धार पर आये। वे सम्भवतः विश्वविद्यालय पर कब्जा करना चाहते थे, पर सर राधाकृष्णन् और डाक्टर इकवाल नारायण गुर्ग के समझाने पर वापस चले गये।

पर १९ अगस्त को प्रातः पाँच बजे गैस के जरिये ताले की जजीरें तोड़ कर सैनिक विश्वविद्यालय में घुस आये, और उन्होंने उस पर अपना कब्जा जमा कर विद्यार्थियों को छात्रावास खाली कर देने के लिए बाध्य किया।

२१ अगस्त को विश्वविद्यालय की कौंसिल ने एक अत्यावश्यक बैठक में सरकार की इस कार्यवाही को विश्वविद्यालय की मानमर्यादा के विरुद्ध बताते हुए सैनिकों और पुलिस को हटा लेने का अनुरोध किया।^२ सरकार ने इन पर ध्यान देने के बजाय २९ अगस्त को इंजीनियरिंग कालेज की मशीनों को माँगा, २ सितम्बर को आदेश दिया कि २४ सितम्बर को कालेज न खोला जाय, ५ सितम्बर को विश्वविद्यालय पर सरकारी कब्जे के संबंध में नियमित आदेश जारी

दिया। इस समय सरकार विश्वविद्यालय में फौजी अस्पताल बनाने की बात सोच रही थी।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सरकार को अधिघातित मशीनें दे दी, तथा छुट्टियाँ २० अक्टूबर तक बढ़ा दी, पर उन्होंने सैनिक अस्पताल खोलने के विचार का विरोध किया, और विश्वविद्यालय से सेना और पुलिस हटा लेने की माग की। सर राधाकृष्णन् और डाक्टर इकबाल नारायण गुट्टू ने लखनऊ और दिल्ली में सरकार के अधिकारियों से बातचीत की, तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों से पत्र-व्यवहार किया। सर राधाकृष्णन् का कहना था कि विश्वविद्यालय का किसी राजनीतिक दल या संस्था की राजनीति से कोई संघ नहीं है, पर आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों की तरह यहाँ पर विद्यार्थियों को राजनीतिक विषयों पर विचार-विमर्श करने की, तथा उनपर अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। सरकारी अधिकारियों का कहना था कि इस विश्वविद्यालय में गरमदलोय नेताओं को आमंत्रित किया जाता है, और उनके भाषण कराये जाते हैं, और यहाँ का वातावरण बहुत ही राजनीतिक बन गया है। उनकी धारणा थी कि वाराणसी क्षेत्र में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और अध्यापकों का बड़ा हाथ है। संयुक्त प्रान्त के गवर्नर का आरोप था कि "डाक्टर गैरोला तथा प्रोफेसर राघवेश्याम के नेतृत्व में बहुत से विद्यार्थियों ने तोड़ फोड़ के अभियान को जारी किया, जिसका इस प्रान्त में किसी दूसरे स्थान पर कोई सादृश्य नहीं है।" सरकारी का यह भी कहना था कि युद्ध के जमाने में विश्वविद्यालय के विशाल भवनो को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। यदि पढाई नहीं होती तो इसका दूसरा उपयोग करना ही होगा।

अन्त में सरकार ने सैनिक अस्पताल खोलने का विचार छोड़ दिया, और विश्वविद्यालय को क्रमशः खोलने की अनुमति दे दी। २६ अक्टूबर को एम० ए०, एम० एस-सी० तथा आचार्य के विद्यार्थियों की पढाई आरम्भ हो गयी। २ नवम्बर को कानून, शास्त्री तथा इंजीनियरिंग और माइनिंग मेटलरजी के तृतीय और चतुर्थ वर्ष की एवं बी० फार्म और बी० एस-सी० (टेक्नालोजी) की पढाइया शुरू हो गयी। ११ नवम्बर सन् १९४२ को बाकी सब कक्षाएँ भी खोल दी गयी। सरकार ने २६ अक्टूबर से कुछ दिन पहले सेना और पुलिस को विश्वविद्यालय से हटा लिया।

प्रगति

इसके बाद मालवीयजी के जीवन-काल में अर्थात् ३ वर्ष तक काशी विश्वविद्यालय किसी गंभीर सकट के बिना काम करता रहा। जो विद्यार्थी जेल से छूटकर आते थे, विश्वविद्यालय में दाखिल कर लिये जाते थे, उन्हें उनकी पुरानी सुविधाएँ दे दी जाती थी। जेल से छूटने पर प्रोफेसर यू० ए० असरानी और डाक्टर मंगल सिंह भी, जो आन्दोलन के जमाने में नजरबन्द थे, विश्वविद्यालय में अपने पुराने स्थानों पर काम करने लगे। यूनिवर्सिटी पार्लिया-मेंट आदि छात्रों की संस्थाएँ सन् १९४५ के बाद पूर्ववत् काम करने लगी। जुलाई सन् १९४५ में जब कांग्रेस के नेता जेल से रिहा होकर देश में काम करने लगे, तब उन्हें फिर पूर्ववत् विश्वविद्यालय में निमन्त्रित किया जाने लगा। आचार्य नरेन्द्र देव, डाक्टर सम्पूर्णानन्द, श्री जयप्रकाश नारायण प्रभृति समाज-वादी नेताओं का भी स्वागत हुआ और उनके भाषण हुए। विद्यार्थियों की संख्या और विश्वविद्यालय का आकार भी बढ़ता गया।

सर राधाकृष्णन् के प्रयास से अध्यापकों के वेतन-क्रम (ग्रेड) में भी पर्याप्त वृद्धि हुई, और वे सब प्राध्यापक जो वर्षों से विभागीय अध्यक्ष का काम करते हुए प्रोफेसर के ग्रेड में थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना दिये गये। इस जमाने में ही जहाँ २५ नवम्बर सन् १९३९ को बहुत से प्रावधिक विभागों को मिलाकर 'कालेज आफ टेकनालोजी' गठित किया गया, वहाँ मार्च १९४४ में 'कृषि खोज संस्थान' को 'कृषि कालेज' का, तथा खनन विज्ञान और धातु विज्ञान विभाग को कालेज का स्वरूप दे दिया गया।

महाराजा सर गंगा सिंह के निधन के बाद २१ अगस्त सन् १९४३ को कोर्ट के विशेष अधिवेशन में सर हरिसिंह, महाराजा जम्मू कश्मीर, चान्सलर निर्वाचित हुए।

नवम्बर सन् १९४३ में प्रो-वाइस-चान्सलर के चुनाव का प्रश्न कोर्ट के सामने उपस्थित हुआ। किसी व्यक्ति ने डाक्टर भोलानाथ सिंह के और किसी ने मालवीयजी के सुपुत्र पण्डित राधाकान्त मालवीय के नाम का प्रस्ताव भेजा। मालवीयजी ने स्वयं पण्डित इकबाल नारायण गुटू के नाम का प्रस्ताव भेजा, और उनसे काम करते रहने का अनुरोध किया। कोर्ट ने गुटू साहब को पुनः तीन वर्ष के लिए प्रो-वाइस-चान्सलर निर्वाचित किया, पर उन्होंने २५ मार्च सन् १९४४ को स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया, और श्री रंग बिहारी लाल उनके स्थान पर प्रो-वाइस-चान्सलर नियुक्त किये गये।

पण्डित इकबाल नारायण गुटू

काशी विश्वविद्यालय के निर्माण और प्रगति में पण्डित इकबाल नारायण गुटू का महत्त्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने युवा अवस्था में ही अपनी बढ़ती हुई वकालत छोड़कर बिना घेतन आजीवन समाज की सेवा करने का निर्णय किया, सेंट्रल हिन्दू स्कूल में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ कर दिया और हेडमास्टर पद से उसकी सुव्यवस्था की देखभाल की। सन् १९१९ में ही काशी विश्वविद्यालय की योजना स्वीकार करते हुए उन्होंने उसके लिए धन जुटाना करना शुरू कर दिया, तथा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसायटी के गठित होने पर उसकी सशुक्त-मन्त्री की हैमियत से वे काम करने लगे। विश्वविद्यालय के निर्माण के बाद उन्होंने उसकी विभिन्न सस्थाओं अर्थात् फोर्ट और कींगल के सदन की हैमियत से उसकी सेवा की। उस समय भी जबकि वे गुप्त प्रान्त के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, बनारस म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन, तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य में सलग्न थे, उन्हें काशी विश्वविद्यालय का ध्यान बना रहा, और उसकी सेवा वे अपना कर्तव्य समझते रहे। नवम्बर सन् १९४० में मालवीयजी के आगम पर एक विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर रहने के बाद काशी विश्वविद्यालय में प्रो-वाइस-चान्सलर का उत्तरदायित्व उन्होंने स्वीकार कर लिया, और सन् १९४२ और १९४३ में ब्रिटिश अधिकारियों के प्रकोप से विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा के लिए डाक्टर राधाकृष्णन् के साथ मिलकर महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की अवैतनिक सेवा की, और अवकाश ग्रहण करते समय विश्वविद्यालय को अपने पिता की स्मृति में तीन हजार रुपये का दान दिया।

इस दान की भी विचित्र कहानी है। एक दिन सन् १९४२ के स्वतंत्रता-सर्घर्ष के जमाने में जबकि गुटू साहब बहुत ही क्षुब्ध थे, वे मालवीयजी से मिले, और आधे पीने घंटे तक दोनों की अकेले में बातचीत हुई। इसके बाद भी गुटू साहब का धोभ पूरे तीर पर दूर नहीं हुआ। उनके चेहरे पर मानसिक तनाव के चिह्न स्पष्ट थे। पर जब वे जानेवाले थे, तब मालवीयजी ने राट पर लेटे-लेटे उनसे कहा—“इकबाल नारायण, राय साहब के नाम से कोई चन्दा विश्व-विद्यालय के खाते में नहीं है।” उन्होंने कहा—“महाराज, एक रकम जमा है।” इस पर मालवीयजी ने कहा—“वह तो बटे गय साहब के नाम से है” (गुटू साहब के पिता नहीं, बल्कि पितामह के नाम से है)। यह सुनकर गुटू साहब ने कहा कि “हो जायगा” अर्थात् पिता जी के नाम से कुछ दान दे दिया जायेगा।

इसके तुरन्त बाद गुटू साहव का चेहरा खिल गया, तनाव के सब चिह्न गायब हो गये । इस पुस्तक का लेखक, जो उस समय मालवीयजी के दर्शनार्थ वहाँ पहुँच गया था, गुटू साहव के चेहरे का उतार-चढ़ाव देखकर दग रह गया । उसने मालवीयजी के बहुत से चमत्कार देखे और सुने थे, पर मानसिक तनाव को दूर करने का तथा पुन पुराना स्नेह और सौहार्द प्रतिष्ठित करने का यह निराला ढग कभी नहीं देखा था । सम्भवतः गुटू साहव जैसे उदार और शिष्ट व्यक्ति ही इस उपचार के पात्र थे । साधारण व्यक्ति पर तो सम्भवतः मालवीय-जी की इस बात का ऐसा तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ पाता । सम्भवतः दोनों का हार्दिक घनिष्ट सम्बन्ध ही इस उपचार की सफलता का मूल कारण था । यद्यपि श्रीमती एनी वेसेंट से ही गुटू साहव ने मूल जीवन-प्रेरणा प्राप्त की थी, पर मालवीयजी ने भी उन्हें, उस समय जबकि वे विद्यार्थी ही थे, अनुप्राणित किया था । मालवीयजी को गुटू साहव की क्षमता, कर्तव्यपरायणता तथा निष्काम सगाज-सेवा की भावना पर पूर्ण विश्वास था ।



१०. भारतीय विधान कौंसिल

(१९१०-१९२०)

कौंसिल की शक्ति

सन् १९१० में मालवीयजी प्रान्तीय कौंसिल के गैर-सरकारी सदस्यो द्वारा केन्द्रीय कौंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए, और बार-बार निर्वाचित होकर सन् १९२० तक वहाँ काम करते रहे। इस जमाने में कौंसिल में निर्वाचित सदस्यो की संख्या सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यो की संख्या से कही कम थी। निर्वाचित सदस्यो में भी बहुत से पृथक् निर्वाचन पद्धति द्वारा किसी विशिष्ट आर्थिक हित या सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, और अधिकतर सरकार का समर्थन करते रहते थे। इनमें से कुछ मुसलमान सदस्य साधारण चुनाव क्षेत्रो से निर्वाचित सदस्यो से मिलकर काम करना, और सरकार की नीति-रीति के बजाय जनता के हितो को पुष्ट करना अपना कर्तव्य समझते थे। इनमें मिस्टर मुहम्मद अली जिना तथा मिस्टर मजहूरल हक प्रमुख थे। जमीदार वर्ग के प्रतिनिधि रात्रबहादुर बी० एन० शर्मा और राजा साहब महमूदाबाद भी प्रगतिशील सदस्यो का साथ देते रहते थे। फिर भी किसी प्रश्न पर प्रगतिशील शक्तियाँ सरकार के विरुद्ध एक चौथाई से अधिक वोट नहीं जुटा पाती थी। सन् १९१७ में इस्लिगटन पब्लिक सर्विस कमिशन की संस्तुतियो के विरुद्ध प्रस्तावित प्रस्तावो का करीब-करीब सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यो ने समर्थन किया, फिर भी उन प्रस्तावो को पास कराने में वे सफल नहीं हुए। बहुधा सरकारी पक्ष निर्वाचित सदस्यो की युक्ति और तर्कों का ठीक तौर पर उत्तर देने के बजाय वोट के जरिये उनके सुझावो को रद्द कर देना ही पर्याप्त समझता था। गोखले साहब ने सरकार की इस गतिविधि से क्षुब्ध हो सन् १९१० में बड़े सन्तप्त हृदय से वाइसराय को सम्बोधित करते हुए असेम्बली में कहा था . “हम अच्छे तौर से जानते हैं कि जब एक बार सरकार ने किसी विषय पर विचार निश्चित कर लिया है, तब कौंसिल में गैरसरकारी सदस्य चाहे कुछ भी कहें, वे उस निर्णय को बदलवाने में व्यावहारिक दृष्टि से निरर्थक हैं।”^१

१ प्रोसीडिंग—गवर्नर-जनरल की कौंसिल (विधायिका), अगस्त सन् १९१०, जि० ४९, पृ० २६।

फिर भी गोखले, मालवीयजी और कुछ दूसरे सदस्य कर्तव्य बुद्धि से तत्परता, दृढता और भद्रता के साथ सरकार की नीति-रीति की समीक्षा में तथा जनता के हितों की पुष्टि में लगे रहते थे। गोखले और मालवीयजी की तत्परता तो निःसन्देह विशेष तौर पर सराहनीय थी। ससदीय भद्रता तथा नियमों का पालन करते हुए दोनों बहुत ही विवेक के साथ सदा शिष्ट भाषा में करीब-करीब सभी सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार और सुझाव कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत करते, तथा प्रशामनिक व्यवस्था में सुधार की, और जनहित की वृद्धि की सरकार से माग करते। उनकी आलोचना रचनात्मक होती थी। राष्ट्र का सर्वांगीण नवनिर्माण ही उनके विचारों का लक्ष्य होता था।

रचनात्मक समीक्षा

जनहित की रक्षा और अभिवृद्धि के निमित्त मालवीयजी ने सरकार की सैनिक, प्रशासनिक, आर्थिक और वित्तीय नीतियों और गतिविधि की रचनात्मक समीक्षा करते हुए माग की कि सैनिक और प्रशासनिक खर्चों को घटाकर जनहितकारी निर्माण कार्यों पर अधिक धन खर्च किया जाय, आर्थिक नीतियों को अधिक जनहितकारी बनाया जाय, और वित्तीय नीतियों और व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन किया जाय जिससे गरीबों पर करो का भार कम पड़े, और विधि विधान देश के आर्थिक और सांस्कृतिक निर्माण में सहायक हो। इस उद्देश्य से उन्होंने जनवरी सन् १९११ में गोखले साहब के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि सरकार के खर्चों की जाच के लिए सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की एक जाच कमेटी नियुक्त की जाय। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले २५-३० वर्षों के अन्दर सरकार का खर्चा दुगुना हो गया है, उसे कम करना नितान्त आवश्यक है।^१

बार-बार प्रान्तीय वित्तीय व्यवस्था की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वह “किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है।”^२ उन्होंने माग की कि “जनता की नैतिक और भौतिक उन्नति को अच्छे ढंग पर बढ़ाने के लिए प्रान्तीय राजस्व का अधिक बड़ा हिस्सा युक्त प्रान्त की सरकार को दिया जाय।”^३

१. प्रोसीडिंग—गवर्नर-जनरल की कौंसिल (विधायिका), १९११, जि० ४९, पृ० २००-२०१।
२. वही, सन् १९१२, जि० ५०, पृ० ६८२।
३. वही, सन् १९१२, जि० ५०, पृ० ४०४-४०९, सन् १९१४, जि० ५२, पृ० ६२७-६३०।

सन् १९१४ में उन्होंने माँग की कि सरकार सैनिक, प्रशासनिक और अनुत्पादक खर्चों को कम करके शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा तथा देश के साधनों और उद्योगों के अभिवर्धन में अधिक धन खर्च करे।^१ इस बात को किसी न किसी रूप में वे बराबर दोहराते रहे।

बड़े-बड़े भवनों के निर्माण तथा अन्य बड़ी-बड़ी योजनाओं की पूर्ति पर बहुतसा धन खर्च हो जाने के कारण जनता की सेवाओं में बाधा न पड़े, इसलिए वे चाहते थे कि लोक-निर्माण (पब्लिक वर्क्स) विभाग की वृहद् निर्माण योजनाओं का खर्चा चालू खाते के बजाय पूँजी खाते में डाला जाय, जिसका भुगतान किसी योजनाबद्ध नियम से हो। उनका कहना था कि “जब किसी कार्य या सेवा से मौजूदा पीढ़ी के साथ-साथ आगामी पीढ़ी को भी लाभ पहुँचता हो, तब उसका भार भी दोनों को बाँटना चाहिए।”^२ अतः वृहद् रचना-कार्यों की लागत को पूँजी खाते में डालना वे न्यायसंगत समझते थे।^३

कर नीति

मालवीयजी कर-नीति का ऐसा पुनर्गठन करना चाहते थे जिससे गरीबों पर से कर का बोझ हलका हो, और समृद्धिशाली व्यक्तियों पर उसका भार अधिक पड़े।^४ वे क्रमिक आयकर (ग्रेजुएटेड इनकमटैक्स) को ‘उत्कृष्ट रूप में न्याय-संगत’ समझते थे।^५ उनका कहना था कि “यह तो स्वयं-सिद्ध सिद्धान्त है कि जो व्यक्ति शासन से सबसे अधिक लाभ उठाता है, उसे उसके संभरण के लिए अपनी आय के अनुपात में सर्वाधिक अंशदान करना चाहिए।”^६

मालवीयजी की माँग थी कि देश के उद्योगों की रक्षा और विकास सरकार की शुल्क नीति का लक्ष्य हो। उन्होंने आयात-शुल्क और उत्पादन-शुल्क की समीक्षा करते हुए उद्योगों के संरक्षण के लिए विदेशी माल पर संरक्षण शुल्क लगाने की माँग की। उन्होंने कहा, “किसी देश के लिए सब समय और सब परिस्थितियों में न संरक्षण और न स्वच्छन्द व्यापार अवश्य ही लाभदायक होता

१ वही, सन् १९१४, जि० ५२, पृ० ७१८-७२३, १०३१-१०३२।

२ वही, मार्च, सन् १९१२, जि० ५०, पृ० ४१८-४१९।

३ वही, फरवरी, सन् १९१७, जि० ५५, पृ० २१२-२१४।

४ वही, मार्च, सन् १९१६, जि० ५४, पृ० २४२, पृ० ५४७।

५ वही, जि० ५४, पृ० २४१।

६ वही, जि० ५४, पृ० २४१-२४२।

है।^१ बदलती परिस्थिति में प्रत्येक प्रगतिशील राष्ट्र को आयात नीति में हेरफेर करना पडा है। आज की परिस्थिति में भारत के देशज उद्योगों के हित में संरक्षण आयात-शुल्क लगाना अनिवार्य है।^२ राष्ट्र के एक बड़े उद्योग की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए उपभोक्ताओं को कुछ काल के लिए उन भौतिक हानियों को सहन करना ही चाहिए, जो संरक्षण-शुल्क लगाने पर कीमतों के बढ़ जाने के कारण उठानी पड़ती है।^३ इन कारणों से, उन्होंने सरकार से प्रार्थना की कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर विदेशी चीनी पर आयात-शुल्क बढ़ा दिया जाय।^४ पर उन्होंने खालो पर ब्रिटिश उपनिवेशों को किसी प्रकार का बढ़ा देने का यह कह कर विरोध किया कि "एक बार निहित स्वार्थों के स्थापित हो जाने पर उन्हें हूर करना कठिन होता है।"^५ उन्होंने सूती कपड़ों पर से उत्पादन-शुल्क उठा लेने की माग की। उन्होंने कहा कि उत्पादन शुल्क बेजा और हानिकार है।^६

भारत के आर्थिक विकास के निमित्त मालवीयजी स्वच्छन्द व्यापार नीति का त्याग तथा सकारात्मक औद्योगिक नीति का अनुसरण आवश्यक समझते थे। उनकी माँग थी कि सरकार देश के औद्योगीकरण पर समुचित ध्यान दे।^७ उनका कहना था कि हमें उद्योग-धंधों में यथा-सम्भव स्वतन्त्र होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और उस समय तक सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए, जब तक हम वे सब चीजें तैयार न कर सकें जिनकी हमें जरूरत है और जिनको तैयार करने के लिए आवश्यक भौतिक साधन देश में मौजूद हैं।^८ वे चाहते थे कि भारत सरकार रेलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले^९, तथा एक स्टेट बैंक खोले, जिसके द्वारा देशी उद्योगों को चलाने में सरकारी कोष का प्रयोग हो।^{१०} उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार कुछ रेलों का, जिनकी वह मालिक है, प्रबन्ध करती है, वैसे ही वह

१ वही, सन् १९११, जि० ४९, पृ० ४१८।

२ वही, जि० ४९, पृ० ४१९। ३ वही, जि० ४९, पृ० ४२१।

४. वही, जि० ४९, पृ० ४२१। ५. वही, जि० ५८, पृ० २६१-६१।

६ वही, सन् १९११, जि० ४९, पृ० ४०५-४०६।

७ वही, सन् १९१५, जि० ५३, पृ० ४००।

८ वही, सन् १९१५, जि० ५३, पृ० ४००।

९ वही, सन् १९१८, जि० ५६, पृ० १०९६-११००।

१० वही, सन् १९१९, जि० ५८, पृ० ४३७।

दूसरी रेलों का भी प्रबन्ध करे।^१ उन्होंने कहा कि कम्पनी के प्रबन्ध की तुलना में राज्य द्वारा प्रबन्ध अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि (१) वह भारत सरकार के अधीन होगा, जिसे जनता के प्रतिनिधि प्रभावित कर सकेंगे; (२) राज्य का प्रबन्ध जनता के हित में होगा, जबकि मुनाफा ही कम्पनी के प्रबन्ध का लक्ष्य है, (३) राज्य द्वारा प्रबन्धित रेलवे में जो नफा होगा, वह जनता के लाभ के लिए या करो के घटाने में खर्च होगा; (४) सरकार विशेषज्ञों को अधिक संख्या में नियुक्त कर सकेगी, (५) सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति में निष्पक्ष होगी, (६) सरकार ऋण को कम व्याज पर जमा कर सकेगी, (७) विभिन्न रेलों के किराये और मालभाड़े में अधिक समन्वयन हो सकेगा, जो भारतीय उद्योगों के हित में होगा, जबकि इस समन्वयन के अभाव के कारण व्यापारियों और उद्योगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, (८) कम्पनियों की विवेकहीन, बेतुकी बातों और हुज्जतों से छुटकारा मिलेगा, और (९) राज्य-प्रबन्ध सस्ता होगा।^२ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा संचालित रेलों में भारतीय यात्रियों और व्यापारियों के साथ अधिक अच्छा व्यवहार होता है।^३ इसी तरह मालवीयजी ने इम्पीरियल बैंक की आलोचना करते हुए आशा व्यक्त की कि स्टेट बैंक भारत की बैंकिंग व्यवस्था का मूलस्तम्भ, देश की वची धनराशि का 'भण्डार', और देश के विभिन्न विभागों, प्रान्तों और क्षेत्रों के कार्यों का पोषण करने का स्रोत होगा, तथा भारत के उद्योगों की वृद्धि में सहायक होगा।^४

मालवीयजी की दृढ़ धारणा थी कि इस देश में "हमारी सहानुभूति का किसानों से अधिक कोई हकदार नहीं।"^५ उनकी दयनीय दशा का निराकरण वे सरकार का परम कर्तव्य समझते थे।^६ उनकी मांग थी कि लगान का बोझ कम किया जाय, उसे २५-३० प्रतिशत घटाया जाय^७, और सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाय। उनके विचार में नहरों की व्यवस्था रेलवे के निर्माण से

१. वही, सन् १९१८, जि० ५६, पृ० १०९६।

२. वही, सन् १९१८, जि० ५६, पृ० १०९८।

३. वही, सन् १९१८, जि० ५६, पृ० १०९८।

४. वही, सन् १९१६, जि० ५८, पृ० ४३७।

५. वही, सन् १९१४, जि० ५२, पृ० ६०३।

६. वही, सन् १९१५, जि० ५३, पृ० ६३७।

७. वही, सन् १९१४, जि० ५२, पृ० ६०३-६०४।

आवेक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि रेल अकाल नहीं रोक सकती, जबकि अच्छी सिंचाई का प्रबन्ध उसके निराकरण का एक साधन है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए कर्जों की अच्छी व्यवस्था, और व्याज की दर का नियन्त्रण भी वे जरूरी समझते थे।^१ वशिष्ठ, मनु, नारद और व्यास की व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया। “इन व्यवस्थापकों की राय में १५ प्रतिशत प्रतिवर्ष ही व्याज की उचित दर है। किन्हीं परिस्थितियों में उसे बढ़ाकर २४ प्रतिशत प्रतिवर्ष किया जा सकता है।”^२ इस समय, उन्होंने कहा, किसानों को बहुत अधिक व्याज देना पड़ता है। जब तक बैंक आदि द्वारा सस्ते कर्जों का प्रबन्ध नहीं होता, तब तक ऊँचे व्याज पर उन्हें कर्जा लेना ही पड़ेगा।^३ उन्होंने समस्या के समाधान के लिए सहकारी कर्जा समितियों के गठन को प्रोत्साहित करना उचित बताया।^४

समाज सुधार

सन् १९१२ में मालवीयजी ने श्री भूपेन्द्रनाथ वसु द्वारा प्रस्तावित ‘विशेष विवाह विधेयक’ का विरोध किया।^५ उनका यह विरोध, जो सनातनधर्मियों की परम्परागत भावनाओं पर आधारित था, प्रगतिशील विधायकों को बुरा लगा। पर इसी वर्ष उन्होंने श्री मानरुजी दादाभाई के ‘स्त्रियों और लड़कियों के संरक्षण विधेयक’ का समर्थन करते हुए देवदासी प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मन्दिरों में लड़कियों को समर्पण किया जाय, इसके पक्ष में कोई व्यक्ति कोई शास्त्रीय प्रमाण पेश नहीं कर सकता। पापमय अपमान का जीवन बिताने के लिए किसी लड़की को समर्पण करने का किसी संरक्षक, माता या पिता को कोई अधिकार नहीं है। विधेयक की दूसरी धाराओं का समर्थन करते हुए मालवीयजी ने कहा कि नावालिंग लड़कियों में अनैतिक व्यापार बन्द होना चाहिए, और सहवास की सम्मति की आयु बढ़ानी चाहिए। प्रस्तावित विधेयक में वेश्याओं द्वारा छोटी लड़कियों को गोद लेने को, तथा पत्नियों के हस्तान्तरण जैसे घृणित व्यवहार को बन्द करने की जो व्यवस्था की गयी थी, उसका भी उन्होंने समर्थन किया।^६

१. वही, सन् १९१७, जि० ५६, पृ० १७४-१७५।

२. वही, सन् १९१७, जि० ५६, पृ० १७५।

३. वही, सन् १९१७, जि० ५६, पृ० १७८।

४. वही, सन् १९१७, जि० ५६, पृ० १७७-१७८।

५. वही, सन् १९१२, जि० ५०, पृ० १७०-१७५।

६. वही, सन् १९१२, जि० ५१, पृ० ९०।

श्री मानकजी दादाभाई ने जो प्रस्ताव दलित वर्गों की दशा सुधारने के निमित्त प्रस्तुत किया था, उस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने उनकी शिक्षा पर समुचित ध्यान देने का सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कहा : “दलित वर्गों के उत्थान का प्रश्न” शिक्षा पर निर्भर है। उन वर्गों में शिक्षा के प्रसार के लिए जो कुछ सरकार कर सकती है, उसे वह करे। सरकार और समाज के स्कूल दलित वर्गों के लिए उतने ही खुले हों, जितने दूसरे वर्गों के लिए।”^१

मालवीयजी ने श्री के० के० चन्दा के इस सशोधन का समर्थन किया कि सरकार पुण्यार्थ निधि और धर्मार्थ निधि पर वास्तविक नियन्त्रण प्रतिष्ठित करे।^२

सितम्बर सन् १९१७ में मालवीयजी ने श्री वी० एन० शर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आग्रह किया कि सरकार मद्यनिषेध की नीति को स्वीकार कर २५-३० वर्ष के अन्दर शराबखोरी को विल्कुल बन्द करा दे। उन्होंने मद्यपान की बढ़ती हुई बुरी आदत पर चिन्ता व्यक्त करते हुए पूर्णरूप से उसका निषेध जनहित के लिए आवश्यक बताया।^३

शिक्षा का विस्तार

मालवीयजी ने सब प्रकार और सब स्तर की शिक्षा के विस्तार की पृष्टि की। वे प्रारम्भिक शिक्षा को सब सुधारों का मूलाधार मानते थे, और चाहते थे कि सरकार सब वर्गों के हित के लिए निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उसकी व्यवस्था करे। सन् १९११ में उन्होंने गोखले द्वारा प्रस्तावित ‘अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा विधेयक’ का समर्थन किया। सन् १९१७ में उन्होंने श्री श्रीनिवास शास्त्री के और सन् १९१८ में श्री वी० एन० शर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए ‘अनिवार्य, निःशुल्क और सर्वमायिक’ प्रारम्भिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की माँग को पुष्ट किया।^४ सन् १९१४ में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर इतना ऊँचा हो कि उसे प्राप्त करने पर विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करने तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा से लाभ उठाने के लिए अधिक योग्य बन सकें। उनका

१. वही, सन् १९१६, जि० ५४, पृ० ३७७-३७९।

२. वही, सन् १९२०, जि० ५८, पृ० ६४२।

३. वही, सितम्बर, सन् १९१७, जि० ५६, पृ० ५४६-५४९।

४. वही, सन् १९१७, जि० ५५, पृ० ४६३-४६६. वही, सन् १९१८, जि० ५६, पृ० ९१०-९११।

सुझाव था कि इंटरमीडियेट कक्ष की दो वर्ष की पढाई की व्यवस्था सब हाई स्कूलों में की जाय, और बी० ए० की शिक्षा की अवधि दो वर्ष के वजाय तीन वर्ष की कर दी जाय ।^१ मालवीयजी चाहते थे कि विश्वविद्यालयों को शैक्षिक संस्थाओं का स्वरूप दिया जाय उन्हें जीवन और ज्योति का केन्द्र बनाया जाय, वहाँ के विद्यार्थी ज्ञान में संसार के दूसरे प्रगतिशील देशों के विद्यार्थियों के समान हों, तथा उत्कृष्ट सम्प्र जीवन बिताने के योग्य बन सकें, भगवद्भक्ति और देश-प्रेम से अपने जीवन को अनुप्राणित कर समाज की सेवा कर सकें । उन्होंने सन् १९१४ में उच्च स्तर की प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त विदेश जानेवाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की मांग की ।^२

अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा

१८ मार्च सन् १९१० को गोपाल कृष्ण गोपाले ने प्रस्ताव किया कि प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें, और उसके सम्बन्ध में सुनिश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को एक कमीशन नियुक्त किया जाय । उन्होंने कहा कि हमारे देश में पिछले चालीस वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार तो अवश्य हुआ है, पर उसकी गति बहुत धीमी है । संसार के बहुत से देशों ने प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बना कर उसे काफी व्यापक बना दिया है । उन्होंने सुझाव दिया कि इस देश में भी कम से कम लड़कों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयत्न किया जाय । उन्होंने कहा कि किसी अर्थ में लड़कियों की शिक्षा लड़कों की शिक्षा से भी अधिक आवश्यक है, पर पूरे देश की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर अनिवार्यता का सिद्धान्त लड़कियों पर लागू न किया जाय । उनका यह भी सुझाव था कि अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क भी हो । उनकी राय में उन्ही क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य बनायी जाय, जहाँ कम से कम ३३ प्रतिशत बालक अब भी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, और जापान की तरह इस देश में भी ६ वर्ष से १० वर्ष तक के लड़कों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाय अर्थात् ४ वर्ष अनिवार्यता का काल हो । उनका सुझाव था कि राज्य के वजाय नगर-पालिकाओं और जिला-पालिकाओं द्वारा उनके निर्णय पर ही किसी भूभाग में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाय, और उसका खर्चा एक तिहाई स्थानीय संस्थाएँ और दो तिहाई सरकार वहन करें, जिसके एक भाग का भुगतान केन्द्रीय

सरकार करे। सरकार के इस आवासन पर कि वह इस पर विचार करेगी, गोखले साहब ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया।

१६ मार्च सन् १९११ को गोखले साहब ने कौंसिल में 'प्रारम्भिक शिक्षा विधेयक' पेश किया। यह विधेयक मूल रूप से उन सिद्धान्तों पर ही आधारित था, जिनका उन्होंने अपने प्रस्ताव पर बोलते हुए उल्लेख किया था। विधेयक को प्रस्तुत करते हुए गोखले साहब ने कहा कि यह विधेयक सरकार को या स्थानीय संस्थाओं को अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने को बाध्य नहीं करता, यह तो केवल स्थानीय संस्थाओं को इजाजत देता है कि यदि वे चाहे तो कतिपय शर्तों के पूरा होने पर प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से अनिवार्यता के सिद्धान्त को लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक लम्बी यात्रा का पहला कदम है।

मालवीयजी ने विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने आलोचकों की शंकाओं और आपत्तियों का उत्तर देते हुए कहा कि अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क होनी ही चाहिए, पर वित्तीय साधनों की कमी के कारण ब्रिटेन, जापान आदि देशों में अनिवार्य शिक्षा को कुछ वर्षों निःशुल्क नहीं बनाया गया था। भारत में भी कुछ समय इसका अनुकरण किया जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा को चालू करने के लिए जनता को नये करो का बोझ अवश्य वहन करना होगा, पर इस पवित्र काम को सम्पन्न करने में उन्हें इसके लिए खुशी खुशी तैयार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आक्षेप कि शिक्षा पाकर बच्चों का दिमाग फिर जायगा एक बेकार बात है। शिक्षा पाकर बच्चों का दिमाग जरूर फिरेगा, पर उसकी दिशा अशिक्षित बालकों की मानसिक प्रवृत्तियों की दिशा से अधिक अच्छी होगी।^१ उन्होंने स्वीकार किया कि कतिपय सामाजिक प्रथाओं के कारण लड़कियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना कठिन जरूर है, पर जिन नगरों में पढ़े की प्रथा चालू नहीं है, और जनता चाहती है कि अनिवार्यता लड़कियों पर लागू की जाय, वहाँ उसे अवश्य लागू कर देना चाहिए। जो सिद्धान्त लड़कों के लिए ठीक समझा जाता है, उसे उचित संरक्षणों के साथ अभिभावकों की राय से लड़कियों पर भी लागू किये जाने की सम्भावना से घबड़ाने का कौन कारण है? उन्होंने कहा : "समाज के आधे भाग को ज्ञान की ज्योति से तथा उस उत्कृष्ट जीवन से, जो ज्ञान द्वारा सम्भव है, वंचित रखना बहुत दुःखदायी बात होगी।"^२

१. वही, सन् १९११, जि० ४२, पृ० ४६८।

२. वही, सन् १९११, जि० ४२, पृ० ४६९।

१८ मार्च सन् १९१२ को गोखले साहब ने प्रस्ताव किया कि प्रारम्भिक शिक्षा विधेयक को विचारार्थ प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय । इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए गोखले साहब ने कहा कि जनता ने विधेयक का स्वागत किया है । देश के अधिकांश उच्चस्तरीय विद्वान् इसके पक्ष में हैं । कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया है । बहुत-सी सार्वजनिक सभाओं, जातीय कान्फ्रेंसों, नगर-पालिकाओं, जिला-पालिकाओं ने भी इसका समर्थन किया है । आलोचकों के आक्षेपों का उत्तर देते हुए गोखले साहब ने कहा कि उनकी राय में शिक्षा के विस्तार से ब्रिटिश शासन को कोई खतरा नहीं है, पर यदि उसकी कोई संभावना हो, तो भी ब्रिटिश सरकार को जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए । मुसलमान आलोचकों को इस बात का उत्तर देते हुए कि अनिवार्य शिक्षा-प्रणाली में उनके बच्चे गैर-मुस्लिम भाषाएँ पढ़ने पर मजबूर होंगे, गोखले साहब ने कहा कि वे अधिनियम में यह व्यवस्था करने को तैयार हैं कि जहाँ पचीस बालक किसी भाषा को बोलते हैं, वहाँ उन्हें उस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जायेगी, और जहाँ उनकी संख्या इससे कम है, वहाँ मुस्लिम समाज को यदि वे चाहें तो अनिवार्यता के बन्धन से मुक्त किया जा सकता है । उन्होंने कहा कि वे समीक्षकों की इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनिवार्य शिक्षा नि शुल्क भी होना चाहिए, और वे विधेयक में इस सशोधन को स्वीकार करने को तैयार हैं । उन्होंने यह भी कहा कि अनिवार्य शिक्षा-पद्धति जहाँ एक ओर अभिभावकों को बाध्य करती है कि वे अपने बच्चों को पढ़ने भेजें, वहाँ स्थानीय संस्थाओं को मजबूर करती है कि शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करें ।

गोखले साहब ने स्वीकार किया कि अनिवार्य शिक्षा-पद्धति से हमारी परेशानियाँ और कमजोरियाँ दूर नहीं हो जायेंगी । फिर भी शिक्षा के विस्तार से जन साधारण का जीवन-स्तर ऊँचा उठेगा, जनता के नैतिक और भौतिक स्तर को ऊँचा उठाने के सरकारी और गैर-सरकारी प्रयत्नों को अधिक सफलता प्राप्त होगी, जनता के लिए शोषण और दमन का मुकाबला करना भी अधिक संभव होगा ।

उन्होंने केन्द्रीय सरकार से अपील की कि यदि प्रान्तीय सरकारें अनिवार्य शिक्षा चालू नहीं करना चाहती, तो वह स्वयं स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से इस कार्य को सम्पन्न करे ।

मालवीयजी का भाषण

इस अवसर पर जहाँ सर गंगाधर चितनवीस, मानकजी दादाभाई, नवाब अब्दुल मजीद, खानबहादुर मिया मुहम्मद शफी आदि ने विधेयक का विरोध

किया, वहाँ मौलाना मजह्रूलहक, मिस्टर मुहम्मद अली जिना, मानवीयजी आदि ने इसका समर्थन किया।

मालवीयजी ने कहा कि राजा और प्रजा दोनों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक बालक और बालिका शिक्षा प्राप्त करे, और यदि इस लक्ष्य को पूरा करना है तो सरकार को यह बात अभिभावकों की इच्छा पर नहीं छोड़नी चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें या न भेजें। बालिकाओं के सम्बन्ध में अवश्य ही अभी कोई अनिवार्यता का नियम नहीं बनाना चाहिए। पर यदि बालकों के लिए भी स्वेच्छा नैतिकता का अवलम्बन किया गया, तो सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकेगा। किसी हद तक शिक्षा अवश्य प्रसारित होगी, पर बहुसंख्यक जनता अशिक्षित ही रह जायेगी। प्रत्येक सम्यक्ष देश ने यह स्वीकार किया है कि अनिवार्य प्रणाली ही एक ऐसा सुगम मार्ग है, जिसके द्वारा सार्वजनिक शिक्षा के लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। इसके बिना किसी देश ने न आज तक सफलता प्राप्त की है, और न वह हमें प्राप्त हो सकती है।^१

अनिवार्यता के नैतिक औचित्य को पुष्ट करते हुए मालवीयजी ने कहा कि प्रत्येक शासन के कुछ विभागों में अनिवार्यता के सिद्धान्त को लागू करना आवश्यक ही होता है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में शान्ति को बनाये रखने के लिए, तथा अपराधों को दवाने के लिए व्यक्तिगत विचारों तथा इच्छाओं पर किसी न किमी प्रकार का अनिवार्य अंकुश लगाना ही पड़ता है। सम्यक्षता की उच्च श्रेणी में तो समाज की उन्नति के लिए भी बहुत से जनोपयोगी मामलों में अनिवार्यता के सिद्धान्त की शरण लेना ही पड़ती है।^२

निर्धेयक की कतिपय धाराओं का विश्लेषण करते हुए मालवीयजी ने कहा कि प्रस्तावित योजना बहुत ही बुद्धिसंगत है, इसमें सुरक्षित उपायों की भरमार है। इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की हानि संभव नहीं है। इस योजना में प्रान्तीय सरकार को इसकी क्षेत्रीय सीमा को निर्धारित करने का, तथा किसी विशिष्ट जाति या जनसमूह को अनिवार्यता से मुक्त करने का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ यह योजना किसी क्षेत्र में तभी लागू हो सकेगी, जब उस क्षेत्र से सम्बन्धित म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इसकी माँग करे। इस तरह यह योजना वही लागू की जा सकेगी, जहाँ जनता का बहुमत इसके पक्ष में है। जहाँ बहुमत से इसका विरोध किया जायगा, वहाँ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता,

१. वही, सन् १९१२, जि० ५०, पृ० ६०८।

२. वही, सन् १९१२, जि० ५०, पृ० ६०४।

और प्रान्तीय सरकार किसी विशिष्ट जाति, सम्प्रदाय या जनसमूह के बहुमत को ध्यान में रखते हुए उसे इससे मुक्त कर सकती है। ये सब शर्तें कम नहीं अधिक हैं, पर यदि सरकार आवश्यक समझे तो कुछ और प्रतिबन्ध भी जोड़े जा सकते हैं।

मालवीयजी ने अपने भाषण में वाइसराय लार्ड हार्डिंग, शिक्षा-सदस्य सर हार्कोर्ट वटलर, तथा विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के विचारों का विश्लेषण करते हुए कहा कि ये सब लक्ष्य की सार्थकता स्वीकार करते हैं, फिर अनिवार्यता के सिद्धान्त को स्वीकार करने से, जिसके बिना लक्ष्य की मिद्धि संभव नहीं, क्यों हिचकते हैं? उन्होंने बताया कि वाइसराय ने अपने एक भाषण में शिक्षा के विस्तार पर हर्ष प्रकट करते हुए कहा है कि वह लक्ष्य अभी बहुत दूर है, जब प्रत्येक बालक या बालिका, नवयुवक और नवयुवती शिक्षा पा सके, जिससे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक, दोनों प्रकार के जीवन में सुन्दरता और पूर्णता आ सके। मालवीयजी ने कहा : "शिक्षा के रावध में भारत सरकार अपने उदार भाव तथा उच्च लक्ष्य को इससे अच्छे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, पर जिस प्रश्न का उत्तर वाछनीय है, वह यह है कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचा जा सकता है?" उन्होंने सर हार्कोर्ट वटलर की इस बात को स्वीकार किया कि प्रचलित प्रणाली द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक उन्नति हुई है, पर कहा : "प्रारम्भिक शिक्षा को स्वेच्छा प्रणाली द्वारा सर्वसाधारण में फैलाने के लिए बहुत अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। गोखले साहब ने जो आकड़े प्रस्तुत किये हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी प्रगति मौजूदा चाल से रही तो प्रत्येक बालक को शिक्षित बनाने में एक सौ पन्द्रह वर्ष और प्रत्येक बालिका को शिक्षित बनाने में छ. सौ पैंसठ वर्ष लगेंगे।"^१

सरकार का विरोध

शिक्षा-सदस्य सर हार्कोर्ट वटलर ने यह तसलीम करते हुए भी कि प्रस्तावित विधेयक उदार है उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और सभी सरकारी और गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों एवं कुछ निर्वाचित सदस्यों ने विधेयक के विरोध में वोट दिये। केवल १३ प्रगतिशील निर्वाचित सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में वोट दिये। इस तरह विधेयक रद्द हो गया। देश के सभी प्रगतिशील राजनीतिज्ञों और समाचार पत्रों ने सरकार की नीति-रीति की कड़ी आलोचना

की, तथा उसकी प्रतिगामिता के लिए ब्रिटिश साम्राज्यशाही और नौकरशाही की कड़े शब्दों में भर्त्सना की। इस विषय पर जनता का रोष और क्षोभ वर्षों बना रहा।

२८ फरवरी सन् १९१७ को श्री श्रीनिवास शास्त्री ने भारत सरकार से संस्तुति की कि वह शीघ्र ही एक ऐसी योजना तैयार और मंजूर करे जिसके जरिये १५ वर्ष में प्रारम्भिक शिक्षा सर्वसाविक, अनिवार्य और निःशुल्क हो जाय, और युद्ध के बाद वह योजना चालू कर दी जाय। मालवीयजी^१ और बहुत से अन्य सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सरकार की ओर से उसका विरोध हुआ। अन्त में २१ भारतीय सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिये, पर ३२ यूरोपियन सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों ने तथा शिक्षा-सदस्य मिस्टर शंकरन नायर और बर्मा के प्रतिनिधि श्री मांग वालू ने प्रस्ताव का विरोध किया। वह नामंजूर हो गया।

मार्च सन् १९१८ में रावबहादुर बी० एन० शर्मा ने प्रस्ताव किया कि 'यदि सारा भूराजस्व प्रान्त को हस्तान्तरित नहीं किया जाता तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सारा खर्चा भारत सरकार दे।' मालवीयजी ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि उस समय से, जबकि सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के महत्त्व को स्वीकार किया है, सरकार के राजस्व और खर्चों में बहुत वृद्धि हुई है, प्रशासन और सेना आदि पर कहीं अधिक धन खर्च किया जा रहा है, पर शिक्षा पर जितना चाहिए उतना खर्च नहीं हो रहा है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नितान्त आवश्यक है।^२ शिक्षा सदस्य मिस्टर शंकरन नायर के इस आक्षेप का कि गोखले साहब का प्रारम्भिक शिक्षा विधेयक दोषपूर्ण था, मालवीयजी ने कहा कि उस विधेयक में कुछ कमियाँ जरूर थी, पर वह तो पहला कदम था। यदि सरकार ने उसे स्वीकार कर उस पर अमल किया होता, तो प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में देश की दशा इस समय कहीं अच्छी होती।^३ सरकार के विरोध के कारण प्रस्ताव नामंजूर हो गया।

१ वही, सन् १९१७, जि० ५५, पृ० ४६३-४६६।

२ वही, सन् १९१८, जि० ५६, पृ० ९१०।

३. वही, जि० ५६, पृ० ९११।

प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा

सन् १९१० में गोखले ने नेटाल के लिए प्रतिज्ञावद्ध कुली भरती करने की प्रथा को बन्द करने का प्रस्ताव किया। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और नेटाल में कुली भेजना बन्द कर दिया गया।

सन् १९१२ में गोखले ने प्रस्ताव किया कि प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा बिल्कुल बन्द कर दी जाय। मालवीयजी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मानवीय और राष्ट्रीय, दोनों दृष्टियों से यह प्रथा निन्दनीय है। इकरारनामे की शर्तों और उसकी दण्ड-व्यवस्था प्रतिज्ञावद्ध श्रमिक की स्वतन्त्रता का अपहरण करती है, उसे दासों जैसा जीवन बिताने को बाध्य करती है। उसे राष्ट्रीय अपमान और नैतिक पतन सहन करना पड़ता है, नाना प्रकार के अत्याचारों को बहन करना पड़ता है।^१

इसके बाद प्रतिज्ञावद्ध कुलियों की दशा की जाँच के लिए भारत सरकार ने मेकलीन और चम्मन लाल की एक कमेटी नियुक्त की। दूसरी तरफ गोखले के अनुरोध पर दीनबन्धु सी० एफ० एडरुज और पियरसन साहब ने फिजी आदि स्थानों का दौरा करके भारतीय प्रवासियों, विशेषतः प्रतिज्ञावद्ध कुलियों की, दयनीय दशा का अध्ययन किया।

२० मार्च सन् १९१६ को गोखले के निधन के बाद मालवीयजी ने प्रस्ताव किया कि "भारतीय कुली प्रथा का अन्त करने के लिए शीघ्र से शीघ्र आवश्यक उपाय काम में लाये जायें।" उन्होंने सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी की कड़ी समीक्षा करते हुए एडरुज कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फिजी में भारतीय कुलियों की दयनीय दशा का विस्तार से विवरण दिया। उन्होंने प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा को समाप्त करने की माँग को पुष्ट करते हुए कहा कि इस प्रथा के द्वारा "साधारण अशिक्षित, अनभिज्ञ तथा निर्धन गामवासी अपने घरदार, सगे-सम्बन्धियों से अलग करके उन दूर स्थानों में जाने को बाध्य किये जाते हैं, जहाँ की दशा से वे एकदम अपरिचित हैं। वहाँ जाकर उन्हें लगातार पाँच वर्ष तक उन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जहाँ वे अपने स्वामियों के मोहताज हैं। उन्हें उन स्वामियों की अधीनता में काम करना पड़ता है, जो उनकी भाषा, नीति-रीति तथा आचार-व्यवहार से अपरिचित हैं।"^२

१ वही, सन् १९१२, जि० ५०, पृ० ३७९-३८२।

२. वही, सन् १९१६, जि० ५४, पृ० ३९८।

मालवीयजी ने कहा कि इस प्रथा में कैसे भारतीय कुलियों को अपनी पुरानी परम्पराओं को तिलाजलि दे इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना होता है, जिसे वे स्वतंत्र अवस्था में कभी करने को तैयार नहीं होते। उन्हें अपने स्वामियों के आदेश पर उस प्रकार के काम करने होते हैं जो उनके धार्मिक विश्वासों के बिल्कुल ही विपरीत होते हैं, और यदि वे ऐसा करने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा की शर्तों के उल्लंघन करने का दोषी ठहराया जाता है।^१

उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा-पत्र 'भ्रामक' है। न तो उसकी शर्तों को समझने की कुलियों में क्षमता है और न उन शर्तों को गौराग औपनिवेशिकों से पालन कराने की कुलियों में शक्ति है। उन्होंने कहा कि यह प्रथा अपने भयंकर परिणामों में दासत्व से किसी तरह कम नहीं है। मनुष्य पर केवल आपत्तिजनक कार्य न करने का, तथा प्रतिज्ञा-भंग करने का ही अभियोग नहीं चलाया जा सकता, बल्कि अपमानजनक शब्द कहने तथा सकेत करने के ऊपर भी अभियोग चलाया जा सकता है।^२

मालवीयजी ने कहा : "कुली प्रथा मनुष्यमात्र के लिए अमिट शाप है", उसे "सुधारा नहीं जा सकता", उसे "समून नष्ट" करना ही होगा।^३ उन्होंने बताया : "जहाँ कहीं कुली प्रथा के अनुसार काम किया गया है, वही वह असफल हुई है। नैटाल में यह प्रथा काम में लायी गयी थी, कुली जीवन केवल पाँच वर्ष का ही रखा गया था, और हम जानते हैं कि यह प्रथा वहाँ किस प्रकार असफल रही। चीनी मजदूर प्रतिज्ञा-बद्ध ठेके में पाँच वर्ष के लिए ट्रान्सवाल भेजे गये थे और वहाँ भी वही दशा रही, और अन्त में वह प्रथा बन्द कर देनी पड़ी। स्ट्रेट सेटिलमेंट में तथा मलाया स्टेट में केवल छ सौ दिन काम करने का समझौता है, किन्तु वहाँ भी कुली प्रथा के स्थान पर स्वतंत्र रूप से मजदूरी चल रही है, और इस परिवर्तन से लाभदायक परिणाम उत्पन्न हुए हैं।"^४

सरकार का आशवासन

भारत सरकार ने भारत-मन्त्री के आदेश पर मालवीयजी के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया कि कुली प्रथा उस समय खत्म कर दी

१. वही, सन् १९१६, जि० ५४, पृ० ३९९।

२. वही, सन् १९१६, जि० ५४, पृ० ३९६-४०५।

३. वही, सन् १९१६, जि० ५४, पृ० ४०५।

४. वही, सन् १९१६, जि० ५४, पृ० ४०५।

जायगी, जब औपनिवेशिक मजदूरो का कोई वैकल्पिक प्रबन्ध कर लें। पर इसके बाद सरकार ने लगभग एक वर्ष तक कुछ नहीं किया, वह केवल आश्वासन देती रही।

२३ सितम्बर सन् १९१६ को मालवीयजी ने सरकार को नोटिस दिया कि वह कौंसिल में प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं। कतिपय सरकारी अफसरो को मालवीयजी की यह बात बुरी लगी। उनकी धारणा थी कि युद्ध के जमाने में किसी विवादास्पद विषय की कौंसिल में चर्चा करना अनुचित है। पर मालवीयजी अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक सभा में कुली प्रथा को खत्म करने की माग की।

गांधीजी ने चेतावनी दी कि यदि यह प्रथा मई सन् १९१७ तक खत्म नहीं की जायेगी, तो इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। जनान्दोलन से घबड़ा कर सरकार ने १ अप्रैल सन् १९१७ को अस्थायी रूप से, और १ जनवरी सन् १९२० को स्थायी रूप से प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा समाप्त कर दी।

संवैधानिक निरंकुशता

मार्ले मिंटो सुधारो के जमाने में भारत सरकार साम्राज्यशाही भावना से अनुप्राणित पुरानी निरंकुशता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए कटिबद्ध रही। लार्ड मिंटो ने नये सुधारो को प्रस्तुत करते हुए अपनी नीति को संवैधानिक निरंकुशता से सम्बोधित किया। वे ब्रिटेन की साम्राज्यशाही की रक्षा के लिए पुरानी दमनकारी व्यवस्था को पर्याप्त नहीं समझते थे, इसलिए वे उग्र राजनीतिक प्रयत्नो को दवाने और कुचलने के लिए जनमत की नितान्त उपेक्षा करते हुए नये दमनकारी कानूनों को कौंसिल द्वारा पास कराने में सलग्न रहे। इनमें प्रेस अधिनियम, विद्रोह सभा विधान, भारतीय संरक्षा नियम, तथा जस्टिस रीलेट कमेटी द्वारा प्रस्तावित विधेयक प्रमुख थे। कौंसिल के अन्य सदस्यो से कही अधिक मानवीयजी ने इन सबका बहुत ही साहस और क्षमता से विरोध किया।

प्रेस विधेयक

सन् १९१० के प्रारम्भ में ही गवर्नर-जनरल और उनकी कार्यपरिपद् ने एक प्रेस विधेयक केन्द्रीय विधान कौंसिल द्वारा पास कराने का निश्चय किया। इसकी कुछ धाराएँ भारत के विधि-सदस्य सर एस० पी० सिन्हा को इतनी

आपत्तिजनक दिखाई दी कि विधेयक को कौंसिल के सामने पेश करने के बजाय अपने पद से इस्तीफा दे देना ही वे उचित समझते थे। जब इसकी सूचना गोखले साहब को मिली, तब उन्होंने इस्तीफा न देने का, तथा उसमें संशोधन करने के लिए प्रयत्न करने का सिन्हा साहब को मशवरा दिया। काफी बहस के बाद वाइसराय के आग्रह पर उनकी कार्यपरिपद् ने प्रेस विधेयक में सिन्हा द्वारा प्रस्तुत ये संशोधन स्वीकार कर लिये कि (१) पुराने मुद्रणालयों से जमानत नहीं मांगी जायेगी, (२) नया कानून समान रूप से हिन्दुस्तानी और एंग्लो इंडियन मुद्रणालयों पर लागू होगा, (३) उसमें हाईकोर्ट को अपील करने की व्यवस्था होगी। इसके बाद गोखले साहब के कहने पर सिन्हा साहब संशोधित प्रेस विधेयक को विधान कौंसिल में पेश करने को राजी हो गये, और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया।

गोखले साहब ने परिस्थिति की गंभीरता को ओर मालवीयजी का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें सलाह दी कि वे कौंसिल में प्रेस विधेयक का विरोध न करें। इस पर मालवीयजी ने गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करने के बाद गोखले साहब को सूचित किया कि वे अपनी अन्तरात्मा के अनुकूल अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, चाहे उसके कारण उनके सम्बन्ध में सरकार को कुछ भी धारणा बन जाय।

८ फरवरी सन् १९१० को मालवीयजी ने प्रेस विधेयक का डट कर विरोध किया। उन्होंने कहा कि केवल तीन चार दिन की सूचना के बाद जल्दी में विधेयक को पास करना अनुचित है। जिन सस्याओं ने इसके विरोध में तार भेजे हैं, उन्हें विस्तार के साथ अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलना ही चाहिए।^१ उन्होंने कहा कि यह विधान गैरजरूरी है, क्योंकि प्रचलित फौजदारी दण्डविधान द्वारा ही समाचारपत्रों के राजविद्रोहात्मक लेखों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय समाचार पत्रों का व्यवहार काफी सन्तुलित रहा है। सन् १९०६ और सन् १९०७ में कुछ समाचारपत्रों ने 'विरोधपूर्ण कटु वचनों का प्रयोग' जरूर किया था, पर इसका मूल कारण लार्ड कर्जन की नीति, तथा "सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार तथा उनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग" ही था।^२ इसके बाद दशा में काफी सुधार हुआ है। लगभग दो वर्ष हुए वाइसराय ने स्वयं स्वीकार किया था कि इस देश के अनेक पत्र अपना कार्य संचालन उत्तम रीति से कर रहे हैं, और उनमें से

१. वही, फरवरी, सन् १९१०, जि० ४८, पृ० १२२-१२३।

२. वही, सन् १९१०, जि० ४८, पृ० १३०।

बहुत कम राजद्रोही है।^१ उन्होंने कहा . “देश के करीब आठ सौ समाचारपत्रों में से केवल छः पत्रों द्वारा किसी एक अपराध को दुहराने से यह सिद्ध नहीं होता कि वर्तमान व्यवस्था में राजद्रोह को या राजद्रोह फैलाने के प्रयत्न को सजा देने का कोई प्रबन्ध नहीं है”, और “उसे दवाने के लिए सब समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अपहरण करना, उन पर विशेष प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।”^२ समाज में कुछ लोग अपराधी होते ही हैं, अर्थात् अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते ही हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि इस कारण से सबके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाय, और निर्दोषों को भी सताया जाय।^३ सब नये समाचार पत्रों को जमानत देने के लिए बाध्य करना किसी तरह भी न्यायसंगत नहीं है। अपराध करने से पहले ही नये समाचारपत्रों के सभी भावी सम्पादकों और संचालकों को राजद्रोही मान कर उनसे भविष्य में सद् व्यवहार के लिए जमानत तलब करना कैसे न्यायोचित समझा जा सकता है ?^४

प्रेस बिल की कतिपय धाराओं की समीक्षा करते हुए मालवीयजी ने कहा कि न्यायालयों के अधिकारों को प्रशासनिक अधिकारियों के सुपुर्द करना सर्वथा अनुचित है। प्रान्तीय सरकारें भी गलती कर सकती और करती रही हैं।^५ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक तो लार्ड लिटन के बर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट से भी कड़ा है। जहाँ सन् १८७८ का अधिनियम प्रान्तीय सरकार को प्रारम्भ में चेतावनी देने का ही अधिकार देना था, वहाँ प्रस्तावित विधेयक प्रान्तीय सरकार को प्रारम्भ में ही समाचार पत्र से जमानत माँग लेने का अधिकार दे देता है।^६

उन्होंने कहा कि जनता के हृदय में इस बात का भ्रम पैदा हो गया है कि न्याययुक्त आलोचना का अधिकार, जिससे जनता का हर प्रकार का लाभ ही है, उससे छीना जा रहा है, और इसलिए यदि यह बिल पास हो गया तो देश में एक नये असन्तोष का प्रसार होगा।^७

१. वही, सन् १९१०, जि० ४८, पृ० १२९।

२. वही, सन् १९१०, जि० ४८, पृ० १२४।

३. वही, सन् १९१०, जि० ४८, पृ० १३२।

४. वही, सन् १९१०, जि० ४८, पृ० १३२।

५. वही, सन् १९१०, जि० ४८, पृ० १३३।

६. वही, सन् १९१०, जि० ४८, पृ० १३२।

७. वही, सन् १९१०, जि० ४८, पृ० १३१, १३३।

अन्त में मालवीयजी ने सरकार से अनुरोध किया कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाय, और यदि यह सम्भव न हो तो पुनः विचार के लिए इसे स्थगित कर दिया जाय ।^१

चूँकि गोखले साहब ने सिन्हा से वायदा किया था कि वे प्रेस बिल का विरोध नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने उसमें निहित सिद्धान्त का विरोध नहीं किया और विधेयक में कुछ संशोधन ही पेश किये । उनका सुझाव था कि सब नये मुद्रणालयों से जमानत नहीं माँगी जाय, केवल नये मुद्रणालयों के उन प्रशासकों और संचालकों से ही जमानत माँगी जाय जिनके सम्बंध में सरकार को किन्हीं ठोस तथ्यों के आधार पर सन्देह हो । उनका यह भी सुझाव था कि जमानत की रकम पाँच हजार रुपये के बजाय दो हजार रुपये निश्चित की जाय, और नये कानून को केवल तीन वर्ष तक चालू रखा जाय । सरकार ने इनमें से किसी संशोधन को भी स्वीकार नहीं किया । उनका यह संशोधन कि नये अधिनियम की अवधि केवल तीन वर्ष हो १६ वोटों के मुकाबले में ४२ वोटों से रद्द हो गया । जिन विधायकों ने संशोधन के विरोध में राय दी, उनमें साठ हिन्दुस्तानी, बाकी सब यूरोपियन थे ।^२

समाचार पत्रों ने प्रेस ऐक्ट की ओर उसके साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले की कड़ी आलोचना की, और दूसरी ओर मालवीयजी की भूरि-भूरि प्रशंसा की । मालवीयजी को समाचार पत्रों द्वारा गोखले की निन्दा बुरी लगी । वे गोखले को 'कायर' या 'सरकार-परस्त' कहना बहुत ही अनुचित समझते थे । वास्तव में गोखले और सिन्हा साहब दोनों ही प्रेस बिल पसन्द नहीं करते थे, पर गोखले को शंका थी कि यदि गवर्नर-जनरल की कार्यपरिपद का पहला भारतीय सदस्य वर्ष भर के अन्दर ही किसी राजनीतिक प्रश्न पर इस्तीफा दे देगा, तो इसका देश की राजनीतिक प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का खूब कडा हो जायगा । इसीलिए उन्होंने सिन्हा साहब को मशवरा दिया था कि वे इस्तीफा न दें और उनसे वायदा किया था कि वे कौंसिल में प्रेस बिल के विरुद्ध वोट नहीं देंगे । संभवतः उन्हें आशा थी कि सरकार नये कानून का दुरुपयोग नहीं करेगी । पर ६ अगस्त १९१० को गोखले साहब ने बहुत ही संतप्त हृदय से कहा कि जिस सावधानी से प्रेस कानून लागू किया जाना चाहिए था, उस सावधानी से अधिकांश प्रान्तीय सरकारों ने काम नहीं किया ।

१. वही, सन् १९१०, जि० ४८, पृ० १३१-१३२ ।

२. वही, सन् १९१०, जि० ४८, पृ० १७२-१७३ ।

कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जजो ने अपने फैसलो में स्वीकार किया कि प्रेस ऐक्ट की कतिपय धाराओं ने प्रकाशको तथा मुद्रणालयों के रखने-वाले व्यक्तियों पर गम्भीर नियंत्रणताएँ लगा दी हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज स्टीफन ने तो कहा कि इस ऐक्ट के अन्दर सरकार के अधिकार इतने व्यापक हैं कि सरकार चोरो और डकैतों के वर्ग को आलोचना और निन्दा करनेवाले समाचार पत्र को भी बन्द करने का आदेश दे सकती है।

विद्रोह सभा विधेयक

सन् १९१० में ही सरकार ने निश्चय किया कि सन् १९०७ के विद्रोह सभा अध्यादेश को पाँच मास तक चालू रखने के लिए कौंसिल में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया जाय। ६ अगस्त सन् १९१० को मालवीयजीने इस विधेयक के विरोध में एक तगड़ा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यह असाधारण व्यवस्था सन् १९०७ की असाधारण परिस्थिति में चालू की गयी थी, और अब जब कि सन् १९०९ के नये राजनीतिक सुधारों के कारण स्थिति बदल गयी है, जनता में सरकार के प्रति श्रद्धा पैदा हुई है, इस प्रकार के दमनकारी कानून का अन्त हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्रान्तिकारी पड़्यन्त्र, जो गुप्त रीति से होते हैं, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबन्ध लगा कर खत्म नहीं किये जा सकते। गत तीन वर्षों में इस विधान से क्रान्तिकारी दलों के कार्यों में तनिक भी रुकावट नहीं पड़ी है। अतएव यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विधान इस मर्ज की दवा है। उन्होंने कहा कि वे वाइसराय के इस विचार से सहमत हैं कि “ब्रिटिश सरकार के प्रति जो दुर्भाव व्याप्त है, वह पारस्परिक समझौते तथा मतभेद को हटा देने से दूर हो सकता है”, पर इस समझौते के लिए तो पारस्परिक स्वतंत्र बहुस द्वारा सार्वजनिक मतभेदों का निवारण करना होगा। जब कलकत्ता, नागपुर तथा पूर्वी बंगाल की पचास हजार व्यक्तियों की बड़ी-बड़ी सभाएँ भी साधारण १४४ धारा के कानून से शान्ति के साथ हटायी जा चुकी हैं, तब इस असाधारण विद्रोह सभा विधान की कौन जरूरत है? उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा इसका दुरुपयोग हो सकता है, और गोखले साहब ने ठीक ही कहा है कि “किसी भी दमन विधान का जब दुरुपयोग किया जाता है तब उससे वह बुराई अधिक फैलती है जिसके सुधारने के लिए उसका निर्माण होता है।”^१

१. प्रोसीडिंग—गवर्नर-जनरल की कौंसिल (विधान), जि० ४९, पृ० ५७-६२, ५५०-५५१।

गोखले साहब ने, जिन्होंने सन् १९०७ में ही डाक्टर रासबिहारी घोष के साथ विद्रोह सभा विधेयक का विरोध किया था, इस अवसर पर भी उसका डटकर विरोध किया। मालवीयजी की तरह उनकी भी धारणा थी कि इस दमनकारी कानून को मंजूर करना जरूरी नहीं है। उन्हें सन्देह था कि सरकार कुछ महीने बाद इस कानून को स्थायी बनाने की कोशिश करेगी। उनका यह अनुमान सही साबित हुआ।

मार्च सन् १९११ में दूसरा 'विद्रोह सभा विधेयक' कौंसिल में प्रस्तावित किया गया। यह विधेयक सन् १९०७ और सन् १९१० के अधिनियमों से कम कड़ा था। बहुत-सी कड़ी बातें निकाल दी गयी थी। फिर भी गोखले, मालवीय आदि प्रगतिशील सदस्यों ने इसे 'अनावश्यक' और मूलरूप से 'दमनकारी' बताते हुए इसका विरोध किया।^१ गोखले ने कहा कि उन्हें डर है कि जिस तरह प्रान्तीय सरकारों ने प्रेस ऐक्ट तथा पुराने विद्रोह सभा अधिनियम का दुरुपयोग किया है, इसी तरह इस नये कानून का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। जनता की स्वतंत्रता का निरर्थक अपहरण हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे निरपेक्ष सिद्धान्त की सार्थकता पूर्ण रूप से नहीं मानते, और स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक सिद्धान्त का प्रयोग परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। उसका रूप परिस्थिति द्वारा नियंत्रित होता है। पर यह बात मानव स्वतंत्रता की तरह राजभक्ति के सिद्धान्त पर भी लागू है।^२ उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह विधेयक वापस ले ले, पर सरकार कहाँ सुननेवाली थी? उसने मनोनीत सदस्यों के बल पर उसे मंजूर करा लिया।

भारत रक्षा विधेयक

सन् १९१४ के विश्वयुद्ध के शुरू होने के कुछ समय बाद सन् १९१५ में सरकार ने कौंसिल में भारत रक्षा बिल (डिफेन्स आफ इंडिया बिल) पेश किया। मालवीयजी, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी आदि ने मानव-स्वतंत्रता की रक्षा के निमित्त विधेयक की कतिपय धाराओं का विरोध करना आवश्यक समझा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि युद्ध की विपम परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए विशेष अधिकारों का प्रयोग किसी हद तक अनिवार्य है। फिर भी

१. वही, सन् १९११, जि० ४९, पृ० ५५९; ५५०-५५१।

२. वही, सन् १९११, जि० ४९, पृ० ५५९-५६३।

उनके विचार में कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यथासंभव रक्षा भी जरूरी है। मालवीयजी ने राष्ट्रविरोधी तत्त्वों की जल्दी से गिरफ्तारी का समर्थन करते हुए माग की कि साधारण न्यायपद्धति और कानून द्वारा ही उनके अपराधों की जांच की जानी चाहिए।^१ उन्होंने इस विधेयक की धारा ३ और ६ का विरोध करते हुए कहा कि इसके जरिए तो वे सभी साधारण अपराध भी नयी व्यवस्था के अन्दर आ जाते हैं, जिनपर साधारण दण्ड व्यवस्था द्वारा मौत, कालापानी या सात वर्ष की सजा दी जा सकती है।^२ विधेयक की धारा ३ की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जज के कम स्तर का कोई व्यक्ति स्पेशल ट्रायुनल का जज न बनाया जाय, तथा उसे मौत की सजा देने का अधिकार न हो।^३ उन्होंने कहा कि युद्धबन्दी नजरबन्द कर दिया जाता है, तब क्या विचाराधीन अपराधियों को नजरबन्दी या कालापानी की सजा देने से सामाजिक सुरक्षा और न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा? मौत की सजा में अटल अन्याय का भय है, और यह भय तब बढ़ जाता है, जब मुकदमे की जांच सरसरी ढंग की हो।^४

रौलेट बिल

सन् १९१९ में मालवीयजी ने बहुत से दूसरे गैर-सरकारी सदस्यों के साथ फौजदारी कानून सशोधन विधेयक का, जो 'रौलेट बिल' के नाम से प्रसिद्ध है, डटकर विरोध किया, और जब सरकार ने इस विरोध की उपेक्षा करते हुए सरकारी और गैर-सरकारी मनोनीत सदस्यों की मदद से उसे कौंसिल में पास करा लिया, तब उन्होंने अन्य तीन सदस्यों के साथ कौंसिल से इस्तीफा दे दिया। अपने मतदाताओं का पुनः विश्वास प्राप्त कर वे कौंसिल में वापस आये, और उन्होंने वहाँ डट कर बड़ी दक्षता के साथ ओडायर और डायर के अत्याचारों के लिए भारत सरकार और पंजाब सरकार की भर्त्सना की, घटनाओं की जांच के लिए शाही कमीशन की माग की। उन्होंने वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड के इस्तीफे की माग की, तथा क्षमा विधेयक का डट कर विरोध किया।^५

१. वही, सन् १९१५, जि० ५३, पृ० ५०१।

२. वही, सन् १९१५, जि० ५३, पृ० ५००, ५०४, ५१२।

३. वही, सन् १९१५, जि० ५३, पृ० ५०३।

४. वही, सन् १९१५, जि० ५३, पृ० ४९२, ४९८।

५. विस्तृत विवरण के लिए अध्याय १२ देखिये।

राजनीतिक सुधार

दिसम्बर सन् १९१० में प्रयाग में तीसरी बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। सर विलियम वेडर्नबर्न ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस में सम्मिलित हो राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग लें, और आशा व्यक्त की कि गरमदलीय नेता कांग्रेस के पुराने नेताओं के साथ मिलकर काम करेंगे।

कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि वह विधान संवंधी नियमों को इस प्रकार शीघ्र ही बदले, जिससे मताधिकार के संवंध में जनता के विभिन्न अंगों में असंगत भेद, तथा उम्मीदवारों की योग्यताओं और चुनाव से संबंधित अन्य अनुचित प्रतिबन्ध दूर हो। इस प्रस्ताव को श्री सतीशचन्द्र वनर्जी ने प्रस्तावित किया, डाक्टर तेजबहादुर सप्रू ने इसका अनुमोदन और नवाब सादिक अली खाँ ने समर्थन किया। जिना साहब ने प्रस्ताव किया कि पृथक् निर्वाचन की पद्धति स्थानीय निकायों में चालू न की जाय। मिस्टर मजहबूलहक ने इसका अनुमोदन और सैयद हसन इमाम साहब ने समर्थन किया। कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि सर विलियम वेडर्नबर्न की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल वाइसराय से मिले। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों के अतिरिक्त सर्व श्री भूपेन्द्र नाथ वसु, ग्राम्बिका चरण मजूमदार, विशन नारायण दत्त, तथा नवाब सादिक अली खाँ, मिस्टर जिना और सैयद हसन इमाम आदि चौदह सज्जन शिष्टमंडल के सदस्य चुने गये।

शिष्टमंडल ने अपने निवेदनपत्र में ग्रामीण जनता की गरीबी और दूसरे आवश्यक प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए वाइसराय से प्रार्थना की कि 'अनुभव की रोशनी में, कौंसिल सम्बन्धी नियम (रैगुलेशन्स) जिसकी आलोचना हुई है, बदले जाये।' इसके जवाब में वाइसराय ने कहा कि 'इस शिष्टमंडल के बहुत से सदस्य मेरी विधान कौंसिल या प्रान्तीय विधान कौंसिलों के सदस्य हैं, जिनके माध्यम से ये सब प्रश्न प्रान्तीय और इम्पीरियल विधान कौंसिलों के सामने प्रस्तुत किये जा सकते हैं।'।

इसके बाद २४ जनवरी सन् १९११ को मालवीयजी ने केन्द्रीय विधान कौंसिल में प्रस्ताव किया कि सरकार गैर-सरकारी और सरकारी सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त करे जो इस बात पर विचार करके रिपोर्ट दे कि "सम्राट् की प्रजा के विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार में असमानता के कारण, तथा कौंसिलों में चुनाव चाहनेवाले उम्मीदवारों के चयन पर लगायी गयी कतिपय अयोग्यताओं और

प्रतिबन्धों के कारण जो न्यायसंगत शिकायतें हैं उन्हें दूर करने के लिए, तथा प्रान्तीय कौंसिलों में 'गैरसरकारी बहुमत की व्यवस्था को व्यवहार में अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए' इंडियन कौंसिल एक्ट सन् १९०९ के अन्तर्गत बने रेगुलेशन्स में क्या परिवर्तन किये जायें।"¹

इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मालवीयजी ने बहुत से तथ्यों और तर्कों द्वारा सिद्ध किया कि वे विधान कौंसिलें, जिनसे ज्ञानसम्पन्न प्रगतिशील भारतीय जनमत पेश करने की आशा की जाती है, किस तरह विशेष हितों और साम्प्रदायिक हितों की गड़ बना दी गयी है। उन्होंने राजाओं, जमींदारों और मुसलमानों के अत्यधिक प्रतिनिधित्व की निन्दा करते हुए मुस्लिम समुदाय के विशेष राजनीतिक महत्त्व के विचार की कड़ी समीक्षा की। उन्होंने कहा : "कोई ऐसा कारण नहीं जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हिन्दू, सिक्ख, ईसाई, पारसी या भारत में रहनेवाली किसी दूसरी जमायत से मुसलमान राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।"²

मालवीयजी के कतिपय तर्कों का उत्तर देते हुए नवाब अब्दुल मजीद खा ने कहा : "सौ डेढ़ सौ वर्ष हुए जब मुसलमान इस देश के शासक थे, और हिन्दू इस देश का प्रजा वर्ग था। यह कैसे संभव है कि वे लोग जिन्होंने प्रभुसत्ता खो दी है, उन लोगों की तुलना में किसी राजनीतिक महत्त्व के न समझें जायें जो सैकड़ों वर्ष उनकी प्रजा रहे हों?"³

श्री भूपेन्द्र नाथ वसु ने मालवीयजी का पूरी तौर पर समर्थन किया। महाराजा बर्दवान ने पृथक् निर्वाचन पद्धति का समर्थन किया। गोखले साहब ने इस विवाद को कौंसिल में खड़ा करने पर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि यद्यपि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, पर इस कारण उनके राजनीतिक महत्त्व को भुलाया नहीं जा सकता, और उस देश में जहाँ हिन्दुओं की भारी बहुसंख्या है, मुसलमानों के लिए किसी विशेष व्यवस्था द्वारा प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध अनिवार्य है। उन्होंने अपने ढंग से जमींदारी के प्रतिनिधित्व की भी पुष्टि की। गोखले साहब ने स्वीकार किया कि कौंसिल सम्बन्धी रेगुलेशन्स में मुसलमानों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी है जिसके लिए भारत सरकार के बजाय

१. वही, जनवरी सन् १९११, जि० ४९, पृ० १३३।

२. वही, सन् १९११, जि० ४९, पृ० १३३-१३८।

३. वही, सन् १९११, जि० ४९, पृ० १३९।

भारतमन्त्री मुख्यरूप से जिम्मेदार हैं। पर दो वर्ष के अन्दर, उन्होंने कहा, उसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने स्वीकार किया कि उम्मीदवारों की क्षमता आदि से सम्बन्धित बहुत से नियम अनुचित हैं, और उन्हें बदलना जरूरी है। उन्होंने मालवीयजी की इस माँग का भी समर्थन किया कि प्रान्तीय कौंसिलों में निर्वाचित सदस्यों का, तथा केन्द्रीय कौंसिल में गैरसरकारी सदस्यों का बहुमत हो। अन्त में गोखले साहब ने मालवीयजी से अनुरोध किया कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।^१

मजहरुलहक साहब ने प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वह और उनके नेता सैयद अली इमाम संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में हैं और समझते हैं कि संयुक्त निर्वाचन द्वारा देश का उद्धार संभव है।^२ उमर हयात खा, शमशुल हुदा आदि मुसलमान सदस्यों ने, तथा यूरोपियन सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया।

सरकार की ओर से लारेन्स जनकिन ने मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन तथा अधिक प्रतिनिधित्व का आश्वासन देते हुए कहा कि वे सब तरफ से सुझाव सुनने को तैयार हैं। प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

सन् १९१२ के शरद सत्र के लिए मालवीयजी ने कौंसिल के रेगुलेशन्स के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का नोटिस दिया। उस प्रस्ताव में सत्सुति की गयी थी कि सरकार सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त करे जो सुझाव दे कि रेगुलेशन्स में क्या परिवर्तन किये जायें जिससे (१) मुसलमानों और जमींदारों के लिए सुरक्षित स्थानों की तरह केन्द्रीय और प्रान्तीय कौंसिलों के सामान्य गैरसरकारी निर्वाचित स्थान भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा पूरित किये जायें, (२) मतदान की अर्हता उतनी ही उदार हो जितनी वह मुसलमान मतदाताओं के सम्बन्ध में है, (३) जिन्हें विशेष सुरक्षित स्थानों के लिए मत देने का अधिकार है, उन्हें सामान्य चुनाव क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी एक चुनाव में ही मतदान करने का अधिकार हो।

मालवीयजी का यह प्रस्ताव सर्वथा न्यायसंगत, तर्कसंगत और प्रगतिशील था, पर प्रतिक्रियावादी नौकरशाही इस देश में लोकतान्त्रिक मताधिकार प्रणाली को चालू करने के पक्ष में नहीं थी। इसलिए उसकी सलाह पर वाइसराय ने इस प्रस्ताव को कौंसिल में पेश करने की इजाजत नहीं दी। वाइसराय का यह

१. वही, सन् १९११, जि० ४९, पृ० १४६-१४८।

२. वही, सन् १९११, जि० ४९, पृ० १४९।

कार्य उनकी अपनी जनवरी सन् १९११ की इस राय के विपरीत था कि कौंसिल के गैरसरकारी सदस्य मतदान सम्बन्धी रेगुलेशन्स पर कौंसिलो में विचार कर सकते हैं ।

मालवीयजी ने कौंसिलो के अधिवेशनों में संवैधानिक और प्रशासनिक विषयो की चर्चा जारी रखी । उन्होने सन् १९११ में श्री सच्चिदानन्द सिन्हा द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि युक्त प्रान्त में एकजीक्यूटिव कौंसिल गठित की जाय ।^१ उन्होने २२ फरवरी सन् १९१७ को डाक्टर तेजबहादुर सप्रू के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि युक्तप्रान्त में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के वजाय वगर्नर नियुक्त किया जाय और उसकी एकजीक्यूटिव कौंसिल में भारतीय सदस्यो की संख्या दूसरे सदस्यो के बराबर हो ।^२ सन् १९१३ में उन्होने इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि न्यायालयो को प्रशासनिक अधिकारियो से अलग रखा जाय, ताकि देश में शुद्ध न्याय-व्यवस्था प्रतिष्ठित हो सके, और जनता को निष्पक्ष न्याय मिल सके ।^३

सन् १९१४ में मालवीयजी ने भारत मन्त्रो की कौंसिल के किसी एक सदस्य को भारत की वित्त-नीति के निरीक्षण का अधिकार दिये जाने के सुझाव का विरोध करते हुए भारत-मन्त्री और उसकी कौंसिल के अधिकारो को सीमित करना आवश्यक बताया । उन्होने सुझाव दिया कि भारतमन्त्री की कौंसिल को इस तरह गठित किया जाय कि उसके नौ सदस्यो में से तीन भारत की केन्द्रीय और और प्रान्तीय विधान कौंसिलो के गैर-सरकारी सदस्यो द्वारा निर्वाचित हो, तीन सदस्य वे अफसर हो जिन्होने भारत में कम से कम दस वर्ष सेवा की हो, और तीन सदस्य ऐसे योग्य सार्वजनिक कार्यकर्ता हो जिनका भारत सरकार से कोई सम्बन्ध न हो । इस कौंसिल की तीन उपसमितिया हो, जिनमें से हरेक में एक भारतीय सदस्य हो ।^४

सन् १९१६ में 'इंडियन डिफेन्स फोर्स विल' और बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने माग की कि फौज के सब पदो के लिए भारतीयो और यूरोपियनो की पोजीशन समान हो । भारतीयो को अपनी योग्यता के आधार पर फौज में ऊँचा पद प्राप्त करने का अधिकार हो, प्रजातीय विभेद

१. वही, सन् १९११, जि० ४९, पृ० १६०-१६१ ।

२. वही, सन् १९१७, जि० ५५, पृ० ३९८-३९९ ।

३. वही, सन् १९१३, जि० ५१, पृ० ३९०-३९२ ।

४. वही, सन् १९१४, जि० ५२, पृ० १०२९ ।

खत्म किये जायें। उन्होंने कहा कि यह अजीब बात है कि सैनिक प्रशिक्षण के लिए भारत में स्थापित कालेज में भारतीयों को दाखिल हो न किया जाय।^१

सन् १९१६ में मालवीयजी तथा अन्य १८ निर्वाचित सदस्यों ने मिलकर राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में एक मेमोरंडम तैयार किया। दिसम्बर सन् १९१६ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर इस मेमोरंडम में कुछ परिवर्तन करके एक योजना तैयार की जो 'कांग्रेस-लीग स्कीम' के नाम से प्रसिद्ध हुई।^२

२३ मार्च सन् १९१७ को बजट पर बोलते हुए मालवीयजी ने मेमोरंडम तथा कांग्रेस-लीग योजना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माग की कि वह शीघ्र ही इनके सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया तथा राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करे, ताकि इस सत्र में ही कौंसिल उस पर विचार करके अपनी राय व्यक्त कर सके। उन्होंने कहा : "युद्ध के बाद ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जिनसे वर्तमान और भविष्य में भारत के हितों की रक्षा हो सके, जिनसे उसकी जनता की कामना पूरी हो सके, और वह अपने देश के उचित शासन-प्रबंध में समर्थ हो सके।" मालवीयजी ने बहुत ही दुःख के साथ यह स्वीकार करते हुए कि "हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि हमारे सभी महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न भारत-मन्त्री की निश्चित नीति के अनुसार तय किये जाते हैं और वे ही भारत के वास्तविक शासन-कर्ता हैं", उन्होंने माग की कि भारत को आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो, विधान कौंसिल को यह निर्णय करने की स्वतंत्रता हो कि कौन-कौन से टैक्स लगाये जायें और उनसे प्राप्त धन को किस प्रकार व्यय किया जाय"। उन्होंने आशा व्यक्त की कि "युद्ध के बाद भारत सरकार का दफ्तर इंग्लैंड से हटाकर भारत में ही पूर्ण रूप से स्थापित किया जायेगा।"^३

इंस्टीगटन कमीशन

१७ मार्च सन् १९११ को श्री सुबाराओ पन्तलू ने भारतीय विधान कौंसिल में प्रस्ताव किया कि सिविल प्रशासन के उच्च पदों पर भारतीयों की अधिक विस्तृत नियुक्ति के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया जाय। २१ अगस्त सन् १९१२ को लार्ड इंस्टीगटन की अध्यक्षता में पब्लिक

१. वही, सन् १९१६, जि० ५५, पृ० ४१४, ३४३।

२. विस्तृत विवरण अध्याय ११ में देखिये।

३. वही, सन् १९१७, जि० ५५, पृ० ८०४-८०७।

सर्विस कमीशन मुकर्रर किया गया । उसके अन्य सदस्यों में आठ यूरोपियन और तीन भारतीय—श्री गोपाल कृष्ण गोखले, सर अब्दुर रहीम और श्री एम० बी० चाओला-थे । कमीशन ने अगस्त सन् १९१५ में अपनी रिपोर्ट तैयार की जो जनवरी सन् १९१७ में प्रकाशित की गयी । कमीशन का निष्कर्ष था कि चूँकि भारत के विभिन्न प्रान्तों और समुदायों के शिक्षा के स्तर में काफी अन्तर है, और भारत के स्कूलों में चरित्र के गठन और विकास पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना ब्रिटेन के स्कूल कालेजों में दिया जाता है, इसलिए इंडियन सिविल सर्विस में भरती के लिए भारत में प्रतियोगिता परीक्षा न शुरू की जाय । उसने संस्तुति की कि इंडियन सिविल सर्विस के लिए ७५ प्रतिशत और इंडियन पुलिस सर्विस के लिए ९० प्रतिशत अफसरों की भरती यूरोप में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाय, और बाकी स्थानों पर भारत में नामजदगी के जरिए नियुक्तियाँ की जायें । उसने यह भी संस्तुति की कि प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थियों की अधिकतम आयु २४ वर्ष से घटाकर १९ वर्ष कर दी जाय । उसने यह भी संस्तुति की कि विभिन्न लोक सेवाओं के वेतनस्तर को ऊँचा उठाया जाय अर्थात् उन्हें अधिक वेतन, भत्ते और पेंशनें दी जायें । कमीशन के भारतीय सदस्यों को कमीशन की ये संस्तुतियाँ ठीक नहीं जँची । सर अब्दुर रहीम ने गोखले साहब की राय और सहमति से एक नोट तैयार किया जिसमें उन्होंने यूरोपियन अफसरों की प्रधानता के सिद्धान्त को चुनौती देते हुए लिखा कि स्पष्ट आवश्यकता की हालत में ही यूरोपियनों को भारत की लोक सेवाओं में नियुक्त करना उचित समझा जा सकता है । भारतीय सदस्यों ने वेतन की वृद्धि की संस्तुति का भी विरोध किया । उन्होंने कहा कि भारत में वेतन-स्तर ब्रिटेन, लका आदि से इस समय ही ऊँचा है, और इसलिए, उनकी राय में, वेतन, भत्ते और पेंशनो में वृद्धि का सुझाव ठीक नहीं है ।

भारतीयों को कमीशन की रिपोर्ट ठीक नहीं जँची । उन्होंने उसका डटकर विरोध किया । २० मार्च सन् १९१७ को मालवीयजी ने भारतीय विधान कौंसिल में एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार से संस्तुति की कि जब तक विधान कौंसिल अपनी राय व्यक्त न करे, तब तक इस्लिगटन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न की जाय । उन्होंने कहा कि कमीशन ने जिन सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया है वे बहुत ही आपत्तिजनक हैं, और उनको स्वीकार करना किसी तरह भी उचित नहीं होगा ।^१

१. वही, २० मार्च, सन् १९१७, जि० ५५, पृ० ६९८-७०३ ।

सितम्बर सन् १९१७ में मालवीयजी ने कौंसिल में इंग्लैंड के साथ-साथ भारत में भी सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा हो, इसके सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने समस्या का ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए बताया कि सन् १८३३ में पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट द्वारा देश की ऊँची नौकरियों पर भारतीयों की नियुक्ति का अधिकार स्वीकार किया, और मैकाले ने इस निर्णय की बहुत प्रशंसा की। सन् १८५५ में प्रतियोगिता परीक्षा प्रारम्भ हुई। सन् १८५८ में महारानी विक्टोरिया ने अपनी शाही घोषणा द्वारा घोषित किया कि सम्राज्ञी की भारतीय प्रजा को उसकी अन्य प्रजा के समान उन सब पदों पर नियुक्त होने का अधिकार होगा, जिसके लिए वे अपनी क्षमता और सत्यनिष्ठा के कारण योग्य हों। पर इस व्यवस्था और घोषणा के बावजूद कोई हिन्दुस्तानी प्रशासन के किसी ऊँचे पद पर नियुक्त नहीं किया गया। सन् १८६० में भारतीयों को सरकारी नौकरियों में भरती करने का सर्वोत्तम उपाय बताने के लिए भारत-मन्त्री ने एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि या तो इंगलिस्तान के साथ-साथ भारत में भी यथासम्भव वैसी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाय, और इन दोनों प्रतियोगिताओं के परिणामों के आधार पर एक लिस्ट तैयार की जाय, या नियुक्तियों की कुल सख्या के एक अंश के लिए भारत में अलग से प्रतियोगिता हो जिसमें भारतीय और भारत में रहनेवाली अन्य ब्रिटिश प्रजा भाग ले सके। मालवीयजी ने कहा कि कमेटी के इन सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और सन् १८७६ तक उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं की गयी। सन् १८७० में पार्लियामेंट ने एक अधिनियम द्वारा सिविल सर्विस की कुछ नियुक्तियों के लिए भारतीयों को भरती करने के निमित्त नियम बनाने का भारत सरकार को अधिकार दिया। पर यह व्यवस्था 'असन्तोषप्रद' सिद्ध हुई। इसके बाद सन् १८८६ में पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त किया गया। इसने भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था करने का विरोध किया। इसके बाद सन् १८९३ में ब्रिटेन की कामन्स सभा ने मिस्टर हर्वर्ट पाल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि भारत और इंगलिस्तान दोनों में साथ-साथ समकालिक प्रतियोगिता परीक्षाएँ हों। पर भारत-मन्त्री ने कामन्स सभा की इस सिफारिश की उपेक्षा की, और उसको कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया। सन् १९११ में भारतीय विधान कौंसिल में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया गया। सन् १९१२ में एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में भारत में समकालीन-प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का विरोध किया।

मालवीयजी ने कमोशन के विचार को गलत बताते हुए कहा कि हमारी यह दृढ़ धारणा है कि भारतीयों के दावे के साथ उस समय तक न्याय नहीं हो सकता, जब तक सिविल सर्विस के लिए परीक्षाएँ हिन्दुस्तान और इंगलिस्तान में साथ-साथ नहीं होती। उन्होंने बताया कि सन् १९१७ तक इंगलिस्तान में आयोजित परीक्षाओं द्वारा केवल ८० भारतीय सिविल सर्विस में दाखिल हो सके हैं, जबकि यूरोपियनों की संख्या २६०० है। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय उन पदों पर, जिन पर साधारणतः इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं, केवल १० प्रतिशत भारतीय हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सन् १९१२ में ५०० रुपये या उससे अधिक वेतन पानेवाले सरकारी अफसरों में ८३ प्रतिशत यूरोपियन और यूरोशियन हैं।

अन्त में उन्होंने बहुत से अंग्रेज राजनीतिज्ञों और प्रशामकों के विचारों तथा जापान की प्रगति का हवाला देते हुए ब्रिटिश अधिकारियों, भारत सरकार तथा इंडियन सिविल सर्विस के यूरोपियन सदस्यों से अपील की कि वे इस समस्या पर संजीदगी से विचार करें, और इसका समाधान करने में हमारी सहायता करें।^१

२४ सितम्बर सन् १९१७ को मालवीयजी ने एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार से सस्तुति की कि यदि इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश के लिए अलग से भारत में परीक्षा की व्यवस्था की जाय तो ५० प्रतिशत स्थान इसके द्वारा भरे जायें। उन्होंने कहा कि अपने देश की सर्विस में नियुक्ति का अधिकार हमें अवश्य ही यूरोपियनों से बेहतर है। फिर भी हम सब के लिए समान रूप से खुली प्रतियोगिता में बराबर की परीक्षा के लिए तैयार हैं, पर यदि अनुपात निश्चित किया जाय तो वह ५० प्रतिशत से कम न हो, और उसके बाद भी लन्दन में आयोजित परीक्षाओं में बैठने की भारतीय नवयुवकों को इजाजत हो।^२ यूरोपियनों की इस बात का उत्तर देते हुए कि भारत में शासन-व्यवस्था का ब्रिटिश स्वरूप बनाये रखना हितकर होगा, मालवीयजी ने कहा कि इसके लिए शासन में यूरोपियनों का बाहुल्य और आधिपत्य बनाये रखना जरूरी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की शासन-व्यवस्था को पूर्णरूप से ब्रिटिश भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रिटेन में प्रचलित व्यवस्था के बहुत

१ प्रोसीडिंग-इण्डियन लेजिस्लेटिव कौंसिल, सन् १९१७, जि० ५६, पृ० ३२५-३३३।

२. वही, सन् १९१७, जि० ५६, पृ० ३७०।

से महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का यहाँ पालन नहीं होता। हमारी शासन-व्यवस्था भारतीय भी नहीं है। हमें एक ऐसी प्रणाली का विकास करना है जो 'प्रधानतः भारतीय' हो, पर जो ब्रिटिश शासन के उन सिद्धान्तों से प्रभावित और संशोधित हो जो व्यवहार में हितकर और सही पाये गये हैं।^१ मालवीयजी के इस प्रस्ताव का गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों ने समर्थन किया, पर सभी सरकारी और गैर-सरकारी यूरोपियन सदस्यों ने इसका विरोध किया, और प्रस्ताव २१ वोटों के मुकाबले में ३५ वोटों से नामजूर हो गया।^२

मालवीयजी ने तीसरे प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार से संस्तुति की कि इंडियन पुलिस सर्विस के लिए लन्दन के अतिरिक्त भारत में भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, उसमें प्रवेश करने का भारतीयों को भी अधिकार हो, पुलिस अफसरों का वेतन न बढ़ाया जाय, और परीक्षार्थियों की आयु की गर्त १९-२१ से बढ़ा कर २१-२३ वर्ष कर दी जाय।^३ भारतीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव का भी डट कर समर्थन किया, पर सरकार इसे मजूर करने को तैयार नहीं हुई, और इसलिए कौंसिल ने उसे रद्द कर दिया।

इंस्टीगटन कमेटी की संस्तुतियों के विरोध में राववहादुर बी० एन० शर्मा और श्री श्रीनिवास शास्त्री ने भी कई प्रस्ताव कौंसिल में पेश किये। बी० एन० शर्मा साहब का प्रस्ताव था कि इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस में ब्रिटिश अफसरों के बाहुल्य के प्रभावित सिद्धान्त को स्वीकार न किया जाय। मालवीयजी ने इसका समर्थन किया।^४ कई दूसरे भारतीय सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में भाषण किये, पर सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

श्री श्रीनिवास शास्त्री का पहला प्रस्ताव था कि सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने की आयु की सीमा को घटाया न जाय। सरकार के आश्वासन पर शास्त्री जी ने उसे वापस ले लिया। शास्त्रीजी का दूसरा प्रस्ताव था कि इंडियन सिविल सर्विस के वेतन, पेशन आदि में कोई परिवर्तन न किया जाय। सरकार के विरोध के कारण यह प्रस्ताव १७ भारतीय सदस्यों के समर्थन के

१. वही, सन् १९१७, जि० ५६, पृ० ३६९-३७०।

२. वही, सन् १९१७, जि० ५६, पृ० ३८८-३८९।

३. वही, सन् १९१७, जि० ५६, पृ० ९१९-९२२।

४. वही, सन् १९१७, जि० ५६, पृ० ३०३-३०५।

विरुद्ध ३० सरकारी सदस्यो और गैरसरकारी यूरोपियनो के वोटो से नामजूर हो गया। उनका तीसरा प्रस्ताव था कि पृथक् मेडिकल सर्विस स्थापित की जाय, पर सरकार इसे भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हुई, और १५ वोटो के विरुद्ध ३५ वोटो से यह भी नामजूर हो गया। शारजीजी का चौथा प्रस्ताव था कि सिविल सर्विस की परीक्षा की विषय सूची में भारतीय इतिहास, फारसी, अरबी और संस्कृत विषय भी शामिल किये जायें। इस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया।

फरवरी सन् १९१८ में श्री श्रीनिवास शास्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिन्दुस्तान में भरती की जानेवाली नौकरियों में हिन्दुस्तानी भरती किये जायें। उन्होंने बताया कि २०० रुपये से अधिक की १४४० ऐसी नौकरियों में ४०४ यूरोपियन और ६३३ यूरोशियन हैं और केवल ४०३ अर्थात् २८ प्रतिशत हिन्दुस्तानी हैं।^१ यह स्थिति, उन्होंने कहा, उचित नहीं है। सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

सिविल सर्विस से सम्बन्धित इन सभी प्रस्तावों पर मालवीयजी, श्री बी० एन० शर्मा और श्री श्रीनिवास शास्त्री के अतिरिक्त श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, मिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना, डाक्टर तेज बहादुर सप्रू आदि ने काफी जोरदार भाषण किये। इन सब प्रस्तावों का सभी सम्प्रदायों और वर्गों के भारतीयों ने समर्थन किया, पर सरकार ने किसी की कोई बात नहीं मानी। सरकार ने अपने व्यवहार से मिट कर दिया कि वह अपनी नीति-रोति में परिवर्तन करने को तैयार नहीं है, और भारतीय सदस्यों की सर्वसम्मत राय को ठुकरा देने में भी उसे कोई हिचकिचाहट नहीं है। भारतीय सदस्यों ने भी अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया कि यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को छोड़कर भारत के किसी वर्ग या सम्प्रदाय को इरिलिगटन कमिशन की रास्तुतियाँ मजूर नहीं हैं, और वे भारतीय शासन व्यवस्था में यूरोपियनों का प्राधान्य सहन करने को तैयार नहीं हैं।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का प्रस्ताव

माटेयू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्ताव पेश किया कि “यह कौंसिल वाइसराय और भारत-मन्त्री को सुधार प्रस्तावों के लिए धन्यवाद देती है और उन्हें

भारत में उत्तरदायी सरकार की क्रमशः उपलब्धि की ओर यथार्थ प्रयत्न और ठोस कदम मानती है, (२) यह कौंसिल गवर्नर-जनरल इन कौंसिल से संस्तुति करती है कि इस कौंसिल के सब गैर-सरकारी सदस्यों की एक कमेटी सुधारों की रिपोर्ट पर विचार करने तथा भारत सरकार को अपनी संस्तुतियाँ करने को नियुक्त करे।

इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा कि यह रिपोर्ट इस बात का अच्छा उदाहरण है कि 'हमारे शासकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और इसलिए अब इस सरकार के प्रति हमारे व्यवहार और भाव में भी ऐसा ही परिवर्तन होना चाहिए।' यदि 'शान्ति, समझौता और सार्वजनिक सन्तोष की ओर हमारे प्रशासक आगे बढ़ते हैं तो साधारण समझ और देशभक्ति की माँग है कि हमारी ओर से भी इसी प्रकार की चेष्टा हो।'।

दिनशा इट्टलजी वाचा तथा श्री निवास शास्त्री ने इसका समर्थन किया। जी० एस० खापर्डे, विट्ठलभाई पटेल, मालवीयजी और जिना साहब ने माटेग्यू के प्रति आभार प्रकट किया, पर रिपोर्ट की सिफारिशों की कमियों की ओर ध्यान दिलाते हुए माँग की कि उन्हें संशोधित किया जाय। अन्त में रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में गैरसरकारी सदस्यों की एक कमेटी गठित हुई। इस कमेटी में नरमदलीय नेताओं तथा सरकार के समर्थकों का बहुमत था। इसलिए नरमदलीय काफ़ेस में स्वीकृत सुझाव ही कमेटी की सिफारिशों का मूलाधार बन पाये। मालवीयजी और श्री वी० एम० शर्मा ने एक संयुक्त नोट में कमेटी के बहुसंख्यक सदस्यों की बहुत-सी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कांग्रेस के प्रस्तावों के अनुरूप कुछ और सिफारिशों की। जमींदारों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में मालवीयजी और श्री वी० एन० शर्मा में भी काफी मतभेद था। कमेटी के जमींदार सदस्यों के आग्रह पर कमेटी के अधिकांश सदस्यों ने प्रतिनिधि सभाओं में जमींदारों को अधिक स्थान देने की सिफारिश की। श्री वी० एन० शर्मा ने भी कमेटी की इस सिफारिश की पुष्टि की, पर मालवीयजी ने एक नोट में इस सिफारिश का विरोध किया।

युद्ध के लिए अनुदान

सन् १९१७ में सरकार ने निश्चय किया कि युद्ध के लिए भारत एक भारी धनराशि ब्रिटेन को दे। भारत-मन्त्री चाहते थे कि भारत १० करोड़ पाउण्ड (डेढ़ अरब रुपये) युद्ध-कोष में दे। भारत सरकार इतना अधिक धन देना भारत की शक्ति के बाहर समझती थी, पर अन्त में वह राजी हो गयी। केन्द्रीय विधान कौंसिल

में बहुत से निर्वाचित सदस्यों ने इस अनुदान के प्रस्ताव का समर्थन किया। मालवीयजी ने कहा - "यह बोझ अत्यधिक है। इसे चुकाने के लिए ३० वर्ष तक ९ करोड़ रुपये वार्षिक के नये कर लगाने होंगे। ब्रिटेन की तो बात ही क्या है, यदि हम स्वशासित डोमीनियनो से आधे भी घनी और समृद्ध होते, तो हमने इस बोझ को खुशी खुशी वहन कर लिया होता, पर दुर्भाग्य से भारत बहुत गरीब है उसके साधन बहुत सीमित हैं। उसकी अनिवार्य घरेलू आवश्यकताएँ बड़ी और बहुत जरूरी हैं।" "वजट का यह प्रस्ताव हमें ऐसी स्थिति का मुकाबला करने पर मजबूर करेगा, जिसमें एक पीढ़ी के जीवन-काल तक तो बहुत आवश्यक किस्म के आन्तरिक सुधार भी बाधाग्रस्त हो जायेंगे।" पर अन्त में उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया।

भारत सरकार ने नब्बे करोड़ रुपये का भुगतान कर्ज लेकर किया, तथा बाकी साठ करोड़ रुपये भारतीय जनता से वसूल करने की कोशिश की। सिद्धान्ततः चन्दा स्वैच्छिक था, पर वास्तव में इसे जमा करने में सरकारी अफसरों ने काफी सख्ती से काम लिया।

सन् १९१८ में सरकारी प्रवक्ता ने यह स्वीकार करते हुए कि युद्ध के कारण जो विशेष पेंशनें भारतीय सेना से सम्बन्धित ब्रिटिश सैनिकों को देनी पड़ेंगी, उनके लिए भारतीय राजस्व दायी नहीं है, उन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत इन पेंशनो की अदायगी का भार वहन करे। उन्होंने यह भी कहा कि कौंसिलो के गैर-सरकारी सदस्य ही अपने वोट द्वारा इस प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। पर जब मालवीयजी ने यह सशोधन पेश किया कि इसकी रकम गत वर्ष के युद्ध अनुदान से दी जायगी, तब अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार का सशोधन प्रत्यक्ष इनकार समझा जायगा। मालवीयजी ने सरकार की प्रतिक्रिया की उपेक्षा करते हुए संशोधन पर तगड़ी तकरीर की। उन्होंने कहा कि जो सहायता हम दे सकते हैं, वह हमारे साधनों से सीमित है, और इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय लेने के पहले हमें भारतीय जनता के प्रति अपने कर्तव्य को भी ध्यान में रखना होगा,^१ यह भी देखना होगा कि जनता उसे कहाँ तक वहन कर सकती है। जनता की गरीबी और आवश्यकताएँ, उन्होंने कहा, जनता के प्रतिनिधियों को १५ करोड़ रुपये का

१ वही, मार्च, १९१७, जि० ५५, पृ० ५५७।

२. आनरेबिल पण्डित मदन मोहन मालवीय : लाइफ और स्पीचेज, पृ० ७०८।

नया बोझ जनता पर लादने की उजाजत नहीं देती।^१ उन्होंने कहा कि, जैसा गांधीजी ने वाइसराय को लिखा है अधिक भन देना हमारी शक्ति के बाहर है।^२ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह १५० करोड़ रुपये के भार को चुकाने की भी समुचित व्यवस्था करे, ताकि वह बोझ हमारी प्रगति में बाधक न हो। गरीबों को सताये बगैर युद्ध-जाग-कर द्वारा ही गुद्ध के कर्जों का भुगतान हो सकता है। यही 'न्याय गगन' भी है। यदि यह नहीं किया गया तो इस कर्जों को चुकाने के लिए तीग वर्ष तक जनता पर भारी करारोपण करना होगा और "यह भारी विपत्ति होगी।"^३ मालवीयजी के इस संशोधन का समर्थन करने को काँग्रेस के सदस्य तैयार नहीं हुए, तब मालवीयजी ने उसे वापस ले लिया।

मालवीयजी का नेतृत्व

भारतीय विधान काँग्रेस में मानवीयजी का काम नि सन्देह बहुत प्रशंसनीय था। यद्यपि बहुत से ब्रिटिश अफसरों की दृष्टि में मालवीयजी 'घास में छिपे सात' थे, पर बहुत से दूसरे अफसर उनसे मतभेद रखते हुए भी उनके 'धवल चरित्र और राजनीतिक ईमानदारी' पर विश्वास करते थे। वे कहते थे कि मालवीयजी को न डराया जा सकता है, और न खरीदा जा सकता है। लार्ड हार्डिंग से उनके सम्बन्ध बहुत ही मधुर थे। वे लार्ड रिपन के बाद हार्डिंग को ही भारत का सबसे अच्छा वाइसराय मानते थे। लार्ड हार्डिंग का भी मालवीयजी को सचार्ड पर पूरा विश्वास था। लार्ड चेम्सफोर्ड से उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। सन् १९१९ में तो इन सम्बन्धों में उरा समय अधिक कड़वाहट पैदा हो गयी जब मालवीयजी ने चेम्सफोर्ड को पंजाब कांड का मुख्य उत्तरदायी घोषित करते हुए उन्हें वापस बुलाने की माग की। भारतीय हितों की रक्षा और पुष्टि में मालवीयजी के क्षमतापूर्ण योगदान ने उनका कीर्ति को पहले से कहीं अधिक व्यापक बना दिया। सन् १९१२ में जब उन्होंने श्री भूपेन्द्र नाथ बसु द्वारा प्रस्तुत 'विशेष विवाह विधेयक' का विरोध किया, तब देश के बहुत से प्रगतिशील व्यक्तियों को बुरा लगा। पर सन् १९१० में ही 'प्रेस बिल' के निर्भीक विरोध द्वारा मालवीयजी ने देश के प्रगतिशील तत्वों को मोहित कर लिया था, और दो एक बातों को छोड़ कर दस वर्ष के अन्दर उन्होंने काँग्रेस में कोई ऐसी बात नहीं कही, जो देश के प्रगतिशील व्यक्तियों को ठीक न जँची हो।

१ वही, पृ० ७१२।

२ वही, पृ० ७१२।

३ वही, पृ० ७१४।

फरवरी सन् १९१५ में गोखले साहब का निधन हो गया। उसके बाद तो मालवीयजी कीसिल में देशके प्रमुख प्रवक्ता बन गये। नवम्बर सन् १९१७ में भारत-मन्त्री माटेयू ने अपनी 'इंडियन डायरी' में लिखा 'पंडित मदन मोहन मालवीय कौंसिल के सबसे अधिक क्रियाशील राजनीतिज्ञ हैं।' सन् १९१९ में रीलेट बिल तथा इडेमनिटी बिल की विद्वत्तापूर्ण कड़ी समीक्षा ने तो मालवीयजी की प्रतिष्ठा को चार चाद लगा दिये, उनकी घबल कीर्ति को चमका दिया और उसे देश के कोने-कोने में फैला दिया।

पुराने नेताओं में सर्वथी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, जी० एस० खापर्डे, विठ्ठल भाई पटेल, भूपेन्द्रनाथ वसु तथा दिनशा इंदुल जी वाचा का योगदान भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण था। इस कौंसिल के जिन दूसरे सदस्यों ने आगे चल कर भारत के राजनीतिक मंच पर बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त किया और इस कौंसिल में भी अच्छा काम किया, उनमें मिस्टर मुहम्मद अली जिना, मिस्टर मजहसूल हक, श्रीनिवास शास्त्री, डाक्टर तेज बहादुर सप्रू, श्री सच्चिदानन्द सिन्हा प्रमुख थे। जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि रावबहादुर बी० एन० शर्मा, महाराजा साहब महमूदाबाद, महाराज मनेन्द्र चन्द नन्दी, तथा राजा रामपाल सिंह का योगदान भी सराहनीय था।



११. राजनीतिक जाग्रति, दमन और सुधार

विश्वयुद्ध

सन् १९१४ में यूरोप में युद्ध प्रारम्भ हुआ, जो आगे चल कर विश्वयुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, इटली तथा तुर्की एक पक्ष में थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान दूसरे पक्ष में थे। संयुक्त राज्य अमरीका भी, जिसकी सहानुभूति ब्रिटेन के साथ थी, आगे चल कर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया।

यद्यपि यह युद्ध वस्तुतः साम्राज्यशाही युद्ध था, अपने साम्राज्यशाही आधिपत्य की रक्षा और वृद्धि ही दोनों पक्षों का मुख्य लक्ष्य था, फिर भी संसार की प्रगतिशील शक्तियों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ब्रिटेन ने घोषित किया कि संसार में लोकतन्त्र को प्रतिष्ठित करना ही मित्र-राष्ट्रों का मुख्य लक्ष्य है। संयुक्त राज्य अमरीका ने इस युद्ध में सम्मिलित होते समय सब राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की। इन घोषणाओं ने तथा विश्वयुद्ध की गतिविधि ने परतन्त्र देशों की जनता में आत्मनिर्णय की भावना तथा स्वतन्त्रता की माँग को परिपुष्ट किया।

इस विश्वयुद्ध ने भारत की राजनीति को भी एक नयी गति प्रदान की। लाखों व्यक्ति, जो अब तक राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उपेक्षित रहते थे, उनमें गहरी दिलचस्पी लेने लगे। निम्न मध्य श्रेणी के नगर-निवासियों के साथ-साथ ग्रामीण जनता में भी राजनीतिक स्फूर्ति पैदा हुई। मुस्लिम जनता की प्रतिक्रिया हिन्दू जनता की प्रतिक्रियाओं से अधिक तीव्र थी।

मुसलमानों की प्रतिक्रिया

हिन्दुस्तान के मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। वे तुर्की साम्राज्य की अखण्डता को मुस्लिम जगत् के धार्मिक हितों की रक्षा के लिए, खिलाफत के अस्तित्व के लिए आवश्यक समझते थे। भारतीय सेना द्वारा उसका विघटन उन्हें असह्य था। जन कि ब्रिटिश सरकार के पुराने समर्थक जमींदार और नवाब क्षुब्ध थे मध्य-वर्गीय मुसलमान तथा मौलवी लोग और उनकी समर्थक जनता रुष्ट थी।

इस स्थिति में मौलाना मुहम्मद अली ने मुसलमानों को सलाह दी कि मुसलमान हिन्दुस्तान में कोई झगडा न खडा करें, अमन और शान्ति बनाये रखने के लिए सरकार को अपनी सेवा अर्पित करें, तथा सरकार न अरब पर चढाई करे और न मुसलमानों के उन धार्मिक क्षेत्रों पर आक्रमण करे जो मुसलमान शासकों के अधीन हैं। पर ब्रिटिश सरकार ने इस सलाह की उपेक्षा करते हुए उन्हें और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली तथा मौलाना आजाद को नजरबन्द कर दिया, और आगे चल कर सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया पर चढाई कर दी, और वहाँ भारतीय सेना भेज दी। इसने मुसलमानों के क्रोध को अधिक प्रज्वलित कर दिया।

देवबन्द के शेख-उल-हिन्द मौलाना महमूद-उल-हसन अरब चले गये, अपने शागिर्द मौलाना उवेदुल्ला सिन्धी को काबुल भेजा, और उन्होंने स्वयं तुर्की के सैनिक शासक गालिव पाशा से जहाद का परवाना प्राप्त किया। पर शरीफ मक्का ने मौलाना महमूद-उल-हसन और उनके शिष्य मौलाना हुसैन अहमद मदनी को अग्नेजो के हवाले कर दिया, और अमीर अफगानिस्तान ने मौलाना उवेदुल्ला साहब को उनके ब्रिटेन-विरोधी पड्यन्त्रों में उन्हें मदद देने से इनकार कर दिया।

क्रान्तिकारी विद्रोह

बहुत से पुराने हिन्दू क्रान्तिकारियों ने भी इस अवसर पर अपने पड्यन्त्रों को अधिक गतिशील बनाने की कोशिश की। उन्होंने बर्लिन में इंडियन नैशनल पार्टी गठित की। सर्व श्रो पिल्ले, हरदयाल, तारकनाथ दास, के० सी० चटर्जी, हरेभाव लाल गुप्त इसके प्रमुख सदस्य थे। मुसलमान क्रान्तिकारी बरकतुल्ला भी उसके एक सम्मानित सदस्य थे। ये लोग जर्मनी की सहायता से बगाल और पंजाब में क्रान्तिकारी विद्रोह को उत्तेजित कर भारत में ब्रिटिश राज्य खत्म करना चाहते थे। जर्मनी ने इन्हें अस्त्र शस्त्र देने का भी वचन दे दिया था। पर बहुत प्रयत्न करने पर भी जर्मनी के हथियार बगाल की खाड़ी में नहीं पहुँच पाये। बगाल के क्रान्तिकारियों का प्रयास बिफल रहा।

काबुल में एक अस्थायी हिन्द सरकार गठित की गयी, जिसके अध्यक्ष राजा महेन्द्र प्रताप और प्रधान-मन्त्री बरकतुल्ला बनाये गये। मौलाना उवेदुल्ला सिन्धी गृह-मन्त्री नियुक्त हुए। पर पंजाब सरकार को इस पड्यन्त्र का सुगम मिल गया, और विद्रोह की योजना बिफल हो गयी। लाला हरदयाल द्वारा

सघटित पार्टी ने युद्ध के जमाने में पंजाब में अपने विद्रोह को तीव्र कर दिया। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से लीटे कुछ सिक्खों ने भी विद्रोह में भाग लिया, पर एक वर्ष के अन्दर पंजाब सरकार ने बहुत से क्रान्तिकारियों को पकड़ कर स्थिति अपने काबू में कर ली।

श्रीमती बेसेंट और तिलक

इधर सन् १९१४ के प्रारम्भ में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुईं, जून सन् १९१४ के प्रारम्भ में लोकमान्य तिलक माण्डले जेल से छः वर्ष की सजा काट कर देश वापस आये, और विश्वयुद्ध के शुरू होने के कुछ महीने बाद गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। ये तीनों युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के पक्ष में थे। पर जहाँ गांधीजी बिना किसी शर्त या माँग के सहायता देना ही उचित समझते थे, वहाँ लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट का कहना था कि भारतीय जनता के लिए युद्ध में पूरी तौर पर सहायता देना तभी सम्भव है, जब उसे यह विश्वास हो कि उसके बलिदान के स्वरूप उसे भी अपने देश में अपना राज्य स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।^१ लोकमान्य तिलक ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक नौकरशाही जनता के अधिकार को स्वीकार नहीं करती, भारतीय सेना-नायकों को फौज में ऊँचा से ऊँचा पद देने को तैयार नहीं होती, तब तक वे और उनके साथी फौज में भारतीयों को भरती करने में सरकार का साथ नहीं दे सकते।^२

श्रीमती बेसेंट चाहती थी कि राजनीतिक कार्य के साथ-साथ उनके धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रम को भी कांग्रेस स्वीकार कर ले। पर जब फीरोज शाह मेहता और उनके साथी उसके लिए तैयार नहीं हुए, तब श्रीमती बेसेंट ने कांग्रेस द्वारा केवल राजनीतिक सुधारों के लिए प्रयत्न करने का निश्चय किया। वे लोकमान्य तिलक से मिली, और जब उन्हें विश्वास हो गया कि तिलक महाराज ब्रिटिश सम्राट् और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा रखते हुए सवैधानिक ढंग से स्वशासन के लिए प्रयत्न करने को तैयार हैं, तब उन्होंने गरम दल और नरम दल में समझौता कराके राजनीतिक नेताओं में पुनः मेल कराने का प्रयत्न किया। अन्ततोगत्वा दिसम्बर सन् १९१५ में कांग्रेस ने अपने विधान में ऐसा संशोधन स्वीकार कर लिया जिससे लोकमान्य तिलक

१ एनी बेसेंट, बिल्डर आफ न्यू इंडिया।

२ प्रधान और भागवत लोकमान्य तिलक, पृ० ३०१।

और उनके साथी अगले वर्ष कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग ले सके। इस कार्य में श्रीमती वेसेंट को मालवीय जी का समर्थन प्राप्त था।

होमरूल आन्दोलन

सन् १९१४ में ही श्रीमती एनी वेसेंट और लोकमान्य तिलक ने स्वशासन की मांग को पुष्ट करने तथा उसके लिए जनमत को सुदृढ़ करने के लिए होमरूल लीग कायम करने का निश्चय किया। चूँकि लोकमान्य तिलक के बहुत से साथी श्रीमती वेसेंट पर पूरी तरह से विश्वास करने को तैयार नहीं थे, और श्रीमती वेसेंट के साथी तिलक महाराज के साथ काम करने से हिचकते थे, इसलिए दोनों ने तय किया कि दो होमरूल लीगें कायम की जायें।

अप्रैल सन् १९१६ में बेलगाँव में बम्बई प्रान्तीय कान्फ्रेंस ने होमरूल लीग स्थापित करने का निर्णय किया। कुछ महीने बाद सितम्बर में श्रीमती वेसेंट ने अपनी होमरूल लीग स्थापित की। लोकमान्य तिलक की होमरूल लीग का कार्यक्षेत्र बम्बई और गन्ध प्रान्त तक सीमित था, जब कि श्रीमती एनी वेसेंट की होमरूल लीग का काम बाकी सब प्रान्तों में फैला हुआ था, और उनकी सस्था 'आल इंडिया होमरूल लीग' के नाम से विख्यात थी। दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए बहुत ही सौहार्द के साथ स्पर्धा के लिए जनता में कार्य किया। दिसम्बर सन् १९१६ में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बाद कांग्रेस के पडाल में हाँ दोनों होमरूल लीगों का संयुक्त अधिवेशन हुआ।

श्रीमती एनी वेसेंट होमरूल लीग के द्वारा स्वशासन के साथ स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा आदि का भी प्रचार करती थी। पर लोकमान्य तिलक ने स्वशासन, होमरूल, तक ही अपनी होमरूल लीग का काम सीमित रखा। उनका कहना था कि "लीग स्वराज्य की प्राप्ति के लिए स्थापित की गयी है और उसके सारे प्रयत्न उसीके लिए ही होने चाहिए। इसमें और कोई चीज शामिल नहीं होगी।"

श्रीमती एनी वेसेंट और लोकमान्य तिलक, दोनों ही सम्राट् और शासन के मौलिक भेद की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए, सम्राट् की सत्ता को स्वीकार करते हुए शासन के हस्तान्तरण पर जोर देते थे। उन दोनों का कहना था कि जिस तरह ब्रिटेन में सम्राट् ने शासन-सम्बन्धी अपने अधिकार ब्रिटेन की जनता और उसके प्रतिनिधियों को सौंप दिये हैं, उसी तरह से भारत में उन

अधिकारों को भारतीय जनता और उसके प्रतिनिधियों को सौंप देना चाहिए। वे स्वतन्त्रता को मानव का जन्म-सिद्ध अधिकार मानते थे, और कहते थे कि स्वशासन बिना जीवन नीरस और घृणास्पद है। श्रीमती एनी वेसेंट का कहना था कि ससार की १।५ जनता को दमनकारी कानूनों द्वारा बेचनी की हालत में रख कर संसार में स्थायी शान्ति कायम नहीं रखी जा सकती।^१

दृष्टिकोण में कुछ अन्तर होते हुए भी कांग्रेस के सभी पुराने नेता चाहते थे कि जनजागृति को ध्यान में रखते हुए नये सवैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में सरकार घोषणा करे, और अपने देश के प्रबन्ध में भरपूर योगदान करने के समुचित अवसर भारतीयों को प्रदान किये जायें। वे यह भी चाहते थे कि भारतीय सैनिकों का पद और गौरव अंग्रेज सैनिकों के समान हो, भारतीय नवयुवकों के लिए सैनिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो, उन्हें सम्राट् की सेवा तथा अपने देश की रक्षा के समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो।

दिसम्बर सन् १९१५ में श्रीमती एनी वेसेंट ने श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस के पुराने नेताओं की एक सभा आयोजित की, और उनसे अनुरोध किया कि वे प्रस्तावित होम रूल लीग में शामिल होकर स्वशासन के लिए आन्दोलन करें। उन सबने कहा कि किसी दूसरी संस्था द्वारा काम करने के बजाय वे कांग्रेस द्वारा ही स्वशासन के लिए प्रयत्न करेंगे।

कांग्रेस-लीग सहयोग

दिसम्बर सन् १९१५ में कांग्रेस ने अपने बम्बई अधिवेशन में निश्चय किया कि अन्य संस्थाओं के सहयोग से राजनीतिक सुधारों की रूप-रेखा तैयार की जाय। इसी अवसर पर मौलाना मजहूरुल हक की अध्यक्षता में ही मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। मजहूरुल हक साहब ने बहुत ही तगड़ी और जोशीली तकरीर की। पर कुछ मुसलमानों द्वारा उत्पात खड़ा कर देने पर अधिवेशन बन्द कर देना पड़ा। मिस्टर मुहम्मद अली जिना के प्रयास से ताजमहल होटल में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। वहाँ निश्चय किया गया कि कांग्रेस से मिल कर राजनीतिक सुधारों की योजना तैयार की जाय। अप्रैल और नवम्बर सन् १९१६ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से कुछ बातें तय की।

१. वेसेंट, विल्डर आफ न्यू इंडिया।

विधायको का मेमोरंडम

इधर अक्टूबर सन् १९१६ में केन्द्रीय विधान कौंसिल के उन्नीस सदस्यो ने, जिनमें मालवीयजी भी थे, एक पत्रक (मेमोरंडम) तैयार करके वाइसराय चैम्सफोर्ड के पास भेजा । इसमें माँग की गयी कि (१) शासन में जनता का भरपूर हाथ हो, और इसके निमित्त केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कार्यपरिपदो के कम से कम आधे सदस्य भारतीय हों, जिनका चयन जनता द्वारा निर्वाचित विधायको की राय से हो, और उनके अग्रेज सदस्यो का चयन भी ब्रिटेन के अनुभवी राजनीतिज्ञों में से किया जाय, अर्थात् इंडियन सिविल सर्विस के आदमी कार्यपरिपद् के सदस्य न बनाये जायें, (२) प्रत्येक विधान कौंसिल में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियो का बहुमत हो, (३) विस्तृत मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा विधान कौंसिल के सदस्यो का चुनाव हो, (४) विधान सभाओ के आधार और अधिकार विस्तृत किये जायें, (५) आर्थिक मामलो में हिन्दुस्तान पूर्ण स्वाधीन हो, (६) प्रान्तीय शासन को स्वायत्तता प्रदान की जाय, (७) प्रत्येक प्रान्त में स्थानीय स्वशासन प्रतिष्ठित किया जाय, तथा (८) भारत-मन्त्री की कौंसिल तोड़ दी जाय । इन सब के साथ इस पत्रक में यह भी माँग की गयी कि यूरोपियनो के समान ही हिन्दुस्तानियो को हथियार रखने, टेरिटोरियल सेना में भरती होने, तथा सैनिक कमीशन पाने के अधिकार प्राप्त हो ।^१

सरकारी क्षेत्रो में विधायको के इस प्रयास की बहुत ही बड़ी आलोचना हुई । लार्ड चैम्सफोर्ड ने विधायको के प्रस्तावो को 'भयंकर परिवर्तन' की माँग बताते हुए उसकी निन्दा की ।^२ भूतपूर्व गवर्नर लार्ड सिडेनहम ने उन्हें 'क्रान्तिकारी प्रस्ताव' बताते हुए कहा कि "जर्मनी का कुचक्र काम कर रहा है, और भारत को सकट से बचाने के लिए" दमन नीति का अनुसरण आवश्यक है । लार्ड पैटलैड, सर माइकल ओडायर आदि बहुत से अफसरों की भी ऐसी ही धारणा थी ।^३

कांग्रेस-लीग स्कीम

दिसम्बर सन् १९१६ के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुए । गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक भी अपने बहुत

१. पट्टाभि सीतारमैया हिस्ट्री आफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिल्द १, पृ० ६१९-६२२ ।

२. वही, जिल्द १, पृ० १३२ ।

३. वही, जिल्द १, पृ० १३२ ।

भी यही राय थी। पर मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। अन्त में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की विषय निर्धारिणी समितियों की संयुक्त बैठक में जिना साहब ने कांग्रेस के सदस्यों से इस समय पृथक् निर्वाचन को मान लेने की अपील की, और कहा 'जब हम साथ साथ काम करेंगे तब विभिन्न सम्प्रदायों में पारस्परिक विश्वास पुनः प्रतिष्ठित होगा, और तब हम संयुक्त निर्वाचन स्थापित कर सकेंगे, और संपूर्ण स्वशासन का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे।' उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे अपने मुसलमान भाइयों को संयुक्त निर्वाचन प्रथा मान लेने को राजी करने का प्रयत्न करेंगे। इस वायदे पर कांग्रेसी नेता पृथक् निर्वाचन को उस समय मानने को तैयार हो गये।^१

अन्य कांग्रेसी नेताओं की तरह मालवीयजी भी पृथक् निर्वाचन प्रणाली के विरोधी थे। उन्होंने इस प्रश्न पर कांग्रेस-लीग की संयुक्त बैठक में वादविवाद भी किया, पर जब लोकमान्य तिलक आदि राजी हो गये, तब मालवीयजी ने भी, राष्ट्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस आशा से कि आगे चल कर विचार-विमर्श द्वारा यह दोष दूर किया जा सकेगा, चुप रहना ही उचित समझा। कांग्रेस द्वारा इस योजना के पास हो जाने पर मालवीयजी ने सन् १९१७ में सारे देश में घूम कर इसका प्रचार किया।

मालवीयजी का प्रचार

कांग्रेस-लीग योजना को जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन से अपना सम्बन्ध तोड़ना नहीं चाहते, पर इसका बना रहना "बहुत हद तक हमारे प्रति अंग्रेजों के व्यवहार पर निर्भर है।"^२

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस लीग योजना द्वारा "सरकार के ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं होनेवाला है। पुरानी संस्थाएँ और पुराने विभाग बने रहेंगे, पर सरकार का लक्षण अवश्य बदल जायगा, वह किसी अंश में "प्रतिनिधि सरकार" अवश्य बन जायेगी,^३ प्रशासन का संचालन भारतीयों और

१. जमनादास द्वारकादास पोलिटिकल मेमो०, पृ० १३३।

२. आनरेबिल पंडित मदनमोहन मालवीय लाइफ एण्ड स्पीच, पृ० ५७२ (युक्त प्रान्त की कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में किया गया भाषण, १० अगस्त, १९१७)

३. वही, पृ० ५७०।

अंग्रेजों की संयुक्त समिति के हाथ में होगा. और उस पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण होगा। इस परिवर्तन से अनर्थ की आशंका करना निरर्थक है। योजना में अनर्थ की सम्भावना से बचने के उपाय हैं, इन उपायों को और दृढ़ किया जा सकता है।^१

स्वशासन, उन्होंने कहा, मानव समाज का स्वाभाविक अधिकार है। उसकी ओर प्रगति स्वाभाविक है। कोई देश किसी दूसरे देश को सदा अपने अधीन नहीं रख सकता। पराधिपत्य निःसन्देह अस्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि कोई भी जाति इसका गर्व नहीं कर सकती कि वह सदा स्वतंत्र रही है, और यह किसी जाति के लिए शोभा की बात नहीं है कि वह अपने पूर्ण वैभव के दिनों में दूसरी जाति के मार्ग में रोड़े अटकाये। ब्रिटिश सरकार को शीघ्र ही घोषणा करनी चाहिए कि “भारत को स्वशासन प्रदान करना ब्रिटिश नीति का लक्ष्य और उद्देश्य है”।^२

योजना के सेना सम्बन्धी सुझावों की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों को “निरस्त्र रखने और सेना के ऊँचे पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने की नीति कठोर ही नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण है”।^३ भारतीय जनता को सैनिक-शिक्षा से वंचित रख कर उसे अयोग्य बनाये रखना “अकल्याणकर अद्वर्द्धशिता” ही है। उन्होंने कहा : “सैनिक शक्ति तथा उसको प्राप्त करने की योग्यता किसी जाति विशेष की बपौती नहीं है”।^४ जिस किसी पद के लिए भारतवासी योग्यता दिखावे वह उन्हें दिया जाय, यही उनकी माँग है।^५

उन्होंने बहुत से उदाहरण देते हुए यह सिद्ध किया कि सरकार जनता के प्रतिनिधियों के प्रस्तावों की किस प्रकार उपेक्षा करती है। इसलिए विधान कौंसिलो द्वारा पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन को बाध्य करना नितान्त आवश्यक है।^६

इसी तरह उन्होंने सरकार की आर्थिक गतिविधि और वित्त नीति की आलोचना करते हुए उन पर विधान कौंसिल के नियंत्रण को अनिवार्य बताया।

१. वही, पृ० ५७०।

२. वही, पृ० ५६९।

३. मद्रास में भाषण, ३१ जनवरी सन् १९१७।

४. वही।

५. वही।

६. वही।

उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रथा के अनुसार सरकार व्यौरेवार वर्णन के द्वाँर, विना उचित निरीक्षण करवाये भिन्न-भिन्न खातों में स्वेच्छानुसार व्यय बढ़ा सकती है । हम ऐसी ही बातों को उठा देना चाहते हैं ।^१

इसी तरह योजना की विभिन्न माँगों की पुष्टि करते हुए मालवीयजी ने देश के सर्वोत्कृष्ट नेता दादा भाई नौरोजी के आदेशों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया, और उन्हें अच्छी तौर से अपने को संगठित कर आन्दोलन करने की सलाह दी । मालवीयजी ने बताया कि हमारे नेता दादा भाई का हमें आदेश है—“आन्दोलन करो, आन्दोलन करो, देश के कोने-कोने में आन्दोलन करो ।” यदि हम वास्तव में अंग्रेजों से न्याय कराना चाहते हैं, तो त्याग और उत्साह के साथ काम करना हमारा कर्तव्य है ।^२ मालवीयजी ने कहा कि हमारे लिए खेद की बात होगी, अगर हम अपने पूज्य नेता की बात का अनुसरण न करें । हमें कलक लगेगा यदि हम उनकी बात कार्यरूप में परिणत न करें ।^३

मालवीयजी की धारणा थी कि अंग्रेज आसानी से बात माननेवाले नहीं हैं, उन्हें राजी करने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि राष्ट्रीय माँग को देश की जनता का समर्थन प्राप्त है, और जनता उसकी प्राप्ति के लिए कटिबद्ध है । इसके लिए जनता का संघटन और आन्दोलन आवश्यक है । जिले-जिले में कांग्रेस कमेटियाँ स्थापित करना, गाँव-गाँव में स्वराज्य का ज्ञान पहुँचाना, और घर-घर तथा झोपड़े-झोपड़े में इसका संदेश फैलाना हमारा कर्तव्य है । यह उचित ही नहीं, बरन् आवश्यक है कि देश के कोने-कोने से, घर-घर से और प्रत्येक मनुष्य के मुँह से अपने अधिकार के लिए आवाज निकले । हमें शिक्षित और अपढ़ भाइयों का सम्मिलित और संगठित आन्दोलन करना चाहिए ।^४

मालवीयजी चाहते थे कि व्यक्तिगत भेद को त्याग कर, नरम दल और गरम दल, तथा हिन्दू और मुसलमान का भेद भुला कर एक साथ मिल कर स्वराज्य के लिए प्रयत्न किया जाय । उनका अनुरोध था कि हिन्दू-मुसलमानों को अपने-अपने धार्मिक मतभेदों को दूर कर देना चाहिए । हिन्दू और मुसलमान दोनों को ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए उसकी सन्तान के साथ प्रेम करना

१. मद्रास में भाषण, ३१ जनवरी, १९१७ ।

२. प्रयाग में भाषण, ८ अगस्त, १९१७ ।

३. वही ।

४. बम्बई में भाषण, १० जुलाई, १९१७ ।

चाहिए।^१ हिन्दूओं और मुसलमान दोनों से उनकी विनती थी कि वे एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों का आदर करें, एक दूसरे के हृदयों को आघात पहुँचाने से रुकें।^२ वे चाहते थे कि नवयुवक बड़ों की आज्ञा न टालें, बल्कि बृद्धों के अनुभव और योग्यता से लाभ उठावें, तथा बृद्ध नवयुवकों को बच्चा समझ कर उन्हें त्याग न दें, उनके उत्साह को फीका न करें, वरन् उनको मार्ग दिखायें।^३

१० अगस्त सन् १९१७ को लखनऊ में पंडित मोतीलाल की अध्यक्षता में संयुक्त प्रान्त की प्रान्तीय राजनीतिक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में मालवीयजी ने एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण में राष्ट्र की राजनीतिक माँगों को पुष्ट करते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे उनके लिए आन्दोलन करें।^४ उन्होंने कहा “हमारा निस्तार मुख्यतया हमारे अपने ऊपर निर्भर है।^५” हमारा कर्तव्य है कि हम अपने को संगठित करें विभिन्न स्थानों में स्वराज्य लीग या होमरूल लीग स्थापित करें, “स्वशासन या स्वराज्य के मानवीय धर्म” का, “महान् मन्त्र” का घर-घर प्रचार करें, प्रत्येक भारतीय को उसका तात्पर्य समझायें, और उन्हें अपनी शक्ति भर उसके लिए काम करने को प्रोत्साहित करें।^६

दमन

विश्वयुद्ध के जमाने में सरकार ने सुधार और दमन की दुधारी नीति का अवलम्बन किया। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अच्छे तौर से जानते थे कि युद्ध के कारण भारतीय जनता में भी काफी व्यापक रूप से आत्मनिर्णय और स्वशासन की भावना जोर पकड़ेगी, और राजनीतिक सुधारों द्वारा ही जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को किसी अंश में शान्त किया जा सकता है।

पर भारत की अंग्रेज नौकरशाही को सुधारों से अधिक दमन पर विश्वास था। उसकी धारणा थी कि दमन द्वारा क्रान्तिकारी पड़्यन्त्रों को कुचला जा सकता है, और उसके साथ ही साथ उग्र राष्ट्रवादी सर्वेधानिक आन्दोलनों को भी बहुत हद तक दबाया जा सकता है। वे इस काम को सुधारों की चर्चा से

१. प्रयाग में भाषण, ८ अगस्त, १९१७। २. वही।

३. बम्बई में भाषण, १० जुलाई, सन् १९१७।

४. आनरेबल पंडित मदनमोहन मालवीय : लाइफ एण्ड स्पीच, पृ० ५५८-५८४।

५. वही, पृ० ५८४।

६. वही, पृ० ५८४।

अधिक आवश्यक समझते थे। भारत में दमनकारी कानूनों की भरमार थी, फिर भी भारत सरकार ने युद्ध के प्रारम्भ होने के कुछ दिन बाद ही भारत रक्षा अधिनियम केन्द्रीय विधान कौंसिल से पास करा लिया, और इस कानून को, एवं राज्य विद्रोह सभा अधिनियम को और प्रेस अधिनियम को कड़ाई से लागू किया। दण्ड विधान की कुछ दमनकारी धाराओं का भी मनमाने ढंग पर प्रयोग किया गया। सन् १८१८ का बंगाल रेगुलेशन नं० ३ भी चालू कर दिया गया। प्रवेश अध्यादेश जारी करके विदेश से आने वाले सद्विध भारतीयों के प्रवेश, भ्रमण तथा निवास पर मनमाने ढंग पर रोक लगाने के अधिकार का दुरुपयोग किया गया।

सरकार की दमनकारी नीति ने बंगाल में गजब ढा दिया। तीन हजार से अधिक नवयुवक भारत रक्षा अधिनियम या बंगाल रेगुलेशन्स के अन्दर पकड़ कर नजरबन्द कर दिये गये। इनमें से कुछ निःसन्देह क्रान्तिकारी थे। क्रान्तिकारी षड्यन्त्र द्वारा वे ब्रिटिश साम्राज्य का तख्ता उलट देना चाहते थे। पर अधिकांश निर्दोष थे। सरकार के इस क्रूर व्यवहार ने बंगाल के नवयुवकों में विशेष रूप से विद्रोह की भावनाओं को कम करने के बजाय तीव्र कर दिया।

कोमागाटा मारु जहाज के सिक्ख यात्रियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार ने सिक्खों में भी विद्रोह की भावना पैदा की। युद्ध से कुछ समय पहले कनाडा की सरकार ने यह व्यवस्था की कि वही जहाज-यात्री कनाडा में रहने के लिए प्रवेश कर सकेगा जिसने बीच में कहीं टिके बिना सीधे कनाडा में जहाज से यात्रा की हो। चूँकि इस समय हिन्दुस्तान से कनाडा को जाने वाले सभी जहाज हागकाग और टोकियो में रुकते थे, इसलिए किसी हिन्दुस्तानी के लिए यह शर्त पूरी करना संभव नहीं था।

इस स्थिति में बाबा गुरदित्त सिंह ने बहुत से सिक्खों को हागकाग में इकट्ठा करके १४ अप्रैल सन् १९१४ को उन सबके साथ 'कोमागाटा मारु' जहाज से कनाडा के लिए प्रस्थान किया। जब जहाज मार्ग में कहीं रुके बिना बेंकोवर पहुँचा, तब कनाडा के अधिकारियों ने उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया, और जहाज को वापस लौटने पर मजबूर किया। जब जहाज २९ सितम्बर सन् १९१४ को बजबज पहुँचा तब 'प्रवेश अध्यादेश' के आधार पर बंगाल के अधिकारियों ने उन्हें आदेश दिया कि वे फौरन रेल में सवार होकर बीच में कहीं रुके बगैर सीधे पंजाब चले जायें। बाबा गुरदित्त सिंह ने कहा कि पंजाब जाने से पहले वे भारत सरकार से अपनी शिकायतों की फरियाद करना चाहते हैं।

पर उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गयी। सिक्ख यात्रियों ने सरकार की आज्ञा की अवहेलना करके कलकत्ता जाने की कोशिश की। इस पर झगडा हो गया, जिसने उपद्रव का रूप धारण कर लिया। १९ सिक्ख यात्री मार डाले गये, बहुत से गिरफ्तार कर लिये गये, २९ फरार हो गये, और ६० यात्री जिनमे २७ मुसलमान थे, ट्रेन द्वारा पंजाब चले गये। जो पकड़ लिये गये थे, उनमें से अधिकांश जनवरी में पंजाब लौटा दिये गये, और ३१ को जेल में नजरबन्द रहने दिया गया।

सरकार और उनके समर्थक बाबा गुरदित्त सिंह और उनके साथियों को ही इन सब दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं, पर भारत के बहुत से राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञों की राय में जहाँ कनाडा की सरकार का आप्रवासन सम्बन्धी कानून तथा शान्तिप्रिय भारतीयों के प्रति उसका व्यवहार सारे भारत का अपमान था, वहाँ बजबज में सरकारी अधिकारियों का व्यवहार सर्वथा सहानुभूति-विहीन कठोर था। बाबा गुरदित्त सिंह के साथी रोटी रोजी कमाने कनाडा गये थे। उनमें विद्रोह की भावना लेशमात्र भी नहीं थी, और भारत सरकार के पास यह सिद्ध करने को कोई प्रमाण नहीं था कि भारत लौटते-लौटते सब-विद्रोह की भावना उनमें इतनी तीव्र हो गयी थी कि उनके साथ हत्या अपराधियों का-सा व्यवहार किया जाना अनिवार्य था। बजबज के दुर्घटना ने सरकार और जनता के पारस्परिक सम्बन्धों में सौहार्द-बन्धन को बिल्कुल अवश्य कर दी।

पंजाब सरकार का व्यवहार तो बगल सरकार के ही इच्छित कठोर था। पंजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर माडकेल ओबेयर ने बड़े सख्तों के नजरबन्दों को फौज में भरती किया, तथा युद्ध के लिए इच्छुक युवकों से बन्दा जमा किया। उन्होंने क्रान्तिकारी पद्धतियों को दबाने के लिए सख्त सैन्य-तान्त्रिक राष्ट्रीय आन्दोलन को खत्म करने की चेष्टा की। वे दो उदात्त विधायकों की माँगों, तथा कांग्रेस-लीग योजना के दो उदात्त ही क्रान्तिकारी समझते थे, जितना गदर पार्टी से सम्बन्धित नन्दूकों के बारे में कहते थे कि भारतीय स्थानीय स्वशासन से ही सन्तुष्ट हो जायें।

सरकार का दमन क्रान्तिकारियों और इच्छित नजरबन्दों तक ही सीमित नहीं था। सरकार को होम्स कानून की पसन्द नहीं थी। बल्कि यथासम्भव ह्कावटों द्वारा ही सब दमन करने की चेष्टा की। इस विचार ने अपने प्रान्त में लैडन-निक का, और बन्दूक सरकार

श्रीमती बेसेंट का प्रवेश रोक दिया। बम्बई सरकार ने तो होमरूल आन्दोलन के प्रारम्भ होने के तीन मास के अन्दर ही तिलक महाराज के तीन व्याख्यानों पर आपत्ति करते हुए उनसे एक वर्ष के लिए बीस हजार रुपये का मुचलका और दस-दस हजार रुपये की दो जमानतें देने की माँग की। जिला मजिस्ट्रेट ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया, पर बम्बई हाईकोर्ट ने उसे रद्द करते हुए कहा कि तिलक के इन तीन व्याख्यानों से राजद्रोह का अर्थात् सम्राट् के प्रति 'शत्रुता, विद्वेष और घृणा' का बोध नहीं होता।

मद्रास के गवर्नर लार्ड पैटलैड ने बम्बई सरकार को भी मात कर दिया। उन्होंने प्रेस एक्ट के अन्दर दी गयी श्रीमती बेसेंट के समाचार पत्रों की जमानत जब्त कर ली, और श्रीमती बेसेंट को फिर से जमानत दाखिल करने को बाध्य किया। उन्होंने आदेश जारी किया कि विद्यार्थी राजनीति में भाग न लें, राजनीति से संबंधित सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों से अलग रहें। जबकि बम्बई सरकार ने न्यायालय में तिलक महाराज पर अभियोग लगा कर उन्हें अपनी सफाई पेश करने तथा हाईकोर्ट को उस पर विचार करने का मौका दिया, लार्ड पैटलैड ने ऐसा न करके १४ जून, सन् १९१७ को श्रीमती एनी बेसेंट और मिस्टर जी० एस० अरडेल और श्री वी० पी० वादिया को गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया। पर इसकी प्रतिक्रिया तिलक महाराज पर चलाये गये मुकदमे से अधिक तीव्र हुई। ससार भर के थियोसाफिस्टों ने नजरबन्दी की तीव्र भर्त्सना करते हुए उसे रद्द करने की माँग की। भारत में जनान्दोलन तीव्र हो गया, होमरूल की माँग तेज हो गयी, जबकि जिना साहब और बहुत से उदार-दलीय राजनीतिज्ञ होमरूल लीग के सदस्य हो गये, कांग्रेस में नजरबन्दी के विरुद्ध सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करने की चर्चा होने लगी।

मालवीयजी ने अपने लेखों और भाषणों में नजरबन्दी की कड़ी आलोचना की, केन्द्रीय विधान कौंसिल के विचार के लिए सरकार के पास इसके विरोध में प्रस्ताव का नोटिस भेजा। उन्होंने जिना साहब को तार दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मुस्लिम लीग कौंसिल की संयुक्त बैठक बुलायी जाय। सविनय प्रतिरोध के सम्बन्ध में मित्रों से बातचीत करने वे कलकत्ता गये, पर वहाँ उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।^१ मालवीयजीने प्रथम बार प्रयाग में होमरूल लीग के तत्त्वावधान में भाषण किया, और स्वशासन की तथा श्रीमती एनी बेसेंट की

रिहाई की माँग की। अगस्त सन् १९१७ में उन्होंने इस माँग को प्रान्तीय कांग्रेस के अधिवेशन में फिर दोहराया।

जुलाई के अन्तिम सप्ताह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। दोनों ने श्रीमती एनी बेसेंट और अली वन्दुओ की नजरबन्दी से रिहाई की माँग की। दोनों ने सरकार की दमन नीति की, तथा राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में सरकार के उच्च अधिकारियों के विचारों की समीक्षा करते हुए माँग की कि (१) दमन नीति खत्म की जाय, (२) भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का स्वशासित प्रदेश बनाने की नीति की ब्रिटिश सरकार शीघ्र घोषणा करे, (३) सुधार योजना की स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय, (४) राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में सरकार अपनी योजना शीघ्र प्रकाशित करे। प्रतिरोध की नीति और औचित्य पर काफी विचार-विमर्श के बाद निश्चय हुआ कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों और प्रान्तीय मुस्लिम लीग कौंसिलों से अनुरोध किया जाय कि वे इस प्रश्न पर विचार करके अपनी राय छः सप्ताह के अन्दर भेजे।

सितम्बर के पहले पखवाड़े में ही सरकार ने श्रीमती एनी बेसेंट और उनके दोनों साथियों को इस आश्वासन पर छोड़ दिया कि वे युद्ध के जमाने में "राजनीतिक आन्दोलन के हिंसात्मक और अवैधानिक तरीकों से परहेज करेंगे।"^१ पर मौलाना मुहम्मद अली नहीं छोड़े गये।

श्रीमती एनी बेसेंट से इस प्रकार का आश्वासन लेना निरर्थक था, क्योंकि उनके होमरूल आन्दोलन का हिंसात्मक और अवैधानिक तरीकों से कोई सबध नहीं था। वे तो अहिंसात्मक सामूहिक प्रतिरोध को भी अवैधानिक तरीका स्वीकार नहीं करती थी, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने नजरबन्दी से रिहा होने के बाद ही कर दिया। वे जो कुछ करती थी, उसे सच्चे दिल से वैधानिक समझती थी। जो भी हो, लार्ड चेम्सफोर्ड उनके व्यवहार से सन्तुष्ट नहीं थे। उनकी धारणा थी कि श्रीमती बेसेंट आश्वासन का ठीक तौर से पालन नहीं कर रही हैं, और सरकार को उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करनी ही होगी। पर श्रीमती बेसेंट की पहली नजरबन्दी ने उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया था कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का चेम्सफोर्ड को साहस नहीं हुआ। श्रीमती बेसेंट अपने ढंग से अपना कार्य करती रही। दिसम्बर सन् १९१७ में उन्होंने

बड़ी शान से कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, और उसके बाद भी वे अपने ढंग पर अपनी सूझबूझ के अनुसार बड़ी तत्परता और निर्भीकता से काम करती रहीं। उनके विचारों और कार्य-प्रणाली से मतभेद हो सकता है, पर उनका साहस और लगन तो अवश्य ही प्रशंसनीय थे। वे जो उचित समझती, उसी को कहती और करती थी, फिर उसके सम्बन्ध में सरकार या जनता की कुछ भी प्रतिक्रिया क्यों न हो।

राजनीतिक सुधार

ब्रिटिश सरकार के लिए राजनीतिक चेतना की उपेक्षा असम्भव थी। राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता अनुभव करते हुए उनकी चर्चा उसने विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने के कुछ बाद ही शुरू कर दी थी। सन् १९१४ में उसने बम्बई के गवर्नर लार्ड विलिंगडन द्वारा गोखले से अनुरोध किया कि वे भावी राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में अपनी राय बतायें, और उन्होंने अपने निधन से कुछ पहले हिज हाइनेस सर आगा खान द्वारा अपनी राय सरकार के पास भिजवा दी।

इसी वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सब पुरानी व्यवस्थाओं, अधिनियमों को इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट (भारत प्रशासन अधिनियम) पास किया, और अगले वर्ष एक दूसरे अधिनियम द्वारा उसके कुछ अंशों को संशोधित किया।

कटिस-ड्यूक योजना

सन् १९१६ के प्रारम्भ में ही कटिस आदि की मदद से भारत-मन्त्री की कौंसिल के सदस्य सर विलियम ड्यूक ने प्रान्तों के प्रशासन को दो भागों में बाँट कर उसके एक भाग को विधान कौंसिल को उत्तरदायी मन्त्रियों को कुछ शर्तों के साथ हस्तान्तरित करने की योजना तैयार की। मई सन् १९१६ में यह योजना एक मेमोरंडम (प्रपत्र) के रूप में भारत सरकार के पास भेज दी गयी।

भारत सरकार की योजना

जून सन् १९१६ में लार्ड चेम्सफोर्ड ने गवर्नर-जनरल का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उन्होंने गुप्त रूप से एक दूसरी योजना तैयार की। यह योजना ड्यूक की प्रस्तावित योजना से बुरी थी। इसमें विधान कौंसिल के विस्तार की तो व्यवस्था थी, पर वित्तीय और प्रशासन के मामलों में विधान कौंसिलों के

नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी। केन्द्रीय कार्यपरिपद् के भारतीय सदस्य सर शकरन नायर को यह योजना पसन्द नहीं थी। उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ एक नोट में इसकी कड़ी समीक्षा की। भारत-मन्त्री सर आस्टिन चेम्बरलेन ने भी इस योजना को अपर्याप्त समझा। उन्होंने लिखा . “निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, जब तक हम उन्हें वित्त और प्रशासन के मामलों में किसी अंश में उत्तरदायित्व देने को तैयार न हो।”^१ इस पर वाइसराय ने भारत-मन्त्री को भारत की दशा का अध्ययन करने को आमंत्रित किया। चेम्बरलैन करीब-करीब राजी भी हो गये, और उन्होंने सुधारों के सम्बन्ध में एक घोषणा भी तैयार की।

भारतमन्त्री चेम्बरलैन का इस्तीफा

इसी वर्ष अर्थात् सन् १९१६ में मेसोपोटामिया में हिन्दुस्तानी फौज की करारी हार हुई, जिगके कारण भारत सरकार की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा, उसकी क्षमता की कड़ी आलोचना हुई। उधर अक्टूबर सन् १९१६ में केन्द्रीय विधान कौंसिल के उन्नीस सदस्यों ने सुधारों के सम्बन्ध में एक मेमोरंडम तैयार किया, और दिसम्बर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिल कर एक योजना तैयार की जिसका अगले वर्ष बड़े जोर से प्रचार किया गया। जुलाई सन् १९१७ में मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट पर आस्टिन चेम्बरलेन ने इस्तीफा दे दिया, और उनके स्थान पर १७ जुलाई को मिस्टर ई० एस० माटेग्यू भारत-मन्त्री नियुक्त हुए।

नीति घोषणा

२० अगस्त सन् १९१७ को भारत-मन्त्री माटेग्यू ने भारत के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति की व्याख्या करते हुए घोषित किया—शासन के हर विभाग में हिन्दुस्तान के निवासियों को अधिक से अधिक पद दे दिये जायेंगे, और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर उत्तरदायित्वपूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना के उद्देश्य से स्वायत्त शासन से सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओं का अनवरत विकास किया जायगा। इस सम्बन्ध में प्रान्तीय क्षेत्र में यथासंभव कदम उठाने का भी वचन दिया गया। भारत के राजनीतिज्ञों ने कुछ आलोचनाओं के साथ इस घोषणा का स्वागत किया।

वेसेंट का अभिभाषण

दिसम्बर सन् १९१७ में कलकत्ता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन हुए। श्रीमती एनी वेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यूरोप के साथ-साथ भारत में भी निरकुशता और नीकरशाही का आधिपत्य सत्तम होना चाहिए। “भारत की स्वतंत्रता ही भारत की राजभक्ति की शर्त है।” ‘साम्राज्य के लिए भारत की उपयोगिता की भी यही शर्त है।’ उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि स्वतंत्रता प्रत्येक राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है, और क्योंकि इस समय उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण हित बिना उसकी सहमति के ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के अधोन बना दिये गये हैं, और उसके साथनों का उसकी आवश्यकताओं के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भारत-मन्त्री की घोषणा का स्वागत करते हुए होमरूल और स्वशासन की मांग की पुष्टि की, और कहा कि केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान कौंसिलों में निर्वाचित सदस्यों का भारी बहुमत और थेली पर अधिकार, इन दो बातों पर हमें डटा रहना चाहिए।^१

कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा भारतमन्त्री की इस घोषणा पर कि उत्तरदायी शासन की स्थापना ही ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है, सन्तोष व्यक्त किया, और मांग की कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए पार्लियामेंट शीघ्र ही एक कानून पास करे, जिसमें इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने की अन्तिम तिथि भी निश्चित हो। उसने यह भी अनुरोध किया कि कांग्रेस-लीग योजना को उत्तरदायी शासन की पहली किस्त के रूप में शीघ्र चालू किया जाय।

कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और नेताओं की तरह मालवीयजीने भी कहा कि कांग्रेस-लीग योजना की स्वायत्त-शासन की मांग में उत्तरदायी शासन की स्थापना निहित है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों को उत्तरदायी प्रशासन ही स्वायत्तशासित होने का दावा कर सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र भावना की मांग है कि हम स्वयं अपने ऊपर शासन करें, और इसकी तुष्टि नितान्त आवश्यक है। उन्होंने कहा : “जब हम स्वायत्त शासन की बात करते हैं, तब हम उपनिवेशों जैसा स्वायत्त शासन चाहते हैं। उपनिवेशों में शासन परिषदें विधान सभाओं को उत्तरदायी है। इसलिए यह कहना गलत

हैं कि जब हम स्वायत्त शासन की मांग करते हैं, तब उत्तरदायी शासन से कुछ कम चाहते हैं।”

उन्होंने कहा कि शासन-व्यवस्था का उपखण्डों में विभाजन कुछ वर्षों में ही प्रशासन को “अप्रिय, क्षमताहीन तथा घृणित बनाने का अचूक उपाय” है। वह वास्तविक मुखारो में बाधा उपस्थित करेगा, और इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रान्तीय स्वतन्त्रता के साथ साथ केन्द्रीय सरकार में केन्द्रीय विधान कौंसिल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित भारतीयों का केन्द्रीय कार्यपरिषद में प्रवेश नितान्त आवश्यक है। उनकी धारणा थी कि यदि जनता के प्रतिनिधियों को कार्यपरिषद के सदस्यों को चुनने का अधिकार प्राप्त हो गया, तब वे लोग, जिनके विचार ‘प्रतिक्रियावादी’ हैं, जो प्रगतिशील नहीं हैं, और जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है, कार्यपरिषद के सदस्य नहीं हो पायेंगे।^१

इस सबसे यह स्पष्ट है कि जब कि कुछ प्रशासक कर्टिस की द्विविध शासन व्यवस्था का समर्थन करते थे, मालवीयजी आदि अधिकांश कांग्रेसी नेता कांग्रेस-लीग योजना को कर्टिस की योजना से अच्छा समझते थे। उनका विचार था कि प्रान्तीय शासन के कुछ विभागों में बहुत से प्रतिवन्धों के साथ उत्तरदायी व्यवस्था को प्रतिष्ठित करना इतना श्रेयस्कर नहीं होगा, जितना कि प्रान्त और केन्द्र में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की प्रशासन में बराबर की साझेदारी और विधान सभाओं का शासन पर व्यापक नियन्त्रण।

मान्टेग्यू

सन १९१७ के जाडो में २० नवम्बर को भारतमन्त्री मान्टेग्यू हिन्दुस्तान आये। उनके साथ इंडिया कौंसिल के सदस्य भूपेन्द्रनाथ वसु तथा सर विलियम ड्यूक (Duke), लार्ड डीनोमीर और मिस्टर चार्ल्स राबर्ट्स भी आये।

उन्होंने लार्ड चेम्सफोर्ड के साथ देश की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया, और इस उद्देश्य से कतिपय महाराजाओं और सरकारी अफसरों के अतिरिक्त बहुत से प्रमुख राजनीतिज्ञों से बातचीत की। उन्होंने नरमदलीय नेताओं को यह भी संकेत किया कि नयी सुधार योजना को सफल बनाने के लिए सहयोग के समर्थक अलग से अपने को एक माडरेट (नरम) पार्टी में गठित करें। इस काम में उन्हें काफी सफलता मिली। बहुत से पुराने कांग्रेसी नेताओं ने इस

सुझाव का स्वागत किया ।^१ भारत-मन्त्री ने उन्हें ड्यूक मेमोरंडम पर आश्रित अपनी सुधार योजना का समर्थन करने के लिए भी बहुत हद तक तैयार कर लिया । वे मालवीयजी को भी अपनी ओर खींचना चाहते थे, पर मालवीयजी तैयार नहीं हुए । वे कांग्रेस-लीग योजना पर डटे रहे । वे ड्यूक की योजना का समर्थन करने को तैयार नहीं थे । उनके विचार में प्रान्तीय शासन के एक छोटे से भाग में बहुत सी शक्तों के साथ उत्तरदायी शासन स्थापित करने से काम नहीं चल सकता । उन्होंने भारत-मन्त्री से स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधान सभाओं का अर्थात् जनता के प्रतिनिधियों का शैली पर अधिकार और प्रशासन पर नियंत्रण भारत की राजनीतिक समस्या का मूल प्रश्न है, और यदि इसकी सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं हुई तो आन्दोलन होगा ।^२

सुधार योजना

जून सन् १९१८ में माटेग्यू और चेम्सफोर्ड द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट प्रकाशित की गयी । इसमें मार्ले-मिटो सुधारों की समीक्षा करते हुए, उनकी कमजोरियों और कमियों की ओर ध्यान दिलाते हुए, तथा भारतीय राजनीतिज्ञों की माँगों और आकांक्षाओं पर विचार करते हुए नये सुधारों के सम्बन्ध में सन्तुष्टियाँ की गयी ।

इस नयी योजना में किन्ही अंशों में पहली बार विधान-मण्डलों का पृथक् अस्तित्व स्वीकार किया गया, तथा केन्द्र में विधान-मंडल के दो सदन स्थापित करने का सुझाव दिया गया । विधान सभाओं में गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्यों को बहुसंख्यक स्थान दिये जाने की राय दी गयी । प्रत्यक्ष चुनाव की प्रथा चालू करने की भी संस्तुति की गयी । विधान कौंसिलों को बजट स्वीकार करने की व्यवस्था की भी सिफारिश की गयी । रिपोर्ट में सन्तुष्टि की गयी कि शासन-व्यवस्था को विकेंद्रित कर कतिपय विषयों का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों के सुपुर्द कर दिया जाय, तथा इनमें से कुछ विषय गवर्नर और उसकी कार्यपरिषद् के हाथ में सुरक्षित रहे, और कुछ विषयों का प्रबन्ध प्रान्तीय विधान सभा को उत्तरदायी मन्त्रियों को हस्तान्तरित कर दिया जाय । पर गवर्नर और गवर्नर-जनरल को अधिकार हो कि वे जब उचित समझें विधान कौंसिल और मन्त्री की राय की उपेक्षा करते हुए उन हस्तान्तरित विषयों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप कर

१ माटेग्यू : इंडियन डायरी, पृ० २१७ ।

२. माटेग्यू : इंडियन डायरी, २७ नवम्बर १९१७ ।

सकें, और उन्हें सुरक्षित विषयो में बदल कर उनका प्रबन्ध कार्य परिषद् के सुपुर्द कर दें। इस योजना में केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-मण्डलो की राय और वोट की उपेक्षा करते हुए गवर्नर-जनरल और गवर्नर को कानून बनाने और कर लगाने के विशेष अधिकार की भी व्यवस्था की गयी।

सन् १९०९ की व्यवस्था की तुलना में प्रस्तावित योजना कही अच्छी थी। पर जनजागृति और जनता की आकांक्षाओं की तुलना में बहुत कम थी। भारत के राजनीतिज्ञों में इसके सम्बन्ध में मतभेद था। सभी चाहते थे कि इसमें कुछ सुधार हो। पर जहाँ कुछ राजनीतिज्ञ इसकी कमियों और त्रुटियों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसकी कड़ी आलोचना करते थे, कुछ इसकी अच्छाइयों पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करते हुए उसका प्रयोग करने पर जोर देते थे।

मालवीयजी की समीक्षा

मालवीयजी ने इस योजना का विस्तृत विश्लेषण करते हुए एक लम्बे लेख में स्वीकार किया कि इन सुझावों में बहुत-सी बातें अवश्य ही "उदार" हैं, और उनसे सही दिशा में वास्तविक और हितकारी परिवर्तन होगा। पर उन्होंने कहा कि इनमें कुछ "भारी कमियाँ" हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है।^१ उनकी राय में रिपोर्ट में, २० अगस्त सन् १९१७ की घोषणा की सकीर्ण व्याख्या करने के कारण, उत्तरदायी शासन की ओर प्रगति की गति धीमी है, और ब्रिटिश जनता और पार्लियामेंट के उत्तरदायित्व पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। रिपोर्ट में समस्या की दशाओं का जो विश्लेषण किया गया है, उसके पढ़ने से ऐसा आभास होता है कि उत्तरदायी शासन को चालू करने के विरुद्ध जो परिस्थितियाँ हैं उन पर बहुत बड़ा चढ़ा कर विचार किया गया है, और जो (परिस्थितियाँ) उनके पक्ष में हैं उन्हें कम किया गया है, उनकी उपेक्षा की गयी है।^२

उन्होंने लिखा कि प्रजा के हितों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, पर यह भुला दिया गया है कि पिछले ६० वर्षों में जनता की हितवृद्धि के लिए नौकरशाही ने कुछ नहीं किया है। जनता के अभ्युदय से सम्बन्धित सेवाओं को चालू करने की बात को घन की कमी की चर्चा करके टाल दिया गया है। गरीबी

१ आनरेबिल पंडित मदनमोहन मालवीय लाइफ एन्ड स्पीचेज, पृ० ६२४।

२. वहीं, पृ० ६३३।

और शिक्षा की कमी को जनता को अपने अधिकारों से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका उत्तरदायित्व मुख्य रूप से ब्रिटेन के मतदाताओं और उनके एजेन्टों पर है, जिन्होंने कांग्रेस और विधान कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों की सस्तुतियों की उपेक्षा करते हुए उन्हें दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। साम्प्रदायिक मतभेद और तनाव भारत में अवश्य है, पर दूसरे बहुत से स्वशासित देशों में भी ये किसी न किसी रूप में पाये जाते हैं। भारत के शिक्षित वर्ग ने, जिसके हाथ में स्वशासन की पूरी मात्रा सौंपने से घबड़ाहट प्रकट की जाती है, नौकरशाही से कहीं अधिक जनता के अभ्युदय का ध्यान रखा है। प्राकृतिक अधिकार और न्याय के आधार पर भारतीय अपने देश के शासन में भाग लेना चाहते हैं, और मिस्टर माटेग्यू तथा लार्ड चेम्सफोर्ड भले ही अपने को यह समझा लें कि भारत अभी उत्तरदायी शासन प्रथा के योग्य नहीं है, पर भारतीय जनता उनके तर्कों से सन्तुष्ट नहीं होने वाली है।^१

मालवीयजी ने बताया कि भारतीय शिक्षितों ने ईसाई मिशनरियों के प्रति कभी वैर नहीं रखा, और स्वतन्त्र भारत में भी वे अपना काम चालू रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह समझना भी भारतीय जनता के साथ अन्याय होगा कि यदि उन्हें अधिकार मिले, तो वे अंग्रेज व्यापारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध उनका प्रयोग करेंगे। यह सन्देह कैसे किया जा सकता है कि उत्तरदायी शासन मिलने पर भारतीय प्रतिनिधि पुराने आर्थिक इकरारनामों को रद्द कर देंगे, या वे विदेश से व्यापार चालू रखने की, और देश के आर्थिक विकास के निमित्त विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता की उपेक्षा करेंगे?^२

मालवीयजी ने इस लेख में यह भी बताया कि, "स्वशासन की पूरी मात्रा", जिसे भारतीय जनता चाहती है, उसे दे भी दी गयी, तो भी प्रशासन की मौजूदा व्यवस्था जड़ से उखड़ नहीं जायेगी।^३ प्रशासन का सम्पूर्ण ढाँचा जो सौ वर्ष में बनाया गया है, अटल बना रहेगा। न्याय का शासन हाईकोर्टों के अधीन रहेगा। कानूनों का मौजूदा ढाँचा भी चालू रहेगा। यदि नयी विधान कौंसिल, किसी अधिनियम को बदलना या रद्द करना चाहेगी, तो ऐसा करने की उसमें शक्ति नहीं होगी, जब तक सरकार का प्रधान उस विधेयक को

१. वही, पृ० ६४८-५५४।

२. वही, पृ० ६५६।

३. वही, पृ० ६५७।

स्वीकार न करे, जिसके द्वारा यह सब कुछ किया जायगा। मौजूदा पदाधिकारियों द्वारा ही लोकसेवाओं में काम चलता रहेगा, और यदि भविष्य में पचास प्रतिशत ऊँचे पद भारतीयों द्वारा भरे गये तो भी बहुत काल के बाद इन सेवाओं के आधे भाग का ही भारतीयकरण हो सकेगा।^१

इस लेख में मालवीयजी ने यह भी बताया कि यद्यपि प्रस्तावित योजना में कांग्रेस-लीग के कुछ सुझाव शामिल कर लिये गये हैं, पर उसके अत्यावश्यक लक्षण को अर्थात् जनता के प्रतिनिधियों के साथ शासन की शक्ति की साझेदारी को बहुत अंश तक छाँट दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ हस्तान्तरित विषयों में ही प्रान्तीय विधान सभाओं को अधिकार दिया है।

उन्होंने कहा कि यदि भारतमन्त्री और गवर्नर-जनरल जनता के प्रतिनिधियों के साथ शासन का अधिकार उस मात्रो में बाँटने को तैयार हो जिसकी कांग्रेस-लीग योजना में सन्तुष्टि की गयी है, तो उस योजना में सशोधन और परिवर्तन करके उन आपत्तियों का, जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, निराकरण किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि विश्वयुद्ध ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को पूरे तीर से सिद्ध कर दिया है, पर उसकी ओर जितना ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया गया है। मिस्टर मान्टेग्यू और लार्ड चेम्सफोर्ड ने यह तो स्वीकार किया है कि भारतीयों की दृष्टि में फौज में ब्रिटिश कमीशन का प्रश्न और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पर रिपोर्ट में उसके सम्बन्ध में कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया है।^२

मालवीयजी ने बताया कि रिपोर्ट में हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति की कमजोरी तो नोट की गयी है, यह भी स्वीकार किया गया है कि भारतीय उसे सुधारना चाहते हैं, और आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक सभी दृष्टि से देश का औद्योगिक विकास आवश्यक है, पर उसके लिए कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया है। मालवीयजी ने बताया कि यदि भारत का औद्योगिक विकास ठीक तौर पर किया जाना है, तो भारत को वित्तीय स्वशासन प्रदान किया जाना चाहिए, अर्थात् केन्द्रीय सरकार में जनता के प्रतिनिधियों को नीति निर्धारित करने का अधिकार मिलना चाहिए।^३

१. वही, पृ० ६५७-६५८।

२. वही, पृ० ६५८-६६०।

३. वही, पृ० ६६४।

उन्होंने माँग की कि “प्रान्तीय सरकार को फौरन स्वायत्त बना देना चाहिए, और समय की अवधि निश्चित कर देनी चाहिए जिसके अन्दर भारत की केन्द्रीय सरकार में भी पूरा उत्तरदायी शासन स्थापित होना चाहिए।”^१ अगर इसके लिए बीस वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, यद्यपि बहुत से हिन्दुस्तानियों को यह अवधि बहुत लम्बी दिखाई देगी।^२ उन्होंने लिखा कि इस अवधि को निश्चित करने के बाद कम से कम पचास प्रतिशत योग्यता-सम्पन्न भारतीयों की फौज तथा सिविल विभागों में नियुक्तियाँ की जायें, ताकि भारतीयों को विश्वास हो जाय कि “भविष्य में इंगलिस्तान भारत के साथ साझी जैसा, न कि अधीन क्षेत्र जैसा व्यवहार करना चाहता है।”^३

इस लेख में मालवीयजी ने यह भी माँग की कि भारत सरकार की एक्जिक्यूटिव कौंसिल के आधे सदस्य भारतीय हों, यदि राज्य सभा (कौंसिल आफ स्टेट) स्थापित की जाय तो उसके आधे सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जायें जिनमें भारतीयों की अधिकता हो, और स्पष्ट तौर पर यह निर्धारित करने के बाद कि कुछ राज्य सेवाओं के खर्चे पर, विशेष रूप से देश की रक्षा के निमित्त फौजी खर्चे पर, गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल की स्वीकृति के बिना कोई कटौती नहीं की जायगी, यह निश्चय किया जाय कि वजट लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा बहुमत से पास किया जायगा।^४

प्रान्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में मालवीयजी का सुझाव था कि प्रान्तीय विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी जाय, और मतदान के अधिकार को यथासंभव व्यापक किया जाय, ताकि सभी आवश्यक हितों का, किसानों का भी, उचित प्रतिनिधित्व हो सके। वही सज्जन मन्त्री नियुक्त हों, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों के बहुसंख्यकों का विश्वास प्राप्त हो। यद्यपि वे विशेष रूप से किसी विषय के चार्ज में होंगे, पर वे प्रान्त की एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सदस्य होंगे। कोई संरक्षित विषय नहीं होगा। यदि किसी विषय का संरक्षण हो तो केवल इतना कि गवर्नर-इन-कौंसिल की स्वीकृति के बिना सुरक्षा और सुव्यवस्था विभाग से सम्बन्धित खर्चा कम नहीं किया जायगा। गाड कमेटी का सुझाव छोड़ दिया जायगा। सुधारों के जो सिद्धान्त दूसरे प्रान्तों के लिए

१. वही, पृ० ६६७।

२. वही, पृ० ६६७।

३. वही, पृ० ६७०।

४. वही, पृ० ६९४।

निश्चित होंगे, उन विशिष्ट सरक्षणों के साथ जिनकी वह माँग करें, बर्मा में भी लागू होंगे ।^१

अन्त में मालवीयजी ने लिखा कि भारत चाहता है कि इंगलिस्तान उसके प्रति न्यायी हो । उसकी माँग है कि उसके भावी संविधान को निश्चित करने में, इंगलिस्तान उस न्याय तथा अपना भाग्य निर्णय करने के जनता के अधिकार पर अमल करेगा, जिनके लिए वह सम्भवत इतिहास के सबसे अधिक शानदार (गौरवपूर्ण) युद्ध में सलग्न है, और जिसमें उसे भारत ने अपने रक्त और धन से सहायता दी है । इंगलिस्तान और भारत दोनों परीक्षण पर है । ईश्वर भारतीयों की पूरी मात्रा के लिए आग्रह करने की, और अंग्रेजों को उसे स्वीकार करने की दूरदर्शिता की स्पष्टता तथा साहस प्रदान करें ।^२

एकता का प्रयत्न

कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों में भारत-मन्त्री और वाइसराय द्वारा प्रस्तुत योजना के सम्बन्ध में गहरा मतभेद हो जाने के कारण कांग्रेस टूटती दिखाई देती थी । मालवीयजी एकता बनाये रखना चाहते थे और इसके लिए मध्यमार्ग का अनुसरण आवश्यक समझते थे । वे नये सुधारों को बिल्कुल ठुकरा देना या बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लेना, दोनों गलत समझते थे । वे प्रस्तावित सुधारों का स्वागत करते हुए उनकी त्रुटियों के सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहते थे । वे इसके लिए देश के प्रगतिशील तत्त्वों में, विशेष तौर पर कांग्रेस-जनो में, ऐक्य नितान्त आवश्यक समझते थे । उनका ऐक्य सम्बन्धी प्रयास पूरे तौर पर सफल नहीं हुआ ।

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन

अगस्त के प्रथम सप्ताह में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने श्रीमती बेसेंट को तार दिया कि विशेष अधिवेशन कुछ समय के लिए टाल दिया जाय, पर यह नहीं हो सका । सर्वश्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दिनशा इंदुलजी वाचा, भूपेन्द्रनाथ वसु, अम्बिकाचरण मजूमदार आदि कांग्रेस के कई पुराने सम्मानित नेता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जो बम्बई में २९ अगस्त १९१८ को आयोजित हुआ, शामिल नहीं हुए । उन्हें समझाकर बुलाने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन एक दिन के लिए स्थगित किया गया । पर मालवीयजी के अनुरोध पर भी दिनशा इंदुलजी वाचा

१. वही, पृ० ६९५ ।

२. वही, पृ० ६९७-६९८ ।

ने कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। बहुत से दूसरे सम्मानित नेता तो बम्बई आये ही नहीं थे। इस तरह कांग्रेस दो भागों में बंट गयी। फिर भी कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों ने, जिनमें कुछ नरमदलीय और अधिकांश गरमदलीय थे, मध्यमार्ग का अनुसरण ही उचित समझा।

विषय समिति की ओर से मालवीयजी ने जो प्रस्ताव पेश किया, उसमें भारत में उत्तरदायी शासन को प्रारम्भ करने के लिए भारतमन्त्री और वाइसराय के प्रयास की सराहना की गयी। जबकि यह स्वीकार किया गया कि 'कुछ दिशाओं में मौजूदा हालातों से उनके कुछ प्रस्ताव प्रगतिशील हैं', यह भी कहा गया कि 'प्रस्तावित सुधार अपर्याप्त और असन्तोषजनक' हैं। प्रस्ताव में उत्तरदायी सरकार की ओर ठोस कदम लिये जाने के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से आवश्यक सशोधन प्रस्तुत किये गये।

प्रस्ताव में माग की गयी कि केन्द्रीय सरकार में भी सरक्षित और हस्तांतरित विषयों की प्रथा अंगीकार की जाय, तथा वैदेशिक मामलों, फौज, नौ सेना, देशीय राजाओं से सम्बन्ध, तथा देश की शान्ति और रक्षा से संबंधित विषय ही सरक्षित विषय हों। संरक्षित विषयों का खर्चा राजस्व पर पहली जिम्मेदारी हो। सरक्षित विषयों के लिए उत्तरदायी एक्जिक्यूटिव कौंसिल के आधे [सदस्य हिन्दुस्तानी हों। राज्य सभा (कौंसिल आफ स्टेट) न बनायी जाय, और अगर गठित हो तो उसके आधे सदस्य भारतीय हों। सर्टिफिकेशन (बिलों को वाइसराय द्वारा प्रमाणित करने) की प्रक्रिया और रेगुलेशन द्वारा कानून बनाने की विधि केवल सरक्षित विषयों तक सीमित रहे। पार्लियामेंट के कानून द्वारा गारंटी दी जाय कि पन्द्रह वर्ष में पूर्ण उत्तरदायी शासन सारे ब्रिटिश इंडिया में स्थापित कर दिया जायगा। यद्यपि कांग्रेस की दृष्टि में प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए भारत पूर्णतः योग्य है, फिर भी छः वर्ष के लिए कानून, पुलिस और न्याय (जेल को छोड़कर) विभागों को संरक्षित विषय स्वीकार करने को कांग्रेस तैयार है। पर इन संरक्षित विषयों के भारधारक सदस्यों में आधे हिन्दुस्तानी होंगे। केन्द्रीय और प्रान्तीय असेम्बली के अस्सी प्रतिशत सदस्य निर्वाचित सदस्य हों। सब कानून असेम्बली द्वारा पास हों, और वजट भी असेम्बली के अधीन हो। प्रान्तीय संरक्षित विषयों के खर्चों के लिए प्रान्तीय कौंसिल की पूरी अवधि के लिए एक निश्चित धनराशि दी जाय। यदि बीच में अधिक करो की आवश्यकता हो, तो वे पूरी प्रान्तीय सरकार द्वारा, जिसमें

हस्तान्तरित और सरक्षित विषय सम्मिलित है, निश्चित हो। यदि किसी सरक्षित विषय पर प्रान्तीय सरकार कोई ऐमा कानून बनाना चाहती है, जिसकी स्वीकृति देने को प्रान्तीय विधान सभा तैयार नहीं है, तब वह उसका विधेयक केन्द्रीय सरकार के पास भेज सकती है, जो यदि वह उचित समझे तो उसे केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्तुत कर सकती है, और वह वहाँ रवीकृत किया जा सकता है। प्रान्तीय मन्त्री प्रान्तीय विधान सभा को उत्तरदायी होंगे और उनकी पदवी, स्टेट्स (महत्त्व) और वेतन एक्जिच्यूटिव कौंसिलों के सदस्यों के समान होगा। भारत-मन्त्री की कौमिल भग कर दी जायगी, तथा दो उपभारत-मन्त्री नियुक्त होंगे जिनमें से एक भारतीय होगा। इंग्लैंड के इंडिया आफिस का सब खर्चा ब्रिटिश राजकोष से किया जायगा। सरक्षित विषयों के प्रशासन और वित्तीय अधिकारों का कंट्रोल भारत-मन्त्री और ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के अधीन होगा। कांग्रेस-लीग योजना के अनुसार मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जायगा। सब वित्तीय मामलों में भारत सरकार को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी।^१

मालवीयजी का यह प्रस्ताव, जो भारी बहुमत से स्वीकार हुआ, मूलरूप से उनके लेख में दिये गये सुझावों पर आधारित था, मूल भेद इतना ही था कि जबकि मालवीयजी का सुझाव था कि बीस वर्ष में पूरा उत्तरदायी शासन स्थापित हो जाय, प्रस्ताव में यह अवधि घटाकर पन्द्रह वर्ष कर दी गयी थी और जब कि मालवीयजी ने अपने लेख में गाग की थी कि सब प्रान्तीय विषय उत्तरदायी मन्त्रियों को फौरन हस्तान्तरित कर दिये जायें, प्रस्ताव में छ वर्ष तक कानून, पुलिस और न्याय विभागों का सरक्षित विषय बनाये रखने का सुझाव था। मालवीयजी ने अपने लेख में सुझाव दिया था कि मन्त्रिगण प्रान्तीय विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को ही उत्तरदायी हों, उसके बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास प्राप्त करना ही उसके लिए आवश्यक हो, प्रस्ताव में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं थी अर्थात् इस प्रश्न पर निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों का भेद नहीं किया गया था। दूसरी तरफ जबकि मालवीयजी के लेख में उपभारत मन्त्री, इंडिया कौंसिल तथा इंडिया आफिस की कोई चर्चा नहीं थी, प्रस्ताव में इनके सम्बन्ध में ठोस सुझाव दिये गये थे।

इस सम्बन्ध अधिवेशन में सविधान से सम्बन्धित तीन अन्य प्रस्ताव भी पास किये गये। पहले प्रस्ताव में कांग्रेस-लीग योजना के सिद्धान्तों पर अपनी आस्था दोहराते हुए घोषित किया गया कि साम्राज्य के अन्दर स्वायत्त शासन से कम कोई चीज भारतीय जनता को सन्तुष्ट नहीं कर सकती है, और ब्रिटिश

कामनवेल्थ में स्वतंत्र और स्वशासित राष्ट्र का उचित स्थान ही ग्रेट ब्रिटेन और भारत के सम्बन्ध को दृढ़ कर सकता है। दूसरे प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने घोषित किया कि भारतीय जनता उत्तरदायी शासन के योग्य है, और वह रिपोर्ट में दी गयी इसके विपरीत धारणाओं का खण्डन करती है।

तीसरे प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने स्वीकार किया कि देश की शान्ति और रक्षा के मामले पर भारत सरकार का पूरा (अविभाजित) प्रशासकीय अधिकार बना रहे, पर मांग की कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून द्वारा भारतीय जनता के मौलिक अधिकार सुरक्षित किये जायें, यह घोषित किया जाय कि सब नागरिकों को कानून में समान अधिकार होंगे, और किसी फौजदारी या प्रशासनीय कानून में सम्राट् की प्रजा में कोई भेद नहीं किया जायगा। सम्राट् की कोई भारतीय प्रजा न्यायसंगत खुले मुकदमे के जरिये साधारण न्यायालय की दण्डाज्ञा (सजा) के अतिरिक्त अपनी स्वतंत्रता, जीवन, सम्पत्ति, स्वतंत्र भाषण और लेखन के अधिकार से वंचित नहीं की जायगी। सम्राट् की किसी भारतीय प्रजा को किसी ऐसे मामले में शारीरिक सजा नहीं दी जायगी, जिसमें ब्रिटिश प्रजा को ऐसी सजा देने का विधान नहीं है। प्रेस स्वतंत्र होगा, और किसी समाचार पत्र या प्रेस के रजिस्ट्रेशन से कोई लाइसेंस या जमानत नहीं मांगी जायगी। ग्रेट ब्रिटेन की तरह भारत में भी हथियार रखने का सारी भारतीय प्रजा को अधिकार होगा। साधारण न्यायालय की दण्डाज्ञा द्वारा ही यह अधिकार छीना जा सकता है। इस अधिवेशन में यह भी मांग की गयी कि इंडियन सिविल सर्विस में ५० प्रतिशत भारतीय भरती किये जायें, तथा कम से कम पचीस प्रतिशत सैनिक कमीशन भी भारतीयों को देने का प्रवन्ध किया जाय।

बम्बई के विशेष अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादियों का बहुमत था। लोकमान्य तिलक उनके प्रमुख नेता थे। यदि वे चाहते तो नरमदलीय प्रतिनिधियों के विचारों की विल्कुल उपेक्षा करते हुए अपने मन का प्रस्ताव स्वीकार करा सकते थे, अपने ढंग से सुझावों की कड़ी आलोचना कर सकते थे, पर वे भी इस अवसर पर यथासंभव एकता बनाये रखना आवश्यक समझते थे और सभी विचार-धाराओं के प्रतिनिधियों की सहमति से प्रस्ताव पास किया जाना उचित समझते थे। इसी लिए अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए जब उनके नाम की चर्चा होने लगी, तब उन्होंने सैयद हसन इमाम को अध्यक्षता के लिए तैयार किया।

इस अधिवेशन में समझौते की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने में मालवीयजी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने बम्बई में उपस्थित नरमदलीय नेताओं

से विशेष अधिवेशन में शामिल होने के लिए बहुत विनय की और जब वे नहीं आये तब भी मेल-मिलाप की कोशिश करते रहे। मालवीयजी के प्रयत्नों से ही सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव इस रूप में स्वीकार हुआ कि अधिवेशन में उपस्थित नरमदलीय प्रतिनिधियों को उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्रीमती बेसेन्ट के विचार में यह अधिवेशन तो मालवीयजी का ही था। इसकी सफलता का मुख्य श्रेय उन्हीं को था।

मालवीयजी वास्तव में कांग्रेस की फूट से दुःखी थे। उनकी धारणा थी कि ब्रिटिश नौकरशाही को ही इससे लाभ होगा, और प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को ही इससे बल मिलेगा। प्रस्तुत सुधार योजना में भारत के हित की दृष्टि से परिवर्तन तभी हो सकता है, जब सब भारतीय राजनीतिज्ञ मिलकर इसके लिए प्रयत्न करें। इसलिए वम्बई अधिवेशन के बाद भी मालवीयजी मेल मिलाप के लिए प्रयत्न करते रहे। उन्होंने नरमदलीय नेताओं से आग्रह किया कि वे अलग अपनी सस्था बनाने के बजाय कांग्रेस में आकर अपने विचारों से उसके निर्णयों को प्रभावित करें।

मालवीयजी का अभिभाषण

सन् १९१८ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में मालवीयजी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की दिल्ली में अध्यक्षता की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में अमरीका के राष्ट्रपति विलसन के १४ सूत्रीय कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि विलसन साहब की दृष्टि में अन्तरराष्ट्रीय न्याय का कोई भी ढांचा तब तक स्थिर नहीं हो सकता, जब तक वह सब जातियों और राष्ट्रों के प्रति न्याय तथा एक दूसरे के साथ स्वतंत्रता और संरक्षता के समान अधिकार पर आश्रित न हो। मालवीयजी ने आशा व्यक्त की कि सन्वि कान्फ्रेंस में इन सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने की कोशिश की जायगी। उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि सन्वि कान्फ्रेंस में भारत के प्रतिनिधि को नियुक्त करते समय जनता के प्रतिनिधियों से इसके सम्बन्ध में कोई राय नहीं ली गयी।^१

उन्होंने माग की कि आत्मनिर्णय का सिद्धान्त भारत में भी लागू किया जाय, और नये विधान की भूमिका में इसे व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया जाय कि पूर्ण उत्तरदायित्व की ओर अगले कदमों के निर्णय में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की प्रभावकारी आवाज (अधिकार) होगी। उन्होंने कहा कि सारा

१. रिपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, १९१८ का अधिवेशन, पृ०

के दूसरे राष्ट्रो की तरह हमें भी स्वशासन प्राप्त करने का अधिकार है। केम्पल वेनरमैन ने ठीक ही कहा है कि "अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है।"^१ उन्होंने कहा : "स्वशासन ही हमारी शिकायतों का इलाज है"^२ "हम राष्ट्रीय आत्मविकास का सुअवसर चाहते हैं।"^३ रीलेट कमेटी ने जिस परिस्थिति पर खेद प्रकट किया है, उसका इलाज 'दमनकारी कानून बनाना नहीं है, बल्कि विस्तृत और उदार सुधारों को देना है' जो असतोप के मूल कारण को दूर करेगा और भारतीय जनता में सतोप पैदा करेगा।^४

मालवीयजी ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तथा नरमदल की कांग्रेसों के निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि ये तीनों चाहते हैं कि (१) स्वायत्तशासन का सिद्धांत केंद्र तथा प्रांत, दोनों में व्यवहृत किया जाय, और सुधार की पहली किस्त में ही केन्द्रीय शासन को भी दो भागों में बांट दिया जाय, एक सरक्षित, दूसरा हस्तांतरित, (२) भारत को राजकोष की स्वतंत्रता मिल जाना चाहिए, (३) राज्यसभा में आधे निर्वाचित सदस्य हों, (४) सरक्षित विषयों की अधिकारिणी कार्यपरिषद में आधे सदस्य भारतीय हों, (५) विधानसभाओं को अपने सभापति, उपसभापति चुनने का अधिकार हो, (६) विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत अस्सी प्रतिशत हो, (७) सरक्षित विषयों की संख्या जितनी कम हो सके उतनी कम हो, हस्तान्तरित विषय अधिक हों, (८) कार्य परिषद के सदस्यों तथा मंत्रियों का पद बराबर हो, (९) न्याय और शासन के विभाग अलग कर दिये जायें, (१०) भारतीय सिविल सर्विस में पचास प्रतिशत तथा सम्राट् के फौजी कमीशन में पचीस प्रतिशत उच्च पद प्रारम्भ से भारतीयों को मिलने चाहिए और सैनिक शिक्षा का देश में ही समुचित प्रबंध हो, (११) साधारण वैध अधिकारों की—जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, सार्वजनिक सभाओं की स्वतंत्रता, खुली अदालत में मुकदमों की सुनवाई का अधिकार—उचित रक्षा की जाय, (१२) भारतमन्त्री की कौंसिल खत्म कर दी जाय।^५

दिल्ली अधिवेशन के प्रस्ताव

कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन ने दो सशोधनों के साथ बम्बई अधिवेशन में स्वीकृत राजनीतिक सुधार सम्बन्धी चारों प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। मुख्य सशोधन प्रांतीय व्यवस्था के संबंध में था। जबकि बम्बई अधिवेशन

१ वही, पृ० ३४।

२ वही, पृ० ३८।

३ वही, पृ० ३८।

४ वही, पृ० ३९।

५ वही पृ० २८-२९।

मे कानून, पुलिस और न्याय विभागों को छ वर्ष के लिए सरक्षित विषय रखना तय हुआ था, दिल्ली अधिवेशन में निश्चय हुआ कि जहाँ तक प्रांतों का सम्बन्ध है पूर्ण उत्तरदायी शासन फौरन प्रदान किया जाय, और ब्रिटिश भारत का कोई भाग प्रस्तावित सवैधानिक सुधारों के लाभ से वर्जित न किया जाय। इस सशोधन के साथ साथ यह भी पास किया गया कि गैरसरकारी यूरोपियनों को इस आधार पर कि वे खनन और चाय उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पृथक् निर्वाचित क्षेत्र बनाने की इजाजत न दी जाय, और यदि इस प्रकार की अनुमति दी जाय तो उनका प्रतिनिधित्व सम्बद्ध प्रांत की जनसंख्या में उनका जो अंश है उसके हिसाब से ही हो, अर्थात् अनुपात से अधिक न हो। इस अधिवेशन में यह भी निश्चय किया गया कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान वोट का अधिकार दिया जाय, और उनके इस अधिकार पर लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाय।

कांग्रेस ने दमनकारी कानूनों को वापस लेने, तथा राजनीतिक कैदियों और नजरबंदों को छोड़ने की मांग की, और आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्णय का सिद्धान्त भारत में भी लागू किया जायगा। उसे भी एक प्रगतिशील राष्ट्र स्वीकार किया जायगा, और भारत को लीग ऑफ नेशन्स (राष्ट्रसंघ) में वही स्थान दिया जायगा जो स्वशासित डोमिनियनों को प्राप्त होगा। कांग्रेस ने लोकमान्य तिलक, सैयद हसन इमाम तथा गांधीजी को शान्ति कांग्रेस के लिए अपना प्रतिनिधि चुना।

कांग्रेस में किसानों का प्रवेश

कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन काफी सफल अधिवेशन था। उसमें ४८६९ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें ६८८ किसान प्रतिनिधि थे। इनमें से अधिकांश युक्त प्रान्त के थे, जो बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, बरेली, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतहपुर, इलाहाबाद, बलिया, आजमगढ़, अलमोड़ा, बिजनौर, बादा, देहरादून, एटा, इटावा, फैजाबाद, गाजीपुर, गोडा, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, जौनपुर, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, उन्नाव, आदि जिलों से अर्थात् युक्त प्रान्त के दो तिहाई से अधिक जिलों से आये थे। इसके अतिरिक्त बहुत से किसान प्रतिनिधि मध्यप्रदेश के खड़वा, बिलासपुर, होशंगाबाद से, बिहार के चम्पारन, शाहाबाद, पटना जिलों से, पंजाब के रोहतक, करनाल, हिसार आदि स्थानों से, मद्रास के नैलोर और चिन्नलपुर से आये थे। इनके अतिरिक्त राजपूताना

के भरतपुर विजोलिया के कुछ किसान भी उपस्थित थे । मालवीयजी ने किसानों का बहुत हर्ष से स्वागत किया, उनसे प्रतिनिधि शुल्क लिये बिना उन्हें प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लेने की स्वीकृति दी । नि सन्देह इतनी बड़ी सख्या में पचास जिलों के किसानों की उपस्थिति भारत के राजनीतिक जीवन की महत्त्वपूर्ण घटना थी, भारत की राजनीतिक चेतना और जनजागृति का अच्छा प्रदर्शन था, इस बात की द्योतक थी कि किसानों में भी जागृति पैदा होने लगी है और भविष्य में भारत के राजनीतिक आन्दोलन में उनका भी योगदान होनेवाला है ।

अन्त में मालवीयजी ने अधिवेशन के प्रबन्धकों को धन्यवाद देते हुए किसान और मुसलमान प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर विशेष रूप से हर्ष प्रकट किया । उन्होंने कहा. "ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं है ।" "लोग पुरुष और स्त्री में भेद करते हैं, पर जहाँ तक ईश्वर की ज्योति का प्रश्न है, दोनों में बिल्कुल भेद नहीं है ।" ^१ उन्होंने कहा कि स्त्रियों को देशहित के लिए काम करना चाहिए, उन्हें भय छोड़ देना चाहिए । "उन्हें विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर का तत्त्व उनमें है और उन्हें अपनी रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं है । जब तक प्रगति के क्षेत्र में वे आगे नहीं आती, तब तक देश के लिए उन्नति करना सम्भव नहीं है ।" ^२

१. वही, पृ० १५० ।

२. वही, पृ० १५१ ।

१२. रौलेट अधिनियम और पंजाब कांड

रौलेट कमेटी

प्रथम विश्वयुद्ध के जमाने में भारत रक्षा विधेयक को पारित कराते समय सरकार ने वायदा किया था कि युद्ध के बाद उसे रद्द कर दिया जायगा। जिन राजनीतिज्ञों ने उस समय उसका समर्थन किया था उन्होंने सोचा था कि जर्मनी की पराजय के बाद भारतीयों को भी स्वतंत्र जीवन बिताने का अवसर प्राप्त होगा। पर ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना आधिपत्य बनाये रखने के लिए किसी न किसी रूप में अपनी दमन शक्ति भी बनाये रखना चाहती थी।

इसलिए १० दिसम्बर सन् १९१७ को भारत सरकार ने न्यायाधीश सिडने रौलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। सिडने रौलेट के अतिरिक्त कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सर वेसिल स्काट, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश कुमार स्वामी शास्त्री, कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील पर पी० सी० मित्र और इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य बरने लावेट इसके सदस्य थे। इस कमेटी ने वद बैठकों में स्थिति की जाँच करके सस्तुति की कि भारत रक्षा अधिनियम के स्थान पर उससे मिलता जुलता एक स्थायी अधिनियम पास किया जाय, तथा राजविद्रोह की सम्भावनाओं को कम करने के लिए साधारण दण्डविधान को सशोधित कर उसे अधिक कड़ा बनाया जाय।

कमेटी की रिपोर्ट जुलाई सन् १९१८ में प्रकाशित की गयी। कांग्रेस ने तथा बहुत सी दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं ने रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की। पर सरकार ने इसकी उपेक्षा करते हुए कमेटी की सस्तुतियों के आधार पर दो विधेयकों को, जो रौलेट बिल के नाम से विख्यात हुए, केन्द्रीय कौंसिल से पास कराने का निश्चय किया।

इन दो विधेयकों में से पहला विधेयक मूल रूप से भारत रक्षा अधिनियम पर आधारित था, और उस अस्थायी अधिनियम की मूल व्यवस्था को बनाये रखने की भावना से प्रेरित था। राजद्रोह के क्रान्तिकारी और अराजक कामों को दृढ़ता और आसानी से दबा देना ही इस सफट-कालीन विशेषाधिकार विधेयक का उद्देश्य था। यह विधेयक इस प्रकार के प्रयत्नों और पद्धतियों से राज्य की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के निमित्त संदिग्ध व्यक्तियों को बिना

मुकदमे के अपनी हिरामत में रखने का, तथा उन्हें अपने आचरण के संबंध में जमानत देने के लिए, किसी विशेष स्थान में विशेष शर्तों के साथ रहने के लिए, एवं किसी काम को न करने के लिए आदेश देने का प्रान्तीय सरकार को अधिकार देता था। इस विधेयक में इस प्रकार के आदेशों के औचित्य की जाँच के लिए एक जज और एक गैर-सरकारी सदस्य की जाँच कमेटी की भी व्यवस्था थी। इस विधेयक में सदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई के लिए तीन जजों के ऐसे विशेष न्यायालय की व्यवस्था भी थी, जिसके फैसले की कोई अपील नहीं थी, और जो विशेष क्रियाप्रणाली द्वारा उनकी सुनवाई कर सकता था। यह विधेयक भारत रक्षा अधिनियमों में गिरफ्तार व्यक्तियों को नजरबन्द बनाये रखने का अधिकार भी प्रान्तीय सरकार को प्रदान करता था। देश के स्थायी दण्डविधान अर्थात् फौजदारी कानून को संशोधित कर उसे अधिक कड़ा बनाना ही दूसरे विधेयक का उद्देश्य था।

१८ जनवरी सन् १९१९ को पहला विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया। उसके दो सप्ताह बाद ही गृह सदस्य ने कौंसिल में प्रस्ताव किया कि इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय। श्री विठ्ठल भाई पटेल ने सशोधन उपस्थित किया कि इस पर विचार स्थगित किया जाय। सर्व श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और जी० एस० खापर्डे तथा महाराजा साहब महमूदाबाद, मौलाना मजहसूल हक, जिना साहब और मालवीयजी ने सशोधन का समर्थन करते हुए विधेयक का टटकर विरोध किया। उन्होंने उसे असामयिक, अनावश्यक, दमनकारी बताया, और सरकार को सलाह दी कि वह उसे वापस ले ले। गांधीजी ने तो घोषित किया कि यदि विधेयक पास कराया जायगा, तो वे उसके विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन करेंगे।

मालवीयजी का विरोध

मालवीयजी ने कौंसिल में इसका विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक एक ऐसे यन्त्र का निर्माण करना चाहता है जिससे प्रजा की स्वतंत्रता का अपहरण हो सकता है। ऐसे दमनकारी विधेयक पर काफी गंभीरता और बहुत सावधानी से विचार करना बहुत जरूरी है। कौंसिल की साधारण कार्यप्रणाली की उपेक्षा करते हुए उसके सम्बन्ध में अपवादात्मक प्रणाली का अनुसरण, उन्होंने कहा, सर्वथा अनुचित है, क्योंकि यदि साधारण प्रणाली का उपयोग किया गया होता, तो विधेयक पर विचार करते समय कौंसिल को बहुत से विधि-विशेषज्ञों तथा सम्मानित व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिक्रियाओं और

विचारो का ठीक-ठीक पता हो पाता। उन्होंने यह भी कहा कि जिन तथ्यों के आधार पर रौलेट कमेटी ने इस विधेयक की सस्तुति की है उन सबको प्रकाशित किये बिना उसे पास करने को कौंसिल से कहना भी ठीक नहीं है।^१

मालवीयजी ने कहा कि भारत रक्षा विधेयक को युद्ध की विशेष स्थिति में कौंसिल ने पास किया था। युद्ध के बाद शान्ति की स्थिति में उस प्रकार के विधेयक को पारित करना किसी तरह भी कौंसिल के लिए उचित नहीं होगा। शान्ति और स शीते के युग में साधारण न्यायव्यवस्था की उपेक्षा करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान करना, उन्हें मनमाने ढंग पर प्रजा की स्वतंत्रता पर आक्रमण करने का अधिकार देना, उचित और न्यायसंगत नहीं समझा जा सकता।^२

मालवीयजी ने कहा कि वे राजद्रोह की निन्दा करते हैं, क्योंकि उनके विचार में वह स्वतः बुरा है, और हमारे देशवासियों को हानि पहुँचाता है। उन्होंने कहा कि मैं उन नवयुवकों के लिए हृदय से दुःखी हूँ जो राजद्रोह के लिए पथभ्रष्ट किये गये हैं, और उन्हें गथ भ्रष्टता के परिणामों से बचाने के लिए संभव और साध्य न्यायसंगत उपायों का समर्थन करने को तैयार हूँ। पर उन्होंने कहा कि हमें "भारत की उज्ज्वल कीर्ति और प्रतिष्ठा तथा न्याय की प्रक्रिया और वातावरण को भी बनाये रखना है।"^३

मालवीयजी ने कहा कि रौलेट कमेटी ने जिन तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया है, उनको पढ़ने से तो पता चलता है कि सन् १८९७ से पहले इन देश में राजद्रोह से संबंधित अपराधों का अभाव था, और १८९७ में भी जो दो हिंसात्मक कांड बम्बई प्रान्त में हुए, उनका भी राजद्रोह से कोई सम्बन्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि कमेटी ने यह भी स्वीकार किया है कि इस समय बम्बई प्रान्त में राजद्रोहात्मक क्रान्तिकारी आन्दोलन व्यवहार में निर्मूल हो गया है, तथा युक्त प्रान्त, मद्रास, मध्य प्रदेश एवं बिहार और उड़ीसा में भी क्रान्तिकारी भावनाओं का बहुत कम प्रभाव हुआ है। इस प्रान्तों की जनता शान्ति-प्रिय है, वह विद्रोहात्मक कामों को नापसन्द करती है, यदि कोई क्रान्तिकारी बाहर से आकर कोई उपद्रव करता है, तो उसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त नहीं होता। इन सबके यह स्पष्ट है कि कमेटी की राय में पंजाब और बंगाल ही क्रान्तिकारी और राजद्रोहात्मक कामों के मुख्य केन्द्र हैं।^४

१. प्रोसीडिंग्स—इंडियन लेजिस्लेटिव कौंसिल, सन् १९१८, जि० ५७।

२. वही, जि० ५७।

३. वही, जि० ५७।

४. वही, जि० ५७।

मालवीयजी ने सरकार से पूछा कि पंजाब और बंगाल के कतिपय व्यक्तियों के विद्रोहात्मक कामों के कारण सारे देश को अपराधी ठहराना, और देशभर के लिए दमनकारी कानून बनाना किस तरह न्यायसंगत समझा जा सकता है।^१

पंजाब की स्थिति का विश्लेषण करते हुए मालवीयजी ने कहा कि उनकी राय में जिन सिक्खों ने गदर आन्दोलन में भाग लिया “उनके पास प्रकोप के पर्याप्त कारण थे” और उनके साथ अधिकारियों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया उसने ‘दुर्भाग्यवश उम कोपान्नि में आहुति’ का काम किया। मालवीयजी ने कहा कि कमेटी ने यह कहते हुए कि ‘यदि बलयाई सब प्रकार का उपद्रव मचाते, तो व्यवस्था का सारा ढाँचा और व्यवस्था सम्बन्धी सभी नियम नष्ट हो जाते,’ यह भी स्वीकार किया है कि ‘अधिक उत्साही, साहसी, शक्ति सम्पन्न सिक्खों के बीच-वचाव करने से गदर सम्बन्धी विचार और उसके प्रयोग की अवधि अधिक काल तक नहीं रही।’ मालवीयजी ने पूछा कि “कुछ सिक्खों में कुछ काल के लिए दुरी भावना रहना सारे प्रान्त पर दमनकारी कानून लाने का पर्याप्त कारण कैसे हो सकता है?”^२

बंगाल की स्थिति का विश्लेषण करते हुए मालवीयजी ने कहा . “सन् १९०५ तक बंगाल में कहीं भी राजद्रोहात्मक और कान्तिकारी भावनाओं का चिह्न नहीं था”, और उसके बाद लार्ड कर्जन का विश्वविद्यालय अधिनियम और बंगाल के बटवारे ने बंगाल के नवयुवकों में इन भावनाओं को विकसित किया। यदि सरकार अपनी जिद पर डटी न रहती, और अनुभवी नरमदलीय राजनीतिज्ञों के शान्तिमय सवैधानिक प्रयत्नों पर ध्यान देकर बंगाल के विभाजन को रद्द कर देती, तो राजद्रोह की भावनाएँ न पनप पाती। सन् १९११ में बंगला भाषा-भाषी क्षेत्रों को फिर एक प्रान्त में मिला देने के बाद राजद्रोही कामों का एक बड़ा कारण खत्म हो जाता है।^३

मालवीयजी ने स्वीकार किया कि विश्वयुद्ध के जमाने में जर्मनी के ब्रिटन-विरोधी पड़्यन्त्रों ने इस देश में राजद्रोह के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित किया, पर अब जबकि जर्मनी की शक्ति और उसके साथ ही उसके पड़्यन्त्रों की सम्भावनाएँ नष्ट हो गयी हैं, राजद्रोह के उन क्रियाकलापों को, जिनका उद्गम विश्वयुद्ध से है, निरन्त्रित करने के लिए किसी नये कानून की जरूरत नहीं है।

१. वही, जि० ५७।

२. वही, जि० ५७।

३. वही, जि० ५७।

भारत रक्षा अधिनियम, जो विश्वयुद्ध से सम्बन्धित सन्धि हो जाने के बाद भी छ महीने तक चालू रहेगा, उन्हें कन्ट्रोल करने के लिए पर्याप्त है।^१

मालवीयजी ने कहा कि उनकी युक्तियुक्त धारणा है कि नये राजनीतिक सुधारों के आरम्भ होने पर वस्तुस्थिति में भी सुधार होगा, जिसके फलस्वरूप उन क्रान्तिकारी अपराधों में कमी की आशा की जा सकती है, जिनकी उत्पत्ति “देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असन्तोष के कारण हुई है।”^२

मालवीयजी ने कहा कि रौलेट कमेटी का यह सन्देह कि “सिपाहियों में अन्तोप की भावना जगाना सम्भव होगा”, उन व्यक्तियों की राजभक्ति पर अत्यन्त निर्दयतापूर्ण आघात है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर साम्राज्य की रक्षा की है, और जिन्हें युद्धकाल में “पथभ्रष्ट करने के सभी प्रयत्न विफल हो चुके हैं।” उन्होंने कहा : “यदि सरकार उचित मार्ग का अवलम्बन करेगी, यदि सरकार व्यवहारतः, यथार्थतः और उदारतापूर्वक उनके त्याग और बलिदान को स्वीकार करेगी यदि सरकार उन्हें साधारण पशु की अपेक्षा अधिक उत्तम जीवन व्यतीत करने का अनसर देने के लिए प्रयत्नशील होगी, तो कोई भी शक्ति उन्हें उनकी दृढ़ राज्यनिष्ठा और राजभक्ति से विचलित करने में समर्थ नहीं होगी।”^३

मालवीयजी ने स्वीकार किया कि “कोई भी गम्भीर और उत्तरदायी व्यक्ति निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि युद्ध के बाद भारत में क्रान्तिकारी और राज-द्रोहात्मक अपराध नहीं हो सकते। अमरीका आदि देश इस प्रकार के अपराधों से मुक्त नहीं हुए हैं। यूरोपीय देशों में भी ऐसे अपराध होते रहते हैं। किसी भी देश में देश के अधिकांश निवासियों के राजभक्त होने पर भी एक उन्मत्त, एक पथभ्रष्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो चित्तविक्षिप्तता के रोग से ग्रसित है राज-द्रोहात्मक अपराध कर सकता है। किन्तु इस आधार पर सारे देश के लिए प्रस्तावित विधान के समान भयकर विवेक कौंसिल से स्वीकार नहीं कराया जा सकता।”^४

रौलेट कमेटी ने, उन्होंने बताया, स्वीकार किया है कि युद्ध के बाद स्थिति सुधर भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। वह इतनी अच्छी हो सकती है कि जब किसी विशेष दण्ड-व्यवस्था की कोई आवश्यकता न हो, पर ऐसी बिगड़ भी सकती है, जिसे साधारण व्यवस्था न सुधार सके, और प्रस्तावित प्रयोग अनिवार्य

१ वही, जि० ५७।

२. वही, जि० ५७।

३ वही, जि० ५७।

४. वही, जि० ५७।

हो जाय। ऐसी स्थिति में मालवीयजी की राय में हमें इस आधार पर ही काम करना चाहिए कि देश को “सुखद विकल्प” प्राप्त होगा। यदि दशा विगड़ी, तो उसे सुधारने के लिए उचित व्यवस्था की जायगी। उन्होंने कहा कि हमको इस धारणा के आधार पर कि सुखद सम्भावना की सिद्धि होगी ही नहीं और दुःखद घडिया ही आवेगी, प्रस्तावित व्यवस्था की रचना के लिए मत देना उचित नहीं है।^१

मालवीयजी ने प्रस्तावित विधेयक की विभिन्न धाराओं में निहित नीतियों का विश्लेषण करते हुए कहा कि वे बहुत ही आपत्तिजनक हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण करनेवाली हैं, और वे अभियुक्तों को अपने को निर्दोष सिद्ध करने की भी न्यायसंगत सुविधाओं से वंचित करती हैं।^२

मालवीयजी ने सरकार से अपनी स्थिति पर फिर से विचार करने की प्रार्थना करते हुए कहा कि उन्हें ता आशा थी कि “विगत महायुद्ध में भारतीयों ने जो महान् कार्य किया है, उसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार किसी भी ऐसे प्रस्ताव का साहस और दृढ़ता से विरोध करेगी, जिसके द्वारा ऐसे विधान को स्थायी स्वरूप दिया जाता हो जिसकी सृष्टि भारत रक्षा अधिनियम के रूप में केवल युद्ध काल के लिए हुई थी।”^३

अन्त में मालवीयजी ने कहा “परिस्थिति की माग यह है कि समस्त जनता को अधिक उदार व्यवस्था प्रदान कर उनके हृदय को अपनी ओर आकर्षित किया जाय, रगभेद का उन्मूलन किया जाय, तथा नये राजनीतिक सुधारों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाय”।^४ उन्होंने कहा : “नौकरियों के प्रश्न को अधिक उदारभाव से हल कीजिये, भारतीयों को सेना में कमीशन देने में उदार भाव का प्रयोग होने दीजिये, व्यवसाय को प्रोत्साहन और प्रवर्धन प्राप्त होने दीजिये, शिक्षा में नयी प्रणाली का प्रसार होने दीजिये और नवयुवकों को जीवन-यापन के नये साधन प्रदान कीजिये, तब देश में कृतज्ञता के भाव व्याप्त होंगे, देश में सतोष और सद्भावना की वृद्धि होगी, और हमको क्रान्तिकारी अपराधों का नाम तक न सुन पड़ेगा। जब यह सब होगा तब भी कहीं ऐसे अपराध दिखाई देंगे, तब उनका सामना भी अधिक उग्र नीति के अवलम्बन से नहीं बल्कि सदय भाव से होना चाहिए, न कि प्रस्तावित विधेयक के प्रयोग द्वारा।” इन शब्दों में मालवीयजी ने रोलेट बिल का विरोध किया।^५

१ वही, जि० ५७।

२ वही, जि० ५७।

३ वही, जि० ५७।

४. वही, जि० ५७।

५ वही, जि० ५७।

सरकार का आग्रह

सरकार ने श्री विठ्ठल भाई पटेल के संशोधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रवर समिति ने, जिसमें सरकार के समर्थकों का भारी बहुमत था, विधेयक में निहित सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए सरकार की अनुमति से संस्तुति की कि विधेयक तीन वर्ष के लिए ही पारित किया जाय। विठ्ठलभाई पटेल, जी० एस० खापर्डे और मालवीयजी ने प्रवर समिति के सदस्यों की हैसियत से समिति की रिपोर्ट पर मतभेद का तगड़ा नोट लिखा। प्रवर समिति के सदस्यों की हैसियत से समिति की रिपोर्ट पर चलेते हुए श्री श्रीनिवास शास्त्री तथा डाक्टर तेजबहादुर सप्रू आदि ने सरकार से अनुरोध किया कि जनमत की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए विधेयक वापस ले लिया जाय। पर सरकार अपनी जिद पर डटी रही और उसने सरकारी सदस्यों के बल पर कौंसिल से विधेयक पास करा लिया।

इस्तीफे

इस पर मालवीयजी, जिना साहब, मौलाना मजहबूल हक आदि चार व्यक्तियों ने कौंसिल की सदस्यता से इस्तीफे दे दिये। जिना साहब का त्यागपत्र निःसंदेह सबसे तगड़ा था। उन्होंने लिखा कि भारी जनमत के विरुद्ध जिस तरह यह कानून पास कराया गया है, उसने केन्द्रीय कौंसिल का खोखलापन सिद्ध कर दिया है, साबित कर दिया है कि वह 'विदेशी सरकार द्वारा चालित एक मशीन है'। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश न्याय पर से जनता का विश्वास डगमगा गया है, क्योंकि इस कानून द्वारा 'न्याय के मौलिक सिद्धान्तों का उन्मूलन तथा जनता के सवैधानिक सिद्धान्तों का अपहरण किया गया है।' जिना साहब ने अपने त्यागपत्र में यह भी लिखा कि यह कानून उन सिद्धान्तों के विपरीत है जिसकी उद्घोषणा युद्ध काल में भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर की थी। उन्होंने लिखा कि उनकी राय में जो सरकार शांतिकाल में इस प्रकार का कानून पास कराती है, वह सभ्य सरकार कहलाने के दावे को खो देती है।

मालवीयजी का पत्र

मालवीयजी ने अपने त्यागपत्र के अतिरिक्त गवर्नर-जनरल को अलग से एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे अनुरोध किया कि जनता की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए इस नये कानून को कम-से-कम छः महीने चालू नहीं किया जाय। वाइसराय ने इसके उत्तर में लिखा—'आपने विधेयक को मार डाला है, वह अब चालू नहीं

किया जायगा।' सरकार दूसरे रीलेट बिल को कौंसिल के अगले सत्र में पेश करना चाहती थी, पर जनता के क्षोभ, रोष और प्रतिक्रियाओं को देखकर उसने ऐसा नहीं किया।

गांधीजी का आन्दोलन

इन कानून के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए गांधीजी ने जनता का आवाहन किया। भारत सरकार ने उसे दवाने का निर्णय किया, और पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओडायर ने आन्दोलन के साथ साथ पंजाब के सारे राजनीतिक जीवन को कुचल डालने का निश्चय किया। गांधीजी ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने तथा 'जनान्दोलन में आगे बढ़कर भाग लेने को' आवाहन किया। सर्वश्रेष्ठ डी० ई० वाचा, श्रीनिवास श्यामी, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने एक वक्तव्य द्वारा गांधीजी के जनान्दोलन को हानिकार बताते हुए उसका विरोध किया।

गांधीजी ने इसकी उपेक्षा करते हुए नये कानूनों के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन करने के लिए ३० मार्च की तारीख निश्चित की। यद्यपि आगे चलकर प्रदर्शन और हड़ताल की तिथि ३० मार्च के बजाय ६ अप्रैल कर दी गयी थी, पर दिल्ली में ३० मार्च को ही जनता द्वारा प्रदर्शन हुए, सारे नगर में हड़ताल मनायी गयी। इस अवसर पर यद्यपि सायंकाल को स्वामी श्रद्धानन्द की अध्यक्षता में आयोजित सभा में विलकुल शान्ति रही, पर उससे पहले ही रेलवे स्टेशन पर कुछ उपद्रव हुआ, तथा आगे चल कर पुलिस तथा फौज ने गोली चलायी, और उसी दिन ८१० आदमी गोली का शिकार हो गये। सरकार के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर मालवीयजी ने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये। ६ अप्रैल को सारे देश में शान्तिपूर्वक हड़ताल मनायी गयी।

९ अप्रैल को पंजाब में रामनवमी धूमधाम से मनायी गयी, और हिन्दू-मुस्लिम एकता के जोर से नारे लगाये गये। उसी दिन सायंकाल को गांधी जी, जो चम्पई से दिल्ली जा रहे थे, पंजाब में पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गये। गांधीजी की गिरफ्तारी के समाचार ने दिल्ली, पंजाब और अहमदाबाद में जनता के रोष और उत्तेजना को काफी बढ़ा दिया। दिल्ली में आन्दोलन सत्रह अप्रैल तक चलता रहा, अहमदाबाद में उराने उपद्रव का रूप धारण कर लिया, पर गांधीजी ने वहाँ पहुँच कर १४ अप्रैल को शान्ति स्थापित कर दी। पर पंजाब में, विशेषतः अमृतसर में स्थिति ने भयंकर रूप धारण कर लिया। १७ अप्रैल को गांधीजी ने आन्दोलन वापस ले लिया।

पंजाब कांड

महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के अतिरिक्त डाक्टर सत्यपाल और डाक्टर शैफउद्दीन किचलू की गिरफ्तारी, सर माइकल ओडायर की नादिरशाही, तथा जनरल डायर की क्रूरता पंजाब की भयंकर स्थिति के मूल कारण थे। जब १० अप्रैल को डाक्टर सत्यपाल और डाक्टर किचलू की गिरफ्तारी और निष्कासन के समाचार अमृतसर की जनता को मिले, तब एक उत्तेजित भीड़ डिण्टी कमिश्नर से अपने नेताओं की रिहाई की माँग के लिए उनके निवास-स्थान की ओर बढ़ी। पर वह रास्ते में ही रोक ली गयी, गोली चलायी गयी, दो आदमी कत्ल हुए। भीड़ अपने साथियों की लाशों के साथ नारे लगाती वापस चली गयी। पर कुछ देर बाद एक दूसरा उत्तेजित भीड़ डिण्टी कमिश्नर के बगले की ओर बढ़ी। इस भीड़ पर भी गोलियों का प्रहार किया गया, और ग्यारह आदमी मार डाले गये। इसमें जनता और उद्दिग्ग हो गयी, और भीड़ ने दो यूरोपियनों को गार डाला, तथा एक गिरजा-घर को आग लगा दी। डिण्टी कमिश्नर ने शान्ति की व्यवस्था का सारा भार फौज को सौंप दिया, और इस तरह १० तारीख की रात को ही अमृतसर में क्रूर सैनिक शासन स्थापित हो गया।

१३ अप्रैल को वैशाखी के दिन जनरल डायर ने जलियाँवाला बाग में एकत्रित निर्दोष निहत्थी जनता पर, जिनमें बच्चे और स्त्रियाँ भी थी, बिना किसी चेतावनी के इस तरह गोली चलाने की आज्ञा दी कि लोगो को भागकर निकलना भी कठिन हो गया। गोली दस मिनट तक चलती रही, १६०० चक्र चले, लगभग चार सौ आदमी मारे गये, और १२० आदमी जखमी हुए^१, जिन्हें अस्पताल पहुँचाने का भी सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। भारतीय जनता को आतंकित और अपमानित करने के लिए उस सडक पर, जहाँ दो यूरोपियन मारे गये थे, हिन्दुस्तानियों को पेट के बल रेंगते हुए चलने का आदेश जारी किया गया।

सर माइकल ओडायर

ओडायर ने जनरल डायर के इन कामों की प्रशंसा करते हुए पंजाब के कई जिलों में मार्शल-ला चालू करके वहाँ का सब प्रबन्ध फौजी अफसरों के सुपुर्द कर दिया। मार्शल-ला अधिकारियों ने जनता को बुरी तरह अपमानित,

१. हंटर कमेटी रिपोर्ट, पृ० ११३।

आतंकित, ताड़ित और आहत किया, और इस सबके लिए त्रिलक्षण अमानुषिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया। मार्चजनिक म्यानों पर रेडियो के सामने बिल्कुल नंगा करने गर्दों को कोड़ों से घुरी तरह पीटा गया। हजारों विद्यार्थियों को कई दिन तक प्रतिदिन १६ गील चलकर हाजिरी देने के लिए बाध्य किया गया। पाँच-सात वर्ष के बच्चों को परेड पर जाकर झड़े को सलामी देने के लिए मजबूर किया गया। लगभग पाँच सौ विद्यार्थी और अध्यापक गिरफ्तार करके तीन दिन तक लाहौर के किले में बन्द रखे गये। लाहौर के एक गाँव में सारी वारात को कोड़ों से पीटा गया। बादशाही मस्जिद छ सप्ताह के लिए बन्द कर दी गयी। लाहौर में इस्लामिया स्कूल के छ सबसे बड़े बच्चों को छाँट कर पीटा गया। मकानों के मालिकों पर मार्शल-ला सम्बन्धी पोस्टरो की रक्षा का उत्तरदायित्व लादा गया। जिन भद्र पुरुषों ने युद्ध में सरकार की सहायता की थी, उन्हें भी बहुत अमानित ढंग से नगर में घुमाकर बिना किसी कारण हवालात में बन्द कर दिया गया। गिरफ्तार मज्जनों को लोहे के पिंजड़े में बन्द कर दिया गया। हवाई जहाज से जनता पर बम फेंके गये, हिन्दू-मुस्लिम एकता का उपहास उड़ाने के लिए हिन्दू-मुसलमान की जोड़ियों को हथकड़ी बाँध कर नगर में फिराया गया। बहुत से लोगों को हथकड़ियों और रस्सियों में बाँधकर पन्द्रह घंटे तक खुली ट्रकों में रखा गया। हिन्दुस्तानियों के घरों से पानी और बिजली काटी गयी, और बिजली के पंखे वहाँ से निकाल कर यूरोपियनों को उनके प्रयोग के लिए दिये गये। हिन्दुस्तानियों से उनकी गाड़ियाँ छीन कर यूरोपियनों में बाँट दी गयी। अप्राप्त न्यक्तियों की जायदादें जब्त कर ली गयी, या बर्बाद कर दी गयी, और उनके सम्बन्धियों को बन्धकों के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत से स्थानों पर निर्दोष व्यक्तियों को दाण्डिक (प्युनिटिव) पुलिस तथा क्षतिपूर्ति का भार वहन करना पड़ा।

गवर्नर-जनरल ने एक अध्यादेश द्वारा मार्शल-ला ट्रिब्युनल को अपने ढंग पर साधारण फौजदारी के अभियोगों की, तथा फौजदारी अदालतों को अर्थात् जिलाधिकारियों को साधारण कार्यप्रणाली की उपेक्षा करते हुए सरसरी ढंग से मार्शल-ला से सबधित मुकदमों की न्यायिक जाच करने का अधिकार दे दिया। मार्शल-ला अदालतों (ट्रिब्युनल) तथा सरसरी (समरी) अदालतों द्वारा खुले तौर पर न्याय का उपहास उड़ाया गया। उन्होंने मनमाने ढंग पर अभियुक्तों को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिये बिना कड़ी सजाएँ दे दी। इस तरह इन अदालतों द्वारा न्याय की भ्रूणहत्या की गयी, उन्हें जनता के सताने का साधन बना लिया गया। उनके द्वारा जनता को नैतिक वेदना और भौतिक कष्ट दिये

गये। १०८ आदमियों को फासी की, तथा सैकड़ों को जल्दी-जल्दी आजीवन दण्ड की अर्थात् २० वर्ष की सजा दे दी गयी। कुल मिलाकर इन विशेष अदालतों द्वारा ७००० वर्ष से अधिक का दण्ड दिया गया।

मार्शल ला के जमाने में सरकार ने समाचारों पर भी इतना कड़ा नियंत्रण (सेन्सर) लागू रखा कि देश के नेताओं तक के लिए स्थिति का सही अनुमान लगाना कठिन था। कतिपय समाचारपत्रों और नेताओं के कहने पर भई में दीनबन्धु सी० एफ० एंडरूज ने पंजाब जाने की कोशिश की, पर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके वापस लौटा दिया। अमियुक्तों की पैरवी के लिए सर्वश्री मोतीलाल नेहरू, चित्तरजनदास, अर्डले नार्टन आदि वकीलों ने पंजाब जाना चाहा, पर उन सब को भी पंजाब सरकार ने इजाजत नहीं दी। उस समय जबकि गांधीजी ने आन्दोलन बन्द कर दिया था, और सरकार के आदेश पर बम्बई प्रान्त से बाहर जाना बन्द कर दिया था, किसी दूसरे नेता या कार्यकर्ता के लिए सरकार की आज्ञा के विरुद्ध पंजाब में जाने का प्रयास करना संभव नहीं था।

कांग्रेस कमेटी की बैठक

ऐसी स्थिति में १९ और २० अप्रैल को बम्बई में मालवीयजी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। उसने सरकार की भर्त्सना करते हुए पंजाब, दिल्ली आदि स्थानों पर सरकार के अफसरो और कर्मचारियों द्वारा किये गये अत्याचारों की जाच की माग की, तथा गांधीजी पर लगाये गये प्रतिबन्धों की कड़ी आलोचना की। सरकार की १४ अप्रैल की विज्ञप्ति का उत्तर तैयार करने के लिए एक उपसमिति गठित की गयी, तथा कांग्रेस की ओर से नये सुधारों के सम्बन्ध में गवाही देने को जाने वाले शिष्ट-मंडल को आदेश दिया गया कि वह पंजाब के अत्याचारों के सबंध में ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों से बातचीत करे। कांग्रेस की ओर से मालवीयजी ने काफी बड़ा समुद्री तार भी ब्रिटेन के प्रधान-मंत्री को भेजा।

८ जून सन् १९१९ को प्रयाग में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार से माग की गयी कि फौजी कानून फौरन हटा लिया जाय, और घटनाओं की जाच के लिए एक कमेटी नियुक्त की जाय। यह भी माग की गयी कि यह कमेटी यह भी जाच करे कि पंजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर माइकल ओडायर ने युद्ध के जमाने में फौज में सिपाहियों को भरती करने के लिए, तथा युद्ध में चन्दा जमा करने के लिए जो काम किये, और पंजाब की

दुर्घटनाओं के संबंध में जो आदेश जारी किये गये, वे कहा तक ठीक थे ? कांग्रेस कमेटी ने पंजाब सरकार के अफसरों और कर्मचारियों के अत्याचारों की जांच के लिए तथा पीड़ितों की सहायता के लिए मालवीयजी, पंडित मोती लाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानन्द आदि की एक उपसमिति भी गठित की। कमेटी की ओर से मालवीयजी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उपभारत-मंत्री को तार भेजे कि प्रस्तावित जांच होने तक फौजी कानून के अन्दर दी गयी सजाएँ स्थगित रखी जावे।

पंजाब में काम

इस विषय पर परिस्थिति में मालवीयजी ने अत्याचारों की जांच तथा पीड़ितों की सहायता के लिए पंजाब जाने का निश्चय किया, और उन्होंने इसकी सूचना वाइसराय तथा पंजाब सरकार को भेज दी। अमृतसर से २०० मील इधर अम्बाला स्टेशन पर उन्हें जगाकर कतिपय सरकारी अधिकारियों ने पंजाब सरकार की इस आज्ञा से उन्हें सूचित किया कि वे पंजाब में प्रवेश न करें। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया कि जब तक मुझे गिरफ्तार करके गाड़ी से निकाला नहीं जायगा, मैं न तो गाड़ी से उतरूंगा और न वापस जाऊंगा। अमृतसर पहुँच कर एक तागेवाले की सहायता से वे स्टेशन के पास की धर्मशाला में चले गये। लगभग एक घंटे के बाद जब स्नान और पूजा-पाठ से निवृत्त होकर वे शहर जाने के लिए धर्मशाला से बाहर निकलने लगे, तब एक व्यक्ति ने अपने को उस स्थान का मालिक और मुख्य ट्रस्टी बताते हुए उनका सामान बाहर निकाल कर धर्मशाला के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। सड़क पर उन्हें कुछ नवयुवक मिले। उनसे उन्होंने किसी दूसरी धर्मशाला में ठहरने के सम्बन्ध में बात-चीत की। इन नवयुवकों ने यह समझकर कि कहीं किसी दूसरी धर्मशाला में भी मालवीयजी को इसी प्रकार की परिस्थिति का सामना न करना पड़े, उन्हें डाक्टर सत्यपाल के घर चलने की सलाह दी। डाक्टर सत्यपाल साहब की धर्मपत्नी उन्हें अपने यहाँ ठहराने को राजी हो गयीं, और मालवीयजी वहाँ रहने लगे।

कुछ दिन बाद वे अपने साथ श्री वेकटेश नारायण तिवारी को, जो उस समय प्रयाग सेवा समिति के मंत्री थे, और कुछ स्वयंसेवकों को ले आये। एक हजार रुपये प्रतिदिन की वकालत का मोह छोड़कर पंडित मोतीलाल नेहरू भी आ गये। पंजाब के सुपुत्र स्वामी श्रद्धानन्द ने भी काम शुरू कर दिया। आगे चलकर दीनबन्धु सी० एफ० एडरुज आदि भी पंजाब आ गये। जाँच और सहायता का काम जोर शोर से शुरू हो गया।

जून के अन्तिम सप्ताह में मालवीयजी, श्रद्धानन्दजी आदि अमृतसर में विभिन्न घटना-स्थलों को देखने गये। उन्होंने उन गिरजाघरों को देखा जिनमें आग लगा दी गयी थी। वे जलियावाला बाग भी गये, जहाँ बड़ी निर्दयता से निहत्थी जनता पर गोली चलायी गयी थी। वहाँ उन्होंने घायलों से घटना की दर्दनाक कहानी, तथा मृतकों के परिवारों का विलाप सुना। वहाँ उन्हें पता चला कि किस तरह छोटे-छोटे अवोध बच्चों को अपनी जान गँवानी पड़ी। इसके बाद मालवीयजी और मोतीलालजी लाहौर, गुजरावाला आदि गये, और वहाँ उन्होंने दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की, और तथ्यों को इकट्ठा किया। उधर दीनबन्धु एडरुज ने बहुत से तथ्य जमा किये। श्री वैकटेश नारायण तिवारी ने सेवा समिति के स्वयंसेवकों द्वारा जलियावाला बाग के गोलीकांड के मृतकों की सूची तैयार करना शुरू की, और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनकी संख्या पाँच सौ के लगभग होगी। उन्होंने लाहौर, सियालकोट, गुरदासपुर आदि जिलों के गावों में भी आहतों, मृतकों और कैदियों के परिवारों की सहायता के लिए स्वयंसेवक भेजे, और लगभग पाँच सौ दुखी परिवारों की सहायता की। इन नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और तत्परता ने पंजाब की जनता में ढाढस और साहस का संचार किया। प्रारम्भ में कुछ घबडाते हुए, आगे चलकर खुले तौर पर, अभियुक्तों और अभिशासितों के सम्बन्धियों और मित्रों ने अपनी शिकायतें और फरयादे उन्हें बतायी।

कांग्रेस कमेटी की बैठक

१९ और २० जुलाई सन् १९१९ को कलकत्ते में मालवीयजी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। मालवीयजी ने कमेटी के सदस्यों को पंजाब की स्थिति बतायी। कमेटी ने निश्चय किया कि कांग्रेस का अधिवेशन पूर्व निश्चय के अनुसार दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अमृतसर में ही किया जाय। उसने माँग की कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी के वजाय सम्राट् द्वारा नियुक्त कमीशन के जरिये पंजाब के अत्याचारों की ठीक तौर पर जाँच करायी जाय। कमेटी ने सर शंकरन नायर को, जिन्होंने फौजी कानून के प्रश्न पर गवर्नर-जनरल की कार्यपरिपद से इस्तीफा दिया था, बघाई दी। पंजाब उपसमिति के लिए दस हजार रुपये भी जमा किये गये। इसके कुछ दिन बाद मालवीयजी ने एक लाख रुपये की अपील की।

कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का समुचित प्रबंध करने का भार पंजाब के सम्मानित नेता स्वामी श्रद्धानन्द ने वहन किया। उनकी अध्यक्षता में स्वागत समिति गठित हुई, जिसने काफी सफलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया।

केन्द्रीय कौंसिल

पंडित मोतीलाल नेहरू की सलाह से मालवीयजी ने अपने निर्वाचको का पुनः विश्वास प्राप्त कर केन्द्रीय कौंसिल का सदस्य बनने का निश्चय किया, ताकि वे वहाँ जाकर सर्वैधानिक मंच से पंजाब सरकार के अत्याचारों का भंडा फोड़ सकें। उन्होंने कौंसिल के सदस्य की हैसियत से कौंसिल के आगामी सत्र के लिए पंजाब कांड से संबंधित लगभग पिचहत्तर प्रश्नों का नोटिस दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव का भी नोटिस दिया कि पंजाब कांड की जाँच के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया जाय। पर गवर्नर-जनरल चेम्सफोर्ड प्रश्न पूछने की इजाजत देने को राजी नहीं हुए। इस पर सब प्रश्न समाचारपत्रों में प्रकाशित करा दिये गये।

३ सितम्बर सन् १९१९ को गवर्नर-जनरल ने अपने संसदीय भाषण में हंटर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त किये जाने की घोषणा की। बम्बई के प्रसिद्ध वकील और उदार दलीय नेता सर चिम्मनलाल सीतलवाड तथा ग्वालियर के न्यायाधीश सुलतान अहमद कमेटी के सम्भावित हिन्दुस्तानी सदस्य थे। इस पर मालवीयजी ने संशोधन के रूप में इस आशय के प्रस्ताव का नोटिस दिया कि सर आमुतोप मुकर्जी, सर अब्दुर रहीम, और डाक्टर तेज बहादुर सप्रू में से एक व्यक्ति हंटर कमेटी का तीसरा भारतीय सदस्य नियुक्त किया जाय। गवर्नर-जनरल ने मालवीयजी को इस प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत नहीं दी, यद्यपि आगे चलकर भारत सरकार ने लखनऊ के प्रसिद्ध वकील श्री तेजनारायण मुल्ला को भी हंटर कमेटी का सदस्य नियुक्त कर दिया।

कमीशन की माँग

इस स्थिति में मालवीयजी ने कौंसिल में अपना यह प्रस्ताव पेश किया कि पंजाब कांड की जाँच के लिए सम्राट् द्वारा एक शाही कमीशन नियुक्त किया जाय, ताकि वह निष्पक्ष भाव से भारत सरकार की नीति-रीति को भी जाँच कर सके, और अपनी रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश मन्त्रिमंडल के पास भेज सके। वे चाहते थे कि इस कमीशन को यह भी अधिकार हो कि वह फौजी अदालतों के फैसलों की जाँच करके जहाँ उचित समझे, वहाँ फौजी अदालतों द्वारा दिये गये दंडों को कम या रद्द करने की प्रिवी कौंसिल को सत्तुति कर सके।^१

१. प्रोसीडिंग इंडियन लेजिस्लेटिव कौंसिल, सितम्बर सन् १९१९, जि० ५८, पृ० ७२-७९।

इस प्रस्ताव पर अन्तिम बार बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि देश भर में लोगो की यही इच्छा है कि पंजाब कांड की जाँच के लिए सम्राट् द्वारा कमीशन नियुक्त किया जाय। बम्बई हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश सर नारायण चन्दावरकर जैसे सम्मानित व्यक्तियों ने, तथा करीब करीब सभी भारतीय समाचार पत्रों ने इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के उपद्रवों में जिन सात अंग्रेजों की जानें गयी हैं, उनके लिए उन्हें अत्यन्त शोक है, पर इसके कारण हिन्दुस्तानियों के साथ किया गया अन्याय भुलाया नहीं जा सकता। निष्पक्ष जाँच नितान्त आवश्यक है। चूँकि पंजाब कांड का सम्बन्ध भारत सरकार के कतिपय निर्णयों और आदेशों से भी है, इसलिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी से निष्पक्ष जाँच की आशा नहीं की जा सकती।^१

मालवीयजी ने कहा. "यदि भारत सरकार अथवा सपरिपद् गवर्नर-जनरल ने घोषणा की कि लाहौर और अमृतसर में खुल्लमखुल्ला बगावत थी, यदि सपरिपद् गवर्नर-जनरल ने लाहौर, अमृतसर तथा अन्य स्थानों में फौजी कानून जारी करने की आज्ञा दी, यदि सपरिपद् गवर्नर-जनरल ने इसको उठा देने की चारों ओर से माँग होने पर भी उसे जारी रखा, यदि सपरिपद् गवर्नर-जनरल ने अपने एक साथी ने इस प्रतिवाद पर कि फौजी कानून का अन्त होना चाहिए, उसका इस्तीफा लेकर फौजी कानून जारी रखा, तो श्रीमन् आपको उन मनुष्यों को क्षमा करना चाहिए, जो यह समझते और कहते हैं कि पंजाब में अवलम्बित नीति से भारत सरकार का घनिष्ठ सम्बन्ध है, और इसलिए वह पक्षपात-रहित जाँच कराने में असमर्थ होगी, चाहे पक्षपात अनैच्छिक ही क्यों न हो।"^२

इन्डेमनिटी विधेयक

२ सितम्बर को गवर्नर-जनरल ने पंजाब कांड की जाँच के लिए एक कमेटी नियुक्त किये जाने की घोषणा की, और १८ सितम्बर को गृह-सदस्य सर विलियम विसेट ने पंजाब कांड से सम्बन्धित सरकारी अफसरो और कर्मचारियों की रक्षा के लिए इन्डेमनिटी बिल (क्षमा विधेयक) कौंसिल में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगो ने विपक्ष परिस्थिति में सरकार के आदेश पर शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए या पुनः स्थापित करने के लिए पूर्ण निष्ठा या ईमानदारी से काम किया है, उनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने

१. वही, जि० ५८, पृ० १४६-१४७। २. वही, जि० ५८, पृ० १५०।

कहा कि प्रस्तुत विधेयक मे क्षमा के क्षेत्र बहुत सीमित है । विधेयक किसी व्यक्ति को विभागीय सजा से मुक्त नहीं करता, वह तो सरकारी अफसर या कर्मचारी को कानूनी सजा से मुक्त करता है, और वह भी इस शर्त पर कि उसने जो कार्रवाइयाँ की हैं वे “शुद्ध निष्ठा (सद्भावना) और युक्तिसंगत विश्वास में यह समझ कर की हैं कि वे व्यवस्था को बनाये रखने या पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक थी ।” उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को यह शिकायत हो कि जो काम व्यवस्था के नाम पर किया गया है, और जिससे उसे क्षति पहुँची है, वह इन शर्तों को पूरा नहीं करता, तो वह इस बात की फरियाद साधारण न्यायालय में कर सकता है, क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है ।^१

जिस समय यह विधेयक कौंसिल के सामने पेश किया गया था, उस समय कौंसिल के बहुत से निर्वाचित सदस्य सर्वधानिक सुधारों के सम्बन्ध में संयुक्त पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने गवाही देने लन्दन गये हुए थे । जो सदन मे मौजूद थे, उनमें दिनशा इंदुलजी वाचा की धारणा थी कि इन्डेमनिटी बिल के सम्बन्ध में सरकार के विचार न्याय-संगत हैं । सरकार द्वारा मनोनीत यूरोपियन सदस्यों की भी यही धारणा थी । जिन्होंने उस विधेयक का विरोध किया, उनमें मालवीय जी का विरोध ही सबसे तगड़ा था ।

मालवीयजी का विरोध

मालवीयजी ने इन्डेमनिटी बिल का विरोध करते हुए कौंसिल का ध्यान सरकारी अफसरों द्वारा घटित अन्यायपूर्ण घटनाओं और कुचक्रों की ओर आकृष्ट किया । उन्होंने बताया कि सिपाहियों ने किस तरह न्याय, कानून और इन्सानियत की अवहेलना करते हुए बिना किसी चेतावनी के जलियावाला बाग में एकत्रित निहत्थी जनता पर गोली चलायी, और सैकड़ों नवयुवकों, बूढ़ों, बच्चों और स्त्रियों को भून डाला, तथा आहतों की चिकित्सा तक का कोई प्रबन्ध नहीं किया । उन्होंने बताया कि किस तरह गुजरावाला मे जनता पर बम गिराये गये, लाहौर के विद्यार्थियों पर घोर अत्याचार किये गये । उन्हें मौलो चल कर दिन में चार बार फौजी अफसर के पास हाजिरी देने के लिए बाध्य किया गया । उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिकों को अपनी सवारी से उतर कर यूरोपियनों को सलामी देने के लिए बाध्य किया गया, तथा बहुत से राजभक्त हिन्दुस्तानियों को बिना किसी अपराध के पकड़कर पिंजड़ों में बन्द कर दिया गया । बहुत से सम्मानित व्यक्तियों को हथकड़ियाँ पहना कर बाजारों मे घुमाया गया । उन्होंने

कहा कि चूँकि सरकार ने उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, उनमें पूछे गये सभी तथ्य सही समझे जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में अफसरों ने फौजी कानून के प्रतिबन्धों का भी ठीक तौर पर पालन नहीं किया। 'फौजी कानून के अनुसार चलाये गये मुकदमों में मुद्दई और मुद्दालेह, दोनों में से एक का वयान लिये बिना ही और फैसला लिखे बगैर ही भारी दण्ड दे दिये गये हैं।'^१

मालवीयजी ने कहा कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले यह सिद्ध करना चाहिए कि राज्य के विरुद्ध युद्ध या वगावत थी, या विद्रोह की ऐसी घोर स्थिति थी कि उसे 'युद्ध' कहा जा सके, और उसे दवाने के लिए फौजी कानून लागू करना, फौजी अदालतें स्थापित करना, तथा साधारण कानूनों के प्रतिबन्धों की उपेक्षा अनिवार्य थी।^२ इन बातों की जाँच कराने से पहले इन्डेमनिटी बिल पास कराना सर्वथा अनुचित है। यदि सरकार इस बात की जाँच कराने के लिए कि फौजी कानून लागू करने लायक घटनाएँ हुईं अथवा नहीं, एक कमेटी गठित करना आवश्यक समझती है, तो उससे पहले यह विधेयक कैसे पास किया जा सकता है ?

मालवीयजी ने मार्शल ला को लागू करने और उसे इतने दिनों तक जारी रखने के औचित्य को चुनौती दी। उन्होंने अमृतसर, लाहौर और गुजरावाला की स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करते हुए कहा कि वहाँ पर १४ अप्रैल को ऐसी स्थिति नहीं थी जिसे भयकर राजविद्रोह या वगावत की स्थिति समझा जा सके। १३ अप्रैल को अमृतसर में जलयावाला बाग में नरसंहार घोर अन्याय था। पर उसे भी जनता ने जिस तरह वर्दाश्त किया उसके बाद मार्शल ला घोषित करना, और उसे इतने दिनों जारी रखना अवश्य ही क्रूर व्यवहार था। उससे पहले जो दुर्घटनाएँ हुईं वे ऐसी नहीं थी कि उन्हें राज्य के लिए भयकर खतरा समझा जाय।^३

मालवीयजी ने कहा कि बम्बई सरकार ने गांधीजी को अहमदाबाद जाने की इजाजत दे दी, और उन्होंने वहाँ जाकर शान्ति स्थापित कर दी, यदि पंजाब की सरकार भी बम्बई की सरकार का अनुसरण करने को तैयार होती, तो सम्भवतः पंजाब में भी मार्शल-ला लागू किये बिना शान्ति स्थापित हो सकती थी।^४

१. वही, जि० ५८, पृ० ३१४-३१५।

२. वही, जि० ५८, पृ० ३१७।

३. वही, जि० ५८, पृ० ३०३-३०६।

४. वही, जि० ५८, पृ० ३२०।

मालवीयजी ने कहा कि कौंसिल सिद्धान्तों को निर्धारित कर सकती है, पर वह न्यायालय नहीं है, अदालत के किसी निर्णय का औचित्य प्रमाणित करना, उसे वैध घोषित करना उसका काम नहीं है। फिर यह कौंसिल उन लोगों को, जो कैद में हैं, किसी कानून द्वारा जेल में बने रहने की व्यवस्था कैसे कर सकती है? यह तो सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार का कानून बनाना तो अवश्य ही गलत होगा।

मालवीयजी ने यह भी कहा कि इस विधेयक के आमुख में कहा गया है कि इसका सम्बन्ध मार्शल-ला के जमाने में की गयी कार्रवाइयों से है, पर विधेयक की धाराओं द्वारा उन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी क्षमा प्रदान करने की व्यवस्था है, जिन्होंने मार्शल-ला की घोषणा से पहले भी अनुचित कार्य किये हैं। यह बात, मालवीयजी ने कहा, किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। जिन विधिविशेषज्ञों ने मार्शल-ला के जमाने में की गयी अनुचित कार्रवाइयों के लिए किन्हीं शर्तों पर क्षमा की व्यवस्था का समर्थन किया है, उन्होंने भी उससे पहले की कार्रवाइयों के लिए क्षमा प्रदान करने की बात को ठीक नहीं बतलाया है।

मालवीयजी ने यह भी कहा कि सरकार अपने उन अधिकारियों और कर्मचारियों को क्षमा करने की तो व्यवस्था करना चाहती है जिन्होंने मार्शल-ला के जमाने में या कुछ पहले ज्यादतियाँ की हैं, पर उन लोगों को हरजाना देने की बात नहीं सोचती, जिन्होंने युद्ध के जमाने में या उपद्रवों को शान्त करने में सरकार की भरपूर सहायता की, और उस पर भी उन्हें सरकार के कर्मचारियों ने बिना किसी न्यायसंगत कारण के कैद करके जेल की यातनाएँ सहने को मजबूर किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने काफी विस्तार के साथ दो एक उदाहरण भी पेश किये।

मालवीयजी ने कहा कि विधेयक की बहुत सी धाराएँ “असन्तोषजनक और हानिकार” हैं, और यदि यह पारित किया गया, तो “घोर अन्याय” होगा, जाच कमेटी उससे दुरी तरह प्रभावित होगी, तथ्यों की निष्पक्ष जाच सम्भव नहीं होगी।^१

मालवीयजी ने कहा . “जाच की प्रतीक्षा करिये, उन घटनाओं की जाच हो जाने दीजिये, और जब घटनाएँ निश्चित हो जायें तो शान्ति की रक्षा के लिए सद्भाव से उपयुक्त सावधानी से किये गये आवश्यक कामों के दायित्व से अफसरों को बचाने की चेष्टा करिये। उस दशा में सम्राट् के अफसरों या उनकी आज्ञा से काम करनेवाले मातहतों को बचाने के लिए किये जाने वाले कार्य का

कोई समझदार मनुष्य विरोध नहीं करेगा। पर जब फौजी कानून का अस्तित्व ही न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुआ हो, जब उसके जारी किये जाने का कारण ही न बताया जा सके, उभ समय न्याय और साम्यभाव की रक्षा के लिए साधारण अदालतों में इन अफसरो को अपने कामों के औचित्य व अनौचित्य का निर्णय कराने का अवसर देना ही चाहिए।^१

मालवीयजी ने कहा कि गृह-सदस्य का यह कहना ठीक नहीं कि चूँकि सरकार ने १४ अप्रैल सन् १९१६ के प्रस्ताव में वचन दिया है कि हम उनकी सहायता करेंगे, इसलिए उन्होंने इसके भरोसे पर जो काम किये हैं, उनके दुष्परिणामों से उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। मालवीयजी ने कहा कि यह बात युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि यदि सरकार का उन्हें भरोसा देना ही ठीक नहीं था, तो वह भरोसा उन्हें कैसे बचा सकता है?^२

मालवीयजी ने कहा कि फौजी अदालतों और फौजी कानून की मर्यादाओं और सीमाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लार्ड हैल्सवरी ने कहा है कि सरकार शान्ति के समय फौजी कानून के अनुसार फौजी अदालतें नहीं स्थापित कर सकती, किन्तु जब युद्ध, राजविद्रोह या युद्ध कहे जाने योग्य फसाद हो, राजा या उसके कर्मचारी उतनी ही शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जितनी शान्ति स्थापित करने के लिए आवश्यक हो।^३

राइट बनाम फिट्ज के मुकदमे का विस्तार से विश्लेषण करते हुए मालवीय जी ने बताया कि इस मुकदमे के अन्त में जूरी को सम्बोधित करते हुए न्यायाधीश चैम्बरलेन ने कहा था कि कानून ने विद्रोह को दबाने के लिए मजिस्ट्रेट आदि को शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया है, पर 'उसे उस आवश्यकता से आगे नहीं बढ़ना है जिसने उसे वह अधिकार दिया है, और उसे अपनी सफाई में यह दिखाना होगा कि उसने उस अपराध का पता लगाने के लिए, जिसे उसने दण्डित किया है, प्रभावशाली उपायों का प्रयोग किया है, और उसके व्यवहार में मनुष्यता के सर्वसाधारण नियमों का व्यतिक्रम नहीं दिखाई देना चाहिए'।^४

मालवीयजी ने बताया कि न्यायाधीश स्पेंको ने फौजी अदालतों की मर्यादा और सीमा का विश्लेषण करते हुए कहा है - "बलवे में घोर अत्याचार करते हुए पकड़े जाने, राजा के शत्रुओं को सहायता देने, अथवा अन्य प्रकार की

१. वही, जि० ५८, पृ० ३१८। २. वही, जि० ५८, पृ० ३१८।

३. वही, जि० ५८, पृ० २९६, ३१८। ४. वही, जि० ५८, पृ० ३२२।

दुश्मनी करते हुए पकड़े जानेवाले लोगों का विचार ही ऐसे न्यायालयों में हो सकता है। ऐसी धाराएँ इसलिए बनायी गयी हैं कि फौजी कड़ाइया केवल हत्याओं का रूप धारण न करे। परन्तु ऐसे नलझनदार मामलों, जिनमें अवस्था-जन्य प्रमाणों की, तथा लगनी जाच की आवश्यकता हो, इन अदालतों की सीमा के बाहर रखे गये हैं।”^१

मालवीयजी ने यह भी बनाया कि सर जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफन का कहना है कि “कानून के अनुकूल सत्ता की स्थापना, तथा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा के निमित्त, तथा उपद्रव दवाने के लिए साम्राज्य के कर्मचारियों द्वारा सैनिक शक्ति के सब अधिकारों का धारण किया जाना, और उनसे काम लेना ‘फौजी कानून’ कहलाता है। इसके अनुसार सरकार के अफसरों द्वारा शारीरिक शक्ति का उपयोग यहाँ तक कि प्राण लेना और सम्पत्ति का नष्ट करना, न्यायसंगत हो जाता है। परन्तु उनको निर्दयतापूर्ण तथा अत्यधिक उपायों को काम में लाने का अधिकार नहीं है,”^२ स्टीफन ने यह भी कहा है - “अधिकारियों द्वारा शान्ति की स्थापना तथा विद्रोह को दवाने के लिए जैसे उपाय वे आवश्यक समझें उन्हें करने में समर्थ है, परन्तु आवश्यकता से अधिक प्रत्येक अत्याचार के लिए, यद्यपि उन्होंने विद्रोह तथा युद्ध संबंधी कानूनों के अनुकूल ही काम किया हो, वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं।”^३

मालवीयजी ने कहा कि लार्ड हैल्सवरी और सर जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफन मानते हैं कि “उपद्रवों के शान्त होते ही फौजी सत्ता समाप्त हो जाती है, और साधारण न्यायालयों का शासन शुरू हो जाता है।”^४ स्टीफन साहब की राय में तो फौजी अदालतें वास्तव में “किसी प्रकार के भी न्यायालय नहीं हैं। वे अधिकारियों द्वारा धारण की गयी शक्तियों को काम में लाने अर्थात् उनकी इच्छा के पूर्ण करने के लिए बनी हुई एक प्रकार की कमेटियाँ हैं।”^५

मालवीयजी ने कहा कि विधि-विशेषज्ञ डायसों की राय में सब कानूनों में, जो एक विधान सभा पास कर सकती है, इडेमनिटी कानून से अन्याय होने का सबसे अधिक भय रहता है। यह अपने बाह्य रूप में ही गैर-कानूनी कानून है। यह केवल कड़ाई करने को ही उत्तेजित नहीं करता, बल्कि कानून और मनुष्यता का उल्लंघन करने को भी उत्तेजित करता है।^६

-
१. वही, जि० ५८, पृ० ३३०। २. वही, जि० ५८, पृ० ३२९।
 ३. वही, जि० ५८, पृ० ३३०। ४. वही, जि० ५८, पृ० २९६, ३२९।
 ५. वही, जि० ५८, पृ० ३२९-३०। ६. वही, जि० ५८, पृ० ३४०।

इन प्रमाणों के आधार पर मालवीयजी ने माँग की कि (१) हत्या और आग लगाने के अपराधों के अतिरिक्त सब अपराधों की जाँच साधारण न्यायालय द्वारा हो, (२) फौजी अदालतों द्वारा दण्डित सभी अभियुक्त छोड़ दिये जायें, और यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति की रिहाई सार्वजनिक शान्ति और सुव्यवस्था के हित में न समझी जाय, तो साधारण दण्डव्यवस्था के अनुकूल उसके साथ व्यवहार किया जाय, (३) सम्राट् द्वारा नियुक्त कमिशन के जरिये पंजाब कांड के तथ्यों की जाँच करायी जाय, (४) यदि कमिशन की जाँच से सिद्ध हो जाय कि सार्वजनिक शान्ति और सुव्यवस्था को बनाये रखने या पुनः स्थापित करने के लिए मार्शल ला अनिवार्य था, तब निश्चय किया जाय कि किन शर्तों के साथ किस प्रकार के अन्यायमूलक कार्यों के लिए दोषी अधिकारियों को क्षमा प्रदान की जाय, (५) प्रस्तावित इडेमनिटी बिल पर, जिसकी बहुत सी धाराएँ दोषपूर्ण भी हैं, इस समय विचार न किया जाय, जाँच से पहले क्षमा की व्यवस्था न की जाय ।^१

इडेमनिटी बिल की विभिन्न धाराओं की समीक्षा करते हुए मालवीयजी ने कहा कि यह सिद्ध करना अफसर का कर्तव्य है कि उसने जो कुछ किया है, वह शुद्ध भाव से ही नहीं, बल्कि तर्कयुक्त उचित विचार से भी किया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को इतनी छूट तो मिलनी ही चाहिए कि वे अपने ऊपर अन्याय करनेवालों से इतना तो प्रमाणित करावें कि सार्वजनिक शान्ति और सुव्यवस्था के लिए मनुष्यत्व के नियमों को भंग किये बिना उन्होंने उचित सावधानी से सब काम किये हैं, पर बिल की धारा ३ और ४ ने यह सब कुछ करीब-करीब असंभव कर दिया है। पीड़ित के इस अधिकार को बहुत हद तक सीमित कर दिया है, उसे सारहीन बना दिया है ।^२

मालवीयजी ने कहा कि देश के सब प्रतिष्ठित भारतीय समाचार पत्रों तथा वम्बई हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री नारायण चन्दावरकर जैसे सम्मानित व्यक्तियों ने भी माँग की है कि जब तक जाँच न हो जाय, इडेमनिटी बिल स्थगित रखा जाय। मालवीयजी ने बताया कि 'केपिटल' पत्र में 'डिचर' ने लिखा है कि—यह स्पष्ट है कि इडेमनिटी एक्ट को पास करने का काम और जाँच कमेटी का निर्णय एक दूसरे के आशय के विरुद्ध होंगे। लंदन के 'डेली न्यूज' ने प्रस्तावित कमेटी पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि—“जाँच कमिशन की नियुक्ति से पहले सरकारी अफसरों को बचाने के लिए इडेमनिटी

बिल पास कराने की चेष्टा यह दुबारा विश्राम पैदा करती है कि सरकार अफसरो की नीति पर पलस्तर फेरना चाहती है।”^१

मालवीयजी ने यह कहते हुए कि “शक्तिशाली सरकार को भी लोकमत के आगे झुकना पड़ता है,”^२ सरकार से प्रार्थना की कि जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश न करे तब तक के लिए वह इस बिल को पास कराने के विचार को स्थगित कर दे।^३ उन्होंने कहा : ‘मैं उनके नाम पर जो अगहीन हो गये हैं, उनके नाम पर जिन्होंने वर्णनातीत अपमान सहन किये हैं, उनके नाम पर जो इस क्षण सम्राट् के कैदखानों में अन्याय से सड़ रहे हैं, उन स्त्रियों के नाम पर जो अपने पतियों पुत्रों, सम्बन्धियों के वियोग पर आँसू बहा रही हैं, इस कानून को कमेटी की रिपोर्ट आने तक स्थगित रखने की प्रार्थना करता हूँ।”^४

सरकार का जवाब

सरकार की ओर से सर्वश्री मेनकम हेली तथा टाम्पान आदि ने मालवीयजी की बातों का उत्तर देने का प्रयत्न किया। हेली साहब ने कहा कि अमृतसर, लाहौर आदि की दशा इतनी भयंकर थी कि फौजी कानून लागू करना अनिवार्य था। टाम्पान साहब ने मालवीयजी द्वारा प्रस्तुत कतिपय तथ्यों को गलत साबित करने की कोशिश करते हुए वैधानिक सीमा के अन्दर रहते हुए मालवीयजी पर कड़े से कड़े हमले किये।

२५ सितम्बर सन् १९१९ को गृह-सदस्य सर विलियम विसेंट ने प्रस्ताव किया कि कौंसिल द्वारा संशोधित इंडेमनिटी बिल पास किया जाय। उन्होंने बिल के संग्रन्थ में गांधीजी के विचारों को उद्धृत करते हुए मालवीयजी से विशेष रूप से अपील की कि वे संशोधित बिल का समर्थन करें। विसेंट साहब ने बताया कि मिस्टर गांधी ने “युक्तियुक्त विश्वास” और “सद्भाव” का उल्लेख किए बिना कहा है कि “हमें इस आशय की एक धारा इस (बिल) में रहने देनी चाहिए कि ऐसे अफसरो पर जिन्होंने गोली चलाने की आज्ञा दी, हत्या का फौजदारी मामला या क्षतिपूर्ति का दीवानी दावा न चल सकेगा”, यद्यपि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोषी अफसरो को सरकार की ओर से दण्ड जरूर दिया जाय। विसेंट साहब ने यह भी बताया कि २० सितम्बर सन् १९१९ के ‘यंग इण्डिया’ में यह भी कहा गया है कि “मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि ऐसा

१. वही, जि० ५८, पृ० ३३९-३४०। २. वही, जि० ५८, पृ० ३४१।

३. वही, जि० ५८, पृ० ३४१। ४. वही, जि० ५८ पृ० ३४१।

बिल उचित रूप से कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही पास हो सकता है—यह बिल जैसा प्रकाशित हुआ है हानिरहित है, और यह ऐसा है जिसे हमें कमीशन की रिपोर्ट के बाद पास करना पड़ेगा।”^१

मालवीयजी का विरोध

मालवीयजी ने विसेंट की अपील के उत्तर में कहा : “मैं गिस्टर गांधी की राय का बहुत सम्मान करता हूँ, पर एक और ऐसी बड़ी शक्ति है जिसके आगे झुकना मेरा कर्तव्य है। यह शक्ति मेरी अन्तरात्मा है, और यह मुझसे कहती है कि यह बिल वर्तमान रूप में पास नहीं होना चाहिए।”^२

मालवीयजी ने पूछा कि क्या गांधीजी की इस राय को पढ़ने के बाद गृह-सदस्य भारत सरकार को यह सलाह देंगे कि केवल दम्बई प्रान्त में रहने की जो पाबन्दी गांधीजी पर लगायी गयी है वह रद्द कर दी जाय, और क्या वे “पंजाब और दिल्ली की सरकारों को भी इसी का अनुकरण करने की अर्थात् प्रवेश निषेध की आज्ञाओं को रद्द करने की सलाह देंगे।”^३

मालवीयजी ने टाम्सन आदि सरकारी प्रवक्ताओं के आक्षेपों का उत्तर देते हुए दावा किया कि जो तथ्य उन्होंने अपने पहले भाषण में कौंसिल में प्रस्तुत किये थे वे मूलरूप से सही हैं, और उन घटनाओं और अपराधों से संबंधित अफसरों को क्षमा करने से पहले उनकी ठीक-ठीक जाच आवश्यक है। उन्होंने टाम्सन साहब के अनावश्यक और व्यक्तिगत भावों के लिए उन्हें “क्षमा” करते हुए उनकी बातों की विस्तार से समीक्षा की, और सिद्ध किया कि टाम्सन की सब बातें भ्रामक और गलत हैं। मालवीयजी ने कहा कि घटनाओं का जो विश्लेषण उन्होंने कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया है यदि सरकार उसे गलत समझती है, तो वह खुलकर साफ-साफ उनके प्रश्नों का जिनका उन्होंने नोटिस दिया या उत्तर क्यों नहीं देती? मालवीयजी ने कहा “उपद्रवों को दवाने के लिए फौजी सहायता लेना एक बात है, और फौजी कानून जारी करना दूसरी बात है। प्रकाशित घटनाओं से यह दिखाई देता है कि फौजी सहायता से शान्ति स्थापित हो गयी थी, इसलिए दूसरे उपायों की अर्थात् जनता को फौजी अफसरों की इच्छा पर छोड़ कर गहर को उनके हवाले करने की जरूरत नहीं थी।”^४

१. वही, जि० ५८, पृ० ५३७।

२. वही, जि० ५८, पृ० ५३७।

३. वही, जि० ५८, पृ० ५३७।

४. वही, जि० ५८, पृ० ५४०।

मालवीयजी ने कहा कि मानव-अधिकार किसी विशेष राजाज्ञापत्र या नियमन पर निर्भर नहीं है। “मनुष्य के अधिकार स्वयं परमात्मा ने अपने हाथों से सूर्य की किरणों के रूप में ही मनुष्य के स्वभाव में लिख दिये हैं, और वे किसी मानव की शक्ति से नहीं मिटाये जा सकते।” इनमें जीवन-स्वतंत्रता और जीवन-रक्षा का अधिकार भी है। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह कैसा ही तुच्छ ब्यो न हो, अपनी सरकार से उनका दावा कर सकता है।^१

मालवीयजी ने स्वीकार किया कि जनता की प्रतिनिधि सभा कुछ कामों के लिए अधिकारियों को क्षमा जरूर कर सकती है, पर ऐसा करने से पहले उसे जांच करके सतुष्ट होना होगा कि “यद्यपि कुछ अन्याय के काम हो गये हैं तो भी स्थिति को और बहुसंख्यक लोगों के कल्याण को देखते हुए इन खेदजनक अन्यायों को क्षमा करना चाहिए”।^२

मालवीयजी ने कहा - “यहां आप हमको ऐसे कानून पर सम्मति देने को कह रहे हैं जिसके द्वारा आप उन कामों को जिनकी जांच अभी बाकी है न्यायानुमोदित बनाना चाहते हैं, और उन कामों के उत्तरदायित्व से जिनकी न्यायानुकूलता, औचित्य और मनुष्यत्व अभी विचाराधीन है, अफसरों को मुक्त करना चाहते हैं। यह तो सर्वथा अनुचित है।”^३

मालवीयजी ने बताया कि विधिविशेषज्ञ सर जेम्स मेकिन्टाश का मत है कि “इंग्लैण्ड का कानून एक मात्र इसी सिद्धान्त पर फौजी कानून का जारी रखना सहन करता है कि वह आवश्यक था। इसको जारी रखने की न्यायानुकूलता के लिए भी इसी आवश्यकता की जरूरत है और जरूरत खत्म हो जाने पर यदि वह क्षण भर भी जारी रहे, तो यह गैरकानूनी अत्याचार का प्रयोग हो जायगा।” पर प्रस्तुत विधेयक फौजी कानून के लागू होने के समय से पहले किये गये कामों को, तथा उन कामों को भी जो फौजी कानून के जारी रहने की लम्बी अवधि में किये गये हैं न्यायानुमोदित और उचित बनाना चाहता है, पर उसे स्वीकार करने का कोई युक्तियुक्त और न्याययुक्त कारण नहीं है।^४

मालवीयजी ने डायरी के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा : “यह सुप्रतिष्ठित सिद्धान्त है कि ऊँचे अफसर की कोई आज्ञा अपने मातहत अफसरों को गैरकानूनी कार्य के उत्तरदायित्व से नहीं बचा सकती, और न उसे बचाना ही उचित है। यदि कोई अफसर अपने मातहत को गैरकानूनी कार्य करने की आज्ञा

१ वही, जि० ५८, पृ० ५५५।

२. वही, जि० ५८, पृ० ५५५।

३ वही, जि० ५८, पृ० ५५५।

४. वही, जि० ५८, पृ० ५५५।

दे तो उस मातहत का कर्तव्य है कि वह उस आज्ञा को न माने ।” “गैरकानूनी कार्य करने की आज्ञा राजा भी नहीं दे सकता”, फिर भला गवर्नर-जनरल राजा से अधिक अधिकार का दावा कैसे कर सकता है ?^१

मालवीयजी ने कहा कि “कौंसिल ने कभी किसी को उसकी रक्षा का वचन नहीं दिया है, इसलिए यह युक्ति कि अपने अफसरों को रक्षा करना कौंसिल का कर्तव्य है बिल्कुल सारहीन है ।”^२ यदि शासकमंडल ने ऐसा वचन दिया है तो हरेक अफसर को यह मालूम होना चाहिए कि उसकी शक्ति कितनी है ।^३ उन्होंने दृढ़ता से कहा “यदि सरकार के किसी अफसर ने मनुष्यत्व के विपरीत तथा अपने अधिकार के बाहर काम किया हो, तो उसको न्यायालय में खड़े होकर अपने ऊपर लगाये अभियोगों का उत्तर देना चाहिए ।”^४

सैनिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विश्लेषण करते हुए मालवीयजी ने कहा : “नागरिकों की तरह सैनिकों का भी यह अधिकार है कि वे शस्त्रधारी का सामना शस्त्र से करें, और जानमाल की रक्षा के लिए उचित उपाय ग्रहण करें, परन्तु यदि सैनिक निहत्थे और विरोध न करनेवाले मनुष्यों की हत्या करें, या उनका अगमंग करें, स्त्रियों और बच्चों को अगहीन करें या उन्हें मार डालें, यदि बाधा न करने वाले लोग काट डाले जायें, तो चाहे सैनिकों के ये काम हों या किसी और के, यह हत्या समझी जायेगी और ऐसे लोगों पर देश के कानून के अनुसार मुकदमा चलना चाहिए ।”^५

इस बात का उत्तर देते हुए कि सैनिकों को अपने अफसरों की आज्ञा कोर्ट-मार्शल के भय से मानना पड़ती है, मालवीयजी ने कहा : “आज्ञापालन सैनिक का कर्तव्य है, परन्तु गैरकानूनी आज्ञाओं का नहीं, ऐसी गैरकानूनी आज्ञाओं का नहीं जैसी कि जलियावाला बाग में गोली चलाने के लिए दी गयी ।” अपनी राय की पुष्टि में मालवीयजी ने विधिविशेषज्ञ चायसी और जस्टिस स्टीफन के प्रमाण पेश किया । चायसी ने अपनी पुस्तक में, उन्होंने कहा, लिखा है “सैनिक का कर्तव्य अपने अफसर द्वारा दी गयी आज्ञाओं का पालन करना है । परन्तु सिविल अफसर की अपेक्षा सैनिक यह कहकर कि मैंने युक्ति-युक्त आज्ञा-पालन के कर्तव्य से ऐसा किया - फिर वह आज्ञा प्रधान सेनापति की ही क्यों न हो—कानून भंग करने के उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता ।”^६ जस्टिस स्टीफन ने अपने एक फैसले में कहा

१. वही, जि० ५८, पृ० ५५६ ।

३. वही, जि० ५८, पृ० ५५६ ।

५. वही, जि० ५८, पृ० ५५७ ।

२. वही, जि० ६८, पृ० ५५६ ।

४. वही, जि० ५८, पृ० ५५६ ।

६. वही, जि० ५८, पृ० ५५७ ।

है—“यह सिद्धान्त कि सैनिक को हर हालत में अपने अफसर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सैनिक शिष्टाचार के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे कप्तान की आज्ञा से कर्नल पर गोली चलाना, अथवा अपने से उच्च अफसर की आज्ञा से शत्रु से जा मिलना ठीक सिद्ध होता है। मेरी समझ में यह समझना कम भयंकर नहीं कि शान्ति के समय में निरूपद्रवी नागरिकों पर गोली चलाना, या विद्रोह के समय में स्त्रियों और बच्चों की हत्या करना इसलिए न्याय-युक्त है कि यह सब उच्च अफसर की आज्ञा से किया गया है”।^१

महाराजा साहब महमूदाबाद, राजा रामपाल सिंह, मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा, राय बहादुर बी० एन० शर्मा आदि कतिपय सदस्यों ने भी मालवीयजी की बात का समर्थन किया, सरकार की ओर से उनपर छीटाकशी की गयी। मालवीयजी ने सरकारी प्रवक्तृओं के अनुचित व्यक्तिगत कटाक्षों का मुँहतोड़ जवाब दिया। अपने सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के आदेश पर पंजाब गया था, पर यदि वह आदेश न होता, तो भी दुःखी जनता की सेवा के लिए जरूर जाता।

सरकार अपनी बात पर डटी रही। उसने विल पास करा लिया।

सम्राट् की घोषणा

२५ दिसम्बर सन् १९१९ को सम्राट् की ओर से एक घोषणा प्रसारित की गयी। इस शाही घोषणा में उन सब राजनीतिक कैदियों को, जो हत्या आदि के संगीन अपराधों में दण्डित नहीं थे, क्षमा प्रदान करते हुए आशा व्यक्त की गयी कि “नये युग का शुभारम्भ मेरी प्रजा और मेरे अफसरों के इस संकल्प से होगा कि वे सर्वमान्य उद्देश्य के लिए मिलकर काम करेंगे”। इस घोषणा के आधार पर पंजाब कांड से संबंधित १८०० कैदियों और नजरबन्दों में से ९६ को छोड़ कर बाकी सब छोड़ दिये गये। इसी तरह मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अली आदि भी नजरबन्दी से मुक्त कर दिये गये, और लाला लाजपत राय पर से भी हिन्दुस्तान न आने की रोक उठा ली गयी।

कांग्रेस का अधिवेशन

इस परिस्थिति में सन् १९१९ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में सम्पन्न हुआ। स्वामी श्रद्धानन्दजी ने स्वागत समिति के अध्यक्ष की हैसियत

से प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए पंजाब सरकार के अत्याचारों का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी मार्शल-ला में की गयी ज्यादतियों पर रोशनी डालते हुए सरकार की भर्त्सना की। कांग्रेस ने मांग की कि जनरल डायर को अपने अधिकार से फौरन हटा दिया जाय, पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर सर माइकेल ओडायर को फौजी कमीशन की सदस्यता से भी अलग कर दिया जाय, तथा सम्राट् से अनुरोध किया कि लार्ड चेम्सफोर्ड को वापस बुला लिया जाय। कांग्रेस ने सर शकरन नायर के प्रति, जिन्होंने पंजाब में मार्शल-ला चालू रखने के विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हुए गवर्नर-जनरल की कार्य-परिपद से इस्तीफा दिया था, आगार प्रकट किया। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि नागरिकों के मौलिक अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित हो, रौलेट अधिनियम और भारतीय रक्षा अधिनियम रद्द किये जायें, और वे सब अधिनियम और अव्यादेश जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो अवैध समझे जायें। उसने क्षमा अधिनियम के लिए सरकार की भर्त्सना की।

कांग्रेस ने तुर्की और खिलाफत के प्रश्नों पर ब्रिटिश मन्त्रियों की द्विद्वेषी मनोवृत्ति के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए सम्राट् की सरकार से अनुरोध किया कि भारतीय मुसलमानों की न्यायसंगत भावनाओं तथा प्रधानमन्त्री की प्रतिज्ञाओं के अनुरूप तुर्की का प्रश्न हल किया जाय, जिसके बिना भारत की जनता में सन्तोष नहीं होगा। उसने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव का स्वागत किया जिसमें मुसलमानों को रालाह दी गयी थी कि वकरीद पर भारत में शोकश्री बन्द कर दी जाय। उसने स्वीकार किया कि यह प्रस्ताव मुसलमानों की ओर से हिन्दू और मुसलमान एकता की ओर सबसे बड़ा कदम है, और आशा व्यक्त की कि मुसलमानों की सद्भावना के जवाब में हिन्दू भी पूरे तौर पर सद्भावना व्यक्त करेंगे।

श्री चित्तरंजन दास ने प्रस्ताव किया कि (१) यह कांग्रेस गत वर्ष की इस घोषणा को दोहराती है कि भारत पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य है, और इसके विपरीत की गयी सब कल्पनाओं का खण्डन करती है, (२) यह कांग्रेस संवैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में पारित दिल्ली कांग्रेस के प्रस्तावों का समर्थन करती है और उसकी राय है कि नया सुधार अधिनियम अपर्याप्त, असन्तोषजनक, तथा निराशाजनक है, (३) यह कांग्रेस पार्लियामेंट से अनुरोध करती है कि वह आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुकूल भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के निमित्त जल्द कदम उठाये।

है—“यह सिद्धान्त कि सैनिक को हर हालत में अपने अफसर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सैनिक शिक्षाचार के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे कप्तान की आज्ञा से कर्नल पर गोली चलाना, अथवा अपने से उच्च अफसर की आज्ञा से शत्रु से जा मिलना ठीक सिद्ध होता है। मेरी समझ में यह समझना कम भयंकर नहीं कि शान्ति के समय में निरूपद्रवी नागरिकों पर गोली चलाना, या विद्रोह के समय में स्त्रियों और बच्चों की हत्या करना इसलिए न्याय-युक्त है कि यह सब उच्च अफसर की आज्ञा से किया गया है” ।^१

महाराजा साहब महमूदाबाद, राजा रामपाल सिंह, मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा, राय बहादुर वी० एन० शर्मा आदि कतिपय सदस्यों ने भी मालवीयजी की बात का समर्थन किया, सरकार की ओर से उनपर छोटाकशी की गयी। मालवीयजी ने सरकारी प्रवक्ताओं के अनुचित व्यक्तिगत कटाक्षों का मुँहतोड़ जवाब दिया। अपने सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के आदेश पर पंजाव गया था, पर यदि वह आदेश न होता, तो भी दुःखी जनता की सेवा के लिए जरूर जाता।

सरकार अपनी बात पर डटी रही। उसने विल पास करा लिया।

सम्राट् की घोषणा

२५ दिसम्बर सन् १९१९ को सम्राट् की ओर से एक घोषणा प्रसारित की गयी। इस शाही घोषणा में उन सब राजनीतिक कैदियों को, जो हत्या आदि के संगीन अपराधों में दण्डित नहीं थे, क्षमा प्रदान करते हुए आशा व्यक्त की गयी कि “नये युग का शुभारम्भ मेरी प्रजा और मेरे अफसरों के इस संकल्प से होगा कि वे सर्वमान्य उद्देश्य के लिए मिलकर काम करेंगे”। इस घोषणा के आधार पर पंजाब कांड से संबंधित १८०० कैदियों और नजरबन्दों में से ९६ को छोड़ कर बाकी सब छोड़ दिये गये। इसी तरह मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अली आदि भी नजरबन्दी से मुक्त कर दिये गये, और लाला लाजपत राय पर से भी हिन्दुस्तान न आने की रोक उठा ली गयी।

कांग्रेस का अधिवेशन

इस परिस्थिति में सन् १९१९ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में सम्पन्न हुआ। स्वामी श्रद्धानन्दजी ने स्वागत समिति के अध्यक्ष की हैसियत

से प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए पंजाब सरकार के अत्याचारों का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी मार्शल-ला में ली गयी ज्यादतियों पर रोशनी डालते हुए सरकार की भर्त्सना की। कांग्रेस ने मांग की कि जनरल डायर को अपने अधिकार से फौरन हटा दिया जाय, पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर सर माइकेल ओडायर को फीजी कमीशन की सदस्यता से भी अलग कर दिया जाय, तथा सम्राट् से अनुरोध किया कि लार्ड चेम्सफार्ड को वापस बुला लिया जाय। कांग्रेस ने सर शकरन नायर के प्रति, जिन्होंने पंजाब में मार्शल-ला चालू रखने के विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हुए गवर्नर-जनरल की कार्य-परिषद से इस्तीफा दिया था, आभार प्रकट किया। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि नागरिकों के मौलिक अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित हों, रोलेट अधिनियम और भारतीय रक्षा अधिनियम रद्द किये जायें, और वे सब अधिनियम और अव्यादेश जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों अवैध समझे जायें। उसने क्षमा अधिनियम के लिए सरकार की भर्त्सना की।

कांग्रेस ने तुर्की और खिलाफत के प्रश्नों पर ब्रिटिश मन्त्रियों की विद्वेषी मनोवृत्ति के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए सम्राट् की सरकार से अनुरोध किया कि भारतीय मुसलमानों की न्यायसंगत भावनाओं तथा प्रधानमन्त्री की प्रतिज्ञाओं के अनुरूप तुर्की का प्रश्न हल किया जाय, जिसके बिना भारत की जनता में सन्तोष नहीं होगा। उसने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव का स्वागत किया जिसमें मुसलमानों को सलाह दी गयी थी कि बकरीद पर भारत में शोकसूची बन्द कर दी जाय। उसने स्वीकार किया कि यह प्रस्ताव मुसलमानों की ओर से हिन्दू और मुसलमान एकता की ओर सबसे बड़ा कदम है, और आशा व्यक्त की कि मुसलमानों की सद्भावना के जवाब में हिन्दू भी पूरे तौर पर सद्भावना व्यक्त करेंगे।

श्री चित्तरंजन दास ने प्रस्ताव किया कि (१) यह कांग्रेस गत वर्ष की इस घोषणा को दोहराती है कि भारत पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य है, और इसके विपरीत की गयी सन कल्पनाओं का खण्डन करती है, (२) यह कांग्रेस संवैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में पारित दिल्ली कांग्रेस के प्रस्तावों का समर्थन करती है और उसकी राय है कि नया सुधार अधिनियम अपर्याप्त, असन्तोषजनक, तथा निराशाजनक है, (३) यह कांग्रेस पार्लियामेंट से अनुरोध करती है कि वह आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुकूल भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के निमित्त जल्द कदम उठाये।

इस प्रस्ताव का लोकमान्य तिलक, एस० सत्यमूर्ति, मौलाना हसरत मौहानी ने समर्थन किया। पर गांधीजी, मालवीयजी, टी० प्रकाशम, विपिनचन्द्र पाल, मौलाना मुहम्मद अली और श्रीमती एनी बेसेंट इससे पूरी तौर पर संतुष्ट नहीं थे। ये सब चाहते थे कि मान्टेग्यू के प्रति आभार प्रकट किया जाय, और नयी व्यवस्था को कार्यान्वयन करने का भी किसी न किसी रूप में सकेत हो। इस उद्देश्य से गांधीजी, विपिनचन्द्र पाल, तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने संशोधन प्रस्तुत किये। गांधीजी ने अपने संशोधन में शाही घोषणा के वाक्यों को दोहराते हुए आशा व्यक्त की कि “अधिकारी और जनता सुधारों को कार्यान्वयन करने में इस तरह सहयोग करेंगे कि पूरा उत्तरदायी शासन शीघ्र मिल पाये।” इस संशोधन में मांटेग्यू को उनके प्रयत्नों के लिए धन्यवाद देते हुए सुझाव था कि मूल प्रस्ताव में से यह बात निकाल दी जाय कि नये सुधार “असन्तोषजनक” हैं। अन्त में बहुत वाद-विवाद के बाद श्रीमती एनी बेसेंट के संशोधन को नामंजूर करते हुए चित्तरंजन दास, लोकमान्य तिलक, मालवीयजी तथा विपिन चन्द्र पाल आदि की अनुमति से निम्नलिखित संशोधन को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने दास साहब का मूल प्रस्ताव भारी बहुमत से पास कर दिया—

“इस प्रकार का शासन कायम होने तक कांग्रेस आशा करती है कि जनता सुधारों को इस तरह कार्यान्वित करेगी कि पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना निकट भविष्य में प्राप्त हो सके। कांग्रेस महामहिम ई० एस० मान्टेग्यू को, उनके परिश्रम के लिए जो उन्होंने सुधारों के सम्बन्ध में किया है, धन्यवाद देती है।”

अमृतसर के इस प्रस्ताव से यह साफ है कि कांग्रेस के सभी नेता सुधारों को अपर्याप्त समझते हुए और पंजाब हत्याकाण्ड से क्षुब्ध होते भी नयी शासन-व्यवस्था का बाइकाट करने के बजाय पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए उसका प्रयोग करना चाहते थे। लोकमान्य तिलक ने तो आगामी चुनावों के लड़ने तथा नयी विधान कौंसिलो में भाग लेने के लिए अधिवेशन के बाद कांग्रेस डिमोक्रेटिक पार्टी को संघटित करना भी प्रारम्भ कर दिया।

हंटर कमेटी और कांग्रेस जाच कमेटी -

हंटर कमेटी ने २६ अक्टूबर सन् १९१६ को अहमदावाद से अपनी जाच प्रारम्भ की। यहाँ गुजरात कांग्रेस कमेटी ने उसके साथ सहयोग किया। २९ अक्टूबर को कमेटी ने दिल्ली में वहाँ की घटनाओं की जाच की। यहाँ कांग्रेस की ओर से श्री चित्तरंजन दास ने गवाहों से जिरह की। नवम्बर के प्रथम

सप्ताह में कमेटी ने पंजाब की घटनाओं की जांच प्रारम्भ की। उसकी पहली बैठक में पर्यवेक्षक की हँसियत से मालवीयजी और दास साहब भी उपस्थित थे। पर यहाँ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि हंटर कमेटी के साथ तभी सहयोग करेंगे जब सरकार उनकी ये तीन शर्तें स्वीकार करे। पहली यह कि गवाहों से जिरह करने की इजाजत होगी। दूसरी यह कि अदालतों के सरसरी फैसलों की परीक्षा के लिए जो जज नियुक्त किये जायें, उनमें से एक पंजाब के बाहर का होगा। तीसरी यह कि जांच के दौरान में मुनासिब जमानत पर कुछ मुख्य कैदी अस्थायी तौर पर जेल से छोड़ दिये जायेंगे। पंजाब सरकार ने पहली दो शर्तें मंजूर कर ली, पर वह तीसरी शर्त पूरी तौर से मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि यदि हंटर कमेटी किसी कैदी की गवाही लेना उचित समझेगी, तो उसका प्रबन्ध कर दिया जायगा, और यदि इस जांच से सबधित कोई वकील किसी कैदी से परामर्श करना आवश्यक समझेगा, तो उसकी सुविधा भी दे दी जायेगी।

पंजाब के कार्यकर्ताओं ने मालवीयजी के नेतृत्व में हंटर कमेटी के सामने अत्याचारों को साबित करने का निर्णय किया। मालवीयजी भी तैयार हो गये, पर गांधीजी इस निर्णय से सहमत नहीं थे। उन्हें यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने पंजाब से चले जाने का इरादा किया। इस परिस्थिति में स्वामी श्रद्धानन्द ने उन सब नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो तीसरी शर्त की पूर्ति के बिना भी हंटर कमेटी के सामने सबूत पेश करने को तैयार थे, समझाया कि वे गांधीजी की बात मान कर हंटर कमेटी से सहयोग करने का विचार छोड़ दें। पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु चितरंजन दास ने, तथा पंजाब के बहुत से कार्यकर्ताओं ने स्वामी श्रद्धानन्द की बात स्वीकार कर ली। पर मालवीयजी तथा पंजाब के दो-तीन नेताओं ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इस पर गांधीजी के निवास स्थान पर दूसरी बैठक हुई, जिसमें उपस्थित सज्जनों ने भारी बहुमत से गांधीजी की बात स्वीकार कर ली। मालवीयजी ने स्वयं इसके विरुद्ध अपनी राय दी। निर्णय हो जाने पर उन्होंने पंजाब गवर्नर के पास भेजे जाने वाले बहुसंख्यक निर्णय का मसौदा स्वयं ही लिखा, और उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ ली। इस घटना की विस्तार से चर्चा करते हुए स्वामी श्रद्धानन्द ने एक सस्मरण में लिखा है : “निःस्वार्थपन और प्रजातंत्रीय भावना का यह उत्कृष्ट उदाहरण था। यह उन अनेक अवसरों में केवल एक है जबकि मालवीय जी ने राजनीतिक नेताओं के सामने शान्त किन्तु शानदार उदाहरण पेश किया था। अपने समय के महान् नेता महात्मा गांधी तथा मालवीयजी को समझने में

यह घटना हमारी काफी सहायता करती है। अपनी बात न माने जाने पर गांधीजी सरकार को पत्र लिख कर पंजाब छोड़ कर जाने को तैयार थे। पर मालवीयजी ! उन्हें बहुमत के सामने सिर झुका देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मालवीयजी की निःस्वार्थ-प्रियता, सदाशयता, उच्चता, निरभिमानता, तथा प्रजातंत्रीय भावना के सम्बन्ध में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है ?”^१

१३ नवम्बर को पंजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर कांग्रेस को दो और वाते देने को तैयार हो गये। पहली यह कि यदि कमेटी के सामने गवाही देने के लिए कोई प्रमुख कैदी बुलाया गया, तो वह थोड़े समय के लिए गवाही देने के दिन इस शर्त पर पेट्रोल पर छोड़ दिया जायगा कि कोई प्रदर्शन नहीं होगा। दूसरी यह कि जाच के दौरान वकील निश्चित समय पर जेल में उस कैदी से मिल सकते हैं जिसका नाम गवाही के लिए कमेटी को दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं की मांग थी कि प्रमुख कैदियों को हिरासत में कमेटीयों की उन बैठकों में मौजूद रहने की आज्ञा दी जाये, जिनमें उस घटना के सम्बन्ध में गवाही होती हो जिससे वह सम्बद्ध है, ताकि वह वकील को उन तथ्यों के सबंध में जिनकी उसे जानकारी है उचित परामर्श दे सके। कांग्रेस की बात सरकार मानने को तैयार नहीं थी, और सरकार की बात गांधीजी मानने को राजी नहीं थे। समझौता नहीं हो सका।

इसके बाद कांग्रेस की पंजाब सब-कमेटी ने कांग्रेस जाच कमेटी नियुक्त करने का निश्चय किया। गांधीजी, अब्बास तैयबजी, श्री चित्तरजन दास, फजलुल हक साहब और पंडित मोतीलाल नेहरू जाच कमेटी के सदस्य नियुक्त हुए। इनमें से फजलुल हक साहब जरूरी काम से कलकत्ते चले गये, और पंडित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिये जाने पर जाच कमेटी से इस्तीफा दे दिया, और इन दोनों की जगह पर श्री मुकुन्द आर० जयकर सदस्य नियुक्त हुए। श्री के० सन्तानम ने जाच कमेटी के सचिव का काम किया।

२५ दिसम्बर को सम्राट् की क्षमा घोषणा से पंजाब के बन्दी मुक्त कर दिये गये। इसके बाद कांग्रेस की पंजाब उपसमिति ने हटर कमेटी के साथ सहयोग करने का निश्चय किया। पर यह संभव नहीं हो सका, और कांग्रेस जाच कमेटी ने स्वतंत्र रूप से जाच करके अपनी रिपोर्ट और निष्कर्षों को जनता के सामने पेश करने का निर्णय किया। पर उसने कांग्रेस उपसमिति के आदेशानुसार हटर कमेटी के सामने प्रस्तुत सरकारी अफसरो की गवाहियों का भी पूरी

तौर पर उपयोग किया। इस तरह कांग्रेस जाच कमेटी की रिपोर्ट सरकारी अफसरों तथा भुक्तभोगी जनता, दोनों के दयानों पर आधारित थी।

कांग्रेस जाच कमेटी की रिपोर्ट

२० फरवरी सन् १९२० को गांधीजी, श्री चितरजन दास, मिस्टर अब्बास तैयबजी और श्री एम० आर० जयकर ने पंजाब कांड पर सर्वसम्मति रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर उसे कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के पास भेज दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब की जनता सर माइकेल ओडायर के शासन की ज्यादतियों और सख्तियों से परेशान और रुष्ट थी, तथा रीलेट अधिनियम से भी उत्तेजित हो गयी थी, पर सरकार को उलट देने की कोई भावना या साजिश नहीं थी। पंजाब की सन् १९१९ की स्थिति की सन् १८५७ की स्थिति से तुलना निराधार थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गांधीजी की गिरफ्तारी और निष्कासन, तथा डाक्टर सत्यपाल और डाक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारियाँ और नजरबन्दियाँ ही अमृतसर की जनता की उत्तेजना के तात्कालिक कारण थे, और रेल के पुल पर भीड़ पर गोली-बर्षा तथा कई आदमियों की उससे मृत्यु ही उत्तेजना और व्यग्रता का कारण थी, जिसका दुष्परिणाम जनता द्वारा दो यूरोपियनों की हत्या तथा गिरफ्तार लोगों की बरबादी था। ये ज्यादतियाँ निःसंदेह निन्दनीय और दण्डनीय थीं। पर इनके कारण सारे नगर का शासन सेना के अधिकारियों के सुपुर्द करना सर्वथा अनुचित था।

कमेटी ने जलियावाला बाग में निर्दोष निहत्थी जनता पर गोली-बर्षा को “क्रूरता का पूर्वनियोजित कार्य” बता कर जनरल डायर की निर्दयता तथा उच्छृङ्खल व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए माग की कि उसे सब सरकारी पदों से अलग कर दिया जाय।

कमेटी की निश्चित राय थी कि मार्शल-ला चालू करने का कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं था। उसे अत्यधिक काल तक जारी रखना तो और भी गलत था। हर जगह मार्शल-ला प्रशासन “क्रूर और दमनकारी” था। मार्शल-ला ट्रिब्यूनल और समरी कोर्ट जनता को सताने के साधन बना लिये गये थे, और उनके द्वारा बुरी तरह से ‘न्याय की झूठहत्या’ की गयी थी।

मार्शल-ला अधिकारियों और कर्मचारियों के बहुत से कार्यों की निन्दा करते हुए कमेटी के सदस्यों (आयुक्तों) ने माग की कि कर्नल जानसन, कर्नल ओबरायन, मिस्टर वासवर्थ स्मिथ, राय साहब श्रीराम सूद और मालिक साहब

खा को सरकारी उत्तरदायित्व और पदों से हटा दिया जाय, निम्नकोटि के कतिपय कर्मचारियों की कार्रवाइयों की स्थानीय जाच करायी जाय ।

आयुक्तों ने पंजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर माइकल ओडायर को ही मारी दुर्घटना का मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए मांग की कि उन्हें "सम्राट् के सब उत्तरदायित्व कार्यभार से अलग कर दिया जाय ।" आयुक्तों ने काफी विस्तार के साथ वाइसराय के कार्यों और दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हुए उन्हें भी पंजाब की दुर्घटनाओं का उत्तरदायी ठहराते हुए संस्तुति की कि उन्हें वापस बुला लिया जाय ।

हटर कमेटी की रिपोर्ट

भारत सरकार द्वारा २४ अक्तूबर सन् १९१९ को नियुक्त हटर कमेटी ने ८ मार्च सन् १९२० को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । कमेटी के हिन्दुस्तानी सदस्य (श्री चिम्मनलाल रीतलवादा, श्री जगत नारायण मुल्ला तथा सरदार साहबजादा सुलतान अहमद) और उसके अंग्रेज सदस्य (लार्ड हटर, जस्टिस जी० सी० रेनकिन, मिस्टर डब्ल्यू० एफ० राइस, मेजर जनरल सर जार्ज वरी और मिस्टर थामस स्मिथ) एक राय के नहीं थे । दोनों के निष्कर्षों में मौलिक भेद था । इसलिए हिन्दुस्तानी सदस्यों ने अंग्रेज सदस्यों से अलग एक अल्प-संख्यक रिपोर्ट लिखी, जिसके स्थिति-विश्लेषण और निष्कर्ष बहुसंख्यक रिपोर्ट से बहुत भिन्न थे ।

कमेटी के अंग्रेज सदस्यों के निचार में अप्रैल सन् १९१९ में विद्रोह (वगावत) की स्थिति थी, जिस पर काबू पाने के लिए मार्शल-ला घोषित करना और सैनिक शासन प्रतिष्ठित करना अनिवार्य था । हिन्दुस्तानी सदस्यों की राय में उपद्रवों को 'विद्रोह' समझ मार्शल-ला घोषित करना अनुचित, अनावश्यक था । उनका निष्कर्ष था कि उपद्रवों के पीछे कोई पूर्वनियोजित साजिश नहीं थी, सिविल अधिकारी साधारण सी सैनिक सहायता से उपद्रवों को कन्ट्रोल कर सकते थे, मार्शल-ला शासन को चालू करना गलत था, पर उसे यदि ठीक भी मान लिया जाय, तो उसे कुछ दिनों के बाद जारी रखना नहीं चाहिए था । कमेटी के अधिकांश सदस्यों ने सरकारी अफसरों के बहुत से कामों को अमानुषिक बताया और मार्शल-ला के अधीन स्थापित न्यायालयों की कार्रवाइयों की आलोचना की ।

कमेटी के अंग्रेज सदस्यों ने भी स्वीकार किया कि मार्शल-ला अधिकारियों के कतिपय आदेश "अविवेकपूर्ण" थे, उन्होंने "कोई अच्छा प्रयोजन पूरा नहीं

किया" और वे नागरिकों को निरर्थक कष्ट से बचाने के पर्याप्त कौशल से तैयार नहीं किये गये थे ।^१ अग्रेज सदस्यों ने यह भी स्वीकार किया कि "सड़क पर पेट के बल रेंगने की सजा" ने "जहाँ बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को निरर्थक कष्ट दिया", "वहाँ इस अपमानजनक कार्य" ने ऐसी "कटुता और प्रजातीय दुर्भावना" पैदा की जो बहुत दिन जारी रही" ।^२

यद्यपि वाइसराय की कार्यपरिषद् के हिन्दुस्तानी सदस्य गियाँ मुहम्मद शफी ने अल्पसंख्यक रिपोर्ट के निष्कर्षों को ठीक समझा, कार्यपरिषद् के अग्रेज सदस्यों ने अधिसंख्यक रिपोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की। भारत सरकार ने अपने परिपत्र में जनरल डायर के व्यवहार की किसी हद तक निन्दा करते हुए यह भी कहा कि "जनरल डायर के कार्य ने किसी हद तक उपद्रवों को फैलने से रोका ।"

भारतमन्त्री ने कमेटी की बहुसंख्यक रिपोर्ट और भारत सरकार के परिपत्र को मान्यता प्रदान करते हुए केवल जनरल डायर के व्यवहार की ही निन्दा की और कमांडर-इन-चीफ की इस आज्ञा का समर्थन किया कि जनरल डायर से ब्रिगेडियर-जनरल पद से इस्तीफा दिला दिया जाय। भारत-मन्त्री ने आशा व्यक्त की कि जिन कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की ओर हटर कमेटी के बहुसंख्यक सदस्यों ने संकेत किया है उन्हें किसी उचित ढंग से चेतावनी दे दी जायगी, और सरकार की निन्दा किसी न किसी रूप में नोट कर दी जायगी। अन्त में भारतमन्त्री ने ब्रिटिश सरकार की ओर से मब सिविल और फौजी अफसरों के प्रति वाइसराय के आदर का समर्थन करते हुए, वाइसराय के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट किया।

ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिकांश सदस्यों ने जनरल डायर का समर्थन करना ही उचित समझा। यद्यपि कामन्स सभा (हाउस आफ कामन्स) ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया, सरदार सभा (हाउस आफ लार्ड्स) ने ८६ मतों के विरुद्ध १२९ मतों से यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि यह सदन 'जनरल डायर' के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय को उस अफसर के प्रति "अन्याय" समझ "क्षोभ" प्रकट करता है, उसकी राय में यह ऐसी मिसाल प्रस्तुत करता है जो "वगावत की हालत में भारत की व्यवस्था की रक्षा में बाधक होगी ।"



१३. असहयोग आन्दोलन

खिलाफत का प्रश्न

युद्ध के जमाने में ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने अरबों से वायदा किया कि युद्ध के बाद तुर्की के साथ आत्मनिर्णय तथा राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों का अनुसरण किया जायगा, और हिन्दुस्तान के मुसलमानों से वायदा किया कि श्रास तथा एशिया माइनर तुर्की से छीना नहीं जायगा। पर गुप्त रूप से उसने यहूदियों से वायदा किया कि युद्ध के बाद उन्हें फिलस्तीन में बसाने का प्रबन्ध किया जायगा। रूस से वायदा किया कि युद्ध के बाद कुस्तुनतुनिया रूस साम्राज्य में मिला दी जायगी, और फ्रान्स से तय किया कि युद्ध के बाद अरब के एक भाग पर फ्रान्स और दूसरे भाग पर ब्रिटेन का अधिकार किसी न किसी रूप में स्थापित किया जायगा।

युद्ध के बाद मुसलमानों ने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने जो वायदे अरबों से और उनसे किये हैं, उन सबकी उपेक्षा करते हुए वह तुर्की साम्राज्य को, जिसका सुलतान मुसलमानों का खलीफा है, बिल्कुल नष्ट कर देना चाहती है। उन्हें उस समय पता चला कि दरें दानियाल को सैनिक-बिहीन कर देने की, कुस्तुतुनिया को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करने की, फिलस्तीन में यहूदियों को बसाने की, श्रास को यूनानियों को सौंप देने की, तुर्की में हार्ड कमिश्नर नियुक्त करने की, तथा अरब को तीन हिस्सों में बाँटकर प्रादेश (मेन्डेट) के नाम पर दो भागों में ब्रिटेन का और एक भाग पर फ्रांस का प्रभुत्व प्रतिष्ठित करने की योजनाएँ बनायी जा रही हैं।

खिलाफत कमेटी

इन योजनाओं के समाचारों ने भारत के मुसलमानों को विह्वल कर दिया। सितम्बर सन् १९१९ में खिलाफत कमेटी गठित की गयी, और २२ नवम्बर सन् १९१९ को दिल्ली में मिस्टर फजलुल हक साहब की अध्यक्षता में खिलाफत कांग्रेस का पहला अधिवेशन सम्पन्न हुआ। दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अमृतसर में कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर मुसलमान नेताओं ने हिन्दू नेताओं से खिलाफत की समस्या पर बातचीत की। हिन्दू नेताओं ने मुसलमानों की भावनाओं के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए उनका साथ देने का उन्हें आश्वासन दिया।

३१ दिसम्बर सन् १९१९ को मौलाना शौकत अली की अध्यक्षता में खिलाफत काफ्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसने खिलाफत के प्रश्न पर ब्रिटेन की गतिविधि पर धोभ प्रकट करते हुए घोषित किया कि “भारतीय मुसलमान उन माँगों पर दृढ़ रहेंगे जो इस्लाम का कानून उन्हें प्रतिपादित करने और अभिव्यक्त करने को वाध्य करता है”, और चेतावनी दी कि “यदि ब्रिटिश सरकार ने सन्धि काफ्रेस में उन बातों को स्वीकार किया जो हमारे दीन की मान्यताओं के प्रतिकूल है, तो उस दशा में हमारा व्यवहार उन कर्तव्यों से शासित होगा जिन्हें हमारे दीन ने हम पर प्रबलरूप से लागू किया है और उसके लिए ब्रिटिश सरकार ही उत्तरदायी होगी।”^१ इस अधिवेशन में बहुत से मुसलमान नेताओं के अतिरिक्त गांधीजी और मालवीयजी भी उपस्थित थे।

१९ जनवरी सन् १९२० को डाक्टर मुख्तार अहमद अन्सारी की अध्यक्षता में मुसलमानों का एक शिष्ट-मंडल वाइसराय से मिला। उसने तुर्की साम्राज्य तथा खलीफा की प्रभुसत्ता की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि धार्मिक सस्था के साथ साथ लौकिक सस्था के रूप में भी खिलाफत का सतत अस्तित्व उनके धर्म का मूल तत्त्व है। वाइसराय ने मुसलमानों की भावनाओं के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि समस्या का निबटारा केवल ब्रिटेन के हाथ में नहीं है। इस उत्तर को असन्तोषजनक समझ कर बहुत से मुसलमानों ने घोषित किया कि “मुस्लिम विशेषज्ञों द्वारा परिसीमित अरब देश तथा मुसलमानों के पवित्र स्थान खलीफा के नियन्त्रण में रहने चाहिए”, और “यदि सन्धि की शर्तें इस्लाम धर्म और मुसलमानों की भावना के विरुद्ध होंगी, तो वह मुसलमानों की वफादारी पर बहुत तनाव सिद्ध होगी”^२।

फरवरी सन् १९२० में खिलाफत कमेटी ने मौलाना मुहम्मद अली की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ब्रिटेन को भेजने का निश्चय किया। यह भी निश्चय हुआ कि यदि प्रधानमंत्री का उत्तर सन्तोषजनक न हो, तो सारे देश में ‘शोक दिवस’ मनाया जाय। मौलाना शौकत अली ने घोषित किया कि उस दिन यह प्रस्ताव पारित हो कि यदि सन्धि की शर्तें भारतीय मुसलमानों की भावनाओं के अनुकूल नहीं होंगी, तो मुसलमान ब्रिटिश ताज से अपना वफादाराना सम्बन्ध तोड़ने पर मजबूर होंगे।^३

१ इंडियन एनुअल रजिस्टर, सन् १९२०, पृ० ४६१।

२. पट्टाभि सीतारमैया हिस्ट्री आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस, पृ० १९०।

३ वही, पृ० १९१।

गांधीजी का वक्तव्य

१० मार्च सन् १९२० को गांधीजी ने एक वक्तव्य प्रसारित किया जिसमें उन्होंने कहा—“इंगलिस्तान हमसे उन अधिकारों के अन्यायपूर्ण अपहरण की विनम्र आज्ञाकारिता की आशा नहीं कर सकता जो मुसलमानों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है।”^१ उन्होंने कहा : “असहयोग कर्तव्य हो जाता है जब सहयोग का अर्थ अधोगति या अपमान हो, अपनी धार्मिक भावना पर अघात हो,”^२ उन्होंने अहिंसात्मक असहयोग के तात्त्विक और व्यावहारिक गुणों की ओर संकेत करते हुए एकमात्र व्यावहारिक दृष्टि से ही उसे स्वीकार करने का मुसलमानों से अनुरोध किया।^३

प्रधान मंत्री का उत्तर

लन्दन में खिलाफत कमेट्री का शिष्ट-मंडल भारत-मंत्री के स्थान पर ब्रिटेन के मंत्री फिशर से, और उसके बाद २७ मार्च को प्रधान-मंत्री लायड जार्ज से मिला। उन्होंने मौलाना मुहम्मद अली से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुर्कों की सलतनत उनकी मातृभूमि पर बनी रहेगी, पर पश्चिमी एशिया पर से उसका आधिपत्य खत्म कर दिया जायगा।

अहिंसात्मक आन्दोलन

१९ मार्च सन् १९२० को भारत के मुसलमानों ने सारे देश में ‘शोक दिवस’ मनाया, तथा खिलाफत के अस्तित्व और गौरव को बनाये रखने के लिए हर कुर्बानी करने का प्रण किया। १४ मई सन् १९२० को मित्रराष्ट्रों ने तुर्कों से की जाने वाले सन्धि की रूपरेखा प्रकाशित की। २ जून सन् १९२० को कतिपय नेताओं की कान्फरेन्स में खिलाफत के प्रश्न पर अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम तैयार करने का निश्चय हुआ। चूँकि इस्लाम धर्म ऐसी परिस्थितियों में मुसलमानों को हिंसात्मक संघर्ष की इजाजत देता है, इसलिए बहुत से मुसलमान “अहिंसा” की शर्त स्वीकार करने से हिचकते थे। पर गांधीजी के समझाने पर तथा लखनऊ के मौलाना अब्दुलवारी के फतवा पर वे अहिंसा को नीति के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गये। मौलाना साहब का कहना था कि इस्लाम हिंसात्मक संघर्ष की इजाजत देता है, पर अहिंसात्मक संघर्ष को मना नहीं करता, परिस्थिति को ध्यान में रख कर नीति के रूप में हिंसा के बजाय अहिंसा का

१ वही, पृ० १९१।

२ वही, पृ० १९१।

३. वही, पृ० १९१।

अवलम्बन किया जा सकता है। १ अगस्त सन् १९२० को खिलाफत कमेटी की ओर से आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। उस दिन गांधीजी ने "कैमरे हिन्द" का तमगा सरकार को लौटा दिया।

हिजरत

इसी प्रसंग में खिलाफत के प्रति ब्रिटिश सरकार की वक्र दृष्टि से क्षुब्ध हो मौलवियों के फतवे पर अगस्त में ही सिन्ध तथा सीमा प्रान्त के लगभग १८००० मुसलमानों ने अफगानिस्तान को हिजरत करने की ठान ली। पर कुछ समय काबुल में रहने के बाद करीब करीब सब हिन्दुस्तान वापस लौट आये, कुछ ताशकन्द चले गये।

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन

३० मई १९२० को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सितम्बर में पंजाब के प्रश्न पर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया था। कांग्रेस के करीब-करीब सभी नेताओं की राय थी कि इस अधिवेशन में खिलाफत के प्रश्न पर भी विचार किया जाय। उनकी धारणा थी कि कांग्रेस के अधिवेशन में ही पुराने निर्णयों को बदल कर नया कार्यक्रम निश्चित किया जा सकता है, और कांग्रेस के विरुद्ध या उससे अलग देशव्यापी संघर्ष या आन्दोलन प्रारम्भ करना अनुचित है।

गांधीजी इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने असहयोग आन्दोलन की रूपरेखा बताते हुए स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस का चाहे कुछ भी निर्णय हो, आन्दोलन शुरू किया जायगा, और १ अगस्त को उन्होंने खिलाफत कान्फ्रेंस की ओर से कार्य प्रारम्भ भी कर दिया।

सितम्बर सन् १९२० के पहले पखवारे में लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सम्पन्न हुआ। पंजाब कांड के सम्बन्ध में प्रतिनिधियों के विचारों में कोई विशेष अन्तर नहीं था, और इसलिए बिना किसी वाद-विवाद के सर्वसम्मति से उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार हो गया। पर असहयोग के सम्बन्ध में प्रमुख नेताओं में गहरा मतभेद था। गांधीजी केवल खिलाफत के प्रश्न पर ही असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने के पक्ष में थे, पर कुछ लोगों के आग्रह पर स्वराज्य की प्राप्ति और पंजाब के अन्याय के परिशोधन के प्रश्नों को भी शामिल कर लिया गया। कांसिलो, विद्यालयों और न्यायालयों के बहिष्कार के सम्बन्ध में ही सबसे गहरा मतभेद था। पंडित मोतीलाल नेहरू

का आग्रह था कि विद्यालयों और न्यायालयों का क्रमिक बहिष्कार हो, और जब गांधीजी ने उनके इस संशोधन को स्वीकार कर लिया, तब उन्होंने गांधीजी के प्रस्ताव का समर्थन किया। जून में उन्होंने कौंसिलो के बहिष्कार के विरोध में एक पत्र गांधीजी को लिखा था, पर इस समय उन्होंने इसका कोई विशेष विरोध नहीं किया। पर मालवीयजी, चित्तरजन दास, बिपिनचन्द्र पाल आदि नेताओं ने प्रस्ताव का डट कर विरोध किया, और विषय समिति में केवल सात वोटों के बहुमत से ही गांधीजी का प्रस्ताव स्वीकार हो सका। कांग्रेस के खुले अधिवेशन में गांधीजी ने प्रस्ताव पेश किया, और मोतीलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया। बिपिनचन्द्र पाल ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जाय कि वे एक भारतीय मिशन (शिष्टमण्डल) से मिलें, जो उनके सामने भारतीयों की शिकायतों तथा स्वशासन की मांग को पेश करें, और यदि प्रधान-मंत्री मिशन से भेट करने को, या पूर्ण स्वशासन देने को तैयार न हों, तो सक्रिय असहयोग की ऐसी नीति अपनायी जाय जिससे ब्रिटिश जनता समझ ले कि भारत अब पराधीन देश के रूप में शासित होने को तैयार नहीं है, और इस सब काम के बीच जनता गांधीजी के कार्यक्रम पर विचार करे, और इसके लिए प्रचार किया जाय।^१

पंडित मोतीलाल नेहरू, डाक्टर शैफुद्दीन किचलू, पंडित रामभज दत्त चौधरी, जितेन्द्र लाल बनर्जी, मौलाना शौकत अली, स्वामी गोविन्दानन्द, सैयद याकूब हुसैन, डाक्टर अन्सारी आदि ने गांधीजी के प्रस्ताव का समर्थन किया। सर आसुतोप चौधरी, श्रीमती एनी बेसेट, पंडित गोकर्ण नाथ मिश्र, पंडित हृदय नाथ कुंजरू आदि ने प्रस्ताव का विरोध किया। मालवीयजी, श्री चित्तरंजनदास, मिस्टर मुहम्मद अली जिना, श्री वेपटिस्टा ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए श्री बिपिन चन्द्र पाल के संशोधन का समर्थन किया। सर्वश्री एन० सी० केलकर, एम० आर० जयकर, कस्तूरी रंगा ऐयंगर, विजयराघवाचार्य और सत्यमूर्ति भी संशोधन के पक्ष में थे।

मालवीयजी ने अपने भाषण में कहा कि वे श्री बिपिनचन्द्र पाल के संशोधन से भी पूरी तौर पर सन्तुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनके विचार में सरकार के सामने राष्ट्रीय माँग पेश करते समय उसे धमकी देना उचित नहीं है। पर वे संशोधन का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके विचार में प्रस्ताव की तुलना में संशोधन अच्छा है। उन्होंने कहा कि वह आज की परिस्थिति में असहयोग को 'न्यायसंगत

और सर्वैधानिक' मानते हैं, और खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों की भावनाओं के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति है, और वे चाहते हैं कि विजयी राष्ट्र तुर्की साम्राज्य के साथ न्याययुक्त सन्धि करें। पर प्रस्तावित असहयोग द्वारा खिलाफत की समस्या का समाधान सम्भव नहीं दिखाई देता। लार्ड चेम्सफोर्ड, उन्होंने कहा, अप्रैल में वापस जा रहे हैं, और पंजाब कांड से सम्बन्धित कई अफसर रिटायर हो चुके हैं। अब दो चार अपराधी अफसरों को दण्डित कराने के लिए देशव्यापी आन्दोलन चलाना किस तरह ठीक होगा? स्वशासन ही अत्याचारों के निराकरण का साधन है। उसके लिए देशव्यापी जनान्दोलन निःसन्देह आवश्यक है, पर कौंसिलों का बहिष्कार हानिकर है। यदि कांग्रेस ने उनका बहिष्कार किया, तो सरकार के समर्थक वहाँ घुस जायेंगे। पारस्परिक झगड़ों के निपटारे के लिए पंचायतों का संगठन ठीक है, पर उनके स्थापित होने से पहले सरकारी अदालतों का बाइकाट कैसे हो सकता है? सब वकीलों के लिए अदालतों का काम छोड़ देना भी सम्भव नहीं है। इस समय जब शिक्षा का विस्तार राष्ट्र की प्रगति के लिए परम आवश्यक है, विद्यालयों का बाइकाट घातक होगा।

कांग्रेस के खुले अधिवेशन में गांधीजी का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया, और उस पर देश में जोर-शोर से काम प्रारम्भ हो गया। नवयुवकों ने बहुत उत्साह से उसका स्वागत किया।

नागपुर अधिवेशन

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में श्री सी० विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पर फिर से विचार हुआ। कतिपय नेताओं के आग्रह पर नये प्रस्ताव में स्वराज्य को प्रमुख स्थान दिया गया। प्रारम्भ में ही घोषित किया गया कि 'भौजूदा भारत सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है', और 'जनता स्वराज्य लेने को कृतसंकल्प है'। इस प्रस्ताव में यह भी घोषित किया गया कि स्वराज्य ही सब शिकायतों के निराकरण का साधन है। स्कूलों और अदालतों के बहिष्कार के प्रस्तावों को सशोधित करते हुए कलकत्ता द्वारा निश्चित मान्यताओं को स्वीकार किया गया, विधान सभाओं के निर्वाचकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र के सदस्यों से इस्तीफे की माँग करें। असहयोग के कार्यक्रम में सविनय-अवज्ञा और लगानवन्दी भी जोड़ दी गयी।

श्री चित्तरंजन दारा ने इन प्रस्ताव को खुले अधिवेशन में प्रस्तुत किया। गांधीजी ने इसका अनुमोदन, और लाला लाजपत राय ने समर्थन किया। मिस्टर मुहम्मद अली जिना ने इसका विरोध किया। ज्वर से पीड़ित होने के कारण मालवीयजी अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सके, पर उन्होंने गांधीजी द्वारा यह मदेश भेज दिया कि उन्हें संशोधित रूप में भी प्रस्ताव मंजूर नहीं है। प्रस्ताव भारी बहुमत में स्वीकार हो गया।

इस अधिवेशन में गांधीजी ने प्रस्ताव किया कि 'इंडियन नेशनल कांग्रेस का लक्ष्य ज्ञान्त और न्यायगंत उपायो द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना है।' गांधीजी ने कहा 'प्रस्ताव के शब्द ऐसे हैं जिनसे दोनों अर्थ निकाले जा सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर स्वराज्य, अथवा ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर स्वराज्य। इस प्रस्ताव में गन्ध दलाजो के लिए गुंजायश है, जो ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध रखना चाहते हैं, और जो ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध रखना नहीं चाहते।' मालवीयजी और जिना गांधी दोनों को यह प्रस्ताव भी पसन्द नहीं था। जिना साहब ने कांग्रेस छोड़ दी, पर आगे चल कर मालवीयजी ने गांधीजी की व्याख्या स्वीकार करते हुए नये लक्ष्य पर हस्ताक्षर कर दिये। परन्तु इसके बाद भी वे पूर्ववत् साम्राज्य के अन्दर स्वराज्य की सम्भावना को सार्थक बनाने में संलग्न रहे, और कौन कह सकता है कि यदि साम्राज्य के बाहर स्वराज्य मिलना सम्भव होता, तो मालवीयजी उसे लेने से इनकार कर देते।

असहयोग का कार्यक्रम

उपाधियों का, तथा अवैतनिक सरकारी ओहदों का, और स्थानीय निकायों की मनोनीत सदस्यता का बहिष्कार, सरकार द्वारा आयोजित दरबारों और समारोहों में जाने से इनकार, सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों और कालेजों का आनुक्रमिक बहिष्कार, वकीलों और बादियों द्वारा धीरे-धीरे अदालतों का बहिष्कार, विधान कौंसिलों का उम्मीदवारों और निर्वाचकों द्वारा बहिष्कार, मद्यनिषेध, विदेशी माल का बहिष्कार, चरखा द्वारा सूत कातने को प्रोत्साहन, कर्षों द्वारा बुनी खादी का प्रयोग, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, निजी हाइड्रो के निपटाने के लिए गैरसरकारी पंचायती अदालतों की स्थापना, छूतछात का निवारण, दलित जातियों का उत्थान, तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता असहयोग आन्दोलन का मुख्य कार्यक्रम था।

खिलाफत कान्फरेन्स

जुलाई सन् १९२१ के पहले सप्ताह में खिलाफत कान्फरेन्स ने अपने कराची अधिवेशन में गोलाना मुहम्मद अली के भाषण के बाद निश्चय किया कि "आज

से किसी ईमानदार मुसलमान के लिए फीज में काम करना या उनकी भरती में सहायता करना, या मीन स्वीकृति देना अनैतिक होगा।”^१ कान्फ्रेन्स ने यह भी घोषित किया कि यदि ब्रिटिश सरकार ने अगोरा सरकार से युद्ध छेड़ा, तो हिन्दुस्तान के मुसलमान सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ कर देंगे, तथा पूर्ण स्वतंत्रता घोषित करके कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भारतीय गणतन्त्र का झंडा फहरा देंगे।^२

कांग्रेस का निर्णय

जुलाई के अन्तिम सप्ताह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घोषित किया कि “सरकार को सैनिक या असैनिक नौकरी करना अभीष्ट है अथवा नहीं, इस पर अपनी राय व्यक्त करना एक नागरिक का जन्मजात अधिकार है, और वह उस सरकार की नौकरी को छोड़ने की खुली अपील करने का हक रखता है, जिसने भारतीय जनता का विश्वास खो दिया है।”^३ इसी अधिवेशन में कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता से अपील की कि वह ब्रिटेन के राजकुमार के स्वागत का बहिष्कार करे,^४ और विदेशी वस्त्रों का परित्याग कर स्वदेशी को अपनाये।

सितम्बर सन् १९२१ में मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अली सेना के भडकाने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिये गये। तब गांधीजी ने मौलाना मुहम्मद अली के कराची के भाषण को स्वयं सार्वजनिक तौर पर दोहराया और ५ अक्टूबर को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने अपने एक वक्तव्य द्वारा घोषित किया कि “किसी भारतीय के लिए किसी भी हैसियत से उस सरकार की नौकरी करना राष्ट्रीय गौरव तथा राष्ट्रहित के विरुद्ध है जिसने रीलेट अधिनियम आन्दोलन के जमाने में जनता की न्यायसंगत आकांक्षाओं को दवाने के लिए सिपाहियों और पुलिस का प्रयोग किया, और जिसने तुर्कों, अरबों, मिस्त्रियों और दूसरे राष्ट्रीयों की राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए सेना का प्रयोग किया।”^५

सरकार ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के विरुद्ध, जिन्होंने इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये थे, कोई कार्यवाही नहीं की। जिन लोगों ने २६ अक्टूबर को कांग्रेस का प्रस्ताव प्रसारित किया, उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की। पर

१ पट्टाभि सीतारमैया वही, पृ० २१७।

२ वही, पृ० २१७।

३. वही, पृ० २१४।

४. वही, पृ० २१५।

५ वही, पृ० २१७।

१ नवम्बर को मौनाना मुहम्मद अली, मौलाना शीकत अली, शैफुद्दीन किचलू, शारदापीठ के शंकराचार्य, मौलाना निसार अहमद, पीर गुलाम मुजादीद, तथा मौलाना हुसेन अहमद को, जिन्होंने खिलाफत कान्फरेन्स के कराची अधिवेशन में भाग लिया था, राजा दे दी।

५ अक्टूबर को बैठक में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उन लोगों को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर व्यक्तिगत सविनय-अवज्ञा की इजाजत दे दी, जो सरकार द्वारा स्वदेशी के प्रचार के काम से रोके गये हों। इसी बैठक में राजकुमार के बहिष्कार का विस्तृत कार्यक्रम निश्चित हुआ, और तय किया गया कि जिस दिन राजकुमार भारत में उतरें, उस दिन सारे देश में हड़ताल हो।

नवम्बर के पहले गप्ताह में दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। कमेटी ने फतवा वन्दियों की सजा की कड़ी आलोचना की। शान्ति और सुव्यवस्था के नाग पर सरकार द्वारा मोगलाओ पर किये जाने वाले अत्याचारों की भी कमेटी ने भर्त्सना की। उसने यह भी निर्णय किया कि खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य के सम्बन्ध में भारत के निश्चय की सरकार द्वारा उपेक्षा के विरुद्ध निर्धारित शर्तें पूरी होने पर वरदोली में 'सामूहिक सविनय-अवज्ञा' आन्दोलन प्रारम्भ किया जाय।

राजकुमार का बहिष्कार

१७ नवम्बर को ब्रिटेन के राजकुमार ने बम्बई में पदार्पण किया। सारे देश में कांग्रेस के आदेश पर हड़ताल हुई। बम्बई में उपद्रव हुए, जो तीन-चार दिन तक चलते रहे, जिनमें लगभग चार सौ आदमी घायल हुए, और ५३ आदमियों की मृत्यु हो गयी। गांधीजी ने प्रायश्चित्त के रूप में पाँच दिन का उपवास किया, तथा श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ शान्ति स्थापित करने के निमित्त बम्बई नगर में चक्कर लगाये।

इसके बाद कांग्रेस तथा खिलाफत कमेटी के स्वयंसेवकों की तत्परता तथा सरकारी दमन, दोनों ने जोर पकड़ा। स्वयंसेवकों ने विदेशी कपड़े के बहिष्कार तथा राजकुमार के स्वागत के विरोध में डटकर काम किया। सरकार ने स्वयंसेवकों की भरती को गैर-कानूनी घोषित करके स्वयंसेवकों की शक्ति को कुचलने का निश्चय किया। क्रिया प्रतिक्रिया ने सविनय-अवज्ञा का रूप धारण कर लिया। बंगाल में इसका शुभारम्भ चित्तरंजन दासजी की धर्मपत्नी बसन्ती देवी ने किया। बंगाल सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए बंगाल

के बहुत से नवयुवक स्वयंसेवक बन कर निकल पड़े। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। नवयुवको का साहस और उत्साह फीका पड़ने के बजाय दुगुना हो गया। बगाल सरकार ने लगभग दो हजार स्वयंसेवको को पकड़ कर जेल भेज दिया। श्री चित्तरजन दास और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी अलीपुर जेल में बन्द कर दिये गये। आसाम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में भी दमन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के अहिंसात्मक सार्वजनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप होने लगा। भयभीत करने के आरोप में स्वयंसेवको को पीड़ित और दण्डित किया जाने लगा, और जेल में उन्हें तरह-तरह से परेशान किया जाने लगा। दफा १४४ का प्रयोग कर सार्वजनिक सभाओं का आयोजन कठिन बना दिया गया। सभाचारपत्रों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा कर दिया गया। बहुत से अन्य कार्य-कर्त्ताओं के साथ लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू भी गिरफ्तार कर लिये गये।

मालवीयजी की धारणाएँ

मालवीयजी ने असहयोग की नीति को सिद्धान्ततः स्वीकार करते हुए भी उसके कार्यक्रम के कतिपय अंशों को अव्यावहारिक और हानिकर बता कर उसका विरोध किया। उनका मुख्य विरोध न्यायालयों, विधानसभाओं, तथा शिक्षा संस्थाओं के बाइकाट पर था। वे न्यायालयों के बाइकाट को अव्यावहारिक तथा विधान-सभाओं और शिक्षा संस्थाओं के बाइकाट को हानिकर समझते थे। उनकी धारणा थी कि विधान-सभाओं में भी स्वराज्य के लिए संघर्ष किया जा सकता है, सरकार की गतिविधि का तीव्र विरोध किया जा सकता है, और राष्ट्र के हित में उनका उपयोग आवश्यक है। वे शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था से पूरी तौर पर सन्तुष्ट नहीं थे। वे सब नवयुवको को देशप्रेम की शिक्षा देना आवश्यक समझते थे। पर वे राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा संस्थाओं का योगदान भी स्वीकार करते थे। वे लाला लाजपत राय की तरह शिक्षा संस्थाओं के वहिष्कार को 'अनर्थकारी' समझते थे। वे तो चाहते थे कि इन संस्थाओं का वहिष्कार करने के बजाय सरकार पर दबाव डाल कर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाय। उनका कहना था कि शिक्षा-प्रणाली के दोषों की समीक्षा करते समय हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि उसने प्रसिद्ध विद्वानों को जन्म दिया है, ऐसे विद्वान पैदा किये हैं जिन्होंने जीवन के भिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की है, जिन्होंने देश के मान और मानसिक विकास की वृद्धि की है। वे चाहते थे कि विद्यार्थी देश-सेवक बनें, सेवा की क्षमता अपने में विकसित करें, रचनात्मक

कार्यों द्वारा देश-सेवा का अभ्यास करे, अपना जीवन जनता के जीवन से आत्म-सात करें। वे यदि चाहें तो अपनी अन्तरात्मा के आदेश पर स्वतंत्रता के निमित्त आत्मोसर्ग करें, और अपने जीवन को बलिदान कर दें। पर वे यह नहीं चाहते थे कि वाइकाट के हडबोग में फँसकर विद्यार्थी अपना समय नष्ट करें, अपनी पढाई-लिखाई बर्बाद करें। मालवीयजी स्वदेशी के पक्ष में थे। उनका खहर से कोई विरोध नहीं था, पर उन्हें विदेशी कपड़ों की होली बुरी लगती थी। उसे वे उचित नहीं समझते थे। वे गांधीजी के अनुरोध तथा कांग्रेस के आदेश को ध्यान में रखकर केन्द्रीय असेम्बली का बहिष्कार कर सकते थे, वहाँ जाकर काम करने का विचार स्थगित कर सकते थे; पर सरकार द्वारा समर्थित शिक्षा संस्थाओं की निन्दा करना, तथा उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना उनके लिए सम्भव नहीं था। न वे काशी विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सकते थे, और न उसका सरकार से सम्बन्ध विच्छेद करा सकते थे। विश्व-विद्यालय के कोर्ट और कौंसिल में भारी बहुमत उनका था, जो सरकार से उसका सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे। उस बहुमत को अल्पमत में बदल देना मालवीयजी के लिए भी नामुमकिन था। यदि मालवीयजी स्वयं उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेते, तो जो कुछ उसका राष्ट्रीय स्वरूप था, वह भी विकृत हो जाता, और उनके दस वर्ष के अथक परिश्रम को बहुत बड़ी क्षति पहुँचती।

इन सब मतभेदों के होते हुए भी गांधीजी से मालवीयजी के सम्बन्ध अच्छे बने रहे। गांधीजी उन्हें अपना बड़ा भाई समझते रहे, और मालवीयजी गांधीजी को सम्मानित भाई कह कर ही सम्बोधित करते रहे। इस बात की चिन्ता न करके कि उनकी बात पर ध्यान दिया जायगा अथवा नहीं, मालवीयजी कांग्रेस के अधिवेशनो में तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकों में जाते, और वहाँ अपने विचार रखते, एवं गांधीजी से अकेले में बातचीत करते, और उन्हें अपनी बात समझाने का प्रयत्न करते रहे। यद्यपि उन्हें असहयोग आन्दोलन की कुछ बातें बुरी लगती थी, और उनकी समीक्षा वे समय-समय पर करते रहते थे, पर वे इसके साथ ही असहयोग आन्दोलन द्वारा जो जनजागृति पैदा हुई थी उसको भी स्वीकार करते थे, और मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा भी करते थे। उनका हृदय उनके साथ था जो अपने विवेक के अनुसार या दूसरे नेताओं के आदेश पर संघर्ष कर रहे थे, अपने सुख वैभव को राष्ट्रहित पर न्यौछावर कर रहे थे। वे नवयुवकों के व्यवहार से क्षुब्ध हो न सरकार से मिल जाने को तैयार थे, न चुपचाप घर बैठ जाने को। कर्मनिष्ठ के लिए कर्म-संन्यास लेना, देशभक्त

के लिए जना-बोलन को दवाने में विदेशी सरकार का समर्थन करना, त्यागी के लिए त्याग के युग में स्वार्थ की बात सोचना असंभव था ।

मालवीयजी लार्ड रीडिंग से मिलते, उनसे देश की समस्याओं पर बातचीत करते, पर स्वार्थ सिद्धि के बजाय राष्ट्रहित की वृद्धि ही इस विचार-विमर्श का लक्ष्य होता । उन्होंने राजकुमार के बहिष्कार का विरोध किया, इसलिए नहीं कि उनके इस कार्य से सरकारी क्षेत्रों में उनके मान की वृद्धि होगी, बल्कि इसलिए कि उनके विचार में बहिष्कार से निरर्थक कटुता बढ़ेगी, सरकार किसी उपद्रव के बहाने से दमन प्रारम्भ कर देगी । सरकार ने उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयत्न किया, पर वह ऐसा नहीं कर पायी । वाइसराय ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से विभूषित करना चाहा, पर उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया ।

राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गांधी-रीडिंग समझौता कराने की अवश्य कोशिश की । इस उद्देश्य से उन्होंने लार्ड रीडिंग के बुलाने पर उनसे बात करने के बाद गांधीजी से अनुरोध किया कि वे वाइसराय से मिल कर देश की समस्या पर उनसे बातचीत करें । कुछ हिचकिचाहट के बाद गांधीजी राजी हो गये, और वे मई सन् १९२१ में वाइसराय से मिले भी, पर कोई नतीजा नहीं निकला ।

मालवीयजी ने अपना प्रयास जारी रखा । वे एक तरफ वाइसराय से, और दूसरी ओर अलीपुर जेल में मौलाना आजाद और देशबन्धु दास से मिले । वाइसराय इस बात पर राजी थे कि मार्च सन् १९२२ में शासन-सुधार के सम्बन्ध में गोलमेज कान्फ्रेंस की जाय । जब मालवीयजी ने इसकी सूचना मौलाना आजाद और देशबन्धु दास को दी, तब उन्होंने सोचा कि राजकुमार के बहिष्कार के कारण ही “भारत सरकार समझौता टूटने के लिए मजबूर हुई है । हमें स्थिति से लाभ उठाना चाहिए, और गोलमेज कान्फ्रेंस में मिलना चाहिए”^१ । उन्हें यह स्पष्ट था कि “यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर नहीं ले जायगा, फिर भी यह हमारे राजनीतिक सघर्ष में एक बड़ा अग्रवर्ती कदम होगा ।”^२ यह सोच कर दोनों नेता इस शर्त पर कि गोलमेज कान्फ्रेंस से पहले सब कांग्रेसी नेता छोड़ दिये जायेंगे, सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हो गये । इस पर मालवीय जी वाइसराय से फिर मिले । वाइसराय ने उन्हें आश्वासन दिया कि अलीबन्धु और दूसरे वे सब राजनीतिक कैदी, जो विचार-विमर्श में भाग लेंगे, छोड़ दिये जायेंगे । मौलाना आजाद और देशबन्धु दास ने इस बात को स्वीकार करते हुए एक पत्र में अपने विचारों को साफ-साफ लिखकर मालवीयजी द्वारा उसे गांधी

जी के पास भिजवा दिया। पर गांधीजी ने उनके सुझाव को मानने से इनकार कर दिया, जिसका उन्हें 'आश्चर्य और क्षोभ' था।^१ गांधीजी का आग्रह था कि सब राजनीतिक नेता और अलीवन्दु भी विना किसी शर्त के पहले छोड़ दिये जायें, उनकी रिहाई के बाद गोलमेज कन्फ्रेंस के प्रस्ताव पर विचार किया जाय।

शिष्टमंडल

इसके बाद भी मालवीयजी समझौता कराने के प्रयास में संलग्न रहे। कुछ समय बाद २१ दिसम्बर को वे एक शिष्टमंडल के साथ वाइसराय से मिले। इस शिष्टमंडल में मालवीयजी के अतिरिक्त श्रीमती एनी बेसेंट, महाराजा मनीन्द्र चन्द्र नन्दी, मिस्टर हसन इमाम, मिस्टर फजलुल हक, मीलवी अब्दुल कासिम, श्री प्रफुल्ल चन्द्र राय, श्री एम० विश्वेश्वरैया, श्री कस्तुरी रंगा ऐयंगर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, मुशी ईश्वर शरण, श्री जमनादास द्वारकादास, सेठ घनश्यामदास विडला आदि शामिल थे।

डेपुटेशन का अनुरोध था कि दमनकारी कानून वापस लिये जाये, सब राजनीतिक बन्दी रिहा कर दिये जायें, तथा जनमत का प्रतिनिधित्व करनेवाली कान्फ्रेंस बुलायी जाय। वाइसराय ने उत्तर में कहा कि उन्हें और उनकी कार्यपरिपद् को सम्मानित सज्जनो और उनके बच्चों को गिरफ्तार करना और जेल भोजना अच्छा नहीं लगता, पर देश में शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखना और नागरिकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, और जब तक आन्दोलन वापस नहीं लिया जाता, तब तक व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी ही होगी। कान्फ्रेंस बुलायी जा सकती है, पर उसके लिए शान्ति के वातावरण की आवश्यकता है। पंजाब कांड के सम्बन्ध में अब क्या किया जा सकता है। जो करने को कहा जाता है, वह ठीक नहीं जचता। खिलाफत के सम्बन्ध में लार्ड चेम्सफोर्ड ने और मौजूदा सरकार ने काफी तगड़े प्रतिवेदन भेजे हैं, और इस सम्बन्ध में भारत सरकार अब क्या कर सकती है। गोलमेज कांफ्रेंस बुलायी जा सकती है। पर राजनीतिक सुधार अभी तो चालू हुए हैं, शीघ्र ही उन्हें बदल देना कहा तक उचित होगा? फिर यह भी समझ लेना चाहिए कि चूँकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ही राज्यव्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है, उसे विश्वास दिलाना होगा कि "भारतीय जनता की विपुल संख्या सम्राट् को वफादार है।" इसीलिए वाइसराय ने कहा, "जो व्यक्ति राजकुमार

का अपमान करने में सहायक होता है, वह भारत को तथा उसके भावी ऐश्वर्य की क्षति पहुँचाता है।”^१

इसके बाद श्याम सुन्दर चक्रवर्ती ने गांधीजी को समझाते के लिए तार दिया। मालवीयजी और श्रीमती एनी बेसेंट के कहने पर पंडित हृदयनाथ कुंजरू और श्री जमनादास द्वारकादास गांधीजी से मिलने अहमदाबाद गये। वातचीत के बाद उन्हें आशा बंधी कि गांधीजी कुछ समय के लिए आन्दोलन बन्द करके गोलमेज कान्फ्रेंस के लिए राजी हो जायेंगे। पर कलकत्ता लौटने पर जब उन्होंने गांधीजी के वक्तव्य को पढ़ा, तब उनकी आशा निराशा में बदल गयी। इस पर उन्होंने एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने गांधीजी के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए लिखा कि शिष्टमंडल के आवेदन के उत्तर में जो बातें वाइसराय ने कही, उनसे सम्भव है कोई सहमत न हो, पर यह स्पष्ट है कि गोलमेज कान्फ्रेंस प्रत्येक प्रश्न पर विचार करने को स्वतन्त्र होती। उन्होंने लिखा कि वाइसराय का उत्तर शान्तिपूर्ण था, क्योंकि वे तो यही चाहते थे कि वातचीत के जमाने में दोनों ओर से अस्थायी विराम का पालन हो ताकि सद्भावना के वातावरण में विचार-विमर्श हो सके।^२

दूसरी ओर गांधीजी का कहना था कि २४ दिसम्बर की हड़ताल वापस की जा सकती थी, यदि सरकार स्वयंसेवकों की भरती के सम्बन्ध में प्रवर्तित अध्यादेश को वापस लेने को, तथा सत्याग्रहियों और फतवा कैदियों को छोड़ने को तैयार होती। उनकी राय में वाइसराय का उत्तर असन्तोषजनक था, और कान्फ्रेंस में शामिल होकर खाली हाथ लौटना किसी तरह भी कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होता।^३

मालवीयजी का प्रयास विफल रहा। राजनीतिक संघर्ष जारी रहा। कलकत्ते में २४ दिसम्बर को राजकुमार का बाइकाट दिल्ली से भी कहीं अधिक जोर-शोर से हुआ। पर मौलाना आजाद और देशबन्धु दास के विचार में “हमने राजनीतिक समझौते का एक सुनहरा अवसर खो दिया”।^४

अहमदाबाद कांग्रेस

देशबन्धु चित्तरजनदास की अनुपस्थिति में हकीम अजमल खाँ साहब ने जो अपनी भद्रता और सद्भावना के लिए सब वर्गों में सम्मानित थे, दिसम्बर सन्

१ ‘इंडिया इन १९२१-१९२२’, पृ० ३४९-३५१।

२. न्यू इण्डिया, २४ दिसम्बर, सन् १९२१।

३. न्यू इण्डिया, २९ दिसम्बर, सन् १९२१।

४. आजाद . वही, पृ० २८।

१९२१ में कांग्रेस के अहमदावाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। देशबन्धु दास द्वारा प्रेषित भाषण में, जिसे श्रीमती सरोजनी नायडू ने पढ़कर सुनाया, सरकार की नीति-रीति तथा गतिविधि की कड़ी आलोचना करते हुए घोषित किया गया कि वे इंग्लैंड के साथ समझौता करने को तैयार हैं, पर शर्त यह है कि सरकार हमारे जन्मसिद्ध अधिकार अर्थात् स्वतंत्रता को स्वीकार करे।

कांग्रेस ने भारी बहुमत से लगान बन्दी प्रारम्भ करने का निश्चय किया। मालवीयजी ने प्रतिनिधियों को एलाह दी कि राजनीतिक समझौते का दरवाजा खुला रखा जाय, और आक्रमणशील सत्याग्रह प्रारम्भ करने का अर्थात् लगानबन्दी शुरू करने का निर्णय न लिया जाय। उन्होंने कहा कि जहाँ तक उनकी जानकारी है, पिछले तीन-चार महीनों में सिमरना और भ्रास के सम्बन्ध में वाइसराय ने भारत-मन्त्री को कई पत्र लिखे हैं, और यदि इनके सम्बन्ध में कोई अच्छा निर्णय हुआ, तो वह उनके प्रयासों का फल होगा। मालवीयजी ने स्वीकार किया कि स्वयं-सेवकों की भरती को गैर-कानूनी घोषित करना सरकार की “गम्भीर गलती” थी, और उसका विरोध आवश्यक और न्यायसंगत है। पर उनके विचार में, उन्होंने कहा, जहाँ यह घोषित करना जरूरी है कि सरकार की इस नीति का विरोध करने को कांग्रेस कुनसंकल्प है, वहाँ यह बात भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि कांग्रेस मौजूदा तनाव बनाये रखना नहीं चाहती। किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए जीवन का बलिदान किया जा सकता है। पर जहाँ सम्मान के साथ राष्ट्रहित को हानि पहुँचाये बिना उसकी रक्षा की जा सकती है, वहाँ आत्मबलिदान की बात सोचना व्यर्थ है। इसलिए जबकि सरकार की नीति के उत्तर में कांग्रेस अपनी मौजूदा नीति जारी रखने का निर्णय घोषित करे, यह भी कहा जाय कि वह “बुद्धिसंगत शर्तों पर गोलमेज कान्फरेन्स के लिए तैयार है” और उसके द्वारा सूचित करें कि आप व्यर्थ में सघर्ष जारी रखना नहीं चाहते उन्होंने कहा कि कान्फरेन्स में आधिकारिक ढंग से स्वराज्य की मांग कांग्रेस द्वारा पेश की जा सकती है।^१ मालवीयजी का मुझाव भारी बहुमत से नामजूर हो गया।

कांग्रेस ने घोषित किया : “जब सरकार के निरंकुश, अत्याचारपूर्ण और शक्ति-घातक प्रयोग रोकने के लिए अन्य सभी उपायों का प्रयोग हो चुका है, तब सविनय-अवज्ञा ही सशस्त्र विद्रोह का सम्य और प्रभावकारी विकल्प है।”^२ उसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे “कांग्रेस के आदेशों को

१ न्यू इण्डिया, ३० दिसम्बर, सन् १९२१, पृ० ८।

२ पट्टाभि सीतारमैया हिस्ट्री आफ् दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, पृ० २२६।

ध्यान में रखते हुए जनता को वैयक्तिक और सामूहिक सविनय-अवज्ञा के लिए तैयार करें।" गांधीजी कांग्रेस के एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिये गये, और उन्हें अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के, तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सब अधिकारों को प्रयोग करने के अधिकार इन प्रतिबन्धों के साथ दे दिये गये कि "वे या उनका उत्तराधिकारी कांग्रेस लक्ष्य को नहीं बदल सकेगा, और अखिल भारतीय कांग्रेस की अनुमति लिये बिना सरकार से कोई सन्धि नहीं कर सकेगा।"^१

अधिवेशन में मौलाना हसरत मुहानी ने पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया, पर गांधीजी ने उसका डटकर विरोध किया, और कांग्रेस ने उसे अस्वीकार कर दिया।

जैसा कि पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है, "राजनीतिक विषयों पर मुसलमान मौलवियों द्वारा कांग्रेस को सलाह देना अहमदावाद कांग्रेस का विशिष्ट लक्षण था।" "कुरान, शरियत और हदीस की रोशनी में राजनीतिक विचारों की व्याख्या में उलमा ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया, और कभी-कभी कांग्रेस को अपने प्रस्तावों को उनकी सलाह की रोशनी में बदलना पड़ा।"^२

सर्वदलीय कान्फरेन्स

कांग्रेस अधिवेशन के बाद मालवीयजी ने कतिपय अन्य नेताओं के हस्ताक्षर से सर्वदलीय कान्फरेन्स आमन्त्रित की। उसका काम १४ जनवरी सन् १९२२ को सर शंकरन नायर की अध्यक्षता में लगभग ३०० व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रारम्भ हुआ। गांधीजी ने भी व्यक्तिगत हिसियत से इसमें सम्मिलित होकर इसकी कार्यवाही में भाग लिया। शंकरन नायर साहब गांधीजी की बातों से ऐसे क्षुब्ध हुए कि उन्होंने अगले दिन की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया। उनके स्थान पर सर विश्वेश्वरैया अध्यक्ष बनाये गये, और उनकी अध्यक्षता में कान्फरेन्स चलती रही। इस सम्मेलन ने सरकार की दमन नीति की निन्दा की, कांग्रेस से प्रार्थना की कि जब तक सरकार से बातचीत चलती है, तब तक सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ न की जाय, और सरकार से माग की कि वह खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य के प्रश्नों पर विचार करने के लिए गोलमेज कांग्रेस बुलाये, 'क्रिमिनल ला अमन्डमेन्ट एक्ट' के अंतर्गत जिन सस्थाओं पर रोक लगा दी गयी है उसे उठा ले, 'सेडिशस मीटिंग एक्ट' (राजद्रोह सभा अधिनियम)

उठा लिया जाय, और सभी सजा-प्राप्त और गिरफ्तार सत्याग्रही और फतवा कैदी छोड़ दिये जायें, और आन्दोलन में भाग लेने के कारण माधारण कानून के अन्दर जो गिरफ्तार या दंडित हैं उनकी जाँच के लिए एक कमेटी बँठा दी जाय ।

कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने सर्वदलीय सम्मेलन की बात मान कर जनवरी के अन्त तक सविनय-अवज्ञा बन्द रखने का निश्चय किया, पर वाइसराय ने सम्मेलन की बात मानने से इनकार कर दिया । इस तरह मालवीयजी का यह प्रयास भी विफल हुआ, फिर भी इस कांग्रेस का, जिसे गांधीजी "मालवीय कांग्रेस" कहते थे, अपना महत्त्व था । खुले सघर्ष से कुछ दिन पहले ३०० गैर-कांग्रेसी राष्ट्रवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार के सामने इस प्रकार की मांगों को पेश करना, और उनके आधार पर राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना निःसन्देह महत्त्वपूर्ण प्रयास था ।

गांधीजी का पत्र

गांधीजी ने १ फरवरी को वाइसराय को सात दिन का नोटिस देते हुए लिखा कि यदि उनकी शर्तें सरकार ने स्वीकार नहीं की, तो सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर दी जायेगी । इस पत्र में गांधीजी ने विधिविहीन दमन की शिकायत करते हुए वाइसराय से माँग की कि वे सब असहयोगी बन्दी जो अहिंसात्मक कार्यों के लिए दण्डित किये गये हैं और जिन पर अहिंसात्मक अपराधों के नाम पर मुकदमे चल रहे हैं छोड़े जायें, तथा देश में चालू अहिंसात्मक कार्रवाइयों के सम्बन्ध में अहिंसात्मक तटस्थता (गैरदस्तदाजी) की नीति घोषित की जाय । प्रेस प्रशासनिक नियंत्रणों से मुक्त किया जाय, और हाल में समाचार पत्रों पर जो जुर्माने किये गये हैं और उनकी जमानतों को जप्त किया गया है, वे उन्हें लौटा दी जायें । उन्होंने लिखा कि यदि सात दिन के अन्दर सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक घोषणा प्रसारित कर दे, तो वह स्वयं उस समय तक के लिए आक्रमक ढंग की सविनय अवज्ञा को स्थगित करने को तैयार है, जब तक कैदी कार्यकर्ता नये सिरे से परिस्थिति पर विचार करके कुछ निर्णय करें । उन्होंने यह भी लिखा कि यदि सरकार ऐसी घोषणा करे, तो उन्हें देश की यह परामर्श देने में हिचक नहीं होगी कि दोनों ओर की हिंसात्मक रुकावट के बिना जनमत को गढ़ने का प्रयत्न किया जाय, और अपनी अपरिवर्तनीय माँगों की उपलब्धि के लिए उसकी प्रक्रियाओं पर विश्वास किया जाय । ऐसी दशा में आक्रमक सविनय अवज्ञा तभी शुरू होगी, जब सरकार तटस्थता नीति से हटेगी, या

भारतीय जनता की भारी बहुसंख्या की स्पष्ट रूप से व्यक्त राय को मानने से इनकार कर देगी ।^१

दुर्घटना

५ फरवरी को भयानक कांड हो गया । पुलिस के दुर्व्यवहार से उत्तेजित भीड़ ने, जिसमें कांग्रेस के कुछ स्वयं-सेवक थे, थाने को आग लगा दी, और २१ कान्सटेबिलो और एक सब-इन्स्पेक्टर की निर्मम हत्या कर दी । यह समाचार पा कर गांधीजी ने सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करने का विचार स्थगित कर दिया ।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी

१२ फरवरी को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने सब कांग्रेस कमेटियों को आदेश दिया कि राष्ट्रीय सघर्ष छोड़ने की सारी तैयारियाँ बन्द कर दी जायें । उसने किसानों को सलाह दी कि वे हर प्रकार की मालगुजारी और लगान शीघ्र दे दें । उसने समस्त कांग्रेस सगठनों को आदेश दिया कि कानून तोड़ने के निमित्त न कोई जुलूस निकाला जाय, न कोई दूसरी कार्रवाई की जाय, पर ताड़ी और शराब की दुकानों पर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा धरना जारी रखा जा सकता है ।

गांधीजी का स्पष्टीकरण

कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की धारणा थी कि पंडित हृदयनाथ कुंजरू की रिपोर्ट पर, उनके विचारों से प्रभावित होकर और सम्भवतः मालवीयजी के कहने पर सत्याग्रह बन्द किया गया । पर गांधीजी ने घोषित किया कि इस निर्णय में कुंजरू साहब और मालवीयजी का कोई हाथ नहीं है, वह उनकी अपनी नीति और सिद्धान्तों पर आधारित है, और वे स्वयं उसके लिए सर्वथा उत्तरदायी हैं । उनका कहना था कि जो समाचार उन्हें विभिन्न स्थानों से मिल रहे थे, उनसे स्पष्ट था कि यदि सत्याग्रह बन्द नहीं किया गया होता, तो उन्हें अहिंसात्मक असहयोग के बजाय हिंसात्मक संघर्ष का नेतृत्व करना पड़ता ।

मालवीयजी का काम

१० मार्च को सरकार ने गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया । १८ मार्च को उन्हें छ. वर्ष की सजा दे दी गयी । इस समय मालवीयजी के अतिरिक्त

राजेन्द्र प्रसादजी जेल के बाहर थे। कांग्रेस के सामने काफी संकट की स्थिति थी। आसाम में उसे कुचला जा रहा था, सारे देश में वेवसी का वातावरण था। सब मतभेद भुलाकर कांग्रेस की सहायता करना, देश की जनजागृति को बनाये रखना मालवीयजी ने अपना कर्तव्य समझा। वे राजेन्द्र बाबू के साथ आसाम गये, और वहाँ काम शुरू किया। राजेन्द्र बाबू ने अपने एक सस्मरण में लिखा है कि उस समय वहाँ गावों में पहुँचना आसान काम नहीं था। भय-व्रण न कोई पास आता था, न भाड़े की गाड़ी मिलती थी। कांग्रेस के स्वयं-सेवक जहाँ तहाँ मिल जाते थे। ऐसे स्थानों में हम लोग गये तो लोगों में जान आयी, जागृति आयी।

मालवीयजी ने वहाँ जाकर अफीम-विरोधी आन्दोलन चला दिया। उन दिनों आसाम में अफीम की बहुत खपत होती थी। नशावन्दी कांग्रेस के कार्यक्रम का अंग था ही। मालवीयजी के अफीम के बाइकाट के आन्दोलन के कारण कम से कम कुछ समय के लिए दुकानों पर अफीम की विक्री काफी कम हो गयी, और जनता पर सरकार का आतंक भी कम हो गया।^१

मालवीयजी ने पंजाब में कई जिलों का दौरा किया, और काफी जोरदार जोशीले भाषण दिये। इन भाषणों में मालवीयजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण, स्वदेशी, खदर आदि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों को जोर-शोर से आगे बढ़ाने की जनता से अपील की, उन्हें सार्वजनिक कामों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्त्रियों से अनुरोध किया कि वे सूत काते और खदर की तैयारी में भरसक योगदान करें। उन्होंने जनता से अपील की कि वह गांधी खदर फड में यथाशक्ति चन्दा दें, तथा ६ अप्रैल से १३ अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनायें। मालवीयजी ने वयस्क नवयुवकों से अपील की कि वे कांग्रेस के सदस्य बनें, प्रत्येक जिले में राजनीतिक संस्था स्थापित करें, जनता में स्वराज्य के लक्ष्य का प्रचार करें, तथा सबको देश की स्थिति से अवगत करायें, अंग्रेजों को स्पष्ट कर दें कि स्वराज्य की प्राप्ति उनका दृढ़ संकल्प है। मालवीयजी ने इन भाषणों में सरकार की नीति-रीति की आलोचना करते हुए सरकार से आग्रह किया कि वह जनमत को सन्तुष्ट करने के लिए, तथा राजनीतिक गतिरोध का समाधान करने के लिए कांग्रेस से बातचीत करने का प्रयत्न करे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि वह दमन द्वारा जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को कुचल नहीं सकेगी, नीति-रीति को बदल कर ही शान्त वातावरण तथा पारस्परिक सौहार्द प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

अपने भाषणों में मालवीयजी ने जनता से भी अनुरोध किया कि वह अपने में स्वराज्य के उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता और शक्ति परिपुष्ट करे। गुजरावाला की सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा कि साधारण अंग्रेज की तुलना में साधारण हिन्दुस्तानी में देशभक्ति, संयम और आत्मत्याग कम होता है, और इन सद्गुणों की कमी उनके (भारतीयों के) पतन का कारण है। आयरलैंड जैसा औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के चरित्र की इन विशेषताओं को भारतीय जनता को अपने में पुष्ट करना होगा। तभी हम अंग्रेजों के समान व्यवहार किये जाने का दावा कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सेना का प्रबंध स्वराज्य की कुंजी है। और जब तक हम सैनिक विषयों के प्रबंध करने की क्षमता अपने में पैदा नहीं करते, तब तक स्वराज्य की आशा नहीं की जा सकती।

पंजाब में कतिपय सरकारी अफसरों के अत्याचारों तथा गैर-कानूनी कार्रवाइयों के आरोपों की जांच के लिए वे एक कमेटी भी नियुक्त करना चाहते थे। मालवीयजी के काम से उद्विग्न होकर सरकार उनकी गिरफ्तारी की बात सोचने लगी थी। लन्दन के प्रसिद्ध दैनिक 'टाइम्स' ने उनकी गतिविधि की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा कि क्या पंडित मदन मोहन मालवीय, जो अपने आप ही देश के नेता बन बैठे हैं, पंजाब में फिर सन् १९१९ की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? पर मालवीयजी ने इन सब बातों की उपेक्षा करते हुए अपना काम जारी रखा।

चौरीचौरा

चौरीचौरा काण्ड के बाद उस क्षेत्र में पुलिस ने अत्याचार और आतंक की हद कर दी। बहुत से निर्दोषों को बुरी तरह से मारा-पीटा गया, और सैकड़ों निर्दोषों का चालान कर दिया गया। पुलिस के आतंक के कारण स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए अभियुक्तों की सफाई का प्रबन्ध करना भी संभव नहीं हो रहा था। इस काम को मालवीयजी ने अपने हाथ में लिया। उन्होंने वहाँ की जनता की रक्षा और सहायता का यथासंभव प्रबन्ध किया, प्रयाग हाईकोर्ट के कई वकीलों को वहाँ भेज कर सफाई के लिए आवश्यक तथ्यों को इकट्ठा करवाया, और कई दिन तक स्वयं वकील की हैसियत से हाईकोर्ट में पैरवी की। उनके प्रयास से २२९ व्यक्तियों में से, जिन्हें फाँसी की सजा दी जा चुकी थी, १४३ को अपील में हाईकोर्ट द्वारा फाँसी की सजा नहीं दी गयी।

१४. हिन्दू संगठन

(१९०९ से १९२८ तक)

पंजाब हिन्दू सभा

दिसम्बर सन् १९०६ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना-सम्मेलन ढाका में हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही जनवरी सन् १९०७ में पंजाब में हिन्दू सभा स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ हुआ। सब मामलों में सारे हिन्दू समाज के हितों के संरक्षण में तत्पर और सतर्क रहना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। लगभग दो वर्ष तक इसने कोई विशेष कार्य नहीं किया।

जून सन् १९०९ में इसकी ओर से लार्ड मिंटो को एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें सरकार के पक्षपात की शिकायत की गयी, तथा बताया गया कि सरकारी नौकरियों के वितरण में मुसलमानों के साथ विशिष्ट व्यवहार किया जाता है, पंजाब भूमि हस्तान्तरण अधिनियम में जब कि करीब-करीब सभी वर्ग के मुसलमानों को जमीन खरीदने की पूरी छूट है, उच्च वर्ग के हिन्दू इस अधिकार से वंचित कर दिये गये हैं, तथा कौंसिलों की नयी चुनाव व्यवस्था किसी सर्वसामान्य न्यायसंगत नियम पर आधारित नहीं है। निवेदन पत्र में चुनाव व्यवस्था की समीक्षा करते हुए शिकायत की गयी कि किसी सम्प्रदाय का राजनीतिक महत्त्व अधिक समझना, और उसके लिए पृथक् निर्वाचन का तथा विशिष्ट नियमों की व्यवस्था करना सर्वथा अनुचित है। सरकार ने इस निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया।

अक्टूबर सन् १९०९ में लाहौर में पंजाब हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज सर प्रतूल चन्द्र चटर्जी की अध्यक्षता में पंजाब हिन्दू सभा का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। राय बहादुर लाला लालचन्द, जो इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे, वास्तव में इस आन्दोलन के प्राण थे। उनकी धारणा थी कि निरन्तर संघर्ष जगत और जीवन का प्राकृतिक नियम है, और इस संसार में वही जाति जीवित रह सकती है जो सबल और सुसंगठित हो। वे चाहते थे कि हिन्दू जाति के हितों के, तथा हिन्दुत्व की रक्षा और अभिवृद्धि के निमित्त सब हिन्दू अपने जातीय संगठन को मजबूत करें। उनकी धारणा थी कि कांग्रेस न तो हिन्दुओं में हिन्दुत्व की भावना को सुदृढ़ कर सकती है, और न हिन्दुओं के

राजनीतिक हितों की रक्षा कर सकती है। इन दोनों कामों की सिद्धि तो, उनके विचार में, हिन्दू महासभा द्वारा ही सम्भव हो सकती है।^१ लाल चन्दजी का तो सन् १९१२ में देहान्त हो गया, पर उनका चलाया आन्दोलन चलता रहा। फिर भी जैसा कि भाई परमानन्द ने लिखा है, “हिन्दू सभा का आन्दोलन पंजाब की जनता की कल्पनाशक्ति को आकर्षित नहीं कर सका। यह आन्दोलन हिन्दू समाज के विशिष्ट वर्ग में सीमित बना रहा। जनसाधारण तो उससे बिल्कुल ही अप्रभावित रहा।”^२

अखिल भारतीय हिन्दू महासभा

सन् १९१२ में श्री शादी लालजी ने पंजाब हिन्दू सभा के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की स्थापना पर जोर दिया। कुछ समय बाद हरिद्वार में इसका कार्यालय स्थापित हो गया, और वही किसी पर्व के अवसर पर इसके अधिवेशन होते रहे। पर सम्भवतः यह संस्था पंजाब हिन्दू महासभा से भी अधिक निष्क्रिय थी। सन् १९१६ में इस संस्था के प्रधान मन्त्री राय बहादुर लाला सुखवीर सिंह ने हरिद्वार में हरि की पैड़ियों पर गंगाजल का अविच्छिन्न प्रवाह होता रहे इस सम्बन्ध में जो कार्य किया वही सन् १९१८ तक उसका मुख्य योगदान था। उसके मन्त्री पण्डित देवरत्न शर्मा ने हरिद्वार में रहकर जो थोड़ा बहुत काम किया, उसका प्रभाव देश के सार्वजनिक जीवन पर नगण्य था।

सन् १९१८ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में कुरोली सदीली के राजा रामपाल सिंह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा का पाँचवाँ अधिवेशन आयोजित हुआ। राजा साहव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आशा व्यक्त की कि भारत को भी आत्मनिर्णय के अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि माटेयू द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक सुधार उत्तरदायी शासन की क्रमशः उपलब्धि की ओर ठोस कदम है, और उन्हें कुछ सशोधनों के साथ स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने साम्प्रदायिकता पर आश्रित निर्वाचन पद्धति की त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाते हुए सरकार से अनुरोध किया कि प्रचलित पद्धति में आवश्यक सुधार किया जाय। उन्होंने कहा कि हिन्दू महा-

भाई परमानन्द का फोरवर्ड (प्राक्कथन), पृ० V-X, इन्द्रप्रकाश : ए रिव्यू आफ् दी हिस्ट्री एण्ड वर्क आफ् हिन्दू महासभा एण्ड हिन्दू संघटन मूवमेंट।

२ भाई परमानन्द : वही, पृ० XVI।

सभा किसी जाति या सम्प्रदाय के न्यायसंगत अधिकारों को भंग करना, या उनका अतिक्रमण करना नहीं चाहती। वह तो केवल “दूसरों के आक्रमण से हिन्दुओं के न्यायपूर्ण और उचित अधिकारों की रक्षा करना चाहती है।” उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म तो कट्टरता, धर्मान्धता और भौतिकवाद के विरुद्ध तितिक्षा, विश्वजनीनता तथा आध्यात्मिकता का मूर्तरूप है। उन्होंने कहा कि हिन्दू सभा का काम है कि वह हिन्दू समाज के बिखरे हुए तत्त्वों को सगठित करे और मिलाये, सारे समाज की उन्नति के उपाय ढूँढ़े, ताकि हम फिर कीर्ति और सम्यता के उस शिखर तक पहुँच सकें जहाँ हमारे पूर्वज पहुँच गये थे।^१

इस सम्मेलन में उत्तरदायी शासन की माग के पक्ष में, तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के विरोध में प्रस्ताव स्वीकार हुए। एक प्रस्ताव में कहा गया कि सम्प्रदाय के वजाय व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व का आधार हो, पर यदि इस सिद्धान्त के विरुद्ध किसी अल्प-संख्यक गैर-हिन्दू समुदाय के साथ रियायत की जाती है, तो वैसी रियायत हिन्दुओं के साथ भी की जाय, जहाँ वे अल्प-संख्यक हैं। इस प्रस्ताव में स्थानीय निकायों में साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति चालू करने का, तथा मुसलमानों को आबादी के अनुपात से कहीं अधिक स्थान दिये जाने का भी विरोध किया गया।^२

अप्रैल सन् १९२१ में हरिद्वार में महाराजा बहादुर कासिम बाजार की अध्यक्षता में छठा अधिवेशन हुआ। इसमें ननकाना साहब में किये गये अत्याचारों के प्रति क्षोभ और रोष प्रकट किया गया, एवं दक्षिण में ब्राह्मण और अन्नाह्मण में तथा पंजाब में सिक्खों और हिन्दुओं में भेद पैदा करने की सरकारी नीति की निन्दा की गयी, और हिन्दुओं से अनुरोध किया गया कि वे कोई ऐसा कार्य नहीं करें जो हिन्दुओं की एकता को हानिकर हो। एक दूसरे प्रस्ताव के जरिये सरकार से अनुरोध किया गया कि उत्तर पश्चिमी प्रान्त पर केन्द्रीय सरकार का शासन बना रहे। इस अधिवेशन में गोरक्षा के सम्बन्ध में पिछले अधिवेशन से कहीं कड़ा प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में गोरक्षा के सम्बन्ध में हिन्दुओं की भावनाओं की उपेक्षा के लिए सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा गया कि अब समय आ गया है जब हिन्दुओं को स्वयं ‘न्यायसंगत और शान्तिमय उपायों द्वारा’ इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, और आवश्यक ‘त्याग और तपस्या के लिए तैयार हो जाना चाहिए।’^३

१ इन्द्रप्रकाश : वही, पृ० ८२-८८।

२. इन्द्र प्रकाश . वही, पृ० १६३-१६४।

३. इन्द्र प्रकाश वही, पृ० १६५-१६७।

इस सबसे यह स्पष्ट है कि सन् १९२० तक मालवीयजी का हिन्दू महासभा के आन्दोलन से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था। वे राय वहादुर लाला लालचन्द आदि की कांग्रेस-विरोधी भावनाओं और धारणाओं को ठीक नहीं समझते थे, और हिन्दुओं के लिए कांग्रेस के नेतृत्व का अनुसरण उचित मानते थे, तथा स्वयं उसके द्वारा देश की सेवा करते रहते थे।^१ हिन्दू धर्म के मूल तत्त्वों का ज्ञान और अनुसरण वे हिन्दुओं का कर्तव्य समझते थे, पर हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य को उभारना पाप समझते थे।^२ उन्होंने सन् १९३१ में गोल मेज कांफ्रेंस की अल्पसंख्यक कमेटी में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह हिन्दू महासभा के संस्थापक और प्रवर्तक (फाउण्डर) नहीं है।^३

मोपला उपद्रव

असहयोग के जमाने में ही सन् १९२१ में मालबार में मोपला विद्रोह ने साम्प्रदायिकता का रूप धारण कर लिया। मोपलाओं ने हिन्दुओं की बड़ी दुर्गति की। मालवीयजी ने उनकी सहायता के लिए रुपये, अन्न, वस्त्र आदि भिजवाये। इस विद्रोह को दवाने के लिए सरकार ने बड़ी कड़ाई से काम लिया, मोपलाओं को बहुत त्रस्त किया। गांधीजी के लिखने पर मालवीयजी ने त्रस्त मोपलाओं के परिवारों को भी आर्थिक सहायता पहुँचायी।

मुलतान में उपद्रव

गांधीजी के गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद सितम्बर सन् १९२२ में मुलतान में हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा हुआ, जिसमें मुसलमानों ने हिन्दुओं पर बहुत अत्याचार किये। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हकीम अजमल खाँ, बाबू राजेन्द्र प्रसाद तथा मालवीयजी को जाँच के लिए भेजा। इन तीनों ने तथ्यों का पता लगा कर मुसलमानों को ही इसके लिए मूलतः उत्तरदायी ठहराया, हिन्दुओं की दयनीय दशा पर दुःख प्रकट किया। हिन्दू स्त्रियों की व्यथा सुनकर तो राजेन्द्रबाबू रो पड़े, और फिर मालवीयजी और हकीम साहब भी जोर-जोर से रोने लगे। इस प्रकार की घटनाओं से देश की रक्षा के लिए मालवीयजी ने मुलतान तथा लाहौर में हिन्दू मुसलमानों की मिली-जुली सभाओं में जनता से एकता कायम रखने

१. सन् १९०९ में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मालवीयजी का अव्यक्तिय भाषण।
२. मालवीयजी के लेख, पृ० २४-२५।
३. राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस, सेकिड सेशन, माइनारिटी कमेरी रिपोर्ट, पृ० १३५०।

की, तथा झगडा करनेवालो से नागरिक सुरक्षा सेना द्वारा मुकाबला करने की सलाह दी ।

मालवीयजी ने १६ सितम्बर सन् १९२२ को लाहौर में मौलाना अब्दुल कादिर के सभापतित्व में भाषण करते हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों पर सन्ताप और लज्जा व्यक्त की । उन्होंने कहा कि उनकी दृष्टि में “सब अत्याचारी धर्महीन और नास्तिक हैं”,^१ “बुराई का परिणाम बुरा होता है”, “हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हम थोड़ी बजह से इन्सानियत को छोड़ कर दूसरे इन्सानों के साथ जुर्म करें।”^२ मुलतान में मुसलमानों द्वारा किये गये अत्याचारों पर रज, अफसोस और लज्जा प्रकट करते हुए उन्होंने उन हिन्दुओं पर भी “लानत” भेजी जिन्होंने बेकसूर मुसलमानों पर हमला किया, चोटें लगायी और मकानों को जलाया, पर इस बात पर उन्होंने सन्तोष प्रकट किया कि अपने धर्मस्थानों पर बार होने पर भी हिन्दुओं ने किसी मस्जिद का अपमान नहीं किया।^३ अन्त में उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को “हिन्दू मुस्लिम दो जातियों का झगडा करार देना बिल्कुल बेजा होगा” । उन्होंने कहा : “दुनियाँ में खुदा, परमात्मा, अकाल पुरुष एक है” हिन्दू, सिक्ख, पारसी, ईसाई, मुसलमान—सब उस परमात्मा^४ के बन्दे हैं, उस बाप के बच्चे हैं । वह तमाम हिन्दुस्तानियों का ही नहीं, तमाम दुनिया के इन्सानों का ही नहीं, बल्कि प्राणिमात्र का रक्षक है । हम सब एक पिता की औलाद हैं, एक ख़ालिक ही ख़िलकत है, एक जगत्पिता की, अकाल पुरुष की सन्तान है । हमारा यह रिश्ता पुराना है, मिटाये मिट नहीं सकता “हम सबको चलते फिरते, सोते हर वक्त यह बात याद रखनी चाहिए कि मन्दिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजे सब सम्मान के काबिल हैं” ।^५ उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तान के हिन्दुओं और मुसलमानों का दूसरा रिश्ता “इन्सानियत” का, और तीसरा रिश्ता “देशवासी” होने का है ।^६ उन्होंने कहा : “ए खुदा के बन्दो ! अपने खुदा के बन्दों से इज्जत के साथ बर्ताव करो, लड़ाई करके ईश्वर के सम्मुख जाने के लिए अपने आपको नाक़ाबिल साबित मत करो” । उन्होंने बताया कि एक ही देश में रहनेवाले हिन्दुओं और मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे आपस में एकता कायम करें, और याद रखें कि स्वराज्य के लिए हिन्दू-मुसलमानों की एकता नितान्त आवश्यक है ।^६ उन्होंने यह भी बताया कि जहाँ

१. सीताराम चतुर्वेदी : महामना पंडित मदनमोहन मालवीय, खंड २ पृ० ७३ ।

२. वही, पृ० ७५ ।

३. वही, पृ० ७६ ।

४. वही, पृ० ७८-७९ ।

५. वही, पृ० ७९ ।

६. वही, पृ० ७९ ।

“अहिंसा हमारा मुख्य धर्म है”, वहाँ “आतताइयो को दण्ड देना भी हमारा कर्तव्य है” । आततायी वह है जो “चोरी-डाका मारने, तूटमार करने, आग लगाने, या वेकसूरो को सताने के इरादे से हमला करे ।”^१ उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा का हक कानून भी स्वीकार करता है, और उसका समुचित प्रबन्ध जरूरी है । उन्होंने सलाह दी कि हर मुहल्ले में “नागरिक सेना” बनायी जाय, और उसके सब सदस्य “परमात्मा को याद रखते हुए” प्रतिज्ञा करें कि वे “ईश्वर की पैदा की हुई हस्तियों से दुश्मनी नहीं रखेंगे—हिन्दुस्तान की इज्जत का खयाल रखेंगे”, तथा “एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हुए, सब वहनो व भाइयो की इज्जत कायम रखेंगे” ।^२

जब मुसलमान गुण्डों के अत्याचारों के कारण हिन्दू मुसलमान झगड़े और हिन्दुस्तानियों की परेशानियाँ बढ़ती चली गयी, नागरिक सेना कहीं भी ठीक तौर पर बन नहीं सकी, और कांग्रेस शान्ति बनाये रखने के लिए कोई प्रभाव-शाली कार्य नहीं कर सकी, तब राजेन्द्र प्रसादजी के अनुरोध पर मालवीयजी ने गया में आयोजित हिन्दू महासभा के सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार कर ली । यह सम्मेलन कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में आयोजित हुआ ।

हिन्दू महासभा में गया सम्मेलन

मालवीयजी ने हिन्दू जाति की दुर्दशा का विश्लेषण करते हुए धर्म से विमुख होना ही उसका कारण बताया । उन्होंने कहा : “हमारा धर्म औरों के गनों का मान करना सिखाता है, सहनशील होना बताता है, और किसी पर आक्रमण करने की शिक्षा नहीं देता । साथ ही यह भी आदेश देता है कि यदि तुम्हारे धर्म पर कोई आक्रमण करे, तो अपनी रक्षा के लिए प्राण तक निछावर करने में कभी संकोच न करो । इस धर्म को शुद्ध हृदय से और अक्षरशः पालन करने में ही हिन्दू-मुसलमानों में एकता स्थापित हो सकती है । जब तक हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इतने बलवान् और सगठित नहीं हो जाते कि वे दूसरी जाति के गुण्डों और बदमाशों से अपनी रक्षा कर सकें, तब तक उनमें एकता स्थापित नहीं हो सकती ।”^३ उनकी इच्छा थी कि “प्रत्येक भारतवासी पुरुष या स्त्री अपनी रक्षा करने के धर्म को अच्छी तरह समझ ले ।”^४ उनका

१ वही पृ० ८१ ।

२ वही, पृ० ८२ ।

३. वही, पृ० ८४ ।

४ वही, पृ० ८५ ।

यह भी निवेदन था कि सब हिन्दू 'सच्चे, दृढ़ और अपने धर्म के पक्के हिन्दू हो, पर सदा इस बात का ध्यान रखे कि आप (वे) पहले भारतवासी हैं और फिर हिन्दू।' उन्होंने हिन्दुओं से यह अपील की कि वे गाव-गाव में हिन्दू समाएं स्थापित करें, अपनी गिरी दशा को सुधारने, तथा उन्नत करने का उपाय सोचें, और "अछूतों से प्रेम का व्यवहार करें। उन्हें भी अपना भाई समझ छूआछूत दूर करें, उनकी अवस्था को सुधारें, और उनकी उन्नति का मार्ग सोचें"।^१

हिन्दू महासभा का सातवा अधिवेशन

अगस्त सन् १९२३ में काशी में मालवीयजी की अध्यक्षता में हिन्दू महासभा का सातवा साधारण अधिवेशन सम्पन्न हुआ। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिन्दू जाति की प्राचीनता, विशिष्टता और गौरव की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि लोकमान्य तिलक की राय में "कम से कम आठ हजार वर्ष से यह जाति जीवित है।"^२ मालवीयजी ने कहा, "ऋग्वेद ३००० वर्ष से आज तक यह जाति एक जीवित जाति के रूप में चली आती है।"^३

अपने इस अभिभाषण में मालवीयजी ने कहा कि बौद्ध, जैन और सिक्ख भी बृहद् हिन्दू जाति के अंग हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने एक प्राचीन कवि के निम्नलिखित श्लोको को उद्धृत किया :—

य शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो ।
बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिका ॥
अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मैति मीमांसका ।
सोऽयं नो विदधानु वाञ्छितफल त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥

इन श्लोको में कवि प्रार्थना करता है कि 'जिसको शैव लोग शिव कह कर पूजते हैं, वेदान्ती लोग, ब्रह्म कह कर, बौद्ध लोग बुद्ध, नैयायिक कर्त्ता, जैन धर्म के अनुयायी अर्हत, और मीमांसक कर्म कहकर पूजते हैं, वह तीनों लोकों का स्वामी आपका मंगल करे।' ^४

मालवीयजी ने कहा कि जब कवि ने यह वाक्य कहे "उस समय सब धर्म के अंग थे। ऐसा नहीं होता तो कवि इस तरह कदापि नहीं लिखता। सब एक ही धर्म की शाखा मान कर बर्तते थे। जैसे एक महावृक्ष की शाखाएँ होती हैं।"^५

१ वही, पृ० ८४-८५।

३. वही, पृ० ९२।

५ वही, पृ० ९३।

२. वही, पृ० ९२।

४. वही, पृ० ९३।

उन्होंने कहा “सिक्ख धर्म भी हमारे धर्म का एक अंग है। गुरुग्रन्थ में भक्तिभाव के जो भजन हैं, वे श्रीमद्भागवत् के श्लोको के अक्षरशः अनुवाद हैं। पद के पद पढ़िये वही भाव अनुवाद के रूप में मिलेंगे। उनके दसो गुरु हमारे धर्म के गुरु थे, वे परम पवित्र थे।”^१

हिन्दू धर्म की विशेषता की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि “एक-मेवाद्वितीयं ब्रह्म” का सिद्धान्त उसकी प्रमुख विशेषता है। हमारे धर्म ने, उन्होंने कहा, हमें बताया है कि “कोट पतंग में, हाथी से चीटी तक सब में एक ब्रह्म का अंश है। एक ही अन्तर्यामी घट-घट में व्याप्त है। धर्म के पीछे किसी से मत लडो।” इसी कारण से, उन्होंने बताया, “यद्यपि बौद्ध समय में कुछ विद्रोह हुए, तथापि थोड़े समय के बाद ही वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी हिल मिलकर रहने लगे, तथा विद्वानों की गोष्ठियों और राजदरबारों में विप्रमण्डली का भी आदर होता था और बौद्धों का भी।”^२

वर्णाश्रम धर्म का विश्लेषण करते हुए मालवीयजी ने कहा . “वर्ण में दोष भी है, गुण भी है। आश्रम में भी ऐसा ही है। परन्तु इनमें गुण बहुत हैं, दोष कम।”^३

धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य के भण्डार की चर्चा करते हुए उन्होंने उसकी रक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न करना हिन्दुओं का पुनीत कर्तव्य बताया, और कहा : “इस निधि की रक्षा में हमारी रक्षा, उसके नाश में हमारा नाश है।”^४

अन्त में मालवीयजी ने काफी विस्तार के साथ हिन्दू जाति की सामाजिक और साम्प्रदायिक समस्याओं पर प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए “हिन्दू सघटन की आवश्यकता” पर जोर दिया, और आशा व्यक्त की कि “जैसे प्रेम से वे कांग्रेस में जाते हैं, उसी प्रेम से हिन्दू महासभा में एकत्र होकर विचार करें कि हिन्दू जाति का गौरव, हिन्दू जाति की प्रतिष्ठा किस प्रकार स्थापित कर सकेंगे।”^५

उन्होंने स्वीकार किया कि “रोग की अवस्था में सबका विचार रोग को दूर करने का होना चाहिए”, पर कहा कि “औषधि भोजन नहीं है - स्थायी सुधार

१. वही, पृ० ९४।

२. वही, पृ० ९४।

३. वही, पृ० ९४।

४. वही, पृ० ९६।

५. वही, पृ० १००।

शाश्वत, सर्वकालीन है, सामयिक नहीं" और "कोई काम किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए जो राष्ट्रीय आन्दोलन में विरोध पैदा करे।"^१

उन्होंने शारीरिक दुर्बलता को हिन्दू जाति की विपत्तियों का एक मूल कारण बताते हुए उसे दूर करने के लिए ब्रह्मचर्य और व्यायाम की ओर समर्पित ध्यान देने का आग्रह किया, तथा वाजपिवाह की प्रचलित प्रथा में सुधार को आवश्यक बताया। उन्होंने शिक्षा के व्यापक प्रसार, तथा ग्रन्थों के सर्वांगीण विकास की ओर भी प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने विद्वद् मण्डली से प्रार्थना की कि वे अन्त्यजोद्धार और शुद्धि के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था दें।^२

उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, "सर्वहित गावन" के लिए, हिन्दू और मुसलमान "भेद भाव भुलाकर" जहाँ तक हो सके देश का काम गाय-साय करें।^३

अस्पृश्यता की समस्या

हिन्दू सभा के सामने अन्त्यजों का उत्थान सबसे आवश्यक, पर सबसे कठिन समस्या थी। कट्टरपन्था सन्यासी छूना मत की प्रचलित व्यवस्था को दृढ़ता से बनाये रखना चाहते थे, और उनके विरोध के कारण इस विषय में हिन्दू सभा को बहुत सावधानी से कदम उठाना पड़ता था। वह प्रगतिशील नवयुवकों की आकांक्षाओं, तथा सभ्य की आवश्यकता का ठीक तीर पर पूरा नहीं कर पाती थी। फिर भी मालवीयजी के प्रयत्नों ने सन् १९२३ में हिन्दू सभा ने निर्णय किया कि सर्व हिन्दुओं के समान ही दलित जातियों को सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ने, कुओं तथा पानी के अन्य जरूरतों से पानी लेने सार्वजनिक सभाओं में अन्य लोगों के साथ बैठने, राहको पर चढ़ने तथा देवदर्शन का अधिकार है। उसने यह भी निर्णय किया कि प्रत्येक हिन्दू को, चाहे वह किसी जाति का हो, समान सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार हैं।

सन् १९२५ में हिन्दू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में लाला रामप्रसादजी ने अछूतों और शूद्रों को वेद पाठ करने का अधिकार देने का प्रश्न उठाया। इस पर वहाँ बैठे सनातनधर्मियों में खलबली मच गयी। परिस्थिति को सुधारते हुए मालवीयजी ने कहा, "ईश्वर के दिये हुए प्रसाद सबके लिए सुलभ है। पर वेदों के अध्ययन करने

१. वही, पृ० १००।

२. वही, पृ० १०१-१०९।

३. वही, पृ० १०१।

के लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता है, जो सबके लिए साध्य नहीं है।”^१ गीता भूमण्डल में सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। उसका अध्ययन और मनन सबके लिए सुलभ है। शूद्र और अन्त्यज भी उसका पाठ करके सफल मनोरथ हो सकते हैं। वह वेद ही के समान पूज्य और फलप्रद है। मानवजाति के कल्याण के लिए उसमें सब कुछ है। आप लोग प्रयत्न करें कि घर घर में गीता का प्रचार हो। प्रत्येक हिन्दू के पास गीता की पोथी रहे। शूद्र और अन्त्यज भी उसका पाठ करें, और अल्प प्रयास से ही वेदों का मुख्य तत्त्व प्राप्त करें।”^१

अछूतोंद्वारा के सम्बन्ध में हिन्दू महासभा ने जो प्रस्ताव जिस ढंग से स्वीकार किये थे वे स्वामी श्रद्धानन्दजी को पसंद नहीं थे। वे उन्हें पर्याप्त नहीं समझते थे। इसलिए वे हिन्दू सभा के तत्त्वावधान में आयोजित सार्वजनिक सभाओं में हिन्दूसभा के लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यक्रम आदि पर भाषण करने के बाद कहते थे कि अब हिन्दू सभा की बैठक समाप्त हुई, और अब मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ विचार आपके सामने रखूंगा। इसके बाद वे अछूतोंद्वारा के सम्बन्ध में अपने निजी विचार जनता के सामने प्रस्तुत करते थे। इन विचारों को हिन्दू महासभा ने स्वीकार नहीं किया था, और उससे संबंधित सनातनधर्मी उन्हें धर्मसगत नहीं समझते थे। पण्डित दीनदयालु व्याख्यानवाचस्पति ने श्रद्धानन्दजी की इस गतिविधि का विरोध किया। इससे कटुता पैदा हो गयी, जिसे मालवीयजी और लाला लाजपत राय कठिनाई से किसी प्रकार शान्त कर पाये।

शुद्धि की समस्या

शुद्धि का प्रश्न हिन्दू महासभा के सामने दूसरी कड़ी समस्या थी। बहुत से मलकाना राजपूत, जिनके पूर्वज किसी कारण से मुसलमान हो गये थे, इस शर्त पर हिन्दू समाज में प्रवेश करने को तैयार थे कि उन्हें उनकी राजपूत विरादरी स्वीकार करे। मुसलमान और प्रचलित परम्परा के उपासक सनातनधर्मी दोनों शुद्धि के विरोधी थे। मुसलमान तबलीग़ (धर्मप्रचार) के जरिये दूसरे धर्मों पर विश्वास रखनेवाले व्यक्तियों को अपने मजहब (धर्म) में शामिल करना अपना अधिकार और कर्तव्य समझते थे। पर शुद्धि-आन्दोलन द्वारा मुसलमानों को हिन्दू बनाने की बात उन्हें असह्य थी। वह इस प्रक्रिया को हिन्दू-मुस्लिम झगड़े की जड़ समझते थे। उनमें से कुछ का तो कहना था कि

इस समय दुनिया के अन्दर अगर कोई खुला और विश्वव्यापी धर्म है तो वह केवल "इस्लाम" ही है, और केवल इस्लाम को ही "तवलीग" का हक़ हासिल है। गांधीजी कहते थे कि धर्मपरिवर्तन कराने की दृष्टि से शुद्धि और तवलीग दोनों ख़त्म की जायें। पर मुसलमान तवलीग बन्द करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, फिर भला दूसरे धर्मावलम्बी राष्ट्रीय एकता के नाम पर अपने धर्म के प्रचार का अधिकार कैसे छोड़ सकते थे। मालवीयजी का मुसलमानों से कहना था कि "आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप दूसरे भाइयों को अपने धर्म के प्रचार से रोकें।"^१ इस तर्क को गांधीजी भी स्वीकार करते थे। सनातनधर्मी भी इस बात को धर्मसंगत मानने को तैयार थे। पर फिर भी वे किसी ईसाई, मुसलमान को हिन्दू जाति में शामिल करना अपने धर्म और मर्यादा के विरुद्ध समझते थे, और इस कारण से शुद्धि का विरोध करते थे। मालवीयजी इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि ज्ञान का प्रसार प्रत्येक ज्ञानवान् का कर्तव्य है। वे कहते थे, "जो लोग अज्ञान के कारण अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, उनके विषय में समस्त हिन्दू जाति और विशेषकर हमारे ब्राह्मण भाई अपराधी हैं जो अपने धर्म का ज्ञान अपने अज्ञानी भाइयों में नहीं फैलाते।"

"ज्ञानं प्राप्य तु ससारे य. परेभ्यो न यच्छति ।
ज्ञानरूपी हरिस्तस्मै अप्रसन्नो हि लक्ष्यते ॥"

(अर्थात् संसार में ज्ञान प्राप्त करके जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उसके ऊपर ज्ञान रूपी ईश्वर अप्रसन्न से दिखलायी देते हैं।^२)

मालवीयजी का कहना था कि हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित्त कराना एक पंडित का धर्म है, और प्रायश्चित्त के बाद दोषी व्यक्ति निर्दोषी हो जाता है, उसके बाद उसके पुराने दोष या पाप की चर्चा धर्मविरुद्ध है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भूले-भटके भाइयों को सनातन-धर्म का मर्म समझा कर, उन्हें प्रायश्चित्त कराकर उनकी शुद्धि करें, उनके साथ सद् व्यवहार करें, उन्हें अपनी पंगत में शामिल करें। मालवीयजी का यह भी कहना था कि ईश्वरी ज्ञान सबके लिए है, उसका प्रचार हर विद्वान् का धर्म है। धर्म की व्यापकता और सार्वभौमिकता के लिए उसका विस्तार नितान्त आवश्यक है। उनके विचार में शास्त्रों में भी इसका विधान है, ऋषियों का आचरण भी

१. लाहौर में भाषण, २८ जून सन् १९२३।

२. 'अभ्युदय' २३, अक्तूबर सन् १९०८।

इसके अनुकूल है। मालवीयजी व्यावहारिकता की दृष्टि से भी शुद्धि का अनुष्ठान आवश्यक समझते थे। उनका कहना था : “यदि कोई चाहता है कि वह पूजा पाठ किया करे, गंगा-स्नान करके भोजन करे, और आपके धर्म को पवित्र मानकर उसकी ज्योति से मुक्ति पाये, तो हम उससे कैसे कह दें कि तुम्हें हिन्दू होने का अधिकार नहीं ?”^१ उन्होंने कहा : “प्राचीन काल के ऋषि समझदार थे। उन्होंने इसीलिए असभ्यो को सम्य किया था। यदि आज भी यह साधुमण्डली, पंडितमण्डली, विद्वदमण्डली यह आज्ञा दे दे कि जो छल या बल से मुसलमान बनाये गये हैं उन्हें वापस ले लो, तथा जो और लोग भी आना चाहते हो उन्हें भी ले लो, तो आज ही विजय की घोषणा हो जाय। विश्वनाथ का नाम लो, और आज ही यह व्यवस्था कर दो कि जो चाहे हिन्दू हो सकता है।”^२

मालवीयजी के प्रयास से हिन्दू महासभा ने अपने बनारस अधिवेशन में शुद्धि का प्रस्ताव पारित किया। इसके कुछ महीने पूर्व ही ३१ दिसम्बर सन् १९२२ को शाहपुरा (मेवाड़) के राजाधिराज सर नाहर सिंह के नेतृत्व में आगरे में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें साठे चार लाख मुस्लिम राजपूतों को शुद्धि द्वारा हिन्दु विरादरी में सम्मिलित करने का निश्चय किया गया। १३ फरवरी सन् १९२३ को अखिल भारतीय हिन्दू शुद्धिसभा गठित की गयी। स्वामी श्रद्धानन्द उसकी प्रबन्ध-समिति के अध्यक्ष चुने गये। उनकी देख-रेख में हजारों अतिथियों की उपस्थिति में मलकाना (मुस्लिम राजपूत) काफ़ी बड़ी संख्या में हिन्दू भाइयों द्वारा बहूत उत्साह और धूमधाम से हिन्दू राजपूत विरादरी के अंग बना लिये गये। पर शुद्धि के सम्बन्ध में हिन्दू महासभा स्वयं कोई विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकी। सनातन-धर्मवलम्बियों को इसमें कोई विशेष रुचि ही नहीं थी। आर्यसमाजियों ने अपने पुराने ढंग से आर्य समाज के तत्त्वावधान में काम करना ही उचित समझा। परिवर्तित राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में उन मुसलमान परिवारों की दृष्टि में भी धर्मपरिवर्तन सारहीन हो गया, जिनके पूर्वज हिन्दू थे, और जो किसी समय फिर से हिन्दू धर्म ग्रहण करना चाहते थे।

स्त्रियों की रक्षा और उत्थान

स्त्रियों की रक्षा और उत्थान हिन्दू समाज की एक दूसरी बड़ी समस्या थी, जिसकी ओर ध्यान देना हिन्दू महासभा के लिए नितान्त आवश्यक था।

१. हिन्दू महासभा का ७ वा अधिवेशन १९२३, सीताराम चतुर्वेदी : वही, खण्ड २, पृ० १०९। २. वही।

मालवीयजी ने हिन्दू जनता से अनुरोध किया कि वे उन सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्रीजाति की उत्थिति में बाधक हैं। स्त्रियों की समुचित रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि “जो पुरुष अपनी माता, बहन या पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, उसके जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि वह अपनी आँखों के सामने अपनी माता, बहन या पत्नी पर आक्रमण देखकर जीता रहता है, तो उसका जीने से मर जाना बेहतर है।”^१

वे चाहते थे कि हिन्दू स्त्रियों में इतनी मानसिक और शारीरिक शक्ति विकसित की जाय कि वे स्वयं हिम्मत के साथ गुण्डों से अपनी रक्षा कर सकें।

वे बाल-विवाह को हिन्दू जाति के ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण समझते थे, और उस कुरीति को दूर करना हिन्दू जाति के उत्थान के लिए, विघेपत-स्त्री जाति के उत्कर्ष के लिए, नितान्त आवश्यक समझते थे। सन् १९२३ में ही उन्होंने हिन्दू महासभा के अधिवेशन में कहा था : “आठ दस वर्ष की कन्याओं का विवाह करने से तो रजो-दर्शन के बाद ही विवाह करना श्रेष्ठ है और इसके लिए यदि नरक में जाना पड़े, तो नरक में जाना अच्छा है, पर बाल-विवाह करना अच्छा नहीं।”^२ उनका आदेश था कि “लड़की का दारह तथा लड़के का अठारह वर्ष की आयु से पहले विवाह कभी मत करो, और यदि कन्या का सोलह और बालको का २० या २५ वर्ष की अवस्था में विवाह कर सको, तो और भी उत्तम है। ब्रह्मचर्य का प्राचीन नियम चलाओ, तभी हमारे पूर्वजों के समान उच्च श्रेणी के पुरुष पैदा हो सकेंगे।” उन्होंने कहा . “मैं २५ वर्ष के विवाह को सबसे उत्तम समझता हूँ। उससे उतर कर २० वर्ष की उम्र के विवाह को समझता हूँ। १८ वर्ष से पहले तो किसी बालक का विवाह होना ही नहीं चाहिए।”^३ सन् १९३४ में तो उन्होंने रावलपिंडी में पंजाब सनातन धर्मसम्मेलन में घोषित किया कि “सनातन धर्म यही है कि पहले पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो।”^४

दहेज की प्रथा

वे दहेज जैसी दूसरी विवाह सम्बन्धी कुरीतियाँ भी दूर करना आवश्यक समझते थे। वे चाहते थे कि विवाह का उत्सव जितनी सादगी से किया जा

१. पंजाब हिन्दू सम्मेलन, २३ फरवरी, सन् १९२३।

२. सीताराम चतुर्वेदी : वही, खण्ड २।

३. सीताराम चतुर्वेदी : वही, खण्ड २, पृ० १२०-१३१।

४. महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लेख और भाषण, भाग १, पृ० १८८।

सके उतनी सादगी से किया जाय, व्यर्थ के खर्चे को जितना घटाया जा सके उतना घटाया जाय ।

स्त्री-शिक्षा

वे स्त्री-शिक्षा पर भी जोर देते थे । वे उसे सारे समाज की उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे । वे चाहते थे कि “जातीय जीवन के पुनरुत्थान के लिए स्त्रीशिक्षा के पवित्र कार्य को उत्साह और साहस के साथ किया जाय”, स्त्रियों के “हृदय और मन की सारी शक्तियों का सम्यक् रूप से विकास किया जाय”, “उनकी पूर्ण पुष्टि” की जाय ।^१ उनके विचार में पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी देश-हित का कार्य करना चाहिए । उन्हें याद रखना चाहिए कि ईश्वर का तत्त्व उनमें भी है, और जब तक वे इस मार्ग में अग्रसर नहीं होगी, तब तक देश की उन्नति सम्भव नहीं होगी ।^२

स्त्रियों का सम्मान

वे चाहते थे कि समाज में स्त्रियों का समुचित आदर हो । हिन्दू मुसलमान, जाति और सम्प्रदाय के भेद को भुलाकर, सब माताओं, बहनों और बेटियों का आदर करना अपना कर्तव्य समझे, और उनकी मानमर्यादा और गौरव की रक्षा करे ।

विधवा-विवाह

मालवीयजी इस तरह स्त्रियों के सर्वांगीण विकास के पक्ष में थे । वे यह भी चाहते थे कि विधवाओं की रक्षा, तथा उनके सम्मान और भरण-पोषण की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाय ।

मालवीयजी की अनुमति से हिन्दू महासभा ने स्त्री जाति की उन्नति के लिए बहुत से प्रस्ताव स्वीकृत किये, और बहुत सी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपने ढंग पर जनमन को प्रोत्साहित किया । पर उनके आग्रह व कारण विधवा विवाह के सम्बन्ध में हिन्दू महासभा में कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका । स्वामी श्रद्धानन्दजी को यह बात बहुत अखरी । पर ४ अक्तूबर सन् १९४० को इस सम्बन्ध में जब पंडित यज्ञनारायण उपाध्याय और पंडित महादेव शास्त्री की मालवीयजी से बातचीत हुई, और शास्त्रीजी ने उनसे पूछा कि विधवाओं की रक्षा कैसे की जाय, और विधवाओं का विवाह कराया जाय अथवा नहीं, तब

१. ‘अभ्युदय’, मार्गशीर्ष शुक्ल ९, सम्वत् १९६४ ।

२. कांग्रेस का अध्यक्षीय भाषण, सन् १९१८ ।

मालवीयजी ने कहा कि उनकी राय में “यदि विधवा चाहे तो उसका विवाह कर देना चाहिए, पर इसके सम्बन्ध में सनातनधर्मविलम्बियों की सभा की जानी चाहिए, और उसके निर्णय के अनुसार सब काम होना चाहिए।”^१ शास्त्रीजी से इस पुस्तक के लेखक को यह भी पता चला कि मालवीयजी ने स्वयं एक विधवा-विवाह करा दिया था। पर जब उनकी विधवा बुआ को इसका पता चला, तब उन्होंने मालवीयजी को बहुत डाँटा फटकारा। पंडित यदुनन्दन उपाध्याय ने इस पुस्तक के लेखक को बताया कि एक बार मालवीयजी ने, उस समय जब कि वे बहुत बृद्ध हो गये थे, उनसे कहा कि यद्यपि उन्होंने (मालवीयजी ने) बहुत से क्षेत्रों में बहुतों की सेवा की है, पर वे विधवाओं की कोई सेवा नहीं कर सके।

संरक्षा की समस्या

गुण्डो के अत्याचारों से जाति की रक्षा करने के लिए स्वयं-सेवकों का संगठन महासभा की चौथी बड़ी समस्या थी। मालवीयजी स्वयं चाहते थे कि प्रत्येक क्षेत्र, नगर और मुहल्ले में हिन्दू-मुसलमानों का मिलाजुला नागरिक दल संगठित किया जाय, और इस दल के स्वयं-सेवक सब जातियों के गुण्डों से समान रूप से निष्पक्ष भाव से सब जातियों के लोगों के जान-माल की रक्षा करें। पर जब ऐसे दल संगठित नहीं हो पाये, तब उन्होंने महावीर दल संगठित करने की हिन्दुओं को सलाह दी। जब मुसलमानों ने इसका विरोध किया, तब उन्होंने कहा कि यदि मुसलमान चाहे, तो वे भी मुहाफिज दल संगठित कर सकते हैं, और अच्छा तो यही होगा कि दोनों दलों के स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा दल के स्वयं-सेवकों की हैसियत से आपस में मिल कर साम्प्रदायिक झगड़ों के अवसरों पर सारी जनता के जान-माल तथा धर्म-स्थानों की रक्षा करें। मालवीयजी ने यह भी कहा कि वे महावीर दलों को मुसलमानों पर आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि हिन्दुओं की रक्षा के लिए संगठित करना चाहते हैं। दूसरी जातियों पर आधिपत्य प्रतिष्ठित करने की या उन्हें चोट पहुँचाने की उनकी इच्छा नहीं है। वे कहते थे, “हम प्रभुत्व नहीं चाहते, न ही हम किसी पर अधिकार चाहते हैं।”^२ वे यह जरूर चाहते थे कि हिन्दू अपनी दुर्बलता को दूर करके आततायियों का डट कर मुकाबला करें। पर वे यह नहीं चाहते थे कि हिन्दू मुसलमानों पर

१. रामनरेश त्रिपाठी : मालवीयजी के साथ तीस दिन, पृ० २४५।

२. हिन्दू महासभा का अध्यक्षीय भाषण, १९२३, सीताराम चतुर्वेदी। वही, खंड २, पृ० १००।

किसी प्रकार का अत्याचार करें। वे इस प्रकार के कामों को “घृणित” समझते थे, और उनकी “निन्दा” करते थे।^१ उनका कहना था कि “यदि कोई आदमी निर्दोष है और कोई हिन्दू उस पर अत्याचार करता है और आप मना नहीं करते तो आप बुरे हैं। यदि मुसलमान को अत्याचार करने से नहीं रोकते तो यह कायरपन है।”^२ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा - “जब कहीं हिन्दुओं द्वारा अत्याचार होते मैंने देखा है, तब मुझे दुःख हुआ है। ऐसा करना ठीक नहीं है। बिहार में जो कुछ हुआ था, उससे मुझे सताप हुआ। कटारपुर में जो अत्याचार हुआ उसका मुझे दुःख है। वह ठीक नहीं हुआ, मुझे रोम रोम से दुःख हुआ। मैंने उसको घृणित समझा। उसकी निन्दा की।”^३

जब मार्च सन् १९३१ में कानपुर में दंगा हुआ और उसमें दोनों ओर से अत्याचार हुए, तब उसके बाद ११ अप्रैल सन् १९३१ को कानपुर में एक सार्व-जनिक सभा में भाषण करते हुए मालवीयजी ने कहा कि “मैं मनुष्यता का पूजक हूँ, मनुष्यत्व के आगे जाति-पाँति नहीं मानता। कानपुर में जो दंगा हुआ उसके लिए हिन्दू मुसलमान इनमें से एक ही जाति जवाबदेह नहीं है। जवाबदेही दोनों जातियों पर समान है। मेरा आप सबसे आग्रहपूर्वक ऐसा कहना है कि अब भविष्य में आप अपने भाइयों से ऐसा युद्ध नहीं करेंगे। वृद्ध, बालक व स्त्रियों पर हाथ नहीं छोड़ेंगे। मन्दिर अथवा मस्जिद नष्ट करने से धर्म की श्रेष्ठता नहीं बढ़ती। ऐसे दुष्कर्मों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आप लोगों ने आपस में लड़कर जो अत्याचार किये हैं उसका जवाब ईश्वर के सामने देना होगा। जब तक हिन्दू मुसलमान दोनों में प्रेम-भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक किसी का भी कल्याण नहीं होगा। एक दूसरे का अपराध भूल जाइये और एक दूसरे को क्षमा कीजिये। एक दूसरे के प्रति सद्भाव और विश्वास बढ़ाइये। गरीबों की सेवा कीजिये, उनको प्रेम से आलिंगन कीजिये, और अपने कृत्यों का पश्चात्ताप कीजिये।”^४

इस तरह मालवीयजी साम्प्रदायिक उपद्रवों के युग में भी हिन्दुओं को आत्मरक्षा के निमित्त सगठित और सबल होने का उपदेश देते हुए उनसे आग्रह करते थे कि वे सबके साथ मनुष्यता का व्यवहार करें, किसी के साथ अनाचार और अत्याचार न करें, तथा देश की विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों में प्रेमभाव और सौहार्द को बढ़ाने का ध्यान सदा रखें। उन्होंने सन् १९२३ में हिन्दू महासभा के सम्मेलन में हिन्दू जनता को सम्बोधित करते हुए कहा —

१ वही, पृ० १०१।

२. वही, पृ० १०१।

३ वही, पृ० १०१।

४. सीताराम चतुर्वेदी : वही, खण्ड १, पृ० ९६।

‘मह कभी मत भूलो कि हमारा देश भान्तर्जग है। इसमें भिन्न-भिन्न धर्म के लोग रहते चमते हैं। उस देश का भला उमी में है कि हम सबमें परस्पर मेल रहे। यदि यह याद रहा तो ठीक है, नहीं तो हिन्दू मभा निष्फन हो जायेगी। यदि यह याद रहा तो स्वराज्य पाने में भारी मदद मिलेगी। याद रखो कि यदि गिरजे या गरिजद की तरफ हमारी नजर उठे, नो आदर की नजर उठे। यदि किसी मुसलमान या ईसाई के पनि कोई शब्द निकले, तो आदर का शब्द निकले। नेश्जती हो तो मह लेना, पर दूसरो का दिल दुगानेवाला शब्द कभी न बोलना। याद रखो, बलवान् ज्यादा सहन करता है। कगजोर को जतदो गुस्मा आया करता है। यदि उस समय आप बल का ध्यान कर रहे हैं, तो इसका धगर होना चाहिए। यदि कुछ भाई मन्दिरों पर भी हाथ उठाये, तो आप उनपर उतना ही हाथ उठाओ जितना उनकी दुष्टता दवा सके। उनमें धरावर प्रेम रखो। एक अपनी निवाहिता स्त्रो के सिवा अन्य सबको, चाहे वे मुसलमान हो, चाहे ईसाई, उन्हें अपनी माता के समान समझो। कही ऐसा न हो कि किसी को यह कहने का भीका मिल जाय कि हिन्दू सन्तान अपने धर्म को खो बैठी है। अपना आचरण ऐसा बनाओ कि किसी मुसलमान या किमो ईसाई की बेजा जिकायत न हो। अपना लक्ष्य यही है कि --

सर्वे न सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

ऐसा लक्ष्य रखो कि उसमें अपनी भी उन्नति हो, और दूसरो का भी भला हो, कही किसी का असमल न हो।”

महासभा के उद्देश्य

सन् १९२३ में मालवीयजी की अध्यक्षता में हिन्दू महासभा के लक्ष्य और नया सविधान निश्चित हुआ। “हिन्दू समाज के सभी पन्थवालो में तथा सभी वर्ग-वालो में पारस्परिक प्रेम की वृद्धि करके एकीकरण द्वारा इस अपने महान् समाज को सुसंगठित, प्रबल व उत्कर्षोन्मुख बनाना, और उसकी सर्वांगीण प्रगति करना” हिन्दू सभा का मुख्य उद्देश्य था। सघटित हिन्दू जाति व भारत की अन्य धार्मिक जातियों के साथ परस्पर सद्भाव उत्पन्न करके भारत की स्वयं-शासित स्वराज्य-युक्त एव महान् राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करने के लिए उनसे मित्रता बढ़ाना, मालवीयजी के नेतृत्व में संघटित हिन्दू महासभा का दूसरा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य था। हिन्दू जाति के निम्न वर्गों के साथ सब वर्गों की उन्नति करके उन्हें ऊँचा

उठाना, हिन्दुओं के हित की जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उसकी रक्षा करना, हिन्दुओं का सख्याबल कायम रखना व उसे बढ़ाना, हिन्दू स्त्रियों की स्थिति सुधारना, गोरक्षण व गो-संवर्धन करना, हिन्दू जाति के धर्म, सदाचार, शिक्षण और सामाजिक, राजकीय और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना, उसके दूसरे उद्देश्य थे। हिन्दू महासभा ने अपने विधान में एक टिप्पणी द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया था कि "हिन्दू समाज हिन्दू जाति के किसी भी विशेष पन्थ का, राजनीतिक पक्ष का, पक्षपात अथवा विरोध नहीं करेगी, अथवा किसी पथ के मत में रद्दोबदल नहीं करेगी।"¹

मालवीयजी की नीति-रोसि

मालवीयजी ने गया अधिवेशन से लेकर सन् १९२७ तक अर्थात् पाँच वर्ष तक हिन्दू महासभा का नेतृत्व किया, और इस जमाने में हिन्दू महासभा के सब उद्देश्यों को सदा अपने सामने रखा। उन्होंने हिन्दू समाज को सुसंगठित, प्रबल एवं उत्कर्षोन्मुख बनाने का प्रयत्न किया, साहस के साथ आततायियों का मुकाबला करने का उसे पाठ पढ़ाया, पर साथ ही साथ मुरालमानों के साथ सौहार्द बनाये रखने का उसे उपदेश किया। उनका आदेश था कि ("उन जीवों को नहीं मारना चाहिए जो किसी पर चोट नहीं करते। मारना उनको चाहिए जो आततायी हों, अर्थात् स्त्रियों पर या किसी दूसरे के धन या प्राण पर जो वार करते हों, या जो किसी के घर में आग लगाते हों। यदि ऐसे लोगों को मारे बिना अपना या दूसरों का प्राण या धन न बच सके तो उनको मारना धर्म है।"²) उन्होंने हिन्दुओं के कतिपय हितों की रक्षा के निमित्त कांग्रेस के विरुद्ध राजनीतिक दल संघटित किया, पर हिन्दू महासभाओं को किसी राजनीतिक पक्ष का पक्षपात करने की कभी सलाह नहीं दी, और स्वराज्य की माँग की प्राथमिकता पर सदा ध्यान रखा। उन्होंने समाज-सुधार के काम में सनातन-धर्म पर दृढ़ निष्ठा रखनेवाले हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को सदा ध्यान में रखा, और शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर ही समाज-सुधार का कार्य सम्पन्न किया।

विद्वत् परिषद्

अगस्त सन् १९२३ में काशी में तथा जनवरी सन् १९२५ में प्रयाग में हिन्दू महासभा के अधिवेशनों के अवसरों पर समाज-सुधार के प्रश्नों पर सनातनधर्मी पंडितों की व्यवस्था लेने के लिए मालवीयजी ने विद्वत् परिषद्

१ सोताराम चतुर्वेदी महामना मालवीयजी, पृ० ८८-८९।

२ धर्मोपदेश।

आयोजित की। कुछ पंडितों ने परिपद् में भाग लेने से ही इनकार कर दिया, कुछ ने परिपद् में आकर समाज-सुधार का समर्थन करने से, प्रचलित प्रथाओं में संशोधन करने से इनकार कर दिया। पर कुछ विद्वानों ने शास्त्रों के आधार पर शुद्धि, अन्त्यजोद्धार, बाल-विवाह के सम्बन्ध में व्यवस्था देते हुए किसी अंश में समाज-सुधार का समर्थन किया। ये व्यवस्थाएँ मालवीयजी की तितिक्षा, बुद्धिमत्ता, अथक परिश्रम का परिणाम थी। वे स्वयं इनसे पूरी तौर पर संतुष्ट नहीं थे। फिर भी वे इन्हें लाभदायक समझते थे। इन्हीं के आधार पर हिन्दू महासभा ने शुद्धि, अन्त्यजोद्धार, बाल-विवाह आदि सामाजिक प्रश्नों पर प्रस्ताव पास किये। पर बहुत से समाजसुधारकों की दृष्टि में ये व्यवस्थाएँ किसी व्यापक सामाजिक सिद्धान्त के बजाय शास्त्रों के प्रमाणों पर आधारित होने के कारण अपर्याप्त और अन्तराली थी, पूरी तौर पर कालानुरूप नहीं थी।

गौवो की सेवा

मालवीयजी गो-सेवा को मानवमात्र का, विशेषतः हिन्दुओं का पुनीत कर्तव्य समझते थे, और वे स्वयं इस काम में आजीवन संलग्न रहे। उनका कहना था कि 'गौ मानवजाति की माता के समान उपकार करनेवाली, बल और निरोगता देनेवाली, तथा उसकी आर्थिक उन्नति बढ़ानेवाली देवी है। इसके उपकार से मनुष्य कभी उन्नत नहीं हो सकता। गौ समान रीति से मानव मात्र की सेवा करती है। इसलिए सब जाति, धर्म और सम्प्रदाय के मनुष्यों को गोवंश की रक्षा करने, उसके साथ न्याय और दया का बर्ताव बढ़ाने में प्रेम के साथ शामिल होना चाहिए।'।

गोरक्षा के निमित्त उन्होंने बहुत से सम्मेलनों को आयोजित किया, सनातन धर्म सभा और हिन्दू सभा के अधिवेशनों में गोरक्षा को पुष्ट किया, तथा स्थान-स्थान पर गोशालाओं और पिंजरा-पोलो को स्थापित कराने का प्रयत्न किया। उन्होंने राजाओं, महाराजाओं, जमींदारों और तालुकेदारों से मिलकर गोचर भूमि के लिए जगह छुड़वायी, एवं मथुरा में आशानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट को स्थापित करने में मदद की।

ब्राह्मण-अब्राह्मण सौहार्द

सन १९२४ में हिन्दू महासभा के विशेष अधिवेशन पर पारस्परिक सौहार्द की वृद्धि की आवश्यकता पर जोर देते हुए मालवीयजी ने कहा : "ब्राह्मण अब्राह्मण दोनों ही एक सभ्यता के अन्तर्गत हैं। दोनों को भाई-भाई की तरह

रहना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि गुण और योग्यता जहाँ कहीं भी मिले, उसका आदर करें। ब्राह्मणों का राम, कृष्ण और बुद्ध की, जो ब्राह्मण नहीं थे, भक्ति करना इस बात का प्रमाण है कि गुण कहीं भी मिले उन्हें उसका आदर करने में संकोच नहीं होता था। दुःख की बात है कि सरकारी नौकरियों तथा दो एक मन्त्री पदों के लालच से, जो हिन्दूमात्र की एकाता के सामने तुच्छ वस्तुएं हैं, हम आपस में झगड़ते हैं (हमें दूसरों का सुख और शक्ति देखकर प्रसन्न होना चाहिए। जब तक हमारी बुद्धि में विकार न आ जाये, हमारे लड़ने का कोई कारण नहीं) क्या महात्मा गांधी अब्राह्मण नहीं हैं, और क्या यह सत्य नहीं कि आज देश में जितनी उनकी प्रतिष्ठा है उतनी और किसी की नहीं है? मैं अपने ब्राह्मण तथा अब्राह्मण भाइयों से आपस का भ्रम दूर करने का अनुरोध करता हूँ।”

लाला लाजपत राय का अध्यक्षीय भाषण

अप्रैल सन् १९२५ में कलकत्ते में आयोजित सम्मेलन की लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि घृणा के बजाय ‘प्रेम की वृद्धि ही हमारा उद्देश्य है।’^२ पर आत्मरक्षा का समुचित प्रबन्ध प्रत्येक व्यक्ति और समाज का पुनीत कर्तव्य है। अहिंसा के नाम पर गृहस्थों को संन्यासियों के धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसा करना वर्णाश्रम धर्म के मूल सिद्धान्त के विरुद्ध होगा।^३ उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि बच्चों, युवकों और युवतियों के जीवन में आनन्द की भावना संचारित की जाय, उन्हें उत्साही, प्रयत्नशील और महत्वाकांक्षी बनाया जाय, क्योंकि ऐसा कोई राष्ट्र स्वतंत्रता और समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जिसके युवक और युवतियाँ अभिलाषा-विहीन हों, संसार के प्रति उदासीन हों। उन्होंने कहा कि वह मनुष्य जिसे स्वतंत्र और समृद्ध होने की इच्छा नहीं, कभी सुखी नहीं हो सकता और वह सच्चे मानों में धार्मिक भी नहीं हो सकता। यह मोक्ष का मार्ग नहीं, विनाश का पथ है।^४

लाला लाजपत राय ने कहा. “हिन्दुओं ने अब तक राष्ट्रीय नीति का अनुसरण किया है, और मैं समझता हूँ कि उन्हें इस पर डटे रहना चाहिए। यदि

१ सीताराम चतुर्वेदी : महामना पंडित मदनमोहन मालवीय, खंड २, पृ० १२३।

२. इन्द्रप्रकाश ए रिब्यू आफ दी हिस्ट्री एन्ड वर्क आफ दी हिन्दू महासभा, पृ० ९१।

३ वही, पृ० ९१-९२।

४ वही, पृ० ९२-९३।

वे अपनी राष्ट्रीयता को साम्प्रदायिकता से बदल देंगे, तो वे अपने किये कराये पर पानी फेर देंगे।^१ फिर भी हम इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते कि भारत में ऐसे साम्प्रदायिक समूह हैं जो हमारी राष्ट्रीयता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, और अपनी साम्प्रदायिकता को इस हद तक आगे बढ़ा रहे हैं, जो सारे राष्ट्र के हितों के लिए हानिकर हैं। हिन्दू समाज के लिए तो निश्चित ही अनर्थकारी हैं। ऐसी साम्प्रदायिकता का हमें विरोध करना ही होगा, क्योंकि वह हमारे विचार में चिरस्थायी दासता, चिरस्थायी फूट और अविच्छिन्न पराधीनता का कारण होगी।^२

उन्होंने कहा . “दूसरे सम्प्रदायों से अपनी जाति की पोजीशन को निर्धारित करने के अतिरिक्त हिन्दू महासभा का कोई विशेष राजनीतिक काम नहीं है।”^३ हिन्दू साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध है—लखनऊ समझौते को गलत समझते हैं—प्रतिनिधित्व के सर्वमान्य सिद्धान्त को मानने को तैयार है जो सारे हिन्दुस्तान पर लागू हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि निर्वाचन समूह रायुक्त होगा, और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व विधान-सभाओं के बाहर लागू नहीं किया जायगा।^४

राजनीतिक प्रश्नों पर निर्णय

इस सम्मेलन में हिन्दू महासभा ने निश्चय किया कि “चूँकि देश में स्वराज्य को स्थापित करने और बनाये रखने के लिए शान्ति और सुख के लिए एक राष्ट्र का होना आवश्यक है, और राष्ट्रीय संस्थाओं और सेवाओं (नौकरियों) में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व एक संयुक्त राष्ट्र बनाने में हानिकर है, अतः हिन्दू महासभा इस प्रथा के परिचलन का दृढतापूर्वक विरोध करती है, और वह अपने गैर-हिन्दू भाइयों से प्रार्थना करती है कि वे ऐसी राष्ट्र विरोधी माँगों को छोड़ें, तथा राष्ट्रीय संहति और एक्य प्रतिष्ठित करने में हिन्दुओं का साथ दें।”^५

२३ अगस्त सन् १९२५ को काफी वाद-विवाद के बाद हिन्दू महासभा की कार्यसमिति ने निश्चय किया कि हिन्दू सभा चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़ा न करे, पर जहाँ इस बात का डर हो कि किसी प्रत्याशी का चुनाव हिन्दुओं

१. वही, पृ० ९३।

२. वही, पृ० ९३।

३. वही, पृ० ९३-९४।

४. वही, पृ० ९४।

५. वही, पृ० १७०।

के हित में नहीं होगा, वहाँ उसका विरोध करना हिन्दू मतदाताओं का कर्तव्य होगा ।^१

भाई परमानन्द इस निर्णय को ठीक नहीं समझते थे । वे चाहते थे कि हिन्दू सभा स्वयं प्रत्याशियों को खड़ा करे, और चुनाव लड़े । समाचार-पत्रों और भाषणों द्वारा उन्होंने अपने इस विचार का प्रचार भी किया । पर उनके आग्रह के बावजूद अप्रैल सन् १९२६ में हिन्दू महासभा ने अपने वार्षिक अधिवेशन में अपनी कार्यसमिति के निर्णय को स्वीकार कर लिया, पर कार्यसमिति को अधिकार दिया कि वह प्रान्तीय हिन्दू सभा के परामर्श से हिन्दू हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करे और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ अपने प्रत्याशी खड़ा करे ।^२ इस प्रस्ताव में हिन्दू महासभा ने सब राजनीतिक पार्टियों से प्रार्थना की कि वे विधान-सभाओं में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के सदस्यों को अपने सम्प्रदाय से विशेष रूप से सम्बन्धित मामले में अपनी स्वतंत्र राय देने की छूट देगी ।^३

इसी अधिवेशन में हिन्दू महासभा ने यह निर्णय किया कि उसकी राय में 'चूँकि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व और पृथक् निर्वाचन का सिद्धान्त विभिन्न सम्प्रदायों को पास लाने के बजाय राष्ट्रीय भावना के विकास में तथा म्युनिस्पैलिटियों, जिला बोर्डों एवं प्रान्तीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि सस्थाओं के निर्विघ्न संचालन में बाधक सिद्ध हुआ है, इसलिए सब राजनीतिक विचारों के हिन्दू राजनीतिज्ञ इस दोषपूर्ण सिद्धान्त का डट कर विरोध करेंगे' । महासभा ने यह भी निश्चय किया कि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के हित में लखनऊ पैक्ट का आंशिक सशोधन हिन्दुओं को स्वीकार नहीं होगा । इस प्रस्ताव में यह भी माँग की गयी कि प्रान्तीय स्वशासन या उत्तरदायी स्वायत्त-शासन की योजना में इस बात की स्पष्ट रूप से व्यवस्था कर दी जाय कि जाति या सम्प्रदाय के आधार पर नागरिक अधिकारों या सरकारी नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगाना या भेद बरतना प्रान्तीय सरकारों के लिए गैरकानूनी होगा ।^४

अप्रैल सन् १९२७ में डाक्टर जी० एस० मुजे की अध्यक्षता में हिन्दू महासभा ने अपने दसवें अधिवेशन में निश्चय किया कि चूँकि केन्द्रीय असेम्बली के कतिपय मुस्लिम सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर मुसलमान स्वयं सहमत नहीं, इसलिए इस पर कोई राय देना बिल्कुल व्यर्थ है । फिर भी हिन्दू सभा ने कहा कि प्रान्तों के एनर्गठन के प्रश्न का चुनाव-पद्धति से कोई सम्बन्ध नहीं है, किसी

१ वही, पृ० १७३ ।

२. वही, पृ० १७३-१७४ ।

३. वही, पृ० १७४ ।

४. वही, पृ० १७४-१७५ ।

विशिष्ट समुदाय को बहुसंख्यक बनाने के लिए भी नये प्रान्त का गठन अनुचित ही है। इस प्रस्ताव में हिन्दू महासभा ने साम्प्रदायिक समस्या पर विचार विमर्श के लिए चार सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया (१) सब विधान कौंसिलों के लिए संयुक्त निर्वाचन पद्धति, (२) जनसंख्या, निर्वाचकों की संख्या या कर जैसे अचर (एकरूप) सिद्धान्त के आधार पर किसी निश्चित समय तक के लिए विधान सभाओं में स्थानों की संरक्षता, (३) प्रत्येक प्रान्त में मताधिकार की एकरूपता, (४) धार्मिक अधिकारों और रिवाजों का संवैधानिक संरक्षण।^१

सन् १९२७ में दिसम्बर के अन्तिम साप्ताह में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर मद्रास में पंडित मदन मोहन मालवीयजी की अध्यक्षता में हिन्दू महासभा का विशेष अधिवेशन हुआ। मालवीयजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, “राष्ट्रीयता हिन्दू महासभा का उतना ही लक्ष्य है, जितना हिन्दुत्व”। उन्होंने बताया कि हिन्दू सभा के दो उद्देश्य हैं: “(१) हिन्दू समाज के सब वर्गों में अधिक से अधिक एकता और संहति बढ़ाना और उन्हें एक सूत्र में संगठित करना, तथा (२) हिन्दुओं और भारत के दूसरे सम्प्रदायों में सद्भावनाओं को प्रोत्साहित करना, और संयुक्त स्वशासित भारतीय राष्ट्र की उपलब्धि के निमित्त उनके साथ मैत्रीपूर्वक ढंग से व्यवहार करना,”^२ उन्होंने अपने इस अभिभाषण में दक्षिण के हिन्दुओं से ब्राह्मण-अब्राह्मण के विवाद को खत्म कर मेल के साथ राष्ट्रोत्थान के लिए काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने अन्त्यजोद्धार के लिए सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए तथाकथित अस्पृश्यों के लिए देव-दर्शन की सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, “केवल यह बात कि कोई मनुष्य अस्पृश्य है, उसे मन्दिर में प्रवेश करने और देवदर्शन से वंचित नहीं करता। यदि उसका हृदय शुद्ध है, तो ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है, और मन्दिर में उसे देवाराधन करने देना चाहिए। जो व्यक्ति नैतिक रूप में शुद्ध है, वह व्यक्ति ईश्वर को उस व्यक्ति से अधिक प्यारा है जो केवल शरीर में शुद्ध है।”^३ उन्होंने अपने इस भाषण में विभिन्न सम्प्रदायों में पारस्परिक सौहार्द की वृद्धि पर, तथा स्वतन्त्रता के लिए सतत प्रयत्न करने पर भी जोर दिया।^४

१. वही, पृ० १७९-१८०।

२. इंडियन क्वाटरली रजिस्टर, जुलाई-दिसम्बर, १९२७, पृ० ३५३।

३. वही।

४. वही।

अप्रैल सन् १९२८ मे महासभा ने अपने जबलपुर अधिवेशन मे पिछले वर्ष के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव की सब बातों की इस नयी शर्त के साथ पुष्टि की कि किसी प्रान्त में बहुसंख्यकों के लिए विधान-मंडलों मे स्थानों का संरक्षण नहीं होगा। महासभा ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरियों में कोई साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, और वे सम्प्रदायों के लिए योग्यता और क्षमता के आधार पर, जिनका निर्णय खुली प्रतियोगिता परीक्षण द्वारा होगा, खुली रहेंगी। सीमा प्रान्त के सम्बन्ध मे अपने गत वर्ष के निर्णय मे हेर-फेर करते हुए उसने मांग की कि बलूचिस्तान और सीमा प्रान्त में सामान्य प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र स्थापित की जाय ताकि उन्हें भारत के भात्री संवैधानिक सुधारों से वंचित रखने का कोई कारण न रहे।^१

पर सिन्ध के सम्बन्ध में महासभा की धारणा पहले जैसी बनी रही। मालवीयजी ने महासभा के दूसरे नेताओं और प्रतिनिधियों को समझाया कि सर्वदलीय कान्फ्रेंस की नेहरू कमेटी ने सिन्ध की समस्या पर विचार करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की है, उसे विचार करने दीजिये। पर मालवीयजी के सुझाव की उपेक्षा करते हुए महासभा ने भारी बहुमत से निश्चय किया कि उसकी राय में किसी विशेष सम्प्रदाय की जनसंख्या को ध्यान मे रखकर किसी प्रान्त का विभाजन या किसी नये प्रान्त का निर्माण ठीक नहीं कहा जा सकता।

मालवीयजी के नेतृत्व की उपेक्षा

इसके बाद मालवीयजी ने हिन्दू महासभा के काम से बहुत हद तक अपना हाथ खींच लिया। यद्यपि वे हिन्दू महासभा के उपाध्यक्ष बने रहे, परन्तु उसकी नीति-रीति के निर्धारण मे उनका सक्रिय योगदान बन्द हो गया। वास्तव मे हिन्दू महासभा की गतिविधि और मालवीयजी के दृष्टिकोण में इतना अन्तर हो गया था कि उनके लिए उसका नेतृत्व करना संभव नहीं था। राय बहादुर लाला लालचन्द की तरह डाक्टर मुजे और भाई परमानन्द भी कांग्रेस की नीति-रीति को ही हिन्दुओं की अधोगति का मूल कारण समझने लगे थे। ये दोनों नेता सोचने लगे थे कि हिन्दू-मुस्लिम एकता को स्वराज्य का मूलाधार बता कर कांग्रेस ने हिन्दुओं के मनोबल को कम किया है, और साइमन कमीशन का वहिष्कार हिन्दुओं की भारी ग़लती थी। इन धारणाओं पर आधारित नीति-रीति मालवीयजी को मज़ूर नहीं थी। उनके लिए हिन्दू सभा के साथ काम करना असंभव हो गया। जब कि वे अन्त तक साइमन कमीशन का बाइकाट

करते रहे, राजा नरेन्द्र नाथ ने पंजाब विधान कौंसिल के सदस्य की हैसियत से कमीशन से सहयोग किया, और पंजाब हिन्दू सभा की ओर से उसे निवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। इसी तरह जब कि सन् १९३० में मालवीयजी गोलमेज कान्फरेंस में शरीक होने को तैयार नहीं हुए, डाक्टर मुंजे ने हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि की हैसियत से उसमें भाग लिया। इसी तरह जबकि मालवीयजी यह नहीं चाहते थे कि हिन्दू सभा चुनावों में भाग ले, हिन्दू महासभा ने सन् १९२९ में अपनी कार्यसमिति को चुनावों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का अधिकार दे दिया।

भाई परमानन्द की समीक्षा

बहुत से पर्यवेक्षकों के विचार में सन् १९२३ और सन् १९२७ के बीच में हिन्दू संघटन आन्दोलन ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की, उसका श्रेय मालवीयजी, स्वामी श्रद्धानन्द और लाला लाजपत राय की क्षमता और नेतृत्व को था। पर भाई परमानन्द इससे सहमत नहीं थे। उनके विचार में "हिन्दू संघटन पूरे राष्ट्र से स्वतः प्रसूत उपज की तरह उठा, और किसी व्यक्तित्व से उसका बहुत कम सम्बन्ध है। संघटन, शुद्धि और अछूतोंद्वारा से बने हुए हिन्दू संहति के स्पष्ट कार्यक्रम के साथ देश के सब प्रमुख नगरों में हिन्दू सभाएँ शुरू की गयीं। ऐसा दिखाई देता है कि मुस्लिम समाज के विरुद्ध क्रोध की लहर के परिणाम से हिन्दू जनता ने हिन्दू संघटन आन्दोलन को अपनाया। इस लहर ने कुछ वर्षों में अपनी शक्ति खो दी। स्वामी श्रद्धानन्द ही ईमानदारी के साथ आन्दोलन की भावना से चिपके रहे, और उन्होंने उसे अपनी प्राणशक्ति से पुष्ट किया। उनके बलिदान ने जिसे जनता को नये उत्साह में भर देना चाहिए था, हिन्दू आन्दोलन के नेताओं पर उलटा प्रभाव डाला। उत्साह ठंडा पड़ गया, और हिन्दू आन्दोलन को फिर रोगस्थिति भोगनी पड़ी। साधारण जनता संघर्षप्रिय है, और सदा उस क्षेत्र में काम करना चाहती है जहाँ वह अपने रोष को अभिव्यक्त कर सके। हिन्दू संघटन का रचनात्मक कार्यक्रम उसके मनोभावों को अपील नहीं कर सका।"^१

आलोचना

जनता की कठिनाइयाँ, आवश्यकताएँ, आकांक्षाएँ और मनोवृत्तियाँ ही जनान्दोलन का आधार होती हैं। जनान्दोलन तभी जोर पकड़ता है जब जनता किन्हीं कारणों से स्थिति से तंग आकर उसमें आधारभूत परिवर्तन के लिए त्याग और बलिदान करने को तैयार हो जाती है, अपने पुराने आचार-विचारों का

उत्सर्ग भी ठीक समझने लगती है। हरेक जनान्दोलन का अपना नेता होता है। वही व्यक्ति किसी आन्दोलन का नेता बन सकता है जिसकी क्षमता पर जनता को विश्वास हो, जो जनता को उसकी राय में उसकी कठिनाइयों के निवारण का, तथा नयी स्थिति का मार्ग-दर्शन करा सके। नेता को भी अपने नेतृत्व की दिशा समय के साथ बदलनी होती है। जो व्यक्ति कालानुकूल आन्दोलन की दिशा में आवश्यक परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रखता, वह उसका सही नेतृत्व नहीं कर सकता, और उसके नेतृत्व में आन्दोलन दीर्घकालीन नहीं हो सकता। संपूर्ण आन्दोलन का लक्षण है, पर रचना उसका गुण और लक्ष्य है, तथा जनशक्ति की रक्षा और वृद्धि उसका कर्तव्य है। विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जनता को एक ही समय में बहुत से आन्दोलनों में भाग लेना होता है, उनमें यथासंभव सामंजस्य स्थापित करना होता है। कभी-कभी एक ही नेता का सम्बन्ध कई आन्दोलनों से होता है। व्यक्तिगत कारण से भी सामंजस्य स्थापित करना उसके लिए अनिवार्य होता है। पर यदि किसी नेता का सम्बन्ध केवल एक आन्दोलन से हो, तो भी उसे समाजहित की दृष्टि से सामंजस्य की आवश्यकता स्वीकार करना होती है।)

हिन्दू महासभा के आन्दोलन पर भी ये सब बातें लागू थी। सन् १९२३ में उत्तर भारत के हिन्दुओं का मुसलमानों के प्रति रोष और हिन्दू संघटन की ओर झुकाव उनकी कठिनाइयों, आवश्यकताओं, और मानसिक प्रतिक्रियाओं पर आश्रित थे। मालवीयजी, श्रद्धानन्दजी और लाजपतरायजी ने उन्हें पैदा नहीं किया, केवल उनका नेतृत्व किया। उनके अपने नेतृत्व का रूप भी बहुत कुछ परिस्थितियों की चुनौतियों का प्रत्युत्तर था।

स्वामी श्रद्धानन्द हिन्दू समाज के पुराने सेवक थे। उन्होंने रचनात्मक ढंग से समाज की बड़ी सेवा की थी, उसके सांस्कृतिक उत्थान में महत्त्वपूर्ण योगदान किया था। पर उनके बहुत से सामाजिक और सांस्कृतिक विचार सामाजिक पूर्वाग्रहों में फंसी हिन्दू जनता को पसन्द नहीं थे। इसलिए उन जैसे समाज-सेवी को भी बृहद् हिन्दू जाति कम से कम सन् १९१८ तक अपना सर्वसम्मत नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुई। सन् १९१९ की घटनाओं ने उनके नेतृत्व को विकसित किया, उसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, पर उसने बृहद् हिन्दू जाति के नेतृत्व का रूप तभी धारण किया जब परिस्थितियों से बाध्य हो बहुत से परम्परावादी हिन्दू शुद्धि और अछूतोंद्वार के सम्बन्ध में श्रद्धानन्दजी के विचारों को सुनने और किसी हद तक मानने को तैयार हुए। उनके नेतृत्व में रचना और

संघर्ष का समन्वय था। उन्होंने हिन्दुओं को मुसलमानों की चुनौतियों का साहस से मुकाबला करने का पाठ पढ़ाया, और समझौता कान्फरेंसों में स्वयं निर्भीकतापूर्वक हिन्दू हितों की पुष्टि की, पर उसके साथ ही वे समाज के पुनर्निर्माण में संलग्न रहे। शुद्धि और अन्त्यजोद्धार दोनों ही उनके मूल मन्त्र थे। पर सम्भवतः शुद्धि से भी कहीं अधिक अन्त्यजोद्धार पर उनका आग्रह था, और उनके निर्माण-कार्य का क्षेत्र बहुत व्यापक था। राष्ट्रीय गौरव की रक्षा उनके नेतृत्व का महत्त्वपूर्ण अंग था। उन्होंने हिन्दू महासभा का नेतृत्व करते हुए सरकार के कर्मचारियों की कभी खुशामद नहीं की, उनके सामने अपना और हिन्दू जाति का सिर झुकाने की बात नहीं सोची। वे हिन्दू जाति के बल पर परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहते थे।

यही बातें लाला लाजपत राय के सम्बन्ध में भी कही जा सकती हैं। हिन्दू जाति के पुनरुत्थान में स्वामी श्रद्धानन्द के समान ही उनकी पुरानी अभिरुचि थी। हिन्दू नवयुवकों की शिक्षा, हिन्दू संस्कृति का पुनरुज्जीवन, हिन्दू समाज का सुधार, दलितोद्धार उनके प्रारम्भिक सार्वजनिक जीवन के मुख्य धधे थे। उन्होंने सन् १९०९ में लिखा था : "नैतिकता की माग है कि किसी दूसरे विचार की अपेक्षा बिना न्याय और मानवता की शुद्ध भावना से हमें पतित वर्गों के उद्धार का काम शुरू कर देना चाहिए— हिन्दुओं का साम्प्रदायिक हित भी इसी में है— हिन्दुत्व का घेरा इन वर्गों के बिना जीवित रह सकता है, पर निश्चित ढाँचे की तरह।"^१ वे हिन्दुत्व की पुष्टि के साथ-साथ देशहित की वृद्धि के लिए काम करना भी जरूरी समझते थे। उन्होंने सन् १९०७ में लिखा था : "हमारे लिए उत्कृष्टरूप में अपेक्षित है कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी पर्याप्त मात्रा में इतना देशभक्त और कर्तव्य-परायण हो कि वह इस विचार पर विश्वास और कार्य कर सके कि देश का हित सर्वोपरि है और सब व्यक्तिगत हितों को अभिभूत करता है।"^२ उनका सारा जीवन देश-हित की भावना से अनुप्राणित था, देश की स्वतंत्रता उनके जीवन का परम लक्ष्य था। किसी अखिल भारतीय हिन्दू मंच का नेतृत्व ग्रहण करने से पहले ही उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय मंच पर नेता का गौरव प्राप्त कर लिया था। उनका आर्थिक चिन्तन और उनकी सामाजिक सहानुभूति समाजवाद के रूप में रग गये थे। हिन्दू हितों की रक्षा, दलित वर्गों का उत्थान, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके नेतृत्व के मूल मन्त्र थे। वे हिन्दू महासभा को हिन्दू हितों की रक्षा

का, और कांग्रेस को स्वतंत्रता सघर्ष का मंच स्वीकार करते थे, तथा दलितों के उत्थान के लिए दोनों मंचों का प्रयोग करना चाहते थे। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता की आवश्यकता स्वीकार करते थे। पर उसके नाम पर हिन्दू हितों को न्योछावर करने को तैयार नहीं थे। इसी तरह वे हिन्दू हितों की रक्षा के लिए सतत प्रयत्न आवश्यक समझते थे, पर उसके नाम पर स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा अनुचित मानते थे। वे स्वराज्य की कीमत पर अंग्रेजों से समझौता करके हिन्दू हितों की रक्षा की सम्भावना पर विचार करने को भी तैयार नहीं थे। उनकी दृढ़ धारणा थी कि स्वतंत्र भारत में ही हिन्दुओं के गौरव और हितों की रक्षा और वृद्धि सम्भव है। किसी परतंत्र जाति के लिए ब्रिटिश साम्राज्यशाही से न्याय की आशा निरर्थक है, और स्वतंत्रता की कीमत पर कभी किसी से कोई सौदा नहीं किया जा सकता। इसीलिए यद्यपि सन् १९२६ में उन्होंने कांग्रेस की अडगा नीति का विरोध किया, और हिन्दुओं ने अनुरोध किया कि वोट देते समय स्वराज्य के साथ-साथ हिन्दू हितों की रक्षा का भी ध्यान रखें, पर सन् १९२७ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कही अधिक सरकार की दमन नीति, मुद्रा नीति, तथा रिजर्व बैंक की योजना का विरोध किया, और सन् १९२८ में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, नेहरू कमेटी द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया, तथा साइमन कमीशन के बहिष्कार में आयोजित जुलूस का नेतृत्व किया। जनता की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि वे इन सब अवसरों पर हिन्दू जनता के मनोभावों का प्रतिनिधित्व करते थे।

मालवीयजी के वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन के विकास की प्रक्रिया कुछ भिन्न थी। सनातन-धर्म की परम्पराओं से पोषित जीवन में समाज-सुधार की भावना बहुत धीरे-धीरे काफी स्कावट के साथ विकसित हुई। पर सन् १९२२-२३ की स्थिति में उसने शुद्धि और अन्त्यजोद्धार के दृढ़ समर्थक का रूप धारण कर लिया। इसी तरह हिन्दू जाति के पुनरुत्थान की अभिलाषा ने, जो अब तक सांस्कृतिक पुनर्जीवन के प्रयासों में अभिव्यक्त होती रही थी, हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य की भयंकर स्थिति में मालवीयजी को हिन्दू सघटन का समर्थक बना दिया। पर लाला लाजपत राय की तरह वे भी यह समझते रहे कि स्वतन्त्रता में ही भारतीय राष्ट्र और हिन्दू जाति का स्थायी हित निहित है, और स्वराज्य की कीमत पर ब्रिटिश साम्राज्यशाही से सौदेबाजी जघन्य पाप है, जनता के साथ घोर विश्वासघात है। उनका दृढ़ विश्वास था कि हिन्दू जनता स्वराज्य चाहती है, उसे अपना परम हित समझती है, और वह किसी व्यक्ति को चाहे वह कितना

ही बड़ा कथो न हों अपना सच्चा नेता मानने को तैयार नहीं है जिसको नीति-रीति या क्रिया-कलाप स्वतन्त्रता की ओर बढ़ने में किसी प्रकार बाधक हो। मालवीयजी कांग्रेस को स्वतन्त्रता सघर्ष का मुख्य मंच स्वीकार करते थे, और उसे इस रूप में सुदृढ़ और सबल बनाना सब देशभक्तों का कर्तव्य समझते थे। उनकी दृष्टि में कांग्रेस की गलत नीतिरीतियों और क्रिया कलापों की खुली आलोचना हो सकती थी, और तगड़ा विरोध किया जा सकता था, पर उसके पीछे पीछे या उसके विरोध में साम्राज्यशाही से समझौता, उनकी दृष्टि में, एक ऐसा अपराध था जिसे जनता कभी सहन नहीं कर सकती।

स्वामी श्रद्धानन्द और लाला लाजपत राय के निधन के बाद जिन व्यक्तियों ने हिन्दू महासभा को नया नेतृत्व प्रदान करने का प्रयत्न किया वे पुराने रामाजसेवी और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के निमित्त विभिन्न अवसरों पर काफी कष्ट सहें थे। हिन्दू महासभा के आन्दोलन की प्रगति में भी उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था। उनके विचार हिन्दू महासभा के बहुत से कर्मठ कार्यकर्ताओं के विचारों और भावनाओं से मिलते-जुलते थे। उन्हें उनका विश्वास भी प्राप्त था, और अपनी नीतिरीति को हिन्दू जनता के सामने प्रस्तुत कर उसे अपनाने की अपील करने का उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार था। वे हिन्दू महासभा के निर्णय पर अपने विचारों और भावनाओं की छाप लगा सके, पर हिन्दू जनता को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सके। इसका मूल कारण हिन्दू महासभा के पुराने नेताओं का विश्वासघात नहीं, बल्कि हिन्दू जनता की अपनी भावनाएं थी।

नये नेताओं को शिकायत थी कि पुराने नेताओं के अनुरोध पर साइमन कमीशन का बहिष्कार भारी गलती थी। उनके इस विचार की पुष्टि भारतमंत्री लार्ड बर्केंहेड की इस युक्ति से होती है कि यदि हिन्दू कमीशन का बहिष्कार करेंगे, तो उसके निर्णय मुसलमानों के पक्ष में होंगे। पर ये नेता भूल जाते हैं कि कमीशन के बहिष्कार का मूल कारण सचेत और प्रबुद्ध हिन्दू जनता का रोष था, जिसे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त उन उदारदलीय नेताओं ने भी अनुभव किया जो असहयोग और सविनय-अवज्ञा के विरोधी और सहयोग की नीति के समर्थक थे। यदि इस देशव्यापी रोष की स्थिति में हिन्दू महासभा साइमन कमीशन से सहयोग करने की बात पुष्ट करती, तो वह जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ नहीं सकती थी। वह अपने को उससे विल्कुल अलग कर लेती। सन् १९२९ में तो पंजाब हिन्दू महासभा के नेता राजा

नरेन्द्रनाथ ने विधान सभा के सदस्य की हैसियत से, श्रीर पंडित नानक चन्द ने पत्रात्र हिन्दू सभा के प्रतिनिधि की हैसियत से साइमन कमीशन के साथ सहयोग किया, पर वे न तो साइमन कमीशन के निर्णयो पर कोई प्रभाव डाल सके, और न हिन्दू जनता के मनोभावो को सहयोग की ओर मोड सके । सन् १९३० में बहुत से उदारदलीय नेताओ के साथ डाक्टर वी० ए० मुजे, राजा नरेन्द्र नाथ आदि हिन्दू नेताओ ने भी गोलमेज कान्फरेंस में भाग लिया, पर वे जनता के मन पर प्रभाव नहीं डाल सके । नमक सत्याग्रह में हिन्दू युवको ने, हिन्दू महासभा के बहुत से नेताओ और कार्यकर्ताओ ने भी, डटकर भाग लिया, और सिद्ध कर दिया कि उनमें रोष, उत्साह और साहस की कमी नहीं । सन् १९३४ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो व्यवस्था पास की, उसने भी सिद्ध कर दिया कि ब्रिटेन के कजरवेटिव दल ने उन हिन्दू नेताओ के विचारो और भावनाओ की उपेक्षा करते हुए, जिन्होंने गोलमेज कान्फरेंस में सहयोग की इच्छा से विचार-विमर्श में भाग लिया, विघटनकारी स्वतन्त्रता विरोधी शक्तियो को पुष्ट करना ही उचित समझा ।

भाई परमानन्दजी का यह कहना ठीक है कि जिस क्षोभ ने सन् १९२३ में हिन्दू महासभा के आन्दोलन को गति प्रदान की, वह चार पांच वर्ष में ठंडा पड गया । पर वे यह भूल गये कि पुराना क्षोभ ठंडा पड जाने पर आन्दोलन की गतिविधि को बदलना अनिवार्य हो जाता है । यह ठीक है कि जनता सघर्षप्रिय होती है । पर युद्ध और दगो के रूप में सघर्ष भावना की अभिव्यक्ति प्रगतिघातक असह्य सगट उपस्थित करती है, और सुख की स्वाभाविक इच्छा किसी मनुष्य या समूह को सदा लड़ाई पर डटे नहीं रहने देती । दुर्भावनाओ और हानिकर प्रथाओ से सघर्ष ही सघर्ष शक्ति की अभिव्यक्ति का लाभकर उपयोग है । उस समय जबकि ब्रिटिश साम्राज्यशाही अपने कुचक्रो द्वारा हरिजनो को हिन्दू जाति से कम से कम राजनीतिक क्षेत्र में विलकुल अगल कर देना चाहती थी, हरिजनोद्वार का काम रचनात्मक भी था, संघर्षात्मक भी था । साम्राज्यशाही के कुचक्रो को नष्ट करने के लिए रचनात्मक ढंग से हिन्दू जाति की सहज सघर्ष भावना का उपयोग किया जा सकता था । भाई परमानन्द जैसे साहसी, त्यागी और कर्तव्यपरायण समाजमुधारक से तो हिन्दू जनता की आत्मरक्षा और सघर्ष का सहज भावनाओ को अन्त्यजोद्वार की ओर निर्दिष्ट करने की आशा की जा सकती थी । यदि रचनात्मक कार्य जैसे फोके कार्य में जनता की भावनाओ को अतर्ग्रस्त करना कठिन था, तो हिन्दू हितो के सम्बन्ध में प्रस्ताव, तथा उनके

सम्बन्ध में सरकार से गुप्त या प्रकट वार्ता किस तरह जनता को आन्दोलित कर सकती थी ।

हिन्दू जाति का सजग वर्ग परतन्त्रता को ही हिन्दू जाति के सब कष्टों का मूल कारण समझने लगा था, और वह अपनी सारी शक्ति उसे उखाड़ फेंकने में ही लगा देना चाहता था । उसकी मनोवृत्ति को नया मोड़ देना असम्भव ही था, यदि यह सम्भव भी होता तो हितकर भी होता, यह कहना कठिन है ।

जो भी हो, सन् १९२७ और सन् १९३७ के युग में मालवीयजी द्वारा सरकार की साम्राज्यशाही नीतियों और योजनाओं का विरोध, साइमन कमीशन का वाइकाट, सविनय-अवज्ञा आन्दोलनों में योगदान, दूसरी गोलमेज कान्फरेंस में राष्ट्रीय मांगों का समर्थन, अन्त्यजोद्धार के लिए परम्परावादियों से संघर्ष, तथा कांग्रेस दोनों से संघर्ष अवश्य हिन्दू जनता की संघर्ष भावना का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट का समर्थन, तथा हिन्दू महासभा के अध्यक्ष श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित एकता सम्मेलन में हिन्दू-मुस्लिम समस्या को सुलझाने का भागीरथ प्रयत्न हिन्दू जनता की शान्ति-प्रिय मनोवृत्ति का प्रतीक था ।



भी निश्चय हुआ कि मौलवियों और पण्डितों की ओर से घोषणा की जाय कि जान-माल तथा इवादातगाह (पूजा के स्थानों) पर हमला करना गुनाह है, पाप है।

कांग्रेस ने अपने अधिवेशन के अन्तिम दिन अर्थात् १९ सितम्बर को उपरोक्त कमेटी के निर्णय के अनुसार (१) जनाब अब्बास तैयबजी (२) जनाब टी० के० शेरवानी, (३) बाबू भगवान दास, (४) बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन, (५) मास्टर सुन्दर सिंह, (६) श्री जार्ज जीसेफ और (७) श्री वी० एच० भरुचा की एक जाच कमेटी नियुक्त की। उसे आदेश दिया गया कि जहाँ कहीं दंगे हों, वहाँ जा कर वह उसकी जाँच करे, तथा दंगे बन्द करने का उपाय बताये। नेशनल पैक्ट की तैयारी के लिए डाक्टर एम० ए० अन्सारी और लाला लाजपतराय की कमेटी गठित की गयी। तीसरे प्रस्ताव द्वारा समाचारपत्रों पर कड़ा सार्वजनिक नियंत्रण रखने की व्यवस्था की गयी। चौथे प्रस्ताव द्वारा निश्चय हुआ कि जिलों में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए खिलाफत कमेटी, हिन्दू सभा तथा अन्य प्रमुख स्थानीय संस्थाओं की सलाह से जिला कांग्रेस कमेटियों के निरीक्षण में जिला कमेटियाँ गठित की जायें। ये कमेटियाँ शान्ति-भंग होने पर उसके दुष्परिणामों को कम करने का, तथा शान्ति प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करें, और जनता को प्रोत्साहित करें कि ये प्रतीकारात्मक कार्यवाही के बजाय समझौते के जरिये विवाद का समाधान करें।

इन चार प्रस्तावों में से तीन प्रस्तावों पर ठीक से काम नहीं हो सका। जाच कमेटी दंगों के कारणों की जाँच करने में विफल रही, समाचार पत्र अतिरिक्त ढंग से दंगों के समाचार छापते रहे, तथा अशान्त क्षेत्रों में शान्ति प्रतिष्ठित करने के निमित्त जिला कमेटियाँ भी ठीक तौर से गठित नहीं हो सकीं। दंगे होते ही रहे। पर मौलाना आजाद की सलाह और सहयोग से डाक्टर अन्सारी और लाला लाजपतराय ने नेशनल पैक्ट की रूपरेखा अवश्य तैयार कर ली।

नेशनल पैक्ट

इस नेशनल पैक्ट में पूर्ण स्वराज्य की मांग फिर से पुष्ट की गयी, और स्वराज्य मिलने पर संघीय लोकतान्त्रिक सरकार प्रतिष्ठित करना निश्चित किया गया। पैक्ट में स्पष्ट किया गया कि देवनागरी और उर्दू लिपि में हिन्दुस्तानी ही राष्ट्र-भाषा होगी, सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, पर साम्प्रदायिक संस्थाओं पर सरकारी धन खर्च नहीं होगा। यह भी निश्चय किया गया कि सरकारी नौकरियों में, तथा शैक्षिक संस्थाओं में सम्प्रदाय, रंग या जाति का कोई

भेद नहीं होगा, सयुक्त निर्वाचन-पद्धति स्थापित की जायगी, तथा विभिन्न सम्प्रदायों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित किये जायेंगे। मुसलमान गोहत्या बन्द कर दे, और हिन्दू मस्जिदों के सामने बाजा बजाना बन्द कर दें।

बङ्गाल पैक्ट

इस नेशनल पैक्ट की उपेक्षा करते हुए इसके प्रकाशित होने के पहले ही देशबन्धु चित्तरजन दास ने बंगाल के कतिपय मुसलमान नेताओं से मिलकर बंगाल पैक्ट सूत्रबद्ध करके प्रकाशित कर दिया। इस पैक्ट द्वारा निर्धारित किया गया कि बंगाल में (१) विधान कौंसिल में पृथक् निर्वाचन के साथ जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा, (२) हर जिले में स्थानीय निकायों में बहुसंख्यक सम्प्रदाय का साठ प्रतिशत, और अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का चालीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा, (३) मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों में ५५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित होंगे, (४) मस्जिदों के सामने बाजा बजाने की आज्ञा नहीं होगी, (५) धार्मिक कुर्बानी के लिए गोहत्या पर कोई रुकावट नहीं होगी, पर गौ की हत्या इस प्रकार की जायेगी कि उससे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट न पहुँचे, (६) धर्म से सम्बन्धित कोई भी कानून सम्प्रदाय विशेष के पिछेहत्तर प्रतिशत सदस्यों की स्वीकृति बिना पास नहीं किया जायगा, (७) साम्प्रदायिक झगड़ों के निपटारे के लिए प्रत्येक तहसील में हिन्दुओं और मुसलमानों की सम्मिलित कमेटियाँ बनायी जायेंगी।

भालवीयजी ने बंगाल पैक्ट का विरोध करते हुए कहा कि यद्यपि पैक्ट का सबध केवल बंगाल से है, फिर भी इसका प्रभाव बंगाल तक सीमित नहीं रह सकता। ऐसी दशा में प्रान्तीय स्तर पर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रश्न पर कोई समझौता करना अनुचित था। उन्हें सन्देह था कि इस पैक्ट के बाद लाजपत राय अन्सारी नेशनल पैक्ट पर ठीक तौर से विचार नहीं हो सकेगा। लाला लाजपत राय भी बहुत क्षुब्ध थे।

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में कोकनाडा में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटियों ने इन दोनों पैक्टों पर विचार किया। पंडित मोतीलाल ने प्रस्ताव किया कि दोनों पैक्ट विचारार्थ डाक्टर अन्सारी और लाला लाजपत राय की कमेटियों को भेज दिये जायें। बहुत से सदस्यों ने बंगाल पैक्ट की कड़ी आलोचना की, उसे रद्द करने की मांग की, इसके लिए सशोधन प्रस्तुत किया। इस पर कुछ मुसलमानों ने कांग्रेस छोड़ने की धमकी

दी। बहुमत से पंडित मोतीलाल नेहरू का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। किसी कारण से इस अधिवेशन के लिए मालवीयजी कोकनाडा नहीं गये। पर उन्होंने तार द्वारा बंगाल पैक्ट के विरुद्ध अपनी समीक्षा अध्यक्ष को भेज दी। मई सन् १९२४ में बंगाल प्रान्तीय कान्फरेंस ने अपने सिराजगंज अधिवेशन में बंगाल पैक्ट को भारी बहुमत से मजूर कर लिया।

यद्यपि नेशनल पैक्ट की तैयारी में मौलाना आजाद का भी भरपूर सहयोग था, पर उनका झुकाव बंगाल पैक्ट की ओर था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि गांधीजी की तरह देशबन्धु दास ने भी सकीर्ण साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर बंगाल के मुसलमानों की मांगों को पाँच मिनट में स्वीकार कर उन्हें बंगाल पैक्ट का स्वरूप दे दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक 'इंडिया विन्स फ्रीडम' में लिखा है कि देशबन्धु दास चाहते थे कि जब तक बंगाल और कलकत्ता कारपोरेशन की नीकरियों में मुसलमानों की सख्या जनसंख्या के अनुपात के बराबर नहीं हो जाती, तब तक बंगाल सरकार द्वारा ६० प्रतिशत और कलकत्ता कारपोरेशन द्वारा ८० प्रतिशत नयी नियुक्तियों पर मुसलमान भरती किये जायें। आजाद साहब को दुःख था कि चित्तरजनदासजी की असामयिक मृत्यु के बाद उनकी घोषणा उनके कतिपय अनुयायियों ने अस्वीकार कर दी। नतीजा यह था कि "बंगाल के मुसलमान कांग्रेस से दूर हो गये, और विभाजन के पहले बीज बो दिये गये।"^१

गांधीजी का वक्तव्य

सख्त बीमारी के कारण फरवरी सन् १९२४ में गांधीजी छोट दिये गये। साम्प्रदायिक दमन्या का पूरे तौर पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने मई सन् १९२४ में हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर एक विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित किया। अहिंसात्मक उपायों के महत्त्व की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि समस्या को सुलझाने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि तलवार के बजाय पंचायत से काम लिया जाय। लोगों को अपने मन से यह भ्रान्त धारणा निकाल देनी चाहिए कि अहिंसा कायरो का अस्त्र है। उन्हें यह समझना चाहिए कि कायरता की दवा बलप्रदर्शन नहीं, बल्कि सकट का सामना करना है। हिन्दुओं को मुसलमानों के आतंक से नहीं डरना चाहिए, और मुसलमानों को समझना चाहिए कि अपने हिन्दू भाइयों को सताना उनकी मर्यादा के विरुद्ध है। हिन्दुओं को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वे बलपूर्वक गोहत्या बन्द करवा सकते

हैं, और मुसलमानों को भी यह समझना चाहिए कि वे बलपूर्वक मस्जिदों के सामने बाजा और आरती को नहीं रोक सकते। हिन्दुओं को उचित है कि वे मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो छोड़ दें कि वे किस तरह का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, और इस सम्बन्ध में उनका जो निर्णय हो उसे उदारतापूर्वक मान लें। राष्ट्रीय शासन में नौकरियों का आधार योग्यता ही होना चाहिए, और उसकी जाँच के लिए भिन्नभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों को एक कमेटी होनी चाहिए। शुद्धि और तबलीग का काम ईमानदारी के साथ जँचे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। गाली गलौज तथा उत्तेजना फैलाने वाले लेखों को रोकने के लिए जनमत तैयार किया जाना चाहिए, और नेताओं में जो अविश्वास बढ़ रहा है उसे दूर कर परस्पर विश्वास पैदा करना चाहिए। हिन्दुओं को कायरता त्याग कर विश्वास करना सीखना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही विश्वास का उदय होता है।

मालवीयजी की धारणा

मालवीयजी के लिए गांधीजी के वक्तव्य की सब बातें स्वीकार करना सम्भव नहीं था। मिसाल के तौर पर जबकि गांधीजी चाहते थे कि आततायियों का सामना साहस के साथ पर अहिंसात्मक ढंग से किया जाय, मालवीयजी आत्मरक्षा के निमित्त बल का प्रयोग न्यायोचित और अनिवार्य मानते थे। पर गांधीजी की तरह मालवीयजी भी हिन्दू-मुस्लिम एकता देशोद्धार के लिए आवश्यक समझते थे। मालवीयजी चाहते थे कि "हमारे सब सम्बन्ध देश-प्रेम की नींव पर स्थापित हो।"^१ उन्होंने जून सन् १९२३ में कहा था कि 'अगर कोई हिन्दू किसी मुसलमान को मुसलमान होने के कारण हानि पहुँचाये और कोई मुसलमान किसी हिन्दू को हिन्दू होने के कारण दुःख दे, तो हमारी गणना ससार की सभ्य जातियों में कभी नहीं हो सकती हमें एक दूसरे को भाई समझना चाहिए। हिन्दू मन्दिर में जायें, मुसलमान मस्जिद में, और ईसाई गिरजा में। लेकिन देश के हित में हम सब को एक हो जाना चाहिए।'^२ वे चाहते थे कि सब हिन्दू और मुसलमान शपथ लें कि "हम धर्म और मत के कारण किसी भाई के साथ ज्यादाती नहीं करेंगे, और तमाम वहनो, वेष्टियों और माताओं को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे।"^३ मालवीयजी का कहना था कि किसी

१. सीताराम चतुर्वेदी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, खंड २, पृ० ८७।

२ वही, खंड २, पृ० ८७। ३ वही, खंड २, पृ० ८९।

धर्मवाले को अपने धर्म का प्रचार करने से रोका नहीं जा सकता, पर यह काम ऐसी रीति से करना चाहिए कि किसी को क्लेश न पहुँचे।”^१

२३ फरवरी सन् १९२४ को पंजाब हिन्दू सम्मेलन में इसी बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा - “धर्म-प्रचार का काम बहुत शान्ति और धैर्य से होना चाहिए। जो कोई अपने धर्म से भ्रष्ट होता है, उसे अवश्य वचाने की कोशिश करो। परन्तु जो यत्न करो उसमें सदैव इस बात का ध्यान रखो कि परमात्मा हमारी सब बातों को देखता और सुनता है। अस्तु, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तवलीग और शुद्धि का ज्यादा शोर मचाना या समाचारपत्रों में उसका आन्दोलन करते रहना परस्पर मेल में विघ्न डालता है।”^२ उनकी दृढ़ धारणा थी कि “जिस किसी को जो धर्मोपदेश ग्राह्य हो, उसे उसके ग्रहण करने से रोकना पाप है।” पर वे चाहते थे कि “हिन्दू और मुसलमान दोनों अपने धर्म के सिद्धान्तों को अच्छी तरह से समझ पक्के हिन्दू और पक्के मुसलमान बनें,”^३ “धार्मिक जीवन व्यतीत करें”, और अपने-अपने दायरे के अन्दर काम करें, वहाँ बहुत-सा काम करने को मौजूद है”^४। मालवीयजी कहते थे कि ‘हिन्दूओं और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ न्याय का वर्तव्य करना चाहिए।’^५ उनका उपदेश था कि “जो बात आपको अपने लिए बुरी लगती हो वह और के लिए भी मत चाहो। जो न्याय अपने लिए चाहते हो, वही दूसरे भाइयों के लिए भी चाहो।”^६

ये सब विचार जो मालवीय जी ने गांधी जी के वक्तव्य के पहले ही पंजाब हिन्दू महासभा के सम्मेलनों में अध्यक्ष पद से किये भाषणों में व्यक्त किये थे, गांधीजी के मई के वक्तव्य के विचारों और भावनाओं के अनुकूल थे।

गांधीजी का अनशन और एकता सम्मेलन

गांधीजी की कोशिशों के बावजूद अवस्था दिन पर दिन बिगड़ती गयी। साम्प्रदायिक तनातनी और दंगे जारी रहे। गांधीजी का धैर्य छूट गया और उन्होंने सितम्बर सन् १९२४ में २१ दिन का उपवास शुरू किया। जनता पर उनके उपवास का प्रभाव किसी हद तक जरूर पड़ा। २५ सितम्बर को दिल्ली में पंडित मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में एकता सम्मेलन आयोजित हुआ,

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| १. वही, खंड २, पृ० ९०। | २. वही, खंड २, पृ० ११८। |
| ३. वही, खंड २, पृ० ११८। | ४. वही, खंड २, पृ० ११९। |
| ५. वही, खंड २, पृ० ११९। | ६. वही, पृ० ११६। |
| ७. वही, पृ० ११८। | |

और उसमें हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य के कारणों पर कई प्रस्ताव पास किये गये। ये प्रस्ताव बहुत हद तक गांधीजी के उस वक्तव्य के अनुरूप थे जो उन्होंने मई मास में हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर प्रकाशित किया था। इनमें मौलिक धार्मिक अधिकारों को मान्यता देते हुए अनुरोध किया गया कि इनका इस तरह प्रयोग किया जायगा कि उससे दूसरों की धार्मिक भावनाओं को कम से कम ठेग पहुँचे। इनमें धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति और व्यवहार की स्वतन्त्रता तथा धर्मपरिवर्तन एवं श्रद्धा और तबलीग का अधिकार स्वीकार किया गया, पर व्यापक सहनशीलता को कर्तव्य निश्चित किया गया, और जनता से अनुरोध किया गया कि वह सदा दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी धार्मिक स्वतन्त्रता और अधिकार का प्रयोग करे। तर्क और अनुनय द्वारा ही धर्मपरिवर्तन का कार्य किया जाय, आर्थिक प्रलोभन आदि अनुचित उपायों का प्रयोग न किया जाय, सोलह वर्ष से कम उमर के बच्चों का धर्मपरिवर्तन उनके माता-पिता और अभिभावक के साथ ही किया जाय, धर्मपरिवर्तन के कारण कोई व्यक्ति पुराने धर्मावलम्बियों से दण्डित न किया जाय, तथा श्रद्धा और तबलीग का कार्य शान्तिपूर्वक किया जाय। इन प्रस्तावों में स्वीकार किया गया कि जबरदस्ती गो-हत्या बन्द नहीं हो सकती और न मस्जिदों के सामने मुसलमान बाजा बन्द करा सकते हैं, पर हिन्दूओं और मुसलमानों से अनुरोध किया गया कि वे इन प्रश्नों पर एक दूसरों की भावनाओं का आदर करें, और इस तरह सद्भावना को पुष्ट करें। सम्मेलन ने घोषित किया कि किसी सम्प्रदाय द्वारा किसी दूसरे सम्प्रदाय के व्यक्तियों का सामाजिक या व्यापारिक दहिष्कार या सम्बन्ध-विच्छेद निन्दनीय है और पारस्परिक सौहार्द के विकास में बाधक है। उसने आशा व्यक्त की कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के व्यवहार से अपनी धार्मिक भावनाओं पर आघात अनुभव करे, तो वह कानून की अवहेलना करने के बजाय पंचायत या अदालत द्वारा शिकायत दूर कराने का प्रयत्न करेगा। सम्मेलन ने १५ सदस्यों की एक राष्ट्रीय पंचायत गठित की, और उसे स्थानीय पंचायतों को गठित करने का आदेश दिया। ये सब प्रस्ताव मालवीयजी को गजूर थे। इनके सूत्रीकरण में मालवीयजी का महत्त्वपूर्ण योगदान था, जिसकी भारत के अधिधर्मध्यक्ष (मेट्रोपालिटन) ने बहुत प्रशंसा की थी।

नवम्बर सन् १९२४ में बम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। उसने बंगाल सरकार द्वारा जारी किये गये क्रिमिनल ला अमेंडमेंट बिलिनेन्स (फौजदारी कानून संशोधन अध्यादेश) की निन्दा की, और इस अध्यादेश तथा सन् १८९८ के बंगाल रेगुलेशन न० ३ को वापस लेने की माँग की। इस सम्मेलन ने सभी

राजनीतिक दलों की कमेटी बैठायी, जो साम्प्रदायिक समझौता तथा स्वराज्य के लिए एक योजना तैयार करे। कमेटी को आदेश दिया गया कि मार्च सन् १९२५ तक वह अपनी योजना उपस्थित करे।

जनवरी सन् १९२५ में दिल्ली में कमेटी की बैठकें हुईं। कमेटी दो भागों में विभाजित हो गयी। एक उपसमिति के जिम्मे राजनीतिक योजना तैयार करना, और दूसरी उपसमिति के जिम्मे साम्प्रदायिक समझौते की रूपरेखा प्रस्तुत करना था। दूसरी उपसमिति कोई विशेष कार्य नहीं कर पायी, और फरवरी में अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गयी। साम्प्रदायिक समस्याओं पर कोई समझौता न होने के कारण राजनीतिक योजना की रूपरेखा भी तैयार नहीं हो सकी। इस अवसर पर हिन्दू नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे प्रतिनिधित्व के किसी ऐसे सिद्धान्त को मानने को तैयार हैं जो सारे देश में सब पर समान रूप से लागू हो, पर शर्त यह है कि निर्वाचक मण्डल संयुक्त होंगे, और विधान मंडलों को छोड़कर किसी दूसरी निर्वाचित संस्था पर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू नहीं होगा।

कोहाट के दंगों को जाँच

एकता सम्मेलन के कुछ दिन बाद कोहाट के दंगों की जांच के लिए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी और मौलाना शौकत अली को नियुक्त किया। दोनों इस काम के लिए कोहाट जाना चाहते थे, पर सरकार ने उन्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी। तब उन्होंने रावलपिंडी में जाकर जांच का काम शुरू किया। तथ्यों के सम्बन्ध में उन दोनों की प्रतिक्रिया काफी भिन्न रही। २६ मार्च सन् १९२५ को अपनी और मौलाना शौकत अली की रिपोर्टों को प्रकाशित करते हुए गांधीजी ने लिखा कि अब तक लोग यह जानते हैं कि वे और अलो-वन्धु बहुत-सी सार्वजनिक बातों में एक राय रखते हैं, अब उन्हें यह भी जानना चाहिए कि एक दूसरे पर पक्षपात का सन्देह किये बगैर और पुराने सौहार्द को बनाये रखते हुए उनका आपस में मतभेद भी हो सकता है।^१

मानपत्र

१६ अप्रैल सन् १९२५ को कलकत्ता कारपोरेशन की ओर से डिप्टी मेयर श्री एच० एस० सोहरावर्दी ने मालवीयजी को मानपत्र पेश किया, जिसमें जनता के "अधिकारों और स्वतंत्रताओं के अनथक समर्थन", तथा उनके "हितों की

१. 'यंग इण्डिया', २६ मार्च, १९२५।

रक्षा" के निमित्त चिन्ता, और राष्ट्र की "अभिवृद्धि और शिक्षा" के निमित्त निरन्तर प्रयत्नों के लिए मालवीयजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गयी। मालवीय जी के इस उपदेश की कि सब भारतीय "पारस्परिक अविश्वास और सन्देह के बगैर भाई-चारे और मैत्री के साथ आपस में मिलकर जीवन बितायें" कृतज्ञता के साथ सराहना की गयी। इस मानपत्र में यह भी कहा गया कि "हम आपके इस "निवेदन" को भी नहीं भूल सकते कि हम सब "अपनी इच्छा" से "देश-हित" के लिए "दुःख भोगें", क्योंकि "सर्वसामान्य पीडा, सामूहिक प्रयत्न से ही हम उस महान् चिरस्थायी शक्ति को पाने की आशा कर सकते हैं जो भारत में बसने वाले विभिन्न सम्प्रदायों को—हिन्दुओं और मुसलमानों को, बुद्धों और जैनों को, सिक्खों और पारसियों को, ईसाइयों और यहूदियों को—एक महान् और शानदार राष्ट्र में बाँध पायेगी।" इस मानपत्र में यह कहते हुए कि "बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के संस्थापक और प्रेरक" के रूप में आपने यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ संकल्पी "निःस्वार्थ कार्यकर्ता" क्या कुछ कर सकता है, आशा व्यक्त की कि "विश्वविद्यालय, आपके निर्देशन में, उस व्यापक उदारता और सार्वभौमिक सहानु-भूति और बन्धुत्व को पुष्ट करेगा जो वेदान्त की मूलभूत शिक्षाएँ हैं, और जिसमें इस देश का ही नहीं, बल्कि सारे ससार का निस्तार निहित है।"

इस अवसर पर लाला लाजपतराय को भी एक मानपत्र दिया गया, जिसमें उनकी बहुत-सी सेवाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि "आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने देशवासियों को उन्नत करने में, उनके विचार विशाल और महान् बनाने में, और उनमें निर्भीकता, बन्धुत्व और स्वाधीनता के उस भाव का संचार करने में महान् कष्ट और यातनाएँ भोगी हैं, जो पराधीन राष्ट्र के उत्थान और उन्नति के लिए न स्वकीय हित की दृष्टि से, वरन् मानव समाज के कल्याण के विचार से परम आवश्यक है।"

दोनों ने कलकत्ता कारपोरेशन के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, कारपोरेशन के मेयर देशबन्धु चित्तरंजन दास की बीमारी पर चिन्ता करते हुए उनके स्वास्थ्य की ईश्वर से प्रार्थना की। मालवीयजी ने कहा : "जैसा स्वराज्य हम चाहते हैं, वैसा तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी साम्राज्य के दूसरे बड़े नगर का शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हो रहा है, यह हर्ष और गौरव की बात है। कारपोरेशन में जिस प्रकार पारस्परिक सहयोग का भाव वर्तमान है, वह भारत के भावी स्वराज्य का द्योतक है।"^१

अली बन्धुओं का रोष

अप्रैल सन् १९२६ में पण्डित मोतीलाल नेहरू ने मौलाना मुहम्मद अली में भेट की। मुहम्मद अली साहब ने महात्मा गांधी, पंडित मोती लाल नेहरू और पंडित जवाहर लाल नेहरू को छोड़कर सब काग्रसी हिन्दू नेताओं को मुसलमानों का शत्रु बताया, और सब प्रमुख खिलाफतवालों को राष्ट्रवादी धोपित किया। मौलाना शीकत अली साहब अपने छोटे भाई मौलाना मुहम्मद अली से भी कहीं अधिक रुष्ट दिखाई देते थे। वे तो महात्मा गांधी और पंडित मोतीलाल नेहरू से भी बहुत नाराज थे, क्यों कि उनके विचार में उन दोनों ने आपस में एक होकर मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया है, और वे दोनों “मुसलमानों की आवाज को दवाने के लिए” सरकार से “वातचीत” कर रहे हैं। मौलाना शीकत अली साहब की धारणा थी कि “उनके हिन्दू दोस्त मुसलमानों से धृणा करते हैं।” मौलाना कहते थे कि “जबतक हिन्दू उनसे शुद्ध चित्त से सम्मान के साथ समझौता नहीं करते, तब तक हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, और यदि वे हम से अलग काम करते हैं और निरादर सहते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है? यदि वे हमसे लड़ने का निश्चय करते हैं, तो हम उनसे इस तरह लड़ेंगे कि वे उसे बहुत समय तक याद रखेंगे।”^१ एक दूसरे पत्र में मौलाना शीकत अली ने डाक्टर सैयद महमूद को लिखा “ब्रिटिश शुरू से ही हमारे शत्रु हैं, उनसे कोई समझौता नहीं हो सकता, हिन्दू हमारे खून के प्यासे हैं, लेकिन अब हमारे अपने आदमी उनका समर्थन कर रहे हैं, यह बहुत ही दुःखदायी है।”^२

खिलाफत कान्फरेंस

जून सन् १९२६ में खिलाफत कान्फरेंस ने हिन्दू महासभा द्वारा आयोजित शुद्धि आन्दोलन का विरोध करते हुए हिन्दुओं को मुसलमान बनाने की नीति का समर्थन किया। मौलाना मुहम्मद अली ने कहा कि वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब गांधीजी को मुसलमान बना लें।^३ कान्फरेंस के अत्यधिक साम्प्रदायिक वातावरण से क्षुब्ध हो मौलाना आजाद और डाक्टर अन्सारी ने उसकी कार्रवाई में भाग नहीं लिया।^४

१. शीकत अली साहब का डाक्टर सैयद महमूद को पत्र, देखिये, ए नेशनलिस्ट मुस्लिम एण्ड इंडियन पालिटिक्स, पृ० ९३।

२. वही, पृ० ९४।

३. कृपालानी : गांधीजी, पृ० १०५।

४. वही।

मौलाना आजाद और पंडित मोती लाल नेहरू का प्रयास

जुलाई सन् १९२६ में मौलाना आजाद और पंडित मोती लाल नेहरू ने 'इंडियन नेशनल यूनियन' के नाम से एक राष्ट्रवादी संस्था गठित करने का विचार किया। इस संस्था की प्रस्तावित घोषणा में बताया गया कि १८ वर्ष या उससे अधिक आयु के वे सब लोग इस संस्था के सदस्य हो सकते हैं जो धार्मिक स्वतन्त्रता तथा दूसरों के विचारों और प्रथाओं के प्रति पूर्ण सहिष्णुता, एवं सम्प्रदायों और व्यक्तियों के सुनिश्चित कानूनी अधिकारों के आधार पर साम्प्रदायिक सम्बन्धों के समन्वय के लिए तैयार हैं। प्रत्येक सदस्य को प्रतिज्ञा करनी होगी कि 'वह सत्यभाव से स्वीकार करता है कि भारत के सब सम्प्रदायों द्वारा सर्वसामान्य सयुक्त राष्ट्रीयता की अनुभूति में, तथा उनके सद्भावपूर्ण सहयोग में ही हिन्दुस्तान की स्थायी समृद्धि और स्वतन्त्रता निहित है, और उसका एकमात्र उद्देश्य सम्पूर्ण राष्ट्र का हित ही होगा।'

सर तेज बहादुर सप्रू, श्री श्रीनिवास शास्त्री, हुकीम अजमल खा, महाराजा साहब महमूदाबाद, डाक्टर अन्सारी, श्रीमती सरोजनी नायडू आदि ने इस विचार का समर्थन किया। मालवीयजी न निमन्त्रित किये गये, और न उन्होंने इस यूनियन के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। दोनों नेताओं के निमन्त्रण पर इतने कम लोग इकट्ठे हुए कि आयोजित कान्फरेस को विचार-विमर्श का रूप देना पड़ा, और योजना के सम्बन्ध में आगे चल कर कोई विशेष काम नहीं हुआ।

लार्ड अर्विन का भाषण

१७ जुलाई सन् १९२६ को लार्ड अर्विन ने चेम्सफोर्ड क्लब में साम्प्रदायिक दंगों पर क्षोभ प्रकट करते हुए और उनके लिए सरकार और उसके कर्मचारियों को निर्दोषी बताते हुए हिन्दू और मुसलमान नेताओं से अनुरोध किया कि वे अपने अपने सम्प्रदाय को सहनशीलता की शिक्षा दें, और इस तरह शान्ति प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करें। अगस्त में केन्द्रीय विधान मण्डल को सम्बोधित करते हुए उन्होंने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को शान्ति बनाये रखने के लिए प्रयत्न करने की अपील की।

मुहम्मद याकूब का प्रस्ताव

कुछ दिन बाद मौलाना मुहम्मद याकूब ने एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से अनुरोध किया कि धार्मिक त्योहारों और उत्सवों पर शान्ति की स्थापना के लिए।

उचित कानूनी व्यवस्था की जाय। हिन्दू सदस्यों ने संशोधन पेश किया जिसमें सरकार से एक सर्वदलीय गोलमेज कान्फरेस बुलाने का अनुरोध किया गया। गृह-सदस्य सर अलेक्जेंडर मुडीमेन ने गोलमेज कान्फरेंस की निरर्थकता पर भाषण करते हुए असेम्बली के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे शान्ति के निमित्त प्रयत्न करें। इसके बाद प्रस्ताव और संशोधन वापस ले लिये गये।

मौलवी मुहम्मद याकूब के इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि पुरानी गलतियों को भुलाकर हम सब प्रतिज्ञा करें कि हममें से प्रत्येक जन-साधारण के सम्पर्क में आयेगा और जनता को न बल उसके अधिकार ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति उसके कर्तव्य भी बतायेगा, उसको कहेगा कि भविष्य में वह गलत काम न करे, सदा ठीक काम करे। यदि हम इन अत्याचारों को गलत समझते हैं तो हमें दृढ़ता से यह बात जनता को बतानी चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि मस्जिद के सामने बाजा बजाने के सम्बन्ध में हमें निष्पक्ष रूप से पुराने स्थानीय रिवाजों का अनुसरण करना चाहिए। गौ-हत्या के सम्बन्ध में उन्होंने हिन्दुओं की भावनाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि यह काम इस तरह किया जाय जिससे निरर्थक हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस न लगे। जो मुसलमान हिन्दुओं के बाजारों और गलियों में गीलों को इस तरह ले जाता है जिससे हिन्दुओं की भावनाओं को चोट पहुँचती है, वह मुसलमान अवश्य ही निन्दनीय और दण्डनीय है। इसी तरह उन्होंने कहा कि वह हिन्दू भी निन्दनीय और दण्डनीय है जो उस मुसलमान से गाय छुड़ा लेने का प्रयत्न करता है जो उसे आपत्तिहीन ढंग पर बूचड़खाने में ले जा रहा है।^१

मुसलमानों के विचार

साम्प्रदायिक तनातनी ने कांग्रेस की शक्ति को तथा राष्ट्र की माँग को बहुत क्षति पहुँचायी। उसने राष्ट्रवादी मुसलमानों की शक्ति और प्रभाव को भी बहुत कम कर दिया। यद्यपि जमैयतुल-उलमा कांग्रेस के साथ रही, पर केन्द्रीय खिलाफत कमेटी ने विल्फुल साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया। मौलाना मुहम्मद अली ने भी कुछ ऐसे वक्तव्य दिये जिनके कारण राष्ट्रवादी शक्तियों से उनका सम्बन्ध भी टूटता चला गया। पर डाक्टर अन्सारी आदि राष्ट्रवादी मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे, और अपने ढंग से राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्न करते रहे।

प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर मुसलमानों में कई मत हो गये। जिन प्रान्तों में मुसलमान अल्पसंख्यक थे, उन प्रान्तों के मुसलमान चाहते थे कि सन् १९१६ के लखनऊ समझौते के अन्दर उन्हें उनकी संख्या के अनुपात से अधिक जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह बना रहे। पंजाब और बंगाल के मुसलमान चाहते थे कि लखनऊ समझौते में तब्दीली हो और उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान दिये जावें। अधिकांश मुस्लिम कार्यकर्ता दोनों बातों का समर्थन करते थे। पर कुछ मुसलमान उन प्रान्तों में जहाँ वे अल्प-संख्यक हैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम करने को तैयार थे। कुछ मुसलमान पृथक् निर्वाचन प्रणाली की बुराईयों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त निर्वाचन का समर्थन करते थे। पर अप्रैल सन् १९२४ में मुस्लिम लीग ने भारी बहुमत से यही निश्चय किया कि पृथक् निर्वाचन प्रणाली जारी रखी जाय, बंगाल और पंजाब में संख्या के अनुपात से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाय, पर जहाँ मुसलमान अल्प-संख्यक हैं, वहाँ सन् १९१६ का समझौता लागू रहे।

श्रद्धानन्द का बलिदान

दिसम्बर सन् १९२६ के अन्तिम सप्ताह में एक मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानन्दजी की, जो उस समय दिल्ली में बीमार थे, हत्या कर दी। इस कुकर्म ने सारे देश में सनसनी पैदा कर दी। सभी हिन्दुओं को, और अधिकांश मुसलमानों को इसका क्षोभ था। जैसे ही इसकी सूचना गांधीजी को मिली, उन्होंने श्रद्धानन्दजी के शौर्य और दृढ़ निष्ठा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि स्वामीजी "सुधारक" और "कर्मण्य" थे। वे "जीवित विश्वास" और "साकार वीरता" थे। वे कभी भी "सकट से नहीं डरते थे"। वे 'एक योद्धा' थे, जो "रोगशय्या के बजाय युद्ध-क्षेत्र में" "मरना पसन्द" करता है।

कांग्रेस का अधिवेशन

उसके दो एक दिन बाद श्रीनिवास ऐयंगर की अध्यक्षता में गोहाटी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इन अधिवेशन ने स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या पर शोक प्रस्ताव पास किया। उसने अपनी कार्य समिति को आदेश दिया कि वह हिन्दू और मुसलमान नेताओं की सलाह से हिन्दू-मुस्लिम मतभेद मिटाने के लिए उचित उपाय करे। श्री श्रीनिवास ऐयंगर ने केन्द्रीय असेम्बली में हिन्दू और मुस्लिम सदस्यों से इस सम्बन्ध में बात की।

मुसलमान विधायकों का निर्णय

२० मार्च सन् १९२७ को कतिपय मुसलमान नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई। उन्होंने मुसलमानों की तरफ से एक तालिका पेश की। वे लोग इन बातों पर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधान कांसिलों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्वीकार करने को तैयार थे कि (१) सिंध को अलग प्रान्त बना दिया जाय, (२) उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा बलूचिस्तान को अन्य प्रान्तों के समान अधिकार दिये जायें, (३) पंजाब तथा बंगाल में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाय, (४) केन्द्रीय विधान मण्डल में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जाय।

इस वक्तव्य के प्रकाशित होने के तुरंत बाद इस गोष्ठी में उपस्थित दो तीन राजजनों ने घोषित किया कि उन्होंने इस समझौते के पक्ष में राय नहीं दी है। कई अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी संयुक्त निर्वाचन के विरुद्ध अपने वक्तव्य प्रकाशित किये, पर मिस्टर जिना ने इन सुझावों को पुष्ट किया और आशा व्यक्त की कि वे एक साथ लागू होंगे।

२३ मार्च को कतिपय हिन्दू विधायकों ने एक बैठक करके निश्चय किया कि (१) भारत की राज विधान सभाओं के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली चालू की जाय, (२) जनसंख्या के अनुपात से हर विधान सभा में अल्प-संख्यकों के लिए स्थान (सीटें) सुरक्षित किये जायें, (३) सविधान द्वारा धार्मिक और लौकिक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय, (४) प्रान्तों की पुनर्व्यवस्था का प्रश्न इस समय खुला छोड़ दिया जाय।

मई सन् १९२७ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुसलमानों के इन सुझावों का यह कहते हुए स्वागत किया कि प्रान्तीय विधान कांसिल की तरह केन्द्रीय विधान सभाओं में भी मुसलमानों के लिए सीटें (स्थान) सुरक्षित कर दी जायें, तथा आपसी समझौते से पुराने समझौते में सुधार किया जाय। उसने कार्यसमिति को आदेश दिया कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों, तथा अन्य राजनीतिक नेताओं के परामर्श से मौलिक अधिकारों के आधार पर वह हिन्दुस्तान के लिए सविधान का मसविदा तैयार करे।

शिमला एकता सम्मेलन

सितम्बर सन् १९२७ में शिमला में मिस्टर मुहम्मद अली जिना की अध्यक्षता में एकता कांग्रेस आयोजित की गयी। इस कांग्रेस में काफी वाद-विवाद के बाद मालवीयजी, डाक्टर मुंजे, प्रिंसिपल दीवानचन्द, सरदार शार्दूल सिंह,

श्री जयराम दास दीलतराम, हुकीम अजमल खाँ, डाक्टर अन्सारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना मुहम्मद अली की कमेटी गठित की गयी। यह कमेटी भी कुछ निश्चय नहीं कर पायी। अन्त में मालवीयजी के अनुरोध पर सबने मिलकर हिंसात्मक कार्रवाइयो को बन्द करने के पक्ष में एक अपील प्रकाशित कर दी। इसमें मतभेदों का समाधान करने के लिए और पारस्परिक सौहार्द की वृद्धि के लिए स्थानीय एकता बोर्डों को स्थापित करने की भी जनता से अपील की गयी।

प्रिंसिपल दीवानचन्द के सस्मरण से पता चलता है कि इस कान्फरेंस में अन्य हिन्दू नेताओं की तुलना में मालवीयजी का रुख कहीं अधिक नरम था। यहाँ तक कि प्रिन्सिपल साहव को, जो यह स्वीकार करते थे कि “राजनीति में मालवीयजी का स्थान बहुत ऊँचा था”, “यह निश्चय नहीं था” कि ‘राजनीति में मालवीयजी स्वभावतः अपने अनुकूल वातावरण में थे।’”

कलकत्ता सम्मेलन

कांग्रेस के अध्यक्ष श्री एस० श्रीनिवास ऐयंगर के प्रयास से २७ अक्टूबर सन् १९२७ को कलकत्ता में दूसरी एकता कान्फरेंस आयोजित हुई। इसमें सर्व श्री एस० श्रीनिवास ऐयंगर, टी० प्रकाशम्, तुलसीचन्द गोस्वामी, प्रफुल्ल चन्द्र राय, जे० एम० सेनगुप्त, मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, डाक्टर अन्सारी, दीनबन्धु सी० एफ० एडरुज आदि ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मालवीयजी और लाला लाजपतराय उपस्थित नहीं थे।

इस सम्मेलन में धर्म-परिवर्तन के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि ‘यह कांफरेंस निश्चय करती है कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह तर्क या अनुनय से दूसरे का धर्मपरिवर्तन कराने या पुनर्धर्म-परिवर्तन कराने को स्वतन्त्र है, पर कोई व्यक्ति या समूह बल, धोखा, या आर्थिक प्रलोभनों की भेट जैसे अनुचित उपायों से ऐसा नहीं करेगा। अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का धर्मपरिवर्तन नहीं कराया जायगा, जबतक कि वह उनके माता, पिता या अभिभावक के साथ न हो। यदि अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अपने माता-पिता या अभिभावक के बिना किसी दूसरे धर्म को मानने वाले से असहाय पाया जाय, तब उसे शीघ्र ही उसके धर्म के माननेवाले व्यक्तियों के सुपुर्द कर दिया जायगा। धर्मपरिवर्तन या पुनर्धर्मपरिवर्तन के बारे में व्यक्ति,

स्थान, या ढंग की कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिए । किसी धर्मपरिवर्तन या पुनर्धर्मपरिवर्तन के सम्बन्ध में कोई प्रदर्शन या आनन्दोत्सव भी नहीं होना चाहिए ।^१

श्री० टी० प्रकाशम् के विरोध की उपेक्षा करते हुए भारी बहुमत में गोवध और मस्जिद के सामने वाजा बजाने के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास हुआ ।^२

दूसरे दिन कलकत्ते में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी इन दोनों प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया ।^३

कांग्रेस का मदरास अविवेक्षण

जब दिसम्बर में गोवध सम्बन्धी प्रस्ताव कांग्रेस की विषय समिति के सामने पेश हुआ, तब देशरत्न राजेन्द्रप्रसादजी ने सोचा कि प्रस्ताव की यह बात कि "मुसलमान आँख बचाकर जहाँ चाहे गोवध कर सकते हैं—हिन्दू जनता कदापि नहीं मानेगी । यदि मुसलमान इस हक्क का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो इसका नतीजा बहुत बड़े पैमाने पर बलवा फ़साद के सिवा दूसरा कुछ न होगा । यह किसी तरह भी देश के लिए हितकर न होगा ।"^४ यह समझ कर उन्होंने इसके सम्बन्ध में गांधीजी से बातचीत की । गांधीजी के कहने पर दूसरे दिन सारे प्रस्ताव पर फिर विचार हुआ, और धर्म-परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव को वैसा ही रख कर जैसा वह पहले था, गोकुशी और वाजा सम्बन्धी प्रस्ताव के बजाय यह सन्तुति की गयी कि "उन अधिकारों की पूर्वधारणा (पूर्वाग्रह) के बिना जिसका हिन्दू और मुसलमान दावा करते हैं—एक जहाँ वह चाहे वाजा बजाने और जुलूस निकालने का, और दूसरा जहाँ चाहे कुर्बानियाँ करने या खाने के लिए गोकुशी का—मुसलमान मुसलमानों से अपील करते हैं कि वे गायों के सम्बन्ध में हिन्दुओं की भावनाओं का जहाँ तक संभव हो लिहाज रखें, और हिन्दू हिन्दुओं से अनुरोध करते हैं कि वे मस्जिद के सामने वाजा बजाने के मामले में मुसलमानों की भावनाओं का यथासम्भव लिहाज रखें, और इसलिए यह कांग्रेस हिन्दू और मुसलमान दोनों से अनुरोध करती है कि गोवध को या मस्जिद के सामने वाजा बजाने को रोकने के लिए हिंसा या न्यायालयों का आश्रय न ले" ।^५

१ इंडियन क्वाटरली रजिस्टर, सन् १९२७, जि० २, पृ० ५३ ।

२ वही, पृ० ५५-५८ ।

३ वही, पृ० २५-३१ ।

४ राजेन्द्र प्रसाद : आत्मकथा, पृ० २७९ ।

५ इंडियन क्वाटरली रजिस्टर, सन् १९२७, जि० २, पृ० ३९८ ।

“कांग्रेस की राय है कि प्रान्तों की ऐसी पुनर्व्यवस्था अब उन प्रान्तों में प्रारम्भ कर देना चाहिए जहाँ भाषा के आधार पर उसके पुनर्गठन की मांग है।

“कांग्रेस की राय है कि आन्ध्र, उत्कल, सिन्ध और कर्नाटक को अलग प्रान्त बना कर यह काम प्रारम्भ किया जा सकता है।

“भात्री सविधान में अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता की गारन्टी दी जायेगी, और किसी केन्द्रीय या प्रान्तीय विधायिका को कोई ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा जो अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करता हो।

“अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता का अर्थ है—विश्वास और आराधना की स्वतन्त्रता, धार्मिक रिवाजों के पानन को और साहचर्य की स्वतन्त्रता, और दूसरों की भावनाओं का उचित आदर करते हुए, और दूसरों के इसी प्रकार के अधिकारों में हस्तक्षेप किये बिना धार्मिक शिक्षा और प्रचार की स्वतन्त्रता।

“अन्तः साम्प्रदायिक मामलों में कोई विधेयक, प्रस्ताव, आवेदन या सशोधन किसी केन्द्रीय या प्रान्तीय विधायिका में प्रस्तावित विचार-विमर्शित, या पारित नहीं किया जायगा, यदि उस विधायिका में उनसे प्रभावित होनेवाले सम्प्रदाय के सदस्यों की तीन चौथाई बहुसंख्या उस विधेयक, प्रस्ताव आवेदन या सशोधन के प्रवेश, विचार-विमर्श या पारित किये जाने के विरुद्ध हो।”^१

इस तरह यह प्रस्ताव अन्तःकरण की स्वतन्त्रता, धार्मिक साहचर्य, शिक्षा-दीक्षा और प्रचार की स्वतन्त्रता, धर्मानुचरण की स्वतन्त्रता, समुक्त निर्वाचन पद्धति, भाषा के आधार पर प्रान्तों का गठन, दूसरों की भावनाओं का यथोचित आदर जैसे लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों पर आधारित था। इसमें पारस्परिक सौहार्द की पुष्टि तथा अल्प-संख्यकों के सन्तोष के लिए कुछ अन्य आवश्यक बातों की भी व्यवस्था थी।

श्रीमती सरोजनी नायडू

इस प्रस्ताव को प्रस्तावित करते हुए श्रीमती सरोजनी नायडू ने बहुत ही भावोत्तेजक ढंग से इसे “संयम और तितिक्षा के मेगनाकार्टी” के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, “यह उस एकता की ओर पहला कदम होगा जो आपको उस स्वतन्त्रता की ओर ले जायगा जिसका आप दावा करते हैं, और जिसके बिना राष्ट्र की हैसियत से आप कहीं कुछ नहीं हैं।”^२ उन्होंने कहा, “परतन्त्रता से निस्तार का धर्म ही भारत का एकमात्र धर्म है”^३

१. इंडियन क्वाटरली रजिस्टर सन्, १९२७, जिल्द २, पृ० ३९७-३९८।

२. वही, पृ० ४०२।

३. वही, पृ० ३९९।

और आशा व्यक्त की कि उसकी सिद्धि के लिए हम अपनी चिरसम्मानित परम्पराओं और अभिरुचियों को तिलाजलि देने को भी तैयार होंगे। उन्होंने अन्त में हिन्दू-मुस्लिम एकता की बुनियाद डालने की अपील की, जो हमारी स्वतन्त्रता की एक मात्र गारंटी है।^१

मौलाना आजाद

मौलाना आजाद ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव हमें सन् १९१६ से कहीं आगे ले जाता है। हम एकता के मार्ग में बड़े रोड़े को यानी पृथक् निर्वाचन पद्धति को दूर कर रहे हैं, और राष्ट्रीय सहति प्राप्त कर रहे हैं।^२ उन्होंने भाषा के आधार पर प्रान्तों के बँटवारे का, तथा सीमा प्रान्त में राजनीतिक सुधारों को लागू करने का समर्थन किया। उन्होंने स्वीकार किया कि गोवध और मस्जिद के सामने बाजा बजाने का “कोई आसान हल नहीं है, पर लड़ने से या न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने से भी काम नहीं चल सकता। इसके लिए तो जरूरी है कि दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे के अधिकारों की घोषणा करें, साम्प्रदायिक झगड़ों को त्याग कर एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। यही इस प्रस्ताव में किया गया है।”^३

पण्डित गौरी शंकर आदि

पण्डित गौरी शंकर मिश्र ने माँग की कि पृथक् निर्वाचन पद्धति के साथ-साथ साम्प्रदायिकता के आधार पर स्थानों के संरक्षण की व्यवस्था भी खत्म की जाय। श्री जगत नारायण लाल ने कहा कि गोवध और बाजे के सम्बन्ध में प्रस्ताव इतना अस्पष्ट है कि उससे झगड़े घटने के बजाय बढ़ जायेंगे। सिंध के श्री चोइथराम ने सिंध को बम्बई प्रान्त से अलग करने का विरोध किया।

पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त और श्री जे० एम० सेनगुप्त ने प्रस्ताव के मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह हिन्दू और मुसलमानों के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि दोनों के दावों का उल्लेख करते हुए दोनों से अनुरोध करता है कि वे अपने दावों पर डटे रहने के बजाय एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, तितिक्षा से काम लें। सरदार गार्हूल सिंह कवीश्वर, श्री सत्यमूर्ति तथा श्री श्रीनिवास ऐयंगर ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

१. वही, पृ० ४००।

२. वही, पृ० ४०२।

३. वही, पृ० ४०२-४०३।

श्रीनिवास ऐयंगर

श्री श्रीनिवास ऐयंगर ने कहा : “कांग्रेस उन दो महापुरुषों की नि सन्देह कृतज्ञ है, जिन्होंने कांग्रेस के इस मद्रास अधिवेशन को स्मरणीय बना दिया है। ये महापुरुष महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कलकत्ता प्रस्ताव से पैदा हुई कठिनाइयों को दूर करना सम्भव कर दिया है।”^१ उन्होंने कहा कि हम इस प्रस्ताव द्वारा “पक्के अत्यधिक साम्प्रदायिकता के युग से पूर्ण राष्ट्रीयता की ओर अपूर्ण राष्ट्रीयता की अस्थायी पगडंडी से होकर प्रकट हो (उभर) रहे हैं”।^२

मालवीयजी

मालवीयजी ने कहा कि मतभेदों को सुलझा कर झगड़ों को मिटाकर स्वराज्य के लिए आगे बढ़ना ही इस प्रस्ताव का लक्ष्य है। इस प्रस्ताव द्वारा पृथक् निर्वाचन की पद्धति खत्म होती है। अच्छा होता यदि विधान मंडलों में स्थानों का रिजर्वेशन भी खत्म हो गया होता। हिन्दू और मुसलमानों को मिलकर एक प्रतिनिधि चुनने को तैयार होना चाहिए। चाहे कोई सदस्य किसी सम्प्रदाय या विरादरी का हो, उसे समझना चाहिए कि उसे देश के हित में काम करना है। सीमा प्रान्त को भी न्यायिक प्रशासन की सुविधा होनी चाहिए। प्रस्ताव में व्यवस्था की गयी है कि यदि जनता के वित्तीय और आर्थिक हित में भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन हो तो होना ही चाहिए। मालवीयजी ने कहा कि मुसलमानों को गोवध बन्द कर देना चाहिए हिन्दुओं को मस्जिद के आगे बाजा नहीं बजाना चाहिए। हिंसा को त्याग कर, न्यायालयों में दौड़-दौड़ कर जाने की आदत छोड़ कर झगड़ों को आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए। मालवीयजी ने कहा कि हमें उस दिन की प्रत्याशा करनी चाहिए, जब हमारे जहाज हमारे आदमियों से चालित हमारा झंडा फहराते हुए हिन्दसागर में चलें। हम चाहते हैं कि हमारी सेना हमारे कमान्डरों और जनरलों से आदेशित और नियंत्रित हो। हमारी लोक-सेवा के ऊँचे पदों पर विदेशी न हो। मालवीयजी ने कहा कि यह तभी संभव है जब सब जाति, विरादरी और सम्प्रदाय के लोग मिल कर काम करें। हिन्दू और मुसलमान एक ईश्वर के बन्दे हैं, एक माता, भारत के बच्चे हैं। ६००० मील से आकर अंग्रेज हम पर शासन करते हैं। यह बहुत लज्जा की बात है। इसे धो डालना हमारा कर्तव्य है। ब्रिटिश सरकार एक दिन हम पर शासन नहीं कर सकती,

यदि हिन्दू, मुसलमान, एंग्लो इंडियन आदि सब मिलकर अनुभव करें कि एक ही परमात्मा और एक ही भारतमाता है। इसी में हम सबका, उन्होंने कहा, कल्याण है।^१

मौलाना मुहम्मद अली

मौलाना मुहम्मद अली ने मालवीयजी के बहुत ही अद्भुत भाषण की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि पंडित मदन मोहन मालवीय अपने इस प्रशंसनीय भाषण के अनुसार काम करें, तो जब अर्ल विन्टरटैन (उपभारत-मंत्री) हम से कहेगा कि वह अल्प-संख्यकों का हिमायती है, तब हम उनसे कहेंगे कि यह ग़लत है, अल्प-संख्यकों के हिमायती तो पंडित मालवीय हैं। मौलाना साहब ने बताया कि मिस्र में पिछ्यानवे प्रतिशत मुसलमान और पांच प्रतिशत ईसाई रहते हैं। जंगलोलपाशा का ईसाइयों के साथ ऐसा सद् व्यवहार रहता है कि जब मिलनर कमीशन मिस्र गया और उसने ईसाइयों से बात करनी चाही तो सबने कह दिया कि जंगलोलपाशा से बातें की जाये। उन्होंने बहुत ही भावावेश में भर कर कहा, “मैं पंडित मालवीय में अपना विश्वास रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि वे मुझे धोखा नहीं देंगे”।^२ क्या ही अच्छा होता यदि दो बड़े नेता इस भावना से अनुप्राणित रहते हुए मिलकर काम कर पाते ?



१. इंडियन क्वाटरली रजिस्टर, १९२७, जि० २, पृ० ४०८-४०९।

२. वही, पृ० ४१०-४११।

१६. भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

१९२४—१९२६

चुनाव

नवम्बर सन् १९२३ में केन्द्रीय और प्रान्तीय कौंसिलों का चुनाव हुआ। अन्य पार्टियों की तुलना में स्वराज्य पार्टी को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई। जबकि लिबरल पार्टी का, जिसने असहयोग के जमाने में सरकार के साथ सहयोग किया था, सफाया हो गया, स्वराज्य पार्टी ने बहुत से प्रान्तों में लगभग पचास प्रतिशत उन निर्वाचित स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली जिन पर किसी वर्ग, सम्प्रदाय या हित के हिन्दुस्तानी खड़े हो सकते थे। मध्य प्रदेश में तो उसने कौंसिल में बहुमत प्राप्त कर लिया। बंगाल में बहुत से मुसलमान निर्वाचकों ने स्वराज्य पार्टी का समर्थन किया, और उमने पृथक् निर्वाचन पर आधृत मुस्लिम स्थानों को जीत लिया। युक्त प्रान्त आदि कई प्रान्तों में कांग्रेस के करीब-करीब सभी कार्यकर्ताओं ने स्वराज्य पार्टी के लिए डट कर काम किया, पर मद्रास, बिहार, गुजरात के अपरिवर्तनवादी तटस्थ रहे, जिसके कारण स्वराज्य पार्टी को पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो पायी। मिसाल के तौर पर बिहार में स्वराज्य पार्टी दस-बारह सदस्य ही चुनवा सकी। सामन्तशाही और साम्प्रदायिक शक्तियों का सरकार से सहयोग बना रहा, और उनकी मदद से मध्य-प्रदेश और किसी हद तक बंगाल को छोड़ कर अन्य सब प्रान्तों में द्विविध शासन आसानी से चालू रखा जा सका।

नेशनलिस्ट पार्टी का गठन

सन् १९२३ में मालवीयजी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से इलाहाबाद-झासी-डिबीजन क्षेत्र से केन्द्रीय असेम्बली का चुनाव लड़कर विजय प्राप्त की। उन्होंने मिस्टर मुहम्मद अली जिना के नेतृत्व में २४ सदस्यों की इंडिपेंडेंट पार्टी गठित की। इस पार्टी ने भी निश्चय किया कि यदि सरकार राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करने से इनकार कर देगी, तो उसके विरुद्ध प्रतिरोध की नीति का अनुसरण किया जायगा। कुछ शर्तों के साथ इस पार्टी ने ४३ सदस्यों की स्वराज्य पार्टी से मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी बनायी। इन दोनों पार्टियों के सहयोग के फलस्वरूप महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों पर सरकारी पक्ष को बहुधा पराजित होना पड़ा। पर यह सहयोग एक वर्ष के बाद टूटने लगा।

सैनिक व्यवस्था

५ फरवरी सन् १९२४ को इंडियन टेरिटोरियल फोर्स और आर्मीलरी फोर्स के एकीकरण के प्रस्ताव पर बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि अब अंग्रेजों को भारत में अपने हिन्दुस्तानी भाइयों के साथ मित्र नागरिकों की तरह रहने की मनोवृत्ति बना लेनी चाहिए। आर्मीलरी फोर्स में केवल अंग्रेजों को भरती करने के नियम की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने पूछा कि जब हिन्दुस्तानी और अंग्रेज जज साथ बैठ कर हाईकोर्ट में मुकदमों का फैसला कर सकते हैं, तो क्या कारण है कि केवल अंग्रेज जज ही आर्मीलरी फोर्स का सदस्य हो सकता है ?^१ उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा का भार, देश के लिए शत्रु से लड़ने का उत्तरदायित्व, हिन्दुस्तानियों को स्वयं वहन करना चाहिए, और इसके लिए एक नागरिक सेना संगठित की जानी चाहिए, तथा सारे देश के स्कूलों में देशभक्ति की शिक्षा स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए।^२ उन्होंने माग की कि एक नागरिक संस्थान (सिटीजन एसोसिएशन) गठित किया जाय, वह हर जिले में जा कर होनहार नौजवानों को चुने, उन्हें आवश्यक सैनिक शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध करे, उन्हें देशभक्ति की भावना से अनुप्राणित करे, और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर “अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन तक अर्पण करने को तैयार करे।”^३ उन्होंने यह भी माग की कि राष्ट्रीय-विभाग का उत्तरदायित्व एक हिन्दुस्तानी को सौंपा जाय, और हिन्दुस्तानियों को सैनिक शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यक सुविधाएँ मुहैया की जायें।^४

सर्वसम्मति से केन्द्रीय असेम्बली ने गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल से सन्तुष्टि की कि क्षीघ्र ही विधान मण्डल के सदस्यों को शामिल करते हुए एक कमेटी नियुक्त की जाय जो आवश्यक जाच के बाद रिपोर्ट करे कि (१) टेरिटोरियल फोर्स को संशोधित और विस्तृत करने के लिए क्या काम किया जाय, ताकि वह स्थायी सेना की रिजर्व सेना की दूसरी पक्ति का काम कर सके, और (२) बताया कि भारत की स्थायी सेना में तथा आर्मीलरी फोर्स की व्यवस्था में से रंगभेद को दूर करने के लिए क्या किया जाय ?

१९ फरवरी सन् १९२५ को एक दूसरे प्रस्ताव पर बोलते हुए मालवीयजी ने भारतीय सेना में उच्चस्तरीय कमीशन के पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय

- १ लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट १, पृ० २४१।
- २ वही, सन् १९२४, पार्ट १, पृ० २४२।
- ३ वही, सन् १९२४, पार्ट १, पृ० २४२।
- ४ वही, सन् १९२४, पार्ट १, पृ० २४२।

अफसरों के समुचित परिशिक्षण के निमित्त उच्चस्तरीय सैनिक कालेज खोलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उच्चस्तरीय सैनिक शिक्षा के लिए बीस-पच्चीस भारतीयों को सैन्डहर्स्ट कालेज में परिशिक्षित करने से काम नहीं चलेगा। आठ दस्तों की योजना से तो सौ वर्ष में भी उच्चस्तर पर भारतीय सेना का भारतीयकरण नहीं हो सकता। सरकार के विरोध के बावजूद ३७ मतों के विरुद्ध ५९ मतों से असेम्बली ने उनके कुछ सशोधनों को स्वीकार करते हुए संस्तुति की कि एक कमेटी गठित की जाय जो रिपोर्ट करे कि उच्चस्तरीय सैनिक शिक्षा के निमित्त भारत में सैनिक कालेज खोलने के लिए तथा शिक्षित भारतीयों को सैनिक जीवन की ओर आकर्षित करने के लिए क्या किया जाय, और यह भारतीय सैनिक कालेज सैन्डहर्स्ट के स्थान पर काम करे, या इसका काम सैन्डहर्स्ट और वूलविच कालेजों द्वारा पूरा किया जाय और बताये कि किस गति से सेना के भारतीयकरण को तेज किया जाये।^१

राजनीतिक माग

८ फरवरी सन् १९२४ को श्री रंगाचारियर ने भावी सविधान के संबंध में एक प्रस्ताव केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्तुत किया। उन्होंने संस्तुति की कि सरकार रायल कमीशन की नियुक्ति द्वारा, या किसी दूसरे ढंग से मौजूदा शासन-व्यवस्था को इस तरह बदलने के लिए ठोस कदम उठाये, जिससे हिन्दुस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत पूर्ण स्वशासित डोमिनियन स्टेट्स और प्रान्तों में प्रान्तीय स्वायत्त शासन प्राप्त हो सके।

इस पर पण्डित मोतीलाल नेहरू ने यह संशोधन उपस्थित किया कि 'हिन्दुस्तान में पूर्ण उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों की गोलमेज कांफरेस बुलाई जाय, जो अल्पमत समुदायों के स्वार्थों और अधिकारों का पूरा ध्यान रखते हुए हिन्दुस्तान के लिए शासन-विधान तैयार करे। यह सविधान नवनिर्वाचित विधान असेम्बली के सामने पेश हो, और उसके द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट क़ानूनी रूप प्रदान करे।'

इस सशोधन पर स्वराज्य पार्टी के नेता ने बहुत ही प्रभावशाली विद्वत्तापूर्ण युक्ति-युक्त भाषण किया, जिसे समाचारपत्रों ने बहुत विस्तार के साथ प्रकाशित किया, और जिसने शिक्षित नवयुवकों को बहुत ही अनुप्राणित किया। इस भाषण में पण्डित मोतीलालजी ने देश में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था तथा सरकार की नीतिरीति की कड़ी आलोचना करते हुए जनता की राजनीतिक भावनाओं

और मागो को बहुत ही उत्तम ढंग से पुष्ट किया। उन्होंने कहा कि असहयोगी होते हुए भी हम सहयोग करने को तैयार हैं, यदि सरकार हमसे सहयोग करना चाहे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन चीजों को हम देश के लिए हितकर समझते हैं उन्हें नष्ट करना हमारा काम नहीं। हम तो बुरी चीजों को नष्ट करना चाहते हैं, और चूँकि हम मौजूदा व्यवस्था को बुरा, दोषपूर्ण, देश के लिए हानिकर समझते हैं इसलिए उसे नष्ट कर नयी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं।

इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मिस्टर मुहम्मद अली जिना और मालवीयजी ने भी जोरदार शब्दों में पण्डित मोतीलाल नेहरू के संशोधन का समर्थन किया। मालवीयजी ने आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को पुष्ट करते हुए कहा कि भारतीयों को स्वयं अपने देश का सविधान बनाने का, तथा अपनी समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिलना चाहिए। सविधान का निर्माण, उन्होंने कहा, सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन के बजाय जनता के प्रतिनिधियों की गोलमेज ही अच्छे तौर पर कर सकती है। इस बात का उत्तर देते हुए कि सन् १९१८ में माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की अवहेलना करते हुए उन्होंने पूर्ण उत्तरदायी व्यवस्था के लिए बीस वर्ष की अवधि निश्चित की थी, मालवीयजी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने जिस गलत तरीके से नये सुधारों को कार्यान्वित किया है, और जिस तरह से गलत नीतियों का अनुसरण करते हुए देश के आर्थिक हितों को क्षति पहुँचायी है, तथा जनता की नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण किया है, उसे देखकर ब्रिटिश शासन का शीघ्र से शीघ्र विलीनीकरण और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना ही उन्हें ठीक जचती है। उन्होंने यह भी कहा कि असैनिक क्षेत्र में पूर्ण उत्तरदायी प्रशासन प्रतिष्ठित करने के बाद भी सेना के भारतीयकरण करने में, तथा सेना की व्यवस्था पर पूरा अधिकार हस्तान्तरित होने में दस पन्द्रह वर्ष लग ही जायेंगे।^१

केन्द्रीय असेम्बली ने भारी बहुमत से अर्थात् ४८ वोटों के विरुद्ध ७६ मतों से संशोधन को पास कर दिया। करीब-करीब सभी निर्वाचित हिन्दुस्तानी सदस्यों ने इस तरह नयी शासन व्यवस्था की माग का समर्थन किया। मनोनीत सदस्यों में श्री एन० एम० जोशी ने संशोधन के पक्ष में, तथा श्री पी० एस० शिवस्वामी अय्यर ने उसके विरोध में अपनी राय दी।

बजट पर बहस

मार्च सन् १९२४ में बजट और वित्त विधेयक पर जोरदार बहस हुई नेशनलिस्ट पार्टी के सदस्यों तथा प्रगतिशील स्वतंत्र सदस्यों ने इटकर २५

की गतिविधि तथा नीतिरीति की आलोचना की, तथा विभिन्न विभागों के सम्बन्ध में राष्ट्रहित की दृष्टि से पुरोगामी नीतियाँ प्रतिपादित और पुष्ट की।

मालवीयजी ने वजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वजट, मुद्रा, विनिमय तथा व्यापार के सम्बन्ध में सरकार की कोई निश्चित सुनियोजित राष्ट्रीय नीति नहीं है। टैक्सों का बोझ बढ़ता जा रहा है। व्यय को कम करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि आन्तरिक शान्ति का सब भार पुलिस और हिन्दुस्तानी सिपाहियों को सौंप कर आन्तरिक सुरक्षा के नाम पर नियुक्त २७००० गोरी पलटनों को हटाकर शांति से सात करोड़ रुपये वार्षिक की वचत की जाय। सेना में उच्चपदों का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए योग्य भारतीय नवयुवकों को इस तरह तैयार किया जाय कि बीस-पच्चीस वर्ष के अन्दर भारतीय सेना का समुचित भारतीयकरण हो गये, बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा का सब भार भारतीय नवयुवक स्वयं वहन कर सकें। रेलवे की नीतिरीति की समीक्षा करते हुए मालवीयजी ने कहा कि जबकि रेलों के निर्माण पर लगभग ८००० करोड़ रुपये भारतीय करदाताओं को किसी न किसी रूप में लगाना पड़े हैं, राजकोष को व्याज या मुनाफे के रूप में उससे कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। इस सारी पुरानी तागत पर रेलों को उचित दर से व्याज राजकोष में अवश्य ही जमा करना चाहिए।^१

विभिन्न विभागों की नीति-रीति के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करने को निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने सीमा शुल्क विभाग, नमक और अफीम विभागों एवं आयकर (इनकम टैक्स) विभाग की मांगों को नामजूर कर दिया, तथा वन विभाग और साधारण प्रशासन की मांगों में सांकेतिक कटीती कर दी।

वित्त विधेयक का विरोध

१७ मार्च सन् १९२४ को पण्डित मोतीलाल नेहरू की सलाह से मालवीयजी ने केन्द्रीय असेम्बली से वित्त विधेयक को नामजूर कर देने की अपील की। प्रान्तीय द्विविध शासन की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हस्तान्तरित विषयों के कार्यवाहक मन्त्रियों की दशा उस घाया जैसी है जिस पर वच्चे की देखभाल-भरण-पोषण का उत्तरदायित्व हो, पर जिसके पास वच्चों को दूध पिलाने के पर्याप्त साधन भी न हों। धन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण, उन्होंने कहा, हस्तान्तरित विभागों में निर्माण कार्य ठीक तौर पर नहीं

हो रहा है। प्रान्तीय प्रशासन की बहुत सी दूसरी त्रुटियों की ओर भी ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि “द्विविधशासन विफल हो गया है”, और उसे शीघ्र से शीघ्र “दफना” कर उसकी जगह पर “अधिक स्वस्थ और निर्दोष व्यवस्था की स्थापना ही “सरकार की मानमर्यादा और उपयोगिता, तथा जनता के कल्याण” के लिए लाभप्रद होगी।^१

केन्द्रीय व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मिश्रित और निकम्मी व्यवस्था किसी दूसरे देश में नहीं पायी जाती, जहाँ सरकार जनता के प्रतिनिधियों के विचारों की उपेक्षा और विधान सभा के निर्णयों की अवहेलना करते हुए अपनी मनमानी कर सकती है। उन्होंने सरकार को अपव्यय का दोषी ठहराते हुए कहा कि फौजी खर्च का भार कम करना नितान्त आवश्यक है। उन्होंने सरकार की कर नीति, शासन नीति तथा गतिविधि की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार को जनता की नागरिक और धार्मिक स्वतन्त्रता अपहरण करने का दोषी ठहराया, और माग की कि सेना विभाग और गृह विभाग कीसिल के भारतीय सदस्यों के सुपुर्द किये जायें। आन्तरिक रक्षा के लिए नियुक्त अंग्रेजी सेना को हटाकर फौजी खर्च घटाया जाय, प्रशासनिक व्यय और नमक कर कम किया जाय, उत्तरदायी स्वशासन की स्थापना के लिए कदम बढ़ाया जाय।^२

भारत-मन्त्री ओलिवियर को, उन्होंने कहा, अच्छे तौर पर समझ लेना चाहिए कि असेम्बली द्वारा पारित सविधान सम्बन्धी सन्तुतियों की उपेक्षा से समस्या का समाधान सम्भव नहीं है, राजनीतिक सहयोग की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए तो जनता की आकांक्षाओं, और उसके प्रतिनिधियों की बातों पर ध्यान देना ही होगा।

अन्त में मालवीयजी ने कहा . “जब तक टैक्सों से प्राप्त धन को खर्च करने में इस देश की जनता के प्रतिनिधियों को वे अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते, जो सप्ताह में प्रत्येक विधान सभा के सदस्यों को प्राप्त हैं, तब तक हम टैक्सों के भार को जारी रखने के पक्ष में अपना नैतिक समर्थन या वोट नहीं दे सकते।” इस बात का उत्तर देते हुए कि यदि वे वित्त विधेयक का समर्थन करने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने बजट में की गयी मांगों का समर्थन क्यों किया, मालवीयजी ने कहा कि उन्होंने कुछ माँगों का विरोध किया और कुछ पर

१ वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० १९१५-१९१६।

२. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० १९१६-१९२०।

चुप रहे, समर्थन किसी का नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य में किसी वित्त विधेयक का समर्थन उस समय तक करने को तैयार नहीं है जब तक सरकार सन् १९१९ की शासन व्यवस्था में उचित परिवर्तन नहीं करती।^१

सरकारी पक्ष की धमकियों की ओर सचेत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार यदि चाहे तो वह सन् १९१९ की व्यवस्था वापस ले सकती है, पर यदि वह सम्य सरकारों की तरह शासन करना चाहती है, तो उस ढोंग के स्थान पर जो उसने रच रखा है उसे वास्तविकता सन्निष्ट करनी होगी।^२

व्यापार मंडल के प्रतिनिधि सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने वित्त विधेयक का समर्थन काफी जोरदार शब्दों में किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय व्यवस्था के बिना किसी सरकार के लिए कोई काम करना संभव नहीं है। आर्थिक मागों को पास कर देने के बाद उसके लिए उचित वित्तीय प्रबंध असेम्बली का नैतिक कर्तव्य है। पंडित मोतीलाल नेहरू ने मालवीयजी की राय का जोरदार शब्दों में समर्थन किया, और आशा व्यक्त की कि सब निर्वाचित सदस्य वित्त विधेयक को नामंजूर करके अपनी राजनीतिक माग को पुष्ट करेंगे।

अन्त में ५७ मतों के विरुद्ध ६० मतों से अर्थात् ३ मतों की अधिकता से असेम्बली ने वित्त विधेयक नामंजूर कर दिया। इस मतदान से यह स्पष्ट था कि यद्यपि साठ प्रतिशत से अधिक निर्वाचित सदस्य सरकार की गतिविधि से इतने क्षुब्ध थे कि वे अपने विश्वास और रोप को व्यक्त करने के लिए वित्त विधेयक नामंजूर करने को तैयार थे, पर कम से कम एक दर्जन निर्वाचित सदस्य, जिन्होंने फरवरी में पंडित मोतीलाल नेहरू के संशोधन का समर्थन किया था, वित्त विधेयक नामंजूर करने को तैयार नहीं थे।

राष्ट्रवादी समाचारपत्रों और शिक्षित नवयुवकों द्वारा वित्त विधेयक के विरुद्ध किये गये मालवीयजी के इस भाषण का लगभग वैसा ही स्वागत हुआ जैसा राष्ट्रीय माग पर किये गये पंडित मोतीलाल नेहरू के भाषण का हुआ था।

ली कमीशन

९ जून सन् १९२४ को मालवीयजी ने सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह संशोधन पेश किया कि ली कमीशन द्वारा प्रस्तुत

१. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० १९२४।

२. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० १९२४।

प्रश्न को गत फरवरी में असेम्बली द्वारा पारित स्वशासन की भाग से अलग नहीं किया जा सकता, और दोनों पर एक साथ ही विचार किया जा सकता है। इस संशोधन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने कहा कि कमीशन की संस्तुतियों से यह पता नहीं चल पाता कि उसे इस बात का भी ध्यान था कि भारत में उत्तरदायी शासन प्रतिष्ठित होनेवाला है, और नयी शासन-व्यवस्था की आवश्यकताएँ आज जैसी नहीं होगी। कमीशन की कार्य-प्रणाली की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि बन्द कमरे में गुप्त रूप से सरकारी अफसरों की गवाही लेना और फिर उन्हें प्रकाशित भी नहीं करना किसी तरह ठीक नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इससे पता ही नहीं चल पाता कि ये गवाहियाँ किस सिद्धान्त पर आधारित थीं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ब्रिटेन में भारतीय सिविल सर्विस की भरती बन्द नहीं होती, तब तक पुरोगामी उत्तरदायी शासन की आशा नहीं की जा सकती। कमीशन की संस्तुतियाँ, उन्होंने कहा, देश की सवैधानिक उन्नति में भारी बाधा पैदा कर सकती हैं, हानिकर सिद्ध हो सकती हैं। इनकी दोषपूर्ण संस्तुतियों को जनता के प्रति-निधि किसी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते।^१

सितम्बर सन् १९२४ में पण्डित मोतीलाल नेहरू ने सारी नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से एक बड़ा लम्बा चौड़ा संशोधन प्रस्तुत किया। मालवीयजी ने इसका समर्थन किया। दोनों ने बहुत ही युक्तियुक्त प्रभावशाली भाषणों द्वारा संशोधन की संस्तुतियों को पुष्ट किया। उन्होंने माग की कि इंग्लैंड में सिविल सर्विस और मेडिकल सर्विस की भरती बन्द कर दी जाय। उन्होंने यह भी माग की कि भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन (लोकसेवा आयोग) स्थापित किया जाय, जिसका संविधान और कार्यक्षेत्र भारत की केन्द्रीय असेम्बली द्वारा निर्वाचित कमेटी की संस्तुतियों पर निश्चित किया जाय। उन्होंने यह भी माग की कि राजकर्मचारियों को भरती करने और कन्ट्रोल करने के सब अधिकार भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दिये जायें, और उनका प्रयोग केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा पारित कानूनों के आधार पर किया जाय। पण्डित मोतीलाल जी का संशोधन जिसमें मालवीयजी का संशोधन भी शामिल था, ४६ मतों के विरुद्ध ६८ मतों से पास हो गया।^२

१. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ४, पृ० २८२४-२८२९।

२. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ५, पृ० ३१४७-३१६४, ३३४६-३३५८।

मुडीमैन कमेटी

२८ फरवरी सन् १९२४ को पंडित मोतीलाल नेहरू के राजनीतिक सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोलते हुए सर मैलकाग हेली ने कहा था कि सरकार मौजूदा शासन-व्यवस्था की प्रक्रियाओं की गतिविधि की जांच कराने को तैयार है। उन्होंने वायदा किया था कि यदि गतिविधि के दोषों की जांच के बाद मौजूदा कानून के अन्तर्गत नियमों में परिवर्तन करके प्रगति की कोई सम्भावना और औचित्य प्रतीत हुआ तो सरकार उसकी संस्तुति करने को भी तैयार है। इसके बाद भारत सरकार ने कानून की प्रक्रिया की जांच के लिए, तथा व्यवस्था की गति-विधि में सुधार की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए एक शासकीय कमेटी नियुक्त की। इसके कुछ समय बाद जुलाई में गृह-सदस्य सर अलेक्जेंडर मुडीमैन को अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसके अधिकांश सदस्य हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञ थे। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट और नियमों के अन्तर्निहित दोषों तथा उसकी प्रक्रिया की कठिनाइयों की जांच करना, तथा उन कठिनाइयों और दोषों को दूर करने के लिए ऐक्ट के ढांचे, नीति और उद्देश्य के अनुरूप सुझाव देना इस कमेटी का काम था।

काफी जांच के बाद कमेटी ने ३ दिसम्बर सन् १९२४ को अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। कमेटी के अधिकांश सदस्यों ने निर्देश की शर्तों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की प्रक्रियाओं को सुधारने के निमित्त ऐक्ट के अन्तर्गत नियमों और कार्यविधि में संशोधन करने के सम्बन्ध में बहुत-सी संस्तुतियाँ कीं। पर सर तेज बहादुर सप्रू, सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर, डाक्टर आर० पी० पराजपेय, और मिस्टर मुहम्मद अली जिना ने अपनी अल्पसंख्यक रिपोर्ट में बहुसंख्यक रिपोर्ट की बहुत-सी संस्तुतियों के औचित्य और महत्त्व को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रस्तावित संशोधनों द्वारा राजनीतिक स्थिति की कठिनाइयाँ दूर नहीं हो सकेंगी। उन्होंने यह भी लिखा कि 'किसी ऐसी वैकल्पिक सांक्रातिक व्यवस्था का आविष्कार भी नहीं किया जा सकता जो प्रशासनिक और राजनीतिक कठिनाइयों का सन्तोषपूर्वक समाधान कर सके'। उन्होंने निवेदन किया कि उनके विचार में प्रशासन में स्थायित्व को, तथा जनता के स्वेच्छिक सहयोग को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि स्वचालित विकास के प्रयत्नों के साथ संविधान को स्थायी आधार पर स्थापित किया जाय, और इस समस्या पर विचार करने के लिए रायल कमीशन या कोई दूसरी एजेंसी नियुक्त की जाय।

राष्ट्रीय माग

७ दिसम्बर सन् १९२५ को गृह-सदस्य रार अलकजेंडर मुडीमैन ने केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि यह असेम्बली गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को संस्तुति करती है कि वे 'सुधार जाच कमेटी' की बहुसंख्यक रिपोर्ट में 'निहित सिद्धान्त' को स्वीकार करें, और 'राज्य व्यवस्था में सुधार के लिए की गयी उनकी विस्तृत संस्तुतियों पर विचार करें।'

पण्डित मोतीलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव पर एक सशोधन पेश किया। इसमें माग की गयी कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की संवैधानिक व्यवस्था में उन मूलभूत परिवर्तनों की घोषणा करे जिनसे देश में उत्तरदायी शासन स्थापित हो सके। इस सशोधन में यह भी संस्तुति की गयी कि सरकार सब भारतीयों, यूरोपियनों और एंग्लो-इण्डियनों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली गोलमेज कांफरेन्स या अन्य उपयुक्त एजेंसी गठित करे जो इन सिद्धान्तों के आधार पर अल्पसंख्यकों के हितों को मान्यता प्रदान करते हुए शासन-व्यवस्था को योजना तैयार करे, जिसे केन्द्रीय असेम्बली के सामने स्वीकारार्थ पेश किया जाय, और उसकी स्वीकृति के बाद पार्लियामेंट को संवैधानिक कानून में उसे समाविष्ट करने को भेजा जाय। संशोधन में जिन मूलभूत सिद्धान्तों को घोषणा की माग की गयी, वे थे—(१) भारत के राजस्व और उसकी राजकीय सम्पत्ति पर सब अधिकार भारतमन्त्री से गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को हस्तान्तरित किये जायें, (२) सैनिक सेवाएँ, राजनीतिक और वैदेशिक विषय एवं पुराने कर्ज और भार की अदायगी के प्रश्नों को छोड़कर जिनकी व्यवस्था भारत-मन्त्री के अधीन होगी, बाकी सब कामों के प्रबन्ध और व्यय के लिए गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल केन्द्रीय विधान मण्डल को उत्तरदायी होगी, (३) भारत-मन्त्री की कौंसिल खत्म कर दी जायगी, और उसका पद स्वशासित उपनिवेशों के मन्त्री के रादृश बना दिया जायगा, (४) भारतीय सेना का भारतीयकरण होगा, और सब प्रकार की सैनिक सेवाओं के लिए भारतीय भरती किये जायेंगे, तथा सेना के प्रबन्ध में सेनाध्यक्ष की सहायता करने के लिए विधान-मण्डल को उत्तरदायी मन्त्री नियुक्त किया जायगा, (५) निश्चित समय के लिए सेना तथा राजनीतिक और वैदेशिक विषयों के प्रबन्ध पर गवर्नर-जनरल के विशेष साक्रान्तिक, सरक्षित और अवशिष्ट अधिकारों को छोड़कर सब शासनिक विभागों का संचालन जनता द्वारा निर्वाचित विधान सभा को उत्तरदायी होगा, (६) प्रान्तों में द्विविध शासन-व्यवस्था खत्म करके अन्त-प्रान्तीय और अखिल भारतीय

विषयो पर केन्द्रीय सरकार के साधारण और अवशिष्ट अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रान्तों में ऐकिक तथा स्वाधीन उत्तरदायी सरकार स्थापित की जायेगी, (७) कुछ निश्चित समय के बाद भारतीय विधानमण्डल को भारतीय संविधान में यथावश्यक संशोधन करने का पूरा अधिकार होगा।^१

पंडित मोतीलाल नेहरू ने प्रभावशाली ढंग से 'सुधार जाच कमेटी' की अधिसंख्यक रिपोर्ट तथा प्रान्तीय और केन्द्रीय शासन-व्यवस्था की त्रुटियों की आलोचना करते हुए संशोधन में निहित मागों को पुष्ट किया। उन्होंने कहा कि अब जब कि सरकार ने मौजूदा संविधान के निहित दोषों को करीब-करीब स्वीकार ही कर लिया है, इस सदन के लिए एक ऐसे उचित संविधान की माग करना जिसमें सब अधिकारों और हितों की रक्षा हो अवश्य ही बुद्धि-संगत है। आत्मनिर्णय ही, उन्होंने कहा, नये संविधान का आधार हो सकता है। देशबन्धु चित्तरंजनदास के फरीदपुर भाषण के कुछ अंशों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार हृदय परिवर्तन के लिए तैयार हो, तो सहयोग की प्रक्रिया प्रशस्त हो सकती है।^२

सुधार जाच कमेटी के सदस्य सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर ने कहा कि अधिसंख्यक रिपोर्ट की सभी संस्तुतियाँ अच्छी हैं, और उनका कार्यान्वयन लाभप्रद होगा, पर उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। संशोधन की मागों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि वे सब की सब लिबरल पार्टियों ही की मागें हैं। सहयोग की कमी, उन्होंने कहा, क्षमता की कमी का द्योतक नहीं है।^३

सुधार जाच कमेटी के दूसरे सदस्य जिना साहब ने बड़े रोषभरे शब्दों में लार्ड वर्केंहेड और सरकारी प्रवक्ताओं के विचारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सहयोग की कमी की दुहाई देकर राजनीतिक प्रगति में अड़चन डालना ग़लत है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार चाहती है कि आज़ादी हासिल करने के लिए हिन्दुस्तान आयरलैंड जैसी क्रान्तिकारी परिस्थिति पैदा करे। अन्त में उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान ने आज़ादी हासिल करना तय कर लिया है। या तो आप (सरकार) उचित भावना से उसका ढग, समय और परिमाण निश्चित करें, वरना वह स्वयं अपने लिए उन्हें निर्धारित कर लेगा।^४

१. वही, सन् १९२५, जि० ६, पार्ट २, पृ० ८५४-८५५।

२. वही, सन् १९२५, जि० ६, पार्ट २, पृ० ८५५-८६७।

३. वही, सन् १९२५, जि० ६, पार्ट २, पृ० ८७२-८७६।

४. वही, सन् १९२५, जि० ६, पार्ट २, पृ० ९३८-९४४।

अन्त में मालवीयजी ने बहुत ही आकर्षक ढंग से आपत्तिहीन सयत भाषा में सशोधन के विरोधियों की आलोचनाओं का उत्तर देते हुए उसका समर्थन किया। उन्होंने सरकारी पक्ष की इस बात को स्वीकार किया कि पिछले साठ वर्षों में देश ने उन्नति की है, पर कहा कि यदि देश स्वतंत्र होता, तो अधिक प्रगति कर पाता। उन्होंने सर मुहम्मद शफी के वक्तव्य को उद्धृत करते हुए कहा कि अधिसंख्यक रिपोर्ट तो वास्तव में अल्पसंख्यक रिपोर्ट है, क्योंकि शफी साहब, जिन्होंने इस अधिसंख्यक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये हैं, स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उसकी सस्तुतियों द्वारा दशा में कुछ सुधार हो सकता है, पर अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रस्तावित जाच ही भारतीय राजनीतिज्ञों को सन्तुष्ट कर पायेगी। उन्होंने भूतपूर्व भारत-मन्त्री लार्ड ओलिवियर के भाषण का उद्धरण देते हुए आशा व्यक्त की कि भारत-मन्त्री लार्ड बर्केनहेड उनके विचारों पर ध्यान देकर अल्पसंख्यक रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति स्वीकार करेंगे। मालवीय जी ने कहा कि लार्ड बर्केनहेड की यह बात कि “हिन्दुस्तान को व्यक्तिगत सत्ता (individual entity) बताना इतना ही निरर्थक है जितना यूरोप को व्यक्तिगत सत्ता (entity) बताना” बिल्कुल ही बेतुकी है, क्योंकि जबकि यूरोप बहुत से राज्यों में बंटा है जो आपस में बराबर युद्ध करते रहते हैं, हिन्दुस्तान की राजनीतिक सत्ता निर्विवाद है। मिस्टर कोक की शका का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिक को राय में, जिसने इस विषय पर विचार किया है, वे लोग जो एक देश में रहते हैं, जो एक प्रभुसत्ता की प्रजा हैं, जो एक शासन-व्यवस्था से शासित हैं, जो एक विधि-शृंखला से, जो उन सब को समान रूप से प्रभावित करती है, वधे हैं एक राष्ट्र बनाते हैं, चाहे वे धर्मों और मतों में किसी तरह भी विभाजित हों।^१ इस बात को स्वीकार करते हुए कि कतिपय बातों में हिन्दुओं और मुसलमानों में भारी मतभेद है, मालवीयजी ने कहा कि यदि सन् १९१६ में हिन्दू-मुस्लिम समझौता हो सकता था, तो वह अब भी हो सकता है। सरकार हमारी सर्वसम्मत प्रस्तुत माग स्वीकार करे, उस पर अमल करना शुरू करे, बाकी राजनीतिक प्रश्न भी पारस्परिक परामर्श और समझौता द्वारा तय कर लिये जायेंगे। असहयोग की मनोभावना का मूल कारण, उन्होंने कहा, जनता की यह धारणा है कि सरकार उनपर विश्वास नहीं करती, उनकी बात नहीं सुनती। सहयोग की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सरकार को अपनी मनोवृत्ति बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि

१. वही, सन् १९२५, जि० ६, पार्ट २, पृ० ९९६-९९७।

जब सरकार भी स्वीकार करती है कि द्विविध-शासन सफल हुआ यह नहीं कहा जा सकता, तब उसे शालीनता से दफना क्यों न दिया जाय ? उन्होंने कहा कि केन्द्रीय असेम्बली पार्लियामेंट के अधिकार को चुनौती नहीं देती, वह तो शान्ति और युद्ध के प्रश्न पर उसका अधिकार स्वीकार करती है। वह कई विषय निश्चित समय के लिए पार्लियामेंट को उत्तरदायी भारत-मन्त्री को सौंपने को तैयार है। वह तो केवल यह चाहती है कि देश के आन्तरिक प्रशासन के लिए वे व्यक्ति भारत की कार्यपरिपद् के सदस्य नियुक्त किये जायें जिन्हें जनता के प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त हो, और वे असेम्बली को अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हो।^१ उन्होंने कहा कि यदि सरकार रायल कमीशन नियुक्त करना चाहती है तो कर सकती है। पर वह कमीशन ऐसा होना चाहिए जिसमें जनमत के सब प्रमुख रंगों के विश्वसनीय प्रतिनिधि शामिल हो, ताकि उसे सम्पूर्ण जनता का विश्वास प्राप्त हो।^२

सर अलेक्जेंडर मुडीमैन ने मालवीयजी के इस भाषण की प्रशंसा की, पर उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर भी मोतीलालजी का संशोधन भारी बहुमत से स्वीकार हो गया। सभी निर्वाचित हिन्दुस्तानी सदस्यों ने, जो वहा उस समय उपस्थित थे, उसके पक्ष में अपना मत दिया। मनोनीत गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों में सर्वश्री शिवस्वामी अय्यर, एन० एम० जोशी, डाक्टर एस० के० दत्त प्रभृति सज्जनों ने संशोधन के पक्ष में राय दी। नवाब सर अब्दुल क़यूम जैसे दो चार गैर-सरकारी मनोनीत भारतीयों ने ही संशोधन के विरोध में राय दी। सरकारी अफसरों के अतिरिक्त यूरोपियनों के प्रतिनिधियों और अंग्रेज मनोनीत सदस्यों का समर्थन ही संशोधन के विरुद्ध सरकार को प्राप्त हो सका।

मानव स्वतंत्रता की पुष्टि

मानव-स्वतंत्रताओं का संरक्षण और समुचित आदर मालवीयजी सभ्य शासन का पुनीत कर्तव्य समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपने भाषणों में सरकार की दमननीति की आलोचना करते हुए बार-बार माग की कि सब दमनकारी क़ानून वापस लिये जायें। साधारण क़ानूनों द्वारा ही विधिवत् राजनीतिक अपराधों की भी जांच की जाय। तथाकथित राजनीतिक अपराधी छोड़ दिये जायें। वरना उन पर बाक़ायदा मुक़दमा चलाया जाय, उन्हें अपने को निर्दोष

१. वही, सन् १९२५, जि० ६ पार्ट, २ पृ० ९९९।

२. वही, सन् १९२५, जि० ६ पार्ट, २ पृ० १००१।

सिद्ध करने का मौका दिया जाय। उन्होंने यह भी माग की कि जनता की मौलिक, नागरिक, और धार्मिक स्वतंत्रताओं को पुष्ट किया जाय, और दमनकारी तरीकों से उनका अपहरण कर आतंक और अत्याचार की स्थिति पैदा न की जाय। उन्होंने सरदार खडगसिंह की रिहाई के प्रस्ताव का समर्थन किया,^१ और सरकार की भर्त्सना करते हुए माग की कि श्री बी० जी० हारनीमैन का निष्कासन रद्द किया जाय^२, और कहा की कि मौलाना हसरत मुहानी पर लगाया गया आरोप वापस लिया जाय, वरना उन पर विधिवत् मुकदमा चलाया जाय। उन्होंने यह भी माग की कि तुर्की को जानेवाले खिलाफत के शिष्टमण्डल के सदस्यों को विधिवत् पासपोर्ट दिये जायें, और उन्हें वहां जाने से न रोका जाय। जाबता फौजदारी की दफा १४४ द्वारा नागरिकों की शान्तिपूर्ण गतिविधि पर प्रतिबन्ध लगाने की शासनिक प्रवृत्ति की निन्दा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं छ बार दफा १४४ पर आधृत आज्ञा की अवहेलना करते हुए भाषण किये हैं, पर एक बार भी कभी उसके कारण शान्ति भंग नहीं हुई।

मालवीयजी ने कहा कि दफा १४४ के जरिये सिक्खों की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाना, और उसकी अवहेलना करने पर उन्हें आहत करना, बुरी तरह मारना पीटना सर्वथा अन्याय है। सिक्खों पर किये जानेवाले अत्याचारों की बार-बार भर्त्सना करते हुए मालवीयजी ने माग की कि सिक्खों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाय, उनकी मार्गें स्वीकार की जाये, उनके साथ मानवोचित व्यवहार किया जाय, सिक्ख कैदियों के साथ न्याय हो, और उन्हें छोड़ दिया जाय।^३

मालवीयजी केन्द्रीय असेम्बली में महाराजा नाभा के प्रश्न पर भी सरकार की आलोचना करना चाहते थे। पर असेम्बली के अध्यक्ष ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। पर पंजाब हिन्दू सभा के अधिवेशन में उन्होंने नाभा की स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा - "अगर फुलकियो की रियासतों के एक बड़े राजा को गद्दी से उतारे जाने पर सिक्खों को रंज हो, तो किसी इसानी या ईश्वरीय नियम से सिक्खों का ऐसा अनुभव अनुचित नहीं कहा जा सकता"।^४ उनके वाक्यों पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाना और इसके लिए उन्हें

१. वही, सन् १९२४, जि० ४ पार्ट, २ पृ० ९९४-१०००।

२. वही, सन् १९२४, जि० ४ पार्ट, २ पृ० ८०२-८०३।

३. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० १९४१-१९४२।

४. सीता राम चतुर्वेदी : महामना पंडित मदनमोहन मालवीय, खंड २. पृ० ११५।

मारना पीटना सर्वथा अनुचित है। सिक्खों द्वारा ग्रंथ साहब के शान्तिमय पाठ पर रोक लगाने का, मालवीयजी ने कहा, सरकार को कोई न्यायोचित अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन सिक्खों ने सख्त कष्ट सहते हुए भी अपना हाथ नहीं उठाया, उनपर "गोली चला देना किसी भी राज्य के लिए लज्जा और शर्म की बात है।"^१ सरकार को समझना चाहिए कि जिसके पास जितनी ही अधिक ताकत हो, उतनी ही अधिक उसकी जिम्मेदारी होती है।^२ सिक्खों की समस्या का न्यायोचित समाधान निश्चय ही सरकार का कर्तव्य है।

सितम्बर सन् १९२५ में मालवीयजी ने सिक्खों द्वारा स्वीकृत सिक्ख गुरु द्वारा (सप्लीमेंटरी) बिल का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि सिक्ख बन्दी बिना किसी शर्त के छोड़ दिये जायें।^३

लोक न्याय की पुष्टि

लोक न्याय की पुष्टि तथा मानव-स्वतंत्रताओं के संरक्षण के निमित्त मालवीयजी ने श्री विठ्ठल भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत 'स्पेशल लाज् रिपील बिल' का^४, तथा सर हरिसिंह गौड द्वारा प्रस्तुत 'क्रिमिनल ला (अमेंडमेंट) ऐक्ट सन् १९०८' की बहुत सी धाराओं को रद्द करने का समर्थन किया। उन्होंने काफी विस्तार के साथ इस कानून के दुरुपयोग की चर्चा करते हुए कहा कि जब वह अधिनियम जो "डकैतो और अराजकतावादियों" और क्रान्तिकारियों के नियंत्रण के लिए बनाया गया था, "उन लोगों को दण्डित करने और उनकी अन्त-रात्मा (स्फिरिट) को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्होंने अपराध नहीं किया," तब यह स्पष्ट है कि उसका "सावधानी, मर्यादा और ईमानदारी से प्रयोग नहीं हो रहा है," और उसे रद्द कर देना ज़रूरी है।^५ सरकार के विरोध के बावजूद ये दोनों विधेयक बहुमत से पास हो गये।

सितम्बर १९२४ में मालवीयजी ने बंगाल आर्डिनेन्स १९२४ के विरोध में प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया। मार्च सन् १९२५ में उन्होंने 'बंगाल क्रिमिनल

१. वही, पृ० ११५।

२. वही, पृ० ११५।

३. लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स, सन् १९२५, जि० ६, पार्ट १, पृ० ५३४-५३५।

४. वही, सन् १९२५, जि० ५, पार्ट १, पृ० ९२४-९३३।

५. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ५, पृ० ३५३५-३५३९।

संशोधन (सप्लीमेंटरी) बिल' का विरोध किया, और जब असेम्बली द्वारा उसके रद्द किये जाने पर गवर्नर-जनरल ने उसे पास करने की संस्तुति की, तब मालवीय जी ने काफी कड़े शब्दों में सरकार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संस्तुति अवश्य ही "अवैधानिक" है, यद्यपि भारत की व्यवस्था इसकी इजाजत देती है। इस तरीके से उस विधेयक को पास कराने का प्रयत्न, जिसे जनता के प्रतिनिधियों ने असेम्बली में रद्द कर दिया हो, "भारत के जनमत का घोर अपमान" है, और भारत की "संवैधानिक अवस्था को नग्नरूप में खोल कर रख देता है।" विधेयक की कड़ी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वह अनावश्यक है। जिन ९६ व्यक्तियों को बंगाल अध्यादेश के अन्दर गिरफ्तार करके नजरबन्द किया गया है, उनमें से किसी एक के विरुद्ध भी मुकदमा चला कर "किसी न्यायालय में उनका अपराध सिद्ध नहीं किया गया है।" इस प्रकार के "अध्यादेश को पांच वर्ष तक चालू रखना निन्दनीय है"।^१

सीमाशुल्क नीति

मार्च १९२४ में बजट पर भाषण करते हुए मालवीयजी ने राष्ट्रहित की दृष्टि से मुद्रानीति को निर्धारित करने की, सूती कपड़ों पर उत्पादन शुल्क को खत्म करने की, तथा आयात शुल्क द्वारा भारतीय उद्योगों को वित्तीय संरक्षण प्रदान करने की माग की। इन मागों को वे समय-समय पर दोहराते रहे, और उनको पुष्ट करनेवाले प्रस्तावों का समर्थन करते रहे। सितम्बर सन् १९२४ में उन्होंने श्री कस्तूर भाई लाल भाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माग की कि सूती कपड़ों पर उत्पादन शुल्क (एक्साइज् ड्यूटी) खत्म की जाय।^२

फौलाद संरक्षक विधेयक

जब सन् १९२४ में सरकार ने फौलाद संरक्षक विधेयक असेम्बली में प्रस्तुत किया, तब मालवीयजी ने किसी अंश में उसका स्वागत किया। दूसरे भारतीय सदस्यों की तरह उन्हें भी इस बात की खुशी थी कि सरकार ने आखिर भारत के बहुत बड़े उद्योग को आयात-शुल्क द्वारा वित्तीय संरक्षण देने का निश्चय किया। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि सरकार आयात-शुल्क से प्राप्त धन के एक अंश को वदान्यता (वाउन्टी) के रूप में टाटा तथा दूसरे फौलाद के

१. वही, सन् १९२५, जि० ५, पार्ट ३, पृ० २८७५-२८७७।

२. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ५, पृ० ४०७२-४०७६।

भारतीय देशज उद्योगों को देना चाहती है। पर प्रस्तुत विधेयक में नये विदेशी कारखानों को भी वदान्यता (वाउन्टी) दिये जाने की व्यवस्था थी। यह बात मालवीयजी तथा बहुत से दूसरे भारतीय सदस्यों को ठीक नहीं लगती थी। इसलिए विधेयक के इस अंश का उन्होंने डट कर विरोध किया, और मांग की कि विधेयक के इस अंश को निकाल दिया जाय। मालवीयजी को भय था कि बहुत से विदेशी व्यापारी वित्तीय संरक्षण से लाभ उठाकर यहाँ अपना औद्योगिक आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। उनका कहना था कि यथावश्यक विदेशी पूंजी का प्रयोग एक बात है, और देश के औद्योगिक जीवन को विदेशी पूंजी-पतियों के हाथ में सौंप देना दूसरी बात है। जहाँ किसी स्थिति में पहली चीज अनिवार्य और लाभप्रद है, वहाँ दूसरी चीज सर्वथा हानिकर और भयावह है। उनका यह भी कहना था कि देशज उद्योगों की उन्नति के लिए जनता को कुछ आर्थिक कष्ट सहने के लिए प्रेरित और बाध्य किया जा सकता है, पर विदेशियों के व्यापार की अभिवृद्धि के लिए भारतीय जनता को कष्ट सहने के लिए बाध्य करना अन्याय होगा। किसी सम्य देश में ऐसा नहीं होता, और यहाँ भी ऐसा करना अवश्य ही अनुचित होगा।^१ उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसे देश को नहीं जानता जिसमें "साधारण कर-दाताओं पर कर लगाया गया हो, और करों के द्वारा वदान्यता (वाउन्टी) दी गयी हो, केवल देशज उद्योगों को ही नहीं बल्कि उन उद्योगों को भी जो देशज न हो और सम्पूर्णतः विदेशी हो।"^२ अधिकांश निर्वाचित भारतीय सदस्य मालवीयजी की बात से सहमत थे, पर सरकार मालवीयजी की बात मानने को तैयार नहीं थी।

मालवीयजी स्वयं श्रमिक वर्ग के नेता श्री एन० एम० जोशी की इस बात को स्वीकार करते थे कि उद्योगों के संरक्षण के साथ मजदूरों की न्यायसंगत मांगों का भी संरक्षण होना चाहिए। इस सम्बन्ध में उनका कहना था कि जब कोई कम्पनी केन्द्रीय असेम्बली से संरक्षण मांगने आती है, तब असेम्बली का, जो जनता का, न केवल पूंजीपतियों का, प्रतिनिधित्व करती है, अधिकार है कि वह इस आश्वासन का आग्रह करे कि मजदूरों की युक्तिसंगत उचित शिकायतों पर विचार किया जायगा, तथा जहाँ आवश्यक होगा वहाँ उन्हें दूर किया जायगा।^३

१. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० २३२०-२३२४।

२. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० २३२८।

३. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० २३२३।

साराण, जबकि निर्वाचित सदस्य कुछ संशोधनो के साथ विधेयक को पास करना चाहते थे, सरकार को वे संशोधन स्वीकार नहीं थे। सरकार ने विधेयक को वापस लेने की धमकी दी। गतिरोध को दूर करना आवश्यक समझ पड़ित मोतीलाल नेहरू ने दोनों पक्षों को समझौता करने की सलाह दी, और उनके माध्यम से सरकार और जनता के कतिपय प्रमुख प्रतिनिधियों में समझौता हो गया। इसके आधार पर पण्डित मोतीलालजी ने संशोधन प्रस्तुत किया कि नयी कम्पनियों को भी गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल द्वारा वदान्यता (वाउन्टी) दी जा सकती है, वशर्ते कि (१) वह इंडियन कम्पनी ऐक्ट, १९१३ के अन्दर बनी और पजीकृत हुई हो, (२) उसके शेयर कैपिटल की धनराशि कम्पनी के परिपत्र में रुपये में व्यक्त की गयी हो, (३) डाइरेक्टरो का एक अंश, जिसे सरकार निर्धारित करे, भारतीय हो, (४) वह माल तैयार करने की (मैनूफैक्चरिंग) प्रक्रिया में भारतीयों को शिल्प वैज्ञानिक (प्राविधिक) प्रशिक्षण की सुविधाएँ मुहैया करे।

मालवीयजी को यह संशोधन स्वीकार था, और उनकी अनुमति से असेम्बली ने इसे स्वीकार कर लिया। पर चूँकि मालवीयजी इससे पूरे तौर पर संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने यह संशोधन भी प्रस्तुत किया कि असेम्बली की सहमति से ही नयी कम्पनियों को वदान्यता (वाउन्टी) दी जा सकेगी।^१ अर्थ-सदस्य मिस्टर ब्लेकेट ने मालवीयजी के तर्क का उत्तर न देते हुए उनकी वाक्पटुता का तिरस्कार करते हुए उनके इस संशोधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। असेम्बली ने भी इसे नामजूर कर दिया।

इस पर अन्तिम बार बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि वह न इसका विरोध कर सकते हैं और न समर्थन। उन्होंने कहा कि वह इसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इसने विदेशी पूँजी की मात्रा पर जो इस देश में आ सकेगी, कोई सीमा नहीं निश्चित की है, और असेम्बली की स्वोक्तित्व के लिए इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने को सरकार को बाध्य नहीं किया है, वह इसका विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय फौलाद उद्योग को यह संरक्षण मुहैया करता है, और क्योंकि नयी कम्पनियों की वाउन्टी (वदान्यता) का प्रश्न असेम्बली के सामने पेश करना सरकार के लिए सम्भव है।^२

विधेयक को मोतीलालजी के संशोधन सहित असेम्बली ने पास कर दिया।

१. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० २६६७।

२. वही, सन् १९२४, जि० ४, पार्ट ३, पृ० २७२९।

मुद्रा और विनिमय कमीशन

जनवरी सन् १९२५ में श्री वंकटपति राजू ने प्रस्ताव किया कि विनिमय और मुद्रा के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने को, और उनके संबंध में संस्तुति करने को शीघ्र ही एक ऐसी कमेटी नियुक्त की जाय जिसका अध्यक्ष एक भारतीय हो, और जिसके अधिकांश सदस्य भी भारतीय हों। मालवीयजी ने इसका समर्थन करते हुए बहुत ही मधुर भाषा में सरकार से इसकी वांछ मानने का अनुरोध किया।^१ पर सरकार ने इस प्रश्न पर जांच करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव को ठर्ते मानने से इनकार कर दिया। सरकार के विरोध के बावजूद ३८ वोटों के मुकाबले में ५२ वोटों से प्रस्ताव पास हो गया।

अगस्त सन् १९२५ में सम्राट् ने मुद्रा और विनिमय कमीशन नियुक्त किया। इसके ६ सदस्य अंग्रेज और चार भारतीय थे। इसका अध्यक्ष भी एक अंग्रेज ही था। जिना साहब ने २० अगस्त को इस पर विचार करने के लिए 'काम रोको प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। भारतीय सदस्यों ने कमीशन की बनावट पर आपत्ति की। सरकारी प्रवक्ताओं ने जोश में भरकर कहा कि इस प्रकार के प्रश्न की जांच के लिए निष्पक्ष और क्षमता-सम्पन्न व्यक्ति ही नियुक्त किये जा सकते हैं। इस पर कुछ गैर-सरकारी सदस्यों ने कमीशन के कतिपय सदस्यों की क्षमता और निष्पक्षता पर भी टीका टिप्पणी कर दी। इससे तनाव और कटुता बढ़ गयी। मालवीयजी ने कमीशन के किसी सदस्य के व्यक्तित्व पर छोटाकगी को अनुचित बताते हुए सरकार से अनुरोध किया कि वह कमीशन में तीन हिन्दुस्तानी सदस्यों को और नियुक्त करने की सिफारिश करे।^२ पर सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। इस पर सरकार के विरोध के बावजूद ४५ वोटों के मुकाबले में ६५ वोटों से प्रस्ताव पास हो गया। सभी प्रगतिशील निर्वाचित भारतीय सदस्यों के साथ-साथ मनोनीत सदस्यों में डाक्टर एस० के० दत्त, श्री एन० एम० जोशी, सर शिवस्वामी अय्यर, तथा श्री चिम्मन लाल सीतलवाद ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मत दिये।

वजट पर बहस

मार्च सन् १९२५ में स्वराज्य पार्टी और इंडिपेंडेंट पार्टी में खिचाव पैदा हो गया। वे सब बातों में एक राय नहीं हो सके, जिसके कारण कई मामलों में राष्ट्रीय पक्ष को पराजय का सामना करना पड़ा। स्वराज्य पार्टी के सदस्यों

१. वही, सन् १९२५ जि० ५, पार्ट १, पृ० १८५-१८८।

२. वही, सन् १९२५ जि० ६, पार्ट १, पृ० १८९-१९१।

द्वारा प्रस्तुत कटौती और विलोपन के बहुत से प्रस्ताव भारी बहुमत से गिर गये, और सरकार की बहुत सी आर्थिक मागें आसानी से मंजूर हो गयीं, फिर भी अफीम, सूती कपड़ों पर उत्पादन शुल्क आदि कुछ विषयों से सम्बन्धित मागों पर कटौती के प्रस्ताव पास हो गये, और असेम्बली ने फिर एक बार उत्पादन शुल्क को उठा लेने की माग को पुष्ट किया, तथा सरकार की अफीम सम्बन्धी नीति की आलोचना की। मालवीयजी ने माग की कि देश में अफीम की खपत कम की जाय, तथा विदेशों को औपधीय प्रयोजनों के लिए ही अफीम भेजी जाने की व्यवस्था की जाय।

१४ मार्च सन् १९२५ को पंडित मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव किया कि वजट में से कार्यकारिणी परिषद् (एक्जीक्यूटिव) के लिए की गयी ६२०००) के अनुदान की माग निकाल दी जाय। जिना साहब और मालवीयजी दोनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मोतीलालजी ने अपने इस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध निन्दा-प्रस्ताव घोषित करते हुए सरकार की गति-विधि, नीति-रीति की बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कड़ी आलोचना की। जिना साहब ने भी बहुत ही जोरदार शब्दों में सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय पक्ष को पुष्ट किया।

मालवीयजी ने अपने भाषण में सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केन्द्रीय शासन-व्यवस्था "एक ऐसी मिश्रित (दोगली) व्यवस्था है जो न तो शुद्ध निरंकुशता है और न ही लोकतान्त्रिक सवैधानिक सरकार के सादृश्य है।" उन्होंने माग की कि गृह और वित्त विभाग भारतीय सदस्यों को हस्तान्तरित किये जायें, राष्ट्रीय रक्षा के विभाग का कार्यभार एक भारतीय सदस्य को सौंपा जाय, वैदेशिक तथा राजनीतिक विभाग का भार भी गवर्नर-जनरल के वजाय किसी दूसरे सदस्य के सुपुर्द किया जाय। उन्होंने यह भी माग की कि केन्द्रीय असेम्बली को रियासतों के मामलों पर भी विचार करने का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने इस अवसर पर कोहाट में हिन्दुओं पर किये गये अत्याचारों की चर्चा करते हुए उपद्रवों की जाच के लिए एक स्वतंत्र जाच कमेटी नियुक्त करने की भी माग की।^१

इंडिपेंडेंट पार्टी के मुसलमान सदस्यों को मालवीयजी की यह बात बुरी लगी। जिना साहब ने भी मालवीयजी के इस काम को उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अब जबकि वहां एक प्रकार से शान्ति कायम हो गयी है,

जाच कमेटी की नियुक्ति करके स्थिति को गंदा करना ठीक नहीं होगा। गांधी लालजी का प्रस्ताव ४८ मतों के विरुद्ध ६५ मतों से पास हो गया।

वित्त विधेयक

१६ मार्च सन् १९२५ को श्री विठ्ठल भाई पटेल ने वित्त विधेयक पर बोलते हुए असेम्बली से अपील की कि इस पर विस्तार से विचार ही नहीं किया जाये। उन्होंने अपने भाषण में जिना साहब पर भी छोटाकशी की। उन्होंने कहा कि जिना साहब तो द्विविध शासन (डायरकी) की सफलता पर विश्वास करते थे। जिना साहब को पटेल साहब की छोटाकशी बुरी लगी। उन्होंने गुंहे बिगाड़ कर उसका जवाब दिया, जिसका पटेल साहब ने प्रत्युत्तर दिया। पटेल साहब का सुझाव असेम्बली ने स्वीकार नहीं किया।

१८ मार्च सन् १९२५ को पंडित मोतीलाल नेहरू ने वित्त विधेयक को रद्द कर देने के पक्ष में बहुत जोरदार भाषण किया। जिना साहब और श्री विपिन चन्द्र पाल ने मोतीलालजी के विचार का विरोध किया। विवाद ने पारस्परिक प्रत्यारोप और व्यक्तिगत कटाक्ष का रूप धारण कर लिया, भयंकर स्थिति पैदा कर दी। प्रमुख नेताओं के वादविवाद से सरकारी पक्ष रुश था। बहुत से राष्ट्रवादी इस निरर्थक विवाद से दुःखी थे। कुछ राष्ट्रवादी सदस्य जिना साहब की इस बात से सहमत थे कि जब सब प्रगतिशील तत्त्वों ने मिलकर दो दिन हुए मोतीलालजी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केन्द्रीय कार्यपरिषद् पर अर्थात् भारत सरकार पर अपना रोप प्रकट ही कर दिया था, तब वित्त विधेयक को रद्द कर देने का प्रस्ताव पेश करके आपस में विवाद खड़ा करने की कौन जरूरत थी? इस कटुता की स्थिति में चुप रहना ही मालवीयजी ने उचित समझा। वित्त विधेयक पर न वे बोले, और न उन्होंने अपना मत दिया। ४० मतों के विरोध में ७५ मतों से वित्त विधेयक स्वीकार हो गया।

मालवीयजी की गतिविधि

स्वराज्य पार्टी और इंडिपेंडेंट पार्टी में बढ़ते हुए वैगनस्य से मालवीयजी दुःखी थे। वे दोनों पार्टियों के पारस्परिक सौहार्द को राष्ट्र-कल्याण की वृद्धि के लिए आवश्यक समझते थे। उनके लिए स्वराज्य पार्टी का विरोध करते हुए सरकार का समर्थन करना असह्य था। इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी के उन निर्णयों को मानने से इनकार कर दिया, जिनमें उसने स्वराज्य पार्टी के विरुद्ध सरकार के पक्ष में वोट देना निश्चित किया। ऐसे अवसरों पर मालवीयजी या तो तटस्थ रह जाते, या खुल कर स्वराज्य पार्टी का समर्थन कर देते थे। इस

तब जव स्वराज्य पार्टी की इच्छा के विरुद्ध इडिपेंडेंट पार्टी ने मार्च सन् १९२५ मे वित्त विधेयक का समर्थन किया, तब मालवीयजी तटस्थ रहे। इसी तरह जव जिना साहव ने पंडित मोतीलाल नेहरू का विरोध करते हुए रेलवे की मांगो पर सरकार का समर्थन किया, तथा जव सेना विभाग के खर्च पर जिना साहव ने सरकार के समर्थन मे वोट दिया, तब मालवीयजी ने स्वराज्य पार्टी का साथ दिया। इसी तरह भारत-मन्त्री के अधीन इंग्लैंड में होने वाले व्यय के अनुदान के प्रश्न पर जिना साहव तटस्थ रहे, उनकी पार्टी के अधिकांश सदस्यो ने सरकार का समर्थन किया, मालवीयजी ने विपक्ष मे वोट दिया।

सहयोग

इस विषय पर परिस्थिति मे भी स्वराज्य पार्टी और इडिपेंडेंट पार्टी ने कुछ महत्त्वपूर्ण मामलो मे मिलकर काम किया। १९ मार्च सन् १९२५ को इडिपेंडेंट पार्टी ने विट्ठल भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत 'स्पेशल लाज् रिपील बिल' के पक्ष मे वोट देकर उसे पास कराया। इसी तरह २० अगस्त सन् १९२५ को 'मुद्रा और विनमय कमीशन' पर जिना साहव के काम रोको प्रस्ताव का स्वराज्य पार्टी ने समर्थन किया। सितम्बर सन् १९२५ में राजनीतिक सुधारो के सम्बन्ध में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का इडिपेंडेंट पार्टी ने समर्थन किया। जनवरी सन् १९२६ में दोनो पार्टियो ने मिलकर रेलवे बोर्ड में भारतीयो की नियुक्ति पर आग्रह करते हुए रेलवे बोर्ड से सम्बन्धित अनुदान की माग को वजत मे से निकाल देने का प्रस्ताव पास कराया, तथा माग की कि राजनीतिक नजरबन्द रिहा किये जायें, उन पर लगे सब प्रतिबन्ध हटा दिये जायें।

कौंसिल ६.१ बाइकाट

कांग्रेस के आदेश का पालन करते हुए मार्च सन् १९२६ में पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी के सदस्यो द्वारा असेम्बली के बहिष्कार का निर्णय घोषित किया। उसके बाद असेम्बली मे निर्वाचित सदस्यो की शक्ति आधी रह गयी, और वह सरकार के हाथ की कठपुतली बन गयी। उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रस्ताव को पास कराना नामुमकिन हो गया।

बोवारीपण

गृह-सदस्य सर अलेक्जेंडर मुडीमैन ने स्वराज्य पार्टी के निर्णय पर खेद प्रकट करते हुए उसे ही असहयोग की परिस्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराया, और कहा कि इससे कोई लाभ होनेवाला नहीं है। कुछ दिन बाद एक प्रस्ताव पर बोलते हुए जिना साहव ने स्वराज्य पार्टी पर छोटाकशी की। उन्होंने कहा कि

जबकि इंडिपेंडेंट पार्टी और उदार दलीय सदस्य सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, केवल सात हजार सदस्यों की कांग्रेस पार्टी असहयोग करती है, और दावा करती है कि वह सारे देश का कार्य है।

मालवीयजी का उत्तर

मालवीयजी ने इस असहयोग की परिस्थिति के लिए सरकार के व्यवहार को ही उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने कहा कि जनता की भाग को पूरा करने के लिए सरकार को जो कुछ करना चाहिए था वह उसने नहीं किया और उसे अपना रुख बदलना चाहिए।^१ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की वित्तीय और राजनीतिक नीतियों के प्रति नापसन्दगी जाहिर करने के लिए वित्त विधेयक को रद्द कर देना सर्वथा वैध है, उसे अनुचित बताना ग़लत है, और उसके लिए पंडित मोतीलाल नेहरू से कहीं अधिक वे उत्तरदायी हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे रद्द करने की सदन से अपील की थी।^२ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भाग के सम्बन्ध में जनता का प्रतिनिधित्व कांग्रेस अवश्य करती है। देश में शीघ्र ही उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, यह कांग्रेस की दृढ़, तीव्र, अमिट इच्छा है, और यही कुल मिलाकर देश की मनोभावना है। सरकार के व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए मालवीयजी ने कहा कि जब सरकार ने सभी राष्ट्रवादियों की संयुक्त राजनीतिक भाग को ठुकरा दिया, तब वह किस मुंह से कांग्रेस पार्टी को असहयोग के लिए दोषी ठहराते हुए सहयोग की भाग करती है। सरकार और जनता के प्रतिनिधियों में अच्छे सम्बन्ध निःसन्देह आवश्यक है, पर यह तभी सम्भव है जब सरकार शासन को जनमत के अनुसार जनहित में बदलने को तैयार हो। सरकार की गतिविधि, उसकी नीतिरीति की बहुत ही प्रभावोत्पादक ढंग से कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने मौजूदा शासन-व्यवस्था को बदलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा : "उत्तरदायित्व का अभाव अच्छे प्रशासन में भारी बाधा है। सरकार को जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होना ही चाहिए"। उन्होंने इन शब्दों के साथ अपनी कतिपय पुरानी मांगों को दुहराते हुए जिना साहब के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि 'कार्यपरिषद के लिए की गयी भाग को वज्र से निकाल दिया जाय।'^३ पर स्वराज्य पार्टी के सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण जिना साहब का यह प्रस्ताव ३१ मतों के विरुद्ध ४७ मतों से नामंजूर हो गया।



१. वही, सन् १९२६, जि० ७, पार्ट ३, पृ० २१४७।

२. वही, सन् १९२६, जि० ७, पार्ट ३, पृ० २४०९।

३. वही, सन् १९२६, जि० ७, पार्ट ३, पृ० २४०५-२४१४।

१७. चुनाव संघर्ष

कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन

सन् १९२५ में सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव किया कि यदि फरवरी सन् १९२६ तक सरकार राष्ट्र की मांग स्वीकार न करे, तो स्वराज्य पार्टी विधान कौंसिलो का बहिष्कार कर दे। मालवीयजी ने इस प्रस्ताव में यह संशोधन पेश किया कि 'विधान कौंसिलो में सब कार्य इस प्रकार किये जायेंगे जिससे उत्तरदायी सरकार की निकट भविष्य में स्थापना में उनका सबसे अधिक प्रयोग हो सके, राष्ट्रीय उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जब आवश्यक होगा तब सहयोग किया जायगा, और जब आवश्यक होगा तब प्रतिरोध किया जायगा।' इस संशोधन का श्री एम० आर० जयकर ने अनुमोदन किया। कांग्रेस ने भारी बहुमत से संशोधन को नामजूर करते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस पर जयकर साहब ने घोषित किया कि श्री एन० सी० केलकर, डाक्टर बी० एस० मुंजे और उन्होंने निश्चय किया है कि स्वराज्य पार्टी और विधान कौंसिलो की सदस्यता से इस्तीफा देकर देश में कांग्रेस के इस निर्णय के विरुद्ध प्रचार किया जाय। उन्होंने कांग्रेस स्वराज्य पार्टी के विरोध में 'रिस्पासिव कोआपरेशन पार्टी' (अनुक्रियाशील सहयोगिक दल) बनाने का निर्णय किया। मालवीयजी ने भी इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी के नाम से एक दल गठित करने का निश्चय किया। इस अधिवेशन में गांधीजी ने राजनीतिक प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त नहीं किये, और आगे चलकर उन्होंने घोषित किया कि वे एक वर्ष तक देश की राजनीति में कोई भाग न लेकर केवल रचनात्मक काम करेंगे।

तेजबहादुर सप्रू का प्रयास

चुनाव में सक्रिय भाग लेने के लिए सर तेज बहादुर सप्रू कांग्रेस की नीति के विरोधी प्रगतिशील राजनीतिज्ञों की एक राष्ट्रवादी पार्टी गठित करना चाहते थे। उनकी अध्यक्षता में ३ अप्रैल सन् १९२६ को बम्बई में सर्वदलीय सहमिलन सम्मेलन हुआ। सम्मेलन ने स्वराज्य अर्थात् उत्तरदायी शासन और औपनिवेशिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए नयी नेशनलिस्ट पार्टी बनाने का निश्चय किया। इस सम्मेलन ने सन् १९१९ की राजव्यवस्था को अपर्याप्त और असन्तोषजनक स्वीकार किया, पर अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए उसका यथासंभव उपयोग

करना आवश्यक समझा। इस काम के लिए मन्त्रिपद को स्वीकार करना भी उचित घोषित किया गया। रावैधानिक आन्दोलन को मान्यता प्रदान करते हुए 'सामूहिक सविनय-अवज्ञा' तथा 'टैक्सो की गैर-अदायगी (अशोधन)' का विरोध किया गया। इस नये सगठन में जिना साहब, मालवीयजी और श्रीमती एनी बेसेट को शामिल करने का विचार भी व्यक्त किया गया।

मालवीयजी कांग्रेस से पृथक् इस प्रकार की पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं थे। वे तो सब राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञों को कांग्रेस में आमन्त्रित कर कांग्रेस को एक सुदृढ़ राष्ट्रवादी मोर्चा बनाना चाहते थे। उन्होंने दिसम्बर सन् १९२५ में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अपने इस सुझाव को प्रस्तुत भी किया था। सर तेजबहादुर सप्रू के प्रयास के उत्तर में भी उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा कि सब राष्ट्रवादी कांग्रेस के लक्ष्य को स्वीकार करके कांग्रेस में शामिल हो जाये, और कांग्रेस 'अनुक्रियाशील सहयोग' (रिस्पासिव कोऑपरेशन) की नीति को अपना कर एक बृहद् राष्ट्रीय संगठन की हैसियत से स्वराज्य के लिए प्रयत्न करे। उन्होंने जनकल्याण की रक्षा और वृद्धि के लिए एक लम्बा-चौड़ा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। पर जब मालवीयजी की बात कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में स्वीकार नहीं की थी, तब मोतीलालजी या कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू उसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? सर तेज बहादुर भी कांग्रेस के 'क्लीड' पर हस्ताक्षर कर कांग्रेस में शामिल होने को तैयार नहीं थे। इसलिए मालवीयजी की यह बात आगे नहीं बढ़ पायी।

सप्रू साहब द्वारा प्रस्तावित नेशनलिस्ट पार्टी भी गठित नहीं हो सकी। श्रीमती एनी बेसेट ने 'रिस्पासिव कोऑपरेशन' पार्टी का समर्थन करने का निश्चय किया, तथा जिना साहब ने, जो इस प्रकार की पार्टी बनाने के पक्ष में थे जो कांग्रेस और लिबरल पार्टी के बीच की हो, एक स्वतन्त्र उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ना ही उचित समझा। मालवीयजी ने पंडित हृदयनाथ कुंजरू, मुंशी ईश्वरशरण आदि उदारदलीय राजनीतिज्ञों को अपनी पार्टी में शामिल कर चुनाव में उनका समर्थन किया। उन्होंने श्री सी० वाई० चिन्तामणि का भी इस चुनाव में समर्थन किया।

मोतीलालजी का प्रयास

साम्प्रदायिकता के वातावरण में विशुद्ध साम्प्रदायिक नीतियों के आधार पर साम्प्रदायिक पार्टी या सरथा द्वारा चुनाव लड़ने के विचार को भी बहुत से साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के लोगो ने पुष्ट किया। हिन्दू महासभा ने जनवरी सन्

१९२६ में ही उसकी चर्चा शुरू कर दी। इस बात से घबड़ा कर मार्च में पंडित मोतीलाल नेहरू ने हिन्दू महासभा के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित होकर उससे ऐसा न करने की अपील की। उनकी इस बात का हिन्दू महासभा पर भला क्या प्रभाव पड़ने वाला था? उन्हें यह कहकर ही टाल दिया गया कि यदि वे मुसलमानों को साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोकते या रोक पाते, तो फिर हिन्दुओं को ही क्यों रोकते हैं? पर जब मालवीयजी और लाजपतरायजी ने महासभा के नाम पर चुनाव लड़ने या लड़ाने से इनकार कर दिया, तब बात खत्म हो गयी। हिन्दू सभा को सघटित रूप से चुनाव लड़ने का विचार छोड़ना पड़ा। दो चार स्थानों पर ही कुछ सज्जनों ने हिन्दू सभा के नाम पर चुनाव लड़े, पर किसी प्रमुख राजनीतिज्ञ ने ऐसा नहीं किया। हिन्दू महासभा से संबन्धित अधिकांश राजनीतिज्ञों ने इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी और रिस्पासिव कोऑपरेशन पार्टी का ही समर्थन किया।

नेहरू-जयकर वार्ता

अप्रैल सन् १९२६ में मोतीलालजी और जयकर साहब का मन्त्रि-पद स्वीकार करने के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया जो 'सावरमती पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पर यह समझौता टिकाऊ नहीं रहा। इस समझौते में यह तय हुआ था कि सरकार की ओर से फरवरी सन् १९२४ की माँग का उत्तर सन्तोषजनक समझा जायगा, यदि प्रान्तों में मन्त्रियों को अपने अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्तव्यों के समुचित निर्वाह के लिए साधन सुनिश्चित कर दिये जायें। इसके प्रकाशित होते ही श्री टी० प्रकाशम् आदि कतिपय कांग्रेसी नेताओं ने इसका विरोध किया। इस पर पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने एक वक्तव्य में उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि मन्त्रिपद को स्वीकार करने से पहले तीन बातों को पूरा करना आवश्यक होगा—(१) विधान कौंसिल को मन्त्री पूरे तौर पर उत्तरदायी हो तथा वे सरकार के नियन्त्रण से मुक्त कर दिये जायें, (२) राष्ट्र-निर्माण के विभागों के विकास के लिए राजस्व का पर्याप्त अंश प्रदान किया जाय, (३) हस्ताक्षरित विभागों में लोक-सेवकों (सर्विसेज) का पूरा नियन्त्रण मन्त्रियों को दिया जाय। जयकर साहब को समझौते की यह व्याख्या मजूर नहीं थी। ५ मई सन् १९२६ की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में मोतीलालजी ने घोषित किया कि समझौते की व्याख्या के सम्बन्ध में भारी मतभेद के कारण वह खत्म हो गया है।^१

१. पट्टाभि सीतारमैया : हिस्ट्री आफ़ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जि० २, पृ० ३००-३०१।

मोतीलाल-मालवीय वार्ता

इसके बाद सन् १९२६ में ही मोतीलालजी की मालवीयजी से भी बातचीत हुई। पर इन दोनों में भी नीतिरीति के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका। मोतीलालजी कानपुर कांग्रेस द्वारा स्वीकृत स्वराज्य पार्टी की नीति से हटने को तैयार नहीं थे, शायद उसमें मौलिक परिवर्तन करना उनके लिए सम्भव भी नहीं था। दूसरी ओर मालवीयजी स्वराज्य पार्टी की पुरानी नीति का अनुसरण निरर्थक और हानिकर, अतः उसमें मूलभूत परिवर्तन आवश्यक समझते थे।

मालवीयजी का सुझाव था कि साम्प्रदायिक समस्याओं पर समझौता न होने पर विधायकों को अपना मत अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त करने की छूट दी जाय, अविच्छिन्न विरोध के बजाय विवेचक (डिस्क्रिमिनेटिंग) विरोध की नीति अपनायी जाय, राजनीतिक विरोध को व्यक्त करने के लिए कार्य-परिषद (एक्जीक्यूटिव कौंसिल) से संबंधित आर्थिक मांग पर ही कटौती का प्रस्ताव किया जाय, अपव्यय के विरोध में वित्त विधेयक को रद्द कराने का प्रयत्न किया जाय, और जब तक राजनीतिक कैदी विशेषतः बंगाल अध्यादेश के अन्दर गिरफ्तार कैदी न छोड़े जायें, तब तक प्रान्तों में मन्त्रिपद स्वीकार न किया जाय, पर इस शर्त के पूरा होने पर प्रान्तीय विधायक बहुमत से मन्त्रिपद को स्वीकार करने का निश्चय कर सकते हैं।

ये सब बातें मोतीलालजी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि प्रान्तों में मन्त्रिपद तभी स्वीकार किया जाय, जब सब दमनकारी कानून वापस ले लिये जायें, और गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने की प्रथा खत्म कर दी जाय, मन्त्रियों को अपने विभागों पर पूरा कन्ट्रोल रखने का अधिकार हो, तथा राष्ट्रीय निर्माण के लिए समुचित फंड का प्रबन्ध हो। वे स्वराज्य पार्टी की लिस्ट में तब्दीली करके मालवीयजी के उम्मीदवारों को भी कोई स्थान देने को तैयार नहीं थे। वे सब विषयों पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने को भी राजी नहीं थे।

लाजपत राय का दृष्टिकोण

किसी नये आधार पर नये साथियों के साथ नयी पार्टी बनाने के बजाय कांग्रेस के तत्त्वावधान में गठित कांग्रेस पार्टी में काम करना, उसे अधिक शक्तिशाली बनाना ही लाला लाजपत राय को ठीक जँचता था। इसलिए पंडित मोतीलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने जनवरी सन् १९२६ में कांग्रेस पार्टी का सदस्य

वनकर मार्च सन् १९२६ में लाहौर में ब्रेडला हाल में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में एक बहुत ही जोशीला, प्रभावशाली भाषण किया, पर मालवीयजी और जयकर साहव की तरह वे भी अचर, अविच्छिन्न प्रतिरोध, और अपरिमित अवरोध की नीति, तथा सदन-त्याग की प्रतिक्रियाओं को निरर्थक और हानिकर, तथा लोकमान्य तिलक द्वारा प्रतिपादित अनुक्रियाशील सहयोग की नीति के आधार पर कांग्रेस पार्टी की नीति-रीति का निरूपण श्रेयस्कर समझते थे। जब इस सम्बन्ध में उनका और पंडित मोतीलाल नेहरू का कोई सन्तोपजनक समझौता नहीं हो सका, तब वे भी मालवीयजी के साथ हो गये।

मालवीयजी और जयकर साहव की नीति-रीति में काफी सामंजस्य था। इसलिए दोनों ने मिलकर काम करने का निर्णय किया। निश्चय हुआ कि बंगाल, मध्य प्रदेश और बम्बई प्रान्त में रिस्पासिव कोआपरेशन पार्टी (अनुक्रियाशील सहयोगिक दल) जो पहिले ही गठित हो चुकी है कार्य करेगी। पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बिहार आदि प्रान्तों में इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी गठित की जायेगी। दोनों पार्टियों के निर्वाचित सदस्य केन्द्रीय असेम्बली में संयुक्त ससदीय पार्टी गठित कर काम करेंगे।

चुनाव घोषणा-पत्र

इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनाव-घोषणा में पुरानी स्वराज्य पार्टी की नीति-रीति और कार्यवाहियों के औचित्य को पुष्ट करते हुए अचर और निरन्तर प्रतिरोध तथा अपरिमित अवरोध की नीति का पुनः प्रतिज्ञापन किया। इस घोषणा में बताया गया कि जबकि स्वराज्य पार्टी ने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद चुनाव में भाग लिया, इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी और रिस्पासिव कोआपरेशन पार्टी कांग्रेस के निर्णय के विरुद्ध, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के विरुद्ध चुनाव लड़ना चाहती है। ये दोनों पार्टियाँ इस कारण निश्चय ही कांग्रेस-विरोधी हैं, और सुदृढ़ संघटन के अभाव में देश में कुछ ठोस काम नहीं कर सकेंगी।^१

दूसरी ओर इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनाव-घोषणा में स्वराज्य पार्टी की नीति-रीति और कार्यवाहियों के औचित्य को चुनौती दी। उसने घोषित किया कि स्वराज्य पार्टी की पुरानी प्रतिरोध और अवरोध की नीति निरर्थक और हानिकर सिद्ध हुई है, और उससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

१. इंडियन क्वाटरली रजिस्टर, सन् १९२६, जि० २।

सदन को छोड़कर चले आने की प्रक्रिया भी बिल्कुल नाकामयाब साबित हुई है। इस घोषणापत्र में यह भी कहा गया कि चूँकि कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के बाद जनमत में काफी परिवर्तन हो गया है, और चूँकि कांग्रेस की मौजूदा कार्य-कारिणी उन पक्षों पर जो जनता को उद्विग्न कर रहे हैं देश का आदेश प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने को तैयार नहीं है, उन कांग्रेसियों के लिए, जो स्वराज्य पार्टी की नीति और कार्यक्रम से सहमत नहीं हैं, कांग्रेस के तत्त्वावधान में एक स्वतंत्र कांग्रेस दल गठित कर आगामी चुनावों में देश का आदेश प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है।^१

इस घोषणा में डिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी ने विधान सभाओं का मौजूदा संविधान दोषपूर्ण बताते हुए यह भी घोषित किया कि पूर्ण उत्तरदायी सरकार को प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए, जनता के हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए, अन्याय और कुशासन के विरुद्ध उनकी प्रतिरोध की शक्ति को पुष्ट करने के लिए इन विधान कौंसिलों का जितना भी उपयोग हो सकेगा किया जायेगा। प्रान्तीय पार्टी अपने बहुमत से प्रान्त में मन्त्रिपद स्वीकार करने का निर्णय भी कर सकती है। साम्प्रदायिक मतभेद के सब मामलों में प्रतियोगी गुटों में बुद्धि-संगत गमझौता कराना पार्टी के सदस्यों का कर्तव्य होगा, पर जब किसी विषय में कोई ऐसा समझौता नहीं हो पाये, तब पार्टी का प्रत्येक सदस्य जिस तरह ठीक और उचित समझे उस तरह विधान कौंसिलों में वोट करने को स्वतंत्र होगा। पार्टी ने यह भी घोषित किया कि वह रिस्पासिव कोआपरेशन पार्टी के साथ मिल कर काम करेगी, पर उस पार्टी को अधिकार होगा कि जहाँ वह पहले से बनी हुई है वहाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करे।^२

रिस्पासिव कोआपरेशन पार्टी ने भी अविच्छिन्न प्रतिरोध और अवरोध की नीति का विरोध करते हुए अनुक्रियाशील सहयोग की नीति के आधार पर देशहित की पुष्टि और वृद्धि के निमित्त विधान सभाओं तथा मन्त्रिपदों का यथासंभव उपयोग अपना ध्येय निश्चित किया।

चुनाव अभियान

अपनी तथा नयी पार्टी की नीति को स्पष्ट करते हुए लाला लाजपतराय ने कहा कि इस समय जबकि मुट्ठी भर कांग्रेसी मुसलमानों को छोड़कर सारा मुस्लिम समाज जी-जान से सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है, हिन्दुओं के लिए "असहयोग की मनोवृत्ति से विधान कौंसिलों में जाना व्यर्थ नहीं, हानिकर

है।^१ कौंसिल के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मौजूदा स्थिति में राष्ट्र और समाज के हित में उनका ठीक-ठीक प्रयोग ही लाभप्रद है। कोई व्यक्ति सरकार से सहयोग न करना चाहे, न करे। वास्तव में कोई भारतीय देशभक्त ऐसा करना नहीं चाहता। पर यदि कोई वहिष्कार की मनोवृत्ति से अपने को प्रभावित होने देता है, तो वह निश्चय ही उन मार्गों और रीतियों में घिर जायगा जो देश और हिन्दू समाज के लिए अनर्थकारी होगी।^२ उन्होंने कहा कि वे मुसलमानों से समझौता करने के पक्ष में हैं, और स्वीकार करते हैं कि "ठीक समय पर ठीक समझौता राजनीति का प्राण है।"^३ पर वे और उनकी पार्टी "हिन्दू अधिकारों की कीमत पर एकता खरीदना नहीं चाहते।" उनकी पार्टी की धारणा है कि "हिन्दू समाज के प्रति न्याय से राष्ट्रीयता का कोई विरोध नहीं है।"^४ उन्होंने कहा कि वे "प्रत्येक सम्प्रदाय के न्यायपूर्ण अधिकारों से सुसगत, दृढ़ और वास्तविक राष्ट्रीयता के पक्ष में हैं, और वे उस मनोवृत्ति को पुष्ट करना चाहते हैं जो सरकार या किसी दूसरे सम्प्रदाय का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अपने देश या समाज का सम्मान बेचने को तैयार न हो।"^५ उन्होंने घोषित किया कि वे "यह नहीं चाहते कि हिन्दू जनता कौंसिलों में उन्हें भेजे जो हिन्दू राज्य के विचार के समर्थक हैं, या सरकार के साथ प्रत्युत्तर सहयोग (काउन्टर अलायंस, करने के पक्ष में हैं।"^६ वे तो यह चाहते हैं कि "हिन्दू निर्वाचक सच्चे राष्ट्रवादियों, दृढ़ देशभक्तों, और पक्के हिन्दुओं को भेजे, जो सरकार से इस तरह पर कोई समझौता न करें और उस हद तक न झुकें जिससे हिन्दू समाज की पोजीशन संकट में पड़ जाय।"^७

लाला लाजपतराय की इन सब बातों से मालवीयजी पूरे तौर पर सहमत थे। वे मुसलमानों से मिलकर रहना देश के हित में आवश्यक समझते थे, हिन्दू राज्य के विचार को गलत समझते थे। सरकार से सहयोग करने के सम्बन्ध में मुसलमानों से होड़ करना भी वे ठीक नहीं समझते थे। पर वहिष्कार की मनोवृत्ति से सरकार के हर काम में अड़ंगा लगाना भी उन्हें पसन्द नहीं था। वे इसे अव्यावहारिक और हानिकार मानते थे। उन्होंने तो सन् १९२२ में ही कांग्रेस में कौंसिलों में प्रवेश करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था कि

१. वी० एस० जोशी (सम्पादक) : लाला लाजपतराय, राइटिंग एंड स्पीचिंग, जि० २, पृ० ३१९। २. वही, पृ० ३१९।
३. वही, पृ० ३२१। ४. वही, पृ० ३१८।
५. वही, पृ० ३२१। ६. वही, पृ० ३१९।
७. वही, पृ० ३१९।

हमें कौंसिलो का उपयोग करना चाहिए, जहाँ संभव हो वहाँ सरकार से सहयोग किया जाय, जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसका विरोध किया जाय। उनका विश्वास था कि न्याय पर आश्रित समझौता ही टिकाऊ हो सकता है, और वे उसके लिए सदा तैयार थे। वे मुसलमानों के साथ किसी हद तक उदारता का व्यवहार करना भी ठीक समझते थे, पर वे उनकी सब मागें मानने को तैयार नहीं थे। स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयत्न करने के साथ-साथ हिन्दू हितों की रक्षा करना भी वे हिन्दू विधायकों का कर्तव्य समझते थे। उन्हें दुःख था कि स्वराज्य पार्टी के हिन्दू सदस्य हिन्दू हितों की रक्षा के निमित्त अपने दिल की बात कहने से, अपने निर्वाचकों की भावनाओं को व्यक्त करने से घबड़ाते हैं, जिसके कारण बहुत से महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिनका हिन्दुओं के हितों और अधिकारों से गहरा सम्बन्ध होता है, ठीक तौर पर विधान कौंसिलो में विचार भी नहीं हो पाता।

कड़वाहट

सन् १९२३ के चुनावों से कहीं अधिक सन् १९२६ के चुनावों ने मालवीयजी और मोतीलालजी के आपसी सम्बन्धों में कड़वाहट पैदा कर दी। मालवीयजी मोतीलालजी से छः मास छोटे थे। वे मालवीयजी पर, उनके रहने-सहने के ढंग पर, सदा फवतिरियाँ कसते रहते थे। पर मालवीयजी को सदा ध्यान रहता था कि मोतीलालजी उनसे बड़े हैं और इसलिए जब वे उनसे मिलते उनके साथ "अदब का वर्ताव" करते थे। "जैसे कोई छोटा अपने बड़े के सामने जाता है, वैसे ही वे उनके सामने जाते थे।" सन् १९२३ के चुनाव में स्वराज्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालवीयजी की उन सभाओं को भंग करने की, मालवीयजी को अपमानित करने की भरसक चेष्टा की, जिनमें उन्होंने स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध प्रोफेसर पी० के० तेलग का समर्थन किया। मोतीलालजी ने स्वयं काशी की सार्वजनिक सभा में चुनाव के अवसर पर मालवीयजी पर फवतिरियाँ कसी। पर मालवीयजी ने इस सब की उपेक्षा करते हुए स्वराज्यपार्टी के उम्मीदवारों का दूसरे स्थानों पर समर्थन किया।

सन् १९२६ में तनाव इतना बढ़ गया कि मालवीयजी स्वयं मोतीलालजी के विरुद्ध चुनाव में खड़ा होना चाहते थे, ताकि हिन्दू जनता निश्चय कर सके कि उसे किस नेता की नीतिरीति पसन्द है। पर कांग्रेस के कतिपय कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर मालवीयजी अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र से ही खड़े हो गये। पर

इसके दो दिन बाद मोतीलालजी ने लाला लाजपत राय के विरुद्ध रायज़ादा हसराम को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा कर दिया। इस बात से क्षुब्ध हो लाला लाजपत राय ने अपने जालंधर निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त लाहौर निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का निश्चय किया। इससे कड़वाहट काफी बढ़ गयी। मोतीलालजी बार बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रायज़ादा हसराम और दीवान चम्पन लाल के समर्थन में जालंधर, लाहौर आदि स्थानों में भाषण करते, और मालवीयजी वहाँ जा कर लाला लाजपत राय का समर्थन करते थे। दोनों ओर के कार्यकर्ता एक दूसरे पर फव्वती कसते, बुरा भला कहते। मालवीयजी को ये बातें पसंद नहीं थी। उनकी उपस्थिति में जब एक बार अमृतसर की एक सार्वजनिक सभा में किसी कार्यकर्ता ने मोती लालजी पर छोटाकजी की तो मालवीयजी ने उसे रोक दिया, और आधे घंटे तक मोती लालजी की इतनी प्रशंसा की कि लोग दग रह गये।^१

संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में मालवीयजी के अतिरिक्त लाला लाजपत राय ने भी दौरा किया। ये दोनों उन रात नगरों में भी गये जहाँ से मोती लालजी खड़े थे। उन्होंने वहाँ कांग्रेस पार्टी की नीतिरीति का विरोध किया, अपनी पार्टी की नीतिरीति का समर्थन किया, प्रान्तीय काँग्रेस के लिए खड़े किये गये अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। पर उन्होंने मोतीलालजी के व्यक्तित्व तथा उनकी उम्मीदवारी के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा।^१ मेरठ की एक सार्वजनिक सभा में मालवीयजी को एक मानपत्र भेंट किया गया, और एक कवि ने उनकी प्रशंसा करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की निन्द करना शुरू की। मालवीयजी ने कवि को कविता पढ़ने से रोक कर कहा "मोतीलाल जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी शान के विरुद्ध कोई बात नहीं सुन सकता।"^२

इस चुनाव में पंडित मोतीलाल नेहरू के विरुद्ध कोई साधु खड़े हो गये थे। यह सज्जन मालवीयजी की पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। उन्होंने और लाला लाजपत राय ने उनके समर्थन में कहीं कोई भाषण नहीं किया। मोतीलालजी की तुलना में उक्त सज्जन का व्यक्तित्व और कार्य नगण्य था, उनके समर्थक इसलिए कांग्रेस की नीतिरीति के बजाय मोतीलालजी के व्यक्तित्व पर कीचड़ फेंकते रहते थे।

१. मालवीयजी, जीवन झलकिया, पृ० १९४।

२. सीताराम चतुर्वेदी : महामना मालवीयजी, पृ० १५५।

मोतीलालजी को सम्भवतः सन्देह था कि मालवीयजी ने ही उनके विरोध में उक्त साधु को खड़ा किया था, और उसकी अपमानजनक बातों में उनका हाथ था। पर मोतीलालजी या उनके किसी समर्थक ने इस सन्देह के समर्थन में कोई प्रमाण पेश नहीं किया। मोतीलालजी की जीवनी के लेखक श्री वी० आर० नन्दा ने भी इसकी कोई चर्चा मोतीलालजी की जीवनी में नहीं की है।

मोतीलालजी को दुःख था कि इस चुनाव में उनके बहुत से पुराने कार्यकर्ताओं ने, यहाँ तक कि उनके भतीजे श्यामलालजी ने भी, उनकी पार्टी के विरोध में काम किया। उन्हें शोभ था कि उनके पुराने साथियों ने उन्हें हिन्दू-विरोधी कहा, उन्हें गोकुणों को कानूनी बनवाने का, तथा काबुल के साथ पट्टयन्त्र करने का दोषी बताया। चुनाव के बाद उन्होंने लाला लाजपत राय के उर्दू साप्ताहिक "बन्देमातरम" पर उसके काबुल सम्बन्धी आरोपों के लिए मानहानि का मुकदमा दागर कर दिया, और माग की कि या तो संपादक क्षमा याचना करें, या एक लाख रुपया हर्जाने में दे। मामले ने काफी तेजी पकड़ी। तब गांधीजी ने बीच में पड़कर किसी तरह उसे शान्त कराया, मुकदमा वापस कराया।

मोतीलालजी को यह भी सन्देह था कि लाला लाजपत राय और मालवीयजी बिड़ला के रुपये की सहायता से गोहाटी के कांग्रेस अधिवेशन पर कब्जा कर लेने के प्रयत्न में हैं। पर उनका यह सन्देह सर्वथा निर्मूल सिद्ध हुआ। लाला लाजपत राय, जयकर, और केलकर गोहाटी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। अणु साह्य और गुंजे वहाँ गये, पर चुप रहे। मालवीयजी ने कुछ शर्तों के साथ मन्त्रिपद स्वीकार कर लेने की बात जरूर की, पर कांग्रेस ने मोतीलालजी द्वारा प्रस्तुत और समर्थित स्वराज्य पार्टी के पुराने कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। इस पर मोतीलालजी ने अपने सुपुत्र जवाहरलाल को लिखा कि "हम दृढ़ता से सब प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध डटे रहे, और हमने ज़बर्दस्त बहुमत से जो चीज हम चाहते थे उसे पारा करा दी।" ^१ सम्भवतः गोहाटी काफेरेंस मोतीलालजी के संसदीय दल की भारी विजय थी, क्योंकि जो राजनीतिक प्रस्ताव वहाँ स्वीकार हुआ उसमें सविनय-अवज्ञा का औपचारिक राकेत भी नहीं था। ^२

इस संदेह और कटुता की स्थिति में भी लाला लाजपत राय ने आम चुनाव के बाद लाहौर निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार श्री नन्दलाल

१ नन्दा नेहरूजी, पृ० २६९।

२ पट्टाभि सोतारामैया : हिस्ट्री आफ़ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, पृ० ३१२।

वैरिस्टर का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री चम्पनलाल का समर्थन किया, और उनकी विजय में महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

जवाहरलालजी द्वारा बटु आलोचना

पंडित जवाहर लाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में चुनाव संघर्ष बुरा लगता था। वे समझ नहीं पाते थे कि “सिद्धान्त के किन आधारों ने नयी पार्टी को पुरानी पार्टी से अलग किया।”^१ उनकी राय में नयी नेशनलिस्ट पार्टी अधिक नरम दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थी, और स्वराज्य पार्टी से अधिक दक्षिण-पक्षीय थी। वह निल्कुल हिन्दू पार्टी थी, जो हिन्दू महासभा के निकट सहयोग में काम करती थी।^२ उन्होंने लिखा, “नेशनलिस्ट पार्टी ने सफलता की बड़ी मात्रा प्राप्त की, पर इस सफलता ने लेजिस्लेटिव असेम्बली के राजनीतिक वातावरण को अवश्य ही नीचे गिरा दिया। गुरुत्व केन्द्र अधिक दक्षिण की ओर हटा। स्वराज्य पार्टी स्वयं कांग्रेस का दक्षिण पक्ष था। अपनी शक्ति को बढ़ाने के प्रयत्न में उसने बहुत से सदिश व्यक्तियों को अपने में घुस आने दिया, और इसके कारण उसके गुण में क्षति पहुँची है। नेशनलिस्ट पार्टी ने भी इसी नीति का अनुमरण किया, पर अधिक नीचे स्तर पर, और खिताबधारियों, बड़े जमींदारों, उद्योगपतियों आदि का पचरंगी जूथा जिसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं उसकी पक्ति में आ गया।”^३

नेहरू साहब की आलोचना किसी अंश में ठीक थी। नेशनलिस्ट पार्टी हिन्दू पार्टी कही जा सकती थी, क्योंकि उसके सभी सदस्य हिन्दू थे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा कर सकती थी, क्योंकि इसमें कुछ मुसलमान भी थे, और वम्बई काँग्रेस की कांग्रेस पार्टी का नेता एक पारसी राजनीतिज्ञ मिस्टर के० एफ० नारीमान था। इसमें भी सदेह नहीं कि स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक बातों में दोनों पार्टियों की एक राय थी। फिर भी दोनों की नीति रीति में अंतर अवश्य था। इस अंतर के आन्तर पर कांग्रेस पार्टी की तुलना में नेशनलिस्ट पार्टी को अधिक नरम और दक्षिण-पक्षी कहा जा सकता था, पर अंतर यदि बहुत बुनियादी नहीं, तो उसे सतही भी नहीं समझा जा सकता। इसके कारण ही सन् १९२५ में स्वराज्य पार्टी टूटी थी, और उसका संतोषजनक समाधान न होने पर दो पार्टियों का बनना स्वाभाविक था। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि चुनाव में इन दो पार्टियों का संघर्ष हितकर नहीं समझा जा

१. जवाहरलाल नेहरू : आटोबायोग्राफी, पृ० १५७।

२. वही।

३. वही, पृ० १६०।

सकता था । मोतीलाल-लाजपतराय विवाद ने तो संघर्ष की ओर भी अशोभनीय बना दिया था । इसमें संदेह नहीं कि यदि दोनों ने मिलकर काम किया होता, तो उम्मीदवारों के चयन का स्तर कहीं ऊँचा होता । होड़ में दोनों ओर से कुछ ग़लत आदमी उम्मीदवार जरूर बनाये गये । पर यदि कांग्रेस की शिकायत थी कि मालवीयजी की पार्टी ने गणेश शंकर विद्यार्थी के विरुद्ध एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जिसका भारत की राजनीति में कोई योगदान नहीं था, तो लाला लाजपतराय को इस बात की शिकायत थी कि कांग्रेस की ओर से एक ऐसा व्यक्ति अपना प्रत्याशी खड़ा किया गया जो 'सरकार का मुख़्बिर' रह चुका था ।^१

यह कहना कि नेशनलिस्ट पार्टी की सफलता ने 'लेजिस्लेटिव असेम्बली के राजनीतिक स्तर को अवश्य ही नीचे गिरा दिया' बिल्कुल निराधार है । लाला लाजपतराय, मालवीयजी और जयकर राहव के नेतृत्व में गठित नेशनलिस्ट पार्टी का काम केन्द्रीय असेम्बली में किसी तरह भी कांग्रेस पार्टी के काम से कम गौरवपूर्ण, तगड़ा और प्रभावकारी नहीं था । वास्तव में कभी-कभी तो नेशनलिस्ट पार्टी के नेता लाला लाजपतराय और उपनेता मालवीयजी का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित मोतीलाल नेहरू और उपनेता श्री श्रीनिवास ऐयंगर से अधिक तगड़ा होता था । पंडित मोतीलाल नेहरू और श्री श्रीनिवास ऐयंगर के पारस्परिक संबंधों से भी जो क्षोभ और अव्यवस्था कांग्रेस पार्टी में पैदा हो गयी थी, उसका शतांश भी नेशनलिस्ट पार्टी में नहीं था । समाज-सुधार के प्रश्नों पर लाला लाजपतराय और मालवीयजी के विचारों में बहुत अंतर था । पर उसके कारण पार्टी में क्षोभ की स्थिति पैदा नहीं हुई । दोनों ने पूरी पारस्परिक सद्भावना के साथ अपने विचार असेम्बली में प्रस्तुत कर दिये । पार्टी के साधारण सदस्यों को भड़का कर अपने को ऊँचा उठाने की, और दूसरे को नीचा गिराने की बात तो इन दोनों में कोई सोच ही नहीं सकता था ।

जवाहर लाल जी द्वारा मालवीयजी के विचारों की आलोचना

सन् १९२६ के चुनावों के संदर्भ में ही पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मालवीयजी के विचारों और सेवाओं की भी समीक्षा की । उन्होंने लिखा : "मालवीयजी केवल राष्ट्रवादी थे, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था । वे सांस्कृतिक, सामाजिक, और आर्थिक क्षेत्रों में पुरानी

परम्परागत व्यवस्था के समर्थक थे और हैं। भारतीय राजे-महाराजे, तालुकेदार और ज़मींदार उन्हें ठीक ही अपना शुभचिन्तक मित्र समझते हैं। जो परिवर्तन वे तीव्रता से चाहते हैं वह हिन्दुस्तान में विदेशी नियंत्रण का पूर्ण विलीनीकरण है। नीजवानी की शिक्षा और अध्ययन बहुत कुछ उनके चिन्तन को प्रभावित करते हैं, और वे इस बीसवीं शताब्दी के गतिशील, क्रान्तिकारी, युद्धेतर संसार को टी० एच० ग्रोन और जान स्टुअर्ट गिन तथा ग्लैडस्टन और मार्ले की अर्ध-स्थिर उन्नीसवीं शताब्दी के चश्मे से, तथा तीन-चार हजार पुरानी हिन्दू संस्कृति और समाजदर्शन के आलोक में देखते हैं। विरोधों से मंपूक्त यह एक अद्भुत समुच्चय है, और इन विरोधों का समाधान करने की क्षमता पर उन्हें आश्चर्यजनक विश्वास है। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी लम्बी सार्वजनिक सेवा ने, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी संस्था की स्थापना में उनकी सफलता ने, उनकी स्पष्ट सच्चाई और गंभीरता ने, उनकी प्रभावशाली वाग्मिता ने, उनके सरल स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व ने, भारतीय जनता को, विशेष रूप से हिन्दू जनता को, उनका प्रिय बना लिया था, और बहुत से वे लोग भी, जो यदि उनसे सहमत न हो और राजनीति में उनका अनुसरण न करते हो, तो भी उनका आदर करते और उनसे स्नेह रखते हैं। अपनी आयु और अपनी लम्बी सार्वजनिक सेवा के कारण वे भारतीय राजनीति के वरिष्ठ सदस्य हैं। पर वे एक ऐसे वरिष्ठ हैं जो कुछ कुछ समयातीत हैं और मौजूदा संसार से संपर्क-रहित हैं। उनकी बाणी ध्यान आकर्षित करती थी, पर जो नापा वे बोलते वह बहुतां की समझ में नहीं आती थी, बहुत से उम्र पर ध्यान नहीं देते थे।^१

यदि गाँवे में आकर जवाहरलालजी ये सब बातें न कहते तो अच्छा होता। इनसे तो यही मिश्र होता है कि मालवीयजी की सार्वजनिक सेवा और क्षमता तथा उनका शील उनके नेतृत्व का मूलाधार था, और उनके व्यक्तित्व ने जनता को इतना मोहित कर लिया था कि जब उन्हें उनकी बात ठीक नहीं जँचती थी, तब भी वे उनका आदर करते थे। यदि यह ख़ास भी बता दिया जाता कि सन् १९२६ में नयी पार्टी के नेतृत्व का उत्तरदायित्व ग्रहण करने से पहले उन्होंने बीस वर्ष प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान कौंसिलों में बहुत ही समता के साथ राष्ट्रीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था, तो यह विल्कुल स्पष्ट हो जाता कि जो उत्तरदायित्व उन्होंने सन् १९२६ में ग्रहण करने का निश्चय किया उसके वे सर्वथा योग्य थे।

नेहरूजी स्वीकार करते हैं कि मालवीयजी “राष्ट्रवादी” थे, राजनीतिक स्वतंत्रता की उपलब्धि उनके सार्वजनिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था। यही तो उस समय राष्ट्र की सबसे बड़ी माँग थी, यही तो स्वराज्य पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मुख्य ध्येय था; इसके लिए सतत प्रयत्न करना प्रत्येक देशभक्त कार्यकर्ता का कर्तव्य था। चालीस वर्ष तक अथक प्रयत्न करने के बाद भी वे इस कर्तव्य के पालन में डटे रहे, यह क्या कोई कम बात है? यदि वे अपनी पुरानी सेवाओं से संतुष्ट होकर, या नवयुग के युवक राजनीतिज्ञों के तौर तरीके से रुष्ट होकर राजनीति से अलग हो गये होते, या किसी आर्थिक या सामाजिक कार्यक्रम को प्राथमिकता देने लगे होते तो वे अपने कर्तव्य-पथ से हट गये होते।

नेहरूजी ने लिखा है कि ‘मालवीयजी का हृदय अक्सर कांग्रेसकैम्प में था’। नेहरूजी की यह बात अवश्य ही भ्रामक है। वे सन् १८८६ में कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद जीवन पर्यंत कांग्रेस में बने रहे। वे कांग्रेस को स्वतंत्रता संघर्ष का रंगमंच स्वीकार करते थे, और उसके इस स्वरूप को विकसित करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहते थे। कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा अचल थी। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने की, या उसके विरुद्ध कोई स्थायी राजनीतिक सस्था बनाने की बात कभी सोची ही नहीं। सन् १९३२ में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार करते हुए मालवीयजी ने जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि “कांग्रेस के प्रायः जन्मकाल से ही उसके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त रहा है। कई अवसरों पर जबकि कुछ महत्त्व के प्रश्नों पर मेरा मतभेद रहा है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा-भक्ति में कमी नहीं पड़ने पायी।” मालवीयजी की इस निष्ठा के प्रति जवाहर लालजी की चाहे कुछ ही राय क्यों न हो, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, पट्टाभि सीतारामैया और स्वयं गांधीजी को इसमें कोई संदेह नहीं था।

नेहरूजी की यह बात कि ‘मालवीयजी परम्परागत आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था के समर्थक थे, और आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से उनका कोई वास्ता नहीं था’ बिल्कुल ही भ्रामक है। बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में मालवीयजी ने युक्त प्रान्त को कौंसिल में बजट की आलोचना करते हुए जो भाषण किये थे, उनको पढ़ने से तो यह स्पष्ट होता है कि मालवीयजी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि राष्ट्र का आर्थिक और सांस्कृतिक नवनिर्माण भी करना चाहते थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति

के समर्थक थे, और चाहते थे कि भारतीय विद्यार्थी प्राचीन भारतीय वाङ्मय के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और शिल्पशास्त्र का भी अध्ययन करें, और उनकी सार्थक उपलब्धियाँ ग्रहण करें, तथा राष्ट्र के नवनिर्माण में उनका उपयोग करें। उन्होंने अपने समकालीन सभी राजनीतिज्ञों की तरह मालगुजारी के स्थायी बन्दोबस्त की माँग को पुष्ट किया, पर उसके साथ यह भी माँग की कि किसानों का लगान पचीस तीस प्रतिशत घटा दिया जाय, और इस घटे लगान के आधार पर मालगुजारी का भी स्थायी बन्दोबस्त किया जाय। उन्होंने तो एक बार भारतीय निधान कोसिल में घोषित किया कि उन्होंने बंगाल के ढग के स्थायी बन्दोबस्त का कभी समर्थन नहीं किया। उन्होंने कृषि आयोग के सामने गवाही देते हुए कहा कि उन्होंने पिछले चुनावों में जमींदारों से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि वे उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो उन्हें (जमींदारों को) अपने काश्तकारों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा।^१ मालवीयजी ने कमीशन से यह भी कहा था कि वे चाहते हैं कि किसानों को अधिक हट-पुट और ऊँचा जीयन बिताने की सुविधा प्राप्त हो, उनमें आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्भरता की भावना पुष्ट की जाये, उन्हें सरकार के प्रशासनिक, माल, तथा पुलिस के अफसरों एवं जमींदारों और उनके कारिन्दों की ओर मुँह उठाकर बात करने की शिक्षा दी जाय, उन्हें बताया जाय कि उन्हें नागरिकता के वही अधिकार प्राप्त हैं जो उनके अधिक सम्पन्न रागी-साथियों को प्राप्त हैं।^२ सन् १९३१ में उन्होंने नेहरूजी द्वारा प्रस्तुत मौखिक अधिकारों की रूपरेखा स्वीकार करते हुए किसानों के उन अधिकारों को मान्यता प्रदान किये जाने की माँग का समर्थन किया, जिसका उल्लेख उस रूपरेखा में था। सन् १९३६ में नेहरू साहब के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो चुनाव घोषणा तैयार की, उसमें भी किसानों के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नहीं कही गयी थी, जिसका किसी न किसी रूप में मालवीयजी ने उससे पहले ही समर्थन न किया हो। यह ठीक है कि सन् १९२८ में मालवीयजी ने सर्वदलीय सम्मेलन में जमींदारों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया था, पर इसका भी यही मतलब था कि बिना मुआवजे के, बिना समुचित कानूनी व्यवस्था के, जमींदारियाँ जब्त नहीं की जा सकती। कुछ नवयुवकों ने इसका विरोध जरूर किया, पर किसी

१. एग्रीकलचरल कमीशन रिपोर्ट, जिल्द ७, पृ० ७३२, पृ० ४२६

२. वही, पृ० ७०९।

वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता ने, किसी कांग्रेसी विधायक ने, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठायी। इस से यह स्पष्ट है कि सन् १९२६-३१ में कृषि व्यवस्था के सम्बन्ध में मालवीयजी के विचार उतने क्रान्तिकारी भले ही न हो जितने जवाहर लालजी के थे, पर उनमें सुधार और परिवर्तन जरूर निहित थे, और वे कम से कम इतने प्रगतिशील जरूर थे जितनी कांग्रेस की सन् १९३६ की चुनाव घोषणा।

मालवीयजी चाहते थे कि पुराने कला-कौशल और शिल्पो की समुचित रक्षा की जाय, पर वे यह भी चाहते थे कि आधुनिक शिल्प विज्ञान, यंत्र-विज्ञान और विद्युत-विज्ञान की शिक्षा का भी देश में समुचित प्रबन्ध किया जाय, और इन सबकी मदद से बड़े-बड़े कल कारखाने खोले जायें, और बड़े पैमाने पर देश में औद्योगीकरण किया जाय। उन्होंने केन्द्रीय असेम्बली में ब्रिटेन के राजनीतिक आधिपत्य के साथ साथ उसके आर्थिक आधिपत्य का भी विरोध किया, राजनीतिक स्वराज्य के साथ साथ आर्थिक स्वराज्य की माग को भी पुष्ट किया। जहाँ उन्होंने इस बात की माग की कि वित्तीय संरक्षणों द्वारा भारत में देशज उद्योगों की वृद्धि की जाय, वहाँ उन्होंने श्री एन० एम० जोशी की इस माग का भी समर्थन किया कि मजदूरों के हितों और अधिकारों की समुचित रक्षा की जाय, और ब्रिटिश उद्योगों और औद्योगिकों को बाउन्टी या साम्राज्यिक अधिमान देने का विरोध किया। सन् १९२८-२९ में जहाँ उन्होंने कम्युनिस्टों की धर्म-सम्बन्धी धारणाओं का विरोध किया, वहाँ उनकी कतिपय आर्थिक और सामाजिक धारणाओं को न्याय सगत और धर्मानुकूल बताया। इस सबके बाद मालवीयजी को 'यथा पूर्वस्थितिवादी' नहीं कहा जा सकता। वे समाजवादी नहीं थे। पर सन् १९१९ में रेलों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में जो तर्क उन्होंने दिये वे समाजवादी ही थे।^१ फिर सन् १९२६ में किस कांग्रेसी नेता ने अपने को समाजवादी घोषित किया था? वास्तव में उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में जिस व्यक्ति का झुकाव समाजवाद की ओर दिखाई पड़ता था, वह नेशनलिस्ट पार्टी के नेता लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने नवम्बर सन् १९२० में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में पूंजीवाद को चुनौती देते हुए कहा था। "सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं। वे तीन में एक और एक में तीन हैं। उनकी छाया, उनके फल और उनकी छाल—सभी जहरीले होते हैं।"^२

१. इंडियन लेजिस्लेटिव कौंसिल सन् १९१८ जि० ५६, पृ० १०९८।

२. जोशी : लाला लाजपत राय, राइटिंग्स एंड स्पीचिंग जि० २, पृ० ५७।

यह ठीक है कि समाज-सुधार के मामले में मालवीय जी के विचार यथोचित प्रगतिशील नहीं थे, पर केन्द्रीय असेम्बली में इस कमी की पूर्ति नेशनलिस्ट पार्टी के नेता लाला लाजपत राय करते थे ।

यह ठीक है कि मालवीयजी टी० एच० ग्रीन, जान स्टुअर्ट मिल, ग्लैडस्टन, के विचारों से प्रभावित थे । यही सिद्ध करता है कि उनका चिंतन पुरातनवादी नहीं, बल्कि समन्वयवादी था, उनकी उदारवादी धारणाएं व्यक्तिवाद के वजाय 'सामाजिक उपयोगिता' या 'सामाजिक हित' के मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित थी, और वे 'पुलिस राज्य' के वजाय 'कल्याण राज्य' पर विश्वास करते थे, स्वतंत्रता और समता पर आश्रित लोकतन्त्र पर उनकी निष्ठा थी । ये सब धारणाएं नि सदेह उन्नीसवीं शताब्दी के विचारकों द्वारा प्रतिपादित की गयी थी, और सम्भवतः उस शताब्दी के अंतिम दशक में ही मालवीयजी ने उन्हें ग्रहण कर लिया था । वे इन सब बातों को बीसवीं शताब्दी के भारत के लिए भी, स्वतंत्र भारत के राजनीतिक निर्माण के लिए भी आवश्यक समझते थे । स्वतंत्र भारत के लिए जो सविधान पंडित नेहरू की सहमति से तैयार हुआ वह सर जान स्टुअर्ट मिल और ग्लैडस्टन के विचारों से मिलता जुलता लोकतान्त्रिक विधान है, जिसमें मुआवजा देकर ही निजी सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण तथा ज़मींदारी को खत्म करने की व्यवस्था है, और समाजवादी समाज को स्थापित करने की कोई चर्चा नहीं है ।



१८. लेजिस्लेटिव असेम्बली

१९२७-१९३०

दलों की स्थिति

सन् १९२६ के चुनाव में उत्तर प्रदेश और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की करारी हार और इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी की भारी विजय हुई। मध्य प्रान्त, महाराष्ट्र में भी जयकार साहब की 'गिमपानगिव कोजापरेशन पार्टी' ने कांग्रेस पार्टी को हराकर अपने उम्मीदवारों को जिता दिया। दोनों पार्टियों के सभी प्रमुख नेता केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य निर्वाचित हो गये। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी गठित की। इसमें कुछ वे सदस्य भी शामिल हुए गये जिन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार की हेंसिंगत से चुनाव लड़ा था। दोनों सदस्यों की इस पार्टी के लाला राजपत राय नेता, और मालवीय जी उपनेता चुन लिये गये।

मद्रास, बंगाल, बिहार आदि प्रान्तों में अत्यधिक सफलता मिलने के कारण केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रेस पार्टी ही प्रमुख विरोधी दल बना रहा। पर इस पार्टी के सदस्यों की सहमा पहुँचे से कुछ कम हो गयी, जिसके कारण उसकी पोजीशन को धक्का लगा। पंडित मोतीलाल नेहरू नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष बी० एस० श्रीनिवास ऐंगरर उपनेता चुने गये।

असेम्बली में नेशनलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सब राष्ट्रीय प्रश्नों पर मिलकर काम किया। पर सरकार के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए इन दोनों पार्टियों की संयुक्त शक्ति भी काफी नहीं थी। इसके लिए जिना साहब की इंडिपेंडेंट पार्टी की सहायता की आवश्यकता होती थी। पर विरोधी पक्ष को इस दल का पूरा बल नहीं मिल पाता था। कभी कभी जब जिना साहब स्वयं कांग्रेस पार्टी का साथ देने को तैयार हो जाते थे, तब भी उनकी पार्टी के सदस्य सरकार का साथ दे देते थे, या तटस्थ रह जाते थे।

पर कांग्रेस पार्टी की अनुशासन-हीनता भी विरोधी-पक्ष की परेशानी का एक बड़ा कारण बन गयी थी। इसके कारण बहुधा उस समय जबकि मोतीलाल जी ने सरकार के विरोध में वोट किया, कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्यों ने वोट नहीं दिया, संभव है वे उस समय सदन में ही नहीं।^२ वास्तव में

मोतीलालजी स्वयं अनुशासन-हीनता से इतने क्षुब्ध थे कि वे केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य भी बने रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने जवाहरलालजी को लिखा— “पार्टी के मामले बंद से बंदतर होते जा रहे हैं। मैंने पार्टी के उपनेता श्री ऐयंगर को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पार्टी के सब मामलों में पूरा और स्वतंत्र अधिकार दे दिया है, जबकि मैंने अपने को लगभग पीछे रखा है। उन्होंने इस बात से लाभ उठा कर रंगा अय्यर तथा दूसरों को भिन्न भिन्न तरीकों से मुझे बदनाम करने में बढ़ावा देकर पार्टी में मनमुटाव और असन्तोष को प्रोत्साहित किया। जब मैं अनुशासन की कार्रवाई लेने को बाध्य हुआ, तब उन्होंने उनकी ओर से मध्यस्थता की, और सदस्यों में उनके लिए सहानुभूति बढ़ायी। जब कार्यवाही वापस ले ली गयी, तब उन्होंने उनको किसी दूसरी शरारत में लगा दिया। मेरे सामने यही विकल्प है कि मैं कड़ाई से वग़ावत की भावना को दबा दूं, या रिटायर हो जाऊं। मैं सोचता हूँ कि दूसरा रास्ता ही ठीक होगा, लेकिन मैं अभी पूरे तौर पर निर्णय नहीं कर पाया हूँ”।^२ मोतीलालजी ने गांधीजी को भी लिखा “मैंने असेम्बली से खिसक जाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। पिछले सेशन में मैंने यथासंभव अपने को पीछे रखा। जब सितम्बर में नया सेशन होगा, मैं सम्भवतः यूरोप में हूँगा। गवर्नर-जनरल चाहे तो वह मेरी सीट खाली घोषित कर सकते हैं। पर मुझे डर है कि वे ऐसा नहीं करेंगे”।^३ इस पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि वे तो स्वयं यही चाहेंगे कि असेम्बली से “बाहर रह कर जितनी भी अधिक से अधिक सेवा वह कर सकें करें”।^४ इसी अवसर पर डॉक्टर अन्सारी ने भी कांग्रेस पार्टी की गतिविधि पर एक वक्तव्य प्रकाशित किया। इसका भी मोतीलालजी को काफी क्षोभ था।

दिसम्बर सन् १९२७ में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में कौंसिलो में कांग्रेस पार्टी का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित कर दिया, और मई सन् १९२९ में उसने सदस्यों को आदेश दिया कि वे असेम्बली की बैठकों में न जायें। इन कारणों से भी वे सन् १९२८ और सन् १९२९ में बहुत ही कम काम कर सके। जनवरी सन् १९३० में कांग्रेस पार्टी ने असेम्बली का बहिष्कार कर दिया। वास्तव में सन् १९२७ के बाद कुछ प्रश्नों को छोड़कर जिनमें कांग्रेस पार्टी ने भी भाग लिया, नेशनलिस्ट पार्टी को ही मुख्य विरोधी दल का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की अनुपस्थिति के कारण जनता-पक्ष को बार-बार पराजित होना पड़ा।

१. नन्दा : नेहरूजी, पृ० २७०।

२. वही।

३. वही।

समाज-सुधार

समाज-सुधार के प्रश्न पर मालवीयजी के दल में भी मतभेद था। लाला लाजपतराय पुराने समाज-सुधारक थे, वे कानून द्वारा सामाजिक कुरीतियों का निराकरण सर्वथा उचित और आवश्यक समझते थे। पंडित हृदय नाथ कुंजरू और मुंशी ईश्वर शरण भी विल्कुल उनके साथ थे। पर मालवीयजी बाल-विवाह आदि कुरीतियों का निराकरण हिन्दू-जाति के उत्थान के लिए आवश्यक समझते हुए भी समाज-सुधार के प्रश्नों पर हिन्दुओं के परम्परागत विचारों और भावनाओं का ध्यान रखना विधायकों का कर्तव्य समझते थे। इसलिए जबकि लाला लाजपत राय, पंडित हृदय नाथ कुंजरू, मुंशी ईश्वर शरण आदि ने श्री हर विलास शारदा द्वारा प्रस्तुत हिन्दू विवाह-विधेयक का डट कर समर्थन किया, मालवीयजी ने उसे जनमत के लिए प्रसारित करने, और उसके पक्ष में जनमत तैयार करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि एक वर्ष से कम आयु की विधवाएँ केवल हिन्दुओं में ही नहीं, बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों में भी पायी जाती हैं, और इसलिए बाल-विवाह के सम्बन्ध में एक ऐसा व्यापक कानून पास होना चाहिए जिसका सम्बन्ध सब सम्प्रदायों से हो^१। मालवीयजी सोलह वर्ष की कन्या और पचीस वर्ष के नवयुवक के विवाह को ही सर्वोत्तम समझते थे। बारह वर्ष की आयु में कन्या का विवाह तो वे घटिया दर्जे का विवाह मानते थे। फिर भी हिन्दू जनता की परम्परागत भावनाओं का ध्यान में रखते हुए वे कानून द्वारा १२ वर्ष की ही कन्याओं के विवाह की निम्नतम सीमा निर्धारित करना उचित समझते थे। उन्होंने इसलिए शारदा साहब के विधेयक में इस प्रकार के संशोधन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि व्यवस्था में प्रतिनिधियों के लिए हिन्दू जनता की भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है, बहुत से ऐसे प्रगतिशील देश हैं जहाँ विवाह की निम्नतम आयु बारह वर्ष ही है, और यहाँ भी यही आयु निर्धारित करना उचित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन देशों में विवाह रद्द कर दिये जाते हैं, वहाँ किसी को दंडित नहीं किया जाता, जबकि प्रस्तुत विधेयक में दण्ड का भी विधान है। वे भी बाल-विवाह और संसर्ग के कुप्रभाव से समाज की रक्षा के लिए सहयोग की सम्मति आयु (एज आफ कंसेंट) १४ वर्ष निर्धारित करने को तैयार थे^२। मालवीयजी का संशोधन नामजूर हो गया, और मूल विधेयक केन्द्रीय असेम्बली ने बहुमत से पास कर दिया।

१. वही सन् १९२७, जि० ५, पृ० ४४३९-४४४६।

२. वही, सन् १९२९, जि० ५, पृ० १०४२-१०५४, १२९५-१२९६।

इसी तरह जब आर्य-समाजियों के आगह पर “आर्य विवाह विधेयक” केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्तुत हुआ, तब मालवीयजी ने यह कह कर उसका विरोध किया कि आर्य समाजी तो हिन्दू-समाज का अंग हैं, उनके लिए अलग विवाह सम्बन्धी कानून पास करना नामुनासिव है। पर पंडित हृदयनाथ कुजूरु ने इस विधेयक का भी डट कर समर्थन किया।

इसी तरह सन् १९२९ में जबकि मालवीयजी ने यह कह कर कि असेम्बली को हिन्दुओं के पर्सनल-ला में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हिन्दू-ला इनहेरिटेंस अमडमेन्ट बिल (हिन्दुओं के कानून विरासत में सशोधन विधेयक) का विरोध किया, उनकी पार्टी के अधिकांश सदस्यों ने उसके पक्ष में अपना मत प्रदान किया।

पर फरवरी सन् १९२८ में मालवीयजी ने अछूतोंद्वारा के निमित्त जयकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का तथा लाला लाजपत राय द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट का पूरे तौर पर समर्थन किया। श्री एम० आर० जयकर का प्रस्ताव था कि “असेम्बली गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को संस्तुति करती है कि वह अछूतों तथा दूसरे दलित वर्गों की शिक्षा के निमित्त तथा उनको सब सरकारी नौकरियों, विशेषतः पुलिस रॉबिस, को खोलने के निमित्त विशेष सुविधाएँ देने के लिए आदेश निकाले।” लाला लाजपत राय ने प्रस्ताव किया कि इसके अन्त में यह जोड़ा जाय कि “असेम्बली गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल से यह भी संस्तुति करती है कि वह दलित वर्गों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय कोष से एक करोड़ रुपये मजूर करे, और यह आज्ञा निकाले कि वे सब कुएँ जो निजी नहीं हैं, वे सब सड़कें जो सार्वजनिक हैं, और वे सब संस्थाएँ जिनका सरकारी फण्डो से अंशतः या पूर्णतः आर्थिक प्रवध किया जाता है, दलित वर्गों के लिए खुली रहेंगी, तथा अछूतों की ओर उनकी जो अछूत तो नहीं है पर सरकारी विवरण में दलित वर्गों में शामिल किये गये हैं, एक सूची तैयार की जायेगी।”

प्रस्ताव और सशोधन के पक्ष में बोलते हुए मालवीयजी ने शिक्षा की ओर सरकार का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सन् १९१६ में ही भारतीय विधान कौंसिल में कहा था कि दलित वर्गों के उत्थान का प्रश्न शिक्षा पर निर्भर है, उन वर्गों में शिक्षा का प्रसार के लिए जो कुछ सरकार कर सकती है उसे वह करे। उस समय, मालवीयजी ने कहा, उन्होंने यह भी कहा था कि “सरकार और समाज के स्कूल दलित वर्गों के लिए उतने ही खुले हो जितने दूसरे वर्गों के लिए।” उन्होंने कहा कि यदि सरकार

प्रति वर्ष कुछ करोड़ रुपये उनकी शिक्षा पर खर्च करने को तैयार हो, तो उनकी समस्या सुलझ जाय। खेद है कि सरकार उनके प्रति सहानुभूति तो बहुत प्रकट करती है, पर उनके उत्थान के लिए करती बहुत कम है। मालवीयजी ने सरकार की शिक्षा-नीति की कड़ी आलोचना करते हुए आशा प्रकट की कि सरकार प्रस्ताव और संशोधन दोनों स्वीकार कर लेगी।^१

सरकार का उत्तर संतोषजनक नहीं था। सरकारी प्रवक्ता श्री गिरजाशंकर वाजपेयी ने लाला लाजपत राय का संशोधन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सन् १९१९ के संविधान के अंतर्गत शिक्षा हस्तान्तरित विषय है, जिसका प्रबंध प्रान्तीय विधान सभा को उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में है, और जिनपर केन्द्रीय सरकार का कोई विशेष अधिकार या नियंत्रण नहीं है। सरकार, उन्होंने कहा, अछूतों और अन्य दलितों के उत्थान के लिए प्रयत्न करती रही है, और आगे भी करती रहेगी।

एक अंग्रेज सदस्य ने प्रस्ताव किया कि जयकर साहव के प्रस्ताव में से पुलिस सर्विस का विशेष उल्लेख निकाल दिया जाय। यह संशोधन सदन ने स्वीकार कर लिया। पर लाला लाजपत राय का संशोधन २४ के विरुद्ध ४७ रायों से रद्द हो गया, और सरकार की अनुमति से जयकर साहव का मूल प्रस्ताव "पुलिस" शब्द निकाल देने पर मजूर हो गया।

लाला लाजपत राय के संशोधन रद्द होने का मूल कारण स्वराज्य पार्टी की उपेक्षा थी। जबकि मालवीयजी की पार्टी के सब सदस्यों ने, औद्योगिक सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास ने, मनोनीत मजदूर नेता एन० एम० जोशी ने, ईसाई पादरी एन० सी० चटर्जी ने, तथा अपने तीन मुसलमान साथियों के साथ जिना साहव ने लाला लाजपत राय के संशोधन के पक्ष में वोट दिये, स्वराज्यपार्टी के सदस्य मतदान के समय असेम्बली में उपस्थित ही नहीं थे। अंग्रेज सदस्यों ने सरकारी और मनोनीत सदस्यों के साथ संशोधन के विरोध में राय दी।

मुद्रा विधेयक

भारत सरकार सन् १९२६ में ही स्वराज्य पार्टी के सदस्यों की अनुपस्थिति में एक विधेयक द्वारा भारतीय रुपये की दर सोलह पैस के बजाय अठारह पैस कर देना चाहती थी। पर मतदान के समय स्वराज्य पार्टी के सदस्यों के उपस्थित हो जाने पर विधेयक पास नहीं कराया जा सका, और समस्या पर विचार नये

निर्वाचन तक टल गया। सन् १९२७ में सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया, भारतीय नेताओं और विधायकों ने फिर इसका विरोध किया।

मालवीयजी ने करेसी बिल (मुद्रा विधेयक) पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार की वित्त नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अपने ताबे भाषण में राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्र के विद्वानों, तथा सरकारी अफसरों के वक्तव्यों का उद्धरण देते हुए सिद्ध किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित भारत की मुद्रा नीति भारत के हित के बजाय ब्रिटेन के हित को लाभान्वित करती रही है। उन्होंने माँग की कि देश में स्वर्णमुद्रा के साथ स्वर्णमान प्रतिष्ठित किया जाय, भारतीय स्वर्णमुहर तील और शुद्धता में ब्रिटिश अशरफी सावरन के समान हो, दोनों की एक जैसी स्थिति हो, एवं जो भी चाहे वह अपने सोने को टकसाल द्वारा स्वर्ण मुहर में गढ़वा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने रुपये के सिक्के में दस आने की चाँदी लगाकर छः आने की वचत इसलिए ही की थी कि आगे चलाकर मुद्रा-अतिरिक्त निधि (रिजर्व फण्ड) द्वारा स्वर्णमुद्रा चालू की जाय, और बहुत से विरोधज्ञों ने इसकी रालाह भी दी थी। पर सरकार ने ऐसा न करके भारी अनर्थ किया है, और भारत के हितों को हानि पहुँचायी है।^१

उन्होंने यह भी माँग की कि सम्प्रति रुपये की दर अठारह पैसे न बढ़ाकर सोलह पैसे ही कायम रखनी जाये। उन्होंने ब्रिटेन के भारत-मन्त्री तथा भारत के वित्त-सदस्य पर आरोप लगाया कि वे अंग्रेजों की हित-वृद्धि के लिए ही रुपये की दर अठारह पैसे निर्धारित करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस तरकीब से भारत में ब्रिटिश माल १२½ प्रतिशत सस्ता हो जायगा, और उसकी खपत बढ़ जायेगी, तथा भारत में रहनेवाले अंग्रेजों को भी अपना रुपया ब्रिटेन भेजते समय अधिक ब्रिटिश मुद्रा मिल सकेगी। उनकी निश्चित धारणा थी कि अठारह पैसे की दर भारत के किसानों और औद्योगिकों को हानिकारक सिद्ध होगी। वित्तीय संरक्षण साढे बारह प्रतिशत घट जाने के कारण विदेशी माल से प्रतियोगिता (होड) बढ़ जायेगी, और भारतीय उद्योगों की क्षति होगी। किसानों को भी निर्यात में हानि उठानी पड़ेगी। उन्हें सोलह पैसे के बजाय अठारह पैसे के लिए एक रुपया मिल सकेगा। सरकारी अफसरों का कहना था कि रुपये की दर ऊँची कर देने से मजदूरों को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें माल सस्ते दामों में मिल सकेगा। इसके जवाब में मालवीयजी का कहना था कि "मजदूरों का हित रोजगार में है, उन्हें काम तभी मिल सकेगा, जब पूँजीपति

उद्योगों में अपनी पूँजी लगाने में लाभ देखेंगे, और यह तभी हो सकेगा जब उद्योग उन्हें उचित मुनाफा छोड़े। अगर आप उद्योगों को हानि पहुँचाते हो, अगर आप विदेशी उद्योगों की होड़ को अधिक तीव्र (गंभीर) बना देते हो, और अगर आप उसके (पूँजीपति) लिए उद्योग चलाना निरर्थक बना देते हो, तो उद्योग खत्म हो जायगा और उसके साथ ही मजदूर की मजदूरी भी जाती रहेगी। इस तरह पूँजीपतियों के साथ-साथ मजदूरों को भी क्षति पहुँचेगी।”^१

केन्द्रीय असेम्बली में ६५ सदस्यों ने सोलह पेंस की दर के पक्ष में, और ६८ सदस्यों ने इसके विपक्ष में वोट दिये, और इस तरह राष्ट्रवादियों का संशोधन स्वीकार नहीं हो सका।

अन्तिम बार मुद्रा विधेयक पर बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि मतदान से यह प्रत्यक्ष है कि जनता के अधिकांश प्रतिनिधि सोलह पेंस की दर के पक्ष में हैं, उन्हें सरकारी सदस्यों और सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के वोटों के कारण ही पराजित होना पड़ा है। उन्होंने उस संवैधानिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की, जिसके अन्तर्गत सरकार केन्द्रीय असेम्बली में लगभग दो तिहाई निर्वाचित सदस्यों को इस तरह पराजित कर सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संविधान, जो इतने स्थायी सिविल सर्वेन्टों (सरकारी नौकरों) को असेम्बली में बैठने का तथा सरकार को इतने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार देता है, अवश्य ही “दोषपूर्ण” और “अनैतिक” है। उन्होंने माँग की कि सरकारी सदस्यों को अपने इच्छानुसार वोट देने की छूट दी जाय^२, पर सरकार ने मालवीयजी की इस माँग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

अन्त में ५१ वोटों के विरुद्ध ६५ वोटों से सरकार द्वारा प्रस्तुत मुद्रा विधेयक पास हो गया। इस समय जहाँ एक अग्रज उद्योगपति तथा सभी भारतीय औद्योगिकों ने और सभी राष्ट्रवादी सदस्यों ने विधेयक के विरुद्ध वोट दिया, वहाँ मिस्टर मुहम्मद अली जिना, मियाँ मुहम्मद शफी, औद्योगिक इब्राहीम रहमतुल्ला तथा खान बहादुर सरफराज हुसेन खाँ को छोड़ कर जिना साहब की इंडिपेंडेंट पार्टी के मुसलमान सदस्यों ने विधेयक के विरुद्ध वोट नहीं दिये। यदि इंडिपेंडेंट पार्टी का भी पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हो जाता तो सरकार की पराजय निश्चित थी।

१. वही, सन् १९२७, जि० २, पृ० १७७३-१७७९।

२. वही, सन् १९२७, जि० २, पृ० २१३८।

पण्डित मोतीलाल नेहरू स्वयं यह निश्चय नहीं कर पाते थे कि रुपये की कौन-सी दर व्यावहारिक और देश के हित में होगी। वे संभवतः यह चाहते थे कि कानून द्वारा कोई दर निश्चित न की जाय, और व्यापार की स्वतंत्र प्रक्रिया द्वारा विनमय का दर व्यवस्थित हो। पर उन्होंने अपने दूसरे साथियों के साथ सोलह पैसे के पक्ष में वोट दिया। अन्त में उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि विधेयक वापस ले लिया जाय। पर जब सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई, तब उन्होंने उसके विपक्ष में वोट दिया।

फौलाद संरक्षण विधेयक

सन् १९२१ में फौलाद और लोहा उद्योग के वित्तीय संरक्षण के प्रश्न पर विचार करने के बाद टेरिफ बोर्ड ने बाउन्टी (वदान्यता) दिये जाने की सिफारिश की। सन् १९२३ में टेरिफ बोर्ड ने इस उद्योग के संरक्षण के प्रश्न पर फिर विचार किया। इस बार उसने सस्तुति की कि आयात शुल्क द्वारा वित्तीय संरक्षण की व्यवस्था की जाय। उसने सस्तुति की कि ब्रिटेन के सामान पर एक बुनियादी आयात शुल्क लगाया जाय, और दूसरे देशों के माल पर अधिक शुल्क लगाया जाय। इन सस्तुतियों के आधार पर सरकार ने फौलाद विधेयक तैयार करके असेम्बली में स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया।

मालवीयजी का विरोध

मालवीयजी टाटा के कारखाने के महत्वपूर्ण योगदान के बहुत प्रशंसक थे, और आयात शुल्क द्वारा भारतीय फौलाद उद्योग का वित्तीय संरक्षण उचित समझते थे। पर उनके विचार में प्रस्तावित विधेयक में आवश्यकता से अधिक संरक्षण की व्यवस्था की गयी थी, और उपभोक्ताओं को परिस्थिति की मांग से कहीं अधिक बोझ वहन करने को बाध्य किया जा रहा था। उनकी धारणा थी कि इतने अधिक संरक्षण से अन्य उद्योगों पर भी निरर्थक बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इस विधेयक में अन्य देशों के माल की तुलना में ब्रिटेन के माल पर आयात शुल्क की दर कम थी। मालवीयजी और सभी राष्ट्रवादी सदस्य इस भेद-मूलक शुल्क व्यवस्था के विशेष रूप से विरोधी थे। उनका कहना था कि अन्य यूरोपियन औद्योगिकों की तुलना में ब्रिटेन के औद्योगिक अपना माल सस्ते दामों में बेच सकें इसके लिए उन्हें अधिमानिक (प्रिफरेंशियल, तरजीही) शुल्क द्वारा मदद देना इस असेम्बली का काम नहीं है।" ब्रिटेन के यूजीपजियों ने

लाभ के निमित्त भारतीय उपभोक्ताओं को अधिक बोझ वहन करने के लिए बाध्य करना ये सर्वथा अनुचित समझते थे ।^१

कांग्रेस स्वराज्य पार्टी और जयपूर माहव का दल भी इस दान से विल्कुल सहमत था । पर मिस्टर मुहम्मद अली जिना और उनकी पार्टी इम राय से पूरे तौर पर सहमत नहीं थी । उन्होंने अभिशप्तक मुक्त व्यवस्था का समर्थन किया, और उनकी पार्टी की मदद से केन्द्रीय असेम्बली में विशेषतः पाग हो गया ।

देशी उद्योगों का संरक्षण

मालवीयजी ने सूनी तागा को आगमन मुक्त द्वारा संरक्षण दिये जाने का समर्थन करते हुए भाग की हिमिल के कपड़े का भी इसी तरह संरक्षण किया जाय । इस समय उन्होंने कहा कि "हमें मिन के उद्योग और कपड़े के उद्योग, दोनों को राष्ट्रीय उद्योग" समझना होगा, और दोनों को गन्तुमान और सहयोग देना होगा । उन्होंने यह भी कहा कि भारत में तैयार किये गये सूनी तागे से घना वर्ग ही स्वदेशी समझा जा सकता है । उन्होंने जापान की औद्योगिक प्रगति की ओर संस्कार का ध्यान आकृष्ट करने हुए सरकार से अनुरोध किया कि वह "देश के उद्योगों को प्राथमिक संरक्षण देने में और उन्हें बढ़ा करने में जनता के साथ मिलकर काम करे ।"^२

अमेनिक-विमानन-विधेयक (मिनिन एविएशन बिल) पर बोलते हुए मालवीयजी ने कहा . "भारतीयों के हित में भारत के गौरव के लिए विमानन का विकास किया जाय ।" अमेनिक विमानन या तो सरकारी कारोबार हो, या एक भारतीय कम्पनी द्वारा, जिसके अधिकांश डाइरेक्टर भारतीय हों, संचालित हो ।^३

रिजर्व बैंक विधेयक

सन् १९२७ में ही सरकार के वित्त सदस्य ने रिजर्व बैंक विधेयक प्रस्तुत किया । इस पर सन् १९२८ तक वाद-विवाद चलता रहा । सरकार रिजर्व बैंक को "क्षेयर कैपिटल बैंक" के रूप में गठित करके उसे राजकोष और मुद्रा का प्रबंध सौंपना चाहती थी । वह यह भी चाहती थी कि सब अनुसूचित बैंकों की

१. वही, सन् १९२७, जि० १, पृ० १०८१ ।

२. वही, सन् १९२७, जि० ५, पृ० ४१०६ ।

३. वही, सन् १९२७, जि० २, पृ० १५६७ १५७० ।

पूँजी का एक अंश रिजर्व बैंक में जमा रहे, ताकि किसी बैंक की दुर्व्यवस्था के कारण देश को वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। वह इस बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और तीन डाइरेक्टरों को स्वयं नियुक्त करना चाहती थी, और वह व्यापार मण्डलों और केन्द्रीय कोऑपरेटिव बैंक को भी कतिपय डाइरेक्टरों को निर्वाचित करने का अधिकार देने को तैयार थी, पर वह डाइरेक्टरों के बोर्ड में विधान सभाओं को प्रतिनिधित्व देने के विरुद्ध थी। उसका विचार था कि बैंक को राजनीति से अलग रखा जाय, और इसलिए व्यवस्थापिका द्वारा कोई डाइरेक्टर निर्वाचित या नियुक्त न किया जाय। इस बैंक की स्थापना के बाद ब्रिटेन के भारत-मन्त्री अपना आर्थिक नियंत्रण कम करने को तैयार थे।

केन्द्रीय असेम्बली के सभी सदस्य रिजर्व बैंक के महत्त्व को स्वीकार करते थे, और सुसंघटित केन्द्रीय बैंक की स्थापना के पक्ष में थे। पर उसके संघटन की रूप-रेखा के सम्बन्ध में सरकार और अधिकांश निर्वाचित सदस्यों में गहरा मतभेद था, जिसके कारण उस समय बैंक स्थापित ही नहीं हो सका। जबकि सरकार "शेयर कैपिटल बैंक" स्थापित करना चाहती थी, असेम्बली के राष्ट्रवादी सदस्य "स्टेट बैंक" के पक्ष में थे। प्रारम्भ में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास प्रभृति औद्योगिक "शेयर कैपिटल बैंक" के पक्ष में दिखायी देते थे, पर अन्त में वे भी स्टेट बैंक के विचार के पक्ष में हो गये। असेम्बली के अधिकांश निर्वाचित सदस्य चाहते थे कि रिजर्व बैंक पर विधान मंडल का भी समुचित नियंत्रण हो, और उसके संचालन में जनता के प्रतिनिधियों का भी हाथ हो, और इसलिए उनकी मांग थी कि रिजर्व बैंक के कम से कम तीन डाइरेक्टर केन्द्रीय असेम्बली और राज्य सभा (कौंसिल आफ स्टेट) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जायें, तथा कुछ डाइरेक्टरों को प्रान्तीय विधान कौंसिलों के सदस्य चुने। सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। तिस पर भी प्रवर समिति के अधिकांश सदस्यों ने इसकी संस्तुति की।

केन्द्रीय असेम्बली में वित्त-सदस्य सर वेसिल ब्लेकट ने प्रवर समिति की अल्प संख्यक रिपोर्ट की संस्तुतियों का समर्थन किया। मालवीयजी ने अधिसंख्यक रिपोर्ट को पेश किया। उन्होंने वित्त-सदस्य की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि संसार में कोई देश ऐसा नहीं जहाँ दो केन्द्रीय शेयर कैपिटल बैंक हों। ऐतिहासिक कारणों से बैंक आफ इंग्लैंड अवश्य शेयर कैपिटल बैंक है, पर कई अन्य देशों में केन्द्रीय बैंक का स्वरूप बहुत अंश में स्टेट बैंक जैसा है। स्टेट बैंक के विचार का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा : "स्टेट बैंक भारत की सारी जनता

का बैंक होगा, भारत की सम्पूर्ण जनता उसकी पूजी की मालिक होगी, जो कुछ नफ़ा उसे प्राप्त होगा, वह सरकार द्वारा भारत की सारी जनता में वँटेगा^१; दूसरी ओर शेयर कैपिटल बैंक मुट्ठी भर धनियो की सम्पत्ति होगा, उनके हित में ही उसका संचालन होगा। उन्होंने बताया कि इसी समय एक पूजीपति एक करोड़ रुपये के शेयर खरीदने को तैयार है, कुछ दूसरे पूजीपति भी उन्हीं की तरह एक बड़ी रकम के शेयर खरीद सकते हैं। ऐसी दशा में, उन्होंने कहा, “रिजर्व बैंक जनता का बैंक नहीं होगा। फिर राजकोष का प्रबन्ध, मुद्रानीति का निर्धारण, तथा दूसरे बैंको की पूँजी के एक अंश का संरक्षण उसके सुपुर्द करना कैसे उचित समझा जा सकता है? ‘शेयर कैपिटल बैंक’ का संचालन देश की जनता के हित में ही होगा, यह कैसे कहा जा सकता है?”^२

मालवीयजी ने बताया कि बैंको के अधिकांश शेयर-होल्डर्स (हिस्सेदार) बैंक के प्रबंध में कोई सार्थक भाग या दिलचस्पी नहीं ले पाते, सारा संचालन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में ही होता है और उनकी हितदृष्टि से ही उसकी नीति निर्धारित होती है।^३ प्रवर समिति के बहुसंख्यको की ओर से यह माग पेश करते हुए कि केन्द्रीय असेम्बली और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों को रिजर्व बैंक के तीन डाइरेक्टरो को चुनने का अधिकार हो, उन्होंने कहा कि यदि सरकार गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और दो डाइरेक्टर नियुक्त करती है, तो जनता के प्रतिनिधियों को भी कुछ डाइरेक्टर चुनने का अधिकार मिलना ही चाहिए। देश का वित्तीय नियंत्रण अवश्य ही जनता के प्रतिनिधियों को हस्तान्तरित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों के १३२ निर्वाचित सदस्यों द्वारा जिस तरह उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से और आसानी से डाइरेक्टरो का चुनाव हो सकता है, उतना सारे देश में बिखरे शेयर-होल्डरो द्वारा नहीं हो सकता।

उन्होंने अन्त में जोरदार शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से सरकार रिजर्व बैंक गठित करना चाहती है उसका अर्थ तो यह होगा कि एकमात्र देश की जनता के हित में बैंक को चलाने के बजाय वह इस तरह चलाया और संचालित किया जायगा जिससे उन हितों की उपेक्षा हो, उनका बलिदान हो, और

१. वही, सन् १९२७, जि० ४, पृ० ३४७१।

२. वही, सन् १९२७, जि० ४, पृ० ३४६९।

३. वही, सन् १९२७, जि० ४, पृ० ३४६९।

असेम्बली के पास बैंक की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने और रोकने के पर्याप्त अवसर और उपाय भी न हो ।^१

राष्ट्रवादी तत्त्वों और सरकार में संघर्ष चलता ही रहा । वित्त-सदस्य सर वेसिल ब्लेकट ने महसूस किया कि बहुत से निर्वाचित सदस्यों के तगड़े विरोध के कारण विधेयक का पास होना कठिन है । उन्होंने सोचा कि यदि सरकार अपनी बात पर डटी रहती है, तो वह पराजित भी हो सकती है, और यदि शक्तिशाली राजनीतिक और आर्थिक हितों के विरोध के बावजूद वह दो-एक वोट से जीत भी गयी, तो यह विजय रिजर्व बैंक के हित में नहीं होगी ।^२ यह सोचकर उन्होंने घोषित किया कि वह रिजर्व बैंक को स्टेट बैंक के रूप में स्थापित करने को तैयार है, बशर्ते कि असेम्बली के निर्वाचित सदस्य डाइरेक्टरी के निर्वाचन के सम्बन्ध में श्री श्रीनिवास ऐयंगर द्वारा प्रस्तुत "स्टाक होल्डर योजना" स्वीकार कर लें, जिसमें प्रत्येक होल्डर को केवल एक वोट देने का अधिकार था, और जो अपने वोटों से कुछ ट्रस्टियों को चुनेंगे जो रिजर्व बैंक के डाइरेक्टर चुनेंगे । वित्त-सदस्य का यह सुझाव बहुत से निर्वाचित सदस्यों को मजूर था और यदि वे चाहते, तो इस रूप में विधेयक आसानी से पास हो सकता था । पर उन्होंने विधेयक पर अन्तिम निर्णय अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया ।

इसके बाद उन्होंने लन्दन जा कर विधेयक के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री से बातचीत की । वापस लौटने पर उन्होंने १ फरवरी सन् १९२८ को दूसरा रिजर्व बैंक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जिसमें उसे शेयर-होल्डर बैंक का रूप दिया गया था, पर असेम्बली के अध्यक्ष विट्टल भाई पटेल ने ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स की परम्पराओं के आधार पर उसकी अनुमति नहीं दी, तब पुराने विधेयक के ऊपर ही विचार प्रारम्भ हुआ ।

प्रवर समिति की बहुसंख्यक रिपोर्ट की संस्तुति के अनुसार पुराने विधेयक की धारा ८ में यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि बैंक के तीन डाइरेक्टर केन्द्रीय विधान मण्डल द्वारा चुने जायें । यह संशोधन ४९ वोटों के मुकाबले में ५० वोटों से अर्थात् एक वोट के बहुमत से नामजूर हो गया । इसके बाद पूरी धारा ८ पर वोट लिये गये, और यह धारा एक वोट से अर्थात् ४८ वोटों के

१. वही, सन् १९२७, जि० ४, पृ० ३४७५ ।

२. कोटमेन : इंडिया इन १९२७-२८, पृ० २७ ।

मुकाबले में ४९ वोटो से नामंजूर हो गयी। जहाँ सरकारी सदस्यों ने, श्री एन० एम० जोशी को छोड़कर अन्य मनोनीत सदस्यों ने, तथा ब्रिटिश व्यापार मंडलो के प्रतिनिधियों ने धारा ८ के पक्ष में वोट दिये, वहाँ नेशनलिस्ट पार्टी के करीब करीब सभी सदस्यों ने विपक्ष में वोट दिये। जिना साहब के नेतृत्व में गठित इंडिपेंडेंट पार्टी के भी बहुत से सदस्यों ने, तथा मर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, सर आर० के० षण्मुखम् चेटी, मिस्टर फजल इब्राहीम रहमतुल्ला ने भी विरोध में ही वोट दिये। कांग्रेस स्वराज्य पार्टी के उपनेता श्री श्रीनिवास ऐयंगर तथा उसके बहुत से दूसरे सदस्यों ने भी सरकार के विपक्ष में राय दी। पर किसी कारण से स्वराज्य पार्टी के नेता पण्डित मोती लाल नेहरू और उसके लगभग पचास प्रतिशत सदस्यों का सहयोग विरोध पक्ष को प्राप्त नहीं हो सका।^१

दूसरे दिन अर्थात् १० फरवरी को वित्त-सदस्य सर वेसिल ब्लेकट ने निर्वाचित सदस्यों पर असहयोग का दोपारोपण करते हुए रिजर्व बैंक विधेयक वापस लेने की घोषणा की। इस अवसर पर जमुनादास मेहता, मिस्टर जिना, मिस्टर फजल इब्राहीम रहमतुल्ला, श्री षण्मुखम् चेटी, मालवीयजी और लाला लाजपत राय ने कड़े शब्दों में सरकार के व्यवहार की आलोचना की, और वित्त-सदस्य से अधिक भारत-मन्त्री को इसके लिए मुख्य रूप से दोषी बताया। दूसरी ओर से यूरोपियनों के प्रतिनिधि मिस्टर एच० सी० कोक ने सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक जैसे आर्थिक संस्थान को राजनीति से अलग रखना ही व्यापारी वर्ग उचित समझता है।

मालवीयजी ने सरकार के इस व्यवहार को भारत-मन्त्री की क्रूरता बताते हुए कहा कि यह वित्तीय स्वशासन के सिद्धान्त के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि हम इस विधेयक को अपने ऊपर लादने देते तो यह बैंक जनता का हित-वर्धक बैंक नहीं होता, बल्कि ऐसा बैंक होता जो जनता को उस तरह से राष्ट्रीय जीवन का निर्माण नहीं करने देता जिस तरह उसे विकसित करना चाहिए।^२ उन्होंने कहा कि वे "वित्तीय नियंत्रण को भारत-मन्त्री से भारत सरकार को नहीं, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों को हस्तान्तरित कराना चाहते हैं।"^३

श्री जमनादास मेहता ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक के पास हो जाने पर तो जनता के प्रतिनिधियों को मुद्रा नीति की परीक्षा करने के

१. लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट, सन् १९२८, जि० १, पृ० २१२।

२. लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट, सन् १९२८, जि० १, पृ० २७६।

३. वही, सन् १९२८, जि० १, पृ० २७६।

उतने भी अधिकार नहीं रह जाते जितने इस समय हैं।^१ मिस्टर फजल इब्राहीम रहमतुल्ला ने कहा कि जब बैंक जनता के हित के लिए है, तब जनता के प्रतिनिधियों को सरकार से अपनी बात मनवाने का अवश्य अधिकार है, और सरकार को जनता के प्रतिनिधियों पर विधेयक लादने का या यह कहने का अधिकार नहीं कि वे सदन के सशोधनों और सुझावों को मानने को तैयार नहीं हैं।^२ मिस्टर पण्मुखम चेट्टी ने कहा कि "प्रातः काल वित्त-सदस्य की घोषणा राहत, अपमान और दुःख की भावनाओं से ग्रहण की गयी है, राहत क्योंकि हमें उपहास और विडम्बना से छुटकारा मिल जाता है, दुःख क्योंकि हम वित्त शासन की सम्भावना से वंचित कर दिये गये हैं, और अपमान क्योंकि हम ह्वाइट-हाल के तानाशाह के शिकार बना दिये गये हैं।"^३

लाला लाजपतराय ने कहा : "जबतक वे (सरकार) अल्प संख्या की मदद से इस सदन पर अपने सुधार लादने का इरादा करेंगे, जैसा कि उन्होंने मुद्रादर के प्रश्न पर किया है, तब तक उन्हें इस सदन में और बाहर जनता के प्रतिनिधियों के ठोस विरोध का सामना करना होगा। अगर सरकार जनमत का विरोध करती है, तब जनमत सरकार का विरोध करेगा।"^४ मिस्टर कोक के भाषण का जवाब देते हुए लाला लाजपत राय ने कहा कि यूरोपीयन व्यापारियों की राय को देश की राय समझने की आदत छोड़ देना चाहिए, और जितनी जल्दी ही इसे छोड़ दिया जाय उतना ही अच्छा है।^५ उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीयन व्यापारी समाज की सहायता से और उन थोड़े से सदस्यों की राय से जिन्हें वे (सरकार) अपने साथ फुसला कर मिला सके, इस देश में शासन करने का प्रयत्न निष्फल होगा और यथासंभव मतैक्य और शक्ति से उसका विरोध किया जायगा।^६ यदि सरकार एक वोट से विपक्ष को पराजित कर सकती है, तो विरोधी दल भी एक वोट से उसे हरा सकता है। कुछ थोड़े से व्यक्तियों को छोड़कर, जो किसी न किसी कारण से सरकार के साथ हैं, सभी जानकार भारतीय सरकार की राय के विरुद्ध हैं, और वे जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब यूरोपीयन व्यापारी राजनीति का प्रश्न उठाते हैं

१ वही, सन् १९२८, जि० १, पृ० २७४।

२ वही, सन् १९२८, जि० १, पृ० २८४।

३ वही, सन् १९२८, जि० १, पृ० २८०।

४ वही, सन् १९२८, जि० १, पृ० २७८-२७९।

५ वही, सन् १९२८, जि० १, पृ० २७९।

६ वही, सन् १९२८, जि० १, पृ० २७९।

तो क्या वे कह सकते हैं कि उनका अपना व्यापार राजनीति से मुक्त है। इस अवसर पर भी कम से कम प्रत्यक्ष रूप से असेम्बली को पण्डित मोतीलाल नेहरू की प्रतिक्रिया का पता नहीं चल सका।

बजट पर बहस

बजट और वित्त विधेयक की बहसों में केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों ने काफी दिलचस्पी और तत्परता से भाग लिया। यद्यपि बजट के दो तिहाई से अधिक भाग पर केन्द्रीय असेम्बली को वोट करने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी करीब-करीब सभी विभागों से सम्बन्धित किसी न किसी माँग पर केन्द्रीय असेम्बली को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था, और उन माँगों पर साकेतिक कटौती के प्रस्ताव पेश करके असेम्बली के सदस्य प्रशासन के विभिन्न विभागों को नीति-रीति और क्रियाकलापों की समीक्षा कर सकते थे। इसी तरह वित्त विधेयक में संशोधन पेश करके वे सरकार की वित्त नीति पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर सकते थे। असेम्बली के सदस्यों ने अपने इन दोनों अधिकारों का यथासंभव प्रयोग करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने कटौती के प्रस्तावों तथा वित्तीय संशोधनों द्वारा प्रशासन को लोकप्रिय दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया। उन्होंने माँग की कि रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाय, रेलवे की सब सेवाओं का भारतीयकरण हो, तीसरे दर्जे का भाड़ा कम किया जाय, तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाय, पोस्टकार्ड और लिफाफों की कीमत कम की जाय, नमक-कर घटाया जाय, देश की औद्योगिक व्यवस्था का संरक्षण और विस्तार वित्त-नीति का एक प्रमुख लक्ष्य हो, आयात शुल्क और निर्यात शुल्क को निर्धारित करते समय इस लक्ष्य पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। उन्होंने यह भी माँग की कि प्रशासनिक लोक सेवाओं तथा सेना का भारतीयकरण किया जाय।

सरकार पर अविश्वास

सन् १९१९ की संवैधानिक व्यवस्था में केन्द्रीय असेम्बली को गवर्नर-जनरल या उसकी कार्य परिषद के सदस्यों के वेतन को मजूर करने का कोई अधिकार नहीं था। पर उनकी यात्राव्यय की मद पर वोट देने का अर्थात् उससे संबंधित माग को स्वीकार करने का असेम्बली को अधिकार अवश्य था। इस मद की माग पर कटौती का प्रस्ताव पास करके असेम्बली सरकार की नीति के विरुद्ध अविश्वास प्रकट कर सकती थी। असेम्बली के सभी प्रगतिशील तत्वों ने मिल कर प्रत्येक वर्ष इस प्रकार अपना अविश्वास प्रकट किया।

वित्त विधेयक को मजूर किया जाय अथवा नहीं, इस बात में भारतीय सदस्यों में काफी मतभेद था। मुस्लिम सेट्रल पार्टी के साथ-साथ जिना साहब की इंडिपेंडेंट पार्टी भी वित्तविधेयक को बिल्कुल रद्द कर देना ठीक नहीं समझती थी। भारतीय औद्योगिक वर्ग के सदस्यों की भी यही राय थी। पर कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी वित्तविधेयक को नामंजूर करने के पक्ष में थी, यद्यपि इन दोनों पार्टियों के कुछ सदस्य इस विषय पर अपना वोट नहीं देते थे। मालवीयजी वित्तनीति की आलोचना करते हुए वित्तविधेयक को नामंजूर करने के पक्ष में अपना मत देते रहेते थे।

मार्च सन् १९२७ में वित्तविधेयक का विरोध करते हुए मालवीयजी ने कहा : "टैक्सो द्वारा जो धन वसूल किया जाता है उसके व्यय को सुव्यवस्थित करने का जब हमें अधिकार नहीं, तब टैक्सो के लगाने का उत्तरदायित्व भी हम नहीं ले सकते।"^१ गाँवों की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने माँग की कि नयी दिल्ली के निर्माण पर बहुत-सा रुपया खर्च करने के बजाय गाँवों की दशा सुधारने में, तथा भारतीय जनता को औद्योगिक शिक्षा और शिल्पविज्ञान की शिक्षा देने में अधिक रुपया खर्च किया जाय।

१७ मार्च सन् १९२८ को असेम्बली को वित्तविधेयक नामंजूर करने की सलाह देते हुए मालवीयजी ने कहा कि युद्ध के बाद भारी करारोपण (टेक्सेशन) उस समय बनाये रखना जबकि उसकी जरूरत नहीं है "जनता के प्रति अपराध है।"^२ उन्होंने सविधान की वित्तीय व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार के खर्चों के ऊपर केन्द्रीय असेम्बली का नियन्त्रण नगण्य है, क्योंकि जब कि दो तिहाई बजट पर असेम्बली का कोई अधिकार ही नहीं है, एक-तिहाई बजट के सम्बन्ध में भी असेम्बली के वोट की अवहेलना करते हुए गवर्नर-जनरल अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर कटौती की रकम पुनः स्थापित कर सकता है।^३ उन्होंने सरकार की मुद्रानीति की कड़ी आलोचना की^४, और बहुत क्षोभ के साथ कहा कि खर्चा कम करने के सम्बन्ध में सरकार ने इंचेप कमेटी की सस्तुतियों पर उचित ध्यान नहीं दिया।^५ उन्होंने कहा कि वित्तीय और सैनिक

१. वही, सन् १९२७, जि० ३, पृ० २७२७।

२. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १६५४।

३. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १६५३-१६५४।

४. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १६६६।

५. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १६५५।

प्रशासन इतना बुरा है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति यह कह सकता है कि “जब तक मौजूदा व्यवस्था कायम है तब तक सरकार की वफादारी उसका कर्तव्य नहीं है।”^१ उन्होंने कहा कि हमारी माँग है कि (१) वाइसराय की काँसिल केबिनेट की तरह व्यवहार करे, और जनता के प्रतिनिधियों को उत्तरदायी हो, तथा (२) अपने वित्तों पर भारत का नियन्त्रण हो।^२ उन्होंने कहा कि हम अपने देश के गृह विभाग, वित्त विभाग, उद्योग-विभाग और भारत सरकार के दूसरे विभागों पर कन्ट्रोल करने का अधिकार चाहते हैं।^३

५ मार्च सन् १९२९ को वजट पर बोलते हुए मालवीयजी ने फौजी खर्च को कम करने का आग्रह करते हुए कहा कि भीतर के दंगों को शान्त करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों का प्रयोग न किया जाय। उन्होंने माग की कि रुपये की दर फिर से १६ पैसे निर्धारित की जाय, तथा किसानों को बैंकों से कर्ज लेने की सुविधाएँ मुह्य्या की जायें। जनता की बहुत-सी कठिनाइयों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक शासन व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन नहीं होता, प्रशासक वर्ग जनता को उत्तरदायी नहीं बनाया जाता, तब तक जनता की कठिनाइयों का निराकरण और समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।^४

१२ मार्च सन् १९२९ को पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक्जीक्यूटिव काँसिल की माग में कटौती का प्रस्ताव पेश किया। मालवीयजी ने काफी कड़े शब्दों में सरकार की नीति-रीति, गतिविधि की समीक्षा करते हुए मोतीलालजी का समर्थन किया।^५ कटौती का प्रस्ताव ५२ वोटों के विरुद्ध ६३ वोटों से स्वीकार हो गया।

२० मार्च सन् १९२९ को वित्त विधेयक पर बोलते हुए मालवीयजी ने माग की कि अनिवार्य विलम्ब के बगैर देश में औपनिवेशिक स्वराज्य (डोमिनियन स्टेट्स) प्रतिष्ठित किया जाय।^६

सेना नीति

केन्द्रीय असेम्बली के आग्रह पर सन् १९२५ में लेफ्टिनेंट-जनरल सर एडरू स्कीन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी। इस कमेटी ने

१. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १६६८।
२. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १६६८।
३. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १६६९।
४. वही, सन् १९२९, जि० २, पृ० १५५६-१५६२।
५. वही, सन् १९२९, जि० २, पृ० १८००-१८०८।
६. वही, सन् १९२९, जि० २, पृ० २२४०-२२४६।

सर्वसम्मति से संस्तुति की कि आठ यूनिट की योजना को खत्म करके एक ऐसी योजना चालू की जाय जिसके जरिये सन् १९५२ तक भारतीय सेना में किंग-कमिशन अफसरों में आधी सख्या भारतीय अफसरों की हो। कमेटी ने सर्वसम्मति से यह भी संस्तुति की कि सन् १९३३ में भारत में सेंडहर्स्ट के स्तर का सैनिक कालेज खोला जाय, भारतीयों को सेना के सब विभागों में भरती किया जाय। उसने यह भी संस्तुति की कि जब तक भारत में सेंडहर्स्ट जैसा सैनिक विद्यालय नहीं खुलता अर्थात् १९३३ तक सेंडहर्स्ट कालेज में दस के स्थान पर बीस भारतीय प्रतिवर्ष भरती किये जायें। उसकी यह भी संस्तुति थी कि कान्वेल और वूलविच के सैनिक विद्यालयों में भी निश्चित सख्या में भारतीय नवयुवक भरती किये जायें, तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा का यथोचित प्रबन्ध किया जाय।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर सन् १९२६ में भारत सरकार के पास भेज दी थी। पर सरकार ने उसे अप्रैल सन् १९२७ में प्रकाशित किया। इस बीच में मार्च सन् १९२७ में बजट की सेना विभाग की मद पर केन्द्रीय असेम्बली में वृद्धि हुई।

पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने इस मद की मांग पर सौ सौ रुपये की कटौती के दो प्रस्ताव पेश किये। एक प्रस्ताव का सम्बन्ध “भारतीय प्रादेशिक सेना” (इंडियन टेरिटोरियल फोर्स) और दूसरे का सम्बन्ध सैनिक नीति और व्यय से था। कुंजरू साहब के ये दोनों प्रस्ताव ४४ वोटों के विरुद्ध ६३ वोटों से पास हो गये।

इसके बाद सेना विभाग की मांग पर बोलते हुए मालवीयजी ने सरकार की सेना-नीति की कड़ी आलोचना की, और मांग की कि सेना पर खर्चा घटाया जाय, सेना का बजट ५५ करोड़ रुपये से घटा कर चालीस करोड़ कर दिया जाय। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा का भार भारतीयों को स्वयं ग्रहण करना चाहिए, और इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। भारतीय सेना को, उन्होंने कहा, ब्रिटिश सेना की दुम नहीं होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा कौंसिल के गठन का सुझाव प्रस्तुत किया, और आशा व्यक्त की कि ‘भारतीय रियासतें भी इस प्रयास में साथ देंगी।’^१

यद्यपि जिना साहब और उनकी पार्टी के कतिपय सदस्यों ने कुंजरू साहब के कटौती के प्रस्तावों का समर्थन किया था, पर सेना विभाग की सारी मांग

रद्द करने की बात उन्हें ठीक नहीं जँची, और वे तटस्थ रहे। फिर भी ४६ रायों के विरुद्ध ५५ रायों से सारी मांग रद्द कर दी गयी।

२४ मार्च सन् १९२७ को वित्त विधेयक पर चोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि ब्रिटन का सैनिक कार्यालय एक तानाशाह है, जो भारत पर अत्याचार करता है, मनमाने ढंग पर अपनी आक्रमणशील साम्राज्यशाही योजनाओं को भारत पर लाद देता है, उसे साम्राज्यिक युद्धों में भाग लेने पर, और उसका खर्चा वहन करने पर मजबूर करता है। उन्होंने सरकार की अग्रवर्ती नीति (फारवर्ड पालिसी) की समीक्षा करते हुए कहा कि आक्रमणशील नीति का भारत की रक्षा से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, वह तो विशुद्ध साम्राज्यिक नीति है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार ही उसका लक्ष्य है। बहुत से अंग्रेज अफसरों और विशेषज्ञों के विचारों का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा कि अफगान युद्ध का सारा घर्षा भारत के वजाय ब्रिटन को वहन करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सेना के अंग के रूप में ही, तथा ब्रिटिश साम्राज्य के हित में ही गोरो सेना भारत में रहती है, और इसलिए उसका सब खर्चा ब्रिटन को ही वहन करना चाहिये।^१

स्कीन कमेटी की रिपोर्ट पर बहस

१ अप्रैल सन् १९२७ को स्कीन कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी, और २५ अगस्त को डाक्टर वी० एस० मुंजे ने केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्ताव पेश किया कि १५ वर्ष के अन्दर ही सेना के आधे उच्चाधिकारी भारतीय आफिसर बना दिये जायें। स्कीन की संस्तुतिओं के अनुसार भारतीय सेडहर्स्ट कालेज खोला जाय, और सेना के उन विभागों में भी भारतीय भरती किये जायें जिनमें वे अब तक भरती नहीं किये जाते हैं।

कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास ऐयंगर ने संशोधन पेश किया कि यद्यपि ब्रिटिश युवकों के भरती करने का विचार भारतीय जनमत के तथा भारत के राजनीतिक लक्ष्य के विरुद्ध है, फिर भी केन्द्रीय असेम्बली की राय है कि (स्कीन)कमेटी की सर्वसम्मत् संस्तुतिओं से भारत में सेना के भारतीयकरण में ठोस शुरुआत होगी, और इसलिए वह गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को संस्तुति करती है कि वे उन संस्तुतिओं को स्वीकार करने की तथा शीघ्र ही उन्हें कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे।”

अन्त में मत विभाजन के बिना श्री श्रीनिवास ऐयंगर का संशोधन असेम्बली ने स्वीकार कर लिया ।

कमांडर-इन-चीफ की घोषणा

मार्च सन् १९२८ में कमांडर-इन-चीफ सर विलियम वर्डवुड ने वजट की वृहत् में भाग लेते हुए सरकार की सेना नीति की घोषणा की । उन्होंने भारतीय सेडहर्स्ट कमेटी की कतिपय सन्तुतिओ को स्वीकार करते हुए दो तीन महत्त्वपूर्ण सन्तुतिओ को मानने से इनकार कर दिया । उन्होंने घोषित किया कि भविष्य में प्रति वर्ष १० के बजाय २० भारतीय नवयुवक सेडहर्स्ट में भरती किये जायेंगे, और वाइसराय-कमिशन प्राप्त अफसरों के उच्चस्तरीय परिनिक्षण के लिए प्रतिवर्ष दस-पाँच स्थान सेडहर्स्ट में संरक्षित रहेंगे । उन्होंने यह भी घोषित किया कि बूलविच और कारनवेल में भी प्रतिवर्ष छ' भारतीय भरती किये जायेंगे । इस तरह प्रतिवर्ष ३७ भारतीयों को उच्चस्तरीय सैनिक शिक्षा के लिए भरती किया जायेगा । पर सरकार, उन्होंने कहा, कमेटी की यह सन्तुति स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि सन् १९५२ तक भारतीय सेना में आधे उच्चस्तरीय अफसर भारतीय होंगे । उन्होंने यह भी घोषित किया कि आठ यूनिटों की योजना चालू रहेगी, और सेडहर्स्ट जैसी उच्चस्तरीय शैक्षिक तथा भारन में इस समय स्थापित नहीं की जायेगी । अन्त में उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सवैधानिक विकास के साथ-साथ सेना का भी भारतीयकरण हो, औपनिवेशिक सेनाओं की तरह राष्ट्रीय आधार पर भारतीय सेना भी संगठित हो, पर भारतीयकरण की नीति क्रिरी पूर्व निश्चित समय के मापक्रम द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

विरोध

१० मार्च सन् १९२८ को जिना साहब ने सेनापति की घोषणा पर विचार करने के लिए सदन में काम रोको प्रस्ताव पेश करने की इजाजत माँगी । सरकार के प्रवक्ता सर बेसिल ब्लेकट ने यह स्वीकार करते हुए कि प्रश्न सार्वजनिक महत्त्व का है कहा कि इस पर तीन-चार दिन के बाद 'सेना विभाग के अनुदान' पर वृहत् करते समय विचार किया जा सकता है । पर मालवीयजी आदि ने जिना साहब का समर्थन किया । मालवीयजी ने कहा : 'यह प्रश्न कि भारत में सैनिक कालेज खोला जाय अथवा न खोला जाय, देश की जनता के सामने जीवन-मरण का प्रश्न है । इस देश में भावी उत्तरदायी शासन का सारा प्रश्न इस पर निर्भर है, और इसलिए इस प्रश्न से सम्बन्धित घोषणा

पर जनता की प्रतिक्रियाओं को जीध से शीघ्र व्यक्त करना नितान्त आवश्यक है।^१ अध्यक्ष ने प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दे दी। जिना साहब का प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। १४ मार्च को दीवान चामन लाल ने सेना की माँग पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया, जो बहुमत से पास हो गया।

१७ मार्च सन् १९२८ को वित्त विधेयक का विरोध करते हुए मालवीयजी ने फौजी खर्च को भारत की आवश्यकता और सामर्थ्य से अधिक बताते हुए कहा कि उसे कम करने के लिए सेना का भारतीयकरण, तथा जापान के ढंग पर सेना का गठन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा की समुचित व्यवस्था, उसके गौरव की पुष्टि, तथा खर्च की कमी इन सबके लिए ब्रिटिश सैनिकों और अफसरों के स्थान पर योग्य भारतीयों की नियुक्ति आवश्यक है। उन्होंने माँग की कि आन्तरिक सुरक्षा का भार भारतीय सैनिकों के सुपुर्द कर दिया जाय, तथा आन्तरिक दंगों को शान्त करने के लिए अंग्रेज सैनिकों का प्रयोग न किया जाय, क्योंकि उससे अंग्रेजों और भारतीयों में कटुता पैदा होती है।^२ उन्होंने यह भी माँग की कि प्रति वर्ष लगभग पाँच हजार ब्रिटिश सैनिक कम कर दिये जायें, और धीरे-धीरे आन्तरिक सुरक्षा के साथ-साथ बाह्य सुरक्षा का भार भी भारतीय सैनिकों के सुपुर्द कर दिया जाय।^३ उन्होंने उच्चस्तरीय सैनिक कालेज खोलने का आग्रह करते हुए कहा कि इस समय हमारे सैनिक एक मात्र भूतिभोगी (मर्सिनरी) हैं, उनमें देशभक्ति और राजभक्ति की भावना का संचार किया जाय, और भारतीय सेना को सच्चे मानों में राष्ट्रीय सेना बनाया जाय।^४

१९ सितम्बर सन् १९२९ को श्री एम० आर० जयकर के प्रस्ताव पर बोलते हुए मालवीयजी ने कहा : "जिस तरह बुद्धि किसी विशेषवर्ग की इजारादारी नहीं है, इसी तरह सैनिक भावना (शौर्य) भी किसी विशेष वर्ग की इजारादारी नहीं है"।^५ उन्होंने कहा कि जिस तरह शिवाजी ने सब जातियों के नवयुवकों को अपनी सेना में भरती किया और गुरुगोविन्द सिंह ने जाति-पाँति को उपेक्षा करते हुए सुदृढ़ सिक्ख पथ स्थापित किया, उसी तरह सब सम्प्रदायों

१. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १२४३।

२. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १६५८।

३. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १६६३।

४. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १६६२।

५. वही, सन् १९२९, जि० ४, पृ० १००५।

और जातियों के योग्य नवयुवकों को भरती करके भारतीय सेना का निर्माण किया जाय। उन्होंने भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के नवयुवकों को विभिन्न सस्थाओं में शिक्षा दिये जाने का विरोध करते हुए कहा कि सेना में देशभक्ति का संचार करने के लिए जिस पर देश का भविष्य निर्भर है, यह आवश्यक है कि सब सैनिक रंगरूट, चाहे वे किसी जाति या सम्प्रदाय के हों, "समान नियमों के अधीन", बिना किसी पार्थक्य के, "समान रूप से एक ही मस्था में" साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करें, तथा जीवननिर्वाह करें, खेले-कूदें और काम करें।^१

पब्लिक सेफ्टी बिल

सितम्बर सन् १९२८ में विदेश से आने वाले कम्युनिस्टों की गतिविधि और कामों पर खास तौर पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 'पब्लिक सेफ्टी बिल' (सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक) के नाम से असेम्बली में एक विधेयक प्रस्तुत किया। कांग्रेस और नेशनलिस्ट पार्टियों के सदस्यों के अतिरिक्त कतिपय अन्य सदस्यों ने भी विधेयक का डटकर विरोध किया। अन्त में उसके पक्ष और विपक्ष में वोटों की संख्या बराबर रही, तब ब्रिटेन की कामन्स सभा की परम्परा का अनुकरण करते हुए असेम्बली के अध्यक्ष विठ्ठल भाई पटेल ने विपक्ष में अपनी राय दी और विधेयक नामजूर हो गया।

फरवरी सन् १९२९ में सरकार ने दुबारा विधेयक को असेम्बली में पेश किया और सदन ने बहुमत से उसे प्रवर समिति के पास भेज दिया। पर जब १ अप्रैल को समिति की रिपोर्ट सदन में पेश करने का प्रस्ताव आया, तब अध्यक्ष ने कहा कि इस विधेयक का मेरठ के साजिश (विद्रोह) मुकदमे से काफी सम्बन्ध है, इसलिए सरकार या तो मेरठ मुकदमे तक इस विधेयक पर विचार स्थगित कर दे, या मुकदमा वापस ले ले।^२ ४ अप्रैल को गृह सदस्य केरार साहब ने सदन के नियमों की व्याख्या करते हुए कहा कि मुकदमे को वापस लिए बिना विधेयक को प्रवर समिति की रिपोर्ट पर बहस हो सकती है, और सरकार अध्यक्ष की दोनों बातों में से कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। इस पर दो दिन तक कुछ अन्य प्रमुख सदस्यों की राय सुनने के बाद ११ अप्रैल को अध्यक्ष ने विधेयक पर विचार करना वर्जित कर दिया।^३

१. वही, सन् १९२९, जि० ४, पृ० १००५-१००६।

२. वही, सन् १९२९, जि० ३, पृ० २६५३।

३. वही, सन् १९२९, जि० ३, पृ० २९८७-९१।

दूसरे दिन अर्थात् १२ अप्रैल को वाइसराय ने केन्द्रीय विधान : दोनो सदनों को संयुक्त बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी अध्यक्ष का निर्णय नियमों के मूल अभिप्राय के अनुकूल नहीं है, पर : अन्दर उनका निर्णय ही प्रामाणिक है। दूसरी ओर, उन्होंने कहा, समुचित सुरक्षा के लिए विधेयक को कानून की शक्ल देना मेरी सरव : राय में जरूरी है, और इसलिए उसे अध्यादेश के रूप में जारी किया जा : इसके बाद पटेल साहब ने वाइसराय को लिखा कि अध्यक्ष की रूलिंग (व्य : पर आक्षेप करना सर्वथा अनुचित था। इस पर वाइसराय ने अपने निजी : के पत्र द्वारा अध्यक्ष को सूचित किया कि उनकी रूलिंग पर आक्षेप क : उनका कोई इरादा नहीं था।^१

मालवीयजी ने सितम्बर सन् १९२८ तथा फरवरी सन् १९२९ में प : सेपेटी बिल का विरोध किया। इसे उन्होंने "अनावश्यक" तथा उसकी ध : को "आपत्तिजनक" बताया^२। उन्होंने कहा कि इस विधेयक द्वारा कम्यु : के प्रसार को, उसकी ओर नवयुवकों की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा स : "सब हड़तालें प्रारम्भ से अन्त तक गलत नहीं हैं"^३। हड़तालों के समय : मजदूरों के लिए विदेश से भेजी सहायता को गैर-कानूनी घोषित क : उन्होंने कहा, अवश्य ही अनुचित होगा। उन्होंने कॅनेडा और आस्ट्रेलि : कानूनों की प्रासंगिक धाराओं के उद्धरण देते हुए कहा कि सरकार क : कहना कि प्रस्तुत विधेयक उन कानूनों की व्यवस्था के अनुकूल है, विल्कुल : है। जबकि आस्ट्रेलिया और कॅनेडा के कानूनों में किसी जाँच के बाद, अधि : द्वारा प्रस्तुत सफाई पर विचार करने के बाद, किसी विदेशी को निष्प : का दण्ड देने की व्यवस्था है, प्रस्तावित विधेयक में बिना किसी मुकदम : अभियुक्त को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिये बगैर प्रशासन अधि : को निष्कासन का अधिकार दिये जाने की व्यवस्था है। न्यायिक अधि : को प्रशासनिक अधिकारियों के सुपुर्द करना, बिना न्यायिक जाँच (ट्रायल : सजा देना, उन्होंने कहा, निःसन्देह अभ्यास है, सुव्यवस्था के नाम पर प्रशास : निरंकुशता स्थापित करना है।^४ उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रसिद्ध वि

१ वही, सन् १९२९, जि० ४, पृ० १११।

२. वही, सन् १९२८, जि० ३, पृ० ८५६।

३ वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ५९३।

४. वही, सन् १९२८, जि० ३, पृ० ८५७-८५८; वही, सन् १९ : जि० १, पृ० ५८८।

प्रोफेसर ओपेनहाइमर के विचारों का उद्धरण देते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि हमें दूसरे राज्यों की जनता के साथ उसी सम्य आधार पर व्यवहार करना चाहिए जिस पर हम अपनी जनता के साथ व्यवहार करते हैं।^१ मालवीयजी ने यह भी कहा कि सरकार के समर्थक "पाइनीयर" समाचार पत्र ने भी यह स्वीकार किया है कि "किसी आदमी को पूरी तौर पर यह जानकारी कराये बिना कि उसे किस अभियोग का सामना करना है दण्ड दे देना अन्याय है। जब तक अभियोग सिद्ध न हो और सबधित व्यक्ति को जवाब देने का पूरा मौका न मिला हो, तब तक एक कुख्यात कम्युनिस्ट को भी निर्वासित करना ब्रिटिश न्याय नहीं है।"^२

मालवीयजी ने कहा कि जिस तरह ब्रिटेन में हड़तालों को पारस्परिक परामर्श द्वारा शान्त करने की कोशिश की जाती है, उसी तरह भारत में भी की जानी चाहिए। उसके लिए "कठोर अधिकार" की कौन जरूरत है?^३ उन्होंने औद्योगिक श्रमिकों की दयनीय दशा का विश्लेषण करते हुए कहा कि सरकार को दगो (विस्फोटों) पर आश्चर्य है, जबकि "मुझे आश्चर्य है कि ये दगो पहले क्यों नहीं हुए, और कहीं अधिक संख्या में क्यों नहीं हुए?"^४ पठानों के अत्याचार और अमानुषिक व्यवहार द्वारा हड़ताल को बन्द कराने का प्रयत्न निन्दनीय है। बम्बई की दुर्गवस्था का उत्तरदायित्व सरकार की वित्तीय नीति पर है, उसने रुपये की दर अठारह पैसे निश्चित करके ऐसी औद्योगिक स्थिति पैदा कर दी है कि बम्बई के बहुत से पूजीपति स्वयं चाहते हैं कि हड़ताल जारी रहे, ताकि उन्हें माल तैयार करके उसे गोदामों में जमा करते रहने की जरूरत न पड़े।^५ दशा को सुधारने के लिए वित्त नीति बदलनी होगी, मजदूरों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना होगा।

उन्होंने कहा कि नवयुवकों को कम्युनिज्म के प्रभाव से बचाने के लिए उनमें देशभक्ति की भावना को संचरित करना होगा, उनकी स्वराज्य की भाग

१. वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ५९२।

२. वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ५९४।

३. वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ५९४।

४. वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ५९८।

५. वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ५९८-५९९।

६. वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ६०२;

वही, सन् १९२८, जि० ३, पृ० ८५५।

को पूरा करना होगा। यदि ये अपने देश में स्वशासन प्रतिष्ठित नहीं करते, तब ये संसार में कहीं भी अपने साथी मनुष्यों द्वारा मनुष्य की तरह व्यवहार किये जाने के पात्र नहीं हैं।^१ उन्होंने कहा कि यदि सब दलों से समर्थित राष्ट्रीय माग को सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी, तो नवयुवकों की भावना उग्र होगी, उनमें भारत और ब्रिटेन के बीच पूर्ण विच्छेद हो—यह भावना बढ़ेगी, जिसे हथियारों द्वारा दबाया नहीं जा सकेगा।^२

कम्युनिज्म के सिद्धान्तों की चर्चा करते हुए मालवीयजी ने कहा कि कम्युनिज्म सत्य, न्याय, धर्म और प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है।^३ उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी हिंसा और शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति के अपहरण या अधिग्रहण के कम्युनिस्ट सिद्धान्त को ठीक नहीं समझते। उन्होंने कहा कि कानून की उचित व्यवस्था को छोड़ किसी अन्य उपाय से कानूनी ढंग से उपाजित सम्पत्ति के उपभोग में बाधा पहुँचाने के हम विरुद्ध हैं।^४ उन्होंने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि “यथोचित कानून और उस कानून के अन्दर उचित प्रशासनिक आज्ञा को छोड़ कर” किसी दूसरे ढंग पर “किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति के उपभोग (उपयोग) से वंचित किया जाय।”^५ इस बात में सदन के सब निर्वाचित सदस्य सरकार के साथ हैं, और कम्युनिस्टों की रीति-नीति के विरुद्ध हैं।

पर मालवीयजी ने कहा कि वे कम्युनिस्टों को इस बात को स्वीकार करते हैं कि “समाज का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि जो उसके लिए काम करे वह पुरस्कृत किया जाय”,^६ और उसे सुखी जीवन व्यतीत करने की सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि वे कम्युनिस्ट सकलतवाला के इस विचार से भी सहमत हैं कि “सब मनुष्यों का जन्म एक ढंग से हुआ है, और सब ही वृद्धि और विकास के समान नियमों के अधीन हैं। यदि सब को एक प्रकार की शिक्षा दी जाय, तो परिणाम भी एक जैसा होगा, केवल उसकी आकृति और अभिव्यक्ति ही एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से भेद दिखला पायेगी।”^७ समाज

१. वही, सन् १९२९, जि० ९, पृ० ६०४।

२. वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ६०४।

३. वही, सन् १९२८, जि० ३, पृ० ८५२।

४. वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ५८७-५८८।

५. वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ५८८।

६. वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ५८६-५८७।

७. वही, सन् १९२९, जि० १, पृ० ५८७।

की इस कम्युनिस्ट कल्पना को भी स्वीकार करने को वे तैयार थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सब आवश्यकताओं की पूरी-पूरी पूर्ति के अनुरूप पुरस्कार मिलना चाहिए, जब तक वह व्यक्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार ईमानदारी के साथ समाज के लिए काम करता है।^१ उन्होंने घोषित किया कि यह सब सिद्धान्त तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुकूल है और इनके आधार पर समाज का निर्माण आवश्यक और अनिवार्य है।

ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल

मजदूरों के क्रियाकलापों पर विशेषतः हड़तालों पर, प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार ने असेम्बली में ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पेश किया। मजदूरों की ओर से ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता दीवान चम्मन लाल ने उसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के अन्य बहुत से सदस्यों ने भी उसका विरोध किया। शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा झगड़ों का निपटारा इस विधेयक का लक्ष्य बताया जाता था। पर दीवान चम्मन लाल आदि की धारणा थी कि इस विधेयक द्वारा औद्योगिक मजदूरों के हितों की पूरी तौर पर रक्षा नहीं होती, और मजदूरों के हकों को अनुचित ढंग पर सीमित किया जा रहा है। सर्वश्री जमनादास मेहता, वी० वी० जोग्या, एस० श्रीनिवास ऐयंगर, एम० एस० अणे आदि ने भी विधेयक का विरोध किया। औद्योगिक फजल इब्राहीम रहमतुल्ला ने विधेयक को कड़ा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए एक संशोधन भी प्रस्तुत किया। पर भारी बहुमत से वह नामंजूर हो गया। केवल १३ सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में राय दी।

३८ वोटों के विरुद्ध ५६ वोटों से विधेयक पास हो गया। जब कि कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के अधिकांश सदस्यों ने, तथा उनके नेता मोतीलालजी और मालवीयजी ने विधेयक के विपक्ष में वोट दिये, जिना साहब ने किसी तरफ वोट नहीं किया, और उनकी पार्टी के अधिकांश सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में अपने वोट दिये। मिस्टर फजल इब्राहीम रहमतुल्ला ने इस धारणा से कि सदन ने उनका संशोधन स्वीकार नहीं किया, विधेयक के विरोध में वोट दिया। पर जिन १२ सदस्यों ने उनके संशोधन का समर्थन किया था, उन सब ने विधेयक के पक्ष में वोट दिया। सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, सेठ घनश्याम दास बिडला आदि कतिपय औद्योगिकों ने भी किसी तरफ वोट नहीं दिये।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

जिस तरह मालवीयजी ने पब्लिक सेफटी बिल का विरोध किया तथा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरुद्ध वोट दिया, उससे यह स्पष्ट है कि वे संपत्ति के अधिकार से कहीं अधिक मानव व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता और गौरव की रक्षा, तथा सबके लिए सुखी जीवन की व्यवस्था को महत्त्व देते थे। वे इन्हें मानव के मौलिक अधिकार मानते थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र सम्मानित जीवन व्यतीत करने की, तथा अपने व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएँ प्राप्त हो। वे कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति और जनसमूह को संस्था संगठित करने का, सभा और प्रदर्शन आयोजित करने का, अपने विचारों को प्रकाशित करने का, भाषण करने का, तथा अपने साथियों को सलाह देने का, तथा उनके साथ हड़ताल करने का न्यायसंगत और युक्तिसंगत अधिकार है। उन्होंने असेम्बली में बार बार माँग की कि मानव के इन अधिकारों की कानून द्वारा रक्षा की जाय, और जो मौजूदा कानून और व्यवहार इनके विरुद्ध है, उन्हें बदला जाय। उन्होंने जोरदार शब्दों में सरकार की निन्दा करते हुए कहा : "जब तक भीड़ हिंसात्मक नहीं हो जाती या गैरकानूनी काम नहीं करने लगती, कानून के अन्दर किसी मनुष्य को सगौन प्रयोग करने का, या भीड़ में किसी मनुष्य पर गोली चलाने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह अपने खतरे पर ऐसा करता है।"^१

धार्मिक स्वतन्त्रता

धार्मिक स्वतन्त्रता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने कहा कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के सिद्धान्तों और मतों पर अपने विचार व्यक्त करने का, उन पर बादविवाद करने का अधिकार है, पर जिन बातों से साथियों की भावनाओं को आघात पहुँचे उन्हें उसे बचाना ही चाहिए। इस तरह धार्मिक महापुरुषों, धर्म के प्रवर्तकों, अवतारों, धर्मगुरुओं के सम्बन्ध में बातचीत करते समय उनका व्यक्तित्व अद्धापूर्ण सम्मान का अधिकारी समझा जाना चाहिए, अर्थात् उनकी चर्चा सम्मानपूर्वक की जानी चाहिए।^२ नेशनलिस्ट पार्टी के नेता लाला लाजपत राय भी इस बात से सहमत थे। वे भी धार्मिक व्यक्तित्वों की अश्लील आलोचना के विरोधी थे, तथा धर्म और

१. वही, सन् १९२७, जि० १, पृ० १०२९।

२. वही, सन् १९२७, जि० ४, पृ० ३९४७-३९५०।

श्रेष्ठ धार्मिक व्यक्तियों के साभिप्राय अपमान को 'अपराध' मानते थे और कानून द्वारा उसे वन्द कर देना देश में शान्ति और सौहार्द प्रतिष्ठित करने के लिए आवश्यक समझते थे ।

कांग्रेस के निर्णय

मालवीयजी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के निर्णयों से पूरी तौर पर सन्तुष्ट नहीं थे । वे अब भी औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में थे, उसे ही पूर्ण स्वतंत्रता मानते थे, और कांग्रेस के विधान में घोषित 'स्वराज्य' की व्याख्या अनावश्यक समझते थे । वे विधान सभाओं का वहिष्कार भी उचित नहीं समझते थे । वे चाहते थे कि वहाँ भी सरकार का डटकर विरोध किया जाय, स्वराज्य के लिए संघर्ष किया जाय । उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस के वजाय जनता के प्रतिनिधियों को स्वयं वहिष्कार के प्रश्न पर विचार-विमर्श करके निर्णय करना चाहिए था । कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित सदस्यों के लिए कांग्रेस के नियंत्रण और आदेश की अवहेलना या उपेक्षा करना ठीक हो अथवा न हो, पर नेशनलिस्ट पार्टी के टिकट पर निर्वाचित मालवीयजी इस प्रश्न पर कांग्रेस के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं थे । अतः मालवीयजी और नेशनलिस्ट पार्टी के दूसरे सदस्यों ने तुरन्त इस्तीफा देने के वजाय केन्द्रीय असेम्बली के बजट सत्र में भाग लेने का निर्णय किया । आन्ध्र के प्रमुख नेता टी० प्रकाशम, आसाम के प्रमुख नेता टी० आर० फूकन, उड़ीसा के नेता नील कंठ दास, पंजाब के मजदूर नेता दीवान चम्पन लाल तथा मद्रास के एम० के० आचार्य और के० वी० रंगास्वामी ऐयंगर और बंगाल के एस० सी० मित्र और अमरनाथ दत्त, आदि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी असेम्बली का बाइकाट नहीं किया, और उनमें से अधिकांश ने 'न्यू स्वराज्य पार्टी' के नाम से एक नया दल गठित कर लिया ।

बजट

५ मार्च सन् १९३० को बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने कहा कि यह बजट हमें याद दिलाता है कि भारत एक ऐसी व्यवस्था के अधीन है जिसमें सरकार जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उत्तरदायी नहीं है, और वह इंग्लैंड से प्राप्त आदेशों से नियंत्रित इच्छा के अनुसार प्रशासन का संचालन करती है ।^१ उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत "जनता के प्रतिनिधियों

के लगातार प्रोटेस्ट के बावजूद" खर्च बढ़ना चला जा रहा है।^१ उन्होंने बहुत ही सन्तुष्ट हृदय से कहा कि उससे "अधिक दृष्ट सरकार" कीनसी हो सकती है जिसमें जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सरकार द्वारा नियत नियमों के अन्तर्गत जनता द्वारा निर्वाचित जनता के प्रतिनिधियों को यह भी अधिकार नहीं कि वे सरकार को मजबूर कर सकें कि जो द्रव्य उनके बोटो से एकत्रित किया जाता है उसे जैसा वे ठीक समझते हैं वैसे ही खर्च किया जाय।^२ उन्होंने कहा कि ऐसी "बुरी शासन-व्यवस्था से जितनी जल्दी हमारा पिंड छूटे उतना ही भारत और बाह्य जगत में मानव जाति के लिए अच्छा होगा।"^३

मालवीयजी ने सरकार की सेनानीति की आलोचना करते हुए कहा कि जबकि यूरोप के राजनीतिज्ञों की धारणा है कि राजस्व का २० प्रतिशत से अधिक सेना पर खर्च न किया जाय, भारत सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। जबकि सभी देशों ने युद्ध के बाद खर्चों को घटाकर करो में काफी कमी कर दी है, इस देश में अब भी जनता को युद्धकालीन करो का भार वहन करना पड़ रहा है।^४ सरकार की मुद्रा नीति की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि १६ पैस के बजाय १८ पैस की दर निश्चित करके सरकार ने भारतीय उद्योगों और वित्तीय स्थिति को भयंकर विपत्ति में डाल दिया है।^५ उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर आय-कर में वृद्धि की मांग करती है, और दूसरी ओर कपड़ों पर लगाये जाने वाले कर में ब्रिटेन के कपड़ों पर ५ प्रतिशत की छूट चाहती है। यह कहाँ का न्याय है? सरकार चाहती है कि राजस्व की वृद्धि के लिए सूती कपड़ों पर आयात शुल्क ११ प्रतिशत से बढ़ा कर १५ प्रतिशत कर दिया जाय, और उन कपड़ों पर जो ब्रिटेन से नहीं आते हैं ५ प्रतिशत संरक्षण शुल्क लगाया जाय। इस तरह सरकार ब्रिटेन के कपड़ों पर आयात शुल्क में ५ प्रतिशत की छूट देती है। इस सुझाव को प्रस्तुत करते समय, मालवीयजी ने कहा, सरकार हमें यह नहीं बताती कि इस छूट से हिन्दुस्तान को क्या लाभ होगा। पिछले पाँच वर्षों में सूती कपड़ों में जापान का व्यापार ३३० लाख गज बढ़ गया है, जबकि उसी जमाने में लंकाशायर का व्यापार

१. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १३३३।

२. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १३३३।

३. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १३३४।

४. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १३३४।

५. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १३३४-१३३५।

३८० लाख गज घट गया है।^१ प्रस्तावित अधिमान के जरिये ब्रिटेन के व्यापार को लाभ अवश्य होगा, वह सम्भवतः हिन्दुस्तान में जापान के इस व्यापार को खत्म कर देगा, पर क्या इससे हिन्दुस्तान को भी कोई लाभ होनेवाला है? उन्होंने बताया कि फिसकल कमीशन (शुल्क आयोग) की धारणा है कि इस प्रकार की व्यवस्था से अधिमान-प्राप्त देश के व्यापार को अवश्य लाभ होगा, पर शुल्क की नीची दर के कारण सरकार की आमदनी घटेगी, और उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होगा।^२ ऐसी हालत में टेरिफ बोर्ड से पूछे बिना ब्रिटेन के माल को ५ प्रतिशत का अधिमान देना सर्वथा अनुचित है।

कटौती का प्रस्ताव

७ मार्च सन् १९३० को श्री एन० सी० केलकर ने प्रस्ताव किया कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल से सम्पन्नित वित्तीय माँग को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जनता को उत्तरदायी नहीं है और कटौती का यह प्रस्ताव इस सवैधानिक स्थिति के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव गांधीजी के अल्टीमेटम के अनुरूप है जिससे सिद्ध होता है कि जो लोग कौंसिल में रहकर काम कर रहे हैं और जो इसे छोड़ कर बाहर चले गये हैं उनका ध्येय एक ही है।

कटौती के इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि इस समय कोई भी ऐसा स्वाभिमानो भारतीय नहीं है जो 'सवैधानिक प्रगति के प्रश्न को, जो राष्ट्र के सम्मान और हितों से बहुत सम्बन्धित है, केवल ब्रिटिश सरकार के निर्णय पर छोड़ने को तैयार होगा।'^३ उन्होंने भारत सरकार से माँग की कि वह ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करे कि वह गोलमेज काफरेन्स को शीघ्र बुलाने का कष्ट करे और घोषित करे कि वह सहमत है कि "विधान के मंशोधन" द्वारा भारत में "डोमिनियन स्टेट्स" प्रतिष्ठित किया जायगा।^४ उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार इस प्रकार की घोषणा करे, तो वह वायदा करते हैं कि महात्मा गांधी उसे स्वीकार कर लेंगे, और अपना आन्दोलन बन्द कर देंगे।^५

१. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १३३८।

२. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १३३६-१३३७।

३. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १४०४।

४. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १४०७।

५. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १४०७।

जिना साहब ने कटौती के प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में समर्थन किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार को समझ लेना चाहिए कि हिन्दू हमसे समझौता करें अथवा न करें, वे हमारे साथ आगे बढ़ें या न बढ़ें, हम आगे बढ़ेंगे, और हम इस देश में मुसलमानों और दूसरे अल्प सख्यकों के लिए संरक्षणों की समुचित व्यवस्था के साथ उत्तरदायी शासन-व्यवस्था चाहते हैं।^१

कटौती का प्रस्ताव ३९ वोटों के मुकाबले में ५० वोटों से रद्द हो गया। कटौती के प्रस्ताव के विरोध में वोट देनेवालों में केवल २२ भारतीय थे, जिनमें अधिकांश गवर्नर-जनरल द्वारा मनोनीत थे। इस तरह लगभग तीन चौथाई निर्वाचित हिन्दुस्तानी निन्दा का प्रस्ताव पाम करने के पक्ष में थे। कांग्रेस पार्टी द्वारा असेम्बली का बाइकाट ही भारतीय पक्ष की पराजय का मूल कारण था।

वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी

१० मार्च सन् १९३० को सरदार वल्लभभाई पटेल की गिरफ्तारी पर सरकार की भर्त्सना करते हुए मालवीयजी ने आशा व्यक्त की कि सरकार दमन के बजाय सुलह की नीति का अनुसरण करेगी, तथा भारत को उसके जन्म-सिद्ध अधिकार को देने का वायदा करेगी, और इस तरह संघर्ष और कष्टों को टाल कर सन्तोष और आनन्द का अवसर प्रदान करेगी।^२ पर यदि सरकार ने इस बात का वायदा नहीं किया कि संविधान का आगामी संशोधन "डोमिनियन स्टेट्स" के आधार पर आधारित होगा, तो यह मामला "लीग आफ नेशन्स के पास भेजा जायगा, और सम्पूर्ण जगत् के जनमत के कठघरे में सरकार को सड़ा होना होगा।"^३

सूती कपड़ा उद्योग (संरक्षण) विधेयक

मार्च सन् १९३० के दूसरे सप्ताह में सरकार की ओर से एक आयात शुल्क विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसमें सब देशों के सूती कपड़ों के आयात पर ११ प्रतिशत के बजाय १५ प्रतिशत आयात शुल्क लगा देने की व्यवस्था थी, और यह भी प्रस्ताव था कि ब्रिटेन के माल को छोड़कर अन्य देशों के माल पर ५ प्रतिशत संरक्षण शुल्क और लगेगा। मालवीयजी और दूसरे बहुत से निर्वाचित सदस्य ब्रिटेन के माल पर ५ प्रतिशत की छूट ठीक नहीं समझते थे।

१. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १४०८।

२. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १५२२।

३. वही सन् १९३०, जि० २, पृ० १५२२।

उन्होंने इस साम्राज्यिक अधिमान का डटकर विरोध किया। वाणिज्य-सदस्य ने घोषित किया कि यदि उनकी यह बात स्वीकार नहीं की गयी, तो वह पूरा विधेयक वापस ले लेंगे। इससे भयभीत होकर औद्योगिक वर्ग के अधिकांश विधायक इस छूट का समर्थन करने को तैयार हो गये। जिना साहब ने भी, जो स्वयं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहते थे, इस भय के कारण विधेयक का पूरी तौर पर समर्थन करना ही उचित समझा।^१ वित्त-सदस्य ने यह भी कहा कि इस छूट या अधिमान का विरोध गोलमेज कांफरेन्स के कामों में बाधा पहुँचा सकता है।

मालवीयजी को ये बातें बुरी लगी। उन्होंने इस प्रकार की धमकियों को "विधिविहित निरंकुशता का अत्याचार"^२ बताकर सरकार की भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि सरकार की मुद्रा नीति ने बम्बई के उद्योग की दशा बहुत बिगाड़ दी है, और उसे इस समय २० प्रतिशत संरक्षण की जरूरत है और यदि हमारी शक्ति होती तो हम इतना संरक्षण, उसे जरूर दे देते।^३ यदि सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव पेश करने को तैयार हो, तो वह और उनकी पार्टी उसका समर्थन करेंगे। पर वह और उनके साथी ब्रिटिश माल पर ५ प्रतिशत की छूट देकर उस पर १५ प्रतिशत और दूसरे देशों के माल पर २० प्रतिशत का आयात शुल्क लगाने की व्यवस्था का समर्थन करने को तैयार नहीं है।

मालवीयजी की धारणा थी कि प्रस्तावित व्यवस्था से बम्बई के उद्योगों को कोई दीर्घकालीन लाभ होने वाला नहीं है। उनका विश्वास था कि "सरकार के प्रस्ताव से बम्बई के औद्योगिकों को "अल्पकालिक" और "दिखावटी राहत" भले मिल जाये, पर "वदान्यता (वाउन्टी) का विष" आगे चलकर "भारी संकट" उत्पन्न कर देगा।^४ वदान्यता के बल पर लंकाशायर दूसरे देशों के व्यापार को धक्का देकर भारत के बाजार में छा जायेगा, और "बम्बई का उद्योग बहुत देर तक लंकाशायर का मुकाबला नहीं कर सकेगा"।^५ मालवीयजी को इस बात का भी भय था कि अधिमान के जरिए भारत के बाजार पर कब्जा करके लंकाशायर जब उचित समझेगा तब कपड़ों की कीमत बढ़ा देगा, और हम उसे रोक

१ वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २४३०।

२ वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २६२६।

३ वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २६१५।

४ वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २६२१।

५ वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २६२६।

नहीं सकेंगे।^१ इस तरह प्रस्तावित व्यवस्था सारे देश के लिए हानिकर सिद्ध होगी। बम्बई के औद्योगिकों को, मालवीयजी ने कहा, अच्छी तौर पर समझ लेना चाहिए कि “बम्बई समृद्ध नहीं हो सकता, अगर भारत कगाल और विकृत हो जाता है, और देश में मन्दी हो जाती है।”^२

उन्होंने कहा : “सरकार विप की एक बड़ी बूँद के साथ हमें दूध का प्याला देना चाहती है, मेरी आपसे विनती है कि आप उसे लेने से इनकार कर दें और इस महान् देश की जनता की हैसियत से अपने जन्म-सिद्ध अधिकार के रूप में विशुद्ध और निर्मल दूध का प्याला लेने का आग्रह करें।”^३

मालवीयजी ने कहा कि उनके लिए उनका देश ही सर्वोपरि है। उसका चिन्तन ही उनका मुख्य विषय है। बम्बई के उन मित्रों को, जिन्होंने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को बहुत आर्थिक सहायता दी है, समझना चाहिए कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के हित पर देश का हित कुर्बान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा “मैं अपनी आत्मा और अपने परमात्मा के प्रति निष्ठाहीन हो जाऊँगा, यदि मैं हिन्दू यूनिवर्सिटी के हितों या किसी दूसरे हित को अपने और अपने देश के हितों के बीच टिकने दूँ। यदि सौ हिन्दू यूनिवर्सिटियों का बलिदान करना भी आवश्यक होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करेगा कि मैं बिना हिचक के उन्हें बलिदान कर दूँ, और अपने देश के हित का बलिदान न करूँ”।^४

मालवीयजी को सन्देह था कि भारत सरकार स्वयं लंकाशायर के कपडों को अधिमान शुल्क या वदान्यता देने के पक्ष में नहीं थी, और ब्रिटिश सरकार के दबाव और आग्रह से बाध्य होकर ही उसने इस प्रकार का प्रस्ताव असेम्बली के सामने पेश किया। उन्होंने सरकार से माँग की कि इस विषय पर जो पत्रव्यवहार भारत मन्त्री से हुआ है, वह असेम्बली के पटल पर रखा जाय, और जब सरकार ने ऐसा करने से इनकार किया तब मालवीयजी ने कहा, “हमने उस पत्र को पेश करने की माँग की जो भारत सरकार ने सम्राट् के मन्त्री को भेजा है, पर भारत सरकार ने उस पत्र को प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए जैसा

१. वही, सन् १९३०, जि० २, पृ० १७४७।

२. वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २६२७।

३. वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २६२७।

४. वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २६२६।

कि हरेक वकील कहेगा, अनुमान यही है कि वह गवाही जो पेश नहीं की जाती वह उस पार्टी को जो उसे पेश नहीं करती अवश्य ही हानिकर होगी।^१

भारत सरकार और भारत-मन्त्री के व्यवहार को अनुचित घोषित करते हुए उन्होंने बहुत ही सन्तप्त हृदयसे कहा : “विदेशी सरकार की अधीनता सबसे बड़ा अभिशाप है जो किसी राष्ट्र पर हो सकता है। वह जनता के पुरुषत्व को नष्ट करता है और भयंकर मात्रा में नैतिक स्वभाव को प्रभावित करता है। विदेशी नीकरशाही सरकार एक ऐसी सस्था है जो उन लोगों को भ्रष्ट कर देती है जिन पर वह अपना अधिकार, आश्रय, और प्रभाव का प्रयोग करती है। उसकी मौजूदगी ही भ्रष्टाचारी प्रभाव रखती है।”^२

मालवीयजी की दृढ़ धारणा थी कि भारत सरकार का व्यवहार और उसकी घमकी उद्घोषित वित्तीय स्वतन्त्रता का अपहरण करती है। उन्होंने माँग की कि सरकार उस घोषणा का आदर करना अपना कर्तव्य समझ निर्वाचित सदस्यों के निर्णय को स्वीकार करे, और सरकारी सदस्य विधेयक पर वोट न करें। उन्होंने असेम्बली के अध्यक्ष श्री विट्ठल भाई पटेल के समक्ष व्यवस्था की आपत्तियाँ प्रस्तुत की। इन पर अपना निर्णय व्यक्त करते हुए सभाध्यक्ष ने कहा कि उचित यही होगा कि सरकारी सदस्य संशोधन पर वोट न करें ताकि भारतमन्त्री असेम्बली के निर्वाचित सदस्यों की राय का ठीक-ठीक पता लगा सकें, वित्तीय स्वतन्त्रता के निमित्त मिश्रित कर सके कि सरकार की राय और असेम्बली के निर्णय में से कौन बात ठीक है।^३ उन्होंने यह भी घोषित किया कि वित्तीय स्वतन्त्रता की घोषणा और मर्यादा के अन्दर असेम्बली विधेयक के एक अंश को स्वीकार करते हुए दूसरे अंश को नामजूर कर सकती है।^४ पर चूँकि अध्यक्ष का इस प्रकार का सुझाव सरकारी सदस्यों को वोट न देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता था, उन्होंने अध्यक्ष की राय की अवहेलना करने का निश्चय किया। वाणिज्य-मन्त्री ने भी अपनी घमकी वापस नहीं ली। इस पर मालवीयजी के संशोधन पर वोट लेने से पहले अध्यक्ष ने कहा, “मैंने सरकार को कुछ सुझाव दिया था, और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। वाणिज्य-सदस्य ने इस सदन

१. वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २६१५।

२. वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २६१६।

३. वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २६७६।

४. वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २६७५।

को जो घमकी दी है, वह वापस नहीं हुई, और इस दृष्टि से मैं अभिलेख में दर्ज करता हूँ कि इस महत्त्वपूर्ण विषय पर असेम्बली कोई भी निर्णय ले, वह इस सदन का स्वतन्त्र वोट नहीं होगा।”^१ सरकारी सदस्यों ने मालवीयजी के संशोधन के विरुद्ध वोट दिये, और संशोधन ४४ वोटों के मुकाबले में ६० वोटों से नामजूर हो गया। मिस्टर पन्मुखम चेट्टी का संशोधन ४२ वोटों के मुकाबले में ६२ वोटों से स्वीकार हो गया। मालवीयजी ने वोटों का विश्लेषण करते हुए कहा कि जिन सदस्यों ने उनके संशोधन के विरुद्ध वोट दिये उनमें २६ सरकारी सदस्य थे। इस तरह गैरसरकारी सदस्यों का बहुमत उनके संशोधन के पक्ष में था। इसी तरह जिन सदस्यों ने श्री पन्मुखम चेट्टी के संशोधन के पक्ष में राय दी उनमें २६ सरकारी सदस्य थे। गैरसरकारी सदस्यों के वोटों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि सेठ धनश्यामदास विडला ने मालवीयजी के संशोधन के पक्ष में राय दी और सर पन्मुखम् चेट्टी के संशोधन के विरोध में वोट दिया, बाकी सब औद्योगिकों ने मालवीयजी के संशोधन का विरोध किया और मिस्टर पन्मुखम् चेट्टी के संशोधन का समर्थन किया। बम्बई के नरम दलीय सदस्य सर कावसजी जहाँगीर ने भी सरकार का साथ देना ही उचित समझा। नेशनलिस्ट पार्टी और नयी स्वराज्य पार्टी के सभी सदस्यों ने, जिनमें पंडित हृदयनाथ कुजूर, मुन्शी ईश्वर शरण, श्री एन० सी० केलकर, श्री एम० एस० अणे, श्री एम० आर० जयकर, श्री टी० प्रकाशम, श्री टी० आर० फूरुन, श्री नीलकंठदास, दीवान चम्पनलाल भी थे, मालवीयजी के संशोधन के पक्ष में और चेट्टी साहब के संशोधन के विरुद्ध राय दी। कुछ मुसलमान सदस्यों ने, जिनमें युक्तप्रान्त के जनाब मुशहिर हुसैन किदवाई और बंगाल के डाक्टर अब्दुल्ला सोहरावर्दी भी थे, मालवीयजी के संशोधन का समर्थन तथा चेट्टी साहब के संशोधन का विरोध किया, पर मिस्टर जिना और उनकी इंडिपेंडेंट पार्टी के करीब-करीब सभी सदस्यों ने, जिनमें डाक्टर जियाउद्दीन और डाक्टर के० एल० हैदर तथा मौलाना मुहम्मद याकूब भी थे, मालवीयजी के विरोध में तथा चेट्टी साहब के पक्ष में राय दी। चेट्टी साहब का संशोधन मूलरूप से सरकारी प्रस्ताव के पक्ष में था, उसमें और सरकार के प्रस्ताव में केवल शब्दों का हेर-फेर था। चेट्टी साहब का संशोधन, जो सरकारी सदस्यों के वोट से पास हुआ, ब्रिटिश माल पर १५ प्रतिशत और दूसरे विदेशी माल पर २० प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के पक्ष में था।

इस विधेयक पर अन्तिम बार बोलते हुए मालवीयजी ने कहा कि जब अध्यक्ष के सुझाव की अवहेलना करते हुए सरकारी सदस्यों के वोट से प्रस्ताव को पास कराने का निश्चय सरकार ने कर लिया है, तब मेरी पार्टी का सदन में रहना व्यर्थ है।^१ इस विधेयक की वृहत् में अब और भाग लेना "पाप" होगा।^२ यह कहकर वे और उनकी पार्टी के सब सदस्य सदन छोड़कर चले गये। इसके बाद दीवान चम्पन लाल ने भी यह कह कर कि वे मालवीयजी से सहमत हैं, नयी स्वराज्य पार्टी के दूसरे सदस्यों के साथ सदन छोड़ दिया। इन पार्टियों की अनुपस्थिति में सरकार ने आसानी से विधेयक पास करा लिया।

इस्तीफा

कुछ दिन बाद मालवीयजी ने असेम्बली की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने ९ पृष्ठ के त्यागपत्र में काफी विस्तार के साथ सरकार की प्रशासनिक, सैनिक, आर्थिक और वित्तीय नीति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा वैधानिक सुधारों को अपर्याप्त और असन्तोषजनक समझते हैं। फिर भी यदि सरकार ने सुधारों की भावना के अनुरूप काम किया होता, तो देश का कुछ भला हो सकता था। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। पिछले दस वर्ष के अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि वह सरकार, जो असेम्बली को उत्तरदायी नहीं है और उसके द्वारा हटायी नहीं जा सकती, सरकारी और मनोनीत सदस्यों के अपने गुट द्वारा और उन वोटों की सहायता से जिन्हें वह अपने अधिकार और आश्रय (पेट्रोनेज) के बल पर जुटा सकती है, किसी भी प्रस्ताव को कार्यान्वित कर सकती है, और जनता को सहायता और राहत पहुँचाने से इनकार कर सकती है, चाहे वह कितनी ही आवश्यक क्यों न हो। उसने यह भी प्रदर्शित कर दिया है कि "इन सुधारों के बावजूद ब्रिटेन के हितों में भारत का शोषण करने की भारत सरकार की शक्ति बहुत कम घटी है" और उसने अपनी इस शक्ति का प्रयोग पहले की तरह ही रवच्छन्दता से किया है। यह साफ हो गया है कि मौजूदा असेम्बली उस समय "जनता के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है जब सरकार द्वारा उन पर प्रहार किया जाय या उन्हें जोखिम में डाला जाय।" उन्होंने लिखा कि आयात शुल्क विधेयक पर सरकार का व्यवहार संसार के किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायसंगत सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए, उन्होंने कहा, मैंने निश्चय किया है कि "अब मैं असेम्बली का सदस्य रहकर उस संविधान का समर्थन न करूँ जिसके अन्तर्गत

१. वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २७१७।

२. वही, सन् १९३०, जि० ३, पृ० २७१७।

मेरी जनता के ऊपर इस प्रकार का अन्याय लादा जा सकता है। इस व्यवस्था के स्थान पर एक अच्छी व्यवस्था प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न में ही मैं अब अपना समय लगाऊँगा। मुझे आशा है कि इस देश की जनता के साथ न्याय के निमित्त और संसार के सम्य राष्ट्रों के समक्ष अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए आप और दूसरे न्यायप्रिय अंग्रेज उस बड़ी तब्दीली को प्रतिष्ठित करने में हमारी सहायता करेंगे जो हमें अपने मामलों के प्रबन्ध की वही स्वतंत्रता प्रदान करेगी, जो आपको अपने देश में प्राप्त है।

इसके बाद श्री विठ्ठल भाई पटेल ने भी असेम्बली की अध्यक्षता और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

साइमन रिपोर्ट की आलोचना

मालवीयजी के इस्तीफे के बाद असेम्बली का दस बारह दिन का एक छोटा-सा सत्र जुलाई में आयोजित किया गया। इस सत्र में १० जुलाई को वित्त-सदस्य ने गोलमेज कॉन्फरेन्स के खर्चे के लिए २,६६,००० रुपये के अनुदान की माँग पेश की। सेन्ट्रल मुस्लिम पार्टी के सम्मानित सदस्य मिया मुहम्मद शाहनवाज ने १०० रुपये की कटौती का सशोधन पेश करते हुए साइमन कमीशन की संस्तुतियों की कड़ी आलोचना की। काफी बहस के बाद ४१ वोटों के विरुद्ध ६६ वोटों से कटौती का प्रस्ताव पास हो गया, और इस तरह कमीशन की रिपोर्ट करीब करीब सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने रद्द कर दी।

समीक्षा

असेम्बली में कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके पूर्ण सहयोग के बिना किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर सरकार को हाराना असम्भव था। पर इसके लिए नेशनलिस्ट पार्टी का सहयोग भी नितान्त आवश्यक था। उसने डट कर सरकार का विरोध किया। तीन वर्ष के अन्दर किसी भी प्रश्न पर नेशनलिस्ट पार्टी की उपेक्षा के कारण विरोधी पक्ष को हार का सामना नहीं करना पड़ा। वित्त विधेयक को रद्द करने के प्रश्न पर नेशनलिस्ट पार्टी के कतिपय सदस्य तटस्थ रहे, पर इस प्रश्न पर स्वराज्य पार्टी के सब सदस्यों ने भी अपने नेता पंडित मोती लाल नेहरू का साथ नहीं दिया। बहस में नेशनलिस्ट पार्टी का योगदान किसी तरह कांग्रेस पार्टी से कम नहीं रहा। मालवीय जी, लाला लाजपत राय, मिस्टर जयकर, मिस्टर कैलकर, मुंशी ईश्वर शरण,

पंडित हृदयनाथ कुंजरू आदि ने हर प्रश्न पर सरकार की नीतिरीति और क्रियाकलापो की कड़ी समीक्षा की। वास्तव में मुद्राविधेयक, रिजर्व बैंक विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल (सार्वजनिक रक्षा विधेयक) पर तथा सीमा शुल्क आदि कतिपय प्रश्नों पर मालवीयजी के भाषण सबसे उत्तम और उनकी समीक्षा सर्वोपरि थी। साइमन कमीशन, सैनिक नीति, तथा राजनीतिक सुधार के प्रश्नों पर सरकार को कांग्रेस और नेशनलिस्ट पार्टी के अतिरिक्त जिना साहब की इंडिपेंडेंट पार्टी के तगड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा। इन प्रश्नों पर जिना साहब की समीक्षा भी काफी महत्वपूर्ण होती थी। समाज-सुधार के प्रश्नों पर मालवीयजी का योगदान नगण्य था, पर नेशनलिस्ट पार्टी के नेता लाला लाजपत राय और उसके सम्मानित सदस्य मुंशी ईश्वर शरण और पंडित हृदय नाथ कुंजरू का योगदान भरपूर था। मजदूरों की समस्याओं पर कांग्रेस पार्टी के सदस्य और मजदूर आन्दोलन के नेता दीवान चम्पन लाल और जमनादास मेहता का कार्य भी सराहनीय था।



१८. साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट

साइमन कमीशन

नवम्बर सन् १९२७ में संवैधानिक प्रगति की जाँच के लिए सर जान साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सात सदस्यों का एक स्टैंड्यूटरी कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन के सभी सदस्य पार्लियामेंट के यूरोपियन सदस्य थे और इसकी नियुक्ति इस सिद्धान्त पर आधारित थी कि भारत के संविधान की गतिविधि का निर्णय करना ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही उत्तरदायित्व है। कमीशन की नियुक्ति की घोषणा करते हुए वाइसराय ने यह भी कहा कि सम्राट की सरकार की राय में गवाहियाँ लेने में कमीशन का काम आसान हो जायगा, यदि वह केन्द्रीय विधान मंडल के निर्वाचित और मनोनीत गैरसरकारी सदस्यों को अपने में से एक कमेटी नियुक्त करने को आमन्त्रित करे, और उसे लिखित रूप में अपने विचार कमीशन के सामने पेश करने का मौका दे।

बाइकाट

भारतीय समाचारपत्रों और राजनीतिज्ञों ने इसकी कड़ी आलोचना की। सरकार को उदारदलीय नेताओं के सहयोग की आशा थी, पर वे भी सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं हुए। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के संवैधानिक अधिकार को स्वीकार करते थे। पर उन्हें कमीशन में किसी एक हिन्दुस्तानी का भी नियुक्त न किया जाना अखरता था, और केन्द्रीय विधान मंडल की संयुक्त कमेटी का साक्षी या परीक्षार्थी के रूप में कमीशन के सामने उपस्थित होना अपमानजनक दिखाई देता था। जिना साहब बहुत क्षुब्ध थे। करीब-करीब सभी प्रगतिशील संस्थाओं के प्रमुख नेताओं ने कमीशन के विरुद्ध वक्तव्य प्रकाशित किये।

मालवीयजी के वक्तव्य

मालवीयजी ने साइमन कमीशन की नियुक्ति से पहले ही ब्रिटिश सरकार से तार द्वारा माँग की थी कि कमीशन में हिन्दुस्तानी सदस्यों की संख्या यूरोपियनों के बराबर हो, और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी थी कि यदि कमीशन में हिन्दुस्तानी नहीं रखे गये, तो हिन्दुस्तान उसका बाइकाट करेगा। जब कमीशन

नियुक्त हो गया, तब अन्य नेताओं की तरह मालवीयजी ने भी जनता को उसके बाइकाट की सलाह दी। उन्होंने जनता से अपील की कि “वह दृढ़-प्रतिज्ञा होकर जितनी शीघ्र हो इस शासन-प्रणाली का अन्त कर देने के लिए प्राणपण से तैयार हो जाये”, तथा “प्रतिज्ञा करे कि वे अपने देश भाइयों के साथ जाति-पाँति का भेद छोड़कर अपने ही सदृश उनके जीवन, उनकी प्रतिष्ठा, तथा उनकी स्वतंत्रता का आदर करेंगे, तथा जातिगत या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश के स्वार्थ का बलिदान नहीं करेंगे”।^१ २४ नवम्बर के इस लेख में मालवीयजी ने सलाह दी कि (१) जनवरी सन् १९३० तक पूर्ण स्वराज्य ले लेने की घोषणा की जाय, (२) सभी दलों और विचारों के प्रतिनिधि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में उपस्थित हो, (३) प्रान्तीय कौंसिलों और केन्द्रीय असेम्बली के सब निर्वाचित सदस्य कांग्रेस के सदस्य समझे जायें, (४) नवनिर्मित कांग्रेस फरवरी सन् १९२८ में पूर्ण स्वराज्य के उपयुक्त शासन-विधान तैयार करे।^२

मालवीयजी ने अपने इस लेख में यह भी लिखा कि ब्रिटिश सरकार और जनता को यह भी सूचित किया जाय कि “यदि वह कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित राज्यव्यवस्था को पूर्णतः अथवा परस्पर निर्णीत परिवर्तनों के साथ स्वीकार नहीं करती, तो कांग्रेस को बाध्य होकर भारतीय जनता को यह आदेश देना पड़ेगा कि वह असहयोग का चरम स्वरूप धारण करे, अर्थात् करो का देना बन्द कर दे, तथा ब्रिटिश वस्तुओं के पूर्णतः बहिष्कार का आन्दोलन करे”।^३

मालवीयजी यह चाहते थे कि भारतीय नागरिक समाज स्थापित किया जाय, जिसके द्वारा प्रत्येक गाँव और नगर में नागरिकता की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, तथा प्रत्येक भारतीय में अपने को भारतीय राज्य का स्वतन्त्र नागरिक समझने की भावना पैदा की जाय।^४

उनकी यह भी इच्छा थी कि नवनिर्मित कांग्रेस की समितियों में पूर्ण विश्वसनीय नेता हों, जो दो वर्षों तक अपने सभी अन्य कामों को छोड़कर स्वराज्य की प्राप्ति के निमित्त अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दें, और जनता को इसकी शिक्षा दें।^५

१. हिन्दुस्तान टाइम्स, २४ नवम्बर, सन् १९२७।

२. वही।

३. वही।

४. वही।

५. वही।

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल

२५ नवम्बर को भारत-मन्त्री लार्ड वर्कनहेड ने पार्लियामेंट में कहा कि केन्द्रीय विधान मंडल को साक्षी समझ बैठना किसी तरह न्याय संगत नहीं होगा। वे तो ईमानदारी से सहयोगी के रूप में कमीशन से सहयोग करने को निमंत्रित किये गये हैं। प्रधान-मन्त्री वाल्डविन ने इस आश्वासन की ओर संकेत करते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपना उत्तर-दायित्व स्वयं वहन करना होगा, कोई दूसरी प्रतिनिधि संस्था उसमें हिस्सेदार नहीं बनायी जा सकती।

मालवीयजी की प्रतिक्रिया

इस पर २७ नवम्बर को मालवीयजी ने एक लेख में कहा कि यद्यपि पार्लियामेंट में केन्द्रीय कमेटी के सम्बन्ध में सहयोगी और समकक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, पर कमीशन की किसी कार्य-प्रणाली द्वारा वे समकक्षता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हिन्दुस्तान का बहिष्कार जारी रहेगा।^१

बहिष्कार

दिसम्बर में कांग्रेस, हिन्दू महासभा, अखिल भारतीय लिबरल फेडरेशन आदि संस्थाओं ने ब्रिटिश सरकार की नीतिरोति की आलोचना करते हुए साइमन कमीशन के बहिष्कार की जनता तथा विधान कौंसिलो से अपील की। लिबरल फेडरेशन ने अपने वार्षिक अधिवेशन में निर्णय किया कि कमीशन की योजना स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि वह अपने देश के भावी संविधान के बनाने में समता के आधार पर भाग लेने के अधिकार से भारतीय जनता को वंचित करती है। हिन्दू महासभा ने भी योजना को आपत्तिजनक और अपमानजनक घोषित करते हुए जनता से अपील की कि वह किसी मजिल और किसी रूप में कमीशन से सहयोग न करे।

कांग्रेस

कांग्रेस ने भी डाक्टर अन्सारी की अध्यक्षता में आयोजित अपने मद्रास अधिवेशन में हर मजिल में और हर प्रकार से कमीशन के बाइकाट का निर्णय किया। उसने विधान कौंसिलो के निर्वाचित सदस्यों से अपील की कि वे कमीशन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दें। उसने स्थानीय कांग्रेस संगठनों को आदेश दिया कि वे बाइकाट को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके सम्बन्ध में

जनता में प्रचार करे, तथा जिस दिन कमीशन भारत आये उस दिन सारे देश में उसके विरोध में हड़ताल और प्रदर्शन आयोजित किये जायें, और जब कमीशन किसी नगर में जाये तब वहाँ भी विरोधी प्रदर्शन हो। उसने जनता को आह्वान किया कि वे इन प्रदर्शनों में भाग लेकर उन्हें सफल बनाये। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि देश की दूसरी पार्टियों के सहयोग से भारत का संविधान तैयार किया जाय। इसी अवसर पर कांग्रेस ने राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास करते हुए कतिपय उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जिनके कारण हिन्दुओं और मुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्धों में उलझने पैदा हो रही थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्ष में भी प्रस्ताव पास किया।

मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया

साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रश्न पर गहरा मतभेद हो जाने के कारण मुस्लिम लीग दो टुकड़ों में बँट गयी। एक के प्रमुख नेता जिना साहब और दूसरे के सर मुहम्मद शफी थे। जिना साहब को सर अली इमाम, डाक्टर अब्दुल क़रीम, मौलाना आजाद, और मौलाना मुहम्मद अली आदि का, और शफी साहब को सर अमीर अली, और हिज हाइनेस आगा खा, डाक्टर मुहम्मद इकबाल, मौलाना हसरत मोहानी आदि का समर्थन प्राप्त था। दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए मुस्लिम लीग के नाम पर अलग-अलग अधिवेशन किये। शफी साहब की अध्यक्षता में आयोजित अधिवेशन में सहयोग के पक्ष में, तथा जिना साहब के नेतृत्व में आयोजित अधिवेशन में बाइकाट के समर्थन में प्रस्ताव पास हुए।

राजनीतिक समझौते के सम्बन्ध में मुस्लिम विधायकों का मार्च सन् १९२७ का सुझाव शफी साहब की लीग स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसने राजनीतिक सुधारों से सम्बन्धित मद्रास कांग्रेस के प्रस्ताव को भी नामजूर कर दिया। पर कलकत्ते में आयोजित मुस्लिम लीग काफरेन्स ने कांग्रेस का प्रस्ताव इस शर्त पर स्वीकार किया कि जब सिन्ध अलग प्रान्त बना दिया जायेगा, तथा सीमाप्रान्त और बलूचिस्तान में राजनीतिक सुधार लागू कर दिये जायेंगे, तब सयुक्त निर्वाचन-पद्धति भी चालू हो जायगी। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के आधार पर विधान मण्डलों में स्थान सुरक्षित होंगे; पर जिस अनुपात से हिन्दू अपने बहु-संख्यक प्रान्तों में मुसलमानों को अधिक स्थान देने को तैयार होंगे, उसी अनुपात से सीमा प्रान्त, सिन्ध और बलूचिस्तान में

हिन्दुओं को स्थान दिये जायेंगे। इसके बाद लीग के कलकत्ता अधिवेशन में मालवीयजी ने भारत को "समृद्धि और अधिकार के नये युग में" प्रवेश कराने के लिए एकता को सुदृढ़ करने की अपील की। उन्होंने कहा : "हम यह याद रखें कि हम पहले हिन्दुस्तानी और बाद को हिन्दू और मुसलमान हैं, हम एक दूसरे के साथ ध्याय का व्यवहार करें, और यदि हमने ऐसा किया तो स्वराज्य कोई रोक नहीं सकता।" इसके बाद जिना साहब ने कहा—“जलियांवाला बाग शारीरिक हत्याकांड था, साइमन कमीशन हमारी आत्माओं पर कुठाराघात है। एकमात्र मोरो का कमीशन नियुक्त करके लार्ड वर्केंहेड ने स्वशासन के लिए हमारी अयोग्यता घोषित की है। मैं पंडित मालवीय का स्वागत करता हूँ। मैं कांग्रेस और हिन्दू महासभा के गंचों से हिन्दुओं के मंत्री के हाथ का स्वागत करता हूँ। मुझे यह भेट उन सब रियायतों से अधिक प्रिय है। हमें मंत्री के हाथ को कस कर पकड़ना चाहिए। यह शुभ दिन है और इसके लिए हमको लार्ड वर्केंहेड को धन्यवाद देना चाहिए।”

कमीशन की कार्य-प्रणाली

७ फरवरी सन् १९२८ को कमीशन की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सर जान साइमन का लिखा पत्र वाइसराय ने प्रकाशित किया। इस पत्र में बताया गया कि कमीशन का काम सान अंग्रेज और सात हिन्दुस्तानियों के बीच संयुक्त स्वतन्त्र कांग्रेस का रूप धारण करेगा। केन्द्रीय विषयों के सम्बन्ध में सात हिन्दुस्तानियों का चुनाव केन्द्रीय विधान मण्डल करेगा। कमीशन अपनी रिपोर्ट सम्राट् की सरकार को भेजेगा, हिन्दुस्तानी सदस्य अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय विधान मंडल को भेज सकते हैं। वे चाहे तो उनकी रिपोर्ट कमीशन की रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में नत्थी की जा सकती है। जब विभिन्न प्रान्तों की स्थिति की जाँच के लिए कमीशन प्रान्तों में जायेगा, तब वह वहाँ की प्रान्तीय विधान कौंसिल द्वारा निर्वाचित सात हिन्दुस्तानी सदस्यों के साथ काम करेगा।

भारतीय नेताओं को साइमन साहब की यह योजना पसन्द नहीं थी। उन्होंने ८ फरवरी को दिल्ली में इकट्ठे होकर घोषित किया कि वे कमीशन के बहिष्कार पर अडिग हैं, और कमीशन की शर्तों पर उसके साथ सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। २० फरवरी को जिना साहब ने असेम्बली के साथियों से

सलाह करने के बाद साइमन कमीशन के बाइकाट के निर्णय को दुहराते हुए सब पार्टियों के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और सब राजनीतिक संस्थाओं से अपील की कि वे आपस में मिलकर साम्प्रदायिक समस्या हल करें, भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करके कन्वेंशन द्वारा इसे स्वीकार करायें, तथा उसकी स्थापना के लिए प्रयत्न करें^१।

केन्द्रीय असेम्बली द्वारा बाइकाट

१६ फरवरी सन् १९२८ को लाला लाजपत राय ने केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि यह असेम्बली गवर्नर-जनरल इन-कौंसिल को संस्तुति करती है कि सदन को कमीशन का गठन और योजना विलुगल नामजूर है, और इसलिए वह किसी अवस्था और ढंग में कमीशन से सहयोग नहीं करेगी। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए उन्होंने बहुत ही कटे शब्दों में ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए स्पष्ट कहा कि समता के आधार पर ही जनता के प्रतिनिधि सरकार से सहयोग कर सकते हैं। सरकार की इस घमकी का जवाब देते हुए कि यदि अंग्रेज चले जायेंगे तो देश में अराजकता फैल जायेगी, उन्होंने कहा कि किसी विदेशी या विदेशी सस्था द्वारा सगीन की नोक पर कानून की अराजकता लागू करने से बड़ी अराजकता क्या हो सकती है^२।

इस प्रस्ताव पर सेट्रल मुस्लिम पार्टी के सम्मानित सदस्य सर जुल्फिकार अली खान ने संशोधन पेश किया कि "यह असेम्बली गवर्नर-जनरल-इन कौंसिल को संस्तुति करती है कि वह सम्राट् की सरकार को इस असेम्बली की यह राय बता दे कि भारतीय साविधिक आयोग (इण्डियन स्टैट्यूटरी कमीशन) द्वारा प्रस्तुत कार्यप्रणाली असेम्बली के स्वीकारात्मक विचार के योग्य है"^३।

लाला लाजपत राय के प्रस्ताव का समर्थन जोरदार भाषणों द्वारा सर्वश्री एस० श्रीनिवास ऐयंगर, एम० आर० जयकर, मुहम्मद अली जिना, टी० सी० गोस्वामी, मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास, ठाकुरदास, रंगा अय्यर तथा मालवीय जी ने किया। सरकार की ओर से श्री केरार, सर भूपेन्द्र मित्र, सर बेसिल ब्लेकट ने सर जुल्फिकार अली खान साहब के संशोधन का समर्थन किया।

मालवीयजी ने कहा कि वे आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को मानते हैं। उनके विचार में "जनता द्वारा जनहित में जनता की सरकार ही सर्वोत्तम है।"

१ नौमान: मुस्लिम इंडिया, पृ० २६९।

२. असेम्बली डिबेट्स, सन् १९२८, जि० १, पृ० ३८४।

“भारत के संविधान का निर्माण”, उन्होंने कहा, “भारतीयों के सुपुर्द ही किया जाना चाहिए।” ब्रिटिश पार्लियामेंट उसे नियमानुसार कानूनी रूप दे दे। उन्होंने कहा, “हम स्वतन्त्रता चाहते हैं, और हमारा दावा है कि हम अपना शासन स्वयं चलाने के योग्य हैं, और अंग्रेज जवर्दस्ती हमें अपने अधिकार के अधीन बनाये रखना चाहते हैं।” उन्होंने कहा . “अपना अधिकार प्राप्त करने के वास्ते युद्ध और समझौता, यही दो तरीके हैं। हम इस समय समझौते द्वारा अधिकार प्राप्त करने के प्रयत्न में हैं। पर यदि हम इसमें विफल हुए तो शासन की मौजूदा पद्धति से छुटकारा पाने के लिए इस देश की जनता दूसरे उपायो को, हर सम्भव और न्यायसंगत उपाय, को अपनाने के लिए सोचने को बाध्य होगी।”^१

लाला लाजपत राय का प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार हो गया। ६८ सदस्यों ने उसके पक्ष में और ६३ ने उसके विरोध में राय दी।

इसके कुछ दिन बाद बजट पर बहस के दौरान में १३ मार्च सन् १९२८ को पण्डित मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन के खर्चों के लिए अनुदान की माँग का विरोध किया। मालवीयजी ने मोती लालजी की राय का समर्थन किया। दोनों की राय थी कि जिसने कमीशन नियुक्त किया उसे ही उसका खर्चा वहन करना चाहिए। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि जबकि कमीशन काम कर रहा है, तब उसके लिए अनुदान नामजूर करना अवैधानिक होगा। इसके उत्तर में मालवीयजी ने कहा . “भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की आकाक्षाओं का ध्यान रखे बिना भारत की ओर से रुपया खर्च करना सरकार का सर्वाधिक अवैधानिक कार्य है।”^२ ५९ रायों के विरुद्ध ६६ रायों से असेम्बली ने अनुदान की माँग रद्द कर दी।

बाइकाट प्रदर्शन

कांग्रेस की तरह नेशनलिस्ट पार्टी ने भी साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित प्रदर्शनों में भाग लिया। जहाँ भी कमीशन गया वहाँ जनता ने उसके विरुद्ध प्रदर्शन किये, ‘साइमन वापस जाओ’ के नारे लगाये। पुलिस ने प्रदर्शनकारी जनता को बुरी तरह मारा पीटा। लखनऊ में पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत और पण्डित जवाहरलाल नेहरू पर भी प्रहार किये गये। पर लाहौर में तो उसने

१. वही, सन् १९२८, जि० १, पृ० ४८८।

२. वही, सन् १९२८, जि० २, पृ० १३८३।

अपनी बर्बरता की हद कर दी। वहाँ प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। मालवीयजी उसमें शामिल थे। लालाजी के नेतृत्व में जुलूस शान्ति के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। सरकार ने रोक के लिए एक स्थान पर सड़क पर काँटेदार तार लगवा दिये थे, जिसे तोड़कर साइमन कमीशन के सदस्यो तक पहुँचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। फिर भी पुलिस के अफसरो और सारजेण्टो ने वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय को इस तरह पीटा कि कुछ दिन बाद १७ नवम्बर को उनका निधन हो गया।

१४ फरवरी सन् १९२९ को पण्डित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने केन्द्रीय असेम्बली में लाला लाजपत राय के निधन पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल से संस्तुति की गयी थी कि वे "भारत-मन्त्री और उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार को 'असेम्बली का यह सदेश पहुँचा दें कि यह सदन लाला लाजपत राय के निधन पर २५ नवम्बर सन् १९२८ को किये गये मजदूर दल के प्रश्न पर उप-भारत-मन्त्री अर्ल विंटरटन के अपमान-जनक उत्तर पर अपना रोप प्रकट करता है, और विश्वास करता है कि लाला लाजपत राय के निधन में उस चोट से जल्दी हुई, जो उन्हें लाहौर में साइमन कमीशन के आगमन पर बहिष्कार-प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पुलिस के हाथों पहुँची थी, तथा उसकी राय है कि व्वायड कमेटी द्वारा जो जाँच की गयी वह अवास्तविक थी, और जान बूझकर पुलिस द्वारा किये गये अपराधो को उचित सिद्ध करने तथा छिपाने के लिए नियुक्त की गयी थी"।

पण्डित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने मिस्टर व्वायड के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत की 'नयी पीढी का सरकार पर से विश्वास बिल्कुल उठ गया है', और 'लाला लाजपत राय के कत्ल ने ब्रिटिश सरकार के प्रति अनम्य विद्वेष के हमारे भाव को केवल पुष्ट कर दिया है'।

मुंशी ईश्वर शरण ने सशोधन उपस्थित किया कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह कहा जाय कि "असेम्बली गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल से संस्तुति करती है कि वे गृहसदस्य, पण्डित मोतीलाल नेहरू, पण्डित भदन मोहन मालवीय, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, नवाब सर साहबजादा अब्दुल कयूम, मौलवी मुहम्मद याकूब और मुंशी ईश्वरशरण की एक कमेटी उन आरोपो की जाँच के लिए नियुक्त करे जो असेम्बली की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता लाला लाजपत राय पर प्रहार, तथा उनके द्वारा उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में किये जाते हैं, और कमेटी को आदेश दे कि वह अपनी नियुक्ति के एक मास के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे"।

रायजादा हंसराज ने, जो लाहौर के जुलूस में लाला लाजपत राय के साथ थे सब हाल विस्तार से बताते हुए कहा कि पुलिस सिर्फ लाला जी को पीटना चाहती थी, और यदि सब चोटें उनको लगती तो उनकी वही मृत्यु हो गयी होती। सर्वश्री जयकर, मोतीलाल नेहरू और जिना ने सरकार की कड़ी आलोचना की।

मालवीयजी ने कहा कि यदि सरकार निष्पक्ष जाँच कराने को तैयार नहीं है तो उसे चुपके से लाला लाजपत राय और लाला हंसराज जैसे सम्मानित व्यक्तियों का वयान स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की दृढ़ धारणा है कि पुलिस का आघात पूर्व-निर्धारित था। उन्हें शक है कि जिस अनजान व्यक्ति ने लाला लाजपत राय पर कुछ देर छनरी लगायी, उसने पुलिस को लालाजी को पहचनवाने के लिए ऐसा किया था। मालवीयजी ने कहा कि प्रदर्शन शान्त था, उसे शान्त रखने में लालाजी का महत्त्वपूर्ण हाथ था, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने का सब नागरिकों को अधिकार है। उन्होंने बताया कि यदि दफा १४४ नहीं लगायी गयी होती, तो लालाजी और वह प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होते। पुलिस के दुर्व्यवहार से, मालवीयजी ने कहा, लाला लाजपत राय को शारीरिक चोट में भी वही अधिक मानसिक वेदना हुई। वे समझ नहीं पाते थे कि उन जैसा व्यक्ति भी इस तरह एक साधारण पुलिस अधिकारी द्वारा सबके सामने पीटा जा सकता है। मालवीयजी ने बताया कि दो डाक्टरों का वयान है कि चोट ने लालाजी की मृत्यु में जल्दी कर दी। इस वयान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार के व्यवहार ने मौजूदा शासन-व्यवस्था के विरुद्ध जनता में असन्तोष बढ़ा दिया है। सरकार लाला हंसराज के वयान को स्वीकार करके पश्चात्ताप प्रकट क्यों नहीं करती ?

काफी लम्बी बहस के बाद ४५ वोटों के विरुद्ध ५७ वोटों से मुंशी ईश्वर शरण का संशोधन असेम्बली ने पास कर दिया।

सर्वदलीय कांफरेन्स

१२ फरवरी सन् १९२८ को दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें निश्चय हुआ कि उत्तरदायी शासन के आधार पर हिन्दुस्तान के लिए विधान तैयार किया जाय, लेकिन जिन्हें पूर्ण स्वराज्य पर विश्वास है उन्हें उसके लिए प्रयत्न करते रहने की स्वतन्त्रता होगी। इसके बाद १९ मई को बम्बई में सर्वदलीय कांफरेन्स की बैठक हुई। यहाँ संविधान की रूपरेखा तैयार करने की पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की

गयी। मोतीलालजी के अतिरिक्त सर्वश्री तेजबहादुर सप्रू, अली इमाम, एम० आर० जयकर, एम० एस० अणे, शुएब कुरेशी, जी० आर० प्रधान, तथा सरदार गंगल सिंह कमेटी के सदस्य नियुक्त हुए। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कमेटी के मन्त्री का काम किया।

कमेटी के सामने साम्प्रदायिक प्रश्न ही सबसे जटिल प्रश्न था। जबकि सिक्ख प्रतिनिधि सरदार गंगल सिंह किसी भी सम्प्रदाय के लिए स्थानों के संरक्षण के पक्ष में नहीं थे, कतिपय हिन्दू सदस्य अल्प-संख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित किये जाने के पक्ष में थे। मुसलमान सदस्य चाहते थे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों हालतों में मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित हो। अन्ततोगत्वा इस प्रश्न के कुछ अंश को पूरी कांफरेन्स के निर्णय पर छोड़ते हुए कमेटी की रिपोर्ट तैयार की गयी। इसका कुछ अंश जवाहर लालजी की सहायता से मोतीलालजी ने, और कुछ अंश सर तेजबहादुर सप्रू ने लिखा।

लखनऊ अधिवेशन

अगस्त के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ में कांफरेन्स का अधिवेशन हुआ। उसमें कमेटी की रिपोर्ट पर विचार हुआ, तथा सिंध और पंजाब के प्रतिनिधियों ने आपस में बातचीत करके सर्वसम्मति से कुछ निर्णय किये, जिन्हें कांफरेन्स ने स्वीकार किया। सिंध के प्रतिनिधियों ने तय किया कि स्वराज्य मिलने पर सिंध एक अलग प्रान्त होगा। पंजाब के मुसलमान प्रतिनिधियों ने निश्चय किया कि वे संयुक्त निर्वाचन के साथ नेहरू रिपोर्ट की प्रतिनिधि सम्बन्धी संस्तुति स्वीकार करते हैं, और यदि निर्वाचन-पद्धति वयस्क मताधिकार पर आश्रित हो, तो किसी सम्प्रदाय के लिए कोई स्थान सुरक्षित न किया जाय, पर दस वर्ष के बाद स्थिति पर फिर से विचार किया जा सकता है। मास्टर तारा सिंह, और ज्ञानी शेर सिंह ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया।

मालवीयजी ने कांफरेन्स में प्रस्ताव किया कि उन राजनीतिक पार्टियों की स्वतन्त्रता पर कोई रोक लगाये बिना जो पूर्ण स्वतन्त्रता पर विश्वास करते हैं, यह कांफरेन्स निश्चित करती है कि भारत में उत्तरदायी शासन प्रतिष्ठित किया जाय, और उसका स्तर स्वशासित डोमिनियन से किसी प्रकार कम न हो। कुछ वृहत् के बात बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

मालवीयजी ने यह भी प्रस्ताव किया कि कमेटी की संस्तुतियों में सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाय।

इस प्रस्ताव का आशय यह था कि भारतीय कामनवेल्थ की स्थापना के समय जिन लोगों के अधीन जो जायज (ला-फुल) सम्पत्ति होगी, उस पर उनका पूरा अधिकार माना जायगा, और उसके उपयोग की उन्हें पूरी स्वतन्त्रता होगी। प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

कमेटी ने पण्डित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, डा० एनी बेसेंट, डाक्टर अन्सारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्री सी० विजयराघवाचार्य तथा मिस्टर अब्दुल लतीफ कसूरी को भी कमेटी में शामिल कर लिया।

नेहरू कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट पर लाला लाजपतराय के अतिरिक्त, जो साइमन कमीशन के बहिष्कार में आयोजित जुलूस में चोट खाने के कारण बीमार हो गये थे, बाकी सबके हस्ताक्षर थे। पर लाला लाजपत राय ने २७ अक्टूबर सन् १९२९ को ही अपने एक भाषण में कहा था—“नेहरू रिपोर्ट के सिद्धान्त ही वे सिद्धान्त हैं जिन पर इस समय हिन्दुस्तान के लिए लोकनाट्रिक संविधान तैयार किया जाना संभव है। वह अल्पसंख्यकों को काफी गारंटी (सुरक्षा) प्रदान करता है, और वह उनके लिए राष्ट्र के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों में ठोस और प्रभावकारी भाव सुनिश्चित करता है।”^१ उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट जैसी है मैं जी-जान से इसका समर्थन करता हूँ, और “मैं सारे हिन्दुस्तान के हिन्दुओं को सलाह दूंगा कि वे क्रीडकौशल मिश्रित विशुद्ध देशभक्ति की भावना से इसे स्वीकार करें और इसका समर्थन करें।”^२

कांग्रेस ने नेहरू कमेटी द्वारा प्रस्तावित संविधान को “भारत की राजनीतिक और साम्प्रदायिक समस्याओं की ओर एक बड़ा योगदान” मानते हुए उसका “स्वागत” किया, पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि ३१ दिसम्बर सन् १९२९ तक या उससे पहले इस संविधान को सरकार ने मंजूर नहीं किया, तो कांग्रेस उसे मानते रहने को तैयार नहीं होगी, और उसके बाद सरकार को कर या अन्य आर्थिक सहायता न दी जाय इस बात की जनता को सलाह देते हुए अहिंसात्मक असहयोग फिर चालू कर दिया जायगा।

सर्वदलीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन

दिसम्बर में सर्वदलीय कांग्रेस की बैठक में कतिपय उपस्थित सज्जनों ने मांग की कि मालवीयजी द्वारा प्रस्तावित सम्पत्ति सम्बन्धी धारा प्रस्तावित

१. जोशी : लाला लाजपत राय स्पीचेज एंड राइटिंग्स, जि० २, पृ० ४४४।

२. वही, पृ० ४४९।

संवैधानिक योजना में से निकाल दी जाय। मालवीयजी ने इस सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि यदि नयी व्यवस्था समझौते तथा रजामन्दी से बनना है, तो जमींदारों की भावनाओं का भी ध्यान रखना ही होगा, तथा जमींदारों और खेतिहरों के बीच में न्यायसंगत और उचित सम्बन्धों को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सम्पत्ति संवर्धनी प्रस्तावित धारा एक सुप्रसिद्ध परम्परा है जो प्रत्येक लोकतान्त्रिक संविधान में पायी जाती है। जल्दी से सम्पत्ति की रक्षा ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि न्याय की प्रतिष्ठा तथा देश के हित में जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन कभी आवश्यक समझा जाय, तो यह धारा उसमें बाधक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय पार्लियामेंट भूमिस्वामियों को समुचित मुआवजा दे कर कानून द्वारा सम्पूर्ण भूमि प्राप्त कर सकती है। उन्होंने इस विचार का खण्डन करते हुए कि मौजूदा सरकार के अधीन स्वामित्व के जो कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं वे सब दोषपूर्ण हैं, कहा कि निजी सम्पत्ति की परम्परा बहुत पुरानी है। सशोधन नामजूर हो गया।

इस काफरेन्स में कतिपय उग्रवादी सदस्यों ने औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात् डोमिनियन स्टेट्स के सुझाव का विरोध करते हुए पूर्ण स्वराज्य का समर्थन किया, और इस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये। कुछ बाद-विवाद के बाद सब सशोधन नामजूर हो गये, और औपनिवेशिक स्वराज्य की व्यवस्था स्वीकार हो गयी। मालवीयजी ने इस विवाद में कोई भाग नहीं लिया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि चूँकि नेहरू कमेटी द्वारा तैयार की हुई व्यवस्था देश के प्रमुख दलों में सबसे अधिक सहमति की द्योतक है इसलिए कांग्रेस उसे स्वीकार करती है, और निश्चय करती है कि वह उसे अपना लेगी, यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट ३१ दिसम्बर सन् १९२९ तक उसे पूरी तौर पर स्वीकार कर ले।

सर अली इमाम, डाक्टर अन्सारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजा साहब महमूदाबाद आदि मुसलमान नेता कमेटी द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था स्वीकार करने को तैयार थे। करीब-करीब सभी ईसाई और पारसी भी इसे ठीक समझते थे। कांग्रेस, लिबरल दल, और नेशनलिस्ट पार्टी से संबंधित सभी हिन्दू नेता भी इसे स्वीकार करते थे। हिन्दू सभा के नेताओं का भी कोई विशेष विरोध नहीं था, यद्यपि सिन्ध के सम्बन्ध में उनमें मतभेद अवश्य था, और बंगाल के कतिपय हिन्दू नेता अपने प्रान्त में अपने हितों की रक्षा के निमित्त जनसंख्या के अनुपात से हिन्दुओं के लिए विधान सभा में स्थान सुरक्षित रखना चाहते थे। पर सेंट्रल

खिलाफत कमेटी और मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट की संस्तुतियों से इतनी असंतुष्ट थी कि उनके प्रतिनिधियों ने सर्वदलीय काफरेन्स में भाग लेने से भी इनकार कर दिया। सेंट्रल सिक्ख लीग भी संतुष्ट नहीं थी।

इस परिस्थिति में काफरेन्स ने डाक्टर अन्सारी की अव्यक्षता में एक कमेटी साम्प्रदायिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए बनायी। मालवीयजी भी इस कमेटी के सदस्य बनाये गये। कमेटी ने मुस्लिम लीग तथा केन्द्रीय खिलाफत कमेटी के प्रतिनिधियों से बातचीत की, सेंट्रल सिक्ख लीग के सदस्यों से भी मुलाकात की। कमेटी ने कुछ बातें स्वीकार की, कुछ सुझाव रद्द कर दिये, और कुछ माँगों पर कोई सर्वसम्मत राय नहीं व्यक्त की। उसने यह स्वीकार किया कि संविधान तब तक सशोधित नहीं होगा या बदला जायेगा जब तक प्रस्तावित सशोधन या तब्दीली भारतीय पार्लियामेण्ट के 'दोनों सदनों से अलग अलग उपस्थित सदस्यों के अस्सी प्रतिशत बहुमत से स्वीकार न हो, और जब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उसे अस्सी प्रतिशत उपस्थित सदस्य स्वीकार न करें। कमेटी ने संस्तुति की कि अवशिष्ट अधिकार केन्द्रीय विधान मंडल में ही निहित रहें। कमेटी ने हिन्दू सभा बंगाल की यह बात मानने से इनकार कर दिया कि बंगाल में हिन्दुओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित किये जायें। कमेटी इस बात पर सहमत नहीं हो सकी कि मुसलमानों के लिए केन्द्रीय विधान सभा में एक तिहाई स्थान सुरक्षित किये जायें, और सिक्खों के लिए पंजाब विधान सभा में तीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहे।

डाक्टर अन्सारी ने कमेटी की रिपोर्ट काफरेन्स में पेश की। जिना साहब ने इस अवसर पर वहाँ उपस्थित ही रिपोर्ट की, आलोचना की। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम समझौते को देश की उन्नति के लिए नितान्त आवश्यक बताते हुए मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए कई संशोधन पेश किये। उन्होंने प्रस्ताव किया कि केन्द्रीय विधान सभा में संयुक्त निर्वाचन द्वारा एक तिहाई निर्वाचित स्थान मुसलमानों को दिये जायें। उन्होंने काफरेन्स से यह भी अनुरोध किया कि यदि वयस्क मताधिकार लागू न हो, तो पंजाब और बंगाल के मुसलमानों के लिए जनसंख्या के अनुपात से विधान सभाओं में स्थान सुरक्षित रखने की संस्तुति की जाय, और इस प्रश्न पर दस वर्ष के बाद फिर विचार किया जाय। उनका एक प्रस्ताव यह था कि अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को सौंपे जायें। उन्होंने यह भी कहा कि सिंध का पृथक्करण और उत्तर पश्चिम प्रान्त में

राजनीतिक सुधारों की व्यवस्था नेहरू रिपोर्ट के लागू होने पर निर्भर नहीं की जा सकती। जिना साहब ने कहा कि मुसलमानों से यह कैसे आशा की जा सकती है कि यदि सरकार नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किये बगैर सिन्ध को बम्बई प्रदेश से अलग करने के लिए, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त में राजनीतिक सुधारों की व्यवस्था को चालू करने को तैयार हो जाय, तो मुसलमान उन्हें नामजूर कर दें।

सर तेज बहादुर सप्रू ने अवशिष्ट अधिकारों को केन्द्र में बनाये रखने पर आग्रह करते हुए जिना साहब की अन्य बातों पर गंभीरता से विचार करने का काफरेन्स से अनुरोध किया। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट की संस्तुतियों के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि जिना साहब जिद करें तो केन्द्रीय असेम्बली में मुसलमानों को तैसी प्रतिशत स्थान दे दिये जायें। अखिल भारतीय ईसाई काफरेन्स के प्रतिनिधि रलिया राम तथा रेवेरेन्ड आर० बनर्जी ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध करते हुए कहा कि 'यह राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करने में ही विफल नहीं हुआ है, राष्ट्र की जीवन-शक्ति को भी नष्ट कर रहा है'। श्री एम० आर० जयकर ने भी जिना साहब के सशोधनों और सुझावों का विरोध किया। काफरेन्स ने उन सबको रद्द कर दिया। मालवीयजी ने जिना साहब के सशोधनों पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की।

जब काफरेन्स ने सेंट्रल सिक्ख लीग के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सिक्खों को पंजाब की विधान सभा में तीस प्रतिशत स्थान दिये जायें, तब उसके सब प्रतिनिधि काफरेन्स छोड़कर चले गये। इस पर ईसाइयों के प्रतिनिधि रलिया राम ने प्रस्ताव किया कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त और बलूचिस्तान में सिक्ख अल्पसंख्यकों को प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में वही अधिकार प्राप्त हो जो किसी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को दिये जाने की व्यवस्था की जाय। मालवीयजी ने सिक्खों की माग को न्यायसंगत बताते हुए डाक्टर आलम के इस सुझाव का समर्थन किया कि पंजाब के हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख स्वयं एक काफरेन्स में इस बात पर निर्णय करें। उन्होंने सरदार भगल सिंह की इस बात का समर्थन किया कि प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर साम्प्रदायिकता के बजाय राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाय। उन्हें इस बात की खुशी थी कि पंजाब के हिन्दुओं ने अपने लिए स्थानों को सुरक्षित करने का प्रश्न काफरेन्स के सामने उपस्थित नहीं किया।

काफरेन्स की इस बैठक में सरदार मेहताव सिंह ने यह प्रस्ताव किया कि साम्प्रदायिकता विलुप्त गतम कर दी जाय, और प्रस्तावित योजना को आवश्यक संशोधन के लिए नेहरू कमेटी के पास लौटा दिया जाय। पर सी० विजय-राघवाचार्य की सलाह से अध्यक्ष ने, इस अवस्था में जबकि मुसलमानों के लिए स्थानों की सुरक्षित रखने की बात स्वीकार हो चुकी है, इस प्रस्ताव को नियम-विरुद्ध बता कर उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी। फिर भी डाक्टर एनी बेसेन्ट ने श्री रलिया राम के सिवाय सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि साम्प्रदायिकता को विलुक्त गिटा दिया जाय। उन्होंने बहुत दुःख के साथ कहा कि निर्धनता और अकाज से संघर्ष करने के बजाय साम्प्रदायिकता से संघर्ष करने में और एक संविधान बनाने में इतना समय बर्बाद करना पड़ रहा है।

इस तरह सर्वदलीय काफरेन्स संविधान की रूप-रेखा तैयार करने में सफल रही, पर साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने में विफल रही। करीब करीब सभी हिन्दू नेता उसे स्वीकार करने को तैयार थे। कांग्रेस से सम्बन्धित नेशनलिस्ट मुसलमान भी उसका पूरी तौर पर समर्थन करते थे। पर हिजहाइनेस सर आगा खा, गर मुहम्मद शफी, गोलाना मुहम्मद अली आदि बहुत से मुस्लिम नेता उसे स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने दिल्ली में आयोजित मुस्लिम काफरेन्स में चौदह सूत्री कार्यक्रम निश्चित किया। जिना साहब शुब्ध थे। पर उन्होंने भी अन्त में इन चौदह सूत्रों को स्वीकार कर लिया और ये सब जिना साहब के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। फिर भी जब मार्च सन् १९२९ में पंडित मोतीलाल नेहरू ने केन्द्रीय असेम्बली में प्रस्ताव किया कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के लिए जो वित्तीय व्यवस्था बजट में की गयी है, वह निकाल दी जाय, तब मालवीयजी और जयकर साहब के साथ-साथ जिना साहब ने भी इसका समर्थन किया। सबने डोमोनियन स्टेट्स की प्राप्ति राष्ट्र का लक्ष्य बताते हुए उस ढंग का उत्तरदायी शासन शीघ्र ही स्थापित किये जाने की माग की। जो मुसलमान सदस्य मोतीलालजी और जिना साहब से पूरी तौर पर सहमत नहीं थे, उनमें से अधिकांश तटस्थ रहे, और प्रस्ताव ५२ रायों के विरुद्ध ६३ रायों से स्वीकार हो गया।

२०. नमक सत्याग्रह और गोलमेज कांफरेन्स

वाइसराय को पत्र

जून सन् १९२९ में भारत-मन्त्री के निमन्त्रण पर वाइसराय लार्ड अविन ने प्रधान-मन्त्री, भारत-मन्त्री आदि से भारत की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए लन्दन जाने का निश्चय किया।

उस समय मालवीयजी ने उन्हे देश की राजनीतिक स्थिति पर एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वाइसराय को बताया कि जनता पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए उतावली है, और यद्यपि अधिकांश विवेकशील अब भी औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में हैं, जनमत का झुकाव पूर्ण स्वराज्य की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि किसी सभा में कुछ थोड़े से सम्मानित व्यक्ति ही किसी विरोधी प्रदर्शन की रूकावट के बगैर औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात् डोमिनियन स्टेट्स की चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी लिखा “जनता में यह भावना जोरो से फैल रही है कि ब्रिटेन उसकी स्थापना के लिए राजी न होगा, और संघर्ष करके ही स्वतन्त्रता जीतनी होगी।” उन्होंने लिखा . “भावनाओं की उत्तेजना तथा औपनिवेशिक स्वराज्य के समर्थकों की स्थिति की कमजोरी का कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणा का अभाव है कि संविधान के आगामी संशोधन द्वारा ‘डोमिनियन स्टेट्स’ की स्थापना सम्भव है।” उन्होंने आशा व्यक्त की कि मजदूर सरकार समस्या पर अच्छी तौर से विचार करके कोई ऐसा काम करेगी जिससे जनता को विश्वास हो कि औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग पर सजीदगी से विचार किया जा रहा है। अन्त में उन्होंने आशा की कि लन्दन से वाइसराय महोदय कोई ऐसा समझौता नहीं लायेंगे, जो औपनिवेशिक सरकार की स्थापना से कम हो, और ब्रिटिश इंडिया तथा भारतीय रियासतों के मान्य प्रतिनिधियों की काफरेन्स आमन्त्रित की जायेगी।^१

वाइसराय ने मालवीयजी को तो उनके पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, पर सर तेज बहादुर सप्रू और श्री विट्ठल भाई पटेल को जरूर लिखा कि समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया जायगा, और आशा व्यक्त की कि वे दोनों

१. प्रोसीडिंग्ज राउण्ड टेबिल काफरेन्स, सेक्विण्ड सेशन, पृ० १२२०-

भी इस कार्य में उनकी सहायता करेंगे। उन्होंने पटेल साहब को लिखा कि वे कांग्रेस के नेताओं को आधे मार्ग पर मिलाने का प्रयत्न करेंगे।

वाइसराय की घोषणा

लन्दन में ब्रिटिश मंत्रिमण्डल से बात-चीत करने के बाद ३१ अक्टूबर सन् १९२९ को वाइसराय ने ब्रिटिश सरकार के मन्तव्य की घोषणा की। उन्होंने घोषित किया कि आगामी शरदऋतु में लन्दन में एक गोलमेज काफरेन्स निर्मन्त्रित की जायेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासतों और ब्रिटेन की समस्त पार्टियों के प्रतिनिधि मिलकर नये भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने यह स्पष्ट रूप से कहने को अधिकार दिया है कि उसकी राय में सन् १९१७ की घोषणा में यह अन्तर्निहित है कि भारत की संवैधानिक उन्नति का स्वाभाविक परिणाम, जैसा वहा सोचा गया है, डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति है।

वाइसराय के वक्तव्य की संभावना पर कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुनायी। दूसरे बहुत से नेता भी जमा हो गये। १ नवम्बर सन् १९२९ को दिल्ली में नेताओं की काफरेन्स हुई।

काफरेन्स में उपस्थित नेताओं ने वाइसराय की घोषणा का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि गोलमेज काफरेन्स डोमिनियन स्टेटस की स्थापना की तिथि निश्चित करने के बजाय भारत के लिए डोमिनियन संविधान तैयार करने के लिए बैठेगी। उपस्थित नेताओं ने अपने वक्तव्य में यह भी लिखा कि शान्ति-पूर्ण वातावरण को स्थापित करने के लिए मेल मिलाप की नीति अपनायी जाय, शासन में नयी उदार भावना संचारित की जाय, शासन परिषदों और विधान सभाओं के सम्बन्धों को प्रस्तावित लक्ष्य के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाय, संवैधानिक तरीकों और व्यवहारों को अधिक मान्यता प्रदान की जाय ताकि जनता अनुभव कर सके कि नया युग प्रारम्भ हो गया है।

ब्रिटेन के राजनैतिक क्षेत्रों में वाइसराय की घोषणा का कोई विशेष स्वागत नहीं हुआ। लार्ड रीडिंग, लार्ड वर्कनहेड आदि के आक्षेपों का उत्तर देते हुए भारत-मन्त्री वेजवुड बेन ने कहा कि वाइसराय की घोषणा तो सन् १९१७ की घोषणा की व्याख्या है। उस पर लायड जार्ज ने भारत-मन्त्री का उपहास उड़ाया।

पार्लियामेंट की बहस ने घोषणा का प्रभाव कम कर दिया। फिर भी भारतीय नेताओं ने वाइसराय की घोषणा के आधार पर सहयोग की प्रक्रिया को चालू रखने का प्रयास जारी रखा। सप्रू साहब ने इस सम्बन्ध में वाइसराय और पंडित मोतीलाल नेहरू से बातचीत की, और उनके अनुरोध पर मोतीलाल जी के निमन्त्रण पर १६ नवम्बर को प्रयाग में दूसरी काफरेन्स सम्पन्न हुई। इसने वाइसराय की घोषणा पर पार्लियामेंट की बहस को निराशाजनक बताते हुए दिल्ली काफरेन्स की घोषणा का समर्थन किया, और आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही स्पष्ट उत्तर दिया जायगा।

इसके बाद पटेल साहब और सर तेज बहादुर सप्रू ने वाइसराय से फिर बातचीत की। २३ दिसम्बर सन् १९२९ को महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, प्रेजीडेंट पटेल, सर तेजबहादुर सप्रू और मिस्टर जिना वाइसराय से मिले। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि जब तक सरकार इस बात का आश्वासन नहीं देती कि डोमोनियन सविधान की तैयारी ही काफरेन्स का उद्देश्य होगा और ब्रिटिश सरकार उसका समर्थन करेगी, तब तक कांग्रेस के लिए उसमें शामिल होना संभव नहीं होगा। वाइसराय ने इसके उत्तर में कहा कि प्रत्येक प्रतिनिधि को अपना सुझाव काफरेन्स में प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी, और काफरेन्स में मतभेद की प्रत्येक मात्रा ब्रिटेन के विचारों पर अपना प्रभाव डालेगी ही। उन्होंने यह भी कहा कि काफरेन्स सहमति की अधिक से अधिक मात्रा जानने के लिए बुलायी गयी है, और उनके या सम्राट की सरकार के लिए काफरेन्स के काम के सम्बन्ध में कोई पूर्व-धारणा निश्चित करना या पार्लियामेंट की स्वतंत्रता सीमित करना संभव नहीं है। इस अवसर पर सप्रू साहब और जिना साहब ने गांधीजी और मोतीलालजी को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। मोतीलालजी ने साफ शब्दों में कह दिया कि कोई हिन्दुस्तानी डोमोनियन स्टेट्स से कम लेने को तैयार नहीं होगा, और वाइसराय का गोलमोल आश्वासन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

महात्मा गांधी और पंडित मोती लाल नेहरू वाइसराय के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे, पर श्री तेज बहादुर सप्रू और जिना साहब उसे पर्याप्त समझ कर काफरेन्स में भाग लेने को राजी हो गये। लिबरल फेडरेशन ने वाइसराय की ३१ अक्टूबर की घोषणा का स्वागत किया, चूँकि उसने आधिकारिक रूप से इस राय की पुष्टि की कि भारत के लिए डोमोनियन स्टेट्स ही सन् १९१७ की

घोषणा में निर्दिष्ट था, चूँकि वह निश्चित रूप से स्वीकार करती है कि ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतें मिल कर संयुक्त भारत बनायें, और चूँकि वह भारत के भावी संविधान के बनाने में ब्रिटिश मन्त्रिमंडल के साथ समता के स्तर पर परामर्श करने के अधिकार के भारतीय दावे को स्वीकार करती है। मालवीयजी इस काफ़रेन्स में भाग लेने को राजी नहीं हुए, पर सरकार के निर्मंत्रण पर हिन्दू सभा के नेता डाक्टर मुंजे, राजा नरेन्द्र नाथ उसमें भाग लेने को राजी हो गये। श्री एम० आर० जयकर भी तैयार हो गये।

कांग्रेस का निर्णय

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस ने निश्चय किया कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ है, विधान सभाओं का बहिष्कार किया जाय, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भावी चुनावों में कोई भाग नहीं लिया जाय। यह भी निर्णय किया गया कि विधान की धारा १ में वर्णित 'स्वराज्य' शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होगा। उसने राष्ट्र से रचनात्मक कार्यक्रम उत्साह से चलाने का अनुरोध किया, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिकार दिया कि वह जब चाहे तब सीमित क्षेत्रों में या व्यापक रूप से, जिन प्रतिबन्धों के साथ ठोक समझे, सत्रिनय अवज्ञा और कर-बन्दी शुरू करे।

पूर्ण स्वराज्य दिवस

२६ जनवरी को कांग्रेस के आदेश पर सारे देश में 'पूर्ण स्वराज्य दिवस' मनाया गया। जनता ने ब्रिटिश शासन के दुराचारों को काफी विस्तार के साथ बताते हुए प्रतिज्ञा की कि अहिंसात्मक ढंग से स्वराज्य प्राप्त करने के लिए वे "ब्रिटिश सरकार से सब स्वैच्छिक सहयोग को खत्म करने की, तथा सविनय अवज्ञा की और कर-बन्दी की तैयारी करेंगे"। उन्होंने "सत्य संकल्प" किया कि वे कांग्रेस के उन आदेशों का पालन करेंगे, जिन्हें वह समय-समय पर पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के लिए जारी करे।

ग्यारह सूत्र

३० जनवरी सन् १९३० को गांधीजी ने अपने अंग्रेजी साप्ताहिक 'यंग-इंडिया' में नमक-कर का अन्त, लगान में पचास प्रतिशत की कमी, विदेशी कपड़े पर संरक्षक आयात, सोलह पैसे रुपये की दर, फौजी खर्चों में तथा सरकारी अफसरों के वेतन में कमी, पूरी तौर पर नशाबन्दी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई,

नागरिक अधिकारों की रक्षा, खुफिया पुलिस की वख्तिगी, हथियार रखने की छूट, तथा तटवर्ती नौका परिवहन का भारतीय पोतों के लिए सरक्षण— ये ग्यारह मागें पेश करते हुए लिखा कि यदि सरकार इन्हें स्वीकार करने को तैयार हो तो सविनय अवज्ञा शुरू नहीं की जायगी।

यद्यपि बहुत से कांग्रेसी नेता गांधीजी के इस वयान को पसन्द नहीं करते थे, फिर भी फरवरी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गांधीजी को संघर्ष का नेता स्वीकार करते हुए उन्हें उसकी गतिविधि निश्चित करने का अधिकार दिया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने आशा व्यक्त की कि आन्दोलन के प्रारम्भ हो जाने पर कांग्रेसजन सविनय प्रतिरोध की हर सभव सहायता करेंगे, तथा हर स्थिति में अहिंसा का पालन करेंगे। वर्किंग कमेटी ने यह भी आशा व्यक्त की कि जब यह अभियान जनान्दोलन का रूप धारण कर लेगा, तब वकील और विद्यार्थी सरकार से अपना सहयोग विच्छेद कर उसमें सक्रिय भाग लेंगे।

वाइसराय को पत्र

२ मार्च को गांधीजी ने वाइसराय को एक लम्बा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने काफी विस्तार से यह बताया कि ब्रिटिश सरकार की नीति-रीति के कारण हिन्दुस्तान की गरीब जनता का किस तरह शोषण हो रहा है, और उसकी दशा किस तरह दयनीय होती जा रही है, सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करने का अपना निर्णय व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूर्णरूप से अहिंसात्मक होगा और वह नमक कानून को तोड़ने से प्रारम्भ किया जायगा, क्योंकि उनकी राय में गरीब आदमी की दृष्टिकोण से यह कर सबसे अधिक अन्यायपूर्ण है। उन्होंने यह भी लिखा कि जिन 'बुराद्यों' को पत्र में चर्चा की गयी है, उन्हें दूर करने को यदि वाइसराय तैयार हो, तो आन्दोलन स्थगित किया जा सकता है। अन्यथा १२ मार्च से प्रतिरोध का कार्य प्रारम्भ हो जायगा।^१

डांडी यात्रा

पत्र का सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर १२ मार्च को गांधीजी ने साबरमती आश्रम के ७९ साथियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी

१ पट्टाभि सीतारमैया : हिस्ट्री आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस, खण्ड १, पृ० ३७२-३७६।

की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जनता ने इनका भव्य स्वागत किया। वे स्वयं इकट्ठी भीड़ को खहर, नशाबन्दी तथा अस्पृश्यता-निवारण का उपदेश देते हुए अहिंसात्मक संघर्ष में भाग लेने की सलाह देते जाते थे। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन से भारत का नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अपतन हुआ है और इसलिए वह “इस शासन को अभिशाप” समझते हैं और इस “शासन-व्यवस्था को नष्ट” करना चाहते हैं। वे यह भी कहते जाते थे कि “हमारा युद्ध अहिंसात्मक है। हम किसी को मार डालना नहीं चाहते, पर इस सरकार के अभिशाप को मिटा देना हम अपना कर्तव्य” समझते हैं^१। गांधीजी ने ६ अप्रैल को डाडी में नमक कानून को तोड़कर सत्याग्रह शुरू कर दिया। यद्यपि सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्री जे० एम० सेनगुप्त बहुत पहले गिरफ्तार कर लिये गये थे, पर सरकार ने गांधीजी को फौरन गिरफ्तार नहीं किया। वे लगभग चार सप्ताह अपने ढंग से अपना काम करते रहे। पर जब गांधीजी ने घरसन्ना में सत्याग्रह करने का निर्णय किया, तब मई के पहले सप्ताह में वह गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिये गये।

पेशावर कांड

२३ अप्रैल सन् १९३० को पेशावर में भारी जुलूस निकाला गया। दूसरे दिन खान अब्दुल गफ्फार खा गिरफ्तार कर लिये गये। इस पर जनता ने पेशावर में फिर जुलूस निकाला। उस जुलूस पर फौज ने गोली चलायी। लगभग २२५ आदमी आहत हुए। यह समाचार पा कर कि इस गोलीकांड में बहुत से आदमी मारे गये, मालवीयजी मई सन् १९३० में पेशावर चल दिये। रास्ते में कई स्थानों पर पंजाब की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। रास्ते में ही उन्हें आज्ञा मिली कि वे पेशावर में प्रवेश नहीं कर सकते, पर वे आगे बढ़ते चले गये। इस पर सरकार ने उन्हें पेशावर से कुछ दूर एक स्टेशन पर रोक कर दूसरी गाडी से वापस कर दिया। इस अवसर पर मोती लालजी ने कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष की हैसियत से श्री विठ्ठल भाई पटेल की अध्यक्षता में एक जाच कमेटी नियुक्त की। सरकार ने पटेल साहब को भी पेशावर नहीं जाने दिया। पेशावर की स्थिति बहुत समय तक सरकार को परेशान करती रही। वे खुदाई खितमदगारों का साहस कुचल न सके।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी

मई सन् १९३० में प्रयाग में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उसने गांधीजी के नेतृत्व तथा सविनय अवज्ञा के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा प्रकट करते हुए सब वर्ग के लोगों से अनुरोध किया कि वे स्वतंत्रता-संघर्ष में भाग लें, और अपनी शक्ति भर कुर्बानियाँ करें। उसने नमक सत्याग्रह को जारी रखते हुए उन प्रान्तों में जहाँ रैयतवारी भूमि-व्यवस्था चालू है, लगान बन्दी की, तथा अन्य प्रान्तों में चौकीदारी टैक्स न देने की सविनय अवज्ञा शुरू करने की अनुमति दी। उसने मध्य प्रदेश तथा बम्बई में वन सम्बन्धी कानूनों को तोड़ने के प्रयत्नों का अनुमोदन करते हुए निश्चय किया कि दूसरे प्रान्तों में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की स्वीकृति से इस प्रकार के दूसरे कानूनों को तोड़ा जा सकता है। उसने विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए विदेशी कपड़ों की दुकानों की पिकेटींग करने का कांग्रेस कमेटियों को आदेश दिया। वर्किंग कमेटी ने जनता से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को कारगर बनाने का, तथा ब्रिटिश वर्किंग, इश्योरेंस, शिपिंग आदि सस्याओं का बहिष्कार करने का प्रयत्न करे। कमेटी ने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को आदेश दिया कि नशाबन्दी का प्रचार किया जाय, तथा शराब की दुकानों का पिकेटींग किया जाय। कमेटी ने हाथ से कते और हाथ से बुने कपड़े के उत्पादन की वृद्धि की आवश्यकता की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया।

संघर्ष और दमन

गांधीजी की गिरफ्तारी और कांग्रेस कमेटी के नये प्रस्ताव के बाद आन्दोलन ने और जोर पकड़ा। सत्याग्रहियों ने धरसत्ता, वादला आदि नमक डिपो पर बार बार आक्रमण किया, स्त्रियों ने जोरशोर से विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों की पिकेटींग की। जगह जगह पर गैरकानूनी ढंग पर नमक बनाया गया। विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सभाएँ और जुलूस आयोजित किये गये, जिनमें हजारों नरनारियों और बच्चों ने बहुत ही साहस और उत्साह से भाग लिया। बम्बई में निश्चय हुआ कि प्रतिमास की चार तारीख को गांधी दिवस, और अन्तिम रविवार को झंडा दिवस मनाया जाय। मध्य प्रदेश और बम्बई प्रान्त में जंगलों का कानून जोरशोर से तोड़ा गया।

सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिए, कई नये दमनकारी अध्यादेश, तथा सार्वजनिक सभाओं को बन्द करने के लिए आदेश जारी किए। सभाओं और जुलूसों को भंग करने के लिए बड़ी निर्दयता के साथ निहत्थी जनता

पर लाठियों का प्रहार किया गया। सरकार के अपने वयान के अनुसार मई में विभिन्न स्थानों पर चौदह बार गोली चलायी गयी, जिसमें ५० से अधिक लोग मारे गये, और ३०० से अधिक घायल हुए। आन्दोलन को दवाने के लिए सरकार के कर्मचारियों और पिट्टुओं ने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करनेवाले स्वयं-सेवकों के साथ दुर्व्यवहार किया। आन्दोलन और दमन का यह चक्र जून में भी चलता रहा। सरकार के एक वक्तव्य से पता चलता है कि १५ जुलाई तक प्रेस आध्यादेश के अन्दर १३१ समाचार-पत्रों से दो लाख चालीस हजार रुपये की नयी जमानतें मांगी गयीं।

समझौते का प्रयास

२० मई को गांधीजी की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद जार्ज स्लोकांम्बे उनसे जेल में मिले। उसके बाद स्लोकांम्बे साहब ने समझौते के सम्बन्ध में कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष पंडित मोती लाल नेहरू से बातें की। इसके बाद सप्रू साहब और जयकर साहब द्वारा वातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वातचीत कई महीने चलती रही, पर कोई समझौता नहीं हो पाया। लार्ड अविन ने समझौते के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री को कई पत्र लिखे। पर कंजर-वेटिव पार्टी के नेताओं के विरोध के कारण ब्रिटेन की मजदूर सरकार ने बाइसराय की बात न मानना ही ठीक समझा।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी

२७ जून को पंडित मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रयाग में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कमेटी ने विदेशी कपड़ों तथा ब्रिटिश माल के बाइकाट को अधिक तीव्र बनाने के लिए कांग्रेस कमेटियों को आदेश दिया। कमेटी ने यह भी आदेश दिया कि उन सरकारी कर्मचारियों और पिट्टुओं का सामाजिक बहिष्कार किया जाय जिन्होंने स्वयं-सेवकों के साथ अनुचित अपमान-जनक व्यवहार किया है। कमेटी ने यह भी आदेश दिया कि फौज और पुलिस के कर्तव्यों के सम्बन्ध में उसके ७ जून के प्रस्ताव को, जिसकी कापियाँ सरकार ने जर्बत कर ली हैं, अधिक से अधिक प्रसारित किया जाय। कमेटी ने सरकार की मुद्रा नीति की कड़ी आलोचना करते हुए जनता को सलाह दी कि वह अपने निर्यात का मूल्य स्वर्ण में वसूल करे, सरकार के प्रति अपने आर्थिक दावों को स्वर्ण में लेने को आग्रह करे, तथा अपनी मुद्रा सम्पत्ति को स्वर्ण में बदलने का प्रयत्न करे।

इसके बाद सरकार ने कांग्रेस, वर्किंग कमेटी को गैरकानूनी घोषित कर दिया। पंडित मोती लाल नेहरू गिरफ्तार कर लिये गये, और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो तीन मास की सजा काट कर रिहा हो गये थे, अपनी जगह पर स्थानापन्न अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। मालवीयजी वर्किंग कमेटी के सदस्य बना लिये गये।

जुलाई के अन्तिम सप्ताह में बम्बई में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मालवीयजी भी इस बैठक में उपस्थित थे। चूँकि बम्बई में कमेटी अभी तक अवैध घोषित नहीं हुई थी, इसलिए सरकार के हस्तक्षेप के बिना तीन दिन तक उसकी बैठकें होती रही।

तिलक जयन्ती

३१ जुलाई को रात को तिलक जयन्ती मनाने के लिए श्रीमती हंसा मेहता के नेतृत्व में एक वृहद् सार्वजनिक जुलूस निकाला गया, जिसमें वल्लभ-भाई पटेल, मालवीयजी, जयरामदास दौलतराम, मनिबेन पटेल, श्रीमती कमला नेहरू, श्रीमती अमृत कौर, डाक्टर हाडिकर आदि शामिल थे। बम्बई सरकार ने दफा १४४ लगाकर जुलूस पर रोक लगा दी। जुलूस तितर-बितर होने के बजाय सड़क पर बैठ गया, और सारी रात वर्षा में वहाँ ही डटा रहा। प्रातः काल बम्बई के गृह-सचिव हाटसन की आज्ञा से प्रतिष्ठित नेताओं और महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, और बाकी जुलूस को लाठियों की मार से तितर-बितर कर दिया गया। मालवीयजी आदि सभी नेताओं को २०० रुपया जुर्माना या १५ दिन की सजा दे दी गयी। इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री जयरामदास दौलतराम यरवदा जेल भेज दिये गये, जहाँ उन्होंने १४ और १५ अगस्त को अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ सप्रू साहब और जयकर साहब से बातचीत की। मालवीयजी की गिरफ्तारी और सजा की सूचना पा कर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के लगभग सौ विद्यार्थी सत्याग्रह करने को बम्बई चल दिये, पर उनके वहाँ पहुँचते-पहुँचते मालवीयजी छोड़ दिये गये। सुना जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति ने उनका जुर्माना अदा कर दिया था, जिसका मालवीयजी को बहुत क्षोभ था।

जेल से छूटने के बाद मालवीयजी सत्याग्रह के सम्बन्ध में दौरा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम भी तैयार कर लिया था। पर जब उन्हें पता चला कि सरकार ने दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी पर रोक

लगा दी है, और वह वहाँ उसकी बैठक नहीं होने देना चाहती, तब मालवीयजी दौरे का कार्यक्रम स्थगित कर दिल्ली चल दिये ।

गिरफ्तारी

२० अगस्त सन् १९३० को दिल्ली में डाक्टर अन्सारी की अध्यक्षता में उनके मकान पर ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई । कमेटी का काम समाप्त होते-होते डाक्टर अन्सारी, मालवीयजी आदि कमेटी के सभी उपस्थित सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये । सबको छ-छ. मास की सजा दे दी गयी ।

मालवीयजी प्रयाग की नैनी जेल में भेज दिये गये । यहाँ उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू के वहनोई रणजीत एस० पण्डित से जर्मन भाषा सीखना शुरू की, तथा स्वयं कैदियों को कथा सुनायी । उन्होंने यहाँ पंडित जवाहर लाल नेहरू से भारतीय राजनीति पर भी काफी बातचीत की, जिससे पारस्परिक सौहार्द में काफी वृद्धि हुई । जब मालवीयजी जेल में बीमार पड़ गये, तब वे अस्पताल भेज दिये गये, और २४ दिसम्बर को प्रधान-मन्त्री रमसे मेकडोनल्ड के आदेश पर रिहा कर दिये गये ।

सरकार का रोप

सरकार मालवीयजी की गतिविधि से बहुत क्षुब्ध थी । वह अपना सारा रोप बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी पर उतारना चाहती थी । उसने विश्वविद्यालय पर यह आरोप लगाकर कि वहाँ उग्र राजनीति का प्रचार होता है और वहाँ का वातावरण राजनीतिक है, उसे वार्षिक अनुदान देना बन्द कर दिया । वह चाहती थी कि विश्वविद्यालय आश्वासन दे कि भविष्य में उसके व्यवहार में मौलिक परिवर्तन होगा, विश्वविद्यालय में उग्र विचार के साम्राज्य-विरोधी राजनीतिज्ञों को अपने विचार व्यक्त करने की इजाजत नहीं दी जायेगी, जिन अध्यापकों ने सविनय अवज्ञा में भाग लिया है उन्हें बर्खास्त कर दिया जायगा, और जिन विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया है उन्हें निकाल दिया जायगा । मालवीयजी सरकार के आरोप और उसके सुझावों को मानने को तैयार नहीं थे । इन सब प्रश्नों पर उस समय ही जबकि वे जेल में थे, उनकी सलाह से विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय और प्रान्तीय अधिकारियों के साथ पत्र-व्यवहार किया, जिसका विस्तृत विवरण 'बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी' के अध्याय में दिया गया है । जेल से छूटने के बाद उन्हें सरकार के कड़े दृष्टिकोण के कारण जिन कठिनाइयों का विश्वविद्यालय को सामना करना पड़ रहा था, उनके निराकरण पर बहुत समय

लगाना पड़ा। उन्होंने सरकार के अधिकारियों और जनता दोनों को स्पष्ट कर दिया कि वे सरकार की शर्तें मानने को और उन शर्तों के साथ सरकारी अनुदान या आर्थिक सहायता लेने को तैयार नहीं हैं। यह संघर्ष फरवरी सन् १९३१ तक चलता रहा, और अविन-गांधी समझौते के बाद ही शान्त हुआ।

संघर्ष

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के दमन और आतंक की उपेक्षा करते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णयों और गांधीजी के आदेश के अनुसार जोश और साहस के साथ संघर्ष जारी रखा, और वर्किंग कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की करीब-करीब सभी बातों को कार्यान्वित करने की कोशिश की। मुद्रा सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रचार वे नहीं कर सके, शायद उसे अव्यावहारिक समझ कर उस पर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, पुलिस और सैनिकों से सबधित प्रस्ताव का भी वे कितना प्रचार कर पाये, इसका भी पता नहीं चलता, पर सारे देश में कार्यकर्ताओं और स्वयं-सेवकों ने डटकर विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का पिकेटिंग किया, तथा ब्रिटिश माल के बहिष्कार पर विशेष रूप से जोर दिया। बंगाल तथा बिहार और उड़ीसा में तो ब्रिटिश माल के बहिष्कार में इतनी सफलता प्राप्त हुई कि सन् १९३० में उसका आयात केवल पाँच प्रतिशत रह गया। करनाटक के कनारा जिले में ताड़ी-विरोधी अभियान में तीन लाख ताड़ और खजूर के वृक्ष काट डाले गये। शराब और ताड़ी की विक्री बहुत कम हो गयी। सरकार की आवकारी से आमदनी सभी प्रान्तों में कम हो गयी। वह मध्य प्रदेश में ६० प्रतिशत और केरल में ७० प्रतिशत कम हो गयी। प्रत्येक प्रान्त में विभिन्न स्थानों और अवसरों पर विशेष रूप से विदेशी कपड़ों की होली, तथा ताड़ी के प्रयोग के विरुद्ध प्रचार होता रहा। कानून के विरुद्ध नमक का बनना भी जारी रहा, पर धीरे-धीरे इसका महत्त्व कम हो गया। दफा १४४ की अवहेलना करते हुए सभाओं और जुलूसों का ताँता भी अन्त तक जारी रहा। मध्य प्रदेश में जगलो के कानूनों को भी काफी सफलता के साथ तोड़ा जाता रहा, जिसमें बहुत से वनवासियों ने सक्रिय योगदान किया। शोलापुर में आन्दोलन ने इतना जोर पकड़ा कि अपने अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए सरकार को वहाँ १५ मई को ही मार्शल-ला लागू करना पड़ा। कर्नाटक में केनरा जिले में तथा गुजरात के बारदोली और वोरसद के किसानों ने लगान बन्दी का जोर-शोर से सत्याग्रह किया। बिहार के कतिपय जिलों में चौकीदारी टैक्स को देना बन्द कर दिया गया, और

युक्तप्रान्त में अक्तूबर सन् १९३० में मालगुजारी और लगान, दोनों की अदायगी बन्द कर देने का अभियान प्रारम्भ किया गया। बंगाल के मिदनापुर जिले में भी लगान-बन्दी हुई।

गोलमेज कांफरेन्स

१२ नवम्बर सन् १९३० को लन्दन में सम्राट् के स्वागत-सन्देश से गोलमेज काफरेन्स प्रारम्भ हुई, जो १९ जनवरी सन् १९३१ तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मेकडोनल्ड की अध्यक्षता में चलती रही। लार्ड चान्सलर लार्ड सेनके फ्रेडरल स्ट्रकचर कमेटी के अध्यक्ष चुने गये। छः दिन तक काफरेन्स के पूरे अधिवेशनों में कांफरेन्स के सदस्यों ने भारत की राजनीतिक स्थिति और संवैधानिक समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किये। सर तेज बहादुर सप्रू, 'मिस्टर' मुहम्मद अली जिना, महाराजा वीकानेर, महाराजा पटियाला, महाराजा अलवर, नवाब भोपाल आदि ने 'अखिल भारतीय संघ' के विचार को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया। लन्दन की कंजरवेटिव पार्टी की ओर से लार्ड पील, ने और लिबरल पार्टी की ओर से लार्ड रीडिंग ने भावी संविधान में अपनी-अपनी पार्टी की धारणाओं को बताया। श्री श्रीनिवास शास्त्री, मिया मुहम्मद शफी, डाक्टर अम्बेदकर, महाराजा 'रीवां', कर्नल गिडने आदि ने भी अपने अपने विचार काफरेन्स के समक्ष उपस्थित किये।

लार्ड पील और लार्ड रीडिंग की बातों से यह स्पष्ट था कि ब्रिटेन की कंजरवेटिव और लिबरल पार्टियाँ केन्द्र में उत्तरदायी शासन-व्यवस्था स्थापित करने को तैयार नहीं थी। भारतवासी यूरोपियन और एंग्लो-इंडियन भी कुछ शर्तों के साथ प्रान्तों में ही उत्तरदायी व्यवस्था के विस्तार के पक्ष में थे। खा अब्दुल कयूम खा को केवल सीमा-प्रान्त की चिन्ता थी। मिस्टर फजलुलहक, सर मुहम्मद शफी और सर पी० सी० मित्र ने राष्ट्रीय माग की चर्चा करते हुए अल्प-संख्यकों के हितों पर ही अधिक जोर दिया। पर ब्रिटिश भारत के अन्य करीब करीब सभी प्रतिनिधियों ने प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के साथ साथ केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना तथा ब्रिटिश कामनवेल्थ में बराबर के डोमीनियन पद को राष्ट्र की माग घोषित किया, इसी पर सब से अधिक जोर दिया। मौलाना मुहम्मद अली ने तो कहा कि वे पूर्ण स्वराज्य के समर्थक हैं। ब्रिटिश भारत के अधिकांश प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि यदि राष्ट्रीय माग स्वीकार नहीं होगी, तो संघर्ष तीव्र हो जायगा, पुरानी व्यवस्था के आधार पर शान्ति और व्यवस्था प्रतिष्ठित नहीं रखी जा सकेगी। भारतीय नरेशों की बातों से यह

स्पष्ट था कि जबकि महाराजा रीवा को भारतीय संघ की सार्थकता और औचित्य पर सन्देह था, कुछ राजे और नवाब इसका स्वागत करने को तैयार थे, पर उन शर्तों के साथ जिन पर समझौता होना कठिन मालूम होता था।

सारी कांफरेन्स की ६ बैठकों के बाद विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए उपसमितियाँ गठित की गयीं और उनकी रिपोर्टों पर अन्त में १६ और १९ जनवरी सन् १९३१ को पूरी कांफरेन्स में विचार हुआ। उपसमितियों की रिपोर्टें पूरी तौर पर सन्तोषजनक नहीं थीं। गहरे मतभेद के कारण बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर कोई निर्णय ही नहीं लिया जा सका। जो निर्णय हुए भी, उन्हें भी 'अन्तरिम' समझा गया। फेडरल स्ट्रक्चर समिति ने यह तो निश्चय किया कि ब्रिटिश भारत से सम्बन्धित प्रान्त उन अधिकारों के आधार पर जो भारत सरकार उन्हें हस्तान्तरित करे उन रियासतों को मिलाकर जो स्वेच्छा ने ऐसा चाहें, एक भारतीय संघ स्थापित करें, पर महाराजा रीवा और महाराजा धोलपुर ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उनकी स्वीकृति अस्थायी है, संघ व्यवस्था की पूरी रूप रेखा तैयार हो जाने पर ही वे निश्चय कर सकते हैं कि वे संघ में शामिल हो अथवा न हो। इस समिति ने अस्थायी तौर पर वित्तीय संरक्षणों के सम्बन्ध में भी कुछ फैसले किये। अल्प-संख्यक कमेटी सर्वसम्मति से कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकी, और कांफरेन्स की बैठक में मुसलमानों की ओर से खान बहादुर हाफिज़ हिदायत हुसैन ने घोषित किया कि अल्पसंख्यक और अस्पृश्य वर्ग हिन्दुस्तान के लिए स्वशासन की व्यवस्था करनेवाले किसी संविधान को मानने की राजी नहीं हो सकते, जब तक उनकी माँगें युक्तियुक्त ढंग पर पूरी नहीं की जाती।^१ डाक्टर अम्बेदकर ने भी यह बात स्वीकार करते हुए कि "जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में—राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक—प्रत्येक व्यक्ति को एक मूल्य के आदर्श की उपलब्धि हो" अस्पृश्य वर्गों का लक्ष्य है, घोषित किया कि जिस प्रकार बहुत ही सीमित मताधिकार के आधार पर नया विधान तैयार किया जा रहा है, वह भारत की सरकार को उच्चवर्गों द्वारा जनता पर शासन ज़रूर बना देगा"^२। उन्हें इस बात का शोभ था कि जबकि दूसरे अल्प-संख्यकों के अधिकार ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कारणों से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिये हैं, प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में अस्पृश्य वर्गों के दावों की उपेक्षा की जा

१. इडियन राउंड टेबिल कांफरेन्स १२ नवम्बर सन् १९३०—१९ जनवरी सन् १९३१ विवरण, पृ० ४०४। २. वही, पृ० ४३९।

रही है।^१ उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्रीय शासन के नौकरशाही ढाँचे में परिवर्तन पर ध्यान जरूर दिया गया है, पर परिवर्तन दिखावटी है, महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तरदायित्व वोगस है, वास्तविक नहीं है।^२ श्री० जे० एन० वसु ने काफरेन्स के निर्णयों की समीक्षा करते हुए कहा : “बहुधा जनता के साधारण अधिकारों की उपेक्षा करते हुए निहित स्वार्थों की सेवा की गयी है”।^३ मजदूरों के अभिवक्ता श्री शिवराव ने कहा कि काफरेन्स ने मजदूरों की एक बात भी स्वीकार नहीं की है, और जब तक आगे चलकर प्रस्तावित प्रस्ताव ठीक तौर पर संशोधित नहीं होते, नयी व्यवस्था मजदूरों के लिए हितकर नहीं हो सकती।^४ भारतीय संघ पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सर शफात अहमद खाँ ने कहा कि भारतीय नरेशों का भारत के राजनीतिक अखाड़े में प्रवेश सन्देह से खाली नहीं है, पर ऐसा दिखाई देता है कि संघ को स्थापित किये बिना केन्द्र में उत्तरदायी व्यवस्था की स्थापना असम्भव है। इसलिए, उन्होंने कहा, भारत असमंजस में फँस गया है। “नरेशों के बिना मौजूदा निरंकुश शासन जारी रहेगा, नरेशों के साथ विधान आकार में लोकतान्त्रिक होगा, व्यवहार में अल्पतन्त्रीय” होगा।^५ श्री एच० पी० मोदी ने कहा . “संघीय व्यवस्था विकसित हो अथवा न हो, भारत को केन्द्र में स्वायत्तता की इतनी पूर्ण मात्रा मिलनी चाहिए जितनी परिस्थिति इजाजत दे।”^६ उन्होंने रिपोर्ट में लिखित बहुत से वित्तीय संरक्षणों पर भी आपत्ति करते हुए कहा “पूर्ण वित्तीय और कर-सम्बन्धी स्वायत्तता भारत की अवाधित मांग है।”^७ श्री चन्द्रशेखर बरुआ ने कहा कि भारत के राजनीतिक विकास के समय कुछ संरक्षणों की व्यवस्था अनिवार्य है, पर उनकी व्यवस्था करते समय यह नहीं भूल जाना है कि हमारा उद्देश्य हिन्दुस्तान को इतनी अधिक स्वतन्त्रता देना है जितनी इस साम्राज्य की दूसरी डोमिनियनों उपभोग कर रही है, और उसे इतनी जल्दी देना है जितनी वह व्यावहारिक हो।^८

यद्यपि अर्धगोरो के प्रवक्ता कर्नल गिडने को क्षोभ था कि उनके हिन्दुस्तानी भाइयों ने यूरोपियनों के निहित व्यावसायिक हितों को मानने से इनकार

१. वही, पृ० ४३९।

३. वही, पृ० ४०२।

५. वही, पृ० ४१०।

७. वही, पृ० ४४३।

२. वही, पृ० ४३८।

४. वही, पृ० ४१३।

६. वही, पृ० ४४३।

८. वही, पृ० ४६१।

कर दिया,^१ पर कंजर्वेटिव पार्टी के प्रवक्ता लार्ड पील और लिबरल पार्टी के प्रवक्ता लार्ड रीडिंग गोलमेज काफरेन्स के निर्णयो से काफी सन्तुष्ट थे। भारत-निवासी यूरोपियनो के प्रवक्ता मिस्टर गोविन जोन्स तथा सर हुवर्ट कार भी काफी सन्तुष्ट थे। वे यह और चाहते थे कि (१) रियासतो को प्रतिनिधित्व का बड़ा अंश मिले, ताकि वे उसके जरिये स्थिरता और प्रशासनिक अनुभव ला सकें, (२) विधान मंडलो में ताज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, जिसे साक्रान्तिक काल खत्म होने पर घटा दिया जाय, (३) कार्यपालिका की पदावधि पार्लियामेंट का जीवन-काल हो, या जब तक वे विधान मंडल के दो तिहाई सदस्यों का विश्वास न खो दें, या गवर्नर जनरल उन्हें बर्खास्त न कर दे।^२

काफरेन्स की आखिरी बैठक में श्री जाधव ने तथा श्री चन्द्रशेखर बरुआ^३ आदि ने सरकार से अनुरोध किया कि शान्ति का वातावरण स्थापित करने के लिए राजनीतिक बन्दी छोड़ दिये जायें। सर तेज बहादुर सप्रू ने भी प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया कि वे अपने अभिभाषण में राजनीतिक बन्दियों की रिहाई की घोषणा करें। उन्होंने भारत के राजनीतिज्ञों से भी अनुरोध किया कि वे संघर्ष को बन्द कर देश की राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में रचनात्मक योगदान करें।

प्रधान-मन्त्री की घोषणा

प्रधानमन्त्री मेकडोनल्ड ने अपने अन्तिम भाषण में काफरेन्स की सफलता पर अपना हर्ष प्रकट करते हुए संरक्षणों के औचित्य को समझाते हुए तथा वास्तविक प्रगति के लिए सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए घोषित किया कि "मैं चाहूँगा कि यह काफरेन्स भारत और हमारे बीच के सम्बन्धों में एक नया अध्याय प्रारम्भ करे। यदि सर तेज बहादुर सप्रू की भारत को और हमें की गयी अपील को भारत में सुनवायी हुई, और सिविल शान्ति घोषित और सुनिश्चित कर दी गयी, तो सम्राट् की सरकार उनकी अपील का, जो उनके बहुत से साथियों द्वारा भी पुष्ट की गयी है, उचित उत्तर देने में पीछे नहीं रहेगी।"^४

अन्त में उन्होंने घोषित किया : "सम्राट् की सरकार की राय है कि भारत के शासन के लिए उत्तरदायित्व केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान मण्डलों पर उन प्रतिवन्धों के साथ रखा जाय जो संक्रान्तिकाल में कतिपय दायित्व के

१. वही, पृ० ४०६।

२. वही, पृ० ४४४।

३. वही, पृ० ४५६, ४६३।

४. वही, पृ० ४८०।

अनुपालन की गारन्टी के लिए तथा अन्य विशेष स्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक हो, और जो उन गारन्टीओ से युक्त हो जिन्हें अल्प-संख्यक अपनी स्वतन्त्रताओं और अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक समझें। इस मूलभूत नीति की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि (१) संरक्षित अधिकार इस तरह तैयार किये जायेंगे और प्रयोग में लाये जायेंगे कि वे नये संविधान द्वारा पूर्ण उत्तरदायित्व की ओर प्रगति में बाधक न हों। (२) केन्द्रीय शासन-द्विसदनीय विधानमंडल में गठित अखिल भारतीय संघ होगा, जिसमें भारतीय रियासतें और ब्रिटिश भारत दोनों शामिल होंगे। (३) संघीय आधार पर गठित विधान मंडल को प्रशासन (कार्यपालिका) उत्तरदायी होगा। (४) रक्षा सम्बन्धी मामले और वैदेशिक विषय गवर्नर-जनरल के हाथ में रक्षित रहेंगे। (५) आकस्मिक सफट में राज्य में शान्ति बनाये रखने का तथा अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के अनुपालन कराने का विशेष उत्तरदायित्व गवर्नर-जनरल का होगा, और उसे पूरा करने के लिए उचित अधिकारों की व्यवस्था की जायगी। (६) वित्तीय उत्तरदायित्व उन शर्तों के साथ हस्तान्तरित किया जायगा जो भारतमन्त्री के अधिकार के अधीन लिये वित्तीय आभारों को पूरा करने के लिए, तथा भारत की वित्तीय स्थिरता और साख को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए जरूरी हो, (७) इस तरह मौजूदा परिस्थिति में केन्द्रीय विधानमंडल और कार्यपालिका दोनों का द्विविधता का स्वरूप होगा, (८) गवर्नरों के प्रान्त पूर्ण उत्तरदायित्व के आधार पर गठित किये जायेंगे, (९) प्रान्तीय विषयों का क्षेत्र इस तरह निर्धारित किया जायगा, जिससे प्रान्तों को स्वशासन की अधिकतम सम्भव मात्रा प्राप्त हो सके, और संघीय सरकार का अधिकार उन प्रबन्धों तक सीमित होगा जो संघीय विषयों के प्रशासन के लिए और संविधान द्वारा निश्चित अखिल भारतीय विषयों के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जरूरी हो, (१०) गवर्नरों के लिए निम्नतम विशेष अधिकार इस तरह सुरक्षित किये जायेंगे कि वे विशेष परिस्थितियों में शान्ति सुरक्षित रख सकें, तथा पब्लिक सर्विसेज (लोकसेवाओं) और अल्पसंख्यकों के कानून द्वारा निश्चित अधिकारों को बनाये रख सकें। (११) प्रान्तीय विधानमंडलों का विस्तार किया जायगा, और वे अधिक उदार मताधिकार पर आधारित होंगे; (१२) संवैधानिक प्रबन्धों द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त, इस बात की भी गारन्टी दी जायगी कि धर्म, प्रजाति, सम्प्रदाय या जाति के भेद स्वयं नागरिक (सिविक) नियोग्यताएं नहीं हों।^१

समझौता

२५ जनवरी सन् १९३१ को गांधीजी तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अन्य सब सदस्य छोड़ दिये गये। १५ फरवरी को कांग्रेस की ओर से गांधीजी ने वाइसराय से बातचीत शुरू की। कुछ दिन तक बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण ढंग से होती रही। पर बाद को इतना गतिरोध पैदा हो गया कि समझौता असम्भव दिखाई देने लगा। सर तेज बहादुर सप्रू और श्री श्रीनिवास शास्त्री ने गतिरोध दूर करने की भरसक कोशिश की। अन्त में ५ मार्च को प्रातः काल एक बजे गांधीजी और वाइसराय में समझौता हो गया।

५ मार्च को भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा समझौते की शर्तें प्रकाशित की। इस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया गया कि गोलमेज काफरेन्स में उसकी विचाराधीन योजना पर विस्तार के साथ विचार किया जायगा। सद्य व्यवस्था, भारतीय उत्तरदायित्व, तथा भारत के हितों में देश की रक्षा, वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यकों की प्रोtection, भारत की आर्थिक साख और दायित्व की अदायगी आदि विषयों के सम्बन्ध में संरक्षण या प्रतिबन्ध इस विचाराधीन योजना के मुख्य अंग हैं। विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि प्रधानमन्त्री की १९ जनवरी की घोषणा के अनुसार संवैधानिक सुधार की योजना पर होने वाले विचार-विमर्श में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए उचित कार्यवाही की जायगी।

पंडित जवाहर लाल नेहरू को यह समझौता पसन्द नहीं था। वे इसे आत्म-समर्पण समझते थे। पर अन्त में वे इसे स्वीकार करने को राजी हो गये, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसे सर्वसम्मति से मजूर कर लिया, और सविनय अवज्ञा को वापस लेकर पिकेटिंग आदि के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये। सरकार की ओर से भी समझौते को कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियाँ की जाने लगी।

कराची अधिवेशन

समझौते के कुछ दिन बाद मार्च में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसने गांधी-अविन समझौते का समर्थन किया, पर यह स्पष्ट कर दिया कि उसका 'पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अक्षुण्ण बना रहता है,' और यदि उसके प्रतिनिधि को गोलमेज काफरेन्स में हिस्सा लेने का अवसर मिला, तो वह वहाँ इस लक्ष्य के लिए प्रयत्न करेगा, और विशेष रूप से देश की 'संरक्षण सेनाओं पर, वैदेशिक मामलों पर, वित्त पर, कर

सम्बन्धी और आर्थिक नीतिओं पर नियन्त्रण प्राप्त करने की कोशिश करेगा।” प्रतिनिधि मंडल एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के वित्तीय निर्णयों (ट्रिजैक्शन्स) की जाँच कराने का भी अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, ताकि यह निर्णय हो सके कि दातव्यों में कितना भारत को और कितना इंगलिस्तान को देना है। वह इस बात का भी प्रयत्न करेगा कि भारत और इंगलिस्तान दोनों में से प्रत्येक को अधिकार हो कि वह “स्वेच्छा से साक्षादारी खत्म कर सके, और भारत उस समाधान को स्वीकार करने को स्वतन्त्र होगा जो स्पष्टतः उसके हित में आवश्यक हो।”

कांग्रेस ने गांधीजी को गोलमेज कांफरेन्स के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अधिकार दिया कि वह गांधीजी के नेतृत्व में काम करने के लिए अन्य प्रतिनिधियों को भी नियुक्त कर सकती है।

कांग्रेस ने इस अवसर पर सरदार भगत सिंह और उनके साथी सर्व श्री सुखदेव और राजगुरु के वलिदान पर प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा को नापसन्द करते हुए तथा इन तीनों नवयुवकों के शौर्य और कुर्बानी की प्रशंसा करते हुए राय जाहिर की कि “इन तीनों की फासी निरर्थक बदले का काम है, तथा राष्ट्र की सर्वसम्मति छोटी सी मांग का सकल्पित तिरस्कार है।” उसने यह भी कहा : “सरकार ने दो राष्ट्रों के बीच सद्भावना की वृद्धि करने का, जो इस समय सर्वसम्मति से आवश्यक है, तथा उस दल को जो निराशा से पराभूत हो हिंसा करते हैं; शान्ति के मार्ग की ओर आकर्षित करने का सुनहरा अवसर खो दिया है।”

इस प्रस्ताव को जवाहर लालजी ने पेश किया, और मालवीयजी ने इसका अनुमोदन किया। मालवीयजी ने बहुत ही संतप्त हृदय से भगतसिंह आदि क्रान्तिकारियों के ‘वलिदान’ के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए नौजवानों के क्रान्तिकारी कार्यों के लिए सरकार की स्वराज्य-विरोधी गतिविधि को उत्तरदायी ठहराया, पर ‘अहिंसात्मक कार्यक्रम’ पर अपनी आस्था प्रकट करते हुए उन्होंने नौजवानों से कहा : “यदि आप वास्तव में भगतसिंह से प्रेम करते हो, तो प्रण करो कि हम शान्तिमय मार्ग पर चलते हुए विदेशी राज्य को शीघ्र से शीघ्र हटा देंगे।”

साम्प्रदायिक निर्णय

जुलाई सन् १९३१ में मालवीयजी और डाक्टर अन्सारी की रजामन्दी से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने साम्प्रदायिक समस्या पर एक योजना तैयार की जो एक वक्तव्य के रूप में प्रसारित की गयी। योजना में जिसे वर्किंग कमेटी विशुद्ध

सम्प्रदायवाद और विशुद्ध राष्ट्रवाद पर आश्रित प्रस्तावों में समझौता घोषित करती थी निर्धारित किया गया कि (१) सविधान की मौलिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था द्वारा सब सम्प्रदायों को उनकी संस्कृतियों, भाषाओं, लिपियों, धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों तथा धार्मिक स्थायी निधियों की गारंटी दी जायेगी, (२) संविधान की विशेष व्यवस्था द्वारा प्रत्येक सम्प्रदाय का पर्सनल ला सुरक्षित किया जायगा, (३) विभिन्न प्रान्तों में अल्पसंख्यकों के राजनीतिक और दूसरे अधिकारों की रक्षा केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा, (४) सब वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को वोट देने का अधिकार होगा, हर हालत में यह अधिकार एक-सा होगा और इतना विस्तृत होगा कि वह प्रत्येक सम्प्रदाय की जनसंख्या के अनुपात को निर्वाचक सूची में अभिव्यक्त कर सके, (५) भारत के भावी संविधान में संयुक्त निर्वाचन ही प्रतिनिधित्व का आधार होगा। सिंध में हिन्दुओं के लिए, आसाम में मुसलमानों के लिए, पंजाब में तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त में सिक्खों के लिए, तथा उन प्रान्तों में जहाँ वे जनसंख्या के २५ प्रतिशत से भी कम हैं, हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए संघीय और प्रान्तीय विधान सभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित होंगे और उन्हें दूसरे स्थानों पर चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, (६) नियुक्तियाँ निर्देशनीय आयोग द्वारा की जायेंगी जो निम्न योग्यताएँ निर्धारित करेगा, तथा लोकसेवा की कार्य-कुशलता और देश की लोक-सेवाओं में उचित हिस्से के लिए सब सम्प्रदायों को समान अवसर के सिद्धान्त को ध्यान में रखेगा, (७) संघीय और प्रान्तीय मंत्रिमण्डल के गठन में संवैधानिक परम्परा (कन्वेंशन) द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों को मान्यता दी जायेगी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और बलूचिस्तान की सरकार और प्रशासन का ढाँचा दूसरे प्रान्तों के ढाँचों के समान होगा, (८) सिन्ध एक पृथक् प्रान्त बनाया जायगा, बशर्ते कि सिन्ध की जनता पृथक् प्रान्त के वित्तीय बोझ को वहन करने को तैयार हो, (९) देश का भावी विधान संघीय होगा, अवशिष्ट अधिकार संघ की इकाइयों में निहित होंगे, जब तक कि और जाँच के बाद यह सिद्ध न हो जाय कि यह भारत के सर्वोच्च हितों के विरुद्ध होगा।^१

मौलिक अधिकार

अगस्त सन् १९३१ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कराची कांग्रेस में प्रस्तावित मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को किसी हद तक सशोधित कर

निश्चित किया। इस प्रस्ताव में नागरिकों की मौलिक स्वतन्त्रताओं, उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की व्याख्या के अतिरिक्त किसानों और मजदूरों के आर्थिक हितों की रक्षा के सम्बन्ध में भी निर्देशन थे। यह प्रस्ताव निःसन्देह मौलिक अधिकारों से सुसज्जित लोकतान्त्रिक कल्याणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता था। प्रस्ताव के शुरू में ही घोषित कर दिया गया था कि 'कांग्रेस की ओर से स्वीकृत होनेवाले किसी भी शासन विधान में' इन बातों की व्यवस्था रहनी चाहिए, या स्वराज्य सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह इनकी व्यवस्था कर सके।

इस तरह गोलमेज सम्बन्धी कराची का प्रस्ताव, साम्प्रदायिक समझौता सम्बन्धी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का वक्तव्य, और मौलिक अधिकार सम्बन्धी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह प्रस्ताव कांग्रेस के लक्ष्य, सिद्धान्तों और नीति को अच्छी तौर पर स्पष्ट कर देते हैं। मालवीयजी को कांग्रेस के ये तीनों प्रस्ताव मंजूर थे, यद्यपि पूर्ण स्वतन्त्रता की उनकी व्याख्या में औपनिवेशिक स्वराज्य के सिद्धान्त की पुट थी।

सरकार गोलमेज कांफरेन्स में कांग्रेस को बीस प्रतिनिधि देने को तैयार थी। कतिपय कांग्रेसी नेता भी चाहते थे कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल १५ सदस्यों का हो। पर अन्त में यही निश्चय हुआ कि अकेले गांधीजी ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करें। वाइसराय ने गांधीजी को विश्वास दिलाया था कि वे मालवीयजी, श्रीमती सरोजनी नायडू तथा डाक्टर अन्सारी को भी गोलमेज कांफरेन्स में आमन्त्रित करेंगे, पर उन्होंने डाक्टर अन्सारी को आमन्त्रित नहीं किया।

२१. गोलमेज कांफरेन्स का दूसरा सत्र

लन्दन यात्रा

२९ अगस्त सन् १९३१ को 'राजपूताना' जहाज से गांधीजी, और बहुत से दूसरे महानुभाव गोलमेज कांफरेन्स में भाग लेने लन्दन के लिए रवाना हुए। रास्ते में नवाब भूपाल ने गांधीजी और मालवीयजी से बातें की। गांधीजी कांग्रेस की मांग पर अडिग रहे। इससे कम पर वे सरकार से कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। मालवीयजी ने भी नवाब साहब से स्पष्ट शब्दों में कह दिया—“जीवन-मरण का प्रश्न है, मैं लन्दन इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि पौने सोलह आना लेकर लौटूँ। गांधीजी का साथ मैं हरगिज नहीं छोड़ूँगा।” नवाब भूपाल ने कहा—“फिर तो बात टूटेगी।” मालवीयजी ने कहा, “चाहे जो हो।”^१

१२ सितम्बर को मालवीयजी और गांधीजी लन्दन पहुँचे। वहाँ एक सभा में दोनों का स्वागत, तथा गांधीजी का भाषण हुआ। इसके बाद मालवीयजी ने गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करते हुए सेठ घनश्यामदास विडला से कहा—“गांधीजी कपड़े नहीं पहनते, कहीं इन्हें कुछ हो न जाये। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रोग हो तो मुझे हो, मौत आये तो मुझे आये।”^२

गांधीजी

१५ सितम्बर सन् १९३१ को गांधीजी ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी (संघ ढाचा समिति) में पहली बार बोलते हुए कांग्रेस के इतिहास और पोजीशन की कुछ चर्चा करने के बाद दावा किया कि वह भारत की प्रमुख राजनीतिक और राष्ट्रीय संस्था है, जो देश के 'सब हितों और वर्गों' का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि उसने रियासतों के आन्तरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, फिर भी उसने समय-समय पर राजाओं की भी सेवा की है।^३ कांग्रेस, उन्होंने कहा, 'किसानों की संस्था है और बनती चली जा रही है' और गरीब जनता की सेवा वह अपना कर्तव्य समझती है।^४ अपने सम्बन्ध में उन्होंने कहा, 'एक समय था

१. घनश्यामदास विडला की डायरी के कुछ पन्ने, पृ० २६।

२. वही, पृ० ३१।

३. राउंड टेबल कांफ्रेन्स : सेफिड सेशन जि० १, पृ० ४३।

४. वही, पृ० ४३।

जब मैं ब्रिटिश प्रजा होने और कहे जाने पर गर्व करता था। पर कई वर्षों से मैंने अपने को 'ब्रिटिश प्रजा' कहना बन्द कर दिया है। मैं अपने को प्रजा के बजाय 'विद्रोही' कहा जाना चाहूँगा। लेकिन मैं अब नागरिक होने की आकांक्षा करता हूँ, साम्राज्य में नहीं कामनवेल्थ में, अगर ईश्वर की इच्छा से सम्भव हो तो चिरस्थायी साझेदारी में, पर ऐसी साझेदारी में नहीं, जो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे पर आघ्यारोपित हो।^१

राष्ट्रीय भाग के सम्बन्ध में कांग्रेस के निर्णयों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव को पढ़ कर सुनाया और कहा कि यह उसका आदेश पत्र है जिसकी पुष्टि उनका कर्तव्य है। इस प्रस्ताव की कतिपय बातों की व्याख्या करते हुए गांधीजी ने कहा कि कांग्रेस वित्तीय ऋण की अदायगी से इनकार नहीं करती, पर जानना चाहती है कि उसका कितना भार भारत पर बाजिव है।^२ उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनिवार्य रूप से सम्बन्ध विच्छेद की बात नहीं करती, वह तो केवल "सम्बन्ध विच्छेद करने के अधिकार" का दावा करती है, और चाहती है कि सम्बन्ध स्वैच्छिक हो, दो विलुप्त बराबरो के बीच में हो, दोनों के "पारस्परिक हित" में हो।^३

गांधीजी की इस व्याख्या से स्पष्ट था कि यदि ब्रिटिश मंत्रिमण्डल और पार्लियामेंट भारत को स्वतंत्रता देने को, केन्द्र और प्रान्त दोनों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने को, सेना, वैदेशिक विषय, वित्त, सीमा शुल्क और आर्थिक नीति पर कंट्रोल देने को, तथा सरक्षणों के सम्बन्ध में कांग्रेस के विचारों पर समुचित ध्यान देने को तैयार होती, तो कांग्रेस भी भारत को ब्रिटिश कामनवेल्थ का स्वैच्छिक स्वतंत्र सदस्य बनाने को राजी हो जाती।

१७ सितम्बर को गांधीजी ने कहा कि यहाँ उपस्थित हम सब भारतीय 'राष्ट्र द्वारा, जिसका हमें प्रतिनिधित्व करना चाहिए, चुने हुए नहीं हैं, हम सरकार द्वारा चुने हुए हैं' और प्रतिनिधियों की सूची में स्पष्ट खाली स्थान है, अर्थात् जिन्हें यहाँ होना चाहिए नहीं हैं। उन्होंने भाग की कि सरकार क्या देना चाहती है, उसे बताये, ताकि उस पर विचार किया जा सके।^४ सरकार के इस आक्षेप का उत्तर देते हुए कि कांग्रेस भारत में अपनी समानान्तर (परेलल) सरकार स्थापित करना चाहती है, गांधीजी ने कहा : 'यद्यपि मौजूदा सरकार ने

१. वही, पृ० ४३।

३. वही, पृ० ४५।

२. वही, पृ० ४६।

४. वही, पृ० १५७।

हम पर धृष्टता के साथ समानान्तर सरकार स्थापित करने का दोष लगाया है; मैं इस अभियोग को अपने ढंग पर मंजूर करूंगा। यद्यपि हमने कोई समानान्तर सरकार स्थापित नहीं की है, हम निःसन्देह किसी न किसी दिन मौजूदा सरकार को हटा देने की, और यथोचित प्रक्रिया में विकास के पथ में उस सरकार का उत्तरदायित्व ग्रहण करने की भी आकांक्षा करते हैं।^१

जबकि करीब-करीब सभी चाहते थे कि संघीय विधान मंडल के दो सदन हों, गांधीजी की राय में एक सदन ही पर्याप्त था।^१ इसी तरह जबकि मताधिकार को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी अधिकांश वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, गांधीजी इसके पक्ष में थे,^२ पर उन्होंने प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के बजाय परोक्ष चुनाव पद्धति का समर्थन किया।^३ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख ग्रन्थियों को सुलझाने के लिए वे उन तीनों के सम्बन्ध में 'विशेष व्यवहार' की बात सोचने को तैयार हैं, पर वे अन्य वर्गों और हितों के लिए 'विशेष प्रतिनिधित्व' की व्यवस्था के विरुद्ध हैं।^४

उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका की तरह के दो प्रकार के मुख्य न्यायालयों की स्थापना का विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट हो जो सभ के सविधान, संघ के कानून, संघ सरकार के आदेशों से सम्बन्धित मामलों पर निर्णय करे, और दूसरा ऐसा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय हो जो प्रान्तीय कानूनों और आदेशों से सम्बन्धित मामलों की अपील सुने। वे चाहते थे कि भारत के फेडरल कोर्ट का क्षेत्राधिकार यथासंभव विस्तृत हो, वही देश का सर्वोच्च मुख्य न्यायालय हो, उसे संघीय कानूनों और आदेशों के साथ साथ प्रान्तीय कानूनों और आदेशों से सम्बन्धित मामलों की अपीलों सुनने का भी अधिकार हो।^५ गांधीजी की यह भी मांग थी कि सविधान में जनता के मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था हो, न्यायालयों द्वारा उनका न्यायिक संरक्षण हो, और इस सम्बन्ध में रियासतें फेडरल कोर्ट का न्यायाधिकार स्वीकार करें।^६ उन्होंने काफरेन्स में उपस्थित राजाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि रियासती जनता के अपने प्रतिनिधि नहीं हैं, उनके हितों और आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व का भार भी आप पर है। अच्छा यही होगा कि इस सम्बन्ध में

१. वही, पृ० १६२।

२. वही, पृ० १६०।

३. वही, पृ० १५९।

४. वही, पृ० १६३।

५. वही, पृ० ७२१।

६. वही, पृ० ७२२।

आप कुछ ऐसा निश्चय करें कि आप को प्रजा अनुभव कर सके कि राजाओं द्वारा उनका प्रतिनिधित्व हो रहा है।^१ गांधीजी ने कहा : “फेडरल कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय की पोजीशन प्राप्त हो, जिसके बाहर कोई व्यक्ति जो भारत में रहता हो, न जा सके।”^२ उन्होंने कहा कि मेरे विचार में “जितने अधिकार आप फेडरल कोर्ट को देंगे, उतना ही अधिक विश्वास हम संसार और राष्ट्र में प्रेरित कर सकेंगे।”^३

१७ नवम्बर सन् १९३१ को फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में गांधीजी ने सेना और वैदेशिक विषयो पर पूरे नियंत्रण की माग की, और कहा कि मौजूदा सेना, ब्रिटिश “आधिपत्य की सेना है”, और “यह सारी सेना भंग कर दी जाय”, यदि वह भारत के नियंत्रण में हस्तान्तरित नहीं होती।^४

१९ नवम्बर सन् १९३१ को गांधीजी ने अंग्रेजों के व्यापारिक हितों के संरक्षण की विशेष व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तावित संरक्षणों को भारतीय जनता के हितों के विरुद्ध बताया। उन्होंने प्रजाति के आधार पर किसी प्रकार का पक्षपात या विरोध दोनों को गलत बताया।

मालवीय जी

मालवीयजी ने गांधीजी की तरह कांग्रेस को राष्ट्र की प्रमुख संस्था बताया हुए उसकी ओर से प्रस्तुत गांधीजी के अधिकांश विचारों तथा राष्ट्रीय माँग का समर्थन किया, तथा उन सब पर अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने पूर्ण स्वतन्त्रता, पूर्ण उत्तरदायी शासन, अखिल भारतीय सघीय व्यवस्था, वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, सर्विसेज (लोकसेवाओं) के भारतीयकरण तथा ब्रिटेन के साथ स्वतन्त्र भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की डटकर पुष्टि की। स्वतन्त्रता के लिए वे प्रान्तीय स्वशासन के साथ-साथ केन्द्र में उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी आवश्यक समझते थे। वे गांधीजी के इस विचार से सहमत थे कि ‘वाह्य शक्ति द्वारा प्रशासित और संचालित सुदृढ़ केन्द्र और सुदृढ़ प्रान्तीय स्वशासन दो विरोधी विचार हैं, प्रान्तीय स्वशासन और केन्द्रीय उत्तरदायित्व का साथ-साथ कार्यान्वयन नितान्त आवश्यक है।’ उनकी धारणा थी कि “केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक व्यवस्था का प्राण है, और जब तक वह

१. वही, पृ० ७२२।

२. वही, पृ० ७२२।

३. वही, पृ० ७२३।

४. वही, जि० २ पृ० १००१, १००३।

निर्दोष और स्वस्थ आधार पर प्रतिष्ठित नहीं होती, तब तक निर्दोष प्रान्तीय व्यवस्था असंभव है।”^१ उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रीय स्वशासन को स्थापित किए बिना जनता की भावनाओं की तुष्टि तथा अखिल भारतीय संघ की स्थापना नामुमकिन है। शान्ति और सुव्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए उत्तरदायी शासन के मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर केन्द्रीय व्यवस्था का पुनर्गठन नितान्त आवश्यक है।

मालवीयजी गांधीजी के इस विचार से भी सहमत थे कि संरक्षण अर्थात् सेना राष्ट्र के अस्तित्व का तत्व है, और जब तक किसी राष्ट्र का संरक्षण किसी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित है, तब तक वह राष्ट्र निःसन्देह उत्तरदायित्व ढंग से शासित नहीं समझा जा सकता।^२ उनका कहना था कि राष्ट्रीय संरक्षण का उत्तरदायित्व स्वशासन का महत्वपूर्ण अंग है, और सेना पर केन्द्रीय विधान सभा का पूरा नियन्त्रण स्वस्थ उत्तरदायी प्रशासकीय व्यवस्था की स्थापना के लिए नितान्त आवश्यक है। वे चाहते थे कि सेना का नियन्त्रण भारतीय सदस्य को हस्तान्तरित कर दिया जाय, जो राष्ट्रीय सरकार के दूसरे मन्त्रियों की तरह केन्द्रीय विधान सभा को उत्तरदायी हो, और संकट-कालीन परिस्थिति में ही मन्त्रिमण्डल की राय से गवर्नर-जनरल सेना के संचालन और प्रबन्ध का भार स्वयं ग्रहण कर सके। अपने विचार को स्पष्ट करते हुए मालवीयजी ने कहा : “जब मैं सेना को भारतीय सदस्य के अधीन रखने की बात कहता हूँ, तब मेरा तात्पर्य वैसे ही अधिकार से है जैसा कि प्रत्येक सभ्य शासन के अधीन सदस्य को दिया जाता है।” वे राष्ट्र की प्रगति के लिए सेना का पुनर्गठन और भारतीयकरण भी आवश्यक समझते थे। उनके विचार में भारतीय जनता के लिए राष्ट्रीय राजस्व का पैतालिम प्रतिशत सेना पर खर्च करना अवश्य ही कष्टदायक है। वे चाहते थे कि स्थायी सेना को घटाकर एक नागरिक सेना गठित की जाय जो संकट में काम में लायी जा सके। उनकी धारणा थी कि नागरिक सेना का व्यय स्थायी सेना की तुलना में कम होगा, और उसके द्वारा “जनता में राष्ट्र की रक्षा की भावना” भी जागृत और विकसित होगी।^१ देश के आर्थिक भार को कम करने के लिए वे गोरी पल्टनों को घटाना और हटाना आवश्यक समझते थे। उनका प्रस्ताव था

१. इण्डियन राउंड टेबल कांफरेन्स, सेकिड सेशन, फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी, जि० २, पृ० १२२३। २. वही, पृ० १००१।

कि गोरी पल्टन का वह भाग जो देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए नियत है ब्रिटेन वापस बुला लिया जाय, तथा उसका दूसरा भाग भी धीरे-धीरे कम करके भारतीय सेना का पूर्ण भारतीयकरण कर दिया जाय। वे चाहते थे कि भारतीय सेना में सब जाति, सम्प्रदाय, और वर्ग के भारतीय भरती किये जायें, और उन्हें हर प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों की ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जाय, ताकि भारतीय नवयुवक सेना के प्रत्येक विभाग में काम करने की क्षमता प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि उन्होंने विश्वयुद्ध के बाद गठित रोलिसन कमेटी को कहा था कि सैनिक शिक्षा के लिए भारत में एक उच्चस्तरीय कालेज तथा कुछ सैनिक स्कूल स्थापित हो, और सरकार से वायदा किया था कि यदि वह इस काम के लिए धन लगाने में असमर्थ हो, तो सैनिक कालेज के लिए धन एकत्र करने को वे तैयार हैं। इसके बाद सरकार ने देहरादून में एक स्कूल स्तर की सैनिक शिक्षा संस्था अवश्य स्थापित की, पर वह देश की सैनिक आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं ममझी जा सकती। उनकी धारणा थी कि भारतीय सेना का पुनर्गठन और परिशिक्षण सेना के भारतीय सदस्य का उत्तरदायित्व होना चाहिए।^१

कांफरेन्स के सभी भारतीय सदस्य प्रान्तीय स्वशासन के साथ ही केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना के पक्ष में थे। देशी नरेशों ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि वे अखिल भारतीय सभ में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक केन्द्र में उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू नहीं की जाती। सभी प्रान्तीय सदस्य सेना के भारतीयकरण के भी पक्ष में थे। पर सर तेज बहादुर सप्रू और श्री श्रीनिवारा शास्त्री आदि चाहते थे कि कुछ काल के लिए सेना का भारतीय सदस्य केन्द्रीय विधान मण्डल के बजाय गवर्नर-जनरल को उत्तरदायी हो।^२ मालवीयजी इस सुझाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।^३ जिस तरह मालवीयजी गोरी पलटन कम करके और हटाकर तथा नागरिक सेना को संघटित करके भारतीय सेना का भारतीयकरण करना चाहते थे, वह गतिविधि भी सम्भवतः बहुत से भारतीय सदस्यों को अब्यावहारिक दिखाई देती थी, कम से कम वे इतने आगही नहीं थे जितने मालवीयजी। लार्ड रीडिंग आदि अंग्रेज सदस्य तो इसे विल्कुल ही मानने को तैयार नहीं थे।^४ सर तेज बहादुर सप्रू की यह भी राय थी कि वैदेशिक मन्त्री भी गवर्नर-जनरल को

१ वही, ९८०-९९१।

२. वही, पृ० ९७२, १००८।

३. वही, पृ० ९८१।

४. वही, पृ० ९९७।

ही उत्तरदायी हो, वह भारतीय मन्त्रिमण्डल का सदस्य होते हुए इस विभाग के प्रबन्ध के लिए विधान मण्डल को उत्तरदायी न हो।^१ यही राय श्री श्रीनिवास शास्त्री की थी।^२ पर मालवीयजी की तरह श्री० ए० आर० ऐयंगर चाहते थे कि रक्षा और वैदेशिक विषय, दोनों ही विधान मण्डल के अधीन हो।^३

गांधीजी की तरह मालवीयजी भी वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे। दोनों का विचार था कि इससे जनता का राजनीतिक स्तर ऊँचा उठेगा। पर जबकि गांधीजी का झुकाव परोक्ष निर्वाचन पद्धति की ओर दिखाई देता था, मालवीयजी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में थे। इसी तरह जबकि गांधीजी एक सदनीय विधायिका के पक्ष में थे, मालवीयजी दो सदन आवश्यक समझते थे, और दूसरे सदन में रियासतों के प्रतिनिधियों को चालीस प्रतिशत स्थान देने को तैयार थे। पर जबकि विधेयको का संशोधन वे दूसरे सदन का मुख्य काम समझते थे, द्रव्य विधेयको (मनी बिल) पर पहले सदन का ऐकान्तिक अधिकार ही वे उचित समझते थे। रियासतों के प्रवक्ता चाहते थे कि दोनों सदनों के अधिकार समान हो, और पहले सदन में भी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए एक तिहाई स्थान सुरक्षित किये जायें। मालवीयजी इन बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।

कांग्रेस के पूर्णस्वराज्य सम्बन्धी निर्णय को ध्यान में रखते हुए गांधीजी ब्रिटेन से भारत के भावी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को "स्वैच्छिक समान साक्षादारी" के नाम से सम्बोधित करते थे, मालवीयजी अपने पुराने अभ्यास के अनुरूप उसे पूर्ण "औपनिवेशिक पद (डोमीनियन स्टेट्स)" कहते थे। यद्यपि भाषा भिन्न थी, दोनों के विचार और भाव एक जैसे थे। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के वयोवृद्ध सदस्य लार्ड वेलफोर ने सन् १९१८ में ही ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित कर दिया था कि पूर्ण स्वतन्त्र उपनिवेश 'कामनवेल्थ के समान और स्वतन्त्र सदस्य हैं।' इस रूप में ही सन् १९२५ में देशबन्धु चित्तरजन दास ने अपने फरीदपुर भाषण में ब्रिटिश कामनवेल्थ की सदस्यता के विचार का समर्थन किया था। सन् १९३१ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी वेस्ट मिनिस्टर स्टेचूट में दास साहब के विचार के विल्कुल अनुरूप ही कामनवेल्थ की सदस्यता की व्याख्या की थी। कांफरेन्स के अन्य सभी सदस्य 'डोमीनियन स्टेट्स' को ही भारत का राजनीतिक ध्येय स्वीकार करते थे।

१. वही, पृ० १०१०।

२. वही, पृ० १००८।

३. वही, पृ० १०२३।

गांधीजी की तरह मालवीयजी भी उन ब्रिटिश व्यापारियों की, जो भारत में कोई व्यापार कर रहे थे, यह विश्वास देने को तैयार थे कि उनके व्यापार, उद्योग तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई ऐसा कानून या आदेश पारित नहीं किया जायगा जो समान रूप से भारतीय औद्योगिकों और व्यापारियों पर लागू न हो। पर दोनों में से कोई भी यह आश्वासन देने को तैयार नहीं था कि किसी प्रकार का भेदमूलक कानून या भेदमूलक आदेश जारी नहीं किया जायगा। गांधीजी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गरीब जनता की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए भारत सरकार को बहुत से ऐसे कानून पास करना होंगे जिन्हें औद्योगिक वर्ग या सम्पत्ति-सम्पन्न अपने विरुद्ध समझ सकते हैं। मालवीयजी ने कहा कि देश के औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार को नाना प्रकार से भारतीय उद्योगों को ऐसी सहायता देनी होगी जो भारत में चालू विदेशी उद्योग व्यापार को समान रूप से नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा : “भारत में व्यापार करने वालों के हक की चर्चा एक बात है, भारत के देशज उद्योगों की न्यायसंगत उपायों द्वारा उन्नति करना दूसरी बात है। भारत में व्यापार करने वाले विदेशी और अंग्रेज अपने व्यापारिक अधिकारों की रक्षा माँगने के हकदार हैं, पर वे भारत में भारतीय देशज उद्योगों के समान सहायता और संरक्षण माँगने के अधिकारी नहीं हैं”^१। इन कारणों से वेन्थल की इस माग का विरोध करते हुए कि अंग्रेजों के व्यापार का संरक्षण भारतीय व्यापार के समान हो, और कोई भेदमूलक कानून पास न हो, तथा गांधीजी के सुझाव की भाषा को किसी अंश में सशोधित करते हुए मालवीयजी ने प्रस्ताव किया कि केवल प्रजाति, धर्म या रंग के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो हिन्दुस्तान में विधिसंगत ढंग से रह रहा है या प्रवेश करता है न कोई भेदमूलक कानून पास किया जायगा न कोई भेदमूलक प्रशासनीय कार्यावाही की जायेगी।^२ मालवीयजी और गांधीजी के विचार में इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा विदेशी व्यापारियों के न्यायसंगत हितों की भरपूर रक्षा हो सकेगी। इस सम्बन्ध में लार्ड रीडिंग से, जो वेन्थल की तरह सब प्रकार के भेदमूलक कानून के विरुद्ध थे, और चाहते थे कि ब्रिटिश उद्योग और व्यापार की भारत के उद्योग व्यापार के समान ही रक्षा हो, मालवीयजी का विवाद भी हुआ।

श्री एम० आर० जयकर, श्री श्रीनिवास शास्त्री, श्री ए० आर० ऐयंगर प्रभृति बहुत से दूसरे नेताओं ने मालवीयजी के विचारों का समर्थन किया।

श्री श्रीनिवास शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी सहायता सरकार द्वारा दी जाती है, उसका भार जनता को सहन करना होता है, जिसे वह राष्ट्र के हित में वहन कर सकती है, पर विदेशी उद्योगों को वही सहायता देकर भारतीय जनता को भार वहन करने के लिए बाध्य करना न्यायसंगत नहीं समझा जा सकता। भारतीय औद्योगिकों के प्रतिनिधि सर फीरोज सेठना और सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने भी बेन्थल के विचारों का विरोध करते हुए मालवीयजी के विचारों का समर्थन किया। उन्होंने बहुत से दृष्टान्त देते हुए बताया कि भारत में अंग्रेज औद्योगिकों ने भारतीय व्यापार और उद्योगों की प्रगति में किस तरह रोड़े अटकाये, और कहा कि कामनवेल्थ की सदस्यता के नाम पर अंग्रेज औद्योगिक उन सुविधाओं की आशा नहीं कर सकते जिनसे भारत के औद्योगिक विकास को क्षति पहुंचे। सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने कहा कि जिस समान साक्षादारी की चर्चा बेन्थल साहब करते हैं, वह तो भारत के आर्थिक विकास में बाधा डालेगी, देश के आर्थिक सुधार और उन्नति पर अनुद्धार्य बन्धकपत्र लागू कर देगी, और काफरेन्स में विचाराधीन राजनीतिक स्तर की उन्नति को निरर्थक कर देगी”।^१

सम्पत्ति अधिकार

गांधीजी ने सम्पत्ति-सम्बन्धी हितों की रक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया कि किसी मौजूदा स्वत्व में जो न्यायसंगत ढंग से प्राप्त किया गया है, और जो राष्ट्र के उत्कृष्ट हितों के विरुद्ध नहीं है, हस्तक्षेप नहीं किया जायगा, बजुज एक कानून के जरिये जो इन स्वत्वों पर लागू हो। जब मालवीयजी का ध्यान सम्पत्ति सम्बन्धी उस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया, जो उन्होंने सन् १९२८ में लखनऊ में सर्वदलीय काफरेन्स में प्रस्तावित किया था, तब उन्होंने उसे मानते हुए भी गांधीजी के इस प्रस्ताव का समर्थन करना न्यायोचित बनाया, अर्थात् उनके विचार में इन दोनों में कोई मौलिक विरोध नहीं था।^२ गांधीजी और मालवीयजी दोनों ने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और उसकी रक्षा और वृद्धि के निमित्त सब सम्य देशों में वैयक्तिक सम्पत्ति और स्वत्वों में कानून द्वारा हस्तक्षेप और परिवर्तन होता ही रहता है। अपने इस तर्क के समर्थन में मालवीयजी ने कई देशों की संवैधानिक धाराओं का उदाहरण देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रिटिश शासन में सरकारी अफसरों ने राष्ट्र के हितों की उपेक्षा

करते हुए गलत तरीके से राष्ट्र की सम्पत्ति पर कतिपय व्यक्तियों का स्वत्व प्रतिष्ठित कर दिया है, उन सब स्वत्वों की तुलना न्यायसंगत विधि से प्राप्त स्वत्वों से नहीं की जा सकती। गलत तरीके से प्राप्त स्वत्व की जात्र कानून के आधार पर न्यायालयों द्वारा अवश्य ही न्यायसंगत है।^१ सर तेज बहादुर सप्रू का विचार था कि स्थायी प्रदानों का फिर से संपरीक्षण न्यायोचित नहीं होगा।^२

अल्पसंख्यक कमेटी

२८ सितम्बर सन् १९३१ को अल्पसंख्यक कमेटी की पहली बैठक हुई। कुछ बातचीत के बाद कमेटी की बैठक तीन दिन के लिए स्थगित हो गयी। १ अक्टूबर को गांधीजी ने कहा कि बैठक को एक सप्ताह के लिए और स्थगित कर दिया जाय, ताकि किसी छोटी सी गोष्ठी में या वैयक्तिक विचार विमर्श द्वारा शान्ति के वातावरण में समाधान ढूँढा जा सके। कई सदस्यों ने इसका विरोध किया, पर अन्त में बैठक एक सप्ताह के लिए मुलतवी कर दी गयी। इसके बाद गांधीजी ने काफरेन्स के बहुत से सदस्यों से अनौपचारिक ढंग से साम्प्रदायिक समस्या पर बातचीत की, पर कोई सर्वसम्मत समाधान नहीं निकल पाया।

८ अक्टूबर को अल्पसंख्यक कमेटी की दूसरी बैठक हुई। गांधीजी ने गम्भीर खेद और गम्भीरतर नदामत के साथ स्वीकार किया कि वह प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत द्वारा साम्प्रदायिक समस्या का कोई समाधान निकालने में बिल्कुल विफल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विफलता के कारण भारतीय प्रतिनिधियों की बनावट में निहित थे। करीब करीब हम सब पार्टियों या ग्रुपों के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि सरकार की नामजदगी से ही यहाँ हैं। समाधान के लिए जो व्यक्ति अनिवार्य रूप से आवश्यक है, वे भी यहाँ नहीं पाये जाते। गांधीजी को सलाह थी कि अल्पसंख्यक कमेटी की बैठकें उस समय तक के लिए स्थगित कर दी जायें जब तक सविधान की बुनियादी बातें तय नहीं हो जाती, और यदि उसके बाद भी साम्प्रदायिक प्रश्न बने रहें, तो संविधान में न्यायिक ट्रिब्युनल की नियुक्ति की व्यवस्था कर दी जाय, जो इसका निर्णय करे।^३

१. वही, पृ० ११२७, ११२९।

२. वही, पृ० ११२७।

३. राउंड टेबिल काफरेन्स, सेकिन्ड सेशन-माइनारिटी कमेटी, जि० २।

साम्प्रदायिक समस्या

इसके बाद अल्पसंख्यक कमेटी तो पाँच सप्ताह के लिए स्थगित हो गयी, पर साम्प्रदायिक समस्या बराबर परेशान करती रही। गांधीजी की इस बात के जवाब में कि बुनियादी राजनीतिक और संवैधानिक प्रश्नों के तय हो जाने के बाद ही वास्तविकता के आधार पर साम्प्रदायिक समस्या का समाधान संभव है, मुसलमान प्रतिनिधियों का कहना था कि मुसलमानों के लिए उनके अधिकारों और हितों का समुचित प्रबन्ध तथा राज्याधिकार में उनके हिस्से का निर्णय ही सर्वाधिक बुनियादी प्रश्न है। सर शफात अहमद खान ने घोषित किया : “जब तक साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं होती और हमें (मुसलमान प्रतिनिधियों को) पता नहीं चलता कि उनकी स्थिति क्या है, तब तक अन्य विषयों पर हमारे विचार-विमर्श में कोई यथार्थता नहीं है।”^१ मिस्टर मुहम्मद अली जिना और सर मुहम्मद शफी ने घोषित किया कि जब तक मुसलमानों की माँगों और संरक्षाएँ संविधान में शामिल नहीं हो जाती तब तक वह उन्हें मंजूर नहीं होगा।^२ गांधीजी का यह सुझाव कि प्रत्याशित संविधान में अनिश्चित प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए न्यायिक ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की व्यवस्था कर दी जाय, मुसलमान प्रतिनिधियों को मंजूर नहीं था, क्योंकि वे तो सबसे पहले साम्प्रदायिक प्रश्नों पर सर्वसम्मत निर्णय भारत के संवैधानिक ढाँचे को निश्चित करने के लिए जरूरी समझते थे।

अल्पसंख्यक पैकट

इस गतिरोध और तनाव की स्थिति में यूरोपियन समुदाय के नेता ब्रान्थल साहव ने सब अल्पसंख्यकों से बातचीत करके एक अल्पसंख्यक पैकट तैयार करवाया। सिक्ख इस पैकट में शामिल नहीं किये गये। यह पैकट पृथक् निर्वाचन पद्धति और पृथक् प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर आधारित था, और उसके समर्थकों का दावा था कि वे भारतीय जनता के ४६ प्रतिशत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर हेनरी गिडने का कहना था कि ‘हममें से जिन्होंने इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये हैं, उन्होंने भारतीय राजनीति में एक और फूट पैदा करने के उद्देश्य से ऐसा नहीं किया है।’ ‘उनका लक्ष्य तो विभिन्न सम्प्रदायों के

१. वही, जि०, पृ० १००८।

२. वही, पृ० ९६४-९६५; पृ० १२१३-१२१४।

दृष्टिकोण और हितों की यथासंभव स्पष्ट व्याख्या करके और उन्हें सीमित कर के सहमति का यथासंभव बड़ा सामूहिक माप प्राप्त करना था' ।

१३ नवम्बर सन् १९३१ को अल्पसंख्यक कमिटी की बैठक हुई । प्रधानमंत्री मेकडोनल्ड ने कमिटी का ध्यान अल्पसंख्यक पैक्ट की ओर दिलाते हुए कहा कि साम्प्रदायिक प्रश्न की गुत्थी संविधान की तैयारी में रुकावट पैदा कर रही है । गांधीजी ने कहा कि पैक्ट के समर्थक चाहे कुछ कहे, कांग्रेस ब्रिटिश भारत ही नहीं, बल्कि सारे भारत की ८५ प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करती है । उन्होंने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए साम्प्रदायिक प्रश्न का निर्णय करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक ट्रिब्यूनल का सुझाव पेश किया । उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दू, मुसलमान और सिक्खों को जो हल मजूर होगा उसे कांग्रेस स्वीकार कर लेगी, पर वह किसी दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रिजर्वेशन या विशेष निर्वाचन पद्धति का समर्थन नहीं करेगी ।

प्रधानमंत्री मेकडोनल्ड की अनुमति से हिज हाइनेस आगा खान ने अल्पसंख्यक पैक्ट पेश किया और कहा : "हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस कठिन और उलझी समस्या के ऊपर बहुत सावधानी और चिन्ता के साथ सोचने के बाद हम इस समझौते पर आये हैं, और उसे पूरा स्वीकार करना चाहिए । इस समझौते के सब अंश अन्योन्याश्रित हैं, और समझौता पूरा का पूरा लागू होता है या गिर जाता है ।"

प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि पैक्ट की सार्थकता पर कोई वाद-विवाद हो, पर विवाद छिड़ ही गया । कुछ सदस्यों ने इसका समर्थन और कुछ ने इसका विरोध किया । बहस ने तनाव की गम्भीर स्थिति पैदा कर दी ।

मालवीयजी अल्पसंख्यक कमिटी में अन्त तक चुप रहे । उन्होंने इस तरह गांधीजी का भूक समर्थन किया । केवल एक बार जब सर मुहम्मद शफी ने मालवीयजी की ओर संकेत करते हुए कहा कि यहाँ हिन्दू-महासभा के प्रवर्तक भी मौजूद हैं, तब मालवीयजी ने कहा कि मैं उसका प्रवर्तक या संस्थापक नहीं हूँ ।^१

अन्त में प्रधान-मन्त्री रेमजे मेकडोनल्ड ने विश्वास दिलाया कि अवतक जो काम गोलमेज कांफरेन्स में हुआ है उसे बेकार नहीं होने दिया जायगा, सरकार

१. राउन्ड टेबिल कांफरेन्स-सेकिड सेशन-माइनारिटी कमिटी प्रोसीडिंग, जि० २, पृ० १३५० ।

अपने पुराने वायदे पर अमल करती रहेगी। सर चिम्मनलाल सीतलवाद की इस बात की ओर संकेत करते हुए कि मेकडोनल्ड साहब स्वयं इस ग्रन्थी को सुलझाएँ, उन्होंने पूछा कि 'क्या कमेटी के सब सदस्य मुझसे साम्प्रदायिक समस्या का समाधान करने की, मेरे निर्णय को स्वीकार करने की प्रार्थना पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं?'^१ इस पर श्री श्रीनिवास शास्त्री ने कहा कि इस ओर के हम सब राजी हैं। इस पर मेकडोनल्ड ने कहा कि मैं किसी एक व्यक्ति या ग्रुप की नहीं, बल्कि कमेटी के सब सदस्यों की स्वीकृति चाहता हूँ।^२

इसके बाद मालवीयजी, डाक्टर मुजे, राजा नरेन्द्र नाथ तथा डाक्टर एस० के० दत्त ने एक पत्र द्वारा मेकडोनल्ड को सूचित किया कि वे चाहते हैं कि वे इस समस्या का निपाटारा करें, पर किसी मुसलमान ने इस प्रकार का कोई पत्र मेकडोनल्ड को नहीं भेजा।

केन्द्रीय उत्तरदायित्व

भारतीय प्रतिनिधियों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण तो नये भारत-मन्त्री की गतिविधि थी जिससे काफरेन्स टूटती नजर आती थी। वे सब की बात सुनते जाते थे, पर अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कहते थे। वे साइमन कमीशन की रिपोर्ट से काफी प्रभावित दिखाई देते थे। उन्होंने ९ नवम्बर सन् १९३१ को ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल को लिखा था कि "जब तक पार्टियाँ प्रान्तीय स्वशासन के रूप में अनुभव और शक्ति के साथ केन्द्र का ढाँचा निर्णय करने को नहीं बन जाती, तब तक संघ पर विचार करना समय से पूर्व है। इस बात को स्वीकार करना संघ को पाँच वर्ष के लिए सम्भवतः दस वर्ष के लिए मुलतवी करना है।"^३ इस गोपनीय नोट का हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों को सम्भवतः कोई पता नहीं हो सका, पर भारत-मन्त्री की गतिविधि से उन्हें ऐसा दिखाई देता था कि वह पारस्परिक परामर्श की प्रक्रिया का अन्त कर, केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रश्न को खटाई में डालकर साइमन कमीशन के सुझावों के आधार पर प्रान्तीय स्वशासन ही प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इससे भारतीय प्रतिनिधियों के साथ-साथ ब्रिटेन के मजदूर दल के प्रतिनिधि भी विचलित थे।

१ वही, पृ० १३८६।

२ वही, पृ० १३८७।

३ ताराचन्द्र : हिस्ट्री आफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, जि० ३, पृ० १७५।

इस विषम परिस्थिति में सर तेज बहादुर सप्रू, सर चिमनलाल सीतलवाड, सर काउसजी जहाँगीर, सर फिरोज सेठना, श्रीमती सुवरायन, श्री श्रीनिवास शास्त्री, श्री रामचन्द्र राव, दीवान बहादुर मुदालियर, श्री एम० आर० जयकर, श्री ताम्बे, श्री एन० एम० जोशी, श्री जाधव, श्री वी० वी० गिरि तथा श्री शिवराव ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी के अध्यक्ष लार्ड सेनके को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी यह निश्चित राय है कि सघीय आधार पर उत्तरदायी व्यवस्था को भविष्य में स्थापित करने का केवल आश्वासन पाकर पहली किस्त के रूप में प्रान्तीय स्वशासन को आरम्भ करने के विचार का जरा-सा भी समर्थन करने को भारत की कोई भी प्रतिष्ठित पार्टी तैयार नहीं होगी। यदि सम्राट् की सरकार यह कदम उठाना ही चाहती है, तो वह हमारी सहमति से नहीं, बल्कि हमारी सलाह के बिल्कुल विरुद्ध होगा, और इस काम के लिए सरकार को सम्पूर्ण और अनन्य उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करना होगा। हम गत १९ जनवरी को सरकारी घोषणा की पूर्ति की माँग करते हैं, जिसकी कुछ दिन हुए प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रीय सरकार की ओर से साफ तौर पर पुष्टि की थी। केन्द्र में उत्तरदायित्व की स्थापना को भविष्य के लिए छोड़ कर किसी नये वक्तव्य या प्रान्तीय स्वशासन के विधेयक की प्रस्तावना में घोषणा की पुनरावृत्ति को हमारा समर्थन नहीं होगा, और भारत में उसे विश्वासघात और देश की आवश्यकताओं के सर्वथा अपर्याप्त समझकर बुरा माना जायगा।

ब्रिटिश लेबर पार्टी के सम्मानित प्रतिनिधि प्रोफेसर लीज स्मिथ ने भी इस पत्र की बातों को ठीक समझते हुए उनकी पुष्टि में उस पर हस्ताक्षर कर दिये थे। उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में भावी राजनीतिक प्रक्रिया पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रान्तीय स्वशासन की व्यवस्था अठारह मास में चालू की जा सकती है, जबकि अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था को बनाने में तीन वर्ष या उससे कुछ अधिक समय लगेगा, फिर भी उनके विचार में जल्दी में प्रान्तीय स्वशासन को अलग से चालू करने से कहीं अच्छा होगा कि केन्द्र और प्रान्त दोनों में साथ-साथ उत्तरदायित्व शासन स्थापित किया जाय।^१ भारतीय प्रतिनिधियों ने इस बात का पूरी तौर पर समर्थन किया।

तेज बहादुर सप्रू ने कहा कि "केन्द्र में उत्तरदायित्व से पृथक् प्रान्तीय स्वशासन का मैं अनन्य विरोधी हूँ—इस अवसर पर प्रान्तीय स्वशासन को

स्वीकार करके हम अपने भविष्य को हानि पहुँचाने को तैयार नहीं हैं।^१ श्री श्रीनिवास शास्त्री ने कहा “जनता केवल प्रान्तीय स्वशासन से सन्तुष्ट नहीं होगी, और सन्देह और अविश्वास के वातावरण में भयकर स्थिति पैदा होगी, जो भविष्य के लिए बहुत हानिकार होगी।”^२ दीवान बहादुर मुंदालियर ने कहा कि वह जस्टिस पार्टी की ओर से यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि उसके लिए, जिसने सदा ब्रिटेन से सहयोग किया है, केन्द्रीय उत्तरदायित्व के अभाव में प्रान्तीय स्वशासन की योजना कार्यान्वयन करना, तथा असन्तुष्ट जनता के आन्दोलन का दमन करना असम्भव है।^३ भारतीय मजदूरों के नेता एन० एम० जोशी ने कहा कि श्रमिक वर्ग जनता के कल्याण की वृद्धि के लिए स्वशासन चाहता है, और समझता है कि जब तक पूर्ण स्वशासन प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक देश के राजनीतिज्ञों और सरकार के लिए जनकल्याणकारी रचनात्मक कार्यों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना संभव नहीं है।^४ एम० आर० जयकर ने कहा : “मेरे देश ने स्वतन्त्र होने का निश्चय कर लिया है। अब प्रश्न यह है कि क्या आप उसे वह सदिच्छा से देंगे ताकि हिन्दुस्तान से आपके सम्बन्ध बने रहें और दोनों के व्यापारिक सम्बन्ध चालू रहे, या उसे कटुता के वैकल्पिक ढंग से देना चाहते हैं।”^५ श्रीमती सुवरायन ने कहा “इस समय सारे भारत की दृष्टि प्रान्त पर नहीं बल्कि केन्द्र पर जमी हुई है। वही हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। जो सुधार मिलेंगे उनका मूल्यांकन एकमात्र केन्द्र में प्राप्त उत्तरदायित्व की मात्रा से होगा। उसकी अस्वीकृति या स्थगन सारे देश में जनता के सर्व वर्गों और श्रेणियों में बहुत ही दुःखद निराशा पैदा कर देगा।”^६

श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने अपनी ओर से तथा अपने साथी धन श्याम दास बिडला एवं अपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष जमाल मुहम्मद की ओर से भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत पत्र का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि “भारतीय अधूरे सुधारों से तग आ गये हैं”, और उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए “केन्द्र में सच्चे ठोस सुधार” बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि भारत में ब्रिटिश व्यापार की रक्षा करनी है, तो जो थोड़ी सी सद्भावना बच रही है उसे ब्रिटिश सरकार की सद्भावना से सीचना होगा, वरना कम्युनिज्म और

१. वही, पृ० ११६९।

२. वही, पृ० ११७७-११७८।

३. वही, पृ० ११७२।

४. वही, पृ० ११७३-११७४।

५. वही, पृ० ११७६।

६. वही, पृ० ११७६।

बालशेविज्म का वृक्ष बढेगा, 'जिसके लिए जानकारों की दृष्टि में भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार ही उत्तरदायी समझी जायेंगी' ।

मालवीयजी ने कहा कि यदि प्रान्तीय स्वशासन ही स्वीकार करना था, तो फिर गांधीजी यहाँ क्यों निर्मन्त्रित किये गये, और काफरेन्स में रियासतों के राजे-महाराजे तथा राजनीतिज्ञ क्यों इकट्ठे किये गये, क्योंकि जब तक केन्द्र में उत्तरदायी पद्धति स्थापित नहीं होती तब तक वे अपनी रियासतों को संघ में सम्मिलित करने को तैयार नहीं हैं । उन्होंने कहा कि १९ जनवरी सन् १९३१ को प्रधान-मंत्री मैकडोनाल्ड ने अपनी घोषणा में केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान पालिकाओं पर भारतीयों को शासन का उत्तरदायित्व सौंपने का वचन दिया था, और अब यदि सरकार केवल प्रान्तीय स्वशासन प्रतिष्ठित करेगी, तब भारतीय जनता उसे "विश्वासघात" का दोषी अवश्य ठहरायेंगे, वे समझेंगे कि उन्हें "ठगा गया है" और "अशान्ति दस गुनी बढ़ जायेगी" ।^२ मालवीयजी ने कहा कि मिस्टर जिना और सर मुहम्मद शफी भी कहते हैं कि वे राष्ट्र की प्रगति में बाधा नहीं डालना चाहते, केवल अल्पसंख्यकों के हितों की समुचित रक्षा चाहते हैं । भारत और ब्रिटेन के पारस्परिक सम्बन्धों के बड़े प्रश्न पर समझौता हो जाने पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रश्न समझौते द्वारा तय किया जायगा ।^३

अन्त में भूतपूर्व भारत-मंत्री वेजवुड बेन ने बहुत ही सतप्त हृदय से कहा कि "ग्रेट ब्रिटेन और भारत के सम्बन्धों में इस प्रकार की काफरेन्स पहले कभी देखने में नहीं आयी—क्या यह सहयोग मौन सरकार से नष्ट कर दिया जायगा, जो हमारी टिप्पणियाँ लिख लेगी, पर उन पर कुछ कहेगी नहीं और अन्त में एक ऐसा मनमाना आदेश निकालेगी.....जो इस कमेटी की इच्छाओं के विरुद्ध होगा । इस क्षण भारत में शान्ति और भारतीय जनता में सहयोग और सब कुछ दाँव पर है, और मैं बहुत गम्भीरता से अनुरोध करता हूँ कि हमें सरकार से आश्वासन मिले कि वह अपने अनुमोदन द्वारा, जो इस कमेटी की सर्वसंगत माँग है, दोनों देशों की जनता में शान्ति और सद्भाव का मार्ग खुला रखेगी ।"^४

पिलीनरी सेशन

काफी निराशा और असन्तोष के वातावरण में पूरी काफरेन्स का अधिवेशन २८ नवम्बर सन् १९३१ को प्रारम्भ हुआ । बहुत से प्रतिनिधि इसलिए असन्तुष्ट

१. वही, पृ० ११७९ ।

३. वही, पृ० १२२४ ।

२. वही, पृ० १२२४ ।

४. वही, पृ० १२२९ ।

थे कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। बहुतेको इस बात का शोभ था कि जितना काम हो सकता था नहीं हुआ, और ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी के विचार-विमर्श को सफल बनाने में पर्याप्त योगदान नहीं किया। ब्रिटेन की नेशनल गवर्नमेण्ट के मीन ने तथा तरह-तरह की खबरों ने, एव घोलपुर-पटियाला ग्रुप के राजाओं के दृष्टिकोण ने, और अल्पसंख्यक कमेटी की विफलता ने बैन्यल जैसे थोड़े से प्रतिनिधियों को छोड़कर, जो भारत की राजनीतिक प्रगति में रोड़े अटकाना ही अपना कर्तव्य समझते थे, बाकी सबको परेशान और उदास कर दिया था। फिर भी ब्रिटिश भारत के अधिकांश प्रतिनिधियों की यही कामना थी कि रियासतें किसी तरह भारतीय संघ में सम्मिलित होने को राजी हो जायें, और यदि वे राजी न हों तो भी नये राजनीतिक सुधार प्रान्तों तक सीमित न रहें। कर्नल गिडने, हाफिज हिदायत हुसैन, मिस्टर फजलुल हक, गजनवी आदि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि चाहते थे कि प्रान्तों के साथ ही साथ केन्द्र में भी उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय।

गांधीजी ने इस अवसर पर अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा : “भारत को वास्तविक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। उसे किसी नाम से पुकारा जा सकता है। गुलाब किसी दूसरे नाम से भी उतनी ही मीठी सुगन्ध देगा, पर उसे स्वतन्त्रता का गुलाब होना चाहिए।”^१ उन्होंने कहा : “मैं ग्रेट ब्रिटेन का साथी बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं हूबहू उस स्वतन्त्रता का उपयोग करना चाहता हूँ, जिसका आप उपभोग कर रहे हैं, और मैं इस साझेदारी को केवल भारत के लाभ के लिए नहीं, केवल पारस्परिक लाभ के लिए ही नहीं चाहता, इसलिए भी चाहता हूँ कि वह भारी बोझ जो संसार को कणों में पीस रहा है उसके कंधों से उठ सके।”^२

गांधीजी ने कहा कि कांग्रेस उन संरक्षणों को देने के लिए वचनबद्ध है जिन्हें “भारत के हित में प्रमाणित किया जा सके”। यह संरक्षण अवश्य ही “ग्रेट ब्रिटेन के हित में भी होना चाहिए”, पर प्रस्तावित संरक्षण भारत के हित में नहीं है, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।^३

१. इण्डियन राउंड टेबिल कान्फ्रेस, पिलीनरी सेशन प्रोसीडिंग्स, पृ० २६९।
२. वही, पृ० २६९।
३. वही, पृ० २७९।
४. वही, पृ० २७१।

उन्होंने स्वीकार किया कि जब तक अल्पसंख्यकों की समस्या नहीं सुलझती, तब तक भारत के लिए स्वराज्य नहीं, पर उन्होंने कहा जब तक विदेशी शासन के रूप में पञ्चर सम्प्रदाय को सम्प्रदाय से, वर्ग को वर्ग से अलग करती रहती है, तब तक कोई वास्तविक सजीव समाधान नहीं हो पायेगा, इन सम्प्रदायों में कोई जीवित मित्रता नहीं होगी ।^१

राजाओं को सम्बोधित करते हुए गांधीजी ने कहा कि यदि वे कुछ मौलिक अधिकारों को सारे भारत की सामान्य थाती के रूप में स्वीकार करते और यदि वे इन अधिकारों की न्यायालयों द्वारा जाँच किये जाने की अनुमति देते, और "अपनी प्रजा के लिए प्रतिनिधित्व का एक अश जोड़ते, तो वे अपनी प्रजा को बहुत कुछ सन्तुष्ट कर पाते, तथा सारे संसार और सारे भारत को दिखा पाते कि वे भी लोकतान्त्रिक भावना से उत्साहित हैं, वे विशुद्ध निरंकुश रहना नहीं चाहते, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट् जार्ज की तरह संवैधानिक राजा बनना चाहते हैं ।"^२

मालवीयजी ने बहुत संतप्त हृदय से कहा कि यहाँ भारत की समस्या पूरी तौर पर नहीं समझी गयी है—यहाँ यह वातावरण नहीं है कि जिसमें भारत की जनता की सही दशा और जो भारत माँगता है उसकी सच्चाई की मान्यता हो सके ।^३ उन्होंने कहा कि जनता की आर्थिक दशा आधी भी इतनी अच्छी नहीं जितनी उसे होना चाहिए, और "हम उनको इस दयनीय दशा से उबार नहीं सकते जब तक हमारे हाथ में हमारे मामलों के प्रबन्ध करने का अधिकार न हो ।"^४ भारतीय जनता की स्वतन्त्रता की अभिलाषाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती । उन्हें यह कह कर भी सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता कि सरकार अपनी गतवर्ष की प्रतिज्ञा पर दृढ़ है, या नया संविधान बनाने में दो या तीन वर्ष लगेंगे ।^५ उन्होंने कहा कि आवश्यक बातों पर सहमति की घोषणा तुरन्त होनी चाहिए । उसके बाद शीघ्र ही एक प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा जाय जो तीन मास में भारत की दशा की सही जानकारी प्राप्त करके भारतीय जनता की कामनाओं का मूल्यांकन करे, और उसके बाद शीघ्र नया संविधान तैयार किया जाय । उन्होंने कहा कि उन युक्तियुक्त संरक्षणों की व्यवस्था की जा सकती है जो भारत के हित में हो, पर

१. वही, पृ० २७३ ।

२. वही, पृ० २७५ ।

५. वही, पृ० २८० ।

२. वही, पृ० २७४ ।

४. वही, पृ० २७९ ।

जब तक सेना पर खर्चा घटाकर आघा नहीं किया जाता, और जब तक यह निश्चय नहीं हो जाता कि दूसरी स्वतंत्र सरकारों की तरह हमें भी खर्चों के सारे बजट को पुनरायोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा, हमें यह विचार करने का कि कौन सी बचतें चालू की जायें, वैसा ही अधिकार होगा, जैसा दूसरी स्वतंत्र सरकारों को है", तब तक "उत्तरदायी सरकार या उसकी छाया की बात करने से क्या लाभ है?"^१ उन्होंने कहा "हममें से कोई नहीं चाहता कि जनता सरकार के विरुद्ध विद्रोह करे, हम चाहते हैं कि कानून का आदर किया जाय, पर कानून को भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए, और व्यक्ति को वह देना चाहिए जिसे वह सरकार से दावा करने का अधिकार रखता है।"^२ उन्होंने कहा "भारत की जनता को स्वतंत्रता का अधिकार उतना ही है, जितना आपको।"^३ अन्त में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह अंग्रेजों की अधिकारों को हस्तान्तरित करने की सद्बुद्धि, उदारता और शक्ति प्रदान करे।^४

प्रधानमन्त्री की घोषणा

१ दिसम्बर सन् १९३१ को प्रधान मन्त्री मेकडोनल्ड ने काफरेन्स के पूर्ण सत्र में सरकार की ओर से वक्तव्य देते हुए कहा कि मौजूदा नेशनल गवर्नमेन्ट आश्वासन देती है कि पुरानी गवर्नमेन्ट द्वारा घोषित नीति ही उसकी नीति है। उन्होंने उस नीति-वक्तव्य के कुछ अशों को उद्धृत करते हुए उद्धोषित किया कि सरकार अखिल भारतीय सघ को "भारत की सबैधानिक समस्या का एक आशाजनक समाधान"^५ समझती है और उसको स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। उन्होंने यह भी घोषित किया कि सम्राट् की सरकार साक्रांतिक काल के लिए कुछ रिजर्वेशन और सेफगार्ड के साथ उत्तरदायी सघ सरकार के सिद्धान्त को स्वीकार करती है, और इस बात से सहमत है कि गवर्नरों के प्रान्तों में ऐसा उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय जो अपने क्षेत्र में अपनी नीतियों को कार्यान्वयन करने में बाह्य हस्तक्षेप और आदेशों से अधिक से अधिक सम्भव स्वतंत्रता का उपभोग करें।^६

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सघ को स्थापित करने में काफी समय लगेगा, जबकि प्रान्तों में वास्तविक स्वशासन की व्यवस्था शीघ्र ही आसानी

१ वही, पृ० २७९।

२. वही, पृ० २८२।

३. वही, पृ० २८२।

४. वही, पृ० २८२।

५. वही, पृ० २९०।

६. वही, पृ० २९१।

से की जा सकती है। इसलिए कुछ लोगो का सुझाव है कि प्रान्तीय स्वशासन की दिशा में शीघ्र कदम उठाया जाय, पर चूंकि काफरेन्स चाहती है कि एक ही विधान में केन्द्र और प्रान्त दोनों की व्यवस्था हो, इसलिए सम्राट् की सरकार इस समय प्रान्तों में उत्तरदायित्व के विस्तार की दिशा में जल्दी करना नहीं चाहती, पर इस सम्बन्ध में "कोई अटल निर्णय लेना भी आवश्यक नहीं समझती", क्योंकि "विचार और परिस्थितियां बदल सकती हैं"।^१

प्रधान-मंत्री ने घोषणा की कि कुछ विशेष संरक्षणों के साथ उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त में सन् १९१९ के राजनीतिक सुधार शीघ्र ही चालू कर दिये जायेंगे, और यदि वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक पायी गयी तो सिन्ध को अलग प्रान्त बना दिया जायगा। उन्होंने वायदा किया कि विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए कमेटियाँ नियुक्त की जायेंगी। संघ को स्थापित करने के लिए उसकी समस्याओं को विचार-विमर्श द्वारा हल करने का प्रयत्न किया जायगा। साम्प्रदायिक समस्या की गम्भीरता पर काफरेन्स का ध्यान, आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा "नैसर्गिक अधिकारों की व्यवस्था से ही समस्या का समुचित समाधान संभव नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था करनी होगी जिस पर काफी विचार करना होगा, ताकि वे एक तरफ अपने उद्देश्य के लिए पर्याप्त हों, और दूसरी ओर वे प्रतिनिधि उत्तरदायी शासन के सिद्धान्तों पर इतना अतिक्रमण न करें कि वे निरर्थकता के बराबर हो जायें।"^२

प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि इसमें (१) भारत के लिए डोमीनियन स्तर की स्वतंत्रता और समता की कोई घोषणा नहीं थी, (२) गवर्नर-जनरल के विशेष सुरक्षित अधिकारों, तथा वित्तीय और व्यावसायिक संरक्षणों की सीमाओं की भी सुस्पष्ट व्याख्या नहीं थी, (३) इस बात का भी पूरा आश्वासन नहीं था कि प्रान्तों और केन्द्र, दोनों में उत्तरदायी व्यवस्था साथ-साथ स्थापित की जायेगी, (४) केन्द्र में उत्तरदायी शासन के प्रश्न को अखिल भारतीय संघ की स्थापना के साथ इस तरह जोड़ दिया गया था कि राजाओं की राजामन्दी के बिना केन्द्र में उत्तरदायित्व का शुभारम्भ असंभव हो गया था, (५) जनता के मौलिक अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं था, (६) यह भी स्पष्ट नहीं था कि अनिर्णीत प्रश्नों पर विचार-विमर्श के लिए गोलमेज काफरेन्स का तीसरा सत्र होगा।

चिन्ता

प्रधानमन्त्री की इस घोषणा से कहीं अधिक भारत-मन्त्री सर सेमुअल होर की कड़ी प्रशासनिक नीतिरिति चिन्ताजनक थी। गोलमेज कांफरेन्स के पहले सत्र के बाद सहयोग की प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया था, इस बार गांधीजी के यह आश्वासन देने पर भी कि वे सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करना नहीं चाहते और विचार-विमर्श के लिए समय देने को तैयार हैं, कांफरेन्स के खत्म होते-होते दमन जोरो से प्रारम्भ कर दिया गया। जब इसका समाचार लन्दन में मालवीयजी को मिला, तब वे वहाँ प्रधानमन्त्री तथा ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के कई अन्य सदस्यों, विरोधी दलों के नेताओं, दो भूतपूर्व वाइसरायों से, और कुछ प्रसिद्ध वकीलों से मिले, और उन्होंने उनका ध्यान विशेष रूप से काले कानून के भयकर स्वरूप की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध किया कि उन्हें वापस लिया जाय।

सम्राट् से भेंट

लन्दन में गोलमेज कांफरेन्स के अवसर पर मालवीयजी को सम्राट् पंचम जार्ज से भेंट हुई। पहुँचते ही बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या वे मिस्टर गांधी के अनुयायी हैं। मालवीयजी ने कहा कि नहीं, मैं उनका सहयोगी हूँ। इसके बाद ही बादशाह ने कहा कि 'यदि हिन्दुस्तान में हमारे एक आदमी पर भी वार होगा, तो उसके लिए मैं एक लाख आदमी यहाँ से भेजूंगा।' इसके उत्तर में मालवीयजी ने कहा कि 'आप यह क्या कह रहे हैं? आप हमारा हक स्वीकार करें, और हिन्दुस्तान चलकर दरबार करें, औपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा करें, इससे हमारे देश के सब लोग 'धन्य-धन्य' कहेंगे, और एशिया में आपका कीर्तिमान होने लगेगा। आपके एक आदमी पर वार हो और उसका बदला लेने के लिए एक लाख आदमी यहाँ से भेजे जायें, यह प्रश्न हल करने के लिए हम यहाँ नहीं आये हैं।' इसके बाद भारत-सम्राट् ने बात का सिलसिला बदल दिया, तथा रुखाई और घमकी की भावना छोड़ कर प्रेम और सद्भाव का प्रदर्शन करते हुए बातचीत करने लगे।

समीक्षा

कांफरेन्स में मालवीयजी, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री ए० रंगास्वामी ऐयंगर तथा सेठ घनश्यामदास बिडला ने गान्धीजी का समर्थन किया, जबकि अन्य प्रतिनिधि बहुत हद तक उनके प्रति उपेक्षित रहे। श्री श्रीनिवाम शास्त्री आदि कतिपय प्रतिनिधियों को शिकायत रही कि मालवीयजी ने अपनी बातें

कहकर समस्याओं के समाधान में योगदान करने के बजाय बड़ी निष्ठा के साथ गांधीजी का समर्थन किया।

'लन्दन' जाने से पहले ही मालवीयजी ने राजव्यवस्था, साम्प्रदायिक समस्या तथा मौलिक अधिकारों पर पारित कांग्रेस के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था। कांफरेन्स में उनका समर्थन मालवीयजी का कर्तव्य था। आगा खा-होर-बेन्थल के कुचक्रों से घबड़ा कर राष्ट्रीय मागों को प्रतिपादित करने के बजाय कुचक्रों की गुत्थियों में अपने को फँसा लेना कौन बुद्धिमानी होती? उन्होंने गांधीजी का भरपूर समर्थन जरूर किया। कांफरेन्स में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसके विचारों से मालवीयजी के विचार अधिक मिलते थे? और जहाँ नहीं मिलते थे, वहाँ उन्होंने उसे काफी साहस से व्यक्त किया। मिसाल के तौर पर गांधीजी द्वारा प्रतिपादित एक सदनीय विधान सभा के बजाय उन्होंने द्विसदनीय विधान मंडल का समर्थन किया, गांधीजी के परोक्ष निर्वाचन का विरोध करते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को पुष्ट किया। उन्होंने बहुत ही खुले शब्दों में घोषित किया कि वह डोमीनियन स्टेट्स के पक्ष में है, और ब्रिटिश कामनवेल्थ में स्वतन्त्र और समान प्रभुसत्तासम्पन्न राज्यव्यवस्था को ही पूर्ण स्वराज्य मानते हैं। वित्तीय और सम्पत्ति सम्बन्धी सरक्षणों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव गांधीजी ने किये उनका कुछ संशोधनों के साथ ही मालवीयजी ने समर्थन किया। दोनों ने इन प्रस्तावों के पक्ष में भिन्न-तर्क उपस्थित किये, और जिन तर्कों के आधार पर मालवीयजी ने उनकी पुष्टि की, उन्हीं के आधार पर सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और कतिपय उदार दलीय सदस्यों ने उनका अनुमोदन किया। इसी तरह मालवीयजी ने गांधीजी से कहीं अधिक विस्तार के साथ सघीय व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्तावों का विश्लेषण किया। इस तरह कुछ बातों में उन्होंने गांधीजी के विचारों का समर्थन किया, कुछ प्रस्तावों पर सप्रू साहव के विचारों की पुष्टि की, और कुछ विषयों पर अपने स्वतन्त्र विचार व्यक्त किये।

करीब करीब सभी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ मालवीयजी के विचारों से सहमत नहीं थे। भारत के भूतपूर्व वाइसराय और ब्रिटिश लिबरल पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता लार्ड रीडिंग से तो कई बार उनका विवाद भी हुआ। फिर भी, जैसा कि सर तेजबहादुर सप्रू ने अपने एक संस्मरण में लिखा है, "इस कांफ्रेन्स में कोई भी ऐसा हिन्दुस्तानी नहीं था जिसे मालवीयजी से अधिक मात्रा में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का सम्मान प्राप्त था।"^१

२२. दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन, एकता कांफरेन्स, हरिजनोद्धार

१९३२-३४

लार्ड विलिंगडन

लार्ड अविन के उत्तराधिकारी लार्ड विलिंगडन, जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर रह चुके थे, पुरानी साम्राज्यशाही मनोवृत्ति रखते थे। उन्होने दूसरी गोलमेज कांफरेन्स के जमाने में ही भारतमन्त्री सर सेमुअल होर की अनुमति से दमन आरम्भ कर दिया था। यद्यपि यह दमन देशव्यापी था, पर सीमाप्रान्त, युक्तप्रान्त, और बंगाल में उसका विशेष जोर था।

पत्र-व्यवहार

२८ दिसम्बर सन् १९३१ को गांधीजी लन्दन से बम्बई वापस आये। कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने प्रान्त की गम्भीर स्थिति उन्हें बताया। इसके बाद २९ दिसम्बर को गांधीजी ने वाइसराय को तार दिया, जिसमें उन्होने युक्तप्रान्त, सीमाप्रान्त और बंगाल के अध्यादेशों और गिरफ्तारियों की, तथा सीमाप्रान्त के गोली-कांड की चर्चा करते हुए पूछा कि “क्या इसका मतलब यह है कि हमारे बीच में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध खत्म हो गये हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपसे मिलूँ और कांग्रेस को परामर्श देने में मार्गदर्शन प्राप्त करूँ।”^१ इस तार से यह स्पष्ट था कि कांग्रेस की नीति निश्चित करने से पहले गांधीजी वाइसराय से बात करना चाहते थे।

३१ दिसम्बर को वाइसराय के निजी सचिव ने गांधीजी को सूचित किया कि वाइसराय “आपसे उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने को तैयार नहीं होंगे जिन्हें भारत सरकार ने सम्राट् की सरकार की पूरी सहमति से बंगाल, युक्तप्रान्त और उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त में करना आवश्यक पाया है। ये उपाय हर हालत में चालू रखने होंगे, जब तक कि वे उस उद्देश्य को पूरा

१. पट्टाभि सीतारमैया, हिस्ट्री आफ् दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जि० १, पृ० ५११।

न कर पायें, जिसके लिए वे लागू किये गये थे, अर्थात् अच्छे शासन के लिए आवश्यक कानून और व्यवस्था की संरक्षा”,^१ पर वाइसराय उनसे “भेंट करने को और उन्हें यह बताने को तैयार है कि सहयोग की उस भावना को बनाये रखने के लिए, जो गोलमेज काफरेन्स की कार्यवाहियों को अनुप्राणित करती थी, वे अपना क्या प्रभाव डाल सकते हैं।”^२

यह तार निश्चय ही निराशाजनक था। इसका मतलब तो यही था कि वाइसराय गांधीजी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, उन्हें केवल अपनी बात समझाना चाहते थे।

१ जनवरी को गांधीजी ने वाइसराय के सचिव को एक दूसरा तार दिया जिसमें उन्होंने वाइसराय के उत्तर पर क्षोभ प्रकट करते हुए, तथा उनके तर्कों का उत्तर देते हुए वाइसराय से अनुरोध किया कि कोई शर्त लगाये बगैर मिला जाय, और वे वाइसराय से वायदा करते हैं कि वे उन तथ्यों को जो उनके सामने रखे जायेंगे निष्कपट बुद्धि से विचार करेंगे। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सत्याग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव भेजते हुए लिखा कि यदि वाइसराय उनसे मिलने को तैयार हो तो सविनय अवज्ञा का कार्य स्थगित कर दिया जायगा, इस आशा पर कि अन्त में उस पर अमल करने की आवश्यकता ही नहीं होगी।^३

वाइसराय ने सविनय अवज्ञा की घमकी के साथ वर्किंग कमेटी और गांधीजी की शर्तों पर उनसे मिलने से इनकार कर दिया।

सविनय अवज्ञा

२ जनवरी सन् १९३२ को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में १२ सूत्रीय कार्यक्रम निश्चित किया। उसमें अहिंसा पर विशेष जोर दिया गया। उसमें आदेश दिया गया कि उन्हीं स्थानों पर सविनय अवज्ञा आरम्भ हो, जहाँ जनता संघर्ष के अहिंसात्मक लक्षण को समझती हो, और जान-माल की क्षति वर्दाश्त करने को तैयार हो। घोर उत्तेजना की स्थिति में भी विचार, वचन और कार्य में अहिंसा का पालन किया जाय, क्षति पहुँचाने के इरादे से सरकारी अफसरों, पुलिस और राष्ट्र-विरोधी तत्वों का सामाजिक बहिष्कार न किया जाय, क्योंकि वह अहिंसा की भावना के विरुद्ध है। वही लोग जुलूस और

१. वही, पृ० ५१२।

२. वही, पृ० ५१२।

३. वही, पृ० ५१२-५१४।

दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन, एकता कांफरेन्स, हरिजनोद्धार ४६१

प्रदर्शनो में भाग लें जो अपनी जगह से हटे बगैर लाठी और गोली का प्रहार सहन करने को तैयार हो। पूरी तौर पर अहिंसा का ध्यान रखते हुए शराब तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों का स्त्रियो द्वारा पिकेटींग हो। इस कार्यक्रम द्वारा कांग्रेसजनों को आदेश हुआ कि वे हाथ का कता और हाथ का बुना खदर ही प्रयोग करें। विदेशी कपड़ों का वहिष्कार, बिना लाइसेन्स के नमक का बनाना और जमा करना, ब्रिटिश माल और सस्थाओं का वहिष्कार, एवं अनैतिक कानूनों तथा जनता को हानि पहुँचानेवाले कानूनों और आदेशों का, और अध्यादेशों के अन्दर जारी की गयी न्यायविहीन आज्ञाओं का सविनय उल्लंघन उसके अंग घोषित हुए।^१

४ जनवरी को प्रातःकाल गांधीजी और सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिये गये, और चार नये अध्यादेश जारी कर दिये गये। कुछ दिन के अन्दर ही वे सारे देश पर लागू कर दिये गये, सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये, कांग्रेस और उससे सम्बन्धित संस्थाएँ गैरकानूनी घोषित कर दी गयी, और उनकी चल और अचल सम्पत्तियाँ जब्त कर ली गयी। नये अध्यादेश पुराने अध्यादेशों से भी अधिक कड़े, तीव्र और व्यापक थे, मानव अधिकारों पर कुठाराघात थे। अराजकता से देश की रक्षा करना, सुशासन के ढाँचे को बनाये रखना, इनका उद्देश्य बताया जाता था। पर सुशासन के आधारभूत सिद्धान्तों की अवहेलना, तथा क्रूर अवैधानिक उपायों द्वारा जनान्दोलन का दमन ही अध्यादेशों पर आश्रित शासन का वास्तविक लक्ष्य था। मानव गौरव का अनादर, नागरिक स्वतन्त्रताओं का अपहरण, वैधीकृत आतंक की स्थापना अध्यादेश शासन के प्रमुख ध्येय थे।

कांग्रेस के आदेश के अनुसार सरकार के कानूनों, अध्यादेशों और आदेशों की सविनय अवज्ञा इस जनान्दोलन का मुख्य काम था। सरकार की निषेध-आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए सभाएँ करना, जुलूस निकालना, तथा गांधी दिवस, मोती लाल दिवस, सीमा प्रान्त दिवस, शहीद दिवस और झंडा दिवस मनाना, एवं साहस के साथ पुलिस की लाठियों के प्रहार को सहन करना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों का साधारण काम था। सभी प्रान्तों में ब्रिटिश माल और ब्रिटिश संस्थाओं के वहिष्कार का विशेष रूप से प्रयत्न किया गया, शराब की दुकानों तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों का डटकर धरना दिया गया। नमक का बनाना भी जारी रहा। मध्यप्रदेश, करनाटक, युक्तप्रान्त, मद्रास प्रान्त

तथा बिहार के कतिपय स्थानों में जंगलों का कानून तोड़ा गया। युक्तप्रान्त और बंगाल के कुछ भागों में लगानबन्दी का काम भी हुआ।

मालवीयजी के प्रयास

भारत को वापस आते हुए मालवीयजी रास्ते में पेरिस रुक गये, और वहाँ उन्होंने सिलवा लेवी आदि विद्वानों तथा कतिपय राजनीतिज्ञों से भेंट की, तथा उन्हें एक भोज दिया। जब उन्हें यह समाचार मिला कि वाइसराय गांधीजी से बातचीत करने को तैयार नहीं हैं, तब उन्होंने प्रधानमन्त्री, भारतमन्त्री तथा वाइसराय को तार दिये कि गांधीजी से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय, और आशा व्यक्त की कि समझौते द्वारा कांग्रेस और सरकार के बीच में विवाद-ग्रस्त बातों का निपटारा किया जायगा।

दम्बई आकर तीन चार दिन तक परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद उन्होंने २९ जनवरी सन् १९३२ को एक पत्र में परिस्थिति का विस्तार के साथ विश्लेषण करते हुए वाइसराय से अनुरोध किया कि "दमन नीति का अवलम्बन करके आपने जो भारी भूल की है उसको सुधारें, कानून कानूनों को वापस लें, और महात्मा गांधी को तथा इस नीति के अनुसार जो दूसरे लोग कैद किये गये हैं उन सभी स्त्रियों, पुरुषों तथा बालकों को छोड़ दें, जो जर्मनी वसूल हो चुके हों वे लौटा दिये जायें, तथा देश में फिर कानून का राज्य स्थापित किया जाय। जिन विशेष बातों के विषय में कुछ प्रान्तों में सरकार और जनता में मतभेद है, उन्हें तय करने के लिए महात्माजी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को सरकार आमंत्रित करे, और सब लोग मिलकर उन स्थानों में जा कर सब तरह से सन्तोषजनक स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न करें, और जब आप इस प्रकार शान्त परिस्थिति उत्पन्न कर चुकें, तब महात्मा गांधी और अन्य व्यक्तियों को शासन-सुधार सम्बन्धी बड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए निर्मंत्रित करें, और उन्हें भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाने के प्रयत्न में सहायता करने का अवसर दें, जिससे उसे ग्रेट ब्रिटेन की बराबरी का गौरव प्राप्त हो जाय, और इस प्रकार इंग्लैंड और भारत के बीच ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो जाय जो दोनों के लिए सम्मानजनक और हितकर हो।"

२८ फरवरी सन् १९३२ को उन्होंने लन्दन को एक समुद्री तार भेजने का प्रयत्न किया, जिसमें उन्होंने संक्षेप में भारत की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराने

के निमित्त कुछ ऐसी चुनी हुई घटनाओं का जिक्र किया, जो उस तारीख तक भारत सरकार की उस दमन-नीति के कारण देश के सभी भागों में हो रही थी, जो सत्याग्रह आन्दोलन को दवाने और कांग्रेस को कुचलने के उद्देश्य से जारी थी। पर सरकार ने उस तार को लन्दन नहीं जाने दिया।

स्वदेशी आन्दोलन

इस बीच काशी में मालवीयजी ने अपनी अध्यक्षता में अखिल भारतीय स्वदेशी संघ स्थापित किया। डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय, डाक्टर भगवान दास, पण्डित हृदयनाथ कुंजरू और श्री मुशीर हुसैन किदवाई उपाध्यक्ष, तथा श्री शिवराव, आचार्य जे० बी० कृपालानी और प्रोफेसर मुकुट बिहारीलाल मन्त्री मनोनीत किये गये। इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य स्वदेशी का प्रचार था, पर जनता की राजनीतिक चेतना को दृढ़ करना, तथा उसके उत्साह को बढ़ाये रखना भी उसका परोक्ष लक्ष्य था। अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इसका स्वागत किया। कई प्रान्तों और नगरों में इसकी प्रान्तीय और जिला शाखाएँ स्थापित हुईं, पर बंगाल और उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक काम हुआ। बम्बई में 'स्वदेशी लीग' ने, तथा मद्रास में 'वाई इंडिया लीग' ने भी काफी काम किया।

मालवीयजी के आदेश पर स्वदेशी सघ के तत्त्वावधान में २९ मई सन् १९३२ को अखिल भारतीय स्वदेशी दिवस मनाया गया। देश के विभिन्न नगरों में बहुत उत्साह और उल्लास के साथ जुलूस निकाले गये, और सार्वजनिक सभाएँ की गयीं। इस अवसर पर मालवीयजी ने एक वक्तव्य प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश भारत की जनता के साथ-साथ देशी रियासतों के राजाओं, सरकारों और प्रजा से भी स्वदेशी सघ और स्वदेशी प्रदर्शनी आयोजित करने का अनुरोध किया। उन्होंने लिखा : "स्वदेश का अर्थ है अपना देश और स्वदेशी के मतलब हैं अपने देश के लोग और अपने देश की चीजें। भारत जिस तरह ब्रिटिश भारत की जनता का देश है, उसी तरह देशी रियासतों के लोगो और राजाओं का देश है, और मातृभूमि की भलाई के लिए स्वदेशी आन्दोलन को प्रोत्साहित करना देशी रियासतों के राजाओं और वहाँ की जनता का उतना ही कर्तव्य है जितना ब्रिटिश भारत की जनता का"। इस वक्तव्य में उन्होंने यह भी लिखा, "जनता का आर्थिक सुधार किसान और कारखानेदार दोनों के उद्योग-धंधों की उन्नति पर निर्भर है। स्वदेशी आन्दोलन में संलग्न लोगो को इन

दोहरे कामों को ध्यान में रखना चाहिए, किसानों की भलाई के लिए घरेलू उद्योग-धंधों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए ।”^१

बहुत ही शानदार जुलूस के बाद, जिसमें सब वर्गों और राजनीतिक विचारों के लोगों ने बहुत जोश के साथ भाग लिया, वाराणसी के टाउनहाल में मालवीयजी की अध्यक्षता में विराट सभा हुई। मालवीयजी ने अपने भाषण में कहा कि गोखले ‘स्वदेशी’ को ‘देश के प्रति गाढ प्रेम’ कहते थे, और गांधी उसे ‘कामधेनु’ कहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सकल्प करें कि स्वदेशी चीजें ही काम में लायेंगे और जो चीज हमारे देश में नहीं बनती, उसका प्रयोग यथा सम्भव टाल देंगे। स्वदेशी ही खरीदो, स्वदेशी ही बेचो—इसका खूब प्रचार होना चाहिए ।^२

मालवीयजी के आदेश पर पंडित रामनारायण मिश्र के अध्यक्ष प्रयत्न से वाराणसी में सेंट्रल हिन्दू स्कूल के मैदान में स्वदेशी प्रदर्शनी हुई। इसका उद्घाटन करते हुए मालवीयजी ने देश की आर्थिक और औद्योगिक स्थिति का चित्र खींचते हुए जनता से अनुरोध किया कि वे स्वदेशी के व्रत को धारण कर निष्ठा, लगन और त्याग के साथ राष्ट्र के आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के निमित्त स्वदेशी के पवित्र आन्दोलन में भाग लें।

मालवीयजी के इन क्रियाकलापों का अंग्रेज अफसरों पर क्या प्रभाव हुआ, उसका अनुमान इस बात से किसी हद तक हो सकता है कि जब अगले वर्ष मई सन् १९३३ में इस पुस्तक का लेखक बनारस जिला हरिजन सेवक सघ के मन्त्री की हैसियत से बनारस जिले के अंग्रेज पुलिस सुपरिटेण्डेंट से मिला, तब उन्होंने बहुतसी झुठ-उधर की बातें करते हुए कहा : “मैं नहीं जानता कि मालवीयजी का स्वदेशी कहा खत्म होता है, और उनको राजनीति कब शुरू होती है ।”

कांग्रेस की अध्यक्षता

१४ मार्च सन् १९३२ को कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद की गिरफ्तारी पर उनके आदेश पर श्रीमती सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के संचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। वे २६ मार्च को मालवीयजी से मिलने बनारस आयी। यहाँ उन्होंने मालवीयजी से देश की दशा तथा कांग्रेस के

१. ‘आज’, २९ मई सन् १९३२।

२. ‘आज’, १ जून सन् १९३२।

भावी कार्यक्रम पर कई घंटे बात की। इसके आस-पास ही गोलमेज कांफरेन्स की परामर्श-समिति के अध्यक्ष लार्ड लोथियन ने मालवीयजी को लिखा कि आप कमेटी को अपनी राय दीजिये। मालवीयजी ने इसके उत्तर में लिखा कि जब तक सब आर्डिनेंस (अध्यादेश) वापस नहीं लिये जायेंगे, सब राजनीतिक कैदी छोड़े नहीं जायेंगे, और सरकार अपनी दमननीति बन्द नहीं करेगी, तब तक मैं किसी कमेटी से सहयोग करने की बात सोच भी नहीं सकता।^१

दिल्ली के कार्यकर्ताओं से बात-चीत करने के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने निश्चय किया कि अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में मालवीयजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किया जाय। जब स्थानापन्न अध्याक्षा श्रीमती सरोजनी नायडू ने मालवीयजी को अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार करने को लिखा, तब उन्होंने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए एक छोटा-सा वक्तव्य प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा—“कांग्रेस के प्रायः जन्मकाल से ही उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त रहा है। कई अवसरों पर जबकि कुछ महत्त्व के प्रश्नों पर मेरा मतभेद रहा है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति में कमी नहीं पड़ने पायी। मैं सदा कांग्रेस द्वारा ही देश-सेवा का यत्न करता रहा हूँ। अतः इस अवसर पर कांग्रेस के सिद्धान्त, विचार और कार्य का पथ-प्रदर्शक बनने का आदेश मेरे लिए धर्मदेश है, जिसका पालन करना अवश्य ही मेरा कर्तव्य है”^२

२० अप्रैल को मालवीयजी ने एक लम्बा तार ब्रिटेन को भेजने के लिए तैयार किया। उसमें उन्होंने २० अप्रैल तक की घटनाओं का विश्लेषण करते हुए सरकार के दमन की कड़े शब्दों में निन्दा की। उन्होंने लिखा कि यद्यपि सरकार की घोषणा के मुताबिक अब तक ६६ हजार ६ सौ आदमी गिरफ्तार किये गये हैं, पर वास्तव में उनकी संख्या ८० हजार से कम नहीं है। उन्होंने लिखा कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनमें ५ हजार से अधिक स्त्रियाँ हैं। इन गिरफ्तारियों में से बहुत-से लोगों का सम्बन्ध कांग्रेस के झंडे के फहराने से है। लगभग ४२६ स्थानों पर झंडा फहराने के अभियोग में हजारों नागरिक गिरफ्तार कर लिये गये हैं। ये गिरफ्तारियाँ, उन्होंने लिखा, सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि बहुत से सम्मानित नागरिक बिना किसी न्याय-संगत कारण के गिरफ्तार कर लिये गये और जब छोड़े गये, तब उन्हें आदेश

१. 'आज', अप्रैल सन् १९३२।

२. 'आज', ७ अप्रैल सन् १९३२।

हुआ कि वे नियत समय पर आज्ञानुसार पुलिस थाने में हाजरी दें। इस अपमानजनक आदेश का उल्लंघन करने पर इस आरोप पर उन्हें कड़ी सजाएँ दे दी गयी। जब कैदियों को तीन श्रेणियों में विभाजित करने के नियम बनाये गये थे, उस समय कहा गया था कि राजनीतिक कैदी 'ए' श्रेणी में रहेंगे, पर इस आश्वासन की उपेक्षा की जा रही है, तीन सौ-चार सौ राजनीतिक कैदियों को छोड़ कर बाकी सब 'बी' और 'सी' श्रेणी में रखे गये हैं। कांग्रेस के अवैतनिक कोषाध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज, और श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसे सम्मानित व्यक्ति 'सी' श्रेणी में हैं। महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी भी कुछ समय तक 'सी' श्रेणी में ही रखी गयी थी। जेल में कैदियों के साथ जिलाधिकारियों का व्यवहार अमानुषिक, निन्दनीय और अन्यायपूर्ण है। सरकार के अत्याचार और दमन से समस्या सुलझनेवाली नहीं है।^१

सरकार ने मालवीयजी का यह तार लन्दन नहीं जाने दिया। इस पर उनके सुपुत्र गोविन्दजी ने उनके निजी सचिव की हैसियत से उसे पुस्तकाकार में प्रकाशित कर दिया। भारत के कुछ समाचारपत्रों में भी वह प्रकाशित हो गया।

भारत सरकार ने कांग्रेस की स्वागत समिति को गैर-कानूनी घोषित करते हुए उसके पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीमती सरोजनी नायडू को आदेश हुआ कि वे बम्बई से बाहर न जायें, कांग्रेस के हजारों प्रतिनिधियों को रास्ते में रोक लिया गया, दिल्ली में कार्यकर्ताओं को ढूँढ ढूँढ कर गिरफ्तार किया जाने लगा। इस पर भी अधिवेशन किये जाने का निर्णय बना रहा। २३ अप्रैल को सरकार के आदेश की उपेक्षा करते हुए श्रीमती सरोजनी नायडू बम्बई से दिल्ली खाना हुईं, पर कुछ दूर जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और दूसरे दिन उन्हें एक वर्ष की सजा दे दी गयी। मालवीयजी से भी कहा गया कि वे दिल्ली न जायें, पर उन्होंने इसकी उपेक्षा की, और अपने सुपुत्र गोविन्दजी, तथा डाक्टर मंगल सिंह और श्री रंजीत पण्डित के साथ दिल्ली चल दिये। जमनापुर पर चारों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये।

इन तमाम बातों के बावजूद निश्चित समय पर चांदनी चौक में घटाघर के पास लगभग १५० कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक कार्यकर्ता की अध्यक्षता में, जिसका नाम सेठ रणछोड़दास घोषित किया गया, कांग्रेस का अधिवेशन विधिवत् सम्पन्न करके दस मिनट के अन्दर पूर्ण स्वराज्य, अहिंसा, सविनय अवज्ञा और बाइकाट के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किये। इतने में

पुलिस के बहुत से सिपाही वहां पहुंच गये, और सब कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये, जिन्होंने पुलिस गाड़ी में चलते-चलते प्रस्तावों की छपी प्रतियाँ जनता में वितरित की। इसके बाद नौ बजे से बारह बजे के बीच में बहुत से जत्थों ने चांदनी चौक में आने का प्रयत्न किया। इनमें एक जत्था स्त्रियों का, दूसरा जत्था मौलाना हफीजुल रहमान की अध्यक्षता में मौलवियों का था, और तीसरा जत्था सिक्खों का भी था जिन्होंने बहुत ही शान के साथ शीशगज गुरुद्वारे से चांदनी चौक जाने का प्रयत्न किया। सभी जत्थे बीच में ही रोक कर गिरफ्तार कर लिये गये। इस तरह दोपहर १२ बजे तक ८०० कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये। सायंकाल को फिर कांग्रेसी जत्थों ने आना शुरू किया। पर इस बार पुलिस ने गिरफ्तार करने के बजाय मार-पीट कर जत्थों को तितर-बितर करने का प्रयत्न किया।

भारत-मन्त्री की घोषणा

इसके बाद भारत-मन्त्री सर सेमुएल होर ने पार्लियामेंट में घोषित किया कि सरकार उन भारतीयों से सहयोग करने को तैयार है, जो पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सहयोग करने को राजी हों।

मालवीयजी का वक्तव्य

२ मई को मालवीयजी और उनके साथी छोड़ दिये गये। ३ मई को मालवीयजी ने प्रयाग से एक लम्बा वक्तव्य प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली का अधिवेशन साबित करता है कि कांग्रेस ने लोगों के दिलों में कितनी गहरी जड़ जमा ली है, और इस बड़ी संस्था की ओर से जो आन्दोलन हो रहा है, उसे दवाने का प्रयत्न करना ब्रिटिश सरकार जैसी शक्तिशाली सरकार के लिए भी कितना व्यर्थ है।^१ भारतमन्त्री के वक्तव्य की समालोचना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत-मन्त्री और प्रधान-मन्त्री ने पार्लियामेंट में जिन "संरक्षणों पर जोर दिया है" उन्हें गांधीजी और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी "भारत के लिए सन्तोषजनक नहीं समझते", और उन्हें "चुपचाप मान लेना कांग्रेस के लिए सम्भव नहीं है।"^२ कांग्रेस तो भारत के लिए इंग्लैंड तथा स्वाधीन देशों के समान ही स्वाधीनता चाहता है। "भारत और इंग्लैंड के बीच मित्रता की यही शर्त है", और यही दोनों के लिए सम्मानयुक्त है।^३ इस

१. 'आज', ४ मई सन् १९३२।

२. वही।

३. वही।

वक्तव्य में उन्होंने यह भी लिखा कि भारत-मन्त्री को भारतीयों के स्वभाव के सम्बन्ध में भ्रम है कि उस समय जब कि "भारत के अस्सी हजार पुत्र और पुत्रिया जेल में बन्द हैं ... कोई स्वाभिमानी भारतीय भारत में नयी योजना को कार्यान्वित करने को सरकार से समझौता करने का कोई प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है।"

साम्प्रदायिक निर्णय और गांधीजी का अनशन

१७ अगस्त १९३२ को प्रधान-मन्त्री मेकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक समस्या पर अपना निर्णय प्रकाशित किया। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यह निर्णय नि सन्देह हानिकर था। पृथक् निर्वाचन द्वारा पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन का विस्तार ही इसका लक्ष्य था। पृथक् निर्वाचन पद्धति द्वारा अस्पृश्यों के लिए भी पृथक् प्रतिनिधित्व की व्यवस्था उसका एक विशिष्ट लक्षण था। गांधीजी को इस कारण उस पर विशेष रूप से आपत्ति थी। उन्होंने १३ नवम्बर सन् १९३१ में ही गोलमेज कांफरेन्स की अल्पसंख्यक कमिटी में कह दिया था कि वे अपनी जान पर खेल कर हिन्दू समाज से हरिजनो (अस्पृश्यों) को पृथक् करने का विरोध करेंगे।

११ मार्च १९३२ को उन्होंने जेल से ही भारत-मन्त्री सर सेमुअल होर को चेतावनी दे दी थी कि यदि पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जायेगी, तो वे उसके विरोध में आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने लिखा कि उनकी राय में पृथक् निर्वाचन अस्पृश्यों और हिन्दुत्व, दोनों के लिए घातक हैं। वह हिन्दू समाज को 'विघटित' कर देगा और अस्पृश्यों को 'हानिकर' होगा। उन्होंने लिखा कि उनके लिए यह प्रश्न राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक और धार्मिक है।"

१८ अगस्त सन् १९३२ को गांधीजी ने प्रधान-मन्त्री मेकडोनल्ड को सूचित किया कि वे २० सितम्बर को दोपहर से किसी प्रकार का भोजन लिये बिना आमरण अनशन करेंगे, पर वह बन्द कर दिया जायगा, यदि ब्रिटिश सरकार अपनी इच्छा से या जनमत के दबाव पर, अपने निर्णय को बदल देगी, और अस्पृश्य वर्गों के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन की योजना वापस ले लेगी, जिनके

१ वही।

२ पट्टाभि सीतारमैया हिस्ट्री आफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जि० १, पृ० ५३९-५४१।

प्रतिनिधि सार्विक निर्वाचन क्षेत्रों से सामान्य सामूहिक मताधिकार के अन्दर, फिर वह चाहे कितने ही क्यों न हों, चुने जाने चाहिए ।^१

८ सितम्बर सन १९३२ को प्रधान मंत्री ने गांधीजी को लिखा कि सरकार की योजना में दलित वर्ग हिन्दू समाज के अंग बने रहेंगे, और हिन्दू निर्वाचकों के साथ बराबर स्तर पर मतदान करेंगे, लेकिन पहले बीस वर्ष के लिए निर्वाचकों के रूप में हिन्दू समाज का अंग रहते हुए वे विशेष निर्वाचन क्षेत्रों की सीमित संख्या द्वारा अपने अधिकारों और हितों की सुरक्षा के साधन प्राप्त करेंगे, जिसकी आज की परिस्थिति में आवश्यकता है ।^२ उन्होंने लिखा कि इस योजना में दलित वर्ग के मतदाता सामान्य हिन्दू निर्वाचकों की सूची में होंगे, और चुनावों में ऊँची जाति के प्रत्याशियों को उनके वोटों की याचना करनी होगी, और उन्हें ऊँची जाति के मतदाताओं की, इस तरह हर प्रकार से हिन्दू समाज की एकता बनायी रखी गयी है ।^३ प्रधान मंत्री ने गांधीजी को सूचित किया कि दलित वर्गों के लिए थोड़े से ही स्थान सुरक्षित किये गये हैं, और सरकार का यह निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से ही बदला जा सकता है ।

इसके उत्तर में गांधीजी ने प्रधान-मंत्री को सूचित किया कि उनकी राय में दलित वर्गों को दो वोट मिल जाने से ही वे या हिन्दू समाज विघटन से नहीं बच पाते । दलित वर्गों के लिए पृथक् चुनाव क्षेत्र की स्थापना में मुझे विष के इंजेक्शन का बोध होता है, जो हिन्दुत्व को नष्ट करने के लिए अभिकल्पित है, और जो दलित वर्गों का कोई हित करने वाला नहीं है ।^४ उन्होंने यह भी सूचित किया कि उनका निर्णय भी अपनी जगह पर अटल है ।

ये सब पत्र १२ सितम्बर को प्रकाशित कर दिये गये । आमरण अनशन की सूचना ने सारे देश में तहलका मचा दिया । बहुत से सज्जनों ने गांधीजी से आमरण अनशन न करने का अनुरोध किया, पर वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे । सप्रू साहब ने माग की कि गांधीजी रिहा कर दिये जायें, पर जिन शर्तों पर सरकार उन्हें छोड़ने को तैयार थी वे उन्हें मजूर नहीं थी ।

२० सितम्बर को गांधीजी का अनशन आरम्भ हुआ । दलित वर्गों के नेता श्री एम०सी० राजा ने पृथक् निर्वाचन व्यवस्था की निन्दा में एक वक्तव्य प्रसारित

१. वही, पृ० ५४२-५४३ ।

२. वही, पृ० ५४५ ।

३. वही, पृ० ५४५ ।

४. वही, पृ० ५४६ ।

किया। मालवीयजी ने हिन्दू नेताओं की काफरेन्स आमन्त्रित की। पहले दिल्ली और बम्बई में, अन्त में पूना में हिन्दू नेताओं ने वातचीत की, और २५ सितम्बर को गांधीजी की अनुमति से, तथा श्री एम० सी० राजा और डाक्टर अम्बेदकर की सहमति से एक समझौता निश्चित किया गया, जो 'पूना पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

पूना पैक्ट

इस पैक्ट द्वारा केन्द्रीय असेम्बली में हरिजनो के लिए साविक (जनरल) स्थानों के १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये गये। इसी तरह प्रान्तीय विधान कौंसिलो के लिए भी साविक स्थानों में हरिजनो की संख्या निश्चित कर दी गयी, जो साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा निश्चित संख्या तथा हरिजनो की जनसंख्या के अनुपात से अधिक थी। चुनाव के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि प्रत्येक हरिजन स्थान के लिए हरिजन मतदाता चार हरिजन प्रत्याशी चुनेंगे, और इनमें से एक साधारण चुनाव द्वारा साविक क्षेत्रों में सब मतदाता मिलकर चुनेंगे। यह प्रथा दस वर्ष तक चालू रहेगी, पर पारस्परिक समझौते से हरिजनो द्वारा प्रत्याशियों का चुनाव इसके पहले भी खत्म हो सकता है।^१

यह पैक्ट हरिजन और सर्वर्ण हिन्दू नेताओं के हस्ताक्षर से २५ सितम्बर को निश्चित हुआ, और २६ सितम्बर को सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया, और उसी दिन सायंकाल ५-६ बजे गांधीजी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस प्रयास की सफलता में मालवीयजी का महत्त्वपूर्ण योगदान था। पर उनके साथ ही साथ सर्वश्री अमृतलाल ठक्कर, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राजेन्द्रप्रसाद, एम० आर० जयकर, हृदयनाथ कुंजरू, चुन्नीलाल मेहता, घनश्याम दास बिडला, एम० सी० राजा, बी० आर० अम्बेदकर तथा श्रीमती सरोजनी नायडू का भी भरपूर योगदान था।

बम्बई में विराट सभा

जन्मजात अस्पृश्यता के निवारण के लिए सर्वर्ण हिन्दुओं द्वारा सतत प्रयत्न इस समझौते का आवश्यक अंग था। इसका शुभारम्भ २५ सितम्बर को बम्बई में मालवीयजी की अध्यक्षता में आयोजित विराट सभा में किया गया। बम्बई के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के भी बहुत से सम्मानित हिन्दू नेताओं की उपस्थिति ने सभा को काफरेन्स का रूप प्रदान कर दिया। काफरेन्स ने निश्चय किया कि

अब से हिन्दुओं में अपने जन्म के कारण कोई अछूत नहीं समझा जायगा, और जो अब तक ऐसे माने गये हैं उन्हें दूसरे हिन्दुओं के समान ही सार्वजनिक कृषि, सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक विद्यालयों तथा दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं को प्रयोग करने का अधिकार होगा। इस अधिकार को पहले अवसर पर ही कानूनी मान्यता दे दी जायेगी, और यह स्वराज्य संसद के पहले अधिनियमों में से होगा, यदि उसे स्वराज्य से पहले ही ऐसी मान्यता प्राप्त नहीं हो गयी है। काफरेन्स में यह भी निश्चय हुआ कि न्यायसंगत और शान्तिमय उपायों द्वारा मन्दिरों में प्रवेश के सम्बन्ध में लगी रुकावटों के साथ उन सब सामाजिक असमर्थताओं को, जो इस समय तथाकथित अछूतों पर लागू हैं, दूर कराना भी सब हिन्दू नेताओं का कर्तव्य होगा।^१

इस काफरेन्स ने अस्पृश्यता-निवारण संस्थान (एन्टी अनटचेबिलिटी लीग) स्थापित करने का भी निर्णय किया। सेठ घनश्यामदास बिडला अध्यक्ष, और श्री अमृतलाल ठक्कर प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। बिडला साहब की देख-रेख में ठक्कर साहब की तत्परता और कार्यकौशल से संस्थान ने तेजी से प्रगति की। सारे देश में इसकी शाखाएँ स्थापित हो गयी, और उसके तत्त्वावधान में अस्पृश्यता-विरोधी प्रचार के साथ-साथ बहुत-सा हरिजन हितकारी रचनात्मक कार्य हुआ। आगे चल कर यह संस्था 'हरिजन सेवक सघ' के नाम से विख्यात हुई। इसे प्रगतिशील हिन्दू जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था।

आमरण अनशन के बाद जेल की पाबन्दियाँ फिर से गांधीजी पर लगा दी गयी। पर गांधीजी के आग्रह पर अस्पृश्यता-निवारण से सम्बन्धित उनके कार्यों पर से सरकार ने रुकावटें हटा ली।

एकता कांफरेन्स

बम्बई में ही मौलाना आजाद और सैयद महमूद मालवीयजी से मिले और उनसे हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर बातचीत की। उसके बाद डाक्टर सैयद महमूद मौलाना शौकत अली से मिले। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मौलाना आजाद, मौलाना शौकत अली और डाक्टर सैयद महमूद ने बम्बई काँग्रेस के मुसलमान सदस्यों को सूचित किया कि मुस्लिम हितों के संरक्षणों के साथ संयुक्त निर्वाचन के आधार पर हिन्दू-मुस्लिम समझौता करने को मौलाना शौकत अली तैयार हो गये हैं, तथा मौलाना आजाद और डाक्टर सैयद महमूद मुसलमानों की मांगों

को मनवाने के लिए हिन्दुओं पर दबाव डालेंगे। इसके बाद कतिपय मुस्लिम नेताओं ने एक काफरेन्स में जमा होकर एकता काफरेन्स के विचार का स्वागत किया, और मुस्लिम मागों के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव मंजूर किया। एक वक्तव्य द्वारा मुस्लिम काफरेन्स के अध्यक्ष डाक्टर इकवाल ने इस प्रस्ताव को पसन्द किया।

इसके बाद मालवीयजी के नेतृत्व में इलाहाबाद में एकता काफरेन्स आयोजित हुई। उनके अनुरोध पर श्री सी० विजयराघवाचार्य ने दो चार दिन सम्मेलन की अध्यक्षता की। पर मालवीयजी को ही उसके संचालन का भार मुख्यतः वहन करना पड़ा। इकहत्तर वर्ष की आयु में उन्हें अकसर दिन में बारह-चौदह घंटे काम करना पड़ता था। अन्त में २४ दिसम्बर सन् १९३२ को एकता सम्मेलन कमेटी ने सर्वसम्मति से एक समझौता किया।

इस समझौते में कहा गया कि इस सम्मेलन की राय में जनता को पूर्ण उत्तरदायी तथा सरकार के पूर्ण अधिकारों से सम्पन्न केन्द्रीय सरकार ही भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, और जनहित को सुरक्षित रख सकती है। सम्मेलन ने माग की कि रक्षा, वैदेशिक नीति, वित्तीय अधिकारों के साथ केन्द्रीय शासन, उन संरक्षणों के साथ जो भारतीय हितों के लिए प्रामाण्य रूप से आवश्यक हो, भारतीय जनता को हस्तान्तरित कर दिये जायें। उसने यह भी निश्चय किया कि प्रान्तीय सरकारें स्वाधीन हो, और प्रान्तीय विधान सभाओं को पूरे तौर पर उत्तरदायी हो। यह भी निश्चय हुआ कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के अधिकारों की विस्तृत सूचिया तैयार की जायें, तथा अवशिष्ट अधिकारों का प्रयोग प्रासांगिकता तथा अनुसूचित विषयों से घनिष्ठता के आधार पर केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों द्वारा किया जाये। यह भी निश्चित किया गया कि न्याय की दृष्टि में सब नागरिक समान होंगे। सबको सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग का समान अधिकार होगा, और उन सबकी स्वतन्त्रता और जीवन की राज्य द्वारा रक्षा की जायेगी। इन सब मामलों में धर्म, सम्प्रदाय, जाति, प्रजाति, और लिंग के आधार पर नागरिकों में कोई भेद नहीं किया जायेगा। कानूनी या प्रशासनिक व्यवस्थाओं द्वारा अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के नागरिकों के सम्बन्ध में न कोई भेदमूलक व्यवहार स्थापित किया जायेगा, और न किसी भेदमूलक ढंग पर उनकी व्याख्या की जायेगी, या उनका प्रयोग किया जायेगा। साधारण सार्वजनिक व्यवस्था और शिष्टता के अधीन प्रत्येक नागरिक को विश्वास की स्वतन्त्रता, तथा अपने धर्म की

स्वतंत्र अभिव्यक्ति और व्यवहार की गारंटी होगी। प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को अपने खर्चे पर परोपकारी, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक संस्था स्थापित करने का, तथा संचालन और प्रवन्ध करने का, और उनमें अपनी भाषा और लिपि प्रयोग करने का, एवं अपने धर्म के अनुसरण करने का समान अधिकार होगा। निजी ससर्ग, व्यापार और धर्म, एवं प्रेस, प्रकाशन और सार्वजनिक सभाओं और भाषा और लिपि के प्रयोग के स्वतंत्र प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा। प्रत्येक नागरिक को अधिनियम के अनुसार हथियार रखने का अधिकार होगा। सिक्खों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता होगी। सधारण लिपि के रूप में हिन्दी और उर्दू अक्षरों के प्रयोग के अधिकार के साथ हिन्दुस्तानी केन्द्रीय सरकार की भाषा होगी। अंग्रेजी के उपयोग की इजाजत होगी। प्रान्तों में प्रान्तीय भाषा सरकारी भाषा होगी, पर हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी के उपयोग की इजाजत होगी। मौलिक अधिकारों का प्रारूप बनाने के लिए जो कमेटी नियुक्त की जायगी वह इन बातों को, तथा नेहरू रिपोर्ट की बुनियादी अधिकार सम्बन्धी सस्तुतियों को, एवं कराची में स्वीकृत कांग्रेस के प्रस्तावों को ध्यान में रखेगी।

यह भी निश्चय किया गया कि प्रत्येक सम्प्रदाय के धर्म, संस्कृति और परसनल ला की पूरे तौर पर रक्षा की जायगी, और उसके लिए (१) बुनियादी अधिकारों से सम्बन्धित परिच्छेद में प्रत्येक सम्प्रदाय को संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा तथा धर्म की स्वीकारोक्ति और व्यवहार की एवं धर्मादा कोष के अधिकार की गारंटी दी जायेगी, (२) सविधान की विशिष्ट व्यवस्था द्वारा परसनल ला सुरक्षित किया जायगा, (३) विभिन्न प्रान्तों में अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत होगा, (४) सम्बन्धित सम्प्रदाय के जनमत के समर्थन पर ही किसी सम्प्रदाय के परसनल ला में तब्दीली हो सकेगी, (५) मुसलमानों के परसनल ला में इस्लाम के सिद्धान्तों के आधार पर ही कोई तब्दीली की जा सकेगी। यह भी निश्चय हुआ कि यदि किसी सम्प्रदाय के दो-तिहाई विधायकों की राय में विधान सभा द्वारा पारित कोई बिल उनके धर्म को या धर्म पर आधारित किसी सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है, या यदि एक तिहाई विधायकों की राय में कोई बिल बुनियादी अधिकारों को प्रभावित करता है, तो ये विधायक उस बिल के पारित होने के एक मास के अन्दर अपनी आपत्ति विधान-सभा के अध्यक्ष को भेज सकते हैं, और वह उसे गवर्नर या गवर्नर-जनरल के

पास भेज देगा, जो उस विल के प्रचलन को एक माल के लिए रोक देगा और उसके बाद उसे विधान-सभा के पास फिर से विचार करने के लिए भेज दिया जायगा। उसके बाद गवर्नर या गवर्नर-जनरल स्वनिर्णय द्वारा उसे स्वीकार या रद्द कर सकता है, और उसकी वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में विचार किया जा सकता है।

इस सम्मेलन में यह भी निश्चय हुआ कि सेना प्रान्तीयता से निर्मुक्त होगी, और सभी जाति और सम्प्रदाय के लोग योग्यता के आधार पर उनमें भरती हो सकेंगे। भरती करते समय परिवार की गैरिक परम्परा का ध्यान रखा जायगा, पर इस परम्परा के अभाव के कारण किसी भारतीय नागरिक को सेना में भरती करने से रोका नहीं जा सकेगा।

यह भी निश्चय हुआ कि केन्द्रीय और प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल विधान-सभाओं को संयुक्त रूप में उत्तरदायी होंगे, और उनमें मनीषानिक परम्परा (कनवेन्शन) द्वारा प्रमुख अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के सदस्य भी शामिल किये जायेंगे, जिन्हें संबंधित सम्प्रदाय के वांछी विधायकों का समर्थन प्राप्त हो। यह भी निश्चय हुआ कि सम्प्रदाय, जाति, धर्म, प्रजाति या लिंग के आधार पर कोई भारतीय नागरिक न तो सरकारी नौकरी से वंचित किया जायगा, और न उसकी पदोन्नति या प्रतिस्थापन किया जा सकेगा। सब नियुक्तियाँ निर्दलीय केन्द्रीय और प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमिशन (लोक सेवा आयोग) द्वारा होगी, जिसमें सभी प्रमुख सम्प्रदायों के सदस्य होंगे। एक कमेटी नियुक्त की जायेगी जो सरकारी नौकरियों में क्षमता बनाये रखते हुए योग्यताओं को निर्धारित करेगी, जिससे उनमें विभिन्न सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व हो सके।

यह भी निश्चय हुआ कि सब विधान-सभाओं के चुनाव संयुक्त निर्वाचन पद्धति द्वारा होंगे, पर दस वर्ष तक मुसलमानों के लिए केन्द्र में, बंगाल और पंजाब में, तथा उन प्रान्तों में जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं, कतिपय स्थान सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह पंजाब और केन्द्र में सिखों के लिए, तथा पंजाब, बंगाल और सिन्ध में हिन्दुओं के लिए संयुक्त निर्वाचन पद्धति के अन्तर्गत निश्चित अनुपात से स्थान सुरक्षित रहेंगे, और इसी प्रकार का प्रबन्ध हिन्दुओं के लिए उत्तर पश्चिम सीमा-प्रान्त में भी किया जायगा। यह निश्चय किया गया कि केन्द्रीय विधान-सभा में मुसलमानों के लिए ३२ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे, १ स्थान एंग्लो-इंडियन के लिए सुरक्षित होगा, और बाकी स्थान आम चुनाव क्षेत्र होंगे। बंगाल में मुसलमानों के लिए ५१ प्रतिशत, और हिन्दुओं के लिए ४४ प्रतिशत

स्थान होंगे। इस अनुपात में विशेष निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। पंजाब में मुसलमानों के लिए ५१ प्रतिशत, हिन्दुओं के लिए २७ प्रतिशत, सिक्खों के लिए २० प्रतिशत, और भारतीय ईसाइयों के लिए ३ स्थान और एंग्लो इण्डियन के लिए एक स्थान सुरक्षित रहेगा। सिन्ध में हिन्दुओं के लिए ३७ प्रतिशत स्थान सुरक्षित होंगे। जिन प्रान्तों में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उन प्रान्तों में सन् १९१६ के कांग्रेस-लीग समझौते के अनुसार गुस्त्व के साथ उनके लिए स्थान सुरक्षित होंगे। इस दस वर्ष की अवधि में जबकि संयुक्त निर्वाचन पद्धति के अन्तर्गत कतिपय साम्प्रदायिक समूहों के लिए विधान-सभाओं में स्थान सुरक्षित होंगे, मौलाना मुहम्मद अली का फार्मूला (नुसखा) चुनाव के परिणामों की घोषणा में प्रयोग किया जायगा, अर्थात् उन उम्मीदवारों में से जिन्हें सम्बन्धित सम्प्रदाय के कम से कम तीस प्रतिशत वोट मिले हैं वह चुना जायगा जिसे सबसे अधिक वोट संयुक्त निर्वाचन में प्राप्त है। यदि किसी भी उम्मीदवार को अपने सम्प्रदाय के तीस प्रतिशत वोट भी प्राप्त नहीं है, तो उनमें से उन दोनों में से जिन्हें अपने सम्प्रदाय के सबसे अधिक वोट मिले हैं, वह चुना जायगा जिसे सब निर्वाचकों के सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए हैं।

कुछ शर्तों के साथ सिन्ध को भी एक अलग प्रान्त बनाना निश्चित हुआ, पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि सिन्ध का पृथक्करण देश के साम्प्रदायिक समझौते का अविच्छिन्न अंग है, और यदि किसी कारण से पूरा समझौता लागू नहीं होता तो यह पृथक्करण भी लागू नहीं होगा।

यह भी निश्चय हुआ कि उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त में उसी तरह की सरकार और शासन-व्यवस्था संस्थापित की जाय जैसी अन्य प्रान्तों में है, और प्रशासन की साधारण सवैधानिक पद्धति बलूचिस्तान में भी लागू की जाय।

अन्त में यह निश्चय हुआ कि इस समझौते के विभिन्न अंग परस्पर संबंधित हैं, और पूरा समझौता एक अविभाज्य इकाई समझा जायगा और लागू किया जायगा।

मुसलमानों की इस राय पर विचार करने के लिए कि उनके विवाह और तलाक के मामलों का निर्णय करने को काजी नियुक्त किये जायें, एक कमेटी नियुक्त की गयी।^१

मालवीयजी का वक्तव्य

एकता कांफरेन्स के बाद मालवीयजी ने एक काफी लम्बा वक्तव्य प्रसारित किया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आंकने पर इस समझौते में कई दोष दिखाई देंगे, पर इसका कारण तो वह परिस्थिति है जिसमें उसे तैयार करना पड़ा है। फिर भी राष्ट्रीय एकता के बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि यह एक श्रेष्ठ प्रासाद है जो जनता की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और आत्मनिर्णय की आशाओं और आकांक्षाओं को, एवं उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान को प्रतिष्ठापित करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समझौते ने एकता और सद्भाव की जिन शक्तियों को पैदा किया है वे सब पार्टियों को जनहित की वृद्धि की दिशा में प्रेरित करेंगी। इस समझौते के जरिये यूरोपियनों की मदद से हिन्दुओं और मुसलमानों के दरमियान एकता आसानी से प्रतिष्ठित हो सकती है। अगर बंगाल में जो अत्यधिक प्रतिनिधित्व यूरोपियनों को दिया गया है उसका एक भाग वे छोड़ने को तैयार हो जायें, तो समस्या आसानी से हल हो जाती है और उन्हें भी हिन्दुओं और मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त होगी, जिससे वे काँग्रेस में "अधिक नैतिक प्रभाव" डाल सकेंगे। मालवीयजी ने इस वक्तव्य में यह भी कहा कि यदि यूरोपियन राजी न हों, तो भी हिन्दू और मुसलमान आपस में मिलकर दूसरे अल्पसंख्यकों के सहयोग से ऐसा समझौता कर सकते हैं, जिसे प्रधान-मन्त्री को मानना पड़ेगा।

गतिरोध

उसके बाद बंगाल की समस्या सुलझाने के लिए मालवीयजी, मौलाना आजाद, राजेन्द्र प्रसादजी आदि कतिपय नेता यूरोपियनों तथा हिन्दुओं और मुसलमानों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए कलकत्ता गये। यूरोपियनों ने बात करने से इनकार कर दिया। हिन्दू नेताओं से मालवीयजी और राजेन्द्र प्रसादजी ने कई दिन बातचीत की। अन्त में बंगाल के हिन्दू नेताओं ने यह सुझाव पेश किया कि हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर यूरोपियनों के अत्यधिक प्रतिनिधित्व का विरोध करें, पर बंगाल के मुसलमानों के प्रमुख नेता फजजुल हक साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए।^१

मुसलमानों का विरोध

वास्तव में सर फजले हुसेन इस एकता-सम्मेलन को पसन्द नहीं करते थे। उनके इशारे पर सम्मेलन के जमाने में ही २० नवम्बर सन् १९३२ को आल इंडिया मुस्लिम काफरेन्स की वर्किंग कमेटी, आल इंडिया मुस्लिम लीग की कौंसिल, और जमयैत-उल-उलमाए हिन्द (कानपुर) की वर्किंग कमेटी की संयुक्त काफरेन्स ने निश्चय किया कि उनकी राय में समझौते का प्रस्तावित आधार मुसलमानों के हितों के लिए हानिकर तथा अव्यावहारिक और अग्राह्य है। १० दिसम्बर सन् १९३२ को राजा साहब सलीमपुर द्वारा आयोजित सर्वदलीय मुस्लिम काफरेन्स ने भी २० नवम्बर के निर्णय की पुष्टि की। इन दोनों कांफरेन्सों ने मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय को मुस्लिम दृष्टिकोण से किसी हद तक दोषपूर्ण बताते हुए भी उसे स्वीकार करना उत्तरदायी स्वशासन की प्रगति के लिए आवश्यक समझा। इस तरह मुसलमानों के एक बड़े समूह का झुकाव एकता-सम्मेलन के निर्णयों से अधिक साम्प्रदायिक निर्णय की ओर था।^२

भारत-मन्त्री की घोषणा

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में भारत-मन्त्री सर सेमुएल होर ने घोषित किया कि केन्द्रीय असेम्बली में पृथक् निर्वाचन द्वारा मुसलमानों के लिए एक तिहाई स्थान सुरक्षित किये जायेंगे। इस घोषणा का मुसलमानों में व्यापक रूप से स्वागत हुआ और एकता-सम्मेलन के सब निर्णय खटाई में पड़ गये।

सुभाषचन्द्र बोस की राय में यद्यपि काफरेन्स किसी सफल निर्णय पर नहीं पहुँच पायी, फिर भी उसका नैतिक महत्त्व था, उसने वातावरण को साफ करने में बड़ा काम किया।^३

मुस्लिम यूनिटी बोर्ड

इसके बाद चौधरी खलीकुज्जमा साहब ने जिन्होंने एकता-सम्मेलन के काम में बड़ी दिलचस्पी ली थी, मुस्लिम लीग के नेता राजा साहब सलीमपुर की अव्यक्तता में मुस्लिम यूनिटी बोर्ड गठित किया, जिसने निश्चय किया कि पार्टियों

१. इण्डियन काटरली रजिस्टर, सन् १९३२, जि० २,

२. वही।

३. सुभाषचन्द्र बोस . इण्डियन स्ट्रगिल, पृ० २५१।

का सर्वसम्मत समझौता ही साम्प्रदायिक निर्णय का विकल्प है।^१ बोर्ड के अध्यक्ष राजा साहब सलीमपुर तो पृथक् निर्वाचन पर आश्रित मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय को मौलाना मुहम्मद अली के फार्मुले पर आश्रित संयुक्त निर्वाचन पद्धति से अच्छा समझते थे, और वे एकता-सम्मेलन के निर्णयों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। बोर्ड के सेक्रेटरी चौधरी खलीकुज्जमा साहब का एकता-सम्मेलन के निर्णयों में भरपूर योगदान था, और वे मुहम्मद अली फार्मुला के समर्थक थे। पर वे भी आगे चल कर पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन को ठीक समझने लगे थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है—“सर सैयद अहमद खाँ के सुयोग्य उत्तराधिकारी नवाब मोहसन-उल-मुल्क ने मुसलमानों के लिए जो अद्वितीय मूल्यवान् अधिकार प्राप्त किया, वह पृथक् निर्वाचन था, जिसके विरुद्ध हमने व्यूह की रचना ही नहीं की, बल्कि उनकी निन्दा की जिन्होंने उसका समर्थन किया।”^२

कलकत्ता अधिवेशन

कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष अणे साहब ने अप्रैल सन् १९३३ के पहले सप्ताह में कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन करने का निर्णय कर मालवीयजी से उसकी अध्यक्षता करने का अनुरोध किया। मालवीयजी उसके लिए तैयार हो गये, पर जब वे नियत समय पर कलकत्ता के लिए रवाना हुए, तब आसन्सोल स्टेशन पर वे और उनके साथ श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू और डाक्टर सैयद महमूद भी गिरफ्तार कर लिये गये। इसी तरह अणे साहब और लगभग एक हजार प्रतिनिधि भी रास्ते में ही रोक लिये गये। स्वागत समिति के अधिकारी और सदस्य भी पकड़ लिये गये। जो प्रतिनिधि कलकत्ता पहुँच पाये उनमें से भी अधिकांश अधिवेशन से पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये।

फिर भी पूर्वघोषित समय पर और पूर्वघोषित स्थान पर कई सौ प्रतिनिधि इकट्ठे हो गये। श्रीमती सेन गुप्ता की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। पुलिस ने उपस्थित प्रतिनिधियों को बुरी तरह आहत किया। फिर भी प्रतिनिधियों ने बहुत धैर्य के साथ विषय-निर्धारिणी समिति द्वारा निश्चित सात प्रस्ताव स्वीकार किये। अधिवेशन ने इन प्रस्तावों द्वारा लाहौर कांग्रेस के ‘पूर्ण स्वराज्य’ सम्बन्धी प्रस्ताव की, तथा कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के ‘सविनय अवज्ञा’ सम्बन्धी प्रस्ताव की फिर से पुष्टि की, विदेशी कपड़े और ब्रिटिश माल के

१. खलीकुज्जमा : पाथ वे टु पाकिस्तान, पृ१२०।

२. चौधरी खलीकुज्जमा वही, पृ० ९१।

दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन, एकता कांफरेन्स, हरिजनोद्धार ५०६

बाइकाट की, तथा खट्टर को अपनाने की जनता से अपील की, एवं घोषित किया कि भारत की जनता ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये हुए संविधान को और श्वेतपत्र की योजना को स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस ने देश को गांधीजी के अनशन की सफलता पर बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही छुआछूत दूर हो जायगी। उसने कराची कांग्रेस के बुनियादी अधिकारों के प्रस्ताव को भी फिर से पुष्ट किया।

मालवीयजी का अभिभाषण

कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए जो अध्यक्षीय भाषण मालवीयजी ने तैयार किया था, उसमें उन्होंने सरकार की दमन नीति की निन्दा करते हुए कहा : “यह अनुमान है कि पिछले पन्द्रह महीनों में कई हजार स्त्रियों और बच्चों सहित लगभग एक लाख बीस हजार मनुष्य गिरफ्तार और कैद कर लिये गये हैं”। पर “सरकार”, उन्होंने कहा, “इस प्रकार आन्दोलन बन्द नहीं कर सकेगी।”^१

श्वेत पत्र की निन्दा करते हुए मालवीयजी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने नये विधान को ऐसे दम्भ-भरे अधिकार को मानकर बनाया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का यह कर्तव्य और नैतिक भार है कि वह इस बात का निर्णय करे कि कहाँ तक और किन-किन नियंत्रणों और सरक्षणों के साथ वह भारत को अपने घरेलू शासन में अधिकार देगी। सरकार को इस मनोवृत्ति की भर्त्सना करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि कोई भी स्वाभिमानी भारतीय, जो मातृभूमि के प्रति अपना उचित धर्म समझता है, श्वेतपत्र से सम्बन्धित किसी भी मामले में भाग नहीं लेगा, जब तक कि ब्रिटिश सरकार अपनी वर्तमान नीति में परिवर्तन न करे, और भारतीयों को बराबरी का सम्मान न दे, जो इंग्लैंड की तरह ही अपने देश का स्वयं प्रबन्ध करने के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा : “भारत और इंग्लैंड का सम्बन्ध विषाक्त आधार पर स्थित है, और सरकार के लिए उचित मार्ग यही होगा कि वह अपना व्यवहार जनता के अनुकूल तथा स्वतंत्रता, समानता, पारस्परिक सद्भाव और मैत्री के आधार पर स्थिर करे, और वे द्वेष और दुर्भाव दूर हो जिनका वर्तमान परिस्थिति में एक मात्र अनिवार्य प्रतिफल सविनय अवज्ञा है”।^२

१. इंडियन क्वाटरली रजिस्टर, सन् १९३३, जि० १।

२. वही।

मालवीयजी ने अंग्रेज विधि-विशेषज्ञों के प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि किन्हीं परिस्थितियों में सरकार के कानूनों और आज्ञाओं की सविनय अवज्ञा संवैधानिक है। उन्होंने कहा : "सरकार के उस कानून की अवज्ञा, जो अन्यायपूर्ण और दमनात्मक है और जनता की प्राथमिक स्वतंत्रताओं का अपहरण करता है, जनता का एक ऐसा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है जिसके द्वारा जनता विधान सभा तथा निरंकुश शासक को अपने अधिकार को विवेक और न्याय की सीमा में प्रयोग करने को बाध्य कर सकती है।"^१

मालवीयजी ने कहा : "हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता विचार की स्वतंत्रता है। इसके द्वारा सरकार भी अपने कर्तव्य के अधीन हो जाती है। इसने सब काल में सत्यता को अमरत्व प्रदान किया है और ससार के उन लोगों के पवित्र रक्त से अपनी अज्ञानता धोयी है, जिन्होंने उसे प्रकाशित किया था। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोग ऐसे कानून और आज्ञा का विरोध करें जिससे हमारे सहमिलन और सम्भाषण की स्वतंत्रता का अपहरण होता है। महात्मा गांधी ने ऐसी परिस्थिति में अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा के प्रयोग की भारतीयों को शिक्षा देकर मानव समाज की महान् सेवा की है। यह प्रतिवाद वैध और अहिंसात्मक है।"^२

मालवीयजी का वक्तव्य

अधिवेशन के बाद श्रीमती सेन गुप्ता को छ महीने की कड़ी सजा दे दी गयी, पर मालवीयजी तथा बहुत से दूसरे बन्दी छोड़ दिये गये। मालवीयजी आसनसोल से सीधे कलकत्ता गये, और वहाँ उन्होंने पुलिस के सिपाहियों और यूरोपियन सारजेंटों के अत्याचारों और अमानुषिक व्यवहार की जाँच की, आहतों के बयान लिये। वाराणसी वापस आकर ९ अप्रैल सन् १९३२ को उन्होंने ६ पृष्ठ का एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने बताया कि लगभग २,५०० प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लेने का प्रयत्न किया, लगभग एक हजार रास्ते में गिरफ्तार कर लिये गये, १४०० से अधिक कलकत्ता पहुँच गये, इनमें से अधिकांश को अधिवेशन से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, फिर भी पुलिस की सतर्कता के बावजूद श्रीमती नलनी सेन गुप्ता की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और सात प्रस्ताव पास हुए। इस अवसर पर

पुलिस ने प्रतिनिधियों को खूब मारा पीटा, पर वे सब यातनाओं को सहते हुए अपने कार्य में डटे रहे। इस वक्तव्य में मालवीयजी ने काफी विस्तार के साथ यह भी बताया कि अधिवेशन से पहले ही जो प्रतिनिधि गिरफ्तार किये गये थे, इनमें से बहुतों को पुलिस थाने में ले जाकर सार्जेंटों ने बहुत ही अमानुषिक ढंग से आहत किया, कई आहतों को तो अस्पताल भेजना पड़ा। अपने वक्तव्य के अन्त में मालवीयजी ने लिखा कि अधिवेशन में मारपीट की बात तो समझी जा सकती है, पर हिरासत में कैदियों को पाशविक ढंग में आहत करना किसी तरह भी ठीक नहीं समझा जा सकता। आहतों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने उन्हें उनके धैर्यपूर्ण साहस पर बधाई दी, और लिखा कि उनके मौन कष्ट शीघ्र उस व्यवस्था को खत्म कर देंगे जो इस अपराध पर कि वे अपने देश के लिए वही स्वतन्त्रता चाहते हैं जो उनके दमन करनेवालों को अपने देश में प्राप्त है, लोगों के साथ इस तरह निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने की, तथा उन्हें अपमानित करने की इजाजत देती है।

मालवीयजी के इस वक्तव्य के बाद लेजिस्लेटिव असेम्बली के २५ सदस्यों ने भारत सरकार के गृहमन्त्री को लिखा कि मालवीयजी के आरोपों की जाच करायी जाय। गृह-सदस्य सर हेरो हेग ने उन्हें उत्तर दिया कि बंगाल सरकार को आरोपों की जाच कराने के लिए लिखा जा रहा है। मई में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारतमन्त्री सर सेमुअल होर ने कहा कि बंगाल सरकार ने ये सब आरोप गलत बताये हैं। इस पर मालवीयजी ने भारत-मन्त्री को लिखा कि उनके आरोपों की सार्वजनिक खुली जाच करायी जाय, और वे उन्हें सही साबित करने को तैयार हैं, पर यदि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, तो उन पर मुकदमा चलाया जाय। भारतीय समाचार-पत्रों ने भी सरकार की निन्दा करते हुए मालवीयजी की इन मांगों को दोहराया। बहुत से आहत सज्जनों ने भी मालवीयजी के वक्तव्य की पुष्टि में समाचार-पत्रों को अपनी आपबीती की सूचना दी। इस पर भी भारतमन्त्री ने मार्गन जोन्स के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार किसी पर मुकदमा चलाना नहीं चाहती। जिन्हें दुर्व्यवहार की शिकायत है वे यदि चाहें तो न्यायालय में दावा दायर कर सकते हैं।

गतिविधि

दूसरे सविनय अवज्ञा आन्दोलन के जमाने में एक बार चौधरी खलीकुज्जमा मालवीयजी से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि आन्दोलन को बन्द करने की

घोषणा की जाय। इस पर श्री जगन्नाथ प्रसाद रावत ने मालवीयजी से अकेले में बात की, और उनसे अनुरोध किया कि वे इस प्रकार का कोई वक्तव्य न दें। उसके बाद मालवीयजी ने खलीकुज्जमा साहब से कह दिया कि जिसने आन्दोलन चलाया है, वही उसे बन्द कर सकता है।

खलीक साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि “मालवीयजी, सर टी० बी० सप्रू और डाक्टर अन्सारी को इस बात पर राजी करने के लिए कि वे सविनय अवज्ञा आन्दोलन को बन्द कराने के लिए गांधीजी पर अपना प्रभाव काम में लावें, वे इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, दिल्ली दौड़ते फिरें”।^१

मालवीयजी के निजी पत्रों के देखने से पता चलता है कि एक बार मद्रास के प्रसिद्ध नेता श्री सत्यमूर्ति ने मालवीयजी को लिखा कि वे वाराणसी या किसी दूसरे केन्द्रीय स्थान में उन कांग्रेसजनों की एक सभा आयोजित करें जो इस समय जेल से बाहर हैं, और उस सभा में कौंसिल सम्बन्धी कार्यक्रम पर विचार किया जाय। पर मालवीयजी ने यह नहीं किया।

प्रोफेसर राघवश्याम शर्मा ने बताया कि जब प्रान्तीय काफरेन्स के लिए धन इकट्ठा करने की मालवीयजी से प्रार्थना की गयी, तब उन्होंने कहा कि इस समय रुपया इकट्ठा करना तो कठिन है, उनके मकान को गिरवी रख कर रुपया जुटाया जा सकता है। जब लोगो को इसका पता लगा, तब उन्होंने काफरेन्स के लिए रुपया दे दिया।

डाक्टर पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है कि सन् १९३२-३३ के सकट काल में मालवीयजी “अपने दुर्दमनीय आत्मबल और अपूर्व शक्ति द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित और अनुप्राणित करते रहे”। उन्होंने यह भी लिखा है कि “सन्देह और कठिनाई के अवसरो पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके (मालवीयजी) के पास जाते और कभी निराश होकर नहीं लौटते थे।”^२ श्री जयप्रकाश नारायण, जो कांग्रेस सचिव की हैसियत से उस समय सारे देश में भ्रमण करते थे, मालवीयजी की आदमियत और उनके सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें मालवीयजी उत्प्रेरणा और प्रोत्साहन के महास्रोत, पीडितों के बड़े सहायक, तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के पक्के समर्थक प्रतीत हुए। आचार्य नरेन्द्र देव और युक्त प्रान्त के दूसरे बहुत से नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी ऐसा ही अनुभव था।

१. खलीकुज्जमा : पाथ वे टु पाकिस्तान, पृ० १२७।

२. पट्टाभि सीतारमैया : वही, पृ० ५८९।

गांधीजी का अनशन

२ मई सन् १९३३ को इक्कीस दिन के उपवास का निर्णय कर गांधीजी ने मालवीयजी को आशीर्वाद के लिए पत्र लिखा। मालवीयजी ने गांधीजी को लिखा "आपका २ तारीख का पत्र कल सायंकाल मिला, परमात्मा की आप पर कृपा हो। जैसा कि मैंने उपवास दिवस के अपने भाषण में कहा था मेरी यह निश्चित धारणा है कि भगवान् ने ही आपको इस निर्णय का आदेश दिया है। मैं उन्हीं से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे इस महान् व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने की आपको शक्ति दें, और मेरा विश्वास है कि वे आपको शक्ति देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप अनन्य भाव हो जावें। जो भगवान् हमारा रक्षक और सहायक है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी विचारों को यथाशक्ति अपने मन से निकाल दीजिये। द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) के जप के साथ-साथ दिन के किसी भाग में श्वास-प्रश्वास के साथ, 'सोहम्' का भी अभ्यास कीजिये। प्रकाश और जीवन की धारा को अन्तर में बनाये रखने में यह अभ्यास सहायक होगा। कुछ महान् तपसियों की दृष्टि आपके तप की ओर लगी है, और असंख्य जन आपकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने पास के वातावरण को सब प्राणियों में स्थित वासुदेव की चर्चा के अतिरिक्त अन्य बातों से अधिक से अधिक मुक्त रखिये। भगवान् के इस आदेश और प्रतिज्ञा को ध्यान में रखिये—'मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यामि'। स्वास्थ्य ठीक होते ही आप से मिलूंगा" १।

गांधीजी ने तार द्वारा उत्तर दिया "आपके आशीर्वाद मेरे लिए सुखकारी है। मैं आदेश का तत्त्वतः पालन कर रहा हूँ। वचन से ही राम नाम मेरा ताबीज रहा है। मैं अच्छा हूँ और शान्ति का अनुभव करता हूँ। अनुरोध करता हूँ कि आप आने का कष्ट न करें" २।

८ मई सन् १९३३ को गांधीजी ने आत्मशुद्धि तथा हरिजनोद्धार के निमित्त २१ दिन का अनशन प्रारम्भ किया, और उनके परामर्श पर कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष अण्णे साहब ने छः सप्ताह के लिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया। इस समय गांधीजी ने, जिन्हें अनशन के कारण सरकार ने रिहा कर दिया था, आशा व्यक्त

१. महामना मालवीयजी बर्थ सेन्टिनरी कोमिमोरेसन वाल्युम, पृ० १८२ (त्रिलोचन पन्त का लेख)।

२. वही, पृ० १८२।

की कि सरकार अध्यादेश वापस ले लेगी, और सब राजनीतिक कंदियों को छोड़ देगी। पर सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

विठ्ठल भाई पटेल और सुभाष चन्द्र बोस को, जो उस समय यूरोप में थे, गांधीजी की ये बातें पसन्द नहीं आयी। उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य में लिखा कि सविनय अवज्ञा को स्थगित करने के निर्णय ने पिछले तेरह वर्ष के कामों पर पानी फेर दिया। यह निर्णय, उन्होंने लिखा, सविनय अवज्ञा की, और गांधीजी के नेतृत्व की विफलता का, और इस बात का चेतक है कि अधिक उग्र नीति और नेतृत्व की आवश्यकता है।^१ जनता पर इस वक्तव्य का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सुभाष बाबू ने स्वयं स्वीकार किया कि “मित्रों ने भी सोचा कि उस समय जब उनका (गांधीजी का) जीवन अनशन के कारण खतरे में था, महात्मा की आलोचना करना घृणित काम था।”^२

जो भी हो, गांधीजी के इस अनशन ने हरिजनोद्धार के आन्दोलन में नयी जान डाल दी। सारे देश में बहुत से कार्यकर्ताओं ने बहुत ही जोरशोर से अस्पृश्यता के निवारण के लिए काम किया, और २९ मई को हरिजन दिवस मनाया, जुलूस निकाले, और सभाएँ की।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

जुलाई के दूसरे सप्ताह में गांधीजी के आदेश पर अणे साहब ने घोषित किया कि उन सब लोगों से, जो कांग्रेस संगठन से किसी प्रकार की सहायता की आशा बिना व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की क्षमता रखते हो, ऐसा करने की आशा की जाती है।

गांधीजी ने अपने सावरमती आश्रम को भंग कर आश्रम-निवासियों को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की सलाह दी, और स्वयं इसी उद्देश्य से १ अगस्त को दास गांव में जाने का निश्चय किया। पर रात को वे और ३४ आश्रम-निवासी गिरफ्तार कर लिये गये। ४ अगस्त को वे इस आदेश के साथ छोड़ दिये गये कि वे यरवदा गांव को छोड़ कर पूना में रहेंगे। गांधीजी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इस पर वे उसी दिन गिरफ्तार कर लिये गये, और उन्हें एक वर्ष की सजा दे दी गयी।

१. सुभाषचन्द्र बोस : इंडियन स्ट्रगल पृ० २६२।

२. सुभाष चन्द्र बोस . वही, पृ० २६३।

गांधीजी की गिरफ्तारी और सजा के समाचार ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के अभियान को गति प्रदान की। विभिन्न प्रांतों में सैकड़ों व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। १४ अगस्त को कार्यवाहक अध्यक्ष श्री एस० माधवराव अणे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। उसके कुछ दिन बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार शार्दूल सिंह गिरफ्तार कर लिये गये। उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले कार्यवाहक अध्यक्ष और डिप्टी के प्रथा खत्म कर दी, और सत्याग्रह ने शुद्ध व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का रूप धारण कर लिया।

हरिजन आन्दोलन

इधर गांधीजी ने जेल में फिर अनशन शुरू कर दिया, और वे २३ अगस्त को बीमारी के कारण बिना किसी शर्त के छोड़ दिये गये। उन्होंने निश्चय किया कि वे ३ अगस्त सन् १९३४ तक हरिजनोद्धार का कार्य ही मुख्य रूप से करेंगे, वे स्वयं सविनय अवज्ञा नहीं करेंगे, पर उसके सम्बन्ध में दूसरों को सलाह दे सकेंगे।

९ नवम्बर सन् १९३३ को गांधीजी ने 'हरिजन सेवक सघ' के तत्वावधान में हरिजनोद्धार के निमित्त देशव्यापी दौरा प्रारम्भ किया, जो नौ महीने के बाद २९ जुलाई सन् १९३४ को वाराणसी में समाप्त हुआ। इस दौरे में गांधीजी ने अस्पृश्यता-निवारण के धार्मिक और नैतिक स्वरूप की व्याख्या करते हुए सवर्ण हिन्दुओं से अनुरोध किया कि वे जन्मजात अस्पृश्यता की घृणित भावना को त्याग कर हरिजनों के साथ आत्मीयता का व्यवहार करें। उन्होंने बार-बार कहा कि ऊँच-नीच और अस्पृश्यता की भावनाएँ हिन्दू समाज के अभिशाप हैं, और उनसे छुटकारा पाना समाज और जीवन की पवित्रता और उत्कर्ष के लिए बहुत जरूरी है। इस दौरे में उन्होंने लगभग १२,५०० मील की यात्रा की और ८ लाख रुपये हरिजन कार्य के लिए जमा किये। उन्हें पूना और देवघर में छूतछात के समर्थकों के हिंसात्मक दुर्व्यवहार का, तथा लालनाथजी के उत्तेजनात्मक कृत्यों का सामना करना पड़ा। फिर भी जब ५ जुलाई को गांधीजी को पता चला कि उस समय जबकि लालनाथजी हरिजनोद्धार की सभा में अस्पृश्यता के पक्ष में धोला चाहते थे तो जनता ने उन्हें पीटा, तब गांधीजी ने इस व्यवहार की निन्दा करते हुए लालनाथजी को सभा में अपने विचार व्यक्त करने को निमंत्रित किया, और घोषित किया कि वे सात दिन का उपवास करेंगे, जिसे उन्होंने दौरे के खत्म होने के बाद ७ अगस्त से १३ अगस्त तक किया।

अन्त्यजोद्धार

मालवीयजी अपने ढंग पर सनातन धर्म महासभा के माध्यम और सहयोग से धर्म-प्रचार करते हुए सर्वर्ण हिन्दुओं को सनातन धर्म के उदार सर्वजनीन सिद्धान्तों का, तथा हरिजनो को सदाचार का उपदेश देते हुए अन्त्यजोद्धार का काम करते रहे। जब जुलाई सन् १९३४ में गांधीजी हरिजनोद्धार के काम से वाराणसी आये, तब उनकी सभा में ही उनकी अनुमति से श्री देवनायकाचार्य ने अन्त्यजोद्धार के कार्य को शास्त्रविरुद्ध प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। इसके बाद मालवीयजी ने अपने भाषण में शास्त्रों का प्रमाण देते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म की महिमा है कि मनुष्य चाहे किसी जाति में रहे, किन्तु धर्म से चले तो उसका उद्धार हो सकता है। मैं धर्मग्रन्थों के अध्ययन के अनुसार कहता हूँ कि हरिजनो को भी देवदर्शन का लाभ मिलना चाहिए। यही अभिलाषा गांधीजी की भी होगी। स्कन्द पुराण में ही इसका प्रमाण है कि यदि चाण्डाल सदाचारी हो, तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य के समान आदर पाने के योग्य हो जाता है। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर हम अपने अछूत भाइयों को सदाचारी क्यों न बनायें? हम उनको सदाचारी बनाकर दिखा दें कि जो भाई छोटे से छोटा हो उसे भी हिन्दू धर्म ऊँचा उठा सकता है।^१ उन्होंने कहा कि सदाचार ऐसी वस्तु है जिससे नीच कुल में उत्पन्न होकर भी मनुष्य ऊँचा सम्मान पा सकता है। इस प्रकार का उपदेश महात्मा गांधी भी आपको देते हैं। वे चाहते हैं कि इन लोगों की तकलीफ दूर हो। यदि कुएँ पर हमारा एक अछूत भाई रामदास जाता है, जिसके सिर पर चुटिया है, जो एकादशी व्रत रखता है, सत्यनारायण की कथा सुनता है गंगा-रनान करता है, यदि वह प्यासा रह गया तो समझ लो कि हमारे पूर्व पितर सब प्यासे रह गये। चाडाल भी हमारा अंग है। हमारा धर्म है कि स्मृति में उनके लिए जो मार्ग दिखाया गया है, उसका उन्हें उपदेश दें।^२ उन्होंने कहा कि “आज चार-पाँच करोड़ हिन्दू अछूत कहे जाते हैं। इनमें अछूता वे ही लोग हैं जो मीले काम करनेवाले हैं। वे मानव जाति की वह सेवा करते हैं, जो कोई नहीं कर सकता। यदि वे एक दिन भी अपना काम बन्द कर दें, तो हमारी क्या दुर्गति होगी, विचार कर लो। शगवान् ने कहा—‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः ससिद्धिं लभते नरः’—अपने अपने काम में लगे हुए लोग मेरा पद पा सकते हैं। ये भंगी चमार अपना काम करें, फिर जब स्नान करके सूर्य नारायण को

१ सीताराम चतुर्वेदी महामना मालवीय जी, पृ० ६५।

२ वही, पृ० ६६।

अर्घ्य दें, मन्त्र जपें तो वोलो उनका मंगल होगा कि नहीं ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्त्यज सबके लिए भगवान् के दर्शन का अधिकार है । जहाँ मन्दिर के अधिकारी प्रसन्नता से जाने का अवसर दें, वहाँ गर्भद्वार के बाहर से ही दर्शन करा दें । जहाँ आज्ञा न हो वहाँ न जायें । अन्त में मालवीयजी ने कहा - “हमें इन अछूतों को जल देना है, रहने को स्थान देना है, और इन्हें शिक्षा देनी है । मैं तो चाहता हूँ कि उनके चार करोड़ घरों में मूर्तियाँ रखी हों, और भगवान् का भजन हो, तभी तो मंगल होगा ।”

मालवीयजी के नेतृत्व में सनातन धर्म महामभा ने अन्त्यजोद्धार का समर्थन करते हुए निर्णय किया कि अस्पृश्य कही जानेवाली जातियों को सर्वसाधारण कुएं, तालाब, बावली, बाग, सड़क, सराय, भ्रमशान घाट तथा सर्वसाधारण स्कूलों और सभाओं में जाने के लिए कोई रोक नहीं होनी चाहिए । उसने यह भी निर्णय किया कि “जो जातियाँ अस्पृश्य मानी गयी हैं, वे भी सनातन धर्म को मानने-वाली हैं और सनातनधर्मी होने के कारण उनको देव-दर्शन का अधिकार है और उनको गर्भ मन्दिर के बाहर से सर्वमान्य मर्यादा के अनुसार दर्शन पाने का अवसर देना चाहिए । महासभा ने मन्दिरों के प्रवन्ध-कर्ताओं से अनुरोध किया कि वे अपने अपने मन्दिर की स्थिति के अनुसार इन जातियों को देवदर्शन प्राप्त करने का प्रवन्ध कर दें । उसने यह भी निर्णय किया कि इन जातियों के लोगों की “सनातन धर्म के अनुयायी होने का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त करने में सहायता की जाय, तथा जहाँ-जहाँ अदीक्षित हिन्दू सन्तान हैं, वहाँ-वहाँ ब्राह्मण से लेकर अन्त्यज पर्यन्त पुरुष और स्त्री समस्त सनातन-धर्मावलम्बी सन्तान को जिनको दीक्षा लेने की श्रद्धा हो, तद्देशीय मर्यादा के अनुसार शैव पंचाक्षर मन्त्र की दीक्षा दी जाय” ।

इसी अवसर पर मालवीयजी ने हरिजनोद्धार के निमित्त ‘अन्त्यजोद्धारविधि’ नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की । इसमें उन्होंने बहुत सी पौराणिक कथाओं का उल्लेख करके बताया कि देवदर्शन का उन सबको अधिकार है, जिनका उस पर विश्वास हो, और उसके द्वारा निकृष्ट भी उत्कृष्ट हो सकता है । मन्त्र दीक्षा के महात्म्य की काफी विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया :

“यथा काञ्चनता याति कास्थं रसविधानतः ।

तथा दीक्षाविधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्”

‘जिस तरह रस के विधान से कासा काञ्चन हो जाता है, इसी तरह दीक्षा द्वारा मनुष्य द्विजत्व अर्थात् श्रद्धता प्राप्त कर लेते हैं ।’

मालवीयजी ने यह स्वीकार करते हुए कि जन्म ही वर्ण का मूलधार है ‘सनातन धर्म’ के नाम से प्रकाशित लेख में बताया कि

(तप. श्रुतश्च योनिश्च त्रयं ब्राह्मणकारणम् (पातञ्जलि) ।)

तप, ज्ञान और जन्म ब्राह्मण के कारण हैं अर्थात् ‘पूर्ण ब्रह्मणत्व’ के लिए तीनों आवश्यक हैं ।

उन्होंने बताया कि श्रीमद्भागवत में नारद ने विभिन्न वर्णों के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है :

“यस्य यत्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् ।

यदन्यथापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्” ।^१

(अर्थात् ‘जिस पुरुष को जिस वर्ण को प्रकट करनेवाला जो लक्षण कहा गया है, जहाँ वह लक्षण दूसरे में भी दिखाई दे तो उसको उसी गुणवाले वर्ण के नाम से बताना चाहिए ।’)

मालवीयजी ने कहा कि इसी तरह युधिष्ठिर ने तक्षक के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है—

“शूद्रे तु यद् भवेत् लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते ।

न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः” ।^२

“सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा ।

दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः” ॥^३

“यत्रैतत् लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः ।

यत्रैतन्न भवेत् सर्प तं शूद्रमिति निर्दिशेत्” ॥^४

(‘शूद्र में यदि ब्राह्मण के गुण हो और ब्राह्मण में वे गुण न हो, तो न वह शूद्र शूद्र है और न वह ब्राह्मण ब्राह्मण ।’)

(‘हे नागेन्द्र, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शील, अहिंसा, तप, दया दिखायी दे, उसको ब्राह्मण कहते हैं ।’)

१. भागवत ७-११-२५ ।

२. महा भारत, वनपर्व, १८०-२५ ।

३. महा भारत, वनपर्व, १८०-२१ ।

४. महा भारत, वनपर्व, १८०-२६ ।

दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन, एकता कांफरेन्स, हरिजनोद्धार ५१६

(जहाँ अच्छा शील स्वभाव दिखायो दे, उसको ब्राह्मण कहना, जहाँ वह दिखाई न दे उसे शूद्र कहना चाहिए।)

मालवीयजी ने 'अन्त्यजोद्धार विधि' में धर्मव्याघ और ब्राह्मण के वार्तालाप की चर्चा करते हुए बताया कि धर्मव्याघ ने ब्राह्मण से कहा—

“शूद्रयोनी हि जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठत ।

वैश्यत्वं लभते ब्रह्मन् क्षत्रियत्वं तथैव च ॥”

आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते” ॥^२

शूद्रयोनि में भी उत्पन्न हुआ पुरुष यदि अपने में अच्छे गुण सम्पन्न करे, तो हे ब्राह्मण, वह वैश्य हो जाता है और क्षत्रिय भी। यदि वह सदाचरणपूर्ण जीवन बितावे तो उसमें ब्राह्मण की योग्यता भी प्राप्त हो जाती है।

उन्होंने कहा कि महाभारत में यह भी कहा गया है ·

“यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थितः ।

तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद् द्विजः” ॥^३

“वर्णोत्कर्षमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा ।

यथाऽपकर्ष पापेन इति शास्त्रनिदर्शनम्” ॥^४

‘जो शूद्र मन और इन्द्रियो के रोकने में, सत्य में, धर्म में, सदा लगा रहता है, उसको मैं ब्राह्मण मानता हूँ। ब्राह्मण चरित्र से ही होता है।’

मनुष्य पुण्य कर्मों के करने से वर्ण में ऊपर उठ जाता है और नीच कर्म करने से नीचे गिर जाता है। यह शास्त्र का कहना है।

‘सनातन धर्म’ के लेख में, जो जुलाई सन् १९३४ में लिखा गया था, मालवीयजी ने यह भी बताया—

“शूद्रोऽपि शीलसम्पन्नो गुणवान् ब्राह्मणो भवेत् ।

ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीन शूद्रात् प्रत्यवरो भवेत्” ॥^५

‘शील-सम्पन्न, गुणवान् शूद्र भी ब्राह्मण हो जाता है और क्रियाहीन ब्राह्मण भी शूद्र से नीचे गिर जाता है।

१. महाभारत, वनपर्व, २१२.११ ।

२. महाभारत, वनपर्व, २१२.१२ ।

३. महाभारत, वनपर्व, २१५ ।

४. महाभारत, शान्तिपर्व, १६१ ।

५. महाभारत, वनपर्व, १८० २५ ।

इस प्रकार के शास्त्रीय प्रमाण देते हुए मालवीयजी अपने इस लेख के अन्त में कहते हैं : “यदि ऊपर लिखे विचार शास्त्र के अनुकूल हैं तो इन्हीं के अनुसार अछूतों की आर्थिक दशा सुधार कर, सदाचार सिखा कर, उनको मन्त्रदीक्षा देकर उनका उद्धार करना हमारा धर्म है। ईसाई, मुसलमान जिन अछूतों को अपने धर्म में मिलाते हैं, उनको अपने समाज में बराबर का स्थान देते हैं। अछूत सनातन धर्म समाज के अंग हैं; इनकी उन्नति करना, इनके दुःख दारिद्र्य को दूर करने का यत्न करना, इनको सामान्य और धार्मिक शिक्षा देना, और समाज के दूसरे अंगों के समान इनकी रक्षा करना और इनको आगे बढ़ाना, हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इससे हमारे धर्म की रक्षा और वृद्धि होगी, और धर्म को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी। हिन्दू जाति का इसी में भला होगा, ऐसे ही मार्ग का अवलम्बन करने से सनातनधर्म की महिमा, पूर्ण रीति से स्थापित होगी। इसी प्रकार धर्मवृद्धि से धर्म के प्रश्नों का निर्णय करने से और उनके अनुसार चलने से समाज में धार्मिक एकता और शक्ति स्थापित होगी।”

‘अन्त्यजोद्धार विधि’ में उन्होंने पुराणों के बहुत से प्रमाण देते हुए बताया कि शूद्र, अतिशूद्र आदि को भी सर्व्व हिन्दुओं की तरह भगवान् की भक्ति करने का पूरा अधिकार है, और वे सब भी भगवद्भक्ति द्वारा गौरव और सद्गति प्राप्त कर सकते हैं, और उनके इस पवित्र कार्य में बाधा पहुँचाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मालवीयजी ने बहुत से प्रमाणों को उद्धृत करते हुए बताया कि काशीखण्ड में लिखा है :

“शालिग्राम-शिला येन पूजिता तुलसीदलैः ।

स पारिजातमालाभि पूज्यते सुरसद्मनि ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा यदि वेतरः ।

विष्णुभक्तिसमायुक्तो ज्ञेय सर्वोत्तमश्च स ” ॥^२

अर्थात् ‘तुलसीदल से शालिग्राम की पूजा करनेवाले चाहे कोई भी हो वह देवताओं के यहाँ पारिजात की माला से पूजा जाता है। विष्णुभक्ति से युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज को सर्वोत्तम समझना चाहिए।’

१. महामना पंडित मदन मोहन मालवीयजी के लेख और भाषण भाग १ धार्मिक पृ० १३-१४।

२. काशी खण्ड अध्याय १८, श्लोक ६२, ६३।

उन्होंने बताया कि 'पद्मपुराण उत्तरखण्ड' में आया है कि कलियुग में विष्णु के ध्यान में लगे हुए शूद्र घन्य होते हैं। वे इस लोक में सुख भोगकर परलोक में विष्णु पद प्राप्त करते हैं।

“कलौ घन्यतमा. शूद्रा विष्णुध्यानपरायणा.।

इहलोके सुखं भुक्त्वा यान्ति विष्णो. सनातनम्” ॥^१

मालवीयजी ने बताया कि चण्डालादि विषयक कथादि में अर्थवाद की कल्पना करना ठीक नहीं है। शिष्टों का यह वचन है कि “भगवान् के नाम में जो मनुष्य अर्थवाद की सम्भावना करता है, वह नरक में गिरता है।”

“अर्थवादं हरेर्नाग्निं सम्भावयति यो नर ।

स पापिष्ठो मनुष्याणां निरये पतति स्फुटम्” ॥^२

मालवीयजी का कहना था कि “अन्त्यजों में जो कुछ भी त्रुटि समझी जाती है, उसका सबसे प्रबल कारण उनमें विद्या-प्रचार की कमी है।”^३ उनकी धारणा थी कि अन्त्यजों को भी विद्या का अधिकार है। उन्होंने बताया, कि देवी पुराण में आया है कि विद्या कुल की, जाति की, रूप की, और पुरुष सम्बन्धी पात्रता की परवाह नहीं करती है। किन्तु जो कोई भी उसको पढता है, उसका उपकार करती है।

“न हि विद्या कुल जातिर्त्पं पीरूपपात्रताम् ।

वशते सर्वलोकानां पठिता उपकारिका” ॥^४

उन्होंने बताया कि यही पर एक श्लोक बड़े गौरव का है :

“अन्त्यजा अपि या प्राप्य क्रीडन्ते ग्रहराक्षसैः ।

सा विद्या केन गीयेत यस्याः कोऽन्य. समोऽपि न” ॥

अर्थात् ‘जिस विद्या के प्रभाव से या विद्या को पढ कर अन्त्यज भी चन्द्र सूर्यादि ग्रह और पराक्रमशील राक्षसों के साथ खेला करते हैं, और जिसके बराबर इस ससार में और कोई भी नहीं है, उस विद्या की उपमा किससे हो सकती है ?’^५

१ महामना पंडित मदनमोहन. मालवीयजी के लेख और भाषण, भाग-१-
(धार्मिक) पृ० २६६।

२. वही, पृ० २७१।

३. वही, पृ० २८३।

४. वही, पृ० २८४।

५. वही, पृ० २८४।

मालवीयजी ने बताया कि शूद्रों को द्विज-सेवा के अतिरिक्त श्राद्ध, देवपूजन, दर्शन, गर्भाधानादि द्वादश संस्कार, व्रत उपवास, पौराणिक मन्त्रजप, मालाधारण, स्तुति, दया, दान और अहिंसा आदि अनेक धर्मों का पूर्ण अधिकार है।^१

याज्ञवल्क्य ने, उन्होंने कहा, अन्त्यज पर्यन्त सब शूद्रों को सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, दान, दया और शान्तिधर्म का उपदेश किया है।

“अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

दानं दमो दया शान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्” ॥^२

मालवीयजी ने बताया कि गनुरमृति में भी दिया गया है।

“अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽत्रावीन् मनुः”^३

मालवीयजी ने बताया कि भगवान् कृष्ण ने श्रमोद्भूतगद्गीता में कहा है कि यदि दुराचारी भी मुझे अनन्यभाव से भजता है, तो उसे साधु ही समझना चाहिए, वह “धर्मात्मा” हो जाता है और “शाश्वच्छान्ति” प्राप्त कर लेता है। “यही बात है कि भगवान् रामचन्द्र एक अन्त्यजजाति की बुढ़िया स्त्री श्वरी की कुटिया में गये, और उसके अर्घा, फल, फूलदि को ग्रहण किया। यही बात है कि जाजलि जैसा तपस्वी ब्राह्मण एक बनिया तुलाधार के पास धर्मोपदेश सुनने गया, और एक तपस्वी ब्राह्मण धर्मोपदेश के लिए धर्मव्याध के पास गया”।^४

सारांश

मालवीयजी के वक्तव्यों, भाषणों और लेखों से यह स्पष्ट है कि हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म की रक्षा, कीर्ति और अभिवृद्धि के लिए एव तथाकथित अस्पृश्यों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए छूतछात की प्रथा का धर्मानुकूल परिशोधन मालवीयजी नितान्त आवश्यक समझते थे। वे जन्म को वर्णों का मूल-आधार मानते थे। पर उनके विचार में अन्त्यज शूद्र वर्ण का अंग है, तथा शील, सदाचार और भगवद्भक्ति द्वारा अन्त्यज पर्यन्त सभी शूद्र द्विजत्व प्राप्त कर सकते हैं, लोक में आदरणीय और सम्मानित होकर अभ्युदय और निःश्रेयस

१. वही, पृ० २७८।

२. वही, पृ० २६९।

३. वही, पृ० २६८।

४. वही, पृ० २७२।

की सिद्धि कर सकते हैं, परमानन्द प्राप्त कर सकते हैं । उनकी दृढ़ धारणा थी कि वेदों के अध्ययन तथा वेदमन्त्रों के जप तथा वैदिक तप का अधिकार शूद्रों को भले ही न हो, पर धर्मज्ञान और लौकिक विद्या प्राप्त करने का, सर्वसामान्य शील और सदाचार पालन करने का पौराणिक मन्त्रों की दीक्षा लेने और उनका जप करने का, तथा भगवान् की विधिवत् आराधना करने का उन्हें पूरा अधिकार है । कोई व्यक्ति उन्हें उनके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों से सम्बन्धित व्यक्तियों का कर्तव्य है कि शास्त्र-विहित शील, सदाचार और भगवद्भक्ति द्वारा वे स्वयं द्विजत्व के वास्तविक अधिकारी बनने का प्रयत्न करें, और अन्त्यज पर्यन्त सब शूद्रों को उसका उपदेश दें, उनके साथ आत्मौपम्य व्यवहार करें, तथा उनके उत्कर्ष में उनकी यथोचित सहायता करें । यही सनातनधर्म का आदेश है, इसी में सनातनधर्म का गौरव है ।

२३. साम्प्रदायिक निर्णय

साम्प्रदायिक निर्णय

१७ अगस्त सन् १९३२ को प्रधान-मन्त्री मेकडोनल्ड ने अपना साम्प्रदायिक निर्णय घोषित किया। पिछले बीस वर्षों में एक राजनीतिक नेता की हैसियत से वे कई बार साम्प्रदायिक निर्वाचन-पद्धति के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त कर चुके थे। १२ जनवरी सन् १९३१ को तो उन्होंने प्रधान-मन्त्री की हैसियत से भी कामन्स सभा में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की निन्दा की थी। वे सयुक्त निर्वाचन प्रणाली के समर्थक समझे जाते थे। सम्भवतः इसी कारण मालवीयजी, डाक्टर मुंजे, राजा नरेन्द्र नाथ और डाक्टर एस के दत्त ने, जो सयुक्त निर्वाचन के पक्ष में थे, साम्प्रदायिक समस्या पर अपना निर्णय देने की उनसे प्रार्थना की थी; और सम्भवतः इसी कारण से पृथक् निर्वाचन के समर्थक मुसलमानों में से किसी ने भी उनके निर्णय या फैसले को मानने का उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया था।

पर मेकडोनल्ड का साम्प्रदायिक निर्णय, जिसे उन्होंने 'अवार्ड' (पंचनिर्णय) के नाम से घोषित किया, लोकतान्त्रिक भावना के वजाय सम्प्रदायवादी और पृथक्तावादी प्रेरणाओं और प्रवृत्तियों पर आधारित था। वह निःसन्देह लोकतान्त्रिक संहति का विनाशक तथा सामाजिक विघटन को बढ़ानेवाला था। मेकडोनल्ड ने उन सब शक्तियों की उपेक्षा करते हुए जो विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों को एक सूत्र में बाँधने के पक्ष में थी, विघटनकारी तत्त्वों को ही भारत का वास्तविक प्रवक्ता स्वीकार करते हुए उनकी आकांक्षाओं की तुष्टि ही ठीक समझी।

मेकडोनल्ड ने अपने साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीय निर्वाचकों को मुसलमान, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, भारतीय ईसाई, सिक्ख, व्यावसायिक और औद्योगिक वर्ग, जमींदार, मजदूर, विश्वविद्यालय आदि कोटियों में विभाजित कर दिया, और इन सब के लिए पृथक् निर्वाचन पद्धति द्वारा पृथक् प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। अर्ध-गोरे और यूरोपियनों के लिए भी पृथक् प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी। व्यावसायिक वर्ग को प्रजातीयता के आधार पर विभाजित कर यूरोपियन व्यापार-मंडलों के प्रतिनिधित्व का अलग से प्रबन्ध कर दिया।

मेकडोनल्ड का साम्प्रदायिक निर्णय ब्रिटेन की साम्राज्यवादी कंजर्वेंटिव पार्टी के राजनीतिज्ञों की बड़ी विजय थी। जिस तरह उन्होंने मजदूरों के नेता मेकडोनल्ड की सहायता से सन् १९३१ में ब्रिटेन की लेबर पार्टी को पराजित किया, इसी तरह सन् १९३२ में मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय के माध्यम से वे भारत की राष्ट्रवादो शक्तियों को मुसवीत में डालने में सफल हुए। ऐसे महानुभाव की न्यायभावना पर विश्वास करना, जिसने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की हो, और उससे पंचनिर्णय की प्रार्थना करना मालवीयजी की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती थी।

मालवीय-जिना वार्ता

अप्रैल सन् १९३४ में मालवीयजी की जिना साहब से बातचीत हुई। जिना साहब ने उनसे कहा कि जब तक कोई अच्छा विकल्प (सबस्टीट्यूट) तय नहीं पाता, तब तक मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय को रद्दीकार करके सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना का विरोध किया जाय। मालवीयजी साम्प्रदायिक निर्णय मानने को तैयार नहीं थे। वे पृथक् निर्वाचन-पद्धति के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन-पद्धति लागू करने के पक्ष में थे। यदि कोई पारस्परिक समझौता न हो पाये, तो सन् १९१६ को कांग्रेस-लीग योजना द्वारा निश्चित निर्वाचन व्यवस्था भी चालू रखने को वे तैयार थे। उनका यह भी सुझाव था कि पंजाब में जहाँ मुसलमानों को प्रान्तीय कौंसिल में ४९ प्रतिशत स्थान मिले हैं, मुसलमान कम से कम एक बार उन चार विशिष्ट (स्पेशल) स्थानों से जो विश्वविद्यालय, व्यापार और श्रमिक वर्ग को दिये गये हैं, खड़े न हो। जिना साहब को ये बातें मजूर नहीं थी। इसलिए बिना किसी अच्छे परिणाम के बातचीत खत्म हो गयी।

रांची कांफरेन्स

२ और ३ मई सन् १९३४ को रांची में स्वराज्य पार्टी को संघटित करने के लिए कांफरेन्स आयोजित हुई। इस कांफरेन्स में निश्चित हुआ कि केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव लड़े जायें। स्वराज्य पार्टी का विधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ। श्वेतपत्र को रद्द करने के लिए प्रयत्न करना, राष्ट्रीय माँग की तैयारी के लिए संविधान सभा को बुलाने की माँग करना, उन सब कानूनों, अध्यादेशों और रेगुलेशनों को जो राष्ट्र के स्वस्थ विकास में तथा पूर्ण स्वराज्य की उपलब्धि में बाधक हैं रद्द करवाना, सब राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए प्रयत्न करना, उन सब कामों, कानूनों और प्रस्तावों का विरोध करना जो

देश का शोषण करने को परिकल्पित है, गाँवों का संगठन करना; श्रम, मुद्रा, विनमय तथा खेती आदि में सुधार कराने का प्रयत्न करना, एवं कांग्रेस के रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाना स्वराज्य पार्टी का कार्यक्रम निश्चित हुआ। साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में कुछ निश्चय नहीं किया गया।

वक्तव्य

९ मई सन् १९३४ को मालवीयजी ने लाहौर से एक वक्तव्य प्रसारित किया जिसमें उन्होंने सलाह दी कि जुलाई में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाय जो सविनय अवज्ञा को स्थगित कर कौंसिल के कार्यक्रम को चालू करे, जिसका संचालन स्वराज्य पार्टी के बजाय कांग्रेस द्वारा ही हो। उन्होंने इस वक्तव्य में यह भी कहा कि राची में आयोजित स्वराज्य पार्टी ने साम्प्रदायिक निर्णय पर अपनी राय को स्थगित करके ठीक नहीं किया। “पृथक् निर्वाचन पद्धति के फौलादी ढाँचे से समन्वित साम्प्रदायिक निर्णय तो हमें विभाजित करने और सदा परतंत्रता में बनाये रखने के लिए तैयार किया गया है, और इसलिए हम सब भारतीयों को मिल कर उसकी निन्दा करनी चाहिए। कांग्रेस साहस के साथ घोषित करे कि ऐसा कोई विधान जो संयुक्त निर्वाचन पर आधारित न हो स्वीकार-योग्य नहीं होगा। संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में देशव्यापी प्रचार किया जाना चाहिए”। स्वतः-पत्र की आलोचना करते हुए मालवीयजी ने कहा कि “उसका उद्देश्य तो उत्तरदायी सरकार का रूप और उपकरण प्रदान करते हुए सारे अधिकार को ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के हाथ में बनाये रखना, और भारतीय सविधान की ऐसी नींव डालना है जिस पर लोकप्रिय स्वशासन या उत्तरदायी शासन का निर्णय कभी हो ही नहीं सके, और भारत को डोमीनिघन स्टेट्स जैसी स्वतंत्रता भी प्राप्त न हो सके”।^१

भारत इंडिया कांग्रेस कमेटी

१८ और १९ मई सन् १९३४ को मालवीयजी की अध्यक्षता में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। कमेटी ने गांधीजी के वक्तव्य को स्वीकार करके सामूहिक सत्याग्रह को बन्द करने का, और गांधीजी की विशेष स्थिति में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की इजाजत देने का निर्णय किया। इसके बाद गांधीजी ने कौंसिलो में प्रवेश करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि वे अब भी कौंसिलो के बहिष्कार को ही ठीक

समझते हैं। पर यह समझकर कि कांग्रेस में बहुत से लोग कौंसिलो में काम करने के पक्ष में हैं, वह एक व्यावहारिक आदर्शवादी के रूप में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। पर उन्होंने कहा, “कांग्रेस आत्महत्या करेगी, यदि उसका ध्यान केवल कौंसिलो के कार्य में लगा रहेगा। इस तरह स्वराज्य नहीं मिल सकता, स्वराज्य तो जनता की व्यापक चेतना द्वारा ही आ सकता है।”^१ अणु साहव ने प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि यद्यपि स्वराज्य कौंसिलो द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी यदि संगठित प्रयत्न किये जायें, तो कौंसिलो द्वारा रुकावटें दूर की जा सकती हैं। मालवीयजी ने पहले प्रस्ताव को व्याख्या करते हुए कहा कि सविनय अवज्ञा और कौंसिलो में प्रवेश परस्पर विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। अन्त में कांग्रेस कमेटी ने सोशललिस्टों के संशोधन को सत्तर प्रतिशत वोटो से नामंजूर करते हुए गांधीजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव द्वारा कमेटी ने निश्चय किया कि ‘मालवीयजी और डाक्टर अन्सारी’ अधिक से अधिक पच्चीस सदस्यों का पार्लियामेन्टरी बोर्ड गठित करें। यह बोर्ड अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधीन काम करेगा, और जो नियम वह बनायेगा वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास उसकी रवीकृति के लिए भेजे जायेंगे। २५ व्यक्तियों का जो बोर्ड गठित हुआ, उसके अध्यक्ष डाक्टर अन्सारी बनाये गये। सर्वश्रो विधानचन्द्रराय और भूलाभाई देसाई प्रधान-मन्त्री नियुक्त हुए। यह भी निश्चय हुआ कि डाक्टर अन्सारी की अनुपस्थिति में मालवीयजी अध्यक्ष का काम करेंगे।

कांग्रेस के निर्णय

जून सन् १९३४ में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने सरकार के श्वेत-पत्र और साम्प्रदायिक निर्णय पर एक प्रस्ताव पास किया। उसने घोषित किया कि श्वेत-पत्र किसी तरह भी भारतीय जनता की इच्छा को अभिव्यक्त नहीं करता, सभी राजनीतिक पार्टियों से न्यूनाधिक तिरस्कृत कर दिया गया है, कांग्रेस के लक्ष्य से कम पड़ता है, यदि वह उसकी ओर प्रगति को रोकता न हो। श्वेतपत्र का एक मात्र मन्तोपजनक विकल्प वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा से तैयार किया संविधान है। इस सभा में यदि आवश्यक हो तो प्रमुख अल्प-संख्यकों के प्रतिनिधि अपने अल्पसंख्यक निर्वाचकों द्वारा चुने जा सकते हैं। इस प्रस्ताव में वर्किंग कमेटी ने कहा, “श्वेत-पत्र के गिर जाने पर साम्प्रदायिक निर्णय आपसे आप गिर जाता है। संविधान सभा का कर्तव्य होगा कि वह अन्य

बातों के साथ-साथ प्रमुख अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का तरीका निश्चित करे और हितों की रक्षा की व्यवस्था करे। चूंकि साम्प्रदायिक निर्णय पर देश के विभिन्न सम्प्रदाय बुरी तरह विभक्त हैं, और चूंकि कांग्रेस भारतीय राष्ट्र से सम्बन्धित सभी सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, इसलिए कांग्रेस उस समय तक जब तक मतभेद बना है साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार कर सकती है, न रद्द कर सकती है। पर साम्प्रदायिक प्रश्न पर कांग्रेस की नीति की व्याख्या जरूरी है। कांग्रेस किसी ऐसे समाधान को प्रतिपादित नहीं कर सकती जो विशुद्ध राष्ट्रीय न हो। पर राष्ट्रीयता से गिरा हुआ सुझाव भी वह मानने को वचनबद्ध है, यदि सबन्धित पार्टियां उस पर सहमत हैं और उस समाधान को भी अस्वीकार करने को वचनबद्ध है जिस पर संबन्धित पार्टियां सहमत न हो। दूसरे आधारों पर गंभीर आपत्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय माप-दण्ड से साम्प्रदायिक निर्णय बिल्कुल असन्तोषजनक है, यह भी स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक निर्णय के अशुभ परिणामों को रोकने का उपाय यही है कि सर्व-सम्मत समाधान का मार्ग और उपाय ढूँढा जाय, न कि इस घरेलू मामले पर ब्रिटिश सरकार या किसी दूसरे बाह्य अधिकारी से अपील की जाय”।

इस तरह कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था की कड़ी आलोचना करते हुए उसे नामंजूर कर दिया। उसने मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय को सर्वथा दोषपूर्ण बताया, पर निश्चय किया कि परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वह उसे न तो मंजूर करती है और न रद्द करती है।

मालवीयजी को कांग्रेस का यह निर्णय पसन्द नहीं था। वे चाहते थे कि कांग्रेस प्रधान-मन्त्री के साम्प्रदायिक निर्णय को स्पष्ट शब्दों में रद्द करने की घोषणा करे। चूंकि कांग्रेस का नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं था, मालवीयजी ने पार्लियामेंटरी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। उनके साथी एस० एम० अणे ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे दिया। पर गांधीजी के आग्रह पर और आश्वासन पर कि इस प्रश्न पर फिर विचार किया जायगा, दोनों ने अपने त्यागपत्र वापस ले लिये।

२९ जुलाई को वाराणसी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस प्रश्न पर फिर से विचार करने के बाद पुराने निर्णय पर डटा रहना ही उचित समझा। इस पर इन दोनों ने फिर इस्तीफे दे दिये।

नेशनलिस्ट मुसलमानों का दृष्टिकोण

१८ जुलाई सन् १९३४ को कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के सदस्य चौधरी खलीकुज्जमा ने बोर्ड के सेक्रेटरी मिस्टर आसफ अली को लिखा कि साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में हिन्दू महासभा के विरुद्ध तगड़ा मोर्चा कांग्रेस को मुसलमानों का विश्वास प्राप्त करने में सहायक होगा, और मुसलमानों का सहयोग ही भारत के भविष्य को शानदार और कामयाब बना सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, महासभा से समझौता करने के बजाय उसके विरुद्ध चुनाव अवश्य लड़ना चाहिए। पर मुरालमान उम्मीदवारों का प्रश्न बहुत कठिन है। हमारे हिन्दू दोस्त यह नहीं समझ पाते कि हमारे लिए मुसलमान उम्मीदवारों को कांग्रेस के टिकट पर खड़ा होने के लिए राजी करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि चुनाव में यह बात उनके लिए महाभार होगी। बम्बई में किये गये सकेत का प्रभाव इतना फीरी (तुरन्त) नहीं होगा कि वह उनके दिमाग में ऐसी तब्दीली पैदा कर दे जिसका मीजूदा चुनाव पर प्रभाव पड़ पाये। कुछ समय बाद यह मुसलमानों को शान्त अवश्य कर देगा, पर इसमें समय लगेगा। इसलिए जो कुछ हम कर सकते हैं, वह यही है कि अपने सम्प्रदाय के नेतृत्व को प्रतिक्रियावादियों से छीनने के लिए मुस्लिम यूनिटी बोर्ड के टिकट पर जो कांग्रेस के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, कुछ चुनाव लड़े जायें।^१

इससे कुछ मास पहले फरवरी सन् १९३४ में जिना साहब और खलीकुज्जमा साहब की बातचीत हुई थी। जिना साहब ने खलीक साहब से कहा कि यदि वे उनका साथ नहीं देंगे, तो वह हिन्दुस्तान लौट कर नहीं आयेंगे। इस पर खलीक साहब ने जवाब दिया : “साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में जो स्टैंड मैंने लिया है उसके बाद हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गये हैं, और कौन जानता है कि भविष्य में हम कामन लक्ष्य के लिए मिलकर काम न करते हो।”^२

९ अगस्त सन् १९३४ को ‘मुस्लिम यूनिटी बोर्ड’ ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया, चुनाव घोषणा तैयार की, तथा कई उम्मीदवारों का चयन किया, जिनमें कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के सदस्य मिस्टर तसद्दुक अहमद खाँ शेरवानी भी थे।

१. चौधरी खलीकउज्जमा : पाथवे टु पाकिस्तान, पृ० १२७।

२. चौधरी खलीकउज्जमा : वही, पृ० १३१।

डाक्टर अन्सारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले को बिल्कुल ठीक समझते थे। वे साम्प्रदायिक निर्णय को ठीक नहीं समझते थे, पर उनकी दृढ़ धारणा थी कि जबतक समझौते के जरिये उसका कोई विकल्प तय नहीं हो पाता, तब तक उसे रद्द करना उचित नहीं होगा।

कांग्रेस के दूसरे मुसलमान नेताओं और कार्यकर्ताओं के भी करीब-करीब यही विचार थे। वे मालवीयजी और अणे साहब के इस्तीफे से खुश थे।^१ कम से कम चौधरी खलीकुज्जमा साहब तो मालवीयजी और अणे साहब को ही नहीं, सोशलिस्टों को भी, सम्प्रदायवादी ही समझते थे। उनकी धारणा थी कि इन सोशलिस्टों से, जो "सोशलिस्टों से अधिक हिन्दू हैं, सम्प्रदायवादी अधिक 'सोशलिस्ट कम हैं', एक जुदा (पृथक्) मंच से भी सहयोग करना नामुमकिन होगा।^२

समीक्षा

पर सुभाषचन्द्र बोस और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के निर्णय को बहुत अच्छा नहीं समझते थे। सुभाष बाबू का कहना था कि श्वेतपत्र की तरह साम्प्रदायिक निर्णय को भी तुरंत रद्द कर देना चाहिए, चाहे उसका विकल्प तुरंत मिल पाये या नहीं^३। उन्हें दुःख था कि राष्ट्रवादी मुसलमानों के आग्रह पर कमेटी को यह हास्यास्पद निर्णय करना पड़ा कि वह साम्प्रदायिक निर्णय को न तो स्वीकार करती है और न नामंजूर करती है। ऐसा दिखाई देता है कि नेशनलिस्ट मुसलमान सम्भवतः अनजाने अपने साम्प्रदायिक धर्मविलम्बियों की लीक में प्रवेश कर रहे हैं।^४

सन् १९३४ में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भी नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी की गतिविधि की समीक्षा करते हुए लिखा : "कांग्रेस में बहुत से मुसलमान थे। उनकी संख्या काफी बड़ी थी और उनमें बहुत ही योग्य, लघ्वप्रतिष्ठ और लोकप्रिय मुसलमान शामिल थे। इन कांग्रेसी मुसलमानों में से बहुतों ने मिल कर अपने को 'मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी' के नाम से एक ग्रुप में गठित किया, और उन्होंने साम्प्रदायिक मुसलमान नेताओं से सघर्ष किया। प्रारम्भ में उन्हें इसमें कुछ सफलता प्राप्त हुई, और मुसलमान बुद्धिजीवियों का एक बड़ा अंश

१. चौधरी खलीकुज्जमा : वही, पृ० १३२।

२. वही, पृ० १३३।

३. सुभाष चन्द्र बोस : इण्डियन स्ट्रैटिगिज पृ० २६८।

४. वही, पृ० २६८।

उनके साथ दिखाई देता था। पर वे सब उच्च-मध्य श्रेणी के लोग थे, और उनमें गतिशील व्यक्तियों की कमी थी। वे अपने पेशे और व्यवसाय में लगे थे, और जनता से उनका सम्पर्क टूट गया था। वास्तव में वे कभी जनता के पास गये ही नहीं। बैठको में जमाव, पारस्परिक समझौते और पैक्ट यही उनका तरीका था, और इस खेल में उनके प्रतिद्वन्द्वी साम्प्रदायिक नेता अधिक दक्ष थे। धीमे-धीरे उन्होंने नेशनलिस्ट मुसलमानों को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर खदेड़ना शुरू किया, और उन्हें एक-एक करके उन सब सिद्धान्तों को छोड़ने पर मजबूर किया जिनके लिए वे खड़े थे। नेशनलिस्ट मुसलमानों ने अगले अपवान (रिट्रीट) को रोकने की तथा छोड़ी बुराई की नीति का अनुसरण कर अपनी पोजीशन को 'दृढ़ करने की कोशिश की'। पर इसने सदा दूसरे अपवान का और दूसरी छोटी बुराई के विकल्प का रास्ता दिखाया। एक समय आया जब कुछ भी नहीं बचा जिसे वे अपना कह सकें, कोई बुनियादी सिद्धान्त नहीं था जिस पर वे खड़े थे, वजुज एक के और वही उनकी गुट का लगर था, यानी संयुक्त निर्वाचन-पद्धति। लेकिन छोटी बुराई की नीति ने उनके सामने घातक विकल्प उपस्थित किया, और वे बिना उस लगर के कठिन परीक्षा से बाहर निकले। बस आज वे उस सिद्धान्त और व्यवहार के लेशमात्र से भी वंचित खड़े हैं जिसके आधार पर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, और जिसे उन्होंने गर्व के साथ अपने मस्तूल शिखर पर लगाया था। एक ग्रुप की हैसियत से नेशनलिस्ट मुसलमानों की विफलता और त्रिलोपन—व्यक्तिगत हैसियत से वे अब भी प्रभावशाली नेता हैं—एक दयनीय कथा है। इसे कई वर्ष लगे और उसका अन्तिम अध्याय इसी वर्ष (१९३४) में ही लिखा गया है"।^१

रमजे मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय की समीक्षा करते हुए नेहरूजी ने लिखा : "साम्प्रदायिक निर्णय एक प्रत्यक्ष धेतुकी चीज है। उसे स्वीकार करना असम्भव था, क्योंकि जब तक वह बना रहता था तब तक किसी प्रकार की स्वतंत्रता अलभ्य थी। इसलिए नहीं कि वह मुसलमानों को बहुत देता है। सम्भवतः जो कुछ वे मागते हैं वह करीब करीब सभी उन्हें दूसरे रूप में दिया जाना संभव था।" ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिन्दुस्तान को एक दूसरे को संतोलन और निष्प्रभावन करते हुए आपस में बहुत से पृथक् भागों में बांट दिया, ताकि विदेशी ब्रिटिश तत्त्व सर्वोपरि रह सके। उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अधीनता अनिवार्य बना दी"।^२

१, जवाहरलाल नेहरू - आटोबायोग्राफी, पृ० १३९।

२. वही, पृ० ५७६।

साम्प्रदायिक निर्णय पर कांग्रेस की नीति की समीक्षा करते हुए जवाहर लालजी ने लिखा : "साम्प्रदायिक निर्णय पर कांग्रेस का दृष्टिकोण विलक्षण था, और परिस्थितियों के संदर्भ में वह इससे भिन्न कैसे हो सकता था ? वह उनकी पुरानी तटस्थ और दुर्बल नीति का अनिवार्य परिणाम था । परिणामों पर ध्यान दिये बगैर पहली अंतरथा में दृढ़ नीति का ग्रहण करना और अनुसरण करना अधिक गौरवपूर्ण और सही होता । चूँकि कांग्रेस उनके लिए तैयार नहीं, उसके लिए जो मार्ग उगने आनाया उसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था" ।^१

राजेन्द्र प्रसादजी ने अपनी 'आत्मकथा' में कांग्रेस के निश्चय का समर्थन करते हुए लिखा है : "वकिंग कमेटी के इस निर्णय का यह अर्थ नहीं था कि वह उसका समर्थन करती है अथवा उसे न्यायसंगत समझती है । उसने उसकी निन्दा कठे शब्दों में की थी । पर वह उसका विरोध नहीं करना चाहती थी, क्योंकि विरोध का अर्थ होता दूसरों के साथ गुल्लमगुल्ला शगडा और यह विरोध अनावश्यक भी था । कमेटी ने तो गारं निधान को ही नामंजूर कर दिया था । इस लिए विधान का यह अंश भी उसके साथ नामंजूर हो गया था । अलग से नामंजूर करने का अर्थ यह भी होना था कि हम परोक्ष रूप में और अशो को मान लेते हैं, तभी तो एक अंग को विशेष रूप में नामंजूर करते हैं । साथ ही विधान का यही अंश ऐसा था जिसको बदलने का अधिकार हमारे हाथ में था, किसी दूसरे अंश को बदलने की शक्ति हमको विधान द्वारा नहीं मिली थी । इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर वकिंग कमेटी ने अपना निश्चय व्यक्त किया था, जिसका सारांश यह था कि कमेटी सारे विधान को नामंजूर करती है और सारे विधान के साथ यह अंश भी गिर जायगा, और यद्यपि वह उसे राष्ट्रीयता की दृष्टि से घातक समझती है तथापि उपरोक्त कारणों से न उसे स्वीकार करती है, और न विरोध करती है ।"^२

इन सबसे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस के दो प्रमुख वामपक्षी नेता, जवाहर लाल नेहरू और सुभाषचन्द्र, नेशनलिस्ट मुसलमानों के व्यवहार से, मैकडोनाल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय से, तथा उस पर कांग्रेस वकिंग कमेटी के दृष्टिकोण से असन्तुष्ट थे । जवाहर लाल इस दृष्टिकोण को पुरानी दुर्बल नीतियों का अनिवार्य परिणाम समझ कर उसका किसी अंश में समर्थन करते थे । राजेन्द्र प्रसादजी

१. वही, पृ० ५७५-५७६ ।

२. राजेन्द्र प्रसाद • आत्मकथा, पृ० ४१६ ।

ने वर्किंग कमेटी के निर्णय के पक्ष में जो बात कही है, वह किसी अंश में सत्य होते हुए भी सर्वथा ठीक नहीं समझी जा सकती। यह बात कि जब कमेटी ने सारे विधान को ही नामंजूर कर दिया था, तब विधान का यह अंश (साम्प्रदायिक निर्णय) भी सबके साथ नामंजूर हो जाता है और विधान के किसी एक अंश को विशेष रूप से नामंजूर करना भ्रामक होता, वर्किंग कमेटी के इस निर्णय से मेल नहीं खाती कि वह साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार करती है और न रद्द करती है। यह ठीक है कि साम्प्रदायिक निर्णय को समझौते के जरिये बदला जा सकता था। वर्किंग कमेटी कह सकती थी कि वह सारे विधान के साथ-साथ साम्प्रदायिक निर्णय को भी रद्द करती है, परन्तु जब कि वह समझौता द्वारा साम्प्रदायिक समस्या का समाधान कर साम्प्रदायिक निर्णय को बदलने का प्रयत्न करेगी, सारे देश की सामूहिक शक्ति द्वारा प्रस्तावित विधान का प्रतिरोध करेगी। यदि प्रस्ताव इस रूप में पास कर दिया गया होता, तो मालवीयजी, अणे साहव और बगाल के कांग्रेसी नेता संभवतः सन्तुष्ट हो जाते, और कांग्रेस का खुला विरोध नहीं करते।

कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी

१८ और १९ अगस्त सन् १९३४ को कलकत्ते में मालवीयजी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रवादियों की सभा में 'कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी' बनाने का निश्चय किया गया। इस दल के निर्णयों का स्पष्टीकरण करते हुए मालवीयजी ने एक विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड की सदस्यता से उनके त्यागपत्र का यह आशय नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस से चिरकाल के लिए एकदम सम्बन्ध त्याग दिया है। कांग्रेस से साम्प्रदायिक निर्णय के अतिरिक्त और किसी बात में उनका मतभेद नहीं है। उन्होंने बताया कि उनका विश्वास है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति तथा पार्लियामेंटरी बोर्ड ने इस साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में जिस नीति को स्वीकार किया है वह कांग्रेस की उस नीति और सिद्धान्त के सर्वथा प्रतिकूल है जिसका पालन और पोषण वह अपने जन्म-दिन से कर रही है और यह नीति अवश्य ही देश के कल्याण के लिए "घोर घातक" और "विशेषतः हिन्दुओं के लिए—दोषपूर्ण और अग्राह्य" है। उन्होंने यह भी घोषित किया कि जिस दल को वे सघटित करना चाहते हैं, वह केवल राष्ट्रीय भाव के आधार पर काम करेगा, और उस प्रयत्न का सर्वथा साथ देगा जो साम्प्रदायिक प्रश्न का सर्वसम्मति निर्णय करने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने यह भी घोषित किया कि इस दल

के विचार में जब तक सम्बन्धित सम्प्रदायों की सम्मति से कोई नया निर्णय नहीं होता, तब तक लखनऊ के समझौते की सब बातें बदस्तूर बनी रहें। उन्होंने यह भी बताया कि उनका दल 'नेहरू रिपोर्ट' की संस्तुतियों का समर्थन करता है, और वह साम्प्रदायिक प्रश्न पर बातचीत के समय "जुलाई सन् १९३१ की कांग्रेस की उस योजना पर काम करेगा, जिसे महात्मा गांधी ने गोलमेज कांफरेन्स के सागन रखा था और जिसका समर्थन राष्ट्रीय विचार के देश के सभी मुसलमानों ने किया था।"^१

इस वक्तव्य में कांग्रेस, नेहरू कमेटी, राष्ट्रीय मुस्लिम कांफरेन्स के निर्णयों के, तथा माटैग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और साइमन कमीशन की रिपोर्टों के उन उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए, जिनमें पृथक् निर्वाचन के बजाय संयुक्त निर्वाचन पद्धति का समर्थन किया गया था, इस बात पर खेद प्रकट किया गया कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय सरकार ने इन सब न्यायसंगत विचारों की अवहेलना करते हुए केवल पृथक् निर्वाचन की रक्षा नहीं की, बल्कि उसके सिद्धान्त की कहीं-कहीं सम्बद्ध सम्प्रदायों की इच्छा के विरुद्ध भी नवीन ढंग से और भी विस्तृत कर दिया।^२

देश की जनता को पन्द्रह प्रकार के पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर देने की भर्त्सना करते हुए कहा गया कि पृथक् निर्वाचन पद्धति द्वारा बंगाल और पंजाब में बहुसंख्यक सम्प्रदाय के लिए स्थान सुरक्षित करना साम्प्रदायिक निर्णय का सबसे अधिक आक्षेपपूर्ण अंग है। जैसा कि नेहरू रिपोर्ट में बताया गया है "बहुसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित रखना केवल उत्तरदायी शासन की ठुकरावाही ही नहीं है, बल्कि उस सिद्धान्त की, जिस पर उत्तरदायी शासन अवलम्बित रहता है, जड़ खोदना है।"^३

अपने इस वक्तव्य में सन् १९३२ के एकता सम्मेलन की चर्चा करते हुए मालवीयजी ने बताया कि यदि भारतमन्त्री सर सेमुअल होर अपनी घोषणा द्वारा उसके निर्णयों को मुसलमानों की दृष्टि में सारहीन नहीं बना देते, और बंगाल-निवासी अंग्रेज सहयोग को तैयार होते, तो साम्प्रदायिक समस्या हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख नेताओं के आपसी समझौते से हल हो सकती थी।

१ सीताराम चतुर्वेदी : महामना पंडित भदन मोहन मालवीय, खंड ३, पृ० १४२-१४७। २. वही। ३. वही।

मालवीयजी ने साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में बीमारी की हालत में दौरा किया। जब वे बिहार में थे, तब उनकी धर्मपत्नी प्रयाग में मर्मान्तक आघात से पीड़ित थी, और वे स्वयं जाँघ में कार्बन्कल फोड़े से परेशान थे, पर इस दोनों की उपेक्षा करते हुए वे अपने काम में संलग्न रहे।

मालवीयजी ने अपने भाषणों में प्रधान-मंत्री के साम्प्रदायिक निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए पृथक् निर्वाचन पद्धति की बुराईयों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि स्वराज्य जनता द्वारा शासन है, वह सम्प्रदाय द्वारा शासन नहीं है। उनका कहना था कि स्वतन्त्र राज्य में चुनाव धर्म के आधार पर नहीं लड़े जाते, पृथक् निर्वाचन द्वारा हिन्दू राज और मुस्लिम राज होगा, स्वराज्य नहीं होगा। उनकी धारणा थी कि "पृथक् निर्वाचन द्वारा ब्रिटिश सरकार हमें विभाजित रखते हुए सदा के लिए हमें अपने अधीन रखना चाहती है।" उनके विचार में पृथक् निर्वाचन पर आधारित संविधान हमें कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए।

कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन

अक्तूबर सन् १९३४ में बम्बई में राजेन्द्र प्रसादजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। डाक्टर अन्सारी ने श्वेतपत्र, साम्प्रदायिक निर्णय, तथा आगामी चुनावों में भाग लेने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया। मालवीयजीने साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में सशोधन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव की यह दलील कि श्वेतपत्र के साथ ही साम्प्रदायिक निर्णय समाप्त हो जायगा, गलत है, क्योंकि ये दोनों अलग चीजें हैं। ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि साम्प्रदायिक निर्णय उनका अन्तिम निर्णय है, यद्यपि श्वेतपत्र में परिवर्तन हो सकता है। मालवीयजी ने कहा कि साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में कांग्रेस की अनिश्चित धारणा का अन्तिम परिणाम उसकी परोक्ष स्वीकृति ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सन् १९३२ में उन्होंने एकता काफरेन्स द्वारा साम्प्रदायिक समस्याओं के समाधान का प्रयत्न किया था, जो करीब-करीब सफल भी हो गया था, और वह अब भी विभिन्न सम्प्रदायों के बीच सर्वसम्मत् समाधान निकालने के लिए प्रयत्न करने को तैयार है, क्योंकि एकमात्र धरेलू मामले को निर्णय कराने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के पास जाना वह लज्जाजनक समझता है।^१ कांग्रेस का यह प्रस्ताव तो, उन्होंने

कहा, गांधीजी के उन विचारों के भी विपरीत हैं, जो उन्होंने इस समस्या पर गोलमेज काफरेन्स में व्यक्त किये थे । नेशनलिस्ट मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए मालवीयजी ने कहा : “यदि आप महसूस करते हैं कि वह (साम्प्रदायिक निर्णय) विषाक्त और राष्ट्रविरोधी है, तो आप उसे रद्द करने में आपत्ति क्यों करते हैं ?”^१ उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने रेमजे मेकडोनल्ड से व्यक्तिगत हैसियत से, न कि प्रधान-मंत्री की हैसियत से, साम्प्रदायिक समस्या को निपटाने को कहा था ।^२

अणे साहब ने मालवीयजी के संशोधन का अनुमोदन किया । सरदार गोपाल सिंह कौमी और मौलवी अब्दुल सलाम ने उसका समर्थन किया । सिध्वा आदि कई व्यक्तियों ने उसका कडा विरोध किया । सरदार पटेल ने कहा कि साम्प्रदायिक निर्णय किसे पसन्द है ? वह तो राष्ट्रविरोधी है, और देश में फूट डालने के लिए बनाया गया है । हम सब मालवीयजी का आदर करते हैं, उनकी भावना के प्रति हमारी सहानुभूति है, और हम चाहते हैं कि साम्प्रदायिक निर्णय रद्द हो । पर विभिन्न सम्प्रदायों को निकट ला कर ही वह बदला जा सकता है । साम्प्रदायिक निर्णय को रद्द करने की घोषणा करके यह सम्भव नहीं होगा । मालवीयजी के ढंग से तो वह स्थायी बन जायगा । सरदार पटेल ने कहा कि इस प्रश्न पर पृथक् पार्टी बनाना भारी गलती है । उन्होंने मालवीयजी से अनुरोध किया कि वे नेशनलिस्ट पार्टी विघटित कर दें । डाक्टर आन्सारी ने कहा कि नेशनलिस्ट मुसलमान अपने पुराने विचारों पर दृढ़ हैं, और वे सब सम्प्रदायों के सहयोग से समस्या हल करने का प्रयत्न करेंगे । कांग्रेस ने भारी बहुमत से मालवीयजी के संशोधन को नामंजूर करते हुए मूल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ।

चुनाव

वम्बई अधिवेशन के बाद ही केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों का चुनाव था । यद्यपि बिहार, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, महाराष्ट्र के बहुत से कार्यकर्ता साम्प्रदायिक निर्णय पर मालवीयजी जैसे विचार रखते थे, पर वे उस समय तक बंगाल में ही अपनी पार्टी का सघटन कर पाये थे । वहाँ उनकी पार्टी को चुनावों में काफी अच्छी विजय प्राप्त हुई । वहाँ करीब-करीब सभी सीटों पर नेशनलिस्ट पार्टी विजयी हुई । सतीशचन्द्र बोस, अखिल, चन्द्र दत्त, माखन सेन, प्रभृति नेताओं ने पार्टी की ओर से विजय प्राप्त की । पंजाब में भी कांग्रेस एक ही स्थान जीत सकी । बरार से अणे साहब निर्विरोध चुन लिये गये । युक्त प्रान्त

से मालवीयजी की भी निर्विरोध चुने जाने की सम्भावना थी, पर मतदाताओं की सूची में उनका नाम न होने के कारण वे चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं हो सके। कुल मिला कर कांग्रेस पार्टी ४४ स्थान, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ११ स्थान प्राप्त कर सकी। इस चुनाव के बाद भी साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध मालवीयजी का प्रचार जारी रहा। पर जैसा कि पट्टाभि सीतारमैया ने स्वीकार किया है, केन्द्रीय असेम्बली में नेशनलिस्ट पार्टी "साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न को छोड़ कर और सब मामलों में कांग्रेस के साथ थी"।^१

साम्प्रदायिक-निर्णय-विरोधी कांग्रेस

मालवीयजी की प्रेरणा से २३-२४ फरवरी सन् १९३५ को दिल्ली में श्री० सी० वाइ० चिन्तामणि की अध्यक्षता में साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध एक सम्मेलन आयोजित हुआ। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि साम्प्रदायिक निर्णय ब्रिटिश सरकार का निर्णय है, उसे पक्षनिर्णय नहीं समझा जा सकता। ब्रिटिश अफसरों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार ही, उन्होंने कहा, साम्प्रदायिक समस्या को इतना भयंकर रूप देने को उत्तरदायी है, और स्वराज्य मिलने के बाद ही साम्प्रदायिक समस्या हल हो सकती है। साम्प्रदायिक निर्णय गलत है, क्योंकि वह सिंध और सीमाप्रान्त तथा पंजाब और बंगाल में बहु-संख्यकों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था करता है, पंजाब और बंगाल के हिन्दुओं के लिए उनकी आवादी से भी कम स्थान सुरक्षित करता है, और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पर पृथक् निर्वाचन पद्धति लादता है, यूरोपियनों को बहुत ही अधिक स्थान प्रदान करता है। चिन्तामणिजी ने कहा कि साम्प्रदायिक निर्णय की तरह भावी संविधान की रूपरेखा भी निन्दनीय है।^२

२४ फरवरी को कांग्रेस ने सर्वसम्मति से मालवीयजी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए घोषित किया कि साम्प्रदायिक निर्णय निन्दनीय है, क्योंकि वह हिन्दुओं और सिक्खों के लिए विशेषरूप से "अन्यायपूर्ण" है, उससे "साम्प्रदायिक कलह" बढ़ेगी, वह "राष्ट्रविरोधी और लोकतन्त्रविरोधी" है, और उसके कारण "जनता की दशा को सुधारने के निमित्त विधान सभाओं

१. पट्टाभि सीतारमैया : हिस्ट्री आफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जि० १, पृ० ५९४।

२. इंडियन क्वाटरली रजिस्टर, सन् १९३५, जि० १, पृ० ३१५-३२४।

के लिए गैरसाम्प्रदायिक आधार पर काम करना बहुत कठिन होगा" और वह "भारत के ऊपर ब्रिटेन के आधिपत्य को दृढ़ करेगा" ।^१

इस प्रस्ताव को पेश करते हुए मालवीयजी ने कहा कि यह साम्प्रदायिक निर्णय "स्वशासन के वृक्ष को जड़ पकड़ने नहीं देगा, और इससे यूरोपियनों को छोड़ कर किसी दूसरे सम्प्रदाय का भला होनेवाला नहीं है । इसका विरोध हम सब का राष्ट्रीय कर्तव्य है" ।^२

काफरेन्स ने मालवीयजी की अध्यक्षता में कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर, सर प्रफुल्लचन्द्र राय, श्री० सी० वाई० चिन्तामणि आदि बहुत से सुविख्यात सज्जनों की कमेटी गठित की, जिसने मालवीयजी के नेतृत्व में लन्दन को एक डेपुटेशन भेजने का निश्चय किया ।

इस काफरेन्स के जवाब में बहुत से प्रतिष्ठित मुसलमानों ने १ मार्च को दिल्ली में ही नवाब ढाका की अध्यक्षता में एक काफरेन्स आयोजित की, जिसने निश्चय किया कि यद्यपि साम्प्रदायिक निर्णय पूरे तीर पर सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि वह मुसलमानों की सब मांगों को पूरा नहीं करता, फिर भी यह काफरेन्स उसे गंजूर करती है ।

केन्द्रीय असेम्बली में बहस

कांग्रेस पार्टी के नेता श्री भूला भाई देसाई ने असेम्बली में प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ज्वाइन्ट पार्लियामेन्टरी कमेटी (संयुक्त संसदीय कमेटी) की रिपोर्ट की योजना के आधार पर कोई विधान तैयार न किया जाय । जिना साहब ने इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित लम्बा संशोधन प्रस्तुत किया :—

१. यह कि असेम्बली साम्प्रदायिक निर्णय को स्वीकार करती है, जब तक कि विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा उसके विकल्प के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं होता ।

२. प्रान्तीय सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस सदन की राय है कि वह बहुत ही असन्तोषजनक और निराशाजनक है, क्योंकि उसमें बहुत से आपत्तिजनक तत्त्व सम्मिलित हैं, विशेषरूप से दूसरे सदनों की स्थापना, गवर्नरों के असाधारण और विशेष अधिकार, पुलिस नियमों, खुफिया सेवाओं और गुप्तचर विभागों के सम्बन्ध में व्यवस्था, जिन्होंने कार्यपालिका और विधानपालिका के वास्तविक नियंत्रण और उत्तरदायित्व को प्रभावहीन बना दिया है, और इसलिए

जब तक ये आपत्तिजनक तत्त्व दूर नहीं किये जाते, तब तक वह भारतीय जनमत के किसी वर्ग को सन्तुष्ट नहीं करेगी।

(३) केन्द्रीय सरकार की योजना के सम्बन्ध में जो अखिल भारतीय संघ के नाम से विख्यात है, इस सदन की निश्चित राय है कि वह बुनियादी तौर पर खराब है, और ब्रिटिश भारत की जनता को विल्कुल ही मंजूर नहीं है, और इसलिए यह सदन भारत सरकार से संस्तुति करता है कि वह सम्राट् की सरकार को सलाह दे कि वह इस योजना के आधार पर कोई कानून न बनाये, और अनुरोध करता है कि वह विचार करे कि किस तरह ब्रिटिश भारत में वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाये, और इस दृष्टि से बिना विलम्ब के भारतीय जनमत के परामर्श से सारी स्थिति पर विचार करने के लिए फार्वाई करे।

इस संशोधन के पहले भाग पर कांग्रेस की ओर से यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि सदन साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार करता है और न, रह करता है, पर इस संशोधन के पक्ष में केवल कांग्रेस पार्टी के ४४ सदस्यों ने वोट दिया, और इसलिए वह भारी बहुमत से गिर गया।

जिना साहब के अनुरोध पर संशोधन के पहले भाग पर अलग से वोट लिये गये। कांग्रेस पार्टी तटस्थ रही, नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने इसके विरोध में राय दी। मुसलमानों और सरकारी सदस्यों की राय से जिना साहब का यह संशोधन स्वीकार हो गया। जिना साहब के संशोधन के अन्य दो खण्डों का सरकार के प्रवक्ताओं और समर्थकों ने डट कर विरोध किया, पर कांग्रेस पार्टी, नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तथा जिना साहब के समर्थकों के वोटों से वे भी असेम्बली ने स्वीकार कर लिये। इस तरह जिना साहब का पूरा संशोधन स्वीकार हो गया।

जिना साहब की विजय पर भारतीय मुसलमान प्रसन्न थे, पर साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में असेम्बली के निष्पक्ष से हिन्दू जनता क्षुब्ध थी। कांग्रेस ने अनुभव किया कि उसकी तटस्थता निरर्थक सिद्ध हुई। उसके सदस्य साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर न तो हिन्दू जनता के भावों को, जिन्होंने उन्हें वोट दिये थे, अभिव्यक्त कर सके, और न विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण को पुष्ट कर सके। अपनी इस नीति से कांग्रेस न तो मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित कर सकी, और न अपने को साम्प्रदायिक वादविवाद से अलग रख सकी।

जिना-राजेन्द्र बाबू वार्ता

२२ जनवरी सन् १९३४ को कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से राजेन्द्र प्रसादजी ने साम्प्रदायिक निर्णय के विकल्प की तलाश में जिना साहब से बातचीत शुरू की। बातचीत का सिलसिला १ मार्च तक चलता रहा। पर प्रयास सफल नहीं हुआ।

इस बातचीत के शुरू में ही राजेन्द्र प्रसादजी ने जिना साहब से कह दिया था कि “यदि वह मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों को कायम करने पर तुले होंगे, तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम अलग चुनाव को राष्ट्रीयता की दृष्टि से इतना घातक मानते हैं कि यदि वह रह जाय तो किसी समझौते से कोई काम न होगा। इसलिए बातचीत इसी आधार पर होगी कि वह अलग निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने पर तैयार हो जाय। इस पर उनकी ओर से यह प्रश्न हुआ कि जो चीज मुसलमानों को मिल चुकी है और वे इसे कुछ दिनों से काम में लाते रहे हैं, इसके बदले में उनको जब तक कुछ निश्चित रूप में न मिले तब तक उनको मनाना और राजी करना सम्भव न होगा।”^१ राजेन्द्र प्रसाद जी ने मुसलमानों के लिए उतने ही स्थान मान लिये, जितने उनको साम्प्रदायिक निर्णय में मिले थे।^२ जिना साहब के आग्रह पर राजेन्द्र प्रसाद जी ने यह बात भी मान ली कि “मतदाताओं में उनकी संख्या आबादी के अनुपात में हो”।^३ राजेन्द्र प्रसादजी ने अपनी ‘आत्मकथा’ में लिखा है कि सिक्खों ने इसका जवर्दस्त विरोध किया, पंजाब के कुछ व्यक्तियों ने इसे मान लिया, पर बंगाल के हिन्दू किसी तरह पर मानने को राजी न हुए।^४ जब पंडित मालवीयजी से बातें हुईं, तब उन्होंने सिक्खों और बंगाल के हिन्दुओं का हवाला देते हुए कहा कि जब तक वे नहीं मानेंगे, तब तक वह कुछ नहीं कर सकते।^५ इसके बाद राजेन्द्र प्रसादजी ने जिना साहब से बहस की कि वे इस माग पर न अडें, क्योंकि इसमें कोई तत्त्व की बात नहीं है। जहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा बहुमत है, वहाँ सैकड़ों एक या दो की कमी से चुनाव के नतीजे पर कोई विशेष प्रभाव या फर्क नहीं पड़ेगा। पर वह इस पर राजी नहीं होते थे। कांग्रेस की ओर से मैं (राजेन्द्र प्रसाद) उसे मान लेने को भी राजी था। पर उन्होंने इस पर जोर दिया कि पंडित मालवीयजी की अनुमति भी आवश्यक है, क्योंकि

१. राजेन्द्र प्रसाद . आत्मकथा, पृ० ४२५।

२. वही, पृ० ४२५।

३. वही, पृ० ४२६।

४. वही, पृ० ४२६।

५. वही, पृ० ४२६।

समझौता अगर हुआ भी, और पड़ित मालवीयजी के नेतृत्व में साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन होता ही रहा, तो मुसलमानों को इससे कोई लाभ न होगा।^१ जब मालवीयजी से फिर बातें हुईं तब उन्होंने साफ कह दिया कि जितनी जगहें मुसलमानों को मिली हैं, विशेषकर बंगाल और केन्द्र में, उन्हें भी घटाना चाहिए, और जब तक वे घटायी न जायेंगी, तब तक वे राजी नहीं हो सकते। इधर श्री जिना साहब भी इस बात पर तुल गये कि जब तक पड़ित मालवीयजी का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वे राजी नहीं होंगे। अपनी ओर से वे कहते थे कि मुसलमान नेताओं की मजूरी वह दे सकेंगे।^२

राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा है: "यद्यपि यह बातचीत कांग्रेस की ओर से मैंने शुरू की थी—और कांग्रेस तथा मुस्लिम लोग के अध्यक्षों के बीच ही यह चली थी, तथापि अन्त में वह इसलिए टूट गयी कि मिस्टर जिना केवल कांग्रेस के साथ समझौता करने को राजी नहीं हुए और हिन्दू सभा की अनुमति जरूरी समझने लगे।"^३

समझौता नहीं हो सका, इसका राजेन्द्र प्रसादजी को बहुत अफसोस रहा, क्योंकि वे समझते थे कि जिन शर्तों पर वे समझौता करना चाहते थे और जिन पर उन्होंने जिना साहब को राजी कर लिया था वे शर्तें देश के लिए हितकर होती। इससे अधिक अफसोस इसलिए हुआ कि जिस कारण समझौता नहीं हो सका, वह ऐसी बात थी जिसका कोई विशेष महत्त्व नहीं था। उसको न मानना अथवा उस पर जिद्द करना उनके खयाल में दोनों ही बेकार थे।^४

सन् १९३५ में मालवीयजी और हिन्दू महासभा के अध्यक्ष भाई परमानन्द के विचारों में इतना गहरा मतभेद था कि हिन्दू सभा की ओर से जिना साहब को कोई आश्वासन देना या किसी समझौते को स्वीकार करना मालवीयजी के लिए सम्भव नहीं था। वे कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के नेता अवश्य थे और बंगाल में सन् १९३४ के चुनाव में उनकी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई थी, इसलिए बंगाल की जनता का प्रतिनिधित्व करने का उन्हें लोकतान्त्रिक अधिकार अवश्य था; पर बंगाल के उन नेताओं की अवहेलना कैसे की जा सकती थी जिन्होंने इसी प्रश्न पर चुनाव लड़कर जनता का विश्वास प्राप्त किया था। इसीलिए मालवीयजी ने राजेन्द्र प्रसाद जी से कहा था कि वे बंगाल के लोगों से बात

१. वही, पृ० ४२६।

३. वही, पृ० ४२७।

२. वही, पृ० ४२६-४२७।

४. वही, पृ० ४२७।

करें। सिक्खों से मालवीयजी के बहुत अच्छे सम्बन्ध थे। पर सिक्खों का प्रतिनिधित्व करने का या उनकी ओर से मुसलमानों से समझौता करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। जिना साहब तो संयुक्त निर्वाचन पद्धति के पुराने समर्थक थे। पर हिज हाइनेस आगा खाँ, सर मुहम्मद शफी, सर फजले हुसेन आदि मुस्लिम नेताओं ने उनकी बात कभी नहीं मानी, और सन् १९३४ के चुनावों में, कोई ऐसी घटना नहीं घटी, जिसके आधार पर यह मान लिया जाय कि इस सम्बन्ध में जिना साहब का समझौता सब मुसलमान नेता स्वीकार कर लेते। दूसरी तरफ सन् १९३४ के चुनावों में कांग्रेस को भारी विजय हुई थी और उसे भारतीय जनता का, विशेष रूप से हिन्दू मतदाताओं का, प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार था। वह जनता के नाम पर किसी विषय पर किसी से समझौता कर सकती थी। जिना साहब भी साम्प्रदायिक समस्या पर कांग्रेस से समझौता कर सकते थे।

नेहरूजी की आलोचना

यद्यपि पंडित जवाहर लाल नेहरू नेशनलिस्ट मुसलमानों के दृष्टिकोण से तथा साम्प्रदायिक प्रश्न पर कांग्रेस के निर्णय से असन्तुष्ट थे, और बंगाल के हिन्दुओं की परेशानियों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते थे, पर उन्हें कांग्रेस का विरोध तथा उसके लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का गठन असह्य था। उन्होंने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा है : "नेशनलिस्ट पार्टी और उससे भी अधिक हिन्दू महासभा और दूसरी साम्प्रदायिक संस्थाएँ सम्भवतः इस प्रदान (साम्प्रदायिक निर्णय) पर नाराज थी, पर उनकी समीक्षा उस निर्णय के समर्थकों की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिद्धान्तों पर आधारित थी, जिसने उन्हें एक विचित्र नीति को अभिग्रहण करने के लिए प्रेरित किया और कर रही है, जो सरकार को अवश्य ही खुश करनेवाली होगी। निर्णय से परेशान, वे दूसरे अत्यावश्यक विषयों में अपने विरोध को सरकार द्वारा निर्णय को अपने पक्ष में बदलवाने की आशा में हलका कर रहे हैं। हिन्दू महासभा इस मामले में दूर तक चली गयी है।"

जवाहर लालजी का यह विश्लेषण हिन्दू महासभा पर पूरे तौर पर लागू होता था, पर कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी पर लागू नहीं होता था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसी पुस्तक में स्वीकार किया है कि जब तक मालवीयजी उसके

प्रमुख मनीषियों में से एक थे, तब तक हिन्दू महासभा अपनी साम्प्रदायिकता के बावजूद राजनीति में प्रतिक्रियावादी नहीं थी, और इस समय उसका नेतृत्व मालवीयजी के हाथ में नहीं था ।^१ मालवीयजी की राजनीतिक समीक्षा धीरे-धीरे नरम पड़ जाने के बजाय अधिक कड़ी होती गयी ।

यह ठीक है कि मालवीयजी और कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की सन् १९३४ की घोषणाएँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी धारणाओं पर आधारित नहीं थी, पर उन्हें तो कम से कम उस समय तक गांधीजी और कांग्रेस ने भी स्वीकार नहीं किया था । पर जवाहरलालजी का यह समझना कि कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की धारणाएँ, उसका दृष्टिकोण गवर्नमेंट के सिद्धान्त पर आधारित था बिल्कुल गलत था । मालवीयजी और कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की नीतिरिति और गतिविधि उन लोकतान्त्रिक और स्वतंत्रता-संबन्धी सिद्धान्तों पर आधारित थी जिन्हें कांग्रेस और सम्भवतः नेहरूजी भी पूरे तौर पर स्वीकार करते थे । अन्तर केवल इतना था कि जबकि कांग्रेस साम्प्रदायिक निर्णय पर गोल बातें करती थी, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक और स्वतंत्रता-सम्बन्धी सिद्धान्तों के आधार पर खुले तौर पर साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध करती थी ।

जवाहरलालजी ने यह भी लिखा है • “तथाकथित कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का व्यवहार मुझे विशेषरूप से शोचनीय प्रतीत हुआ । साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध उसका तीव्र विरोध एक आदमी समझ सकता है, पर अपनी पोजीशन को दृढ़ करने के लिए उन्होंने उग्र साम्प्रदायिक सस्थाओं से अपने को सम्बद्ध कर लिया, सनातनियों से भी जिनसे अधिकतम प्रतिक्रियावादी ग्रुप, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से हिन्दुस्तान में कोई दूसरा नहीं है, और बहुत ही बदनाम किस्म के बहुत से राजनीतिक प्रतिक्रियावादियों से ।”^२

नेहरू साहब की प्रतिक्रियावाद की व्याख्या कितनी व्यापक थी, इसका पता उनकी आत्मकथा के पढ़ने से कुछ-कुछ चल सकता है । इस व्याख्या के अनुसार तो सम्भवतः वे सब जो कांग्रेस का विरोध करते थे, और कांग्रेस में उनकी विचारधारा का विरोध करते थे, किसी न किसी अंश में प्रतिक्रियावादी थे । वे गांधीजी का बहुत आदर करते थे, उन्हें देश की सबसे बड़ी विभूति मानते थे, उनके नेतृत्व में काम करना अपने लिए बड़े गौरव की बात समझते थे, पर नेहरू जी की प्रतिक्रियावाद की छाप से वे भी नहीं बच पाते थे । इस व्यापक व्याख्या

सैं यदि मूल्यांकन किया जाय तो कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के संगी-साथी ही क्या, सारी पार्टी स्वयं प्रतिक्रियावादी थी, और कांग्रेस के नेताओं में से भी कुछ ही अपने को प्रगतिशील या क्रान्तिकारी होने का दावा कर सकते थे। पर इस व्यापक व्याख्या को भुलाकर 'नेहरू साहब' के वक्तव्य पर विचार किया जाय तभी नेहरू साहब के इस वक्तव्य की सही-सही जाच हो सकती है।

देश की साम्प्रदायिक संस्थाओं में हिन्दू महासभा मालवीयजी के सबसे निकट थी। वह चाहती थी कि मालवीयजी के साथ या उनसे मिलकर वह साम्प्रदायिक प्रश्न पर चुनाव लड़े, पर मालवीयजी ने हिन्दू महासभा को कौंसिलो का चुनाव लड़ने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया, और कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनावों के सम्बन्ध में हिन्दू महासभा से कोई गठबन्धन नहीं किया। इसका हिन्दू महासभा के अध्यक्ष भाई परमानन्द को बहुत दुःख था। हिन्दू महासभा के बहुत से सदस्य और समर्थकों ने, तथा कांग्रेस की गतिविधि से रुष्ट बहुत से प्रतिक्रियावादी और उदारवादी तत्त्वों ने कांग्रेसी प्रत्याशियों के विरुद्ध कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन जरूर किया होगा। पर क्या कांग्रेस कह सकती है कि सन् १९३४ में केवल क्रान्तिकारी और प्रगतिशील मतदाताओं ने ही उसे वोट दिये। यदि सन् १९३४ के चुनाव में जिन लोगों को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, और जिन मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया था वे सब क्रान्तिकारी होते, तो उसी वर्ष भारत की राजनीतिक दशा कुछ की कुछ हो जाती। कौन कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता श्री भूलाभाई देसाई और उपनेता खान अब्दुल क़यूम खा की तुलना में नेशनलिस्ट पार्टी के नेता एम० एस० अणे तथा उसके सदस्य बी० एन० ससमल, अखिल चन्द्र दत्त, माखन सेन, सतीश चन्द्र बोस की देशसेवाएं नगण्य थी, और वे उनसे कम देशभक्त थे।

नेहरू साहब को दुःख था कि कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी ने सनातनियों से भी, जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों बातों में सबसे प्रतिक्रियावादी थे, सम्पर्क स्थापित किया। नेहरू साहब अज्ञेयवादी या नास्तिक थे, उनकी परिभाषा में सभी धर्मावलम्बी समाज के प्रतिक्रियावादी तत्त्व माने जाने चाहिए। फिर केवल सनातनियों को ही सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी बताने का क्या अर्थ है?

जो भी हो, इस सम्बन्ध में मालवीयजी और अणेजी की पोजीशन बिल्कुल साफ थी। वे दोनों सनातनधर्म पर दृढ़ आस्था रखते थे। सनातनियों से सम्पर्क

बनाये रखते हुए उनमें राजनीतिक और सामाजिक चेतना पैदा करना, और देश-भक्ति की भावना संचारित करना, तथा उन्हें देश की राजनीति में सक्रिय योगदान करने के लिए तथा देश-सेवा के लिए प्रोत्साहित करना वे अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे। वे समझ नहीं सकते थे कि जिस देश में करोड़ों अपने को 'सनातनी' कहते हों, उस देश में सनातनियों में राजनीतिक चेतना पैदा किये बिना लोकतन्त्र कैसे स्थापित किया जा सकता है? वे देशभक्ति को अपने धर्म का महत्त्वपूर्ण अंग मानते थे, और इस बात का उन्होंने आजीवन प्रचार किया। वे देशोत्थान के निमित्त कतिपय पुरानी रूढ़ियों और धार्मिक परम्पराओं में आवश्यक सुधार और संशोधन करने को भी तैयार थे। पर वे देशसेवा के लिए सनातन धर्म को छोड़ना, तथा सनातनियों से अपना सम्पर्क विच्छेद करना आवश्यक नहीं समझते थे।

कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन

अप्रैल सन् १९३६ में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में नये राजनीतिक विधान की कड़ी आलोचना की, पर निश्चय किया कि आगामी प्रांतीय चुनावों में हिस्सा लिया जाय। जवाहर लाल नेहरू ने अपने अव्यक्त भाषण में ब्रिटिश साम्राज्यशाही के कुचक्रों की भर्त्सना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लक्ष्य की सिद्धि के लिए कांग्रेस के संगठन को अधिक सुदृढ़ और उसके कार्यक्रम को अधिक व्यापक बनाया जाय, तथा देश की समस्याओं पर विश्व की परिस्थिति के सदर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय। उनकी धारणा थी कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन प्रगतिशील शक्तियों का समर्थन किया जाय जो साम्राज्यवादी और फासिस्टवादी शक्तियों का विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके विचार में समाजवाद ही विश्व की समस्या का समाधान है, और कांग्रेस को किसानों और मजदूरों के हितों की पुष्टि करते हुए स्वतन्त्रता संघर्ष के लिए उनका समर्थन और सहयोग प्राप्त करना चाहिए। उनकी धारणा थी कि साम्प्रदायिक मनोवृत्ति से समझौता करके किसी पैक्ट द्वारा साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं हो सकती। उसके लिए, उनकी राय में, व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर जनता से सम्पर्क स्थापित करना होगा, मुस्लिम जनता को समझाना होगा कि हिन्दू और मुस्लिम जनता के आर्थिक हित समान हैं और उन दोनों के संयुक्त प्रयासों द्वारा ही उन आर्थिक हितों की पुष्टि और वृद्धि सम्भव है।

कांग्रेस की चुनाव घोषणा

अगस्त सन् १९३६ में कांग्रेस ने अपनी चुनाव घोषणा में, जिसे कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं तैयार की थी, १९३५ की शासन व्यवस्था के साथ साथ साम्प्रदायिक निर्णय को भी रद्द करने की घोषणा की। चुनाव घोषणा में कहा गया—“पूरे शासन-विधान को अलग रखकर साम्प्रदायिक निर्णय कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वाधीनता और लोकतांत्रिक शासन के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इसके कायम रहने से देश को छिन्न-भिन्न करने-वाली और बाधक शक्तियाँ पैदा होगी, आर्थिक प्रश्नों का स्वाभाविक विकास रुक जायगा, समाज की प्रगति कुन्द हो जायेगी। राष्ट्रीय विकास में बाधा उपस्थित होगी, और हिन्दुस्तान की एकता पर कुठाराघात होगा। इससे हिन्दुस्तान के किसी सम्प्रदाय या जाति को कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा, क्योंकि इससे कुछ लोगों को लाभ होगा, वह हानि की अपेक्षा तुच्छ होगा। वल्कि इसका अन्तिम परिणाम उस जाति के लिए भी हानिकर होगा जिसके लाभ के खयाल से यह बनाया जा रहा है। इससे उस तीसरे दल को लाभ होगा जो हम पर शासन कर रहा है और हमें लूट रहा है”^१। आगे चल कर यह भी कहा गया—“इस साम्प्रदायिक निर्णय से जो स्थिति पैदा हो गयी है, उसका उचित ढंग से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी स्वाधीनता के सग्राम को और भी संगीन बनाना चाहिए और साथ ही साथ इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई ऐसा उपाय ढूँढ निकालना चाहिए जो सभी जातियों और सम्प्रदायों को कबूल हो, और जिससे भारत की एकता की नींव मजबूत हो”^२। इस अवसर पर कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसके सदस्य साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आवश्यक होने पर वोट करेंगे।

मालवीयजी की गतिविधि

कांग्रेस की यह घोषणा मालवीयजी की महत्त्वपूर्ण विजय थी। सम्भवतः संघर्ष यही खत्म कर देना उचित था। शायद मालवीयजी तो, जैसा कि प्रिंसिपल दोवानचन्दजी ने अपने सस्मरण में लिखा है, कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के साम्प्रदायिक-निर्णय-विरोधी वक्तव्य पर ही पार्टी के बनाने के विचार को छोड़ने को तैयार थे,^३ पर उनके सामने उनके साथियों की मनोभावना और राजनीतिक भविष्य का प्रश्न था।

१ काल टू दि नेशन, पृ० ६।^२ वही।

३. महामना मालवीय जी वर्थ सेन्टिनरी कोमिमेंटेशन वाल्यूम, पृ० ७१८।

युक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रफी अहमद किदवई साहब ने मालवीयजी से यह समझौता किया कि चूंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के राजनीतिक लक्ष्य एक ही हैं, इसलिए राजनीतिक मामलों में ये दोनों पार्टियाँ एक ही नेता को अपना नेता मान कर काम करेंगी, परन्तु साम्प्रदायिक निर्णय (कम्युनल अवार्ड) या उसके प्रासंगिक विषयों पर नेशनलिस्ट पार्टी अपना नेता चुन कर उसी नेता के आदेशानुसार काम करेगी।

रफी साहब ने कुछ स्थान भी मालवीयजी के समर्थकों के लिए छोड़ दिये। पर कांग्रेस के कतिपय उच्च स्तरीय नेताओं को यह समझौता पसन्द नहीं आया। उन्होंने रफी साहब की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तो स्वीकार कर लिया, पर मालवीयजी से और कहीं किसी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया। फिर भी बंगाल कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने अनौपचारिक ढंग से बंगाल में विधान सभा के स्थानों के सम्बन्ध में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं से समझौता कर लिया। अन्य प्रान्तों में कोई समझौता नहीं हुआ। युक्त प्रान्त में मालवीयजी ने समझौते के अनुसार कांग्रेस के उम्मेदवारों का समर्थन किया, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर उनके पक्ष में भाषण किये। सन् १९३७ के चुनाव अभियान में यही उनका मुख्य काम था।

इन संघर्षों के बीच में ही मालवीयजी ने २८ दिसम्बर सन् १९३५ को सबसे बृद्ध कांग्रेसी नेता की हैसियत से तेजपाल सस्कृत विद्यालय बम्बई में कांग्रेस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर स्मृति शिला का उद्घाटन किया।

२९ दिसम्बर सन् १९३५ को पूना में हिन्दू महासभा के सत्रहवें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मालवीयजी ने कहा, “प्रत्येक भारतीय को संकल्प कर लेना चाहिए कि प्राणों की बाजी लगा कर हम स्वराज्य लेंगे, और तब तक प्राणपण से इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे जब तक हमारे दम में दम है।” इन्होंने इस अवसर पर हिन्दू महासभा को हरिजनोद्धार पर अपनी सारी शक्ति केन्द्रित करने की सलाह दी। पर जब हिन्दू महासभा के अन्य नेता इसके लिए राजी नहीं हुए, तब वे हिन्दू महासभा से अलग हो गये, यद्यपि सम्भवतः इसकी घोषणा उन्होंने कभी नहीं की। उन्हें वीर सावरकर, डाक्टर मुजे और भाई परमानन्द की नीति-रीति पसन्द नहीं थी।

जनवरी सन् १९३६ में अखिल भारतीय सनातन धर्म महासभा का कार्यक्रम निश्चित करते समय “हिन्दुओं के विभिन्न सम्प्रदायों का संगठन करना एवं

उनमें धार्मिक तितिक्षा तथा एकता का भाव बढ़ाना, और देश के भिन्न-भिन्न धर्मों को माननेवाले भाइयों में सद्भावना और मेल बढ़ाना” मालवीयजी ने उसका विशिष्ट कार्य निर्धारित किया।

उसके कुछ दिन बाद जब एक समय बातचीत करते हुए इस पुस्तक के लेखक ने मालवीयजी का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया कि डाक्टर मुंजे हिन्दू राष्ट्र के सिद्धान्त को मानते हैं, तब उन्होंने बड़े ऊँचे स्वर में कहा ‘‘मैं इसे नहीं मानता।’’ मालवीयजी हिन्दू समाज की रक्षा के लिए आतताइयों का विरोध और अत्याचार का दमन अनिवार्य रूप से आवश्यक समझते थे, पर वे यह भी सदा याद रखना जरूरी समझते थे कि ‘‘भारतवर्ष केवल हिन्दुओं का देश नहीं, यह तो मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों का भी देश है। यह देश तभी समुन्नत और शक्तिशाली हो सकता है, जब भारतवर्ष की विभिन्न जातियाँ और यहाँ के विभिन्न सम्प्रदाय पारस्परिक सद्भावना और एकात्मकता के साथ रहे, और स्वशासित संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करें।’’

२४. अन्तिम दस वर्ष

(१९३७-१९४६)

डी० ए० वी० कालेज

मालवीयजी की सनातनधर्म पर दृढ़ निष्ठा थी और आर्यसमाज द्वारा उसकी कड़ी आलोचना उन्हें बुरी लगती थी। पर वे आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द को विद्वान्, तपस्वी और राष्ट्र-निर्माता मानते थे। मालवीयजी ने अक्टूबर सन् १९३६ में डी० ए० वी० कालेज, लाहौर के जुवली समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा : “स्वामी दयानन्दजी ने ऐसे समय पर अपना काम प्रारम्भ किया, जब सब ओर अविद्या का अंधकार फैला हुआ था। यह उनकी तपस्या और देश-प्रेम का ही फल था कि उन्होंने जीते जी वैदिक सभ्यता के दर्शन किये, क्योंकि वैदिक सभ्यता ही संसार की सबसे पुरानी सभ्यता है।”

फैजपुर अधिवेशन

दिसम्बर सन् १९३७ में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में मालवीयजी ने कहा : “हम अंग्रेजी राज्य सहन नहीं कर सकते। हम अपना शासन अपने आप कर सकते हैं। शासन करने की हमारी वह शक्ति क्षीण नहीं हो गयी है, जो हमारे पूर्वजों में थी। संसार के सभी देशों ने यहाँ तक कि मिस्र ने भी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। क्या कोई भी भारतीय ऐसा है, जिसका हृदय भारत की दुर्दशा देखकर बार-बार न रोता हो? सामर्थ्य और बुद्धि रखते हुए भी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं, क्या हमें लज्जा नहीं आती? हम ब्रिटेन से मित्रता चाहते हैं। यदि ब्रिटेन हमारे मित्रता चाहता है, तो हम तैयार हैं, किन्तु यदि वह हमें अपने अधीन रखना चाहता है, तो हम उसकी मित्रता नहीं चाहते। आप स्मरण रखें कि अंग्रेज जब तक आप से डरेंगे नहीं, तब तक यहाँ से नहीं भागेंगे। अपनी कायरता को दूर भगा दो, बहादुर बनो, और प्रतिज्ञा करो कि आजाद होकर ही हम दम लेंगे।” इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि “मैं पचास वर्ष से कांग्रेस के साथ हूँ। संभव है, मैं बहुत दिन तक न जिऊँ और अपने जी में यह कलक लेकर मरूँ कि भारत अभी भी

पराधीन है। फिर भी मैं यह आशा कर सकता हूँ कि मैं इस भारत को स्वतंत्र देख सकूँगा।"

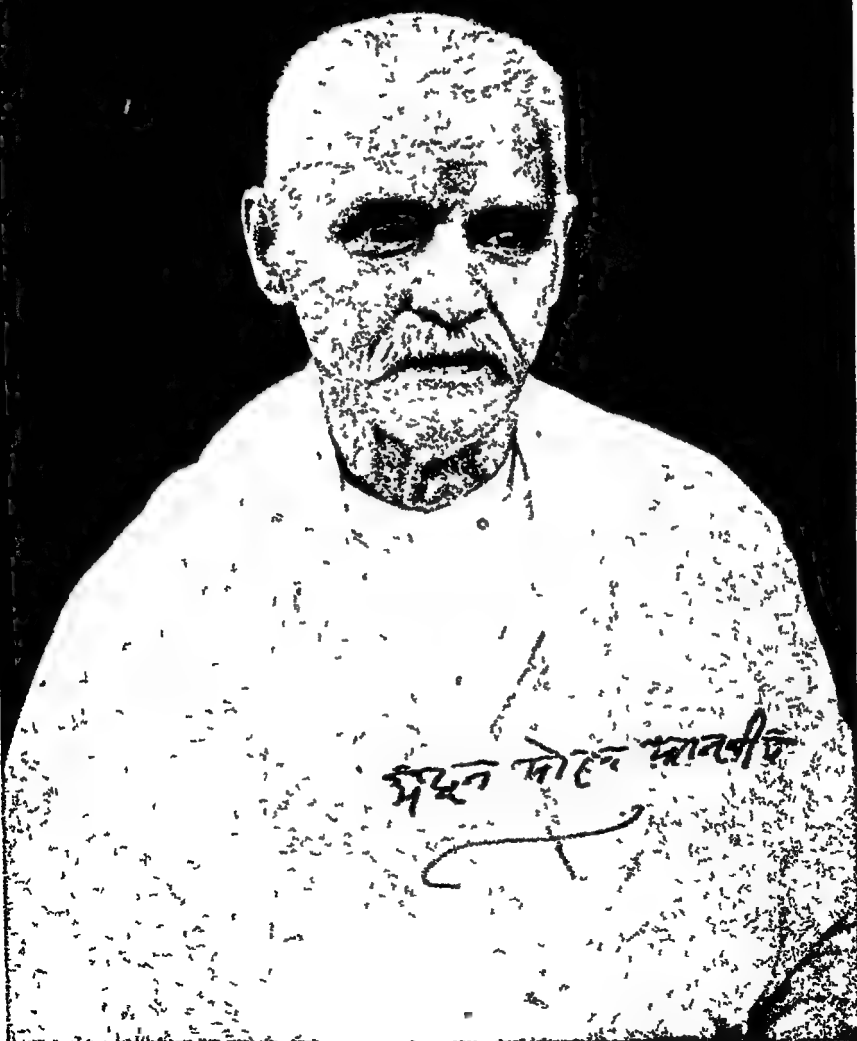
सन् १९३७ में चुनावों के बाद कांग्रेसी विधायकों की सभा में मालवीयजी ने उन्हें सलाह दी कि चुनावों में की गयी प्रतिज्ञा को तथा नयी व्यवस्था की कमियों को ध्यान में रखकर उन्हें मन्त्रिमण्डल बनाकर शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर जब कांग्रेस विधायकों ने उनकी यह बात नहीं मानी, तब मालवीयजी ने एक नये विवाद का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के बजाय पचास वर्ष से अधिक राष्ट्र की सेवा करने के बाद अपनी आयु के छिहत्तरवें वर्ष में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में नवयुवक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते हुए सक्रिय राजनीति से छुट्टी ले ली। विश्व-विद्यालय के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व फिर भी बना रहा। बहुत सी अन्य संस्थाओं के संचालन की चिन्ता भी बनी रही।

कायाकल्प

१६ जनवरी सन् १९३८ को मालवीयजी ने तपसी बाबा की देखभाल में, रामबाग (शिवकोटि, प्रयाग) में कायाकल्प का प्रयोग आरम्भ किया। ४० दिन विधिवत् एक कुटी में विश्राम करने के बाद २४ फरवरी सन् १९३८ को बाहर निकले। उस समय उनका वजन ६ पौंड बढ़ गया था, सिर के कुछ बाल भी काले हो गये थे, नेत्रों की रोशनी भी कुछ बढ़ गयी थी, और चेहरे पर भी बुढ़ापे के चिह्न कुछ कम हो गये थे। पर शीघ्र ही शरीर काफी शिथिल हो गया, और कायाकल्प का प्रयोग विफल सिद्ध हुआ। इस सम्बन्ध में मालवीयजी का कहना था कि उन्होंने कायाकल्प के नियमों का ठीक तौर पर पालन नहीं किया, इसी से उनकी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। पण्डित राधाकान्त मालवीय का विचार था कि आयुर्वेदाचार्य वाग्भट्ट ने तो आयु के मध्य भाग अर्थात् ४० वर्ष की आयु में कायाकल्प को सलाह दी थी, मालवीयजी की जैसी वृद्धावस्था में उसका प्रयोग बेकार था। पण्डित गोविन्द मालवीय का निष्कर्ष था कि कायाकल्प-कुटी में जिना कार्य लेटे रहना मालवीयजी के लिए अस्वाभाविक था, उसने उनकी जीवनधारा बदल दी, उनके परिश्रम की शक्ति को खत्म कर दिया।

विश्वविद्यालय

चाहे जो भी हो, कायाकल्प के बाद किसी भारी उत्तरदायित्व को वहन करना उनके लिए असम्भव था। काशी विश्वविद्यालय के प्रबन्ध का भार किसी



श्रीधर मोहन झावरी

दूसरे को सौपना अनिवार्य था। वे यह उत्तरदायित्व पण्डित हृदयनाथ कुंजरू को सौंपना चाहते थे। उन्हें कुंजरू साहब की योग्यता, कार्यक्षमता, कर्तव्य-परायणता, तथा सेवा भावना पर पूरा विश्वास था। वही वास्तव में मालवीयजी के सर्वोत्तम उत्तराधिकारी हो सकते थे। बहुत संकोच के बाद बहुत आग्रह पर कुंजरू साहब कुछ राजी भी हो गये थे, पर सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी के अधिकांश सदस्य यह नहीं चाहते थे कि कुंजरू साहब इस उत्तरदायित्व को वहन कर राजनीति में अपना योगदान कम कर दें। अतः मालवीयजी को किसी दूसरे व्यक्ति की खोज करनी पड़ी। अन्त में डाक्टर राधाकृष्णन् विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनने को राजी हो गये।

सितम्बर सन् १९३९ में विश्वविद्यालय के कोर्ट ने मालवीयजी का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए डाक्टर राधाकृष्णन् को विधिवत् उपकुलपति निर्वाचित किया।

प्रबन्ध के भार से मुक्त हो जाने के बाद भी विश्वविद्यालय से उनका सम्बन्ध बना रहा, और इसके साथ ही उसके अभ्युदय की चिन्ता भी उन्हें बनी रही। मालवीयजी अपने पुराने निवास-स्थान से ही विश्वविद्यालय की शुभ कामना करते रहे। यद्यपि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में उनका योगदान करीब-करीब खत्म हो गया, फिर भी परामर्श किसी मात्रा में बना रहा। जब डाक्टर राधाकृष्णन् कलकत्ता से वाराणसी आते, तो वे सबसे पहले मालवीयजी से मिलते और विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उनसे बात करते थे। यह सिलसिला उस समय तक चलता रहा, जब तक डाक्टर साहब कलकत्ता छोड़ कर स्थायी रूप से वाराणसी नहीं रहने लगे। इसके बाद भी दोनों में बातचीत होती ही रहती थी।

इस समय विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जिस बात की उन्हें सबसे अधिक चिन्ता थी, वह धन की कमी थी। वे चाहते थे कि वे किसी तरह इतने स्वस्थ हो जायें कि एक बार देश का दौरा लगाकर चन्दा जमा कर सकें, विश्वविद्यालय की आर्थिक कठिनाई दूर कर सकें, अपनी अपूर्ण योजनाओं को पूरी कर सकें। वे इस बात की अपने डाक्टर से बार-बार चर्चा भी करते थे, पर वह लाचार था, उन्हें इस योग्य कैसे बना सकता था।

मंदिर का निर्माण, धर्मोपदेशक विद्यालय की स्थापना, एक हजार वृत्तियों का प्रबन्ध, संस्कृत कालेज के भवन का निर्माण तथा विद्यार्थियों के आवास के लिए तीन-चार छात्रालयों के निर्माण, की व्यवस्था उनकी चिन्ता के विषय थे।

अस्वस्थ होते हुए भी वे विद्यार्थियों की जितनी सहायता कर सकते और उन्हें जितना अनुप्राणित कर सकते थे करते रहते थे। वे नियमित रूप से प्रति सप्ताह रविवार को गीता प्रवचन में जाते थे, पर वहा उसके प्रति छात्रों की उपेक्षा देख कर उन्हें दुःख होता था। वे बहुधा भिवाजी हाल जाते, कसरती नवयुवकों के हृष्ट-पुष्ट शरीर को देख कर प्रसन्न होते, उन्हें आशीर्वाद देते थे। वास्तव में इस समय शरीर-सम्पत्ति की रक्षा और वृद्धि उनके उपदेश का विशेष विषय बन गया था। जो विद्यार्थी उनसे मिलता, उसे वे कसरत करने की प्रेरणा प्रदान करते थे। विद्यार्थियों के प्रति उनका स्नेह अतुलनीय था। छात्रों के दुर्व्यवहार तथा शैशवियों के समाचार उन्हें अवश्य दुःखी करते थे। उनके प्रति उपेक्षा इस दुःख और चिन्ता से उनकी रक्षा किसी अंश में अवश्य कर सकती थी। पर स्नेह ही वास्तव में उनकी संजीवनी थी, यही उनके जीवन का मूलधार था। विश्वविद्यालय के ऊँचे-ऊँचे भवन तथा वहा के प्राकृतिक सौन्दर्य के दृश्यों से कही अधिक छात्रों की चहल-पहल उन्हें आनन्दित करती थी। शारीरिक कष्ट और मानसिक चिन्ता के बीच वे ही उनकी आशा की किरण, उनके सन्तोष का स्रोत थे।

सक्रिय राजनीति तथा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध से अवकाश ले लेने के बाद भी मालवीयजी का सनातनधर्म सभा से पुराना सम्बन्ध बना रहा। उनके निवास-स्थान पर ही सभा का कार्यालय था, यही से साप्ताहिक "सनातन धर्म" प्रकाशित और वितरित होता था, धर्मोपदेश में संलग्न पंडितों को पुरस्कार और प्रोत्साहन प्राप्त होता था, तथा गौरक्षा और गोवर्धन का काम होता था।

महारथ्याग

८ अगस्त सन् १९४० को द्वितीय विश्वयुद्ध के जमाने में विश्व-शान्ति के निमित्त उन्होंने महारथ्याग का अनुष्ठान किया। यह यज्ञ १० दिन तक चलता रहा। इसके प्रबन्ध की देख-भाल महामहोपाध्याय पंडित प्रमथनाथ तर्कभूषण के सुपुर्द थी। इस बीच में गवर्नर से भेंट करने के लिए वे तीन दिन बाहर गये। पर बाकी रोज प्रतिदिन सायंकाल वे स्वयं यज्ञस्थल पर जाते और डेढ़ घंटा वहा बैठते थे। ज्यादा देर तक बैठे रहने के कारण उनकी जाँघें और पीठ जकड़ जाती थी, उसमें काफी पीडा होने लगती थी। पर डाक्टरों के मना करने पर भी दोपहर तक जाघ, घुटने और पीठ में दवा की मालिश कराने के बाद वे सायंकाल को वेद का सस्वर पाठ सुनने, तथा सुगंधित यज्ञ-धूम का

सेवन करने यज्ञशाला चले ही जाते थे । अन्तिम दिन अर्थात् १७ अगस्त को उन्होंने यज्ञदेवता से प्रार्थना की कि—

- (१) संसार में शान्ति, न्याय और धर्म का राज्य स्थापित हो,
- (२) भारत को स्वराज्य प्राप्त हो, और
- (३) हिन्दुओं को हिन्दुस्तान में उचित गौरव और 'मान से रहने की स्वतंत्रता प्राप्त हो ।'

जनसेवा

अवकाश ग्रहण करने के बाद भी मालवीयजी दिन भर जनता से घिरे रहते थे । श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने, जो सन् १९४० में तीस दिन उनके साथ रहे, अपनी पुस्तक में उनकी दिनचर्या का चित्र खींचते हुए लिखा है. "मिलने वाले सात बजे से घर घेरने लगते हैं । कोई सनातन धर्म-सभाओं की बात लेकर आता है, तो कोई हिन्दू सघटन के समाचार लाता है । महाराज सब की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं, और जरूरी आदेश देते हैं । 'गाँव गाँव जाओ, घर घर जाओ, जन जन से मिलो, सबको धर्म की बातें बताओ और हिन्दुओं को संगठित करो', यही आदेश देकर वे उनको विदा करते हैं । कोई धर्मोपदेशक व्रतन लेने आता है, उसे वे व्रतन दिलाते हैं । कोई विद्यार्थी कोर्स की पुस्तकों के अभाव में अपनी पढाई की रुकावट का कष्ट लेकर आता है, वह दो रुपये, चार रुपये, पाँच रुपये जैसी आवश्यकता होती है, ले जाता है । कोई अपनी गरीबी सुनाने आता है, वह भी कुछ ले जाता है । कोई स्वरचित कविता सुनाने आता है, कोई श्लोक बनाकर लाता है, और कोई गाना सुनाने आता है । महाराज सब की सुन लेते हैं, और सब को स्वदेश के लिए, स्वजाति के लिए कविता करने और गाना सुनाने का आदेश करते हैं । कितने ही पण्डित और कितने ही कोट पण्डित वाले भी आते हैं । महाराज सबसे मिलते हैं, किसी को निराश वापस नहीं जाने देते । दिन के दूसरे पहर में वे एक घण्टा मालिश कराते हैं, फिर घण्टा-डेढ़ घण्टा भोजन और विश्राम में लगता है । बाकी दिन भर का उनका सारा समय देश और धर्म की चर्चा और भरसक दूसरों की सहायता में बीतता है । शाम को रेडियो सुनते हैं । उसके बाद भोजन होता है । फिर वही देश के भविष्य की चिन्ता, हिन्दू-संगठन और धर्म प्रचार की

उत्कंठा भा घेरती है। इस तरह दस बजे के लगभग यह वृद्ध तपस्वी अपने अरमानों में लिपटा हुआ सो जाता है।”

इस प्रकार की दिनचर्या एक स्वस्थ नवयुवक के लिए भी कष्टदायक सिद्ध हो सकती है, फिर एक ऐसे वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए जिसका सारा शरीर ढल गया हो, जो ४०-५० कदम भी चल न सकता हो, तीन चार व्यक्तियों से भी ठीक आवाज से बात न कर सकता हो, जिसके सब अङ्ग पीड़ा ले ग्रसित हों, इस प्रकार की दिनचर्या कितनी कष्टदायक होगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। पर स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट को दूर करना—यही तो मालवीयजी का जीवन था। इसी में तो वे उसकी सार्थकता अनुभव करते थे।

पारिवारिक शोक

इस जमाने में उन्हें बहुत से पारिवारिक शोक भी सहन करने पड़े। सन् १९४० में उनकी धर्मपत्नी का, सन् १९४१ में उनके सबसे बड़े भतीजे पण्डित कृष्णकान्त मालवीय का, जिनका देश, जाति और भाषा की सेवा में भरपूर योगदान था, तथा उनकी विधवा बहिन का निधन हुआ। १८ फरवरी सन् १९४३ को उनके सबसे बड़े पुत्र पण्डित रमाकान्त मालवीय का, जो शील और योग्यता में भी सब भाइयों में वरिष्ठ थे, निधन हुआ। इसी वर्ष जनवरी में उनके पुराने स्नेही पंडित बलदेव राम दवे का, तथा फरवरी में विश्वविद्यालय के चान्सलर महाराजा सर गंगा सिंह का निधन हुआ। सन् १९४४ में उनके छोटे भाई श्याम सुन्दर का निधन हुआ। इसके अतिरिक्त उन्हें कई अन्य पारिवारिक अशोभनीय और दुःसद घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। इन सबका उनके कोमल हृदय पर अवश्य ही कष्टदायक प्रभाव पड़ा।

परिवार

इन सब कष्टदायी घटनाओं में ज्येष्ठ पुत्र रमाकान्तजी का निधन सबसे अधिक कष्टदायक था। वे आयु में ही नहीं, शील और योग्यता में भी सब भाइयों में वरिष्ठ थे। उन्होंने सेवा समिति, सनातनधर्म महासभा, हिन्दू महासभा, तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संचालन में मालवीयजी के साथ काफी काम किया। उन्होंने सिरौही राज्य के दीवान, उदयपुर में नाथद्वारा के प्रमुख

प्रबन्धक, तथा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से भी समाज की सेवा की। अपने निधन के समय वे काशी विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व वहन कर रहे थे।

इस दुःखद स्थिति में उनके पुत्र गोविन्दजी, उनकी पुत्रवधु आशाजी, उनकी पुत्री मालतीजी, उनके पौत्र श्रीधर और गिरधर की सेवा-भक्ति उनका जीवन-प्राण था। मालवीयजी और गोविन्दजी के स्वभाव और दृष्टिकोण में बहुत अन्तर था। फिर भी पिता का पुत्र पर विशेष स्नेह था, और पुत्र ने भी पिता की काफी सेवा की। गोविन्दजी ने मालवीयजी के राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यों में काफी योगदान किया, तथा कई अवसरों पर उनके निजी सचिव के रूप में उनकी सेवा की। गोविन्दजी ने स्वतन्त्रता संघर्षों में डटकर भाग लिया, और जेल की यातनाएँ सही। पुत्रवधू आशादेवी तो शील और आशा की मूर्ति थी। वे बहुत धैर्य के साथ अपने कुटुम्ब, पतिदेव और स्वसुर की सेवा करती रहती थी। उन्होंने भी सन् १९३२ के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कई मास जेल के कष्टों को बहुत साहस के साथ सहन किया। रमाकान्तजी के ज्येष्ठ पुत्र श्रीधर और गोविन्दजी के सुपुत्र गिरधर पर मालवीयजी के शील और देशप्रेम की भावना की गहरी छाप थी। सौजन्य और देश-सेवा के प्रति अभिरुचि उनके सदगुण थे। सुपुत्री मालतीजी पर भी मालवीयजी के शील और सदुपदेशों की गहरी छाप थी। वे सदा सच बोलती, कड़वे सत्य को कहने से परहेज करती, तथा छलमिश्रित सत्य को बुरा समझती थी। वे अपने वक्त्रों को मालवीयजी के शील में दीक्षित करती, तथा उनसे मालवीयजी की महत्वपूर्ण सेवाओं की चर्चा करनी। वे अपने वक्त्रों को श्रीमद्भागवत, श्रीमद्भगवद्गीता और महाभारत के वे श्लोक सुनाती जो मालवीयजी को बहुत प्रिय थे, और यह भी बताती कि उनके सम्बन्ध में मालवीयजी के क्या विचार थे। उनके वक्त्रों को ऐसा प्रतीत होता मानो उनकी माता तो 'मालवीयजी की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी' ही है।

कार्य

इस स्थिति में ही मालवीयजी ने सन् १९४१ में गोरक्षा मंडल की स्थापना कर उसकी विधिवत् रजिस्टरी करायी, और नवम्बर में पण्डित यज्ञनारायण उपाध्याय को उसका उपमन्त्री नियुक्त किया। इस मंडल द्वारा बिहार, युक्तप्रान्त और मध्य प्रदेश में गोरक्षा के प्रचार तथा गोशाला के संगठन का तथा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक गोसप्ताह मनाने का प्रयत्न किया गया।

शिवपुर में जयवन आश्रम में गोशाला की स्थापना और उसका प्रबन्ध इस संस्था का मुख्य कार्य था ।

सम्बत् २००० विक्रमी की पूर्ति के समय विक्रमादित्य की स्मृति में 'अखिल भारतीय विक्रम परिषद्' स्थापित की गयी । ग्रन्थों का प्रकाशन तथा कालिदास जयन्ती समारोह और विक्रम-महोत्सव का आयोजन इसके मुख्य कार्य निश्चित हुए । पूर्व निश्चय के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी (अक्षय नवमी, सम्बत् २०००) को काली के चित्राभवन में हरिद्वार के महन्त शान्तानन्द नाथजी की अध्यक्षता में विराट उत्सव हुआ, जिसमें विद्वानों के भाषण हुए । एक वर्ष बाद 'कालिदास ग्रन्थावली' प्रकाशित हुई, जिसे अल्पमूल्य में विद्वानों और छात्रों में वितरित किया गया । इस संस्था की ओर से कई वर्ष अक्षय नवमी के दिन कालिदास जयन्ती महोत्सव मनाया जाता रहा, तथा विशिष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन होता रहा । इसके तत्त्वावधान में महाकवि कालिदास के नाटकों का भी अभिनय किया गया, कवि सम्मेलन भी आयोजित हुए ।

देश की राजनीतिक गतिविधि

सन् १९३७ के चुनावों में मद्रास, युक्त-प्रान्त, बिहार, मध्य-प्रदेश और उड़ीसा की विधान सभाओं में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया । बम्बई और सीमाप्रान्त में भी कुछ स्वतंत्र सदस्यों के सहयोग से कांग्रेस पार्टी बहुसंख्यक पार्टी बन गयी । कुछ गतिरोध के बाद इस आश्वासन पर कि गवर्नर मन्त्रिमण्डल के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, और विशेष अधिकारों का प्रयोग इस तरह होगा कि उससे गवर्नर और मन्त्रिमण्डल के पारस्परिक सम्बन्धों में कड़वाहट पैदा न हो, कांग्रेस पार्टियाँ उन सात प्रान्तों में शासन का उत्तरदायित्व वहन करने को तैयार हो गयी । सन् १९३८ में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाषचन्द्र बोस के आदेश और अनुमति तथा सरदार पटेल की सहमति से कांग्रेस पार्टी के नेता वरदोलाई ने आसाम में भी संयुक्त मन्त्रिमण्डल गठित कर लिया । ये मन्त्रिमण्डल अक्टूबर सन् १९३९ तक काम करते रहे, और उन्होंने अपने व्यवहार और क्षमता से सिद्ध कर दिया कि भारत के राजनीतिज्ञ उत्तरदायी शासन के संचालन की क्षमता और योग्यता रखते हैं । कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने वित्तीय साधनों की कमी होते हुए भी समाज-कल्याण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया । नशाबन्दी के अतिरिक्त साक्षरता और शिक्षा का विस्तार, अस्पृश्यता का निवारण, हरिजनों की दशा में सुधार, जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा, भूमिव्यवस्था में संशोधन, तथा किसानों के हितों

की रक्षा और वृद्धि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो के मुख्य काम थे । 'भूमि व्यवस्था के सुधार के लिए कई अधिनियम पास किये गये । जमींदारों के आधिपत्य और शोषण पर नियंत्रण, लगान में कमी, वेदखलियों पर रोक, किसानों के अधिकारों और हितों की पुष्टि उनके मुख्य उद्देश्य थे । करीब-करीब सभी विधान सभाओं में जमींदारों के हितों का समर्थन करते हुए मुस्लिम लीग ने इन अधिनियमों का विरोध किया । उत्तर प्रदेश में तो चौधरी खलीकुज्जमा और नवाबजादा लियाकत अली खा के नेतृत्व में मुस्लिम लीग पार्टी ने अपने विरोध की हद कर दी । उसने भूमिव्यवस्था के सुधार की योजनाओं को मुस्लिम सस्कृति पर भारी आघात घोषित किया, और उन्हें मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं की साजिश बताया । अधिनियम तो पास हो गये, पर उनके कारण कांग्रेस के प्रति मुस्लिम लीग में कड़वाहट अधिक पैदा हो गयी ।

मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू किया कि कांग्रेस एकमात्र हिन्दुओं की राजनीतिक संस्था है, वह देश में हिन्दुओं का राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करना चाहती है । उसकी सारी योजनाएँ हिन्दुत्व की भावनाओं से प्रेरित और हिन्दू धारणाओं पर आधारित होती हैं, और उन्हें चालू करते समय दूसरे सम्प्रदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता । इस सम्बन्ध में मुस्लिम लीग ने मध्य प्रदेश की त्रिद्यामन्दिर की योजना की, तथा गांधीजी की बुनियादी शिक्षा वी विशेष रूप से निन्दा की । मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो पर यह भी दोष लगाया कि वे मुसलमानों के साथ निष्कपट पक्षपात-रहित व्यवहार नहीं कर रहे हैं । उसने कहा कि मुसलमानों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर बेजा तौर पर प्रनिबन्ध लगाये जा रहे हैं । उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनकी जान-माल की रक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं हो रहा है । मुस्लिम लीग की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार में की गयी ज्यादतियों की रिपोर्टें भी तैयार करके प्रकाशित की गयी । सन् १९३८ में ही उसने अपने वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो के विरुद्ध सीधा सघर्ष (डाइरेक्ट एक्शन) करने का निश्चय किया । तनाव को शान्त करने के लिए गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, और सुभाषचन्द्र बोस ने जिना साहब से बातचीत करके समझौता करने की कोशिश की । पर मुस्लिम लीग उस समय तक कांग्रेस से कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी, जब तक कांग्रेस अपने को एकमात्र हिन्दुओं की संस्था, और मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एकमात्र राजनीतिक संस्था मानने को तैयार न हो । चूँकि कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं था, इसलिए बातचीत नहीं चल पायी । कांग्रेस मुस्लिम लीग के

आरोपो को बेबुनियाद समझता था, और फेडरल कोर्ट के चीफ जज द्वारा उनकी जात्र कराने को तैयार था। पर जिना साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए। कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो ने गवर्नरो से अनुरोध किया कि अल्पसंख्यको के हितो की रक्षा के निमित्त वे जब आवश्यक समझें, तब अपने विशेष अधिकारो का प्रयोग करें, पर गवर्नरो ने मन्त्रिमण्डलों के आदेशो और व्यवहारो में हस्तक्षेप करने की जरूरत महसूस नहीं की। जिना साहब ने गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलिथगो से अत्याचारो की शिकायत करते हुए उनसे अनुरोध किया कि इनके सम्बन्ध में वे उचित कार्रवाई करें। पर लार्ड लिनलिथगो ने भी महसूस किया कि शिकायतो में कोई विशेष तथ्य नहीं है, कांग्रेस मन्त्रिमंडलों पर मुसलमानो के विरुद्ध पक्षपात का दोष आरोपित नहीं किया जा सकता, दो-चार शिकायतें ठीक हो सकती हैं, पर उनकी सम्भावना पर व्यापक जाच कैसे करायी जा सकती है। इस तरह मुस्लिम लीग की शिकायतो और आरोपो की कोई आधिकारिक जांच नहीं हो सकी, पर मुस्लिम लीग उनका प्रचार करती रही, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ता चला गया।

विश्व-युद्ध

अप्रैल सन् १९३९ में भारत सरकार ने अदन की सैनिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए वहाँ एक सैन्य दल भेजा, और ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ने सन् १९३५ के विधान में एक नयी धारा जोड़कर केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया कि युद्ध या युद्ध के खतरे की स्थिति में वह प्रान्तीय सरकारो को आदेश दे सकती है कि उनके शासन का संचालन किस तरह हो, और केन्द्रीय विधायक शक्ति को अधिकार दिया कि वह प्रान्तीय क्षेत्रो में ऐसे कानून बना सकेगी जिनके द्वारा प्रान्तीय सरकार के शासन अधिकार केन्द्रीय सरकार या उसके कर्मचारियो को सौंपे जा सकें। ३ सितम्बर सन् १९३९ को यूरोप में युद्ध शुरू हो गया। वाइसराय ने दूसरे दिन भारत की ओर से भी युद्ध की घोषणा कर दी, और उनके आदेश पर गवर्नरो ने जिलाधिकारियों को गुप्त आदेश जारी कर दिये।

गांधीजी, नेहरूजी आदि कांग्रेसी नेताओ को ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति थी। वे युद्ध के जमाने में ब्रिटेन को परेशान करना नहीं चाहते थे। पर उन्हें ब्रिटिश सरकार और वाइसराय की ये बातें पसन्द नहीं थी। उनकी दृढ़ धारणा थी कि भारतीय जनता और उनके प्रतिनिधियो की रजामन्दी के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना सर्वथा अनुचित और अन्याय है।

वे हिटलरशाही के विरोधी तथा लोकतन्त्र के समर्थक थे, पर उनकी राय में संसार में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए फासिस्टवाद और नाजीवाद के विनाश के साथ-साथ साम्राज्यशाही का विलीनीकरण भी नितान्त आवश्यक था। उनकी यह भी धारणा थी कि भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा भी जरूरी है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कमेटी ने माँग की कि ब्रिटेन युद्ध के उद्देश्यों को घोषित करे। हिन्दुस्तान में लोकतंत्र स्थापित किया जाय, और उसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपना संविधान तैयार करने का अधिकार दिया जाय। कमेटी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत फासिस्टवाद, नाजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लोकतांत्रिक संसार से सहयोग के लिए युद्ध में शामिल हो सकता है।

ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस की ये बातें मंजूर नहीं थी। वह यह वायदा करने को तैयार थी कि जर्मनी और इटली को पराजित कर ब्रिटेन अपने साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहता, पर ब्रिटिश साम्राज्यशाही का विलीनीकरण करने की घोषणा करने को वह तैयार नहीं थी। वह केन्द्रीय शासन परिषद् में भारतीय सदस्यों की मर्यादा बढ़ाने को राजी थी, पर भारत के भावी संविधान के सम्बन्ध में वह लार्ड अर्विन की सन् १९२९ की घोषणा से आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थी।

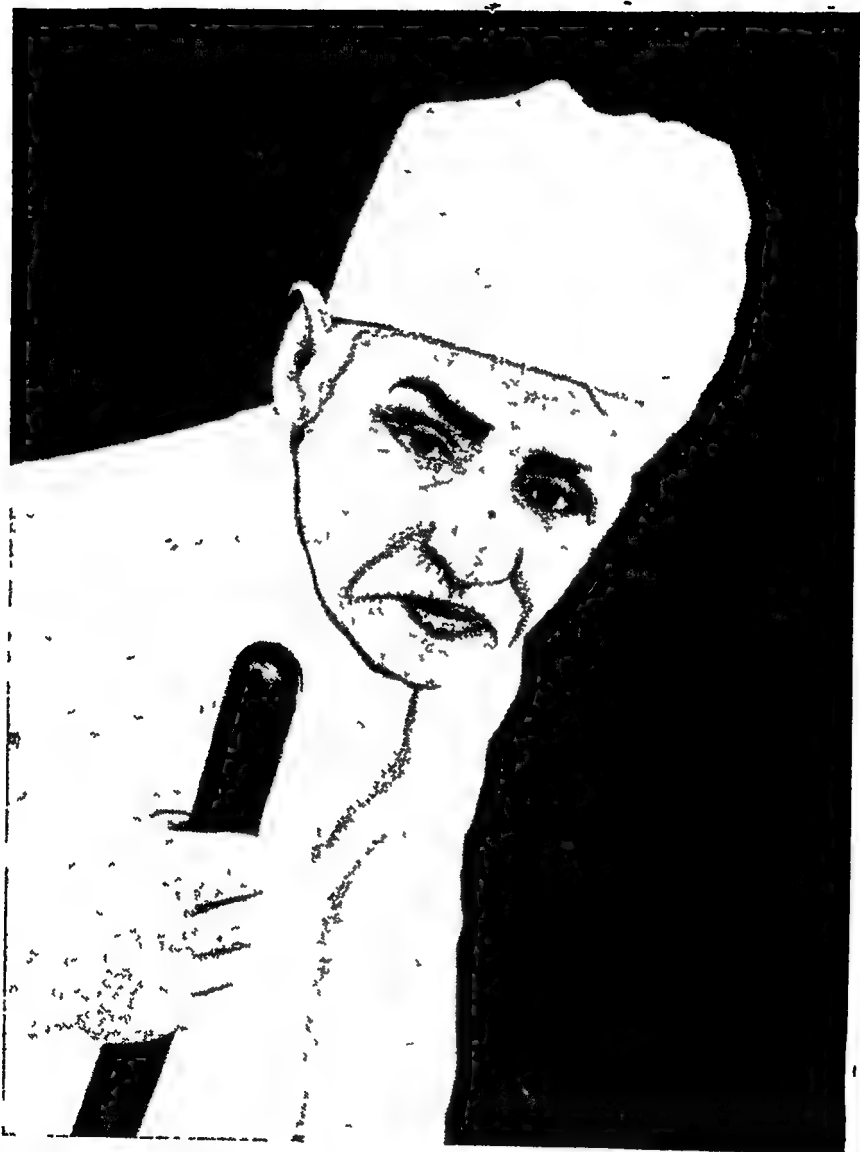
इसलिए १७ अक्टूबर को वाइसराय लार्ड लिनलिथगो ने एक वक्तव्य द्वारा स्पष्ट किया कि ब्रिटेन युद्ध से अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बल्कि सच्ची अन्तर्राष्ट्रीय नीति और शान्ति चाहता है। उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की उपलब्धि को भारत की राजनीति का अन्तिम लक्ष्य बताते हुए वायदा किया कि युद्ध के बाद सम्राट की सरकार भारत के विभिन्न सम्प्रदायों, दलों और हितों के प्रतिनिधियों से और भारतीय नरेशों से राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करेगी। उन्होंने यह भी घोषित किया कि युद्ध के प्रयासों में भारत का अधिक निकट सहयोग प्राप्त करने के लिए भारतीय नरेशों का तथा ब्रिटिश भारत के प्रमुख दलों का एक सलाहकार प्रतिनिधि-मंडल गठित किया जायगा।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने २४ अक्टूबर को इस वक्तव्य की कड़ी आलोचना करते हुए घोषित किया कि ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को किसी प्रकार का सहयोग देना साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करना होगा। उसने असहयोग की नीति

निर्धारित करते हुए कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो को इस्तीफा देने का आदेश किया, और कुछ दिन के अन्दर इन सब ने इस्तीफा दे दिया ।

‘‘ कांग्रेस और मुस्लिम लीग से वाइसराय का विचार-विमर्श चार मास तक चलता रहा । ’’ पर समस्या सुलझाने के बजाय उलझती चली गयी । वाइसराय ने कहा कि केन्द्रीय कार्यपरिपद् का विस्तार अभी हो सकता है, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में प्रान्तीय विषयों के सम्बन्ध में भी कोई समझौता हो जाय । जिना साहब ने माग की कि (१) प्रान्तों में संयुक्त मन्त्रिमण्डल गठित किये जायें, (२) मुसलमानों को प्रभावित करनेवाला कोई कानून लागू न किया जाय, अगर विधान सभा के दो-तिहाई मुसलमान सदस्य इसके विरुद्ध हो, (३) सार्वजनिक संस्थाओं पर कांग्रेस का झंडा न लगाया जाय, (४) बन्देमातरम् के प्रोग्राम के सम्बन्ध में समझौता हो, (५) मुस्लिम लीग को तोड़नेवाली सब कार्रवाइयों को कांग्रेस बन्द कर दे । उन्होंने वाइसराय से अनुरोध किया कि (१) भारत की सवैधानिक समस्या पर नये सिरे से विचार किया जाय, (२) हिन्दुस्तान के दोनों प्रमुख सम्प्रदायों की रजामन्दी के बिना कोई नया संविधान नहीं बनाया जाय, (३) फिलस्तीन के अरबों की न्यायसंगत राष्ट्रीय माग पूरी कराने के लिए ब्रिटिश सरकार प्रयत्न करे, (४) किसी मुस्लिम देश के विरुद्ध भारतीय सेना भारत के बाहर इस्तेमाल न की जाय । २२ दिसम्बर को मुस्लिम लीग के आदेश पर सारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के पदत्याग की खुशी में ‘मुक्ति दिवस’ मनाया । १३ मार्च सन् १९४० को जिना साहब ने वाइसराय से कहा कि यदि साम्प्रदायिक विवाद की समस्या का कोई समुचित समाधान नहीं होता, तो मुसलमान हिन्दुस्तान के बँटवारे की माग करेंगे । वाइसराय के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जिना साहब ने कहा कि वे तो चाहेंगे कि मुस्लिम क्षेत्र मुसलमानों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से शासित हों । २० मार्च सन् १९४० को मुस्लिम लीग ने धर्म की राष्ट्रीयता का आधार बताते हुए मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धान्त को पुष्ट किया, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों को पृथक् स्वतंत्र राज्यों में गठित करने की माग की, तथा सब अल्पसंख्यकों के लिए उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारों की पर्याप्त रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया ।

१९-२० मार्च सन् १९४० को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ । मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत की अखंडता पर जोर दिया, और कांग्रेस की माग को पुष्ट किया । कांग्रेस ने निम्नलिखित



भालवीयजी वृद्धावस्थामें*

कि गांधीजी के नेतृत्व में, जब वे उचित समझें, संघर्ष शुरू कर दिया जाय। उसने यह भी निश्चय किया कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम कोई भी बात कांग्रेस को स्वीकार नहीं होगी, और वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित विधान सभा ही देश का संविधान तैयार करेगी, और संसार के दूसरे राष्ट्रों से भारत का सम्बन्ध निश्चित करेगी।

इसी अवसर पर किशन नगर में सुभाष चन्द्र बोस ने समझौता-विरोधी सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन ने समझौते की नीति का विरोध करते हुए संघर्ष करने की जनता से अपील की, और ६ अप्रैल को संघर्ष शुरू कर देने का निश्चय किया।

इस सब के बाद भी कांग्रेस संघर्ष को टालती रही। इधर जून सन् १९४० में फ्रांस के पराजित हो जाने पर युद्ध की स्थिति काफी गम्भीर हो गयी, और वाइसराय को भारतीय जनता से सहयोग की विशेष रूप से अपील करनी पड़ी।

उस समय जिना साहब ने मुस्लिम लीग की ओर से मांग की कि मुस्लिम भारत की अनुमति के बगैर संविधान की कोई स्थायी या अन्तरिम योजना चालू नहीं की जायेगी, गवर्नर-जनरल की कौंसिल में तथा युद्ध सलाहकार कौंसिल में मुसलमान हिन्दुओं के बराबर होंगे, यदि कांग्रेस शामिल होने को तैयार होगी, अन्यथा मुसलमान बहुसंख्यक होंगे, उन प्रान्तों में जहाँ दफा ९३ लागू है गैर-सरकारी सलाहकार नियुक्त किये जायेंगे, जिनमें आधे मुसलमान होंगे, मुसलमान सलाहकारों और सदस्यों का भी चयन मुस्लिम लीग करेगी।

कांग्रेस ने ७ जुलाई को समझौते की नयी शर्तें पेश की। उसने युद्ध के लक्ष्यों की माँग को छोड़ते हुए माँग की कि सरकार भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग स्वीकार करे, और युद्धकाल के लिए मौजूदा शासन व्यवस्था के अन्दर ही ऐसी राष्ट्रीय सरकार गठित करे, जिसका अध्यक्ष वाइसराय हो, और जिसका एक सदस्य कमांडर-इन-चीफ हो, पर जिसके अन्य सब सदस्य भारतीय हो।

८ अगस्त सन् १९४० को वाइसराय ने एक वक्तव्य प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने गवर्नर-जनरल की कौंसिल के विस्तार का और युद्ध सलाहकार समिति गठित करने का वायदा दोहराते हुए घोषित किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान के प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों की सभा बुलायेगी जो नये शासन-विधान का खाका तैयार करेगी, और उचित निर्णयों पर पहुँचने के लिए सरकार उसकी सहायता करेगी। उन्होंने यह भी घोषित

किया कि अधिकार किसी ऐसी शासन-प्रणाली को हस्तान्तरित नहीं किये जायेंगे जिसे भारत के राजनीतिक जीवन के सब प्रमुख तत्त्व स्वीकार करने को तैयार न हो ।

मुस्लिम लीग ने इस वक्तव्य पर सन्तोष प्रकट करते हुए कांसिल के विस्तार के सम्बन्ध में वाइसराय से कुछ प्रश्न पूछे । पर कांग्रेस ने इस वक्तव्य पर असन्तोष प्रकट करते हुए गांधीजी के नेतृत्व में उनके बताये दग पर व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निर्णय किया ।

१७ अक्टूबर सन् १९४० को भाषण की स्वतंत्रता पर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ हो गया । यह सत्याग्रह लगभग एक वर्ष तक चलता रहा । लगभग २०,००० नर-नारियो ने इसमें भाग लिया, और जेल की यातनाएँ सही ।

इस आन्दोलन के प्रारम्भ होने के कुछ दिन बाद मालवीयजी ने गांधीजी से इसमें भाग लेने की इजाजत माँगी । पर गांधीजी ने मालवीयजी की आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी ।

यद्यपि गांधीजी व्यक्तिगत सत्याग्रह के नैतिक प्रभाव से सन्तुष्ट थे, कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता राघर्ष को सामूहिक सत्याग्रह का रूप देने के पक्ष में थे ।

दिसम्बर में सब सत्याग्रही छोड़ दिये गये, और जापान युद्ध में कूद पड़ा । इस स्थिति में कांग्रेस ने सरकार के साथ इस गर्त पर सहयोग करने का निर्णय किया कि ब्रिटेन ऐसी स्थिति पैदा करे जिसमें भारत स्वतंत्रता और लोकतन्त्र के लिए युद्ध में सम्मानपूर्वक भाग ले सके ।

काफी हिचकिचाहट के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट के आग्रह पर प्रधानमन्त्री चर्चिल ने मार्च के अन्तिम सप्ताह में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिज्ञों से विचार-विमर्श के लिए भारत भेजा । उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ओर से वक्तव्य प्रसारित किया, जिसमें इस बात का वायदा किया गया कि युद्ध के बाद प्रान्तीय विधान-सभाओं के चुनाव कराये जायेंगे, और उनके नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने सदस्य और राजाओं द्वारा मनोनीति सदस्य मिल कर संविधान-सभा गठित करेंगे जो भारत यूनियन का संविधान तैयार करेगी और इस संविधान के आधार पर भारत यूनियन को ब्रिटिश कामनवेल्थ में डोमिनियन का स्टेटस प्राप्त होगा । पर इस वक्तव्य में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि कोई प्रान्त या रियासतें भारत यूनियन में शामिल न होना चाहें, तो वे अपने को स्वतंत्र यूनिटों में गठित कर सकते हैं, और इन यूनिटों को भी कामनवेल्थ में डोमिनियन स्टेटस प्राप्त होगा ।

भावी संविधान की यह योजना भारतीय राजनीतिज्ञों को पसन्द नहीं थी। मुस्लिम लीग को यह योजना मजूर नहीं थी, क्योंकि यद्यपि इसमें प्रान्तों का आत्मनिर्णय स्वीकार किया गया था, पर मुसलमानों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया गया था, और यह सम्भव था कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों के गैरमुसलमान प्रतिनिधि थोड़े से मुसलमान प्रतिनिधियों की मदद से मुसलमान बहुसंख्यकों की राय के विरुद्ध उन प्रान्तों को भारत यूनियन में शामिल कर दें। अन्य दलों के नेताओं को यह योजना नामंजूर थी, क्योंकि वह विभाजन और विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहित करती थी। उनकी धारणा थी कि प्रस्तावित प्रक्रिया भारत की एकता और रक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।

फिर भी युद्ध की गम्भीर स्थिति का ध्यान करके कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ इन शर्तों पर सहयोग करने को तैयार थी कि (१) गवर्नर-जनरल की कौंसिल एक कैबिनेट की हैसियत से काम करेगी, (२) भारतीय रक्षा-सदस्य को सेना के प्रबन्ध में प्रभावकारी अधिकार प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री चर्चिल और वाइसराय लिनलिथगो, इन दो में से एक बात भी मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए कोई समझौता नहीं हो सका। इसके बाद क्रिप्स ने जो वक्तव्य प्रसारित किया उससे कड़वाहट बढ़ गयी।

क्रिप्स-मिशन की विफलता ने गतिरोध पैदा कर दिया। उसे दूर करने के लिए राजगोपालाचारी का सुझाव था कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करके नेशनल सरकार के गठन के सम्बन्ध में उससे समझौता किया जाय, पर कांग्रेस के अधिकांश नेता और कार्यकर्ता विभाजन का सिद्धान्त स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।

मौलाना आजाद और पण्डित नेहरू सरकार के व्यवहार से क्षुब्ध थे, पर वे युद्ध की गम्भीर स्थिति में कोई संघर्ष छेड़ना उचित नहीं समझते थे। लेकिन गांधीजी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष नितान्त आवश्यक समझते थे। उनकी धारणा थी कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का अस्तित्व जापान को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण है। उनका विचार था कि भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति इतनी कटुता है कि उनके रहते वह जापान की विजय के दुष्परिणामों को सोचने को भी तैयार नहीं है। यदि ब्रिटिश सत्ता यहाँ बनी रही, तो भारत की दशा भी दक्षिणपूर्वी एशिया की तरह की हो सकती है। अंग्रेजों के चले जाने पर बहुत संभव है कि जापान भारत पर आक्रमण करने

का विचार छोड़ दे। पर यदि इसके बाद भी जापान ने आक्रमण किया, तो उसके साम्राज्यिक स्वरूप को पहचान कर भारतीय जनता अहिंसात्मक असहयोग द्वारा जापानी आक्रमण का हटकर मुकाबला कर सकती है।

८ अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत से ब्रिटिश सत्ता उठा लेने की गति करते हुए देशव्यापी अहिंसात्मक संघर्ष प्रारम्भ करने का निर्णय किया।

इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद गांधीजी वाइसराय से एक बार फिर मिलना और बातचीत करना चाहते थे। पर सरकार ने ९ अगस्त को प्रातःकाल ही गांधीजी तथा कांग्रेस के दूसरे वहुत से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष आजादी के दूसरे संघर्षों से अधिक व्यापक और भीषण था। सरकार तो कांग्रेस के सभी नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं को जल्दी से गिरफ्तार करके आन्दोलन को तीन-चार दिन के अन्दर ही समाप्त कर देना चाहती थी, पर नेताओं की गिरफ्तारी ने जनता के रोष को शान्त करने के बजाय प्रज्वलित कर दिया। जनता के विद्रोह ने भयकर भूमिगत संघर्ष का रूप धारण कर लिया। जान और माल के मौलिक भेद को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन के प्रति अहिंसात्मक व्रत का पालन करते हुए तोड़-फोड़ के जरिये ब्रिटिश साम्राज्यशाही के राजतन्त्र को ठप करना, तथा उसके युद्धसामन्थी प्रयत्नों में बाधा पहुँचाना ही इस भूमिगत आन्दोलन का मुख्य स्वरूप था।

सरकार ने आन्दोलन को दवाने के लिए काफी नियोजित ढंग से भद्रता, इनसानियत और न्याय की ताक पर रखकर सख्ती से काम लिया। उसने न्याय-विहीन अध्यादेशों का तथा अपनी पाशविक शक्ति का व्यापक प्रयोग कर आतंक का राज स्थापित कर दिया। सुरक्षा और सुव्यवस्था को पुनः स्थापित करने के नाम पर पुलिस और फौज ने अशान्त क्षेत्रों में घुसकर निर्दोष व्यक्तियों पर भी अत्याचार किये। छोटे-छोटे बच्चों को सताया गया, नवयुवकों की निर्दयता से बेतों से पीटा गया, बूढ़ों को लहलुहान किया गया, सम्मानित घरों की पर्दानशीन स्त्रियों को भी अपमानित और परेशान किया गया। सरकार की अपनी रिपोर्ट से पता चलता है कि ३१ दिसम्बर सन् १९४३ तक पुलिस ने ६०१ बार और फौज ने ६८ बार गोली चलायी। पुलिस की गोली से ७६३ आदमी मारे गये और १९४१ घायल हुए। फौज की गोली से २९७ आदमी मरे और २३८ आदमी घायल हुए। इस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि ५ बार हवाई जहाज से

से मिलते और उनसे अपनी व्यथा कहते, पुलिस के अत्याचारों का रोना रोते, अपने संगी-साथियों पर वीती बताते । मालवीयजी उन 'सबकी बातें सुनते, उन्हें धैर्य बघाते, सेक्रेटरी को आदेश देते कि सब बात विस्तार से लिख ली जायें । पर जबकि वे पीड़ितों को धैर्य रखने का उपदेश देते, स्वयं उनके दुःख में दुःखी हो रो पड़ते, स्त्रियों के अपमान तथा बच्चों की पीड़ा का समाचार सुन कर क्रोधित हो जाते । एक दिन एक बूढ़ा आया । उसने अपने कपड़े उतार कर उन्हें अपनी पीठ दिखायी कि उसे किस बुरी तरह पीटा गया है । उसे देख कर मालवीयजी जोर-जोर से रोने लगे । यह सिलसिला कई सप्ताह तक चलता रहा । इसे रोकना असम्भव था, क्योंकि वे इस बात को वर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि कोई मीलो चल कर आवे और वे उसकी बात भी न सुनें, उनके कर्मचारी उन्हें उनसे मिलने भी न दें । यह सब देख कर लेखक की अन्तरात्मा तो पुकार उठी कि यह महामना देश के नेता ही नहीं, सारे राष्ट्र के कौटुम्बिक हैं, जिस तरह एक कुटुम्ब का पिता सारे कुटुम्ब से अपने जीवन को आत्मसात कर प्रत्येक बच्चे की पीड़ा में स्वयं पीड़ा अनुभव करता है, अपने घर की बहू-बेटियों के अपमान की बात सुन कर विह्वल और क्रोधित हो जाता है, उसी तरह इस राष्ट्रपिता ने सारे राष्ट्र से अपने को ऐसा आत्मसात कर लिया है कि उनकी पीड़ा और अपमान में वह सहज रूप से दुःखी, क्रोधित और विह्वल होता है ।

उस परिस्थिति में पीड़ितों की ठीक-ठीक सहायता करना तो मालवीयजी की शक्ति के बाहर था, पर जो कुछ भी सहायता की जा सके, उसके लिए उन्होंने अपनी अव्ययता में एक कमेटी गठित की, तथा कुछ धन जुटा कर वितरित किया । उन्होंने जौनपुर, गाजीपुर, बलिया आदि जिलों में किये गये अत्याचारों का एक संक्षिप्त विवरण तैयार कराके एक पंजाबी सज्जन द्वारा जो सम्भवतः सनातन धर्म सभा के कार्य से उनसे मिलने आये थे, दिल्ली में केन्द्रीय विधान मंडल के सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और श्री के० सी० नियोगी के पास भिजवा दिया, ताकि अगस्त की घटनाओं पर असेम्बली और राजसभा में वाद-विवाद के समय उसका प्रयोग हो सके । असेम्बली में गृह-सदस्य मेक्सवेल ने कांग्रेस को उपद्रवों के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए बहुत ही अतिरजित ढंग से उनका विवरण उपस्थित किया । इस समाचार को विस्तार से सुनकर मालवीयजी विह्वल और क्रोधित हो गये । जोर से बड़े तीखे स्वर में वे कहने लगे— 'सब मर गये, किसी ने भी जवाब नहीं दिया । अत्याचारों का जिक्र नहीं किया । उन्हें शांत करने के लिए इस पुस्तक के लेखक ने उनसे कहा— "महाराज, आपने

सारा जीवन असेम्बली में गुजारा है। जब एक सज्जन बोलता हो, तब दूसरा कैसे बोलता !” यह सुन कर वे चुप हो गये। दूसरे दिन समाचारपत्रों में पण्डित हृदयनाथ कुजूरू, श्री के० सी० नियोगी आदि राष्ट्रवादी सदस्यों के भाषण थे, जिनमें उन्होंने पुलिस और फौज के अत्याचारों के उदाहरण देते हुए कड़े शब्दों में सरकार की भर्त्सना की थी। जब मालवीयजी द्वारा भेजी गयी घटनाओं की चर्चा पण्डित कुजूरू ने राज्य-सभा में शुरू की, तब एक सरकारी सदस्य ने पूछा कि क्या उन्होंने इसकी जाँच की है, तथाकथित पीड़ितों से वयान लिये हैं। इसके उत्तर में कुजूरू साहब ने कहा कि ये सब तथ्य मुझे एक ऐसे सज्जन ने मेरे पास भेजे हैं जिसकी सच्चाई और ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। श्री के० सी० नियोगी ने भी कुजूरू साहब की तरह अत्याचारों के लिए सरकार को खरी-खोटी सुनायी। यह सब समाचार सुन कर मालवीयजी ने अनुभव किया कि भारतीय सदस्य उस परिस्थिति में जो कर सकते थे, वह उन्होंने किया। इस पर उन्हें अधिक सन्तुष्ट करने के लिए लेखक ने उनसे कहा कि पण्डित कुजूरू और नियोगी साहब की आपने उनके चुनावों में मदद की थी, निर्वाचकों से उन्हें चुनने की अपील की थी, आपने उन पर जो विश्वास किया था, उन्होंने अपने को आपके विश्वास के योग्य सिद्ध कर दिया, आपका विश्वास बिल्कुल सही साबित हुआ। संभवतः उन्हें भी इसका सन्तोष था।

इसी जमाने में एक दिन पुलिस ने डाक्टर मंगल सिंह के यहाँ, जो यूनिवर्सिटी के एक आवास में रहते थे, तलाशी ली। उनके पास कोई आपत्तिजनक चीज पुलिस को नहीं मिली। पर वह उन्हें गिरफ्तार करके ले गयी। उस समय इस बात की जोरों से खबर थी कि पुलिस मालवीयजी और लेखक की भी तलाशी लेना चाहती है। पर कोई ऐसी घटना नहीं घटी। सायंकाल को नियमानुसार लेखक मालवीयजी के पास गया, तब उन्होंने कहा—“मुकुट विहारी, अगर कोई मेरे पास आया तो मैं कह दूँगा कि आज कल मेरे पास कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं है। प्रोफेसर मुकुटविहारी लाल हों सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं”। लेखक ने कहा—“जरूर कह दोजिये”। पर न कोई उनके पास आया, न लेखक से किसी ने कोई पूछताछ की।

एक दिन जबकि आन्दोलन बहुत ठंडा पड़ गया था, मालवीयजी ने लेखक से पूछा—“मुकुट विहारी, अब क्या होगा ?” उसने कहा—“महाराज आपकी और महात्माजी की तपस्या व्यर्थ थोड़े ही जायेगी। स्वराज्य तो मिलेगा ही। गांधीजी के नेतृत्व में स्वराज्य लेने का प्रयत्न हो रहा है। यदि इससे सफलता

नहीं मिली, तो किसी दूसरे नेतृत्व द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायगा।” इस पर मालवीयजी ने कहा “जय प्रकाश।” इस पुस्तक का लेखक जानता था कि मालवीयजी महाराज की जयप्रकाश की योग्यता और कर्तव्य-परायणता पर बहुत विश्वास है। पर वह यह नहीं जानता था कि जयप्रकाश ने वयोवृद्ध नेता मालवीयजी को अपनी प्रतिभा से इतना आकृष्ट कर लिया है कि वह उसे एक नया नेतृत्व प्रदान करने के योग्य समझने लगे हैं। जयप्रकाश जी, उस समय हजारीबाग जेल की चहार-दीवारी फाँद कर बाहर आने पर गुप्त रूप से गुरिल्ला सघर्ष के लिए नवयुवकों के दस्ते तैयार करने में सलग्न थे।

इस जमाने में ही एक दिन प्रयाग के एडवोकेट सुरेन्द्रनाथ वर्मा सर तेज बहादुर सप्रू और डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा के साथ-साथ मालवीयजी से मिले और उन्होंने मालवीयजी से पूछा : “महाराज ! इस (१९४२ के) आन्दोलन में हिंसा का जो प्रदर्शन हुआ, क्या वह गांधीजी के अहिंसात्मक विचारों के अनुरूप था, और क्या इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं ?” मालवीयजी ने तपाक से उत्तर दिया—“हाँ, गांधीजी अवश्य ही सारी बातों के लिए जिम्मेदार हैं। जो कुछ हुआ, उसकी न केवल नैतिक जिम्मेदारी उन पर है बल्कि सम्पूर्ण है, किन्तु यदि यही आन्दोलन सफल हो जाता तो दुनिया कहती और इतिहास में भी लिखा जाता कि भारत ने क्रान्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। आन्दोलन असफल हो गया तो इसी का नाम ‘शान्तिमय विद्रोह’ या जो चाहो दे सकते हो।”^१

श्री सुरेन्द्र नाथ वर्मा के इसी संस्मरण से पता चलता है कि मालवीयजी नैराश्य का वातावरण मिटाने के लिए, देश में चेतना लाने के लिए कुछ करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग में अपने निवास-स्थान पर सर तेज बहादुर सप्रू और डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा को बुलाया था, तथा उनसे बातचीत की थी। पर बात क्या हुई और तय क्या हुआ, यह श्री सुरेन्द्रनाथ वर्मा जी ने नहीं बताया। हो सकता है कि उस समय उस निर्दलीय काफरेन्स की चर्चा चली हो और बात तय हुई हो, जिसे आगे चल कर सर तेजबहादुर सप्रू ने आमन्त्रित और आयोजित किया।

मनःस्थिति

उस समय की उनकी मन स्थिति का पता कुछ संस्मरणों से लग सकता है। गोस्वामी गणेश दत्त जी अपने एक संस्मरण में लिखते हैं कि एक दिन

एक महाराजा साहब मालवीयजी से मिलने काशी आये और जब मिले तो पचास हजार रुपये का एक चैक उन्हें देते हुए बोले—“महाराज, ये रुपये आप के व्यक्तिगत कार्यों के लिए हैं, जैसे चाहें, आप खर्च करें।” मालवीयजी की आँखों में आँसू छलछला आये, और उन्होंने महाराजा साहब को धन्यवाद देते हुए उस चैक को व्यक्तिगत कार्यों के लिए लेना अस्वीकार कर दिया। महाराजा ने बहुत आग्रह किया, पर मालवीयजी माने नहीं। अन्त में महाराजा साहब ने कहा—“महाराज ! आप तो विद्वान् शास्त्रज्ञ हैं। दिया हुआ दान कही वापस लिया जाता है ? मैं यह चैक अब कैसे वापस ले सकता हूँ ?” मालवीयजी ने “मुझे बुलाया और चैक मुझे देते हुए बोले—इसे सनातनधर्म महासभा के खाते में जमा कर दो। आधा सभा के लिए है और आधा धर्मग्रन्थों को संस्कृत से हिन्दी में प्रकाशित करने के लिए।”

पण्डित अम्बादत्त भट्ट साहित्याचार्य ने एक संस्मरण में लिखा है . “८४ वर्ष की अवस्था में महामना अपनी खटिया पर लेटे हुए एक मित्र को एक पत्र लिखा रहे थे। सहसा आवाज आयी—च्यवनाश्रम से। च्यवनाश्रम एक स्थान का नाम है, जहाँ पर गोशाला बनी है। महामना जी ने कहा—‘देखो, बाहर कौन है ? कोई च्यवनाश्रम से आया है। बुलाओ उसे।’ च्यवनाश्रम से आने वालों में छोटे लाल नाम का एक गोरक्षक तथा श्री यज्ञनारायण उपाध्याय एम० एल० ए० थे। उनकी बातचीत से पता चला कि गायें भूसे के बिना भूँखी मर रही हैं। कहीं से कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है। महामना जी ने दो-तीन जगह फोन करवाया, पर जब शीघ्र किसी प्रकार प्रबन्ध की आशा न दिखायी दी तो महामनाजी ने अपने मूडी नामक सेवक को बुलाया और कहा—‘वे रुपये ले आओ जो अभी गोविन्द (मालवीयजी के सबसे छोटे पुत्र) ने दिये हैं।’ अशिक्षित किन्तु अनन्य सेवक मूडी ने पूछा—काहे जरूरत है ? चारे के लिए। गया भूँखी मर रही है—मालवीयजी ने उत्तर दिया। मूडी ने कहा—ऊँ रुपया भैया जी फल का और खद्दर भंडार का कपड़ा का दिहिन है। महामनाजी ने तुरन्त कहा न हम फल खाइव और न कपड़ा पहनव। तू रुपया दे दे। मूडी मेरी तरफ देख कर कहता गया—‘कितने दिन से फल नहीं ले रहे हैं। फुरता फट गई हैं। आज भैयाजी से रुपया लिया है तो वह भी दिला दे रहे हैं।’ महामनाजी ने इतना सुनते ही एक और डाट दी और वह सब रुपया उनके सामने रख कर

चला गया। महामनाजी ने अपने हाथ से रुपये उठाये और, उनमें से १०१) रुपये उस छोटेला ल गोरक्षक को दे दिये।”^१

पंडित अम्बादत्त भट्टजी ने अपने इसी संस्मरण में यह भी लिखा है कि एक बार जबकि मालवीयजी किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर सभा कर रहे थे एक गंगापुत्र धाराप्रवाह गालिया देता वहा पहुँचा। तब मालवीयजी ने बहुत ही मधुर वाणी में उससे पूछा—“क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा अपराध क्या है?” गंगा-पुत्र ने बताया कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उसकी नौका को कितनी क्षति पहुँचायी है। सुनते ही मालवीयजी ने कहा—“भगवन्, वास्तव में आपकी बड़ी क्षति हुई है। ये छात्र आपके ही पुत्र हैं। इन्हें क्षमा कर दो। आपकी नौका ठीक करा दी जायगी।”^२

प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा ने इस पुस्तक के लेखक को बताया कि जब सन् १९४६ के जाडो में वे मालवीयजी से मिले और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि उनके पक्ष में चुनाव-अपील लिख दें, तब मालवीयजी ने उनसे कहा कि ‘अब तो स्वराज्य मिल गया।’ इस पर राधेश्यामजी ने कहा कि ‘महाराज, अभी तो ब्रिटेन की प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष ‘करना होगा’। इस पर मालवीयजी ने पूछा कि तो फिर तैयार हो, और जब उन्हें बताया गया कि तैयारी के साथ संघर्ष होगा, तब मालवीयजी ने राधेश्याम को पास बुला कर उनकी पीठ ठोकी।

डाक्टर शिवनाथ काटजू अपने एक संस्मरण में लिखते हैं कि “एक बार मालवीयजी अपने निधन से कुछ ही दिनों पहले प्रयाग आये, और उन्होंने उनसे कहा—गंगाजी की धारा की अविच्छिन्न रखने के लिए मुझे बहुत प्रयत्न करने पड़े हैं। हरिद्वार में केवल ६ फुट का छेद बाध में रह गया है। हो सकता है कि मेरे बाद यह समस्या फिर कभी खड़ी हो, उस ६ फुट के छेद को भी बन्द करने का प्रयत्न किया जाय। यदि ऐसा कभी हो तो तुम से मैं कह जाता हूँ कि तुम इसका विरोध करना और जैसे भी हो, ऐसा होने मत देना।”^३

श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र ‘माधव’ अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जब उन्होंने मालवीयजी को नोआखाली के हिंदुओं पर आयी महाविपत्ति की कथा सुनायी तब वे “काप उठे—फूट-फूट कर रो पड़े! मेरा प्रश्न था कि ‘क्या बलात् धर्म

१. वही, पृ० १०६-१०७।

२. मालवीयजी-जीवन झलकियाँ, पृ० १०६।

३. मालवीयजी-जीवन झलकियाँ, पृ० ३१।

परिवर्तन को स्वीकार कर सहसा सहस्र हिन्दुओं का परित्याग कर दिया जाय ?' इस पर मालवीयजी महाराज का अन्तर्हृदय उद्वेलित हो उठा और उन्होंने अपने बंगले पर काशी के मूर्धन्य पण्डितों की एक सभा बुलायी और सबने एक स्वर से स्वीकार किया और व्यवस्था दी कि बलात् मुसलमान बनाये गये हिन्दुओं को वापस लेने के लिए किसी प्रकार की शुद्धि प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है—एक मात्र गंगाजल और राम नाम पर्याप्त है। मालवीयजी महाराज बहुत थक गये थे, उनके मुँह के पास मैने कान लगाया तो सुन सका—राम नाम, गंगा जल-वस' ।^१

वक्तव्य

चार-पाच दिन मेहनत करके मालवीयजी ने एक वक्तव्य तैयार कराया। इस वक्तव्य में उन्होंने लिखा कि "धर्म परिवर्तन बन्द होना चाहिए।" "जो जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये हैं और फिर हिन्दू बनना चाहते हैं, उन्हें फिर हिन्दू समाज में प्रवेश करने की सुविधा मिलनी चाहिए। हिन्दुओं की आत्मरक्षा का प्रवन्ध करना चाहिए।" "स्वयं जीवित रहना और दूसरों को जीवित रखना उमका उद्देश्य हो।" "मैं अपने हिन्दू भाइयों से यह नहीं कहता कि जहाँ मुसलमान कमजोर या कम हो, वहाँ वे उन पर आक्रमण करें, पर मैं हिन्दुओं को यह अवश्य कह रहा हूँ कि जहाँ वे दुर्बल हैं वहाँ सबल बनें, जहाँ उनकी संख्या कम है, वहाँ वे सफलतापूर्वक अपनी रक्षा करें।" उन्होंने लिखा कि "यदि मुसलमान तथा अन्य जाति या धर्म के माननेवाले लोग हिन्दुओं के साथ शान्ति से रहना चाहते हैं, तो उन्हें हिन्दुओं के धर्म का आदर करना पड़ेगा। वे हिन्दुओं के पूजागृहों, मन्दिरों को भ्रष्ट नहीं कर सकेंगे, और धार्मिक स्वतन्त्रता, जीवन की पवित्रता एवं स्त्रियों के सतीत्व का उन्हें अवश्य सम्मान करना होगा।" उनका यह भी कहना था कि "हिन्दुओं की तथा अन्य जातियों की राजनीतिक उन्नति कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित हो सकती है। पर हिन्दुओं के विरुद्ध साम्प्रदायिक प्रश्नों पर, तथा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के प्रश्नों पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निश्चय ही किसी हिन्दू-संस्था को ही है, जो इसकी ओर से बोलने तथा कार्य के लिए प्रतिनिधित्व करती हो।" उनकी धारणा थी कि "सामाजिक संगठन के आधार पर निर्मित अराजनीतिक संस्थाओं के अभाव ने राष्ट्रीयता के मोर्चे को दुर्बल बना दिया है"

तथा “खुश करने की राजनीतिक नीति तथा मुस्लिम लोग की असम्भव मांगों को जन्म दिया है।” वे चाहते थे कि “अत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए हिन्दू स्वयंसेवकों की संस्थाएं कायम की जायें। हिन्दू हिन्दुओं की रक्षा करें, और मुसलमानों के अत्याचारों का दृढ़ता से मुकाबला करें।”

इस वक्तव्य की भाषा बहुत कड़ी और कड़वी थी। इसमें मालवीयजी के अपने सन्तुलन और धैर्य की कमी थी। पर यह वक्तव्य मुस्लिम नेताओं की नीतिरीति तथा कलकत्ता और नोआखाली में किये गये अत्याचारों की प्रतिक्रिया थी। वक्तव्य मूलरूप से रक्षात्मक था, उसका उद्देश्य न तो हिन्दू साम्प्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम लोग की तरह को किसी राजनीतिक संस्था को कायम करना था, और न आक्रमणशील हिन्दुत्व को प्रोत्साहित करना था। नोआखाली की प्रतिक्रिया में बिहार में उपद्रव हुए, जिनमें मुसलमानों के जान-माल की बहुत क्षति हुई। उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ा। इन उपद्रवों के सम्बन्ध में मालवीयजी का वक्तव्य अवश्य ही महत्वपूर्ण होता। पर वे तो नोआखाली से सम्बन्धित वक्तव्य देने के दो-चार दिन बाद ही इतने बीमार हो गये कि स्वस्थ चित्त से कोई काम करना उनके लिए सम्भव ही नहीं था। पर सन् १९२३ और सन् १९३१ में इस प्रकार के उपद्रवों के सम्बन्ध में मालवीयजी ने जो कहा था उससे यह स्पष्ट है कि बिहार की घटनाओं ने उन्हें बहुत दुःखी किया होगा। अप्रैल सन् १९२३ में उन्होंने कहा था—“हिन्दू बलवान् होकर मुसलमानों को तकलीफ दें, ऐसी मेरी स्वप्न में कल्पना नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा था कि “अगर कोई हिन्दू किसी मुसलमान को मुसलमान होने के कारण हानि पहुँचावे, और कोई मुसलमान किसी हिन्दू को हिन्दू होने के कारण दुःख दे, तो हमारी गणना संसार की सभ्य जातियों में कभी नहीं हो सकती।” अगस्त सन् १९२३ में उन्होंने हिन्दू महासभा के अधिवेशन में कहा था—“अपना आचरण ऐसा बना लो कि किसी मुसलमान या किसी ईसाई को बेजा शिकायत न हो।” सन् १९३१ में उन्होंने कहा था : “मैं मनुष्यत्व के सामने जाँत-पाँत नहीं मानता” । हिन्दू और मुसलमान, इन दोनों में जब तक प्रेम-भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा।”

अस्वस्थ

वक्तव्य के तीन चार दिन बाद गोपाष्टमी को संध्या समय वे ७-८ मील दूर शिवपुर गोशाला के उत्सव में गये। यह गोशाला उनके प्रयत्न और प्रेरणा से तैयार हुई थी। उत्सव में उन्होंने गोरक्षा पर छोटा-सा भाषण किया।

विश्वविद्यालय को लौटते-लौटते काफी रात हो गयी। रास्ते में ठण्ड लग जाने से शरीर में पीड़ा हो गयी। एक दो दिन कुछ ख्याल नहीं किया। जब पंवर का प्रकोप बहुत बढ़ने लगा, तब आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग शुरू किया। पर दशा विगडती हो गयी। देश की कारुणिक दशा की चिन्ता करते हुए वे बेहोश से हो गये और इस दशा में वे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते रहे। इस समय भी उनमें इतनी चेतना थी कि जब उनके दोहित्र शिवकुमार ने उन्हें पुरुषसूक्त सुनाते हुए कुछ गलती की, तब उन्होंने शिवकुमार जी को रोक कर शुद्ध उच्चारण बताया। इसी तरह जब डाक्टर घाण्डेकर ने रक्त की परीक्षा के लिए रक्त लेने का प्रयत्न किया, तब यह समझ कर कि उन्हें इंजेक्शन दिया जा रहा है, सूई चुभोने से रोक दिया। जब गोविन्दजी ने बताया कि इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है, रक्त निकाला जायगा, तब वे चुप हो गये। इसी तरह जब दशा इतनी बिगडी की ऊर्ध्व-श्वास चलने लगा, तब चिकित्सको ने आक्सीजन देने का निश्चय किया। मालवीयजी को यह बुरा लगा। इस पर उनकी पुत्री मालतीजी ने कहा कि आक्सीजन कोई ऐलोपैथिक दवा नहीं है, और यदि आप इसका प्रयोग स्वीकार करेंगे तो हम सब को सुख मिलेगा, तो वे राजी हो गये। ऊर्ध्व-श्वास का प्रकोप बढ़ता गया। ज्वर भी १०५ ६ डिग्री हो गया। ऊर्ध्व-श्वास तीन दिन तक चलता रहा। सहसा तापमान १०५ ६ पर से घट कर १०५ पर आ गया, और उनकी शान्ति गम्भीर होने लगी—श्वास की गति मन्द हो चली। बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन ने, जो वहाँ उस समय उपस्थित थे, कहा—“अब वे जा रहे हैं।” ‘हरे राम हरे राम’ ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ की ध्वनि सब ने ऊँची कर दी। उन्हें शय्या पर से उठा लिया गया, भीतर चौकी पर ले जा कर रक्खा गया। उनके मुख में तुलसीदल और गंगाजल छोड़ा गया। वहाँ पर गोबर से लिपी भूमि पर अपनी स्वाभाविक शान्तमुद्रा में उन्होंने १२ नवम्बर सन् १९४६ को प्राण छोड़ दिये।

शोक और श्रद्धांजलि

मालवीयजी के निधन से हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ-साथ सारी वाराणसी में शोक छा गया। विश्वविद्यालय दस दिन के लिए बन्द कर दिया गया। नगर की अन्य शैक्षिक संस्थाएं भी एक दिन के लिए बन्द कर दी गयी। व्यापारियों ने भी उस दिन अपना कारोबार बन्द कर दिया। शवयात्रा में विश्वविद्यालय के अध्यापको, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त सब जाति और सम्प्रदाय के नागरिकों की अपार भीड़ थी। कांग्रेस और हिन्दू सभा के अतिरिक्त बहुत

से दूसरे सम्प्रदायों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल थे। सड़क के दोनों ओर बहुत से नागरिक दर्शनार्थ खड़े थे। जब अर्थी गुरुद्वारे के पास पहुँची, तब सिक्खों ने अपने जातीय झंडे से शव का सम्मान किया, रेशमी वस्त्र अर्पण किये और फूलों की वर्षा की। कई घंटों के बाद मणिकर्णिका घाट पर विल्व-चन्दन की चिता पर उनका विधिवत् दाहसंस्कार हुआ।

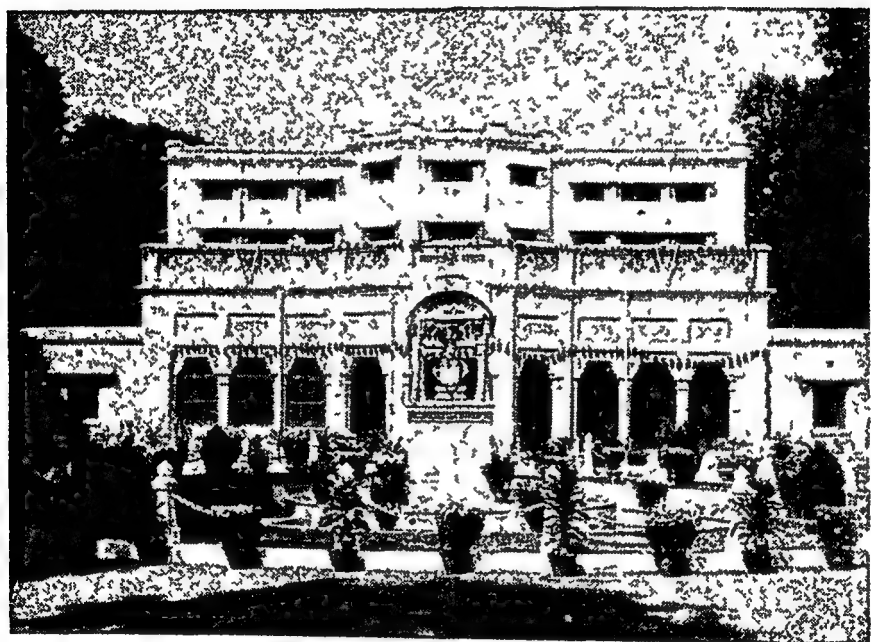
काशी में कई दिन तक जनता तथा विभिन्न संस्थाओं की ओर से शोक सभाओं में मालवीयजी को श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित की गयीं। प्रयाग, लखनऊ, कानपुर तथा सुल्तानपुर, बलिया आदि युक्त प्रान्त के नगरों के अतिरिक्त बगलौर, मद्रास, पटना, मुजफ्फरपुर, लाहौर, अमृतसर, नागपुर, आदि नगरों में भी एक दिन के लिए बाजार बन्द करके शोक सभाएँ की गयीं। देश के बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मालवीयजी के निधन पर अपनी समवेदना के साथ उनके व्यक्तित्व और उनकी सेवाओं के सम्वन्ध में वक्तव्य प्रकाशित किये।

श्रद्धाञ्जलि

उनके निधन पर गांधीजी ने जो उस समय नोआखाली के गाँवों में भ्रमण कर रहे थे, लिखा : 'मालवीयजी अमर हैं' प्रारम्भिक जीवन से लेकर परिपक्व बुढ़ापे तक परिश्रम ने उन्हें अमर बना दिया है। वे अपने अनुयायियों के सेवक थे समझोते की भावना उनके स्वभाव का अंग था।' उनका आन्तरिक जीवन पवित्रता का मूर्तिमान था। वे करुणा और कोमलता के निधान थे। धार्मिक ग्रन्थों का उनका ज्ञान बृहद् था।' महात्माजी ने तो सन् १९३१ में एक सदेश में लिखा था : "आज मालवीयजी के साथ देशभक्ति में कौन मुकाबला कर सकता है। जीवन काल से प्रारम्भ करके आज तक उनकी देशभक्ति का प्रवाह अविच्छिन्न चलता आया है।"

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा "हमें अत्यन्त शोक है कि अब हम उस उज्ज्वल नक्षत्र का दर्शन नहीं कर सकेंगे जिसने हमारे जीवन में प्रकाश दिया, बालकाल से ही प्रेरणा दी तथा भारत से प्रेम करना सिखाया"।^१

डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने लिखा . "एक महान् व्यक्तित्व आज संसार से उठ गया। पंडित मालवीयजी के काम और उनके नाम से भावी पीढ़ी को यह प्रेरणा मिलेगी कि दृढ़ भक्ति से मनुष्य के लिए सब कुछ सम्भव है। मालवीयजी



मालवीय भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

की सेवाएँ बहुत ऊँची हैं और कुछ शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मालवीयजी के रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं हो सकती। वे सच्चे देशभक्त थे”।^१

सन् १९६१ में डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने एक सस्मरण में लिखा : “देशभक्ति की वह चिनगारी जिसने उन्हें कांग्रेस के एक शुरू के अधिवेशन में लब्धप्रतिष्ठित बना दिया था वह दूसरों के मार्गदर्शन के लिए अग्निशिखा बन गयी, और उनके जीवन के अन्तिम दिनों तक, उस समय भी जबकि आयु के कारण वह दुर्बल हो गये थे, जलती रही। आयु के भार ने देशप्रेम को और देश की प्रगति से सम्बन्धित हर चीज की चिन्ता को कम नहीं किया। उन्होंने बहुत से क्षेत्रों में, जिनमें उन्होंने बड़े-बड़े काम प्रारम्भ और पूरे किये, देश के लिए समर्पित सेवा और बलिदान की मूल्यवान् वपौती हमें छोड़ी है। उनकी याद हमें और नवयुवक पीढ़ी को प्रोत्साहित और अनुप्राणित करती रहेगी”।^२

सर तेजबहादुर सप्रू ने मालवीयजी के निधन पर काफी बड़ा वक्तव्य प्रकाशित किया जिसका आशय था कि मालवीयजी के निधन से एक महान् व्यक्ति उठ गया। उनकी सेवाओं का इतिहास देश की प्रगति का इतिहास है। उनका निकृष्टतम निंदक भी उनके आदर्शों और उनके लक्ष्यों की उच्चता के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कह सकता। सम्भवतः मालवीयजी हम लोगों के समय में प्राचीन हिन्दू संस्कृति और दर्शन के सर्वोत्तम प्रतिनिधि थे।^३

पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहा : “मालवीयजी ने ६० वर्ष तक जिस श्रद्धा, लगन, तथा नि स्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है, वह किसी भी देश के इतिहास में अद्भुत और स्मरणीय है”।^४

आचार्य नरेन्द्रदेव ने फैजाबाद की सभा में अध्यक्षता करते हुए कहा : “मालवीयजी भारत के गौरव स्तम्भ थे। उनकी देशभक्ति और सेवा भारतीयों को नया उत्साह देती रहेगी। देश की पुकार पर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। देश में शिक्षा का प्रचार कर उन्होंने अमूल्य सेवा की है। हिन्दू विश्वविद्यालय उनका सर्वोत्तम स्मारक है”।^५

श्री श्रीप्रकाशजी ने बनारस की शोक सभा में बोलते हुए कहा “मालवीय जी बड़े ही निर्भीक, सत्यनिष्ठ और परम्परानुसार चलने वाले थे। उन्होंने

१. वही,

२. महामना मालवीयजी वर्थ सेनटिनरो कोमिमोरेशक वाल्यूम।

३. आज १५ नवम्बर सन् १९४६।

४. वही,

५. वही,

अपने जीवन में कभी किसी की बुराई नहीं की, और यह मिसाल रख दी कि आदमी ईमानदारी, सच्चाई और हिम्मत से अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है।^१

मिस्टर रफी अहमद किदवई ने कहा . “मालवीयजी के निधन से देश ने एक महान् निर्माता खो दिया है”।^२ सरदार अब्दुलरवनिस्तर ने कहा : “मालवीयजी की मृत्यु से भारतीय रंगमंच से एक महान् व्यक्ति उठ गया। वे महान् विधानवादी ही नहीं, अपितु एक महान् शिक्षाप्रचारक और सुधारक थे”।^३



१. वही,

२. वही, १६ नवम्बर सन् १९४६।

३. आज १५ नवम्बर सन् १९४६।

२५. मालवीयजी का व्यक्तित्व

धर्मनिष्ठ जीवन

ईश्वरभक्ति और देशभक्ति मालवीयजी के जीवन के दो मूल मन्त्र थे। इन दोनों का उत्कृष्ट संश्लेषण, ईश्वरभक्ति का देशभक्ति में अवतरण, तथा देशभक्ति की ईश्वरभक्ति में परिपक्वता उनके व्यक्तित्व का विशिष्ट सद्गुण था। उनकी धारणा थी कि “मनुष्य के पशुत्व को ईश्वरत्व में परिणत करना ही धर्म है। मनुष्यत्व का विकास ही ईश्वरत्व और ईश्वर है”,^१ और निष्काम भाव से प्राणिमात्र की सेवा ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। इन सब की साधना ही उनकी जीवनचर्या थी, इसकी सिद्धि ही उनका जीवनलक्ष्य था। उनका सारा जीवन मनुष्यत्व की भावना से अनुप्राणित, ईश्वरत्व की भावना से ओत-प्रोत था। उनकी देशसेवा निष्काम उपासना की भावना, तथा लोक-कल्याण की कामना से समन्वित और अलंकृत थी। वे नि सन्देह मनुष्यता की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति थे।

मालवीयजी उच्चकोटि के तपस्वी थे। सात्त्विक तप के सब सद्गुण उनमें विद्यमान थे। वे श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित कायिक, वाचिक और मानसिक तप के साधक थे। सब प्रकार के द्वन्द्वों को सहन करते हुए निष्काम भाव से, फल की इच्छा त्याग कर शम-दम से सम्पन्न होकर, श्रद्धा और धैर्य के साथ मन, वाणी और शरीर से प्राणिमात्र की सेवा में सदा सलग्न रहना ही उनकी तपश्चर्या थी। काम-क्रोध-लोभ-मोह से वचना, मदा शुद्ध संकल्पयुक्त रहना, किसी विषय-वृत्ति के कारण विक्षिप्त हो जाने पर उस पर विजय प्राप्त करना, व्यवहार काल में छल-कपट, धोखा और फरेव से अपने को दूर रखना, उनका मानसिक तप था। असत्य, दुःखदायी, अप्रिय और खोटे शब्दों का त्याग, तथा प्रिय, सत्य, मीठे और मधुर शब्दों का प्रयोग उनका वाचिक तप था। दूसरों की सहायता और सेवा करना, देश और जाति के लिए अपने शरीर के दुःख और कष्ट की परवाह न करना उनका शारीरिक तप था।

मालवीयजी धर्मनिष्ठ धर्मज्ञ थे। धर्म में उनकी अचल श्रद्धा थी, धर्म के मूल सिद्धान्तों का उन्हें अच्छा ज्ञान था, वे ही उनके जीवन के आधार थे। वे

नित्य विधिपूर्वक पूजा पाठ करते, शास्त्रविहित आचार का पालन करते, श्रीमद्भगवत् तथा श्रीमद्भगवद्गीता आदि ग्रन्थों का अध्ययन करते, पार-लौकिक विषयों पर भी समय मिलने पर चिन्तन-मनन करते, धर्म का प्रसार करते, तथा सदा लोककल्याण में एवं देश के अभ्युदय में संलग्न रहते। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों पर विश्वास था। पर वे इन दोनों में से किसी की कामना नहीं करते थे। वे तो चाहते थे कि वे तप्त प्राणियों के कष्टों का निवारण करें, सत्य और न्याय को प्रतिष्ठित करें, एवं देश की सेवा करें, और इन सबके लिए फिर जन्म लें।

देशभक्त

मालवीयजी उच्च कोटि के देशभक्त थे। वे अनेक प्रकार के दुःखों, संकटों और कष्टों को सहन करते हुए तथा नाना प्रकार के विघ्नों का मुकाबला करते हुए सदा देशसेवा में लगे रहते थे। देश की स्वतंत्रता, राष्ट्र के गौरव की वृद्धि, तथा जनता का सर्वाङ्गीण उत्कर्ष उनकी देशसेवा के मुख्य लक्ष्य थे। वे सब जातियों, सम्प्रदायों और प्रान्तों के भारतीयों को मिलाकर भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। वे एक ही समय में विभिन्न प्रकार के सेवा-कार्यों में संलग्न रहते थे।

उनका कार्यक्षेत्र नि सन्देह बहुत ही विस्तृत और व्यापक था। समाजसेवा का कौन ऐसा काम होगा जो उन्होंने न किया हो। सनातन धर्म का प्रचार, प्राचीन संस्कृति का समर्थन, हिन्दू हितों की रक्षा, हिन्दी का प्रसार, देश की स्वतंत्रता, गौ की सेवा, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, स्वयंसेवकों का संगठन, नाना ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि, शिक्षा का विस्तार, मल्लशालाओं का उद्घाटन, दीनों के कष्टों का निवारण, स्त्रियों का उत्कर्ष, हरिजनो का उत्थान, समाज की आर्थिक उन्नति, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की प्रतिष्ठा, देशप्रेम पर आश्रित राष्ट्रीय भावना की पुष्टि, प्रगतिशील सिद्धान्तों का प्रतिपादन, देश कालानुकूल संस्कृति का विकास, नवयुग का निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने महत्त्वपूर्ण योगदान किया। दैवी सम्पत्तियों से विभूषित जीवन को उन्होंने समाजसेवा में लगाया, और समाजसेवा द्वारा उन्होंने अपने जीवन को उठाया, अपने व्यक्तित्व का विकास किया।

उनका विचार था कि जो मनुष्य अपने व्यक्तित्व को समाज के पीछे रखता, समाजसेवा करते समय निजी हित की दृष्टि से कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे समाज की हानि हो, वह समाज को ऊँचा उठाता है, और समाज की

उन्नति के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पर जो मनुष्य अपने को समाज के आगे रखता है, अपने निजी हित पर समाज के हित को न्योछावर करता है, उसका नैतिक पतन होता है, उसका व्यक्तित्व नीचे गिरता है। उनकी धारणा थी कि, जो काम “अविवेक से दूसरो को हानि पहुँचाने, दिल दुखाने, द्वेष और शत्रुता से किया जाता है, वह तामसी है”,^१ “जो काम अपनी स्तुति, पूजा, प्रतिष्ठा और मान के लिए किया जाता है, वह राजसी है।”^२ इस प्रकार के कामों से, उनके विचार में, लाभ के बजाय हानि होती है, कार्यकर्ताओं में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होता है, और कार्य संभलने के बजाय बिगड़ जाता है, उनके नैतिक जीवन का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। पर ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त निष्काम भावना से की गयी सेवा कार्यकर्ताओं के जीवन को निर्मल करती है, ऊँचा उठाती है, तथा सामाजिक कार्यों की समुचित सफलता में सहायक होती है। मालवीयजी नि सन्देह निःस्वार्थ समाजसेवी थे।

सात्त्विक सार्वजनिक जीवन

निष्काम भाव से अनुप्राणित मालवीयजी के कार्य का ढंग भी निराला था। वे सदा सार्वजनिक कामों में लगे रहते, और उन सबको बड़े पैमाने पर करते थे। पर जैसा कि पुरुषोत्तम दास टंडनजी ने बताया, “यश की उन्हें चाह नहीं थी”, वे “काम स्वयं करते थे”, पर कीर्ति और यश के लिए दूसरो को आगे कर देते थे।^३ वे दूसरो की समाजसेवा का आदर करते, और समाज की सेवा में उनकी हिम्मत बढ़ाते थे। अपने साथियों पर वे सदा विश्वास करते, उनके प्रति सद्भावना रखते, और उनके सहयोग और परामर्श की कद्र करते थे। उनका बहुत-सा समय साथियों के साथ विचार-विमर्श में ही खर्च होता था। वे छोटी की बात को भी धीरज और ध्यान से सुनते, और उनकी बतायी अच्छी बात को खुशी-खुशी ग्रहण करते, और उसके लिए उनकी सराहना करते थे। वे समाज सेवकों के यश से खुश होते थे, और सबके साथ मिलकर काम करते थे। वे सात्त्विक विरोध का आदर करते, पर बेकार के कटाक्ष और तिरस्कार की उपेक्षा करते थे। वे वितंडावाद से कोसी दूर भागते थे। किसी की निन्दा करना या किसी के अपयश का बखाना करना वे बुरा समझते थे। वे विपक्षी के साथ भी प्रेम, धैर्य और नम्रता से बात करते, विरोधियों के अपशब्द को

१. अभ्युदय, १४ जनवरी, सन् १९०९।

२. वही।

३. मालवीयजी—जीवन श्लकियाँ पृ० ३।

सुनकर भी उनके लिए कोई बुरी बात कहे बिना विरोध का मुकाबला करते, और यदि कोई दूसरी बुरी बात कहता, तो उसे मना करते थे। इस तरह वे अपनी ओर से वाद-विवाद और विरोध को व्यक्तिगत द्वेष और ईर्ष्या का स्वरूप न देकर मतभेद के स्तर तक सीमित रखते थे। वे वास्तव में विरोध के समय भी मेल का दरवाजा खुला रखते थे। विरोध पक्ष की अच्छी बातों को भी ग्रहण करने को तैयार रहते थे, उसकी समाज-सेवा की भी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते थे। यदि किसी एक बात में वे किसी का विरोध करते, तो दूसरी बात में उसके साथ मिलकर काम करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती थी। जैसा कि स्वामी धर्मानन्द ने अपने एक संस्मरण में कहा है : "दलबन्दी कर नेता बनने की इच्छा से वे (मालवीयजी) कोसों दूर थे। वह जो कुछ करते, उसमें देशभक्ति और सेवाभाव सर्वोपरि रहता था।" उनकी तबियत ऐसी थी कि जब "राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय विचारों को धक्का लग रहा हो, तब वह उसको वर्दाश्त नहीं कर सकते थे।"^२

जनसाधारण की सेवा

जमींदार, व्यापारी, राजे-महाराजे सभी मालवीयजी का आदर करते, उन्हें पूजनीय समझते, और उनके निर्माण कार्यों में उनकी सहायता करते थे। वे भी उन सबसे प्रेम से मिलते थे, उनका भला चाहते थे। पर उनका हृदय दीन-दुःखी जनता के साथ था। जनता का उत्थान वे राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे, और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। राजाओं को उनकी यही सलाह थी कि वे अपनी प्रजा की समुचित रक्षा और कल्याण-वृद्धि को ही अपना कर्तव्य समझें, कालानुसार अपनी शासन-व्यवस्था में सुधार करके संवैधानिक व्यवस्था प्रतिष्ठित करें, तथा सम्पूर्ण भारत से अपने सम्बन्ध दृढ़ करें। रजवाड़ों में संवैधानिक सरकार प्रतिष्ठित करने की चर्चा जब कभी मालवीयजी करते थे, तब ब्रिटेन की शासन-प्रणाली की तरह शासन-व्यवस्था की स्थापना ही उनका लक्ष्य होता था। वे चाहते थे कि राजे-महाराजे अपनी इच्छा से अपने अधिकारों को सीमित कर जनता के प्रतिनिधियों को शासन का उत्तरदायित्व हस्तान्तरित कर दें, राजकोष के एक निश्चित सीमित अंश का ही अपने निजी खर्च में प्रयोग करें, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत संविधान द्वारा न्याय का शासन प्रतिष्ठित करें, जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा

१. वही, पृ० १०।

२. वही, पृ० ४ (पुरुषोत्तमदास टंडन)।

की समुचित व्यवस्था करें, तथा प्रजा की अभिवृद्धि ही शासन का लक्ष्य निर्धारित करें।

इसी तरह सेठ साहूकारो से घनिष्ठ सम्बन्ध कायम रखते हुए भी उन्हें जनता के हितो तथा सार्वजनिक जीवन की पवित्रता का सदा ध्यान रहता था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जहाँ उन्होंने देश की औद्योगिक उन्नति के लिए देशज उद्योगो के लिए वित्तीय संरक्षण का समर्थन किया, वहाँ मजदूरो के हितो और अधिकारो की समुचित व्यवस्था की मांग को पुष्ट किया, प्रतिज्ञा-वद्ध श्रम-प्रणाली का विरोध किया, इकरारनामे के उल्लंघन पर श्रमिको तथा तथा कर्जदारो को कैद की सजा देने की व्यवस्था की कड़ी आलोचना की, तथा सन् १९२९ मे सेठ साहूकारो को चेतावनी दी कि 'यदि श्रमिक जनता के कल्याण की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो कम्यूनिज्म के प्रभाव को कानून द्वारा नहीं रोका जा सकेगा। जब सन् १९३० में सरकार के दबाव पर बम्बई के औद्योगिको ने आयात शुल्क विधेयक की उन धाराओ को भी स्वीकार कर लिया जिन्हे मालनीयजी राष्ट्र-हित-घातक समझते थे, और उनका ध्यान आकृष्ट किया गया कि बम्बई से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को बहुत आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, तब उन्होंने केन्द्रीय असेम्बली मे स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वे राष्ट्रहित पर सी विश्वविद्यालय न्योछावर करने को तैयार हैं, पर राष्ट्र-हित-विरोधी बात को घन के लोभ से स्वीकार करने को तैयार नहीं।^१ इसी तरह जब एक रईस ने उन्हें पचास हजार रुपये की हुडी भेजकर उनसे अनुरोध किया कि वे सरकार से उसका कोई स्वार्थ सिद्ध करा दें, तब उन्होंने उस हुडी को लौटाते हुए कहला भेजा कि 'मैं वही करूँगा जो उचित होगा।'^२

उन्होंने मालगुजारी के स्थायी बन्दोबस्त का समर्थन करने के साथ ही साथ जमींदारो के व्यवहारो पर प्रतिबन्ध लगा कर किसानो के अधिकारो की रक्षा तथा उनके हितो की वृद्धि पर जोर दिया। उनकी धारणा थी कि "इस देश में हमारी सहानुभूति का किसानो से अधिक कोई हकदार नहीं।"^३ उन्होंने माग की कि किसानो पर लगान का बोझ कम किया जाय, लगान की व्यवस्था को भी स्थायी बनाया जाय, और उनकी दयनीय दशा को सुधारने का प्रयत्न किया

१. लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स, १९३०, जि० ३, पृ० २६२६।

२. रामनरेश त्रिपाठी मालवीयजी के साथ तीस दिन, पृ० ३०।

३. गवर्नर जनरल की कौंसिल (विधान), सन् १९१५, जि० ५३, पृ० ६३७।

जाय।^१ 'अभ्युदय' के सम्पादकीय विभाग को उनकी हिदायत थी कि "उसमें किसानों के हितों की बातें अधिक हो, किसान बड़े ही दुःखी हैं और उनके दुःखों के भागे जमींदारों का जरा भी लिहाज न करो"।^२ मालवीयजी चाहते थे कि किसानों को कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाय, उनके प्रतिनिधियों को बिना शुल्क कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल किया जाय, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा की जाय। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में बताया, "मालवीयजी और गांधीजी का ध्यान हमेशा जाता था किसानों की तरफ, और उनकी तरफ जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं—क्योंकि जैसा ये लोग कहते थे कि अगर हिन्दुस्तान में स्वराज्य आ गया और लोग तैयार न हुए तो वह निकल भी जायगा, रहेगा नहीं। लोग तैयार हैं तो स्वराज्य आ ही जायगा और कायम भी रहेगा।"^३ जनजीवन का उत्थान, पीड़ितों के कष्टों का निवारण, जनता के अधिकारों की रक्षा और वृद्धि मालवीयजी के सार्वजनिक कार्यों का अवश्य ही एक प्रमुख लक्ष्य था।

करुणा और सौहार्द

करुणा और सौहार्द मालवीयजी के जीवन के जोहर थे। अपने भृत्यों और पार्श्ववर्तियों के प्रति भी उनका व्यवहार कोमल, मधुर और अनुग्रहपूर्ण होता था। (वे बहुत कष्ट सहते हुए भी अपने नौकरों के आराम का ध्यान रखते, तथा अपने कारण उन्हें कष्ट नहीं होने देते थे) इस सम्बन्ध में पण्डित रामनरेश त्रिपाठी ने बताया कि एक बार पटना के प्रसिद्ध वैद्य पंडित ब्रजबिहारी चौबेजी ने मालवीयजी को एक काढा पीने की सलाह दी। उसे तैयार करके ठीक समय पर पिलाने के लिए नौकर को प्रातःकाल चार बजे उठना पड़ता था। उसे इतना कष्ट देना अनुचित समझ मालवीयजी ने काढा पीना ही बन्द कर दिया। जब दस-पन्द्रह दिन के बाद नौकर को कारण का पता चला, तब उसने उसका प्रबन्ध किया। रामनरेशजी के एक प्रश्न के उत्तर में मालवीयजी ने उनसे कहा कि "रामनरेशजी, हम तो गरीब आदमी हैं। इससे गरीब के प्रति हमारी सहानुभूति स्वाभाविक है। नौकरों को मैं कुटुम्ब से भिन्न नहीं समझता। मेरे यहाँ नौकर के साथ जैसा व्यवहार होता है, वैसा धनी परिवारों में भी नहीं

१. वही, सन् १९१४, जि० ५२, पृ० ६०३-६०४।

२. मालवीयजी-जीवन झलकियाँ, पृ० ७५।

३. वही, पृ० ३।

होता” ।^१ रामनरेशजी ने स्वयं लिखा है : “मुझे घूमने का तो बहुत मौका मिला है, और मेरा परिचय राजा से लेकर साधारण गृहस्थ तक प्रायः हरेक श्रेणी और हरेक सुरुचि के लोगो से है, पर नौकरो के प्रति जैसी आत्मीयता मैंने मालवीय जी में देखी, वैसी यहा के पहले कहीं देखी नहीं थी। प्रायः अधिकांश मालिक अपने नौकरो के प्रति उदासीन और कहीं-कहीं क्रूर दिखाई पड़े और कहीं तो नौकर ही मालिक बन बैठे हैं। पर यहाँ स्वामी और नौकर का अद्भुत ही रूप देखा।”^२

मालवीयजी के सुपुत्र गोविन्दजी ने एक बार डाक्टर आनन्द कृष्ण को एक साधारण पड़ोसी के प्रति मालवीयजी के सौहार्द और करुणा की एक अद्भुत बात बतायी। गोविन्दजी ने बताया कि जब मालवीयजी भारती भवन में रह कर ही वकालत करते थे, तब एक सज्जन जो वगल में रहते थे अपना मकान बेचने के लिए मालवीयजी के पास आये। पर उन्होंने मकान खरीदने के बजाय उसे कुछ रुपये उधार दे दिये। व्यापार में अधिक घाटा हो जाने के कारण उस पड़ोसी को अपना मकान मालवीयजीके हाथ बेचना ही पड़ा। फिर भी मालवीय जी ने उस मकान पर अपना अधिकार न जमा कर उसे उसके पुराने मालिक के कब्जे में रहने दिया। पर पड़ोसी को यह बात ठीक नहीं लगी। उसने मकान खाली करके मालवीयजी को उसका कब्जा देने की ठान ली। उसके आग्रह पर कब्जे की तिथि निश्चित हो गयी। तब मालवीयजी की धर्मपत्नी मकान देखने गयी। वहाँ उन्होंने देखा कि एक स्त्री सामान बाधती जा रही है, साथ-साथ रोती भी जा रही है। रोने का कारण पूछने पर उसने बताया कि “बहिन, अपना घर है, छोड़ते दुःख होता है”। जब धर्मपत्नीजी ने मालवीयजी से इसकी चर्चा की, तब उन्होंने मकान के पुराने मालिक को बुलाकर कहा कि तुम्हारा मकान तुम्हारे पास ही रहेगा। इस पर उसने इनकार किया, पर मालवीयजी टस से मस नहीं हुए और मकान उसके पास ही बना रहा।

मालवीयजी की करुणा नौकरो और पड़ोसियों तक ही सीमित नहीं थी। सभी गरीब समान रूप से उसके अधिकारी थे। उनके घर पर दीन-दुःखियों की भीड़-सी लगी रहती थी। उन सबके लिए उनका दरबार सदा खुला रहता था। उन्हें उनके पास आने से कौन रोक सकता था ? यदि उनका कोई पुत्र रोकने का प्रयत्न करता, तो वे कहते कि जब तक वे इस घर में हैं, तब तक

१. रामनरेश त्रिपाठी मालवीयजी के साथ तीस दिन, पृ० १६३।

२. वही, पृ० १६९।

तो दीन-दुःखी इस घर में आयेंगे ही। यदि बाबू शिवप्रसाद गुप्त कमरे पर पहरा लगा देते या स्वयं पहरा देने लगते, तो मालवीयजी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते, और वहाँ सबसे मिलने लगते। आखिर इन सब पहरेदारों को हार माननी पड़ती। ऐसा लगता था मानों उन्होंने गजेन्द्रमोक्ष की कथा को अपने जीवन में पूरे तीर पर चरितार्थ कर लिया था। यदि उनके सामने कोई असह्य संकट उपस्थित होता, तो वह गजेन्द्र की तरह विलाप करते हुए उससे छुटकारे के लिए भगवान् से प्रार्थना करते, और वे स्वयं कृष्ण की तरह दुःखियों के कष्टों को दूर करने के लिए दौड़ते फिरते। उनका सारा जीवन इस प्रकार की घटनाओं से भरा पड़ा है।

बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने अपने संस्मरण में लिखा है कि “प्रयाग में गंगा तट पर माघ का मेला था। कडाके की सर्दी थी। रात का समय था। पानी बरसने वाला था जिसके कारण बहुत से साधनहीन यात्रियों को बड़ा कष्ट होने की सम्भावना थी। बस, मालवीयजी टण्डनजी को लेकर टाल पर पहुँचे, लकड़ियाँ खरीदी, कुछ उन्होंने अपने कंधे पर रखी और अपने दूसरे साथियों की सहायता से बहुत-सी लकड़ियाँ मेले में ले जाकर वे “साधुओं के यहाँ, गरीबों के यहाँ, जिनके पास सहारा नहीं था, उनको बाँटने लगे।”^१ इसी तरह एक दूसरे अवसर पर माघ मेले में ही जैसे ही मालवीयजी खाना खाने बैठे थे कि उन्हें मेले में आग लगती दिखाई दी। वह तुरत ही धोती पहने ही आग बुझाने दौड़ पड़े। इस भावना से अनुप्राणित मालवीयजी सन् १९१९ में पंजाब हत्याकाण्ड के तुरत बाद पंजाब गये और वहाँ उन्होंने कई मास दुःखी जनता की सेवा की, उन्हें ढाडस बँधाय़ा, साहस प्रदान किया।

स्वामी श्रद्धानन्दजी ने अपने संस्मरण में लिखा कि सन् १९१९ में अमृतसर कांग्रेस के अवसर पर एक दिन इतनी वर्षा हुई कि प्रतिनिधियों को तम्बुओं में नहीं टिकाया जा सका। उनका प्रबन्ध नगर-निवासियों के घरों में करना पड़ा, और उन्हें स्टेशन से घरों में पहुँचाते-पहुँचाते दो बज गये। इस अवसर पर “रेलवे पर हमारे विनम्र और सीधे सादे नेता पण्डित मदन मोहन मालवीय बराबर बने रहे, भूखप्यास की चिन्ता न कर एक घोड़ा की तरह उस समय तक काम करते रहे, जब तक कि अन्तिम मेहमान भी अपने नियत स्थल पर खाना नहीं हो गया।”^२

१. मालवीयजी—जीवन श्लकियाँ पृ० ४।

२. मालवीयजी—जीवन श्लकियाँ, पृ० १०।

उच्चकोटि के वक्ता

। मालवीयजी “अद्वितीय वक्ता” थे। उनके भाषणों में जैसा कि सच्चिदानन्द सिन्हा ने बताया : “अनमोल वाक्शक्ति के साथ-साथ प्रभावकारी माधुर्य और गम्भीरता का अनुपम सम्मिश्रण रहता था।”^१ वे सदा व्यक्तिगत कटाक्ष से निर्मुक्त तथा युक्तियुक्त विचारों, सद्भावनाओं और सदादर्शों से परिपूर्ण होते थे। ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों से परिपुष्ट, तथा साहस और सौजन्य, विवेक और मनुष्यता, करुणा और शौर्य, एवं युक्तियुक्त तर्क और भाषा की पवित्रता से अलंकृत उनके बहुत से भाषण वाग्मिता के उच्च उदाहरण थे। अंग-विक्षेप के बिना घंटों धारा-प्रवाह के साथ भावनाओं से परिपूर्ण प्रभावशाली भाषण देते रहना मालवीयजी की वाग्मिता का विलक्षण गुण था। उनकी आकर्षक आकृति, उनका शील और सुमधुर स्वर, उनकी निर्भीकता और स्पष्टवादिता, उनका देशप्रेम, सत्य के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा, एवं उनकी निष्कपट भावुकता सोने पर सुहागे का काम करती थी, उनकी वाक्पटुता को चमत्कृत कर देती थी। उन्होंने अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन में अपनी वाक्शक्ति को कभी भी अपने सार्वजनिक प्रतिद्वन्द्वियों की वैयक्तिक निन्दा में नहीं लगाया। प्रभावशाली व्याख्यान द्वारा प्रतिद्वन्द्वी के यश और कीर्ति को मिट्टी में मिला देने की बात उन्होंने कभी सोची ही नहीं। हानिकर नीतियों और कार्यों की निर्भीक और कड़ी आलोचना के साथ ही साथ सबके प्रति सद्भावना तथा सौहार्दवृद्धि की कामना उनकी वाग्मिता का लक्षण था। “उनके मुख से दूसरों के लिए सदा मिठास टपकती थी।”^२ सन् १८८६ में पच्चीस वर्ष की आयु में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में प्रतिनिधि-प्रथा के पक्ष में दिया गया उनका भाषण निःसन्देह उच्चकोटि की वाग्मिता का उच्चतम उदाहरण है। इसी तरह जैसा कि डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ने कहा है, “पंजाब हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में दिये गये मालवीयजी के भाषण वास्तव में बहुत ही उच्चकोटि की विवेचना शक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण है।”^३ श्री एन० सी० केलकर ने जो मालवीयजी के साथ सन् १९२४ से सन् १९३० तक केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य थे, ठीक ही कहा है कि “वाग्मिता और वाक्पटुता में वह (मालवीयजी) कभी-कभी उस ऊँचाई पर पहुँच जाते थे जिसकी असेम्बली का कोई दूसरा सदस्य आकांक्षा भी नहीं कर सकता था।”^४

१. वही. पृ० ४३।

२. महामना मालवीयजी वर्थ सेनटिनरी कोमिमोरेशन वाल्यूम (पुरुषोत्तम दास टण्डन का वक्तव्य)।

३. मालवीयजी—जीवन झलकियाँ, पृ० ४३।

४. मालवीयजी कोमिमोरेशन वाल्यूम, १९३२, पृ० १०३०।

फिर भी यद्यपि जनता उनके लम्बे भाषणों को भी बहुत उत्सुकता से सुनती थी, सुविज्ञ राजनीतिज्ञों की सभा में सुपरिचित बातों का विस्तृत विश्लेषण उनकी वाक्पटुता की गम्भीरता को कम कर देता था ।

सद्भावना

लोक-सेवा में संलग्न सहयोगियों के प्रति सद्भावना तथा विश्वासपूर्ण व्यवहार उनके चरित्र का विशिष्ट सद्गुण था । वे सदा उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते थे और उनके व्यवहार या व्यक्तित्व की कड़ी आलोचना उन्हें व्यथित करती थी । वे गोपनीय विचार-विमर्श को गुप्त रखना मानव का पुनीत कर्तव्य, तथा विश्वासघात उसका घोर अपराध मानते थे । यों तो उनका सारा सार्वजनिक जीवन ही इस सद्भावना और विश्वासपूर्ण व्यवहार का उच्चतम उदाहरण है, पर कुछ परिस्थितियों और अवसरों पर उनके व्यवहार उसकी उच्चता और श्रेष्ठता के निःसन्देह अत्युत्तम दृष्टान्त हैं । वंगभंग के जमाने में हिन्दू बोर्डिंग हाउस के बहुत से प्रबन्धक एक विद्यार्थी के उग्र राष्ट्रवादी व्यवहार से इतने असन्तुष्ट थे कि वे उसे बोर्डिंग हाउस से जहाँ वह रहता था निकाल देना चाहते थे । मालवीयजी इसे ठीक नहीं समझते थे । पर बहुमत से बात तय हो गयी, और वह विद्यार्थी बोर्डिंग हाउस से निष्कासित कर दिया गया । मालवीयजी को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए उन्हें एक विश्वविद्यालय बनाना होगा । पर उस समय भी जबकि वह विद्यार्थी और उसके समर्थक इस निष्कासन के लिए मालवीयजी को ही मुख्य रूप से दोषी बताते थे, उन्होंने "अन्तरंग सभा की बात को नहीं खोला, और सारी बदनामी अपने ऊपर ओढ़ ली ।"^१

जब सन् १९१० में गोखले साहब ने प्रेस विधेयक का समर्थन और मालवीयजी ने इसका विरोध किया, और इस कारण समाचारपत्रों ने मालवीयजी की बहुत प्रशंसा और गोखले साहब की भर्त्सना की, तब मालवीयजी "बहुत दुःखी थे ।" उन्होंने बहुत ही "बेदना" के साथ मुशी ईश्वरशरण से कहा "गोखले कायर हैं और मैं बहादुर हूँ—यह कहा जा रहा है । कितने परिताप की बात है । यह हृदय-विदारक बात है ।"^२ इसी तरह जब सन् १९२२ में देश के बहुत से नेता गांधीजी की आलोचना कर रहे थे कि उन्होंने सरकार से समझौता नहीं किया, मालवीयजी चुप रहे और जब बात बढ़ जाने पर उन्होंने वक्तव्य

१. मालवीयजी, जीवन झलकिया, पृ० १९ ।

२. वही, पृ० २३-२४ ।

दिया, तब अपने प्रयास की विफलता का रोना रोने के बजाय और उसके लिए गांधीजी को दोषी ठहराने के बजाय उनकी कठिनाइयों की ओर ही संकेत किया।

मालवीयजी का सारा जीवन संघर्ष करते गुजरा। पर उन्होंने कभी किसी का अनहित नहीं चाहा। एक बार उनके सम्बन्धी ब्रजमोहनजी व्यास ने उनसे कहा कि महात्माजी माध ने राजनीति की व्याख्या की है कि “अपना उदय और शत्रु का नाश”। यह सुनकर मालवीयजी की मुस्कान घृणा में परिवर्तित हो गयी, वह बोले, “छिः, दुर्घची राजनीति है। दूसरों का भी अपने साथ-साथ अम्युदय हो, यही सच्ची इलाघनीय राजनीति है।”^१ एक दूसरे अवसर पर उन्होंने व्यासजी ही को उपदेश दिया “अम्युदय की ही कामना करना, किसी को नीचा दिखलाने की नहीं।”^२

निर्माण ही मालवीयजी के संघर्ष और क्रियाकलापों का उद्देश्य था। जैसा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा है : “वे महान् क्रान्तिकारी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके सामने हमेशा बनाने की बात रहती थी, बनाने के सिलसिले में चीजें टूट भी जाती थी, और वे हटा दी जाती थी। वे इससे घबड़ाते नहीं थे—किसी के टूटने में या झाड़ू देकर साफ कर देने में। लेकिन उनका खास ध्यान हमेशा बनाने की ओर रहा। खाली यही नहीं कि संस्थाएँ बनायीं हो, बहुत सारी बनायीं उन्होंने, बल्कि उन्होंने भारत के लोगों को बनाया। वे चाहते थे कि भारत के लोगों में हिम्मत पैदा हो, उनका सिर ऊँचा हो, उनमें अपने ऊपर भरोसा हो।”^३

प्राणिमात्र के प्रति प्रेम

मानवता के प्रतीक मालवीयजी का प्रेम मानवसमाज तक ही सीमित नहीं था। वह प्राणिमात्र के लिए था। गोसेवा में उन्हें विशेष आनन्द आता था। उन्होंने आजीवन गौ-की-सेवा की, उसके कल्याण के लिए प्रयत्न किया। पर उनका प्रेम गौ तक ही सीमित नहीं था। कुत्ते आदि जीवों पर भी उनकी दया बनी रहती थी। शिवरामजी वैद्य ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि जब मालवीयजी नवयुवक थे, तब उन्होंने जख्म के दुःख से तड़पते सड़क पर पड़े एक कुत्ते की वेदना से दुःखी हो उस कुत्ते की सेवा की, स्वयं उसके जख्म पर

१. मालवीयजी—जीवन झलकिया, पृ० १५।

२. वही, पृ० १५।

३. वही, पृ० छ।

दवा लगायी। इस पुस्तक के लेखक को भी एक बार मालवीयजी की समदर्शिता देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने से थोड़ी दूर पर शीतल छाया में बैठे एक कुत्ते को देखकर वे प्रेम और आनन्द में मग्न हो कहने लगे कि "इसमें जो आत्मा है, वही गुप्तमें है। जिस प्रकार मुझे इस स्थान पर बैठे शीतल वायु सेवन करने में आनन्द आ रहा है, इस कुत्ते को भी आ रहा है।"

मालवीयजी जीवगात्र से कितना स्नेह करते थे, उससे समता का अनुभव करते थे, इसका पता इग रोचक घटना से भी अच्छे तौर पर लगता है जिसे उन्होंने स्वयं पण्डित रामनरेश त्रिपाठी को सुनाई थी। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि मालवीयजी ने उनसे कहा—“विछीने पर एक चीटी चढ़ आयी थी, उसे पकड़ कर मैं उसे नीचे उतार देना चाहता था, पर वह हाथ आती ही न थी। इधर पकड़ने जाता तो उधर भाग जाती। अपने बचाव के लिए उसका प्रत्येक बार प्रयत्न बड़ा ही प्रिय लग रहा था। एक चीटी में भी जीवन-रक्षा का वैसा ही उद्योग है, जैसा प्रत्येक प्राणी में है। सब में समान जीव है। जब कोई चीटी को लापरवाही से मार देता है, तब मुझे बड़ा कष्ट होता है।”

शील

मालवीयजी सात्त्विक कर्ता, तथा उच्च कोटि के नेता थे। उनकी सेवाएँ विस्तृत, व्यापक और महान् थी। पर उनका बहुगुण-सम्पन्न व्यक्तित्व उन सबसे कहीं अधिक महान् था। उनकी मनुष्यता, शिष्टता, सज्जनता बेजोड़ थी। वे प्रेम, शान्ति, दया, उदारता, विनय, क्षमा और करुणा के अवतार थे। वे सयमी, निर्भीक और गम्भीर थे, उत्साही, साहसी, और सहनशील थे। उनका जीवन अहंकार, दम्भ, पैशुन आदि दुर्गुणों से निर्मुक्त था। वे मृदुता, मुदितता तथा मैत्री की भावना से सम्पन्न थे। उनका सौजन्य रनेह से परिपूर्ण था, उनकी विद्वत्ता विनय से सम्पन्न थी। वे गुणगाहक थे। राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह, मानव व्यक्तित्व का सम्मान, लोककल्याण की कामना उनके सद्गुण थे। उनका शौर्य और साहस मनुष्यता से अलंकृत था। सत्कार्यों में सहयोग, सौम्यता, भावों की संशुद्धि, सिद्धान्तों और जीवनादर्शों की रक्षा उनके शील के अन्य सद्गुण थे। सभा में राष्ट्रकल्याण की पुष्टि, लोकन्याय का अनुसरण, सदादर्शों से सम्पन्न युक्तियुक्त भाषण, मतभेदों में तितिक्षा, सदा भद्रता का पालन उनका लोकशील था।

मालवीयजी शील के बहुत पक्के थे। उसका उन्हें सदा ध्यान रहता था। जब कभी उनसे उसका उल्लंघन हो जाता, तब उन्हें उसका बहुत सन्ताप होता,

और वे संबंधित व्यक्ति से तुरन्त क्षमा प्रार्थना करते। वे अपनी गलतियों को याद रखते, और पाँचवें छठे वर्ष हरिद्वार जाकर विधिवत् सर्व-प्रायश्चित्त करते, और इस तरह अपने जीवन को निर्मल बनाये रखने का सदा प्रयत्न करते रहते थे।

मालवीयजी का सार्वजनिक सौजन्य बहुत ही उत्कृष्ट था। उनकी स्वच्छता और श्रेष्ठता, उनकी सरलता और विनम्रता, उनकी कोमलता और भद्रता, उनके शिष्टाचार और आतिथ्य सत्कार ने उन सबको, जिन्हें उनके सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपना प्रिय बना लिया था। वे सदा बड़ों का आदर करते, हाथ जोड़ कर उनका स्वागत करते, तथा वयोवृद्ध विद्वानों और संबंधियों की यथावत प्रणाम-वन्दना करते थे। उनका सबके साथ आत्मीयता का व्यवहार था। वे जिससे पहली बार मिलते उससे भी ऐसी बातें करते मानो वह चिर-परिचित है, उसे भी परकीय होने का अनुभव नहीं होने देते। घर में कोई अतिथि टिका होता तो जब तक वह भोजन नहीं कर लेता, चाहे वह साधारण श्रेणी का ही क्यों न हो, तब तक वे स्वयं भोजन नहीं करते थे। अतिथि के आराम की क्या व्यस्था है इस बात की जाँच वे कई बार नौकरो से करते रहते थे।

वे बचपन के अपने साथियों और सहपाठियों से, फिर वे चाहे किसी श्रेणी के हो, कृष्ण-सुदागा की तरह स्नेह और आत्मीयता से बातचीत करते थे। श्री सन्त शरण मेहरोत्रा ने बहुत ही मार्मिक ढंग से एक कुबी जाति के सहपाठी से मालवीयजी के मिलने का एक संस्मरण का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन सन् १९४२ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती के उत्सव के पहले वे मालवीयजी के दर्शन करने गये, तब “एक बूढ़ा ग्रामीण, जिसकी कमर प्रायः झुक गयी थी, लाठी टेकता दरवाजे पर आया। अपनी पगड़ी उतार कर उसने साष्टांग दंडवत किया, तब मालवीयजी की दृष्टि भी उस पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही जो दृश्य देखा गया वह स्वर्गीय था। दोनों के ही नेत्रों से प्रेमाश्रु गिर रहे थे, और किसी से बोला नहीं जाता था। कुछ समय बाद स्वस्थ होने पर कुशल क्षेम, उलहने आरम्भ हुए। ‘एतने दिन कहाँ रहल ? काहे नाही खबर लेहल ? तोहई काहे नाही खोज लेहल ?’ आदि आदि। आँसू बह रहे हैं, बोला जाता नहीं, कण्ठ गरा आता है। बोलने की इच्छा भी दोनों ओर बड़ी प्रबल। बात बात में यह तय हुआ कि गले लगकर जैसे हम लोग गाया करते थे, आज गावें। मालवीयजी से तो गद्गद कण्ठ से बोला ही नहीं

जाता था। उन्होंने इशारा किया कि 'गाओ'। वह उनके पैर पकड़ कर गाने लगा। मुँह में दाँत नहीं, पर उसने प्रेम का वातावरण उपस्थित कर दिया। महात्मा जी (गांधी जी) के पास जाने का प्रस्ताव हुआ। इस सबके बाद वे महाशय वही अतिथि हुए।^१

मालवीयजी मतभेद को व्यक्तिगत विद्वेष या शत्रुता का स्वरूप देना अनुचित ही नहीं, मूर्खता समझते थे। इस द्वेषरहित भावना के कारण जैसा कि मुंशी ईश्वर शरण ने कहा, मालवीयजी ने "कभी कोई शत्रु बनाया ही नहीं।" जो उनसे रुष्ट होता, उससे भी वे भद्रता का व्यवहार करते, और अन्त में वह भी उनका गुणगान करने लगता था। कहा जाता है कि सर राजेन्द्र मुखर्जी को जब यह पता चला कि मालवीयजी इंडस्ट्रियल कमीशन (औद्योगिक आयोग) की रिपोर्ट पर एक असहमति नोट लिखना चाहते हैं, तब उन्होंने मालवीयजी को बहुत बुरा-भला कहा। मालवीयजी चुप रहे। कुछ समय के बाद एक दिन वे सर राजेन्द्र मुखर्जी के घर गये। उन्हें देखकर मुखर्जी साहब ने चकित होकर पूछा, "आप मेरे घर कैसे आये, मैंने तो आपको बुरा-भला कहा था?" यह सुनकर मालवीयजी ने कहा—"देश के काम में हम सब एक हैं। इसके बाद सर राजेन्द्र ने उन्हें उनके कामों में काफी सहायता दी।"^२ वास्तव में "वे लोग भी जो सार्वजनिक प्रश्नों पर उनसे (मालवीयजी से) मतभेद रखते थे उनके व्यक्तिगत गुणों के साक्षी थे, और उनके आत्मत्याग तथा देशहित के प्रति उनकी निष्ठा के लिए उनसे प्यार और उनका आदर" करते थे।^३ यद्यपि कुछ सरकारी अफसर उनसे क्षुब्ध हो उन्हें 'घास में छिपा साँप' समझते थे, पर बहुत से उच्चस्तरीय अधिकारी उनकी 'मधुर विवेकशीलता' के कायल थे। उनकी सच्चाई पर विश्वास करते थे, स्वीकार करते थे कि 'निर्दोष जीवन के श्वेत पुष्प' से विभूषित मालवीयजी को न डराया जा सकता है, और न प्रलोभनों द्वारा तोड़ा जा सकता है, पर उनके सौजन्य और सद्भावना पर विश्वास किया जा सकता है। इन सब बातों को देखते हुए पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि मालवीयजी ने कभी किसी के लिए "भूल कर कटुशब्द का प्रयोग नहीं किया", और "वह अजात-शत्रु" थे।^४

१. मालवीयजी—जीवन झलकियाँ, पृ० ७३।

२. रामनरेश त्रिपाठी: मालवीयजी के साथ तीस दिन, पृ० २७४-२७५।

३. मालवीय कोमिमोरेशन वाल्यूम, पृ० १०५१।

४. मालवीयजी—जीवन झलकियाँ, पृ० ३८।

विनोद, साहित्य, संगीत

मालवीयजी विनोदप्रिय थे। उन्हें संस्कृत, हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के बहुत से पद याद थे, जिन्हें वे प्रसंगानुसार अपने भाषणों और लेखों में उद्धृत करते रहते थे। कभी-कभी अपने विचारों और आन्तरिक भावों को व्यक्त करने के लिए वे बात चीत में भी सहज रूप से कुछ पद सुना देते थे। ये सभी पद शिक्षाप्रद होते थे, ऊँचे धार्मिक सिद्धान्तों, नैतिक आदर्शों, सामाजिक विचारों या भगवद्भक्ति की भावना से विभूषित होते थे। परमनु और व्यास तथा तुलसी, मीरा और सूरदास आदि के पदों के साथ बिहारी और कालिदास आदि के उच्चकोटि के साहित्यिक दोहे और छन्द भी उन्हें याद थे, जिन्हें वे प्रौढ और वृद्ध अवस्था में भी छोटी-सी अन्तरंग साहित्य गोष्ठी में सुना देते थे।

उन्हें ग्रामगीत भी बहुत पसन्द थे। कुछ गीत उन्होंने याद भी कर रखे थे। इन ग्रामगीतों को सुनने-सुनाने में वे बहुत आनन्द का अनुभव करते थे। पंडित रामनरेशजी त्रिपाठी तो, जिन्होंने ग्रामगीतों का अच्छा संग्रह किया था, मालवीयजी से जब मिलते तब वे उनसे उन्हें सुनते थे।

पंडित बलदेव उपाध्यायजी ने अपने एक सस्मरण में लिखा है कि एक बार एकान्त में मालवीयजी की पंडित बटुकनाथजी से साहित्य की चर्चा चल गयी, तब मालवीयजी ने उन्हें बहुत शृङ्गारिक पद्य समुचित अभिनय के साथ कह सुनाये। एक बार काशी विश्वविद्यालय में पंडित प्रमथनाथ तर्कभूषण की अध्यक्षता में कविवर कालिदास पर सगोष्ठी हुई थी, जिसमें कुछ विद्वानों ने उनके काव्य पर कुछ शकाए उपस्थित की थी, जिनका समाधान मालवीयजी ने बहुत उत्तम ढंग से कालिदास के ग्रन्थों के अवतरणों द्वारा किया था।

पर मालवीयजी अश्लील शृङ्गार के प्रति रुचि को बुरा समझते थे। उन्होंने इसके विरोध में १४ वर्ष की आयु में लिखा था—

यह रस ऐसो है बुरो, मत को देत बिगारि।

याते पास न आवहु, जेते अही अनारि॥

विद्यार्थी जीवन में उन्हें कविता करने का भी शौक था, और उन्होंने उस समय कुछ ऐसी रचनाएँ की थी, जिन्हें वे कभी-कभी बुढ़ापे में भी नवयुवकों के विनोद के लिए श्रावण मास में अपने अंतरंग कक्ष में आठ-दस पुराने छात्रों की छोटी-मोटी अन्तरंग गोष्ठियों में सुना दिया करते थे। अपने धार्मिक और सामाजिक विचारों के प्रसार के निमित्त इस वयोवृद्ध नेता ने सरल संस्कृत में कुछ श्लोको और हिन्दी में कुछ छन्दों की भी रचना की थी।

मालवीयजी का स्वर मधुर, सुरीला, सुनम्य और संगीतात्मक था, तथा उनकी प्रकृति कलात्मक थी। अपने पिता की तरह वे भी बचपन से ही संगीत में विशेष अभिरुचि रखते थे। विद्यार्थी-जीवन-काल में ही वे बहुत भावात्मक ढंग से बहुत सुरीले स्वर में सूर और मीरा के पदों को गाने-बजाने लगे थे। इस जमाने में ही उन्होंने सितार बजाने का काफी अभ्यास कर लिया था। पर संगीत में पूरी सुविज्ञता प्राप्त करने के लिए जितने अभ्यास की आवश्यकता होती है, उतनी उन्हें कहा फुर्सत थी? फिर भी कम से कम कठ संगीत में उन्होंने इतनी निपुणता अवश्य प्राप्त कर ली थी कि विभिन्न रागों में गायको और संगीतज्ञों की परीक्षा लेते हुए उसकी त्रुटियां सुधारी जा सकें। पण्डित रामनरेश त्रिपाठी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि एक बार मालवीयजी ने एक गायक से मालकोश, भीमपलारी, कैदारा और विहाग गाने को कहा और अन्त में सोहनी में कुछ गाने को कहा, पर जब वे गायक महाशय इस अन्तिम राग को ठीक तौर पर नहीं गा सके, तब मालवीयजी अपनी अस्सी वर्ष की आयु में स्वयं एक सोहनी, जो उन्हें याद थी, गाने लगे। उसके पद इस प्रकार थे—

नीद तोहे बेचोगी, जो कोउ गाहक होय ।

आये रे ललना, फिर गये अंगना, मैं पापिन रही सोय ।

जो कोउ गाहक होय ।

पण्डित रामनरेश त्रिपाठी अपने संस्मरण में यह भी लिखते हैं कि जब एक बार वह स्त्रिय मालवीयजी को कुछ ग्रामगीत गा कर सुना रहे थे, तब एक गीत को सुनकर वे उठ बैठे और यह कहकर कि—रामनरेश जी, यह मल्हार है, इस तरह गाया जाता है—स्वयं गाने लगे, और उन्होंने उसे उसी “स्वर” में गाया जिस स्वर में सुलतानपुर जिले के गांव पापर की एक जीर्ण शीर्ण बुढ़िया, भवाई के मेले में जाती हुई गा रही थी।^१

इस मल्हार गीत के पद निम्नलिखित थे —

धीरे बहु नदिया तै धीरे बहु सैयाँ मोरा उत्तरइये पार ।

धीरे बहु नदिया ।

काहेन की तोरी नैया रि काहे की कखारि ।

को तेरा नैया खेवैया रे को घन उत्तरहू पार ॥

घरमै कै मोरी नैया रे सत कै लगी कखारि ।

सैयाँ मोरा नैया खेवैया रे, हम घन उत्तरव पार ॥

धीरे बहु नदिया तै धीरे बहु ॥

(बाद्य संगीत और कंठ संगीत, दोनों ही मालवीयजी को प्रिय थे। दोनों ही उन्हें अनुप्राणित और आनन्दित करते थे, तथा उनकी थकावट और परेशानी में स्वास्थ्यवर्धक औषधि का काम करते थे। वे जानते थे, जैसा कि उन्होंने मुंशी ईश्वर शरण से कई बार कहा भी था, कि यदि वे प्रतिदिन आधा घंटा अच्छा संगीत सुन सकें तो उनका स्वास्थ्य बहुत कुछ सुधर सकता है) पर दूसरे सामाजिक कार्यों में व्यस्त मालवीयजी स्वास्थ्य के निमित्त भी घंटा आधा घंटा नहीं निकाल पाते थे। कभी-कभी तो संगीत गोष्ठी का आयोजन करते-करते किसी सार्वजनिक कार्य में संलग्न हो जाते और योजना यो ही पड़ी रह जाती थी। पर फिर भी कभी-कभी महादेव कथक या गायनाचार्य शिवप्रसादजी आदि की गोष्ठी हो जाती थी, और मालवीयजी समुचित मनोयोग से संगीत का रसास्वादन कर पाते थे।

आहार-विहार

मालवीयजी के रहने-सहने तथा खाने-पीने का ढंग सादा, सरल, स्वच्छ था। (वे प्रातः काल सन्ध्योपासना के उपरान्त मिश्री और दूध तथा कोई फल, मध्याह्न को भोजन के बाद गाय के दूध का मट्ठा, सायंकाल को कुछ फल तथा रात्रि को भोजन के कुछ देर बाद गौ के दूध का सेवन करते थे। गर्मी की ऋतु में सायंकाल को बिना भाँग की ठंडाई, तथा रात्रि को चूसे जानेवाले आमो का भी सेवन करते थे। अन्न में गेहूँ के आटे के हलके फुल्के और थोड़ा-सा बारीक चावल का भात, तथा अरहर या भूँग की दाल, तरकारी में परवल-लौकी, नेनुआ, भिंडी, पालक जैसे सुपाच्य पदार्थों का ही वे सेवन करते थे। टमाटर भी उन्हें अच्छे लगते थे। आलू खाना उन्होंने छोड़ दिया था।) पिताजी के श्राद्ध के दिन उन्हें बाग से मँगा कर वे खा लेते थे, क्योंकि उनके पिता को वह बहुत पसन्द थे। मालवीयजी ने पण्डित रामनरेश त्रिपाठी को बताया कि उन्हें घर पर बनी अरहर की दाल, "बहुत पसन्द" थी। उन्होंने कहा : "अरहर की दाल को पहले धी में भूनकर फिर उसे खीलते पानी में डाल दिया जाता था। जब वह अधपकी हो जाती थी, तब उसमें फिर धी डाला जाता था, जिसमें वह मलाई की तरह मुलायम हो जाती थी और बहुत स्वादिष्ट लगती थी।" बुढ़ापे में तो उन्होंने पहले अरहर की दाल का, और बाद में भूँग की दाल का भी सेवन वन्द कर दिया था, चावल खाना भी वन्द कर दिया था। युवावस्था में वे सायंकाल के समय ३०-४० वादाम पिसवा कर पी लिया करते थे। मीठी तथा खट्टी चरपरी चीजों में उन्हें विशेष रुचि नहीं थी। युवावस्था तक वे दूध की बनी

मिठाई खा लेते थे, पर आगे चलकर उन्होंने उसे भी छोड़ दिया था। फलो में उन्हें सेब बहुत पसन्द था। उसकी तरकारी तथा उसके रस का सेवन वे बहुत रुचि से करते थे। जैसे-जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता था, आहार की मात्रा घटती जाती थी, पर दूध और मक्खन की पुरानी मात्रा बुढ़ापे में भी बनी रही। वे अपनी माता के आदेशानुसार एक सेर दूध तथा आधी छटाँक मक्खन का सेवन करते थे। (उनका कहना था कि “बुढ़ापे का जिउ, दूध और घिउ।” अस्सी वर्ष की आयु में भी वे प्रातःकाल दवा के साथ मक्खन और दूध, दोपहर और रात्रि को भोजन के साथ मक्खन या घी, सायंकाल को थोड़ा-सा दूध और सोते समय दवा के साथ दूध पीते थे।)

यात्रा में वे बहुधा रसोइये की अनुपस्थिति में स्वयं खिचड़ी पका कर उसका सेवन कर लेते थे। रेल की लम्बी यात्रा में वे बहुधा दूध में गुंघे आटे की घी की पूड़ियाँ तथा मोहनभोग का प्रयोग करते थे। बहुत निश्चित व्यक्तियों द्वारा समाचार मिलने पर गौ के दूध के साथ इस प्रकार के भोजन का या फलाहार का प्रबन्ध स्टेशन पर कर दिया जाता था। पर कभी-कभी समुचित प्रबन्ध न होने पर उन्हें उपवास भी कर लेना पड़ता था।

(उनके शाकाहारी भोजन में चाय, काफी, लहसुन, प्याज, मादक द्रव्य तथा गैस मिश्रित पेय पदार्थों का कोई स्थान नहीं था। वे तो मिर्च, मसाला तथा पान का भी सेवन नहीं करते थे। भोजन के बाद सुपारी की थोड़ी सी डली प्रायः मुख में डाल लिया करते थे। मालवीयजी चाय को बड़ी ही हानिकर वस्तु समझते थे।) उन्होंने पण्डित रामनरेश त्रिपाठी जी को बताया कि उन्होंने एन्ट्रेन्स और एफ० ए० की परीक्षाओं के समय कुछ दिनों तक चाय का प्रयोग किया था, पर उसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। बहुत से सार्वजनिक कार्यों में घिरे रहने के कारण भोजन में उन्हें प्रायः बहुत विलम्ब हो जाता था।

मालवीयजी के परिवार में पहले सिर पर पंडताऊ टोपी, कलीदार अंगरखा, और देशी जूता पहनने का चलन था। उनकी पोशाक भी पहले यही थी। मऊ (जिला आजमगढ़) की बनी हुई रेशमी किनारे की बारीक और चौड़े पनहे की धोती उनको बहुत पसन्द थी। लम्बी बन्ददार अचकन, सिर पर भली-भाँति संवारा हुआ विशेष प्रकार का साफा, गले में घुटनो तक लटकता हुआ दुपट्टा, एवं ललाट पर मलयागिरि चंदन उनके सुघर और गौर वर्ण पर विशेष शोभा देते थे। पगड़ी और दुपट्टे के संवारने में वे काफी सावधानी रखते थे। वे समयानुकूल धोती और पैजामा दोनों का प्रयोग करते थे। अधिक वृद्ध हो

जाने पर उन्होंने पगड़ी के स्थान पर पंडताऊ टोपी का प्रयोग भी प्रारम्भ कर दिया था। मध्यवय में ही उन्होंने चमड़े के जूतों के बजाय खुर की तली के जूते पहनना शुरू कर दिये थे। जाड़ी की ऋतु में वे ऊनी लबादे का तथा शाल (चादर) का भी प्रयोग करते थे। पूजा पाठ के समय, कथा सुनाने के समय, तथा भोजन करते समय वह बुद्ध रेशमी वस्त्र का प्रयोग करते थे। उनके वस्त्र स्वदेशी और शुभ्ररंग के होते थे। सत्रह वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्वदेशी का व्रत ले लिया था। सन् १९२० के बाद वे खदर का प्रयोग विशेष रूप से करने लगे थे।

गुणियाँ

बहुगुणसम्पन्न मालवीयजी के कतिपय सद्गुणों ने उनके लिए काफी कठिनाइयाँ भी पैदा कर दी थी। गांधीजी कहा करते थे कि “मालवीयजी की दया उनका दुश्मन बन गयी है।” दया के पात्र और कुपात्र उन्हें सदा घेरे रहते थे। अपने सच्चे और बनावटी कष्टों की अतिरजित बातों से वे उन्हें दुःखी करते रहते थे। मानव स्वभाव के प्रति उनकी उदार भावना भी उनके लिए कठिन पहेली बन गयी थी। इस उदारता के कारण उनके लिए मनुष्यों की आन्तरिक भावनाओं का सही मूल्यांकन करना बहुधा कठिन हो जाता था। मनुष्यों के सम्बन्ध में उनका अनुमान प्रायः यथातथ्य से अधिक उदार होता था, जिसके कारण उन्हें बाद की कभी-कभी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ जाता था। दूसरों की भावनाओं के प्रति आदर भावना ने भी उनकी जीवनचर्या को किसी अंश में अव्यवस्थित और उनके जीवन को कष्टमय बना दिया था। उनका शील-संकोच उन्हें वक्त वेवक्त लोगों से मिलने को मजबूर करता था, जिसके कारण वे न ठीक समय पर भोजन कर पाते थे, और न ठीक से आराम कर पाते थे। पूर्व निश्चित सार्वजनिक काम करने में भी उन्हें देर हो जाती थी। उनकी समाजसेवा की भावना ने भी उन पर उत्तरदायित्व का इतना बोझ लाद दिया था, जिसका ठीक-ठीक निर्वाह उन जैसे कर्मठ समाजसेवी के लिए भी असम्भव हो रहा था। दिन-रात काम में लगे रहने पर भी काम अधूरा रह जाता था, उनके सहयोगियों को उनसे शिकायत बनी रहती थी। उन्हें भी उसकी चिन्ता सदा बनी रहती थी। समाजसेवा की चिन्ता से वे अपने को कभी भी मुक्त नहीं कर सके। पचपन वर्ष से अधिक समाजसेवा करने के बाद भी सेवा की उत्कट इच्छा बनी रही, अपनी बड़ी-बड़ी योजनाओं के अपूर्ण अंशों की याद उन्हें मरते दम तक परेशान करती रही। आत्मोत्सर्ग और आत्मसमर्पण की

भावनाओं ने उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत हद तक उपेक्षित बना दिया था। उन जैसा विनोद-प्रिय व्यक्ति भी जीवन में मनोरंजन के महत्त्व को भूल-सा गया था। स्वास्थ्यवर्धक संगीत के लिए भी वे आधा घण्टा नियमित रूप से नहीं निकाल पाये। पीछे की चीजों को पकड़े रहने की प्रवृत्ति से उनको विद्वद् भी, फिर भी समाज-सुधार के प्रश्नों पर उन्होंने शास्त्रों की रस्सी इस तरह पकड़ रखी थी कि इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ कर काम करना उनके लिए कठिन हो रहा था। वे मानवता के व्यापक सिद्धान्तों के आधार पर समाज-सुधार की कोई योजना जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर सके। श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर जैसे व्यक्ति भी, जिन्होंने स्वयं हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तुत हिन्दू बालविवाह विधेयक पर मालवीयजी के साथ वोट किया था, उन्हें प्रचलित अर्थों में समाजसुधारक कहने को तैयार नहीं थे। उनकी तितिक्षा, दूसरों के विचारों और भावनाओं का आदर करने की उनकी प्रवृत्ति, प्रत्येक विषय के सब पक्षों पर विचार करने की उनकी आदत के कारण भी बहुधा महत्त्वपूर्ण विषयों पर कोई निर्णय लेने में उन्हें बहुत समय लग जाता था, और कभी-कभी तो समझौते की प्रबल इच्छा के कारण या तो उनके लिए निर्णय लेना ही असम्भव हो जाता था, या समझौते की छाप के कारण निर्णय की स्पष्टता या निदेशकता धूमिल हो जाती थी। पर कभी-कभी उनकी दृढ़ता जिद का रूप धारण कर लेती थी, उन्हें व्यावहारिकता से विलग कर देती थी। फिर भी प्रायः उनके जिस विचार को दूसरे लोग अव्यावहारिक कल्पना या जिद समझते थे, उसे वह कार्यरूप में परिणत कर उसकी व्यावहारिकता और सार्थकता सिद्ध कर देते थे। काशी विश्वविद्यालय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रायः मालवीयजी के जिस विचार को उग्रगामी निरर्थक, गतिरोधात्मक समझते थे, वह परिस्थिति विशेष में देश की अधिकांश जनता का मार्गदर्शन करने में, उसका नेतृत्व करने में, उसे आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता था। रूढ़िवादियों को भी सुधार की ओर प्रवृत्त करना उनके नेतृत्व का गुण था।

अद्वितीय व्यक्तित्व

उनके व्यक्तित्व की सर्वतोमुखी प्रतिभा, साहस एवं उत्साह और त्याग, तथा राष्ट्र-सेवा में उनकी निष्ठा और लगन अतुलनीय थी। उनका व्यक्तित्व निश्चय ही अद्भुत था। वे निःसन्देह उच्चकोटि के जननायक तथा राष्ट्र-निर्माता थे। राष्ट्र के नेताओं में उनका बहुत ऊँचा स्थान था। गांधीजी का कहना था कि मालवीयजी के साथ देशभक्ति में कौन मुकाबला कर सकता है? राजर्षि

पुरुषोत्तमदास टण्डन के विचार में मालवीयजी “आदर्श मनुष्य थे”, जिन्होंने “राजनीति और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में युग परिवर्तक और प्रवर्तक का काम किया।”^१ प्रिन्सिपल दीवानचन्द के विचार में “मालवीयजी पवित्र आत्मा थे। उनके व्यक्तित्व की मनोहरता का उनके लाखों समकालीन लोगो पर उदात्त प्रभाव था।”^२ बंगाल के सुप्रसिद्ध देशभक्त वैज्ञानिक सर प्रफुल्लचन्द्र रॉय का विचार था कि “गांधीजी के बाद कोई दूसरा ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है जिसने इतना अधिक त्याग किया हो, और बहुमुखी कार्यों का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हो जैसा मालवीयजी ने”।^३ लिबरल पार्टी के प्रमुख नेता श्री सी० वाई० चिन्तामणि का भी विचार है कि “मालवीयजी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सावरमती के मनीषी (गांधी जी) के कोष्ठक में रखने योग्य हैं।”^४ दूसरे उदार-दिलीय नेता पंडित हृदयनाथ कुंजरू का विचार है कि “गांधीजी को छोड़कर उनसे बड़ा भारतीय कोई नहीं हुआ।”^५ मुंशी ईश्वर शरण का कहना है कि “हम दूसरे सार्वजनिक पुरुषों की योग्यता और व्यवहार-कौशल को स्वीकार करते हैं, पर महात्मा गांधी को छोड़कर कोई दूसरा हमारा हृदय उस प्रकार आकर्षित नहीं करता जैसा मालवीयजी”।^६ उन्होंने यह भी कहा कि यह उनका “अटल विश्वास है कि जब तक भारत गांधीजी और मालवीयजी जैसे व्यक्तियों को जन्म देता रहेगा, तब तक भारत जीवित बना रहेगा।”^७ भर्तृहरि ने महात्मा के प्रकृतिसिद्ध लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है—

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम ।

यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुती, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥

अर्थात् विपत्ति में धैर्य, सम्पत्ति में क्षमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में विक्रम, यश में रुचि, शास्त्र में लगन—ये गुण महात्माओं में स्वभाव से ही होते हैं।

ये सभी गुण मालवीयजी में स्वभावतः विद्यमान थे, और वे निःसन्देह बहुगुण-सम्पन्न महात्मा तथा सात्त्विक कर्ता थे।

१. महामना मालवीयजी : वर्थ सेनटिनरी कोमिमोरेशन वाल्यूम ।

२. वही, पृ० २१५ ।

३. मालवीय कोमिमोरेशन वाल्यूम, पृ० १००५ ।

४. वही, पृ० १०१२ ।

५. मालवीयजी—जीवन श्लकिया, पृ० ४८ ।

६. मालवीय कोमिमोरेशन वाल्यूम, पृ० १०५१ ।

७. वही ।

२६. संयुक्त स्वशासित भारतीय राष्ट्र

मालवीयजी साम्प्रदायिकता के बजाय राष्ट्रीयता के आधार पर राजनीतिक जीवन का निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने सन् १९०९ में एक ओर मुस्लिम लोग की साम्प्रदायिक राजनीति का तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँग का विरोध किया, दूसरी ओर पंजाब हिन्दू महासभा की साम्प्रदायिक राजनीति की भर्त्सना करते हुए हिन्दू जनता से कांग्रेस का समर्थन करने का अनुरोध किया। वे कई वर्ष तक हिन्दू महासभा से अलग रहे, और जब सन् १९२२ में उन्होंने अखिल भारतीय हिन्दू महासभा का नेतृत्व स्वीकार किया, तब हिन्दू समाज की रक्षा तथा हिन्दुओं के सामाजिक संगठन को दृढ़ करना, उसकी क्रूरतियों को दूर करना, तथा भारतीय राष्ट्र की पुष्टि के लिए अन्य धार्मिक जातियों से मित्रता बढ़ाना उसका लक्ष्य निश्चित कराया। उन्होंने हिन्दू महासभा के मंच से हिन्दू संघटन के साथ-साथ स्वराज्य की भाग पर, तथा स्वतंत्रता के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर दिया, साम्प्रदायिकता के बजाय व्यापक राष्ट्रीयता का समर्थन किया, और घोषित किया कि हम अपने संगठन द्वारा अपने धर्म और मान की रक्षा करना चाहते हैं, किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाहते, किसी के ऊपर प्रभुत्व या अधिकार भी नहीं चाहते हैं, चाहते हो तो परमात्मा हमें दण्ड दे।^१ वे तो उस समय भी यही चाहते थे कि “हिन्दू और मुसलमान भाई जिन कामों में मिलकर काम कर सकते हो करें, शहर नगर की रक्षा में, नागरिक दलों में सब मिलकर एक साथ काम करें।”^२ उनकी यही कामना थी कि “दोनों साथ-साथ रहें और प्रेम से रहें और सोलह आने राष्ट्रवादी बनने का उपाय करें, जिससे देश अपने पुराने वैभवयुक्त स्थान को प्राप्त कर सके और भारत भारतवासियों का ही हो जाय।”^३ दिसम्बर सन् १९२७ में हिन्दू महासभा के मद्रास अधिवेशन में मालवीयजी ने हिन्दू महासभा के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए कहा, “राष्ट्रीयता हिन्दू सभा का उतना ही लक्ष्य है, जितना हिन्दुत्व।”^४ उन्होंने बताया कि हिन्दू सभा के दो उद्देश्य हैं—(१) हिन्दू समाज के सब वर्गों में अधिक से अधिक एकता

१. हिन्दू महासभा, सन् १९२३, अध्यक्षीय भाषण।

२. वही।

३. हिन्दू महासभा, दिसम्बर १९२४, बेलगाव अधिवेशन।

४. इंडियन क्वाटरली रजिस्टर, सन् १९२७, जि० २, पृ० २५३।

और संहति बैठाना, और उन्हें एक सूत्र में सगठित करना, तथा (२) हिन्दुओं और हिन्दुस्तान के दूसरे सम्प्रदायों में सद्भावनाओं को प्रोत्साहित करना और संयुक्त स्वशासित भारतीय राष्ट्र की उपलब्धि के निमित्त उनके साथ मैत्री-पूर्वक ढंग से वर्ताना करना ।^१

मालवीयजी हिन्दूराष्ट्र और मुस्लिमराष्ट्र, तथा हिन्दूराज्य और मुस्लिमराज्य के सिद्धान्तों के विरोधी थे । वे तो सब भारतवासियों को भारतीय राष्ट्र का अंग स्वीकार करते थे, और देशबन्धुता और देशप्रेम के आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करते हुए उसकी बुनियाद पर भारतीय राज्य प्रतिष्ठित करना चाहते थे । वे देश में एक ऐसा भारतीय प्रशासन स्थापित करना चाहते थे जिसके संचालन में सब जाति, सम्प्रदाय और प्रान्त के सदस्यों का सहयोग हो, जिसके द्वारा समान रूप से सबके अधिकारों और हितों की समुचित रक्षा हो । वे प्रधानमंत्री मेकडोन्ल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय के इसलिए विशेष रूप से विरोधी थे कि उसके द्वारा विभिन्न प्रान्तों में भारतीय शासन के बजाय हिन्दू प्रशासन और मुस्लिम प्रशासन कायम हो जायेंगे, जो राष्ट्र की प्रगति और साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए घातक होंगे, और जिनके द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा असम्भव होगी । उन्होंने तो सन् १९२४ में कह दिया था कि "राष्ट्रीय सरकार और जातिगत शासन दोनों एक साथ चल नहीं सकते । राष्ट्रवाद और जातिवाद एक साथ ठहर नहीं सकते ।"^२ सन् १९४१ में प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रसंघ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि "हिन्दू राज्य और मुस्लिम राज्य के दिन लद गये । हमें अब भारतीय राज्य की बात ही सोचनी चाहिए" । वे चाहते थे कि सब हिन्दू इस बात का ध्यान रखें कि "वे पहले भारतवासी हैं, बाद को हिन्दू हैं,"^३ और देशभक्त पारसियों, मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों आदि से मिलकर देश की उन्नति करना उनका कर्तव्य है । वे मानते थे कि जबतक हम यह निश्चय नहीं कर लेते कि हमारे सब सम्बन्ध देशप्रेम पर स्थापित हों, तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते ।^४

राष्ट्रीयता की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा था कि "राष्ट्रीयता उस भावना का नाम है जो देश के सम्पूर्ण निवासियों के हृदय में देश-हित की लालसा

१. वही ।

२. हिन्दू महासभा, दिसम्बर १९२४, बेलगाव अधिवेशन ।

३. हिन्दू महासभा, गया अधिवेशन, १९२२ ।

४. लाहौर में भाषण, जून सन् १९२३ ।

में व्याप रही हो, जिसके आगे अन्य भावों की श्रेणी नीची ही रहती हो।”^१ देशभक्ति की महिमा का बखान करते हुए उन्होंने लिखा था : “गाढ़ देशभक्ति से एकता उत्पन्न होती है, एकता से राष्ट्रीयता का भाव, और राष्ट्रीयता के भाव से देश की उन्नति होती है”^२। उन्होंने बताया कि जिस तरह भगवद्भक्त वे होते हैं जो अपने समस्त कार्यों को भगवान् को अर्पण कर देते हैं, और एकाकी लगन से भगवान् का ध्यान और उपासना करते हैं, सच्चे देशभक्त वे हैं जो “कुछ करे धरें, सब कुछ देश ही के लिए हो, और देश के कार्य में प्रतिक्षण तत्पर रहें, और एकाकी लगन से देश की सेवा में लगे रहें”^३।

इन सब से यह स्पष्ट है कि मालवीयजी चाहते थे कि “देश ही समस्त देशवासियों के प्रेम और भक्ति का विषय बन जाय,” “मतभेद, वर्गभेद, जातिभेद के होते हुए भी राष्ट्रीयता का श्रेष्ठ भाव देशव्यापी हो जाय, और इतना बढ़ जाय कि उसके आगे अन्य भावों का दर्जा नीचे गिर जाय”^४।

भारतीय राष्ट्र की भावना को सुदृढ़ करने के लिए मालवीयजी प्रत्येक विद्यार्थी को देशप्रेम और नागरिकता की ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जो साम्प्रदायिकता को जलमग्न कर दे।^५ वे चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय कौटम्बिक तथा धार्मिक स्तर पर अपनी पुरानी सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करते हुए सार्वजनिक और राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता की सर्वमान्य मान्यताओं का पालन करे, तथा लोकतन्त्र की पृष्ठभूमि में प्राचीन हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियों के विश्वजनीन सजीव तत्त्वों के संश्लेषण से सर्वमान्य मर्यादाएं विकसित की जायें।

मालवीयजी की राष्ट्रीय भावना मानवता से विभूषित थी। वे मानवमात्र की एकता पर विश्वास करते थे, और संकीर्ण आक्रमणशील राष्ट्रीयता के विरोधी थे। वे राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना आवश्यक समझते थे, पर किसी दूसरे राष्ट्र की स्वतन्त्रता का अपहरण अमानुषिक समझते थे। वे न किसी के साथ अन्याय करना चाहते थे, और न किसी का अन्याय सहन करने को तैयार थे। वे चाहते थे कि देश का प्रत्येक नवयुवक अपने जीवन को

१. मालवीयजी के लेख, पृ० ९९।

२. वही, पृ० १००।

३. वही, पृ० १०८।

४. वही, पृ० ९९।

५. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, दीक्षान्त भाषण, सन् १९२९।

शीर्य से विभूषित करे, अपने में अपने राष्ट्र और समुदाय की रक्षा की शक्ति पैदा करे। पर वे शीर्य को मनुष्यता और न्यायनिष्ठा से अलंकृत करना भी आवश्यक समझते थे। मनुष्यता से समन्वित शीर्य ही उनके विचार में, न्याय और मानवकल्याण का आधार बन सकता है, मनुष्यता-विहीन शीर्य तो दमन, क्रूरता, अन्याय का ही उपकरण हो सकता है। उनकी धारणा थी कि “ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है,” यद्यपि “लोग पुरुष और स्त्री में भेद करते हैं, लेकिन जहाँ तक ईश्वर की ज्योति का सम्बन्ध है उनमें विलकुल भेद नहीं।”^१

मालवीयजी राष्ट्रपति विलसन के चौदह सूत्रीय कार्यक्रम पर विश्वास करते थे, और चाहते थे कि उनके आधार पर संसार में विश्वन्याय और शान्ति प्रतिष्ठित की जाय। कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय शर्तों के साथ समुद्रो की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय रक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सेना और युद्ध सामग्रियों में कटौती, सब शान्तिप्रिय राष्ट्रों में व्यापार की समानता, जनता की प्रभुसत्ता और कल्याण के आधार पर सब औपनिवेशिक प्रश्नों का समाधान, पराजित राज्यों की भूमि से विजयी राष्ट्रों का निष्कासन, बड़े-छोटे राज्यों की राजनीतिक स्वतन्त्रता और भौमिक अखण्डता, उसकी गारंटी के लिए सब राष्ट्रों के संघ का संगठन—ये मालवीयजी के कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त थे।^२

मालवीयजी निरंकुशता और परतन्त्रता के विरोधी, तथा वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक थे। उनके विचार में निरंकुशता तथा विदेशी शासन एक “ऐसा घोर अभिशाप है जो जनता के पुरुषत्व को नष्ट कर देता है, और उसकी नैतिक प्रकृति को बुरी तरह विकृत कर देता है।” उनका कहना था कि पराधीनता से “जेता और विजित दोनों समुदायों में से मनुष्यत्व दूर भागता है—स्वतन्त्रता का न होना, उन्नति के अवसरो को खोना है, उन्नति के अवसरो को खोना अधःपतन है, और अधःपात मृत्यु के तुल्य है।”^३

दमन, अन्याय और परतन्त्रता का विरोध वे मानव का पुनीत कर्तव्य समझते थे, और वे स्वयं जीवन भर इसी काम में संलग्न रहे। न्याय, स्वतन्त्रता

१. कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, सन् १९२८, अध्यक्षीय भाषण।

२. वही।

३. अभ्युदय : १९ मई सन् १९१२।

और जनकल्याण की प्रतिष्ठा ही उनका जीवन लक्ष्य था। इसके लिए वे जन-जागृति, जनसंगठन, जनान्दोलन तथा जनकल्याण की भावना नितान्त आवश्यक समझते थे। न्याय के प्रति दृढ़ निष्ठा, तथा सब कामों में उसका सदा अनुसरण, वे एक सार्वजनिक कार्यकर्ता का कर्तव्य समझते थे। कार्य की सफलता के लिए वे साहस, उत्साह, लगन और शौर्य के साथ-साथ धैर्य, सयम तथा दुर्भविनाओं पर नियंत्रण भी आवश्यक समझते थे। उनका अपना सार्वजनिक जीवन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वे आजीवन अन्याय और अत्याचार से संघर्ष करते रहे, पर विषम से विषम परिस्थिति में भी उन्होंने दुर्भविनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, सदा सज्जनता और मनुष्यता का पालन किया, किसी का अनहित नहीं चाहा।

समाज का परिशोधन तथा राष्ट्र का पुनर्निर्माण ही वे रचना और संघर्ष दोनों का लक्ष्य समझते थे। वे संघर्ष को साध्य के बजाय रचना की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग स्वीकार करते थे, और उनके सब संघर्ष रचना की भावना से अनुप्राणित, रचनात्मक कार्य से समन्वित, तथा व्यक्तिगत कटाक्ष से निर्मुक्त होते थे। वे सार्वजनिक जीवन में लोकतांत्रिक शील और मर्यादाओं का पालन आवश्यक समझते थे, और उन्होंने सदा सब परिस्थितियों में स्वयं उसका पालन किया। मालवीयजी चाहते थे कि अन्याय का विरोध भी यथासंभव संवैधानिक ढंग से कानून की सीमा में रहते हुए किया जाय, पर वे अहिंसात्मक शान्तिमय सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह को भी संवैधानिक स्वीकार करते थे, और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग भी उचित समझते थे। परतन्त्रता के विरुद्ध तो सुसंगठित हिंसात्मक विद्रोह को भी वे न्यायसंगत मानते थे, और उपयुक्त परिस्थितियों में उसका प्रयोग उचित समझते थे। आत्मरक्षा के निमित्त आततायी का हिंसात्मक प्रतिरोध भी वे न्यायसंगत समझते थे, पर वे आतक, उद्दण्डता, और तोड़-फोड़ की प्रक्रिया को ठीक नहीं मानते थे।

मालवीयजी वयस्क मताधिकार, तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति द्वारा चुनी जनता की सरकार को ही सर्वोत्तम समझते थे। वे जाति, सम्प्रदाय, या सम्पत्ति को मताधिकार का आधार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनके विचार में आय और सम्पत्ति का स्वामित्व अनिवार्य रूप से योग्यता और चरित्र का परिचायक नहीं है, न ही सम्पत्ति का अभाव मम्मन की कमी का सूचक समझा जा सकता है।^१ एक निर्धन व्यक्ति भी सदाचारी, लोकसेवक तथा जनविश्वास

ने अपने हाथों से सूर्य की किरणों के रूप में ही गनुष्य स्वभाव पर अंकित कर दिये हैं जो किसी मानव की शक्ति से मिटाये नहीं जा सकते ।” उनके विचार में नागरिक स्वतंत्रता मानव के प्राकृतिक अधिकारों पर आश्रित मानव के नैतिक अधिकार हैं जिनकी मान्यता और रक्षा राज्य का कर्तव्य है ।

मालवीयजी के विचार में वही राज्य सुव्यवस्थित है जिसमें सब जाति और सम्प्रदाय के नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उपभोग की पूरी स्वतंत्रता हो । वे धार्मिक स्वतंत्रता को मानव का मौलिक अधिकार स्वीकार करते थे, पर धर्म-ग्रन्थों, धर्मगुरुओं और उपास्यदेवों और उपास्य-स्थलों का आदर प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य समझते थे । राज्य द्वारा अन्तःकरण का नियंत्रण नि सन्देह अमानुषिक है । किसी एक धर्म को राष्ट्र-धर्म की मान्यता प्रदान कर दूसरे धर्मों की उपेक्षा अवश्य ही अन्याय है, धार्मिक विद्वेष और कलह का हेतु है । वे अन्तःकरण की स्वतंत्रता तथा धार्मिक त्रितिक्षा और सद्भावना के महत्त्व को स्वीकार करते थे । वे धर्मनिष्पक्ष राज्य के समर्थक थे । वे चाहते थे कि धार्मिक स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता का महत्त्वपूर्ण अंग स्वीकार करते हुए सविधान द्वारा उसे ठीक तीर पर इस तरह सुरक्षित किया जाय कि बहुसंख्यक सम्प्रदाय अपने बहुमत के दाय पर अल्पसंख्यक सम्प्रदाय की स्वतंत्रता अपहरण न कर सके । वे चाहते थे कि भारतीय लोकतान्त्रिक राज्य में सब नागरिकों को अपने-अपने विश्वास के अनुकूल धार्मिक जीवन व्यतीत करने की, धार्मिक कृत्यों को करने की, तथा अपने धार्मिक विचारों के प्रगिक्षण और प्रसार करने की स्वतंत्रता हो । धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय । न कोई राज्य-धर्म हो, और न राज्य की ओर से किसी धर्म का प्रचार किया जाय । धार्मिक विश्वास या आचरण के कारण किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाय । धार्मिक आचरण या विश्वास तथा मत का सरकारी नौकरी या अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़े ।

मालवीयजी स्वीकार करते थे कि युद्ध कहे जाने योग्य फसादों की स्थिति में तथा व्यापक राजविद्रोह की स्थिति में मार्शल-ला (फौजी कानून) लागू किया जा सकता है, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं । पर उनकी राय में इस स्थिति में भी फौजी अदालतों और फौजी कानून की मर्यादाओं और सीमाओं का ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है । इस स्थिति में

भी सरकार द्वारा उतने ही बल का प्रयोग किया जा सकता है जितना शान्ति स्थापित करने के लिए आवश्यक हो, विधि-व्यवस्था प्रतिष्ठित करने के नाम पर निरर्थक हत्याओं और प्रतिबन्धों द्वारा आतंक स्थापित नहीं किया जा सकता। फौजी कानून अर्थात् मार्शल-ला तभी तक जारी रखा जा सकता है जब तक वह नितान्त आवश्यक हो, उसके बाद उसे जारी रखना अत्याचार और अन्याय है। हत्याओं और आग लगाने के अपराधों की जाँच ही फौजी अदालतों में हो सकती है। राजविद्रोह और व्यापक फसादों की स्थिति में सरकार का उत्तरदायित्व अवश्य बढ़ जाता है, और उसके साथ ही उनके अधिकारों में भी वृद्धि हो जाती है, पर न्याय का पालन करना उनका कर्तव्य बना रहता है।^१

मालवीयजी की दृढ़ धारणा थी कि मार्शल-ला के जमाने में किये गये सरकारी अत्याचारों की निष्पक्ष आधिकारिक जाँच नितान्त आवश्यक है। उस जमाने में भी निर्दयतापूर्ण व्यवहार अन्याय है, और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी इस प्रकार के व्यवहार के लिए व्यक्तिगत हैसियत से उत्तरदायी और दण्डनीय है, पीड़ित उसके विरुद्ध दोषानी और फौजदारी अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। मालवीयजी का कहना था कि "नागरिकों की तरह सैनिकों का भी यह अधिकार है कि वे शस्त्र से शस्त्रचारी का सामना करें और जानमाल की रक्षा के लिए उचित उपायों का प्रयोग करें, पर यदि सैनिक निहत्थे और विरोध न करनेवाले मनुष्यों की हत्या करेगा, तो वह हत्या का दोषी होगा और उस पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है। क्षमा अधिनियम द्वारा दोषी अफसरों को दोष के उत्तरदायित्व से किसी हद तक मुक्त किया जा सकता है। पर इस प्रकार का कानून पास करने से पहले विधान सभा को सन्तुष्ट होना होगा कि शान्ति और व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए मार्शल-ला लागू करना नितान्त आवश्यक था। कानून के अन्दर क्षमा की सीमाओं को भी निर्धारित करना होगा। हर प्रकार के अत्याचारों और दोषों को क्षमा नहीं किया जा सकता। वही व्यवहार क्षमा किये जा सकते हैं जो व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित न हों, और उचित सावधानी के बावजूद हो गये हों, या जो ईमानदारी के साथ इस विश्वास में किये गये हों कि शान्ति और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऐसा करना जरूरी था।"^२

यद्यपि मालवीयजी मानव के मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास की समुचित व्यवस्था लोकतन्त्र का महत्वपूर्ण कार्य समझते थे, फिर

१ प्रोसीडिंग इण्डियन लेजिस्लेटिव कौंसिल, सन् १९१९, जि० ५ - १।

२. वही।

भी वे उन विचारको से सहमत नहीं थे जो व्यक्तिवाद को लोकतंत्र का अनिवार्य अंग स्वीकार करते थे। वे तो व्यक्तिवाद के विरोधी, तथा सामाजिकता और जनकल्याण राज्य के समर्थक थे। वे सामाजिकता को मानव स्वभाव का महत्त्वपूर्ण लक्षण और सद्गुण मानते थे, और मानवव्यक्तित्व के विकास के लिए मानव स्वतंत्रताओं की रक्षा के साथ साथ मानव समाज की पुष्टि और विकास आवश्यक समझते थे। उनकी दृढ़ धारणा थी कि “भारत के प्राचीन धर्म की शिक्षा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने को एक बड़ी समष्टि की इकाई समझ कर उसके हित के लिए जीवित रहे और काम करे, लोककल्याण और लोकसंग्रह को परम पुरुषार्थ समझे।”^१ उनके विचार में स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व का सामंजस्य ही नैतिक और सामाजिक जीवन का मूलाधार है। उत्तरदायित्व से रहित स्वतंत्रता उच्छृंखलता है, और स्वतंत्रता-विहीन उत्तरदायित्व दासता है।

जनकल्याण की वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न वे राज्य का परम कर्तव्य समझते थे। उनके विचार में “जनता को स्थिति में सुधार ही अच्छी सरकार की कसौटी है”, और इस कर्तव्य का निर्वाह करके ही कोई सरकार “सभ्य सरकार” होने का दावा कर सकती है।^२ वे चाहते थे कि विधितन्त्र, राजकोष तथा वित्तीय नीति द्वारा जनकल्याण की पुष्टि और वृद्धि की जाय, वही कानून बनाये जायें जिनसे जनता की स्वतंत्रता की रक्षा हो, सामाजिक न्याय की पृष्टि हो, श्रमिक जनता (किसान मजदूर) का अभ्युदय हो। वे चाहते थे कि सरकार द्वारा ऐसी वित्तनीति अपनायी जाय जिससे देश के आर्थिक हितों की रक्षा और उसकी समृद्धि की वृद्धि हो। वे चाहते थे कि सरकार दुर्गति की स्थिति में जनता की सहायता करते हुए अपनी शक्ति और साधनों को जनता की शक्ति के निर्माण में, लोगों के मस्तिष्क को ज्ञान से प्रदीप्त करने में, उनके घरों के प्रतिवेश के सुधारने में, तथा आमदनी के नये स्रोतों को अपनाने की उनमें क्षमता पैदा करने में लगाये ताकि वे सभ्य संसार में सुखी गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।^३

जनकल्याण राज्य की उनकी कल्पना किसी अंश में आपस्तम्ब, नारद और भीष्म के विचारों पर, और किसी अंश में ब्रिटेन के समकालीन विचारकों की धारणाओं पर आधारित थी। वे निःसन्देह सामाजिक उदारवाद के पोषक थे, जो किन्हीं सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक न्याय पर आश्रित उदारवादी समाजवाद (लिवरल सोशलिज्म) का रूप धारण कर सकता था।



१. सन् १९०४ में विश्वविद्यालय की योजना का प्रारूप।
२. प्रान्तीय कौंसिल में भाषण, सन् १९०७।
३. प्रान्तीय कौंसिल में भाषण, सन् १९०८।

२७. जनकल्याण और सामाजिक न्याय की वृद्धि

सामाजिक न्याय, जनकल्याण और राष्ट्रहित मालवीयजी के आर्थिक मीमांसा के मूलमन्त्र थे। वे चाहते थे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था सामाजिक न्याय पर आश्रित हो, जनकल्याण और राष्ट्रहित की वृद्धि उसका लक्ष्य हो, न्यासिता की भावना से वह अनुप्राणित हो।

उनके कुछ आर्थिक विचार प्राचीन भारतीय विद्वानों के आदेशों पर आश्रित थे, पर बहुत से विचार आधुनिक थे। वे मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुकूल ऋण व्यवस्था का नियमन करना चाहते थे।^१ उनकी कृषिनीति भी कुछ अंशों में प्राचीन विचारों से प्रभावित थी। पर उनकी औद्योगिक नीति मूलतः आधुनिक थी।

मालवीयजी का कहना था कि भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य प्रतिष्ठित होने से पहले हमारा देश कृषि-प्रधान और व्यवसाय-प्रधान दोनों था, और अंग्रेज शासकों की आयात, निर्यात तथा अन्य दोषपूर्ण वित्त-नीतियों एवं आर्थिक गतिविधियों के कारण ही भारत एकमात्र कृषि-प्रधान देश बन गया। व्यावसायिक क्षति के कारण व्यवसायशील जातियाँ बरबाद हो गयीं, खेती पर देश की निर्भरता बढ़ती चली गयी, तथा अकाल की परिस्थिति का सामना करने की हमारी समर्थ्य कम होती गयी।^२

सन् १८५४ और १९०० के बीच में दुर्भिक्ष के कारण सवा दो करोड़ से अधिक भारतीय मौत के शिकार हो गये। सन् १८७८ में अकाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि “भारतीय जनता की घोर दरिद्रता तथा अकाल की विपत्ति, दोनों का कारण यही है कि अधिक जनसंख्या की जीविका केवल खेती से चलती है, और तब तक इन विपत्तियों से छुटकारा पाने का उपाय नहीं हो सकता, जब तक कि भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योगों का प्रसार नहीं किया जाता, जिनके द्वारा अधिक जनसंख्या खेती के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों और उद्योगों से भी अपनी जीविका चला सके।” कमीशन का सुझाव था कि “खेती के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों की उन्नति की जाय, जिनपर ऋतुओं के परिवर्तन

१ प्रोसीडिंग इण्डियन लेजरलेटिव कौंसिल, सन् १।

२ इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट, सन् १९१८, मालवीयजी का नोट।

का कुछ भी प्रभाव न पड़ता हो”। सरकार ने कमिशन की सिफारिश की अपेक्षा करते हुए स्वतंत्र व्यापार की नीति के नाम पर उन आर्थिक नीतियों को चालू रखा जो भारत के औद्योगिक विकास में बाधक थी। पर मालवीयजी प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं ने कमिशन की इस समीक्षा और सुझाव की सत्यता स्वीकार की।^१

मालवीयजी की धारणा थी कि “शुद्ध कृषिप्रधान देश व्यवसायी और उद्योग-धन्धी देश की अपेक्षा कभी अधिक समुन्नत और आत्मसंरक्षण के योग्य नहीं हो सकता।” पर वे वैज्ञानिक बैरन लिंविंग के इस विचार से भी सहमत थे कि “सर्वांगपूर्ण कृषि सभी व्यापार तथा व्यवसाय की जननी है तथा राज्य की समृद्धि का आधार है”, और स्वीकार करते थे कि “भारत की आर्थिक उन्नति का कृषि-व्यवसाय की उन्नति से गहरा सम्बन्ध है।” इस तरह वे औद्योगिक विकास और कृषि-व्यवसाय की उन्नति, दोनों चाहते थे।^२ उन्हें अपने देश के पुराने शिल्प-कारों की कारीगरी पर गर्व, तथा पुराने कुटीर उद्योगों की क्षति पर दुःख था। वे उनका पुनरुज्जीवन करना चाहते थे। पर उनकी धारणा थी कि उनके पुनरुत्थान से ही काम नहीं चल सकता। इस मशीनयुग में वे मशीनों द्वारा संचालित बड़े उद्योगों को स्थापित करना देश की आर्थिक प्रगति के लिए नितान्त आवश्यक समझते थे। इस तरह न्यायाधीश महादेव गोविन्द रानडे की तरह मालवीयजी भी एक ऐसी सन्तुलित आर्थिक नीति और व्यवस्था के पक्ष में थे जिसके द्वारा कृषि-व्यवसाय समृद्ध हो, पुराने कुटीर उद्योगों का पुनरुत्थान हो, तथा आधुनिक औद्योगिक तकनीक के आधार पर देश का उद्योगीकरण हो सके। वे इस देश को फिर से कृषि-प्रधान और उद्योग-प्रधान, दोनों बना देना चाहते थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में न्यायाधीश रानडे ने अंग्रेज अर्थ-शास्त्रियों के स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्त को अपरिवर्तनशील और निर्विवाद वैज्ञानिक सिद्धान्त स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अर्थतन्त्र का ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए बताया कि आर्थिक नियम समाज की ऐतिहासिक परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। वे देशकालानुकूल निर्धारित होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का अपना अर्थतन्त्र होता है, उसे अपनी स्थिति के अनुकूल आर्थिक नीति और व्यवस्था निर्धारित करनी होती है। स्वतंत्र व्यापार की सार्थकता भी

१. प्रान्तीय काँसिल में भाषण, सन् १९०६।

२. वही, सन् १९०७।

परिस्थिति पर निर्भर होती है, हर स्थिति में वह लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती। किन्हीं परिस्थितियों में आर्थिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा उद्योगों का संरक्षण और प्रोत्साहन आवश्यक और लाभप्रद हो सकता है।

मालवीयजी इस विश्लेषण को मूलतः स्वीकार करते थे। उन्होंने सन् १९०७ में रूस के तत्कालीन अर्थ-सचिव काउण्ट डिबिटे के कतिपय वाक्यों को उद्धरित करते हुए इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि काउण्ट के विचार में "समस्त संसार के लिए प्रवेश मार्ग को उन्मुक्त कर स्वतंत्र व्यवसाय जनता को विशेष प्रकार से सस्ता माल प्रदान करता है, किन्तु राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति का इतिहास कठिनता से ऐसा उदाहरण उपस्थित करता है, जहाँ इस प्रकार की नीति ने राष्ट्र की उत्पादक शक्ति में प्रगति प्रदान की हो। इंग्लैंड ने स्वयं कड़े संरक्षणों द्वारा अपना व्यवसाय स्थापित किया है, और जब इस उपाय से वह अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा व्यापार और व्यवसाय में सबल हो गया और उसे किसी प्रतिस्पर्धा का भय नहीं रह गया, तब उसने स्वतंत्र व्यवसाय नीति का अवलम्बन किया।" मालवीयजी ने जान स्टूअर्ट मिल के इस विचार को भी दोहराते हुए कि किन्हीं परिस्थितियों में उन नये उद्योगों को अस्थायी संरक्षण दिया जा सकता है जिनके निर्माण के लिए देश में पर्याप्त प्राकृतिक साधन उपलब्ध हो, उद्धोषित किया कि "सिद्धान्त की बात अलग रखिये, न तो संरक्षण, न स्वतंत्र व्यवसाय ही प्रत्येक देश के लिए प्रत्येक दशा में उन्नति के लिये आवश्यक है। जहाँ इंग्लैंड जैसे उद्योग धन्वों में समुन्नत देश के लिए स्वतंत्र व्यवसाय अनुकूल है, वहाँ "व्यवसाय में अनुन्नत भारत के समान देश के लिए संरक्षण की नीति बुद्धिमानी और रक्षा की नीति है"।^१ इस तरह आर्थिक विकास के लिए मालवीयजी आयात प्रतिरोधक शुल्क द्वारा भारतीय उद्योगों के संरक्षण के पक्ष में थे।

वे आयात प्रतिरोधक शुल्क के अतिरिक्त दूसरे सम्भव उपायों द्वारा भी देश के उद्योग, व्यवसाय और व्यापार का संरक्षण और संवर्धन सरकार का कर्तव्य समझते थे। वे चाहते थे कि सरकार सक्रिय रूप से देश की आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहित करे, तथा कृषकों, औद्योगिकों और व्यापारियों की यथोचित सहायता कर प्रगति में बाधक कठिनाइयाँ दूर करे, एवं जनकल्याण की रक्षा और वृद्धि के लिए आर्थिक व्यवस्था और क्रियाकलापों का नियमन और नियंत्रण करे।^३

१ प्रान्तीय कौंसिल में भाषण, सन् १९०७।

२. प्रोसीडिंग इण्डियन लेजिस्लेटिव कौंसिल सन् १९११।

३ वही सन् १९१५।

रेलो का राष्ट्रीयकरण, राज्य द्वारा सिंचाई के साधनों का विस्तार, कानून द्वारा श्रमिकों के हितों का संरक्षण, और सुखसुविधाओं का प्रबन्ध, ऊँची से ऊँची कृषि शिक्षा तथा व्यापारिक शिक्षा और आधुनिक शिल्पविज्ञान की शिक्षा की राज्य द्वारा व्यवस्था, देश के आर्थिक उत्कर्ष के निमित्त विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक और वैज्ञानिक अनुसंधान का समुचित प्रबन्ध, सहकारी संस्थाओं द्वारा जनोपयोगी सेवाओं का विस्तार, राज्य द्वारा स्टेट बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक का शेयर-होल्डर बैंक के बजाय स्टेट बैंक के रूप में गठन, और उसके द्वारा राजकोष का औद्योगिक उन्नति में उपयोग, तथा राष्ट्रहित में सम्पत्ति का नियमन—मालवीयजी के कतिपय महत्त्वपूर्ण आर्थिक सिद्धान्त थे ।

वे कम्यूनिज्म के सिद्धान्त को “सत्य, न्याय, धर्म तथा प्राकृतिक नियम के विरुद्ध” मानते थे^१, पर वे कम्यूनिस्टों के इस विचार से सहमत थे कि समाज का ऐसा निर्माण किया जाय कि समाजसेवा में संलग्न सब श्रमिक उचित ढंग से सुखपूर्वक जीवन बिताने योग्य पारिश्रमिक प्राप्त कर सकें, सबको जीवनोत्कर्ष की सुविधाएं प्राप्त हों ।^२ उनकी धारणा थी कि आर्थिक अन्याय, दमन और शोषण को मिटाकर ही, जनसाधारण की आर्थिक दगा सुधार कर ही, उनके जीवनस्तर को ऊँचा करके ही कम्यूनिज्म से राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है ।^३

वे संविधान द्वारा सम्पत्ति के अधिकार का संरक्षण आवश्यक समझते थे । उनके विचार में सम्पत्ति की ऐसी व्यवस्था हो कि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा मनमाने ढंग से अपनी निजी सम्पत्ति से, अपने न्यायसंगत अधिकार से, वंचित न किया जा सके, राष्ट्रहित में पारित कानून द्वारा ही निजी सम्पत्ति का नियमन हो सके, सरकार उसे अधिग्रहण कर सके ।^४

इस तरह मालवीयजी सामाजिक न्याय के आधार पर मिश्रित अर्थतन्त्र द्वारा जनहितकारी औद्योगिक व्यवस्था प्रतिष्ठित करना चाहते थे । उनकी इच्छा थी कि देश की आर्थिक उन्नति के निमित्त निजी देशज उद्योगों का आयात शुल्क द्वारा संरक्षण हो, भारतीय पूंजीपतियों और शिल्पकारों को नये नये उद्योगों को चालू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय, श्रमिकों के हितों और अधिकारों की समुचित रक्षा की जाय, उन्हें माननीय वेतन दिलाने का प्रबन्ध किया

१. भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली में भाषण, मन् १९२८ ।

२. भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली में भाषण मन् १९२९ ।

३. वही ।

४. सर्वदलीय काफरेन्स, कलकत्ता अधिवेशन मन् १९२८ ।

जाय, देशहित की दृष्टि से यथावश्यक निजी व्यापार के क्षेत्र में सहकारीकरण प्रोत्साहित किया जाय, सार्वजनिक क्षेत्र में बृहद् उद्योगों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों का गठन किया जाय, तथा उद्योगीकरण के निमित्त सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की जाय, एवं आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सभी लोग न्यासिता की भावना से अनुप्राणित हो, देश के सारे भौतिक वैभव को राष्ट्र की सम्पत्ति और धरोहर समझ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करें, वही करें जो राष्ट्रहित में हो। वे चाहते थे कि “धनी लोग यह समझें कि ईश्वर ने जो धन दिया है, वह मेरा नहीं है, किन्तु उसी का है, और उसी के प्राणियों की सहायता के लिए उसे व्यय करना चाहिए।”

मालवीयजी के विचार व्यक्तिवादी पूंजीपतियों और समाजवादी विचारकों, दोनों से भिन्न थे। वे पूंजीपतियों के मुक्त-व्यापार (फ्री इण्टरप्राइज) के सिद्धान्त को मानने को तैयार नहीं थे। उनकी राय में राष्ट्रहित, श्रमिक क्षेम, और जनकल्याण की दृष्टि से निजी उद्योगों और व्यवसायों का सरकार द्वारा नियंत्रण और नियमन अनिवार्य और आवश्यक है। मालवीयजी मजदूर नेता श्री एन० एम० जोशी से सहमत थे कि निजी उद्योगों के संरक्षण के निमित्त आयात शुल्क का प्रवन्ध करते समय केन्द्रीय असेम्बली को मजदूरों के हितों के संरक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। वे चाहते थे कि छोटे-छोटे बच्चों और स्त्रियों के हितों की रक्षा का विशेष प्रवन्ध किया जाय, और अर्धदासता की स्थिति से मजदूरों को तुरन्त मुक्त किया जाय।

मालवीयजी कम्यूनिस्टों और समाजवादियों की इस धारणा से सहमत थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सब आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति के अनुरूप पुरस्कार मिलना चाहिए, जब तक वह व्यक्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार और ईमानदारी के साथ समाज के लिए काम करता है।^१ वे मजदूरों को उनके व्यक्तित्व और क्षमता के विकास की पूरी सुविधा दिये जाने के भी समर्थक थे। उनकी धारणा थी कि अन्य व्यक्तियों और जन-समूहों की तरह मजदूरों को भी संस्था संगठित करने का, सभा और प्रदर्शन आयोजित करने का, अपने विचारों को प्रकाशित करने तथा भाषण देने का, और अपने साथियों के साथ हड़ताल करने का न्यायसंगत और युक्ति-संगत अधिकार है।^२

१. अभ्युदय, २६ मार्च सन् १९०९।

२. भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली में भाषण, सन् १९२९।

३. वही।

रिजर्व बैंक की भावी व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए मालवीयजी ने कहा था कि 'स्टेट बैंक' भारत की सारी जनता का बैंक होगा, भारत की सम्पूर्ण जनता उसकी पूँजी की मालिक होगी, जो कुछ नफा उसे प्राप्त होगा, वह सरकार द्वारा भारत की सारी जनता में विभाजित किया जायगा। जबकि शेयर होल्डर्स बैंक मुट्ठी भर धनियों की सम्पत्ति होगा, उनके हित में ही उसका संचालन होगा।^१

सन् १९१८ में इस बात पर आग्रह करते हुए कि भारत सरकार सब रेलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले, मालवीयजी ने कहा कि कम्पनी की तुलना में राज्य द्वारा प्रबन्ध अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि वह भारत सरकार के अधीन होगा, जिसे जनता के प्रतिनिधि प्रभावित कर सकेंगे, राज्य का प्रबन्ध जनता के हित में होगा, जबकि मुनाफा ही कम्पनी के प्रबन्ध का लक्ष्य है, राज्य द्वारा प्रबन्धित रेलवे में जो नफा होगा वह जनता के लाभ के लिए या करो के घटाने में खर्च होगा, कम्पनियों की विवेकहीन बातों और हुज्जतों से छुटकारा मिलेगा और राज्य प्रबन्ध निष्पक्ष और सस्ता होगा।^२

इन सबसे यह स्पष्ट है कि मालवीयजी मुट्ठी भर पूँजीपतियों के एकाधिपत्य, पूँजीवादी इजारादारी के विरोधी थे, और उनकी तुलना में राष्ट्रीयकरण को अधिक जनहितकारी समझते थे। पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे कम्युनिज्म या समाजवाद की सब मूलभूत धारणाओं को स्वीकार करते थे। उन्हें कम्युनिस्टों द्वारा प्रतिपादित इतिहास की भौतिक व्याख्या, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की धारणा, तथा हिंसात्मक ढंग से पूँजीपतियों की निजी पूँजी और सम्पत्ति का अपहरण ठीक नहीं जंचते थे। उनके विचार में राष्ट्रहित की दृष्टि से कानून द्वारा मुआवजा देकर विधिवत् निजी सम्पत्ति या उद्योगों का अधिकरण ही न्याय-संगत और उचित है। इसी तरह वे मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को स्वीकार करते थे, पर वर्ग-संघर्ष को तीव्र करने के बजाय समझौते द्वारा मजदूरों के हितों को पुष्ट करना ही वे उचित समझते थे। समाजवादियों की लोकतांत्रिक धारणा तथा व्यक्ति-स्वातंत्र्य के प्रति उनकी निष्ठा मालवीयजी स्वीकार करते थे, पर पूँजीपतियों के सभी निजी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की कल्पना उन्हें अव्यावहारिक और अनुचित प्रतीत होती थी। वे राष्ट्रीयकृत उद्योगों

१ भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली में भाषण, सन् १९२८।

२ भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल प्रोसीडिंग्स, सन् १९१८, जि० ५६, पृ० १०९।

और निजी उद्योगों का सन्तुलित विकास ही राष्ट्र के हित में समझते थे। वे चाहते थे कि भारतीय पूँजीपति भी न्यासिता की भावना से अनुप्राणित हो, अपने कौशल और क्षमता द्वारा देश के आर्थिक विकास में समुचित योगदान करें।

मालवीयजी चाहते थे कि भारतीयों द्वारा भारत के हित में, भारत के गौरव और समृद्धि की वृद्धि के निमित्त ही देश का औद्योगिक विकास हो।^१ उनकी इच्छा थी कि भारतीय उद्योग मूलतः भारतीय औद्योगिकों, विशेषज्ञों तथा अधिकारियों द्वारा भारतीय पूँजी और श्रमिकों के सहयोग से संचालित हो, विदेशी पूँजी और विदेशी विशेषज्ञों का योगदान यथासंभव गौण हो। उनका कहना था कि यथावश्यक विदेशी पूँजी तथा विदेशी विशेषज्ञों का प्रयोग एक बात है, और देश के औद्योगिक जीवन को विदेशियों के हाथ में सौंप देना दूसरी बात है।^२ जहाँ किसी स्थिति में पहली चीज अनिवार्य और लाभप्रद है, वहाँ दूसरी चीज निश्चय ही भयावह और हानिकारक है। इस भय से कि कहीं वित्तीय संरक्षण से लाभ उठाकर विदेशी व्यापारी इस देश में अपना औद्योगिक आधिपत्य न स्थापित कर लें, मालवीयजी चाहते थे कि विदेशी पूँजी के प्रवेश, और विदेशी पूँजीपतियों के औद्योगिक और वित्तीय प्रयासों पर भारत सरकार का समुचित नियमन और नियंत्रण हो। जिस अंश में और जिन शर्तों के साथ ये प्रयास भारत के हित में हो, उन्हीं के साथ उनका योगदान स्वीकार किया जाय।

मालवीयजी भारत में चालू विदेशी उद्योग व्यापार के सम्बन्ध में यह आश्वासन दिये जाने के पक्ष में थे कि कोई ऐसा कानून या आदेश जारी नहीं किया जायगा जो समान रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापारों पर लागू न हो। पर वे यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि किसी प्रकार का भेदमूलक कानून पारित नहीं किया जायगा। उनका कहना था कि “भारत में व्यापार करनेवाले विदेशी और अंग्रेज अपने व्यापारों की रक्षा मागने के हकदार हैं, पर वे भारत में भारतीय देशज उद्योगों के समान सहायता और संरक्षण के अधिकारी नहीं हैं।”^३ उनका कहना था कि देशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी सहायता दी जाती है, उसका भार जनता को वहन करना होता है जिसे वह राष्ट्र के हित में वहन कर सकती है, पर विदेशी उद्योगों को वही सहायता देकर भारतीय जनता को विदेशियों के हित में भार वहन करने को बाध्य नहीं किया जा सकता।^४

१. इंडस्ट्रियल कमिशन रिपोर्ट, मालवीयजी का नोट।

२. राउंड टेबिल काफरेन्स के दूसरे सत्र में भाषण।

३. वही।

४. वही।

भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में मालवीयजी के विचार किसी हद तक सम-कालीन कांग्रेसी नेताओं के विचारों के अनुकूल थे। अन्य नेताओं की तरह मालवीयजी भी मालगुजारी के स्थायी बन्दोवस्त के पक्ष में थे। पर वे बंगाल के ढंग के स्थायी बन्दोवस्त के पक्ष में नहीं थे। मालवीयजी किसानों के अधिकारों और हितों की समुचित रक्षा पर जोर देते थे। वे चाहते थे कि किसानों पर से लगान का बोझ कम किया जाय, उसे पच्चीस तीस प्रतिशत घटा दिया जाय, ताकि किसान अपने श्रम के लाभ का अधिक उपभोग कर सकें, तथा घटायें हुए लगान के आधार पर लगान व्यवस्था का तथा किसानों के अधिकारों का स्थायी बन्दोवस्त किया जाय। और इस तरह किसानों के हितों की पूरी तीर पर रक्षा करते हुए मालगुजारी का स्थायी बन्दोवस्त किया जाय।^१

मालवीयजी को यह उत्कट इच्छा थी कि किसानों में आत्मसम्मान, आत्म-निर्भरता और मानवगौरव की भावना पुष्ट की जाय। सरकारी अफसरों और कर्मचारियों तथा जमींदारों और उनके कारिंदों की ओर मुंह उठाकर देखने की उनमें शक्ति पैदा की जाय। उन्हें बताया जाय कि उन्हें नागरिकता के वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो उनसे अधिक सम्पन्न भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।^२ मालवीयजी की इच्छा थी कि किसान स्वयं अनुभव करें कि राष्ट्रकल्याण की पुष्टि और वृद्धि में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण है, उन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करने का तथा सुखी उत्कृष्ट जीवन बिताने का नैतिक अधिकार है, और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर वे अपने न्यायसंगत हितों की पुष्टि और वृद्धि कर सकते हैं, अपने भाग्य के विधाता और राष्ट्र के निर्माता बन सकते हैं। यद्यपि मालवीयजी ने जमींदारों-उन्मूलन की कोई चर्चा स्वयं कभी नहीं की पर दिसम्बर सन् १९२८ में सर्वदलीय सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय विधान सभाएं यदि चाहें तो न्याय की प्रतिष्ठा तथा देश के हित में कानून द्वारा मुआवजा देकर जमींदारी का उन्मूलन कर सकती हैं।^३



१. प्रान्तीय कौंसिल में भाषण, सन् १९०८।

२. एग््रीकल्चरल कमिशन के सामने गवाही, सन् १९२७।

३. सर्वदलीय कांफरेन्स कलकत्ता अधिवेशन, सन् १९२८।

२८. जीवन का सर्वांगीण विकास

जीवन का सर्वांगीण विकास मालवीयजी की शिक्षा-पद्धति का मूलमन्त्र था। वे चाहते थे कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का ऐसा प्रबन्ध हो कि वे अपनी शारीरिक, बौद्धिक तथा भावात्मक शक्तियों को परिपुष्ट और विकसित कर सकें, और आगे चल कर किसी व्यवसाय द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह कर सकें, कलापूर्ण और सौन्दर्यमय जीवन व्यतीत कर सकें, समाज में आदरणीय और विश्वासपात्र बन सकें, तथा देशभक्ति से, जो मनुष्य को उच्चकोटि की सेवा करने की ओर प्रवृत्त करती है, अपने जीवन को अलंकृत कर राष्ट्र की समुचित सेवा कर सकें।

मालवीयजी शिक्षा को मानव मात्र का अधिकार, तथा उसका समुचित प्रबन्ध राज्य का कर्तव्य समझते थे। वे चाहते थे कि राष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों में सर्वसाधारण के लिए शिक्षा निःशुल्क दी जाय, जो अनिवार्य भी हो। उनका कहना था कि सब स्तर पर शिक्षा का ऐसा प्रबन्ध हो कि कोई बच्चा निर्धन होने के कारण उससे वंचित न रह पाये^१। वे बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर एलफिन्स्टन की इस बात से सहमत थे कि “गरीबों की सुख शान्ति बहुत हद तक शिक्षा पर निर्भर है। इसके जरिये ही वे विवेक और आत्मसम्मान का स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं जिससे सब गुण विकसित होते हैं।”^२ उनकी धारणा थी कि शिक्षा का व्यापक विस्तार समाज में फैली बहुत-सी विषमताओं और कुरातियों को दूर करके छोटी जातियों का जीवन स्तर ऊँचा उठा देगा, और समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करना उनके लिए सुलभ हो जायगा। उन्होंने सन् १९२७ में असेम्बली में लाला लाजपत राय के इस सुझाव का समर्थन किया था कि राजकोष से प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपया हरिजन विद्यार्थियों की शिक्षा पर खर्च किया जाय, और अपने काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रारम्भ से ही हरिजन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी थी।

मालवीयजी स्त्री-शिक्षा का समुचित प्रबन्ध भी समाज का पुनीत कर्तव्य समझते थे। उनका कहना था कि पुरुषों की शिक्षा से स्त्रियों की शिक्षा अधिक

१. भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में भाषण।

२. प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में भाषण, सन् १९०४।

महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वे ही भारत की भावी सन्तानों की माताएँ हैं। वे हमारे भावी राजनीतिज्ञों, विद्वानों, तत्त्वज्ञानियों, व्यापार तथा कलाकौशल के नेताओं आदि की प्रथम शिक्षिकाएँ हैं। वे चाहते थे कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के आधार पर स्त्रियों को इस तरह शिक्षित किया जाय कि उनमें “प्राचीन तथा नवीन सभ्यताओं के सभी सद्गुणों का समन्वय हो, और जो अपनी शिक्षा द्वारा भावी भारत के पुनर्निर्माण में पुरुषों से पूर्णरूप से सहयोग कर सकें।” सन् १९११ में गोखले के विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, “समाज के आधे भाग को ज्ञान की ज्योति से तथा उस उत्कृष्ट जीवन से जो ज्ञान द्वारा सम्भव है, वंचित रखना बहुत दुःखदायी बात होगी।”

उनके विचार में विद्यार्थियों का चरित्रगठन शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है। सज्जनताविहीन ज्ञान, उनकी दृष्टि में, निरर्थक है। वे जीवनोत्कर्ष और राष्ट्र की उन्नति, दोनों के लिए चरित्रगठन को बौद्धिक तथा व्यावसायिक विकास से कहीं अधिक आवश्यक समझते थे। उनकी तो धारणा थी कि “पारस्परिक सद्भाव तथा सहयोग के बिना व्यावसायिक उन्नति हो ही नहीं सकती, और जीवन में सद्भाव और सहयोग को विकसित करने के लिए चरित्र का गठन आवश्यक है।” उनके विचार में चरित्र ही मनुष्य को बनाता है, सदाचार मनुष्य का परम धर्म है, उसकी रक्षा मनुष्य का पुनीत कर्तव्य, तथा उसकी वृद्धि उसका परम पुरुषार्थ है। मालवीयजी का कहना था कि “राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को आचार के ही शासन से सदा शासित तथा प्रभावित रहना चाहिए, तभी उनमें विश्वास, मृदु भाषण तथा व्यवहार की सच्चाई और सद्गुणों का विकास हो सकता है।”

आचरण की शुद्धि, पुष्टि और परिपक्वता के लिए मालवीयजी धर्म, नागरिकता और नैतिकता की शिक्षा आवश्यक समझते थे। उनकी धर्म की व्याख्या नैतिकता से ओतप्रोत और नागरिकता से समन्वित थी। वे देशभक्ति को धर्म का महत्त्वपूर्ण अङ्ग स्वीकार करते थे।^१ उनकी नैतिकता बहुत अंशों में धर्मग्रन्थों में प्रतिपादित नैतिक आदेशों पर आधारित थी। आत्मोपम्य व्यवहार तथा निःस्पृही लोकसेवा उसके सर्वोत्तम सद्गुण थे, और ये दोनों श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा प्रतिपादित समत्व, निष्काम सेवा तथा ईश्वरार्पण सत्कर्म के सिद्धान्तों पर आधारित थे। उनकी नागरिकता की व्याख्या

१. गवर्नर-जनरल की कौंसिल, जि० ४९, पृ० ४६९।

२. अम्युदय

लोकतांत्रिक थी। वह पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित थी। उनके विचार जड़ता से रहित और आधुनिकता से प्रभावित और समन्वित थे। उनकी मूलधारणाएँ निर्विवाद थी। सद्भावनाओं से अनुप्राणित, सदाचार से विभूषित जीवन ही आत्मोत्कर्ष और जनकल्याण का उत्तम साधन हो सकता है। देशप्रेम की शिक्षा ही राष्ट्र का उद्धार कर सकती है। निःस्पृह देशभक्त ही राष्ट्र की सच्ची ठोस सेवा कर सकता है। लोकतांत्रिक नागरिकता के मूल सिद्धान्तों पर आधारित लोकतांत्रिक चरित्र और व्यवहार ही लोकतन्त्र को स्थायी, सुदृढ़ और जनोपयोगी बना सकता है।

मालवीयजी के विचार में मानव के सर्वांगीण विकास तथा उत्कृष्ट आनन्दमय जीवन के लिए विकासोन्मुखी व्यापक शिक्षा तथा चरित्रगठन के साथ-साथ स्वस्थ निर्मल जीवन, ज्ञान-विज्ञान का विस्तार, ललित कलाओं के प्रति अभिरुचि, तथा सुख साधन की भौतिक सुविधाएँ भी आवश्यक हैं। स्वास्थ्य की रक्षा, शारीरिक शक्ति की पुष्टि वे मानव का पुनीत कर्तव्य मानते थे। वे शरीर की रक्षा और पुष्टि के लिए “युक्त आहार विहार” तथा “ब्रह्मचर्य” और व्यायाम आवश्यक समझते थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक विद्यार्थी पञ्चीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, तथा नित्य नियमित रूप से व्यायाम करे। उनका कहना था कि “ब्रह्मचर्य ही हमें वह आत्मबल देता है जिसके द्वारा हम संसार में सब कष्टों और बाधाओं का साहस के साथ सामना कर सकते हैं।” वे प्रत्येक विद्यालय में व्यायाम के साधनों का समुचित प्रबन्ध आवश्यक समझते थे। उनके विचार में कतिपय प्राचीन और अर्वाचीन क्रीड़ा और व्यायाम के उपकरण स्वास्थ्य की रक्षा और शरीर की पुष्टि के साथ-साथ मनोरंजन तथा पारस्परिक सद्भाव और सहयोग की क्षमता की वृद्धि के उत्तम साधन भी बन सकते हैं, और उनका प्रबन्ध विशेष रूप से वाछनीय है।

मालवीयजी यह भी चाहते थे कि विद्यालयों में संगीत, काव्य, नाट्यकला, चित्रकला, वास्तुकला तथा मूर्ति-कला आदि ललित कलाओं की शिक्षा का भी प्रबन्ध हो, और उनमें से कम से कम किसी एक कला में विद्यार्थी अवश्य ही दिलचस्पी ले। उनके विचार में कला-विहीन जीवन शुष्क और नीरस है, जबकि ललित कलाओं का ज्ञान, उनको परखने की क्षमता, तथा शुद्ध भावनाओं के साथ उनके प्रति अभिरुचि, और समयानुकूल उनका अभ्यास जीवन को सरस और आनन्दमय बनाता है।

मालवीयजी को अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक देन पर गर्व था। वे चाहते थे कि भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा अन्य भारतीय विद्याओं के अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान का समुचित प्रवन्ध हो, तथा सब विद्यार्थियों को उनकी रूपरेखा की जानकारी करायी जाय। उनकी धारणा थी कि वह शिक्षा-पद्धति अपूर्ण ही नहीं, निरर्थक और हानिकारक है जिसके द्वारा नवयुवक को अपने देश और समाज की बौद्धिक समृद्धि की ठीक ठीक जानकारी न हो सके। उनके विचार में वह व्यक्ति क्या शिक्षित है, जिसका जीवन अपने पूर्वजों के सद्गुणों से अनुप्राणित नहीं, जिसे अपने पूर्वजों की महत्त्वपूर्ण देन का कोई ज्ञान नहीं, जिसे अपने देश के इतिहास की सही-सही जानकारी नहीं, जिसमें अपने जीवन को जनता से आत्मसात करने की क्षमता नहीं। यद्यपि मालवीयजी भारतीय वाङ्मय का अध्ययन अध्यापन, पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा और पुष्टि सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे, उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उनकी बौद्धिक मान्यताएँ व्यापक और उदार थी। वे ज्ञान को किसी विशिष्ट जाति या देश की वसीती नहीं समझते थे। वे यह कभी नहीं मानते थे कि हमारे पास सब कुछ है, हमें दूसरों से कुछ लेना नहीं है। वे स्वीकार करते थे कि हमारे पूर्वजों की तरह दूसरे देश के विद्वानों ने भी अपनी प्रतिभा और योग्यता से ससार को अलंकृत किया है। सब विद्वानों का आदर तथा ज्ञान का आदान-प्रदान वे मानव प्रगति और राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे। वे दूसरे देशों के विद्वानों के युक्तियुक्त समाजोपयोगी विचारों को ग्रहण करने को सदा तैयार रहते थे। वे मनु, भीष्म, वशिष्ठ, शुक्र आदि विद्वानों के इस विचार से सहमत थे कि हमें अपने गुरुओं और पूर्वजों के सद्गुणों को ग्रहण करते हुए सब विद्वानों के युक्तियुक्त विचारों को, शुभ ज्ञान को विनयपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, उनका अध्ययन अध्यापन करना चाहिए।)

इस तरह मालवीयजी भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन, साहित्य, संस्कृति और अन्य विद्याओं के साथ-साथ अर्वाचीन नीतिशास्त्र, समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान, विधि-विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन आवश्यक समझते थे। वास्तव में वे इन सब विषयों के प्राचीन भारतीय और अर्वाचीन, पाश्चात्य विद्वानों के विचारों का तुलनात्मक और समन्वयात्मक अध्ययन आवश्यक समझते थे। वे विश्वज्ञान का समन्वय, तथा विश्व के विद्वानों के सहयोगात्मक प्रयासों को मानव उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे।

मालवीयजी विज्ञान के प्रयोगात्मक और व्यावहारिक पक्ष के बहुत प्रशंसक थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि विज्ञान के विद्यार्थियों को शब्द-प्रमाण

के आधार पर पाठ्यपुस्तको द्वारा ही विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि प्रचलित सिद्धान्तों और संचित अनुभवों की, सच्चाई प्रयोगशाला में वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध करवायी जाती है, और निजी अनुभवों द्वारा उन सिद्धान्तों को संशोधित तथा नये सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है।^(१) हारवर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम जेम्स से सहमत थे कि इस विधि से "लेबरेटरी वर्क और शाप वर्क प्रेक्षण का अभ्यास, यथार्थता और अस्पष्टता के अन्तर का ज्ञान, तथा प्रकृति की पेचीदगी की और वास्तविक तथ्य के सब शाब्दिक विवरणों की गलतियों की पूरी जानकारी पैदा करते हैं, जो एक बार बुद्धि में बैठ जाने पर आजीवन जम जाता है"।^१ ये यथार्थता प्रदान करते हैं। ये ईमानदारी देते हैं। ये आत्म-निर्भरता का अभ्यास (आदत) पैदा करते हैं। ये विद्यार्थी को उसके युग के स्वतः प्रसूत हितों से बहुत ही उचित ढंग पर सलग्न कर देते हैं। वह उसमें तल्लीन हो जाता है और उस पर टिकाऊ और गहरा प्रभाव डाल देता है।^(२) उस युवक की तुलना में, जो इस ढंग से पढ़ाया जाता है, वह नवयुवक जो केवल पुस्तको पर पढ़ाया लिखाया गया है, जीवन में वास्तविकता से कुछ दूर रहता है। वह एक तरह से घेरे से बाहर रहता है और इसका अनुभव करता है, और बहुधा उदासी और चिन्ता से पीड़ित होता है, जिससे वह अधिक वास्तविक शिक्षा द्वारा बचाया जा सकता था^२। मालवीय जी चाहते थे कि वैज्ञानिक ढंग की शिक्षा अपने देश में भी चालू की जाय, और प्रयोगशाला तथा वर्कशाप में विद्यार्थियों को अपने हाथों के प्रयोग का अभ्यास कराया जाय। उनके ज्ञान को प्रयोगात्मक और व्यावहारिक बनाया जाय। उनमें प्रेक्षण की शक्ति पैदा की जाय। उनके ज्ञान को यथातथ्य तथा जीवनोपयोगी बनाया जाय। उनकी धारणा थी कि भारत अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने में तब तक सर्वथा असमर्थ है, जब तक वह वर्तमान वैज्ञानिक अन्वेषण का अध्ययन नियमित और अनिवार्य नहीं बनाता।^(३) वे चाहते थे कि प्रारम्भिक विज्ञान की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा-पद्धति का अनिवार्य अंग बना दिया जाय, तथा माध्यमिक शिक्षालयों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान और वैज्ञानिक शिल्प-विद्या की उच्चस्तरीय शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाय ताकि हमारा देश बौद्धिक विकास तथा न्यावसायिक उन्नति में दूसरे प्रगतिशील देशों के समकक्ष बन सके।

१. प्रान्तीय कौंसिल में भाषण, सन् १९०७।

२. वही।

३. सीताराम चतुर्वेदी · महामना पंडित मदन मोहन मालवीय खण्ड ३, पृ० ११४।

मालवीयजी चाहते थे कि प्रत्येक जिले'या कम से कम प्रत्येक कमिश्नरी में ऐसी माध्यमिक स्तर की औद्योगिक शिक्षा संस्थाएँ खोली जायें जिनमें बुनाई, रंगाई, धुलाई, वस्त्र-छपाई, लोहारी, बढईगिरी, मीनाकारी आदि की शिक्षा का प्रबन्ध हो। इन संस्थाओं में फोरमैन और उनके सहायकों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध हो। वे यह भी चाहते थे कि प्रत्येक प्रान्त में एक उच्चस्तरीय औद्योगिक शिक्षा महाविद्यालय खोला जाय, जिसमें शिल्पविज्ञान सम्बन्धी विषयों की उच्चस्तरीय शिक्षा दी जाय।^१

मालवीयजी जापान की कृषि-शिक्षा की व्यवस्था के बहुत प्रशंसक थे। उनका कहना था कि जापान में कई सौ कृषि स्कूल हैं जिनमें प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को खेती की प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है, और बहुत सी माध्यमिक कृषि-शिक्षा संस्थाएँ हैं जिनमें भावी कृषकों को कृषि-सम्बन्धी वैज्ञानिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। मालवीयजी चाहते थे कि इस प्रकार के कृषि-स्कूल और माध्यमिक कृषि शिक्षा-संस्थाएँ काफी संख्या में सारे देश में खोली जायें। वे यह भी चाहते थे कि प्रत्येक प्रान्त में टोकियो के कृषि महाविद्यालय की तरह के महाविद्यालय खोले जायें जिनमें योग्य विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान की उच्चस्तरीय शिक्षा दी जाय, बड़े पैमाने पर खेती से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसंधान किया जाय, तथा कृषि-शिक्षक तैयार किये जायें। वे चाहते थे कि ये कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हों, और कृषि-विशेषज्ञ और दूसरे विधान-विशेषज्ञ मिलकर काम करें।^२

मालवीयजी यह भी चाहते थे कि सरकार की ओर से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद दोनों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो, और आयुर्वेदिक औषधियों का वैज्ञानिक परिक्षण कर उनका सदुपयोग किया जाय।

अन्य देशों भाषाओं के साथ-साथ संस्कृत भाषा का समुचित अध्ययन, अध्यापन भी वे आवश्यक समझते थे। उनका कहना था कि "संस्कृत भाषा संसार की समस्त भाषाओं में सर्वोत्कृष्ट है", तथा "मनुष्य के उच्चातिउच्च विचारों को सुन्दर तथा सुचारु रूप में प्रगट करने के लिये सर्वथा उपयुक्त है। वह हमारी अधिकांश देशी भाषाओं की जननी है, और उसके द्वारा ही देशी भाषाएँ परिपुष्ट और समृद्ध हो जा सकती हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म की समुचित जानकारी के लिए संस्कृत साहित्य का अध्ययन आवश्यक है।

हिन्दुओं के लिये तो यह अनिवार्य ही है। मालवीयजी चाहते थे कि संस्कृत भाषा के अध्ययन का क्रम इतना विस्तृत कर दिया जाय कि शिक्षार्थी उसके द्वारा जाति के चरित्र को उच्च बना सकें, राष्ट्र के मानसिक विकास में सहयोग दे सकें, तथा समाजसेवा आदि कर्तव्यों को अत्यन्त सुगमता पूर्वक कर सकें ताकि संस्कृत देश के सब भागों के पठित समाज की फिर वैसी ही भाषा बन जाय जैसी वह “प्राचीन समय” में थी।

मालवीयजी चाहते थे कि ‘सब प्रान्तों में अपने अपने प्रान्त की भाषा की उन्नति हो। सभी भाषाएँ शोभा के साथ प्रौढ और दृढ बनें’ पर हिन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा के तौर पर उपयुक्त की जाए।^१ सब भाई बहिन राष्ट्रीय भाषा के गौरव को मान कर अपनी अपनी भाषा के साथ प्रत्येक बालक को हिन्दी का ज्ञान अवश्य करावें।^२

मालवीयजी का कहना था कि “साहित्य और देश की उन्नति अपने देश की भाषा द्वारा ही हो सकती है”^३। जनता का राजकाज जनता की भाषा में ही सुचारु रूप से चल सकता है। जनभाषा ही लोकतन्त्र की भाषा हो सकती है। उस भाषा में ही जनसाधारण ठीक तौर पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने विचार और भाव व्यक्त कर सकते हैं, राज के क्रियाकलापों में समुचित सक्रिय भाग ले सकते हैं। इसलिये जिस देश की जो भाषा है, उसी में उस देश के न्याय कानून, राजकाज, कौंसिल इत्यादि का कार्य होना चाहिए”^४, और वही भाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अतः मालवीयजी के विचार में हमें केवल स्कूलों में ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों तथा उच्च श्रेणियों में भी देशी भाषाओं के माध्यम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।^५ पर उनका यह विचार कदापि नहीं था कि “हम अंग्रेजी भाषा को सर्वथा त्याग दें”, उनका तो कहना था कि “हमारे युवकों को विदेशी भाषाएं सीखने की आवश्यकता है और कोई विदेशी भाषा हमारे लिए उतनी लाभदायक नहीं हो सकती जितनी अंग्रेजी”^६। अतः सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी को उचित स्थान मिलना

१. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, सन् १९१९, अध्यक्षीय भाषण।

२. वही।

३. वही।

४. वही।

५. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय दीक्षान्त भाषण, सन् १९२०।

६. वही।

चाहिए ।^१ किन्तु अंग्रेजी दूसरी भाषा की तरह पढ़ाई जानी चाहिए, और उसके द्वारा युवकों को शिक्षा देने की व्यवस्था बदल देनी चाहिए ।^२

जब हम किसी भाषा के विषय में कुछ कहते हैं तब हमें उस भाषा की लिपि का विचार स्वभावतः आ जाता है । मालवीयजी का विचार था कि हिन्दी भाषा रोमन या फारसी लिपि के बजाय नागरी लिपि में ही लिखी जाय । उनका कहना था : “भारतवासियों को अपनी भाषा विदेशी अक्षरों में लिखने को कहना वैसा ही है जैसा कि अंग्रेजों से अपनी भाषा को नागरी अक्षरों में लिखने को कहना” ।

मालवीयजी सरल हिन्दी के पक्ष में थे । उनका कहना था कि “हिन्दी में फारसी-अरबी के बड़े-बड़े शब्दों का व्यवहार जैसा बुरा है, हिन्दी को अकारण ही संस्कृत शब्दों से गूँथ देना भी वैसा ही बुरा है । जहाँ तक हो हिन्दी में हिन्दी ही रखी जाय । अनावश्यक शब्दों को हिन्दी से अलग कीजिये । उर्दू और हिन्दी दोनों भाषाओं के रूप गठ बन गये हैं । अब इन दोनों का यथासंभव एक स्थान में लाइए । इस बात के लिए यत्न करना जैसा हिन्दुओं के लिए जरूरी है वैसा ही मुसलमानों के लिए भी आवश्यक है । दोनों ओर से यत्न होने से हम भाषा के क्रम को बहुत कुछ एक कर सकते हैं” ।^३ वे कहते थे : “हम स्वच्छ भाषा में हिन्दी लिखें—जब भाषा में शब्द न मिलें, तब संस्कृत से लीजिए या बनाइए—हिन्दी में जो उर्दू फारसी के शब्द आ गए हैं उनका व्यवहार कीजिए” ।^४ मालवीयजी “अंग्रेजी भाषा और देगी भाषा दोनों भाषाओं के ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद कर हिन्दी साहित्य के भण्डार को भरना चाहते थे । उनका कहना था कि हमें जगह-जगह से और विभिन्न भाषाओं से अच्छे-अच्छे विचारों को चुनना चाहिए” ।^५

मालवीयजी के विचार में विश्वविद्यालयों की तुलना हम वृक्षों से कर सकते हैं जिनकी जड़ें प्रारम्भिक पाठशालाओं की गहराई तक पहुँचती हैं, और जो अपना रस और शक्ति द्वितीय श्रेणी के स्कूलों से ग्रहण करते हैं ।^६ अतः अच्छी ऊँची शिक्षा के लिए वे प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था आवश्यक

१. वही ।

२. वही ।

३. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, अध्यक्षीय भाषण, १९१० ।

४. वही ।

५. वही ।

६. काशी विश्वविद्यालय दीक्षान्त भाषण, १९२९ ।

समझते थे।^१ उनका सुझाव था कि इण्टरमीडियेट कक्षा के दो वर्ष की पढ़ाई सब हाई स्कूलों में की जाय, और बी० ए० की शिक्षा की अवधि तीन वर्ष कर दी जाय।^२ वे विश्वविद्यालयों को विश्व की सारी विद्याओं का ऐसा उच्चस्तरीय शिक्षा केन्द्र बनाना चाहते थे कि वहाँ विभिन्न विषयों के विद्यार्थी एक साथ रहते हुए पारस्परिक सम्पर्क और विचार-विमर्श द्वारा तथा विशेषज्ञों के सुबोध भाषणों द्वारा अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का सरल ज्ञान प्राप्त करें, प्राच्य और अर्वाचीन ज्ञान का तुलनात्मक और समन्वयात्मक अध्ययन करें, तथा विभिन्न विशेषज्ञों के सहयोग से उच्चकोटि का अनुसन्धान करें, और जहाँ सम्भव हो वहाँ प्रयोगशालाओं में अपने विचारों की सच्चाई की परख करें एवं प्रयोगात्मक ढंग से अपने ज्ञान को वास्तविक और ठोस बनायें, उन्हें व्यवहार में लाने की अपने में क्षमता पैदा करें।

मालवीयजी का अपना काशी विश्वविद्यालय एक प्रकार से उनकी अपनी कल्पना का प्रतीक था। वह प्राच्य और अर्वाचीन विद्याओं का संगम, विश्वज्ञान का विद्या-मन्दिर था। वर्तमान सभ्यता की अनुकरणीय तथा लाभदायक बातों के साथ भारतीय सभ्यता का उचित सामंजस्य उसका उद्देश्य था। प्राचीन भारतीय आयुर्वेद के साथ अर्वाचीन शल्यशास्त्र की शिक्षा का मेल, आयुर्वेदिक औषधियों का वैज्ञानिक परीक्षण तथा उनपर अनुसन्धान, विभिन्न विषयों पर प्राच्य और अर्वाचीन ज्ञान का तुलनात्मक और समन्वयात्मक अध्ययन, प्राचीन भारतीय संस्कृति, दर्शनशास्त्र, साहित्य और इतिहास के गम्भीर अध्ययन अध्यापन के साथ-साथ आधुनिक मनोविज्ञान, नीतिविज्ञान, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान आदि का अध्ययन अध्यापन, वेद, वेदांग तथा सस्कृत साहित्य और वाङ्मय की शिक्षा के अतिरिक्त आधुनिक ज्ञान विज्ञान, धातुविज्ञान, खनन विज्ञान, विद्युत इंजीनियरी, यान्त्रिक इंजीनियरी, कृषि विज्ञान का अध्ययन इसकी विशेषता थी। यहाँ ईश्वरभक्ति के साथ साथ देशभक्ति की शिक्षा दी जाती थी, और विद्यार्थियों को राष्ट्र के जीवन का ज्ञान कराया जाता था, उन्हें समाज की सेवा के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। मालवीयजी की कामना थी कि उनका विश्वविद्यालय जीवन और ज्योति का केन्द्र बने, और वहाँ के विद्यार्थी ज्ञान में संसार के दूसरे प्रगतिशील देशों के विद्यार्थियों के समान हों, तथा उत्कृष्ट जीवन वित्ताने के योग्य बनें, देशभक्ति और भगवद्भक्ति से अपने जीवन को अनुप्राणित कर समाज की सेवा करें।

१. इंडियन लेजिस्लेटिव कौंसिल, सन् १९१४, जि० ५२, पृ० १०३२।

२. वही।

मालवीयजी अध्यापक को समाज का 'सर्वश्रेष्ठ सेवक' स्वीकार करते थे। उनकी धारणा थी कि अगर वह देशभक्त है, राष्ट्रीयता से उसे प्रेम है और अगर वह अपने उत्तरदायित्व को समझता है, तो वह देशभक्त पुरुषों और स्त्रियों की जाति उत्पन्न कर सकता है, जो स्वभावतः देश को किसी ऐसी श्रेणी पर पहुँचा देंगे जहाँ राष्ट्रहित के सामने जातीय स्वार्थ और द्वेष का लेश भी नहीं रहेगा।^१ वे चाहते थे कि अध्यापक अपने जीवन को देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की भावना से विभूषित कर इस भूमि से शिक्षा को हटा दें, अपने नवयुवकों में नागरिकता की शिक्षा तथा प्रेम की भावना का ऐसा विस्तार कर दें कि राष्ट्रीयता रूपी सूर्य के सामने साम्प्रदायिकता कभी टिक नहीं सके,^२ अपने विद्यार्थियों में सद्गुणों तथा सज्जान का प्रसार करें, उन्हें इस योग्य बना दें कि वे दूसरे देशों के स्नातकों से टक्कर ले सकें, उनमें इतनी क्षमता पैदा कर दें कि वे अपने देश की शक्ति का निर्माण कर सकें, उसे समृद्ध ज्ञान-सम्पन्न और गौरवान्वित कर सकें।

मालवीयजी चाहते कि जिस तरह प्राचीनकाल में भारत में गुरु सर्वसम्मानित था, उसी तरह अब भी सरकार, अधिकारी और विद्यार्थी गुरुओं के मान की रक्षा तथा उनके गौरव की वृद्धि अपना कर्तव्य समझें। इसके बिना शिक्षा की सुव्यवस्था असम्भव है।

मालवीय जी का विद्यार्थियों को उपदेश था—

सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्यया ।

देशभक्त्यात्मत्यागेन सम्मानर्हः सदाभव ॥

अर्थात् सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, विद्या, देशभक्ति, आत्मत्याग द्वारा अपने समाज में सम्मान के योग्य बनें।

वे चाहते थे कि विद्यार्थी सदा सत्य का आचरण करें, ब्रह्मचर्य और व्यायाम द्वारा अपनी जीवन शक्ति को परिपुष्ट करें, नियमित रूप से विद्याध्ययन कर अपनी बौद्धिक शक्ति का विकास करें, अपने में अपने कुटुम्ब तथा अपने राष्ट्र की सेवा करने की क्षमता पैदा करें, सदा शुद्धता से रहें और शील का पालन करें, अपने सद्व्यवहार से अपने विद्यालय का गौरव बढ़ायें, गुरुजनों का आदर करें, सहपाठियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, छोटे कर्मचारियों के साथ सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करें, अपने से छोटे की सेवा अपना कर्तव्य समझें, दूसरों के प्रति कोई भी ऐसा आचरण न करें जिसे वह अपने प्रति किया जाना अनुचित समझें, उन कार्यों से डरें जो निष्कृष्ट और त्याज्य हैं, मातृभूमि से प्रेम करें,

१. सन् १९२५ का दीक्षांत भाषण ।

२. वही ।

जनता को सुखवृद्धि करें, जहाँ कहीं भी अवसर मिले भलाई करें। वे चाहते थे कि विद्यार्थी अपने अवकाश तथा छुट्टियों में गावों में जाकर गाँव वालों के साथ काम करें, अविद्या रूपी अन्धकार को जो हमारी अधिकांश जनता को आच्छादित किए हुए है ज्ञान के प्रकाश से दूर कर दें। वे चाहते थे कि भारतीय शिक्षित सहनशीलता, क्षमा, तथा निःस्वार्थ सेवा के भाव को अपने जीवन में विकसित कर अपने छोटे भाइयों के उत्थान के लिए अधिक से अधिक अपना समय तथा शक्ति लगावें, उनके साथ मिलकर काम करे, उनके शोक तथा आनन्द में उनका हाथ बटावें, और उनके जीवन को दिनोदिन सुखमय बनाने का प्रयत्न करें। वे तो वास्तव में यह भी चाहते थे कि हम ईश्वर का स्मरण रखें, तथा यह विश्वास रखते हुए कि ईश्वर सभी प्राणियों में विद्यमान है अपने अन्य जीवधारी भाइयों से अपना सच्चा सम्बन्ध प्रतिष्ठित करें।



२९. धर्माधृत मानवता

मालवीयजी की भागवत पर दृढ़ निष्ठा थी। भागवत में प्रतिपादित अद्वैतवाद और ईश्वरवाद का, तथा भक्ति और निष्काम सेवा का सामंजस्य उन्हें स्वीकार था। ईश्वर पर उनकी अचल अगाध श्रद्धा थी। नित्य नियमित रूप से उसकी आराधना, तथा सदा उसका स्मरण वे प्रत्येक मानव का पुनीत कर्तव्य समझते थे। वे ईश्वर को सम्पूर्ण सृष्टि का “कर्ता, नियन्ता, तथा व्यवस्थापक”, सारे विश्व का “साक्षात्कार” समझते थे। उनके विचार में यह “अद्वितीय शक्ति” निःसन्देह “अविनाशी, सर्वव्यापक”, “सत्यज्ञानस्वरूप” एवं “अनन्त” है। वह सभी धर्मों का मूलाधार तथा आराध्यदेव है। वे “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए “ब्रह्मा, विष्णु, महेश” को इस ब्रह्म की तीन संज्ञाएं मानते थे, और रान देवी देवताओं को उसकी विभूतियाँ समझते थे। वे वेदव्यास की इस बात को स्वीकार करते थे कि “ज्योतिरात्मनि नान्यत्र समं तत्सर्वजन्तुषु” अर्थात् यह ज्योति अपने भीतर ही है, अन्यत्र नहीं है, और सब जीवधारियों में एक सम है। वे चाहते थे कि हम यह समझ कर कि “वह सभी में विद्यमान है”, अपने अन्य जीवधारी भाइयों से अपना “सच्चा सम्बन्ध” स्थापित करें। इस तरह वे “सर्वभूतेष्व्वात्मदेवता बुद्धिः” के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए प्राणिमात्र के साथ “आत्मीपम्य व्यवहार” ही न्यायसंगत, तथा धर्मनिष्ठो का पुनीत कर्तव्य समझते थे। वे इस सम्बन्ध में श्रीमद्भगवद्गीता के इस श्लोक को बार-बार दुहराते थे :—

आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥^१

हे अर्जुन, जो व्यक्ति, ‘चाहे दुःख हो चाहे सुख, सब स्थितियों में अपनी उपमा से सबको समान देखता है, वह परम योगी है।’

समत्व के सिद्धान्त को वे सनातन-धर्म का ऐसा मूल मन्त्र स्वीकार करते थे जिसकी सिद्धि को ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, मनोयोग, नीतिशास्त्र सबने निःश्रेयस अर्थात् आत्मोत्कर्ष और मोक्ष के लिए आवश्यक बताया है। समदृष्टा ही ज्ञानी, योगी, भक्त और सत्यनिष्ठ हो सकता है।

कतिपय विद्वान् दृष्टि और व्यवहार के अन्तर पर जोर देते हुए भेदमूलक व्यवहार तथा वैषम्ययुक्त परम्पराओं को न्यायसंगत तथा शास्त्रानुकूल बताते हैं। पर मालवीयजी कहते थे कि समत्व की आध्यात्मिक कल्पना कोरा सिद्धान्त नहीं है, वह तो साधना का मूल मन्त्र तथा लक्ष्य है, जीवन में उसका अवतरण सिद्धि के लिए आवश्यक है। आत्मोपम्य निष्पक्ष व्यवहार, तथा प्राणिमात्र के प्रति सद्भावना उसका व्यावहारिक पक्ष तथा सामाजिक लक्ष्य है, जिसके बिना एक सामाजिक व्यक्ति के लिए समत्व की सिद्धि असम्भव है। मालवीयजी जात्यहकार, वंशाभिमान तथा पार्थक्य की भावना को समत्व की सिद्धि के लिए घातक समझते थे, तथा विश्वबन्धुत्व की भावना तथा सौहार्दपूर्ण व्यवहार को उसका धर्मसंगत नैतिक और सामाजिक साधन स्वीकर करते थे। अपनी इस समीक्षा को वे सर्वथा शास्त्रानुकूल समझते थे, और इसके समर्थन में शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत करते रहते थे।

वे हमें बताते थे कि शास्त्रों में कहा गया है —

यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत् ।^१

‘जो जो बात मनुष्य अपने लिए चाहता है, उसे चाहिए कि वही-वही बात औरो के लिए भी सोचे ।’

महर्षि वेदव्यासजी ने कहा है—

श्रूयता धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् ।

आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ॥^२

न तत्परस्य संदध्यान् प्रतिकूल यदात्मनः ।

एष सामासिको धर्मः कामादन्य प्रवर्तते ॥^३

‘सुनो धर्म का सर्वस्व और सुनकर इसके अनुसार आचरण करो। जो अपने को प्रतिकूल जान पड़े, जिससे अपने को पीड़ा पहुँचे, उसको दूसरो के प्रति न करो ।’

‘दूसरो के प्रति हमको वह काम नहीं करना चाहिए, जिसको यदि दूसरा हमारे प्रति करे तो हमको बुरा मालूम हो या दुःख हो। संक्षेप में, यही धर्म है, इसके अतिरिक्त दूसरे सब धर्म किसी बात की कामना से किये जाते हैं।’

१. महाभारत : शान्तिपर्व, ५९.२२।

२. विष्णुधर्मोत्तर ३.२५५.४४।

३. महाभारत, अनुशासन पर्व, ११३.८।

श्रीमद्भागवत में भक्त-शिरोमणि प्रह्लाद कहते हैं—

ततो हरी भगवति भक्तिं कुरुत दानवा ।

आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे ॥^१

‘अतएव हे दानवो, सबको अपने समान सुख दुःख होता है, ऐसी बुद्धि धारण करके सब प्राणियों के आत्मा और ईश्वर भगवान् श्रीहरि की भक्ति करो ।’

इस प्रकार के शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर मालवीयजी कहते हैं कि “मनुष्यमात्र को विमल भक्ति के साथ घट-घट-अ्यापी उस एक परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, और यह ध्यान करके कि वह प्राणिमान में व्याप्त है, प्राणिमात्र से प्रीति करनी चाहिए” ।^२

मालवीयजी पूजापाठ के विवि-विधान पर तथा शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित कर्मकाण्ड पर विश्वास करते थे, तथा धर्म-जिज्ञासुओं के लिए उनकी थोड़ी बहुत व्याख्या भी करते रहते थे । पर उन्हें पशुबलि आदि हिंसात्मक प्रयोगों पर विश्वास नहीं था । वे उसे तामसिक प्रक्रिया समझते थे । समत्व और निष्काम लोकसेवा पर आश्रित कर्मयोग, एव ईश्वर को सब सत्कर्मों का समर्पण, और उनके द्वारा भगवान् की आराधना ही उनको सर्वप्रिय थी । उनकी दृष्टि में भक्तियुक्त लोकसेवा ही अम्बुदय और निःश्रेयस की मिद्धि का सर्व श्रेष्ठ मार्ग है । सब में समान रूप से अवस्थित ईश्वर की “सर्वोत्तम पूजा यही है कि हम प्राणिमात्र में ईश्वर का भाव देखें, सब में मित्रता का भाव रखें, और सबका हित चाहें ।”^३ वे चाहते थे कि हम “दीन निर्धन देशवासियों की सेवा द्वारा ईश्वर की उपासना करें, तथा सार्वजनीन प्रेम से इस सत्य ज्ञान के प्रचार से ईश्वरीय शक्ति का संगठन और विस्तार करें, जगत् से अज्ञान को दूर करें, अन्याय और अत्याचार को रोकें, और सत्य, न्याय और दया का प्रचार कर मनुष्यों में परस्पर प्रीति, सुख और शान्ति बढ़ावे ।”^४

वे कर्मकाण्ड और नैतिकता दोनों को धर्म का अंग स्वीकार करते थे, और उन्हें दोनों ही प्यारे थे । फिर भी धर्मविहित नैतिकता का प्रसार, तथा उसके आधार पर सामाजिक व्यवहार का, और वैयक्तिक चरित्र का परिशोधन और नवनिर्माण ही उनका मुख्य काम था । अपने चरित्र और उपदेशों द्वारा इसका विस्तार ही उनकी जीवनचर्या थी । उनका अपना चरित्र और व्यवहार निःसन्देह

१. श्रीमद्भागवत, ७.७.५३ ।

२. सीताराम : महामना पंडित मदन मोहन मालवीय खंड ३ पृ० १० ।

३. वही, पृ० २३ ।

४. वही, पृ० १३ ।

भारतीय नैतिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका अनुकरण अवश्य ही एक हिन्दू नवयुवक के जीवन को ऊँचा उठा सकता है, उसे समाज-सेवी सत्पुरुष बना सकता है। उनकी नैतिकता की व्याख्या धर्मसंगत, तथा मनुष्यता की भावना से अनुप्राणित, एवं समाजोत्कर्ष और जीवनोत्थान की कामना और क्षमता से परिपूर्ण थी।

मालवीयजी बार-बार कहते थे कि मनु के अनुसार—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(‘धैर्य, क्षमा, बुरी वृत्तियों का दमन करना, चोरी न करना, शौच, आत्म-निग्रह, विवेक, विद्या, सत्य, क्रोध न करना—ये धर्म के दश लक्षण हैं।’)

तप की व्याख्या करते हुए मालवीयजी लिखते हैं—“तप अपने उद्देश्य, प्रयोजन या गरज से अच्छा या बुरा, ऊँचा या नीचा, तामसिक, राजसी और सात्त्विक एवं कायिक, वाचिक और मानसिक कहलाता है।” “जो काम निष्काम भाव से, फल की इच्छा त्याग कर, शम-दम से सम्पन्न हो कर, श्रद्धा और धैर्य के साथ मन, वाणी या शरीर से किया जाता है, वह ‘सात्त्विक तप’ कहलाता है। मन को जीतना अर्थात् काम-क्रोध-लोभ-मोह से बचना और शुद्ध संकल्प-युक्त रहना, किसी विषय-वृत्ति के कारण विक्षिप्त हो कर फिर भी उस पर विजय प्राप्त करना, व्यवहार काल में छल-कपट, धोखा और फरेब से मन को दूर रखना, मन को सात्त्विक बनाना—यह ‘मन द्वारा सात्त्विक तप’ करना है। ‘वाणी का सात्त्विक तप’ यह है कि जो वाक्य असत्य, दुःखदायी, अप्रिय और खोटा हो उसको किसी समय, किसी भी अवस्था में मुँह से न निकालना, बल्कि प्रिय, सत्य, मीठे और मधुर वचन बोलना—यह वाणी द्वारा सात्त्विक तप करना है। शरीर से अर्थात् शरीर के अवयवों से, हस्तपादादि कर्मेन्द्रियों के द्वारा दूसरों की सहायता और सेवा करना, गिरे हुए को उठाना, देश और जाति के लिए, अपने शरीर के दुःख और कष्ट की परवाह न कर, बल्कि यदि आवश्यकता हो तो धर्म और परोपकारार्थ प्राण अर्पण कर देना—यह ‘काया का सात्त्विक तप’ है। परन्तु अपनी स्तुति, मान, पूजा, सत्कार, प्रतिष्ठा, और नाम या भोग-विलास के लिए इन्हीं सब कामों को मन, वाणी या शरीर द्वारा करना इनको ‘राजसी’ बना देता है। जो तप अविवेक से, दूसरों को हानि पहुँचाने, दिल दु खाने, द्वेष और शत्रुता से किया जाता है—वह ‘तामसी’ है”।^१ उन्होंने लिखा : “इन रूपों का भिन्न-

मित्र वर्णन करने से अभिप्राय यह है कि लोग अपनी-अपनी मन, वाणी, शरीर की परीक्षा करें, और सात्त्विक तपो को ग्रहण करते हुए राजसी और तामसी को त्याग दें ।”

वे कहते थे :—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा ॥

(‘नीति में निपुण लोग निन्दा करें वा प्रशंसा करें, लक्ष्मी जाय या रहे, आज ही मृत्यु हो या युगान्तर में हो, परन्तु धीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते ।’)

सदाचार की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते थे—

वाञ्छा सज्जनसंगमे परगुणे प्रीतिर्गुरी नम्रता ।
विद्याया व्यसनं स्वयोपिति रतिः लोकापवादाद् भयम् ॥
भक्तिश्चक्रिणि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले ।
ये ज्येते निवसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥

(‘सज्जनो के सत्संग में इच्छा, पराये के गुणों से प्रीति, गुरु के साथ नम्रता, विद्या में व्यसन, अपनी स्त्री में प्रीति, लोकनिन्दा से भय, विष्णु की भक्ति, आत्म-दमन की शक्ति, दुष्टों के संसर्ग से मुक्ति, ये निर्मल गुण जिनमें बसते हैं, उन पुरुषों को नमस्कार है ।’)

भारतीय शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित नैतिक नियमों तथा सदाचार की महिमा का विस्तृत दिग्दर्शन कराते हुए वे कहते थे कि “सदाचार के सेवन से, सत्कर्म करने से, शूद्र भी द्विजत्व को पहुँच सकता है, और दुराचार अर्थात् बुरे कर्म करने से ब्राह्मण भी नीचे गिर कर शूद्रता को पहुँच सकता है ।”

मालवीयजी ने बताया कि महाभारत में कहा गया है—

वर्णोत्कर्षमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा ।
यथाऽपकर्षं पापेन इति शास्त्रं निदर्शनम् ॥^३

१. वही ।

२. अन्त्यजोद्धार विधि ।

३. महाभारत, शान्तिपर्व, १९२ ।

शूद्रोऽपि शीलसम्पन्नो गुणवान् ब्राह्मणो भवेत् ।
ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीनः शूद्रात् प्रत्यवरो भवेत् ॥^१

सत्यं दानं क्षमा शीलमानुशस्यं तपो दया ।
दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥^२
यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सतोत्तित्यतः ।
तं ब्राह्मणमह मन्ये वृत्तेन हि भवेद् द्विजः ॥^३

‘मनुष्य पुण्य कर्म से वर्ण के उत्कर्ष को तथा पाप कर्म से अपकर्ष को अर्थात् पतन को प्राप्त करता है, यह शास्त्र का निर्देश है ।’

‘शील-सम्पन्न शूद्र भी गुणवान् ब्राह्मण के समान हो जाता है, क्रियाहीन ब्राह्मण भी शूद्र से गिरा हो जाता है ।’

‘सत्य, दान, क्षमा, शील, कटुता का अभाव, तप और दया जहा दिखाई दे, नागेन्द्र, वह ब्राह्मण है,—ऐसा स्मृतियों का कहना है ।’

जो शूद्र आत्मसंयम, सत्य, धर्म में सदा प्रगति करता हुआ है, उसे मैं ब्राह्मण मानता हूँ । सदाचरण से ही द्विज होता है ।’

श्रीमद्भागवत में भी सातवें स्कन्ध में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलग-अलग गुणों का वर्णन करते हुए नारदजी ने कहा है—

यस्य यत्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् ।
यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिदिशेत् ॥^४

जिस पुरुष को जो वर्ण का प्रकट करनेवाला लक्षण कहा है, जहा दूसरो में भी वह लक्षण दिखाई दे तो उसको उसी गुणवाले वर्ण के नाम से बताना चाहिए ।’

मालवीयजी के विचार में “इन वचनों से यह स्पष्ट है कि यदि जन्म से ब्राह्मण होनेवाला भी अपने धर्म से रहित हो जाय या कुकर्म करने लगे, तो वह शूद्र से भी नीचे गिर जाता है, और नीच से नीच शूद्र भी यदि अच्छे आचरणों को ग्रहण करे और ऊँचा पवित्र जीवन व्यतीत करने लगे तो वह भी ब्राह्मण के समान मान पाने के योग्य हो जाता है ।”^५

१ महाभारत, वनपर्व ।

२. वही ।

३. वही ।

४ श्रीमद्भागवत ।

५ अन्त्यजोद्धार विधि ।

मालवीयजी शील की तरह कतिपय पौराणिक मन्त्रों और भगवद्भक्ति को भी जीवनोद्धार का उपाय बताते हुए कहते हैं कि “ब्राह्मण से लेकर अन्त्यज पर्यन्त सभी सनातन-धर्मानुयायी पुरुषों और स्त्रियों को मन्त्रदीक्षा लेकर मन्त्रजाप करने का तथा भगवान् की भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है।”^१ ‘अन्त्यजोद्धार विधि’ में वे बहुत से पौराणिक प्रमाणों से अपने विचारों की पुष्टि करते हुए सब वर्णों और जातियों के नर-नारियों से अनुरोध करते हैं कि वे विधिपूर्वक मन्त्र-दीक्षा लेकर, शास्त्रविहित शील का पालन करते हुए नियमित रूप से मन्त्रों का जाप करें, तथा विधिवत् भगवान् की आराधना करें। वे चाहते थे कि देवमन्दिरों के पुजारी तथा अधिकारी भगवद्भक्ति में सबका समान अधिकार स्वीकार करते हुए भेदबुद्धि त्यागकर अन्त्यज पर्यन्त सब धर्मनिष्ठ हिन्दुओं के लिए समानरूप से देवदर्शन की व्यवस्था कर दें, तथा धर्मज्ञ विद्वान् पुराणों द्वारा प्रतिपादित मन्त्र महिमा को स्वीकार करते हुए अन्त्यज पर्यन्त सब श्रद्धालु नरनारियों को विधिवत् मन्त्रदीक्षा लेने को प्रोत्साहित करें।

मालवीयजी ने इसी पुस्तक में बहुत-सी कथाओं और महात्म्यों का उदाहरण देते हुए लिखा है कि इन सबका तात्पर्य यही है कि “मनुष्य चाहे पहले कैसा ही स्वाभाविक या नैमित्तिक दोषों से युक्त क्यों न हो, यदि वह मन्त्रदीक्षा, भक्ति-भावना और सदाचार से सम्पन्न हो जाता है, तो वह दोषनिर्मुक्त होकर सम्मान्य, आदरणीय और स्ववर्ग का सामाजिक साधारण धर्माधिकारी हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी बीजसम्बन्धी और शरीरसम्बन्धी अपवित्रता चली जाती है।”^२

मालवीयजी यह भी चाहते थे कि “सार्वजनिक स्थानों से वर्ण भेद का प्रश्न हटा दिया जाय”^३, और हरिजनो को दूसरे नागरिकों की तरह उन स्थानों के प्रयोग का समानरूप से अधिकार हो। उनका हमें आदेश था कि हम उनसे प्रेम का व्यवहार करें, और उन्हें अपना भाई समझ छूत-छात को दूर करें^४, उनसे ‘हिल मिल कर’ काम करें, उनके उत्थान का उपाय सोचें^५। उनकी धारणा थी कि हरिजन हिन्दू समाज के अङ्ग हैं, वे भी हमारी ही तरह हिन्दू सभ्यता तथा संस्कृति

१. अन्त्यजोद्धारविधि।

२. वही।

३. हिन्दू महासभा, पूना १९३५।

४. हिन्दू महासभा, गया अधिवेशन, सन् १९२२, में भाषण।

५. हिन्दू महासभा, पूना अधिवेशन, सन् १९३५।

के उत्तराधिकारी हैं^१, उनकी उन्नति करना, उन्हें सामान्य और धार्मिक शिक्षा देना, और दूसरे अङ्गो-के समान उनकी रक्षा करना, और उनको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है।

उनका कहना था कि “वे हमारी परमावश्यक सेवा करते हैं। इसलिए उनका उपकार करना हमारा धर्म है। दूसरे यह कि वे हमारे सधर्मी हैं। जिस सनातन-धर्म को हम मानते हैं, उसी को वह भी मानते हैं। बहुत-सा भय और बहुत-सा लालच दिखाये जाने पर भी, और बहुत-सा क्लेश सहने पर भी उनकी श्रद्धा आज तक इस धर्म में बनी है। वे हमारे हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। उनके साथ विशेष रूप से उदारता का व्यवहार करें।”^२

इस तरह यद्यपि मालवीयजी जन्म को ही चातुर्वर्ण-व्यवस्था का आधार स्वीकार करते थे, और रोटी-बेटी के सम्बन्ध में केवल समान शीलसम्पन्न उपजाति का अन्तर दूर करने की ही बात करते थे, पर वर्णाश्रम धर्म की उनकी व्याख्या प्रचलित मान्यताओं और परम्पराओं से कहीं अधिक उदार थी। उन्होंने प्रयाग में ब्राह्मण सम्मेलन कर निर्णय कराया कि समान शीलसम्पन्न विभिन्न ब्राह्मण जातियों में विवाह हो सकता है, और अपनी पौत्रियों का विवाह गौड़ तथा सनाढ्य ब्राह्मणों से किया। उन्होंने पचास वर्ष की आयु में जीविकोपार्जन का धन्धा छोड़ दिया, और इस तरह गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर वन में जाकर एकान्त में घोर तपस्या करने के बजाय समाज में रहते हुए एकमात्र लोकसेवा अपना धर्म निश्चित किया, और दूसरे वानप्रस्थियों को ऐसा करने का ही उपदेश दिया। वे तो इसी तरह यह भी चाहते थे कि ब्राह्मण शारीरिक श्रम के महत्त्व को स्वीकार करें, शूद्र सेवा के अतिरिक्त व्यवसाय द्वारा भी जीविकोपार्जन करें, सब लोग राष्ट्र की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझें, सब जातियों और वर्णों को सैनिक शिक्षा दी जाय, और सेना में भरती किया जाय, ऊँची से ऊँची शिक्षा प्राप्त करने का सबको अधिकार हो, स्त्रियाँ भी सुशिक्षित हो, लोककल्याण के निमित्त वे सार्वजनिक कार्यों में योगदान करें, जन्मजात अस्पृश्यता दूर हो, हरिजन भी द्विजत्व अर्थात् द्विज समान श्रेष्ठता प्राप्त करें।

१. हिन्दू महासभा, कानपुर अधिवेशन, सन् १९२५।

२. हिन्दू महासभा, प्रयाग अधिवेशन।

हिन्दू धर्म के प्रति मालवीयजी की दृढ़ निष्ठा थी । वे अपने सनातन-धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, पर उनकी निष्ठा सहिष्णुता से समन्वित थी । वे समान रूप से सब धर्मों, धर्मग्रन्थों, धर्मगुरुओं का आदर करना सब धर्मनिष्ठ व्यक्तियों का कर्तव्य समझते थे । वे “मन्दिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजा सबको सम्मान के काविल” समझते थे, और कहते थे कि “जब मैं किसी गिरजा या मस्जिद के पास से गुजरता हूँ, तब मेरा सिर सम्मान से झुक जाता है ।”^१ यद्यपि उन्होंने शुद्धि आन्दोलन को प्रोत्साहित किया, अपने धर्म का व्यापक प्रसार और प्रचार शास्त्रसंगत तथा हिन्दुओं का कर्तव्य बताया, फिर भी उन्होंने कभी किसी दूसरे धर्म, धर्मगुरु या धर्म-ग्रन्थ की निन्दा नहीं की । उनका कहना था कि “मैं सदैव अपने धर्म का दृढ़ विश्वासी और पाबन्द हूँ, परन्तु किसी के धर्म का अपमान करने का खयाल तक मेरे दिल में कभी नहीं आया”^२ । वे चाहते थे कि धर्मप्रचार का काम बहुत शांति और धैर्य से होना चाहिए ।^३ वह इस रीति से करना चाहिए कि जिससे किसी को क्लेश न पहुँचे । एक दूसरे को कटुवचन कहने से रोकना चाहिए, और ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिनसे प्रीति और मित्रता बढ़े ।^४ उन्होंने अपने धर्म की कतिपय प्रचलित पद्धतियों की यदा-कदा समीक्षा भले ही की हो, पर उन्होंने किसी दूसरे धर्म की आलोचना कभी नहीं की । उन्होंने धर्म-समन्वय के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं किया, पर वे यह स्वीकार करते थे कि सत्य और ईश्वर की आराधना सब धर्मों का मूलधार है, कतिपय मूलभूत सद्गुण सभी धर्मों में विद्यमान हैं, जीवनसिद्धि के अनेक मार्ग हैं, मानव अपनी रुचि और परम्परा के अनुकूल अपना मार्ग निश्चित कर दृढ़ निष्ठा से उस पर चल कर सद्गति प्राप्त कर सकता है । वे चाहते थे कि हिन्दू ‘पक्का हिन्दू’ और मुसलमान ‘पक्का मुसलमान’ बने, दोनों ‘ईश्वर भक्त हो’, सब अपने धर्म के सिद्धान्तों को अच्छे तौर पर समझें ।^५ उनकी धार्मिक सहिष्णुता ने वास्तव में धार्मिक सद्भावना का ऐसा अपूर्व रूप धारण कर लिया था कि उन्होंने सत्तर वर्ष की आयु में समुद्र-यात्रा करते हुए जहाज में बाइबिल हाथ में लेकर पूर्ण निष्ठा के साथ ईसाइयों की उपासना में निःसंकोच भाग लिया ।^६ वे मनुष्यता को जातिपांति और साम्प्रदायिक भेदों से ऊँचा समझते थे ।^७

१. लाहौर में भाषण, २८ जून सन् १९२३ ।

२. वही । ३. पंजाब हिन्दू सम्मेलन, सन् १९२४ ।

४. लाहौर में भाषण, सन् १९२३ ।

५. पंजाब हिन्दू सम्मेलन, सन् १९२४ ।

६. विडलाजी की डायरी ।

७. कानपुर में भाषण, सन् १९३१ ।

मालवीयजी स्वीकार करते थे कि शास्त्रविहित विधियों का यन्त्रवत् अनुकरण निःसन्देह हानिकर है,^१ तथा हमारे नित्यकर्मों में कई ऐसी प्रथाओं का समावेश हो गया है जो किसी प्रकार शास्त्रविहित नहीं हैं।^२ वे परम्पराओं का परिशोधन तथा प्रगति का नियमन समाजोत्थान और जीवनोत्कर्ष के लिए परमावश्यक समझते थे। पर उनके विचार में आधुनिक सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन करने पर प्रचलित परम्पराओं को शास्त्र के आधार पर भी बहुत हद तक संशोधित किया जा सकता है, और उन्होंने स्वयं सुधार के काम में इसी प्रथा का सदा अनुसरण किया। उनका कहना था कि “मैं शास्त्र की रस्सी थाम कर चलता हूँ, और मैं जो कुछ कहता हूँ शास्त्र के आधार पर कहता हूँ”^३। उनकी धारणा थी कि प्राचीन भारतीय सस्कृति के विश्वजनीन आदेशों का अनुसरण प्राचीन परम्पराओं की जड़ताओं को दूर कर सकता है, जीवन को मानवीय, प्रगतिशील और समाजोपयोगी बना सकता है।

मालवीयजी की धार्मिक धारणाएं मानवकल्याण की भावना से अनुप्राणित थी। कल्याण की वृद्धि वे सब वर्णों और आश्रमों का लक्ष्य स्वीकार करते थे। उनके विचार में निष्काम भाव से समाज की सेवा ही परम तप और परम धर्म है। निष्काम भाव के महत्त्व की व्याख्या करते हुए वे कहते थे कि “जो लोग निष्काम भाव से काम नहीं करते—उन लोगों में परस्पर ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं और कार्य सफल नहीं होने पाता। किन्तु जहाँ निष्काम भाव से कार्य होता है, वहाँ लोग दूसरे की सफलता देख कर प्रसन्न होते हैं, और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव उत्पन्न होता है, और कार्य में शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। सकाम भाव से काम करनेवालों को विपत्तियाँ काम करने से विमुख कर देती हैं, किन्तु निष्काम भाव से काम करनेवाले लोग यह समझ कर कि जो काम हम कर हैं, वह ईश्वर का काम ही है, और इसमें ईश्वर हमारा सहायक है, किसी विघ्न या बाधा से पीछे नहीं हटते।”^४

तप की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चे तप का भाव उस देशभक्त में है जो अपने देश एवं अपनी जाति के गौरव और प्रतिष्ठा, कीर्ति और मान, सम्पत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि और उन्नति के लिए दृढ़ इच्छा रखता है। अनेक

१. अम्युदय, १ मई, सन् १९०८।
२. वही।
३. पंजाब हिन्दू सम्मेलन, सन् १९२४।
४. अम्युदय, २६ मार्च, सन् १९०९।

प्रकार के दुःखों, संकटों और कष्टों को सहन करने, कठिन से कठिन मेहनत और श्रम को उठाने और विघ्नों का मुकाबला करने के लिए उद्यत रहता है। सच्चे देश-प्रेमी देशानुरागी कल्याण की उच्छा करते, तप का अनुष्ठान करते, आत्मा और मन को धर्माचरण रूपी प्रचण्ड अग्नि में दग्ध करके अपने और अपने देश की अपवित्रता, मलिनता और अन्य अशुद्धियों को दूर कर जाति को आरोग्यता एवं सुख-सम्पत्ति को योग्यता प्रदान करते हैं।^१

मालवीयजी देशभक्ति को धर्म का महत्त्वपूर्ण अंग स्वीकार करते थे। उनका कहना था “सच्चा तप यह है कि अपने भाइयों के ताप से तपा जाय। सच्चा यज्ञ यह है जिसमें अपने स्वार्थ की आहुति दी जाय। सच्चा दान वह है जिसमें परमार्थ किया जाय, और सच्ची ईश्वर-सेवा यह है कि उसके दुःखी जीवों की सहायता की जाय। परमात्मा सबके हृदय में व्यापक है, इसलिए जितने प्राणियों को हम प्रसन्न करेंगे, उतने ही गुना ईश्वर को प्रसन्न करेंगे। यह सच्चा धर्म देशभक्ति द्वारा प्राप्त है।”^२ मालवीयजी को विश्वास था कि देशभक्ति का संचार हमारे हृदय से दुर्भाव निकाल कर फेंक देगा, हम अदूरदर्शी, स्वार्थी और खुशामदियों की तरह ऐसे काम कदापि न करेंगे, जिनसे देशवासियों को हानि पहुँचे, बल्कि दूरदर्शी, परमार्थी, सत्यशील और दृढताप्रिय आत्माओं की भाँति असंख्य कष्ट उठाते हुए वही करेंगे, जिससे देश का भला हो तथा निर्धन धनवान्, निर्बल बलवान् और मूर्ख भी बुद्धिमान् हो जायें। प्रत्येक प्रकार के सामाजिक दुःख मिटें और दुर्भिक्ष आदि विपत्तियाँ दूर होकर लाखों बिलबिलाती हुई आत्माओं को सुख पहुँचे।^३ उनका कहना था कि “देशभक्ति द्वारा इतने धर्मों का सम्पादन हुआ देख कर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ नहीं समझता, उस पुरुष को जान लीजिये कि वह धर्म के पहले तत्त्व को नहीं पहचानता, वह ‘धर्म’ शब्द गा रहा है, पर यह नहीं जानता कि धर्म क्या वस्तु है।”^४

मालवीयजी चाहते थे कि भारतवासी स्वार्थभक्ति छोड़कर देश-भक्ति अपनायें जिसके आगे हम अपने को भूल जायें, देश की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझें, देश के यश में अपना यश समझें, देश के ही जीवन में अपना जीवन समझें, और देश की मृत्यु में ही अपनी मृत्यु समझें।^५

१. अम्युदय, १५ जनवरी, सन् १९०९।

२. अम्युदय, भाद्रपद शुक्ल ६, सम्बत् १९६४।

३. वही।

४. वही।

५. अम्युदय।

इस तरह मालवीयजी का सामाजिक चिन्तन 'धर्माधृत सामाजिक मनुष्यता' पर आश्रित था। वही उनका भूल मन्त्र था। वही उनकी जीवनचर्या और उनके लोकशील का मूलाधार था। वेदान्त का अद्वैत, भागवत धर्म द्वारा प्रतिपादित ईश्वरार्पित निष्काम लोकसेवा द्वारा भगवान् की आराधना, श्रीमद्भगवद्गीता का सात्त्विक कर्त्ता, मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म के दश लक्षण, हिन्दू शास्त्रों में वर्णित सात्त्विक शील, ज्ञान का व्यापक प्रसार, विभिन्न मतमतान्तरो के प्रति हिन्दू धर्म की उदार भावना मालवीयजी के विश्वजनीन चिन्तन के आधार थे। मेत्सनी की उदार राष्ट्रीयता, इंग्लैंड की लोकतांत्रिक वैधानिकता, वुड्रो विलसन की अन्तर्राष्ट्रीयता, मानव की स्वाभाविक साधुता पर उन्नीसवीं शताब्दी के बुद्धिवादी मनोवैज्ञानिकों का दृढ़ विश्वास, यूरोपीय विद्वानों के लोकोपयोगी वैज्ञानिक आविष्कार, समाजवादियों की सामाजिक न्याय की धारणा, उदारवादियों के नागरिकता के सिद्धान्त, आधुनिक शिल्पवैज्ञानिक प्रगति द्वारा औद्योगिक विकास—इन सब का भी उनके मानवीय समाजदर्शन में भरपूर समावेश था। इस तरह उनका दर्शन समाजोत्कर्षोन्मुख, लोकसेवापरक, तथा मानवचिन्तन की उत्कृष्ट उपलब्धियों का समन्वय था।^१



३०. निष्कर्ष

विचारो की विभिन्नता तथा नाना प्रकार के सिद्धान्तों और नियमों का प्रतिपादन और अनुसरण स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज का महत्त्वपूर्ण लक्षण है। विभिन्न हितों, आकांक्षाओं और विचारों का समन्वय एक लोकतांत्रिक नेता और पार्टी का काम होता है, पर कोई नेता या पार्टी पूर्ण समन्वय नहीं कर पाती है। विभिन्नता बनी रहती है, और उसकी स्वतंत्रता लोकतांत्रिक जीवन के उत्कर्ष के लिए आवश्यक समझी जाती है। इस तरह लोकतन्त्र में कोई भी नेता कभी भी अपने को सारे समाज का एक-मात्र नेता होने का दावा नहीं कर सकता। वह यह नहीं कह सकता कि उसके सिद्धान्तों और विचारों में सब वर्गों के हितों का तथा सब विचार-धाराओं के मूलभूत तत्वों का सर्वांगीण समन्वय है। इस तरह एक लोकतांत्रिक नेता किसी विशिष्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व ही करता है, और उसके सिद्धान्त तथा विचारों का दूसरी विचारधारा से टकराव होता ही रहता है। पर एक उच्चकोटि का लोकतांत्रिक नेता विशिष्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए भी अपने चरित्र, अपने वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता द्वारा सारे समाज का आदर और विश्वास प्राप्त कर सकता है। (लोकतन्त्र में उत्कृष्ट नेता वही है जो अपने उत्तरदायित्वपूर्ण सद्ब्यवहार से सारे समाज का सम्मान प्राप्त करते हुए अपने विश्वास के अनुसार सारे राष्ट्र के हित में ईमानदारी के साथ किन्हीं विशिष्ट सिद्धान्तों और नीतियों को प्रतिपादित करता है, और लोकतांत्रिक ढंग से सब प्रकार की विघ्न बाधाओं का मुकाबला करते हुए उन्हें कार्यान्वित करने का यत्न करता है।)

इस दृष्टि से भारत के इस लोकतांत्रिक युग के लिए मालवीयजी का वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं के लिए अवश्य ही अनुकरणीय है। उनकी तत्परता, दृढ़ता, भद्रता, तितिक्षा और कर्तव्य-परायणता, तथा निर्भीकता और निःस्वार्थ सेवा-भावना का अनुकरण अवश्य ही इस देश के लोकतांत्रिक जीवन को ऊँचा उठा सकता है, देश के सार्वजनिक जीवन की बहुतांसी विषमताओं को दूर कर सकता है। इस तरह मालवीयजी का जीवन आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है, जितना वह स्वतंत्रता के पहले था।

मालवीयजी इस देश में स्वतंत्र लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था प्रतिष्ठित करना चाहते थे। उन्होंने अपने ५० साल के लम्बे सार्वजनिक जीवन में विभिन्न समस्याओं और परिस्थितियों के सन्दर्भ में लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया। उनके बहुत से लोकतांत्रिक सिद्धान्त भारत के इस लोकतांत्रिक युग के लिए सर्वथा प्रासंगिक हैं। उन्होंने जिस ढंग से प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान-सभाओं में काफी विपम परिस्थितियों में कार्य किया, उसका अध्ययन अवश्य ही लाभप्रद हो सकता है। जिस प्रकार वे लम्बे-लम्बे व्याख्यान वहाँ देते थे, उस तरह से आधुनिक विधान-सभाओं में विधायकों को व्याख्यान देने का अवसर तो नहीं मिल सकता, और उन्हें बरबस सीमित समय में ही अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना होगी, और मालवीयजी से कहीं अधिक अपना सम्पर्क अपने चुनाव-क्षेत्र की जनता से बनाये रखना होगा। पर उन्होंने जिस तरह संसदीय भद्रता का विधान-सभाओं में पालन किया और जिस भावना से उन्होंने निरर्थक व्यक्तिगत आक्षेप तथा वितण्डावाद की उपेक्षा करते हुए दृढ़ता पर भद्रता के साथ विवेकपूर्ण ढंग से तथ्यों और प्रमाणों को उपस्थित करते हुए देशहित में निःस्वार्थ भावना से अपने विचारों को विधान-सभा के सामने प्रस्तुत किया, वह अवश्य ही विधायकों के लिए एक उत्कृष्ट अनुकरणीय उदाहरण है। उनका संवैधानिक व्यवहार अवश्य ही इस लोकतांत्रिक युग के लिए प्रासंगिक और अनुकरणीय है।

मालवीयजी के धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों के सम्बन्ध में इस युग में भी काफी मतभेद हो सकता है। उनके विचारों के प्रति प्राचीन भारतीय संस्कृति में निष्ठावान् व्यक्तियों की विभिन्न प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं। कुछ विद्वान् पुरानी परम्पराओं और मर्यादाओं का अक्षरशः अनुकरण ही हिन्दू समाज का कर्तव्य समझ सकते हैं। उनकी यह धारणा हो सकती है कि हमें किसी से न कुछ लेना है और न नयी परिस्थिति के सन्दर्भ में पुरानी बातों में परिवर्तन करने की जरूरत है। इस प्रकार के विद्वानों के लिए मालवीयजी के धार्मिक विचार आज भी उतने ही निरर्थक हैं, जितने कि वे उनके जीवनकाल में थे। हिन्दू राष्ट्र पर दृढ़ विश्वास रखने वाले विचारक भी मालवीयजी के विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें मालवीयजी की व्याख्या ठीक नहीं जच सकती। देश में कुछ ऐसे विचारक भी हो सकते हैं जो किसी अंश में भी धर्म तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति की सार्थकता स्वीकार करने को तैयार न हों, और समझते हों कि संसार की आधुनिक विचारधाराओं के समुचित प्रयोग द्वारा ही देश का उत्थान सम्भव है। उनके लिए भी मालवीयजी के धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों की कोई

सार्वकता नहीं है। देश में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो हिन्दू धर्म के बजाय किसी अन्य धर्म पर विश्वास करते हैं, और अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में किसी प्रकार का हेरफेर करने को तैयार नहीं हैं। उनके लिए मालवीयजी के धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती।

पर देश में बहुत से ऐसे विचारक होंगे जो राष्ट्र की प्रगति के लिए भारतीय संस्कृति के सार्वजनिक, सर्वमान्य सजीव तत्त्वों का आधुनिक विचारधारा के प्रगतिशील तत्त्वों से समन्वय राष्ट्र के निर्माण में आवश्यक समझते हैं, और जो या तो धर्म के प्रति स्वयं निष्ठावान् हैं या जनसाधारण की निष्ठा को देखते हुए धर्म के उदात्त विचारों का देश में प्रसार आवश्यक समझते हैं। उनके लिए मालवीयजी के विचार आज भी प्रासंगिक और सार्थक हैं।

इस तरह से मालवीयजी के धार्मिक और सांस्कृतिक विचार यदि सारे समाज के चिन्तन का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकते, तो भी वे एक विशिष्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व अवश्य करते हैं, और उस विचारधारा के माननेवालों का मार्गदर्शन अवश्य कर सकते हैं।

आधुनिक भारत के आर्थिक जीवन में मालवीयजी के कतिपय आर्थिक विचारों की कोई सार्वकता नहीं है, और इस समय देश के सामने कई ऐसी आर्थिक समस्याएँ हैं जिनके ऊपर मालवीयजी को अपने विचार व्यक्त करने का कोई अवसर ही नहीं मिल पाया, तथापि लोककल्याण और सामाजिक न्याय पर आश्रित उनके आर्थिक विचार आज भी बहुत हद तक सार्थक हैं, और उनकी विचारधारा के आधार पर एक आर्थिक कार्यक्रम अवश्य तैयार किया जा सकता है।

मालवीयजी शिक्षा की सब सुविधाओं का मूलाधार समझते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका कार्य अवश्य ही बहुत महत्वपूर्ण था। शिक्षा के सम्बन्ध में उनके विचार परिपक्व, उदात्त और बहुत हद तक परिपूर्ण हैं। वे अवश्य ही आज भी प्रासंगिक हैं। उनका अनुसरण कर एक अच्छी शिक्षा-पद्धति देश में प्रतिष्ठित की जा सकती है। उनके उपदेशों का अनुसरण करके शिक्षक और विद्यार्थी अपने जीवन को अवश्य ही काफी ऊँचा उठा सकते हैं, तथा पारस्परिक वैमनस्य का निराकरण कर एक स्वस्थ सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रतिष्ठित कर सकते हैं।



तिथिसूची

मालवीयजी के जीवन से सम्बन्धित मुख्य तिथियों की सूची

| | |
|---------------------|---|
| २५ दिसम्बर सन् १८६१ | प्रयाग में मदन मोहन मालवीय का जन्म |
| सन् १८७८ | कुन्दन देवीजी से मालवीयजी का विवाह |
| सन् १८८४ | कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी० ए० परीक्षा में मालवीयजी उत्तीर्ण |
| जुलाई सन् १८८४ | इलाहाबाद जिला स्कूल में अध्यापक |
| दिसम्बर सन् १८८५ | मध्यभारत हिन्दू समाज के समारोह के आयोजन में मालवीयजी का सक्रिय सहयोग |
| दिसम्बर सन् १८८६ | कलकत्ते में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन—कौंसिलो में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर मालवीयजी का भाषण । उसके बाद आजीवन कांग्रेस से मालवीयजी का घनिष्ठ सम्बन्ध |
| जुलाई सन् १८८७ | कालाकाकर में 'हिन्दुस्थान' पत्र का सम्पादन कार्य प्रारम्भ |
| सन् १८८७ | भारत धर्म महामंडल का स्थापना सम्मेलन । १५ वर्ष तक उसके काम में मालवीयजी का सक्रिय योग-दान । उसके बाद सम्बन्ध विच्छेद |
| सन् १८८९ | हिन्दुस्थान पत्र का सम्पादन छोड़कर प्रयाग में वकालत की पढाई प्रारम्भ |
| सन् १८९१ | वकालत की परीक्षा पास करके जिला अदालत में वकालत प्रारम्भ करना |
| दिसम्बर सन् १८९३ | मालवीयजी का प्रयाग हाईकोर्ट में वकालत करना |
| मार्च सन् १८९८ | पश्चिमोत्तर प्रान्त मौजूदा उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर को हिन्दी के सम्बन्ध में मेमोरंडम |
| सन् १९०२-१९०३ | मालवीयजी के प्रयास से प्रयाग में हिन्दू बोर्डिंग हाउस का निर्माण |
| सन् १९०३-१९१२ | प्रान्तीय कौंसिल की सदस्यता—मालवीयजी द्वारा कौंसिल में प्रान्त की महत्त्वपूर्ण सेवा |

- सन् १९०४ काशीनरेश प्रभुनारायण सिंह की अध्यक्षता में वाराणसी में मालवीयजी का विश्वविद्यालय की स्थापना पर भाषण
- जनवरी सन् १९०६ कुम्भ के अवसर पर प्रयाग में मालवीय जी द्वारा आयोजित सनातन धर्म महासभा का अधिवेशन। उदार सनातन धर्म का प्रचार। काशी में भारतीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय
- सन् १९०७ मानवीयजी के सम्पादकत्व में "अभ्युदय" का प्रकाशन, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों और उदार हिन्दू धर्म का प्रसार।
- सन् १९०८ मालवीयजी की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रान्तीय राजनीतिक कान्फरेन्स का दूसरा अधिवेशन
- सन् १९०८ विवेकानंदीकरण कमीशन के सामने मालवीयजी की गवाही, संघीय व्यवस्था का समर्थन
- सन् १९०९ प्रयाग में मालवीयजी के सम्पादकत्व में 'लीडर' पत्र का प्रकाशन
- दिसम्बर १९०९ पंजाब हिन्दू सभा का प्रस्ताव कि हिन्दू-हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस से पृथक् मुस्लिम लीग जैसी हिन्दू राजनीतिक संस्था स्थापित की जाय।
- “ मालवीयजी की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन, अध्यक्षीय भाषण में पंजाब हिन्दू सभा के विचार का सङ्गठन, तथा साम्प्रदायिक राजनीति और पृथक् निर्वाचन पद्धति की कड़ी समालोचना। मार्तें-मिन्टो सुधार की कड़ी आलोचना।
- सन् १९१०-१९२० भारतीय विधान कौंसिल में मालवीयजी की सदस्यता तथा योगदान
- सन् १९१० कौंसिल में मालवीयजी द्वारा प्रेस विधेयक और राजद्रोह-सभा विधेयक का विरोध
- अक्तूबर सन् १९१० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में मालवीयजी का अध्यक्षीय भाषण
- नवम्बर सन् १९१० मिंटो द्वारा प्रयाग में घोषणा स्तम्भ का शिलान्यास
- जनवरी सन् १९११ केन्द्रीय कौंसिल में राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में मालवीयजी का प्रस्ताव
- ११ अक्तूबर सन् १९११ काशी विश्वविद्यालय की योजना के सम्बन्ध में मालवीयजी और महाराजा दरभंगा की लार्ड हारडिंग से भेंट, लार्ड हारडिंग का प्रोत्साहन

- २८ नवम्बर सन् १९११ हिन्दू यूनिवर्सिटी सोसाइटी का गठन
- ४ दिसम्बर सन् १९११ सोसाइटी की ओर से वाइसराय को डेपुटेशन
- दिसम्बर सन् १९११ पचास वर्ष की आयु होने पर मालवीयजी का वकालत का त्याग, सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में बिताने का दृढ़ संकल्प, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विशेष प्रयत्न करने का निर्णय
- १२ मार्च सन् १९१२ गोखले द्वारा प्रस्तावित प्रारम्भिक शिक्षा विधेयक का मालवीय जी द्वारा समर्थन
- २३ मार्च सन् १९१३ इस्लिगटन कमीशन के समक्ष उनकी गवाही
- फरवरी सन् १९१५ मालवीयजी की अध्यक्षता में प्रयाग सेवा समिति का संगठन
- अक्तूबर सन् १९१५ बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल पारित
- फरवरी सन् १९१६ बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का शिलान्यास
- मार्च सन् १९१६ प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा के विरुद्ध कौंसिल में मालवीय जी का प्रस्ताव
- सन् १९१६-१९१८ इन्डस्ट्रियल कमीशन के सदस्य की हैमियत से उसके काम में मालवीयजी का योगदान, औद्योगिक ह्रास के कारणों पर तगड़ा नोट
- सन् १९१६ हरिद्वार में गंगा की धारा के सम्बन्ध में मेमोरंडम
- अक्तूबर सन् १९१६ असेम्बली के उन्नीस सदस्यों का राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में मेमोरंडम
- दिसम्बर-सन् १९१६ कांग्रेस-लीग सुधार योजना
- सन् १९१७ कांग्रेस लीग योजना के समर्थन में मालवीयजी का प्रचार। विधान कौंसिल में योजना का समर्थन तथा इस्लिगटन कमीशन की संस्तुतियों का विरोध
- २० अगस्त सन् १९१७ भावी राजनीतिक लक्ष्य के सम्बन्ध में भारत मंत्री की घोषणा
- सन् १९१८ सेवा समिति द्वारा स्काउट असोसिएशन का गठन, मालवीय जी चीफ स्काउट
- सन् १९१८ माटेगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मालवीयजी की आलोचना
- २९-३१ अगस्त सन् १९१८ बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, गरम दल और नरम दल में सहयोग बनाये रखने के लिए मालवीयजी का प्रयत्न
- दिसम्बर सन् १९१८ मालवीयजी की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन

- फरवरी सन् १९१९ रौलेट बिल पर कौंसिल में बहस । कौंसिल से मालवीयजी का इस्तीफा ।
- मार्च-अप्रैल सन् १९१९ रौलेट एक्ट के विरुद्ध गांधीजी का आन्दोलन
- अप्रैल-जून सन् १९१९ पंजाब के पांच जिलों में मार्शल ला । सरकारी अफसरों के अत्याचार, मालवीयजी की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस कमेटीयों द्वारा अत्याचारों की निन्दा और निष्पक्ष जाँच की मांग
- १९ अप्रैल सन् १९१९ बंबई में मालवीयजी की अध्यक्षता में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन
- जुलाई-दिसम्बर १९१९ पंजाब में पीड़ित जनता की सहायता
- सितम्बर सन् १९१९ केन्द्रीय कौंसिल में मालवीयजी द्वारा क्षमा विधेयक का विरोध
- नवम्बर सन् १९१९ मालवीयजी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के उप-कुलपति । सितम्बर सन् १९३९ तक इस पद का उत्तरदायित्व वहन करते रहे ।
- सितम्बर सन् १९२० कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन । गांधीजी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ
- दिसम्बर सन् १९२१ कांग्रेस और सरकार के बीच समझौता कराने का मालवीयजी का प्रयास
- २१ दिसम्बर सन् १९२१ मालवीयजी के नेतृत्व में वाइसराय के पास शिष्ट-मंडल
- जनवरी सन् १९२२ मालवीयजी द्वारा आयोजित सर्वदलीय कांग्रेस
- अप्रैल-मई १९२२ मालवीयजी का आसाम और पंजाब में दौरा
- सितम्बर सन् १९२२ मुलतान में साम्प्रदायिक उपद्रव ; मालवीयजी, हुकीम अजमल खाँ और राजेन्द्र प्रसादजी द्वारा स्थिति की जाँच ।
- १६ सितम्बर सन् १९२२ लाहौर में मालवीयजी का हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द पर भाषण
- ३१ दिसम्बर सन् १९२२ मालवीयजी की अध्यक्षता में गया में हिन्दू महासभा का विशेष अधिवेशन
- अगस्त सन् १९२३ मालवीयजी की अध्यक्षता में काशी में हिन्दू महासभा का अधिवेशन । उसके बाद सन् १९२७ तक मालवीयजी द्वारा हिन्दू महासभा का नेतृत्व ।
- सन् १९२४ प्रयाग में संगम पर मालवीयजी का सत्याग्रह

| | |
|-------------------------|--|
| जनवरी सन् १९२४ | असेम्बली में मालवीयजी और जिना द्वारा इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन। उसके बाद स्वराज्य पार्टी से मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी का गठन। |
| फरवरी सन् १९२४ | असेम्बली में राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में मोतीलाल नेहरू का सशोधन, मालवीयजी का तगड़ा भाषण, टेरिटोरियल फोर्स और आकजलरी फोर्स के एकीकरण पर असेम्बली में मालवीयजी का भाषण। |
| मार्च सन् १९२४ | वित्तविधेयक के विरुद्ध मालवीयजी का सुझाव, तथा फौलाद सरक्षण विधेयक पर कौंसिल में बहस, ब्रिटिश कम्पनियों को वाउन्डी देने का मालवीयजी द्वारा विरोध |
| जून सन् १९२४ | असेम्बली में मालवीयजी द्वारा ली कमीशन की संस्तुतियों का विरोध |
| सितम्बर सन् १९२४ | ली कमीशन की संस्तुतियों के विरोध में मालवीयजी और मोतीलालजी के संशोधन असेम्बली में स्वीकार |
| फरवरी सन् १९२५ | सेना के सम्बन्ध में असेम्बली में प्रस्ताव, मालवीयजी का सशोधन स्वीकृत। |
| सितम्बर सन् १९२५ | असेम्बली में मुडीमेन कमेटी की बहुसंख्यक रिपोर्ट की संस्तुतियों की कड़ी आलोचना। मोतीलाल द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय माँग के प्रस्ताव का मालवीयजी द्वारा समर्थन। प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत |
| अगस्त सन् १९२६ | मालवीयजी और लाजपतराय के नेतृत्व में कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन |
| नवम्बर-दिसम्बर सन् १९२६ | कौंसिलो का चुनाव, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी की भारी विजय। |
| जनवरी सन् १९२७ | कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी और रिस्पासबिलिस्ट पार्टी द्वारा मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी संगठित करना। लाला लाजपतराय नेता और मालवीयजी उपनेता। |
| फरवरी सन् १९२७ | कृषि आयोग के सामने मालवीयजी की गवाही। |
| फरवरी सन् १९२७ | अन्त्यजपर्यन्त सब वर्णों के लोगों को मालवीयजी द्वारा मन्त्र दीक्षा। इसके बाद नासिक, काशी, कलकत्ता प्रयाग आदि में मन्त्र दीक्षा देना। |
| सन् १९२७-१९२८ | असेम्बली में सरकार द्वारा प्रस्तुत मुद्रा विधेयक, रिजर्व बैंक विधेयक तथा पब्लिक सेफ्टी बिल का मालवीयजी आदि राष्ट्रवादियों द्वारा विरोध। सेना के भारतीयकरण की माँग। मालवीयजी द्वारा सरकार की सेनानीति की कड़ी अलोचना। |

- नवम्बर सन् १९२७ साइमन कमिशन की नियुक्ति । मालवीयजी आदि नेताओं द्वारा उसके बहिष्कार की घोषणा । इस सम्बन्ध में मालवीयजी के लेख और वक्तव्य ।
- दिसम्बर सन् १९२७ डा० अन्सारी की अध्यक्षता में मद्रास में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन । साम्प्रदायिक समस्याओं पर एक लम्बा प्रस्ताव । मालवीयजी और मौलाना आजाद आदि नेताओं द्वारा उसका समर्थन ।
- फरवरी सन् १९२८ साइमन कमिशन के वाइकाट पर असेम्बली में लाला लाजपत राय का प्रस्ताव । मालवीयजी आदि सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का समर्थन । बहुमत से स्वीकृत ।
- सन् १९२८ सर्वदलीय काफरेन्स—संविधान बनाने में सफल, साम्प्रदायिक समस्या सुलझाने में विफल—मालवीयजी का पूर्ण सहयोग ।
- सन् १९२८-१९२९ पब्लिक सेप्टी बिल का विरोध । मालवीयजी का तगड़ा भाषण । कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट पार्टियों द्वारा समर्थित भारत सरकार के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत ।
- जून सन् १९२९ स्वराज्य के सम्बन्ध में वाइसराय को मालवीयजी का पत्र
- सितम्बर सन् १९२९ सैनिक शिक्षा के सम्बन्ध में जयकर का प्रस्ताव, मालवीयजी का समर्थन
- अक्तूबर सन् १९२९ राउड टेबिल कांफरेन्स तथा भावी राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में वाइसराय की घोषणा
- दिसम्बर सन् १९२९ काशी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में मालवीयजी का दीक्षान्त भाषण, विद्यार्थियों को देशसेवा और राष्ट्रीयता का उपदेश ।
- सन् १९३० कांग्रेस द्वारा पूर्णस्वराज्य की घोषणा, गोलमेज कांफरेन्स का बहिष्कार तथा गांधीजी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह, राष्ट्रीय संघर्ष में मालवीयजी का सहयोग
- मार्च सन् १९३० असेम्बली में मालवीयजी द्वारा टेरिफ बिल का विरोध
- २ अप्रैल सन् १९३० मालवीयजी का असेम्बली से इस्तीफा
- ३१ जुलाई सन् १९३० बम्बई में श्रीमती हन्सा मेहता की अध्यक्षता में सत्याग्रह, मालवीयजी आदि की गिरफ्तारी
- २० अगस्त सन् १९३० दिल्ली में मालवीयजी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी, छः मास की सजा

| | |
|--------------------------|---|
| ५ मार्च सन् १९३१ | गांधी-अविन समझौता |
| ५ अप्रैल सन् १९३१ | कानपुर में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर मालवीयजी का भाषण |
| जुलाई सन् १९३१ | मालवीयजी और डाक्टर अन्सारी की सलाह से साम्प्रदायिक समस्या पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव |
| सितम्बर-दिसम्बर सन् १९३१ | लन्दन में गोलमेज कान्फरेन्स का दूसरा अधिवेशन, राष्ट्रीय माँग पर गांधीजी और मालवीयजी के तर्क भाषण । |
| ४ जनवरी सन् १९३२ | गांधीजी की गिरफ्तारी—दूसरा सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू । |
| २९ जनवरी सन् १९३२ | मालवीयजी का वाइसराय को पत्र |
| २८ फरवरी सन् १९३२ | मालवीयजी द्वारा सरकार के दमन की घटनाओं का उल्लेख करते हुए लन्दन को तार |
| मार्च सन् १९३२ | वाराणसी में मालवीयजी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय स्वदेशी संघ का संगठन |
| २० अप्रैल सन् १९३२ | दमनचक्र पर मालवीयजी द्वारा लन्दन को तार |
| अप्रैल सन् १९३२ | कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन । मनोनीत अध्यक्ष मालवीयजी की गिरफ्तारी |
| ८ अगस्त सन् १९३२ | मेकडोनल्ड द्वारा साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा |
| २०-२६ सितम्बर सन् १९३२ | साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा हरिजनो को पृथक् प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के विरुद्ध गांधीजी का अनशन । हरिजनो से सवर्ण हिन्दुओं का समझौता । समझौते में मालवीयजी का योगदान । |
| २५ सितम्बर सन् १९३२ | मालवीयजी की अध्यक्षता में वम्बई में अन्त्यजोद्धार पर सभा । अस्पृश्यता-निवारण पर प्रस्ताव |
| नवम्बर-दिसम्बर सन् १९३२ | प्रयाग में मालवीयजी द्वारा आयोजित एका कान्फ्रेन्स, सरकार द्वारा श्वेत पत्र का प्रकाशन |
| अप्रैल सन् १९३३ | कलकत्ते में कांग्रेस का अवैध अधिवेशन, मनोनीत अध्यक्ष मालवीयजी की आससोल में गिरफ्तारी |
| मई सन् १९३४ | पटना में कांग्रेस कमेटी द्वारा सत्याग्रह स्थगित, कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड का गठन |
| जून सन् १९३४ | श्वेत पत्र और साम्प्रदायिक निर्णय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय । मालवीयजी का विरोध |
| अगस्त सन् १९३४ | काशी में गांधीजी की सभा में मालवीयजी का हरिजनोद्धार पर भाषण |

- अगस्त सन् १९३४ कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा निर्णय कि वह साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार करती है और न उसे रद्द करती है। मालवीयजी और अणे का विरोध और इस्तीफे
- अगस्त सन् १९३४ कलकत्ते में मालवीयजी के नेतृत्व में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का गठन
- अक्तूबर सन् १९३४ बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन, साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में मालवीयजी का संशोधन नामजूर
- फरवरी सन् १९३५ मालवीयजी द्वारा आयोजित दिल्ली में साम्प्रदायिक निर्णय विरोधी कान्फरेन्स
- जनवरी सन् १९३६ प्रयाग में मालवीयजी के नेतृत्व में सनातन धर्म महासभा का अधिवेशन, अन्त्यजोद्धार पर प्रस्ताव
- सन् १९३६ कांग्रेस के चुनावघोषणा में साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध, मालवीयजी और रफी अहमद किदवयी का समझौता
- सन् १९३७ प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव में मालवीयजी का कांग्रेस को समर्थन—कांग्रेस की भारी जीत
- सन् १९३७ फैजपुर कांग्रेस में मालवीयजी का भाषण
- सन् १९३८ कायाकल्प।
- सितम्बर १९३९ मालवीयजी का त्यागपत्र और उनके प्रस्ताव पर सर राधाकृष्णन् हिन्दू यूनिवर्सिटी के उपकुलपति
- नवम्बर १९३९ मालवीयजी विश्वविद्यालय के आजीवन रेक्टर
- सन् १९४० विश्वशान्ति के लिए महारुद्र याग
- सन् १९४१ गोरक्षा मंडल की स्थापना
- जनवरी सन् १९४२ बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को रजत जयन्ती, गांधी जी का दीक्षान्त भाषण
- सन् १९४२ भारत छोडो आन्दोलन—मालवीयजी द्वारा पीडितों की सहायता, अखिल भारतीय विक्रम परिषद की स्थापना
- १२ नवम्बर सन् १९४६ मालवीयजी का निधन

अनुक्रमणिका

अं

अंगोरा सरकार २८९

अंग्रेज २, ३, ७, १३, ५८, ७२, ७७,
८३, ११९, १२३, १४३, १४६,
२२५, २२६, ३०१, ३५५, ३६६,
३७२, ३९८, ३९९, ४३०, ४३७,
४३८, ४७०, ४९४, ५३४, ५४९,
५६३, ६०७, ६२२,

अंग्रेजी १४३, १४६, ५०३, ५९१,
६२१, ६२२,

अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी सैनिक ३५९,
४१४,

अंग्रेजी राज्य ५४९

अ

अकबर २५, १४५

अकाल ५, ६४, १०८, १०९, ११५,
१२३, १२९,

अकाल कमीशन ५, १०८, १०९,
१२३, १२६, ६०७,

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी २३०,
२३१, २५९, २६१, २६३, २८५,
२८९, २९१, २९२, २९७, ३४६,
३५२, ३७९, ४५०, ४५१, ४६५,
४६६, ५२६, ५५०, ५६४ देखो
कांग्रेस, कांग्रेस वर्किंग कमेटी

अखिल भारतीय सघ ४५८, ४५९,
४६०, ४६२, ४६८, ४७०, ४७१,
४८५, ४८६, ५३९, ५५०,

अग्रवर्ती नीति ७, ४१२, देखो फार्वर्ड

पालिसी

अग्रस्त घोषणा २३३

अछूत, अछूतोद्धार १३९, ३०८, ३१०,
३११, ३२७, ३९८, ५०१, ५१६,
५२० देखो हरिजनोद्धार

अजमल खाँ, हकीम २९५, ३०५, ३४३,
३४७

अजीतसिंह, सरदार ८५, ८९

अणे एम० एस० ३८६, ४१९, ४२८,
४४१, ५०८, ५१३, ५१४, ५१५,
५२७, ५२८, ५३०, ५३३, ५३६,
५४४

अधिमानिक शुल्क ४०१, ४२३, ४२६,

अध्यापक ३५-३६, ६२४

अनुक्रियाशील सहयोग ३८१, ३८२,
अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता ३५०

अन्त्यज ५१७, ५२१, ५२२, ५२३,
५२०, ६३२ देखो गस्पृश्य

अन्त्यजोद्धार ३१०, ३११, ३२०,
३२४, ३२८, ३२९, ३३१, ३३२,
५१६-५२३, देखो हरिजनोद्धार

अन्तर्राष्ट्रीय कानून ४१६, ४१७

अन्तर्राष्ट्रीयता ६३७

अन्तर्राष्ट्रीयनीति ५५९

अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त ६०१

अन्सारी, डाक्टर मुख्त्यार अहमद
१६१, २८३, २८६, ३३४, ३३५,

३४२, ३४३, ३४४, ३४७, ३९५,
४३३, ४३४, ४३५, ४४२, ४४३,
४४४, ४४६, ४६४, ४६६, ५१२,
५२७, ५३०, ५३५, ५३६

अफगान युद्ध ४१२,

अफगानिस्तान ७, २१७, २८५

अब्दुररहीम, सर २०७, २६२

अब्दुल कयूम खाँ, सर ३६६, ४३९,
४५८

अब्दुल गफफार खाँ ४५२

अब्दुलवारी, मौलाना २८४

अब्राह्मण ३०४, ३२०, ३२१

अभ्युदय (पत्र) ५०-५१, ५५, ७७,
५८२

अमीर अली १०३, ४३५

अमृतकौर ४५५

अमृतसर २५७, २५९, २६१, २६५,
२७०, २७३, २७४, २७६, २८९,
५८४

अम्बेदकर, डाक्टर ४५८, ४५९, ५००

अयोध्यानाथ, पंडित एडवोकेट ४१, ४२,
४३, ४६

अरब २१७, २८२, २८९, ५६०

अरबी ४९, १२०, १४४, १४८, २११

अराजकता ७०, ९७, २४९, ३६८,
४३७

अर्धगोरे ४६०, ५२४ देखो एंग्लो इंडियन
और यूरोशियन

अर्विन, लार्ड १७०, ३४३, ४४७,
४४८, ४५४, ४८९, ५५९

अली इमाम, सर ४३५, ४४१, ४४३

अलीगढ़ कालेज ७५

अलीबन्धु २३१, २९३, ३४०, ३४२

अल्पसंख्यक ९३, ९५, १०३, ३०४,

३३५, ३३७, ३४५, ३४९, ३५३,

३५६, ३६३, ४२४, ४४१, ४४२,

४४५, ४५८, ४५९, ४६२, ४६३,

४६५, ४७७, ४७८, ४८२, ४८६,

४८८, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५,

५०६, ५२७, ५२८, ५६०, ५९९,

६०४

अल्पसंख्यक कमेट्री ४५९, ४७६-४७९,

४८३, ४८९

अल्पसंख्यक पैक्ट ४७७, ४७८

अल्पसंख्यक रिपोर्ट २८०, २८१, ३६२,
३६५, ४०३

अवशिष्ट अधिकार ४४४, ४४५, ४६५,
५०२

असरानी, यू० ए० १७०, १७१,
१७४, १७७

असहयोग, अहिंसात्मक ५९, २८२-

३०१, ३०५, ३३०, ३५४, ३५७,

३६५, ४३३, ४४२, ५६५

असेम्बली ५५, ६०, १२७, २९१,

३५४-३७६, ३८७, ३८८, ३९१,

३९३, ३९४-४३१, ४३७-४४०,

४४६, ५००, ५०७, ५११, ५२५,

५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५६६,

५६७, ५८५, ६११, ६१५

अस्पृश्य १३७, १३८, १४०, ३२४,

४५९ ४९८, ५१७, ५२२

अस्पृश्यता १३९, ३१०, ५००, ५१५,

६३३ देखो छूतछात

अस्पृश्यता निवारण ३००, ४५२,

५००, ५०१, ५१५, ५५६

अहिंसा १७५, २८४, ३०७, ३३६,
४५०, ४५१, ४५२, ४६४. ४९०,
४९१, ४९६, ५१८
अहिंसात्मक संघर्ष ४५२, ५६४

आ

आक्रमणशील राष्ट्रीयता ८४, ६००
आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय १५५, १७२,
१७६
आगा खा ७५, ७६, १५१, २३२,
४३५, ४४६, ४७८, ४८८, ५४२
आजाद, अबुल कलाम २१७, २९१,
२९३, २९५, ३३३, ३३४ ३३६,
३४२, ३४३, ३४७, ३५१, ४३५,
४४२, ४४३, ४९४, ५०१, ५०६,
५६०, ५६३
आठ यूनिट ४११, ४१३
आतंक ३६७, ६०२, ६०५
आतंकवाद ८४
आतताई ३०७, ३१९, ३३७, ६०२
आत्मत्याग १६२, २३१, ५९०, ६२४
आत्मनिर्णय २१६, २४५, २७५, २८२,
३०३, ३५७, ३६४, ४३७, ५०६,
५६३
आत्मरक्षा ३०७, ३१७, ३२२, ३६१,
३३७, ५७१, ५७२, ६०२
आत्मोपम्य व्यवहार १३३, १३४,
५२३, ६१६, ६२६, ६२७
आदित्य नारायण सिंह, काशी नरेश १५७
आपसतम्ब ६०६
आयरलैंड ३०१, ३६४
आयात शुल्क १११, १२०, १२१, १८२,
१८३, ३६९, ४०१, ४०२, ४२२,

४२४-४३०, ५८१, ६०७, ६०९,
६११
आयुर्वेद ६२०, ६२३
आर्चीबोल्ड ७५
आर्थिक अधिकार ५६०
आर्थिक आधिपत्य ३९२
आर्थिक उन्नति, विकास ५, १८३, ४७५,
६०९, ६१०
आर्थिक नीति १२३, १८१, ४२९,
४६४, ४६८
आर्थिक सिद्धान्त ६१०
आर्थिक स्वराज्य ३९२
आर्थिक व्यवस्था ६०७-६१४
आर्यसमाज १५, ३१३, ५४९
आर्यसमाजी १३९, ३१३, ३९७
आलकाट ३९
आलम, डाक्टर मुहम्मद ४४५
आमरण अनशन (गांधी) ४६८
आश्रम १३९, ३०९, ६३५
आसफअली ५२९
इ
इंगलिस्तान ३, ८, ७५, ९८, ११३,
२०८, २४०, २४१, २८४, ४६४,
इंगलैंड ९, ५८, ६३, ६४, ६६, ७७,
८२, ११९, २०८, २४३, ४९७,
५०९, ६३७
इंचकेप कमेटी ४०९
इजील ७९
इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी ३७७, ३७९,
३८१, ३८२, ३९४
इंडिपेंडेंट पार्टी ३५४, ३५७, ३७२,
३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३९४,

४००, ४०६, ४०९, ४२८, ४३१
 इंडियन असोसिएशन १८
 इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन ५०,
 १२१-१२४, ५९०
 इंडियन कौंसिल एक्ट २३, ६६, ६७,
 ९२, २०३
 इंडियन टेरिटोरियल फोर्स ३५५, ४११
 इंडियन पुलिस सर्विस २०७, २१०
 इंडियन नेशनल काफरेंस (कलकत्ता) १८
 इंडियन नेशनल यूनियन ३४३
 इंडियन यूनियन १९
 इंडियन सिविल सर्विस २, ३, ४, १८, २०,
 २३, ८९, १२०, २०७, २०९,
 ६१०, २२१, २२३, २४४, २४६
 इंडिया कौंसिल २, २०, २०५, २२१,
 २२३, २४३, २४६
 इंडेमिनिटी बिल २०१, २१५ २६३-
 २७४
 इकबाल, डाक्टर मुहम्मद ४३५, ५०२
 इटली ७०, २१६, ५५९
 इतिहास की भौतिक व्याख्या ६१२
 इन्सानियत ३०६
 इब्नाहिम रहमतुल्ला १२०
 इलहावाद हाईकोर्ट ४३-४५, ४९, ३०१
 इस्लाम २८३, २८४, ३१२, ५०३
 इस्लिगटन कमीशन ४९, ११९, १८०,
 २०६, २१०, २११
 ई
 ईश्वर १०, १४, ६४, १३३, १३४,
 १३८, २४८, ३०६, ३०७, ३१०,
 ३१२, ३१७, ३२४ ३४१, ४२६,
 ४६७, ६०१, ६११, ६२५, ६२६,

६२८, ६३४, ६३५, ६३६
 ईश्वर भक्त ६३४
 ईश्वर भक्ति १५६, ५७७, ६२३
 ईश्वर शरण, मुणी १५८, २९४,
 ३७८, ३९६, ४२८, ४३०, ४३१,
 ४३९, ४४०, ५९०, ५९३, ५९७
 ईश्वर सेवा ८०, ६३६
 ईश्वरीय शक्ति ६२८
 ईश्वरार्पण सत्कर्म ६१६
 ईश्वरार्पित निष्काम लोकसेवा ६३७
 ईसाई ७९, १००, १०१, १४५,
 १५६, २०३, २३८, ३०६, ३१२,
 ३१८, ३३७, ३४१, ३९६, ५०५,
 ५२४, ५४८, ५७२, ५९९, ६३४
 ईसाई धर्म १७
 ईस्ट इंडिया कम्पनी १, ५, १२३

उ

उत्तरदायी शासन २३३-२३६, २३८,
 २४०, २४७, २७५, २७६, ३०३,
 ३०४, ३२३, ३५६, ३५७, ३६३,
 ३७७, ३८२, ४१३, ४२४, ४४०,
 ४४१, ४४६, ४५८, ४६१, ४६८,
 ४७०, ४७९, ४८६, ५२६, ५३४,
 ५३९, ६०३.
 उत्तर प्रदेश-देखो युक्त प्रान्त
 उत्पादन शुल्ल ६, १२०, १२१, १६२,
 १८३, ३६६, ३७३
 उदार दल ४३२
 उदार राष्ट्रीयता ६३७
 उदार लोकतान्त्रिक संवैधानिकता ५७
 उदारवाद १४, ६०६, ६३७

उदारवादी समाजवाद ६०६

उद्योग-प्रधान ६०८

उद्योगीकरण १८३, ३९२, ६०८, ६१२

उपाध्याय, बलदेव १४७, ५९१,

उपाध्याय, यदुनन्दन ३१६

उपाध्याय, यज्ञनारायण ३१५, ५५५,
५६९

उमैद सिंह, महाराजा जोधपुर १५७

उर्दू ४६, ४७, १४३, १४८, ३३४,
५०३, ५९१, ६२२

ऋ

ऋग्वेद ३०८

ऋषि १५, ३०८, ३१२, ३१३

ए

एंगलो-इंडियन ७, १७, १९६, ३६३,

४५८, ५०५ दे० अर्धगोरे, यूरोशियन

एडरुज, सी० एफ० १९३, २५९,
२६०, २६१, ३४७

एकता काफरेन्स, सम्मेलन ३३२,
३३८-३३९, ३४६, ३४७, ३४८,

५०१-५०६, ५०७, ५०८, ५३४

एडवर्ड, युवराज १६५

एलगिन, लार्ड ६९

एल्फिंस्टन १२६, ६१५

ऐयंगर, ए० आर० ४७३, ४७४, ४८७

ऐयंगर, कस्तूरी रंगा २८६, २९४

ऐयंगर, श्री निवास ३४५, ३४७, ३५१,
३५२, ३८८, ३९४, ३९५, ४०५,
४१२, ४१३, ४१९, ४३७

ओ

ओकोनूर १०८, १२६, १४६

ओडायर, सर माइकल ६०, १४६,
२०१, २२०, २२९, २५६, २५७,
२५९, २७५, २७९, २८०

ओपन हाइमर ४१७

ओलीवियर, भारत मन्त्री ३५९, ३६५

औ

औद्योगिक ८९, ३८७, ४२५, ४२६,
४२८, ४७५, ५२४, ५८१, ६०९;

६१३ देखो भारतीय औद्योगिक

औद्योगिक आयोग ५०, १२१-१२४,
५९०

औद्योगिक आधिपत्य ३७०, ६१३

औद्योगिक उन्नति, विकास १४, ११०,
१२०, १२१, १२९, २३९, ४७४,

४९४, ५८१, ६०८, ६१०, ६१३,
६३७

औद्योगिक नीति १२२, १२३, १८३,
६०७

औद्योगिक बैंक १२२

औद्योगिक शिक्षा ११०, ११२, १२१,
१२२, १२३, ४०९, ६२०

औद्योगिक श्रमिक ४१७, ४१९

देखो मजदूर

औद्योगिक ह्रास १२३

औद्योगीकरण १८३, ३९२

औपनिवेशिक प्रश्न ६०१

औपनिवेशिक सेना ४०३, ४१३

औपनिवेशिक स्वराज्य ३०१, ४१०,
४२१, ४४३, ४४७, ४६६, ४८७

क

कंजरवेटिव पार्टी (ब्रिटेन) ७०, ४५४,
४५८, ४६१, ५२५

कनाडा २१८, २२८, २२९, ४१६
 कपिल, महर्षि १६०
 कम्यूनिज्म ४१६, ४१७, ४१८, ४८१,
 ५८१, ६१०, ६१२
 कम्यूनिस्ट ३९२, ४१५, ४१७, ४१८,
 ४१९, ६१०, ६११, ६१२
 करनीति १८२, ३५९
 करवन्दी ४३३, ४५०
 करारोपण ६३, ७३, ४०९
 कर्जन, लार्ड ६२, ६९, ७३, १४९,
 १९६, २४३
 कर्मकांड १५, ६२८
 कर्मयोग ६२६, ६२८
 कर्टिस २३२, २३५
 कलकत्ता कारपोरेशन ६९, ३३६, ३४०,
 ३४१
 कल्याण राज्य ५, ३९३
 कस्तूरबा गांधी ४९६
 कांग्रेस के अधिवेशन १९, २०, ३८,
 ४२, ४३, ६३-६८, ७१-७२,
 ७३-७५, ८५-८६, ९४-१०४,
 २०२, २२०, २२२-२२४, २३४-
 २३५, २४१-२४४, २४५-२४८,
 २७४-२७६, २८५-२८८, २९५-
 २९७, ३३३-३३४, ३३५-३३६,
 ३४८-३५३, ३७७, ३८६, ४३४-
 ४३५, ४५०, ४६३-४६४, ४९६-
 ४९७, ५०८-५११, ५३५-५३६,
 ५४५, ५४९, ५६०-५६१
 कांग्रेस जांच कमेटी (पंजाब) २७८,
 २७९
 कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी ५३३, ५३४,

५३५, ५३६, ५३७, ५३९, ५४१,
 ५४२, ५४३, ५४४, ५४७
 कांग्रेस पार्टी ३७६, ३८०, ३८१, ३८५,
 ३८७, ३८८, ३९०, ३९४, ३९५,
 ३९८, ४०२, ४०६, ४०९, ४१५,
 ४१९, ४२४, ४३०, ४३१, ५३७,
 ५३९, ५४६, ५४७, ५५६
 कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड ५२७, ५२८,
 ५२९, ५३०, ५३३
 कांग्रेस-लीग योजना, समझौता २०६,
 २२०-२२४, २२९, २३६, २३९,
 २४३, ५०५, ५२५, ५२९
 कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ५५६-५६०
 कांग्रेस वर्किंग कमेटी १६७, २८९,
 २९०, २९९, ३०५, ३४०, ३९४,
 ३९५, ३९८, ४०२, ४०६, ४१५,
 ४१९, ४२४, ४३०, ४३१, ४३८,
 ४४८, ४५३, ४५५, ४५६, ४५७,
 ४६३, ४६४, ४६६, ४९०, ४९७,
 ५०८, ५२७, ५२८, ५३०, ५३२,
 ५३३, ५३९, ५५६, ५५९, देखो
 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,
 कांग्रेस अधिवेशन
 काट १६०
 काबुल २१७, २८५, ३८६
 कामन्स सभा ६७, ६८, २०८, २८१,
 ४१५, ५२४
 कामेश्वर प्रसाद सिंह, महाराजा दरभंगा
 १५७
 कायाकल्प १७५, ५५०
 कार, हुवर्ट ४६१
 कारनवेल, सैनिक कालेज ४११, ४१३

कालिदास १७७, ५५६, ५९१
 काशी हिन्दू विश्वविद्यालय २९०,
 ५५०, ५५१, ५५२, ५५५, ५८१,
 ५८९, ६१५, ६२३ देखो बनारस
 हिन्दू यूनिवर्सिटी
 किंग कमीशन ४, १२२, ४११
 किचलू, डाक्टर शैफ उद्दीन २५७,
 २७९, २८६, २९०
 किदवर्दी, मुशीर हुसैन ४२८, ४९३
 किदवर्दी, रफी अहमद ५४७, ५७६
 किसान ३, ५, ६, ७, ९, ११, १३,
 ६२, ८८, ८९, १०७, १०८,
 ११०, १२५-१२९, १८४, २४७,
 २४८, ३९१, ३९९, ४४३, ४५७,
 ४६६ ४६७, ४९३, ४९४, ५४५,
 ५५६, ५५७, ५८१, ५८२, ६०८,
 ६१४ देखो कृषक
 कुजूरू, हृदय नाथ ५३, ५४, ५५-५६
 १५८, १५९, २८६, २९४, २९५,
 २९९, ३७८, ३९६, ३९७, ४११,
 ४२८, ४३१, ४९३, ५००, ५५१,
 ५६६, ५६७, ५७५, ५९०, ५९७
 कुटीर उद्योग १४, १२१ १२२, ६०८
 कुन्नन देवी, मालवीय जी की धर्मपत्नी
 ३४, ३५, ५३५, ५५४, ५८३
 कुरेशी, सुएव ४४१
 कृपालानी, जे० बी० ४९३
 कृषक ७, १०९, ११०, देखो किसान
 कृषि १२३, ६०८ देखो खेती
 कृषि आयोग १२५-१२९, ३९१
 कृषि कालेज १२५, ६२०
 कृषि नीति ६०७

कृषि प्रधान ५, ६०७, ६०८
 कृषि विज्ञान १२५, ६२०, ६२३
 कृषि व्यवस्था ६, ३९२
 कृषि शिक्षा १०९, ११०, ११२
 १२३, ६१०, ६२०
 कृष्ण २६, २९, ३४, ३२१, ५२२,
 ५८४
 कृष्ण कान्त मालवीय ५०-५१, ५५४
 कृष्णराज वादियर, महाराज मैसूर
 १५७
 कृष्णराम मेहता १५३
 कृष्ण स्वामी १४५
 केनरा ४५७
 केनिंग, लार्ड १, ५२
 केन्द्रीय उत्तरदायित्व ४५८, ४६२,
 ४७०, ४७२, ४७९, ४८०, ४८२,
 ४८३, ४८६, ५०२
 केन्द्रीय विधान मंडल ४३२, ४३४,
 ४३६, ४३७, ४६२
 केन्द्रीय शासन व्यवस्था ३७३
 केन्द्रीय सरकार ४७०, ५३९
 केगर, गृह सदस्य ४१५, ४३७
 केलकर एन० सी ९६, १०४, २८६,
 ३७७, ३८६, ४२३, ४२८, ४३०,
 ५८५, ५९६
 कोक ३६५, ४०७
 कोमागाटामारू २२६
 कोर्ट मार्शल २७३
 कौंसिल ३, ६४, ६६, ६७, ७६, ८९,
 ९०, ९१, ९२, ९३, ९६, १०३,
 १०६, ११४, २३०, २८७, २८८,
 ३५४, ३८३, ३९०, ४२३, ५२६,
 ५२७

कोंसिलों का वहिष्कार २८६, २८८,
२९१-२९२

कौशिल्या १४२, १४३

क्रमिक आयकर १८२

क्रान्ति ५६८

क्रान्तिकारी १०४, १०५, २१७,

२१८, २२७, २२९, २४९, २५१-

२५२, २५३, ३६४, ३६८, ५४४,

५८७

क्रिमिनलला अमेंडमेंट अध्यादेश ३३९,

३६८

क्रिप्स, सर स्ट्रेफर्ड ५६२, ५६३

क्लार्क, विलियम १२१

क्ष

क्षत्रीय ५१६, ५१७, ५१९, ५२०,

५२३, ६३१

क्षमा अधिनियम २६३-२७०, ६०५

ख

खलीकुज्जमा, चौधरी ५०७, ५११, ५१२,

५२९, ५३०, ५५७

खलीफा २८२, २८३

खादी, खहर २८८, २९१, ३००, ४५२,

५०९, ५९५

खापडें, जी. एस. २१२, २१५, २५०,

२५५

खिलाफत २१६, २७५, २८२, २८७,

२९४, २९७, ३६७

खिलाफत काफरेन्स, कमेटी २८२, २८३,

२८५, २८८, २९०, ३३४, ३३५,

३४२, ३४४, ४४४

खुदाई खिदमतगार ४५२

खेतिहर ६, १२९, ४४३

खेती ५, ९०, १०९, १२२, १२५,

१२८, १२९, ६१०, ६२०

ग

गंगाप्रसाद वर्मा ६२

गंगानहर ५६, ५७०

गंगासिंह, महाराजा वीकानेर १५३,

१५७, १७२, १७७, १७८, ४५८,

५५४

गंगा स्नान, जल ३१३, ५१६, ५७१

गजनवी, ए. के १५५, ४८३

गदर आन्दोलन २५३

गरमदल ५७, ५८, ७१, ७३, ७७,

८५, ८६, ८७, ८०२, २२६, २४०

गजाधर प्रसाद, पंडित ३३, ३४

गजाधर प्रसाद, हरिजन १४०

गजेन्द्र मोक्ष १९६, ५८४

गणेशदत्त गोस्वामी १३९, ५६८

गणेश शंकर विद्यार्थी ३८८

गांधी, महात्मा-असहयोग और खिलाफत

२८४-२८९; काशी विश्वविद्यालय

१५७, १६१, १६४, १७०, १७३,

१७४, १७५; गोलमेज काफरेन्स

४४९, ४६४, ४६६, ४६७-४७०,

४७३-४७७, ४८३-४८४; नमक

सत्याग्रह ४५०-४५२, ४५३, ४५४,

४६३, भारत छोड़ो आन्दोलन ५६३-

५६४; भारतीय अप्रवासी ९१,

१९५; मालवीय २९२, ४६६, ४६७;

५१३, ५७३, ५७४, ५८२, ५९६,

५९७; राजनीतिक सुधार (१९१९)-

२७६; रीलेट विस का विरोध और
पंजाब काड २५०, २५६, २५७,
२५९, २७०, २७१, २७७, २७८,
२७९; व्यक्तिगत सत्याग्रह ५१४,
५२६, ५६२, सन्निध अवज्ञा आन्दो-
लन ४८९-४९२, साम्प्रदायिक
समस्या ३१२, ३३६, ३३७, ३३८-
३३९, ३४०, ३४८, ३५१, ४७६-
४७८, हरिजनोद्धार ४९८-५०१,
५१३-५१४, ५१५-५१६
गांधी-अविन समझौता १७०, ४५७,
४६३-४६४
गाय १२९, १३७, ३२०, ३४४, ५६९
गिडने, कर्नल ४५८, ४६०, ४७७,
४८३
गिरजा ३०६, ३१८, ३३७, ६३४
गिरधर (पौत्र) ५५५
गिरधारीला, चौधरी १६४
गिरि, बी बी ४८०
गुजराती १४५, १४६
गुप्ता, मनमोहन १०५
गुप्त, हरेभाव २१७
गुरदित्तसिंह २२८, २२९
गुरु ६२४, ६३०
गुरु गोविन्दसिंह ४१४
गुरु ग्रन्थ साहब ३०९, ३६८
गुरुद्वारा ३०६, ६३४
गुरुद्वारा बिल ३६८
गुट्टे, इकवाल नारायण १५३, १५८,
१७२, १७७, १७८, ४५८, ५५४
गृहस्थाश्रम ६३३
गैरोला, के. एन. १७४, १७६
४२

गोकरणाथ मिश्र १५२
गो कुशी, गो हत्या, गो वध २७५,
३३५, ३३६, ३३९, ३४४, ३४८,
३५१, ३५२, ३५६, ३८६
गोखले, गोपाल कृष्ण १० ४५, ५२,
५५, ७०, ७१, ९४, १०४, ११५,
१८०, १८१, १८६, १८७, १८८,
१८९, १९१, १९३, १९६, १९८,
१९९, २००, २०३, २०७, २१५,
२३२, ४९८, ५८६, ६१६
गोपाल सिंह कौमी ५३६
गो रक्षा १३७, १३८, ३०४, ३१९,
३२०, ५५१, ५५५, ५७२
गोरी पलटन, सेना ४, १२४, ४१२,
४७१, ४७२
गोलमेज काफरेन्स ६१, २९३-२९६,
३०५, ३३१, ३३२, ३४४, ३५६,
३६३, ४२३, ४२५, ४३०, ४४८,
४५८-४६२, ४६३, ४६४, ४६६,
४६७-४८८, ४९५, ४९८, ५३४,
५३६
गोविन्द मालवीय ३५, ४९६, ५५०,
५५५, ५६९, ५७३, ५८३
गो सेवा १३७, ३२०, ५७८, ५८७
गोस्वामी, टी सी. ३४७, ४३७
ग्रामगीत ५९१-५९२
ग्याग्रह सूत्र ४५० ४५१
ग्रीन, टी एच ३८९, ३९३
ग्लेडस्टन ३८९, ३९३
घ
घरेलू उद्योग घघे ११०
घोष, अरविन्द ८६

घोष, रासबिहारी ५७, ८५, ८६,
१५२, २००

घोष, शिशिर कुमार १७

च

चक्रवस्त, ब्रजनारायण १४५

चक्रवर्ती, श्यामसुन्दर २९५

चक्रवर्ती, ज्ञानेन्द्र नाथ १५८

चटर्जी, योगेश चन्द्र १०५

चन्दावरकर, नारायण गणेश २६३,
२६९

चरित्र गठन ६१६, ६१७

चर्चिल, प्रधान मन्त्री ५६२, ५६३

चातुर्वर्ण व्यवस्था १४, ६३३,

चितनत्रीस, गंगाधर १५५, १८९,
३७८

चिन्तामणि, सी, बाई. ६, ५१-५२,
६२, ११५, ३७८, ५३७, ५३८,
५९७

चुनाव सघर्ष ३७७-३९३

चेट्टी, धम्ममुखम ४०६, ४०७, ४२८

चेम्बर लेन, आस्टिन २३३

चेम्बर लेन, न्यायाधीश २६७

चेम्सफोर्ड, लार्ड २०१, २१४, २२१,
२३१, २३२, २३५, २३६, २३८,
२३९, २६२, २७५, २८७, २९४

चोइथराम ३५१

चौकीदारी टैक्स ४५३, ४५७

चौदह सूत्री कार्यक्रम ४४६

चौरी चौरा २९९, ३०१

च्यवनश्रम ५५६, ५६९

छ

छूतछात ३१०, ५०९, ५१५, ५२२,
६३२ देखो अस्पृश्यता

.ज

जगजीवन राम १६४

जगत नारायण लाल ३५१

जगन्नाथ प्रसाद वाजपेयी १७०

जनकल्याण ६०२, ६०६, ६०७, ६०९,
६११, ६१७

जनकल्याण राज्य ६०६

जनजागृति ७१, ७४, ७७, ११६,
२४८, ६०२

जनसंघटन ७१, ६०२

जनान्दोलन ७१, ७४, ७८, ११६,
३२६, ६०२

जमनादास द्वारकादास २९४, २९५

जमनालाल बजाज ४९६

जमाल मुहम्मद ४८१

जमीदार ६, ८, ९, १०, २१, २२,
२३, २५, ४९, ७६, ८६, ९४,
१२६, १२७, २०३, २०४, २१२,
३८७, ३९१, ४४३, ५२४, ५२७,
५५७, ५८१, ५८२

जमीदारी-उन्मूलन ६१४

जमैयतुल उलेमा ३३३, ३४४

जयकर, एम० आर० २७८, २७९,
२८६, ३७७, ३७९, ३८१, ३८६,
३८८, ३९४, ३९७, ३९८, ४०२,
४१४, ४२८, ४३०, ४३७, ४४०,
४४१, ४४५, ४४६, ४५०, ४५४,
४७४, ४८, ४८१, ५००

जयप्रकाश नारायण १७७, ५१२,
५६८,

जयरामदास दीलतराम ३४७, ४५५

जर्मनी २१६, २१७, २२१, २५२,
५५९

जलियावाला बाग २५७, २६१, २६४,

२६५, २७३, २७९, ४३६,

जहाँगीर, कावसी ४२८, ४८०

जाति ४, ११, २१, २२, १२०, १३७,

३२०, ३२३, ३३४, ५०४, ५४८,

५९९, ६०३, ६३२, ६३५

जातिगत शासन ५९९

जातिपाति २४, ३१७, ४१४, ४३३,

५७२, ६३४

जातिवाद ५९९

जाधव ४६१, ४८०

जापान ७०, ८२, १०९, ११०, १२५,

२१६, ४०२, ४१४, ४२२, ४२३,

५६२, ५६३, ५६४, ६२०

जायसी १४५

जिना, मुहम्मद अली-असेग्वली ३५४,

३५७, ३६२, ३६४, ३७२, ३७३,

३७४, ३७५, ३७६, ३७८, ३९४,

३९८, ४००, ४०२, ४०६, ४०९,

४११, ४१३, ४१४, ४२१, ४२५,

४२८, ४३१, ४३७, ४४०, ८४६,

कौंसिल (विधान) १८०, १९०,

२१२, २१५, २५०, २५५, गोलमेज

काफरेन्स ४४९, ४५८, ४७७,

मुस्लिमलीग २२०, ४३५, ४३६,

साइमन कमीशन ४३२, ४३५,

४३६, ४३७, साम्प्रदायिक प्रश्न

२२०, २२३, २२४, ३४६, ४४४,

४४५, ४४६, ४७७, ५२५, ५२९,

५३८, ५३९, ५४०-५४२, ५५८,

५६१

जिला बोर्ड ७६, ९३, ९५, ९६, ११२,

१८७, १८९

जुलफिकार अली खाँ, सर ४३७

जेम्स, विलियम ११२, ६१९

जैन ३०८, ३४१

जोशी, एन० एम० ३५७, ३६६, ३७०,

३७२, ३९२, ३९८, ४०६, ४८०,

४८१, ६११

ज्वाला प्रसाद, राजा १५८, १७१,

ज्ञ

ज्ञान ६१८, ६१९, ६२१, ६२८, ६३७

ज्ञानयोग ६२६

ज्ञानानन्द, स्वामी ३९

ट

टडन, पुरुषोत्तम दास ४१, ४९, ५०,

१०५, ३३४, ५७३, ५७९, ५८४,

५९७

टेरिफ बोर्ड ४०१, ४२३

टैगोर, रवीन्द्रनाथ २६, ५३८

ठ

ठक्कर, अमृतलाल ५००, ५०१

ड

डफरिन, लार्ड १९, २१

डाडी यात्रा ४५१-४५२

डायर, जनरल ६०, २०१, २५७,

२७५, २७९, २८१

डायसी, विधि विशेषज्ञ २६८, २७२,

२७३

डिवटे, काउन्ट १११, ६०९

डी ए वी कालेज १३९, ५४९

डोमिनियन २१३, २२३, २४७, ४५९,

४६०

डोमिनियन संविधान ४४८, ४४९

डोमिनियन स्टेट्स ३५६, ४२३, ४२४,

४४३, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९,

४५८, ४७३, ४८६, ४८८, ५२६,

५५९, ५६२

ड्यूक, विलियम २३२, २३५, २३६

त

तप ८०, १३२, १३४-१३५, ५७७,

६२९, ६३१, ६३५, ६३६

तबलीग ३१२, ३३३, ३३७, ३३८,

३३९

तर्कभूषण, प्रमथनाथ १७१, ५५१,

५५२, ५९१

तारसिंह, मास्टर ४४१

तिलक जयन्ती ४५५

तिलक, लोकमान्य ५७, ७३, ८५, ८७,

१०४, २१८, २१९, २२२, २२३,

२२९, २३०, २४४, २४७, २७६,

३०८

तिवारी, बंकटेश नारायण ५४, २६०,

२६१

तुर्की २१६, २१७, २७५, २८२, २८३,

२८९, २९६, ३६७

तुलसी ५९१

तैयबजी, अब्बास २७८, २७९, ३३४

तैयबजी, बद्रुद्दीन १८

तैलग, काशीनाथ त्रिम्बक १८

त्रिपाठी, रामनरेश ५५३, ५८२, ५८३,

५८८, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४

द

दक्षिण अफ्रीका ९९, १०४, १९४,

२१८

दक्षिण पूर्वी एशिया ५६३

दत्त, अखिल चन्द्रदत्त ५३६, ५४४

दत्त, एस. के ३६६, ३७२, ४७९,

५२४

दमन ६२, ६३, ७२, ७३, ८४, ८५,

१०५, २२७-२३२, २५७-२५९,

२९०, २९१, ३६६-३६९, ४५३-

४५४, ४९१, ४९२, ४९५-४९७,

५०९, ५१०, ५११, ५६४-५६६.

६०१

दमनकारी कानून १९५-२०१, २२०,

२९४

दलित वर्ग १८६, ३१०, ३२८, ३९७,

३९८, ४९९, ५२४ देखो अस्पृश्य

दयानन्द, सरस्वती १४, १५, ५४९

दवे, कन्हैयालाल १५८, १५९

दवे, बलदेव राम ५०, १५८, १५९,

५५४

दादाभाई, मानकजी १५५, १८५, १८६,

१८९

दास, चित्तरंजन (देशबन्धु) २५९,

२७५ १७६, २७७, २७८, २७९,

२८६, २८८, २९०, २९१, २९३,

२९५, २९६, ३३५, ३३६, ३४१,

३६५, ४७३

दीनदयालु शर्मा ३८, ३११

दीवानचन्द, लाला ३४६, ३४७, ५४६,

५९७

दीवान चम्पनलाल ३८५, ३८७, ४१४,

४१९, ४२१, ४२८, ४२९, ४३१

देवदर्शन ३१०, ३२४, ५१६, ५१७,

५४९, ६३२ ।

देवनागरी ४६-४७, १७३, ३३४
 देशज उद्योग ४७४, ४७५, ५८१,
 ६१०, ६१३
 देश प्रेम १४९, १५६, १६१, ३३७,
 ५७८, ५९९, ६००, ६१७, ६३६
 देशबन्धुता १३, २४, ५९९
 देशभक्त ८०, १००, १०१, १३५,
 ५४४, ५७८, ५९९, ६००, ६१७
 ६२४, ६३५, ६३६
 देशभक्ति २४, ७७, ८०, ८१, ८३,
 ८४, १००, १०१, १०२, १०५,
 १३५, १६२, १६६, १६८, १७५,
 ३०१, ४१४, ४१५, ४१७, ४४१,
 ४४५, ५७७, ५८०, ५८८, ५९६,
 ६००, ६१५, ६१६, ६२३, ६२४,
 ६३६
 देश सेवा ६९, १३५, १४९, ४९४,
 ५४५, ५७७, ५७८, ६००
 देसाई, मूला भाई ५२७, ५३८, ५४४
 द्विज ६३१, ६३३
 द्विजत्व ५१७, ५२२, ५३३, ६३०,
 ६३३
 द्विविध शासन २३५, ३५८, ३५९,
 ३६३, ३६६, ३७४

ध

धरसन्ना ४५२, ४५३
 धर्म १०, १६, ७९, ८०, ८३, ९१,
 १०१, १०२, ११५, १३१, १३२,
 १४२, १४३, १५५, १६०, १६१,
 १६८, ३०७, ३०८, ३०९, ३१२,
 ३२०, ३३३, ३३५, ३३७, ३३८,

३४७, ३५०, ४१८, ४२०, ४६२,
 ५०२, ५०३, ५०४, ५२०, ५४५,
 ५४८, ५४९, ५५३, ५६०, ५७१,
 ५७७, ५७८, ६०४, ६१०, ६१६,
 ६२०, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९,
 ६३०, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७,
 ६३९, ६४० देखो सनातन धर्म,
 हिन्दू धर्म ।

धर्म गुरु १०४, ६३४

धर्म ग्रन्थ ५१६, ५६९, ६०४, ६१६,
 ६३४

धर्मज्ञान ५२३

धर्म निष्पक्ष राज्य ६०४

धर्मनिष्ठ ५७७, ६२६

धर्म परिवर्तन ३३९, ३४७, ३४८,
 ५७१

धर्म समन्वय ६३४

धर्मस्थान ३१६

धर्माधृत मानवता ६२६-६३७

धर्माधृत सामाजिक मनुष्यता ६३७

धार्मिक अधिकार ३२४, ३३९, ५६०

धार्मिक धारणा, विचार ६३५, ६३९,
 ६४०

धार्मिक भावना ९०, ३३५

धार्मिक महापुरुष ४२०

धार्मिक शिक्षा १५६, १६०, १६१,
 ५२०, ६३३

धार्मिक सहिष्णुता ६३४

धार्मिक सिद्धान्त ५९१

धार्मिक स्वतन्त्रता ३३९, ३४३, ३५०,
 ३५९, ४२०, ५०२-५०३, ५७१,
 ६०४

ध्रुव आनन्द शंकर बापु भाई १५८, १६७

न

ननकाना साहब ३०४

नन्दा, वी० आर ६०, ३८६

नन्दी, मनीन्द्र चन्द्र १५५, २१५

नमक सत्याग्रह ३३१, ४५०-४५८

नयी स्वराज्य पार्टी ४२१, ४२८, ४२९,

नरमदल ४९, ७०, ८६, ८७, १०४,

२१२, २२६, २३५, २४०, २४५,

२४६, २५२, ४२८,

नरेन्द्र देव, आचार्य १०५, १७७, ५१२,

५७५

नरेन नाथ, राजा ३३१, ४५०, ४७९,

५२४

नशाबन्दी ४५२, ४५३, ५५६

नागरिक अधिकार ३२३, ४५१

नागरिकता १६८, ४३३, ६००, ६१४,

६१६, ६२४, ६३७

नागरिक सेना ३०७, ३५५, ४७१,

४७२

नागरिक स्वतन्त्रता ३५९, ३६७, ५०३,

६०४

नागरी लिपि ४६, ४७, १४४, १७३,

६२२ दे० देवनागरी

नाजीवाद ५५९

नाभा महाराजा ३६७, ३६८

नामजदगी ६४

नायडू सरोजनी २९०, २९६, ३४३,

३५०, ३७८, ४६६, ४८७, ४९४,

४९५, ४९६, ५०५

नायर, शंकरन १९२, २३३, २६३,
२७५, २९७

नारद मुनि १८५, ५१८, ६०६, ६३१,
नार्टन, अर्हले ४२, २५९

नार्थब्रुक, चार्ड ३

नियोगी के० सी ५६६, ५६७

निरंकुशता ६९, १०५, १९५, २३४,
६०१

निरंकुश शासक ६९, ५१०

निरंकुश शासन ४६०

निवासीय शिक्षण संस्थान १५१, १५२

निर्वाचन पद्धति ९५, १०२

निर्यात शुल्क, नीति ४०८, ६०७

निष्काम कर्म १३३, ६१६

निष्काम भाव १३३, १३४, ५७७,

५७९, ५८०, ६२९, ६३५

नि श्रेयस १३४, ६२६, ६२८

नि स्पृही लोक सेवा ६१६

निःस्पृही देशभक्त ६१७

नि स्पृही समाजसेवी ५७९

नि स्वार्थी सेवा ३१, ६३८

नीतिशास्त्र ६२३, ६२६

नीलकंठ दास ४२१, ४२८

नृपतन्त्र २४, १३६

नेशनल कन्वेंशन ८६

नेशनल पेक्ट ३३३, ३३४, ३३५, ३३६

नेशनलिस्ट पार्टी ३५४, ३५७, ३६१

३८७, ३८८, ३९२, ३९३, ३९४,

३९५, ४०६, ४०९, ४१५, ४१९,

४२०, ४२१, ४२८, ४३०, ४३१,

४३८, ४३९

नेशनलिस्ट मुसलमान ४४६, ५२९,

५३०, ५३१, ५३२, ५३६, ५४२

नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी ५३०, ५३१,
५३४

नेशनल मुहामेडन असोसिएशन १८

नेहरू, कमला ४५५

नेहरू कमेटी रिपोर्ट ३२५, ३२९, ४४१,
४४२, ४४३, ४४५, ४४६, ५०३,
५३४

नेहरू, जवाहरलाल ६०, १६१, २९१
३४२, ३८७-३९३, ३९५, ४३८,
४४१, ४५०, ४५२, ४५४, ४६३,
४६४, ५३०, ५३१, ५३२, ५४६,
५५७, ५५८, ५६३ ५७३, ५७४,
५८२, ५८७

नेहरू मोतीलाल २६, ४४ ५१, ५२,
५६-६१, ८५, २२३, २२७, २५९,
२६०, २६१, २६२, २७४, २७५,
२७७, २७८, २७९, २८५, २८६,
२९१, ३३५, ३३६, ३३८, ३४२,
३४३, ३५६, ३६०, ३६२, ३६३,
३७१, ३७३, ३७४, ३७५, ३७७,
३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८४,
३८५, ३८६, ३८८, ३९४, ४०१,
४०६, ४०८, ४१०, ४१९, ४३०,
४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१,
४४६, ४४८, ४४९, ४५२, ४५४,
४५५,

नेहरू, स्वरूप रानी ५०८

नेटाल १९३

नैतिक अधिकार ६०४, ६१४

नैतिक आदर्श ५९१

नैतिकता १०, १६१, ६१६, ६२८,
६२९

नैतिक नियम ६३०

नौआखाली ५७०, ५७२, ५७४

नौकरशाही १९२, २०४, २२७, २३४,
२३८, ४२७, ४५९

नौरोजी, दादा भाई १२, १३, ३८,
६३, ७३, ७४, ७७, ८४, ९४,
२२६

न्याय ४, ६६, ७०, २३८, २४५,
२५१, २६४, २६७, ३२८, ३८३,
३८४, ४१८ ४२२, ४३६, ४४३,
५५३, ५८०, ५८८, ६०१, ६०२,
६०५, ६०६, ६०७, ६१०, ६१४,
६२१, ६२८, ६३०, ६३७, ६४०

देखो लोक न्याय

न्याय तन्त्र ४, २०५, २५१, ६०३

न्यायिक ट्रिब्यूनल ४७७, ४७८

न्यासिना ६०७, ६११, ६१३

प

पजाब १५, ५९, ६०, ८४, १३०,
१५२, २१७, २१८, २२९, २५६,
२५७, २५८, २५९, २७५, २७७,
२७८, २८५, २८७, २९१, २९४,
२९७, ३००, ३०१, ३४५, ३४६,
३४९, ३९५, ४४१, ४४५, ४५२,
४६५, ५०४, ५०५, ५२५, ५३५,
३६, ५३७, ५४०, ५८४

पजाबकाड २५७-२६१, २६२, २६३,
२६९, ५८४, ५८५

पजाब सरकार ८४, ८५, २०१, २०७,
२१८, २२९, २६०, २६२, २७५,
२७७, ३०४

पटियाला, महाराजा ४५८
 पटेल, बल्लभ भाई १६७, ४२४, ४५२,
 ४५५, ४६३, ४६५, ४९१, ५००,
 ५३६
 पटेल, विठ्ठल भाई २१२ २१५, २५०,
 २५५, ३६८, ३७५, ४०५, ४१५,
 ४२७, ४३०, ४४७, ४४८, ४४९,
 ४५२, ५१४
 पन्त, गोविन्द बल्लभ ३५१, ४३८
 पत्तलू, सुवाराव ११६, २०६
 पब्लिक सर्विस कमीशन ४९, ६५, ११९,
 १८०, २०७, २०८, ३६१, ५०४
 पब्लिक सेफटी बिल ४१५, ४१६-४१९,
 ४२०, ४३१
 परतन्त्रता २२१, ३२२, ३५०, ६०१,
 ६०२
 परमात्मा १०, २७२, ३०५, ३०७,
 ३३७, ५१३, ५९८, ६०३, ६२८,
 ६३६
 परमानन्द, भाई ३०३, ३२३, ३२५,
 ३२६-३३२, ५४१, ५४४, ५४७
 परसनल ला ४६५, ५०३
 परोक्ष प्रतिनिधित्व ४६९, ४७३, ४८८
 पशुबलि ६२८
 पाकिस्तान ५६०, ५६३
 पारसी १२, ७९ १००, १०१, १५१,
 २०३, ३०६, ३४५, ३८७, ५४८,
 ५९९
 पार्लियामेंट (ब्रिटिश) १८, २५, ४२,
 ६०, ६४, ६५, ७२, २०८, २७५,
 ३६३, ३६६, ४३२, ४३४, ४४९,
 ४६१, ४९७ देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट

पाल, बिपिन चन्द्र २७६, २८६, ३७४
 पावल, वेडिन ५४, ५५
 पिकेटिंग ४५३, ४५४, ४५७, ४६३,
 ४६४
 पिछड़ा वर्ग ५२४
 पियरसन १९३
 पील, लार्ड ४५८, ४६१
 पील कमीशन ४
 पुराण १५, १६, १३९, १४२, ५१६,
 ५१७, ५२०, ५२१, ५२३, ६३२
 पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ३६०, ३९८,
 ४०३, ४०६, ४१९, ४३७, ४३९,
 ४७५, ४८१, ४८८
 पुलिस राज्य ३९३
 पुस्तक का लेखक ४९४, ५४८, ५६५,
 ५३६, ५८ दे० मुकुट बिहारी लाल
 पूजीपति ३७०, ३९९, ४००, ४४४,
 ४१७, ६१०, ६११, ६१२, ६१३,
 ६१४
 पूजीवाद ३९२, ६११
 पूना पैक्ट ५००
 पूर्ण स्वतन्त्रता ४३५, ४४१, ४५०,
 ४६६, ५६१, ५९० दे० स्वतन्त्रता
 पूर्णस्वराज्य ४३३, ४४०, ४४७, ४५०,
 ४५८, ४६३, ४७३, ४८८, ४९६,
 ५०८, ५०९, ५२५ दे० स्वराज्य
 पूर्ण स्वराज्य दिवस ४५०
 पूसा इन्स्टीट्यूट १२५
 पृथक् निर्वाचन ७३, १८०, २२२,
 २२३, २२४, ३०२, ३२३, ३३५,
 ३५१, ३५२, ४७७, ४९८, ५०७,
 ५०८, ५२४, ५२५, ५३४, ५३५,
 ५३७

पृथक् प्रतिनिधित्व ९३, ४७७, ४९८,
 ६०३ दे० साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व
 पेंटलैड, लार्ड २२१, २३०
 पेट्रियाटिक असोसिएशन २२
 पेशावर ४५२
 पीराणिक मन्त्र ५२३, ६३२
 प्रकाशम, टी २७६, ३४७, ३४८, ३७९,
 ४२१, ४२८
 प्रजाति १, ७, १३, १००, ११५,
 २०५, ४६२, ५०४, ५२४
 प्रताप, राणा १४३
 प्रतिक्रियावाद ५४३, ५४४
 प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा १९३-१९५, ५८१
 प्रतिनिधित्व ३८, ९४, ९५, १०२,
 ३०४, ३२२, ३३५, ३३७, ३४५,
 ३४९, ३६३, ५२८
 प्रतिनिधि-शासन ६९, २२४
 प्रतियोगिता परीक्षा ३, २२, ६२, ११५,
 २०७, २०८, २०९, २१०, ३२५
 प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व ६२, ६७, ९५,
 २०४, २२१, ४६९, ४७०, ४७३,
 ४८८
 प्रधानमन्त्री २६०, २८४, २८६, ४९२,
 ४९९, ५३५
 प्रधानमन्त्री की घोषणा ४६१-४६२,
 ४८५-४८६
 प्रफुल्ल चन्द्र राय २६, २९४, ३४७,
 ४९३, ५३८, ५९७
 प्रभुनारायण सिंह, काशी नरेन्द्र १४९,
 १५७, १७०
 प्रयाग सेवा समिति ५३, २६०, २६१
 प्रवेश अधिनियम २२८

४३

प्रह्लाद ६२८
 प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी २९०, ४५३
 प्रान्तीय राजनीतिक काफरेन्स ५७-५८,
 ८७-९०, १०४, २२७
 प्रान्तीय विधान (लेजिस्लेटिव) कौंसिल
 ५९, ९०, ९५ ९६, १०३ १०६-
 ११६, ११८, ३४६, ३८५, ४०३;
 ४३३, ४३६, ४६२, ५००
 प्रान्तीय सरकार ९०, ९४, ९८, १०५,
 १०७ ११८, १९०, १९१, १९७,
 २००, २२१, २२२, ५०२, ५३८,
 ५५८
 प्रान्तीय सिविल सर्विस १२०
 प्रान्तीय स्वशासन ३२३, ४७०, ४७२,
 ४७९, ४८०, ४८१, ४८६
 प्रान्तीय स्वायत्तता ३५६, ४५८
 प्रारम्भिक शिक्षा ९८, ११२, १२२
 १८६, १८७, १८८, १८९, १९१,
 १९२, ६२२
 प्रार्थना समाज १३
 प्रेमधर (मालवीयजी के दादा) २६, २७
 प्रेस ऐक्ट, अधिनियम १९५, १९६-
 १९९, २१४, २२८, ५८६

फ

फजल इब्नाहीम रहमतुल्ला ४००, ४०६,
 ४०७, ४१९
 फजल भाई करीम भाई १२१, १५५
 फजलुल हक २७८, २८२, २९४,
 ४५८, ४८३, ५०६
 फजले हुसैन, सर ५०७, ५३२, ५४२
 फारवर्ड पालिसी ४१२ दे० अग्रवर्ती
 नीति

फारसी ४६, ५७, १४४, १४८, २१०,
६२२

फासिस्टवाद ५४५, ५४९, ५५९

फिजी १९३

फिलस्तीन २१७, २८२, ५६०

फीरोज सेठना ४७५, ४८०

फूकन, टी, आर ४२१, ४२८

फेडरलकोर्ट ४६९, ४७०, ५५८

फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी ४५८, ४५९,
४६७-४७६, ४७९-४८२, ४८३

फौज ४, २०५, २१८, २५९

फौजदारी अदालत ४, ९३, २५८, ६०५

फौजी अदालत २६२, २६५, २६७,
२६८, २६९, ६०४, ६०५

फौजी कमीशन २४६

फौजी कानून २५९, २६३, २६५,
२६७, २६८, २७०, २७१, २७२,
६०४, ६०५

फौजी खर्चा ४१०, ४१४

फौलाद संरक्षण विधेयक ३६९-३७१,
४०१

फास २१६, २८२

ब

बंगभंग ६२, ६९, ७०, ७३, ९७,
१०३, ५८६

बंगाल ३, ६, ८, १२, १९, २१, ६२,
६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७४,
९२, १०६, १०७, ११५, १५२,
२१७, २२८, २२९, २५१, २५२,
२९०, २९१, ३३५, ३३६, ३४५,
३४६, ४४४, ४५७, ४८९, ५०४,
५०६, ५३३, ५३४, ५३६, ५३७,
५४०, ५४१, ५४७

बंगाल पैकट ३३५, ३३६

बंगाल नेशनल लीग १७

बंगाल रेगुलेशन ८५, ९७, १०३, २२८,
३३६

बजट ६६, ११४, २०६, २२२, ३५७-

३५८, ४०८, ४१०, ४२१, ४२२, ✓

४२३, ४२४, ४३८

बटलर, सर हार्कोर्ट १५२, १५३, १५४,

१५५, १५६, १९१

बनर्जी, गुरुदास १५२

बनर्जी, व्योमकेश चन्द्र १९

बनर्जी, सतीशचन्द्र २०२

बनर्जी, सुरेन्द्र नाथ ३, १८, ३८, ५७,

७३, ८५, १०२, १०३, ११६,

१५५, २००, २११, २१२, २१५,

२२०, २४१, २५०, २५६

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ४९, ५०,

५५, ५९, १४९-१७९, ३४१,

३८९, ४२६, ४५५, ४५६, देखो

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

बम्बई २, ३, १२, ९६, १०६, १०७,

११६, २५६, २९०, ३५१, ४२५,

४२६, ४४५, ४५३, ४८९, ५५६

बरकतुल्ला २१७

बर्कनहेड, लार्ड ३३०, ३६५, ४३४,

४३६, ४४४, ४४८,

बलूचिस्तान ३२५, ३४६, ३४९, ४३५

बसु, भूपेन्द्र नाथ ७३, ८६, १८५,

२०२, २१४, २१५, २३५, २४१

बसु, ज्ञानेन्द्र नाथ १६३

बहिष्कार ६२, ७०, ७१, ७४, २८५,

२८७, २९१, ४२४, ४३४, ४३५,

४५३, ४५७, ४९०

वाइकाट ५८, ७२, ७३, ७४, ८४, ८५,
२८७, २९२, ३००, ३२५, ४२४,
४३२, ४३३, ४३७, ४९६, ५०९

वाइबिल ६३४

वाउन्टी ३६९, ३७०, ३७१, ३९२,
४०१, ४२५-४३०

वादला ४५३

वाम्बे असोसिएशन १२, १३, १८

वाम्बे प्रेसीडेन्सी असोसिएशन १८

वारदोली ४५७

वाल विवाह ११, ३१०, ३२०, ३९६

वालशेविज्म ४८२

वाल्डविन, प्रधानमन्त्री ४३४

विडला, घनश्यामदास २९४, ४१९,
४२८, ४६७, ४८१, ४८७, ५००,
५०१

बिहार ८, १२७, ३५४, ३९५, ४५७,
५३५, ५३६, ५५६, ५५७, ५७२

बिहारी ५९०

बुद्ध ३२१, ३४१

बुनियादी शिक्षा ५५७

वेगार ११४

वेनरमैन, हेनरी केम्पबल ८३, २४६

वेलफोर ४७३

वेसिल ब्लेकेट ४०३, ४०५, ४०६,
४१३, ४३७

वेसेन्ट, एनी १४९, १५१, १५२, १६१,
१६३, १७१, १७९, २१८, २१९,
२२०, २२३, २३०, २३१, २३४,
२४१, २४५, २७६, २९४, २९५,
३७८, ४४२, ४४६

वीरसद ४५७,

वीस, आनन्द मोहन १८, ११६

वीस, सुभाष चन्द्र ५०७, ५१४, ५३०;
५३२, ५५६, ५५७, ५६१.

वीर ३०८, ३०९

ब्रह्मचर्य १६२, ३१०, ३१३, ६१७, ६२४

ब्रह्मचर्याश्रम १५, १३९

ब्रह्म समाज ११, १२

ब्रान्थल ४७७, ४८३, ४८८, ४८९

ब्राह्मण १५, ३०, ६३, १३८, ३२०,
३२१, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९,
५२०, ५२३, ६३०, ६३१, ६३२,
६३३

ब्राह्मण सम्मेलन ६३३

ब्रिटिश इण्डियन असोसिएशन ८, १८,
२१

ब्रिटिश उपनिवेश ७४, १२०

ब्रिटिश कामनवेल्थ ४५८, ४६८, ४७३,
४८८, ५६२, ५६३

ब्रिटिश पार्लियामेंट १, २, ६६, २३२,
२३४, २३७, २४२, २४४, २८१,
२९४, ३३१, ३५६, ३६३, ४३२,
४३४, ४३८, ४४३, ४६८, ४७३,
५०९, ५११, ५५८ देखो पार्लियामेंट

ब्रिटिश भारत ९८, ४४७, ४४८, ४५८,
-४५९, ४९३, ५३९, ५५९

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल २, ६, ६६, २८२,
४१२, ४३३, ४३४, ४४८, ४५०,
४६८, ४७३, ४७९, ४८७

ब्रिटिश राजकोष ६७, ९८, २४३

ब्रिटिश राज्य १२, ७६, ११९, २१७

ब्रिटिश लेबर पार्टी ४८०, देखो
मजदूर दल

ब्रिटिश व्यापार उद्योग २, ६, ७, ७३,
१२३, ३९२, ४०१, ४२२, ४२३,

४२४, ४२५, ४२९, ४५३, ४७४,

४७५, ४८१

ब्रिटिश शासन १७, १९, ११४, २१०,

३५७, ४७५

ब्रिटिश सरकार ६, ७, ८, ९, ६३,

६७, ७६, ९६, ९७, ९९, १२३,

१७३, १८९, १९९, २१६, २१७,

२१८, २३१, २३२, २३४, २४७,

२५५, २८१, २८२, २८३, २८६,

३५२, ३६३, ४२३, ४२६, ४३२,

४३७, ४३९, ४४७, ४४८, ४४९,

४५०, ४५९, ४६४, ४८१, ४८२,

४९७, ४९८, ५०९, ५२८, ५३१,

५३४, ५३५, ५३७, ५४२, ५५८,

५५९, ५६०, ५६१, ५६२

ब्रिटिश सत्ता ४, ५६३, ५६४

ब्रिटिश सेना ४११, ४१२, ४१४

ब्रिटिश साम्राज्य १७, ९८, २१८,

२२३, २२८, २३१, २३४, २८८,

३५६, ४१२

ब्रिटिश साम्राज्यशाही ४, ५, २६, ६०,

७०, ८६, १९२, ३२९, ३३१

५४५, ५५९, ५६४

ब्रिटेन ४२, ५८, ६४, ६५, ७३, ८७,

१२४, २०९, २१२, २१३, २१९,

२४४, ३६१, ४१७, ४१८, ४७३,

४८३, ४९२, ५२६, ५४९, ५८०

ब्रिटेन का सेना कार्यालय ४१२

ब्रेडला, चार्ल्स ४२, ६६

व्वाय स्काउट ५४

व्वाय स्काउट असोसिएशन ४५, ५५,

१३६

भ

भगतसिंह, सरदार ४६४

भगवद्गीता २९, ३४, ३११, ५२२,

५५५, ५७७, ५७८, ६१६, ६२६,

६३७

भगवद्भक्त ८०, ६००

भगवद्भक्ति ३४, १६६, १८७, ५१९,

५२०, ५२२, ५२३, ५९१, ६३२

भगवान् १३९, ५१३, ५१६, ५१७,

५२०, ५२३, ६००, ६२८, ६३२,

६३७

भगवान दास, डाक्टर १५२, १६२,

१६३, ३३४, ४९३

भट्ट, बाल कृष्ण ३६, ३८, ४७

भट्टाचार्य, आदित्य राम ३४, ३६,

१५७

भरतुहरि ५९७

भागवत २६, २७, ३२, ३३, ३०९,

५१८, ५५५, ५७८, ५९७, ६२६,

६२८, ६३७

भाषण की स्वतन्त्रता ५६२

भारत १, २, ४, ५, ६, ९, १०,

१७, १९, २०, २६, ५८, ६२,

६४, ६६, ६७, ७५, ७७, ८७,

८९, ९८, ११३, १२२, १२३,

१४३, २०६, २०७, २०८, २०९,

२१०, २१२, २१३, २१६, २१७,

२१९, २३१, २३४, २३८, २४०,

२४१, २४८, २८६, २९५, ३१८,

३४१, ३५५, ३६१, ३६३, ३६९,

३९३, ३९९, ४०२, ४०४, ४११,

४१२, ४१४, ४२२, ४२५, ४३२,

४३५, ४३८, ४४१, ४४८, ४५०,
४६०, ४६१, ४६३, ४६४, ४६५,
४६७, ४७५, ४८०, ४८२, ४८३,
४८४, ४९२, ४९७, ४९८, ५०९,
५२९, ५३८, ५४६, ५५३, ५५९,
५६०, ५७४, ६०७, ६०९, ६१३,
देखो हिन्दुस्तान

भारत धर्म महामण्डल ३९, १३१,
१३५, १३६

भारत मन्त्री २, ३, २०, ६६, ६७,
७०, १५१, १५४, १९४, २०४,
२०६, २०८, २११, २१२, २२३,
२३३, २३४, २३५, २३९, २४१,
२४२, २४३, २८१, २९६, ३६३,
३६६, ३९९, ४०३, ४०५, ४०६,
४२६, ४२७, ४३४, ४४७, ४५४,
५६२, ४७९, ४८७, ४९२, ४९७,
४९८, ५०७, ५११, ५३४, ५६१,
५६३, ६०३, ६३८

भारतमाता २६, २७, ३८, ३५३

भारत-यूनियन ५६२, ५६३

भारत सरकार २, ८, १७, ३८, ६०,
७१, ७५, ८५, ९३, ११२, ११७,
११८, १२०, १२३, १२४, १५१,
१५३, १५४, १८३, १८४, १९१,
१९४, २०१, २०३, २०७, २०९,
२१०, २१२, २१३, २२३, २२८,
२४०, २४४, २४९, २५४, २५५,
२५६, २६३, २८१, २८७, २९४,
३७४, ४०६, ४१०, ४११, ४२२,
४२३, ४२६, ४२७, ४२९, ४५९,

४६४, ४७४, ४८२, ४९३, ४९६,
५३९, ५५८, ६१२

भारती भवन २४, ४७, ४८, ५८३

भारतीय ७, १०, १३, १४, १७, २०,
२६, ६२, ६३, ६५, ६६, १४९,
२०६, २०९, २११, २२०, २३८,
२४०, २४२, २८६, ३०१, ३४१,
३५६, ३५७, ३५८, ३६३, ३७०,
३७१, ३७२, ४०२, ४०७, ४११,
४१३, ४१४, ४२३, ४३३, ४३८,
४८२, ४८४, ४९८, ५०९, ५२७,
५५९, ५७५, ५९९, ६०३, ६०७,
६१३, ६३६ देखो हिन्दुस्तानी

भारतीय आप्रवासी ९९

भारतीय उद्योग व्यापार ११०, ४२२,
४७५, ६१३

भारतीय औद्योगिक ४०६, ४७४, ४७५,
६१३, देखो औद्योगिक

भारतीय औद्योगिक आयोग १२१-१२४

भारतीयकरण ९९, १२४, २३९,
३५६, ३५७, ३५८, ३६३, ४०८,
४१२, ४१३, ४१४, ४७०, ४७१,
४७२,

भारतीय नरेश ४५८, ४६०, ५५९
देखो राजा

भारतीय पोलियामेंट ४४३, ४४४

भारतीय राज्य ४३३, ५५९

भारतीय राष्ट्र १३, २१, ६०, ५७८,
५९८, ५९९, ६००

भारतीय राष्ट्रीयता २४, ५९९

भारतीय रियासतें ४११, ४४७, ४४८,
४५०, ४५९, ४६२

भारतीय विधान कौंसिल १८०-२१३,
२४९-२५६, २६२-२७४, ३९१

भारतीय वाङ्मय ३९१, ६१८

भारतीय संघ ४५९, ४६०

भारतीय संरक्षा अधिनियम १९५,
२००-२०१, २२८, २४९, २५०,
२५१, २५३, २५४, २७५

भारतीय संस्कृति १०, १४, १६, २७,
१३६, १४९, १५०, १५९, १७३,
४१९, ६१८ ६२०, ६२३, ६३५,
६३९, ६४०

भारतीय सिविल सर्विस ३६१

भारतीय सेना १२४, ३५५, ३५८,
३६३, ४११, ४१३, ४१५, ४७२,
५६०

भारतीय सैनिक ४, २६, १२४, २२०,
४१४

भाषण की स्वतन्त्रता ५६२

भीष्म ६०६, ६१८

भूमिगत आन्दोलन ५६४

भूमि व्यवस्था ६, १०३, ५५६, ५५७,
६१४,

भोपाल, नवाब ४५८, ४६७

म

मंगल सिंह, डाक्टर १७७, ४९६, ५६७

मंगला प्रसाद १५३

मंगल सिंह, सरदार ४४१, ४४५,

मजदूर ६, ९, १०८, ३९२, ३९९,
४००, ४१६, ४१७, ४१९, ४३१,
४६०, ४६६, ५४५, ५८१, ६११,
६१२ दे० श्रमिक

मजदूर दल ४७९, देखो लेबर पार्टी

मजदूर सरकार ४४७, ४५४

मजहूरलहक १८०, १९०, २०२, २०४,
२१५, २२०, २५०, २५५

मजुमदार, अम्बिका चरण २४१

मताधिकार ४६९, ४७३

मदनी, हुसैन अहमद २१७, २९०

मद्रास २, ३, १९, ६८, १०६, १०७,
११६, ३२४, ३५४, ३९४, ४३३,
५५६

मद्रास नेटिव असोसिएशन १९

मध्य प्रदेश १०३, ३५४, ३९५, ४५३,
४५७, ५५६, ५५७

मध्यवर्गीय शिक्षित ९, १०, १४, १७,
२२, ९४

मनु ९४, १२८, १३२, १६१, १८५,
५२२, ५९१, ६१८, ६२९, ६३७

मनुष्यता २६९, ३१७, ५७२, ५७७,
५८८, ६०१, ६०२, ६२९, ६३४

मनुस्मृति २९, ३२, ६०७ देखो मनु
मन्त्रदीक्षा १३७, १३९, ५१७, ५२०,
६३२

मन्दिर १३९, ३०६, ३१७, ३१८,
३२४, ३३७, ५१७, ५७१, ६३२,
६३४

मन्दिर प्रवेश १३९, ३२४

मलकाना ३१३

मस्जिद ३०६, ३१७, ३१८, ३३५,
३३७, ३३९, ३४४, ३४८, ३५१,
३५२, ६३४

महमूद उल हसन, मौलाना २१७

महमूदाबाद, महाराजा १८०, २१५,
२५०, २७४, ३४३, ४४३

माटेग्यू २१२, २१५, २३३, २३५,
२३६, २३८, २३९, २७६, ३०३

माटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, रिपोर्ट २११,
३५७

महाजन, बी एन १५०

महाजन सभा १९

महादेव पाण्डेय, प्राध्यापक १७१, ३१५

महाभारत १४२, ५१९, ५५५, ६३०

महाभद्रयाग ५५२

महावीर दल १४०, ३१६, ३१७

महेन्द्र प्रताप, राजा २१७

माघ, कवि ५८७

माध्यमिक शिक्षा १८७, ६२२-६२३

मातृभाषा १४३

मातृभूमि ४५, १६७, ३५५, ४९३,
५०९, ६२४

माथुर, प्रो० कृष्ण कुमार १७१

मज्रव अधिकार २७२, २८४

मानवता १३, १४, ३२८, ५९६, ६००

मानव स्वतन्त्रता ३३६, ३३८, ३६६,
३६८

मार्ले, लार्ड ५८, ७३, ९१, १०२,
१९५, ३८९

मार्ले-मिटो सुधार ९२, ११६, २३६

मार्शल ला कोर्ट २५८, २७९

मार्शल ला २५७-२५९, २६५, २६६,
२६९, २७५, २७९, २८०, ४५७,
६०४, ६०५,

मालगुजारी १२६, १२७

मालगुजारी का स्थायी बन्दोबस्त ६२,
१०८, १२७, ३२१, ३९१, ५८१,
६१४

मालती ३५, ५५५, ५७३

मालवीय, मदन मोहन—अध्ययन ३२-

३३, अध्यापन ३५-३६, अन्त्यजोद्धार

५००-५०१, ५१६-५२३; अभ्युदय

४९-५०, असहयोग आन्दोलन २८६-

२८७, २९१-२९२, २९९-३०१;

असेम्बली में काम ३५४-३७६,

३९४-४३१; अस्पृश्यता ३१०-३११,

आत्मनिर्णय २४५, ३५७, ४३७-

४३८, आदित्य राम भट्टाचार्य ३४

३६, इंडिपेंडेन्स कांग्रेस पार्टी ३७७-

३९४, इंडिपेंडेन्स पार्टी ३५४, ३७४-

३७५, इंडेमिनिटीबिल २६४-२७४,

इस्तीफा २५५, ४२९-४३०,

उत्पादन शुल्क ३६९, उदार हिन्दू

धर्म की व्याख्या १३०-१४०,

५१६-५२३, ६२६-६३७, औद्यो-

गिक विकास ११०-११२, ११९-

१२४, १८३, ३६९-३७१, ४०१-

४०२, ५७४, ६०९-६१०, कांग्रेस

में काम ३८-३९, ४२-४४, ६२-

७६, ८७-९०, ९४-१०२, २३४-

२३५, २४१-२४८, २८६-२८७,

२९१-२९२, ३५२-३५३, ३७६,

४५५-४५६, ४९२, ४९४-४९८,

५०८-५१२, ५२६-५२८, ५३५,

५४९, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी

५३३-५३५, किसान और कृषि

विकास १०७+१०८, १२५-१२९;

१८४-१८५, क्रान्तिकारी ९७,

१०४-१०५, २५१-२५४; गांधीजी १७३, २७१, २७७ २७८, २९२, ३१३, ३३६-३३८, ५७४ गांधी-रीडिंग समझौते का प्रयास २९३-२९८, गो सेवा १३७, ३२०, ५५५ गोलमेज काफरेन्स ४७०-४७५, ४८२, ४८४-४८५, चीफ रकाउट ५४-५५, छात्रावास का निर्माण ४८, जनकल्याण पर आश्रित आर्थिक व्यवस्था ६०७-६१४, जन्म २५, दमन का विरोध ७२, १९६-२०१ ३६६-३६९, ४९२-४९३, ४९५-४९६, ५१०-५११, दमन से पीड़ितों की सहायता १०५, २६०-२६१, ३०५, ५६५-५६७, धार्मिक स्वतन्त्रता ४२०, ५०२-५०३, ६०४, धर्मधृत मानवता ६२६-६३७, नमक सत्याग्रह ४५५-४५६, नागरी लिपि ४६-४८, १४७, नामजदगो की प्रथा ६४, ९६, नेशनलिस्ट पार्टी ३५४, ३९४-३९८, ४३०-४३१, पब्लिक सेफ्टी विधेयक ४१६-४१९, परिवार २७, ५५४-५५५, पिता २७, पुरुषोत्तम दास टंडन ४९, प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा का विरोध ९९, १९३-१९५, प्रत्यक्ष निर्वाचन ९५, ४७३, प्रयाग म्युनिस्पलटी ४८, प्रयाग सेवा समिति ५३-५४, प्रान्तीय कौंसिल में काम १०५-११६, प्रारम्भिक शिक्षा ९८, ११२, १८६-१९२, प्रेस विधेयक १९६-१९८, बजट ११४-११५, १८१-१८३, ३५६-३५८, ३७२-३७३, ४१०, ४२१-४२२, ४२३,

वनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी १४९-१७९, ५५१-५५२, वलदेव राम दवे ५०; बालचर ५४-५५; भारत धर्म महा-मंडल ३९, भारती भवन पुस्तकालय ४७-४८, भारतीय विधान कौंसिल १८०-२१६, २४९-२५६, २६२-२७४, माता २८, मानव स्वतन्त्रता की पुष्टि ३६६ ३६९, ४२०, ५१०, ६०४, मुद्रानीति का विरोध ३९९-४००, ४२२, मोती लाल नेहरू ५६-६१, ३८०, ३८३-३८६, राज-नीतिक सुधार ३८, ३९, ४२, ६७-६९, २२४ २२७, २३४-२३५, २३७ २४०, ३५७, ३६५-३६६, ३७३, ४२३, ४२४, ४३७-४३८, मौलिक अधिकार २७२, ५१०, ६०४, रिजर्व बैंक विधेयक ४०३-४०४, ४०५, ४०६, रियासतें ४७३, ४९३, ५८०, रोलेट बिल २५०-२५२, लाजपत राय का निधन ४४०, 'लोडर' ५०-५१, वकालत ४३-४५, ३१०, वदान्यता ३६९-३७०, वयस्क मताधिकार ४७३, ६०२-६०३, वित्त विधेयक ३५८-३६०, ४०९-४१०, ४१४, वित्त व्यवस्था और नीति ६३-६४, ११५, १८१-१८३, ३५८, ४०९, विद्रोह सभा विधेयक १९९-२००, विनोद ३३-३४, ५९१-५९३, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ४२०; व्यक्तित्व ५७७-५९७, शिक्षा का विस्तार ९८, १०९-११०, ११२-११३, १८६-

१९३, ६१५-६२५, शील का पालन
और प्रचार २८-२९, १६०-१६२,
५८६-५९०, श्वेत पत्र का विरोध
५०९, ५२६, संघ व्यवस्था ११७-
११८, ५७३; संयुक्त भारतीय राष्ट्र
३१८, ३२४, ५९८-६०६, संयुक्त
निर्वाचन ९५, ५२६-५३५, ६०२-
६०३, सनातनधर्म ३९, १३१-१४३,
५१६-५२३, ६२६-६३७ समाज-
सुधार १८५-१८६, ३१०-३१६,
३९६-३९९, ५१६-५२३, सम्पत्ति का
अधिकार ४४१-४४२, ४४३, ४७५-
४७६, सम्राट से भेंट ४८७; सविनय
अवज्ञा १४१, ४५५-४५६, ५०९-
५१०; साइमन कमीशन का दाइकाट
४३१-४३४, ४३७-४३८, साम्प्र-
दायिकता का विरोध १००-१०१,
१३०-१३१, ३०६-३०७, ५९८-
५९९, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व
का विरोध ९१-९२, ९५, २०३,
२२४, ५२५-५३८, साम्प्रदायिक
समझौते का प्रयत्न (एकता काफ-
रेन्स) ५०१-५०७, साम्प्रदायिक
समस्या ३३३, ३३७-३३९, ३४६-
३४७, ३५२-३५३, साम्राज्यिक
अधिमान का विरोध ४०१, ४२२-
४२३, ४२५-४२९, सिक्ख ३०९,
३६७-३६८, ४४५; सिविल सर्विस
६५-६६, ११४-११५, ११९-१२०,
२०७-२१०, ३६१, सीमा शुल्क
३६९, ४०१-४०२, ४२२-४२३,
४२४-४२९, ६०९; सुन्दर लाल

डाक्टर ४८-४९, सेना का भारतीय-
करण १२४, ३३५-३५६, ३५८,
४१०. ४१२, ४१४, ४१५, ४२२,
४७१-४७२, स्त्री का गौरव व शिक्षा
१८८, २४८, ३१३-३१६, स्थाई
वन्दोवस्त १०७-१०८, ६१४,
स्वदेशी ३६, ३७, ७२, ७५, ८१,
४९३-४९४, स्वराज्य और स्वशासन
८३-८४, २२५, ३१० ५४९,
स्वराज्य पार्टी से सम्बन्ध ३५४,
३७४-३७५, ३७६, हरिद्वार ५६,
१४०-१४३, हिन्दी १४३-१४८,
१५९, १७४, ६२१-६२२,
'हिन्दुस्थान' का सम्पादन ४०-४१,
हिन्दू सगठन ३०२-३३२, हिन्दू-
मुस्लिम सौहार्द ३०६-३०७, ३१८,
३३७-३३८, ३५२, ४३६, हृदय
नाथ कुजर ५५

मिटो, लार्ड ५२, ५८, ७३, ७५, ७६,
१०२, १९५, ३०२

मिटो, लेडी ७६

मिटो पार्क ५३,

मित्र, चारुचन्द्र ४२, ५०

मित्र, भूपेन्द्रनाथ ४३७

मित्र, राजेन्द्र लाल २२, २३

मित्र, शारदा चरण १४५

मित्र, एस० सी० ४२१

मिल, जान स्टुअर्ट ३८९, ३९३, ६०९

मिश्र, रामनारायण ४९४

मीरा २९, ५९१, ५९२

मुआवजा ३९१, ३९३, ४४३, ६१२,
६१४

मुजे ३२३, ३२५, ३३१, ३४६, ३७७,
४१२, ४५०, ४७९, ५२४, ५४७,
५४८

मुकर्जी, आसुतोप १४५, २६२

मुकर्जी, राजेन्द्र १२१, ५९०

मुकुट बिहारी लाल १७१, ४९३, ५६५,

५६७ दे० पुस्तक का लेखक

मुकुन्द मालवीय ३५

मुक्तव्यापार ५, ६११

मुक्ति दिवस (मुस्लिमलीग) ५६०

मुडीमैन, अलाकजंडर ३४४, ३६२,

३६३, ३६६, ३७५

मुडीमैन कमेटी ३६२-३६६

मुदालियर, दीवान बहादुर ४८०, ४८१

मुद्रा ३७२, ३९८-४००, ४०२

मुद्रानीति ३६९, ३९९, ४०४, ४०६,

४०९, ४२२, ४३१, ४५४

मुवारक १४५

मुल्ला, जगत नारायण २६२, २८०

मुसलमान १४, २२, २३, ६६, ७३,

७६, ७९, ९१, ९३, ९४, ९५,

१००, १०१, १०२, १०३, १३१,

१४५, १५१, १५५, १८०, २०३,

२०४, २१७, २२६, २२७, २४८,

२७५, २८२-२८५, २८७, २८९,

२९७, ३०२, ३०४, ३०५, ३०६,

३०७, ३१०, ३१२, ३१७, ३२३,

३२७, ३२८, ३३३, ३३५, ३३६,

३३७, ३३८, ३३९, ३४१, ३४२,

३४४, ३४६, ३४८, ३४९, ३५१,

३५२, ३५३, ३५४, ३६५, ३८२,

३८३, ३८४, ४००, ४४१, ४४५,

४४६, ४५९, ४७७, ४७८, ४७९,

५०४, ५०५, ५०६, ५२४, ५२५,

५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३४,

५३६, ५३८, ५३९, ५४२, ५४५,

५४८, ५७१, ६२२, ६३४, देखो

मुस्लिम लीग

मुस्लिम काफरेन्स ४४६, ५०२, ५०७

मुस्लिम डिफेन्स असोसिएशन २२

मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी ४३१

मुस्लिम प्रशासन ५९९

मुस्लिम यूनिटी बोर्ड ५०७-५०८, ५२९

मुस्लिम यूनीवर्सिटी १५१, १५५,

४३०, ५२७, ५२९

मुस्लिम राज्य ५३५, ५९९

मुस्लिम राष्ट्र ५६०, ५९९

मुस्लिम लीग ७५, १३०, २०६, २२०,

२२१, २२२, २२३, २२४, २४६,

२७५, ३०२, ३४५, ४३५, ४३६,

४४४, ५०७, ५४०, ५४१, ५५७,

५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५७२,

५९८

मुस्लिम शिष्ट मंडल ७५

मुस्लिम संस्कृति ५५७, ६००

मुहम्मद अली, मौलाना २१७, २३१,

२७४, २७६, २८३, २८४, २८८,

२८९, २९०, ३४२, ३४४, ३४७,

३५३, ४३५, ४४६, ४५८ देखो

अली बन्धु

मुहम्मद अली फार्मुला ५०५, ५०८

मूना देवी, मालवीयजी की माता २८

मेकडोनल्ड, प्रधान मंत्री ३२२, ४५६,

४५८, ४६१-४६२, ४७८, ४७९,

४८२, ४८५, ४८६, ४९८, ४९९,
५०७, ५२४, ५२५, ५२८, ५३१,
५३६, ५९९
मेकडोनल, एन्टनी ४७
मेकडोनल हिन्दू बोर्डिंग हाउस ४८,
५८६
मेकाले २०८
मेकिनटाश २७२
मेक्सवेल ५६६
मेगना कार्टा ८, ९
मेत्सनी ४३७
मेयो, लार्ड ११८
मेसोपुटेमिया २१७, २३३
मेस्टन, सर जेम्स ५६, १४०
मेहता, जमनादास ४०६, ४१९, ४३१
मेहता, फीरोजशाह १८, ८५, ८७,
११५, २१८
मेहताब सिंह, सरदार ४४६
मोक्ष १३४, ३२१, ६२६
मोतीचन्द, राजा १५८, १७१,
मोदी, एच. पी. ४६०
मोपला विद्रोह ३०५
मोहसिन उलमुल्क ५०८
मौलिक अधिकार ३४६, ३६७, ३९१,
४२०, ४४१, ४६५, ४६६, ५६९,
४८४, ५०३, ५५६, ५८०, ६०३,
६०४, ६०५
म्युनिस्पलटी ७६, ९२, ९५, १९०,
३२३

य

यज्ञ ८०, ६३६
यन्त्र विज्ञान ३९२

यहूदी २८२, ३४१
याकूब, सर मुहम्मद ३४३, ३४४,
४२८, ४३९
याज्ञवल्क्य ५२२
यान्त्रिक इंजीनियरी ११०, १२०,
१६०, ६२३
यान्त्रिक उद्योग १२१
युक्तप्रान्त ३, ९, ४९, ५२, ५५, ५६,
६६, ९६, १०३, १०४, १०६,
११०, १११, ११३, ११५, ११६,
१४१, १५२, २०५, २४७, २५१,
३५४, ३८१, ३८५, ३९४, ४५८,
४९१, ४९२, ४९३, ५३६, ५४६,
५५४, ५५६, ५५७
युक्तप्रान्त की विधान कौंसिल १०६-
११६
युद्ध ६७, १२२, २१२, २१३, २५९,
२६७, २६८, २८२, ५५८, ६०४
युद्ध-लाभ-कर २१४
युद्ध सलाहकार समिति ५६१
युधिष्ठिर १४२, ५१८
यूथोपिया ७०
यूरोशियन ६५, ९३, ११५, २०९,
२११, ३६६, ४०१
यूरोप ११०, ११७, २१६, २३४
३६५, ४२२, ५५८
यूरोपियन १७, ६५, ८८, ९३, ११४,
११५, १९८, २०५, २०७, २०९,
२११, २४७, ३६३, ४३२, ४५८,
४६०, ४७७, ५०६, ५१०, ५३७,
५३८, ६३७
यूरोपियन व्यापारी ४०६, ४०७

र

रंग बिहारी लाल १७८
 रंग भेद ७, ६९, ११५, २५४, ३३४,
 ३६५
 रंगा अय्यर ३९५, ४३७
 रगा चारियर ३५६
 रघुनाथ राव १९
 रमा, मालवीयजी की पुत्री ३५
 रमाकान्त मालवीय ३५, ५३, ८७,
 ५५४, ५५५
 रलियाराम ४४५, ४४६
 रसखान १४५
 रहीम १४५
 राजकुमार का बहिष्कार २६०, २९३,
 २९४, २९५,
 राजकोष ११२, ४०२, ४०४, ४०६,
 ६०६, ६१०, ६१५
 राजगुरु, क्रान्तिकारी ४६४
 राजगोपालाचारी, सी. ५००, ५६३
 राजभक्ति ७५, ८१, ८२, १३५, ४१४
 राजनीतिक अपराध ३६६-३६७
 राजनीतिक सुधार ५८, ७३, ९०,
 १०३, २०६, २२०, २३१, २३२,
 २३३, २३६-२४१, २४२-२४७,
 २५३, २५४, २९३, २९४, ३०३,
 ३६२, ३६३, ३७५ ४३१, ४३५,
 ४४५
 राजनीतिक हिंसा ४६४
 राजविद्रोह ८७, १०५, २२८, २३०,
 २४९, २५१-२५२, २५३, २६३,
 २६५, ६०५
 राजा ८, ८१, ८८, १२८, ४६७,
 ४६९, ४८२, ४८४, ४९३, ५८०
 देखो भारतीय नरेश

राजा, एम. सी. ४९९, ५००
 राजेन्द्र प्रसाद, डाक्टर १६१, ३००,
 ३०५, ३०७, ३४८, ३९०, ५००,
 ५०६, ५३२, ५३५, ५४०, ५४१,
 ५७४, ५७५
 राज्यसभा ५६, २४६, ४०३, ४०४,
 ५६६, ५६७
 राधाकान्त (बंगाल) ११
 राधाकान्त मालवीय ३५, ४४, १७०,
 ५५०
 राधाकृष्ण, डाक्टर १५७, १७२, १७५,
 १७६, १७७, ५५१
 राधेश्याम शर्मा १७४, १७५, १७६,
 ५१२, ५७०,
 रानडे, महादेव गोविन्द १३, १४, १५,
 १८, २३, ६०८
 राम ३४, १४२, ३२१, ५१३, ५२२,
 ५७१
 रामकृष्ण परमहंस १६
 राम चरण दास ४२, ४८
 रामचन्द्र राभो ४८०
 रामपाल सिंह, राजा कालाकाकर २१,
 २७, ४०-४१
 रामपाल सिंह, राजा कुररी सुदौली
 २१५, २७३, ३०३
 राम मोहन राय १०, ११, १२, १३,
 २३
 रामशरण दास, रामबहादुर १३९
 रामेश्वर सिंह, महाराजा दरभंगा १५१
 रालिसन १२४, ४७२,
 रावर्टस, चार्ल्स २३५
 राष्ट्र ८, ९२, १११, १२९, १८१,
 २८७, २९९, ३२०, ३२२, ३५०,

- ३६५, ३९०, ४२७, ४४२, ४६४,
४६८, ४७०, ४७१, ४७५, ५२५,
५६५, ५६६, ५७५, ५७८, ५८०,
५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०४,
६०८, ६०९, ६११, ६१४, ६१६,
६१७, ६१८, ६२१, ६२३, ६३३,
६४०
- राष्ट्रकल्याण ५८८, ६१४
- राष्ट्र की रक्षा ६३३
- राष्ट्रभाषा १४, १४६, १४७, ३३४,
६२१,
- राष्ट्रवाद ४६५, ५९९
- राष्ट्रवादी ३८८, ३९०, ४००, ५९८
- राष्ट्रवादी मुसममान ३४४, ५३०
- राष्ट्र सेवा ४५, ५५, १५८, १६४,
१६५, ६२४
- राष्ट्रहित २२९, २९१, २९२, २९३,
२९६, ३५८, ३६९, ४७५, ४८१,
६०७, ६१०, ६११, ६१२, ६१३,
६२४, ६३८,
- राष्ट्रीय अर्थतन्त्र १४
- राष्ट्रीय एकता १९, १००, ३१२, ३४४,
५०६, ६०३
- राष्ट्रीय उद्योग ४०२
- राष्ट्रीयकरण ३९२, ३९३, ६१०, ६१२
- राष्ट्रीयता १२, ७७, ८०, ८२, ८४,
३२२, ३२४, ३५२, ३८३, ४४५,
४८१, ५०६, ५२८, ५४०, ५६०,
५७१, ५८०, ५९८, ५९९, ६००,
६२४, ६३७
- राष्ट्रीय नीति ३२१, ३५८
- राष्ट्रीय भावना ११, १२, १३०, १६१,
- १६८, २८९, ३२३, ५३३, ५८७,
६००, ६०३
- राष्ट्रीय माग ५८, २२६, २८६, ३५४,
३६३-३६४, ३७६, ४१८, ४५०,
४६८, ५२५, ५६०
- राष्ट्रीय रक्षा ३५५, ३७३, ४११
- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ७१, ७४, ८५,
१४९, २१९, ६१५
- राष्ट्रीय सरकार ४७१, ४८०, ५६१,
५९९
- राष्ट्रीय सेना ४१४, ४७१
- राष्ट्रीय स्वशासन ४७०, ५०६
- रिचार्ड, जस्टिस ४५
- रिजर्व बैंक विधेयक ४०२-४०६, ४३१,
६१०, ६१२
- रिपन, लार्ड ३, ६, ७, ३६, २१४
- रियासत ४५९, ४६१, ४६९, ४७३,
४८२, ५६२, देखो देशी रियासतें
- रिस्पासिव कोआपरेशन पार्टी ३७७,
३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२,
३९४
- रीडिंग, लार्ड १६५, २९३, ४४८, ४५८
४६१, ४७२, ४७४, ४८८
- रीवाँ, महाराजा ४५८, ४५९
- रूजवेल्ट, प्रेसीडेंट ५६२
- रूस ७०, १११, २१६, ६०९
- रिसले, हर्वर्ट ६९, १४०
- रेल १०९, १२२, १८३, १८४, ३५८,
३७५, ४०८, ६१०, ६१२
- रेलवे बोर्ड ३७५, ४०८
- रैयतवारी ४५३
- रोमन लिपि ६२२

रीलेट अधिनियम २७५, २७९, २८९
रीलेट कमेटी २४६, २४९, २५०,
२५३
रीलेट बिल २०१, २१५, २४९-२५६

ल

लंकाशायर ४२५
लक्ष्मण शास्त्री द्राविड १३६
लक्ष्मेश्वर सिंह, महाराज दरभंगा २१
लखनऊ समझौता ३२२, ३२३, ३४५
लगान ६२, ८८, १०७, ५५७, ६१४
लगान बन्दी २८७, २९६, ४५३, ४५७,
४५८, ४९२
लाजपतराय ७०, ७१, ८५, ९७, २७४,
२८५, २८८, २९१, ३१०, ३११
३२१, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०,
३३४, ३३५, ३४१, ३७९, ३८०,
३८२, ३८३, ३८५, ३८६, ३८८,
३९२, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७,
३९८, ४०६, ४०७, ४२०, ४३०,
४३१, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०,
४४२, ६१५
लायडजार्ज ४४८
लारेंस, सर हेनरी १२८
लालचन्द, लाला ३०२, ३०३, ३२५
लिटन, लार्ड ३, ५, ६, ८, १९७
लिनलिथगो, लार्ड १२५, ५५८, ५५९,
५६३
लिबरल पार्टी, ब्रिटेन की ७०, ४५८,
४६१, ४८८
लिबरल पार्टी, भारत की ३५४, ३६४,
३६५

लिबरल फेडरेशन, ४३४, ४४९
लियाकत अली खाँ ५५७
ली कमीशन ३६०, ३६१
लीग आफ नेशन्स २४७ ४२४
लीजस्मिथ ४८०
'लीडर' ५१-५२
लेबर पार्टी ५२५ दे० मजदूर दल
लैसडाउन लार्ड ६९
लोक कल्याण ५७७, ५७८, ६०६,
६३३, ६४०
लोकतन्त्र ९, १३, १७, २४, ७७,
१३६, २१६, ३९३, ४४५, ५५९,
६००, ६०५, ६०६, ६१७, ६२१,
लोकतान्त्रिक अधिकार ६१४
लोकतान्त्रिक कल्याणराज्य ४६६
लोकतान्त्रिक चरित्र ६१७
लोकतान्त्रिक जीवन ६०३, ६३८
लोकतान्त्रिक नागरिकता १६६, ६१७
लोकतान्त्रिक धारणा ६१२
लोकतान्त्रिक भावना ४८४, ५२४
लोकतान्त्रिक मताधिकार २०४
लोकतान्त्रिक मर्यादा, शील, भद्रता २५,
५७८, ६०२, ६०३
लोकतान्त्रिक मान्यता २४
लोकतान्त्रिक युग ६३८, ६३९
लोकतान्त्रिक वैधानिकता ६३७
लोकतान्त्रिक व्यवस्था ६०१
लोकतान्त्रिक शासन ५४६
लोकतान्त्रिक संविधान ४४२, ४४३
लोकतान्त्रिक सधीय व्यवस्था ६३८
लोकतान्त्रिक संसार ५५७

लोकतान्त्रिक सिद्धान्त २१, २४, ३५०,
५४३, ६१७

लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता ५५९

लोकन्याय ३६८, ५८८, ६०४

लोक संग्रह ६०६,

लोक सेवा आयोग ६०३

लोक सेवाएँ ३५२, ३७९, ४०८, ४६२,
४६४, ४७०

लोथियन, लार्ड ४९५

व

वंकटपतिराज ३७२

वदान्यता ३६९, ३७०, ३७१, ४०१,
४२५-४३०

वयस्क मताधिकार ४४१, ४६९, ४७०,
४७३, ५२७, ५६०, ५६१, ६०१,
६०२, ६०३

वर्ग २१, ६५, १२०, १३६, ४७२,
४८४, ६००, ६१२, ६३८

वडंबुड, विलियम ४१३

वर्ण १४, १३७, १३८, १३९, ३०९,
५१८, ५१९, ६३१, ६३३, ६३५,

वर्णश्रम धर्म ३०९, ३२१, ६३३

वर्णश्रम स्वराज्य सच १३६

वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ७, १९७

वशिष्ठ १८५, ६१८

वाइसराय ७५, ७६, ९७, १२८, १८०,
१९६, १९९, २०४, २१४, २८०,
२८१, २९३, २९४, २९५, २९८,
४१०, ४१६, ४३२, ४४७, ४४९,
४५४, ४६२, ४६६, ४८७, ४८९,
४९०, ४९२, ५५८, ५६०, ५६१,
५६२, ५६४

वाइसराय कमीशन ४१३

वाइसराय की घोषणा ४४८-४४९

वग्मट्ट ५५०

वाघा, दिनशा इटुलची १८, २१२,
२१५, २४२, २५६, २६४

वानप्रस्थ १४, ६३३

विटरटेन ३५३, ४३९

विसेंट, विलियम २६३, २७०, २७१

विकेन्द्रीकरण ११७-११८, ६०३

विकेन्द्रीकरण आयोग ९४, ११७ ११९

विक्टोरिया १, ७, ८, ९, २०, २६,
५२, ५८, ६५, ६८, ७७, २०८

विक्रमादित्य १४७, ५५६

विचार की स्वतन्त्रता ५१०,

विजयराधवाचार्य चक्रवर्ती ११६, २८६,
२८७, ३३२, ४४२, ४४६

विजयानगरम, महाराजा १५८

विज्ञान १०, ६१९,

वित्त ४६३, ४६८

वित्तनीति ११५, ११७, १२२, २०५,
२२५, ४०८, ४०९, ४१७, ६०६,
६०७

वित्त विधेयक ३५७-३६०, ३७४, ३७६,
४०८-४१०, ४१२

वित्तीय ऋण ४६८

वित्तीय उत्तरदायित्व ४६२

वित्तीय नीति, १२३, १८१, ३७६,
४०८, ४१७, ४२९, ६०६, ६०७

वित्तीय विकेन्द्रीकरण ९०, ९८

वित्तीय व्यवस्था (प्रान्तीय) १०६, १०७
१०९, ११५, ११७, १८१,

वित्तीय संरक्षण ७५, ३९२, ४५९,
४६०, ५८१,

वित्तीय स्वतन्त्रता ४२७
 वित्तीय स्वशासन १२०, १२१, २३९,
 ४०६
 वित्तीय स्वायत्तता ४६०
 विदेशी ४१६
 विदेशी उद्योग ४७४, ४७५, ६१३
 विदेशी कपडे ४५३, ४५४, ४५७,
 ४९१
 विदेशी पूँजी ३७०, ३७८, ६१३
 विदेशी राज्य ४६४
 विदेशी विशेषज्ञ ६१३
 विदेशी व्यापारी ४७४, ६१३
 विदेशी शासन ४८४, ६०१
 विदेशी सरकार २५५, ४२७
 विद्या ९४, १६२, ५२१, ६२३, ६२४,
 ६२९, ६३०
 विद्यार्थी १०२, ११०, ११६, १२५,
 १४९-१७९, २५४, २६४, २९१,
 ५५२, ५५३, ५७३, ५८६, ६००,
 ६१५, ६१८, ६१९, ६२०, ६२३,
 ६२४, ६२५, ६४०
 विद्यामन्दिर ५५७
 विद्युत विज्ञान ३९२
 विद्रोह सभा अधिनियम १९५, १९९-
 २००, २२८
 विद्युत परिषद १३६, ३१९-३२०
 विघवा १०, ३१५, ३१६
 विधायको का मेमोरेण्डम २२१
 विधान कौंसिल ६२, ६६, ६८, ८८,
 ८९, ९१, ९५, ११८, २०६, २२१,
 २२२, २२३, २२५, २२८, २३०,
 २३४, २३८, ३२४, ३३५, ३७७,
 ३८२, ३८९, ४३४

विधान सभा ९१, २९१, ३२२, ३२३,
 ३४६, ३५९, ४०३, ४२१, ४४४,
 ४४५, ४४८, ४७१, ५०३, ५०४,
 ५०५, ५०९, ५५७, ५६०, ५६१,
 ६०३, ६०५, ६१४, ३३९,
 विधान मंडल ३४०, ३४९, ३५२,
 ३५५, ३६४, ४०३, ४३२, ४३४,
 ४३५, ४३६, ४६१, ४६२, ४७२,
 ४७३
 विनिमय ३१८, ३७२
 विप्लव, सन् १८५७ का १, ५, ८, १६,
 २५, ८४
 विलसन, वुड्रो २४५, ६०१, ६३७
 विलिंगडन, लार्ड २३२, ४८९
 विवेकानन्द १६
 विश्व धर्म सम्मेलन १६
 विश्वम्भर नाथ ४२, ४६
 विश्वज्ञान ६१८, ६२३
 विश्वयुद्ध १७२, २००, २५९, २५३,
 ५४२, ५५८
 विश्ववन्दुत्व ६२७
 विश्वविद्यालय ६२, ११३, ११५, १२४
 २५२, ५२४, ५२५, ६१०, ६१९,
 ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४
 विश्व शान्ति १७३, ५५२
 विश्वेश्वरैया २९४, २९७
 विष्णु प्रसाद २६
 विष्णु भक्ति ५२०, ६३०
 वुड, चार्ल्स १२६
 वूलविच कालेज ४११, ४१३
 वेजवुड वेन ४४८, ४८२
 वेडरनवर्न, विलियम २०२

वेद १५, १६, १४२, ३१०, ३११,
५२३, ६२३

वेद व्यास १००, १४२, १८८, ५९१,
६२६, ६२७

वेदान्त ३४१, ६२७

वेस्ट लैंड, जेम्स १११

वैज्ञानिक खेती ११०

वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति ३९०, ६१९

वैदिक धर्म ३०९

वैदिक संस्कृति १५

वैदिक सम्यता ५४९

वैदेशिक मामला, विषय ४६२, ४६८,
४७०, ४७२, ४७३

वैद्य ५१६, ५१७-५२०, ५२३, ६३१

व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा सत्याग्रह

५१४, ५१५, ५२६, ५६२

व्यक्तिवाद ३९३, ६०७

व्यक्ति स्वातन्त्र्य २०१, ४२०, ६१२

व्यवसाय प्रधान ६०७

व्यापारिक शिक्षा १२३, ६१०

व्यायाम १६२, ६१७, ६२४

व्यास, ब्रजनाथ मालवीयजी के पिता ५३

व्यास, ब्रजमोहन ५८७

शंकर १८०

शफात अहमद खाँ, प्रोफेसर ४६०, ४७७

शफी, सर मुहम्मद १८९, २८१, ३६५,
४००, ४३५, ४४६, ४५८, ४७७,
४७८, ४८२, ५४२

शर्मा, वि० एन १८०, १८६, १९२,
२१०, २११, २१२, २१५, २७३

शार्दूल सिंह, सरदार ३४६, ३५१,
५२५

शादीलाल, सर ३०३

शासन व्यवस्था ८८, ३६१, ३६२,
३६३, ३७३, ३७६, ४१०, ४२०,
४४०, ५६१, ५८०

शास्त्र १०, ३१२, ३२०, ५१६, ५२०,
५९६, ५९७, ६२७, ६२८, ६३०,
६३१, ६३४, ६३५, ६३७

शाह नवाज, मुहम्मद ४३०

शाही घोषणा सन् १८५८ १, ७, ८,
९, २०, २६, ४३, ६५, ६८, ७७,
२०८

शिक्षा ६२, ११२, ११३, १८२, १८६-
१९२, ३९०-३९१, ३९८, ४१८,
५५६, ५७८, ६१५, ६३३, ६४०

शिक्षा पद्धति ६१५, ६२५

शिक्षा सस्थाओं का बहिष्कार २८६,
२८८, २९१-२९२

शिल्पविज्ञान शास्त्र ६२, १५०, ३९१,
३९२, ४०९, ६१०, ६१९, ६२०,
६३७

शिवकुमार ५७३

शिवनाथ काटजू ५७०

शिव प्रसाद गुप्त १५९, ५८४

शिव प्रसाद सितारे हिंद २२

शिवराम वैद्य ५८७

शिवराव ४६०, ४८०, ४९३

शिवस्वामी ऐय्यर, पी० एस० १५७,
३५७, ३६०, ३६२, ३६४, ३६६,
३७२

शिवा जी ४१४

शील २८, ३०, १६१, ५१९, ५२२,
५२३, ५३३, ५८८-५९०, ६२४,
६३१, ६३२, ६३७

शुक्र ६१८

शुद्धि १५, १३६, ३१०, ३११, ३१२,
३१३, ३२०, ३२६, ३२७, ३२९,
३३३, ३३७, ३३८, ३३९, ६३४

शुल्क आयोग ४२३

शूद्र १५, १३८, ३१०, ५१७, ५१८
५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३,
६३०, ६३१, ६३३

शेयर केपिटल होलडर्स बैंक ४०२, ४०३,
४०४, ४०५, ६१०, ६१२

शेरवानी, तस्दुक अहमद खाँ ३३३,
५२९

शेर सिंह, ज्ञानी ४४१

शोकत अली, मौलाना २१७ २७४,
२८३, २८६, २८९, २९०, ३८०
३४२, ३४७, ५०१

श्यामाचरण दे १५९

श्रमिक १२१, ४८१, ६१०, ६११,
६१३

श्रमिक जनता ५८१, ६०६

श्रद्धानन्द, स्वामी २६०, २६१, २७४,
२७७, ३११, ३१३, ३१५, ३२६,
३२७, ३२८, ३३०, ३३३, ३४५,
५८०, ५८४

श्रीधर (पौत्र) ५५५

श्री प्रकाश ५७५

श्री निवास शास्त्री १८६, १९२, २१०,
२११, २१२, २१५, २२३, २५५,
२५६, ३४३, ४५८, ४६३, ४७२,
४७३, ४७४, ४७५, ४७९, ४८०,
४८१, ४८७

श्रीराम वाजपेयी ५४, १३६

श्वेत पत्र ५०९, ५१५, ५२६, ५२७,
५३०, ५३५

स

संघ सरकार ४६९,

संघीय व्यवस्था ११८, ४५८, ४५९,
४६२, ४६८, ६०३

संघि काफरेन्स २४५, २८३

संन्यास १४, ३२१

संयुक्त निर्वाचन २२३, २२४, ३२४,
३३५, ३४५, ३४६, ३४९, ३५०,
४३५, ४४१, ४४४, ४६५, ५०१,
५०४, ५०५, ५०८, ५२४, ५२५,
५२६, ५३१, ५३४, ५४२, ६०२,
६०३

संयुक्त राज्य अमरीका २१६, २१८,
४६९, ६०३

संयुक्त राष्ट्र १०१, ३१८, ३२२

संयुक्त राष्ट्रीयता ३४३

संयुक्त, स्वशासित भारतीय राष्ट्र ३२४,
५९८, ५९९

संरक्षक आयात ४५१,

संरक्षण शुल्क १८२, १८३, ४२४-
४२९ देखो सीमा शुल्क

संरक्षा की समस्या ३१६-३१७, ४७१,
४७२

संरक्षित विषय २४२, २४३, २४६

संरक्षित अधिकार ४६२

संवैधानिक अधिकार ४३२, ४६२, ६०२

संवैधानिक आन्दोलन १०१

संवैधानिक निरंकुशता १९५

संवैधानिक प्रतिबन्ध ४६२

संवैधानिक राजा ४८४

संवैधानिक व्यवस्था ५८०, ६०३

संवैधानिक व्यवहार ६३९

संवैधानिक सरकार ७२, ५८०

संवैधानिक सुधार १०२, ४२९

संसदीय भद्रता ६३९

संसदीय व्यवस्था ६०३

संस्कृत २६, ३३, १२०, १४४, १४६,

१४८, १५९, २११, ५९१, ६२०,

६२१, ६२२

संस्कृति १०, १५०, ४६५, ५०३, ५७८

सकलतवाला ४१८

सत्य १४२, १६२, ५१८, ५१९, ५२१,

६२९

सत्यपाल, डाक्टर २५७, २६०, २७९

सत्यमूर्ति २७६, ३५१, ५१२

सत्याग्रह १४१, २५६, २९९, ४५२,

४५४, ४५५, ५२६, ६०२

सदाचार ५१९, ५२२, ५२३, ५८२-

५८४, ६१६, ६३०, ६३१, ६३२

सनातन धर्म ३४, ७०, १३१, १३६,

१३७, १३८, १३९, ३१२, ३१४,

३१९, ३२९, ५१६ ५१७, ५२०,

५२३, ५४५, ५४९, ५५२, ५७८,

६२६, ६३३, ६३४, देखो धर्म,

हिन्दू धर्म

सनातन धर्म समा १६, ३९, ४०,

१३१, १३२, १३७, १३८, १४०,

१५०, ३२०, ५१६, ५१७, ५४७-

५४८, ५५२, ५५३, ५६९

सनातन धर्म सम्मेलन ३९, १३६, ३१४

सनातन धर्मी ३९, १३५, १३९, १८५,

३१०, ३१२, ३१४, ३१६, ५१७,

५४३, ५४४, ५४५, ६३२

सप्रू, सर तेजबहादुर ४४-४५, २०२,

२०५, २११, २१५, २२३, २५५,

२६२, ३४३, ३६२, ३७६, ३७७,

३७८, ४४१, ४४५, ४४७, ४४९,

४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६१,

४६३, ४७२, ४८०, ४८८, ४९९,

५१२, ५६८, ५७५

सम्य सरकार ११२, ११५, २५५,

३६०, ४७१, ६०६

समझौता विरोधी सम्मेलन ५६१

समता १७, ३९३, ५०९

समत्व ६१६, ६२६, ६२७, ६२८

समरी कोर्ट २७९

समाजवाद ३२८, ५४५, ६१२

समाजवादी ३९२ ६११, ६१२, ६३७

समाजवादी धारणाएं ५४३

समाजवादी समाज ३९३, ५४५

समाजसुधार १२, १८, १५, १६, १३६,

३२०, ३२९ ३८८, ३९३, ३९६-

३९८, ४३८, ५९६

समाज सेवा १४, १५ ५७८, ६२१,

६२३

समानान्तर सरकार ४६८-४६९

सम्पत्ति ४४१, ४४२, ४७५, ६१०

सम्प्रदाय १, ४, ७६, ९३, १०१, १२०,

३२०, ३२३, ३३३, ३३४, ३३९,

३४३, ३४९, ३८३, ४४१, ४६२,

४६५, ४८४, ५०२, ५०३, ५०४,

५२८, ५२९, ५३४, ५३५, ५३६,

५३८, ५४६, ५४८, ५५७, ५५९,

५६०, ५७८, ५९९

सम्प्रदायवाद ४६५

सम्राट् १, २, ९९, २१८, २१९, २२३,
२४४, २७४, २७८, २८३, ३७२,
४५८, ४८७

सम्राट् की सरकार १०३, २७५, ४३२,
४३६, ४३७, ४४९, ४६१, ४८०,
४८५, ४८६, ४८९, ५३९, ५५९

सयाजीराव गायकवाड १५७

सर्वदलीय कांफरेन्स, सम्मेलन २९७,
२९८, ३२५, ३३९-३४०, ३९१,
४४०-४४६, ४७५, ६१४

सर्वहारा वर्ग की तानाशाही ६१२

सर्वांगीण विकास ७८, ५७८, ६१५-
६२५

सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी ५५१

सलीमपुर, राजा साहब ५०७, ५०८

सविनय अवज्ञा २८७, २८९, २९०,
२९६, २९७, २९८, ३६०, ३७८,
३८६, ४५१, ४५३, ४५६, ४६३,
४८७, ४९०, ४९६, ५०८, ५०९,
५१०, ५१४, ५२७, ६०२

सविनय अवज्ञा आन्दोलन १६८, १७१,
१७२, १९०, २९८, ३२१, ४९०,
५११, ५१२, ५२६

सविनय प्रतिरोध ७०, ७१

ससमल. बी. एन ५४४

सांस्कृतिक अधिकार ४६६

सांस्कृतिक दृष्टिकोण ६१८

सांस्कृतिक मान्यता ६४०

सांस्कृतिक विचार ६३९, ६४०

साइमन कमीशन ३२५, ३२९, ३३०,
३३१, ३३२, ४३०, ४३१, ४३२-
४४०, ४७९, ५३४

सात्त्विक कर्ता ५८८, ६३७

सात्त्विक तप १३४, १३५, ५७७,
६२९, ६३०,

सात्त्विक सार्वजनिक जीवन ५७९-५८०

सामन्तवाद, सामन्तशाही ९, ३५४

सामाजिक उत्तरदायित्व ६०६, ६११

सामाजिक उदारवाद ६०६

सामाजिक उपयोगिता ३९३

सामाजिकता ६०६

सामाजिक न्याय ६, १४, ६०६,
६११, ६३७, ६४०

सामाजिक बहिष्कार ४५४

सामाजिक हित ३९३,

साम्प्रदायिक उपद्रव, कलह ३०६, ३१७
५३७

साम्प्रदायिक एकता ११, १७४

साम्प्रदायिक दंगे, झगड़े ३१६, ३३५,
३४३, ३५१

साम्प्रदायिक तनातनी, वैमनस्य ७९,
२३८, ३३३, ३३८, ३४४

साम्प्रदायिकता ६९, १०१, १२०,
१५६, २२३, ३०३, ३२२, ३३६,
३५१, ३५२, ३५४, ३७८, ३७९,
४४५, ४४६, ५२४, ५४३, ५७२,
५९८, ६००, ६२४

साम्प्रदायिक निर्णय, उसका विरोध १७२,
३३२, ४६४-४६५, ४९८-५००,
५०७, ५०८, ५२४-५४८, ५९९

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, चुनाव ७६,
९१, ९३, ९५, ३०३, ३०४,
३२२, ३२३, ३२५, ३४०, ४९८,
५०८, ५२५ ५९८

साम्प्रदायिक प्रश्न ४४१, ४४४, ४७६,
४७८, ५३३, ५३४, ५४२, ५७१,
साम्प्रदायिक भावना, मनोवृत्ति ५४५,
६०३

साम्प्रदायिक भेद २३८, ३८२, ६३४
साम्प्रदायिक राजनीति ५९८

साम्प्रदायिक समझौता २२३, ३४०,
४६६

साम्प्रदायिक समस्या ३२४, ३३३,
३३६, ३४०, ३८०, ४३७, ४४२,
४४६, ४७६, ४७७, ४७९, ४८६,
४८८, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६,
५३७, ५४५, ५६०

साम्राज्य ११७, ११८, ४६०

साम्राज्यवाद ३९२, ५५९

साम्राज्यवादी शक्तिया ४४५

साम्राज्यशाही ४, ५, २६, १९५,
३३०, ३३१, ३३२, ४११, ४८९,
५५९

साम्राज्यशाही युद्ध २१६, ४१२

साम्राज्यिक अधिमान ३९२, ४२५

साम्राज्यिक नीति ३३२, ४१२

सार्वजनिक सभा, पूना १८

सालसवरी, लार्ड ३

सावरकर, विनायक ५४७

सिंचाई १०९, १८४, ६१०

सिडनेहम, लार्ड २२१

सिध ३२५, ३४६, ३४९, ४३५,
४४१, ४४३, ४४४, ४४५, ४६५,
४८६, ५०५, ५३७

सिधिया, माधव राव १५७

सिक्ख २०३, २२८, २५३, ३०४,

३०६, ३०८, ३०९, ३४०, ३४१,
३४९, ३६७, ३६८, ४१४, ४४१,
४४४, ४४५, ४४६, ४६५, ४६९,
४७७, ४७८, ४९७, ५०३, ५०४,
५०५, ५२४, ५३४, ५३७, ५४०,
५४२, ५७४

सिन्हा, सच्चिदानन्द २०५, २१५,
२७३, ५६८, ५८५

सिन्हा, सत्येन्द्र प्रसन्न १०३, १९५,
१९६, १९८

सिविल सर्विस ६६, ८८, १०४, २०९,
२१०, २११, २४६, ३६१, ४७०,
सीतलवाद, सर चम्मन लाल ११६,
१५५, २६२, २८०, ३७२, ४७९,
४८०

सीतारमैया, पट्टाभि २९७, ३९०,
५१२, ५३७

सीमा प्रान्त ३०४, ३२५, ३४६,
३४१, ३५१, ३५२, ४३५, ४४४,
४४५, ४५८, ४६५, ४८६, ४८९,
५०४, ५०५, ५३७

सीमा शुल्क ५, ३५८, ३९२, ४३१,
४६८ देखो संरक्षण शुल्क

सुखदेव, क्रान्तिकारी ४६४

सुधार जाच कमेटी ३६३, ३६४

सुन्दरलाल, डाक्टर ४४, ४७, ४८-४९,
१५२, १५७

सुप्रीम कोर्ट ४६९, ५०३, ५०४

सुब्रायन, श्रीमती ४८०, ४८१

सुलतान अहमद, सर २६२, २८०

सूरदास २९, ५९१, ५९२

सेंट्रल मुस्लिम पार्टी ४०९, ४३०,
४३७

सेंट्रल सिव्ख लीग ४४४, ४४५
 सेंट्रल हिन्दू कालेज और स्कूल १४९,
 १५२, १५३, १७१, ४९४
 सेठना, सर फीरोज ४७५, ४८०
 सेंडहर्स्ट, सैनिक कालेज ४, १२४,
 ३५६, ४११, ४१२, ४१३
 सेन, माखन ५३६, ५४४
 सेनको, लार्ड ४५८, ४८०
 सेनगुप्ता, जे एम ३४७, ३५१, ४५२
 सेनगुप्ता, नलिनी ५०८, ५१०
 सेना ४, २६, ६२, ८८, ९८, ९९
 १२४, २६८, २८९, ३१७, ३६३,
 ३७५, ४१२, ४१५, ४२२, ४६८,
 ४७०, ४७१, ५०४, ६०३
 सेना नीति १८१, ३५९, ४१०-४१५,
 ४२२, ४२६, ४३१,
 सैनिक २७३, २७४, ६०६
 सैनिक कार्यालय (ब्रिटेन का) ४१२
 सैनिक कालेज १०४, १-४, ३५६,
 ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४७२,
 सैनिक खर्चा ६७, १८२, २२३
 सैनिक व्यवस्था ३५५-३५६
 सैनिक शिक्षा ५, १७३, २००, २२५,
 २४६, ३५५, ३५६, ४११, ४१३,
 ४७२, ६३३
 सैन्यवाद ३९२
 सैयद अहमद खा, सर २२, २३,
 ५०८
 सैयद महमूद, डाक्टर ३४२, ५०१,
 ५०८
 सोशल काफरेन्स १४, ५९
 सोशलिस्ट ५२७, ५३०

स्कीन कमेटी ४१०, ४११, ४१२,
 ४१३
 स्टॉक होल्डर बैंक ४०५
 स्टीफन, न्यायाधीश १९९, २६८,
 २७३
 स्टेट बैंक १८३, १८४, ४०३, ४०५,
 ६१०, ६१२
 स्टेनली, न्यायाधीश ४५
 स्त्री १०, १८५, २४७, २४८, ३०५,
 ३०७, ३१०, ३१३, ३१४, ३१५,
 ३१८, ३१९, ४५३, ४६५, ४९१,
 ४९७, ५७१, ५८३, ६१२, ६३०,
 ६३२, ६३३
 स्त्री शिक्षा १२, १८८, ३१५, ६१५-
 ६१६
 स्थानीय स्वायत्तता ७, ६९, २२१
 स्पेंकी, न्यायाधीश २६७
 स्लोकांम्बे, जार्ज ४५४
 स्वच्छन्द व्यापार १११, १८३
 स्वतंत्रता १, ४, ७७, ८३, १३६,
 १६६, २१६, २२०, २३४, २४५,
 २४६, २५०, २५१, २८९, २९६,
 ३२१, ३२४, ३२८, ३२९, ३३०,
 ३४३, ३५०, ३८४, ३९०, ३९३,
 ४३३, ४३५, ४३८, ४४७, ४५९,
 ४६०, ४७०, ४८३, ४८४, ४८५,
 ४९७, ५०९, ५११, ५२६, ५३१,
 ५४३, ५४९, ५५९, ५६८, ५७८,
 ५९८, ६००, ६०१, ६०३, ६०४,
 ६०६
 स्वतंत्रता संघर्ष ४९, १७४, ३२८,
 ३३०, ३९०, ४३०, ४३८, ४५३,
 ५५५

स्वतंत्र व्यापार ६०८, ६०९

स्वतन्त्र राज्य ५३५

स्वतंत्र ४७४, ४७५

स्वदेशी ३६, ७१, ७२, ७४, ७७,
८१, ८४, ८५, ९०, १०१, १०३,
१७१, २१९, २८९ ३००, ४०२,
५९५

स्वदेशी संघ ५५, १७१, ४९३ ४९४

स्वराज्य ७१, ७३, ७६, ८१, ८२,
८३, ८४, २१९ २१६, २२७,
२८५, २८७ २८८, २९६, २९७,
३००, ३०१, ३०६, ३१०, ३१८,
३२२, ३२५, ३२९, ३३४, ३४०,
३४१, ३५२, ३७८, ४१७, ४२१,
४३३, ४३६, ४४१, ४४७, ४५०,
४८४, ५२७, ५३५ ५३७, ५४७,
५५३, ५६७, ५७०, ५८२, ५९८

स्वराज्य पार्टी ५९, ३५४, ३५६, ३७२,
३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३८०,
३८१, ३८२, ३८४, ३८७, ३९०,
३९८, ५२५, ५२६

स्वर्णमुद्रा ३९९

स्वशासन ८८, १६६, २१८, २१९
२२०, २२५, २३०, २३४, २३८,
२३९, २४६, ३६१ ४१८, ४३६,
४५९, ४६२, ४७१, ४८१, ५२५,
५३८

स्वशासित उपनिवेश, डोमिनियन ७३,
२१३, ३५६, ३६३, ४४१

स्वशासित संयुक्त राष्ट्र ५४८

स्वामित्व के अधिकार ४४३

स्वायत्तशासन ७३, ७४, ८६, ९१,
२३३, २३४, २४६, ४६०

स्वायत्तशासित सदस्य ८६

स्वास्थ्य ११२, ११३, १८२, ६१७

ह

हटर कमेटी २६२, २७६, २७७, २७८,
२८०-२८१

हंसराज, रायजादा ३८५, ४००, ४४०

हंसा मेहता ४५५

हडताल ४१६, ४१७, ४१९, ४२०,
४३५, ६११

हनुमान २८

हफीज उर्रहमान ४९७

हरदयाल, लाला २१७

हरविलास शार्दा ३९६, ५९६

हरिजन ५६, १६२, १६५, ३३१,
४९८, ५००, ५०१, ५१६, ५५६,
६१५, ६३२, ६३३ दे अन्त्यज्य अस्पृश्य

हरिजन सेवक संघ ५६, ४९४, ५०१,
५१५

हरिजनोद्धार १७१, ३३१, ५१३,
५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५४७

हरिद्वार ४०, ५६, १८०, १४१, १८२,
३०३, ३०४, ५५६, ५७०, ५८९

हरिसिंह गौड सर ३६८

हरिसिंह, महाराजा १७७

हरिश्चन्द्र, राजा १४३

हसन इमाम २०२, २४४, २४७, २९४

हसरत मुहानी २७६, २९७, ३६७,
४३५

हार्डकोर्ट ४, २५, ४३, ४४, ४५, ४७,
१९९, २०१, २३८, ३५४

हावसन, जे. ए. ११०

हाडिंग, लार्ड १५५, १५६, १९१,
२१४

हालैड, सर टी एच. १२१

हिंसा २८४, ३४८, ४१८, ४६४;
५६८

हिजरत २८५

हितलरशाही ५५९

हिदायत हुसैन, हाफिज ४५९, ४८३

हिन्दी ३६, ४६, १४३-१४८, १५४,
१५९, १६०, १७३, १७४, ५०३,
५७८, ५९१, ६२१ ६२२

हिन्दुत्व ३०२, ३२४, ३२८, ४९८,
४९९, ५५७, ५९८

हिन्दुस्तान १, ६५, ७३, ७५, ७६,
७८, ८३, ९८, १४९, २०९,
२१६, ३०७, ३२२, ३५६, ३६४,
४२२, ४२३ ४२४, ४३२, ४४२,
४५९, ४८१, ४८७, ५३१, ५४६,
५५३, ५५९, ५६०, ५९९ दे. भारत

हिन्दुस्तानी २, ६५, ६९, ७२, २११,
२३३, २६३, २६४, ३०१, ३०६,
३०७, ३५४, ३५७, ३६२, ४३२

हिन्दुस्तानी भाषा १४८, ३३४, ५०३

हिन्दू १२, १५ २३, २४ ७८, ७९,
९१, ९३, १००, १०१, १३१,
१३७, १३८, १४०, १४९, १५०,
१५१, १५५, २०३, २२६, २२७,
२७५, २८२, ३३५, ३३७, ३३९,
३४१, ३४४, ३४५, ३४८, ३४९,
३५१, ३५२, ३५३, ३६५, ३८२,
३८४, ३८९, ३९६, ४३५, ४४२,
५०१, ५०२, ५०४, ५०५, ५०६,
५१६, ५३०, ५३३, ५३४, ५४५,
५४८, ५७०-५७२, ५९९, ६२२,
६३२, ६३४, देखो हिन्दू महासभा

हिन्दू जाति ३८३, ५२०, ५३७,
५३९, ५४०

हिन्दू धर्म ११, २३, ५९, ६०, १४९,
१५०, १५५, ३०४, ३०५, ३०७,
३०८, ३०९, ३१३, ५१६, ५२२,
६३४, ६३७, ६३९

हिन्दू प्रशासन ५९९

हिन्दू महासभा, संघटन १३०, ३०२-
३३२, ३३३, ३३४, ३३८, ३४२,
३६७, ३७८, ३७९, ३८७, ४३४,
४३६, ४४३, ४४४, ४५०, ४७८,

५२९, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४,
५४७, ५५३, ५५४, ५७२, ५७३,
५९८

हिन्दू-मुस्लिम एकता ७८-७९, १५५,
२५६, २८८, ३००, ३०६, ३०७,
३१०, ३२५, ३२९, ३३७, ३५१,
३५८, ५९८

हिन्दू-मुस्लिम क्षागडे, वैमनस्य १३०,
३०५, ३०७, ३३३, ३३८, ३४५

हिन्दू-मुस्लिम समझौता ३६५, ४४४

हिन्दू-मुस्लिम समस्या ३३२, ३३६,
३३९, ५०१

हिन्दू राज्य ३८३, ५३५, ५९९

हिन्दूराष्ट्र ५४८, ५९९, ६३९

हिन्दू सस्कृति १७४, ३८९, ५७५,
६००, ६३२

हिन्दू समाज १४०, १५५, ३०४,
३११, ३१३, ३८३, ४९८, ४९९,
५२२, ५४८, ५९८, ६३२, ६३९

हिन्दू सम्मेलन (पंजाब) ३३८

हिन्दू साम्प्रदायिकता ५७२

हिन्दूहित १३०, ३०२, ३१९, ३२३,
३२९, ३३१, ३८३, ३८४, ५७८

हीगल १६०

हीरावल्लभ शास्त्री १७१

हेरीहेग ५११

हेली, सर मेलकम २७०, ३६२

हेवेट, सर जान ९६

हेल्सवरी, न्यायाधीश २६७, २६८

होमरूल लीग, आन्दोलन २१९, २२०,
२२७, २३०, २३४

होर, सर सेमुअल ४८७, ४८८,
४९७, ४९८, ५०७, ५११, ५३४

ह्यूम १९, ३८, ४४

हस्तान्तरित विषय २४२, २४३,
२४६

शुद्धिपत्र

पुस्तक में भाषा और प्रूफ की कुछ अशुद्धियाँ रह गयी हैं। उनको ठीक करते हुए पढ़ने की कृपा की जाय। कुछ विशिष्ट अशुद्धियाँ नीचे दी जा रही हैं :—

| पृष्ठ | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|-------|---------------|-------------------|------------------------|
| ५ | २८ | १८६९ | १८७९ |
| २० | १७ | विधानों | विधान सभाओं |
| २३ | ११ | मसावी | मुसावी |
| ४२ | ६ | रूस के अतिरिक्त | रूस को छोड़कर |
| ५० | २० | दो वर्ष | ढाई वर्ष |
| ५३ | २४ | नापुनर्भवम् | नाऽपुनर्भवम् |
| ५७ | २७ | कांग्रेस | कांग्रेस |
| ६२ | १३ | पराक्षा | परीक्षा |
| ७० | १, ३ | १९०४ | १९०५ |
| ७५ | १६ | मुसलिम | मुस्लिम |
| ७६ | १८, १९, २० | मुसलिम | मुस्लिम |
| ७७ | १२ | दो वर्ष | ढाई वर्ष |
| ८५ | २५ | प्रस्तावित | अनुमोदित |
| १०० | १२ | या | मा |
| १३७ | १ | अस्पृश्यो | अस्पृश्यो |
| १४० | २४ | १९२६ | १९१६ |
| १६२ | ७ | देशभक्त्यात्यागेन | देशभक्त्याऽऽत्मत्यागेन |
| १६२ | ७ | सम्मानर्ह | सम्मानर्हः |
| १७८ | ६ | १९१९ | १९११ |
| २१२ | १९ | वी० एम० शर्मा | वी० एन० शर्मा |
| २३५ | ७ | कार्य पारिषद् | कार्यपरिषद् |
| २५६ | १-२ | पेश करना | पास कराना |
| २७० | १३, १६ | टम्सन | थाम्पसन |
| २७१ | १४, १८, १९ | टाम्सन | थाम्पसन |
| २८३ | नोट नं. २ | पृ. १९० | जि. १ पृ. १९० |

| पृष्ठ | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|-----------------------|---------------|----------------------|---|
| २८८ | २९ | असहयोग | करवन्दी, असहयोग |
| २९१ | ४ | अब्बुल | अबुल |
| २९४ | १६, २१ | कान्फ्रेन्स | कांफरेन्स |
| २९५ | ७, १२ | „ | „ |
| २९६ | नोट नं० २ | पृ० २२६ | जि० १ पृ० २२६ |
| २९९ | ४ | ५ फरवरी को | चौरीचौरा में ५ फरवरी को |
| ३१९ | २७ | १९२५ | १९२४ |
| ३२६ | १५ | हिन्दू सहति | हिन्दू सहति |
| ३३३ | १२ | जमीयतुल उलमा | जमीयतुल उलेमा |
| ३४४ | २४ | „ | „ |
| ३४८ | ८ | मदरास | मद्रास |
| ३५० | २५ | मेगनाकार्टी | मेगनाकार्टी |
| ३६७ | ४ | खडगसिंह | खड़कसिंह |
| ३७९ | नोट नं० १ | जि० २ | जि० १ |
| ३८६, ३९५ | नोट नं० १ | नेहरूजी | नेहरूज |
| ३८६ | नोट नं० २ | काग्रेस | काग्रेस जि० १ |
| ३९६ | नोट नं० १ | वही | लेजिस्लेटिव असेम्बली डिबेट्स |
| ४०० | २४ | औद्योगिक इब्राहीम | औद्योगिक फजल इब्राहीम |
| ४१४ | १ | शीघ्र | शीघ्र |
| ४२० | २३ | आघात | आघात |
| ४३१ | २४ | समस्याओं पर कांग्रेस | समस्याओं पर श्री एन० एम० जोशी तथा कांग्रेस |
| ४४८ | २ | करेंगे | करें |
| ४७४ | २९ | श्री एम० आर० जयकर | सर काउसी जहागीर |
| ४७९ | ११ | वे | रमसे मेकडोनल्ड |
| ५०५, ५०७, ५०९, ५२६ | नोट नं० १ | क्वाटरली | ऐनुअल |
| ५३६ | २८ | सतीश चन्द्र | सरद चन्द्र |
| ५३७ | नोट नं० २ | क्वाटरली | ऐनुअल |

| पृष्ठ | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|-------|---------------|--------------------------|---|
| ५३८ | १७ | अलेम्बली में प्रस्ताव | असेम्बली में सर नृपेन्द्र नाथ सरकार के प्रस्ताव पर संशोधन |
| ५३९ | १२ | इस संशोधन के पहले भाग पर | साम्प्रदायिक निर्णय पर |
| ५३९ | १५ | गिर गया | गिर गया । देसाई साहब के संशोधन का पहला भाग भी गिर गया |
| ५४० | २ | १९३४ | १९३५ |
| ५४० | नोट १ | आत्मकथा | आत्मकथा |
| ५४४ | २२ | सतीश चन्द्र | सरदचन्द्र |
| ५५९ | १८ | बढाने को | बढने को |
| ५७५ | नोट नं० २ | कोमिमोरेशक | कोमिमोरेशन |
| ६०१ | नोट नं० १ | सन् १९२८ | सन् १९१८ |
| ६०७ | १६ | समर्थ | सामर्थ्य |
| ६०७ | नोट नं० १ | सन् | सन् १९१७ |
| ६१२ | ९ | अर्घान | अधीन |
| ६१५ | १९ | कुरातियो | कुरीतियो |
| ६१८ | १० | जनता से | जनता के जीवन से |
| ६३२ | १४ | महालम्यो | माहात्म्यो |
| ६४१ | ७ | दिसम्बर सन् १८८५ | अक्टूबर सन् १८८५ |
| ६४७ | २० | ८ अगस्त | १७ अगस्त |
